

विश्व-इतिहास की झलकें

[दूसरा खण्ड]

लेखक

परिचित जवाहरलाल नेहरू

प्रकाशक

सस्ता साहित्य मण्डल, दिल्ली

प्रकाशक,
मार्तण्ड उपाध्याय,
मंत्री, सस्ता साहित्य मण्डल, दिल्ली ।

पहली बार : ३०००
अप्रैल सन् १९३८
मूल्य, दोनों खण्डों का
आठ रुपये

मुद्रक,
हिन्दुस्तान टाइम्स प्रेस,
नई दिल्ली ।

क्षमा-प्रार्थना

हमारा इरादा 'बालक' के दोनों खण्डों को एकसाथ ही प्रकाशित करने का था जो लेकिन अनचाहो से दूसरे खण्ड का मंदिर आने में और प्रेस की ओर से छपाई में अनिचाय रूप में जो देरी हुई उसके कारण पहला खण्ड दिसम्बर के अन्त में प्रकाशित करना पड़ा। हमने हमें तो अनुविधा हुई ही, पाठकों को भी अनुविधा हुई होगी इसके लिए हम पाठकों से क्षमा चाहते हैं।

इस खण्ड के अन्त में जो निर्देशिका (Index) दी गई है उसके तैयार करने में भी हमें बहुत अनुविधा और मिहनत उठानी पड़ी। एक मित्र ने इसके तैयार करने का भार उठाया था, लेकिन उसपर और दूसरे काम का भार आजाने से वह इसे पूरा न कर सके; इस कारण अपने और कार्यों को करने हुए, वह भी हमीको करना पड़ा। पहले से इस कार्य का कोई अनुभव न होने से हममें कई त्रुटियाँ रह गई होंगी, इसके लिए हम पाठकों से क्षमा चाहते हैं। १५०० पृष्ठों की महीने-बचा महीने के थोड़े-से समय में पहलकर उनकी निर्देशिका बनाना आसान काम नहीं था। अगर इस कार्य में अपने साथी श्री पुरुषोत्तम पन्त और श्री हरिभाऊ उपाध्याय के निजी मंत्री तथा 'राजस्थान-संघ' के सदस्य श्री मृधीन्द्र बी० ए० की अनवरत सहायता न मिलती तो हमें इस पुस्तक में निर्देशिका लगाने का विचार ही छोड़ देना पड़ता। अतः उन दोनों मित्रों का और 'राजस्थान संघ' का हम हृदय से आभार मानते हैं।

पहले खण्ड में हमने सन् १९३३ से अबतक की घटनाओं की सूची देने की बान लिखी थी, लेकिन हमें बड़ा अपराध है कि हम उसका प्रबन्ध अन्त समय तक नहीं कर सके। एक जिम्मेदार मित्र ने इसके तैयार करने का जिम्मा अपने ऊपर लिया था, लेकिन वह भी अपने और कामों में इतने लगे रहे कि इस ओर ध्यान न दे सके। और समय पर सूची बनाकर नहीं दे सके। अतः इसके लिए हम पाठकों से क्षमा चाहते हैं। इसका दूसरा संस्करण हुआ तो उसमें हम अवश्य जोड़ देंगे।

यद्यपि इस पुस्तक की छपाई में प्रेस की ओर से काफ़ी देरी हुई है और पाठकों के मामले इसके देर में आने में, एक बड़े अंशतक, प्रेस जिम्मेदार है, लेकिन फिर भी हिन्दुस्तान टाइम्स प्रेस और उसके कर्मचारी धन्यवाद के पात्र हैं। इसको इतनी सुन्दरता में छापने में उन्होंने मिहनत तो की ही है।

मंत्री

सस्ता साहित्य मण्डल

१७३. मुद्रा की गड़बड़ी	११३१	१८८. महामन्दी और संसारव्यापी	
१७४. दाँव और घात	११८०	संकट	१२३५
१७५. मुसोलिनी और इटली का		१८५. संकट के कारण	१२४५
फ़ैसिज्म	११५२	१८६. नेतृत्व के लिए अमेरिका	
१७६. लोकसत्ता और निरंकुश		और इंग्लैण्ड का झगड़ा	१२५४
शासन	११६२	१८७. डॉलर, पाउण्ड और रुपया	१२६५
१७७. चीन की क्रान्ति और प्रति-		१८८. पूँजीवादी दुनिया की मिल-	
क्रान्ति	११७१	कर प्रयत्न करने की	
१७८. जापान सारी दुनिया को		असमर्थता	१२७६
अँगूठा दिखाता है	११८१	१८९. स्पेन में क्रान्ति	१२८५
१७९. समाजवादी सोवियट प्रजा-		१९०. जर्मनी में नाज़ियों की जीत	१२९०
तंत्र संघ	११९१	१९१. निःशस्त्रीकरण	१३०८
१८०. 'पायाटिलेटका' अथवा रूस		१९२. राष्ट्रपति रुजवेल्ट का रक्षा	
की पंचवर्षीय योजना	१२००	का प्रयत्न	१३११
१८१. सोवियट संघ की कठिना-		१९३. पार्लमेण्टों की असफलता	१३१८
इयाँ, असफलतायें और		१९४. दुनिया पर एक आखिरी	
सफलतायें	१२०९	नज़र	१३२५
१८२. विज्ञान की प्रगति	१२२०	१९५. युद्ध की छाया	१३३२
१८३. विज्ञान का सदुपयोग और		१९६. आगिरी खत	१३४३
दुरुपयोग	१२२८		

परिशिष्ट

विश्व-इतिहास का तिथिक्रम

निर्देशिका

विश्व-इतिहास की भूलक

[दूसरा खण्ड]

समाजवाद का आगमन

१३ फरवरी, १९३३

मैं तुम्हें लोकसत्ता की प्रगति के बारे में लिख चुका हूँ; मगर, याद रखना, इस प्रगति के लिए खूब लड़ना पड़ा था। किसी प्रचलित व्यवस्था में जिन लोगों का स्वार्थ होता है, वे तब्दीली नहीं चाहते और कोई तब्दीली होती है तो उसे सारा जोर लगाकर रोकने की कोशिश करते हैं। फिर भी ऐसी तब्दीलियों के बिना कोई मुधार या तरक्की नहीं हो सकती। किसी भी संस्था या शासन-प्रणाली को उससे अच्छी के लिए जगह खाली करनी पड़ती है। जो लोग यह तरक्की चाहते हैं, उन्हें पुरानी संस्था या पुराने रिवाज पर हमला करना ही पड़ता है। इस तरह उन्हें सदा मौजूदा हालत की मुखालफत करनी और जो लोग उस हालत से फायदा उठाते हैं उनके साथ जद्दोजहद करना लाजिमी होजाता है। पश्चिमी योरोप में शासकवर्ग ने हर तरह की तरक्की की क्रदम-क्रदम पर मुखालफत की। इंग्लैण्ड में उन्होंने तब हथियार डाले जब देख लिया कि ऐसा न करने से हिंसात्मक क्रांति होने की सम्भावना है। जसा मैं पहले बता चुका हूँ, उनके लिए आगे बढ़ने का दूसरा कारण नये व्यवसायी लोगों का यह खयाल था कि थोड़ी-सी लोकसत्ता तिजारत के लिए फायदेमन्द है।

मगर मैं तुम्हें फिर याद दिलाता हूँ कि उन्नीसवीं सदी के पहले आधे हिस्से में ये लोकसत्तात्मक विचार पढ़े-लिखे लोगों तक ही महदूद थे। मामूली आदमियों पर उद्योगवाद की तरक्की का ज़वरदस्त असर हुआ था और वे ज़मीन छोड़-छोड़कर कारखानों में जाने लगे थे। कारखानों के मजदूरों का वर्ग बढ़ रहा था। आम तौर पर कोयले की खानों के पासवाले शहरों में वे भड़े और गन्दे मकानों में भेड़-बकरियों की तरह भरे रहते थे। इन मजदूरों के खयालात जल्दी-जल्दी बदल रहे थे और उनके अन्दर एक नई मनोवृत्ति का विकास हो रहा था। जो किसान और कारीगर भूख के मारे कारखानों में आ-आकर भरती हुए थे उनसे ये मजदूर बिल्कुल जुदा थे। जैसे इन कारखानों के खोलने में इंग्लैण्ड सबसे आगे बढ़ा हुआ था, वैसे ही कारखानों के मजदूरों का वर्ग भी पहलेपहल इंग्लैण्ड में पैदा हुआ और बढ़ा। कारखानों के भीतर की हालत खौफनाक थी और मजदूरों के घर या क्षोपड़े और भी बुरी हालत में थे। उन्हें तकलीफ भी बहुत थी। छोटे-छोटे बच्चों और औरतों को इतनी देर तक काम करना पड़ता था कि आज उस बात पर यकीन नहीं होता।

फिर भी इन कारखानों और घरों की हालत कानून के जरिये सुधारने के लिए जितनी कोशिशें की गईं, मालिकों ने डटकर उनकी मुल्लाफकत की। उनका कहना था कि यह सम्पत्ति के अधिकारों में शर्मनाक दस्तन्दाजी है। खानगी मकानों को जबरदस्ती साफ़ करवाने का उन्होंने इसी बिना पर विरोध किया। बहुत-कुछ इसी तरह की मनोवृत्ति आज हिन्दुस्तान में भी न सिर्फ़ कारखानेदारों और जमींदारों में बल्कि सामाजिक और धार्मिक कट्टरों में भी पाई जाती है। ये पिछले भले आदमी सुधार में बाधा डालने को सदा मजहब और रिवाज की आड़ लेते हैं।

गरीब अंग्रेज मजदूर धीरे-धीरे भूख और ज्यादा काम के बोझ से मरे जा रहे थे। नेपोलियन की लड़ाइयों से देश थक गया था और आर्थिक मन्दी फैल गई थी। इससे ज्यादा तकलीफ़ मजदूरों को हो गई। (१९१४-१८ के महायुद्ध की विरासत की शकल में आज कुछ इसी तरह की हालत सारी दुनिया की हो रही है।) स्वभावतः मजदूर अपनी हिफ़ाजत करने और अच्छी हालत के लिए लड़ने को संघ बनाना चाहते थे। पुराने ज़माने में कारीगरों और दस्तकारों की पंचायतें होती थीं, मगर वे इन संघों से बिल्कुल जुदा ढंग की थीं। फिर भी उन पंचायतों की याद से कारखानों के मजदूरों को अपने संघ बनाने में प्रोत्साहन मिला होगा। मगर उन्हें ऐसा नहीं करने दिया गया। ब्रिटेन का शासक-वर्ग फ़्रांस की राज्यक्रांति से इतना डर गया कि उन्होंने 'सम्मिलन कानून' (Combination Acts) के नाम से ऐसे नियम बना दिये कि गरीब मजदूर अपने दुःख-सुख की चर्चा करने के लिए इकट्ठे भी न हो सकें। 'कानून और व्यवस्था' का सदा से यही काम रहा है—इंग्लैंड में भी था और हिन्दुस्तान में भी है—कि जिन मुट्ठीभर लोगों के हाथ में सत्ता है उनके ज़ेदिय पूरे होते रहें और उनकी जेबों पर आंच न आने पावे।

लेकिन मजदूरों की इकट्ठा होने से रोकनेवाले कानूनों से हालत नहीं सुधरी। उनसे वे और भड़क गये और निराश होगये। उन्होंने गुप्त समितियाँ बनाई, अपनी बातें गुप्त रखने की क्रसम खाई और सुनसान जगहों में आधी रात गये सभायें करने लगे। धोखा खाने या भेद खुल जाने पर षड्यंत्र के मुकदमे चलते और भयंकर सज़ायें दी जातीं। कभी-कभी वे गुस्से में आकर कलों को तोड़-फोड़ डालते, कारखानों में आग लगा देते और अपने मालिकों का खून भी कर डालते थे। अखिर १८२५ ई० में मजदूर संगठनों पर से पाबन्दियाँ कुछ-कुछ हटाली गईं और मजदूर-संघ (Trade-Unions) बनने लग गये। ये संघ अच्छी तनखाह पानेवाले होशियार मजदूरों ने बनाये। मामूली मजदूर लम्बे अर्से तक असंगठित ही रहे। इस तरह मजदूर-आंदोलन की यह सूरत होगई कि मिलकर शर्तें तय करने के तरीक़े पर मजदूरों

की हालत सुधारने के लिए मजदूर-मंघ बन गये । मजदूरों के हाथ में असली हथियार तो सिर्फ हड़ताल करने के अधिकार का था, यानी वे जिस कारखाने में या जहाँ कहीं काम करते थे वहाँ काम बन्द करके उसका चलना रुकवा सकते थे । बेशक यह बड़ा हथियार था, मगर उनके मालिकों के हाथ में इससे भी जबरदस्त हथियार यह था कि वे मजदूरों को भूखों मारकर फँसे में कर सकते थे । इस तरह मजदूरों की लड़ाई जारी रही । उन्हें कुरबानी बहुत करनी पड़ी और धीरे-धीरे फ्रायदा भी होता गया । पार्लमेण्ट पर उनका सीधा असर नहीं था, क्योंकि उन्हें मत देने का हक भी नहीं मिला था । १८३२ ई० के जिस 'सुधार क़ानून' (Reform Bill) पर इतना शोर मचा था उससे सिर्फ सम्पन्न मध्यमवर्ग के लोगों को राय देने का हक हासिल हुआ था । मजदूर ही नहीं, गरीब मध्यमवर्ग के लोग भी वोट के हक में महरूम रहे थे ।

इस बीच में मजिस्टर के कारखानेदारों में ही एक रहमदिल आदमी पैदा हुआ । उसे मजदूरों की दिल दहलाने वाली हालत देखकर दर्द हुआ । उसका नाम राबर्ट ओवेन था । उसने अपने कारखानों में बहुत-से सुधार किये और मजदूरों की हालत अच्छी की । वह अपने मालिक भाइयों में आन्दोलन मचाता रहा और दलीलों से उन्हें मजदूरों के साथ अच्छा बर्ताव करने के लिए समझाता रहा । कुछ उसके कारण और कुछ दूसरी हालतों से मजबूर होकर ब्रिटिश पार्लमेण्ट ने मजदूरों को मालिकों के लालच और खुदगर्जी से बचाने के लिए पहला क़ानून पास किया । यह १८१९ ई० का 'कारखानों का क़ानून' (Factory Act) था । इस क़ानून में एक नियम यह था कि नौ-दो वर्ष के छोटे बच्चों से बारह घण्टे से ज्यादा काम न लिया जाय ! इस धारा से भी तुम्हें कल्पना होजायगी कि मजदूरों को कैसी दर्दनाक हालत में रहना पड़ता था ।

कहते हैं कि राबर्ट ओवेन ने ही १८३० ई० के आसपास 'समाजवाद' शब्द का पहलेपहल प्रयोग किया । अलवत्ता गरीब-अमीर को एक सतह पर लाने का और सम्पत्ति के बराबर बँटवारे का विचार नया नहीं था । पहले भी बहुत लोगों ने यह खयाल जाहिर किया था । पुरानी ग्राम-पंचायतों में एक तरह का साम्यवाद था ही, क्योंकि उनमें जाति या गाँवभर का ज़मीन और दूसरी सम्पत्ति पर सम्मिलित अधिकार होता था । इसे प्रारम्भिक साम्यवाद (Primitive Communism) कहते हैं और यह हिन्दुस्तान और दूसरे कई देशों में पाया जाता था । मगर नये समाजवाद में सबको बराबर कर देने की निश्चित इच्छा के अलावा और भी बहुत कुछ था । यह अधिक निश्चित है और शुरू में इसका उद्देश्य यह था कि यह

कारखानों वाली उत्पत्ति की नई प्रणाली पर लागू होजाय। इस तरह यह औद्योगिक प्रणाली की औलाद था। ओवेन का खयाल यह था कि मजदूरों की सहयोग-समितियाँ बन जायें और मजदूरों का कारखानों में हिस्सा होजाय। उसने इंग्लैंड और अमेरिका में नमूने के कारखाने और आश्रम खोले और उन्हें कहीं कम और कहीं ज्यादा कामयाबी भी मिली। मगर वह अपने मालिक भाइयों या सरकार के खयालात नहीं बदल सका। फिर भी अपने समय में उसका असर बहुत था और उसने 'समाजवाद' का एक ही शब्द ऐसा चला दिया जिसने उसी समय से करोड़ों के दिलों पर कब्जा कर लिया।

इस बीच में पूंजीवादी उद्योग-धन्धे बराबर बढ़ते गये, और जैसे-जैसे इसे कामयाबी-पर-कामयाबी मिलती गई वैसे-वैसे मजदूरों का सवाल भी जोर पकड़ता गया। पूंजीवाद का नतीजा यह हुआ कि उत्पत्ति बहुत बढ़ गई और उसकी वजह से आवादी भी बहुत तेजी से बढ़ी, क्योंकि अब पहले से ज्यादा आदमियों की परवरिश हो सकती थी। एक तरफ़ बड़े-बड़े व्यवसाय खड़े होगये और उनके अलग-अलग विभागों में पेचीदा ढंग का सहयोग स्थापित होगया। दूसरी तरफ़ छोटे-छोटे धन्धों की मुक्ताविला करने की ताकत कुचलकर बरबाद करदी गई। इंग्लैंड में दौलत का दरिया उलट पड़ा, और उसे ज्यादातर नये कारखाने और रेलें बनाने या ऐसे ही दूसरे व्यवसाय खड़े करने में लगाया गया। मजदूरों ने भी हड़तालें कर-करके अपनी हालत सुधारने की कोशिश की, मगर ये हड़तालें आम तौर पर बुरी तरह नाकामयाब होती थीं। बाद में मजदूर १८४० ई० के चार्टिस्ट आन्दोलन में शामिल होगये। मैं तुम्हें किसी पिछले खत में बता चुका हूँ कि यह आन्दोलन १८४८ ई० की क्रान्ति के वर्ष में बैठ गया था।

पूंजीवाद की कामयाबी से लोगों की आँखों में चकाचौंध होगई, मगर फिर भी कुछ उग्र सुधारक, ऊँचे खयालात के या दूसरों की भलाई की इवाहिश रखनेवाले ऐसे लोग रह गये थे, जिन्हें इस हत्यारी स्पर्धा यानी एक-दूसरे का गला काटनेवाली लाग-डाँट से खुशी नहीं होती थी। वे देश की दौलत बढ़ती रहने पर भी इससे होने-वाले मजदूरों के दुखों से दुखी थे। इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी में इन लोगों ने जुदा-जुदा उपाय भी सोचे और अलग-अलग हल सुझाये। इन्हीं सबका इकट्ठा नाम समाजवाद, समष्टिवाद या सामाजिक लोकसत्ता है। थोड़े-बहुत फ़र्क के साथ इन सब शब्दों का एक ही अर्थ है। ये सब सुधारक आमतौर पर इस बात पर सहमत थे कि झगड़े की जड़ उद्योगों पर व्यक्तिगत स्वामित्व और नियंत्रण यानी कुछ थोड़े-से लोगों की मालिकी और कब्जे का होना है। व्यक्तियों के बजाय राष्ट्र या राज्य

उद्योगों का या कम-से-कम जमीन और बड़े-बड़े उद्योगों का, यानि उत्पत्ति के खास-खास जरियों का, मालिक बन जाय और वही उन्हें चलावे तो मजदूरों के यों चूसे जाने का खतरा न रहे। इस तरह, एक धुंधली शकल में ही सही, लोग पूंजीवादी व्यवस्था के मुक्ताविले का दूसरा कोई उपाय ढूँढने लगे। मगर पूंजीवादी व्यवस्था घर बैठना नहीं चाहती थी। उसका जोर तो बढ़ता चला जा रहा था।

इन समाजवादी विचारों के चलानेवाले शिक्षित और दिमागी लोग ये और कारखानेदारों में मे राँवट ओवेन था। मजदूर-मंघों का आन्दोलन कुछ समय के लिए दूसरी दिशा में चला गया और सिर्फ़ ज्यादा मजदूरी और पहले से अच्छी हालत के लिए कोशिश करने लगा। मगर उसपर इन विचारों का आम तौर पर असर पड़ा और उसका ख़ुद का असर समाजवाद के विकास पर भी ख़ूब हुआ। योरोप के बड़े-बड़े उद्योगवादी देश इंग्लैंड, फ़्रांस और जर्मनी थे। इन तीनों में अपने-अपने यहाँ के मजदूरवर्ग के बल और स्वभाव के मुताबिक़ समाजवाद का विकास ज़रा अलग-अलग तरह से हुआ। सारी बातों को देखते हुए अंग्रेज़ों का समाजवाद अनुदार था। उसका विश्वास धीरे-धीरे उन्नति के तरीक़ों पर था और दूसरे यूरोपियन देशों का समाजवाद उग्र और क्रान्तिकारी था। अमेरिका की हालत बिल्कुल जुदा थी, क्योंकि वह बड़ा लम्बा-चौड़ा देश ठहरा और वहाँ मजदूरों की माँग भी बहुत थी। इसीलिए बहुत असें तक वहाँ कोई जोरदार मजदूर-आन्दोलन नहीं पनप सका।

उन्नीसवीं सदी के बीच से लगाकर आगे एक पीढ़ी तक ब्रिटिश उद्योग संसार पर हावी रहा और दौलत की नदी उसीकी तरफ़ बहती रही। कारख़ानों का मुनाफ़ा और हिन्दुस्तान और दूसरे गुलाम मुल्कों से चूसा हुआ रुपया बराबर उसकी जेब में आता रहा। इस धन का एक हिस्सा मजदूरों के पास भी पहुँच गया और उनके रहन-सहन का दर्जा इतना ऊँचा हो गया जितना पहले कभी नहीं हुआ था। खुश-हाली और क्रान्ति का क्या साथ? ब्रिटिश मजदूरों की पुरानी क्रान्ति की भावना काफ़ूर होगई। ब्रिटिश छाप का समाजवाद सबसे नरम होगया। इसका नाम फैबियनवाद पड़ गया। इस नाम का एक रोमन सेनापति था। वह दुश्मन से सीधी लड़ाई न लड़कर उसे धीरे-धीरे थका मारता था। १८६७ ई० में इंग्लैंड में राय देने का हक्क और भी बढ़ा दिया गया और थोड़े-से शहरी मजदूरों को भी राय देने का हक्क मिल गया। मजदूर-संघ इतने सयाने और खुशहाल होगये थे कि मजदूरदल का मत ब्रिटिश उदारदल को मिलने लगा था। इस समय के बारे में लिखते हुए कार्ल मार्क्स कहता है:—“अंग्रेज़ी मजदूर का नेता होना इज्जत की बात नहीं है, उसका नेता न होना

इज्जत की बात है; क्योंकि इन नेताओं में से ज्यादातर ने अपनेआपको उदारदल के हाथों बेच दिया है।" यह बात पचास वर्ष से ज्यादा होगया तब लिखी गई थी, मगर आज भी अंग्रेजी मजदूर नेता इस बात के लिए बदनाम हैं कि जिन लोगों के कारण वे बड़े आदमी बनते हैं उन्हींको भूल जाते हैं और अपने पुराने दल और काम के प्रति बेवफा साबित होते हैं। आज तो उन्होंने इतनी तरक्की और करली है कि उदारदल के बजाय अब उनकी राय अनुदार दल के साथ रहती है।

इधर इंग्लैण्ड वैभव के मारे फूला न समा रहा था और उधर योरोप के दूसरे मुल्कों में एक नया मत जोर पकड़ता जाता था। यह मत अराजकतावाद (Anarchism) कहलाता था। जो लोग इसके बारे में कुछ नहीं जानते वे इस शब्द से ही डर जाते हैं। अराजकतावाद का अर्थ यह है कि जहाँतक होसके समाज में हुकूमत करने-वाली कोई केन्द्रीय सरकार न रहे और व्यक्तियों को खूब आजादी मिले। अराजकता के आदर्श में अलौकिक ऊँचाई थी। उसके अनुसार एक "ऐसे आदर्श राष्ट्र में विश्वास होना चाहिए, जिसका आधार परोपकार-बुद्धि, ऐक्य-भाव और दूसरे के अधिकारों का स्वेच्छापूर्वक लिहाज हो।" राज्य की तरफ से कोई बल-प्रयोग या जबरदस्ती न हो। थोरो नाम के अमेरिकन ने कहा है:—"सरकार सबसे अच्छी वह है जो बिल्कुल शासन न करे और जब मनुष्य ऐसी सरकार के लिए तैयार होजायेंगे तब उन्हें वसी ही सरकार मिल जायगी।"

यह आदर्श बड़ा बढ़िया मालूम होता है। हरेक को पूरी आजादी हो, हरेक आदमी दूसरे का लिहाज रखे, सब तरफ निःस्वार्थता का बोलवाला हो और लोग खुशी-खुशी आपस में सहयोग करें—इससे ज्यादा और क्या चाहिए? मगर आज की खुदगर्ज और हिंसा से भरी दुनिया के लिए यह दिल्ली अभी बहुत दूर है। अराजकतावादियों की यह इच्छा कि केन्द्रीय सरकार क़तई न हो या वह नाम-मात्र को शासन करे, शायद इस कारण पैदा हुई होगी कि स्वेच्छाचारी एकतंत्री शासन ने लोगों को बहुत दिनों तक दुःख दिये थे। चूँकि सरकारों ने रियाया को कुचला और सताया था, इसलिए सरकार रहने ही न दी जाय। अराजकतावादियों को ऐसा भी लगा कि कुछ तरह के समाजवाद में राष्ट्र उत्पत्ति के सारे साधनों का मालिक होता है और इसलिए मुमकिन है वह खुद निरंकुश बन जाय। इस तरह अराजकतावादी लोग ऐसे समाजवादी थे जिनका स्थानीय और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पर बहुत जोर था। समाजवादियों में से भी बहुत लोग अराजकतावादियों के मत को एक आगे या बहुत दूर के आदर्श के रूप में मानने को तैयार थे, मगर उनकी राय में कुछ समय तक समाजवाद में भी एक केन्द्रीय और मजबूत सरकार का होना जरूरी था। इस तरह,

हालाँकि समाजवाद और अराजकतावाद में काफी अन्तर था, फिर भी दोनों के बहुत-से विचारों की छाया एक-दूसरे पर पड़ती और मिलती थी।

आधुनिक उद्योग-धंधों के कारण एक संगठित मजदूरवर्ग पैदा हुआ। अराजकतावाद का स्वभाव ही ऐसा था कि वह कोई सुसंगठित आन्दोलन नहीं बन सकता था। इसलिए उद्योगवादी देशों में जहाँ मजदूर-संघ और ऐसी ही संस्थाएँ बढ़ रही थीं, वहाँ अराजकतावादी विचारों के फैलने की बहुत कम संभावना थी। इस तरह न इंग्लैण्ड में और न जर्मनी में ही अराजकतावादियों की कोई बड़ी संख्या हुई। लेकिन दक्षिणी और पूर्वी योरोप उद्योग-धंधों में पिछड़ा हुआ था, इसलिए वहाँ इन विचारों के लिए ज्यादा उपजाऊ जमीन थी। जैसे-जैसे वर्तमान उद्योगवाद का दक्षिण और पूर्व में प्रचार हुआ, वैसे-वैसे अराजकतावाद कमजोर पड़ता गया। आज यह करीब-करीब एक मुर्दा उन्तूल हो गया है, मगर स्पेन जैसे पिछड़े हुए बड़े-बड़े कल-कारखानों से सूनने देश में फिर भी कहीं-कहीं इसके निशान मिलते हैं।

अराजकतावाद का आदर्श भले ही बहुत सुन्दर हो, मगर इससे न केवल जल्दी भड़कनेवाले और असन्तुष्ट लोगों को ही बल्कि ऐसे स्वाधियों को भी आश्रय मिला जो आदर्श की आड़ में अपना फ़ायदा करना चाहते थे। और इसके कारण एक खास तरह की हिंसा का जन्म हो गया जो अराजकता का नाम लेते ही तुरन्त हर किसीकी समझ में आजाती है और जो इतनी बदनाम भी हो चुकी है। अराजकतावादी चाहते तो यह थे कि समाज को बदला जाय, मगर किसी बड़े पैमाने पर यह कुछ न हो सका तो उन्होंने एक नये ढंग से प्रचार करने का इरादा किया। यह 'करके दिखाने का तरीक़ा' कहलाता था। इसके अनुसार वे मुल्क के खिलाफ़ बहादुरी के काम करके और अपने प्राणों की कुरबानी देकर साहस का नमूना पेश करते और उसका असर डालते थे। इस खयाल से अलग-अलग मुक़ामों पर बलबे हुए। जिन लोगों ने इनमें हिस्सा लिया उन्होंने तुरन्त किसी कामयाबी की उम्मीद नहीं रखी थी। अपने काम का इस नये ढंग से प्रचार करते हुए वे खुशी से अपनी जान जोखिम में डालते थे। पर ये विद्रोह दबा दिये गये और फिर अराजकतावादियों ने व्यक्तिगत आतंकवाद का आश्रय लेना शुरू कर दिया। राजाओं और बड़े हाकिमों पर बम फेंके जाने लगे और उन्हें गोली का शिकार बनाया जाने लगा। यह बेवकूफी से भरी हिंसा बढ़ती हुई कमजोरी और निराशा की खुली निशानी थी। धीरे-धीरे उन्नीसवीं सदी के ख़तम होते-होते अराजकतावाद आन्दोलन की हैसियत से एकदम ख़तम हो गया। बहुत-से अराजकतावादी नेताओं ने बम फेंकने और 'कुछ काम कर दिखाने' के प्रचार के इस तरीक़े को नापसन्द किया और उसकी निन्दा भी की।

तुम्हें कुछ मशहूर अराजकतावादियों के नाम बताऊंगा। मजे की बात यह है कि खानगी जीवन में अधिकांश अराजकतावादी नेता निहायत शरीफ, आदर्शवादी और पसन्द करने लायक आदमी थे। शुरू के अराजकतावादी नेताओं में पायरे प्राउ-ढन नाम का एक फ्रांसीसी था। यह १८०९ से १८६५ ई० तक ज़िन्दा रहा। उससे ज़रा उम्र में छोटा माइकेल बैकुनिन नाम का रूसी रईस था। यह योरोप का, और खास तौर पर दक्षिण में, एक बड़ा लोकप्रिय मजदूर नेता था। इसने एक अन्तर्राष्ट्रीय संघ बनाया था, मगर मायर्स के साथ भिड़न्त हो जाने के कारण उसने इसे संघ से निकलवा दिया। तीसरा नाम रूसी राजकुमार पीटर क्रोपाटकिन का है। यह तो हमारे अपने समय की बात है। उसने अराजकतावाद और दूसरे विषयों पर कुछ बहुत ही रोचक पुस्तकें लिखी हैं। चौथा और आखिरी नाम जो मैं तुम्हें बताऊंगा वह है इटली-निवासी एनरिको मालाटेस्टा का। यह अभी ज़िन्दा है और ८० वर्ष से ज्यादा उम्र का है। यह उन्नीसवीं सदी के महान् अराजकतावादियों का बचा हुआ निशान है।

मालाटेस्टा के बारे में एक सुन्दर कहानी कहे बिना मैं नहीं रह सकता। इटली की एक अदालत में उसपर मुकदमा चल रहा था। सरकारी वकील ने बहस में कहा कि उस इलाक़े के मजदूरों में मालाटेस्टा का बहुत ज्यादा असर है और उसने उनका स्वभाव ही घिलफुल बदल दिया है। वह तो अपराधवृत्ति का ही ख़ात्मा कर रहा है और जुर्मों की तादाद बहुत घटती जा रही है। अगर अपराध बन्द हो गये तो फिर अदालतें क्या करेंगी? इसलिए मालाटेस्टा को जेल भेजा जाय! मालाटेस्टा को सचमुच छः महीने क़ैद की सज़ा हुई!

बदकिस्मती से अराजकतवाद के साथ हिंसा का दूध-पानी का-सा सम्बन्ध हो-गया और लोग यह भूल गये कि यह भी एक तत्त्वज्ञान और एक आदर्श है जिसने बहुत-से अच्छे-अच्छे आदमियों पर असर डाला है। आदर्श के रूप में हमारी आज-कल की अधूरी दुनिया से यह अब भी बहुत दूर है और इसने जो सरल उपाय बताये हैं वे हमारी आधुनिक पेचीदा सभ्यता के अनुकूल नहीं हैं।

कार्ल मार्क्स और मजदूर-संगठनों की वृद्धि

१४ फरवरी, १९३३

उन्नीसवीं सदी के बीच के आसपास योरोप के मजदूर और समाजवादी संसार में एक नये और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला आदमी हुआ। यह आदमी कार्ल मार्क्स था, जिसका नाम इन खतों में पहले ही आ चुका है। वह एक जर्मन यहूदी था। उसका जन्म १८१८ ई० में हुआ था। उसने कानून, इतिहास और तत्त्वज्ञान का अध्ययन किया और एक अखबार निकाला, जिसके कारण उसका जर्मनी के अधिकारियों से झगड़ा हो गया और वह पेरिस चला गया। पेरिस में वह नये-नये लोगों के सम्पर्क में आया, उसने समाजवाद और अराजकतावाद पर नई-नई किताबें पढ़ीं और समाजवादी बन गया। वहीं पेरिस में फ्रेडरिक एञ्जेल्स नामक दूसरे जर्मन से उसकी मुलाकात हुई। यह इंग्लैण्ड आकर बस गया था और वहाँ रुई के बढ़ते हुए उद्योग में एक कारखाने का मालिक बन गया था। एञ्जेल्स भी वर्तमान सामाजिक स्थिति से दुखी और असन्तुष्ट था और अपने चारों तरफ़ दीखनेवाली गरीबी और शोषण को रोकने के उपायों की तलाश कर रहा था। सुधार-सम्बन्धी रॉबर्ट ओवेन के खयालात और कोशिशों उसे अच्छी लगीं और वह ओवेन का अनुयायी बन गया। पेरिस जाने पर उसकी कार्ल मार्क्स से पहलेपहल मुलाकात हुई। इससे भी उसके खयालात बदले। आगे से मार्क्स और एञ्जेल्स गहरे दोस्त और साथी हो-गय। दोनों के एक-से खयाल थे और दोनों एक ही उद्देश्य के लिए दिलोजान से मिलकर काम करने लगे। उम्र में भी दोनों करीब-करीब बराबर के थे। उनका सहयोग इतना गहरा था कि जो किताबें उन्होंने छपाई उनमें से ज्यादातर दोनों की लिखी हुई थीं।

उस वक्त की फ्रांस की सरकार ने मार्क्स को पेरिस से निकाल दिया। यह लुई फ़िलिप का ज़माना था। मार्क्स लन्दन चला गया और वहाँ बहुत वर्ष तक रहा। वहाँ वह ब्रिटिश म्यूज़ियम की किताबें पढ़ने में लगा रहता। उसने खूब मेहनत करके अपने उसूल पक्के कर लिये और फिर उनपर लिखने लगा। मगर वह कोरा अध्यापक या तत्त्वज्ञानी नहीं था, जो उसूल गढ़ा करता हो और मामूली बातों से सरोकार न रखता हो। जहाँ उसने समाजवादी आन्दोलन की धुंधली विचार-रेखा का विकास किया और उसे स्पष्ट किया और उसके सामने निश्चित और साफ़-साफ़ विचार और ध्येय उपस्थित किये, वहाँ वह मजदूरों और उनके आन्दोलन को

संगठित करने का काम भी असली तौर पर, जोरों के साथ, करता रहा। सन् १८४८ में, जो योरप में क्रान्तियों का वर्ष कहलाता है, जो घटनाएँ हुई उनका मार्क्स पर स्वभावतः खूब असर हुआ। उसी साल उसने और एन्जेलस ने मिलकर एक घोषणा-पत्र या मैनीफेस्टो प्रकाशित किया, जो बहुत मशहूर हुआ। यह 'साम्यवादी घोषणापत्र' (Communist Manifesto) था, जिसमें उन्होंने उन खयालात का इजहार किया था जो फ्रांस की महान् राज्य-क्रान्ति और बाद में १८३० और १८४८ ई० की घटनाओं की जड़ में थे। उन्होंने इस घोषणापत्र में यह भी बताया कि वे खयालात असली हालात से किस तरह मेल नहीं खाते थे और उनके लिए वे कितने नाकाफी थे। उन्होंने उस वक्त की स्वतन्त्रता, समानता और भ्रातृभाव की लोकसत्तावादी आवाजों की आलोचना की और यह दिखाया कि इन आवाजों का आम लोगों के लिए तो कोई मतलब है नहीं, हाँ, मध्यम श्रेणी के अमीरों के राज्य को एक अच्छा परदा जरूर मिल गया है। उस घोषणा में उन्होंने आगे चलकर, मुद्दतसर में समाज-वाद के अपने उसूलों का प्रतिपादन किया। इसका कुछ हाल मैं तुम्हें आगे कहूँगा। घोषणापत्र के अखीर में उन्होंने सारे मजदूरों से इन शब्दों में अपील की :—“संसार के मजदूरों, एक हो जाओ। तुम्हें खोना कुछ नहीं है सिवाय अपनी गुलामी की जंजीरों के और पाने को संसार पड़ा है !”

यह अपील काम करने की पुकार थी। इसके बाद मार्क्स ने अखबारों और पत्रों के जरिये जोरदार प्रचार शुरू कर दिया और मजदूर संगठनों को नज़दीक लाने की दिन-रात कोशिश करने लगा। ऐसा जान पड़ता है कि उसे योरप में कोई बड़ा संकट-काल आता दिखाई दे रहा था और वह चाहता था कि मजदूर उसके लिए तैयार रहें, ताकि वे उससे पूरा फ़ायदा उठा सकें। उसके समाजवादी उसूलों के मुताबिक पूँजीवादी प्रणाली में सचमुच ऐसा संकट-काल आये बिना नहीं रह सकता था। १८५४ ई० में न्यूयार्क के एक अखबार में लिखते हुए मार्क्स ने कहा था—“फिर भी हमें यह न भूलना चाहिए कि योरप में छठी सत्ता भी है जो खास-खास मौकों पर पाँचों बड़ी कहलाने वाली सत्ताओं पर अपनी प्रभुता रखती है और उन सबको थरथरा देती है। यह सत्ता क्रान्ति की सत्ता है। इसे चुपचाप एकान्तवास करते हुए बहुत दिन होंगये। अब मुसीबतें और भूख इसे फिर लड़ाई के मैदान में बुला रही हैं। सिर्फ़ एक इशारे की जरूरत है। फिर तो योरप की छठी और सबसे बड़ी ताकत चमकता हुआ कवच पहने और हाथ में तलवार लिये हुए निकल पड़ेगी। यह इशारा आनेवाले योरप के युद्ध से मिल जायगा।”

योरप के अगले युद्ध के बारे में मार्क्स की भविष्यवाणी ठीक नहीं निकली।

उसके लिखने के साठ साल बाद समाजवादी युद्ध हुआ और उससे योरप के एक हिस्से में ही क्रान्ति हुई। यह तो हम देख ही चुके हैं कि पेरिस के पंचायती राज्य के रूप में १८७१ ई० में क्रान्ति की जो कोशिश हुई वह स्वेदर्न के साथ कुचल दी गई थी।

१८६४ ई० में मार्क्स लन्दन में एक पंचमेल सभा करने में कामयाब हुआ। उसमें अनेक दलों के लोग, जो अपनेको समाजवादी कहते थे, इकट्ठे हुए। उनके विचार सुलझे हुए नहीं थे। एक तरफ तो योरप के कई गुलाम देशों के लोकसत्तावादी और देशभक्त आये थे। समाजवाद में उनका विश्वास बहुत दूर की चीज था और उनकी ज्यादा दिलचस्पी क्रांती आजादी हासिल करने में थी। दूसरी तरफ अराजकतावादी लोग थे, जो तुरन्त लड़ाई मोल लेना चाहते थे। सभा में मार्क्स के सिवा दूसरा प्रभावशाली आदमी अराजकतावादी नेता बैकुनिन था। वह कई वर्ष साइबेरिया में क़द रहकर तीन साल पहले भागकर निकल आया था। बैकुनिन के अनुयायी खास तौर पर दक्षिण योरप के इटली और स्पेन वगैरह लैटिन मुल्कों से आये थे। इन देशों में बड़े उद्योग-धंधों का विकास नहीं हुआ था और वे इसमें पिछड़े हुए थे। वे पढ़े-लिखे बेरोजगार और तरह-तरह के क्रान्तिकारी लोग थे जिनको मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में कोई जगह नहीं मिलती थी। मार्क्स के अनुयायी उद्योगवादी देशों से, खासकर जर्मनी से, आये थे, जहाँ मजदूरों की हालत अच्छी थी। इस तरह मार्क्स तो बढ़ते हुए, संगठित और खुशहाल मजदूरों का प्रतिनिधि था और बैकुनिन गरीब और असंगठित मजदूरों, शिक्षितों और असंतुष्ट लोगों का। मार्क्स का यह कहना था कि जबतक कुछ कर गुजरने का वक़्त आवे, उस वक़्त तक धीरज के साथ मजदूरों को समाजवादी उसूलों की तालीम दी जाय और उसी ढंग पर उनका संगठन किया जाय। बैकुनिन और उसके चेले तुरन्त कुछ करने के पक्ष में थे। सब बातों को देखते हुए जीत मार्क्स की हुई। 'अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ' (International Workingmen's Association) कायम हुआ। यह मजदूरों का पहला अन्तर्राष्ट्रीय संगठन (Worker's International) था।

तीन साल बाद यानी १८६७ में मार्क्स का महान ग्रंथ कैपिटल (Capital) अर्थात् 'पूँजी' जर्मन भाषा में प्रकाशित हुआ। लंदन में उसने कई वर्ष तक जो मेहनत की थी, यह उसीका परिणाम था। इसमें उसने प्रचलित आर्थिक सिद्धान्तों की छानबीन करके उनकी बुराई-भलाई दिखाई और अपने समाजवादी उसूल विस्तार के साथ समझाये। यह शुद्ध वैज्ञानिक ग्रंथ था। उसने सारी अनिश्चित और आदर्शवाद की बातें छोड़कर व्यावहारिक ढंग से, निष्पक्ष और वैज्ञानिक तरीक़े पर, इतिहास और अर्थशास्त्र के विकास का निरूपण किया। उसने खास तौर पर

बड़ी-बड़ी मशीनों की औद्योगिक सभ्यता के विकास की चर्चा की और विकास, इतिहास और मानवसमाज के वर्गयुद्ध के बारे में कुछ दूर तक असर करनेवाले नतीजे निकाले । मार्क्स का यह नया गढ़ा-गढ़ाया और जोरदार दलीलों वाला समाजवाद इसीलिए 'वैज्ञानिक समाजवाद' (Scientific Socialism) कहलाया । यह उस अस्पष्ट, हवाई या आदर्शवादी समाजवाद से जुदा था जो अवतक प्रचलित था । मार्क्स की किताब 'पूँजी' (Das Capital) पढ़ने में सहूल किताब नहीं है । असल में इससे ज्यादा मुश्किल किताब की कल्पना नहीं की जा सकती । फिर भी यह उन थोड़ी-सी किताबों में से एक है जिनसे बहुत लोगों के विचार करने के तरीके पर असर हुआ है; उनके खयालात बदल गये हैं और मानव विकास पर प्रभाव पड़ता है ।

१८७१ ई० में पेरिस की पंचायत (Commune) की घटना हुई । शायद यह जान-बूझकर की गई पहली ही समाजवादी चगावत थी । इससे योरप की सरकारें डर गईं और मजदूर-आन्दोलन की तरफ से उनका रुख और भी कड़ा होगया । दूसरे वर्ष मार्क्स के क्रायम किये हुए अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ की बैठक हुई और मार्क्स ने उसका प्रधान कार्यालय सात समन्दर पार अमेरिका के न्यूयार्क शहर में भिजवा दिया । इसमें मार्क्स का साफ़ मतलब यही होगा कि वैकुनिन के अराजकतावादी अनुयायियों से पीछा छूटे; और शायद यह भी कि चूँकि उसके खयाल से पेरिस की पंचायत के बाद योरप की सरकारों की आँखें लाल हो गई थीं इसलिए उनकी हुंक्मत्त में संघ इतना महफूज नहीं रह सकेगा जितना अमेरिका में । मगर सदा के लिए अपने सारे मुख्य केन्द्रों से इतनी दूर रह सकना मुमकिन नहीं था । उसकी ताकत योरप में थी और योरप में भी मजदूर-आन्दोलन के बुरे दिन थे । इसलिए पहला अन्तर्राष्ट्रीय संघ धीरे-धीरे बेजान होकर मर गया ।

मार्क्सवाद या मार्क्स का समाजवाद योरप के और खास तौर पर जर्मनी और आस्ट्रिया के समाजवादियों में फैला । वहाँ यह आम तौर पर 'समाजवादी लोकसत्ता' (Social Democracy) के नाम से मशहूर हुआ । लेकिन इंग्लैण्ड ने इसकी अन्धी नक़ल नहीं की । उस वक़्त वह इतना खुशहाल था कि वहाँ किसी आगे बढ़े हुए सामाजिक मत के प्रचार की गुञ्जाइश नहीं थी । अंग्रेज़ों के समाजवाद का नमूना फ़ैबियन सोसायटी थी और उसका बहुत दूर की और हल्की तब्दीली का कार्यक्रम था । फ़ैबियन लोगों का मजदूरों से कोई वास्ता नहीं था । ये आगे बढ़े हुए उदार विचारों के तालीमयापता लोग थे । शुरू के फ़ैबियन लोगों की नीति का पता दूसरे मशहूर फ़ैबियन सिडनी वेब के इस मशहूर जुमले से लग सकता है कि 'परिवर्तन धीरे-धीरे होना अनिवार्य है ।' यह महाशय अब लार्ड बन गये हैं ।

फ्रांस में पंचायत के बाद समाजवाद को फिर से जोर पकड़ने में धीरे-धीरे करके बारह वर्ष लग गये; मगर इस बार इसका स्वरूप नया हो गया। वह अराजकतावाद और समाजवाद के मेल से बना। इसे सिंडिकेट 'Syndicalism' या संघवाद कहते हैं। फ्रेंच भाषा के सिंडिकेट (Syndicat) शब्द से निकला है, जिसका मतलब मजदूरों का संगठन या मजदूर संघ है। समाजवाद का उसूल यह था कि राज्य सारे समाज का प्रतिनिधि है, इसलिए उसीका उत्पत्ति के साधनों यानी जमीन और कारखानों पर स्वामित्व और कब्जा होना चाहिए। थोड़ा-सा मतभेद था तो यह कि समाज का स्वामित्व और कब्जा कहाँ तक हो? यह जाहिर है कि औजारों और घरेलू यंत्रों जैसी बहुत-सी खानगी चीजों पर समाज का कब्जा करना बेहूदा-सी बात होगी। मगर इस बात पर समाजवादियों का एक मत था कि जिस किसी चीज का इस्तेमाल दूसरों के कामों से खुद फायदा उठाने में किया जा सकता हो वह राष्ट्र की सम्पत्ति बना दी जानी चाहिए। अराजकतावादियों की तरह संघवादी राज्य-संस्था को बहुत पसन्द नहीं करते थे और वे उसकी ताकत को महद्द कर देने की कोशिश करते थे। वे चाहते थे कि हरेक उद्योग पर उस उद्योग के मजदूरों का अपने संघ के जरिये कब्जा रहे। (तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि मजदूर से मतलब सिर्फ हाथ से काम करनेवालों का ही नहीं है, बल्कि हाथ और दिमाग दोनों से काम करनेवाले सब तरह के मजदूरों से है)। कल्पना यह थी कि अलग-अलग संघ अपने-अपने प्रतिनिधि चुनकर बड़ी परिषद में भेजेंगे और परिषद सारे देश के मामलों को सम्हालेगी। यह परिषद मामूली काम-काज के लिए एक तरह की पार्लमेण्ट होगी, मगर उसे किसी खास उद्योग के भीतरी इन्तजाम में दखल देने का हक न होगा। यह स्थिति पैदा करने के लिए संघवादी आम हड़ताल के पक्ष में थे, यानी वे देश के सब उद्योग-धंधों और कारखानों में एकसाथ काम बन्द करवाकर अपना उद्देश्य पूरा करना चाहते थे। मार्क्स के अनुयायी संघवाद को बिल्कुल पसन्द नहीं करते थे, मगर दिल्लगी की बात यह थी कि मार्क्स के मरने के बाद संघवादी उसे अपनेमें का ही एक आदमी मानते थे।

कार्ल मार्क्स ठीक पचास साल पहले यानी १८८३ ई० में मरा। उस वक्त तक इंग्लैण्ड, जर्मनी और दूसरे उद्योगवादी देशों में मजदूर संघों का संगठन जबरदस्त और ताकतवर हो चुका था। ब्रिटिश उद्योगों के अच्छे दिन बीत चुके थे और जर्मनी और अमेरिका की बढ़ती हुई लाग-डाँट के मुकाबिले में उनका पतन हो रहा था। यह ठीक है कि अमेरिका को कुदरत की तरफ से बड़ी सहाूलियतें थीं, जिनसे वहाँ औद्योगिक विकास तेजी से होने में मदद मिली। जर्मनी में राजनैतिक निरंकुशता और औद्योगिक प्रगति का अजीब मेल था। उस निरंकुशता में कमजोर और सत्ताहीन-सी

पार्लमेण्ट का पुट भी लगा हुआ था। विस्मार्क की मातहत में और बाद में भी जर्मन सरकार ने उद्योग-धंधों की कई तरह मदद की और मजदूरों की हालत अच्छी करनेवाले समाज-सुधार के क़ानून बनाकर मजदूरवर्ग को खुश करने की कोशिश की। इसी तरह अंग्रेजी उदारदल ने कुछ सामाजिक क़ानून पास करके काम के घंटे घटा दिये और मजदूरों की हालत कुछ सुधार दी। जबतक खुशहाली रही तबतक इस तरीक़े से काम चल गया और अंग्रेज़ मजदूर नरम और दबे हुए रहे और बफ़ा-दारी के साथ उदारदल के पक्ष में राय देते रहे। मगर १८८० के बाद दूसरे देशों की लाग-डाँट के कारण खुशहाली का लम्बा ज़माना ख़त्म हुआ और इंग्लैंड में व्यापार की मन्दी शुरू होगई और मजदूरों की मजदूरी घटगई। इस तरह फिर मजदूरों में जागृति हुई और वायुमण्डल में क्रान्ति की भावना फैल गई। इंग्लैंड में बहुत लोगों की नज़र मार्क्सवाद की तरफ़ जाने लगी।

१८८९ में अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ बनाने की दूसरी बार कोशिश हुई। बहुत-से मजदूरसंघों और श्रमजीवी दलों का बल और साधन अब काफ़ी बढ़ गया था और उनके बहुत-से तनख़्वाह पानेवाले कर्मचारी थे। मार्क्स और वैकुनिन के ज़माने से अब उनकी इज़्जत भी बहुत ज्यादा होगई थी। १८८९ में बना हुआ यह संघ दूसरा अन्तर्राष्ट्रीय संघ (Second International) कहलाता है। मेरे ख़याल से उस वक़्त इसका नाम 'मजदूर और समाजवादी अन्तर्राष्ट्रीय संघ' (Labour and Socialist International) रक्खा गया था। यह पच्चीस वर्ष तक रहा। फिर महा-युद्ध आगया। उसमें इसका इग़िहान होगया और यह बेकार साबित हुआ। इस संघ में बहुत लोग ऐसे भी थे जिन्होंने आगे चलकर अपने-अपने देशों में ऊँचे-ऊँचे पद ग्रहण किये। मालूम होता है, उन्होंने मजदूरों का अपने सहारे और तरक्की के लिए इस्तेमाल किया था और जब उनका काम होगया तो उन्होंने मजदूरों को क्रिस्मत के भरोसे छोड़ दिया। वे प्रधान मंत्री, अध्यक्ष और इसी तरह और कुछ बन-बनकर अपनी जिन्दगी सफल कर गये, मगर जिन लाखों आदमियों ने उन्हें आगे बढ़ाया और उनपर यक़ीन रक्खा उन्हें इन लोगों ने मँझधार में छोड़ दिया। इन नेताओं में से जो मार्क्स के नाम की क्रसमें खाते थे या बड़े जोशीले संघवादी थे, वे भी पार्लमेण्टों में घुस गये या बड़ी-बड़ी तनख़्वाहें पाने वाले मजदूरसंघों के मुखिया बन बैठे। उनके लिए अपनी आराम की जगहों को जोखिम में डालकर बिना सोचे-समझे किसी बात का बीड़ा उठा लेना दिन-दिन मुश्किल होगया। इस तरह वे ठण्डे पड़ गये और जिस वक़्त मामूली मजदूरों ने निराश होकर, क्रान्ति का बाना पहना और कुछ-न-कुछ करने की माँग की तब भी इन लोगों ने उन्हें दबाकर रखने

की ही कोशिश की। युद्ध के बाद जर्मनी के समाजवादी लोकसत्तात्मक दल के लोग प्रजातन्त्र के अध्यक्ष और प्रधान मंत्री (Chancellor) बने। फ्रांस में आम हड़ताल का पक्षपाती आग उगलने वाला संघवादी त्रियाँद ग्यारह बार प्रधान मंत्री बना और उसने अपने पुराने साथियों की हड़ताल को कुचला। इंग्लैंड में रैम्जे मैकडोनाल्ड इस समय प्रधान मंत्री हैं। यह दूसरी बात है कि नरम होते हुए भी उसके अपने मजदूर दल और ब्रिटिश मजदूर संघों ने उससे कोई वास्ता नहीं रखा है। यही हाल स्वीडन, डेनमार्क, बेलजियम और आस्ट्रिया का है। पश्चिम योरोप आज ऐसे सर्वसर्वा यानी डिक्टेटर शासकों और सत्ताधारियों से भरा पड़ा है जो अपने शुरू के जमाने में समाजवादी थे, मगर ज्यों-ज्यों उनकी उम्र ढलती गई त्यों-त्यों वे नरम पड़ते गये और कार्य का पुराना जोश भूल गये। इतना ही नहीं, कभी-कभी तो ये लोग अपने पुराने साथियों के खिलाफ भी होगये। इटली का कर्ताधर्ता मुसोलिनी पुराना समाजवादी है। पोलैंड का सर्वसर्वा पित्सूदस्की भी समाजवादी रह चुका है।

मजदूर-आन्दोलन को ही क्या, क़रीब-क़रीब आज़ादी की हर क़ौमी तहरीक को नेताओं और मुख्य कार्यकर्ताओं की ऐसी बेवफ़ाई से अक्सर नुक़सान पहुँचा है। कामयाबी न मिलने से वे थोड़े असें वाद थक जाते हैं और शहीदी का थोथा चोला उन्हें बहूद दिन तक अच्छा नहीं लगता। उनका जोश ठण्डा पड़ जाता है। कुछ लोग, जो ज्यादा महत्वाकांक्षी या बेउसूल होते हैं, दूसरे पक्ष में जा मिलते हैं और जिन लोगों से कल तक झुकाविला और लड़ाई करते थे उन्हीं से जाती समझौता कर लेते हैं। आदमी जो कुछ करने की ठान लेता है उसके अनुकूल अन्तःकरण बना लेना उसके लिए आसान है। इस बेवफ़ाई से आन्दोलन की हानि होती है और वह थोड़ा पीछे हटता है। जो लोग मजदूरों के दुश्मन होते हैं वे यह बात अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए वे तरह-तरह के लालच देकर और मीठी-मीठी बातें करके व्यक्तियों को अपनी तरफ़ मिलाने की कोशिश करते हैं। मगर व्यक्तियों पर महर-वानी कर देने या उनसे मीठी-मीठी बातें करने से मामूली मजदूरों या आज़ादी के लिए लड़नेवाले किसी दलित राष्ट्र का कण्ट दूर नहीं होता। इसलिए व्यक्तियों की बेवफ़ाई और आन्दोलन के बीच-बीच में पीछे हटने के बावजूद लड़ाई अपनी मंज़िल की तरफ़ ज़रूरी तौर पर चलती रहती है।

१८८९ ई० में बने हुए दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय संघ के सदस्यों की तादाद और संघ की इज्जत बढ़ी। थोड़े ही वर्ष बाद उन्होंने मालाटेस्टा और उसके अराजकतावादी अनुयायियों को इस बिना पर निकाल बाहर किया कि वे पार्लमेण्टों के मताधिकार

का फायदा उठाने को राजी नहीं थे। अन्तर्राष्ट्रीय संघ के समाजवादियों ने साधित कर दिया कि उन्हें आम लड़ाई में अपने पुराने साधियों का साथ देने से पालंमेण्टों में जाना ज्यादा पसन्द है। योरोप में लड़ाई छिड़ जाने पर समाजवादी क्या करें, इस बारे में उन्होंने बड़ी बड़-बड़कर बातें कीं। जहाँतक काम का ताल्लुक था, समाजवादी राष्ट्रीय सीमाओं यानी क़ीमी हद्द को नहीं मानते थे। वे मामूली मानी में राष्ट्रवादी नहीं थे। उन्होंने कहा कि लड़ाई की मुलालक़त करेंगे। मगर जब १९१४ ई० में लड़ाई छिड़ी तो दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय संघ का सारा ढाँचा तहस-नहस होगया और हर देश के समाजवादी और मजदूर दल ही नहीं, क्रोपाटकिन-जैसे अराजकतावादी भी और लोगों की तरह निरे राष्ट्रवादी और दूसरे मुल्कों से नफ़रत करनेवाले बन गये। थोड़े ही आदमियों ने लड़ाई की मुलालक़त की और इसके लिए उन्हें तरह-तरह की तकलीफ़ें और कुछ लोगों को लम्बी-लम्बी सजायें दी गईं।

लड़ाई ख़त्म होने पर लेनिन ने १९१९ ई० में मास्को में एक नया अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर-संघ खोला। यह शुद्ध साम्यवादी संगठन था और इसमें खुली घोषणा करनेवाले साम्यवादी ही शामिल हो सकते थे। यह अब भी है और तीसरे अन्तर्राष्ट्रीय संघ (Third International) के नाम से मशहूर है। पुराने दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय संघ के दबे-खुचे लोग भी लड़ाई के बाद धीरे-धीरे इकट्ठे होगये। थोड़े मास्को के संघ में मिल गये। मगर ज्यादातर को मास्को और उसके मत से सख़्त नफ़रत थी और वे उसके पास फटकने को भी तैयार नहीं थे। उन्होंने दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय संघ को फिर से चलाया। यह भी मौजूद है। इस तरह आजकल दो अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर-संघ हैं और दूसरे और तीसरे संघ के नाम से मशहूर हैं। ताज्जुब की बात यह है कि दोनों ही मार्क्स के अनुयायी होने का दावा करते हैं, मगर दोनों ही उसके विचारों का अपना-अपना अलग अर्थ करते हैं और अपने समान शत्रु-पूँजीवाद से भी कहीं अधिक घृणा आपस में रखते हैं।

इन दोनों अन्तर्राष्ट्रीय संघों में संसार के सारे मजदूर-संघ शामिल नहीं हैं। बहुत-से संगठन दोनों से ही अलग हैं। अमेरिका के मजदूर-संघ इसलिए अलग हैं कि उनमें से ज्यादातर बहुत पुराने विचार के हैं। हिन्दुस्तान के मजदूर-संघों का भी दोनों में से किसी अन्तर्राष्ट्रीय संघ से सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि वे कोई निश्चय ही नहीं कर पाते।

शायद तुम 'इण्टरनेशनल' गीत को जानती हो, जोकि दुनियाभर के मजदूरों और समाजवादियों का माना हुआ गीत है।

मार्क्सवाद

१६ फरवरी, १९३३

पिछले पत्र में मैंने तुम्हें मार्क्स के खयालात के बारे में कुछ बताने का इरादा जाहिर किया था। इन खयालात ने योरोप को साम्यवादी दुनिया में बड़ी हलचल मचा दी थी। मगर मेरा खत बहुत लम्बा हो गया था और मुझे यह विषय रोक लेना पड़ा था। मैं इस विषय का कोई खास जानकार नहीं हूँ, इसलिए इसके बारे में लिखना मेरे लिए आसान नहीं है। फिर भी विशेषज्ञों और पंडितों में भी मतभेद होता है। मैं तुम्हें मार्क्सवाद की सिर्फ मोटी-मोटी बातें बताऊँगा और इसके मुश्किल हिस्सों को छोड़ दूँगा। यह जोड़-गाँठकर बनाई हुई-सी चीज होगी, मगर मेरा काम यह भी नहीं है कि इन खतों में किसी चीज की पूरी और लम्बी-चौड़ी तसवीरें दूँ।

मैं कह चुका हूँ कि समाजवाद कई तरह का होता है। मगर उद्देश्य की इस एक बात में सब सहमत हैं कि पैदावार और उसे बाँटने के साधनों पर यानी खानों, जमीन, कारखानों, रेलवे और बंकों वगैरा संस्थाओं पर राज्य का नियंत्रण यानी कब्जा रहे। कल्पना यह है कि व्यक्तियों को अपने खानगी फ्रायदे के लिए इन साधनों या संस्थाओं से और दूसरों की मेहनत से काम न लेने दिया जाय। आज तो ये ज्यादातर अलग-अलग आदमियों के हाथ में हैं और वे ही इनसे काम लेते हैं। नतीजा यह हो रहा है कि कुछ लोग मालामाल होकर आनन्द भोगते हैं और समाज का खूब नुकसान होता है और आम जनता गरीब बनी हुई है। उत्पत्ति के इन साधनों के मालिकों और अधिकारियों की भी बहुत सारी ताकत आजकल आपस की गहरी रक्काबत या लाग-डाँट में—एक दूसरे से लड़ने में—ही खर्च हो जाती है। अगर इस खानाजंगी के बजाय समझदारी के साथ पैदावार का और खूब विचारपूर्वक बँटवारे का इंतजाम कर दिया जाय तो समाज की हालत कहीं अच्छी हो जाय और यह फ़िज़ूल की ज़वरदस्त लाग-डाँट न रहे और जुदा-जुदा वर्गों और देशों के बीच की धन-सम्बन्धी महान् असमानतायें मिट जायें। इसलिए उत्पत्ति, बँटवारा और कुछ दूसरे महत्त्व के काम ज्यादातर समाज यानी राज्य के हाथ में रहें; मतलब यह कि वे सारी जनता के कब्जे में आजायें। समाजवाद की यही मूल कल्पना है।

समाजवाद में राज्य या सरकार का रूप क्या हो, यह सवाल है तो बड़े महत्त्व का, मगर अभी हमें उसकी चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है।

समाजवाद के आदर्श की बात पर एकराय होजाने के बाद दूसरी बात तय

करने की यह रह जाती है कि उसे हासिल कैसे किया जाय ? यहाँसे समाजवादियों में मतभेद शुरू होता है । उनमें कई दल हैं और वे अलग-अलग रास्ते बताते हैं । मोटे तौर पर उनके दो हिस्से किये जा सकते हैं : (१) धीरे-धीरे परिवर्तन और विकास चाहनेवाले दलों का यह विश्वास है कि एक-एक कदम बढ़ाकर चलना चाहिए और पार्लमेण्टों के जरिये काम करना चाहिए । ब्रिटिश मजदूर दल और फ्रेंचियन लोग इसी वर्ग में हैं । (२) क्रान्तिकारी दलों का विश्वास यह है कि पार्लमेण्टों से कुछ बहुत मिलनेवाला नहीं है । दूसरे वर्ग में ज्यादातर लोग मार्क्सवादी हैं । कभी-कभी ये लोग भी पार्लमेण्टों में पहुँचते हैं, मगर इनका मतलब दूसरे दलों से मिल-जुलकर काम करना नहीं बल्कि अडंगे डालना और झगड़ा खड़ा करना होता है ।

पहला यानी विकासवादी दल अब बहुत छोटा-सा रह गया है । इंग्लैण्ड में भी अब इसकी ताकत कम हो रही है और इसके, उदार (लिबरल) दल के और दूसरे असमाजवादी दलों के बीच का भेद मिटता जा रहा है । इसलिए अब मार्क्सवाद को ही आमतौर पर समाजवादी मत समझ लेना चाहिए । मगर मार्क्सवादियों में भी योरोप में दो मुख्य भेद हैं । एक तरफ़ इसी साम्यवादी हैं और दूसरी तरफ़ लोकसत्ता के माननेवाले जर्मनी, आस्ट्रिया और दूसरे देशों के समाजवादी हैं । इन दोनों में ज़रा भी प्रेम नहीं है । महायुद्ध के वक़्त और बाद में भी ये लोकसत्तावादी अपने दावे पूरे नहीं कर सके, इसलिए इनकी पुरानी इज्जत बहुत कम होगई । इनमें से ज्यादा जोशीले लोग तो बहुत-से साम्यवादियों में जा मिले हैं, मगर अब भी पश्चिमी योरोप के विशाल मजदूर-संघों का संचालन इन्हींके हाथों में है । इस में कामवादी मिल जाने के कारण साम्यवादी मत बढ़ रहा है । आज योरोप और दुनिया-भर में यही पूँजीवाद का सबसे बड़ा विरोधी है ।

तो फिर यह मार्क्सवाद है क्या ? यह इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र, मानव-जीवन और मानव-इच्छाओं को समझने का एक तरीका है । इसमें उसूल भी हैं और कुछ कर गुज़रने की पुकार भी है । यह ऐसा तत्त्वज्ञान है जो मनुष्य-जीवन के ज्यादातर कामों के बारे में कुछ-न-कुछ बात बताता ही है । इसमें मानव इतिहास पर—गुज़रे हुए, आजकल के और आगे आनेवाले ज़माने पर—विचार करके यह साबित करने की कोशिश की गई है कि यह सब कडे तर्कों या दलीलों के मुताबिक चलने-वाली प्रणाली है और 'क्रिस्मत' की तरह इसके क्रानून भी टल नहीं सकते । जिन्दगी यों बिल्कुल दलीलों पर चलनेवाली और कडे नियमों और प्रणालियों पर इतनी ही निर्भर हो, ऐसा बहुत साफ़ तो नहीं दीखता और बहुत लोगों को इसमें शक भी है ;

मगर मार्क्स ने वैज्ञानिक ढंग से पिछले इतिहास को देखा और उससे कुछ खास नतीजे निकाले। उसे मालूम हुआ कि इनसान को शुरू से ही जिन्दगी की लड़ाई करनी पड़ी है। यह लड़ाई कुदरत के साथ भी थी और आदमी के साथ भी। आदमी को खाना और दूसरी जीवन-सामग्री जुटाने के लिए काम करना पड़ा। जैसे-जैसे समय बीता वैसे-वैसे उसके तरीके बदलते और पेचीदा और प्रगतिशील होते गये। मार्क्स की राय के मुताबिक़ रोज़ी हासिल करने के ये तरीके इनसान और समाज की जिन्दगी में सभी युगों में सबसे महत्व की बात रहे हैं। इतिहास के हरेक युग में इन तरीकों की प्रधानता रही और उस युग के सारे कामों और सामाजिक सम्बन्धों पर इसका असर पड़ा। जैसे-जैसे ये बदले वैसे-वैसे बड़ी-बड़ी ऐतिहासिक और सामाजिक तब्दीलियाँ हुईं। इन ख़तों के दौरान में हम कुछ हद तक तो देख चुके हैं कि इन तब्दीलियों का कितना बड़ा असर हुआ है। उदाहरण के लिए, जब पहले-पहले खेती शुरू हुई तो बड़ा भारी फ़र्क़ होगया। आबारा फिरनेवाले ख़ानाबदोश लोग बस गये और गाँव और शहर बन गये। खेती से पैदावार बढ़ी तो माल बच रहा और आबादी बढ़ी। दौलत और फ़ुर्सत की वजह से कला-कौशल यानी कारीगरी पैदा हुई। दूसरी मिसाल औद्योगिक क्रान्ति की भी जाहिर है। पैदावार के लिए बड़ी-बड़ी मशीनों के जारी होने से दूसरा बड़ा भारी अन्तर पैदा हुआ। इसी तरह और भी बहुत-से दृष्टान्त दिये जा सकते हैं।

इतिहास के किसी खास समय में पैदावार के तरीके वैसे ही होते हैं जितनी लोग निश्चित रूप में प्रगति कर चुके होते हैं। उत्पत्ति के इस काम के बीच में और इसके कारण मनुष्यों के आपसी ताल्लुकात क़ायम होते हैं : जैसे चीज़ों का तबादला, ख़रीदना, बेचना और विनिमय वग़ैरा। ये ताल्लुकात उत्पत्ति यानी पैदावार के तरीकों के मुताबिक़ होते हैं। ताल्लुकात मिलकर समाज का माली ढाँचा बनाते हैं। इसी आर्थिक बुनियाद पर क़ानून, राजनीति, सामाजिक रीति-रिवाज, विचार और दूसरी सब बातों की उठान होती है। इसलिए मार्क्स के इस ख़याल के मुताबिक़ जैसे-जैसे पैदावार के तरीके बदलते हैं वैसे-वैसे आर्थिक रचना भी बदलती है और उसका नतीजा यह होता है कि लोगों के विचारों, क़ानूनों और राजनीति वग़ैरा में भी तब्दीलियाँ होती हैं।

इतिहास के बारे में मार्क्स का यह भी ख़याल था कि वह जुदा-जुदा वर्गों के आपसी संघर्ष का एक रेकॉर्ड यानी बयान है। “सारे मानव-समाज का पिछला और मौजूदा इतिहास वर्ग-युद्ध का इतिहास है।” जिस वर्ग के हाथ में उत्पत्ति के साधन होते हैं उसीकी प्रधानता रहती है। वह दूसरे वर्गों की मेहनत से बेजा

फायदा उठाता है। जो परिश्रम करते हैं उन्हें अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता। उन्हें जिन्दगी की मामूली जरूरियात के लिए भी मुश्किल से थोड़ा-सा हिस्सा मिलता है और बाकी का सारा हिस्सा शोषक यानी उनको चूसनेवाले वर्ग को मिलता है। इस तरह शोषक-वर्ग इस क़ालतू धन से और भी धनवान बनता है। चूंकि उत्पत्ति पर इस वर्ग का क़ब्ज़ा होता है इसलिए राज्य या सरकार पर भी इसीका नियंत्रण या दबाव रहता है और इस तरह इस शासक-वर्ग की रक्षा करना ही राज्य का मुख्य उद्देश्य रह जाता है। मार्क्स कहता है : "राज्य सारे शासक-वर्ग के काम-काज का इंतज़ाम करने के लिए हमारी प्रबंध-समिति यानी इंतज़ामिया कमेटी है।" इसी गरज से क़ानून बनाये जाते हैं और तालीम, मज़हब और दूसरे जरूरियों से लोगों को यह समझाया जाता है कि इस वर्ग की प्रभुता न्यायानुकूल और स्वाभाविक है। इस तरह सरकार और क़ानून के इस वर्गीय रूप को छिपाने की हर तरह कोशिश की जाती है, ताकि दूसरे शोषित वर्ग असली हालत न जान सकें और उनमें असंतोष पैदा न हो। मगर कोई शरस नाराज होकर इस प्रणाली का सामना करता है तो राज्य उसे समाज और सदाचार का दुश्मन और पुराने रीति-रिवाज तोड़नेवाला कहकर फुचल देता है।

मगर हजार कोशिश करने पर भी एक ही वर्ग सदा सबके सिर पर बैठा नहीं रह सकता। जिन कारणों से उसे यह ताक़त और हुकूमत हासिल होती है वे ही उसके ख़िलाफ़ काम करने लगते हैं। वह शासक और शोषक-वर्ग इसी कारण बन जाता है कि उस वर्ग के उत्पत्ति के साधन उसके हाथ में होते हैं। जब पैदावार के तरीक़े नये होते हैं तो उनपर क़ाबू भी नये वर्गों का होजाता है और वे किसीसे दबकर रहना नहीं चाहते। नये-नये विचार मनुष्यों के दिल और दिमाग में हलचल मचा देते हैं और जिसे विचार-क्रान्ति कहते हैं वह होने लगती है। इससे पुराने ख़यालात और उसूलों की वेड़ियाँ टूटती हैं। और इस उठते हुए नये वर्ग के और सत्ता से चिपटे रहनेवाले पुराने वर्ग के बीच में क़शमक़श होती है। नये वर्ग के हाथ में आर्थिक सत्ता यानी माली ताक़त होती है, इसलिए जीत उसीकी होती है और पुराने वर्ग का खेल ख़त्म होकर वह नेस्त-नाबूद हो जाता है।

इस नये वर्ग की विजय राजनैतिक और आर्थिक दोनों तरह की होती है। यह उत्पत्ति के नये तरीक़ों की फ़तह की निशानी होती है और इसके पीछे-पीछे समाज की सारी रचना में ही तब्दीली होने लगती है—नये ख़यालात, नई राजनैतिक रचना, क़ानून, रीति-रिवाज, सभी बातों पर असर पड़ता है। अब यह नया वर्ग अपने नीचे के वर्गों के लिए शोषक-वर्ग बन जाता है और फिर उन वर्गों में से किसी एक के हाथों

वह हटा दिया जाता है। इस तरह जबतक एक वर्ग दूसरे का शोषण करनेवाला रहेगा तबतक यह कशमकश चलती रहेगी, जैसे कि अबतक चलती आई है। यह झगड़ा उसी वक़्त ख़त्म होगा जब अनेक वर्ग न रहकर सिर्फ़ एक ही वर्ग रह जायगा; क्योंकि तब शोषण की गुंजायश ही नहीं रहेगी। कोई वर्ग अपना शोषण तो कर नहीं सकता। इसलिए, उसी वक़्त समाज में समझौता और सहयोग होगा। फिर यह आज का-सा लगातार संघर्ष और प्रतिस्पर्धा न रहेगी। और राज्य के लिए आज दमन का काम जो मुख्य हो रहा है वह भी न रहेगा; क्योंकि दवाने के लिए कोई वर्ग ही न होगा। इस तरह धीरे-धीरे राज्य ख़ुद मिट जायगा और अराजकतावाद का आदर्श नजदीक आ जायगा।

इस तरह मार्क्स इतिहास को इस नज़र से देखता था कि वह अनिवार्य वर्ग-युद्ध की एक विशाल विकास-क्रिया है। ढेरों मिसाल और तफ़्सील देकर उसने साबित किया कि गुज़िश्ता ज़माने में यह सब किस तरह हुआ, बड़ी-बड़ी मशीनों के आने से सामन्तशाही का युग पूंजीवादी ज़माने में कैसे बदल गया और ज़ामीरदारों की जगह दौलतमन्द कैसे आगये। उसके मत से आख़िरी वर्ग-युद्ध हमारे ज़माने में अमीरों और मजदूरों में हो रहा है। पूंजीवाद ख़ुद उस वर्ग की ताक़त और तादाद बढ़ा रहा है जो अख़ीर में पूंजीवाद पर ग़ालिब आकर वर्ग-रहित समाज और समाजवाद की स्थापना करेगा।

इतिहास को इस ढंग से देखने का तरीक़ा, जो मार्क्स ने समझाया, 'इतिहास की पदार्थमूलक या भौतिक धारणा' कहलाता है। इसे भौतिक इसलिए कहते हैं क्योंकि यह 'आदर्शवादी' तरीक़ा नहीं है और इस 'आदर्शवादी' शब्द का प्रयोग एक ख़ास मानी में मार्क्स के ज़माने के तत्त्ववेत्ताओं ने बहुत किया था। उस वक़्त विकास-वाद के विचार लोकप्रिय हो रहे थे। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि जहाँतक प्राणी-समूहों की उत्पत्ति और विकास का ताल्लुक है, डार्विन ने ये ख़याल लोगों के दिमाग़ में जमा दिये थे। मगर इससे मनुष्यों के सामाजिक सम्बन्धों के कारण समझ में नहीं आ सकते थे। कुछ तत्त्ववेत्ताओं ने अनिश्चित आदर्शवादी कल्पनाओं के जरिये यह बताने की कोशिश की कि मनुष्य की प्रगति मन की प्रगति पर निर्भर है। मार्क्स इन सब बातों को ग़लत कहता था। उसके ख़याल से बिना सिर-पैर की हवाई कल्पनाएँ और आदर्शवाद ख़तरनाक चीज़ें हैं, क्योंकि इस तरह से लोग तरह-तरह की निराधार बातों को मानने लग सकते हैं। इसलिए मार्क्स ने ज्यादा अमली और वैज्ञानिक ढंग से घटनाओं और स्थिति को देखा। पदार्थमूलक या भौतिक शब्द इसीलिए प्रचलित हुआ।

माक्स ने लगातार शोषण और वर्ग-युद्ध की चर्चा की है। हममें से भी बहुत लोग करते हैं और हमें जोश भी आजाता है। मगर माक्स के ख्याल से नेक सलाह पर गुस्ते में आने की कोई बात नहीं हो सकती। शोषण में शोषण करनेवाले व्यक्ति का क्रूर नहीं है। एक वर्ग पर दूसरे की प्रभुता होना ऐतिहासिक प्रगति का कुदरती नतीजा है। समय पाकर उसकी जगह दूसरी व्यवस्था होजायगी। अगर कोई आदमी मत्ताधारी वर्ग का है और उस हँसियत से दूसरों को चूसता है तो इसमें वह कोई भयंकर पाप नहीं करता। वह एक पद्धति का अंग है और उसे गालियाँ देना बाह्यात बात है। व्यक्तियों और प्रणालियों के बीच का यह भेद हम बहुत भूल जाते हैं। हिन्दुस्तान ब्रिटिश साम्राज्यवाद के मातहत है और हम अपनी सारी ताकत लगाकर इस साम्राज्यवाद से लड़ते हैं। मगर जो अंग्रेज हिन्दुस्तान में इस प्रणाली का पोषण करते हैं उनका क्या क्रूर है? वे बेचारे एक बड़ी भारी मशीन के छोटे-छोटे पुर्जे हैं। उसकी चाल में जरा भी फ़र्क करना उनकी ताकत के बाहर की बात है। इसी तरह हममें से भी कुछ लोग समूची जमींदारी-प्रथा को बुरी और किसानों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह समझ सकते हैं, क्योंकि इससे उनको बुरी तरह चूसा जा रहा है। मगर इसका भी यह मतलब नहीं है कि जुदा-जुदा जमींदारों का कोई क्रूर है। पूँजीपतियों को अक्सर शोषण करनेवाले कहकर बुरा बताया जाता है, मगर उनकी बात भी ऐसी ही है। क्रूर सदा प्रणाली यानी तौर-तरीके का होता है, व्यक्तियों का नहीं।

माक्स ने वर्ग-युद्ध की तालीम नहीं दी। उसने यह साबित किया कि असल में वर्ग-युद्ध पहले से मौजूद है और किसी-न-किसी शकल में सदा से रहा है। 'पूँजी' नाम की किताब लिखने का उसका उद्देश्य यह था कि 'वर्तमान समाज की गति के आर्थिक नियम साफ़-साफ़, अपने नंगे रूप में, जाहिर हो जायें।' ऊपर का यह परदा हटा देने से समाज के जुदा-जुदा वर्गों की ज़बरदस्त आपसी कशमकश सामने आगई। वर्ग-युद्ध की तरह ये संघर्ष सदा प्रकट नहीं होते, क्योंकि प्रधान वर्ग हमेशा अपने वर्गीय रूप को छिपाने की कोशिश करता है। लेकिन जब वर्तमान व्यवस्था के लिए ही ख़तरा पैदा होजाता है तब प्रधान वर्ग सारे बहाने और आड़ छोड़कर असली शकल में जाहिर होजाता है और फिर वर्ग-वर्ग में खुली लड़ाई होने लगती है। जब यह होता है तब लोकसत्ता, साधारण क़ानून और जाबता सब ताक में रख दिये जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये वर्ग-युद्ध शलतफ़हमीया आन्दोलकों की शरारत के कारण होते हैं। मगर बात ऐसी नहीं है। यह तो समाज के स्वभाव में है और असल में जब हित-विरोध की बात लोग अच्छी तरह समझने लगते हैं तब तो वर्ग-युद्ध और भी बढ़ जाते हैं।

अब जरा मार्क्स के इन उसूलों का मुकाबिला हिन्दुस्तान की मौजूदा हालत से करो। ब्रिटिश सरकार का शुरू से यह दावा है कि हिन्दुस्तान में उसकी हुकूमत का पाया इनसाफ़ और हिन्दुस्तानियों की भलाई है। पहले हमारे बहुत-से देशवासी भी जरूर यह मानते थे कि इस दावे में थोड़ी सचाई है। मगर अब तो इस शासन के खिलाफ़ बड़ा सार्वजनिक आन्दोलन खड़ा होकर इसे जोरदार चुनौती दे रहा है; इस कारण इसकी असली शक्ल बड़े ही भद्दे और नंगे तरीके पर जाहिर हो रही है। आज अन्धे को भी दीख सकता है कि बन्दूकों के बल पर चलनेवाले इस साम्राज्यवादी शोषण की असलियत क्या है। इसके ऊपर का सुहावनी सूरतों और चिकनी-चुपड़ी बातों का सारा मुलूमा जाता रहा है। आर्डिनेसों और भाषण, सम्मेलन और लेखन यानी बोलने, मिलने और लिखने के प्रारम्भिक अधिकारों के दमन ने देश के साधारण कानून और जायते की जगह लेली है। मौजूदा हुकूमत की जितनी ज्यादा मुत्तालफ़त होगी, यह हालत उतनी ही बढ़ती जायगी। जब एक वर्ग दूसरे वर्ग के लिए खतरनाक होजाता है तब भी यही हाल होता है। यह भी आज हमारे देश में होता हुआ हम देख रहे हैं। किसानों और मजदूरों को और उनके लिए काम करनेवाले कार्यकर्त्ताओं को अमानुषिक सजायें दी जाती हैं।

इस तरह इतिहास के बारे में मार्क्स का उसूल यह था कि समाज सदा बदलता और बढ़ता रहता है। इसमें कोई चीज़ स्थिर नहीं है। इस कल्पना में गति ही गति है। कुछ भी होता रहे, यह तो आगे ही आगे बढ़ती है और एक तरह की सामाजिक व्यवस्था के स्थान पर दूसरी आजाती है। लेकिन एक व्यवस्था उसी समय नष्ट होती है जब वह अपना काम पूरा कर चुकती है और उसका पूरी तरह विकास हो चुकता है। इससे पहले वह व्यवस्था नहीं मिटती। जब समाज उससे आगे बढ़ जाता है तब भी वह सिर्फ़ पुरानी व्यवस्था के वस्त्र उतारकर फेंक देता है और नई और बड़ी पोशाक पहन लेता है; क्योंकि पुराने कपड़े तंग होकर बदन को जकड़ने लगते हैं।

मार्क्स के मत से इनसान का काम इस महान् ऐतिहासिक विकास-क्रिया में मदद पहुँचाना था। पहले की सब मंजिलें तय हो चुकीं। अब पूँजीवादी समाज और मजदूरवर्ग की आखिरी लड़ाई हो रही है। (अलबत्ता यह बात उन देशों की है जहाँ उद्योग-धंधे बहुत बढ़े-चढ़े हैं और पूँजीवाद का पूरा विकास हो चुका है। दूसरे देशों में जहाँ पूँजीवाद का विकास नहीं हुआ है, लड़ाई की शक्ल कुछ खिलत-मिलत और दूसरी ही तरह की है। मगर असलियत यह है कि वहाँ भी लड़ाई की कुछ-न-कुछ यही शक्ल है; क्योंकि संसार के देशों का सम्बन्ध एक-दूसरे से दिन-दिन ज्यादा बढ़ता

जा रहा है ।) माक्स का कहना है कि पूंजीवाद को मुश्किल पर मुश्किल और मुसीबत पर मुसीबत का सामना करना पड़ेगा और अखीर में वह गिर पड़ेगा; क्योंकि उसमें समता तो कहीं है ही नहीं । यह बात लिखे हुए माक्स को साठ वर्ष से ऊपर होगये और तबसे पूंजीवाद के लिए नाजुक वक़्त भी बहुत आये । लेकिन उसका खात्मा तो इस के सिवा कहीं नहीं हुआ । वह अभी ज्यों-का-त्यों कायम है, बल्कि पहले से भी ज्यादा ताकतवर हुआ है । हाँ, जिस वक़्त में यह लिख रहा हूँ उस वक़्त दुनियाभर में पूंजीवाद बुरी तरह बीमार दिखाई देता है और चिकित्सक लोग उसके अच्छा होने के बारे में सिर हिला-हिलाकर चिन्ता प्रकट कर रहे हैं ।

कहा जाता है कि पूंजीवाद ने जो अपनी जिन्दगी इतनी बढ़ाली, इसका एक खास कारण था, जो माक्स के ध्यान में भी पूरी तरह नहीं आया होगा । वह यह कि पश्चिम के जो देश उद्योग-धंधों में बहुत बढ़ गये हैं वे पिछड़े हुए देशों पर राज्य करके उनका शोषण करते हैं । इससे पूंजीवाद को नई जिन्दगी और खुशहाली हासिल होगई और उसकी कीमत चुकानी पड़ी उन गरीब गुलाम और चूसे जानेवाले देशों को ।

हम इस बात की बहुत बार निन्दा करते हैं कि मौजूदा पूंजीवाद में गरीब का अमीर और मजदूर का पूंजीपति शोषण करते हैं । बात सोलह आने सही है । इसलिए नहीं कि पूंजीवादी का क्रसूर है, बल्कि इसलिए कि इस प्रणाली का पाया ही इस तरह के शोषण पर है । मगर साथ ही हमें यह भी नहीं समझ लेना चाहिए कि पूंजीवाद में ही यह कोई नई बात है । सभी पिछले युगों और सारी प्रणालियों में मजदूरों और गरीबों की क्रिस्मत में शोषण तो रहा ही है । असल में यह कहा जा सकता है कि पूंजीवादी शोषण के बावजूद वे आज पिछले ज़माने से ज्यादा खुशहाल हैं । पर इतना कहने से पूंजीवाद की अच्छाई साबित नहीं होती । उसके पक्ष में यह बहुत छोटी-सी बात है ।

माक्सवाद का सबसे बड़ा आधुनिक व्याख्याता लेनिन हुआ है । उसने इसकी व्याख्या और अर्थ ही नहीं किये, उनके अनुसार आचरण भी किया । फिर भी उसने हमें यह चेतावनी दी है कि कहीं हम माक्सवाद को कोई ऐसा सिद्धान्त न मान बैठें जिसमें किसी तरह के उलट-फेर की गुंजाइश न हो । उसे इसके तत्त्व की सचाई पर विश्वास था, मगर वह इसकी हरेक छोटी-छोटी बात को मानने और हर कहीं बिना सोचे-समझे लागू करने को तैयार नहीं था । वह हमें बताता है—“हम किसी भी मानी में माक्सवाद को कोई ऐसी चीज़ नहीं समझते कि वह सम्पूर्ण है और उसमें कोई दोष नहीं निकाला जा सकता । इसके खिलाफ़ हमारा बृढ़ विश्वास है कि वे उसूल एक ऐसे विज्ञान के आधार हैं जिसकी समाजवादियों को हर दिशा में उन्नति

करनी चाहिए, वर्ना वे जिन्दगी की दौड़ में पीछे रह जायेंगे। हमारे खयाल से रूसी समाजवादियों के लिए मार्क्स के उसूलों का निष्पक्ष अध्ययन खास तौर पर जरूरी है, क्योंकि इन उसूलों से सिर्फ रास्ते की तरफ इशारा करनेवाले मामूली विचार मिलते हैं। ये विचार इंग्लैण्ड, फ्रांस, जर्मनी और रूस में अलग-अलग ढंग पर लागू हो सकते हैं।”

इस खत में मैंने तुम्हें मार्क्स के उसूलों का कुछ हाल बताया है, मगर न मालूम इस भानमती के पिटारे से तुम्हें कुछ फायदा होगा या नहीं और कोई साफ़ विचार मिलेंगे या नहीं। इन उसूलों को जान लेना इसलिए अच्छा है कि आज इनका विशाल जन-समूहों पर असर पड़ रहा है और इनसे हमें अपने देश में भी मदद मिल सकती है। रूस के महान् राष्ट्र और सोवियट संघ के दूसरे हिस्सों ने मार्क्स को अपना बड़ा पैगम्बर बनाया है और आज के कण्ट-पीड़ित संसार में बहुत लोग इलाज और प्रेरणा के लिए उसकी तरफ़ आँखें लगाये हुए हैं।

मैं इस खत को अंग्रेज़ कवि टेनोसन की कुछ पंक्तियों के साथ खतम करूँगा :

“The old order changeth yielding place to new,
And God fulfils himself in many ways,
Lest one good custom should corrupt the world.”

पुरानी व्यवस्था बदल कर नई के लिए जगह खाली करती है;

और परमात्मा का काम कई तरीकों से पूरा होता रहता है, ताकि ऐसा न हो कि कहीं एक अच्छा रिवाज सारी दुनिया को खराब कर दे।

मार्क्स का प्रथाओं के बदलने में विश्वास था, लेकिन धर्म में उसकी श्रद्धा नहीं थी। उसे तो वह ‘लोगों के लिए अक्रिम’ बताता था।

: १३५ :

इंग्लैण्ड का विक्टोरिया-युग

२२ फ़रवरी, १९३३

समाजवादी विचारों के विकास का वर्णन करते हुए मैंने अपने खतों में तुम्हें बताया है कि अंग्रेज़ों का समाजवाद सबसे नरम ढंग का रहा है। उस वक़्त योरोप में जितनी विचार-सरणियाँ प्रचलित थीं उनमें यह सबसे कम क्रांतिकारी था। हालत सुधारने के लिए यह बहुत धीरे-धीरे तब्दीली होने की बाट देखा करता था। कभी-कभी जब व्यापार बिगड़ जाता, मन्दी फैल जाती, बेकारी बढ़ जाती, मजदूरी घट जाती और लोगों को तकलीफ़ होने लगती, तब इंग्लैण्ड में भी क्रान्ति की लहर

उठ खड़ी होती थी। मगर जरा हालत अच्छी हुई कि फिर जोश टण्डा पड़ जाता। उन्नीसवीं सदी में अंग्रेजों के विचारों की इस नरमी का इंग्लैण्ड की खुशहाली से गहरा ताल्लुक था, क्योंकि खुशहाली और क्रांति में मेल नहीं होता। क्रांति का अर्थ है बड़ा परिवर्तन, और जो लोग मौजूदा हालत से संतुष्ट-से होते हैं उन्हें और अच्छी हालत होजाने की अनिश्चित आशा पर अपने को जोखिम में डालकर साहस का काम कर बैठने की इच्छा नहीं होती।

उन्नीसवीं सदी असल में इंग्लैण्ड की महानता का समय था। अठारहवीं सदी में उसने औद्योगिक क्रांति करके और दूसरे देशों से पहले नये कारखाने बनाकर जो अगुआपन हासिल कर लिया था वह उन्नीसवीं सदी के ज्यादातर हिस्से में भी कायम रहा। मैं कह चुका हूँ कि वह दुनिया का कारखाना था और उसमें दूर-दूर के देशों से आ-आकर धन की वर्षा होती थी। हिन्दुस्तान और दूसरे उप-निवेशों की लूट से उसके पास वैशक्कीमत और अटूट दौलत चली आ रही थी और उसकी प्रतिष्ठा खूब बढ़ती थी। जिस वक़्त योरप के करोड़-करोड़ सभी मुल्कों में तब्दीलियाँ हो रही थीं उस वक़्त भी इंग्लैण्ड में कोई क्रांति या विस्फोट नहीं हुआ और वह चट्टान की तरह मजबूत और ठोस होकर खड़ा दिखाई देता था। समय-समय पर मुसीबतें जरूर आईं, मगर वह थोड़े-से और आदमियों को राय देने का हक़ देकर टाल दी गईं। हम यह भी देख चुके हैं कि इस बीच में फ़्रांस में एक के बाद एक प्रजातन्त्रों और साम्राज्यों का ताँता बँधा रहा; इटली में एक लम्बे जमाने की फूट के बाद सारा प्रायद्वीप एक होगया और एक नया राष्ट्र बन गया; और जर्मनी में एक नये साम्राज्य ने जन्म लिया। बेलजियम, डेनमार्क और यूनान जैसे छोटे-छोटे देश भी कई तरह बदले। आस्ट्रिया में तब भी योरप के सबसे पुराने राजघराने हँसवर्ग की राजधानी थी, लेकिन उसे फ़्रांस, इटली और प्रशिया ने बार-बार नीचा दिखाया। सिक्र पूर्व में रूसी ज़ार बड़े मुग़लों की तरह निरंकुश शासन चला रहा था और रूस में कोई तब्दीली दिखाई नहीं दे रही थी। मगर वह औद्योगिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ था और किसानों का राष्ट्र था। नये विचारों और नये कारखानों की अभी उसे हवा भी नहीं लगी थी।

इंग्लैण्ड अपनी दौलत, अपने साम्राज्य और अपनी समुद्री ताक़त के कारण योरप और संसार-भर पर हावी होरहा था। वह बहुत बड़ा राष्ट्र होगया था और उसका जाल दुनियाभर में फैला हुआ था। अमेरिका के संयुक्तराष्ट्र अभी-तक अपने भीतरी झगड़ों में फँसे हुए थे और उन्हें दुनिया के मामलों से घर की तरक्की की ज्यादा फ़िक्र थी। आमदरपत के जरियों में हैरतअंगेज तब्दीलियाँ हो

रही थीं और उनके कारण पृथ्वी छोटी और घनी होती दिखाई दे रही थी। इन बातों से भी इंग्लैण्ड को दूर देशों पर अपना पंजा मजबूत करने में मदद मिली। इन सब तब्दीलियों के होते हुए भी इंग्लैण्ड में सरकार की सूरत वही रही। वहाँ वैध यानी ऐसा राजा रहा जिसके हाथ में नाम-मात्र की सत्ता हो और सारी असली ताक़त पार्लमेण्ट की समझी जाय। इस पार्लमेण्ट को पहलेपहल मुट्ठीभर ज़मींदारों और धनी व्यापारियों ने चुना था, मगर बाद में जब-जब विकट स्थिति पैदा हुई तब-तब आफ़त ढालने के लिए ज्यादा-ज्यादा लोगों को राय देने का हक़ दे दिया गया।

इस सदी के ज्यादातर हिस्से में विक्टोरिया इंग्लैण्ड की रानी थी। वह जर्मनी के हनोवर घराने की लड़की थी। इस घराने ने अठारहवीं सदी में ब्रिटिश राज-सिंहासन को जार्ज नाम के कई राजा दिये। विक्टोरिया १८३७ में गद्दी पर बैठी। उस वक़्त वह १८ वर्ष की लड़की थी। उसने सदी के अन्त यानी १९०० ई० तक ६३ वर्ष राज्य किया। इंग्लैण्ड में इस लम्बे समय को अक्सर विक्टोरिया-युग के नाम से पुकारते हैं। इस तरह रानी विक्टोरियाने योरप में और दूसरे देशों में बहुत-सी बड़ी-बड़ी तब्दीलियाँ देखीं, जिनसे पुराने ज़माने के निशानात मिट गये और उनकी जगह पर नये क़ायम हो गये। उसने योरप की क्रांतियाँ, फ़्रांस की तब्दीलियाँ, इटली के राज्य और जर्मनी के साम्राज्य का जन्म देखा। मरते समय वह एक तरह से योरप और योरप के राजाओं की दादी थी। मगर योरप में विक्टोरिया का सम-कालीन एक और राजा भी था, जिसका भी वैसा ही इतिहास है। वह आस्ट्रिया के हैप्सबर्ग राजघराने का सम्राट् फ़्रांसिस जोज़ेफ़ था। जब क्रांति के वर्ष १८४८ ई० में वह अपने साम्राज्य की गद्दी पर बैठा तो उसकी भी उम्र १८ वर्ष की ही थी। उसने ६८ वर्ष हुकूमत की और किसी तरह आस्ट्रिया, हंगरी और दूसरे हिस्सों को अपने मातहत एक करके रखने में कामयाब हुआ। लेकिन महासमर ने उसका और उसके साम्राज्य दोनों का काम तमाम कर दिया।

विक्टोरिया उससे ज्यादा खुशकिस्मत थी। अपने शासन-काल में उसने इंग्लैण्ड की ताक़त को बढ़ते और उसके साम्राज्य को फैलते हुए देखा। जब गद्दी पर बैठी तब कनाडा में उपद्रव था। वहाँ खुली बग़ावत थी और उपनिवेश के बहुत-से बाशिन्दे इंग्लैण्ड से अलग होकर अपने पड़ोसी अमेरिका के संयुक्त राज्यों में मिल जाना चाहते थे। मगर इंग्लैण्ड ने अमेरिका की लड़ाई से सक्क सीख लिया था और उसने जल्दी से कनाडा वालों को स्वशासन का बड़ा हिस्सा देकर राज़ी कर लिया। थोड़े समय बाद वह बढ़ते-बढ़ते अन्दरूनी मामलों में पूरी तौर पर आज़ाद उपनिवेश बन गया।

साम्राज्य में यह नये ढंग का प्रयोग था, क्योंकि आजादी और साम्राज्य साथ-साथ नहीं रह सकते। मगर परिस्थिति से मजबूर होकर इंग्लैण्ड को ऐसा करना पड़ा, वर्ना वह कनाडा को खो बैठता। कनाडा के ज्यादातर लोग अंग्रेजी नस्ल के थे, इसलिए मातृ-भूमि यानी मादरे वतन इंग्लैण्ड के साथ उन्हें बड़ी मुहब्बत थी। इधर इस नये देश में लम्बी-चौड़ी जमीन यूँ ही पड़ी थी; उसका कोई विकास नहीं था और आबादी भी बहुत कम थी। इसलिए उसे अपनी तरक्की के लिए अंग्रेजी माल और अंग्रेजी पूँजी पर निर्भर रहना पड़ता था। इस तरह उस वक़्त दोनों देशों के स्वार्थों में कोई विरोध नहीं था और उनके बीच में जो अजीब और नया रिश्ता कायम हुआ उसपर कोई जोर नहीं पड़ा।

इसी सदी में आगे चलकर अंग्रेजों की विदेशी वस्तियों को स्वराज्य देने के इस तरीके का और विस्तार हुआ। सदी के बीच तक आस्ट्रेलिया क़ैदियों को रखने की जगह थी। सदी के अन्त में वह साम्राज्य के भीतर आजाद उपनिवेश बना दिया गया।

दूसरी तरफ़ हिन्दुस्तान में अंग्रेजों का पंजा और भी मजबूत होगया और लड़ाइयों पर लड़ाइयाँ करके और इलाक़े पर इलाक़े जीतकर यहाँ अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार किया गया। हिन्दुस्तान अंग्रेजों के पूरी तरह मातहत होगया। स्वशासन का नाम-निशान भी नहीं रहा। १८५७ का विद्रोह कुचल दिया गया और हिन्दुस्तान को साम्राज्य के पूरे बोझ का अनुभव करा दिया गया। मैं तुम्हें दूसरी जगह बता चुका हूँ कि इंग्लैण्ड ने मुक्तलिफ़्त तरीक़ों से हिन्दुस्तान को किस तरह लूटा और चूसा। बिला किसी श्रुवहे के ब्रिटेन का साम्राज्य हिन्दुस्तान ही था और संसार के सामने इस सचाई का ऐलान करने के लिए रानी विक्टोरिया ने हिन्दुस्तान की साम्राज्ञी की पदवी ग्रहण की। मगर हिन्दुस्तान के अलावा दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में और भी कई छोटे-छोटे देश इंग्लैण्ड के मातहत थे।

इस तरह दो किस्म के मुल्कों से बना हुआ ब्रिटिश साम्राज्य एक अजीब भानमती का पिटारा होगया। एक तरफ़ तो अपने अन्दरूनी मामलों में खुदमुस्तार देश थे जो बाद में आजाद उपनिवेश होगये, और दूसरी तरफ़ मातहत और रक्षित देश थे। पहली तरह के देश थोड़े या बहुत एक ही कुटुम्ब के सदस्य थे और मातृ-देश इंग्लैण्ड को अपना मुखिया मानते थे। दूसरी किस्म के देश साफ़ तौर पर चाकर और गुलाम थे; उन्हें नीचा समझा जाता था, उनके साथ बुरा बर्ताव होता था और उनका शोषण किया जाता था। खुदमुस्तार उपनिवेशों के लोग ब्रिटिश या दूसरे यूरोपियन और उनकी औलाद थे और मातहत देशों के लोग गैर-ब्रिटिश और गैर-

यूरोपियन थे । ब्रिटिश साम्राज्य के दोनों हिस्सों में यह फ़र्क आज तक बना हुआ है ।

इंग्लैण्ड के पास दीलत भी थी और ताक़त भी । इसलिए वह सन्तुष्ट-सा था । बिल्कुल सन्तुष्ट तो नहीं था, क्योंकि साम्राज्य की भूख कभी पूरी नहीं होती । सीमायें उसे नहीं सुहातीं और वह आगे-से-आगे बढ़ना चाहता है । फिर भी इंग्लैण्ड को ख़ास चिन्ता यह नहीं थी कि और ज्यादा कैसे लिया जाय, बल्कि यह थी कि जो मिल गया है उसकी हिफ़ाज़त कैसे की जाय ? हिन्दुस्तान उसके लिए सोने की चिड़िया थी । उसे अख़ीर तक अपने पंजे में रखने की उसे बड़ी ख़्वाहिश थी । उसकी सारी वैदेशिक नीति का आधार यह था कि हिन्दुस्तान उसके क़ब्ज़े में रहे और पूर्व के समुद्री रास्ते महफूज़ रहें । इसी कारण उसने मिस्र में हाथ डाला और अख़ीर में उसे अपने क़ब्ज़े में किया; और इसी वजह से उसने ईरान और अफ़ग़ानिस्तान में दस्तन्दाजी की । उसने बड़ी चालाकी से स्वेज़ नहर की कम्पनी के हिस्से ख़रीद कर नहर पर अधिकार पा लिया ।

उन्नीसवीं सदी के ज्यादातर हिस्से में योरप के बहुतेरे दूसरे देशों की तरफ़ से इंग्लैण्ड को चिन्ता नहीं रही, क्योंकि उनके घर के झगड़े ही बहुत थे और अक्सर वे आपस में लड़ते रहते थे । इंग्लैण्ड अपने उसी पुराने खेल के मुताबिक़ योरप में एक देश को दूसरे से लड़ाकर समतौल क़ायम रखता और उनके आपसी झगड़ों से ख़ुद फ़ायदा उठाता रहा । तीसरे नेपोलियन से उसे ख़तरा लगा था, मगर वह ख़त्म हो गया और फ़्रांस को सम्हलने में कुछ वक़्त लग गया । जर्मनी अभी इतना नहीं बढ़ा था कि उसकी संजीदगी के साथ मुख़ालिफ़ समझा जाता । लेकिन एक देश ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देनेवाला जरूर दिखाई देता था और वह था ज़ारशाही रूस । वह पिछड़ा हुआ था, मगर नक़शे में वह बड़ा लम्बा-चौड़ा देश था । जैसे इंग्लैण्ड हिन्दुस्तान और दक्षिणी एशिया में फैल गया था, वैसे रूस का विस्तार उत्तरी और मध्य-एशिया में हो चुका था । उसकी सरहद हिन्दुस्तान से बहुत दूर भी न थी । रूस की यह निकटता ब्रिटिश लोगों के लिए सदा ख़तरे की बात थी । मैंने हिन्दुस्तान का बयान करते वक़्त तुम्हें बताया है कि ब्रिटिश लोगों ने अफ़ग़ानिस्तान पर हमले किये थे और अफ़ग़ानों से लड़ाई की थी । इस सबका मुख्य कारण ज़ारशाही रूस का डर था ।

योरप में भी इंग्लैण्ड और रूस की टक्कर हुई । रूस एक ऐसा अच्छा बन्दरगाह चाहता था जो वारहों महीने काम दे सके और जाड़े में जिसका पानी जम न जाय । उसका इलाक़ा बहुत लम्बा-चौड़ा था, मगर उसके सारे बन्दरगाह कहीं-न-कहीं आर्टिक घेरे के पास थे और कुछ महीनों तक वहाँका पानी जमकर बर्फ़ हो जाता था ।

हिन्दुस्तान और अफ़ग़ानिस्तान में, इसी तरह ईरान में, भी ब्रिटिश लोग उसे समुद्र तक नहीं पहुँचने देते थे। काले समुद्र का मुँह वास्कोरस और दर्रे दानियाल पर तुर्कों का कब्ज़ा होने से बन्द था। पहले रूस ने कुस्तुन्तुनिया पर कब्ज़ा करने की कोशिश की, मगर तुर्क लोग उससे ज्यादा ताक़तवर साबित हुए। इस वक़्त तुर्कों का जोर घट गया था और जिस चीज़ पर रूस की अर्से से राल टपक रही थी वह उसके हाथ में आती दिखाई दी। उसने उसे लेने की कोशिश की। मगर इंग्लैंड आड़े आगया और विलकुल स्वार्थपूर्ण कारणों से वह तुर्कों का हिमायती बन गया। १८५४ ई० में क्रीमिया की लड़ाई से और बाद में दूसरी लड़ाई की धमकी से रूस की तलवार म्यान में ही रक्खी रह गई।

१८५४ से १८५६ तक की इसी क्रीमियन लड़ाई में वीरांगनाओं का एक स्वयं-सेविका-दल फ्लोरेंस नाईटिंगेल के नेतृत्व में घायलों की सेवा के लिए गया। उस वक़्त यह एक ग़ैरमामूली बात थी, क्योंकि ब्रिटोरिया-युग की मध्यमवर्ग की स्त्रियाँ आजकल की बहुत-सी शिक्षित हिन्दुस्तानी स्त्रियों की तरह घर में पड़ी रहनेवाली और मुख्यतः दीवानख़ाने की शोभा बढ़ानेवाली थी। फ्लोरेंस नाईटिंगेल ने उनके सामने सेवा करने की एक नई मिसाल रक्खी और वे बहुत-सी औरतों को घर की चहारदीवारी से बाहर लाई। इस तरह स्त्रियों की उन्नति के आन्दोलन में उनका महत्वपूर्ण स्थान है।

ब्रिटेन की सरकार का ढाँचा ऐसा था जिसे वैध एकतंत्री शासन या 'मुकुटधारी प्रजातंत्र' कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि राजा के हाथ में असली ताक़त कुछ न थी और उसे वही कहना और करना पड़ता था जो पार्लमेण्ट के विश्वासपात्र मंत्री चाहते थे। राजनैतिक दृष्टि से वह मंत्रियों के हाथ की कठपुतली होता था और कहा यह जाता था कि वह 'राजनीति से परे' है। असल बात यह है कि कोई तेज़ बुद्धि या मजबूत इरादे वाला आदमी सिर्फ़ कठपुतली बनकर नहीं रह सकता और अंग्रेज़ राजाओं या रानियों को भी सरकारी मामलों में दख़ल देने के बहुत अवसर मिलते थे। आमतौर पर यह बात परदे के भीतर होती है, और जनता को या तो कुछ मालूम ही नहीं हो पाता या होता भी है तो बहुत समय बाद। खुली दस्तन्दाजी पर बड़ा असन्तोष फैल सकता है और बादशाहत ख़तरे में पड़ सकती है। वैध शासक में बड़ा गुण जो होना चाहिए वह है कौशल। अगर यह उसमें है, तो फिर उसका काम चल सकता है और वह कई तरह से अपना असर डाल सकता है।

विधान और क़ानून की रू से अमेरिका की तरह प्रजातन्त्रों के अध्यक्षों के पास पार्लमेण्ट वाले देशों के मुकुटधारी शासकों से कहीं ज्यादा सत्ता होती है। मगर

अध्यक्ष जल्दी-जल्दी बदलते रहते हैं और राजा लम्बे समय तक बने रहने हैं और चुपचाप ही सही, मगर काम-काज पर किसी खास दिशा में लगातार असर डाल सकते हैं। राजा को साजिश रचने और सामाजिक दबाव डालने के भी बहुत मौके मिलते हैं, क्योंकि सामाजिक दुनिया में उसीकी तूती बोलती है। असल में शाही दरबारों का सारा वायुमण्डल अधिकारवाद, ऊँच-नीच, पदवियों और वर्गों से भरा रहता है और उससे देशभर के लिए एक खास पैमाना बन जाता है। इस चीज का सामाजिक समानता और वर्ग-नाश से मेल नहीं बैठ सकता। इसमें कोई शक नहीं कि इंग्लैण्ड के शाही दरबार का अंग्रेजों की मनोवृत्ति बनाने और उनको समाज की वर्ग-व्यवस्था से सहमत करने में बड़ा असर पड़ा है। या शायद यह कहना ज्यादा ठीक होगा कि जहाँ दुनिया के सारे बड़े-बड़े देशों में से राजाशाही यानी बादशाहत गायब होगई वहाँ इंग्लैण्ड में वह अब भी बची रह गई है और उसका कारण यही है कि वहाँ लोगों ने ऊँच-नीच वर्ग की व्यवस्था को मंजूर कर रक्खा है। एक पुरानी कहावत है कि “हरेक अंग्रेज को किसी-न-किसी सामन्त से प्रेम है।” इसमें बहुत-कुछ सचाई है। योरप या अमेरिका में, और शायद जापान और भारत के सिवा एशिया में भी, कहीं वर्गभेद इतने तीव्र नहीं हैं जितने इंग्लैण्ड में हैं। यह ताज्जुब की बात है कि जो इंग्लैण्ड पहले राजनैतिक लोकसत्तावाद और उद्योगवाद का नेता रह चुका है वह आज सामाजिक दृष्टि से इतना पिछड़ा हुआ और मौलिक बातों में इतना अनुदार है।

ब्रिटिश पार्लमेण्ट ‘पार्लमेण्टों की जननी’ कहलाती है। उसका जीवन लम्बा और सम्मानपूर्ण रहा है और बहुत-सी बातों में राजा की मनमानी से लड़ने में वह सबसे आगे रही है। उस एकतंत्री शासन की जगह मुट्ठीभर अमीरों की पार्लमेण्ट का राज्य क्रायम हुआ। फिर लोकसत्तावाद की सवारी गाजे-बाजे के साथ आई और बड़ी खींचतान के बाद ज्यादातर लोगों को पार्लमेण्ट की आम सभा के मेम्बर चुनने के लिए राय देने का हक मिला। अमल में इसका नतीजा यह नहीं हुआ कि शासन पर सचमुच लोकसत्तात्मक नियंत्रण क्रायम होगया, बल्कि इतना-सा ही नतीजा निकला कि धनवान कारखानेदारों के हाथ में पार्लमेण्ट की वागडोर आगई। लोक-सत्ता के बजाय धन-सत्ता क्रायम होगई।

ब्रिटिश पार्लमेण्ट में शासन चलाने और क़ानून बनाने का काम-काज करने के लिए एक अजीब प्रणाली पैदा होगई। यह दो दलों की प्रणाली कहलाती है। इन दोनों में कोई खास फ़र्क नहीं था। उनके कोई विरोधी सिद्धान्त न थे। दोनों अमीरों के गिरोह थे और उस वक़्त की सामाजिक व्यवस्था को मानते थे। एक दल में पुराने

जमींदार वर्ग के आदमी ज्यादा थे तो दूसरे में धनी कारखानेदारों की बहुतायत थी। मगर यह तो एक ही चीज के दो नामों वाली बात थी। वे पहले टोरी और विंग कहलाते थे। बाद में उन्नीसवीं सदी में उनका नाम अनुदार और उदार दल पड़ गया। पार्लमेण्ट के भीतर और बाहर वे एक-दूसरे के खिलाफ खूब शोर मचाते थे। मगर यह दोनों की मिली भगत का खेल था। एक दल के हाथ में सत्ता होती तब दूसरा दल विरोधी दल नाम धारण कर लेता। ताज्जुब की बात यह है कि सत्ताधारी दल 'सम्राट् की सरकार' और विरोधी दल 'सम्राट् का विरोधी दल' कहलाता था।

योरप के दूसरे देशों में दूसरी ही बात थी। वहाँ सचमुच अलग-अलग विचार और कार्यक्रम रखनेवाले दल होते थे और उनकी पार्लमेण्ट के भीतर और बाहर खूब गर्मागर्म लड़ाई होती थी। मगर इंग्लैण्ड में तो घर की-सी बात थी, विरोध भी एक प्रकार का सहयोग होगया था, और दोनों दल बारी-बारी से सत्ताधारी और विरोधी बन जाते थे। गरीबों और अमीरों की सच्ची कशमकश और वर्ग-युद्ध पार्लमेण्ट में प्रकट नहीं हुआ, क्योंकि दोनों बड़े-बड़े दल धनवानों के दल थे। न तो जनता के जोश को उभाड़नेवाले कोई मजहबवी सवाल थे और न दूसरे यूरोपियन देशों के-से जातीय या क्लोमी सवाल थे। सदी के पिछले हिस्से में गरमी आई तो वह आयरलैण्ड के राष्ट्रीय सदस्यों की तरफ से आई थी, क्योंकि उनके लिए आयरलैण्ड की आजादी का सवाल राष्ट्रीय सवाल था।

जब इतने बड़े दो दल पार्लमेण्ट के लिए मेम्बर खड़े करें तो आजाद आदमियों या छोटे-छोटे गिरोहों के आदमियों का चुना जाना बहुत मुश्किल होता है। लोक-सत्ता और मताधिकार के होते हुए भी गरीब वोटर को इस मामले में बोलने का कुछ भी हक नहीं होता। वह मानों दोनों में से किसी दल के उम्मीदवार के लिए राय देदे या घर बैठ रहे और राय ही न दे। और दोनों दलों के मेम्बरों को पार्लमेण्ट में कोई आजादी भी नहीं रहती। वे अपने-अपने दल के नेताओं की आज्ञा मानकर राय देने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। इसके बिना वे अपने दल को संगठित और मजबूत नहीं बना सकते और न ताकत हासिल कर सकते हैं। यह संगठन और एकरसता अपनी जगह पर अच्छी चीज है, मगर इसे लोकसत्ता नहीं कह सकते।

हम देखते हैं कि इंग्लैण्ड को अक्सर लोकसत्ता की उत्पत्ति का नमूना बताया जाता है, मगर वहाँ भी लोकमत को बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं मिली। शासन का बड़ा सवाल यह होता है कि जनता अपने ऊपर शासन करने के लिए अच्छे-से-अच्छे आदमी कैसे चुने ? यह सवाल वहाँ भी संतोषजनक रूप में हल नहीं हुआ। अमल

में लोकसत्ता का यह अर्थ होता है कि लोग जोरदार व्याख्यानबाजी करें और गरीब वोटर या मतदाता ऐसे आदमियों को चुन दें जिनके बारे में वे कुछ भी नहीं जानते। आम चुनावों को खुला नीलाम कहा गया है, जहाँ तरह-तरह के वादे किये जाते हैं। मगर इन सब खामियों के होते हुए भी यह झूठी या नकली लोकसत्ता चलती रही, क्योंकि इंग्लैण्ड खुशहाल था और इस खुशहाली के कारण वहाँकी व्यवस्था नहीं टूटती थी और लोगों में एक हद तक सन्तोष रहता था।

उन्नीसवीं सदी के पिछले आधे हिस्से में इंग्लैण्ड के राजनैतिक दलों के दो बड़े नेता डिज़रैली और ग्लैडस्टन थे। डिज़रैली आगे चलकर वीकंसफील्ड का अर्ल बना दिया गया था। वह अनुदार दल का नेता था और कितनी ही बार प्रधानमंत्री बना। यह उसके लिए बड़ी कामयाबी की बात थी, क्योंकि वह यहूदी था और उसके कोई बड़े ताल्लुक़ात भी नहीं थे और यहूदियों को अंग्रेज़ लोग पसन्द भी नहीं करते। लेकिन सिर्फ़ अपनी योग्यता और लगन के जोर पर उसने अपने विरोध पर फ़तह हासिल की और वह रास्ता चोरकर आगे आगया। वह बड़ा साम्राज्यवादी था, उसीने विक्टोरिया को 'कैसरे हिन्द' बनाया। ग्लैडस्टन एक पुराने अंग्रेज़ धनी घराने का आदमी था, वह उदारदल का नेता बन गया और वह भी कई बार प्रधानमंत्री हुआ। जहाँतक साम्राज्यवाद और विदेशी नीति का ताल्लुक़ था वहाँतक ग्लैडस्टन और डिज़रैली में कोई मौलिक अन्तर नहीं था। मगर डिज़रैली अपने साम्राज्यवाद की बात साफ़-साफ़ कहता था और ग्लैडस्टन पूरा अंग्रेज़ था। वह असलियत को मीठी बातों और मजहब की दुहाइयों में छिपा लेता था। वह ऐसा प्रकट करता था, गोया जो कुछ वह करता था उसमें परमात्मा की ख़ास तौर पर सलाह रहती हो। बालकन देशों में तुर्कों के जुल्मों के खिलाफ़ उसने बड़ा आन्दोलन मचवाया और डिज़रैली ने उसके विरोध में तुर्कों का पक्ष लिया। असल में दोष तुर्कों और उनकी कई बालकन जातियों की रियाया इन दोनों का था। वे बारी-बारी से एक-दूसरे पर भयंकर हत्याकाण्ड और अत्याचार करते थे।

ग्लैडस्टन ने आयर्लैण्ड के लिए होमरूल (स्वराज्य) का भी समर्थन किया। उसे कामयाबी नहीं मिली और अंग्रेज़ों ने इतनी मुख़ालफ़त की कि ख़ुद उदारदल के दो टुकड़े हो गये और एक हिस्सा अनुदार दल में जा मिला। इन्हें अब यूनियनिस्ट कहते हैं, क्योंकि ये आयर्लैण्ड के साथ मेल बनाये रखना चाहते हैं।

मगर इस बारे में और विक्टोरिया-युग की दूसरी बातों के बारे में तो अब अगले ख़त में ही ज्यादा बातें लिखूंगा।

संसार का साहूकार इंग्लैण्ड

२३ फरवरी, १९३३

उन्नीसवीं सदी में इंग्लैण्ड जो इतना सम्पन्न हुआ उसका कारण उसके उद्योग-धंधे और उपनिवेशों और मातहत देशों का शोषण था। उसकी बढ़ती हुई दीलत का आधार चार उद्योग थे। इन्हें प्रधान उद्योग कह सकते हैं। ये रई, कोयला, लोहा और जहाज-साजी थे। इनके साथ-साथ और इनसे अलग भी वेशुमार छोटे-बड़े दूसरे उद्योग खड़े होगये। बड़े-बड़े व्यवसाय-भवन और साहूकारी कोठियाँ बन गईं। अंग्रेजों के व्यापारी जहाज दुनिया के हर हिस्से में पाये जाने लगे। वे ब्रिटिश माल ही नहीं ले जाते थे, बल्कि दूसरे उद्योग-प्रधान देशों का माल भी ले जाते थे। ये जहाज संसार के व्यापार की सामग्री को लेजाने के मुख्य साधन बन गये। लन्दन में लॉयड का बीमे का बड़ा दफ्तर संसार के समुद्री व्यापार का मुख्य केन्द्र बन गया। पार्लमेण्ट पर इन उद्योगों और व्यवसायों के मालिकों का नियंत्रण था।

देश में धन की बाढ़ आगई और ऊँचे और मध्यमवर्ग के लोग मालामाल होते चले गये। इस धन का कुछ हिस्सा मजदूरों को भी मिला और उनका रहन-सहन भी ऊँचा होगया। धनवानों को जो इतना सारा धन मिला था उसका वे क्या करते? उसे पड़ा रखना तो बेवकूफी होती। इसलिए हर कोई उद्योग-धंधों को उत्तेजन देने और ज्यादा-ज्यादा माल पैदा करके ज्यादा-से-ज्यादा मुनाफ़ा करने लगा। इस धन के अधिकांश भाग से इंग्लैण्ड और स्कॉटलैण्ड में नये-नये कारखाने, रेलें और दूसरे ऐसे ही धंधे जारी किये गये। थोड़े असें बाद जब कारखानों की तादाद बहुत बढ़ गई और देश में उद्योग-धंधों का पूरा जाल बिछ गया, तो नफ़े की दर घटना स्वाभाविक था, क्योंकि साथ-साथ स्पर्धा यानी लाग-डाँट भी बढ़ गई थी। तब पूँजीपतियों ने पूँजी लगाने को अधिक लाभदायक क्षेत्रों के लिए विदेशों में आँखें फैलाई और उन्हें साधन भी बहुतायत से मिल गये। दुनियाभर में रेल, तार और कारखाने बन रहे थे। योरप, अमेरिका, अफ़रीका और ब्रिटिश-राज्य के मातहत देशों में ऐसे बहुतसे कामों में ब्रिटेन की फ़ालतू पूँजी ख़ूब लगी। अमेरिका के संयुक्त राज्यों के पास प्राकृतिक धन की कमी नहीं थी, मगर वे तेज़ी से तरक्की कर रहे थे, इस कारण उनकी रेलों वगैरा में बहुत-सी ब्रिटिश पूँजी खप गई। दक्षिण अमेरिका में, और वहाँ भी खासकर अर्जेण्टाइन में, अंग्रेजों ने बड़े-बड़े व्यापारी बगीचे लगा लिये। कनाडा और आस्ट्रेलिया की तो रचना ही ब्रिटिश रूपये से हुई। चीन में रियायतों की जो लड़ाई हुई उसका कुछ हाल में

वता चुका हूँ । और हिन्दुस्तान पर तो अंग्रेजों का कब्जा ही था । यहाँ उसने रेलों और दूसरों कामों के लिए अपनी मनमानी शर्तों पर क़र्ज़ दिया ।

इस तरह इंग्लैण्ड संसार का साहूकार बन गया और लन्दन दुनिया का सराफ़ा यानी पूँजी का बाज़ार होगया । मगर इसका यह अर्थ न समझ लेना कि जब रुपया भेजा जाता था तो कोई सोने, चाँदी या सिक्कों की बोरियाँ भर-भरकर इंग्लैण्ड से दूसरे मुल्कों की जाती थीं । आजकल व्यापार इस तरीक़े से नहीं होता । ऐसा हो तो काफ़ी सोना-चाँदी घूमने-फिरने को कहाँसे आये ? बेवकूफ़ लोग सोने-चाँदी को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, मगर वे तो विनिमय के साधन मात्र हैं और माल को इधर-उधर पहुँचाने के काम आते हैं । इन्हें न कोई खा-पहन सकता है और न इनसे और कुछ काम निकल सकता है । इनके जेवर अलबत्ता बन सकते हैं, मगर उनसे किसीको कोई फ़ायदा नहीं । सच्चा धन तो ऐसे माल का हाथ में होना है जो किसी काम आ सके । इस तरह ब्रिटिश पूँजीपतियों के रुपया उधार देने का अर्थ यह हुआ कि वे विदेशी कारख़ानों या रेलों में एक रक़म लगाते थे, मगर नक़द रुपया न भेजकर उसके बराबर की क़ीमत का अंग्रेज़ी माल देते थे । इस तरह ब्रिटिश मशीनों और रेलों का सामान दूसरे देशों को भेजा जाता था । इससे ब्रिटिश उद्योग-धंधों को मदद मिलती थी और साथ ही साथ ब्रिटिश पूँजीपतियों को अपनी फ़ालतू पूँजी बढ़िया मुनाफ़े के कामों में लगाने के साधन मिलते थे ।

साहूकारी मुनाफ़े का धन्धा है और इंग्लैण्ड ने जितना ही इसे अपनाया उतना ही वह मालदार हुआ । इससे एक बड़ा निठल्ला वर्ग पैदा होगया । वह केवल व्यवसाय के मुनाफ़े और हिस्से पर गुज़र करने लगा । इन लोगों को किसी चीज़ को बनाने या पैदा करने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती थी । उनके किसी रेलवे-कम्पनी, चाय के बगीचे या किसी और व्यापार में हिस्से होते थे और उनका मुनाफ़ा उनके पास वक़्त पर पहुँच जाता था । इन निठल्ले अंग्रेज़ों की फ़्रेञ्च रिवीरा, इटली और स्वीज़रलैण्ड जैसी अच्छी-अच्छी जगहों में बस्तियाँ बस गई । हाँ, इनमें से ज्यादातर लोग तो इंग्लैण्ड में ही रहे ।

जिन देशों ने इस तरह इंग्लैण्ड से क़र्ज़ लिया था वे सब व्याज या मुनाफ़ा किस तरह चुकाते थे ? यह भी वे सोना-चाँदी की शक्ल में नहीं भेज सकते थे । उनके पास ये पदार्थ साल-दर-साल देने को काफ़ी थे भी नहीं । इसलिए वे माल की शक्ल में अदा करते थे । पक्का माल तो इतना नहीं देते थे, क्योंकि खुद इंग्लैण्ड पक्का माल पैदा करनेवाले देशों में मुखिया था । मगर वे खाद्य पदार्थ और कच्चा माल भेजते थे । उनके यहाँ से इंग्लैण्ड की ओर गेहूँ, चाय, क़हवा, मांस, फल, शराब, रूई और ऊन वग़ैरा की अटूट धारा बहती थी ।

दो देशों के व्यापार का अर्थ है चीजों का तबादला । यह मुमकिन नहीं कि एक खरीदता ही रहे और दूसरा बेचता ही चला जाय । ऐसा कोई करने लगे तो चुकारा सोना या चांदी के रूप ही में करना पड़ेगा और वहाँ थोड़े ही समय में सोना चांदी खतम होजायगा या फिर एकतर्फी व्यापार अपनेआप बन्द होजायगा । परस्पर व्यवसाय में लेन-देन दोनों होते हैं और वे घटते-बढ़ते रहते हैं । कभी कोई देश बेचता अधिक है तो कोई खरीद ज्यादा लेता है । अगर हम उन्नीसवीं सदी के इंग्लैण्ड के व्यापार की जांच करें तो मालूम होगा कि सारी बातों को देखते हुए इंग्लैण्ड से जितना माल बाहर गया उससे ज्यादा माल उसके यहाँ आया । यानी, हालांकि उसने भारी निर्यात में माल बाहर भेजा, ताहम उसने उससे ज्यादा कीमत का माल मंगाया । फ़र्क इतना ही था कि उसने भेजा पक्का माल और मंगाया ज्यादातर फच्चा माल और ख़ाद्य पदार्थ । इस तरह जाहिरा तौर पर तो उसने ख़रीदा ज्यादा और बेचा कम, और यह व्यापार करने का कोई अच्छा तरीका मालूम नहीं होता । मगर असल बात यह थी कि उसके आयात की अधिकता उसके उधार दिये हुए रुपये का मुनाफ़ा ही थी । यह वह नज़राना या कर था जो क़र्ज़दार देश या हिन्दुस्तान-जैसे मातहत मुल्क उसे भेजते थे ।

लगी हुई सारी पूंजी का मुनाफ़ा इंग्लैण्ड में ही नहीं पहुँच जाता था । उसका बहुत-सा हिस्सा क़र्ज़दार देश में रह जाता था और उसे ब्रिटिश पूंजीपति फिर वहीं लगा देते थे । इस तरह, बिना नई पूंजी लगाये या इंग्लैण्ड से माल भेजे हुए, विदेशों में लगी हुई अंग्रेज़ों की पूंजी की रक़म बढ़ती जाती थी । हिन्दुस्तान में हमें बार-बार याद दिलाया जाता है कि रेलों, नहरों और बहुत-से दूसरे कामों में अंग्रेज़ों का बेशुमार रुपया लगा हुआ है और इस हिसाब से हिन्दुस्तान पर इंग्लैण्ड का बड़ा भारी क़र्ज़ा बत़ाया जाता है । हिन्दुस्तानियों को इसपर कई तरह का एतराज़ है, परन्तु यहाँ उस बात की चर्चा करने की ज़रूरत नहीं । हाँ, इतना ध्यान में रखना चाहिए कि लगी हुई पूंजी की इस भारी रक़म में इंग्लैण्ड से आया हुआ नया रुपया बहुत नहीं है । यह तो हिन्दुस्तान में कमाया हुआ मुनाफ़ा यहीं फिरसे लगाया हुआ है । मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि प्लासी और क़लाइव के समय में सचमुच अंग्रेज़ हिन्दुस्तान से बहुत-सा सोना और खज़ाना इंग्लैण्ड ले गये थे । उसके बाद हिन्दुस्तान के शोषण का तरीका दूसरा होगया और इतना खुला नहीं रहा और मुनाफ़े का कुछ हिस्सा इसी देश में व्यवसाय में फिर लगा दिया गया ।

इंग्लैण्ड ने देख लिया कि साहूकारी का संसार-व्यापी धन्धा चलाने का सिर्फ़ यही उपाय सम्भव है कि माल के रूप में ब्याज लेना मंज़ूर किया जाय । मैं तुम्हें

ऊपर बता चुका हूँ कि सोना ही लेने की जिद नहीं रखी जा सकती थी। इसके दो बड़े नतीजे हुए। एक तो इंग्लैण्ड ने अपने लोगों के खाने के लिए बाहर से खाद्य-पदार्थ आने दिये और अपनी खेती को बिगाड़ लिया। उसने बाहर बेचने के लिए कारखानों में पक्का माल तैयार करने पर सारा जोर लगा दिया और अपने किसानों की हालत पर ध्यान नहीं दिया। अगर बाहर से खाने की चीजें सस्ती मिल जायें तो घर में पैदा करने की इच्छा क्यों की जाय ? और अगर कारखानों से ज्यादा लाभ हो सके तो खेती करने की तकलीफ़ क्यों गवारा की जाय ? इस तरह इंग्लैण्ड निरा उद्योग-प्रधान देश बन गया और खाने के लिए विदेशों पर निर्भर रहने लगा।

दूसरा नतीजा यह हुआ कि उसने मुक्त-व्यापार (Free Trade) की नीति इस्तिथार करली, यानी उसके बन्दरगाहों पर दूसरे देशों से आकर जो माल उतरता था उसपर वह या तो कर लगाता ही न था या बहुत कम लगाता था। चूँकि वह मुख्य औद्योगिक देश था, इसलिए पक्के माल के मामले में उसे बहुत वक़्त तक स्पर्धा या लाग-डाँट का डर नहीं था। विदेशी माल पर महसूल लगाने का मतलब होता विदेशों से आनेवाली अपनी ख़ूराक और कच्चे माल पर महसूल लगाना। इससे जनता के भोजन का दाम बढ़ता और अपने ही पक्के माल की कीमत भी बढ़ती। इसके सिवा, अगर भारी टैक्स लगाकर वह विदेशी माल को अपने यहाँ आने से रोक देता तो विदेशी क़र्ज़दार अपना क़र्ज़ इंग्लैण्ड को कैसे चुकाते ? वे तो माल देकर ही क़र्ज़ चुका सकते थे। यही कारण था कि जहाँ दूसरे सब उद्योग-प्रधान देश संरक्षण-करों के तरफ़दार (Protectionist) थे, यानी वे विदेशी माल पर टैक्स लगाकर अपने बढ़ते हुए उद्योग-धंधों की रक्षा कर रहे थे, वहाँ इंग्लैण्ड ने मुक्त-व्यापार की नीति ग्रहण कर रखी थी। संयुक्तराज्य, फ़्रांस, जर्मनी सब संरक्षणवादी थे।

मुक्त-व्यापार और संरक्षणवाद का सवाल हर मुक़्त में पैदा हो चुका है और उसपर गर्मागर्म बहस हुई है। आज तो असल में सारी दुनिया के सामने यह सवाल है। इंग्लैण्ड के दोनों बड़े दलों में असें तक मतभेद का यही मुख्य विषय रहा। उदार-दल वाले मुक्त व्यापार के तरफ़दार थे। शायद इस सवाल का ऐसा जवाब नहीं दिया जा सकता जो हर हालत में लागू हो सके। मैं तुम्हें याद दिलाऊँ कि जब अंग्रेज़ लोग यहाँ आये ही आये थे तब उन्होंने हिन्दुस्तानी कपड़े को इंग्लैण्ड में न घुसने देने के लिए उसपर भारी चुंगी लगाई थी। उस वक़्त इंग्लैण्ड संरक्षणवादी था, क्योंकि इसीमें उसे सहूलियत थी। बाद में मुक्त या खुला व्यापार उसके अनुकूल पड़ने लगा तो वह उसका तरफ़दार होगया। और अब कुछ महीनों से वह फिर संरक्षण-वादी देश बन गया

हैं और उसने विदेशी माल पर भारी चुंगी लगा दी है। मगर अब वह दुनिया का साहूकार नहीं रहा।

उन्नीसवीं सदी में अंग्रेजों ने खेती की उपेक्षा करने, उद्योग-धंधों पर सारा जोर लगाने, खाने को बाहर से मंगा लेने और बाहर के मुनाफ़े पर मीज करने की जो नीति रखी, वह उस वक़्त तो फ़ायदेमन्द और सुहावनी लगी, मगर उसमें ख़तरा तो था ही और वह अब सामने आ रहा है, उस नीति का आधार इंग्लैंड का उद्योग-धंधों में हावी होना और उसका ज़बरदस्त विदेशी व्यापार था। लेकिन यह प्रधानता न रहे और साथ-साथ विदेशी व्यापार भी बरबाद होने लगे तो ? उस हालत में वह खाने का दाम कैसे चुकाये ? और अगर चुका भी दिया तो किसी ज़बरदस्त दुश्मन के रास्ता रोक लेने की हालत में वह ख़ूराक उसे बाहर से मिल ही कैसे पायेगी ? पिछले महायुद्ध में वहाँके लोगों को आधा भूखा रहना पड़ा था, क्योंकि खाद्य पदार्थों के आने के जरिये क़रीब-क़रीब कट गये थे। इससे भी बड़ा ख़तरा यह है कि विदेशी स्पर्धा की वजह से उसका विदेशी व्यापार दिन-दिन गिरता जा रहा है। यह स्पर्धा उन्नीसवीं सदी के आख़री बीस सालों में ज्यादा स्पष्ट होगई है, क्योंकि तभीसे अमेरिका और जर्मनी भी विदेशी बाज़ार ढूँढ़ने लगे हैं। धीरे-धीरे दूसरे देश भी उद्योग-प्रधान बन गये और इस तलाश में शरीक होगये; और अब तो क़रीब-क़रीब सारा संसार किसी-न-किसी हद तक उद्योगवादी हो चला है। हर देश अपनी ज़रूरत का माल ज्यादा-से-ज्यादा खुद तैयार करके विदेशी माल को अपने यहाँ नहीं आने देना चाहता। हिन्दुस्तान विदेशी कपड़े की आमद रोकना चाहता है। तब लंकाशायर और विदेशी व्यापार पर निर्भर रहनेवाले दूसरे ब्रिटिश उद्योग क्या करें ?

इन सवालों का जवाब देना इंग्लैंड के लिए मुश्किल है और उसके बुरे दिन भी आते दिखाई दे रहे हैं। वह कछुआ बनकर कोने में नहीं बैठ सकता और न अपनी ख़ूराक और दूसरी ज़रूरियात पैदा करके स्वावलम्बी जिन्दगी ही बिता सकता है। आजकल की परस्पर गुंथी हुई दुनिया में यह मुमकिन ही नहीं। और अगर वह अपनेको सबसे अलग-थलग कर भी ले तो इसमें सन्देह ही है कि वह अपनी बहुत ज्यादा आबादी के लिए काफ़ी खाद्य-सामग्री पैदा कर सकेगा। लेकिन ये सवाल आज के हैं; उन्नीसवीं सदी में इनका बहुत थोड़ा महत्व था। इसलिए इंग्लैंड ने अपने भविष्य की बाज़ी लगाई, और इस उम्मीद पर कि उसकी प्रधानता बनी रहेगी, सब-कुछ दाँव पर धर दिया। बाज़ी बड़ी थी और जोखिम भारी था—यानी या तो संसार का मुखिया राष्ट्र बनकर रहने या ख़त्म हो जाने का सवाल था। कोई बीच का रास्ता नहीं था। लेकिन विक्टोरिया-युग के मध्यमवर्ग के अंग्रेज़ में न तो आत्मविश्वास

की कमी थी और न झूठे घमण्ड की। उसे मुद्दत से जो खुशहाली, कामयाबी और व्यवसाय एवं उद्योग में अगुआपन हासिल था उसके कारण उसे यक्रीन होगया था कि वह दुनिया के दूसरे इनसानों से ऊँचे दर्जे का प्राणी है। वह सब विदेशियों को नाचीज समझने लगा। एशिया और अफ्रीका के लोग तो पिछड़े हुए और जंगली थे ही। वे तो इसीलिए पैदा हुए मालूम होते थे कि पिछड़ी हुई जातियों पर हुकूमत करने और उन्हें सुधारने के लिए अंग्रेजों को अपनी जन्मजात प्रतिभा का प्रयोग करने का मौका मिले। योरप के दूसरे देश भी अज्ञानी और अंधविश्वासी थे। उनमें से अंग्रेजी जवान ही बहुत थोड़े लोग जानते थे। सभ्यता की चोटी पर बैठे हुए खास लोग तो अंग्रेज ही थे। योरप बाक़ी की सारी दुनिया का सिरमौर था और इंग्लैण्ड योरप का नेता बनकर आगे बढ़ रहा था। ब्रिटिश साम्राज्य एक तरह की दैवी वस्तु थी और इसने ब्रिटिश जाति की महानता पर मुहर लगा दी थी। लॉर्ड कर्जन तीस वर्ष पहले भारत का वायसराय था और अपने समय का एक निहायत क्राबिल अंग्रेज था। उसने अपनी एक किताब उन लोगों को समर्पण की थी, “जो यह मानते हों कि ब्रिटिश साम्राज्य भगवान की इच्छा से कायम है और आजतक संसार में इससे ज्यादा भलाई करनेवाली कोई चीज़ पैदा नहीं हुई।”

में विक्टोरिया-युग के अंग्रेज के बारे में इतना सब जो लिख रहा हूँ उसमें कुछ ज्यादाती और असाधारणता दिखाई देती है और शायद तुम यह भी सोचने लगो कि मैं उसका मज़ाक़ उड़ा रहा हूँ। यह ताज्जुब की बात है कि कोई भी समझदार आदमी इस तरह का बर्ताव करे और इस तरह का अजीब, घमंड-भरा और अपने मुँह मियाँ-मिट्ठूपन का हल्ला इस्तिहार करे। लेकिन राष्ट्र-समूहों के मिथ्याभिमान को सन्तोष मिलता हो और उनका फ़ायदा भी होता हो तो वे किसी भी तरह की बात पर यक्रीन कर लेते हैं। व्यक्तियों को अपने पड़ोसियों के प्रति ऐसा भद्दा और गँवारू बर्ताव करने का कभी खयाल भी नहीं आता, मगर राष्ट्रों को ऐसी आत्म-ग्लानि नहीं हुआ करती। बदकिस्मती से हम सब एक ही थैली के चट्टे-बट्टे हैं और अपने-अपने राष्ट्रीय गुणों की शेखी बघारते फिरते हैं। थोड़े-से फ़र्क़ के साथ विक्टोरिया-युग के अंग्रेज का नमूना अक्सर सभी जगह मिलता है। सारे यूरोपियन राष्ट्रों के ऐसे ही नमूने हो चुके हैं। जर्मनी का नमूना तो बीस वर्ष पहले खास तौर पर जोर-जबदस्ती से भरा हुआ था। अमेरिका और एशिया में भी ऐसा ही हुआ है।

इंग्लैण्ड और पश्चिमी योरप की खुशहाली की वजह उद्योगवाद और पूँजीवाद की तरक्की थी। यह पूँजीवाद मुनाफे की लगातार खोज में सरपट दौड़ रहा था। सफलता और लाभ ही वहाँके लोगों के आराध्यदेव बन गये थे, क्योंकि पूँजीवाद

में धर्म या सदाचार से क्या वास्ता ? उसूल यह होगया कि जो व्यक्ति और राष्ट्र भयंकर स्पर्धा यानी जबरदस्त लाग-डॉट में आगे निकल जाय वह बाजी मार लेजाय, और जो पीछे रह जाय धूँ जाय जहन्नुम में ! विक्टोरिया-युग के लोगों को अपनी धार्मिक सहिष्णुता पर घमण्ड था । उनका प्रगति और विज्ञान में विश्वास था और उनके व्यापार और साम्राज्य की कामयाबी ने ही यह साबित कर दिया था कि वे एक खास तरह और ऊँचे दर्जे के इन्सान थे और इसीलिए जिन्दगी की लड़ाई में वे बच रहे थे । क्या डार्विन ऐसा नहीं कह गया था ? असल में धर्म के प्रति उनकी सहनशीलता नहीं थी, उदासीनता थी । आर. एच. टॉनी नाम के अंग्रेज लेखक ने इस स्थिति का अच्छा बयान किया है । वह कहता है कि दुनियावी मामलात से अलग करके ईश्वर को अपनी जगह पर बिठा दिया गया था । “जैसी जमीन पर नियंत्रित राजाशाही थी वैसी ही स्वर्ग में भी क़ायम करदी गई !” अमीरों का तो यह खयाल था, मगर गरीबों को गिरजाघर जाने और धर्म को मानने का इस आशा से उत्साह दिलाया जाता था कि इससे शायद उनमें क्रान्तिकारी विचार पैदा न हो पायेंगे । धार्मिक सहिष्णुता का मतलब यह नहीं था कि और मामलों में भी वर्दाश्त से काम लिया जाता हो । जिन बातों को ज्यादातर लोग महत्व देते थे उनमें ज़रा भी सहनशीलता नहीं थी, ज़रा खिंचाव हुआ कि सहनशीलता काफ़ूर ! हिन्दुस्तान में भी अंग्रेज़ी सरकार धर्म के मामलों में निहायत सहनशील है और इसे अपना एक खास सद्गुण बताती है । मगर उसकी राजनीति और उससे ताल्लुक रखनेवाली किसी बात की ज़रा भी टीका करो तो फौरन उसके कान खड़े होजाते हैं । उस वक़्त उसकी सहनशीलता की कोई शिकायत नहीं की जा सकती ! उसपर जितना ज्यादा जोर डालो, वह उतनी ही नीचे उतर आयगी; और अगर जोर काफ़ी पड़ जाय तो फिर सरकार सहनशीलता का बुर्फ़ा उतारकर खुले और शर्मनाक ढंग से आतंकवाद का आश्रय लेती है । हिन्दुस्तान में हम आज यही देख रहे हैं । थोड़े दिन हुए, मैंने अख़बार में पढ़ा था कि कुछ अंग्रेज़ कर्मचारियों को धमकी के तहत लिखने के जुर्म में एक निमूँछिये छोकरे को ८ साल सख़्त क़ैद की सज़ा दी गई है !

पूँजीवादी उद्योग के बढ़ने से कई तब्दीलिया हुई । पूँजीवाद के काम का विस्तार बढ़ता ही गया । छोटे-छोटे व्यवसाय और कारख़ानों की वनिस्वत बड़े पैमाने पर व्यवसाय और कारख़ाने चलते भी अच्छे और उनसे मुनाफ़ा भी ज्यादा होता था । इसलिए बहुत बड़ी-बड़ी कम्पनियाँ बनने लगीं और उन्होंने उद्योग-पर-उद्योग हाथ में लेलिये और छोटे-छोटे स्वतंत्र उत्पादकों और कारख़ानों को हड़प कर लिया । व्यक्तियों के लिए स्वतंत्ररूप से कुछ कर सकने का मौक़ा बहुत कम रह गया, इसलिए

जैसा हो वैसा होने देने (लेसे फ़ेयर) के पुराने खयालात इस नई स्थिति के सामने टिक नहीं सके। ये जबरदस्त कम्पनियाँ और व्यापार-संघ सरकारों पर भी हावी होगये।

पूँजीवाद के कारण साम्राज्य का एक और भी खौफ़नाक रूप पैदा हुआ। उन्नीसवीं सदी के पिछले आधे हिस्से में जो देश उद्योग-धंधों में बहुत आगे बढ़ गये थे उनमें जैसे-जैसे आपसी लाग-डाँट बढ़ी, वैसे-वैसे वे बाजारों और कच्चे माल की तलाश में और भी दूर-दूर देशों की तरफ़ आँखें फाड़ने लगे। दुनियाभर में साम्राज्य के लिए भयंकर छीना-झपटी शुरू हुई। एशिया में यानी हिन्दुस्तान, चीन, बृहत्तर भारत और ईरान में जो कुछ हुआ उसका हाल ज़रा विस्तार के साथ तुम्हें बता चुका हूँ। अब योरोप की क़ौमों गिद्धों की तरह अफ़रीका पर दूट पड़ों और उसे आपस में बाँट लिया। यहाँ भी इंग्लैण्ड ने सबसे बड़ा हिस्सा लेलिया। उत्तर में मिस्र और पूर्व, पश्चिम व दक्षिण में बड़े-बड़े प्रदेश उसके हाथ लगे। फ़्रांस भी मज़े में रहा। इटली इस लूट के माल में से हिस्सा चाहता था, लेकिन एवीसीनिया के मुकाबिले में उसे बुरी तरह मुंह की खानी पड़ी। इससे सभीको बड़ा आश्चर्य हुआ। जर्मनी को हिस्सा मिला, मगर उससे सन्तोष नहीं हुआ। सब जगह साम्राज्यवाद की धूम थी। वह चीखता, धमकाता और इधर-उधर हाथ-पैर पीटता था। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के लोकप्रिय कवि रुडयार्ड किप्लिंग ने 'ग़ोरो के भार' (Whiteman's burden) का गीत बनाया। फ़्रांसवाले अपने सभ्यता-प्रचार के पवित्र ध्येय की बातें करने लगे। जर्मनी को अपनी संस्कृति फैलाना ही था। इस तरह ये सभ्यता के प्रचारक दूसरों की हालत सुधारने और उनका बोझा ओढ़ने की पूरी त्याग-भावना के साथ घर से निकले और भूरे, पीले और काले लोगों की गर्दनो पर सवार होगये। मगर कालों के बोझ का गीत कौन गाता ?

एक-दूसरे से लड़नेवाले ये साम्राज्यवाद इस बुरी तरह पैर फैलाते जा रहे थे कि पृथ्वी इनके लिए छोटी पड़ गई। बाजारों की भूख इनमें से हरेक देश को आगे-से-आगे धकेल रही थी और इनकी आपस में ही अक्सर भिड़न्त हो जाती थी। इंग्लैण्ड और फ़्रांस में लड़ाई होते-होते बच गई। मगर हितों में सच्ची कशमकश तो अंग्रेज़ी और जर्मन उद्योग के बीच पैदा हुई। जर्मनी उद्योग और जहाज़ों के व्यवसाय में इंग्लैण्ड के बराबर होगया और हर बाज़ार में उसका मुक़ाबिला करने लगा। लेकिन उसने देखा कि सरज़मीन के अच्छे हिस्सों पर पहले ही इंग्लैण्ड का क़ब्ज़ा हो चुका है। वह बड़ा घमण्डी और उच्चाकांक्षी देश ठहरा, इस तरह दूसरे राष्ट्र उसे पीछे पड़ा रखें, यह बात उसे दुरी तरह खटकती थी। इसलिए उनके साथ एक जबरदस्त लड़ाई करने के लिए वह जोरों से तैयारी करने लगा। सारे योरोप में तैयारियाँ शुरू होगईं और जल और स्थल सेनायें बढ़ने लगीं। अलग-अलग देशों में गुटबन्दी हुई। अख़ीर में दो

हथियारों से सजे हुए, दल आमने-सामने खड़े नज़र आने लगे। एक तरफ़ जर्मनी, आस्ट्रिया और इटली की त्रिपुटी थी और दूसरी तरफ़ रूस और फ़्रांस की दोस्ती। इंग्लैण्ड भी छिपे तौर पर इस दोस्ती में शामिल था।

इसी बीच में उन्नीसवीं सदी के अख़ीर में इंग्लैण्ड को दक्षिण अफ़्रीका में एक छोटी-सी ख़ानगी लड़ाई लड़नी पड़ी। ट्रांसवाल के बोअर प्रजातंत्र में सोने की खानें निकल आईं और इसी कारण १८९९ ई० में यह लड़ाई हुई। बोअर लोग योरप के प्रमुख राष्ट्र के खिलाफ़ तीन साल तक ज़बरदस्त साहस और धैर्य के साथ लड़े। उन्हें कुचल दिया गया और उन्हें हार माननी पड़ी। मगर थोड़े दिनों बाद अंग्रेज़ों ने एक अक्लमन्दी और उदारता का काम किया और थोड़े ही समय पहले के दुश्मनों को पूरी आज़ादी दे दी। उस समय उदार दल के हाथ में सत्ता थी। कुछ समय बाद सारा दक्षिण अफ़्रीका ब्रिटिश साम्राज्य का स्वतंत्र उपनिवेश बन गया।

: १३७ :

अमेरिका का गृह-युद्ध

२७ फ़रवरी, १९३३

हमारा बहुत ज्यादा समय पुरानी दुनिया के झगड़ों और षड़यंत्रों ने, राजाओं और क्रान्तियों ने, घृणा और राष्ट्रीयता के भावों ने ले लिया। अब ज़रा अटलाण्टिक महासागर पार करके अमेरिका की नई दुनिया में चलकर देखें कि योरप के पंजे से छूटने के बाद इसका क्या हाल रहा। संयुक्तराज्यों पर हमें खास तौर से ध्यान देने की ज़रूरत है। छोटी-सी शुरुआत करके ये इतने आगे बढ़ गये हैं कि आज संसार की परिस्थिति पर इनका बहुत ज्यादा असर है। इंग्लैण्ड की स्थिति अब सबसे बढ़कर नहीं रही। वह संसार का साहूकार नहीं रहा, योरप के दूसरे देशों की तरह वह भी एक कर्जदार मुल्क है। उसे संयुक्तराज्यों से कृपा और उदारता की भीख माँगनी पड़ती है। साहूकारी की पगड़ी अब अमेरिका के सिर बँध गई है, धन का दरिया अब उसके यहाँ जाकर गिरता है; और करोड़पति पैदा करने की उसकी ताक़त पर तो सबको ताज़्जुब होता है। परन्तु पुरानी दन्तकथा के मीडास' की तरह सोने से उसे बहुत सुख नहीं मिल गया। वहाँ बेशुमार करोड़पतियों के होते हुए भी आम जनता आज भी ग़रीबी और मुसीबत में पड़ी हुई है।

१. फ़ीजिया का एक काल्पनिक राजा, जिसमें यह शक्ति थी कि जिस चीज़ को वह छूता वही सोने की होजाती।

समुद्रतट के जिन तेरह राज्यों ने १७७५ ई० में इंग्लैण्ड से सम्बन्ध तोड़ लिया था उनकी आबादी ४० लाख से कम ही थी। आज अकेले न्यूयार्क शहर की आबादी उससे करीब दुगुनी है और सारे संयुक्तराज्यों की साढ़े बारह करोड़ है। इस संघ में अब पहले से बहुत ज्यादा राज्य हैं और वे इस महाद्वीप के एक छोर से दूसरे छोर प्रशान्त महासागर तक फैले हुए हैं। उन्नीसवीं सदी में इस महान् देश का क्षेत्रफल यानी रकबा और आबादी ही नहीं बढ़ी, बल्कि इसके आधुनिक उद्योग और व्यापार, धन और प्रभाव में भी वृद्धि हुई। इन राज्यों को बहुत-सी दिक्कतों और तकलीफों का सामना करना पड़ा और इनके साथ योरोप वालों के युद्ध और झगड़े-टण्टे भी हुए, लेकिन इनपर सबसे बड़ी मुसीबत यह आई कि उत्तर और दक्षिण के राज्यों में जबरदस्त और तबाह करनेवाली घरेलू लड़ाई हुई।

अमेरिका के आजाद होने के चन्द साल बाद फ्रांस की राज्यक्रान्ति हुई और उसके पीछे-पीछे नेपोलियन की लड़ाई हुई। नेपोलियन और इंग्लैण्ड दोनों एक-दूसरे के व्यापार को चौपट कर देना चाहते थे और इस कोशिश में उनकी संयुक्तराज्यों से भी मुठभेड़ होगई। अमेरिका का समुद्री व्यापार बिल्कुल रुक गया और इसलिए १८१२ ई० में उसकी इंग्लैण्ड के साथ दूसरी लड़ाई छिड़ गई। इन दो वर्ष के झगड़े का कोई खास नतीजा नहीं निकला। इस लड़ाई के सिलसिले में जब नेपोलियन एल्बा में ठिकाने लगा दिया गया और इंग्लैण्ड को उधर से छुट्टी मिल गई, तो अंग्रेजों ने किसी तरह अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन पर कब्जा कर लिया और वहांकी बड़ी-बड़ी सभी सरकारी इमारतें जला दीं। कैपिटल नामक भवन, जहाँ कांग्रेस होती है, और व्हाइटहाउस, जिसमें राष्ट्रपति रहते हैं, भी बरबाद कर दिये गये। बाद में अंग्रेजों की हार होगई।

इस युद्ध से पहले भी संयुक्तराज्यों ने दक्षिण में एक बहुत बड़ा प्रदेश अपने इलाक़े में मिला लिया था। यह फ्रांस की लुइज़ियाना नाम की पुरानी बस्ती थी। अंग्रेजों के जहाजी हमलों से इसकी रक्षा बिल्कुल न कर सकने के कारण इसे नेपोलियन ने अमेरिका के हाथ बेच दिया था। कुछ साल बाद, १८२२ ई० में, उसने स्पेन से खरीदकर फ्लॉरिडा को मिला लिया और १८४८ ई० में मैक्सिको से लड़ाई जीतकर कैलीफ़ोर्निया सहित कई और राज्य दक्षिण-पश्चिम में लेलिये। इस दक्षिण-पश्चिमी हिस्से में अब भी बहुत-से नगरों के नाम स्पेनिश हैं और उन दिनों की याद दिलाते हैं जब वहाँ स्पेन वालों का या स्पेन की भाषा बोलनेवाले मैक्सिको-निवासियों का राज्य था। सिनेमैडोम के बड़े शहर लॉस एञ्जेलीस और सैन फ्रांसिस्को के नाम सभीने सुने हैं।

जिस वक़्त योरप बार-बार क्रांतियाँ करने और उन्हें दबा देने की कोशिश कर रहा था, उस वक़्त संप्रसारण पश्चिम की ओर फैलते जा रहे थे। दमन के कारण योरप के लोग अपने-अपने देश छोड़कर जा रहे थे और लम्बे-चौड़े देश और ऊँची-ऊँची मजदूरी की कहानियाँ उन्हें बड़ी तादाद में अमेरिका की तरफ़ खींच रहीं थीं। जैसे-जैसे पश्चिम में आबादी बढ़ी वैसे-वैसे नये-नये राज्य बनते और संघ में शामिल होते गये।

उत्तरी और दक्षिणी राज्यों में शुरु से ही बड़ा भेद था। उत्तरी राज्य उद्योग-प्रधान थे और वहाँ बड़ी-बड़ी मशीनों वाले नये-नये कारख़ाने तेज़ी से बढ़ गये। दक्षिण में बड़े-बड़े व्यापारी बग़ीचे थे और उनमें गुलाम लोग मजदूरी करते थे। गुलामी की प्रथा क़ानून से जायज़ थी, मगर उत्तर के लोग उसे पसन्द नहीं करते थे और वहाँ उसका कोई महत्व भी न था। दक्षिण का सारा दारोमदार ही गुलामी पर था। ये गुलाम अफ़्रीका के हथियारे थे। गोरा एक भी गुलाम नहीं था। आज़ादी के ऐलान में 'सब मनुष्य जन्म से समान हैं' यह जो उल्लूक माना गया था वह ग़ोरों पर ही लागू होता था, क़ालों पर नहीं।

इन हथियारों को अफ़्रीका से किस तरह लाया गया था, यह कहानी बड़ी दर्दनाक है। गुलामों का व्यापार सत्रहवीं सदी के शुरु में आरम्भ हुआ और १८६३ ई० तक जारी रहा। पहलेपहल तो यह हुआ कि जब अफ़्रीका के पश्चिमी समुद्रतट से व्यापार के माल से लदी हुई नावें गुज़रतीं, तो जो भी अफ़्रीका-निवासी उनके हाथ पड़ जाते उन्हें पकड़कर वे अमेरिका ले जातीं। इस किनारे का एक हिस्सा अब भी 'गुलामों का किनारा' (Slave Coast) कहलाता है। खुद अफ़्रीका के बाशिन्दों में गुलामी का रिवाज़ बहुत कम था। वे सिर्फ़ लड़ाई के क़ैदियों और क़र्ज़दारों के साथ ही गुलामों का-सा वर्तव करके थे। अफ़्रीकन लोगों को अमेरिका लेजाकर बेच देने का धन्धा बड़ मुनाफ़े का पाया गया। गुलामों का व्यापार बढ़ा और इसमें अंग्रेज़, स्पेनिश और पोर्चुगीज़ लोगों ने पंसा लगाया। गुलामी के व्यापार के लिए खास तरह के जहाज़ बनाये गये। उनमें पटावों के बीच में लम्बी और तंग कोठरियाँ रखी गईं और उनमें ये अभाग्यवानों पंरों में जंजीरों और हाथों में हथकड़ियाँ बाँधकर दो-दो करके लिटा दिये जाते थे। अटलाण्टिक महासागर पार के समुद्री सफ़र में कई हफ़्ते और कभी-कभी महीने लग जाते थे। इस सारे असें में ये हथियार इन तंग कोठरियों में बंधे पड़े रहते। इनमें हरेक को ५॥ फ़ीट लम्बी और १६ इंच चौड़ी जगह दी जाती थी !

गुलामों के व्यापार के कारण लिवरपूल बड़ा शहर बन गया। १७१३ ई० में ही जब यूट्रेच्ट की संधि हुई तो इंग्लैंड ने स्पेन से अफ़्रीका और स्पेनिश अमेरिका के बीच में गुलामों को लेजाने का विशेषाधिकार छीन लिया। इससे पहले भी इंग्लैंड

अमेरिकन इलाकों में गुलाम पहुँचाया करता था। इस तरह अठारहवीं सदी में कोशिश की गई कि अफ्रीका और अमेरिका के गुलामों के व्यापार पर अंग्रेजों का ठेका हो जाय। १७३० ई० में लिवरपूल के १५ जहाज इस व्यवसाय में लगे हुए थे। यह तादाद बढ़ती-बढ़ती सन् १७९२ ई० में १३२ होगई। औद्योगिक क्रान्ति की शुरुआत में इंग्लैण्ड के लंकाशायर प्रदेश में रई की कताई का काम बहुत बढ़ गया और इसके कारण संयुक्तराज्यों में गुलामों की माँग भी बहुत बढ़ गई। इसका कारण यह था कि लंकाशायर की मिलों में जो रई काम में लाई जाती थी वह अमेरिका के दक्षिणी राज्यों के रई के बड़े बगीचों में से आती थी। ये बगीचे बड़ी तेजी से बढ़े, अफ्रीका से गुलाम भी उतने ही ज्यादा आये और ह्विशियों की औलाद बढ़ाने की कोशिश भी की गई। १७९० ई० में संयुक्तराज्यों में गुलामों की तादाद ६,९७,००० थी। १८६१ ई० में वह बढ़कर ४०,००,००० होगई।

उन्नीसवीं सदी के शुरू में ब्रिटिश पार्लमेण्ट ने गुलामी के रिवाज के खिलाफ कड़े क़ानून पास किये। योरप और अमेरिका के दूसरे देशों ने भी ऐसा ही किया। इसतरह गुलामी का व्यापार ग़ैरक़ानूनी ठहरा दिया गया, मगर ह्विशियों को अफ्रीका से अमेरिका ले जाने का सिलसिला फिर भी जारी रहा। फ़र्क़ इतना ही हुआ कि सफ़र में उनकी हालत और भी ख़राब होने लगी। वे खुले तौर पर तो ले जाये नहीं जा सकते थे, इसलिए उन्हें टांडों पर ऊपर-नीचे पटककर लोगों की नज़र से छिपा दिया जाता था। एक अमेरिकन लेखक कहता है—“कभी-कभी बर्फ़ की भरी गाड़ी (Toboggan) पर सवार होनेवालों की तरह उन्हें एक-दूसरे के ऊपर टाँग पर टाँग रखकर लाद दिया जाता था!” यह कितनी ख़ौफ़नाक बात होती होगी, इसका ख़याल करना भी दुश्वार है। उन जहाजों की इतनी गन्दी हालत हो जाती थी कि चार-पाँच वार के सफ़र के बाद उन्हें छोड़ देना पड़ता था। मगर मुनाफ़ा बहुत ज्यादा होता था और जब व्यापार का ख़ूब जोर था, यानी अठारहवीं सदी के अख़ीर और उन्नीसवीं के शुरू में, तो हर साल अफ़्रीका के गुलामों के किनारे से एक लाख गुलाम लेजाये जाते थे। याद रहे कि इतने आदमियों को लेजाने का यह मतलब था कि ह्विशियों को पकड़ने के लिए जो छापे मारे जाते थे उनमें इनसे कहीं ज्यादा की माँत होती थी।

उन्नीसवीं सदी के शुरू में या उसके आस-पास सभी बड़े-बड़े देशों ने इस व्यवसाय को क़ानून के खिलाफ़ ठहरा दिया। संयुक्तराज्यों ने भी ऐसा ही किया। इस तरह गुलामी का व्यापार बन्द होगया, मगर अमेरिका में गुलामी बन्द नहीं हुई, यानी वहाँ पुराने गुलाम फिर भी गुलाम ही बने रहे। और चूँकि गुलामी जायज़

थी, इसलिए मनाई होने पर भी गुलामों का व्यापार जारी रहा। जब ब्रिटेन ने दास-प्रथा भी उठा दी तब गुलामी के व्यापार के लिए न्यूयार्क मुख्य बन्दर हो गया।

यद्यपि उन्नीसवीं सदी के बीच तक कई वर्ष न्यूयार्क इस व्यवसाय का केन्द्र रहा, फिर भी अमेरिका के उत्तरी राज्य गुलामी के रिवाज के खिलाफ थे। इसके विपरीत, दक्षिण वालों को अपने बग़ीचों के लिए इन गुलामों की जरूरत थी। कुछ राज्यों ने गुलामी उठा दी और कुछ ने रहने दी। ह्वशी गुलामी वाले राज्यों में से भागकर बिना गुलामी के राज्यों में चले जाते और उनके बारे में झगड़े होते।

उत्तर और दक्षिण के आर्थिक हित जुदा-जुदा थे और उनके बीच १८३० ई० में ही चुंगी के मामले में कशमकश होगई। संघ से अलग होजाने की धमकियाँ दीगई। राज्य अपने-अपने अधिकार छोड़ना नहीं चाहते थे और संघ-सरकार की बहुत ज्यादा दस्तन्दाजी पसन्द नहीं करते थे। देश में दो दल हो गये। एक राज्यों की सत्ता का तरफ़दार था, दूसरा मजबूत केन्द्रीय सरकार चाहता था। इन मतभेदों के कारण उत्तर और दक्षिण के बीच की खाई बढ़ती गई और जहाँ कहीं नये राज्य संघ में शामिल होते थे वहाँ यह सवाल उठता था कि वे किस तरफ़ का साथ देंगे। बहुमत किधर होगा ? उत्तर की आवादी तेज़ी से बढ़ रही थी, क्योंकि योरोप से लोग आ-आकर वहाँ बस रहे थे। इससे दक्षिण के लोगों को डर हुआ कि उत्तर की बढ़ी हुई संख्या उन्हें दबा लेगी और हर सवाल पर ज्यादा वोट या राय देकर उन्हें हरा देगी। इस तरह उत्तर और दक्षिण में खिंचाव बढ़ता गया।

इसी बीच, दक्षिण में गुलामी की प्रथा बिल्कुल उठा देने का आन्दोलन खड़ा हुआ। इस आन्दोलन का मुख्य नेता विलियम लॉयड गैरीज़न था। १८३१ ई० में गैरीज़न ने गुलामी दूर करने के इस आन्दोलन के प्रचार के लिए 'लिब्रेटर' (उद्धारक) नामक एक पत्र निकाला। इसके पहले ही अंक में उसने साफ़-साफ़ जाहिर कर दिया कि इस मामले में वह कोई समझौता नहीं करेगा और न नरम नीति रखेगा। उस अंक के कुछ वाक्य इतने मशहूर होगये हैं कि मैं उन्हें यहाँ देता हूँ:—

“मैं सत्य के समान कटु और न्याय की तरह कठोर रहूँगा। इस विषय में मैं नरमी से सोचना, धोलना या लिखना नहीं चाहता। नहीं, नहीं; जिसके घर में आग लगी हो उसे भले ही धीरे-धीरे चिल्लाने को कहो, जिसकी पत्नी का सतीत्व नष्ट किया जा रहा हो उसे चाहे अपनी पत्नी को बचाने में नम्रता से काम लेने को कहो, जिस माता का शिशु आग में पड़ गया है उसे भी आहिस्ता-आहिस्ता बचाने को कहो, लेकिन मुझे मेरे इस काम में मुलायमियत से काम लेने को मत कहो। मैं बहुत उग्र हूँ, मैं गोलमोल बात नहीं कहूँगा, मैं क्षमा नहीं करूँगा, और न तिल भर पीछे हटूँगा। मेरी बात सुननी ही पड़ेगी।”

लेकिन यह बीर-वृत्ति थोड़े-से लोगों तक ही सीमित थी। जो लोग गुलामी की प्रथा के खिलाफ थे उनमें से ज्यादातर यह नहीं चाहते थे कि गुलामी का रिवाज जहाँ है वहाँ उसमें दखल दिया जाय। फिर भी उत्तर और दक्षिण का आपसी खिंचाव बढ़ता ही गया, क्योंकि उनके आर्थिक स्वार्थ जुदा-जुदा थे और कशमकश खास तौर से चुंगी के सवाल पर थी।

१८६० ई० में अब्राहम लिंकन संयुक्तराज्यों का राष्ट्रपति चुना गया। उसका चुनाव क्या हुआ, दक्षिण वालों को अलग होजाने का इशारा मिल गया। लिंकन गुलामी के रिवाज का विरोधी था, मगर उसने साफ़ कर दिया था कि जहाँ गुलामी पहले से है वहाँ उसे नहीं छोड़ा जायगा। मगर वह इस बात के लिए तैयार नहीं था कि यह नये राज्यों में भी फैले और इसे कानूनी रूप मिल जाय। इस आश्वासन से दक्षिण का सन्तोष नहीं हुआ और एक-एक करके कई राज्य संघ से अलग होगये। संयुक्तराज्य छिन्न-भिन्न हुआ चाहते थे। नये राष्ट्रपति के सामने ऐसी भयंकर स्थिति थी। उसने दक्षिण को राजी करके इस अंग-भंग को रोकने की एक और कोशिश की। उसने उन्हें तरह-तरह के आश्वासन दिये कि दास-प्रथा बन्द नहीं की जायगी। उसने यहाँतक कह दिया कि गुलामी जहाँ है वहाँ उसे विधान में शामिल करके स्थायी बनाने को भी तैयार हूँ। असल में वह शान्ति की खातिर किसी भी हद तक जाने को राजी था, मगर वह एक बात को मंजूर नहीं कर सकता था और वह यह कि संघ छिन्न-भिन्न होजाय। किसी राज्य का संघ से अलग होने का हक वह कतई मानने को तैयार नहीं था।

गृह-युद्ध को टालने की लिंकन की सारी कोशिशें बेकार रहीं। दक्षिण ने अलग होजाने का फैसला कर लिया और ग्यारह राज्य अलग हो भी गये। उनके साथ किनारे के कुछ और राज्यों की भी हमदर्दी थी। अलग होनेवाले राज्य अपनेको सम्मिलित राज्य (Confederate State) कहने लगे और उन्होंने जैफ़र्सन डेविस को अपना अलग राष्ट्रपति चुन लिया। १८६१ ई० के अप्रैल में गृह-युद्ध छिड़ गया और पूरे चार वर्ष तक चलता रहा। उस समय बहुत-से भाई भाइयों से और मित्र मित्रों से लड़े। लड़ाई के दौरान में दोनों तरफ़ बड़ी-बड़ी फ़ौजें खड़ी हो गईं। उत्तर को बहुतेरी सहायितें थीं। उसकी आबादी भी ज्यादा थी और दौलत भी ज्यादा। वह पक्का माल तैयार करनेवाला और ऐसा देश था जहाँ उद्योग-धंधे और कल-कारखाने खूब बढ़े हुए थे, इसलिए उसके पास बहुत ज्यादा साधन थे और उसकी रेलें भी ज्यादा थीं। लेकिन दक्षिण के सैनिक और सेनापति अच्छे थे—खासतौर पर जनरल ली बड़ा योग्य था। इसलिए शुरू-शुरू में दक्षिण की ही सारी विजय हुई। लेकिन अखीर में दक्षिण की

ताक़त कमज़ोर पड़ गई। उत्तर वालों की समुद्री फ़ौज ने दक्षिण का उसके योरप के बाज़ारों से ताल्लुक़ घिलकुल काट दिया और रुई और तम्बाकू का बाहर जाना रोक दिया। इससे दक्षिण के हाथ-पैर फट गये। लेकिन इसका असर लंकाशायर पर भी बहुत ज़बरदस्त हुआ। वहाँ रुई न पहुँचने से बहुतसी मिलें बन्द हो गईं। लंकाशायर के मज़दूर बेकार हो गये और उन्हें बड़ी मुसीबत उठानी पड़ी।

इस लड़ाई के बारे में अंग्रेज़ी लोकमत की आम तौर पर दक्षिण वालों के साथ हमदर्दी थी, या कम-से-कम धनिकवर्ग की राय दक्षिण की तरफ़ थी। सुधारक लोग उत्तरवालों के तरफ़दार थे।

गृह-युद्ध की असली वजह दास-प्रथा नहीं थी। जैसा मैं कह चुका हूँ, लिंकन अख़ीर तक आश्वासन देता रहा था कि गुलामी की प्रथा जहाँ कहीं है वहाँ उसका ख़याल रक्खा जायगा। झगड़े की जड़ तो असल में दक्षिण और उत्तर के जुदा-जुदा और कुछ विरोधी आर्थिक स्वायं थे और अख़ीर में लिंकन को संघ की रक्षा के लिए लड़ना पड़ा। युद्ध छिड़ जाने के बाद भी लिंकन ने दास-प्रथा के बारे में कोई साफ़ ऐलान नहीं किया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उत्तर के वे बहुत लोग जो गुलामी की प्रथा के तरफ़दार थे और किनारे के राज्य भड़क न उठें। हाँ, जैसे-जैसे लड़ाई बढ़ती गई वैसे-वैसे वह साफ़ बातें करने लगा। पहले उसने यह प्रस्ताव रक्खा कि मालिकों को मुआवज़ा देकर कांग्रेस गुलामों को आज़ाद करदे। बाद में उसने मुआवज़ा देने का विचार छोड़ दिया और अख़िर १८६२ ई० के सितम्बर में उसने जो मुक्ति की घोषणा निकाली उसमें यह ऐलान कर दिया कि १८६३ ई० की पहली जनवरी से सारे बाक़ी राज्यों के गुलाम आज़ाद होजायेंगे। इस घोषणा के निकालने की ख़ास वजह शायद यह थी कि वह दक्षिण की ताक़त लड़ाई में कमज़ोर कर देना चाहता था। इसका नतीजा यह हुआ कि चालीस लाख गुलाम आज़ाद होगय और उनसे यह उम्मीद ज़रूर रक्खी गई थी कि सम्मिलित राज्यों में ये लोग बख़ेड़ा खड़ा करेंगे।

जब दक्षिणवाले बिलकुल थक गये तो १८६५ ई० में गृहयुद्ध ख़त्म हुआ। वैसे तो लड़ाई कभी भी हो तो भयंकर चीज़ ही होती है, मगर खानाजंगी तो और भी ख़तरनाक चीज़ है। चार वर्ष की इस ज़बरदस्त लड़ाई का बोझ सबसे ज़्यादा राष्ट्र-पति लिंकन पर पड़ा और उसका जो नतीजा हुआ वह भी बहुत कुछ उसीकी शान्त दृढ़ता के कारण ही हुआ। उसने सारी निराशाओं और मुसीबतों की परवा न की और अपना काम जारी रक्खा। उसे सिर्फ़ जीतने की ही धुन नहीं थी। वह यह भी चाहता था कि इस विजय में कम-से-कम बदगुमानी पैदा हो, ताकि जिस संघ के ख़ातिर वह लड़ रहा था वह हृदयों का सम्मेलन हो और कोरा ज़बरदस्ती से लदा हुआ मेल न हो।

इसलिए लड़ाई में विजयी होते ही उसने हारे हुए दक्षिण के साथ उदारता का बर्ताव करना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ दिनों के भीतर ही किसी फिरे दिमारा के आदमी ने उसे गोली से उड़ा दिया।

अब्राहम लिंकन अमेरिका के बड़े-से-बड़े शूरवीरों में से हैं। उसका स्थान दुनियाभर के महान पुरुषों में भी है। शुरू में वह बहुत ही छोटा आदमी था। स्कूल में उसने थोड़ी-सी तालीम पाई थी। जो कुछ उसने सीखा ज्यादातर अपनी ही मेहनत से सीखा था। फिर भी वह बढ़ते-बढ़ते एक बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ और वक्ता बन गया और उसने मुसीबत के बहुत बड़े जमाने में अपने देश की नाव को पार लगाया।

लिंकन के मरने के बाद अमेरिका की कांग्रेस दक्षिणी गोरों के प्रति उतनी उदार नहीं रही, जितनी कि वह हो सकती थी। इन दक्षिणी गोरों को कई तरह की सजा दी गई और बहुतों का मताधिकार छीन लिया गया। उधर हब्ज़ियों को नागरिकता के पूरे हक देकर इस बात को अमेरिका के विधान में शामिल कर दिया गया। यह भी नियम बना दिया गया कि कोई राज्य किसी आदमी को उसकी जाति, रंग या पहले की गुलामी के कारण राय देने के हक से वंचित नहीं कर सकेगा।

हब्ज़ी लोग अब क़ानून की रू से आज़ाद होगये और उन्हें राय देने का हक भी मिल गया। लेकिन उनकी माली हालत वही रही, इस कारण उन्हें बहुत कम फायदा पहुँचा। आज़ाद किये गये हब्ज़ियों में से किसीके पास जायदाद नहीं थी और उनके लिए क्या किया जाय, यह सवाल होगया। उनमें से कुछ लोग उत्तर के शहरों में जा बसे, लेकिन ज्यादातर जहाँ थे वहीं रहे। उनपर उनके पुराने गोरे दक्षिणी मालिकों का वैसा ही दवाव रहा। वे पुराने बागीचों में काम करते रहे और जो मजदूरी उनके गोरे अब्रदाता देते वही उन्हें लेनी पड़ती। दक्षिणी गोरों ने भी हर तरह के आतंक द्वारा हब्ज़ियों को दवाये रखने के लिए अपना संगठन कर लिया। उन्होंने कूक्लक्स क्लैन नाम की एक गैरसामूली ढंग की गुप्त-सी संस्था बना ली। इसके सदस्य बुक्रे पहन-पहनकर हब्ज़ियों को डराते फिरते थे और उन्हें चुनाव में राय देने से भी रोकने लगे।

पिछले पचास वर्ष में हब्ज़ियों ने कुछ तरक्की की है। बहुतों के जायदाद भी होगई हैं और उनकी कई बढ़िया शिक्षण-संस्थायें हैं। फिर भी निश्चित रूप में उनकी जाति गुलाम है। संयुक्त राज्यों में उनकी तादाद एक करोड़ बीस लाख के करीब यानी सारी आबादी का दसवां हिस्सा है। जहाँ कहीं उनकी तादाद थोड़ी है वहाँ उन्हें वरदास्त कर लिया जाता है। उत्तर के कुछ हिस्सों में कुछ ऐसा ही होता है।

मगर ज्योंही उनकी तादाद बढ़ने लगती है त्योंही उनपर बुरी तरह हमले होने लगते हैं और उन्हें यह अनुभव करा दिया जाता है कि पुराने गुलामों से उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं है। होटलों, गिरजों, कालेज, बागों, स्नान करने के घाटों, ट्राम-गाड़ियों और भण्डारों तक में, सभी जगह, उन्हें गोरों से अलग रखा जाता है ! रेलों में उन्हें खास डिब्बों में बंठना पड़ता है। गोरों और ह्विशियों में शादी की क़ानून से मनाई है। असल में तरह-तरह के विचित्र क़ानून हैं। अभी १९२६ ई० में ही वर्जीनिया राज्य ने एक क़ानून बनाकर गोरों और काले का एक आँगन में साथ-साथ बंठना भी मना कर दिया है।

कभी-कभी गोरों और ह्विशियों में भयंकर दंगे होते हैं। दक्षिण में अक्सर ऐसे भयंकर मामले हो जाते हैं कि भीड़ किसी आदमी पर मुजरिम होने का शुबहा करके उसे पकड़ लेती है और मार डालती है। इन्हीं वर्षों में ऐसी घटनायें भी हुई हैं कि गोरों लोगों की भीड़ ने ह्विशियों को खम्भे से बाँधकर ज़िन्दा जला दिया।

यों तो सारे अमेरिका में और खास तौर पर दक्षिणी राज्यों में ह्विशियों की हालत अब भी बहुत दर्दनाक है। जब मजदूरों का मिलना कठिन हो जाता है तब अक्सर बेक़सूर ह्विशियों को दक्षिण के कुछ राज्यों में किसी बनावटी जुर्म में जेल भेज दिया जाता है और फिर उन क़दियों को ठेके पर मजदूरी करने के लिए खानगी ठेकेदारों के हवाले कर दिया जाता है। यह बात खुद ही बहुत बुरी है, मगर इसके साथ और जो हालत होती है वह तो बहुत भयंकर है। इस तरह हम देखते हैं कि आखिर क़ानूनी आज़ादी मिल जाना ही कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। मगर एक बात में ह्विशियों ने पश्चिमी दुनिया पर क़िलहाल फतह हासिल कर ली है और वह है उनका 'जैज़' (Jazz) संगीत।

क्या तुमने हैरियट बीचर स्टो की 'टॉम काका की कुटिया' पढ़ी है, या उसका नाम सुना है ? यह पुस्तक दक्षिणी राज्यों के पुराने ज़माने के ह्वशी गुलामों के बारे में है और इसमें उनकी दर्दनाक कहानी दी गई है। यह गृहयुद्ध से दस वर्ष पहले प्रकाशित हुई थी और अमेरिका के लोगों को दास-प्रथा के ख़िलाफ़ खड़ा करने में इसका बड़ा असर पड़ा था।

अमेरिका का अदृश्य साम्राज्य

२८ फरवरी, १९३३

गृह-युद्ध ने अमेरिका में बहुत ज्यादा तादाद में नीजवानों की जानें लीं और वह कर्ज का बहुत भारी बोझ भी छोड़ गया। लेकिन उस समय यह देश जवान था और उम्रों से भरा था। इसकी तरक्की जारी रही। इस देश में प्राकृतिक सम्पत्ति का पार न था, खासकर खनिज पदार्थ इसमें बहुत ज्यादा पाये जाते थे। कोयला, लोहा और पेट्रोल, जो तीन चीजें आजकल व्यवसाय और सभ्यता की जड़ हैं, इस मुल्क में बहुत काफ़ी थीं। इस देश में जल-शक्ति भी इतनी ज्यादा थी कि खूब बिजली पैदा की जा सके। इस सिलसिले में नियागरा का जल-प्रपात तो तुम्हें याद आ ही जायगा। अमेरिका एक बहुत लम्बा-चौड़ा मुल्क था; इसकी आबादी औरों के मुक़ाबिले कम थी और हरेक आदमी के लिए आगे बढ़ने की गुंजाइश थी। तरक्की करके एक महान् व्यावसायिक और औद्योगिक देश बन जाने की सारी सहूलियतें इस देश में पाई जाती थीं। अमेरिका इस रास्ते पर बहुत तेज़ी के साथ तरक्की भी करने लगा। ईसवी सन् १८८० तक पहुँचते-पहुँचते अमेरिका का व्यवसाय विदेशी बाज़ारों में ब्रिटिश व्यवसाय का मुक़ाबिला करने लग गया था। ब्रिटेन ने वैदेशिक व्यापार पर सौ वर्ष से अपना जो प्रभुत्व यानी क़ब्ज़ा आसानी के साथ कर रक्खा था, अमेरिका और जर्मनी ने उसे ख़त्म कर दिया।

लोग इस देश में दूसरे देशों से आकर बसने लगे। योरप से सब तरह के लोग आये; जैसे जर्मन, स्कैंडीनेवियन, आयरिश, इटालियन, यहूदी, पोल चग़ैरा। इनमें से बहुत-से तो अपने देश में होनेवाले राजनैतिक जुल्मों से घबराकर आये थे और बहुत-से बेहतर रोज़ी और रोज़गार की तलाश में। ज़रूरत से ज्यादा घनी आबादी वाले योरप ने अपनी फ़्राज़िल आबादी को अमेरिका में भेजना शुरू कर दिया। इस मुल्क में जातियों, राष्ट्रों, भाषाओं और धर्मों का एक असाधारण पन्ध्रमेल पैदा होगया। योरप में ये लोग अलग-अलग रहते थे, हरेक की अपनी छोटी-छोटी जुदा दुनिया थी, एक-दूसरे की तरफ़ नफ़रत और डाह के भावों से भरे रहा करते थे। अमेरिका में इन लोगों ने एक-दूसरे को नय वातावरण में जाना, जहाँ पुरानी नफ़रतों का कोई ख़ास असर नहीं दिखाई देता था। अनिवार्य शिक्षा की एक समान प्रणाली ने इनकी राष्ट्रीय विषमताओं को घिसकर चौरस कर दिया और विभिन्न जातियों के इस चों-चों के मुरब्बे से अमेरिकन टाइप पैदा होने लगा। पुराने ऍंग्लो-सैक्सन लोग अपनेको ऊँची जाति का समझते

रहे। समाज के यही अगुआ थे। इनके बाद, किन्तु इनके करीब, उन लोगों का स्थान था जो उत्तरी योरप से आये थे। ये उत्तरी यूरोपियन लोग दक्षिण योरप से आये हुए लोगों को, खासकर इटली के लोगों को, नीची नज़र से देखते थे और उन्हें 'डागो' (Dagos) कहकर पुकारते थे। ह्व्शी लोग तो अलग थे ही। ये सब जातियों से नीचे समझे जाते थे और किसी भी गोरी क्रॉम से मिलते-जुलते नहीं थे। पश्चिमी समुद्र के किनारे कुछ चीनी, जापानी और हिन्दुस्तानी आ बसे थे। ये लोग उस समय आये थे जब अमेरिका में मजदूरों की माँग बहुत ज्यादा थी। एशिया की ये क्रोम भी ओरों से अलहदा ही रहें।

रेल और तार के हर जगह फैल जाने से यह विशाल देश एक सूत्र में बँध गया। पुराने ज़माने में ऐसा होना नामुमकिन था, क्योंकि उस समय एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुँचने में हफ़्तों और महीनों लग जाते थे। हम देख चुके हैं कि पुराने ज़माने में एशिया और योरप में अक्सर बड़े-बड़े साम्राज्य कायम हुए, लेकिन वे एक धागे में इसलिए नहीं बँध सके थे कि आमदरपत और संसर्ग की सहूलियतें नहीं थीं। साम्राज्य के मुहत्तलिफ हिस्से एक-दूसरे से बिल्कुल अलग रहते थे और अपना जीवन पूरी आजादी के साथ गुज़ारते थे। इतनी बात जरूर होती थी कि वे सम्राट की मातहती क़बूल करते थे और उसे ख़िराज देते थे। ये साम्राज्य असल में एक सम्राट या शासक की मातहती में अनेक देशों के ढीले-ढाले गिरोह होते थे। इन सभी में आदर्शों या उसूलों का कोई समान दृष्टिकोण नहीं पाया जाता था। लेकिन अमेरिका के संयुक्तराष्ट्र ने रेलवे और आमदरपत के दूसरे जरियों की वजह से और एक-समान शिक्षा-प्रणाली के कारण अपने देश की अनेक जातियों में समान दृष्टिकोण पैदा कर दिया। ये अनेक जातियाँ धीरे-धीरे मिलकर एक जाति होगई। यह प्रवृत्ति अभीतक ख़त्म नहीं हुई है; मेल का यह सिलसिला अभीतक जारी है। इतने बड़े पैमाने पर सम्मिश्रण का कोई दूसरा उदाहरण इतिहास में नहीं मिलता।

संयुक्तराष्ट्र ने योरप की पेचीदगियों और यूरोपीय ताक़तों की साजिशों से दूर रहने की कोशिश की। संयुक्तराष्ट्र यह भी चाहता था कि योरप उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के मामलात से अलग रहे। मैं तुम्हें 'मनरो सिद्धान्त' (Monroe Doctrine) के बारे में बता चुका हूँ। जब चन्द यूरोपियन शक्तियों ने अपनेको 'पवित्र मित्रदल' (Holy Alliance) का नाम देकर दक्षिण अमेरिका में स्पेन का साम्राज्य कायम रखने के लिए दख़ल देना चाहा, उस वक़्त अमेरिका के प्रेसीडेण्ट मनरो ने एक राजनैतिक उसूल का ऐलान किया था। वह यह कि सारे अमेरिका में संयुक्तराष्ट्र किसी भी यूरोपियन शक्ति को क़ौज़ी दस्तन्दाज़ी करने की इजाज़त न देगा।

इसीका नाम 'मनरो डाक्टरिन' पड़ा। इस उसूल ने नये पैदा हुए दक्षिण अमेरिका के प्रजातन्त्रों को योरप के चंगुल से बचा लिया। इसकी वजह से इंग्लैण्ड से एक दफ़ा लड़ाई भी छिड़ गई, लेकिन अमेरिका इस सिद्धान्त पर, आज सौ बरस से ज्यादा होते हैं, डटा रहा है।

दक्षिण अमेरिका उत्तरी अमेरिका से विलकुल जुदा था और सौ बरस के ज़माने में इस भेद में कोई कमी नहीं हुई। उत्तर में कनाडा दिन-दिन संयुक्तराष्ट्र की तरह होता जाता है। लेकिन दक्षिण अमेरिका के प्रजातन्त्र वैसे नहीं बन रहे हैं। मैंने तुम्हें पहले बताया है कि दक्षिण अमेरिका के ये प्रजातन्त्र—और इनमें मैक्सिको को भी शामिल करलेना चाहिए, गो वह उत्तर अमेरिका में है—लैटिन प्रजातन्त्र कहलाते हैं। अमेरिका और मैक्सिको की सरहद दो भिन्न जातियों और संस्कृतियों को जुदा करती है। इस सरहद के दक्षिण में मध्य-अमेरिका की पतली पट्टी के उसपार और दक्षिण अमेरिका के विशाल महाद्वीपभर में, सभी जगह, जनता की भाषा स्पेनी और पुर्तगाली है। स्पेनी भाषा का ज्यादा जोर है। मेरा खयाल है कि पुर्तगाली सिर्फ़ ब्राज़िल में ही बोली जाती है। दक्षिण अमेरिका के कारण ही स्पेनी भाषा आज संसार की बड़ी भाषाओं में स्थान रखती है। लैटिन अमेरिका अब भी संस्कृति के सम्बन्ध में स्पेन का मुंह देखता है। संयुक्त अमेरिका और कनाडा में जो जातीय वर्ग-भेद पाये जाते हैं वे लैटिन अमेरिका में नहीं पाये जाते। स्पेनी लोगों और अमेरिका के आदिम निवासियों यानी रेडइंडियनों में, और कुछ हद तक हव्ज़ियों के साथ, शादी-व्याह आपस में बराबर होते हैं। इसकी वजह से यहाँ एक मिश्रित जाति पैदा होगई है।

सौ वर्षों से आजाद होते हुए भी लैटिन अमेरिका के ये प्रजातन्त्र शान्तिपूर्वक जिन्दगी बिताना पसन्द नहीं करते। समय-समय पर इन देशों में क्रांति होती है और सैनिक डिकटेटर पैदा होते रहते हैं। यहाँकी हमेशा तब्दील होनेवाली राजनीति और सरकारों की प्रगति को समझना आसान नहीं है। दक्षिण अमेरिका के तीन बड़े-बड़े देश, अर्जेंटाइन, ब्राज़िल और चाइल हैं। इनको ए० बी० सी० देश भी कहते हैं, क्योंकि इनके नाम का पहला अक्षर क्रमशः ए० बी० सी० है। उत्तर अमेरिका में ख़ास लैटिन अमेरिकन देश मैक्सिको है।

'मनरो सिद्धान्त' के जरिये संयुक्तराष्ट्र ने लैटिन अमेरिका के मामलात में योरप को दखल देने से रोक दिया। लेकिन ज्यों-ज्यों संयुक्तराष्ट्र वाले खुद अमीर और खुशहाल होते गये, अपने विस्तार के लिए बाहर नये क्षेत्र की तलाश करने लगे। स्वभावतः इनकी आँखें पहले लैटिन अमेरिका पर पड़ीं, लेकिन ये लोग साम्राज्य बनाने के पुराने ढंग पर नहीं चले। इन्होंने लैटिन अमेरिका के किसी भी हिस्से पर

जबरदस्ती क़ब्ज़ा नहीं किया। इन लोगों ने इन देशों में अपने देश का बना हुआ माल भेजा और इनके बाजारों पर क़ब्ज़ा कर लिया। इन्होंने दक्षिण में रेलवे, खान तथा दूसरे रोज़गारों में अपनी पूंजी लगा दी। सरकारों को, और कभी-कभी क्रान्तियों के समय एक-दूसरे के खिलाफ़ लड़नेवाले दलों को, कर्ज़ देना शुरू किया। 'इन्होंने' से मेरा मतलब अमेरिकन पूंजीपति और साहूकारों से है। अमेरिका की गवर्मेंट इनके पीछे इनकी मदद पर थी। धीरे-धीरे ये साहूकार लोग उस दौलत की वजह से, जो इन्होंने लगा रखी थी या कर्ज़ दे रखी थी, मध्य और दक्षिण अमेरिका की अनेक छोटी-छोटी सरकारों का नियंत्रण करने लगे। ये साहूकार इन देशों की एक पार्टी को धन या लड़ाई का सामान कर्ज़ देकर और दूसरी पार्टी को मदद से इन्कार करके क्रान्ति तक पैदा करा सकते थे। इन साहूकारों और पूंजीपतियों के पीछे उत्तरी-अमेरिका की ताकतवर सरकार थी। इसलिए दक्षिण अमेरिका के छोटे और कमज़ोर देश इनका क्या कर सकते थे? कभी-कभी संयुक्तराष्ट्र ने इन प्रदेशों में शान्ति और अमन क़ामय रखने के बहाने किसी एक दल की मदद करने के लिए बाकायदा अपनी फ़ौजें भी भेजीं।

इस तरह अमेरिकन पूंजीपतियों ने दक्षिण अमेरिका के इन छोटे-छोटे देशों पर प्रभावशाली नियन्त्रण स्थापित कर लिया। अपने बैंक चलाये, रेलें जारी कीं और खानें खोदीं, और इन देशों से खूब मुनाफ़ा उठाते रहे। लैटिन अमेरिका के बड़े देशों में भी पूंजी लगाये रहने की वजह से और मुद्रा पर अधिकार रखने के कारण इनका बहुत काफी असर था। इसका मतलब यह हुआ कि संयुक्तराष्ट्र ने इन देशों के धन पर या उसके बहुत बड़े हिस्से पर क़ब्ज़ा कर लिया था। यह ग़ौर करने की चीज़ है, क्योंकि यह नये किस्म के साम्राज्य—आधुनिक ढंग के—साम्राज्य का नमूना है। इसे अदृश्य यानी आँख से न दिखाई देनेवाला साम्राज्य कहना चाहिए। यह आर्थिक साम्राज्य है, क्योंकि इस किस्म के साम्राज्य में साम्राज्य के जाहिरा चिन्ह न होते हुए भी देशों पर अधिकार रहता है और उनका शोषण किया जाता है। दक्षिण अमेरिका के प्रजातन्त्र राजनैतिक और अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से आज़ाद हैं। नकशे को देखने से ये बड़े विशाल देश मालूम पड़ते हैं और इस बात का कोई भी निशान नहीं दिखाई देता कि किसी भी रूप में ये परतन्त्र होंगे, लेकिन इनमें से ज्यादातर मुल्कों पर संयुक्तराष्ट्र हावी है।

हमने अपने इतिहास की झलक में देखा है कि भिन्न-भिन्न युगों में भिन्न-भिन्न प्रकार के साम्राज्य होते रहे हैं। इतिहास के शुरू में अगर एक जाति दूसरी जाति पर विजय पा जाती थी, तो उसका यह मतलब होता था कि हारी हुई जाति और भूमि

के साथ विजयी जो चाहे करे। विजयी लोग जमीन पर भी कब्जा कर लेते थे और जनता पर भी; यानी हारे हुए लोग गुलाम होजाते थे। यही आम रिवाज था। बाइबिल में हम पढ़ते हैं कि यहूदियों को बैबीलोनियन लोग गुलाम बनाकर अपने देश पकड़ ले गये थे, क्योंकि यहूदी बैबीलोनियन लोगों से लड़ाई में हार गये थे। इस क्रिस्म की बहुत-सी मिसालें मिलती हैं। धीरे-धीरे साम्राज्य का यह ढंग बदला और इसकी जगह पर दूसरे क्रिस्म का साम्राज्य आगया, जिसमें सिर्फ जमीन पर कब्जा कर लिया जाता था लेकिन जनता को गुलाम नहीं बनाते थे; क्योंकि यह स्पष्ट होगया था कि गुलाम बनाने की बनिस्वत टैक्स लगाकर या शोषण के अन्य साधनों से गुलामों से ज्यादा आसानी के साथ पैसा निकाला जा सकता है। हमने से ज्यादातर लोग अभी तक इसी क्रिस्म के साम्राज्य को साम्राज्य समझते हैं, जैसे हिन्दुस्तान में ब्रिटिश साम्राज्य, और हम लोगों का खयाल है कि अगर अंग्रेजों के हाथ से हिन्दुस्तान की राजनैतिक हुकूमत निकल जाय तो हिन्दुस्तान आजाद हो जायगा। लेकिन अब तो साम्राज्य का यह रूप खतम होजाता है और इसकी जगह पर एक उन्नत और परिपूर्ण ढंग का साम्राज्य पैदा हो रहा है। सबसे नई तरह के इस साम्राज्य में हारे हुएों की जमीन पर भी कब्जा नहीं किया जाता। ऐसे साम्राज्य तो सिर्फ देश की दौलत पर या उसकी उत्पत्ति के साधनों यानी पैदावार के जरियों पर अपना अधिकार जमाते हैं। इस ढंग से हारे देश का अच्छी तरह शोषण करके खूब मुनाफा भी उठाया जा सकता है और साथ ही उस देश पर हुकूमत करने या दमन करने की जिम्मेदारी से भी बचत हो जाती है। अमली तौर से जनता और भूमि दोनों पर कब्जा रहता है और कम-से-कम परेगानी से उन्हें वश में रक्खा जाता है।

इस तरह ज्यों-ज्यों जमाना बीतता गया है, साम्राज्यवाद अपनेको पक्का और और ठोस करता गया है; और आधुनिक ढंग का साम्राज्य अदृश्य आर्थिक साम्राज्य है। जब गुलामी का रिवाज मिट गया और उसके बाद जब सामन्ती ढंग की गुलामी दूर हुई, तब लोगों का खयाल था कि मनुष्य अब आजाद रहेंगे। लेकिन जल्दी ही यह मालूम होगया कि जनता को फिर वही लोग दुहा रहे हैं और दबाये हुए हैं, जिनके हाथ में पैसे की ताकत है। गुलाम और आसामी न रहकर लोग मजदूरी के गुलाम होगये। उनके लिए आजादी फिर भी दूर ही रही। यही हालत राष्ट्रों की भी है। लोग समझते हैं कि एक जाति का दूसरे पर राजनैतिक शासन ही सिर्फ एक मुसीबत है और अगर यह जाती रहे तो आजादी आप ही आप आजायगी। लेकिन यह बात सही नहीं मालूम होती, क्योंकि हम देखते हैं कि अनेक देश ऐसे हैं जो राजनैतिक दृष्टि से तो आजाद हैं लेकिन आर्थिक गुलामी के कारण पूरी तौर पर दूसरे देश की मुट्ठी में

है। हिन्दुस्तान में ब्रिटिश साम्राज्य तो बहुत प्रकट और स्पष्ट है। हिन्दुस्तान पर ब्रिटेन का राजनैतिक शासन है। इस दीखनेवाले साम्राज्य के साथ-साथ और इसके एक आवश्यक अंग के रूप में ब्रिटेन का भारतवर्ष पर आर्थिक प्रभुत्व भी है। यह बिलकुल सम्भव है कि भारतवर्ष पर से ब्रिटेन का ऊपर से दीखनेवाला साम्राज्य बहुत दिन गुजरने के पहले ही जाता रहे, लेकिन आर्थिक शासन अदृश्य साम्राज्य के रूप में बना रहे। अगर ऐसी हालत हो तो इसका मतलब यह होगा कि ब्रिटेन के जरिये हिन्दुस्तान का शोषण जारी है।

विजयी शक्ति के लिए आर्थिक साम्राज्यवाद कम-से-कम परेशानी पैदा करने-वाला प्रभुत्व है। इसके कारण पराजितों में उतना असंतोष नहीं फैलता जितना राजनैतिक प्रभुत्व होने पर फैलता है। क्योंकि बहुत-से लोग इसे नहीं देख पाते। लेकिन जब इस प्रभुत्व का बोझ दवाने लगता है, तब लोग इसके घुरे असर को महसूस करने लगते हैं और जनता में क्रोध पैदा होने लगता है। लेकिन अमेरिका में आजकल संयुक्तराष्ट्र के प्रति कोई प्रेम नहीं, काफ़ी क्रोध पाया जाता है। बहुत बार कोशिश की गई कि लैटिन अमेरिकन क्रांती को संगठित करके उत्तरी अमेरिका के प्रभुत्व को रोका जाय। लेकिन ये क्रांति उस वक़्त तक ज्यादा कामयाबी हासिल नहीं कर सकतीं, जबतक इनके आपसी झगड़े और इनकी अक्सर होती रहनेवाली महलों तक ही महद्द क्रांतियाँ बन्द नहीं होतीं।

संयुक्तराष्ट्र का दीखनेवाला साम्राज्य फिलीपाइन के टापुओं पर है। मैंने तुम्हें अपने पहले खत में बताया था कि किस तरह अमेरिका ने इन टापुओं पर स्पेन की लड़ाई के बाद कब्ज़ा कर लिया था। १८९८ ई० में अटलांटिक सागर के क्यूबा नामक टापू के बारे में यह लड़ाई शुरू हुई थी। क्यूबा आजाद होगया, लेकिन यह आजादी सिर्फ़ नाम की है। क्यूबा और हैटी दोनों पर अमेरिका का नियंत्रण है।

कुछ वर्ष हुए, पनामा की नहर खुली। यह मध्य-अमेरिका की एक छोटी-सी पट्टी है, जो प्रशान्तसागर और अटलांटिक सागर को मिलाती है। ५० वर्ष से ज्यादा गुजरे, स्वेज़ नहर को बनानेवाले फर्डिनेण्ड डी लेसेप्स ने इसकी योजना बनाई थी; लेकिन वह बेचारे परेशानी में फँस गये और अमेरिकन लोगों ने इस नहर को बनाया। अमेरिकन लोगों को मलेरिया और पीतज्वर के कारण बहुत कठिनाई में पड़ जाना पड़ा, लेकिन इन लोगों ने इन बीमारियों को मिटा देने का इरादा कर लिया था और उसमें ये सफल रहे। जिन-जिन जगहों पर मलेरिया के मच्छर पैदा होते थे, उनको और बीमारी फैलाने के दूसरे सारे जरियों को इन्होंने मिटा दिया और नहर के क्षेत्र को बिलकुल स्वास्थ्यवर्द्धक बना दिया। यह नहर पनामा के नन्हे-से प्रजातन्त्र के अन्दर है। लेकिन

संयुक्तराष्ट्र का इस नहर पर भी नियंत्रण है, और पनामा के छोटे-से प्रजातन्त्र पर भी । अमेरिका के लिए यह नहर बड़े फायदे की चीज है, नहीं तो जहाजों को दक्षिण अमेरिका के चारों ओर घूमकर जाना पड़ता । लेकिन फिर भी पनामा नहर का उतना महत्व नहीं, जितना स्वेज नहर का है ।

इस तरह संयुक्तराष्ट्र दिन-दिन मजबूत और अधिक दौलतमन्द होता गया । इस देश ने बहुत-सी चीजें पैदा कीं—जैसे करोड़पति लोग और आकाशचुम्बी महल । अमेरिकन लोगों ने बहुत-सी बातों में योरप की बराबरी करली और उससे आगे भी बढ़ गये । व्यावसायिक दृष्टि से ये लोग संसार की प्रमुख क्राँम होगये, और इनके यहां के मजदूरों के रहन-सहन का ढंग और देशों की बनिस्बत ऊँचा होगया । इस खुशहाली की वजह से १९वीं सदी के इंग्लैण्ड के समान इस देश में साम्यवाद और दूसरे उग्र विचारों को प्रोत्साहन नहीं मिला । दो-चार अपवादों को छोड़कर अमेरिका के मजदूर बहुत ठंडे और झगड़ों से अलग रहनेवाले थे । यहांके मजदूरों को दूसरी जगहों की बनिस्बत बेहतर मजदूरी मिलती है, इसलिए ये लोग भविष्य की संदेह से भरी हुई बेहतरी की उम्मीद में वर्तमानकाल के अपने निश्चित सुखों को ख़तरे में क्यों डालें ? अमेरिका के मजदूरों में ज्यादातर इटैलियन और दूसरे 'डागो' वर्ग के लोग थे (जैसा कि उन्हें हिकारत के लफ्जों में कहा जाता था) । ये लोग कमजोर और असंगठित थे और नफ़रत की नज़र से देखे जाते थे । जिन मजदूरों की तनख़्वाहें ज्यादा थीं, वे भी इन 'डागो' से अपनेको अलग और ऊँचा समझते थे ।

अमेरिका की राजनीति में दो दल पैदा हुए । एक 'रिपब्लिकन' (जनतन्त्रवादी) और दूसरा 'डेमोक्रेटिक' (प्रजासत्तावादी) । इंग्लैण्ड के समान, और बहुत हद तक उससे भी ज्यादा, यहां ये दोनों दल दौलतमन्दों के प्रतिनिधि थे । इनमें उसूलों का कोई विशेष झगड़ा नहीं था । इसे अगर नागनाथ और साँपनाथ का उदाहरण कहा जाय तो अनुचित न होगा ।

जब महायुद्ध आरम्भ हुआ तो यह हालत थी और अन्त में अमेरिका भी खिंचकर लड़ाई के भँवर में जा पड़ा ।

आयरलैण्ड और इंग्लैण्ड के बीच संघर्ष के सातसौ वर्ष

४ मार्च, १९३३

आओ, अब अटलांटिक महासागर फिर पार करके पुरानी दुनिया में वापस चलें। मोटर या हवाई जहाज से आते हुए मुसाफिर को पहला मुल्क जो मिलता है, वह आयरलैण्ड है। इसलिए हम यहीं अपनी पहली मंजिल रखेंगे। यह हरा-भरा और सुन्दर टापू योरोप के सबसे आखिरी पश्चिमी छोर पर अटलांटिक सागर में स्थित है। यह टापू छोटा-सा है और संसार के इतिहास की मुख्य धाराओं से दूर जा पड़ा है। लेकिन यद्यपि यह नन्हा-सा है, नगर इसका इतिहास अद्भुत और दिलचस्प घटनाओं से भरा है और पिछली अनेक सदियों से यह क्रीमी आजादी की लड़ाई में जवरदस्त क्रुवानो की भावना और न थकनेवाली बहादुरी का स्यूत देता आया है। एक नज़दीकी ताक़तवर राष्ट्र के खिलाफ़ अपनी इस लड़ाई में आयरलैण्ड ने धीरज का आश्चर्यजनक नमूना दुनिया के सामने रखा है। साढ़े सात सौ बरस से ज्यादा गुज़रे, जब यह लड़ाई शुरू हुई थी और आज तक ख़त्म नहीं हुई। हम ब्रिटिश साम्राज्यवाद की अनली सूरत चीन, हिन्दुस्तान और दूसरी जगहों में देख चुके हैं, लेकिन आयरलैण्ड तो इसका शिकार बहुत पहले से हो रहा है। फिर भी इस देश ने कभी इस साम्राज्यवाद के सामने ख़ुशी से सिर नहीं झुकाया और क़रीब-क़रीब हरेक पीढ़ी में इंग्लैण्ड के खिलाफ़ बगावत करता रहा। इस देश के बहादुर पुत्रों ने स्वतंत्रता के लिए लड़ते-लड़ते प्राण दिये, या अंग्रेज़ अफ़सरों ने उन्हें फांसी पर लटका दिया। आयरिश लोगों की काफ़ी तादाद अपनी मातृ-भूमि को, जिसे वे बेहद चाहते थे, छोड़कर दूसरे देशों में जा बसी। बहुत-से इंग्लैण्ड से लड़नेवाली विदेशी फौजों में भरती होगये, ताकि वे उस मुल्क के खिलाफ़ अपनी ताक़त लगा सकें जिसने उनकी मातृभूमि को दबा रखा था और जो उसपर आत्याचार कर रहा था। आयरलैण्ड के बहुतेरे निर्वासित यानी जलावतन लोग दूर-दूर देशों में फैल गये और जहाँ-जहाँ ये गये वहाँ-वहाँ अपने दिल में आयरलैण्ड का कुछ हिस्सा लेते गये।

दुःखी लोग तथा सताई हुई, पामाल और लड़ाई में फँसी हुई क़ौम, यानी वे तमाम लोग जो असन्तुष्ट हैं और जिन्हें वर्तमान में कुछ भी आनन्द नहीं, पुराने ज़माने की याद में सुख अनुभव करते हैं और उसी बीते ज़माने की याद में शान्ति की तलाश करते हैं। वे अपने गुज़रे ज़माने के बारे में बढ़ा-चढ़ाकर कहते और सोचते हैं और अपने बीते बड़प्पन की याद करके सन्तोष पाते हैं। जब वर्तमान काल दुःख के अँधेरे से भरा होता है, गुज़रे ज़माने से सन्तोष और उत्साह पैदा करनेवाला आश्रय मिल जाता है। पुरानी शिकायतें क़ायम रहती हैं और लोग उनको नहीं भूलते। गुज़रे हुए ज़माने

की ओर इस तरह किसी राष्ट्र का बराबर देखते रहना उसकी तन्दुरुस्ती की निशानी नहीं है। स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ देश वर्तमान काल में कर्म करते हैं और अपने भविष्य की तरफ देखते हैं, लेकिन जो आदमी या देश आजाद नहीं वह स्वस्थ भी नहीं होता। उसके लिए यह स्वाभाविक ही है कि वह बीते हुए जमाने की तरफ नज़र रखे और एक हद तक गुज़रे जमाने में अपनी जिन्दगी का एक हिस्सा बितावे।

इसीलिए आयरलैंड अभी तक अपने भूतकाल में अपनी जिन्दगी गुज़ारता है और आयरिश लोग अभी तक अपने उस गुज़रे जमाने की याद में, जबकि वे आजाद थे, खुशी महसूस करते हैं। अपने देश की आजादी की अनेक लड़ाइयाँ और उसकी पुरानी शिकायतें उन्हें साफ़-साफ़ याद हैं। उन्हें आज से चौदह सौ बरस पुराना जमाना याद आता है—ईसा की छठी सदी का, जब पश्चिमी योरप के लिए आयरलैंड विद्या का केन्द्र था और जब यहाँ दूर-दूर से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। उस वक्त रोमन साम्राज्य का पतन हो चुका था; बंडाल और हूण लोग रोमन सभ्यता को चकनाचूर कर चुके थे। कहा जाता है कि उस जमाने में आयरलैंड एक ऐसा मुल्क था, जिसने योरप में विद्या का पुनरुद्धार होने तक संस्कृति की ज्योति जगाये रखी। ईसाई धर्म पहले आयरलैंड में आया। कहा जाता है कि आयरलैंड के आदि-सन्त सेण्ट पैट्रिक ईसाई मत को आयरलैंड लाये थे। आयरलैंड से ही यह धर्म उत्तरी इंग्लैंड में फैला। आयरलैंड में बहुत-से मठ खुले। हिन्दुस्तान के पुराने आश्रमों और बौद्ध विहारों की तरह वे भी विद्या के केन्द्र थे, जहाँ खुली हवा में शिक्षा दी जाती थी। इन्हीं मठों से उत्तरी और पश्चिमी योरप में ईसाई मत का नया धर्म-प्रचार करने के लिए मिशनरी लोग जाते थे। आयरिश मठों में कुछ साधुओं ने बहुतेरी अच्छी किताबें लिखीं। डबलिन में आज भी इसी तरह की एक सुन्दर पाण्डुलिपि मौजूद है, जिसे 'बुक आफ केल्स' कहते हैं और जो अन्दाज़न बारह सौ बरस हुए तब लिखी गई थी।

छठी सदी से इधर दो-तीन सौ बरस तक के युग को बहुतेरे आयरिश लोग आयरलैंड का सतयुग समझते हैं, जबकि गैलिक संस्कृति अपनी पूरी ऊँचाई पर थी। शायद बहुत जमाना गुज़र जाने की वजह से यह युग ख़ास तौर से दिलचस्प मालूम होता है और जितना महान् यह असल में था उससे कहीं ज्यादा महान् दिखाई देता है। उस वक्त आयरलैंड कई जातियों में बँटा हुआ था और वे जातियाँ बराबर आपस में लड़ा-भिड़ा करती थीं। आपस में झगड़ते रहना, हिन्दुस्तान की तरह, आयरलैंड की भी कमज़ोरी थी। इसके बाद डेन्स^१ और नार्समैन^२ आये और उन्होंने इंग्लैंड और

१. डेन्स—डेनमार्क के लोग।

२. नार्समैन—स्केण्डीनेविया का निवासी।

फ्रांस की तरह आयरिश लोगों को भी हरा कर देश के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। ग्यारहवीं सदी के शुरू में 'वियान चोहना' नाम के मजहूर आयरिश राजा ने ऐंग्लो लोगों को हराकर कुछ चत के लिए आयरलैंड को एक सूत्र में बाँध लिया। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद यह जाति फिर बिखर गई।

तुम्हें याद होगा कि नार्मनों ने विजेता 'विलियम' की मातहत में ग्यारहवीं सदी में इंग्लैंड को जीता था। इन्हीं ऐंग्लो-नार्मनों ने सौ बरस के बाद आयरलैंड पर धावा किया और जिस हिस्से पर कब्जा किया उसका नाम 'पेल' रखवा। शायद इसीसे अंग्रेजी भाषा में 'वियांड वि पेल' वाक्य प्रचलित हुआ है। 'पेल' के बाहर यानी जाति से अलग। ११६९ ई० के इस ऐंग्लो-नार्मन हमले ने गैलिक संस्कृति को सतत धक्का पहुँचाया और इसी समय से आयरिश जातियों के साथ बराबर लड़ाई की शुरुआत होती है। ये लड़ाइयाँ, जो करीब सौ बरस के जारी रहीं, बहुत ज्यादा जंगली और क्रूर थीं। ऐंग्लो-नार्मन लोग, जिन्हें अब अंग्रेज कहना चाहिए, आयरिश लोगों को अर्द्ध-सभ्य जाति समझकर हमेशा नफ़रत की नज़र से देखते रहे। इन दोनों में जाति का भेद था ही—अंग्रेज लोग ऐंग्लो-सैक्सन जाति के थे और आयरिश केण्ट थे—बाद को इनमें धर्म का भी भेद पैदा होगया। अंग्रेज और स्काच प्रोटेस्टेण्ट होगये और आयरिश लोग अपने पुराने धर्म रोमन कैथलिक पर ही क़ायम रहे। इसलिए अंग्रेज और आयरिश लोगों की इन लड़ाइयों में जातीय (Racial) और मजहबी लड़ाइयों की पूरी कटुता पाई जाती है। अंग्रेजों ने इरादा करके दोनों क़ौमों के मिलाप को रोका। एक क़ानून भी इस सम्बन्ध में बना—'किलकैनी का क़ानून', जिसके मुताबिक अंग्रेज और आयरिश में अन्तर्जातीय विवाह रोक दिया गया।

आयरलैंड में एक शहर के बाद दूसरा शहर होता था और ये सब कठोर निर्दयता के साथ दबा दिये जाते थे। आयरिश लोग स्वभावतः अपने विदेशी शासकों और जालिमों से नफ़रत करते थे और जब कभी इन्हें मौक़ा मिलता, और बेमौक़ा भी, ये लोग अंग्रेजों के खिलाफ़ विद्रोह कर बैठते थे। "इंग्लैंड की मुसीबत आयरलैंड का मुअवसर है," यह पुरानी कहावत है। राजनैतिक और धार्मिक कारणों से आयरलैंड अक्सर इंग्लैंड के दुश्मनों की, जैसे फ़्रांस और स्पेन की, तरफ़दारी करता रहता था। इससे अंग्रेजों को बहुत श्रोध होता था और वे समझते थे मानों किसीने पीछे से कटार भोंक दी। इसीलिए वे हर तरह के जुल्म के साथ इनसे बदला लेते थे।

१. नार्मन—स्कैण्डिनेविया की एक जाति जो दसवीं सदी की शुरुआत में उत्तरी फ़्रांस में आकर बस गई और जिसने वहाँ नार्मण्डी की डची का निर्माण किया। इसका मामूली अर्थ नार्मण्डी का वाशिनदा है।

रानी एलिजाबेथ के जमाने में, सोलहवीं सदी में, यह तय किया गया कि आयरलैंड के सरकश वाशिनदों की बारी ताकत को तोड़ने के लिए इनमें अंग्रेज जमींदार क्रायम कर दिये जायं, जो इन्हें बराबर दबाये रहें। इसलिए आयरलैंड की जमीन जब्त करली गई और वहाँ के पुराने जमींदारों की जगह पर अंग्रेज जमींदार क्रायम किये गये। इस तरह आयरलैंड किसानों का राष्ट्र बन गया, जिनके जमींदार विदेशी थे। ये जमींदार लोग आयरिश लोगों के लिए सैकड़ों बरस गुजर जाने पर भी विदेशी ही बने रहे।

रानी एलिजाबेथ के बारिस जेम्स प्रथम ने आयरिश लोगों की शक्ति तोड़ने की कोशिश में एक कदम और आगे बढ़ाया। उसने यह निश्चय किया कि आयरलैंड में विदेशी लोगों का वाक्कायदा उपनिवेश बना दिया जाय और इसलिए बादशाह ने उत्तरी आयरलैंड में अलस्टर के छहों जिलों की सारी जमीन जब्त करली। जमीन मुफ्त में मिलने लगी और लेभगुओं के झुण्ड-के-झुण्ड स्काटलैंड और इंग्लैंड से वहाँ पहुँच गये। इंग्लैंड और स्काटलैंड से आये हुए ये लोग जमीन लेकर यहीं बस गये और किसानी करने लगे। उपनिवेश की इस प्रवृत्ति को सफल बनाने के लिए लन्दन शहर से भी मदद गाँगी गई, और लन्दन वालों ने तो 'अलस्टर की बस्तियाँ' (Ulster Plantations) के लिए एक खास संस्था ही बना दी थी। इसी वजह से उत्तर का 'डैरी' नाम का शहर आज 'लन्दन डैरी' कहलाता है।

इस तरह अलस्टर आयरलैंड में ब्रिटेन का एक पैबन्द बन गया और इसमें कुछ आश्चर्य नहीं अगर आयरिश लोगों को इस बात से बड़ा गुस्सा पैदा होता हो। ये नये अलस्टर आयरलैंड के लोगों से नफ़रत करते थे और उन्हें नीच समझते थे। इंग्लैंड की यह कितनी आश्चर्यजनक चालाकी की साम्राज्यवादी हरकत थी कि उसने आयरलैंड के इस तरह एक-दूसरे के खिलाफ़ दो हिस्से कर दिये। अलस्टर की गुत्थी अभी तक, तीन सौ बरस गुजर जाने पर भी, नहीं सुलझ सकी है।

अलस्टर में इस उपनिवेश के क्रायम होजाने के बाद इंग्लैंड में चार्ल्स प्रथम और पार्लमेण्ट के दरमियान गृह-युद्ध शुरू हुआ। पार्लमेण्ट की तरफ़ प्रोटेस्टैंट और प्यूरिटन थे; कैथलिक आयरलैंड स्वभावतः बादशाह की तरफ़ झुका। अलस्टर ने पार्लमेण्ट का साथ दिया। आयरिश लोग डरते थे और डरने की वजह भी थी कि प्यूरिटन लोग कैथलिक धर्म को नष्ट कर देंगे। इसलिए १६४१ में इन लोगों ने एक बहुत बड़ा विद्रोह खड़ा कर दिया। यह विद्रोह और इसका दमन पहले के विद्रोहों और दमन की बनिस्वत कहीं अधिक जंगली और क्रूर था। आयरलैंड के कैथलिक लोगों ने प्रोटेस्टैंट लोगों को बेरहमी से क़त्ल किया था। कामबेल ने इसका भयंकर बदला लिया।

आयरिश लोगों का कई दफ्ता क़त्लेआम हुआ, खास कर कैथलिक पादरियों का, और आयर्लैण्ड में आजतक ग्रामवेल का नाम कटुता के साथ याद किया जाता है ।

इस जुलम और बेरहमी के होते हुए भी एक पीढ़ी बाद आयर्लैण्ड में फिर चगावत और घरेलू लड़ाई उठ खड़ी हुई, जिसकी दो घटनायें मशहूर हैं । एक लन्दन-डेरी का और दूसरे लिमेरिक का घेरा । १६८८ ई० में आयर्लैण्ड के कैथलिक लोगों ने लन्दनडेरी के प्रोटेस्टेंट लोगों को घेर लिया । प्रोटेस्टेंट लोगों ने बहुत बहादुरी से मुकाबिला किया, हालांकि उनके पास खाने की सामग्री भी नहीं थी और वे भूखों मर रहे थे । अंग्रेज़ी जहाज़ आखिर चार महीने के घेरे के बाद खाने की सामग्री और सहायता लाये ।

१६९० ई० में लिमेरिक में बिलकुल इसका उलटा हुआ । वहाँ कैथलिक मत माननेवाले आयरिश लोगों को अंग्रेज़ों ने घेर लिया था । इस घेरे का वीर पुरुष पैट्रिक सार्सफील्ड था, जिसने बहुतसी दयकतों के होते हुए भी बहुत ज्ञान के साथ लिमेरिक की हिफ़ाज़त की । इस लड़ाई में आयर्लैण्ड की स्त्रियाँ भी लड़ें और आयर्लैण्ड के गाँवों में आजतक सार्सफील्ड और उसके बहादुर जत्थे की वीरता के गाने गैलिक भाषा में गाये जाते हैं । सार्सफील्ड को अख़ीर में यह बहादुराना लड़ाई बन्द करनी पड़ी; लेकिन तब जब अंग्रेज़ों ने उससे सम्मानपूर्ण सुलह की । लिमेरिक के इस सुलहनामे की एक शर्त यह थी कि आयरिश कैथलिकों को पूरी नागरिक और मज़हबी आज़ादी दी जायगी ।

लिमेरिक के इस सुलहनामे को अंग्रेज़ों ने, या यों कहो आयर्लैंड में बसे हुए अंग्रेज़ ज़मींदार के कुटुम्बों ने, तोड़ डाला । ये प्रोटेस्टेंट ज़मींदार डबलिन की मातहत पार्लमेण्ट पर हावी थे । लिमेरिक में कस्मिया वादा करने के बाद भी, इन्होंने कैथलिक लोगों को नागरिक या मज़हबी आज़ादी देने से इन्कार कर दिया । उलटे इन्होंने कुछ खास क़ानून ऐसे बना दिये जिससे कैथलिक लोगों के साथ अन्याय होता था और जिससे आयर्लैंड के ऊन के व्यवसाय का सत्यानाश होगया । कैथलिक किसान बेरहमी से कुचल दिये गये । याद रखो कि यह फ़ार्वार्ड चन्द विदेशी प्रोटेस्टेंट ज़मींदारों ने जनता की बहुत बड़ी तादाद के खिलाफ़ की थी, जो कैथलिक थी और जिसमें ज्यादातर किसान थे । लेकिन सब शक्ति तो इन अंग्रेज़ ज़मींदारों के हाथ में थी और ये लोग अपनी रियासतों से दूर रहते थे और अपने किसानों को इन्होंने अपने कारिन्दों और नौकरों की बेरहमी से भरी लालच के हाथ में छोड़ दिया था ।

लिमेरिक की कहानी तो पुरानी है; लेकिन वादाखिलाफ़ी के कारण क्रोध और विद्वेष की जो आग उस वक़्त भड़की थी, वह अभीतक शान्त नहीं हुई है और आज भी

आयरलैंड के राष्ट्रीय लोगों के सामने लिमेरिक की घटना अंग्रेजों की धोखाबाजी की जबरदस्त मिसाल है। इस वादाखिलाफी, असहिष्णुता, दमन और जमींदारों के अत्याचार के कारण उस वक्त आयरलैंड की बहुत काफ़ी जनता दूसरे देशों में जा बसी। आयरलैंड के चुने-चुने नवयुवक विदेश चले गये और किसी भी ऐसे देश की फौज में भर्ती होगये जो अंग्रेजों से युद्ध कर रहा हो। जहाँ भी कहीं अंग्रेजों के खिलाफ़ लड़ाई होती, ये आयरिश नवयुवक वहाँ जरूर पहुँच जाते थे।

जोनाथन स्विफ्ट, जिसने 'गुलीवर्स ट्रावेल' नामक पुस्तक लिखी है, इसी युग में हुआ है। यह १६६७ से १७४५ तक ज़िन्दा रहा। इसने अपने देशवासियों को एक सलाह दी है। इस सलाह से अंग्रेजों के प्रति इसके क्रोध की मात्रा का अन्दाज़ लगाया जा सकता है। इसकी सलाह यह थी—“इनके (अंग्रेजों के) कोयले को छोड़कर बाक़ी हरेक अंग्रेजी चीज़ जला डालो।” डबलिन में सेंट पैट्रिक गिरजे में चन्द पंक्तियाँ, जो जोनाथन स्विफ्ट की क़ब्र पर लिखी हैं, इससे भी ज़्यादा कटु हैं। ये पंक्तियाँ शायद उसने खुद ही लिखी थीं।

Here lies the body of
Jonathan Swift
For thirty years Dean
Of this Cathedral
Where savage indignation can
No longer gnaw his heart.
Go, traveller, and
Imitate, if you can, one who
Played a man's part in defence
Of liberty.

“यहाँ जोनाथन स्विफ्ट का शरीर पड़ा हुआ है। वह ३० वर्ष तक इस गिरजे का डीन (अधिकारी) था। जंगली रोप उसके हृदय को काट न सका। हे यात्री ! जाओ और कर सको तो उस आदमी का अनुकरण करो, जिसने आज़ादी की रक्षा में एक मर्द का पार्ट अदा किया है।”

१७७४ ई० में अमेरिका की आज़ादी की लड़ाई छिड़ी, और एटलांटिक के पार अंग्रेज़ी फ़ौज का भेजना जरूरी होगया। आयरलैंड में कोई ब्रिटिश फ़ौज न रह गई और उधर फ़्रान्सीसी हमले की चर्चा होने लगी, क्योंकि फ़्रान्स ने भी हॉलैंड के खिलाफ़ लड़ाई शुरू कर दी थी। इसलिए आयरिश कैथलिक और प्रोटेस्टेण्ट दोनों ने रक्षा के लिए वालंटियर (स्वयंसेवक) दल बनाना शुरू कर दिया। कुछ अरसे के लिए ये लोग अपना पुराना झगड़ा भूल गये; आपस में सहयोग करने लगे और इनको अपनी शक्ति का पता चल गया। एक दूसरे विद्रोह का ख़तरा इंग्लैंड के सामने खड़ा होगया और, इस डर से कि कहीं आयरलैंड भी अमेरिका की तरह हाथ से न निकल जाय, इंग्लैंड ने

आयरलैंड को स्वतन्त्र पार्लमेण्ट देदी। इस तरह उसूल की दृष्टि से तो आयरलैंड, ब्रिटिश बादशाह के अधीन, इंग्लैंड से आजाद होगया, लेकिन आयरिश पार्लमेण्ट वही पुरानी और ज़मींदारों की संकीर्ण संस्था रही, जिसमें केवल प्रोटेस्टेण्ट शामिल थे और जो कैथलिक लोगों पर पहले दबाव डालते रहे थे। कैथलिक लोगों पर अभी तक अनेक प्रकार की बन्दिशें थीं। हाँ, फ़र्क सिर्फ़ इतना जरूर होगया था कि अब कैथलिक और प्रोटेस्टेण्ट एक-दूसरे के ज्यादा नज़दीक आते जाते थे। इस पार्लमेण्ट के नेता हेनरी ग्रेटेन, जो स्वयं प्रोटेस्टेण्ट थे, यह चाहते थे कि कैथलिक लोगों पर जो बन्दिशें हैं, वे हटा दी जायें; लेकिन इस बात में उनको बहुत कम कामयाबी हासिल हुई।

इसी दरमियान फ्रान्स में क्रान्ति होगई, और आयरलैंड को उससे बहुत आशायें बँध गईं। आश्चर्य तो यह है कि इस क्रान्ति का स्वागत कैथलिक और प्रोटेस्टेण्ट दोनों ने किया, जो अब धीरे-धीरे एक-दूसरे के बहुत नज़दीक होते जाते थे। 'संयुक्त आयरिश' (United Irishmen) नाम की एक संस्था खुली, जिसका उद्देश्य यह था कि कैथलिक और प्रोटेस्टेण्टों में मेल-जोल पैदा कराया जाय और कैथलिक लोगों को आज़ादी दिलाई जाय। सरकार ने इस 'यूनाइटेड आयरिशमेन' नाम की संस्था को पसन्द नहीं किया और यह दबा दी गई। इसलिए हस्वमामूल होनेवाली अनिवार्य क्रान्ति १७९८ ई० में फिर भड़क उठी। यह क्रान्ति पहले की क्रान्तियों की तरह अलस्टर और देश के दूसरे हिस्सों के दरमियान की मजहबी लड़ाई नहीं थी। यह एक राष्ट्रीय क्रान्ति या बराबत थी, जिसमें कैथलिक और प्रोटेस्टेण्ट दोनों शामिल थे। इस क्रान्ति को भी अंग्रेज़ों ने दबा दिया और इसके वीर पुरुष उल्फ टोन को, बिद्रोही होने के अपराध में, फांसी पर लटका दिया गया।

इस तरह अब यह स्पष्ट था कि आयरलैंड में एक स्वतन्त्र पार्लमेण्ट बना देने से आयरिश लोगों की स्थिति में कोई फ़र्क नहीं आया था। अंग्रेज़ी पार्लमेण्ट भी उस समय एक संकीर्ण और दूषित संस्था थी, जिसमें रिश्तत देकर लोगों का चुनाव हुआ करता था और जिसकी बागडोर ज़मींदारों का एक छोटा-सा गुट और चन्द बड़े-बड़े व्यापारी अपनी मुट्ठी में रखते थे। आयरिश पार्लमेण्ट में भी यही सब दोष पाये जाते थे। इसके अलावा उसमें ख़ास ख़राबी यह थी कि वह पार्लमेण्ट कैथलिक देश में क़ायम होते हुए भी मुट्ठीभर प्रोटेस्टेण्टों के हाथ में थी। ब्रिटिश सरकार ने यह निश्चय किया कि आयरिश पार्लमेण्ट को ख़त्म कर दिया जाय और आयरलैंड को ब्रिटेन से मिला दिया जाय। आयरलैंड में इस प्रस्ताव का ज़ोरों से विरोध किया गया, लेकिन डबलिन की पार्लमेण्ट के मेम्बरों ने बहुत बड़ी-बड़ी रक़में रिश्तत लेकर अपने ही वोट से अपनी पार्लमेण्ट को ख़त्म कर दिया। सन् १८०० ई० में "ऐक्ट आफ यूनियन"

(Act of Union) पास हुआ और इस तरह ग्रेटन की चन्द दिनों की पार्लमेण्ट का खात्मा हो गया। उसकी जगह पर अब चुने जाकर कुछ आयरिश सदस्य ब्रिटिश पार्लमेण्ट में लन्दन जाने लगे।

इस दूषित आयरिश पार्लमेण्ट के खात्मे से शायद बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ, सिवा इसके कि यह मुमकिन था कि कुछ दिन के बाद यह पार्लमेण्ट बेहतर हो जाती। लेकिन यूनियन ऐक्ट ने एक बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया और शायद यही नुकसान पहुँचाने के लिए वह बनाया भी गया था। प्रोटेस्टेण्ट और कैथलिकों के दरमियान उत्तर और दक्षिण में मेल-जोल की जो प्रवृत्ति चल रही थी वह खत्म होगई। प्रोटेस्टेण्ट अलस्टर ने बाक़ी आयरलैंड से मुँह मोड़कर अपना रुख दूसरी तरफ़ कर लिया और ये दोनों हिस्से एक-दूसरे से अलग होकर अपने-अपने रास्ते पर चल पड़े। इन दोनों में एक दूसरा फ़र्क़ और पैदा होगया। अलस्टर ने इंग्लैंड के ढंग पर आधुनिक व्यवसाय को अपना लिया। आयरलैंड के बाक़ी हिस्से में खेती का ही जोर रहा; लेकिन खेती भी इस प्रदेश में तरक्की नहीं कर सकी, क्योंकि कृषि-सम्बन्धी क़ानून दूषित थे। आयरिश जनता दूसरे देशों में जाकर बराबर बस रही थी, इसलिए उत्तर तो व्यावसायिक हो गया लेकिन दक्षिण और पूर्व और खास तौर से पश्चिम व्यावसायिक दृष्टि से पिछड़े और मध्य युग के जैसे ही बने रहे।

‘ऐक्ट आफ यूनियन’ के खिलाफ़ भी बगावत हुई। तेजस्वी नौजवान राबर्ट इम्मेट इस क्षणिक बलवे का नेता था, और इसने अपने अनेक पूर्वज देशवासियों के समान फ़ांसी के तख्ते पर प्राण दिये।

आयरिश सदस्य ब्रिटिश पार्लमेण्ट के ‘हाउस आफ कामन्स’ यानी साधारण सभा में जाते थे, लेकिन कोई कैथलिक नहीं जा सकता था। कैथलिक लोगों को न तो आयरलैंड और न इंग्लैंड में पार्लमेण्ट के सदस्य बनने का हक़ था। ये बन्दिशें १८२९ ई० से टूटीं और तबसे ही कैथलिक लोग ब्रिटिश पार्लमेण्ट में बैठने के अधिकारी समझे गये। डैनियल ओ कॉनेल नाम के आयरिश नेता ने ये बन्दिशें तुड़वाई थीं, इसलिए उसे ‘लिवरेटर’ यानी ‘उद्धारक’ की पदवी दी गई। धीरे-धीरे एक दूसरी भी तब्दीली हुई। वोट देने का हक़ ज्यादा लोगों को दिया गया। चूँकि आयरलैंड इंग्लैंड से मिला दिया गया था, इसलिए इन देशों पर एक ही क़ानून लागू था। इस कारण १८३२ ई० का मशहूर ‘रिफ़ार्म बिल’ आयरलैंड और इंग्लैंड दोनों पर लागू हुआ और इसी प्रकार बाद का मताधिकार यानी राय देने का क़ानून भी। इस तरह ब्रिटिश कामन्स सभा में आयरिश सदस्य का रूप बदलने लगा। जमींदारों के प्रतिनिधि से बदलकर वह कैथलिक किसानों और आयरिश राष्ट्रीयता का प्रतिनिधि होगया।

शरीबी के कारण, जमींदारों से थोड़ा और लगान से दबे हुए आयर्लैंड के किसानों का मुख्य भोजन आलू ही था। ये लोग क़रीब-क़रीब सिर्फ़ आलू ही खाकर ज़िन्दगी बसर करते थे और आजकल के हिन्दुस्तानी किसानों की तरह इनके पास भी संचय का अभाव था। इनके पास कुछ भी नहीं बचता था। जिससे संकट के समय ये सहारा पा सकें। ये लोग ज़िन्दगी और मौत की सीमा पर अपनी ज़िन्दगी गुज़ारते थे और इनमें प्रतिरोध की कोई ताक़त बाक़ी नहीं बची थी। १८६४ ई० में आलू की फ़सल नष्ट होगई, जिसके कारण इस देश में ज़बरदस्त अकाल पड़ गया। लेकिन अकाल के होते हुए भी ज़मींदारों ने लगान वसूल किया और जो न दे सके उन किसानों को खेतों से बेदखल कर दिया। आयरिश लोगों की बहुत बड़ी तादाद अपनी मातृभूमि छोड़कर अमेरिका चली गई, और आयर्लैंड क़रीब-क़रीब उजड़ गया। बहुत-से खेत बेजुते पड़े रहे और चरागाह बन गये।

जोते और बोये जा सकनेवाले खेतों का भेड़ों के लिए चरागाह बनते रहने का यह सिलसिला आयर्लैंड में क़रीब सौ बरस से ज्यादा ब़क्त तक जारी रहा और अभी हम लोगों के ज़माने तक चलता रहा है। इसकी ख़ास वजह यह थी कि इंग्लैंड में ऊनी कपड़ों के कारख़ाने बढ़ रहे थे। जितनी ज्यादा मशीनें काम में आती थीं, उत्पत्ति उतनी ही बढ़ती थी और ऊन की उतनी ही ज्यादा ज़रूरत पड़ती थी। इसलिए आयर्लैंड के ज़मींदारों को खेतों की बनिस्वत, जिनमें किसान काम करते थे, चरागाहों से ज्यादा मुनाफ़ा था जिनमें कि भेड़ें चरती थीं। चरागाहों में बहुत कम आदमियों की ज़रूरत पड़ती है। इनमें तो सिर्फ़ चन्द मज़दूरों से, जो भेड़ों की निगरानी कर सकें, काम चल जाता है। इसलिए खेती करनेवाले मज़दूर ज़मींदारों के लिए बेकार हो गये और उन्होंने अपने यहांसे किसानों को निकाल दिया। इस तरह आयर्लैंड में, जिसकी आबादी बहुत कम थी, हमेशा बहुत-से फ़ाजिल और बेरोज़गार लोग पाये जाते थे। इस कारण आबादी के घटने का सिलसिला भी जारी रहा। आयर्लैंड बस 'व्यवसायी' इंग्लैंड को कच्चा माल पहुँचाने का एक क्षेत्र बन गया। खेतों के चरागाह बनने का पुराना सिलसिला अब उलट गया है और हल को अब फिर अपना पुराना स्थान मिल रहा है। आश्चर्य तो यह है कि यह स्थिति उस व्यापारिक युद्ध का नतीजा है, जो पारसाल १९३२ ई० से इंग्लैंड और आयर्लैंड के दरमियान जारी है।

अन्तीसवीं सदी के ज्यादातर हिस्से में खेती की समस्या, अनुपस्थित यानी दूर रहनेवाले ताल्लुक़ेदारों के शिकार दुःखी किसानों की दुर्वशा, आयर्लैंड की मुख्य समस्या रही है। अन्तीर में ब्रिटिश सरकार ने यह निश्चय किया कि अनिवार्य तरीक़े से सब ज़मींदारियाँ ख़रीद कर और किसानों में बाँटकर ज़मींदारों को बिलकुल

ख़त्म कर दिया जाय। ज़मींदारों को कोई नुकसान नहीं रहा। उन्हें सरकार से अपनी ज़मींदारी के पूरे दाम मिल गये। किसानों को ज़मीन मिली; लेकिन क़ीमत के बोझ के साथ। किसानों को इन खेतों के दाम एकदम नहीं देने पड़े। तब यह हुआ कि छोटी-छोटी सालाना क्रिस्तों में क़ीमत अदा की जाय। ये क्रिस्तें अभी तक पूरी अदा नहीं हो सकी हैं और इनके बारे में इंग्लैंड और आयरलैंड के दरमियान आजकल बहस-मुवाहसा चल रहा है।

१७९८ ई० की क़्रांती बराबत के बाद सौ बरस से ज्यादा तक आयरलैंड में कोई बड़ी बराबत नहीं हुई। पहले की सदियों के प्रतिकूल आयरलैंड की उन्नीसवीं सदी इस बार-बार होनेवाली घटना से ख़ाली रही; लेकिन इसका कारण यह नहीं था कि लोगों में सन्तोष की भावना थी। लोगों में पिछले विद्रोह की, भीषण दुष्काल की और निर्जनता की थकावट थी। इस सदी के पिछले आधे हिस्से में किसी हद तक लोगों का ध्यान ब्रिटिश पार्लमेण्ट की तरफ़ झुका था, और उनको यह आशा बँधी थी कि शायद आयरिश सदस्य ब्रिटिश पार्लमेण्ट के जरिये कुछ काम कर सकेंगे। लेकिन बहुत-से आयरिश लोग ऐसे भी थे, जो इस बार-बार होनेवाली बराबत की परिपाटी ज़िन्दा रखना चाहते थे। उनका ख़याल था कि केवल इसी ढंग से आयरलैंड की आत्मा को स्वच्छ और अकलुषित रखा जा सकता है। अमेरिका में बसे हुए आयरिश लोगों ने आयरलैंड की आज़ादी के लिए एक संस्था खोली। ये लोग, जिन्हें 'फ़ेनियन' कहा जाता था, आयरलैंड में छोटे-छोटे विद्रोह कराया करते थे, लेकिन जनता से इनका भ्रंसर्ग नहीं था और ये लोग बहुत जल्द पस्त कर दिये गये।

अब इस ख़त को मुझे ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि लम्बा काफ़ी होगया है, हालांकि आयरलैंड की कहानी अभी तक ख़त्म नहीं हुई है।

: १४० :

आयरलैंड में होमरूल और सिनफेन

९ मार्च, १९३३

इतने सशस्त्र विद्रोहों के बाद और दुष्काल तथा दूसरी आफतों की वजह से, आयरलैंड आज़ादी हासिल करने के इन साधनों से कुछ थक-सा गया था। उन्नीसवीं सदी के दूसरे आधे हिस्से में जब आयरिश जनता को ज्यादा तादाद में वोट देने का अधिकार मिला, तब अनेक राष्ट्रीय आयरिश कामन्स सभा के सदस्य चुने गये। जनता उम्मीद करने लगी कि शायद यही लोग आयरलैंड की आज़ादी के लिए कुछ कर सकें,

और अब पुराने जमाने के सशस्त्र विद्रोह के वजाय आयरिश जनता पार्लमेण्टरी या वंद्य कामों की तरफ उम्मीद-भरी निगाह से देखने लगी ।

उत्तर के अलस्टर में और आयर्लैण्ड के बाक़ी हिस्सों में फिर भेदभाव पैदा होगया था । जातीय (Racial) और धार्मिक विषमता तो क़ायम ही थी; इसके अलावा आर्थिक असमानता ज्यादा स्पष्ट होगई । इंग्लैण्ड और स्काटलैण्ड की तरह अलस्टर भी व्यावसायिक देश होगया था, और यहाँके कारख़ानों में बहुत काफ़ी माल बनता था । देश का बाक़ी हिस्सा कृषि-प्रधान, मध्यकालीन, उजाड़ और शरीब था । आयर्लैण्ड में फूट पैदा कर देने की इंग्लैण्ड की पुरानी नीति बहुत काफ़ी सफल हो चुकी थी । इस नीति में इतनी सफलता हुई थी कि बाद को जब खुद इंग्लैण्ड ने इस नीति को बदलना चाहा, तो वह भी नाकामयाब रहा । आयर्लैण्ड की आजादी के रास्ते में सबसे बड़ा काँटा अलस्टर था । खुशहाल और प्रोटेस्टेण्ट अलस्टर को डर था कि आयर्लैण्ड के आजाद होने पर शरीब कैथलिक आयर्लैण्ड उसे हज़म कर जायगा ।

अब ब्रिटिश पार्लमेण्ट और आयर्लैण्ड में दो नये शब्द प्रचलित हुए । ये दो शब्द थे—होमरूल । आयर्लैण्ड ने अब 'होमरूल' माँगना शुरू किया । पिछले सात-सौ बरस की आजादी की माँग से यह माँग बहुत कम और जुदा थी । इसका मतलब यह था कि आयर्लैण्ड को एक मातहत पार्लमेण्ट दी जाय, जो स्थानीय मामलात का इन्तज़ाम करे और ख़ास-ख़ास महत्वपूर्ण विषयों पर ब्रिटिश पार्लमेण्ट का ही शासन जारी रहे । बहुतेरे आयरिश लोग आजादी की पुरानी माँग को इस तरह घटा देने के तरफ़दार नहीं थे । लेकिन देश बगावत और विद्रोहों से तंग आगया था, इसलिए उसने बलवा करने की बहुतेरी फुटकर कोशिशों में हिस्सा लेने से इन्कार कर दिया ।

ब्रिटिश कामन्स सभा में चार्ल्स स्टीवर्ट पारनेल नाम का एक आयरिश सदस्य था । यह देखकर कि ब्रिटिश पार्लमेण्ट के दोनों दल, कंज़र्वेटिव और लिबरल यानी अनुदार और उदार, आयर्लैण्ड की तरफ़ ज़रा भी ध्यान नहीं देते, इस शख्स ने निश्चय किया कि ऐसी बात की जाय, जिससे इन दोनों दलों का यह शरीफ़ाना पार्लमेण्टरी खेल चल ही न सके । इसलिए दूसरे आयरिश सदस्यों की मदद से इसने लम्बे-लम्बे भाषणों से और दूसरे विघ्न डालनेवाले और विलम्ब करनेवाले साधनों से पार्लमेण्ट की कार्रवाई में अड़ंगे लगाना शुरू किये । अंग्रेज़ लोग इस ढंग से बहुत नाराज़ हुए । वे कहते थे कि पारनेल का यह रवैया न तो पार्लमेण्टरी दृष्टि और न शराफ़त के ख़याल से उचित है । लेकिन पारनेल के ऊपर इन ऐतराज़ों का कोई असर नहीं हुआ । वह पार्लमेण्ट में अंग्रेज़ों के बनाये हुए क़ायदों के मुताबिक़ अंग्रेज़ी पार्लमेण्टरी शरीफ़ाना खेल खेलने नहीं आया था, वह तो आयर्लैण्ड की सेवा करने आया था; और अगर मामूली तरीक़ों से

वह इस उद्देश में सफल नहीं हो सकता था, तो असाधारण साधनों का सहारा लेने में वह कोई खराबी नहीं देखता था। जो हो, इस बात में तो वह जरूर कामयाब रहा कि आयरलैंड की तरफ उसने ध्यान आकर्षित करा दिया।

पारनेल ब्रिटिश कामन्स सभा में आयरिश होमरूल पार्टी का नेता होगया, और दोनों पुरानी ब्रिटिश पार्टियों के लिए उसकी पार्टी जान की आफ़त होगई। जब यह दोनों पार्टियाँ पार्लमेण्ट में करीब-करीब बराबर संख्या में होती थीं, आयरिश होमरूल वालों को महत्व मिल जाता था; क्योंकि वे किसी भी एक पार्टी से मिलकर उसका पलड़ा भारी कर सकते थे। इस तरह आयरिश सवाल हमेशा सामने रहा करता था। आखिरकार ग्लैडस्टन आयरलैंड को होमरूल देने के लिए राजी होगया और उसने सन् १८८६ ई० में कामन्स सभा के सामने होमरूल बिल पेश किया। इस बिल में यद्यपि स्वराज्य की योजना बहुत मामूली थी, फिर भी इसकी वजह से तूफान मच गया। कंज़र्वेटिव यानी अनुदार दल के लोग तो इसके विलकुल खिलाफ़ थे ही, ग्लैडस्टन की पार्टी यानी लिबरल या उदार लोग भी इसे पसन्द नहीं करते थे। लिबरल पार्टी इसी बात पर दो हिस्सों में बँट गई। एक हिस्सा जाकर कंज़र्वेटिव लोगों से मिल गया और 'यूनियनिस्ट' के नाम से मशहूर हुआ। ये लोग यूनियनिस्ट इसलिए कहलाये कि आयरलैंड और इंग्लैंड को ये एक ही शासन में संयुक्त रखना चाहते थे। होमरूल-बिल पार्लमेण्ट में गिर गया और उसीके साथ ग्लैडस्टन के शासन का भी ख़ात्मा होगया।

इसके सात बरस बाद, १८९३ ई० में, जब ग्लैडस्टन की उम्र ८४ बरस की थी, वह फिर ब्रिटिश पार्लमेण्ट के प्रधान सचिव हुए, और फिर उन्होंने दूसरी मर्तबा होमरूल बिल पेश किया। यह बिल कामन्स सभा में बहुत कम बहुमत से पास हुआ, लेकिन क़ानून बन सकने के लिए तमाम विलों का हाउस आफ़ लार्ड्स में भी मंजूर होना जरूरी है और हाउस आफ़ लार्ड्स संकुचित और प्रगतिविरोधी लोगों से भरा था। इस लार्ड सभा के सदस्यों का चुनाव नहीं होता। यह बड़े ज़मींदारों की एक पुश्तैनी सभा है, जिसमें कुछ पादरी (बिशप) लोग भी शामिल होते हैं। इस सभा ने होमरूल बिल को, जिसे कामन्स सभा ने मंजूर कर लिया था, नामंजूर कर दिया।

इस तरह पार्लमेण्टरी कोशिश से आयरलैंड को वह चीज़ न मिली, जो वह चाहता था। फिर भी आयरिश क्रांती दल या 'होमरूल पार्टी' पार्लमेण्ट में इस उम्मीद से काम करती रही कि शायद आगे कामयाबी हो जाय और आमतौर से यह पार्टी आयरलैंड-निवासियों की विश्वासपात्र भी थी। लेकिन बहुत-से लोग ऐसे भी थे, जिनका इन तरीकों से और ब्रिटिश पार्लमेण्ट से भरोसा जाता रहा था। कितने ही

आयरिश लोग संकीर्ण अर्थ में राजनीति से ऊंच गये थे और सांस्कृतिक तथा आर्थिक प्रवृत्तियों में लग रहे थे। बीसवीं सदी के शुरू-शुरू का जमाना आयरलैंड में सांस्कृतिक जागृति का युग था। खासकर देश की पुरानी भाषा गैलिक को फिर से ज़िन्दा करने की खूब कोशिश की जा रही थी। इस गैलिक भाषा में बड़ा क़ीमती साहित्य पाया जाता था, लेकिन सदियों की अंग्रेज़ी हुकूमत ने इस भाषा को शहरों से निकाल दिया था और यह धीरे-धीरे ग़ायब हो रही थी। आयरिश राष्ट्रवादियों का यह ख़याल था कि उनका राष्ट्र अपनी आत्मा और अपनी संस्कृति की रक्षा अपनी ही ज़वान के जरिये कर सकता है। इसलिए इन लोगों ने पश्चिम के आयरिश गांवों में से इस भाषा को खोज निकालने और इसको एक ज़िन्दा ज़वान बनाने के लिए बड़ी मेहनत की। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक गैलिक-लीग बनाई गई। सब जगहों पर, खासकर गुलाम देशों में, राष्ट्रीय आन्दोलन अपने देश की भाषा को ही अपना आधार बनाता है। जिस आन्दोलन की दुनियाद विदेशी भाषा पर होती है, वह जनता तक नहीं पहुँच सकता, और इसलिए जड़ नहीं पकड़ सकता। आयरलैंड में अंग्रेज़ी भाषा विदेशी भाषा नहीं रह गई थी। इस भाषा को सभी समझते थे और सभी बोलते थे। कम-से-कम गैलिक भाषा से तो इसका प्रचार हर हालत में ज्यादा था ही; इसपर भी आयरिश राष्ट्रीय दल ने आवश्यक समझा कि गैलिक भाषा फिर से ज़िन्दा की जाय, जिससे अपनी पुरानी सभ्यता से आयरिश लोगों का सम्बन्ध न टूटे।

उस समय आयरलैंड में यह ख़याल फैला हुआ था कि ताक़त अन्दर से आती है, बाहर से नहीं। पार्लमेण्ट के अन्दर की कोरी राजनैतिक प्रवृत्तियों के बारे में भ्रम ख़त्म हो रहा था और इसलिए कोशिश यह की जा रही थी कि राष्ट्र का निर्माण अधिक मजबूत दुनियाद पर किया जाय। बीसवीं सदी के शुरू का यह नया आयरलैंड पुराने आयरलैंड से बिल्कुल जुदा था। इसकी इस नई जागृति यानी बेदारी का असर कई तरफ़ और अनेक क्षेत्रों में जाहिर होने लगा—साहित्यिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में, और, जैसा मैंने ऊपर बताया है, आर्थिक क्षेत्र में भी, जहाँ इस बात की कामयाबी के साथ कोशिश की गई कि किसानों में सहकारिता के उसूलों पर संगठन किया जाय।

लेकिन इन सब कारगुजारियों को चलानेवाली ताक़त आज्ञादी की प्यास थी और यद्यपि ब्रिटिश पार्लमेण्ट के आयरिश राष्ट्रीय दल में आयरिश जनता का विश्वास था, लेकिन यह विश्वास ढिग रहा था। पार्लमेण्ट के आयरिश मेम्बरों को आयरिश जनता समझने लग गई थी कि बस ये लोग कोरे राजनीतिज्ञ हैं, जिन्हें भाषण देना बहुत पसन्द है लेकिन कुछ कर-धर सकने की इनमें ताक़त नहीं है। पुराने 'फ़ेनियन'

लोगों का और दूसरों का भी, जो क्राँम की आज्ञादी चाहते थे, इन पार्लमेण्टरी लोगों और इनके होमरूल में विश्वास था ही नहीं, अब नया और नौजवान आयरलैंड भी पार्लमेण्ट से अपना मुँह मोड़ने लगा। अपनी मदद खुद कर लेने का भाव वातावरण में भर रहा था। लोग कहते थे कि इस खयाल को राजनीति में क्यों न जगह दी जाय ? सशस्त्र विद्रोह के विचार लोगों के दिलों में फिर पैदा होने लगे, लेकिन बगावत की इस इच्छा को एक नया 'टर्न' दिया गया। आर्थर ग्रिफिथ नाम के एक नौजवान आयरिश ने एक नये उसूल का प्रचार शुरू कर दिया, जिसे 'सिनफेन' कहते थे। 'सिनफेन' का अनुवाद अक्सर 'हम लोग अकेले' किया जाता है, लेकिन इसका सही तर्जुमा 'हम खुद' है।

इन शब्दों से हमें उस नीति का पता चलता है जो इस आन्दोलन के पीछे काम कर रही थी। सिनफेन वाले चाहते थे कि आयरलैंड अपने ऊपर भरोसा करे और इंग्लैंड से किसी तरह की मदद या भीख न माँगे। ये लोग अन्दर से राष्ट्र की शक्ति का विकास करना चाहते थे और गैलिक आन्दोलन और सांस्कृतिक पुनर्जागृति के पक्ष में थे। राजनैतिक क्षेत्र में ये फ़िज़ूल की पार्लमेण्टरी प्रवृत्ति को, जो उस समय चल रही थी, नापसन्द करते थे और उससे किसी तरह की उम्मीद नहीं रखते थे। साथ ही इनका खयाल यह भी था कि सशस्त्र बगावत मुमकिन नहीं है। ब्रिटिश सरकार से एक प्रकार के असहयोग के जरिये ये पार्लमेण्टरी प्रवृत्ति के बजाय सीधी लड़ाई (Direct action) के प्रचारक थे। आर्थर ग्रिफिथ ने हंगरी की मिसाल पेश की, जहाँ एक पीढ़ी पहले इसी तरह (निष्क्रिय प्रतिरोध) की नीति सफल हो चुकी थी और इसी प्रकार की नीति आयरलैंड में भी चलाने की वकालत की।

पिछले १३ वर्षों में हमारे सामने, हिन्दुस्तान में, असहयोग के अनेक रूप आये हैं। अगर हम आयरलैंड के इस असहयोग से अपने असहयोग की तुलना करें तो बड़ी दिलचस्प बात होगी। तमाम दुनिया जानती है कि हमारे आन्दोलन की बुनियाद अहिंसा थी, लेकिन आयरलैंड के असहयोग में इस तरह की कोई बात नहीं पाई जाती थी। फिर भी उस असहयोग की ताक़त शान्तिमय निष्क्रिय प्रतिरोध में ही थी। इस संग्राम का भी असल में शान्तिमय होना जरूरी था।

सिनफेन के खयालात धीरे-धीरे आयरलैंड के नौजवानों में फैले। इन खयालात की वजह से आयरलैंड में एकदम आग नहीं भड़की; क्योंकि अब भी बहुत-से आदमी ऐसे थे जिन्हें पार्लमेण्ट से उम्मीदें थीं, खासकर इसलिए कि १९०६ ई० में ब्रिटिश पार्लमेण्ट में लिबरल पार्टी बहुत ज्यादा बहुमत से चुनकर फिर आ गई थी। कामन्स सभा में इस बहुमत के होते हुए भी लिबरल लोगों को हाउस आफ लार्ड्स

के स्थायी, संकीर्ण और यूनिवर्निस्ट बहुमत का मुकाबिला करना पड़ता था। इसलिए इन दोनों हाउसों या सभाओं में बहुत ही जल्द संघर्ष पैदा होगया। इस संघर्ष का नतीजा यह निकला कि लार्ड लोगों की ताकत कम करदी गई। आर्थिक मामलात में इन लोगों की दस्तन्दाजी को कामन्स वाले इस तरह खत्म कर देते थे कि उस कानून को, जिसपर लार्ड सभा ऐतराज करती थी, अपने यहाँ मुतवातिर तीन बैठकों में पास कर लिया करते थे। इस तरह १९११ के पार्लमेण्ट कानून के जरिये लिबरल लोगों ने हाउस आफ लार्ड्स के दाँत तोड़ दिये। फिर भी लार्ड लोगों के हाथ में बहुत काफी इस्तियारात बने रहे, जिससे वे कामन्स सभा के काम को रोक सकते और उसमें दस्तन्दाजी कर सकते थे।

लार्ड लोगों के अनिवार्य विरोध का इन्तजाम करके लिबरल लोगों ने फिर तीसरी बार होमरूल बिल पेश किया। लार्ड लोगों ने, जैसी उम्मीद थी, इसको फिर नामंजूर कर दिया। फिर कामन्स सभा ने इस कानून को तीन मर्तबा मुतवातिर पास करने की परेशानी उठाई। इस प्रकार १९१४ ई० में इस बिल ने कानून की शक्ल इस्तियार की और यह सारे आयर्लैंड पर, जिसमें अलस्टर भी शामिल था, लागू हो गया।

ऐसा जान पड़ता था कि आयर्लैंड को आखिरकार होमरूल मिल ही गया, लेकिन इसमें बहुत-से अगर-भगर थे। जब १९१२-१३ में पार्लमेण्ट होमरूल के बारे में बहस-मुवाहसा कर रही थी, उत्तरी आयर्लैंड में आश्चर्यजनक घटनायें हो रही थीं। अलस्टर के नेता लोग इस बात का ऐलान कर रहे थे कि वे होमरूल को स्वीकार नहीं करेंगे, और अगर होमरूल का कानून पास भी होगया तो वे उसे न मानेंगे। ये लोग बगावत की बात करने लगे और उसकी तैयारी भी शुरू करदी। यह भी कहा गया कि इन्हें किसी विदेशी शक्ति को यानी जर्मनी को होमरूल के खिलाफ लड़ाई करने के लिए निमन्त्रित करने में संकोच न होगा। निस्संदेह यह स्पष्ट और बशुद्ध राजविद्रोह था। इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात तो यह थी कि कंजर्वेटिव यानी-अनुदार दल के नेताओं ने इस बगावत के आन्दोलन को आशीर्वाद दिया और बहुतों ने इसकी मदद की। अलस्टर में खुशहाल और धनी कंजर्वेटिव दल की तरफ से पैसा बरसने लगा। यह साफ़ जाहिर था कि वे लोग, जिन्हें ऊँचे वर्ग का कहा जाता है, तथा शासक दल के लोग और अनेक सैनिक अफसर भी, जो इसी वर्ग के थे, अलस्टर के साथ हैं। हथियार चोरी-चोरी आने लगे और स्वयंसेवकों को खुल्लमखुल्ला क़वायद सिखाई जाने लगी। अलस्टर में एक कामचलाऊ सरकार भी बना दी गई, जो वक्त आने पर शासन की ज़िम्मेदारी भी लेले। नोट करने की दिलचस्प बात यह है कि

अलस्टर के विद्रोहियों में से एक प्रमुख विद्रोही पार्लमेण्ट के एक मशहूर कंजर्वेटिव सदस्य एफ० ई० स्मिथ थे, जो बाद को लार्ड बरकेनहेड हुए और भारत-मंत्री बनाये गये और जिन्होंने दूसरे ऊँचे-ऊँचे ओहदों पर भी काम किया।

इतिहास में बगावत मामूली घटना होती है और आयरलैण्ड में तो खासतौर से इनकी तादाद काफी से ज्यादा रही है। लेकिन अलस्टर-विद्रोह की ये तैयारियाँ हम लोगों के लिए खासतौर से दिलचस्पी की चीज हैं; क्योंकि इन तैयारियों के लिए जो पार्टियाँ खास तौर से जिम्मेदार थी, वह वही पार्टियाँ थी जो इस बात पर अभिमान करती रहती थी कि हम विधान को माननेवाले हैं और कंजर्वेटिव या अनुदार हैं। यही वह पार्टियाँ थी जो हमेशा 'अमन और क़ानून' की बात करती रहती थी और उन लोगों को सख्त सजायें देने के पक्ष में थी जो 'अमन और क़ानून' के खिलाफ़ जायें। लेकिन इसी पार्टियों के खास-खास आदमी राज-विद्रोह की बात करते थे और सशस्त्र बगावत की तैयारी करते थे और इसके साधारण सदस्य इस प्रवृत्ति की रूपरेखा से मदद करते थे। यह भी नोट करने की दिलचस्प बात है कि विद्रोह उस पार्लमेण्ट के खिलाफ़ संगठित किया जा रहा था, जो होमरूल बिल पर विचार कर रही थी और जिसने बाद में होमरूल बिल पास किया। इस पार्टियों ने इस तरह प्रजातन्त्र-सिद्धान्त की जड़ पर ही हमला किया था और अंग्रेज़ लोगों की इस पुरानी शेखी को मिट्टी में मिला दिया था कि हम बैंध कार्यों और क़ानून के शासन को माननेवाले हैं।

१९१२-१४ के अलस्टर-विद्रोह ने लच्छेदार और कपटपूर्ण वाक्यों के ऊपर से परदा हटा दिया और आधुनिक प्रजातन्त्र और सरकार के असली रूप को साफ-साफ सामने रख दिया। जबतक 'अमन और क़ानून' का मतलब यह था कि शासक वर्ग के अधिकारों की रक्षा होती रहे तबतक 'अमन और क़ानून' मुनासिब चीज़ थी। जबतक प्रजासत्तात्मक शासन इन रिआयतों और विशेषाधिकारों में दखल नहीं देता था, इसे स्वीकार करने में उन्हें कोई ऐतराज नहीं था; लेकिन जब इन विशेषाधिकारों पर हमला हुआ, तो यह वर्ग लड़ने को तैयार होगया। इस तरह 'अमन और क़ानून' असल में दो सुन्दर शब्द थे, जिनका अर्थ था शासक वर्ग के विशेषाधिकार यानी खास हक़ूक। इससे यह साफ होगया कि ब्रिटिश सरकार असल में एक वर्ग की सरकार है, जिसे पार्लमेण्ट का बहुमत भी आसानी से अलग नहीं कर सकता। अगर बहुमत ऐसा कोई साम्यवादी क़ानून पास करने की कोशिश करे, जिससे इनके रिआयती हक़ों में कमी आती हो, तो प्रजातन्त्र के नियमों के खिलाफ़ भी ये लोग बगावत करने को तैयार थे। इन सब बातों का ख़याल रखना हमारे लिए अच्छा है। क्योंकि ये बातें सब देशों के बारे में कही जा सकती हैं, और इस बात का अन्देशा रहता है कि लच्छेदार बातों

और सुन्दर वाक्यों के माया-जाल में फँसकर कहीं हम असलियत को न भूल जायें। इस बारे में दक्षिण अमेरिका के प्रजातन्त्र में, जहाँ अक्सर विद्रोह हुआ करते हैं, और इंग्लैण्ड में, जहाँका शासन स्थायी रहता है, कोई मौलिक फर्क नहीं पाया जाता। ब्रिटिश शासन में स्थिरता सिर्फ इसलिए है कि इंग्लैण्ड में शासक वर्ग ने अपनी जड़ इतनी मजबूत गाड़ली है कि अभीतक कोई दूसरा वर्ग उसे हिला नहीं पाया। १९११ ई० में हाउस आफ लार्ड्स, जो इस वर्ग का एक किला था, कुछ कमजोर किया गया था। इसपर यह वर्ग घबरा गया और अलस्टर के बहाने विद्रोह करने को तैयार होगया था।

हिन्दुस्तान में 'अमन और क़ानून' का मन्त्र हमारे सामने रोज़ सुनाया जाता है और दिन में कई दफ़ा भी। इसलिए इसका असली अर्थ समझ लेना हमारे लिए ज़रूरी है। हम यह भी याद रखें तो अच्छा है कि हमको सलाह देनेवाले एक सज्जन, जो भारत-सचिव भी रहे हैं, अलस्टर-विद्रोह के नेता थे।

इस तरह अलस्टर हथियार और वालण्टियरों का इन्तज़ाम करके विद्रोह की तैयारी करने लगा और सरकार शान्तिपूर्वक देखती रही। इन तैयारियों के खिलाफ़ कोई ऑर्डिनेन्स नहीं निकाला गया। कुछ दिनों के बाद आयर्लैण्ड के बाक़ी हिस्से ने अलस्टर की नक़ल शुरू करदी और होमरूल के लिए और अगर ज़रूरत पड़े तो अलस्टर से लड़ने के लिए राष्ट्रीय वालण्टियरों का संगठन शुरू कर दिया। इस तरह आयर्लैण्ड में दो मुक़ाबिले की फ़ौजें तैयार होगईं। सबसे ताज़्जुब की बात तो यह है कि ब्रिटिश शासक अलस्टर-विद्रोह के वालण्टियरों को सशस्त्र होते हुए देखकर आँखें मीच लेते थे, लेकिन 'राष्ट्रीय वालण्टियरों' को दबाने में ये लोग बहुत काफ़ी तेज़ और मुस्तैद दिखाई पड़ते थे, हालाँकि ये 'राष्ट्रीय वालण्टियर' होमरूल के खिलाफ़ नहीं थे।

इन दोनों क्रिस्म के वालण्टियरों में झूठभेड़ होजाना लाज़िमी मालूम होने लगा, और इसका अर्थ था गृह-युद्ध। उसी समय १९१४ ई० के अगस्त में एक सबसे बड़ा महायुद्ध छिड़ गया और उसके सामने बाक़ी सब चीज़ें फीकी पड़ गईं। होमरूल का बिल क़ानून ज़रूर बन गया, लेकिन उसमें यह शर्त लगादी गई थी कि युद्ध के बाद ही इस क़ानून पर अमल किया जाय। इस तरह होमरूल पहले के समान दूर ही बना रहा और युद्ध ख़त्म होने के पहले आयर्लैण्ड में बहुत कुछ होगया।

मैं अनेक देशों की अपनी कहानी महायुद्ध की शुरुआत तक लाकर ख़त्म कर रहा हूँ। आयर्लैण्ड के बारे में भी हम उस समय तक पहुँच चुके हैं, इसलिए अब आगे न बढ़ेंगे। लेकिन इस ख़त को ख़त्म करने के पहले एक बात मैं तुम्हें ज़रूर बता देना

चाहता हूँ । अलस्टर-विद्रोह के नेता अपनी हरकतों के लिए सजा पाने के बजाय बाद को इनाम के हकदार समझे गये और वे ब्रिटिश शासक-मण्डली में वजीर बने और उन्होंने ब्रिटिश सरकार में ऊँचे-ऊँचे ओहदे पाये ।

: १४१ :

मिस्र पर ब्रिटेन का कब्ज़ा

११ मार्च, १९३३

अमेरिका से हम लम्बी छलाँग मारकर और अटलाण्टिक महासागर पार करके आयरलैण्ड पहुँच गये थे । अब हमें कूदकर एक तीसरे महाद्वीप अफ़रीका में पहुँचना है और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के एक दूसरे शिकार मिस्र को देखना है । मैंने अपनी पिछली चिट्ठियों में तुम्हें मिस्र के प्राचीन इतिहास के बारे में कुछ लिखा था, लेकिन जो कुछ लिखा था वह बहुत मुस्तसर और खण्डित था, क्योंकि मुझे खुद इस विषय का काफ़ी इल्म नहीं है । पर यदि मुझे अधिक मालूम होता तो भी यह मुमकिन नहीं कि हम प्राचीनकाल की चर्चा इस अवसर पर शुरू कर सकें । हम उन्नीसवीं सदी की अपनी कहानी करीब-करीब ख़त्म कर चुके हैं और अब बीसवीं सदी की सीमा पर पहुँच गये हैं और यहीं हमें कायम रहना ज़रूरी है । हम यह नहीं कर सकते कि कभी प्राचीन की ओर कभी नवीन काल की चर्चा करते रहें । इसके अलावा भी अगर मैंने हरेक देश के प्राचीन समय की कहानी शुरू करदी तो बताओ क्या ये ख़त कभी ख़त्म हो सकेंगे ?

लेकिन तुम यह न समझो कि मिस्र का प्राचीन इतिहास कुछ नहीं है, क्योंकि क़ौमों में मिस्र की क़ौम बहुत पुरानी मानी जाती है और इसका इतिहास सब देशों के इतिहास से पुराना है । यह देश अपना समय छोटी-छोटी सदियों से नहीं बल्कि हजारों वर्षों की नाप से नापता रहा है । विस्मयजनक और चकित कर देनेवाली प्राचीन समय की टूटी-फूटी यादगारें अभी तक हमें इसके गुज़रे हुए ज़माने की याद दिलाती हैं । प्राचीन चीज़ों और बातों की खोज के लिए मिस्र सबसे प्रथम और सबसे बड़ा क्षेत्र रहा है; और जैसे-जैसे बालू के नीचे से पत्थर के टुकड़े और स्तूप खोदकर निकाले गये हैं, उस ज़माने का इतिहास ज्यादा-ज्यादा मालूम होता रहा है, जिसे गुज़रे अब बहुत दिन होगये । पत्थरों और इमारतों को खोद-खोदकर निकालने का सिलसिला अभी तक जारी है और मिस्र के प्राचीन इतिहास में नई-नई बातें बराबर मालूम होती जा रही हैं, फिर भी हम अभी तक यह नहीं बता सकते कि मिस्र का इतिहास कबसे और कैसे शुरू होता है । किन्तु करीब सात हजार वर्ष गुज़रे, नील नदी की घाटी में

सभ्य लोग रहा करते थे और उनका भी अपना पुराना सांस्कृतिक इतिहास था। ये लोग चित्रलिपि में लिखा करते थे; मिट्टी के सुन्दर वर्तन, कलश और हाथीदांत, ताँवे सोने के नक्काशीदार वर्तन और सेलखली के काम बहुत अच्छा बनाते थे।

मकदूनिया-निवासी सिकन्दर ने ईसाई संवत् के चारसौ बरस पहले जब मिस्र को जीता था तब, कहा जाता है, ३१ मिस्री राजवंश इस देश पर हुकूमत कर चुके थे। उस चार या पाँच हजार वर्ष के लम्बे युग में इस देश में कितने ही आश्चर्यजनक व्यक्ति—स्त्री और पुरुष—मशहूर हुए। ऐसा मालूम होता है मानों ये सब अभी-तक ज़िन्दा हैं। इन स्त्री-पुरुषों में अनेक कर्मवीर, विशाल मन्दिरों के निर्माणकर्त्ता, महान् स्वप्नदर्शी और विचारक, बड़े-बड़े सैनिक, निरंकुश और अत्याचारी राजा, सुन्दर महिलाएँ और अभिमानी तथा उद्धत शासक गुजरे हैं। अनेक सहस्राब्दियाँ हमारे सामने से गुज़र जाती हैं और हम देखते हैं कि इनमें फरोहा नरेशों की लम्बी सन्तति चल रही है। इस देश में स्त्रियों को पूरी आजादी थी और स्त्रियाँ राज-सिंहासन पर बैठ सकती थीं। मिस्र देश में पुरोहित समाज पर हावी थे और मिस्री लोग हमेशा भविष्य और परलोक की चिन्ता में फँसे रहते थे। मिस्र के विशाल पिरामिड, जिनकी रचना बेगार के मजदूरों ने की थी और जिनके बनाने में इन मजदूरों के साथ बड़ी बेरहमी दिखलाई गई थी, असल में फरोहा नरेशों के भविष्य को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से बनाये गये थे। ममी भी लाश को सुरक्षित रखने का ही एक तरीका था। यह सब अन्धकारमय, क्रूर और सुख-रहित जान पड़ता है। हमें उस ज़माने की पुरानी चीज़ों में आदमियों के बनावटी बाल (विग) भी मिलते हैं, क्योंकि वे लोग अपना सिर मुँडाय़ा करते थे। इसके अलावा लड़कों के खिलौने, गुड्डे, गेंद और हाथ-पैर हिलानेवाले छोटे जानवरों के खिलौने भी पाये जाते हैं। इन खिलौनों को देखकर हमें पुराने मिस्रियों की मानुषी भावनाओं की याद आजाती है, और ऐसा मालूम होता है कि यद्यपि उन लोगों को हुए अनेक युग बीत गये हैं फिर भी मानों वे हमारे पास ही हैं।

ईसवी सन् के पहले की छठी सदी में यानी बुद्ध के ज़माने के करीब ईरानियों ने मिस्र को जीता और इसे अपने विशाल साम्राज्य का एक हिस्सा बना लिया, जो नील नदी के किनारे से सिन्धु नदी तक फैला हुआ था। ये लोग एकेमनीद वंश के राजा थे और इनकी राजधानी पारसीपोलिस थी। इन लोगों ने यूनान को भी जीतने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे और इन्हें अख़ीर में सिकन्दर ने हरा दिया। ईरानियों की सख्त हुकूमत से छुटकारा दिलानेवाला समझकर मिस्र के लोगों ने सिकन्दर का स्वागत किया। सिकन्दरिया (अलेक्जेंड्रिया) नगर के रूप में सिकन्दर अपनी यादगार छोड़ गया, और यह नगर यूनानी विद्या और संस्कृति का प्रसिद्ध केन्द्र बन गया।

तुम्हें याद होगा कि सिकन्दर की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य उसके सेनापतियों में बंट गया था और मिस्र बतलीमूसी (Ptolemy) के हिस्से में आया था। बतलीमूसी बहुत जल्द मिस्री जलवायु में हिल-मिल गये और ईरानियों के ढंग के खिलाफ़ उन्होंने मिस्री रस्म-रिवाज इस्तिथार कर लिया। ये लोग मिस्रियों की तरह आचार-व्यवहार करने लगे और जनता करीब-करीब यही समझने लगी कि बतलीमूसी राजवंश फरोहाओं के प्राचीन राजवंश का ही सिलसिला है। क्लियोपैट्रा बतलीमूसी वंश की अन्तिम रानी थी। इसकी मृत्यु के बाद, ईसाई सन् शुरू होने के चन्द वर्ष पहले, मिस्र रोमन साम्राज्य का एक प्रान्त हो गया।

मिस्र ने रोम से बहुत पहले ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था। रोमन लोग इन मिस्री ईसाइयों पर बहुत अत्याचार करते थे, जिससे भागकर इन्हें रेगिस्तान में छिपना पड़ता था। इस तरह रेगिस्तानियों में अनेक खुफिया मठ पैदा होगये और इन मठों में रहनेवाले फकीरों द्वारा किये हुए चमत्कारों की आश्चर्यजनक और रहस्य-पूर्ण कहानियाँ उस जमाने के ईसाई जगत् में खूब प्रचलित थीं। बाद को जब सम्राट् कान्स्टेण्टाइन ने ईसाई धर्म इस्तिथार कर लिया तब ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य का राजधर्म होगया। इन मिस्री ईसाइयों ने भी गैर-ईसाइयों से, जो पैगन कहे जाते थे और जो पुराने मिस्री धर्म को मानते थे, बड़ी बेरहमी और जुल्म के साथ बदला लेने की कोशिश की। सिकन्दरिया अब ईसाइयों का एक मशहूर विद्या-केन्द्र होगया, लेकिन राज-धर्म होने पर ईसाई धर्म अनेक मत-मतान्तरों में बंट गया, जो आपस में लड़ते-झगड़ते रहते थे और एक-दूसरे पर प्रभुत्व जमाने की कोशिश करते थे। ये खूनी झगडे जान को आफत हो गये और आम लोग इन ईसाई मत-मतान्तरों से अच्छी तरह ऊब गये थे। इसलिए सातवीं सदी में जब अरब लोग एक नया धर्म लेकर आये, मिस्री जनता ने उनका स्वागत किया। यह भी एक वजह थी कि मिस्र और उत्तरी अफरीका में अरब लोगों ने इतनी आसानी से विजय पाली। अब फिर जुल्म का चक्कर चलने लगा। ईसाई धर्म और ईसाइयों पर बेरहमी से दमन होने लगा।

इस तरह मिस्र खलीफा के साम्राज्य का एक प्रान्त बन गया। अरबी भाषा और अरबी संस्कृति तेज़ी से फैल गई; यहाँतक कि पुरानी मिस्री भाषा दब गई। दोस्रो वर्ष बाद, नवीं सदी में, जब बग़दाद की ख़िलाफ़त और कमज़ोर पड़ी। मिस्र तुर्की हाकिमों की मातहत्य में अर्द्ध-स्वतंत्र यानी नीम-आज़ाद हो गया और तीनसौ वर्ष बाद क्रूसेड युद्ध यानी ईसाई जिहाद में मशहूर मुसलमान बहादुर सलादीन मिस्र का मुल्तान बन बैठा। सलादीन के बाद उसके एक वारिस ने काकेशस-क्षेत्र से बहुत-से तुर्की गुलाम लाकर उन्हें अपना सैनिक बनाया। ये गोरे गुलाम ममलूक कहलाते थे।

ममलूक का अर्थ है गुलाम । ये ममलूक लोग फौज के लिए बहुत सावधानी से चुने गये थे और इन लोगों का जत्था बहुत अच्छा था । चन्द साल के अन्दर ही ममलूक बग़ावत कर बैठे और इन्होंने अपने जत्थे के एक आदमी को मिस्र का सुल्तान बना दिया । इस तरह मिस्र में ममलूकों का राज्य शुरू हुआ, जो ढाई सदी तक रहा और अर्द्ध-स्वतन्त्र अवस्था में इसके बाद करीब तीन सौ बरस के और क़ायम रहा । इस तरह विदेशी गुलामों के समूह ने मिस्र पर पाँचसौ वर्ष से ज्यादा समय तक राज्य किया । इतिहास में यह एक अद्वितीय और अजीब घटना है ।

इन आदि-ममलूकियों ने मिस्र में अपनी कोई पुश्तैनी जाति या वर्ग नहीं बनाया । काकेशस की गोरी जाति के सबसे अच्छे आज़ाद गुलामों को अपनेमें मिलाकर ये लोग अपनी तादाद बराबर बढ़ाते रहते थे । काकेशस जातियाँ आर्य हैं, इसलिए ममलूक भी आर्य थे । ये विदेशी लोग मिस्र की आबोहवा में नहीं फले-फूले और इनके वंश चन्द पुश्तों के बाद लुप्त होजाते थे । लेकिन चूँकि नये-नये ममलूक आते जाते थे, इस वर्ग की तादाद और ख़ासतौर पर इसकी ताक़त और इसका जीवट क़ायम रहा । इस तरह ग़ोकि इन लोगों का कोई पुश्तैनी वर्ग नहीं था, फिर भी इनका एक उच्च वर्ग—शासक वर्ग—ज़रूर था, जो बहुत काफ़ी ज़माने तक क़ायम रहा ।

सोलहवीं सदी के शुरू में कुस्तुनतुनिया के तुर्की उस्मानी सुल्तान ने मिस्र पर क़ब्ज़ा कर लिया और ममलूक सुल्तान को फाँसी पर लटका दिया । मिस्र उस्मानी साम्राज्य का एक प्रान्त बन गया । लेकिन ममलूक शासक लोग रईस वर्ग में बने ही रहे । बाद में जब योरोप में तुर्क लोग कमज़ोर पड़े, तब मिस्र कहने को तो उस्मानी साम्राज्य का हिस्सा बना रहा, लेकिन ममलूक लोग वहाँ अपनी मनमानी करते थे । अठारहवीं सदी के अख़ीर में जब नेपोलियन मिस्र पहुँचा, तो उसकी इन्हीं ममलूकियों से मुठभेड़ हुई थी, और उसने इन्हींको शिकस्त भी दी थी । तुम्हें शायद वह किस्सा याद होगा जो मैंने तुम्हें ममलूक सरदार का सुनाया था । जब फ़्रांसीसी फौज मिस्र में पहुँची, तो मध्यकाल की रीति के अनुसार एक ममलूक सरदार फ़्रांसीसी फौज के सामने घोड़े पर सवार जा पहुँचा और उसने चुनौती दी कि इस सेना का नेता मुझसे अकेले आकर ज़ोर-आज़माई करले ।

अब हम उन्नीसवीं सदी तक आगये । इस सदी के पहले आधे हिस्से में मिस्र पर मुहम्मदअली का प्रभुत्व रहा । यह अलबेनियन तुर्क था और मिस्र का 'खेदीव' यानी तुर्की गवर्नर था । मुहम्मदअली आधुनिक मिस्र का जन्मदाता समझा जाता है । पहली बात जो उसने की वह यह थी कि धोखे से ममलूकों को तलवार के घाट उतारकर उनकी ताक़त का ख़ात्मा कर दिया । इसने मिस्र में एक अँग्रेज़ी फौज को भी हराकर

अपनेको इस देश का स्वामी बना लिया और सिर्फ़ नामनात्र के लिए ही तुर्की सुलतान की अध्रक्षता स्वीकार करता रहा। मुहम्मदअली ने नई मिस्री फ़ौज तैयार की, जिसमें देशी किसानों की भरती की गई, ममलूकों की नहीं। इसने नई नहरें भी खुदवाई और रई की खेती को प्रोत्साहन दिया, जो भविष्य में मिस्र का खास रोज़गार होगया। इसने इस बात की भी धमकी दी थी कि वह कुस्तुनतुनिया के नाम-मात्र के मालिक सुलतान को निकालकर कुस्तुनतुनिया को भी अपने शासन में ले लेगा। लेकिन ऐसा किया नहीं। हाँ, इसने सीरिया को मिस्र में मिला लिया।

नेहमतअली १८४९ ई० में ८० वर्ष की उम्र में मर गया। इसके वारिस कम-जोर, फ़िज़ूलखर्च और अयोग्य आदमी थे। लेकिन अगर वे बेहतर भी होते तो भी उनके लिए अन्तर्राष्ट्रीय साहूकारों की लालच और यूरोपियन साम्राज्यवाद के लोभ का मुक्ताबिला कर सकना मुश्किल था। विदेशियों ने, खासकर अंग्रेज़ और फ़्रान्सीसी साहूकारों ने, खेदीवों को उनके निजी खर्च के लिए बहुत ज्यादा सूद पर रक़म उधार दी थीं। जब वक्त पर सूद अदा न होसका, जंगी जहाज़ उसे वसूल करने के लिए भेजे गये। अन्तर्राष्ट्रीय चालवाज़ी की यह असाधारण कहानी है कि साहूकार और सरकार किस प्रकार दूसरे देश को लूटने और उसपर प्रभुत्व जमाने के उद्देश्य से एक-दूसरे के साथ मिलजुलकर काम करते हैं। अनेक खेदीवों की अयोग्यता के होते हुए भी मिस्र ने काफ़ी तरक्की करली थी, यहाँतक कि प्रमुख अंग्रेज़ी अख़-बार 'टाइम्स' ने जनवरी १८७६ में लिखा था कि "मिस्र उन्नति का आश्चर्यजनक उदाहरण है। इस देश ने ७० वर्ष में इतनी तरक्की करली है, जितनी दूसरे देशों ने ५०० वर्ष में की।" लेकिन इन तमाम बातों के होते हुए भी विदेशी साहूकार, इस बात को जाहिर करते हुए कि मिस्र देश दिवालिया हो रहा है और विदेशी दस्तंदाज़ी की ज़रूरत है, चमड़ी निकालने पर भी तैयार होगये। विदेशी सरकारें, खासकर अंग्रेज़ी और फ़्रान्सीसी सरकारें, तो हस्तक्षेप के लिए तुली बैठी थीं। इन्हें तो सिर्फ़ एक यहाना चाहिए था, क्योंकि मिस्र तो एक सोने की चिड़िया थी, उसे कोई कैसे हाथ से जाने देता? और यह बात भी थी कि मिस्र हिन्दुस्तान के रास्ते में पड़ता था।

इसी दरमियान स्वेज़ की नहर, जो मजहदूरों से बड़ी घेरहमी के साथ बेगार ले-लेकर बनवाई गई थी, १८६९ ई० में खुल गई। (इस बात को जानने में तुम्हें दिलचस्पी होगी कि ईसाई सन् के शुरू होने से १४०० वर्ष पहले, पुराने मिस्र राज-वंशों के जमाने में, इसी तरह की नहर लाल समुद्र और भूमध्यसागर के बीच में थी।) इस नहर के खुल जाने की वजह से योरप, एशिया और आस्ट्रेलिया का सारा व्यापार स्वेज़ से होकर गुज़रने लगा और इस वजह से मिस्र का महत्व और बढ़

गया। इंग्लैण्ड के लिए इन नहर पर और मिस्र पर प्रभुत्व रखना बहुत जरूरी चीज होगई, क्योंकि हिन्दुस्तान और पूर्वी देशों में उसका बहुत गहरा स्वार्थ मौजूद था। बड़ी चालाकी की हरकत तो यह थी कि १८७५ ई० के अंग्रेज प्रधानमन्त्री डिजरेली ने दिवालिये खेदीव के स्वेज नहर के हिस्सों को बहुत कम कीमत पर खरीद लिया। इन हिस्सों में धन लगा देना केवल यही नहीं कि अपनी जगह पर काफ़ी मुनाफ़े की चीज रही हो बल्कि इसकी वजह से ब्रिटिश सरकार को नहर के ऊपर बहुत काफ़ी अख्तियार होगया। मिस्र के नहर वाले बाकी हिस्से फ़्रान्सीसी साहूकारों को मिले। इस तरह मिस्र का नहर पर कोई माली अख्तियार नहीं रह गया। इन हिस्सों से फ़्रान्सीसियों और अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा मुनाफ़ा उठाया है और साथ-ही-साथ नहर के मालिक बने रहे हैं और मिस्र की जान को अपनी मुट्ठी में दबाये रखा। पार-साल, १९३२ ई० में, सिर्फ़ ब्रिटिश सरकार को ४० लाख पाँड असली लागत पर इस नहर से ३५ लाख पाँड मुनाफ़ा रहा है !

यह अनिवार्य था कि ये लोग इस देश पर और ज्यादा अख्तियार जमाने की कोशिश करें और इसलिए १८७९ ई० से इन्होंने मिस्र के खानगी मामलात में बराबर दखल देना शुरू किया और आर्थिक नियंत्रण के लिए अपने आदमी रख दिये। स्वभावतः बहुतेरे मिस्रियों ने इससे बुरा माना और मिस्र को विदेशी हस्तक्षेप से मुक्त करने के लिए उत्सुक एक राष्ट्रीयदल पैदा होगया। इस दल के नेता एक नौजवान सैनिक अरबीपाशा थे, जिनका जन्म एक गरीब मजदूर कुटुम्ब में हुआ था और जो मिस्र की फ़ौज में मामूली सिपाही की शकल में भरती हुए थे। धीरे-धीरे इनका प्रभाव बढ़ा और ये मिस्र के युद्ध-सचिव होगये। युद्ध-सचिव की हैसियत से इन्होंने फ़्रान्सीसी और ब्रिटिश 'कन्ट्रोलरों' यानी नियंत्रण रखनेवालों के हुकम की पाबन्दी करने से इन्कार कर दिया। विदेशियों के सामने सिर न झुकाने का जवाब इंग्लैण्ड ने युद्ध से दिया। १८८२ ई० में अंग्रेजी जल-सेना ने सिकन्दरिया नगर पर गोलाबारी की और उसे जला दिया। इस तरह पश्चिमी सभ्यता की श्रेष्ठता प्रकट करके और मिस्र की फ़ौज को खुशकी पर भी हराकर अंग्रेजों ने मिस्र पर पूरा क़ब्ज़ा कर लिया।

इस तरह मिस्र पर ब्रिटिश अधिकार की शुरुआत हुई। अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून की दृष्टि से, यह एक असाधारण स्थिति थी। मिस्र तुर्की राज्य का एक प्रान्त या हिस्सा था। इंग्लैण्ड से तुर्की की मित्रता समझी जाती थी, इसपर भी इंग्लैण्ड ने बहुत इतमीनान के साथ उसके एक हिस्से पर क़ब्ज़ा कर लिया था। ब्रिटेन ने मिस्र में अपना एक एजेंट मुकर्रर कर दिया। मुगल बादशाहों की तरह या हिन्दुस्तान के बड़े लाट के समान यह साहब हरेक के अफ़सर बन गये। खेदीव और उनके वज़ीर भी

इस ब्रिटिश एजेण्ट के सामने बेबस थे। मिस्र के पहले ब्रिटिश एजेण्ट मेजर बरिंग थे, जिन्होंने मिस्र पर २५ वर्ष तक बराबर राज्य किया और बाद को लार्ड क्रोमर कहलाये। क्रोमर मिस्र का एक दबंग और निरंकुश शासक था। इसका पहला काम यह था कि विदेशी साहूकारों और हिस्सेदारों को मुनाफे की रकम पहुँचा दे। इसने अपनी यह नीति बराबर बाकायदा जारी रखी और इस बात की हर जगह से तारीफ़ सुनने में आने लगी थी कि मिस्र की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है। हिन्दुस्तान की तरह मिस्र में भी राज-प्रबन्ध में कुछ उन्नति की गई, लेकिन २५ वर्ष ख़तम होने पर मिस्र का पुराना क़र्ज़ उतना ही बना रहा जितना शुरू में था। शिक्षा के लिए शासन ने कुछ भी नहीं किया और क्रोमर ने तो राष्ट्रीय विद्यालय का खोलना भी रोक दिया था। इसके विचारों का पता हमें इसके पत्र के एक वाक्य से चलता है, जो इसने १८९२ ई० में उस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री लार्ड सेल्सबरी को लिखा था। इसने लिखा था—“खेदीव बहुत कट्टर मिस्री बन रहे हैं।” किसी मिस्र-निवासी का मिस्री की तरह व्यवहार करना लार्ड क्रोमर की दृष्टि में जुर्म था, जैसे किसी हिन्दुस्तानी के हिन्दुस्तानी की तरह व्यवहार करने पर ब्रिटिशों की त्योरियाँ चढ़ जाती हैं और सजायें मिलती हैं।

मिस्र पर अंग्रेज़ों का यह अधिकार फ़्रांसीसियों को पसन्द नहीं था। इस लूट में इन्हें तो कोई हिस्सा मिला नहीं था। योरप की दूसरी ताकतें भी इस बात को पसन्द नहीं करती थीं, और इसके कहने की तो ज़रूरत ही नहीं कि मिस्री लोग तो अंग्रेज़ों की हुकूमत को बिल्कुल नापसन्द करते थे। ब्रिटिश सरकार हरेक आदमी से यही कहती थी कि इस मामले में किसीको परेशान होने की ज़रूरत नहीं; हम तो मिस्र में सिर्फ़ चन्द दिनों के लिए हैं और बहुत जल्द इस मुल्क को छोड़कर चले जायेंगे। ब्रिटिश सरकार ने सरकारी तौर पर और बाकायदा बार-बार यह ऐलान किया कि हम मिस्र को खाली कर देंगे। यह संजीदा ऐलान करीब पचास दफ़े या इससे ज्यादा तो ज़रूर किया गया होगा। असल में इसकी गिनती याद रखना मुश्किल है। इतनी सब बातों पर भी अंग्रेज़ लोग मिस्र में चिपके रहे और आजतक चिपके हैं।

झगड़े की बहुतेरी बातों के बारे में १९०४ ई० में अंग्रेज़ों ने फ़्रान्सीसियों से समझौता कर लिया। अंग्रेज़ इस बात पर राजी होगये कि फ़्रान्सीसी मोरक्को में जो चाहे करें। इसपर फ़्रान्सीसी मिस्र पर ब्रिटिश प्रभुत्व को मंज़ूर करने के लिए राजी होगये। लेन-देन का यह मुनासिब सौदा होगया। सिर्फ़ तुर्की से, जो मिस्र का अधिपति समझा जाता था, कोई सलाह-मशविरा नहीं किया गया; और मिस्र-निवासियों से तो इस मामले में बातचीत करने का कोई सवाल था ही नहीं।

इस जमाने के मिस्र में एक अजीब बात यह थी कि मिस्र की अदालतें विदेशियों पर मुकदमे नहीं चला सकती थीं। ये अदालतें इस काम के क़ाबिल नहीं समझी जाती थीं और विदेशियों को अपनी अदालतों में अपने मुकदमों का फैसला कराने का हक़ था। इसलिए मिस्री हुकूमत की पहुँच के बाहर कितनी ही परदेसी अदालतें पैदा होगई थीं, जिनमें विदेशी जज होते थे और जिनके हृदयों में विदेशी स्वार्थ भी होता था। इन जजों में से एक बहुत कट्टर विदेशी जज ने इन अदालतों के बारे में लिखा है—“इन अदालतों के इन्साफ़ ने विदेशी गुट्टू की, जो देश को चूस रहा था, ख़ूब सेवा की है।” मेरा विश्वास है कि मिस्र के विदेशी वाशिनदे ज्यादातर टंकसों से घरी रहते थे। क्या आनन्द की स्थिति थी; टंकस न देना पड़े, जिस देश में रहें वहाँकी अदालत और वहाँ-के क़ानून की मातहतों से बचे रहें, और साथ ही साथ मुल्क को दुहने की हरेक क्रिस्म की आसानियाँ हों !

इस तरह ब्रिटेन मिस्र पर राज्य करता था और उसको चूसता था और ब्रिटेन के एजेंट और प्रतिनिधि अपनी रेजीडेन्सी में निरंकुश बादशाहों की तमाम शान व शौक़त के साथ मजे करते थे। ऐसी हालत में लाज़िमी था कि राष्ट्रीयता बढ़े और सुधार का आन्दोलन जोर पकड़े। उन्नीसवीं सदी का सबसे बड़ा मिस्र का सुधारक जमालउद्दीन अफ़ग़ानी था। यह धार्मिक नेता था, जो नये जमाने के संचे में ढालकर इस्लाम को आधुनिक रंग देना चाहता था। यह इस बात का प्रचार करता था कि हर तरह की तरक्की इस्लाम के अनुकूल है। इस्लाम को आधुनिक रूप देने की इसकी यह कोशिश उसी प्रकार की थी, जैसी हिन्दुस्तान में हिन्दू धर्म को आधुनिक बनाने के लिए हुई है। इन प्रवृत्तियों की वृत्तियाँ यह होती हैं कि सुधारक लोग पुराने जमाने के चन्द मौलिक सिद्धान्तों को पकड़ लेते हैं और पुराने रस्म-रिवाज और व्यवस्था के नये मानी लगाते हैं। इस ढंग से आधुनिक ज्ञान पुराने धार्मिक ज्ञान का सहयोगी और सहायक बन जाता है। किन्तु यह ढंग वैज्ञानिक ढंग से बिल्कुल जुदा है, क्योंकि वैज्ञानिक ढंग में हम किसी पुरानी वन्दिश में न फँसकर बहादुरी के साथ आगे बढ़ते हैं। बहरहाल जमालुद्दीन का असर सिर्फ़ मिस्र में ही नहीं बल्कि तमाम अरबी मुल्कों में भी बहुत ज्यादा था।

विदेशी व्यापार की तरक्की के साथ मिस्र में एक नया मध्य-वर्ग पैदा होगया और इसीपर वहाँकी नवीन राष्ट्रीयता की नींव पड़ी। आधुनिक मिस्री नेताओं में सबसे बड़े महान पुरुष सैद जगलूलपाशा इसी वर्ग में पैदा हुए थे। मिस्र में ज्यादातर मुसलमानों की आवादी है, लेकिन अब भी इस देश में काण्ट लोग, जो ईसाई हैं, काफ़ी तादाद में पाये जाते हैं। ये काण्ट लोग पुराने मिस्रियों के विशुद्ध वंशज

हैं। इस नये मध्य-वर्ग में मुसलमान भी थे और फाट्ट भी, और सौभाग्यवश इन दोनों में वैरभाव नहीं था। अंग्रेजों ने इन दोनों में फूट पैदा कराने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बिल्कुल सफलता नहीं हुई। अंग्रेजों ने राष्ट्रीय दल में भी फूट पैदा कराने की कोशिश की। कभी-कभी हिन्दुस्तान की तरह मिस्र में भी इन्हें कुछ नरम-दल वाले लोग लोग मिल जाते थे, जो इनके साथ सहयोग करते थे; लेकिन इसके बारे में मैं तुम्हें ज्यादा बातें बाद की चिट्ठियों में लिखूंगा।

जब अगस्त १९१४ ई० में महायुद्ध शुरू हुआ, मिस्र की यह हालत थी। तीन महीने बाद इंग्लैण्ड, फ्रांस और इनके मित्रराष्ट्रों के खिलाफ़ तुर्की जर्मनी से मिल गया। इसपर इंग्लैण्ड ने मिस्र को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लेने का निश्चय कर लिया। लेकिन इसमें कुछ दिक्कत पैदा होगई और मिस्र को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल करने के बजाय यह ऐलान किया गया कि वह ब्रिटिश संरक्षण में है।

इतनी बात तो मिस्र के लिए हुई। उन्नीसवीं सदी के पिछले आधे हिस्से में अफ्रीका का बाक़ी हिस्सा भी यूरोपियन साम्राज्यवाद का शिकार हो गया। इस मुल्क पर जोरदार दौड़ मच गई थी और इस विशाल महाद्वीप को यूरोपीय ताक़तों ने आपस में बाँट लिया। ये लोग गिद्धों की तरह इस महाद्वीप पर दूट पड़े और कभी-कभी इनमें आपस में दो-दो चोंचें भी होजाती थीं। कोई किसीकी रोक-थाम करने-वाला न था, लेकिन १८९६ ई० में इटली अबिसोनिया से हार गया। अगर तुम आज अफ्रीका के नक्शे को देखो तो तुम्हें दिखाई देगा कि इसका ज्यादातर हिस्सा अंग्रेज़ और फ्रांसीसियों के कब्जे में है और कुछ हिस्सा बेलजियम, इटालियन और पुर्तगालियों के पास है। जर्मन लोगों का भी युद्ध के पहले इस महाद्वीप में हिस्सा था। अफ्रीका में अब तो केवल दो स्वतंत्र राज्य रह गये हैं—पूर्व में अबिसोनिया और पश्चिमी किनारे पर लेबेरिया का छोटा-सा देश। मोरक्को पर तो फ्रांस और स्पेन हावी हैं।

इन विशाल प्रदेशों पर किस तरह कब्जा किया गया, इसकी कहानी तो बहुत लम्बी और भीषण है और अभी वह कहानी ख़त्म भी नहीं हुई है। इस महाद्वीप के शोषण के लिए, खासकर रबर निकाने के लिए, जो साधन काम में लाये गये, वे बहुत भीषण थे। कई वर्ष हुए, बेलजियन कांगो में अत्याचार की दारुण कथा सुनकर सभ्य कहलानेवाला संसार काँप उठा था। निस्संदेह काले आदमी की क्रिस्मत भयंकर रही है।

उन्नीसवीं सदी के पिछले आधे हिस्से तक अफ्रीका, जिसे 'अंधेरा महाद्वीप' कहा जाता था, करीब-करीब एक अज्ञात मुल्क था—खासकर अन्दरूनी हालत के लिए।

इस रहस्यमय देश में अनेक दुस्साहस से भरे हुए और हृदय को थरथराने वाले सफर करने के बाद ही इसका सही नक्शा बनाया जा सका है। स्काटलैण्ड का एक पादरी, डेविड लिंविगस्टोन, इस देश की खोज करनेवाला सबसे बड़ा सैयाह था। वर्षों तक वह इस मुल्क में गायब रहा और बाहर की दुनिया को उसका कुछ पता न चला। इसके साथ-साथ हेनरी स्टेनली का भी नाम मशहूर है। हेनरी स्टेनली पत्रकार और सैयाह थे। यह डेविड लिंविगस्टोन की तलाश में उनके पीछे-पीछे गये थे और अन्त में लिंविगस्टोन इन्हें इस महाद्वीप के बीचोंबीच मिले।

: १४२ :

‘योरप का मरीज़’ टर्की

१४ मार्च, १९३३ ई०

मिस्र से भूमध्यसागर पार करके टर्की में पहुँच जाना स्वाभाविक और आसान है। उन्नीसवीं सदी में उस्मानी तुर्कों का यूरोपियन साम्राज्य धीरे-धीरे बिखर गया। इसके पहले की सदी में ही पतन का आरम्भ हो चुका था। शायद तुम्हें याद होगा, मैंने वियेना के तुर्की मुहासिरें यानी घेरे का जिक्र तुमसे किया था और यह बताया था कि किस तरह कुछ दिनों के लिए तुर्कों की तलवार के सामने योरप काँप उठा था। पश्चिम के धर्मपरायण ईसाई यह समझते थे कि तुर्की लोग ‘खुदा का क्रूर’ हैं, जो ईसाई संसार को उसके गुनाहों की सजा देने के लिए भेजे गये हैं। लेकिन वियेना से तुर्कों के आखिरी बार हार कर वापस आने के बाद से हवा बिल्कुल बदल गई और इसके बाद से तुर्क लोग योरप में सिर्फ आत्म-रक्षा ही में लगे रहे। दक्षिण-पूर्वी योरप की अनेक क्लौमें, जिन्हें इन्होंने जीता था, काँटे की तरह इनको चुभ रही थीं। इन क्लौमों को मिलाने-जुलाने की इनकी तरफ़ से कोई कोशिश नहीं की गई; और अगर कोशिश होती भी तो शायद कामयाबी न होती, क्योंकि तुर्कों की सख्त और बोझेली हुकूमत के खिलाफ़ राष्ट्रीयता के ख़याल जोर पकड़ रहे थे। उत्तर-पूर्व की दिशा में ज़ार का रूस दिन-दिन फैलता और बड़ा होता जाता था और तुर्की प्रदेशों को दबाता जा रहा था। वह तुर्कों का पुश्तैनी और स्यायी दुश्मन होगया और करीब दोसौ वर्ष तक उनसे समय-समय पर युद्ध करता रहा, जिसके बाद ज़ार और सुलतान दोनों करीब-करीब साथ-ही-साथ ख़तम होगये और अपने साथ अपना-अपना साम्राज्य भी लेते गये।

साम्राज्यों की दृष्टि से उस्मानी साम्राज्य काफ़ी दिनों तक क़ायम रहा। एशिया-

माइनर में बहुत दिन क़ायम रहने के बाद सन् १३६१ ई० में इसकी बुनियाद योरप में पड़ी। हालाँकि कुस्तुनतुनियाँ १४५३ ई० तक तुर्कों के हाथ में नहीं आया, लेकिन आस-पास का सारा मुल्क इसके बहुत पहले तुर्कों की मातहतों में आ चुका था। पश्चिमी एशिया में तैमूर के अचानक फट पड़ने से और उससे १४०२ ई० में अंगोरा में तुर्की सुलतान के बुरी तरह हार जाने की वजह से कुस्तुनतुनिया कुछ दिनों के लिए तुर्कों के क़ब्ज़े में आने से बच गया। लेकिन तुर्क लोग इस हार के बुरे असर से बहुत जल्द छूट गये। १३६१ ई० से हम लोगों के ज़माने तक यानी करीब साढ़े पाँचसौ वर्ष तक उस्मानी साम्राज्य क़ायम रहा है और यह काफ़ी लम्बा ज़माना होजाता है।

फिर भी मध्यकाल के ख़तम होने के बाद योरप में जो नई बातें और नई अवस्था पैदा हो रही थी, तुर्क उसमें फिट नहीं होते थे। व्यापार और व्यवसाय बढ़ रहा था। योरप के बड़े-बड़े कारख़ाने वाले शहरों में बड़े पैमाने पर उत्पत्ति का इन्तज़ाम हो रहा था। तुर्क लोगों को इस किस्म के काम में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये लोग बड़े अच्छे सैनिक होते थे; बड़े सख़्त लड़नेवाले और नियंत्रण के माननेवाले होते थे। लेकिन छुट्टी के वक़्त आरामतलब और गुस्सा आजाने पर बेरहम और ख़ौफ़नाक होजाया करते थे। यद्यपि ये शहरों में बस गये थे और ख़ूबसूरत इमारतें बनाकर नगरों को अलंकृत कर रक्खा था, फिर भी अपनी ख़ानाबदोशों की पुरानी आदत बिल्कुल नहीं छोड़ी थी और इनकी ज़िन्दगी पर उसका कुछ-न-कुछ असर बना ही रहता था। अगर तुर्क लोग अपने देश में इस तरह की ज़िन्दगी गुज़ारते तो शायद कोई हर्ज न था। लेकिन योरप या एशिया-माइनर के लिए जो नई परिस्थिति पैदा होरही थी उसमें इस किस्म की ज़िन्दगी बिल्कुल उपयुक्त नहीं थी। तुर्क लोग नये ज़माने के मुताबिक़ अपनेको ढालना नहीं चाहते थे, इसलिए इन दोनों भिन्न प्रणालियों में बराबर खींचतान जारी रही।

उस्मानी साम्राज्य तीन महाद्वीपों को मिलाता था—योरप, एशिया और अफ़्रीका। पूर्व और पश्चिम के दरमियान के सारे तिजारती रास्ते इसी साम्राज्य से होकर गुज़रते थे। अगर तुर्कों में व्यापारिक रुचि होती और इस काम के लिए उनमें आवश्यक क्षमता भी पाई जाती तो ये लोग अपने इस फ़ायदेमन्द मौक़े और स्थिति से फ़ायदा उठा सकते थे और इनकी एक बड़ी व्यापारिक क़ौम बन सकती थी। लेकिन इनमें इस किस्म की कोई रुचि या योग्यता नहीं थी, बल्कि ये लोग तो इस व्यापार को जानबूझकर दवाने की कोशिश करते थे—शायद इसलिए कि इन्हें यह अच्छा नहीं लगता था कि दूसरे इससे फ़ायदा उठायेँ। पुराने तिजारती रास्तों के इस तरह रुक जाने से एक हद तक मजबूर होकर योरप की समुद्री और तिजारती क़ौमों ने पूर्वी देशों तक

पहुँचने के लिए दूसरे रास्ते मालूम किये, और कोलम्बस ने पश्चिम और डायज़ और वास्कोडिगामा ने पूर्व के नये रास्ते खोज निकाले। लेकिन तुर्क लोग इन सब बातों की तरफ़ से बिल्कुल उदासीन रहे और अपने साम्राज्य पर केवल नियंत्रण और सैनिक कुशलता से शासन जमाये रक्खा। नतीजा यह निकला कि तिजारती और धन पैदा करनेवाले कामकाज उस्मानी साम्राज्य के यूरोपियन हिस्से में ख़त्म होगये। किसी हद तक इसकी वजह धार्मिक और जातीय संघर्ष भी थी। तुर्क और बालकन की ईसाई क्रौमों में आपस का मज़हबी और जातीय झगड़ा क्रूसेड के ज़माने से और उसके पहले से भी पुश्त-दर-पुश्त चला आता था। राष्ट्रीय विचारों के बढ़ने से यह आग और भी भड़क गई और आपस में बराबर झगड़ा होता रहा। उस्मानी साम्राज्य के यूरोपीय हिस्से किस तरह बरबाद होते जाते थे, इसकी एक मिसाल देता हूँ। जब यूनान १८२९ ई० में तुर्कों से आज़ाद हुआ, एथेन्स, जो बड़ा मशहूर पुराना शहर है, सिर्फ़ दो हजार बाशिन्दों का गाँव रह गया था (आज सौ वर्ष बाद इस शहर की आबादी ५ लाख से ज्यादा है।)

इन व्यापारिक और धन पैदा करनेवाली प्रवृत्तियों को छोड़ देने से तुर्क शासकों को खुद भी अख़ीर में नुक़सान पहुँचा। साम्राज्य के हाथ-पैर जब कमज़ोर और शिथिल होगये, तब साम्राज्य का दिल भी निर्बल और रोगी होगया। असल में ताज़्जुब की बात तो यह है कि इन तमाम कशमकश और दिक्कतों के होते हुए भी यह साम्राज्य इतने दिनों तक ज़िन्दा रहा।

‘जानिसारी’ कई वर्षों तक उस्मानी सुलतानों की असली ताक़त रही। ‘जानिसारी’ तुर्की सिपाहियों की एक फौजी टुकड़ी थी। इसमें गुलाम ईसाई हुआ करते थे, जिन्हें लड़कपन से बहुत सावधानी के साथ तालीम दी जाती थी। इन जानिसारियों की बात चुनकर मिस्त्र के ममलूकों की याद आजाती है; लेकिन इन दोनों में फ़र्क़ है। यद्यपि जानिसारी लोग तुर्की सेना के रत्न थे, लेकिन मिस्त्र के ममलूकों की तरह ये कभी शासक नहीं हुए। ममलूकों की तरह इनकी भी कोई पुश्तैनी जाति नहीं थी। ये लोग गुलाम थे, लेकिन इनको बहुत-सी रियायतें मिली हुई थीं और ऊँची-ऊँची जगहें और बड़े-बड़े ओहदे इनके लिए महफूज़ रहते थे। इनकी औलाद आज़ाद मुसलमान होगई और इस रियायती जत्थे में नहीं शामिल की जा सकी; क्योंकि यह जत्था सिर्फ़ गुलामों के लिए ही था, जिसमें केवल गोरे ईसाई गुलामों की ही भरती की जाती थी। ये सब बातें अब कितनी आश्चर्यजनक मालूम होती हैं! लेकिन याद रखो कि उस ज़माने में मुसलमान मुल्कों में गुलाम लफ़्ज़ के वह मानी नहीं थे जो आजकल लिये जाते हैं। गुलाम क़ानून और ज़ावते के ख़याल से तो गुलाम समझे जाते थे, लेकिन अक्सर वे बहुत ऊँचे

ओहदे तक पहुँचते थे। तुम्हें दिल्ली के गुलाम बादशाहों का तो खयाल होगा ही। मिस्र के सुलतान सलादीन भी असल में गुलाम थे। तुर्कों का खयाल यह था कि शासक-वर्ग को ज्यादा-से-ज्यादा क़ाबिल बनाने के लिए उनको अच्छी तरह से तालीम देनी चाहिए। तुर्क लोग यह जानते थे, जैसा कि हरेक शिक्षक जानता है, कि तालीम देने का सबसे अच्छा ज़माना लड़कपन से कुछ साल बाद तक हुआ करता है। मुसलमान रिआया के बच्चों को छीन लेना, उनको अपने-अपने माता-पिता से बिल्कुल अलग कर देना, और उनको गुलाम बना लेना, शायद आसान काम नहीं था। इसलिए ये लोग छोटे-छोटे ईसाई लड़कों को ले लेते थे। सुलतान के गुलामों की गृहस्थी में इनको शामिल कर लिया जाता था और इनको सख्त तालीम दी जाती थी। कहने की ज़रूरत नहीं कि ये लोग बड़े होकर मुसलमान होजाते थे।

सुलतान लोग भी इसी तरीक़े पर पाले जाते थे। सुलतानों की शादी साधारण तरीक़े से नहीं होती थी। सावधानी से चुनी हुई गुलाम लड़कियाँ उनके महल में भेज दी जाती थीं और वही इनके बच्चों की माँ होती थीं। अठारहवीं सदी की शुरुआत तक जितने सुलतान हुए, वे गुलाम माताओं की ही औलाद थे, और उन्हें उसी तरह की सख्त तालीम और कठोर नियंत्रण से गुज़रना पड़ता था जैसे घर के किसी भी दूसरे गुलाम को।

सुलतान से लेकर नीचे तक ख़ास-ख़ास कामों को करने के लिए गुलामों के इस सावधानी से किये हुए चुनाव, नियंत्रण और शिक्षा में किसी क़दर वैज्ञानिकता पाई जाती थी। इस वजह से राज्य की कुछ बातों में एक हद तक कुशलता पैदा होगई थी। इस वर्ग में नये गुलामों का खून बराबर मिलता रहता था और इसलिए कोई पुश्तैनी शासक वर्ग क़ायम नहीं हुआ। शायद इस साम्राज्य की प्रारम्भिक शक्ति इसी प्रणाली पर निर्भर थी। लेकिन ये सब बातें यूरोपीय या एशियाई परिस्थिति को देखते हुए बिल्कुल अनुकूल नहीं थीं। टर्की की यह प्रणाली सामन्त-प्रणाली भी नहीं थी, और यह उस प्रणाली से भी बहुत भिन्न थी जो योरप में सामन्तशाही की जगह पर क़ायम हो रही थी। इस प्रणाली की मातृहृती में और व्यापार या उद्योग ज्यादा न होने की वजह से, टर्की में कोई असली मध्यम वर्ग पनप न सका। फिर यह प्रणाली भी अपनी पुरानी शुद्धता के साथ सोलहवीं सदी के पिछले आधे हिस्से के बाद नहीं चल सकी। गुलामों के इस वर्ग में पुश्तैनी बात पैदा होगई और इन गुलामों के लड़के अपने कुटुम्ब में बने रहने लगे। वे अपने पिता का ही पेशा करते थे। और कई तरीकों से भी यह प्रणाली धीरे-धीरे ढीली पड़ गई। लेकिन जड़ में जो बात थी, वह बनी रही और उसकी वजह से सदियों से नज़दीकी ताल्लूक़ात रखते हुए भी टर्की

योरप से अलग और उसके लिए परदेशी बना रहा। ख़ुद टर्की के अन्दर की विदेशी जातियाँ अपना-अपना क़ानून और अपना-अपना गुट बनाये हुए एक-दूसरे से बिल्कुल अलग रहीं।

इस असाधारण और पुरानी तुर्की प्रणाली के बारे में मैंने तुमको इतना ज्यादा इसलिए बताया है कि यह अपनी जगह पर एक अद्वितीय प्रणाली थी और उस्मानी साम्राज्य के निर्माण में इस प्रणाली का काफ़ी असर पड़ा था। जाहिर है कि यह प्रणाली अब नहीं पाई जाती। अब तो यह इतिहास की बात है।

टर्की के पिछले दोसो बरसों का इतिहास उस क़शमक़श का इतिहास है जो उसने बराबर आगे बढ़नेवाले रूसियों के खिलाफ़ और पराजित क़्रीमों के विद्रोह के खिलाफ़ जारी रखी। यूनान, रूमानिया, सर्बिया बल्गेरिया, माण्टेनिग्रो, बोसनिया ये सब बालकन देश उस्मानी साम्राज्य के अंग थे। हम देख चुके हैं कि इंग्लैण्ड, फ़्रांस और रूस की मदद से १८२९ ई० में यूनान उस्मानी साम्राज्य से अलग होगया। रूस स्लाव जाति का देश है, बालकन में बल्गेरिया और सर्बिया भी स्लाव जाति के हैं। ज़ार के रूस ने यह दिखाना चाहा कि हम बालकन के इन स्लाव लोगों के रक्षक और हमदर्द हैं। लेकिन रूस का असली प्रलोभन कुस्तुनतुनिया का नगर था और उसकी कूटनीति का सारा जोर इसी बात पर था कि किसी तरह से आख़िर में साम्राज्य की यह प्राचीन राजधानी हाथ आ जाय। क्योंकि ज़ार अपनेको बिज़ेन्टाइन सम्राटों का वारिस समझता था। १७३० ई० में रूसी-तुर्की लड़ाइयों का सिलसिला शुरू हुआ और बीच-बीच में चन्द दिनों की सुलह के साथ यह १७६८, १७९२, १८०७, १८२८, १८५३, १८७७ और अन्त में १९१४ तक जारी रहा। १७७४ ई० में रूस ने टर्की से क्रीमिया छीन लिया और काले समुद्र तक पहुँच गया। लेकिन इससे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ; क्योंकि काला समुद्र तो बोतल की तरह बन्द है, जिसके मुँह पर कुस्तुनतुनिया की डाट लगी है। १७९२ और १८०७ में रूसी सरहद कुस्तुनतुनिया की तरफ़ बढ़ती गई और तुर्की सरहद पीछे हटती गई। जब यूनान की आज़ादी की लड़ाई छिड़ी तो ज़ार ने तुर्कों को अपनी इस परेशानी में फँसा देखकर उनपर हमला करके फ़ायदा उठाना चाहा था। अगर इंग्लैण्ड और आस्ट्रिया बीच में न पड़ जाते, तो ज़ार ने इस मौक़े पर कुस्तुनतुनिया पर क़ब्ज़ा कर लिया होता।

इंग्लैण्ड और आस्ट्रिया ने टर्की को रूस से क्यों बचाया? टर्की के प्रेम से नहीं, बल्कि रूस की प्रतिद्वन्द्विता और डर की वजह से। मैं तुमको इसके पहले बता चुका हूँ कि इंग्लैण्ड और रूस के दरमियान एशिया और दूसरी जगहों में पुश्तैनी रज़ाबत चलती रही। ख़ासकर हिन्दुस्तान को क़ब्ज़े में कर लेने से अंग्रेज़ लोग बिल्कुल रूसी सरहद

तक पहुँच गये। और इन लोगों को, इस डर से कि जार का रूस हिन्दुस्तान में न जाने क्या करेगा, बराबर खौफनाक सपने दिखाई दिया करते थे; इसलिए अंग्रेजों की यह नीति थी कि रूस के रास्ते में विघ्न डालते रहें और उसे अपनी ताकत न बढ़ाने दें। अगर कुस्तुनतुनिया पर रूस का कब्जा होजाता तो उसे भूमध्यसागर में एक बढ़िया बन्दरगाह मिल जाता और वह हिन्दुस्तान के रास्ते के पास जंगी जहाजों का बेड़ा रख सकता था। इंग्लैण्ड इस खतरे में क्यों पड़े, इसलिए उसने रूस को इस बात का कभी मौक़ा नहीं दिया कि वह टर्की को कुचल दे। रूस को दूर रखने में आस्ट्रिया का भी मतलब था। आस्ट्रिया आज नन्हा-सा देश होगया है, लेकिन कुछ साल पहले यह बालकन प्रायद्वीप से मिला हुआ एक बड़ा साम्राज्य था और चाहता था कि जब टर्की के टुकड़े हों तो बालकन के प्रदेशों में से यह खुद काफ़ी बड़ा हिस्सा दबा ले, इसलिए रूस का दूर रखना इसके लिए जरूरी था।

बेचारे टर्की की बुरी हालत थी। इसके ये ताक़तवर पड़ोसी इसी इन्तज़ार में बैठे रहते थे कि टर्की को कुछ हो कि ये उसपर दूट पड़ें और उसके टुकड़े-टुकड़े कर डालें। १८५३ ई० में टर्की की तरफ़ इशारा करते हुए रूस के जार ने ब्रिटिश राजदूत से कहा था : “हमारे पास एक बीमार है—बहुत ज्यादा बीमार है…… यह किसी समय अचानक हमारी गोद में मर जा सकता है।” यह वाक्य उस वक़्त से मशहूर होगया और टर्की इसके बाद से ‘योरप का बीमार’ (Sick Man of Europe) कहा जाने लगा। लेकिन इस बीमार को मरते-मरते काफ़ी दिन लग गये।

उसी साल, १८५३ ई० में, जार ने इस मरीज की जान निकाल लेने की दूसरी कोशिश की। इसकी वजह से रूस में क्रीमियन युद्ध शुरू होगया और टर्की बच गया। २१ वर्ष बाद, १८७७ ई० में, जार ने फिर टर्की पर चोट की और उसे हरा दिया; लेकिन फिर विदेशी हस्तक्षेप की वजह से टर्की बच गया। कम-से-कम कुस्तुनतुनिया रूस के पंजे में न जा सका। टर्की की किस्मत का फ़ैसला करने के लिए १८७८ ई० में बर्लिन में एक मशहूर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। इसमें बिस्मार्क शामिल था और डिज़रेली भी। योरप के कितने ही मशहूर राजनीतिज्ञ भी इसमें बुलाये गये थे। इस सम्मेलन में इन लोगों ने एक-दूसरे को धमकियाँ दीं और एक-दूसरे के खिलाफ़ साजिश की। इंग्लैण्ड तो रूस से युद्ध तक करने के लिए तैयार होगया था लेकिन अन्त में रूस ठण्डा पड़ गया। बर्लिन के इस सुलहनामे का यह नतीजा हुआ कि बल्गेरिया, सर्बिया, रूमानिया और माण्टेनिग्रो की बालकन रियासतें आजाद होगईं। आस्ट्रिया ने बोसोना और हरज़ोगोविना पर कब्ज़ा कर

लिया। ये उसूलन टर्की की मातहतता में समझे जाते थे और टर्की का साथ देने के बदले में ब्रिटेन ने साइप्रस का टापू उससे कमीशन में लेलिया।

दूसरा रूसी-तुर्की युद्ध ३६ वर्ष बाद, १९१४ ई० में, महायुद्ध के सिलसिले में हुआ।

इस दरमियान टर्की में काफ़ी तब्दीलियाँ हो चुकी थीं। १७७४ ई० में रूसियों से शिकस्त खा जाने पर तुर्की को पहला धक्का पहुँचा था और तुर्की लोग समझने लग गये थे कि योरप के और देशों से वे पीछे होते जा रहे हैं। फ़ौजी क्रौम होने के वजह से सबसे पहले इनका ध्यान फ़ौज को आधुनिक बनाने की तरफ़ गया। कुछ हद तक यह काम हुआ और टर्की में नये अफसरों के जरिये से पश्चिमी ख़यालात फ़ले। जैसा मैंने तुमको बताया है, टर्की में कोई मध्य वर्ग नहीं था और न कोई दूसरा ही संगठित वर्ग पाया जाता था। १८५३-५६ ई० के क्रीमियन युद्ध के बाद टर्की को पश्चिमी रंग में रँगने की ख़ास तौर से कोशिश की गई। बधानिक सरकार बनाने का आन्दोलन चला, जिसका उद्देश्य यह था कि सुलतान के निरंकुश शासन के बजाय प्रजासत्तात्मक धारासभा बने। इस आन्दोलन के नेता मिदहतपाशा थे। १८७६ ई० में कुस्तुनतुनिया में विधान के लिए बलबे हुए, और सुलतान ने विधान मंजूर कर लिया। लेकिन चंद दिन भी न गुजरे थे कि उसने विधान को तोड़ दिया, क्योंकि बलगेरिया में बगावत पैदा होगई और रूसियों के साथ जंग छिड़ गई। एक तो लड़ाई का भारी ख़र्चा, दूसरे सुधार के सिलसिले में धन का व्यय, फिर टर्की में कोई मौलिक आर्थिक परिवर्तन नहीं हुआ था। नतीजा यह निकला कि तुर्की सरकार दिवालिया होगई और उसे पश्चिमी साहूकारों से रुपया ऋज लेना पड़ा और इन साहूकारों ने मालगुजारी के एक हिस्से पर अपना अधिकार जमा लिया। इसलिए टर्की को पश्चिमी रंग देने और वहाँ सुधार करने की कोशिश सफल नहीं रही। साम्राज्य के पुराने ढाँचे में इस नई चीज़ का जोड़ लगाना मुश्किल था।

बीसवीं सदी की शुरुआत में विधान की माँग ने फिर जोर पकड़ा। पहले की तरह सैनिक अफ़सर ही सिर्फ़ एक संगठित वर्ग कहे जा सकते थे और इन्हींके दरमियान 'नौजवान तुर्की दल' की नई पार्टी बनी। खुफ़िया तौर से 'यूनियन और प्राग्रेस की कमेटियाँ' यानी एकता और उन्नति की सभायें बनने लगीं और जब इन कमेटियों ने फ़ौज का बहुत ज्यादा हिस्सा अपनी तरफ़ कर लिया तब १९०८ ई० में इन्होंने सुलतान को इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि वह १८७६ ई० का विधान फिर जारी करे। बड़ी खुशियाँ मनाई गईं। तुर्क, आरमीनियन और दूसरे लोग जो अभी एक-दूसरे का गला काटते थे, एक-दूसरे के गले मिले और इस नये युग के उदय पर खुशी के आँसू बहाये, जिसमें सबको बराबर का हक़ मिलनेवाला था और परा-

जित कौमों को भी पूरे-पूरे अधिकार दिये जानेवाले थे । बिना एक क़तरा खून बहाये होनेवाली इस क्रांति का नायक, खूबसूरत और अभिमानी लेकिन बहादुर और साहसी, अनवरबे था । मुस्तफ़ा कमाल भी, जो बाद को टर्की का उद्धारक हुआ, एक मशहूर नौजवान तुर्की नेता था; लेकिन अनवरबे के मुकाबिले में इसका नाम मशहूर नहीं था और ये दोनों एक-दूसरे को पसन्द भी नहीं करते थे ।

नौजवान तुर्की की ज़िन्दगी कोई आराम की ज़िन्दगी नहीं थी । सुलतान इन लोगों को परेशान करता रहता था । अख़ीर में रक्तपात हुआ ही । सुलतान तख़्त से उतार दिया गया और उसकी जगह दूसरा बैठाया गया । आर्थिक कठिनाइयाँ सामने आईं और विदेशी शक्तियों से भी परेशानी पैदा होने लगी । आस्ट्रिया ने टर्की की इस गड़बड़ी से फ़ायदा उठाकर बोसीना और हरजीगोविना को अपने साम्राज्य में मिलाने का ऐलान कर दिया । इन प्रदेशों पर उसने बर्लिन के सुल्हनामे के बाद १८७८ ई० में कब्ज़ा किया था । इटली ने उत्तर अफ़्रीका में ट्रिपोली पर कब्ज़ा कर लिया और युद्ध की घोषणा करदी । तुर्क लोग कुछ कर-धर नहीं सकते थे, क्योंकि इनके पास जल-सेना नहीं थी और इसलिए इन्हें मजबूर होकर इटली की माँगों को मंज़ूर करना पड़ा । यह सब कार्रवाई हो ही रही थी कि घर के भीतर ही एक-दूसरा क़तरा आ खड़ा हुआ । बल्गेरिया, सर्बिया, यूनान, माण्टेनिग्रो, जो तुर्की को योरप से निकालने के लिए उत्सुक थे, संगठित होगये और ‘बालकन लीग’ बनाकर अक्टूबर १९१२ ई० में टर्की के ऊपर हमला कर दिया । टर्की असंगठित और पस्त था ही और शासन के लिए विधान-दल और संकीर्ण दल में झगड़ा चल रहा था । ‘बालकन लीग’ के सामने टर्की बिल्कुल चारों खाने चित्त होगया और इसे बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा । इस तरह पहला बालकन युद्ध चन्द महीनों में ख़त्म होगया और टर्की योरप से बिल्कुल निकाल दिया गया । सिर्फ़ कुस्तुन्तुनिया उसके क़ब्ज़े में रह गया । टर्की का सबसे पुराना शहर एड्रियानोपल भी टर्की की मर्जी के बिल्कुल खिलाफ़ उससे छीन लिया गया ।

थोड़े ही दिन के बाद लूट के बँटवारे पर विजयी लोग आपस में लड़ गये और बल्गेरिया ने अपने पुराने मित्रों पर धोखे से हमला कर दिया । इन लोगों ने एक-दूसरे का खूब खून बहाया और गड़बड़ी से फ़ायदा उठाने के लिए रूमानिया, जो अभी-तक अलग था, इस झगड़े में शामिल होगया । नतीजा यह हुआ कि बल्गेरिया ने जो कुछ पाया था खो दिया और रूमानिया, यूनान और सर्बिया ने अपना राज खूब बढ़ा लिया । टर्की को एड्रियानोपल वापस मिल गया । बालकन के लोगों की आपसी नफ़रत देखकर आश्चर्य होता है । बालकन की रियासतें छोटी हैं, लेकिन वे कितनी हो दफ़ा योरप का तूफ़ानी केन्द्र रह चुकी हैं ।

नौजवान तुर्कों ने जिस सुलतान को १९०९ ई० में तख्त से उतारा था, वह बड़ा दिलचस्प व्यक्ति था। उसका नाम था अब्दुल हमीद द्वितीय, और वह १८७६ ई० में तख्त पर बैठा था। उसे सुधार या नई ईजाद की कोई बात पसन्द नहीं थी, लेकिन वह अपने ढंग का योग्य आदमी था। उसकी शोहरत इस बात की थी कि वह बड़ी-बड़ी शक्तियों को एक-दूसरे से लड़ा देने में बेमिसाल आदमी है। तुम्हें याद होगा कि तमाम उस्मानी सुलतान खलीफा यानी इस्लाम के धार्मिक प्रमुख भी होते थे। अब्दुलहमीद ने एक 'पैन इस्लामी' यानी अखिल इस्लामी आन्दोलन चलाकर अपनी इस हैसियत का फायदा उठाना चाहा। यह ऐसा आन्दोलन था जिसमें दूसरे देश के मुसलमान लोग भी शामिल हो सकते थे और इस तरह अब्दुलहमीद को इनकी मदद मिल सकती थी। योरोप और एशिया में इस अखिल इस्लामवाद की काफ़ी चर्चा रही, लेकिन इसकी बुनियाद मजबूत नहीं थी और महायुद्ध ने इस आन्दोलन का बिल्कुल ख़ातमा ही कर दिया। टर्की में राष्ट्रवाद ने 'अखिल इस्लामवाद' का विरोध किया और राष्ट्रवाद अधिक ताक़तवर साबित हुआ।

सुलतान अब्दुलहमीद योरोप में बहुत बदनाम होगये, क्योंकि लोग समझते थे कि बल्गेरिया, अरमीनिया और दूसरी जगहों के अत्याचार और क़त्लेआम के लिए यही जिम्मेदार हैं। ग्लेडस्टन इनको 'महान् हत्यारा' कहता था और इन अत्याचारों के बारे में उसने इंग्लैण्ड में एक बड़ा आन्दोलन चलाया था। तुर्क लोग खुद इनके राज्य-काल को अपने इतिहास का सबसे अधिक 'अंधेरा ज़माना' मानते हैं। इनके ज़माने में बालकन प्रायद्वीप में अत्याचार और क़त्लेआम नियमित-सी घटनाएँ थीं और दोनों पार्टियाँ इसमें हिस्सा लेती थीं। बालकन-निवासी और आरमीनियन तुर्कों को क़त्ल करने के उतने ही दोषी थे जितने तुर्क आरमीनियन लोगों के। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आन्दोलन चलाने और राष्ट्रीय आन्दोलन को दबाने का यह तरीक़ा बहुत क्रूर और कठोर था। सदियों के धार्मिक और जातीय विद्वेष ने इन लोगों की प्रकृति में घर कर लिया था और वह भयंकर रूप में प्रकट होता था। आरमीनिया सबसे ज्यादा सताया गया था। अब आरमीनिया काकेशस के पास एक सोवियट प्रजातन्त्र है।

इस तरह बालकन युद्धों के बाद टर्की बिल्कुल पस्त होगया और योरोप में सिर्फ़ एक जगह उसके क़दम रखने के लिए बची। उसके साम्राज्य का बाक़ी हिस्सा भी बिखर रहा था। मिस्र सिर्फ़ नाम-मात्र के लिए उसका था। असल में उसपर क़ब्ज़ा ब्रिटेन का था, जो उसे चूस रहा था। लेकिन दूसरे अरब देशों में राष्ट्रीयता के चिन्ह जाहिर हो रहे थे। आश्चर्य की बात नहीं कि ऐसी स्थिति में टर्की मायूस हो

जाय और उसकी आँखें खुल जायँ । १९०८ ई० के उसके सारे बड़े-बड़े मनसूबे मिट्टी में मिल गये । उस समय जर्मनी इससे कुछ हमदर्दी जाहिर करता मालूम हुआ । उस वक्त जर्मनी की आँखें पूर्व की तरफ़ थीं और वह सारे मध्य-पूर्व (Middle East) पर अपना प्रभाव जमाने का बुरा सपना देख रहा था । टर्की भी जर्मनी की तरफ़ झुका और उसके ताल्लुकात बढ़ने लगे । दूसरे बालकन युद्ध के ख़तम होने के सालभर के बाद, १९१४ ई० में जब महायुद्ध शुरू हुआ, स्थिति यह थी । टर्की की किस्मत में अवकाश नहीं लिखा था ।

पुराने टर्की के बारे में पढ़ते हुए तुम्हें 'सब्लाइम पोर्ट' (Sublime Porte) का शब्द अकसर मिला होगा, जिसका अर्थ है तुर्की सरकार । मैं सोचा करता था कि इतना बढ़िया नाम इसका क्यों पड़ा ? मालूम यह होता है कि जिस इमारत में पुरानी तुर्की सरकार का ख़ास दफ़्तर था उसका फाटक ऊँचा था, इसलिए तुर्की सरकार को ही लोग सब्लाइम पोर्ट (Sublime Porte) कहने लगे । लोग सरकारी दफ़्तरों का नामकरण इसी प्रकार करते हैं । इसमें ज्यादा शान मालूम होती है । ब्रिटिश सरकार को 'हाइट हाल' कहते हैं । इसी तरह जहाँ ब्रिटिश प्रधानसचिव रहते हैं वह डाउनिंगस्ट्रीट कहलाता है और फ़्रान्स के वैदेशिक दफ़्तर को 'क्वे द ओर्ज़े' कहा जाता है ।

लेकिन मेरा ख़याल है कि अब 'शानदार फाटक' जैसी कोई चीज़ बाक़ी नहीं रही । टर्की की राजधानी अब अंगोरा में है और कुस्तुनतुनिया, जो अब इस्तम्बोल कहलाता है, एक प्रान्तीय शहर होगया है ।

: १४३ :

ज़ारों का रूस

१६ मार्च, १९३३

रूस आज सोवियट देश है और किसानों और मजदूरों के प्रतिनिधि इसका राज्य चलाते हैं । बाज़ बातों में यह दुनिया का सबसे आगे बढ़ा हुआ देश है । असली हालत चाहे जो हो, यहाँके समाज और सरकार की इमारत सामाजिक समता के उतूल पर खड़ी की गई है । यह आज-कल की दशा है । लेकिन कुछ साल पहले और सारी उन्नीसवीं सदीभर रूस योरप का सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ और संकीर्ण देश था । यहाँपर निरंकुशता और तानाशाही अपने असली रूप में पाई जाती थी । पश्चिमी योरप में परिवर्तन और क्रान्ति के होते हुए भी ज़ार लोग बादशाहों के

ईश्वरीय अधिकार के उसूल को मानते थे। यहाँका चर्च और पादरी-समुदाय, जो पुराना कट्टर यूनानी चर्च था (रोमन या प्रोटेस्टेण्ट नहीं), और जगहों के मुकाबिले में ज्यादा निरंकुश और हुकूमतपसन्द था और जार की सरकार का खास हिमायती और उसके हाथ की कठपुतली था। इस देश को 'पवित्र रूस' कहते थे और जार हरेक का 'नन्हा गोरा पिता' (Little White Father) समझा जाता था। चर्च के आदमी और पादरी लोग इन कथाओं को आदमियों की बुद्धि को कुन्द करने के लिए और आर्थिक और राजनैतिक दशा से उनका ध्यान दूर हटाने के लिए काम में लाते थे। इतिहास में धर्म ने अजीब-अजीब साथी बनाये हैं।

'पवित्र रूस' का मुख्य प्रतीक 'नाउट' (Knout) यानी चाबुक था और एक विशेष पेशा 'पोग्रोम्स' (Pogroms) हुआ करता था। जार के रूस ने दुनिया के सामने ये दो शब्द पेश किये हैं। 'नाउट' चाबुक को कहते थे, जिससे सर्फ़ यानी किसानों को या किसी दूसरे को सजा दी जाती थी और 'पोग्रोम्स' का मतलब था मारकाट, बरबादी और संगठित अत्याचार। अमली तौर से इसका मतलब होता था लोगों का, खासकर यहूदियों का, क़त्लेआम। जार के रूस के पास साइबेरिया का सुनसान और वीरान मैदान भी था। इस नाम के कहते ही हमें देशनिकाले, क़ैद और निराशा की याद आजाती है। साइबेरिया को राजनैतिक क़ैदी बहुत बड़ी तादाद में भेजे जाते थे और वहाँ देशनिर्वासित लोगों के बड़े-बड़े कैम्प और उपनिवेश पैदा हो गये थे। इन कैम्पों और उपनिवेशों के पास आत्म-हत्या करनेवालों की क़ब्रें हुआ करती थीं। लम्बी तनहाई, जलावतनी और सजा मुश्किल से बर्दाश्त होती है। अनेक बहादुरों का दिमाग़ इनकी वजह से ख़राब होजाता है और इनके बोझ से शरीर टूट जाता है। दुनिया से अलग रहने के लिए और उन दोस्तों, साथियों और लोगों से जुदा रहने के लिए, जिनकी आशायें अपनी आशायें हैं या जो अपनी चिन्ताओं के बोझ को हलका करते हैं, आदमी में मानसिक शक्ति और अन्दरूनी गहराई होनी चाहिए, जो शान्त और निश्चल रखे और बर्दाश्त करने की हिम्मत दे। जिसने सिर उठाया, जार के रूस ने उसको प्रहार करके नीचे गिरा दिया और जब-जब आज़ादी की कोशिश की गई तब-तब जार के रूस ने उसे पस्त कर दिया। सफ़र को भी मुश्किल बना दिया गया था, जिससे स्वतंत्र विचार बाहर से आकर न फैल सकें। लेकिन आज़ादी की ख्वाहिश को जब दबाया जाता है तो वह सूद-दर-सूद के साथ उभरती है, और ऐसी हालत में जब वह आगे बढ़ती है तो बड़ी तेज़ी के साथ कूदकर चलती है जिससे कि पुराना रंग-ढंग चौपट होजाता है।

हमने पहले की चिट्ठियों में टर्की में, ईरान में, मध्य-एशिया में दूर के

पश्चिमी देशों में, यानी एशिया और योरोप के बहुतेरे हिस्सों में, जार के रूस की राजनीति और कारगुजारियों की कुछ झलक देखी है। अब हम इन अलग-अलग कारगुजारियों को असली विषय के साथ जोड़कर देखेंगे कि हमारे सामने कैसी तस्वीर आती है। रूस की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि इसके हमेशा दो मुख रहे हैं। एक पश्चिम की तरफ़, दूसरा पूर्व की तरफ़। अपनी इस स्थिति के कारण ही यह यूरोशियन शक्ति बनी है और अपने इतिहास के आखिरी हिस्से में इसने कभी पूर्व और कभी पश्चिम में दिलचस्पी ली है। जब पश्चिम से भगाया गया तो यह पूर्व की तरफ़ चला और जब पूर्व की तरफ़ रोक दिया गया तो पश्चिम की तरफ़ पलट गया।

मैंने तुम्हें बताया है कि चंगेजखाँ का बनाया हुआ पुराना मंगोल साम्राज्य किस तरह से टूटा और किस तरह से मास्को के राजकुमार के नेतृत्व में रूसी राजवंशियों ने 'मुनहरे कबीले' के मंगोलों को अन्त में रूस से निकाल दिया। यह घटना चौदहवीं सदी के अख़ीर में हुई। धीरे-धीरे मास्को के राजकुमार सारे देश के निरंकुश शासक होगये और अपनेको जार (सीज़र) कहने लगे। इन लोगों के रस्म-रिवाज़ और ख़यालात ज़्यादातर मंगोलियन ही बने रहे और पश्चिमी योरोप और इनमें कोई बात मिलती-जुलती नहीं थी। पश्चिमी योरोप रूस को जंगली समझता था। १६८९ ई० में जार पीटर, जिसको पीटर महान् कहा गया है, तख़्त पर बैठा। उसने यह निश्चय किया कि रूस पश्चिम की तरफ़ झुके और उसने खुद यूरोपियन देशों में वहाँकी हालत समझने के लिए लम्बा दौरा किया। जो कुछ उसने देखा उसमें से ज़्यादातर चीज़ों की उसने नक़ल की और अपने देश के जाहिल, बेदिल और क्षिप्तकते हुए अमीरों में यूरोपीय ख़यालात भर दिये। जनता तो बहुत ही पिछड़ी और दबी हुई थी। इसलिए जार के सामने इस बात का कोई सवाल ही नहीं था कि वे लोग सुधार के द्वारे में क्या राय रखते हैं। पीटर ने देखा कि उसके ज़माने की बड़ी-बड़ी कौमों समुद्र पर बहुत ही मजबूत हैं। उसने समुद्री ताक़त का महत्त्व समझा; लेकिन रूस के पास, जो इतना लम्बा-चौड़ा था, सिवा आर्कटिक समुद्र के, जो बिल्कुल बेकार था, किसी दूसरे समुद्र में बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं था। इसलिए वह उत्तर-पश्चिम में बाल्टिक की ओर और दक्षिण में क्रीमिया की ओर बढ़ा। वह खुद क्रीमिया तक नहीं पहुँचा, लेकिन उसके बाद के जार वहाँतक पहुँचे। हाँ, वह स्वीडन को हराकर बाल्टिक तक ज़रूर पहुँच गया और सेंटपीटर्सबर्ग नाम के शहर की बुनियाद डाली, जो एक नया पश्चिमी ढंग का शहर था। फ़िनलैण्ड की खाड़ी से द्वार, जिससे होकर बाल्टिक में पहुँच सकते थे, यह शहर नेवा नदी के तट पर बसा हुआ था। उसने सेंटपीटर्सबर्ग को अपनी राजधानी बनाया और इस तरह उस पुरानी परिपाटी

को, जिसने मास्को को जकड़ रक्खा था, तोड़ने की कोशिश की। १७२५ ई० में पीटर मर गया।

इससे आधी सदी से ज्यादा समय के बाद, १७८२ ई० में, रूस के एक दूसरे शासक ने इस मुल्क को पश्चिमी बनाना चाहा। यह एक स्त्री थी। इसका नाम कैथरीन द्वितीय था और इसको भी महान् की पदवी मिली है। यह एक असाधारण स्त्री थी—सएत, बेरहम, क्राधिल और अपनी खानगी जिन्दगी के बारे में बदनाम। अपने पति जार को क़त्ल करके यह सारे रूस की निरंकुश शासक होगई थी और इसने चौदह वर्ष तक राज्य किया। यह अपनेआपको संस्कृति की बहुत बड़ी संरक्षक जाहिर करती थी और इसने वाल्तेयर से दोस्ती भी करनी चाही, जिसके साथ इसका पत्र-व्यवहार तो होता ही था। इसने किसी हदतक वर्साई के फ़्रांसीसी दरबार की नक़ल की थी और कुछ शिक्षा-सम्बन्धी सुधार भी किये थे; लेकिन ये सब बातें दिखाने के लिए और चोटी पर की गई थीं। संस्कृति की नक़ल एकदम से नहीं की जा सकती; उठाको तो बढ़ने का मौक़ा देना चाहिए। अगर कोई पिछड़ी हुई क्रौम किसी तरक्की की हुई क्रौम की सिर्फ़ नक़ल करती है, तो वह असली संस्कृति के सोने और चांदी को बदलकर टिन बना देती है। पश्चिमी योरप की संस्कृति चन्द सामाजिक अवस्थाओं पर निर्भर थी। पीटर और कैथरीन ने इन अवस्थाओं को पैदा करने की कोशिश नहीं की, सिर्फ़ बाहरी ढाँचों की नक़ल करनी चाही। नतीजा यह हुआ कि इन तब्दीलियों का बोझ जनता पर पड़ गया और इससे किसानों की गुलामी मज़बूत होगई और जार की निरंकुशता भी बढ़ गई। इसकी तुलना अंग्रेजों के हिन्दुस्तान में आने से की जा सकती है। इन लोगों ने भी खर्चीले शासन की एक मशीन को हिन्दुस्तान में चलाने और क़ायम रखने की कोशिश की, लेकिन सामाजिक अवस्था में कोई तब्दीली पैदा करने की कोशिश नहीं की और न करते हैं। इतना ही नहीं, ये जान-बूझकर सामाजिक संकीर्णता और कट्टरता का पक्ष लेते हैं। इसी वजह से इनके आने के कारण सामन्त प्रथा और सामाजिक संकीर्णता और मज़बूत होगई है।

इसलिए जार के रूस में जब एक रत्ती तरक्की होती थी तो उसकी एक मन प्रतिक्रिया पैदा होजाती थी। रूसी किसान क़रीब-क़रीब गुलाम थे। वे अपने-अपने खेतों से बँधे हुए थे और बग़ैर ख़ास हुक्म के इन खेतों को नहीं छोड़ सकते थे। शिक्षा चन्द अफ़सरों में और ज़मींदार वर्ग के कुछ दिमागी आदमियों में महदूद थी। मध्यम वर्ग क़रीब-क़रीब था ही नहीं, और जनता बिल्कुल अपढ़ और पिछड़ी हुई थी। पिछले ज़माने में अकसर किसानों ने खूनी बलवे किये थे, लेकिन वे बलवे बहुत ज्यादा जुल्म

की वजह से आँख मूँदकर किये गये थे और इसीलिए फ़ौरन ही पस्त भी कर दिये गये। चोटी के लोगों में कुछ शिक्षा थी, इसलिए पश्चिमी योरप में फैले हुए ख़यालात जनता में भी टपक-टपक कर पहुँच गये थे। यह फ़्रान्सीसी क्रान्ति और बाद में नेपोलियन का ज़माना था। तुम्हें याद होगा कि नेपोलियन के पतन से सारे योरप में प्रतिक्रिया पैदा होगई थी, और ज़ार अलेग्ज़ेण्डर प्रथम अपने तमाम बादशाहों की 'पवित्र गोष्ठी' के साथ इस प्रतिक्रिया का नेता था। इसका वारिस इससे भी बदतर था। आज्ञा आकर नौजवान अफ़सरों और विद्वानों के एक जत्थे ने १८२५ ई० में बलवा कर दिया। ये सबके सब ज़मींदार वर्ग के थे और जनता या फ़ौज की इनको कोई मदद न थी। ये लोग भी पीस दिये गये। इनको 'डिसम्बरिस्ट' कहते हैं, क्योंकि इनका बलवा १८२५ ई० के दिसम्बर में हुआ था। यह विद्रोह रूस में राजनैतिक जागृति का पहला चिन्ह है। इसके पहले खुफ़िया राजनैतिक कमेटियाँ बनती थीं, क्योंकि ज़ार की सरकार ने हर तरह की सार्वजनिक राजनैतिक प्रवृत्तियाँ रोक रक्खी थीं। ये खुफ़िया कमेटियाँ बनती गई और क्रान्ति के ख़यालात फैलते गये—खासकर दिमागी आदमियों में और यूनीवर्सिटी के विद्यार्थियों में।

क्रोमियन युद्ध में हार जाने के बाद रूस में कुछ सुधार किये गये। १८६१ ई० में सर्फ़ंडम यानी किसानों की गुलामी का अन्त हुआ। किसानों के लिए यह बहुत बड़ी चीज़ थी, लेकिन इससे उनकी मुसीबतों में कोई ख़ास कमी नहीं आई; क्योंकि आज़ाद किसानों को इतनी ज़मीन नहीं दी गई थी कि वे अपनी गुज़र-बसर कर सकें। इसी दरमियान पढ़े-लिखों में क्रान्ति के विचार फैल रहे थे और उसीके साथ-साथ ज़ार की सरकार का इन विचारों के खिलाफ़ दमन भी जारी था। इस उन्नत शिक्षित वर्ग और किसानों के दरमियान कोई रिश्ता या सम्पर्क में आने के लिए समान क्षेत्र नहीं पाया जाता था। इसलिए १८७० ई० के करीब समाजवादी विचार के विद्यार्थियों ने, जो बहुत आदर्शवादी और अस्पष्ट थे, यह निश्चय किया कि किसानों में अपना प्रचार शुरू किया जाय और हजारों विद्यार्थी गाँवों में घुस पड़ें। किसान लोग इन विद्यार्थियों को नहीं जानते थे। वे इनपर अविश्वास करते थे और सन्देह करते थे कि शायद सर्फ़ंडम यानी किसानों की गुलामी को फिर क़ायम करने की इन लोगों की साज़िश है। इसलिए किसान लोग इन विद्यार्थियों में से बहुतों को, जो अपनी जानपर खेलकर आये थे, गिरफ़्तार करके ज़ार की पुलिस के हवाले कर देते थे। जनता से सम्पर्क में आये बिना कोरी हवा में काम करने की यह एक अजीब मिसाल है।

किसानों के दरमियान इस पूरी असफलता से इन पढ़े-लिखे विद्यार्थियों को

बहुत धक्का पहुँचा। नाउम्मीदी और नफ़रत के आवेश में इन लोगों ने आतंकवाद का सहारा लिया; यानी बम फेंकने लगे और सरकारी अफ़सरों की हत्या करने लगे। यहींसे रूस में आतंकवाद और बम की शुरुआत होती है, जिसकी वजह से क्रान्ति की प्रवृत्तियाँ एक नया रंग पकड़ती हैं। बम फेंकनेवालों का यह दल अपनेको 'बम वाला नरम दल' कहता था और इनके आतंकवादी संगठन का नाम 'जनता का संकल्प' था। यह नाम किसी हद तक अत्युक्ति से भरा था, क्योंकि इससे जिन लोगों का ताल्लुक था वे बहुत छोटे हिस्से के प्रतिनिधि थे। इस तरह दृढ़-प्रतिज्ञ नीजवानों और युवतियों के इन गिरोहों से ज़ार की सरकार की नई कशमकश शुरू हुई। दूसरी कम तादादवाली क़ौमों और पराजित जाति के लोग क्रान्तिकारी दल में आकर शामिल होने लगे और विप्लव की शक्ति बढ़ने लगी। सरकार इन जातियों और छोटी तादादवाली क़ौमों को बहुत सताती थी। ये लोग अपनी मातृभाषा खुल्लमखुल्ला नहीं बोल सकते थे। और दूसरे बहुत-से तरीक़ों से भी इनको ज़लील और परेशान किया जाता था। पोलैण्ड, जो बड़े उद्योग-धंधों में रूस से ज्यादा आगे था, रूस का सिर्फ़ एक प्रान्त समझा जाता था और पोलैण्ड का नाम ही बिल्कुल नाबूद होगया था। पोलिश भाषा का इस्तेमाल क़ानूनन रोक दिया गया था। जब पोलैण्ड का यह हाल था तो दूसरी छोटी तादाद वाली जातियों और क़ौमों से इससे कहीं ज्यादा बुरा बर्ताव किया ही जाता था। १८६० ई० में पोलैण्ड में बहुत बड़ा विद्रोह उठा, जिसे बड़ी बेरहमी और सख़्ती के साथ कुचल दिया गया। पचास हजार पोल देश-निर्वासित करके साइबेरिया भेज दिये गये। यहूदियों का बराबर 'पोग्रोम' यानी क़त्लेआम हुआ करता था, जिससे उनकी बहुत बड़ी तादाद दूसरे देशों में जा बसी।

यह स्वाभाविक बात थी कि अपनी-अपनी जाति पर ज़ार के इस दमन से क्रोधान्ध होकर यहूदी और दूसरी कौम के लोग रूस के आतंकवादियों में शामिल हो जायें। यों यह आतंकवाद, जिसे निहिलिज्म कहते थे, फैलने लगा और सरकार ने ख़ूनी दमन से इसका मुकाबिला किया। राजनैतिक क़ैदियों का लम्बा ताँता साइबेरिया के बीरान की तरफ़ रवाना होने लगा और कितने ही फाँसी पर चढ़ा दिये गये। इस ख़तरे से बचने के लिए ज़ार की सरकार ने एक अजीब तरीक़ा निकाली, जिसे उसने ग़ैरमामूली हद तक पहुँचा दिया। उसने आतंकवादियों और क्रान्तिकारियों में अपने उसकानेवाले एजेंट (Agents-Provocateurs) दाख़िल कर दिये। ये लोग बम फेंकने के लिए बाकायदा प्रोत्साहन देते थे और कभी-कभी खुद बम फेंकते थे, जिससे दूसरों को फाँस सकें। इनमें एक बहुत मशहूर एजेंट अज़ेफ़ था, जो बम फेंकनेवाले क्रान्तिकारियों में भी अगुआ था और साथ ही साथ रूसी खुफ़िया पुलिस का एक

प्रधान अफ़सर भी था। इसके अलावा भी इस किस्म की और भी प्रमाणित घटनायें हैं, जिनमें जार के खुफ़िया पुलिस के अफ़सरों ने पुलिस के एजेण्ट की हैसियत से बम फेंके हैं, जिससे दूसरे फँस जायें।

आतंकवादियों और दूसरे क्रांतिकारियों ने ज़बरदस्ती सरकारी ख़जाने पर छापा मारने का सिलसिला भी शुरू किया। ये लोग सरकारी इमारतों, रेलगाड़ियों, डाकख़ानों वग़ैरा पर धन के लिए छापा मारते थे। दो आदमी, जो आज दुनिया में बहुत मशहूर हैं, इन छापों में बहुत बड़ा हिस्सा लिया करते थे। एक स्टालिन जो आज रुस का करीब-करीब डिक्टेटर है, और दूसरा पिलसूडस्की जो पोलैण्ड का डिक्टेटर है। पिलसूडस्की आजकल तमाम साम्यवादियों, उग्रतावादियों और इसी तरह के लोगों के खिलाफ़ हो रहा है। लेकिन १८८० ई० में और उसके बाद भी वह दूसरे ही ढंग का था। इसको जार की जान लेने की कोशिश के जुर्म में फाँसा भी गया था और यह ५ वर्ष के लिए साइबेरिया भी भेजा गया था।

जब ये सब बातें हो रही थीं, रुस का राज्य पूर्व की दिशा में बराबर बढ़ता जा रहा था और, जैसा मैंने तुमको बताया है, पैसफ़िक (प्रशांत) सागर तक पहुँच गया था। मध्य-एशिया में यह अफ़ग़ानिस्तान की तरह तक पहुँच गया था और दक्षिण में तुर्की तरह से टकराता था। १८६० ई० के बाद से दूसरी महत्त्वपूर्ण बात यह हुई कि पश्चिमी उद्योग-धंधे बढ़ने लगे थे। यह तरक्की सिर्फ़ चन्द जगहों में ही हुई थी—जैसे पीटर्सबर्ग या उसके आसपास और मास्को में। लेकिन रुस का देश ज्यादातर कृषि-प्रधान ही रहा। जो कारखाने खुले थे, वे बिल्कुल नये ढंग के थे और अंग्रेज़ों की देख-रेख में चलते थे। इसके दो नतीजे हुए। इन चन्द व्यावसायिक क्षेत्रों में रुसी पूँजीवाद की खूब तरक्की हुई और मजदूरवर्ग भी इतनी ही तेज़ी से बढ़ गया। जैसा कि ब्रिटिश कारख़ानों में पुराने ज़माने में होता था, रुसी मजदूरों को खूब चूसा जाता था और उनसे दिन-रात काम लिया जाता था। लेकिन इतना फर्क रुस में जरूर था कि अब समाजवाद और साम्यवाद के नये खयालात पैदा होगये थे। रुसी मजदूरों का दिमाग़ ताज़ा था और इन खयालात को ग्रहण करने के लिए तैयार था। ब्रिटिश मजदूर, जिनके पीछे पुरानी परम्परायें थीं, संकुचित थे और पुराने खयालात में फँसे हुए थे।

ये नये खयालात एक शकल इस्तिहार करने लगे और 'सोशल डेमाक्रेटिक लेबर पार्टी' (समाजवादी प्रजातन्त्रात्मक मजदूर दल) बनी। यह मार्क्स के उसूलों के अनुसार बनी थी। मार्क्स को माननेवाले ये आतंकवाद के खिलाफ़ थे। मार्क्स के उसूलों के मुताबिक़ इनको मजदूरवर्ग में क्रियात्मक जोश पैदा करना था, जिससे

वे अमल करें। इसी तरीके से अपना मकसद हासिल किया जा सकता था। आतंक से किसी व्यक्ति को मार डालने से मजदूरवर्ग में इस तरह की क्रियात्मक उत्तेजना नहीं पैदा हो सकती थी, क्योंकि उद्देश्य ज़ारशाही का विनाश था—ज़ार या उसके वज़ीर की हत्या नहीं।

१८८० ई० के फ़रीव एक नौजवान, जो बाद की सारी दुनिया में लेनिन के नाम से मशहूर हुआ, स्कूल में पढ़ने के ज़माने में भी क्रान्तिकारी आन्दोलन में हिस्सा लेता था। १८८७ ई० में जब उसकी उम्र १७ वर्ष की थी, उसे बड़ा सख्त धक्का लगा था। उसका बड़ा भाई अलेग्जेण्डर, जिससे वह बहुत प्रेम करता था, ज़ार की हत्या करने की फोर्शदा के जुर्म में फांसी पर लटका दिया गया। इतना बड़ा धक्का लगने पर भी लेनिन ने कहा था कि आतंकवाद से स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। स्वतंत्रता तो जनता की सामूहिक लड़ाई (Mass Action) से ही मिलेगी। दिल को मजबूत करके और कठोरता के साथ यह नौजवान अपनी पढ़ाई में लगा रहा। परीक्षा में शरीक हुआ और विशेषता के साथ पास हुआ। यह मादा और यह प्रकृति थी तीस वर्ष बाद आनेवाले क्रान्ति के जन्मदाता और नेता की।

मार्क्स का यह खयाल था कि मजदूरवर्ग की क्रान्ति जर्मनी—जैसे उद्योग-प्रधान देश में शुरू होगी, जहाँका मजदूरवर्ग बड़ा और संगठित होगा। उसका खयाल था कि रूस में तो यह होगा ही नहीं; क्योंकि यह पिछड़ा और मध्यकालीन था। लेकिन रूस में उसे नौजवान लोगों में सच्चे अनुयायी मिल गये, जिन्होंने उसकी बातों का बड़े उत्साह के साथ अध्ययन किया, जिससे कि वे अपनी दुर्दशा को ख़तम कर सकें। चूँकि ज़ार के रूस में खुल्लमखुल्ला किसी प्रवृत्ति के चलाने का या बंध तरीके से कुछ करने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए ये लोग मजबूर होकर इस तरह विचार और अध्ययन करते थे। ये लोग बहुत बड़ी तादाद में जेल या साइबेरिया भेज दिये जाते थे या जलावतन कर दिये जाते थे। ये जहाँ जाते, मार्क्स के उसूलों का अध्ययन जारी रखते थे और क्रान्ति के दिन के लिए तैयारी करते थे।

रूस की इस कहानी को मैं अपने दूसरे ख़त में भी जारी रखूँगा।

: १४४ :

१९०५ की असफल रूसी क्रान्ति

१७ मार्च, १९३३

मार्क्स के अनुयायी यानी मार्क्सिस्ट रूसियों को—‘सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी’ को—१९०३ ई० में एक मुसीबत का सामना करना पड़ा। उन लोगों के सामने एक

प्रश्न आगया जिसका जवाब देना उनके लिए जरूरी था। यह सवाल हरेक दल के सामने, जो कुछ निश्चित सिद्धान्तों या आदर्शों पर निर्भर होता है, किसी-न-किसी समय आता है और इसका उत्तर देना उसके लिए जरूरी होता है। सच तो यह है कि हरेक पुरुष और स्त्री को, जिनके कुछ सिद्धान्त और विश्वास होते हैं, ऐसे संकटों का ज़िन्दगी में एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा मुक़ाबिला करना पड़ता है। सवाल यह था कि क्या हम अपने सिद्धान्तों पर बिल्कुल अटल रहें और मजदूर-वर्ग की क्रान्ति करें, या मौजूदा परिस्थिति से ज़रा-सा समझौता कर लें और भावी क्रान्ति के लिए ज़मीन तैयार करें? यह सवाल पश्चिमी योरोप के करीब-करीब सब देशों में उठा था और हरेक जगह, कम या ज्यादा, इसकी वजह से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी या इसी क्रिस्म की पार्टियाँ कमज़ोर पड़ी थीं और उनमें अन्दरूनी झगड़ा पैदा हो गया था। जर्मनी में मार्क्स के अनुयायियों ने ब्रह्मादुरी के साथ सिद्धान्त पर सोलह आने यानी पूरे तौर पर अटल रहने का ऐलान कर दिया, अर्थात् वे क्रान्ति के पक्ष में थे, लेकिन अमली सूरत में वे कुछ नीचे उत्तर आये थे और नरम हो गये थे। फ़्रांस में कितने ही मजदूर समाजवादियों ने अपनी पार्टी को छोड़ दिया और मंत्रिमण्डल में मंत्री बन गये थे। इसी तरह इटली, बेलजियम और दूसरी जगहों में भी हुआ था। ब्रिटेन में मार्क्सवाद कमज़ोर था और वहाँ सवाल ही नहीं उठा, इसपर भी मजदूर पार्टी का एक आदमी मिनिस्टर बना था।

रूस की हालत दूसरी ही थी, क्योंकि वहाँ पार्लमेण्टरी यानी वैधानिक कार-गुजारियों के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं थी। वहाँ कोई पार्लमेण्ट न थी। इसपर भी ज़ारशाही के खिलाफ़ होनेवाली लड़ाई के ग़ैरक़ानूनी तरीक़ों के तर्क करने या छोड़ दिये जाने की उम्मीद थी और कुछ दिनों तक सिरुं सिद्धान्तों का प्रचार जारी रखने का ख़याल हो रहा था। लेकिन इस विषय में लेनिन के विचार स्पष्ट और निश्चित थे। वह अपनी माँग को कमज़ोर करने के लिए या कमज़ोरी के समझौते को तैयार नहीं था, क्योंकि उसे डर था कि ऐसा करने से कहीं अवसर ग़ाँठनेवाले उसकी पार्टी में न भर जायें। पश्चिमी सोशलिस्ट पार्टियों ने जो ढंग इस्तिफ़ार किया था, उन्हें लेनिन देख चुका था और उसका उसपर अच्छा असर नहीं पड़ा था। उसने एक दूसरे सिलसिले में वाद को लिखा था, "पार्लमेण्टरी कारगुजारियाँ या चालें, जैसी पश्चिमी सोशलिस्ट करते या चलते हैं, कहीं ज्यादा नीचे गिरानेवाली हैं। इससे हरेक समाजवादी दल धीरे-धीरे छोटा-मोटा "टैमनी हाल" बन जाता है, जिसमें आपसो नौकरी की तलाश करनेवाले और अपने ओहदे बढ़ानेवाले मिलेंगे।" (टैमनीहाल न्यूयार्क में है और राजनीतिक पतन या भ्रष्टाचार का एक प्रतीक अथवा

नमूना बन गया है ।) लेनिन ने इस बात की परवा नहीं की कि उसके साथ कितने आदमी हैं । एक दफ्ता तो उसने यहां तक कहा था कि अपनी पार्टी में अगर मुझे अकेले रहना पड़े तो मैं अकेला रहना पसन्द करूँगा । उसका आग्रह तो इस बात पर था कि जो उसके दल में शरीक हों वे पूरी तरह साथ हों और क्रान्ति के लिए सब-कुछ न्योछावर करने को तैयार हों और जनता की तालियों की भी परवाह न करें । वह विप्लव के विशेषज्ञों का एक दल तैयार करना चाहता था, जो आन्दोलन को कुशलता से चला सकें । हमदर्दी करनेवालों और अच्छे दिनों में मित्रता दिखानेवालों की उसे जरूरत नहीं थी ।

यह रास्ता बड़ी मुसीबत का था और बहुतों का खयाल था कि इसपर चलना अशुभमन्दी नहीं है । जीत तो बहरहाल लेनिन की रही और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी दो हिस्सों में बंट गई और दो नाम, जो बहुत नश्वर हो गये हैं, पैदा हो गये—बोलशेविकी और मेनशेविकी । कुछ लोगों के लिए आजकल 'बोलशेविक' शब्द बड़ा भयंकर हो गया है, लेकिन इसका अर्थ सिर्फ़ बहुमत है । 'मेनशेविक' का अर्थ अल्पमत है । १९०३ की फूट के बाद सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी में लेनिन का दल बहुमत में था, इसलिए बोलशेविक कहलाता था और उसका मतलब बहुमत दल था । यह बात याद रखने की है कि उस समय ट्राट्स्की, जिसकी उम्र २४ वर्ष की थी और जो १९१७ की क्रान्ति में लेनिन का दाहिना हाथ था, उस वक़्त मेनशेविकों की तरफ़ था । लेकिन उसने मेनशेविकों का साथ बहुत जल्द छोड़ दिया ।

ये बहस-मुवाहसे और भाषण रूस से बहुत दूर लन्दन में होते थे । इसी पार्टी की बैठक लन्दन में इसलिए करनी पड़ती थी, क्योंकि ज़ार के रूस में उसके लिए स्थान नहीं था और उसके बहुत ज्यादा सदस्य जलावतन थे या साइबेरिया से भागे हुए क़ैदी थे ।

इसी दरमियान रूस में खुद आम सुलग रही थी । राजनैतिक हड़तालें इसकी निशानी थीं । मजदूरों की राजनैतिक हड़ताल का अर्थ है वह हड़ताल जो आर्थिक लाभ के वास्ते, जैसे मजदूरी बढ़ाने के लिए, न की गई हो, बल्कि सरकार की किसी राजनैतिक कार्रवाई के खिलाफ़ की गई हो । इसका मतलब मजदूरों में राजनैतिक चेतना का होना है । जैसे अगर हिन्दुस्तानी कारखानों के मजदूर इसलिए हड़ताल करें कि दाग़ गिरफ़्तार कर लिये गये या कोई दूसरा राजनैतिक अत्याचार किया गया है तो वह राजनैतिक हड़ताल कहलायगी । ताज्जुब की बात तो यह है कि पश्चिमी योरोप में, जहाँ ट्रेडयूनियन और मजदूरों का संगठन बहुत शक्तिशाली था, इस क्रिसम की राजनैतिक हड़तालें बहुत कम होती थीं । यह भी होसकता है कि ऐसी

हड़तालों की वहाँ इसलिए कमी थी कि इनके नेता स्वार्थ के खातिर कुछ नरम होगये थे। रूस में ज़ारशाही के लगातार जुल्मों से राजनैतिक पहलू हमेशा सामने रहता था। दक्षिण रूस में १९०३ ई० में भी अनेक राजनैतिक हड़तालें आप ही आप हुई थीं। यह आन्दोलन बहुत बड़े पैमाने पर था; लेकिन चूँकि उसे नेता नहीं मिले, इसलिए दब गया।

अगले साल सुदूर पूर्व (Far East) में गड़बड़ी मची। मैंने तुम्हें दूसरे खत में लिखा था कि साइबेरिया में रेल की लम्बी लाइन उत्तरी एशिया के जंगलों को पार करते हुए प्रशांतसागर के बिल्कुल तट तक कैसे बनाई गई, १८९४ ई० के बाद से जापान के साथ किस प्रकार मुठभेड़ होती रही, और १९०४-१९०५ में रूस-जापान युद्ध कैसे हुआ। मैंने तुम्हें 'रेड सण्डे (खूनी रविवार)' के बारे में भी बताया है जो २२ जनवरी सन् १९०५ ई० को हुआ था जबकि ज़ार की फौज ने एक शान्त जलूस पर गोलियाँ चलाई थीं। यह जलूस एक पादरी के नेतृत्व में 'लिटिल फादर' यानी ज़ार के पास रोटी माँगने गया था। इससे सारे देश में नफ़रत की एक जोरदार लहर फैल गई और कई राजनैतिक हड़तालें हुईं। सबसे अख़ीर में एक आम हड़ताल सारे रूस में होगई। नये ढंग की मार्क्सवादी क्रान्ति शुरू होगई थी।

जिन श्रमिकों ने हड़तालें की थीं, ज़ास्तकर पीटर्सबर्ग मास्को जैसे बड़े केन्द्रों में, उन्होंने हरेक ऐसे केन्द्र में सोवियट नाम की एक नई संस्था बनाई। पहले-पहल सोवियट आम हड़ताल चलाने के लिए बनाई हुई कमेटी को कहते थे। ट्राट्स्की पीटर्सबर्ग में सोवियट का नेता होगया। ज़ार की सरकार पहले तो इन बातों से बिल-हुल हकबका गई और किसी हद तक झुक भी गई और वैधानिक धारासभा और लोकतंत्र के अनुसार सत्ताधिकार देने का वादा किया। ऐसा जान पड़ा मानों निरं-धुशता का गढ़ टूट गया हो। किसानों की पिछली बग़ावतें जिस चीज़ को न पा सकती थीं, आतंकवादी अपने बम से जिस चीज़ में सफल नहीं हुए थे, विधान के माननेवाले नरम दल के लिबरल लोग अपनी नपी-तुली दलीलों से जो नहीं कर सके थे, मज़दूरों ने वह आम हड़ताल से करके दिखा दिया। ज़ारशाही को अपने इतिहास में पहली मर्तबा जनता के सामने सिर झुकाना पड़ा। बाद को यह विजय खोखली निकली, लेकिन इसपर भी मज़दूरों के लिए इसका स्मरण अँधेरे में रोशनी के समान था।

ज़ार ने एक वैधानिक परिपद—'डूमा'—देने का वादा किया था। 'डूमा' का अर्थ है पिचार करने की जगह; पार्लमेण्ट की तरह कोरी बातें बनाने की जगह नहीं (फ़्रांसीसी भाषा के पार्लर Parler से यह शब्द बना है)। इस वादे से नरम दल के लिबरल लोगों का जोश ठण्डा पड़ गया। वे लोग संतुष्ट होगये। लिबरल

लोग हमेशा संतुष्ट हो जाया करते हैं। जमींदार क्रान्ति से डरकर कुछ सुधारों पर राजी होगये, जिससे खुशहाल किसानों को फायदा पहुँचा। इसके बाद जार की सरकार ने असली क्रान्तिकारियों का मुक़ाबिला किया और उनकी कमजोरी समझकर उससे पूरा फायदा उठाया। एक तरफ़ भूखे मजदूर थे, जिन्हें राजनैतिक विधान में इतनी दिलचस्पी नहीं थी, जितनी रोटी और ज्यादा मजदूरी के सवाल में थी, और जो अधिक गरीब किसान थे वे हमें “खेत दो” की छतरनाक आवाज़ उठाते थे। दूसरी तरफ़ क्रान्तिकारी लोग थे, जो खास तौर से राजनैतिक पहलू को देखते थे और पश्चिमी यूरोपियन ढंग की पार्लमेण्ट पाने की आशा रखते थे और जनता की भावना और असली माँग के बारे में ज्यादा विचार नहीं करते थे। बहुत-से ऊँचे दर्जे के कारीगर, जिन्होंने ट्रेड यूनियन का संगठन कर रक्खा था, क्रान्ति में शामिल होगये थे, क्योंकि वे राजनैतिक पहलू समझते थे। लेकिन आम तौर से शहरों और गाँवों में जनता इन बातों की तरफ से उदासीन थी। जार की सरकार ने और पुलिस ने जनता के साथ उसी पुराने ढंग से व्यवहार किया जो तमाम निरंकुश लोग काम में लाते हैं। इन्होंने फूट पैदा कराई और इस भूखी जनता को कुछ क्रान्तिकारी दलों के खिलाफ़ भड़का दिया। बदकिस्मत यहूदी लोगों का रूसियों ने क़त्ल किया और आरमीनियन लोगों का तातारियों ने। क्रान्तिकारी विद्यार्थियों और अधिक गरीब मजदूरों में मुठभेड़ हुई। देश के अनेक हिस्सों में इस तरह क्रान्ति की कमर तोड़ देने के बाद सरकार ने पीटर्सबर्ग और मास्को पर, जो क्रान्ति के तूफानी केन्द्र थे, हमला किया। पीटर्सबर्ग की सोवियट आसानी से कुचल दी गई। मास्को में फ़ौज ने क्रान्तिकारियों की मदद की, और इसलिए पाँच दिन लड़ाई लड़ने के बाद ही सोवियट पूरी तरह दबाई जा सकी। इसके बाद बदला लेना शुरू हुआ। कहा जाता है कि सरकार ने मास्को में बगैर मुकदमा चलाये एक हजार आदमियों को फाँसी देदी और सत्तर हजार को जेल भेज दिया। सारे देश में इन मुस्तलिफ़ बरावतों में क़रीब चौदह हजार आदमी मरे।

इस तरह हार और मुसीबत के साथ १९०५ ई० की रूसी क्रान्ति का ख़ातमा हुआ। इसको १९१७ की क्रान्ति का, जो कामयाब रही, पेशखीमा कहा गया है। जनता की आन्तरिक भावना के जागृत होने और उसके किसी बड़े पैमाने पर काम कर सकने से पहले उसे “बड़ी-बड़ी घटनाओं की शिक्षा मिलनी ज़रूरी है।” १९०५ई० की घटनाओं से बहुत बड़ी कीमत देकर जनता को यह अनुभव मिला।

डूमा का चुनाव हुआ और मई १९०६ में इसकी बैठक हुई। डूमा कोई क्रान्तिकारी जमात नहीं थी, लेकिन इतनी स्वतंत्र ज़रूर थी कि जार इसे पसन्द नहीं करता था,

इसलिए उसने इसे ढाई महीने के बाद बरखास्त कर दिया। विद्रोह को कुचलने के बाद जार को डूमा के क्रोध की कुछ परवा नहीं रह गई थी। डूमा के निकाले हुए डिपुटी या सदस्य, जो मध्य-वर्ग के विधान को माननेवाले लिबरल लोग थे, फ़िनलैंड भाग गये। यह पीटर्सबर्ग के बहुत नज़दीक था और जार की अध्यक्षता में एक अर्द्धस्वतंत्र देश था। इन्होंने रूसियों से अपील की कि वे डूमा की बरखास्तगी के विरोध में टैक्स देने और फ़ौज में भरती होने से इन्कार कर दें। लेकिन ये डिपुटी या डूमा के सदस्य जनता के सम्पर्क में बिल्कुल नहीं थे, इसलिए इनकी अपील का कोई असर नहीं हुआ।

दूसरे वर्ष, सन् १९०७ ई० में, डूमा का दूसरा चुनाव हुआ। पुलिस ने उग्र विचार के उम्मीदवारों के रास्ते में हर तरह की कठिनाइयाँ पैदा करके और बाज़ वक्त उनको गिरफ्तार करके इस बात की बड़ी कोशिश की कि वे न चुने जायें। इसपर भी 'डूमा' जार को पसन्द नहीं आई और उसने इसे भी ३ महीने बाद बरखास्त कर दिया। जार की सरकार ने चुनाव के क़ानून में परिवर्तन करके ऐसे 'अवाञ्छनीय' आदमियों के चुने जाने का रास्ता रोक दिया, जिनको वह नहीं चाहता था। इसमें उसे कामयाबी हुई। तीसरी डूमा बहुत ऊँचे दर्जे के दक्कियानूसी लोगों की संकीर्ण जमात थी और उसकी जिन्दगी बहुत लम्बी रही।

तुम्हें यह ताज्जुब हो सकता है कि जार ने इस कमज़ोर डूमा को बनाने की परेशानी क्यों उठाई जब कि उसमें यह ताक़त थी कि वह जैसा चाहता वैसा करके अपना काम चला सकता था और जब कि उसने १९०५ की क्रान्ति को पस्त कर दिया था। इसकी वजह एक हद तक यह थी कि वह रूस की चन्द छोटी जमातों, खासकर अमीर ज़मींदारों और व्यापारियों को, सन्तोष देना चाहता था। देश की स्थिति भी ख़राब थी। इसमें शक नहीं कि जनता पस्त कर दी गई थी, लेकिन वह नाराज़ और भरी बैठी थी। इसलिए यह मुनासिब समझा गया कि छोटी के अमीर लोगों को तो कम-से-कम मुट्ठी में रक्खा जाय। लेकिन अधिक महत्वपूर्ण कारण यूरोपियन देशों पर इस बात का असर डालना था कि जार एक उदार सम्राट् है। जार के कुशासन और अत्याचार की कहानी पश्चिमी योरोप में हरेक आदमी की ज़बान पर थी। जब डूमा पहली मर्तबा बरखास्त की गई थी, हाउस ऑफ़ कामंस (इंग्लैंड की पार्लमेण्ट की सामान्य सभा) में ब्रिटिश लिबरल पार्टी के एक नेता ने कहा था—“डूमा मर गई, डूमा जिन्दाबाद !” इससे जाहिर होता है कि डूमा के प्रति कितनी हमदर्दी थी। साथ ही उस समय जार को रुपये की और बहुत काफ़ी रुपये की ज़रूरत थी। ख़ुशहाल फ़्रांसीसी उसे रुपया उधार देते आये थे। सच तो यह है कि जार ने १९०५ की क्रान्ति को फ़्रांसीसी क़र्ज़ की मदद से ही कुचला था।

यह एक अजीब बात थी कि लोकतंत्रवादी फ्रांस निरंकुश रूस को क्रान्तिकारियों और उग्र विचार के लोगों को परत करने के लिए मदद दे ! लेकिन लोकतंत्रवादी फ्रांस का मतलब फ्रांसीसी साहूकार थे । बहरहाल बात को जाहिरा तौर से बनाये रहना जरूरी था और डूमा को क्रायम रखने से जाहिरा तौर पर बात बनी रहती थी ।

इस बीच योरप की और संसार की स्थिति जोरों के साथ बदल रही थी । रूस जब जापान से हार गया तो इंग्लैण्ड के दिल से रूस का भय जाता रहा । हाँ, जर्मनी की शक्ति में इंग्लैण्ड के लिए एक नया खतरा पैदा होगया था । व्यवसाय में और समुद्र पर, जिसमें अभीतक इंग्लैण्ड का ही इजारा था, जर्मनी पट्टीदार बनता जाता था । जर्मनी के ठर से ही फ्रांस ने रूस को इतनी उदारता से ऋज दिया था । इस जर्मन खतरे ने दो पुराने दुश्मनों को एक-दूसरे से गले मिलने को मजबूर कर दिया । १९०७ ई० में अंग्रेजी-रूसी सुलहनामे पर दस्तखत हुए जिससे अफ़ग़ानिस्तान, ईरान और दूसरी जगहों में इन दोनों के जितने झगडे थे वे तय होगये । बाद में इंग्लैण्ड, फ़्रान्स और रूस में समझौता (Entente) हुआ । वालकन में आस्ट्रिया रूस का प्रतिद्वन्दी था और आस्ट्रिया जर्मनी का दोस्त था । इसी तरह इटली कागज पर जर्मनी का दोस्त था । इस तरह से इंग्लैण्ड, फ़्रान्स और रूस के त्रिविध समझौते या गुट का मुकाबिला जर्मनी, आस्ट्रिया और इटली के त्रिगुट से होगया, फ्राँजें लड़ाई की तैयारी करने लगीं और सीधे-सादे लोग सोते रहे । उन्हें यह पता नहीं था कि भविष्य में उनके सामने उनके लिए कितनी भयंकरता आनेवाली है ।

१९०५ के बाद, रूस का यह जमाना प्रतिक्रिया का जमाना था । बोलशेविज्म और दूसरे क्रान्तिकारी तत्त्वों को पूरी नीर से कुचला जा चुका था । विदेशों में लेनिन की तरह कुछ निर्वासित बोलशेविक अपना काम धीरज के साथ चला रहे थे । किताबें और पुस्तिकायें लिखते थे और मार्क्स के उसूलों को बदलती हुई परिस्थिति के अनुसार सँचिमें ढालने की कोशिश करते थे । मेनशेविकों में अन्तर बढ़ता ही जाता था । मेनशेविक लोग अल्पसंख्यक नरमदल के मार्क्सवादी थे । मेनशेविक दल प्रतिक्रिया के जमाने में बहुत अधिक मजहूर होगया । और यद्यपि इसे अल्पसंख्यक दल कहा जाता है, पर सच तो यह है कि उस समय इस दल में कहीं ज्यादा आदमी शामिल थे । १९१२ से रूसी दुनिया में फिर एक नई तब्दीली पैदा होगई और क्रान्तिकारी प्रवृत्तियाँ बढ़ने लगीं और इसके साथ-साथ बोलशेविज्म भी बढ़ा । १९१४ के मध्य में पेट्रोग्रेड के वातावरण में क्रान्ति की चर्चा बहुत जोरों से होरही थी और १९०५ की तरह इस साल भी बहुत-सी राजनैतिक हड़तालें हुई । लेकिन क्रान्तियों की बनावट क्या खूब होती है ! बाद को यह पता चलता कि पीटर्सबर्ग की सात सदस्योंवाली एक

बोलशेविक कमेटी में तीन आदमी ऐसे थे जो ज़ार के खुफिया विभाग के नौकर थे। बोलशेविकों की यह छोटी जमात डूमा में भी थी और मालिनोवस्की इसका नेता था। बाद में पता चला कि यह भी पुलिस का आदमी था, और लेनिन इसका विश्वास करता था।

अगस्त १९१४ ई० में महायुद्ध शुरू हुआ और इसकी वजह से लोगों का ध्यान लड़ाई के मोरचों की तरफ खिंच गया और ख़ास-ख़ास काम करनेवाले अनिवार्य भरती में आगये और क्रान्तिकारी आन्दोलन मर गया। बोलशेविक लोग, जिन्होंने लड़ाई के खिलाफ़ अपनी आवाज़ उठाई, तादाद में थोड़े थे और वे बहुत ज्यादा बदनाम होगये।

अब हम फिर अपने निश्चित स्थान यानी महायुद्ध पर आगये और यहीं हमें रुक जाना चाहिए। लेकिन इस ख़त को ख़त्म करने के पहिले मैं तुम्हारा ध्यान रूस के साहित्य और कला पर लेजाना चाहता हूँ। उसमें चाहे जो दोष रहे हों, बहुतसे लोग जानते हैं कि ज़ार के रूस ने अदभुत नृत्य-कला को बनाये रखा था। ज़ार के रूस ने उन्नीसवीं सदी में कितने ही बड़े-बड़े लेखक पैदा किये, जिन्होंने महान् साहित्यिक परिपाटी का निर्माण किया। उपन्यासों और छोटी कहानियों में इन लोगों ने आश्चर्यजनक कुशलता दिखाई है। इस सदी की शुरुआत में बायरन, शेली और कीट्स का समकालिक पुश्किन हुआ, जो रूस के कवियों में सबसे बड़ा माना जाता है। उन्नीसवीं सदी के उपन्यास-लेखकों में गोगल, तुर्गनेव, दास्तोव्स्की और चोखेव मशहूर हुए हैं और सबसे बड़ा तो लियो टाल्स्टाय हुआ, जिसमें सिर्फ़ उपन्यास लिखने की ही प्रतिभा नहीं थी बल्कि जो एक धार्मिक और आध्यात्मिक नेता भी हो गया। उसका प्रभाव बहुत दूर तक फैल गया था। यह प्रभाव बापू पर भी पड़ा, जो उस समय दक्षिण अफ़्रीका में थे। ये दोनों एक-दूसरे के सिद्धान्तों को पसन्द करते थे और इनमें आपस में चिट्ठी-पत्र भी होती थी। अहिंसा में दृढ़ विश्वास इन दोनों के संयोग का बन्धन था। टाल्स्टाय के कथनानुसार ईसा की बुनियादी तालीम यही थी और बापू ने पुरानी हिन्दू किताबों से यही नतीजा निकाला था। टाल्स्टाय पंथमयर बने रहे और उन्होंने अपने सिद्धान्तों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत किया, लेकिन दुनिया से दूर रहे। बापू ने इस जाहिरा तौर पर निषेधात्मक-सी दीखनेवाली चीज़ का हिन्दुस्तान और दक्षिण अफ़्रीका की सामूहिक समस्याओं के सम्बन्ध में अमली प्रयोग किया।

उन्नीसवीं सदी के रूसी लेखकों में से एक महान् लेखक अभी तक सिन्दा है। इसका नाम मैग्निम गोर्की है।

एक युग का अन्त

मार्च २२, १९३३

उन्नीसवीं सदी ! इन सौ वर्षों ने हमें कितने लम्बे असें तक रोक रक्खा । चार महीने से समय-समय पर मैं तुम्हें इस युग के बारे में लिखता आया हूँ और इससे जरा थक और ऊब गया हूँ और जब तुम इन खतों को पढ़ोगी तो शायद तुम भी ऊब जाओगी । मैंने तुमको यह बताते हुए इसका बयान शुरू किया था कि यह एक दिल-चस्प और लुभावना जमाना था, लेकिन कुछ समय के बाद आकर्षण भी घट जाता है । सच तो यह है कि हम उन्नीसवीं सदी से आगे बढ़ गये और बीसवीं सदी में बहुत दूर तक चले आये । १९१४ हमारी हद थी । इसी साल, जैसा कहा जाता है, युद्ध के भेड़िये योरप और संसार पर टूट पड़े । इतिहास इस साल से एक नया रुख पकड़ता है । इस युग का अन्त और दूसरे का आरम्भ होता है ।

उन्नीसवीं सदी ! यह साल भी तुम्हारे बचपन के पहले का है और फिर भी इसे गुजरे उन्नीस वर्ष से कम ही हुए हैं । और इतने वर्ष मनुष्य के जीवन में भी कोई लम्बा जमाना नहीं कहा जा सकता, इतिहास में तो और भी कम समझा जायगा । लेकिन दुनिया इतने ही थोड़े वर्षों में इतनी ज्यादा तब्दील होगई है और अब भी तब्दील होती जा रही है कि मालूम होता है तब से बहुत बड़ा जमाना गुजर गया है और १९१४ तथा उसके पहले के साल अब पुराने इतिहास में मिल गये हैं और गुजरे हुए जमाने के हिस्से बन गये हैं, जिनके बारे में हम इतिहास की किताबों में पढ़ते हैं, और हम लोगों के जमाने से बिल्कुल जुदा चीज हैं । इन बड़ी-बड़ी तब्दीलियों के बारे में मुझे तुम्हें वाद को बताना होगा । मैं इस समय तुम्हें एक चेतावनी दूंगा । तुम स्कूल में भूगोल पढ़ रही हो और जो भूगोल तुम पढ़ रही हो वह उस भूगोल से बिल्कुल मुलतलिफ़ चीज है जिसे १९१४ के पहले मैंने स्कूल में पढ़ा था । यह भी मुमकिन है कि इस भूगोल का बहुत-सा हिस्सा, जिसे आज तुम पढ़ रही हो, जल्द ही तुम्हें भूल जाना पड़े, जैसा कि मुझे भूलना पड़ा । पुराने मुल्कों के निशानात और पुराने देश युद्ध के धुएँ में गायब होगये और नये-नये निशानात और देश उन जगहों पर पैदा होगये, जिनके नाम याद रखना मुश्किल है । सैकड़ों शहरों के नाम रातों-रात बदल गये । सेण्टपीटर्सबर्ग पेट्रोग्राड होगया और फिर लेनिनग्राड । कुस्तुनतुनिया का नाम अब इस्तम्बोल होगया है । पेकिन अब पेपिंग कहलाता है और वोहेमिया का प्रेग अब जेकोस्लोवाकिया का प्रहा हो गया है ।

उन्नीसवीं सदी के बारे में लिखी हुई अपनी चिट्ठियों में मैंने आवश्यकता-वश महाद्वीपों और देशों का अलग-अलग ब्यापन किया है। हमने मुस्तलिफ़ पहलुओं पर और विविध आन्दोलनों के बारे में भी अलग-अलग विचार किया है। लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए कि ये सब बातें कमोवेश साथ-साथ होती रही हैं और इतिहास संसार-भर में अपने हज़ारों पैरों के साथ आगे बढ़ा है। विज्ञान और उद्योग, राज-नीति और अर्थशास्त्र, अमीरी और गरीबी, पूंजीवाद और साम्राज्यवाद, लोकतंत्र और समाजवाद, डार्विन और मार्क्स, आजादी और गुलामी, क्रहत और महामारी, सुलह और जंग, सभ्यता और बर्बरता—इन सब चीज़ों का इस अद्भुत बनावट में अपना-अपना स्थान था, और इनमें से हरेक चीज़ का असर एक-दूसरी पर पड़ा है। अगर हम इस ज़माने या किसी दूसरे ज़माने की तस्वीर अपने मन के सामने खींचें तो वह तस्वीर बड़ी पेचीदा और कैलिडेसकोप यानी बच्चों की उस दूरबीन की तरह जिसने तरह-तरह के रंगीन दृश्य दिखाई देते हैं बराबर तब्दील होनेवाली और हरकत करनेवाली होगी। लेकिन इस तस्वीर के बहुत-से हिस्से ऐसे होंगे जिनपर गौर करना हमें अच्छा न लगेगा।

इस युग की सबसे बड़ी बात, जैसा कि हम देख चुके हैं, बड़ी मशीनों के सहारे बड़े पैमाने पर पूंजीपतियों के उद्योग-धन्धों की उन्नति थी। इस युग में उत्पत्ति किसी यांत्रिक शक्ति के जरिये से—जैसे पानी, भाप या बिजली के जरिये से—की गई। इसका प्रभाव दुनिया के जुदा-जुदा हिस्सों में जुदा-जुदा हुआ है। यह प्रभाव प्रत्यक्ष भी हुआ और अप्रत्यक्ष भी। लंकाशायर में मशीनी करघों (Power looms) से होने-वाली कपड़े की उत्पत्ति से इतने दूर हिन्दुस्तान के गाँवों की स्थिति बिगड़ गई और बहुत-से रोज़गार ख़तम होगये। पूंजीवादी उद्योग बहुत तेज़ शक्तिवाला था। अपने स्वभाव के अनुसार वह बराबर बढ़ता ही गया और उसकी भूख कभी नहीं मिटी। उसकी तयसे दड़ी विशेषता अधिक-से-अधिक चीज़ हथियाने की इच्छा थी। वह हमेशा इस बात की फ़िक्र में रहता था कि क्या पायें और क्या लेलें, और एक चीज़ पर अधिकार करने के बाद फिर दूसरी चीज़ों पर अधिकार जमाने की कोशिश करता था। व्यक्ति और राष्ट्र दोनों यही कोशिश करते थे। इस प्रणाली के अनुसार जो समाज बना उसे परिग्रही या अधिक-से-अधिक पाने की लालसा रखनेवाला समाज कहा जाता है। उद्देश हमेशा यही रहा कि ज्यादा-से-ज्यादा उत्पत्ति हो और मुनाफ़े की फ़ालतू पूंजी नये कारख़ाने खोलने, रेलें बनाने या दूसरी तरह के और रोज़गारों में लगाई जाय, और मालिक लोग तो सम्पन्न होते ही रहें। इस उद्देश्य को प्राप्त करने में बाक़ी दूसरी सब चीज़ें झुरबान करदी गईं। मज़दूर, जो इन उद्योगों से धन पैदा करता था,

सबसे कम फायदे में रहता था, और इन मजदूरों को, जिनमें औरतें और बच्चे शामिल थे, अपनी हालत सुधारने के लिए भयंकर आक्रांतों से गुजरना पड़ा है। और इस पूँजीवादी उद्योग के मुनाफ़े के लिए और उन क़ीमों के मुनाफ़े के लिए, जिनमें ये उद्योग पाये जाते थे, उपनिवेश और मातहत देश भी क़ुरबान कर दिये गये और चूस लिये गये।

इस तरह पूँजीवाद आँख बन्द करके और बेरहमी के साथ आगे बढ़ता गया और बहुत-से शिकार अपने पीछे छोड़ता गया। इसपर भी उसकी प्रगति धूमधाम से होती रही। विज्ञान की मदद से वह बहुत-सी बातों में कामयाब रहा और इस काम-याबी से दुनिया चकाचौंध होगई। ऐसा मालूम होता था, मानों यह प्रणाली उन कष्टों का शमन कर रही हो जो इसकी वजह से पैदा हुए हैं। इसफ़ाक से, कुछ जान-बूझकर नहीं, इस प्रणाली ने जिन्दगी की बहुत-सी अच्छी-अच्छी चीज़ें भी पैदा कर दीं, लेकिन इस चमकदार और खुशनुमा गिलाफ़ के नीचे बहुत-सी ख़राबियाँ छिपी थीं। सबसे ज्यादा उल्लेखनीय बात यह हुई कि विषमता पैदा होगई। यह प्रणाली जितनी तरक्की करती गई विषमता भी उतनी ही बढ़ती गई। एक तरफ़ नितान्त दरिद्रता और दूसरी तरफ़ अत्यन्त सम्पन्नता, एक ओर गन्दे झोंपड़े और दूसरी तरफ़ आकाश से बातें करनेवाले महल, एक ओर साम्राज्य और दूसरी ओर शोषित और मातहत उपनिवेश। योरप हावी था; एशिया और अफ़्रीका के महाद्वीप चूसे जाते थे। इस सदी के ज्यादातर हिस्से में अमेरिका दुनिया के घटना-प्रवाह से अलग रहा। लेकिन वह तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा था और अपने वैभव और साधनों का निर्माण कर रहा था। योरप में इंग्लैण्ड अमीर, अभिमानी और पूँजीवाद का, ख़ासकर पूँजीवाद के साम्राज्य-सम्बन्धी पहलू का, सन्तुष्ट अगुआ था।

पूँजीवादी उद्योग की तरक्की और उसके सब चीज़ों को हथियाने के स्वभाव ने बहुत जल्द मामला नाज़ुक कर दिया। विरोध और आन्दोलन उठ खड़ा हुआ और अख़ीर में मजदूरों की रक्षा के लिए उसपर कुछ बन्दिशें लगाई गईं। बड़े-बड़े कारख़ानों में शुरुआत में मजदूरों का, ख़ासकर स्त्रियों और बच्चों का, भयंकर शोषण होता था। स्त्रियों और बच्चों को मर्दों से ज्यादा नौकरियाँ दी जाती थीं, क्योंकि वे सस्ते पड़ते थे और उनसे कभी-कभी तन्दुरुस्ती को बिगाड़नेवाली और घिनीनी जगहों में १८ घण्टे काम लिया जाता था। आख़िरकार राज्य ने दख़ल दिया और क़ानून बनाये गये। इनको 'क्रैवटी क़ानून' कहते हैं और इनमें इस बात की दफ़ायें रखी गई हैं कि मजदूरी के घण्टे परिमित कर दिये जायें और कारख़ानों की परिस्थिति बेहतर बनाई जाय। इन क़ानूनों के ज़रिये स्त्रियों और बच्चों की

हिफाजत खास तौर से की गई, लेकिन इनको मंजूर कराने में बहुत मुश्किल हुई और बहुत वक्त लगा, क्योंकि कारखाने के मालिकों ने इनका जोरदार विरोध किया।

पूँजीवादी उद्योग ने साम्यवादी और समाजवादी विचार भी पैदा कर दिये। इन विचारों ने नये उद्योगों को स्वीकार किया, लेकिन पूँजीवाद की बुनियाद को चुनौती दी। मजदूरों की संस्थाएँ, ट्रेडयूनियन और अन्तर्राष्ट्रीय जमातें तरक्की करने लगीं।

पूँजीवाद से साम्राज्यवाद पैदा हुआ और पश्चिमी पूँजीवादी उद्योग के धक्के से पूर्वी देशों का बहुत दिनों से चला आनेवाला आर्थिक संगठन तहस-नहस होगया। इन पूर्वी देशों में भी आहिस्ता-आहिस्ता पूँजीवादी उद्योग जड़ पकड़ गया और बढ़ने लगा। इन देशों में पश्चिम के साम्राज्यवाद को चुनौती के रूप में राष्ट्रीयता भी पैदा होगई।

इस तरह पूँजीवाद ने दुनिया को हिला दिया। और हालांकि इसकी वजह से आदमियों को भयंकर तकलीफें हुईं, लेकिन आम तौर पर यह प्रणाली फ़ायदेमन्द रही—कम-से-कम पश्चिम के लिए तो ज़रूर। इसके साथ-साथ भौतिक चीज़ों में बहुत तरक्की हुई और मनुष्य के कल्याण का आदर्श बहुत ऊँचा उठ गया। साधारण आदमी इतना महत्वपूर्ण होगया जितना वह पहले कभी नहीं समझा जाता था। अमली तौर पर तो उसे किसी चीज़ में भी कहने-सुनने या दखल देने का हक़ नहीं था, यद्यपि वोट देने का हक़ मिला था, लेकिन सिद्धान्त-रूप से राज्य में उसकी हैसियत बढ़ गई और इसके साथ-साथ उसमें आत्म-सम्मान की भावना भी बढ़ी। यह बात पश्चिमी देशों के लिए सही कही जा सकती है, जहाँ पूँजीवादी उद्योग ने जड़ पकड़ ली थी। ज्ञान का बहुत बड़ा संग्रह होगया, और विज्ञान ने अद्भुत बातें करके दिखा दीं। इसकी मदद से बनी हुई हजारों चीज़ों ने हरेक आदमी की ज़िन्दगी में बहुत-सी आसानियाँ पैदा करदीं। औषधियों ने, खासकर औषधि-विज्ञान के उत्त हिस्से ने जिससे बीमारियों की वाढ़ रोकी जाती है, और सफ़ाई ने बहुत-सी बीमारियों की जड़ काटना और उनका शमन करना शुरू कर दिया, जिनकी वजह से आदमी की ज़िन्दगी आफ़त में रहा करती थी—जैसे मलेरिया के पैदा होने का कारण और उसकी दवा मालूम की गई और अब इसमें ज़रा भी शक नहीं रह गया है कि अगर मुनासिब कार्रवाई की जाय तो यह रोग किसी भी क्षेत्र से मिटाया जा सकता है। मलेरिया अभी तक जारी है और हिन्दुस्तान में और दूसरी जगहों पर लाखों आदमी इसके शिकार होते हैं; लेकिन यह विज्ञान का दोष नहीं, दोष है लापरवाह सरकार और ज़ाहिल जनता का।

शायद इस सदी का सबसे उल्लेखनीय पहलू यह था कि दूसरे देशों को माल भेजने और आमदरपत के साधनों में बहुत तरक्की हुई। रेल, भाप के जहाज, तार और मोटरगाड़ियों ने दुनिया को बिलकुल बदल दिया और दुनिया को इनसान के लिए ऐसी चीज बना दी जो वह कभी भी नहीं थी। दुनिया सिकुड़ गई और उसमें रहनेवाले एक-दूसरे के ज्यादा नज़दीक आगये। वे एक-दूसरे के बारे में ज्यादा जानने लगे और अज्ञान की वजह से जो अनेक टट्टियाँ खड़ी थीं वे टूट गईं। व्यापक विचार फैलने लगे, जिनकी वजह से सारी दुनिया में किसी क्रूर समानता आ गई। इस युग के अखीर में वेतार का तार और हवाई जहाज पैदा हुए। ये चीजें अब बहुत मामूली होगई हैं। तुम कई दफ़ा हवाई जहाज में बैठ चुकी हो और तुमने उसके बारे में वग़ैर कोई ख़ास विचार किये उसपर सफ़र किये हैं। वेतार के तार और हवाई जहाज की तरक्की बीसवीं सदी और हमारे जमाने में हुई। लोग अकसर बेलून में बैठकर उड़े थे, लेकिन अलिफ़लैला की उड़नेवाली परी और हिन्दुस्तानी कहानियों के उड़नखटोलों के अलावा कोई भी हवा से वज़नी चीज पर बैठकर नहीं उड़ा था। बिलबर और ऑरविले राइट नामके दो भाई, जो अमेरिकन थे, पहले लोग थे जो हवा से वज़नी मशीन पर बैठकर उड़ने में कामयाब हुए। इसी मशीन को मौजूदा हवाई जहाज की जन्मदात्री समझना चाहिए। दिसम्बर १९०३ ई० में ये ३०० गज़ से भी कम उड़े थे। लेकिन फिर भी इन्होंने ऐसी बात करली थी, जो पहले कभी नहीं हुई थी। इसके बाद उड़ने में बराबर तरक्की होती रही और मुझे याद है कि जब १९०९ ई० में फ़्रान्सीसी व्लेरियट फ़्रान्स से इंगलिश चैनल पार करके इंग्लैण्ड तक उड़ आया था, तो बड़ा तहलका मचा था। इसके बाद ही मैंने देखा कि पेरिस में एफ़िल टावर पर पहला हवाई जहाज उड़ा; और उसके बहुत साल बाद मई १९२७ में हम और तुम पेरिस में मौजूद थे, जब चार्ल्स लिण्डबर्ग चाँदी के तीर की तरह चमकता हुआ एटलान्टिक पार करके आया और पेरिस के एयरोड्रम यानी हवाई जहाज के स्टेशन ली बूर्जे में उतरा।

ये सब बातें तो इस युग की तारीफ़ में हुईं, जिसमें पूंजीवादी प्रयोग प्रमुख रहा है। इस सदी में मनुष्य ने निस्सन्देह अद्भुत काम किये। एक चीज और भी हुई जो तारीफ़ की बात समझी जा सकती है। ज्यों-ज्यों लालची और लोलुप पूंजीवाद बढ़ता गया, सहकारिता का आन्दोलन पैदा करके इसपर बन्दिश लगाई गई। सहकारिता का आन्दोलन यह था कि लोग चीजों की बिक्री और ख़रीद के लिए संगठन बना लेते हैं और जो मुनाफ़ा होता है उसे आपस में बाँट लेते हैं। पूंजीवाद का साधारण ढंग यह है कि इसमें इतनी जबरदस्त लाग-डाँट होती है कि हरेक आदमी दूसरे को

गिराने और उससे आगे निकल जाने की कोशिश करता है। सहकारिता का ढंग आपस का सहयोग है। तुमने बहुत-से कोआपरेटिव स्टोर (सहयुक्त भण्डार) देखे होंगे। कोआपरेटिव यानी सहकारिता का आन्दोलन योरप में उन्नीसवीं सदी में खूब बढ़ा। शायद डेनमार्क के छोटे देश में इसकी कामयाबी सबसे ज्यादा हुई।

राजनैतिक क्षेत्र में लोकतन्त्र के विचार बढ़े और अपनी पार्लमेण्टों और असेम्बलियों के लिए सदस्यों को चुनने में वोट देने का हक ज्यादा आदमियों को मिल गया। लेकिन यह मताधिकार सिर्फ़ मर्दों को ही मिला। स्त्रियाँ, चाहे वे कितनी ही क़ाबिल हों, इस अधिकार के लिए काफ़ी बुद्धिमान और उपयुक्त नहीं समझी जाती थीं। बहुत-सी स्त्रियों ने इसका विरोध किया और बीसवीं सदी की शुरुआत में उन्होंने इंग्लैण्ड में बहुत बड़ा आन्दोलन खड़ा कर दिया। इस आन्दोलन को 'सफ़रेज' अर्थात् स्त्रियों के मताधिकार का आन्दोलन कहते थे। और चूँकि मर्दों ने इस आन्दोलन पर कोई ध्यान नहीं दिया और इसे गम्भीरतापूर्वक नहीं लिया, इसलिए स्त्रियों ने ज़बरदस्ती और उद्दण्डता का रास्ता पकड़ा, ताकि लोगों का ध्यान इसकी तरफ़ खिंचे। ब्रिटिश पार्लमेण्ट की कार्रवाई में झगड़ा करके ये लोग विघ्न डाल देती थीं और ब्रिटिश मन्त्रि-मण्डल के मन्त्रियों पर चोट पहुँचाने के लिए हमले करती थीं, जिसके कारण इन मन्त्रियों को बराबर पुलिस के संरक्षण में रहना पड़ता था। बड़े पैमाने पर संगठित उद्दण्डता और हिंसा भी हुई। बहुत-सी स्त्रियाँ जेल भेज दी गईं। वहाँ पहुँचकर उन्होंने भूख-हड़ताल शुरू की। इसपर उन्हें छोड़ दिया गया। फिर ज्योंही वे अच्छी हो जातीं, उनको जेल भेज दिया जाता था। पार्लमेण्ट ने इस काम के लिए एक ख़ास क़ानून बनाया था, जिसे लोग 'विल्ली और चूहे का क़ानून' कहते थे। आन्दोलन करनेवालियों का यह ढंग इस बात में ज़रूर सफल रहा कि लोगों का ध्यान इस ओर खिंच गया। इसके कुछ वर्षों बाद महायुद्ध शुरू हुआ और स्त्रियों का वोट देने का हक़ मंज़ूर कर लिया गया।

स्त्रियों का यह आन्दोलन, जिसे फेमिनिस्ट आन्दोलन कहते हैं, सिर्फ़ वोट माँगने तक ही परिमित नहीं था। माँग यह थी कि उनको हरेक बात में पुरुषों से बराबरी का हक़ मिले। पश्चिम में अभी हाल तक स्त्रियों की हालत बहुत ख़राब थी; उनके कोई अस्तित्वारात नहीं थे। अंग्रेज़ स्त्रियों को क़ानून में यह हक़ नहीं मिला था कि अपने नाम से जायदाद रख सकें। सारी जायदाद, स्त्री की कमाई की भी, पति को मिल जाती थी। इस तरह क़ानूनी तौर से इन लोगों की आज की हिन्दू स्त्रियों से भी, जिनकी हालत काफ़ी बुरी है, बुरी हालत थी। पश्चिम में स्त्रियों की जाति को पराधीन समझा जाता था, जैसे बहुत-सी बातों में आज हिन्दुस्तानी स्त्रियाँ समझी जाती हैं। वोट के लिए आन्दोलन शुरू होने के बहुत पहले स्त्रियों ने

और बातों में पुरुषों के साथ बराबरी के बर्ताव के लिए मांग पेश की थी। आखिर-कार १८८० और ९० के बीच में इंग्लैण्ड में जायदाद की मिलकियत का कुछ हक स्त्रियों को मिला। स्त्रियाँ इस एक बात में एक हद तक इसलिए सफल रहीं कि कारखाने वाले इस बात को पसन्द करते थे। उनका खयाल था कि अगर औरतों को अपनी कमाई अपने पास रखने का हक मिल जायगा तो कारखानों में काम करने के लिए उनको प्रोत्साहन मिलेगा।

हरेक तरफ़ हम बड़ी-बड़ी तब्दीलियाँ देखते हैं, लेकिन शासन-प्रणाली में कोई तब्दीली नहीं आई। बड़ी-बड़ी शक्तियाँ दशावाजी और चालवाजी के ढंग पर चलती रहीं और बहुत दिन हुए प्लोरेंस के रहनेवाले मैक्याविली ने जो रास्ता बताया था, या १८०० वर्ष पहले हिन्दुस्तानी मंत्री चाणक्य ने जो मार्ग दिखाया था, उसीपर चलती रहीं। इनमें बराबर लाग-डॉट और प्रतिद्वन्द्विता होती रहती थी। गुप्त रूप से समझौते और सुलहनामे होते थे, और हरेक ताकत हमेशा ऐसी बात की फोशिश करती रहती थी कि दूसरे से आगे बढ़ जाय। योरप, जैसा हमने देखा है, जबर-दस्त और उग्र रहा और एशिया निष्क्रिय। संसार की राजनीति में औरों के मुकाबिले में अमेरिका का हिस्सा बहुत थोड़ा रहा, क्योंकि वह अपनी ही झंझटों में फँसा हुआ था।

राष्ट्रीयता के विकास के साथ-साथ 'हमारा देश, ग़लत या सही' का भाव बढ़ा। राष्ट्रों ने ऐसी बातों पर अभिमान करना शुरू किया जो अगर कोई व्यक्ति करता तो बुरा और दुष्ट समझा जाता। इस तरह से व्यक्तियों की और राष्ट्रों की नीति में एक अजीब विषमता पैदा होगई। दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क़ आगया और जो बातें किसी व्यक्ति के लिए ख़राब समझी जाती थीं वही राष्ट्रों के लिए अच्छी समझी जाने लगीं। किसी व्यक्ति, पुरुष या स्त्री के लिए स्वार्थी, लालची, अभिमानी और भोंडापन बिल्कुल बुरा और असह्य समझा जाता था; लेकिन बड़े-बड़े समूहों यानी राष्ट्रों के लिए देशभक्ति की आड़ में इन्हीं बातों की तारीफ़ होती थी और इन्हें प्रोत्साहन दिया जाता था, जैसे कि हम आज हिन्दुस्तान में देखते हैं कि साम्प्रदायिक मामलों में कितनी उद्दण्डता, स्वार्थ और भोंडापन पाया जाता है। किसी व्यक्ति में अगर ये बातें हों, तो कोई बर्दाश्त न करेगा। लेकिन अगर बड़ा समूह या बड़े राष्ट्र एक-दूसरे को क़त्ल करना भी शुरू करते हैं तो क़ाबिल तारीफ़ बात समझी जाती है। हाल के एक लेखक ने लिखा है और सही लिखा है कि "सभ्यता एक प्रकार का साधन है, जिसमें व्यक्ति अपने दोषों को अधिकाधिक बड़े समूहों और वर्गों को देता जाता है।"

इस ख़त को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन यह कहानी तो दूसरे ख़त में भी जारी रहेगी।

महायुद्ध की शुरुआत

२३ मार्च, १९३३

मैंने अपना पिछला खत तुम्हें इस बात को बताते हुए खत्म किया था कि राष्ट्र एक-दूसरे के साथ व्यवहार करने में कितने अनैतिक और कुटिल थे। जहाँ भी मुमकिन था, वे एक-दूसरे के साथ कटु और असहिष्णुता का बर्ताव करना अपनी आजादी का चिन्ह समझते थे। कोई शक्ति ऐसी नहीं थी जो उनसे कहती कि तुम एक-दूसरे पर विश्वास करो, क्योंकि वे कहते थे कि हम आजाद हैं और हम अपने मामलों में दूसरों की दस्तन्दाजी कैसे पसन्द कर सकते हैं? उनकी हरकतों पर अगर कोई बन्दिश हो सकती थी तो वह नतीजे का डर था। इसलिए मजबूतों की किसी हद तक इज्जत होती थी और कमजोरों को धमकाया जाता था।

असल में यह राष्ट्रीय प्रतिद्वन्द्विता या लाग-डांट पूंजीवादी उद्योग की तरक्की का अनिवार्य परिणाम थी। हम यह तो देख ही चुके हैं कि बाजार और कच्चे माल की बढ़ती हुई माँग के कारण पूंजीवादी शक्तियाँ साम्राज्य के लिए दुनिया के चारों ओर घुड़दौड़ कर रही थीं। ये शक्तियाँ एशिया और अफ्रीका पर पिल पड़ों और जितनी जमीन इन्हें मिल सकी, शोषण करने के लिए, उसपर क़ब्ज़ा कर लिया। जब वे पृथ्वीभर में फैल चुकीं और फैलने को दूसरी जगह नहीं रह गई, तो ये साम्राज्यवादी शक्तियाँ एक-दूसरे को घूरने लगीं और एक-दूसरे के मातहत देश पर लालचभरी निगाह डालने लगीं। एशिया, अफ्रीका और योरोप में इन शक्तियों के दरमियान अकसर मुठभेड़ होजाती थी, और क्रोधाग्नि भभक उठती थी। इनमें से कुछ शक्तियाँ दूसरों से बेहतर हालत में थीं और इंग्लैंड तो, जो उद्योग में सबसे आगे था और जिसका साम्राज्य बहुत विस्तृत था, सबसे ज्यादा भाग्यवान मालूम पड़ता था। लेकिन इंग्लैंड भी सन्तुष्ट नहीं था, क्योंकि जितना ही ज्यादा जिसके पास होता है उतना ही ज्यादा वह और चाहता है। इंग्लैंड के 'साम्राज्य-निर्माताओं' के दिमाग में ब्रिटिश साम्राज्य को बढ़ाने की लम्बी-चौड़ी योजनायें चक्कर लगाया करती थीं। वे चाहते थे कि अफ्रीका में उनका अखण्ड साम्राज्य काहरा से केप तक, उत्तर से दक्षिण तक का, क़ायम होजाय। उद्योग में संयुक्तराष्ट्र और जर्मनी की लागडांट से भी इंग्लैंड परेशान था। ये देश औद्योगिक माल इंग्लैंड से सस्ता बना रहे थे और इंग्लैंड के बाजारों पर क़ब्ज़ा करते जाते थे।

जब भाग्यवान इंग्लैंड ही सन्तुष्ट नहीं था तो दूसरों का तो और भी ज्यादा

असन्तुष्ट होता लाजिमी था। खासकर जर्मनी बहुत असन्तुष्ट था। इसकी गिनती बड़ी शक्तियों में कुछ देरी से हुई थी और इसने देखा कि बढ़िया-बढ़िया फल हाथ से निकल गये। विज्ञान, शिक्षा और उद्योग में इसने बहुत बड़ी तरफ़ाती की थी और साथ ही बहुत बड़ी फ़ौज भी जमा करली थी। मजदूरों से सम्बन्ध रखनेवाले सामाजिक सुधार के कानूनों में भी यह और देशों से, जिनमें इंग्लैंड भी शामिल था, आगे था। जब जर्मनी सामने आया, दूसरी साम्राज्यवादी शक्तियाँ पृथ्वी पर बहुत हद तक क़ब्ज़ा जमा चुकी थीं और शोषण की गुंजाइश परिमित थी। फिर भी सख्त मेहनत और आत्मानुशासन से जर्मनी उद्योगवाद और पूँजीवाद के युग की सबसे मजबूत और सबसे ज्यादा फुशल ताक़त बन गया। इसके व्यापारी जहाज हरेक बन्दरगाह में दिखाई देते थे और इसके अपने बन्दरगाह हैम्बर्ग और ब्रीमेन दुनिया के सबसे बड़े बन्दरगाहों में समझे जाते थे। जर्मनी के व्यापारिक वेडे सिर्फ जर्मनी का ही माल दूर देशों को नहीं ले जाते थे, बल्कि इन्होंने और देशों के माल ले जाने के काम पर भी क़ब्ज़ा कर लिया था।

कोई ताज्जुब नहीं कि यह नया साम्राज्यवादी जर्मनी इस सफलता को पालेने वाद और अपनी शक्ति को समझते हुए अपनी और ज्यादा बढ़ती के रास्ते की रुकावटों पर दाँत फिटफिटकर रह जाता था। प्रशा जर्मन साम्राज्य का अगुआ था और प्रशा के जमींदार और सैनिक वर्ग, जिनके हाथ में ताक़त थी, अपनी नम्शता के लिए कभी भी मशहूर नहीं रहे। ये लोग उग्र थे और इस बात का इन्हें फ़ख़्र था कि हम निर्दयता के साथ उग्र हैं। इस उद्धत अकड़ और शेखी की भावना का आदर्श नेता इन्हें हायनज़ालर्न वंश के अपने सम्राट् क़ैसर विल्हेल्म द्वितीय के रूप में मिल गया। क़ैसर इस बात की इधर-उधर घोषणा करता रहता था कि जर्मनी दुनिया का लीडर होनेवाला है; उसे पृथ्वी पर स्थान मिलना चाहिए; उसका भविष्य सामुद्रिक ताक़त पर निर्भर है और उसका उद्देश्य सारी दुनिया में अपनी संस्कृति (Culture) का प्रचार करना है।

ये सब बातें इसके पहले भी और लोग और दूसरी क़ौमों कह चुकी थीं। इंग्लैंड का 'गोरे का कर्त्तव्य' (White Man's Burden) और फ़्रांस का 'सभ्यता सिखाने का धर्म' (Civilising Mission) और जर्मनी की संस्कार (Kulture) को एक ही थैली के चट्टेवट्टे समझना चाहिए। इंग्लैंड का दावा था कि वह समुद्री ताक़त में सबसे बड़ा-चड़ा है और उसका यह दावा असल में ठीक भी था। क़ैसर जर्मनी के बारे में भी वे ही बातें कहता था जो अनेक अंग्रेज़ इंग्लैंड के बारे में पहले कह चुके थे। लेकिन क़ैसर भेदे तरीक़े से और शेखी के साथ कहता था। फ़र्क़ इतना था कि इंग्लैंड का

समुद्रों पर कब्जा था, जर्मनी का नहीं। इसपर भी क़ैसर के हेकडी से भरे भाषण अंग्रेजों को बहुत दुरे लगते थे। इस बात का खयाल तक कि कोई दूसरी क़ौम दुनिया की प्रमुख क़ौम बनने का विचार करे, अंग्रेजों को बहुत नागवार मालूम होता था। ऐसा सोचना एक क्रिस्म का कुफ़्र था, इंग्लैण्ड पर आक्रमण था, जो अपनेको सब क़ौमों का अगुआ समझता था। समुद्र तो, सौ बरस पहले ट्रैफलगर में नेपोलियन की हार के बाद, इंग्लैण्ड का इजारा समझा जाता था। इसलिए अंग्रेजों को यह बात बहुत नामुनासिब मालूम होती थी कि जर्मनी या कोई दूसरी क़ौम उसको चुनौती दे। अगर ब्रिटेन समुद्र पर मजबूत न रहा, तो उसके दूर-दूर बिखरे हुए साम्राज्य की क्या दशा होगी ?

क़ैसर की चुनौती और धमकियाँ तो काफ़ी बुरी थीं, लेकिन इससे बदतर बात यह थी कि उसने इन धमकियों के बाद ही अपनी जल-सेना बढ़ा दी। इस बात से अंग्रेजों का मिजाज विगड़ गया और इन लोगों ने भी अपनी जल-सेना को बढ़ाना शुरू कर दिया। इस तरह इन दोनों में एक तरह की घुड़दौड़ शुरू होगई। दोनों देशों के अख़बारों ने एक जोरदार आन्दोलन जारी कर दिया, जिसमें जंगी जहाज बढ़ाने की चीख़ मचाई गई और राष्ट्रीय विद्वेष की आग को बराबर भड़काया जाने लगा।

योरप में यह एक ख़तरे का हलक़ा था। इसके अलावा कई और भी ख़तरे के हलके थे। फ़्रांस और जर्मनी तो पुराने दुश्मन थे ही। १८७० की हार की कटु स्मृति फ़्रांसीसियों के दिलों में बराबर चुभती रहती थी और वे बदला लेने का सपना देखते थे। बालकन तो हमेशा ही बारूद का एक गोला था, जहाँ अनेक स्वार्थ आकर एक-दूसरे से टकराते थे। पश्चिमी एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए जर्मनी ने भी टर्की से दोस्ती शुरू करदी। यह तजवीज की गई कि एक रेलवे बग़दाद तक बनाई जाय और इस शहर को कुस्तुनतुनिया और योरप से जोड़ दिया जाय। यह तजवीज बहुत मुनासिब थी, लेकिन चूँकि जर्मनी इस बग़दाद रेलवे को अपने हाथ में रखना चाहता था इसलिए राष्ट्रीय विद्वेष पैदा होगया।

धीरे-धीरे योरप में युद्ध का डर छा गया और आत्म-रक्षा के लिए शक्तियों ने अपने-अपने गृह बनाने शुरू किये। दडी-बडी ताक़तें दो दलों में बँट गईं। जर्मनी, आस्ट्रिया और इटली का त्रिगुट्ट (Triple Alliance) एक तरफ़ था और इंग्लैण्ड, फ़्रांस और रूस का त्रिगुट्ट (Triple Entente) दूसरी तरफ़ था। इटली पहले त्रिगुट्ट का एक उदासीन सदस्य था और वाक़या तो यह है कि लड़ाई होने पर उसने अपने वचन को तोड़कर दूसरे पक्ष का साथ दिया। आस्ट्रिया एक जीर्ण-शीर्ण साम्राज्य था, नफ़रत में दड़ा दीख़ता था, लेकिन परस्पर-विरोधी तत्त्वों से परिपूर्ण था। मुन्दर वियेना

इसकी राजधानी थी। यह संगीत, कला और विज्ञान का केन्द्र भी था। इसलिए असल में पहले त्रिगुट्ट में सिर्फ जर्मनी ही था। लेकिन यह बात तो माननी ही पड़ेगी कि परीक्षा का दिन आने के पहले कौन कह सकता था कि इटली और आस्ट्रिया की क्या सूरत होगी ?

इस तरह योरोप में भय का राज्य होगया था और भय बहुत भयंकर चीज होती है। हरेक देश युद्ध की तैयारी करने लगा और अधिक-से-अधिक युद्ध की सामग्री इकट्ठी करने लगा। शस्त्रीकरण की दौड़ शुरू होगई। इस शस्त्रीकरण में सबसे अजीब बात यह है कि जब एक देश अपनी सेना बढ़ावे तब दूसरे देशों को भी मजबूरन बढ़ानी पड़ती है। बड़े-बड़े निजी कारखाने, जो तोप, जंगी जहाज, गोली-बारूद तथा युद्ध की और चीजें बनाते थे, मुनाफ़े में रहे और ख़ूब मोटे होगये। ये लोग एक क्रदम और आगे बढ़ गये। इन्होंने युद्ध का भय फैलाना शुरू कर दिया, ताकि उससे प्रभावित होकर क्रोमैं इनसे हथियार खरीदें। युद्ध-सामग्री के ये कारखाने बहुत दौलतमन्द और ताक़तवर थे, और इंग्लैण्ड, फ़्रांस, जर्मनी और दूसरे मुल्कों के अनेक बड़े अफ़सर और मंत्री इनके हिस्सेदार थे। इसलिए इनकी सरसब्ज़ी में इन लोगों का भी स्वार्थ था। युद्ध-सामग्री के कारखाने तभी सरसब्ज़ होते हैं जब लड़ाई का भय हो या लड़ाई छिड़ जाय। इसलिए आश्चर्यजनक स्थिति यह थी कि अनेक सरकारों के मंत्री और सरकारी अफ़सरों का लड़ाई करने में माली फ़ायदा था। इन कारखानों ने अनेक देशों में युद्ध का खर्च बढ़ाने के लिए बहुत-सी दूसरी तरकीबें भी कीं। इन्होंने जनता के मत पर असर डालने के लिए अख़बार निकाले, अकसर सरकारी अफ़सरों को रिश्तों दीं और लोगों को भड़काने के लिए ग़लत ख़बरें फैलाईं। युद्ध-सामग्री का व्यवसाय भी क्या ही भयंकर चीज है ! दूसरों की मौत से इसकी ज़िन्दगी है। युद्ध की बीभत्सता पैदा करने में इसे ज़रा भी संकोच नहीं होता, बल्कि उसे यह प्रोत्साहन देता है, ताकि उससे मुनाफ़ा कमा सके। १९१४ ई० के महायुद्ध को जल्द लाने में इस व्यवसाय ने भी कुछ मदद की। आज भी यह अपनी पुरानी चाल चल रहा है।

मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि इधर लड़ाई की बातचीत हो रही थी और उधर मुलह की एक अजीब कोशिश जारी थी। ताज्जुब है कि सबमें रूस के ज़ार निकोलस द्वितीय ने आगे बढ़कर शक्तियों के सामने यह तजवीज़ पेश की कि सब इकट्ठा होकर सार्वभौम शान्ति का युग शुरू करें। यह वही ज़ार था, जो अपने साम्राज्य में हरेक उदार आन्दोलन को कुचलता रहता था और अपने क्रैदियों से साइबेरिया को आबाद कर रहा था। यह तो मज़ाक़-सा मालूम होता है कि वह शान्ति की बातचीत करे। लेकिन शायद वह सच्चे दिल से शान्ति की कोशिश कर

रहा होगा; क्योंकि उसके लिए शान्ति का मतलब था मौजूदा स्थिति का सदा के लिए बना रहना और उसकी निरंकुशता का कायम रहना। उसके निमंत्रण पर हालैंड के हेग शहर में दो शान्ति-परिषदें, एक १८९९ में और दूसरी १९०७ में, हुईं। इन परिषदों में कोई भी महत्त्व की बात नहीं हुई। शान्ति आसमान से तो एकदम नहीं टपक सकती। वह तो तभी आसकती है जब झगड़ों की जड़ हट जाय।

मैंने तुम्हें बड़ी शक्तियों की आपस की लागडाँट और भय के बारे में बहुत कुछ बताया है। गरीब छोटी क्राँमों को कोई नहीं पूछता, सिवा उस समय के जबकि वे शरारत करने लगती हैं! योरप के उत्तर में कुछ छोटे देश ध्यान देने योग्य हैं, क्योंकि वे इन लालची और लोलुप बड़ी शक्तियों से बिल्कुल मुक्तलिफ़्र हैं। स्कैंडिनेविया में नार्वे और स्वीडन हैं और उनके नीचे डेनमार्क है। ये देश आर्कटिक क्षेत्र से बहुत दूर नहीं हैं। ये बहुत ठंडे मुल्क हैं और इनमें रहना बहुत कठिन है। इनमें सिर्फ़ छोटी आबादी की परवरिश होसकती है। लेकिन चूँकि ये देश बड़ी शक्तियों के द्वेष और नफ़रत और लागडाँट के दायरे से बाहर हैं, इसलिए अपनी ज़िन्दगी शान्ति और सुलह के साथ बिताते हैं और अपनी ताक़त सभ्य तरीक़े से खर्च करते हैं। वहाँ विज्ञान खूब फलता-फलता है और बहुत अच्छा साहित्य पैदा हुआ है। १९०५ ई० तक नार्वे और स्वीडन मिले हुए थे और एक राज्य थे। इस साल नार्वे ने जुदा हो जाने का और अपना जीवन अलग बिताने का निश्चय किया। इस तरह इन दो देशों ने शान्तिपूर्वक अपना सम्बन्ध तोड़ने का निश्चय कर लिया और उस समय से ये दो अलग आज़ाद राज्य रहे हैं। कोई लड़ाई नहीं हुई और न एक मुल्क ने दूसरे को मजबूर किया। दोनों स्नेही पड़ोसी की तरह मित्र-भाव से रह रहे हैं।

नन्हे-से डेनमार्क ने बड़ी क्राँमों के सामने अपनी जल और स्थल सेना को तोड़-कर एक उदाहरण पेश कर दिया है। यह किसानों का देश है—छोटे-छोटे खेतिहरों का, जहाँ अमीर और गरीब में ज्यादा फ़र्क़ नहीं। इस समता (Equalisation) की ज्यादातर वजह यह है कि सहकारिता का आन्दोलन यहाँ खूब बढ़ा है।

लेकिन योरप के सब छोटे मुल्क डेनमार्क की तरह शराफ़त के पुतले नहीं हैं। हालैंड खुद तो छोटा है, लेकिन ईस्टइंडीज़ में (जावा, सुमात्रा में) बहुत बड़े साम्राज्य पर क़ब्ज़ा रखता है। इसके बाद बेलजियम है, जो अफ़रीका में कांगो को घुसता रहता है। यूरोपियन राजनीति में इसका महत्त्व असल में इसकी स्थिति की बिना पर है। यह देश फ़्रांस और जर्मनी के रास्ते पर है और इन दोनों देशों में युद्ध छिड़ने पर इस मुल्क का घिसट आना क़रीब-क़रीब निश्चित है। तुम्हें वाटरलू की याद होगी, जो बेलजियम में ब्रसेल्स के पास है। इसी कारण से बेलजियम योरप का

अखाड़ा (cockpit) कहा गया है । खास-खास बड़ी शक्तियों ने यह समझीता किया था कि युद्ध छिड़ने पर वे वेलजियम की तटस्थता को मानेंगी । लेकिन, जैसा कि हम आगे देखेंगे, जब लड़ाई छिड़ी, तब यह समझीता और वादा टुकड़े-टुकड़े हो गया ।

लेकिन योरप में, या यों कहो कि दूसरी जगहों में, सबसे खराब और परेशानी पैदा करनेवाली क्लॉमें वालकन की हैं । जातियों और राष्ट्रों का यह चोंचों का मुरब्बा, जिसके पीछे पुश्तहापुश्त से द्वेष और लाग-डाँट चली आ रही है, आपसी कशमकश और नफ़रत से भरा हुआ है । १९१२-१३ के वालकन-युद्ध ग्रैरमामूली तरीक़े पर खूनी युद्ध थे और बहुत कम समय में और बहुत कम क्षेत्र में बहुत ज्यादा आदमी हताहत हुए थे । कहा जाता है कि शरणागत और भागते हुए तुर्कों पर बल्गेरियन लोगों ने ख़ौफ़नाक जुल्म किये थे । तुर्कों का ख़ुद भी पुराना इतिहास ख़राब है । सर्बिया, जो अब यूगोस्लेविया का एक हिस्सा है, हत्या के लिए ख़ूब बदनाम हो गया था । अपनेको देशभक्त कहनेवालों के एक खुफिया हत्याकारी दल के एक गुट ने, जिसे 'काला हाथ' (Black Hand) कहा जाता था और जिसमें राज्य के अनेक बड़े-बड़े अफ़सर भी शामिल थे, असाधारण रूप से ख़तरनाक कितने ही ख़ून किये थे । देश के राजा और रानी, राजा अलेक्जेंडर और महारानी ड्रेगा, महारानी के कई भाई, प्रधानमंत्री और कुछ और लोग बहुत दूरे तरीक़े से क़त्ल कर दिये गये । यह सिर्रा महल तक महद्द एक क्रान्ति (Palace Revolution) थी । राजा के मरने पर उसकी जगह दूसरा आदमी राजा बना दिया गया ।

इस तरह बीसवीं सदी का जब आरम्भ हुआ, योरप की हवा में बिजली की कड़क और चमक थी; और ज्यों-ज्यों दिन बीते, वातावरण अधिक तूफ़ानी होता गया । पेचीदगियाँ और गुथियाँ बढ़ने लगीं और योरप के जीवन के धागे में ज्यादा-से-ज्यादा गाँठें पड़ने लगीं, जो अख़ीर में लड़ाई के जरिये ही कटनेवाली थीं । सब शक्तियाँ यह उम्मीद करती थीं कि लड़ाई छिड़ेगी और उसके लिए जोरों के साथ तैयारी करती थीं, लेकिन कोई भी युद्ध छेड़ने के लिए उत्सुक नहीं था । सब किसी-न-किसी हदतक लड़ाई से डरती थीं, क्योंकि कोई भी यक़ीनी तौर पर इस बात की पेशीनगोई नहीं कर सकता था कि लड़ाई का नतीजा क्या होगा । इसपर भी डर की वजह से सब राष्ट्र युद्ध की तरफ़ बढ़ते गये । जैसा मैंने तुमको बताया है, योरप के दोनों गुट एक-दूसरे के खिलाफ़ बने रहे । इसी का नाम 'शक्तियों का समतौल' था; लेकिन यह बहुत नाज़ुक समतौल था, जो ज़रा-से धक्के से बिगड़ जा सकता था । जापान का भी, गोकि वह योरप से बहुत दूर था और उसकी स्थानीय समस्याओं में उसे कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, ग़ुट्टबन्दी के और शक्तियों के इस समतौल के नामले में हाथ था;

क्योंकि वह इंग्लैण्ड का दोस्त था। इस दोस्ती का खास उद्देश्य यह था कि पूर्व में, खासकर हिन्दुस्तान में, ब्रिटेन के स्वार्थ सुरक्षित रहें। यह दोस्ती उस जमाने में क्रायम हुई थी, जब अंग्रेजों और रूसियों की लाग-डाँट चल रही थी। और यद्यपि इंग्लैण्ड और रूस अब एक ही तरफ़ थे फिर भी वह दोस्ती बनी हुई थी। सिर्फ़ अमेरिका ही एक ऐसा मुल्क था जो योरोप की इस गुटबन्दी और समतौल-प्रणाली से दूर रहा।

१९१४ में यह हालत थी। तुम्हें याद होगा कि इस मौक़े पर होमरूल बिल के बारे में इंग्लैण्ड को आयरलैण्ड ने बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अल्स्टर बगावत के लिए उतारू था; वालण्टियर लोग उत्तर और दक्षिण दोनों जगह कवायद कर रहे थे और आयरलैण्ड में गृह-युद्ध की चर्चा हो रही थी। ऐसा हो सकता है कि जर्मन सरकार ने सोचा हो कि इंग्लैण्ड आयरलैण्ड के झगड़े में फँसा रहेगा और अगर कोई यूरोपियन युद्ध होगा तो वह दखल न देगा। लेकिन बात यह थी कि ब्रिटिश सरकार अन्दर-ही-अन्दर फ्रांस से वादा कर चुकी थी कि लड़ाई छिड़ने पर वह फ्रांस का साथ देगी, हालाँकि यह बात लोगों को मालूम नहीं थी।

२८ जून १९१४—यह वह तारीख़ थी जिस दिन चिनगारी पैदा हुई और उसने आग भड़का दी। आर्च ड्यूक फ्रांसिस फरेडीनेण्ड आस्ट्रियन गद्दी का युवराज यानी वारिस था। वह बालकन में बोसनिया की राजधानी सेरावी गया था। जैसा मैं तुम्हें बता चुका हूँ, यह बोसनिया वही देश था जिसको आस्ट्रिया ने चन्द साल पहले, जब नौजवान तुर्क अपने मुलतान से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे थे, अपने राज्य में शामिल कर लिया था। आर्च ड्यूक और उसकी स्त्री, जो उसके पास ही बैठी थी, खुली गाड़ी में सड़क पर जा रहे थे। उनपर गोली चलाई गई और वह और उसकी स्त्री दोनों मर गये। आस्ट्रिया की सरकार और जनता दोनों गुस्से से पागल होगये और सर्बिया की सरकार पर यह इलजाम लगाया कि इसमें उसकी शिरकत थी (सर्बिया बोसनिया का पड़ोसी था)। सर्बिया की सरकार ने इस बात से इन्कार किया। बहुत दिन बाद इस बारे में तहक़ीक़ात करने से पता चला है कि यद्यपि सर्बिया की सरकार पर इस हत्या की ज़िम्मेदारी नहीं थी, पर यह बात भी नहीं है कि इसकी तैयारी का उसे पता न रहा हो। इस क़त्ल की ज़िम्मेदारी ज्यादातर सर्बिया के 'काला-हाथ' नामी हत्यारे दल पर ही डालनी चाहिए।

आस्ट्रिया की सरकार ने कुछ तो गुस्से से और कुछ नीति के कारण सर्बिया के साथ बहुत ही सख्ती का तर्जोमल इस्तिहार किया। उसने तय कर लिया था कि सर्बिया को हमेशा के लिए ज़लील कर दिया जाय और किसी बड़ी लड़ाई छिड़ने की

हालत में वह जर्मनी की मदद का भरोसा करता था। इसलिए सर्बिया ने जब माफ़ी मांगी तो वह मंजूर नहीं की गई और २३ जुलाई १९१४ को आस्ट्रिया ने सर्बिया के पास अपनी अन्तिम चुनौती (Ultimatum) भेज दी। पाँच दिन के बाद यानी २८ जुलाई को आस्ट्रिया ने सर्बिया के खिलाफ़ लड़ाई का ऐलान कर दिया।

आस्ट्रिया की नीति उन दिनों एक अभिमानी और वेवकूफ़ मंत्री के हाथ में थी, जो लड़ाई पर तुला हुआ था। बूढ़े सम्राट् फ्रांसिस जोसेफ (जो १८४८ से आस्ट्रिया के राजसिंहासन पर थे) इस नीति से सहमत कर लिये गये थे और जर्मनी की मदद की मामूली सी बातचीत के यह मानी लगाये गये कि उसने पूरे तौर से मदद करने का वादा किया है। वाक़्या तो यह है कि आस्ट्रिया के अलावा बड़ी ताक़तों में कोई भी ताक़त उस वक़्त युद्ध के लिए उत्सुक नहीं थी। जर्मनी यद्यपि तैयार और झगड़ालू था, पर लड़ाई के लिए उत्सुक नहीं था। क़ैसर विल्हेल्म द्वितीय ने आधे मन से इस लड़ाई को रोकने की कोशिश भी की। इंग्लैण्ड और फ़्रांस भी लड़ाई के लिए ज्यादा उत्सुक नहीं थे। रूसी सरकार का अर्थ था ज़ार, और वह कमज़ोर और वेवकूफ़ आदमी था। उसने अपने चारों ओर अपनी तबदीलत के मुआफ़िक़ वेवकूफ़ और बदमाश लोगों को इकट्ठा कर रखा था, जो उसे कभी इस तरफ़ और कभी उस तरफ़ फिराते रहते थे। फिर भी इस आदमी के हाथ में लाखों की क़िस्मत थी। वह खुद तो लड़ाई के खिलाफ़ था, लेकिन उसके सलाहकारों ने उसे डरवा दिया कि देरी करने का नतीजा घुरा होगा और उसे इस बात पर राज़ी कर लिया कि फ़ौज को लड़ाई के लिए तैयार किया जाय। 'तैयारी' का मतलब था फ़ौज को लड़ने के लिए बुलाना, और रूस ऐसे विस्तृत देश में इस काम में बहुत दिन लग जाते। जर्मनी के हमले के डर से रूसी सेना की लड़ाई की तैयारी में तेज़ी आ गई। सेना की तैयारी की, जो ३० जुलाई से शुरू हुई, ख़बर ने जर्मनी को डरा दिया और उसने यह मतालवा किया कि रूस उसे रोक दे। लेकिन युद्ध की इस विशाल मशीन को अब कौन रोक सकता था? दो दिन बाद, १ अगस्त को, जर्मनी ने भी अपनी सेना तैयार करके रूस और फ़्रांस के खिलाफ़ लड़ाई की घोषणा कर दी; और फ़ौरन ही विशाल जर्मन सेनाओं ने फ़्रांस जाने के लिए बेलजियम पर धावा कर दिया, क्योंकि यह रास्ता आसान था। बेचारे बेलजियम ने जर्मनी का कोई नुक़सान नहीं किया था। लेकिन जब राष्ट्रों में मौत और ज़िन्दगी के लिए लड़ाई होती है तो वे इस क़िस्म की छोटी-छोटी बातों और किये हुए वादों का ख़याल नहीं करते। जर्मन सरकार ने बेलजियम से इस बात की इज़ाजत मांगी थी कि वह अपने देश से उसकी फ़ौज को जाने दे; लेकिन स्वभावतः यह प्रार्थना घृणापूर्वक़ नामंजूर कर दी गई।

बेलजियम की तटस्थता के तोड़े जाने की वजह से इंग्लैंड में और दूसरी जगहों पर भी बहुत शोर उठा और इंग्लैंड ने तो इसी बात को जर्मनी के खिलाफ युद्ध छेड़ने की बुनियाद करार दिया। वाक्या तो यह है कि इंग्लैंड ने इस बारे में अपना फैसला बहुत पहले ही कर लिया था। बेलजियम के सवाल का तो उसे एक अनुकूल बहाना मिल गया। अब तो यह भी पता चला है कि युद्ध के पहले के वर्षों में फ्रांस ने भी यह योजना तैयार की थी कि जरूरत पड़ने पर वह जर्मनी पर चढ़ाई करने के लिए बेलजियम के रास्ते अपनी सेना ले जायगा। बहरहाल, इंग्लैंड ने सत्य और औचित्य का बहुत बड़ा संरक्षक होने का पाखण्ड किया, और जर्मनी के मुकाबिले में अपने को छोटी-छोटी क्रांमों का बहुत बड़ा हिमायती बताना चाहा। जर्मनी के ऊपर यह एतराज किया जाता था कि उसने अपने गम्भीर वादों और अहदनामों को रद्दी कागज का टुकड़ा समझा। ४ अगस्त की आधी रात को इंग्लैंड ने जर्मनी के खिलाफ लड़ाई का ऐलान कर दिया, लेकिन उसने इतनी पेशबन्दी की थी कि किसी दुर्घटना को रोकने के लिए 'ब्रिटिश एक्सपीडिशनरी फोर्स' (अंग्रेजों की हमला करनेवाली सेना) को इंग्लिश चैनल के पार एक दिन पहले ही रवाना कर दिया था। इसलिए हालाँकि दुनिया समझती थी कि इंग्लैंड के युद्ध में शामिल होने का सवाल अनिश्चित है, मगर ब्रिटिश फ़ौज योरोप के प्रायद्वीप पर पहुँच चुकी थी।

बस अब आस्ट्रिया, रूस, जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड सबके सब युद्ध में फँस गये। और छोटा-सा सर्बिया तो था ही, जिसे इस लड़ाई का तात्कालिक कारण कहना चाहिए। आस्ट्रिया और जर्मनी का मददगार इटली क्या करेगा? यह सवाल था; पर इटली अलग रहा। इटली इस बात को देखने लगा कि दोनों में किसकी तरफ जाने से प्रायदा होगा। इटली ने सौदा करना शुरू किया और आखिरकार छः महीने बाद निश्चित रूप से अपने पुराने मददगारों के खिलाफ फ्रांस-इंग्लैंड-रूसी पक्ष में शामिल होगया।

इस तरह १९१४ के अगस्त महीने की शुरुआत के दिनों में योरोप की फ़ौजें इकट्ठी हुई और आगे बढ़ीं। ये फ़ौजें क्या थीं? पुराने ज़माने में फ़ौज में पेशे वाले सिपाही हुआ करते थे। उस वक्त ये स्थायी फ़ौजें हुआ करती थीं। फ्रेंच राजक्रांति से इस बारे में बहुत तब्दीली होगई थी। जब इस क्रान्ति को विदेशी हमले से खतरा हुआ तो साधारण नागरिकों को भरती किया गया था और बहुत बड़ी तादाद में उनको प्रवायद सिखाई गई थी। उस ज़माने के बाद से योरोप का रूख यह हो गया था कि एक नयशुदा तादाद की पेशेवाली और स्वेच्छा से भरती हुई इन दोनों सेनाओं के दजाय 'अनिवार्य सेना' की भरती की जाय। अनिवार्य सैनिक सेवा

(Conscription) उसे कहते हैं जिसमें देश के शारीरिक दृष्टि से भरती के क्राविल सब आदमी जबरदस्ती शामिल होने के लिए मजबूर किये जाते हैं। इसलिए जिस्मानी लिहाज से क्राविल आदमियों की इस व्यापक सैनिक भरती को फ्रेंच क्रान्ति की उपज समझना चाहिए। यह प्रणाली योरोप में सब जगह फैल गई और हरेक नौजवान को छावनी में रहकर दो वर्ष तक या इससे ज्यादा भी सैनिक शिक्षा लेनी पड़ती थी और बाद की जब हुक्म मिले तब उसे लड़ाई पर जाने के लिए आना पड़ता था। इस तरह लड़ाई में लगी हुई सेना का असल में अर्थ होता था राष्ट्र के समस्त नवयुवक। फ्रांस, जर्मनी, आस्ट्रिया और रूस में यही दशा थी और इन देशों में सेना को तैयार करने का मतलब यह था कि दूर-दूर गांवों और कस्बों में फैले हुए नौजवानों को उनके घरों से बुलाया जाय। इंग्लैंड में जब लड़ाई शुरू हुई तो इस तरह की अनिवार्य प्रणाली नहीं थी। अपनी जबरदस्त जल-सेना पर भरोसा करके इंग्लैंड ने अपनी स्यायी और ऐसी सेना को छोटी ही रक्खा था। लेकिन युद्ध के दौरान में इंग्लैंड ने भी और देशों की तरह अपनी नीति करली और सैनिक भरती को अनिवार्य कर दिया।

व्यापक सैनिक सेवा का मतलब यह था कि सारी क्रीम सशस्त्र लड़ाई के लिए तैयार थी। तैयारी के हुक्म का असर हरेक कस्बे, गांव और कुटुम्ब पर पड़ा। योरोप के ज्यादातर हिस्से पर अगस्त की शुरुआत के दिनों में जिन्दगी ठिठक कर रह गई और लाखों नौजवान अपना-अपना घर छोड़कर चल दिये और फिर कभी वापस न जा सके। जहाँ देखो फ्रोंजें मार्च करती हुई दिखाई देती थी, और सैनिकों की जय बोली जाती थी। देशभक्ति की भावना का जोर था। हृदय के तारों को लोगों ने सख्त बना लिया था। लोगों में किसी क़दर हलकापन भी था; क्योंकि उस वक्त लोग यह नहीं समझते थे कि आनेवाले सालों में कितनी भयंकरता है।

देशभक्ति के उत्साह में सभी वह गये। साम्यवादी, जो इतने जोरों के साथ अन्तर्राष्ट्रीयता की बातें करते थे, और मार्क्सवादी भी, जो दुनियाभर के श्रमजीवियों के दुश्मन पूँजीवाद के खिलाफ़ एक होजाने की बात करते थे, देशभक्ति के आवेश में वह गये और पूँजीपतियों की इस लड़ाई में बड़े उत्साह से शामिल हुए। ऐसे थोड़े ही थे; जो अपनी जगह पर खड़े रहे लेकिन लोग उनको नफ़रत की निगाह से देखते थे; उनको गालियाँ और अकसर सजायें भी देते थे। बहुत-से लोग तो दुश्मन की नफ़रत से पागल होगये थे। अंग्रेज और जर्मन मजूर एक-दूसरे को क़त्ल कर रहे थे और इन दोनों देशों के और लड़ाई में शामिल दूसरे देशों के विद्वान लोग, वैज्ञानिक और प्रोफेसर, एक-दूसरे को गालियाँ देते और एक-दूसरे के खिलाफ़ भद्दे-से-भद्दे और बीभत्स किस्सों पर यक़ीन कर लेते थे।

इस तरह लड़ाई आरम्भ होने पर उन्नीसवीं सदी का युग खत्म हुआ। पश्चिमी सभ्यता के ज्ञान और शान्ति के साथ बहनेवाले प्रवाह को युद्ध की भँवर ने निगल लिया। पुरानी दुनिया हमेशा के लिए खत्म होगई और चार वर्ष से ज्यादा समय के बाद इस भँवर से एक नई चीज प्रकट हुई।

: १४७ :

हिन्दुस्तानः महायुद्ध शुरू होने के वक्त

२९ मार्च, १९३३

हिन्दुस्तान के बारे में तुम्हें लिखे हुए बहुत दिन होगये। इस विषय पर वापस आने और तुम्हें यह बताने का मुझे प्रलोभन हो रहा है कि महायुद्ध आरम्भ होने के समय हिन्दुस्तान की क्या दशा थी और मैंने इस प्रलोभन में आजाने का निश्चय भी कर लिया है।

फई लम्बी-लम्बी चिट्ठियों में हम लोग उन्नीसवीं सदी के हिन्दुस्तान में ब्रिटिश राज्य और हिन्दुस्तान की जिन्दगी के कुछ पहलुओं पर अच्छी तरह विचार कर चुके हैं। इस युग का जोरदार पहलू यह था कि हिन्दुस्तान पर अंग्रेजों का अधिकार मजबूत किया गया और साथ-ही-साथ देश का शोषण हुआ। हिन्दुस्तान को तीन क़ब्ज़ा करनेवाली फ़ौजों ने दबोच रक्खा था—सशस्त्र सैनिक, व्यापारिक, और सिविल। जाहिर है कि सशस्त्र सैनिकों में अंग्रेजी फ़ौजें थीं और अंग्रेज अफ़सरों की मातहत में हिन्दुस्तानी सिपाही थे, जो रुपये के लालच से भरती होते हैं। इसे विदेशी सेना कहना चाहिए, जो कि मुल्क के ऊपर क़ब्ज़ा रखने के लिए रखी गई। लेकिन इससे ज्यादा ज़बरदस्त दवाव सिविल सर्विस का था, जिसे अत्यन्त केन्द्रित और निरंकुश नौकरशाही कहना चाहिए। तीसरी फ़ौज व्यापारिक थी, जिसे इन दोनों से मदद मिलती थी। यह सबसे ज्यादा ख़तरनाक चीज़ थी, क्योंकि देश का सबसे ज्यादा शोषण यह खुद करती थी या इसकी तरफ़ से होता था और देश को चूसने का इसका ढंग भी इतना प्रत्यक्ष नहीं था जितना कि दूसरी दोनों का था। बहुत दिनों तक, और कुछ हदतक आज भी, बड़े-बड़े प्रमुख हिन्दुस्तानी दो फ़ौजों पर ज्यादा एतराज करते रहे हैं, और तीसरी को उन्होंने इतना महत्व नहीं दिया।

हिन्दुस्तान में ब्रिटिश नीति का बराबर यह ध्येय रहा है कि स्थापित स्वार्थों (Vested interests) का एक दर्ज बनाया जाय। उन्होंने ख़याल किया कि यह दर्ज उन्हींका बनाया हुआ होगा, इसलिए उन्हींके बरोसे रहेगा और हिन्दुस्तान में

उनकी मदद करता रहेगा। इसी खयाल से सामन्त राजाओं को मजबूत किया गया। बड़े जमींदारों और तालुकेदारों का वर्ग बनाया गया। और यह कहकर कि सरकार मजहबी मामलों में तटस्थ है, सामाजिक कट्टरता को प्रोत्साहन दिया गया। देश के शोषण में इस वर्ग का अपना स्वार्थ था। और सच तो यह है कि यह बिना इस शोषण के जिन्दा भी नहीं रह सकता था। सबसे बड़ा वर्ग जो हिन्दुस्तान में बनाया गया वह ब्रिटिश पूंजीपतियों का था।

एक अंग्रेज राजनीतिज्ञ लार्ड सैलिसबरी ने, जो हिन्दुस्तान के सेक्रेटरी आफ स्टेट (भारत-सचिव) थे, एक वक्तव्य दिया था। वह अकसर उद्धृत किया गया है और उससे स्थिति पर काफ़ी रोशनी भी पड़ती है। मैं उसे यहाँ तुम्हारे सामने रखना चाहता हूँ। लार्ड सैलिसबरी ने सन् १८७५ ई० में कहा था—“चूँकि हिन्दुस्तान का खून निकालना जरूरी है, इसलिए नश्तर उस हिस्से में लगाना चाहिए जहाँ खून ज्यादा है या, कम-से-कम, काफ़ी है। नश्तर उन हिस्सों में न लगाना चाहिए जो खून के अभाव से कमजोर हो चुके हैं।”

हिन्दुस्तान पर अंग्रेजों के क़ब्ज़े से और उस नीति के कारण जिसपर अंग्रेजों ने यहाँ अमल किया कई नतीजे निकले। कुछ ऐसे भी नतीजे निकले जिन्हें अंग्रेज पसन्द नहीं करते थे। लेकिन व्यक्ति अपने कामों के सारे नतीजों पर मुश्किल से अधिकार पा सकते हैं, और क्रोमों के लिए तो यह और भी मुश्किल होता है। अकसर यह होता है कि कुछ कारगुजारियों की वजह से नई ताकतें पैदा होती हैं और यही ताकतें कारगुजारियों का विरोध करती हैं और उनपर विजय पा जाती हैं। साम्राज्यवाद से राष्ट्रीयता पैदा होती है। पूंजीवाद की वजह से कारखानों और मिलों में मजदूरों की बड़ी तादाद जमा हो जाती है, और मजदूरों की यह तादाद संगठित होकर पूंजीपतियों का मुक़ाबिला करती है। सरकार का दमन, जो किसी आन्दोलन को दबाने या राष्ट्र को पस्त करने के लिए शुरू किया जाता है, अकसर उस राष्ट्र को पुष्ट कर देता है, उसे फ़ौलाद की तरह मजबूत बनाता है और अन्तिम विजय के लिए तैयार कर देता है।

हमने देखा है कि हिन्दुस्तान ये अंग्रेजों की व्यावसायिक नीति के कारण गाँवों की आबादी बढ़ गई। रोज़गार न होने की वजह से ज्यादा-से-ज्यादा लोग शहरों से गाँवों में जाने लगे, जिससे ज़मीन पर बोझ बढ़ा और किसानों के खेत छोटे होने लगे। खेत इस हद तक छोटे हुए कि बहुतसे “बेमुनाफ़ा” (Uneconomic) होगये, यानी उनको जोतकर किसान अपनी जिन्दगी की मामूली जरूरियात के लिए थोड़ी-सी आमदनी भी नहीं कर सकता। लेकिन किसानों के पास कोई दूसरा चारा नहीं

था। ये लोग अपनी गुज़र-बसर तभी कर सकते थे जबकि क़र्ज़ लेते जायें। ब्रिटिश सरकार की ज़मीन-सम्बन्धी नीति ने स्थिति को बदतर कर दिया, खासकर ताल्लुकेदारी और बड़े-बड़े ज़मींदारी हलकों में। इन हलकों में, और उन हलकों में भी जहाँ किसान ज़मीन का मालिक होता था, ज़मींदार का लगान न देने पर और सरकार की माल-गुजारी न अदा करने पर खेत का जोतनेवाला बेदखल कर दिया जाता था। इसकी वजह से, और इस कारण कि शहर से नये आनेवालों का ज़मीन पर बोझ बराबर बढ़ता गया, गाँवों में मजदूरों का एक बड़ा वर्ग पैदा होगया, जिसके पास कोई ज़मीन नहीं थी। और, जैसा मैंने तुम्हें बताया है, अनेक भयंकर अकाल भी पड़े।

ज़मीन से वंचित यह बड़ा वर्ग खेती के लिए ज़मीन का भूखा था। लेकिन इतनी काफ़ी ज़मीन नहीं थी कि सबको मिल सके। ज़मींदारों ने ज़मीन की इस माँग से फ़ायदा उठाकर खेतों का लगान बढ़ा दिया। लेकिन कुछ क़ानून ऐसे मौजूद थे जो किसानों की रक्षा के लिए बनाये गये थे और उनकी वजह से एकदम लगान को एक खास हद से ज्यादा बढ़ाना नामुमकिन था। लेकिन ज़मींदारों ने इस कठिनाई को कई तरीक़ों से सुलझा लिया और किस्म-किस्म के ग़ैरक़ानूनी मतालबे वसूल किये जाने लगे। मुझे बताया गया था कि अवध की एक ताल्लुकेदारी रियासत में पचास किस्म के ग़ैरक़ानूनी मतालबे वसूल होते थे। इनमें खास 'नज़राना' था। यह वह रक़म है जिसे किसान खेत लेते वक़्त, शुरू में, ज़मींदार या ताल्लुकेदार को देता है। ग़रीब किसान इतनी रक़म कहाँसे अदा करता? बनिये से उधार लेकर जब क़र्ज़ चुकाने की कोई सम्भावना या शक्ति न दिखाई देती हो, उस वक़्त क़र्ज़ लेना बेवक़ूफी है; लेकिन ग़रीब किसान करे तो क्या करे? उसे कहीं से भी कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती और उसे जोतने के लिए ज़मीन चाहिए ही। इसलिए निराशा में भी आशा रखते हुए वह सोचता है कि शायद भविष्य कुछ अच्छा हो। नतीजा यह होता है कि क़र्ज़ लेने पर भी अक्सर किसान ज़मींदारों की माँग पूरी नहीं कर सकता। वह खेत से बेदखल कर दिया जाता है और उन मजदूरों के ग़िरोह में शामिल होजाता है जिनके पास ज़मीन नहीं होती।

खेत के मालिक किसान, मामूली किसान, और ज़ेजमीन के मजदूर, सभी बनिये के शिकार होते हैं। ये क़र्ज़ से कभी छुटकारा पा ही नहीं सकते। जब कभी कुछ कमाते हैं, तो अदा कर देते हैं; लेकिन अदा की हुई उस रक़म को सूद खा जाता है और पुराना मूलधन ज्यों-कान्‌यों बना रहता है। इस बात के लिए बनियों पर बहुत कम दण्डित पाई जाती है कि वे किसानों को न मूँड सकें। नतीजा यह होता है कि किसान लोग बनिये के गुलाम होकर रहते हैं। बेचारा किसान एक तरह से ज़मींदार और बनिया दोनों का गुलाम होता है।

जाहिर है कि इस क्रिसम की बात बहुत दिनों तक नहीं चल सकती। एक वक्त ऐसा आयगा जब किसान कोई भी रकम अदा करने में बिलकुल असमर्थ हो जायेंगे। तब बनिये रुपया उधार देने से इनकार करेंगे और जमींदार भी कठिनाई में फँसे होंगे। यह ऐसी प्रणाली है कि जिसमें पतन और अस्थिरता के साफ़-साफ़ चिन्ह दिखाई देते हैं। सारे देश में किसानों के झगड़े और फ़साद, जो हाल में हो रहे हैं, इस बात को साधित करते हैं कि अब यह प्रणाली बिखर रही है और बहुत दिनों तक क़ायम न रह सकेगी। इस-उस जगह पैबन्द लगाने से यह प्रणाली बच नहीं सकती; क्योंकि अब इसका जमाना जाता रहा है। ज़रूरत यह है कि ज़मीन के बारे में बिलकुल नई प्रथा चलाई जाय। दोष प्रथा का है, बनिये या जमींदार का नहीं।

मुझे डर है कि मैंने इस ख़त में उसी बात को दोहरा दिया जिसे मैंने एक दूसरे ढंग से पहले के ख़त में लिखा था। लेकिन मैं यह चाहता हूँ कि तुम समझो कि यही लाखों-करोड़ों दुखिया किसान हिन्दुस्तान हैं; मध्यम वर्ग के मुट्ठीभर आदमी नहीं, जो कि सामने आया करते हैं। मुझे अंदेशा है कि बहुत-से आदमी इसको भूल जाते हैं।

बेज़मीन के बेदख़ल मजदूरों की बड़ी जमात की वजह से बड़े-बड़े कारख़ानों का चलना आसान होगया। क्योंकि ये कारख़ाने तभी चल सकते हैं, जब इनमें काम करने के लिए काफ़ी आदमी मिल सकें (और काफ़ी से ज्यादा भी)। जिस आदमी के पास ज़मीन का एक छोटा-सा टुकड़ा भी है, वह उसे नहीं छोड़ना चाहता। इसलिए कारख़ाना चलाने के लिए यह ज़रूरी है कि बेकार और बेज़मीन लोगों की काफ़ी तादाद हो। ये लोग जितने ज्यादा होंगे, मिल-मालिकों के लिए इस बात में उतनी ही ज्यादा आसानी होगी कि मजदूरी घटाकर इनको अपने क़ब्ज़े में रख सकें। इसीलिए मैंने ऊपर कहा है कि काफ़ी से ज्यादा होने चाहिए।

मेरा ख़याल है, मैंने तुमको बताया है कि इसी ज़माने में एक नया मध्यमवर्ग धीरे-धीरे हिन्दुस्तान में पैदा हुआ और कुछ पूँजी कारबार में लगाने के लिए इकट्ठी की। इस तरह चूँकि पैसा था और मजदूर थे, कारख़ाने पैदा होगये। लेकिन हिन्दुस्तान में ज्यादातर पूँजी जो लगी है, विदेशी (अंग्रेज़ी) है। इन कारख़ानों को ब्रिटिश सरकार ने प्रोत्साहन नहीं दिया। ब्रिटिश सरकार की यह नीति थी कि हिन्दुस्तान को बिलकुल क़्षक देश रक्खा जाय। वह इंग्लैण्ड को कच्चा माल दे और इंग्लैण्ड की बनी हुई चीज़ें खरीदे। ये कारख़ाने ब्रिटिश सरकार की इस नीति के विरुद्ध पड़ते थे। लेकिन स्थिति ऐसी थी, जैसा मैंने तुम्हें बताया है, कि बड़ी मशीनों से हिन्दुस्तान में काम शुरू होनेवाला था और ब्रिटिश सरकार आसानी से उसे रोक नहीं सकती थी। इस तरह सरकार के विरोध के बावजूद कारख़ाने बढ़ने लगे। सरकारी विरोध जाहिर

करने का एक ढंग यह था कि हिन्दुस्तान में जो मशीनें आती थीं, उनपर टैक्स लगा दिया जाता था। दूसरा ढंग यह था कि सूत के माल पर, जो हिन्दुस्तान में बनता था, चुंगी लगादी गई थी। हिन्दुस्तान की कपड़े की मिलें जो कुछ माल बनाती थीं, उस-पर यह टैक्स लगता था।

जमशेदजी नसरवानजी ताता हिन्दुस्तान के शुरू के औद्योगिकों में सबसे बड़ा हुआ है। इसने बहुतसे उद्योग खोले, जिसमें सबसे बड़ा ताता आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का था, जो इसने बिहार में सावनी में खोला था। यह उद्योग १९०७ ई० से शुरू हुआ और १९१२ से चलने लगा। लोहे का उद्योग 'बुनियादी' उद्योग समझा जाता है। आजकल लोहे के ऊपर इतनी चीजें निर्भर हैं कि जिस देश में लोहे का उद्योग नहीं, वह ज्यादातर दूसरों के भरोसे रहता है। ताता का लोहे का कारखाना एक बहुत बड़ा कारखाना है। सावनी का गाँव अब जमशेदपुर का शहर हो गया और थोड़ी दूर पर जो रेलवे स्टेशन है उसको तातानगर कहते हैं। लोहे के कारखाने लड़ाई के जमाने में बहुत क़ीमती हो जाते हैं, क्योंकि ये युद्ध की सामग्री बना सकते हैं। हिन्दुस्तान की ब्रिटिश सरकार के लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात थी कि जब महायुद्ध शुरू हुआ, ताता का कारखाना चल रहा था।

हिन्दुस्तानी कारखानों में मजदूरों की दशा बहुत खराब थी। उन्नीसवीं सदी के शुरू में अंग्रेजी मिलों में मजदूरों की जो हालत थी, वह यहाँ भी थी। मजदूरी बहुत कम थी, क्योंकि बहुतसे ऐसे आदमी मिलते थे जिनके पास न ज़मीन थी और न कोई रोज़गार था और काम करने के घण्टे बहुत ज्यादा थे। १९११ ई० में पहला 'इण्डियन फ़ैक्ट्री ऐक्ट' यानी 'भारतीय कारखानों का क़ानून' पास हुआ। इस क़ानून में भी पुरुषों के लिए दारह घण्टे और बच्चों के लिए छः घण्टे मुक़र्रर हुए।

जिनके पास ज़मीन नहीं थी वे सब मजदूर इन मिलों में नहीं खप सके। इसलिए उनकी एक बहुत बड़ी तादाद चाय के खेतों में और दूसरे फ़ार्मों में काम करने के लिए आताम और हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सों में चली गई। इन खेतों और फ़ार्मों की अवस्था ऐसी थी कि जबतक ये लोग वहाँ काम करते थे, अपने मालिक के गुलाम होकर रहते थे।

२० लाख से ज्यादा गरीब हिन्दुस्तानी मजदूर विदेश चले गये। बहुत-से सीलोन (लंका) और मलाया के खेतों में काम करने के लिए गये। बहुत-से मारीशस के टापुओं में चले गये। कुछ ट्रिनीटाड गये, जो दक्षिण अमेरिका के उत्तर में है। कुछ फ़िजी गये, जो आस्ट्रेलिया के पास है। कुछ दक्षिण अफ़्रीका और पूर्वी अफ़्रीका और ब्रिटिश गायना (जो दक्षिण अमेरिका में है) चले गये। इन देशों में बहुत-सी जगहों में ये लोग 'इन्डोचर' (शतदंड) होकर गये थे, जिसका मतलब था कि क़रीब-क़रीब

गुलाम होकर गये थे। इनडेंचर एक दस्तावेज होता था, जिसमें इन मजदूरों के साथ की हुई शर्तें लिखी रहती थीं, जिनके मुताबिक ये लोग अपने मालिकों के गुलाम हो जाते थे। इनडेंचर की इस प्रथा से पैदा होनेवाली अनेक भयंकर घटनाओं का हाल हिन्दुस्तान में आने लगा, खासकर फ़िजी से। इसपर हिन्दुस्तान में आन्दोलन शुरू हुआ और यह प्रथा तोड़ दी गई।

इतनी बात तो हुई किसानों-मजदूरों की और उन लोगों की जो विदेश में मजदूरी करने के लिए जाते थे। इनके अलावा इस देश की गरीब मूक और बहुत दिनों से कष्ट सहनेवाली जनता थी। बोलने-चालनेवाला वर्ग असल में नया मध्यम वर्ग था, जो अंग्रेजों के सम्बन्ध से पैदा हुआ था लेकिन जिसने उनपर आक्षेप करना शुरू कर दिया था। यह वर्ग तरक्की करने लगा और इसीके साथ-साथ राष्ट्रीय आन्दोलन भी बढ़ा। तुम्हें याद होगा कि यह राष्ट्रीय आन्दोलन १९०७-८ में बहुत ज़बरदस्त हो गया था। उस वक़्त एक सार्वजनिक आन्दोलन ने बंगाल को हिला दिया और हमारी कांग्रेस दो दलों यानी गरम दल और नरम दल में बँट गई। अंग्रेजों ने अपनी वही पुरानी नीति चरती। नरम दल को छोटे-मोटे सुधार देकर अपनेमें मिलाने की कोशिश की और गरम दल को पस्त कर देना चाहा। इसी समय एक नई बात सामने आई। अल्पसंख्यक होने की हँसियत से मुसलमानों ने अलहदा और विशेष राजनैतिक अधिकारों का दावा किया। यह सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि सरकार ने मुसलमानों की इस माँग को प्रोत्साहन दिया, ताकि हिन्दुस्तान में फूट होजाय और राष्ट्रीयता की वाढ़ रुक जाय।

उस वक़्त ब्रिटिश सरकार अपनी नीति में कामयाब हुई। लोकमान्य तिलक जेल में थे और उनका दल दबाया जा चुका था। नरम दल के लोगों ने शासन में चन्द सुधारों को, जिनसे हिन्दुस्तानियों के हाथों में कुछ ताक़त नहीं आती थी, मंजूर करके प्रेमपूर्वक उनका स्वागत किया। इन सुधारों को उस समय के वाइसराय और सेक्रेटरी आफ़ स्टेट यानी भारत-सचिव के नाम पर 'मिण्टो-माले सुधार' कहते हैं। थोड़े दिनों के बाद वंग-भंग मंसूख कर दिया गया। इससे बंगालियों का गुस्सा कुछ ठण्डा पड़ गया। १९०७ के बाद राजनैतिक आन्दोलन बड़े आदमियों के छुट्टी के वक़्त का खेल था, जो अपने कमरे में कुर्सी पर बैठे-बैठे बातें बनाया करते थे। इस कारण १९१४ में, जब लड़ाई शुरू हुई, इस देश में कोई क्रियात्मक राजनैतिक जीवन नहीं था। कांग्रेस में सिर्फ़ नरम दल के आदमी थे, जो साल में एक दफ़ा इकट्ठा होकर चन्द कागज़ी प्रस्ताव पास कर दिया करते थे और फिर कुछ नहीं करते थे। राष्ट्रीयता का पारा बहुत नीचे आगया था।

पश्चिम के सम्पर्क में आने की वजह से राजनैतिक क्षेत्र के अलावा और क्षेत्रों पर भी कुछ असर पड़ा। जनता के विचारों पर नहीं, बल्कि नवीन मध्यमवर्ग के धार्मिक विचारों पर असर पड़ा और ब्राह्म-समाज और आर्यसमाज ऐसे आन्दोलन उठ खड़े हुए। जाति-पाँति प्रणाली की कट्टरता कम होने लगी। सांस्कृतिक जागृति खासकर बंगाल में हुई। बंगाली लेखकों ने बंगला भाषा को हिन्दुस्तान की आजकल की भाषाओं में सबसे सम्पन्न बना दिया और बंगाल ने उसके सबसे बड़े हिन्दुस्तानी यानी रवीन्द्रनाथ ठाकुर को जन्म दिया, जो हमारी खुशकिस्मती से अभी तक हमारे बीच मौजूद हैं। बंगाल ने विज्ञान में बड़े-बड़े आदमी पैदा किये—जैसे सर जगदीशचन्द्र बसु और सर प्रफुल्लचन्द्र राय। मैं तुम्हें एक भारतीय वैज्ञानिक का नाम और बताऊँगा, जो इन लोगों से उम्र में बहुत कम है। वह हैं सर चन्द्रशेखर वेंकट रमण। सारी दुनिया इन नामों को जानती है। इस तरह हिन्दुस्तान हरेक चीज़ में, विज्ञान के हरेक क्षेत्र में, श्रेष्ठ बन रहा था; और यह तुम जानती ही हो कि योरोप की महानता की बुनियाद विज्ञान रहा है।

मैं यहाँ एक दूसरे नाम का भी जिक्र करना चाहता हूँ। यह सर मुहम्मद इक़्बाल का नाम है। यह उर्दू और खासकर फ़ारसी के बड़े प्रतिभाशाली कवि हैं। इन्होंने राष्ट्रीयता पर कई सुन्दर कविताएँ लिखी हैं। बदकिस्मती से इन्होंने हाल में कविता लिखना छोड़ दिया और दूसरे काम में लगे हुए हैं।

महायुद्ध के पहले हिन्दुस्तान राजनैतिक दृष्टि से शान्त था; लेकिन एक दूर देश में हिन्दुस्तान की इज्जत के लिए एक वीरतापूर्ण और असाधारण लड़ाई हुई। दक्षिण अफ़्रीका में हिन्दुस्तानी मजदूरों की काफ़ी तादाद थी और कुछ व्यापारी भी वहाँ जाकर बस गये थे। इन लोगों के साथ सैकड़ों तरीकों से बुरा बर्ताव किया जाता था और इनकी बेइज्जती की जाती थी, क्योंकि उस देश में क़ामी ग़ुलूर बहुत बढ़ा-चढ़ा था। इत्तफ़ाक़ से एक नौजवान हिन्दुस्तानी बैरिस्टर एक मुकदमे की पैरवी के लिए दक्षिण अफ़्रीका गया। उसने अपने देशवासियों की हालत देखी तो वह बहुत अपमानित और दुखित हुआ। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि इनकी मदद के लिए जो कुछ हो सकेगा वह करेगा। वर्षों तक वह बहुत ख़ामोशी के साथ काम करता रहा। उसने अपनी जायदाद और कारोबार छोड़ दिया और जिस काम को उसने अपने हाथ में लिया था उसीमें अपनेको पूरे तौर से लगा दिया। यह व्यक्ति मोहनदास परमचन्द गांधी था। आज हिन्दुस्तान का बच्चा-बच्चा इसे जानता है और याद करता है; लेकिन उस वक़्त दक्षिण अफ़्रीका के दाहर इसे कोई नहीं जानता था। मगर एकदम से इसका नाम तारे हिन्दुस्तान में बिजली की तरह फैल गया। लोग इसके बारे में और

इसकी वहादुराना लड़ाई के बारे में आश्चर्य, प्रशंसा और अभिमान के साथ चर्चा करने लगे। दक्षिण अफ़्रीका की सरकार ने वहाँके रहनेवाले हिन्दुस्तानियों को और भी ज्यादा अपमानित करने की कोशिश की और वापू के नेतृत्व में जो आन्दोलन चला उसके सामने सरकार ने झुकने से इनकार किया। बड़े ताज्जुब की बात थी कि गरीब, पद-दलित, जाहिल मजदूरों की एक जमात और छोटे-छोटे व्यापारियों का समुदाय, जो अपनी मातृभूमि से इतनी दूर हो, इस क्रिस्म का वहादुरी का तर्जोअमल इस्तिथार करे। इससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात यह थी कि इस लड़ाई में जिस राजनैतिक शस्त्र का इन्होंने इस्तेमाल शुरू किया, वह संसार के इतिहास में अनोखा था। हमने अब तो इसके बारे में बहुत काफ़ी सुन लिया है। यह शस्त्र था वापू का सत्याग्रह। इसको अक्सर निष्क्रिय प्रतिरोध भी कहते हैं, लेकिन यह ग़लत तर्जुमा है, क्योंकि सत्याग्रह में काफ़ी कर्मण्यता पाई जाती है। सत्याग्रह में सिर्फ़ अविरोध ही नहीं है। अहिंसा इसका मुख्य अंग है। वापू ने इस अहिंसापूर्ण संग्राम से हिन्दुस्तान और दक्षिण अफ़्रीका में खलबली मचा दी और जब हिन्दुस्तान के लोगों ने सुना कि उनके हजारों देशवासी, स्त्री और पुरुष, दक्षिण अफ़्रीका में खुशी-खुशी जेल गये, तो अभिमान और आनन्द से उनका हृदय गद्गद् होगया। हम अपने देश में अपनी असहायता और दासता पर मन-ही-मन लज्जित होने लगे और अपने देशवासियों के वीरतापूर्ण संघर्ष के इस उदाहरण ने हमारे आत्माभिमान को बढ़ा दिया। इस मसले पर हिन्दुस्तान एकदम से राजनैतिक दृष्टि से जग पड़ा। दक्षिण अफ़्रीका को रुपया तेज़ी के साथ भेजा जाने लगा। जब वापू और दक्षिण अफ़्रीका की सरकार का समझौता होगया, यह लड़ाई रुक गई। यद्यपि हिन्दुस्तानियों की उस समय यह एक असंदिग्ध विजय थी, फिर भी कितनी ही बन्दिजों हिन्दुस्तानियों पर अभीतक लगी हुई हैं और कहते हैं कि दक्षिण अफ़्रीका की सरकार ने समझौते की शर्तों का पूरा-पूरा पालन नहीं किया। प्रवासी भारतीयों का सवाल अभीतक हल नहीं हुआ, और जबतक हिन्दुस्तान आजाद नहीं हो जाता, तबतक हल होगा भी नहीं। भला हिन्दुस्तानियों को दूसरे देशों में इज्जत कैसे मिल सकती है, जबकि अपने ही देश में उन्हें वह हासिल नहीं है? और जबतक अपने ही देश में आजादी हासिल करने में हमें कामयाबी नहीं मिलती, हम प्रवासी भारतीयों को कैसे मदद पहुँचा सकते हैं?

युद्ध से पहले के वर्षों में हिन्दुस्तान की यह हालत थी। १९११ में जब इटली ने तुर्की पर हमला किया तो हिन्दुस्तान में तुर्की के लिए बहुत हमदर्दी पैदा होगई, क्योंकि तुर्की को लोग एशियाई और पूर्वी शक्ति समझते थे और इस हैसियत से सारे हिन्दुस्तानियों की उसके साथ हमदर्दी थी। हिन्दुस्तानी मुसलमानों पर इसका ख़ास असर

पड़ा, क्योंकि ये लोग तुर्की के सुल्तान को खलीफ़ा यानी धर्म का प्रमुख नेता मानते थे। उस ज़माने में अखिल इस्लामवाद की कुछ चर्चा चली थी। इसे तुर्की के सुल्तान अब्दुल-हमीद ने शुरू किया था। १९१२-१३ के बालकन युद्ध ने हिन्दुस्तान के मुसलमानों में और भी ज्यादा हलचल पैदा कर दी और अपने सद्भाव और मित्रता को जाहिर करने के लिए डाक्टरों का एक दल, जिसे 'रेड क्रिसेंट मिशन' कहा गया है, हिन्दुस्तान से तुर्की के जल्मी लोगों को मदद देने के लिए रवाना हुआ। हमारे सच्चे मित्र डाक्टर एम० ए० अन्सारी इस मिशन के नेता थे।

इसके बाद ही मशहूद शुरू हुआ और तुर्की उसमें फँसकर इंग्लैंड का दुश्मन बन गया। लेकिन यह चर्चा हमें युद्ध-काल तक पहुँचा देती है, इसलिए मुझे अब यहीं रुक जाना चाहिए।

: १४८ :

युद्ध : १९१४-१९१८

३१ मार्च, १९३३

मैं इस युद्ध के बारे में तुम्हें क्या लिखूँ, जिसे संसार-युद्ध या महायुद्ध कहा गया है और जो ४ वर्ष तक योरप, एशिया और अफ़्रीका के कुछ हिस्सों को बरबाद करता रहा और जिसने लाखों जवानों का उटती जवानी में ही काम तमाम कर दिया। युद्ध का विषय ऐसा नहीं है कि उसपर खुशी के साथ विचार किया जा सके। यह बड़ी दुःखद चीज़ है। लेकिन अक्सर इसकी तारीफ़ की जाती है और इसके गुण गाये जाते हैं। कहा जाता है कि जैसे आग सोने-चाँदी को खरा कर देती है वैसे ही युद्ध आलसी लोगों को, जो बहुत ज्यादा आराम और विलासिता की वजह से नाजुक और दूषित हो जाती हैं, मजबूत और खरा कर देता है। हमारे सामने बहादुरी और त्याग की बड़ी-बड़ी निसालें पेश की जाती हैं, मानों युद्ध ही की वजह से ये सद्गुण पैदा होते हैं !

मैंने तुम्हारे साथ इस युद्ध के कुछ कारणों पर विचार किया है और बताया है कि पूँजीवादी औद्योगिक देशों की और साम्राज्य-शक्तियों की प्रतिद्वन्द्विता किस तरह टषकर खा गई और संघर्ष किस तरह अनिवार्य होगया। इन सारे देशों के उद्योगों के प्रमुख लोग किस तरह शोषण करने के लिए ज्यादा-से-ज्यादा क्षेत्र और मौक़ा चाहते थे। बड़े-बड़े साहूकार किस तरह रुपया कमाने की फ़िक्र में थे और हथियारों के बनानेवाले किस प्रकार ज्यादा मुनाफ़ा चाहते थे। इसलिए ये लोग लड़ाई के लिए तैयार पड़े और इनके हृषम पर और इनके तथा प्रतिनिधि दुर्जुन राजनीतिज्ञों के हृषम

पर राष्ट्रों के नौजवान एक-दूसरे का गला काटने के लिए आगे आगये । इन नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद और इन सारे देशों की साधारण जनता इस बात को बिल्कुल नहीं जानती थी कि युद्ध के क्या कारण हैं ! असल में इस युद्ध से इनका कोई ताल्लुक नहीं था—चाहे सफलता होती या असफलता, हर हालत में इनका नुकसान ही था । यह अमीर आदमियों का जुआ था, जो उन्होंने लोगों की ओर ख़ासकर नौजवानों की जिन्दगी को दाव पर रखकर खेला था । लेकिन जबतक साधारण जनता लड़ने के लिए तैयार न हो, लड़ाई हो ही नहीं सकती । यूरोपिय महाद्वीप के सारे देशों में, जैसा कि मैंने तुमको बताया है, अनिवार्य सैनिक भरती की प्रगाली नहीं पाई जाती थी । इस क्रिस्म की भरती तो बाद की लड़ाई के ज़माने में शुरू हुई । लेकिन ज़बरदस्ती से क्या होता है ? ऐसी हालत में अगर लोग दिल से लड़ने को तैयार न हों तो उन्हें कोई ज़बरदस्ती नहीं लड़वा सकता ।

इसलिए जितने राष्ट्र लड़ाई में शामिल हुए थे, सभी में इस बात की कोशिश की गई कि जनता के देश-प्रेम और उत्साह को भड़काया जाय । हरेक पक्ष दूसरे पक्ष को ज़ालिम कहता था और इस बात का बहाना करता था कि हम आत्म-रक्षा के लिए युद्ध कर रहे हैं । जर्मनी कहता था कि उसके चारों तरफ़ दुश्मनों की जंजीर बिछी हुई है और ये दुश्मन उसका गला घोट देना चाहते हैं । वह रूस और फ़्रांस पर इस बात का इलज़ाम लगाता था कि इन्होंने उसके ऊपर हमला करके लड़ाई की शुरुआत कर दी । इंग्लैण्ड यह वजह बताता था कि नन्हे-से बेलजियम की तटस्थता को जर्मनी वालों ने अन्यायपूर्वक तोड़ डाला, इसलिए नीति की दृष्टि से बेलजियम की रक्षा होनी चाहिए । सारे देश, जो इस लड़ाई में शामिल थे, अपनेको दूध का धुला बतलाते थे और सारा दोष दुश्मन के ऊपर डालते थे । हरेक राष्ट्र के लोगों को इस बात का यक़ीन दिला दिया गया था कि उनकी आज़ादी ख़तरे में है और उसकी रक्षा के लिए उन्हें युद्ध करना ज़रूरी है । हर जगह युद्ध का वातावरण पैदा करने में अख़बारों ने ख़ासतौर से मदद दी, जिसका मतलब यह हुआ कि शत्रु देश के रहने-वालों के बारे में लोगों के दिलों में सख़्त नफ़रत पैदा कर दी ।

पागलपन की यह लहर इतनी मजबूत थी कि जो चीज़ इसके सामने पड़ी वही बह गई । जनता के रोष को भोड़ के अन्दर उत्तेजित कर देना आसान काम था, लेकिन समझने-बूझनेवाले आदमी, स्त्री और पुरुष, जिनके बारे में यह कहा जा सकता है कि शान्त और गम्भीर भिजाज़ के थे, युद्ध में फँसे हुए देशों के लेखक, विचारक, प्रोफ़ेसर, वैज्ञानिक, सभी चक्कर में फँस गये और दुश्मन-देश के निवासियों से नफ़रत करने लगे और उनके खून के प्यासे होगये । पादरी लोग और मजहबी

आदमी, जो शान्त लोग समझे जाते हैं, औरों की तरह ही खून के प्यासे थे, बल्कि उन लोगों से भी ज्यादा। शान्तिवादी और साम्यवादी भी अपनी बुद्धि खो बैठे और अपने उसूल भूल गये। सभी भूल गये, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो नहीं भूले। हरेक देश में बहुत छोटी तादाद ऐसे आदमियों की भी थी जिन्होंने पागल बनने से इन्कार कर दिया और युद्ध का बुझार अपने ऊपर चढ़ने नहीं दिया। लोग इनपर हँसते थे और इनको बुज-दिल कहते थे; और बहुतसे तो ऐसे थे जिन्हें जेलखाने भेज दिया गया, क्योंकि उन्होंने लड़ाई में काम करने से इन्कार कर दिया था। इनमें से कुछ साम्यवादी थे, और कुछ मजहबी लोग थे, जैसे बवेकर लोग जो लड़ाई को धार्मिक दृष्टि से बुरा समझते हैं। यह सच कहा गया है कि आजकल जब लड़ाई छिड़ती है, तो उसमें फँसे हुए आदमी पागल हो जाते हैं।

ज्यों ही लड़ाई शुरू हुई, अनेक देशों की सरकारों ने सचाई छिपाने के लिए और तरह-तरह की झूठी बातें फैलाने के लिए लड़ाई को बहाना बना लिया। लोगों की व्यक्तिगत आजादी भी दबा दी गई। दूसरी तरफ़ की बात तो बिल्कुल ही नहीं बताई जाती थी, जिससे लोगों को सिर्फ़ किस्से का एक ही पहलू मालूम होता था और वह भी बहुत-कुछ बिगाड़कर बताया जाता था और अक्सर तो बिल्कुल झूठी बातें कही जाती थीं। इस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाना मुश्किल नहीं था।

शान्ति के जमाने में भी संकीर्ण राष्ट्रीय प्रचार और अखबारों की मन-नादुनत बातें जनता को बेवकूफ़ बनाती रही थीं और उन्होंने लड़ाई के लिए ज़मीन तैयार कर-दी थी। युद्ध को खुद ही बड़ी आराधना की चीज़ बताया गया था। जर्मनी में, या यों कहो प्रशा में, युद्ध की तारीफ़ करना क़ैसर से लेकर नीचे तक जितने शासक थे उन सभी का परम-कर्तव्य बन गया था। युद्ध को उचित साबित करने के लिए बिहत्तापूर्ण किताबें लिखी गई थीं और इस बात को साबित किया गया था कि युद्ध इन्सान की ज़िन्दगी और तरबज़ी के लिए ज़रूरी है। क़ैसर की बहुत शोहरत होगई, क्योंकि वह हमेशा भोंडे तरीके से शोखी बघारा करता था। लेकिन इंग्लैंड में और दूसरे देशों में भी सैनिक और ऊँचे वर्ग के लोगों में इसी किस्म के ख़याल पाये जाते थे। रस्किन इंग्लैंड का उन्नीसवीं सदी का एक महाहूर लेखक हुआ है। उसकी किताबें वापू को बहुत पसन्द हैं और उसकी कुछ किताबें तुमने भी पढ़ी होंगी। असंदिग्ध रूप से शुद्ध हृदय के इस आदमी ने अपनी एक किताब में लिखा है :—

“संक्षेप में बात यह है कि मैं देखता हूँ, सब बड़ी-बड़ी क़ीमों ने अपने शब्दों की नज़ार और अपने विचारों की मजदूती युद्ध से साँझी और शान्ति से उमे नो दिया। युद्ध ने मिथ्या दी, शान्ति ने धोखा दिया। एक शब्द में यह कह सकते हैं कि बड़ी-बड़ी क़ीमों ने युद्ध से पैदा होती है और शान्ति में मर जाती है।”

इस बात को बताने के लिए कि रस्किन कितना साफ़ साम्राज्यवादी था, उसकी किताब से मैं एक दूसरा उद्धरण तुम्हारे सामने रखूंगा :—

“इंग्लैण्ड को यही बात करनी चाहिए, नहीं तो वह नष्ट होजायगा । उसे उपनिवेश बनाना चाहिए और जहाँ कहीं भी उसे ज़मीन का ऐसा वीरान हिस्सा मिले, जिसमें उपज हो सकती है, उसपर कब्ज़ा कर लेना चाहिए और उसे अपने उपनिवेशियों को यह बताना चाहिए कि समुद्री या खुशकी किसी जरिये से इंग्लैण्ड की ताक़त को बढ़ाना उनका पहला उद्देश्य है ”

मैं एक दूसरा उद्धरण और देता हूँ । यह एक अंग्रेज़ अफ़सर की किताब से लिया गया है, जो ब्रिटिश सेना में मेजर जनरल होगया था । वह कहता है कि युद्ध में विजय उस वक़्त तक बिल्कुल नामुमकिन है जबतक कि “जानबूझकर झूठ न बोला जाय, झुठाई के काम न किये जायें और बातों को गोलमोल ढंग से और घुमा-फिराकर न बताया जाय ।” उसके कथनानुसार कोई भी नागरिक, जो “इन साधनों पर अमल करने से इनकार करता है, अपने साथियों, अपने मातहतों और अपने देश के प्रति जान-बूझकर दगा करता है और इसके अलावा उसके लिए कुछ और नहीं कह सकते कि वह अत्यन्त घृणा-योग्य और वुजदिल है । बड़ी क़ौमों के सामने नीति-अनीति क्या चीज़ है, जबकि उनकी ज़िन्दगी ख़तरे में पड़ी हो ? हरेक क़ौम को चाहिए कि जबतक दुश्मन मर न जाय ।” वह आघात पर आघात करती रहे, मुझे मालूम नहीं कि इन सब बातों के बारे में रस्किन क्या कहता । लेकिन यह न समझना कि यह अंग्रेज़ी मन का कोई ठीक नमूना है, या यह कि क्रैसर की लम्बी-चोड़ी स्पीचें साधारण जर्मनी की मनोदशा जाहिर करती थीं । लेकिन बदक्रिस्मती की बात तो यह है कि जो इस क्रिस्म का विचार रखते हैं, अकसर उन्हीं के हाथ में अधिकार होता है और लड़ाई के ज़माने में वही आदमी सामने आजाते हैं ।

आम तौर पर ऐसी साफ़-साफ़ बातें जनता के सामने नहीं कही जातीं और युद्ध के ऊपर एक मजहब की गिलाफ़ चढ़ा दिया जाता है । इसलिए जब एक तरफ़ थोरप में और दूसरी जगहों पर सैकड़ों मील तक युद्ध के मोरचे में बेतहाशा क़त्ल जारी था, उस क़त्ल को उचित साबित करने के लिए और लोगों को धोखे में रखने के लिए घर पर बड़े सुन्दर और मधुर वाक्य बनाये जा रहे थे । कहा जाता था कि यह युद्ध आत्म-सम्मान और आज़ादी की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा है; युद्ध ख़त्म करने के लिए यह लड़ा जा रहा है; और लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए, आत्मनिर्णय के लिए, छोटी क़ौमों की आज़ादी के लिए यह लड़ाई लड़ी जा रही है । इसी दरभियान बहुत-से साहूकार और व्यवसायी और युद्ध-सामग्री बनानेवाले, जो घर पर बैठे रहते थे और इन नफ़ीस

जुमलों को देशभक्ति के साथ इस्तेमाल करके नौजवान आदमियों को लड़ाई की भट्टी में कूदने के लिए प्रेरित करते थे, बेहद मुनाफ़ा कमा रहे थे और करोड़पति होते जाते थे ।

ज्यों-ज्यों लड़ाई महीने-पर-महीने और साल-पर-साल बढ़ती गई, और-और देश इसके अन्दर फँसते गये । गुप्त रूप से रिश्वतें पेश करके तटस्थ देशों को अपनी तरफ़ मिलाने की कोशिश दोनों ही तरफ़ के लोग करते थे । अगर ये रिश्वतें खुल्लम-खुल्ला पेश की गई होतीं तो वे ऊँचे आदर्श और नफ़ीस जुमले, जिनको मकान की छतों पर से चिल्लाया जाता था, खत्म होगये होते । इंग्लैण्ड और फ़्रान्स की रिश्वत देने की ताक़त जर्मनी से ज्यादा थी, इसलिए तटस्थ, लोग जो लड़ाई में शामिल हुए । ज्यादातर अंग्रेज़, फ़्रान्सीसी और रूसियों की तरफ़ आये । जर्मनी के पुराने मददगार इटली को मित्र-राष्ट्रों ने, एक गुप्त सन्धि करके और उसमें यह वादा करके कि इटली को एशियामाइनर में और दूसरी जगहों पर उपनिवेश दिये जायेंगे, अपनी तरफ़ मिला लिया । रूस के साथ भी एक गुप्त सन्धि हुई थी, जिसमें उसे कुस्तुनतुनिया देने का वादा किया गया था । दुनिया को आपस में बाँटने का यह काम बहुत ही रोचक और दिलचस्प था । ये गुप्त समझौते मित्र-राष्ट्रों के राजनीतिज्ञों के सार्वजनिक वक्तव्यों के धिलकुल ख़िलाफ़ जाते थे और शायद इन समझौतों के बारे में किसीको पता भी न चलता, अगर रूसी बोलशेविकों ने अधिकार पाने पर इनको प्रकाशित न कर दिया होता ।

अख़ीर में मित्र-राष्ट्रों की तरफ़ एक दर्जन या इससे ज्यादा देश आगये थे । संक्षेप के लिए मैं अंग्रेज़-फ़्रांसीसी पक्ष को मित्र-पक्ष कहूँगा । मित्र-पक्ष में ब्रिटेन था, उसका साम्राज्य था और इसके अलावा फ़्रांस, रूस, इटली, अमेरिका, बेलजियम, सर्बिया, जापान, चीन, रूमानिया, यूनान और पुर्तगाल थे । मुमकिन है कि एक या दो और रहे हों, जिनका नाम मुझे याद नहीं । जर्मन-पक्ष में जर्मनी, आस्ट्रिया, तुर्की और बल्गेरिया थे । अमेरिका तीसरे वर्ष लड़ाई में शामिल हुआ । अगर हम इन बातों का ख़याल न भी करें तो भी जाहिर है कि मित्र-पक्ष के साधन जर्मन पक्ष से कहीं ज्यादा थे । इसके पास आदमी ज्यादा थे, पैसे ज्यादा थे, अस्त्र-शस्त्र और युद्ध-सामग्री बनाने के कारख़ाने ज्यादा थे, और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि समुद्रों के ऊपर इन लोगों का अधिकार था जिसकी वजह से तटस्थ देशों की सामग्री से ये आत्तानी के साथ फ़ायदा उठा सकते थे । मित्र-पक्ष अमेरिका से युद्ध-सामग्री और खाने-पीने का सामान ले सकता था और पैसा भी उधार ले सकता था, क्योंकि समुद्र की ताक़त उसके हाथ में थी । जर्मनी और उसके मित्र चारों तरफ़ दुश्मनों से घिरे और जकड़े हुए थे । जर्मनी के सहायक देश कमजोर थे और उनकी ज्यादा मदद नहीं कर

सकते थे। वे जर्मनी के ऊपर एक तरह का बोझ थे, जिसको खड़ा रखने के लिए उसे हमेशा टेका और सहारा लगाना पड़ता था। इसलिए व्यावहारिक दृष्टि से जर्मनी दुनिया के अधिकांश हिस्से से अकेला लड़ रहा था। हरेक दृष्टि से यह संघर्ष बहुत ज्यादा असमान कहा जा सकता है, फिर भी जर्मनी चार वर्ष तक दुनिया के मुकाबिले में खड़ा रहा और विजय के नजदीक बराबर पहुँचता रहता था। हर साल विजय कभी इधर और कभी उधर आती हुई दिखाई देती थी। एक अकेले राष्ट्र की यह कोशिश आश्चर्यजनक थी, और सिर्फ इसलिए मुमकिन हो सकी कि जर्मनी ने शानदार सैनिक मशीन तैयार कर रखी थी। अखीर में जब जर्मनी और उसके साथी अन्तिम रूप से पराजित हो चुके थे, जर्मन सेना उस समय भी संगठित थी और उसका अधिकांश हिस्सा विदेशी जमीन पर था।

मित्र-पक्ष में लड़ाई का सबसे ज्यादा बोझ फ्रांसीसी सेना पर पड़ा और फ्रांसीसी लोगों ने ही लाखों नौजवानों की जिन्दगी खोकर जर्मन सैनिक मशीन का मुकाबिला किया। इंग्लैंड को बड़ी सहायता इस बात की थी कि उसके पास जल-सेना थी और सामुद्रिक शक्ति थी। कूटनीतिज्ञता और प्रचार में भी उसने मदद दी। जर्मनी को अपनी सेना पर अभिमान था और वह तटस्थ देशों से व्यवहार करने में और प्रचार के तरीकों में बहुत ही ज्यादा अनगढ़ साबित हुआ। इसमें जरा भी शक नहीं कि लड़ाई के जानने में इंग्लैंड ने गलत बातों के प्रचार की कुशलता और क्लबलियत तथा झुठाई में दुनिया को मात कर दिया। रूस, इटली और दूसरे सहायक देशों ने इसके मुकाबिले में बहुत मामूली हिस्सा लिया और लड़ाई के मामलात में उनके कारनामों बहुत उल्लेखनीय नहीं रहे। फिर भी रूस को सारे देशों से ज्यादा नुकसान हुआ। अमेरिका अन्त में लड़ाई में शामिल हुआ और उसके आने की वजह से ही जर्मन लोग अन्तिम तौर पर परास्त होगये।

लड़ाई के शुरू महीनों में अमेरिका और इंग्लैंड में बहुत खिंचाव था, और इस बात का कभी-कभी जिक्र होजाता था कि इनमें लड़ाई होजायगी। खिंचाव की वजह यह थी कि इंग्लैंड अमेरिका के सामुद्रिक व्यापार में दस्तन्दाजी करता था, क्योंकि उसे शक था कि अमेरिका के जहाज जर्मनी को माल पहुँचाते हैं। इसपर ब्रिटिश प्रचार-विभाग ने काम करना शुरू किया और अमेरिका को अपनी तरफ़ मिला लेने की खास कोशिश की। पहली बात जो इन लोगों ने हाथ में ली, वह जर्मनों के अत्याचारों के बारे में प्रचार था। जर्मन सेना ने बेलजियम में क्या किया, इसकी भयंकर कहानियाँ बना-बनाकर फैलाई गईं। इसका नाम रक्खा गया था जर्मन हूणों की भीषणता। इन किस्सों में कुछ ऐसे भी थे जो अंशतः घटनाओं पर निर्भर थे, जैसे

लूवेन की यूनिवर्सिटी और पुस्तकालय की तबाही। लेकिन ज्यादातर ये क्रिस्ते बिलकुल मनगढ़न्त हुआ करते थे। एक आश्चर्यजनक क्रिस्सा यह कहा जाता था कि जर्मन लोगों ने लाशों का एक कारखाना खोल रखवा है। दुश्मन देशों की जनता के प्रति हरेक देश में इतनी घृणा थी कि वह सब बातों पर यक़ीन करने को तैयार था।

तुम्हें ब्रिटिश प्रचार के विस्तार और पैमाने का कुछ अन्दाज़ा इस बात से लग सकता है कि अमेरिका में ब्रिटिश वार मिशन यानी युद्ध-प्रचार-विभाग में ५०० अफ़सर और दस हजार आदमी काम करते थे। यह तो सरकारी इन्तज़ाम था। इसके अलावा ग़ैर-सरकारी काम बेहद होता था। इस प्रचार-कार्य के लिए उचित और अनुचित सब क्रिस्म के तरीक़े काम में लाये जाते थे। स्वीडन के स्टाकहोल्म में अंग्रेज़ों ने सरकारी तौर पर एक अंग्रेज़ संगीतालय खोल रखवा था, जिसमें ये लोग लोगों का तरह-तरह से मनोरंजन कराया करते थे, ताकि स्वीडन के वाशिन्टों की सद्भावना इनकी तरफ़ होजाय। इस प्रचार ने और जर्मनों की पनडुब्बी की कारवाइयों ने, जिसके बारे में मैं बाद को कुछ बताऊँगा, अमेरिका को मित्र-दल के पक्ष में आने में बड़ी मदद दी। लेकिन तसफ़िया करनेवाली बात तो पैसे की थी।

लड़ाई बड़ी ख़र्चीली चीज़ है। यह भयंकर रूप से ख़र्चीला व्यापार है। लड़ाई में बहुमूल्य सामान की विशाल मात्रा लग जाती है और उसके बदले सिर्फ़ बरवादी मिलती है। दौलत पैदा करने के ज्यादातर काम इसकी वजह से रक जाते हैं और लोगों की सारी ताक़त तबही और बरवादी के लिए जना होजाती है। इतना सारा धन कहाँसे आता था ? पहली बात तो यह है कि मित्र-पक्ष में इंग्लैंड और फ़्रांस ही ऐसे देश थे जिनकी माली हालत अच्छी कही जा सकती थी। यही नहीं कि ये अपनी लड़ाई का सारा ख़र्चा बरदाश्त करते रहे हों बल्कि अपने मददगारों को भी धन और युद्ध-सामग्री उधार देकर उनकी मदद करते थे। कुछ दिनों के बाद पेरिस बोल गया। उसके आर्थिक साधन ख़त्म होगये। इसके बाद लन्दन ने अकेले सारे मित्र-पक्ष को धन से मदद देनी शुरू की। लड़ाई के दूसरे साल के ख़त्म होने तक लन्दन भी बोल गया। इसलिए १९१६ के अन्त में फ़्रांस और इंग्लैंड दोनों की साख़ ख़त्म हो चुकी थी। इसपर अंग्रेज़ों की एक मण्डली, जिसमें उनके बड़े-बड़े राजनीतिज्ञ शामिल थे, आर्थिक सहायता मांगने के लिए अमेरिका गई। अमेरिका उधार देने के लिए राज़ी होगया और उसके बाद से अमेरिका के पैसे से मित्र-पक्ष की लड़ाई जारी रही। मित्र-पक्ष के ऊपर अमेरिका का क़र्ज़ा दिन दूना और रात चौगुना होने लगा और बढ़कर विस्मय-जनक संख्या तक पहुँच गया। ज्यों-ज्यों क़र्ज़ बढ़ा, अमेरिका के बड़े-बड़े बँक और साहूकार, जिनोंने उधार दिया था, मित्र-पक्ष की विजय के लिए अधिकाधिक उत्सुक

होते गये। उन्होंने सोचा कि अगर जर्मनी ने मित्र-पक्ष को हरा दिया तो वह वेशुमार रक्तम कैसे मिलेगी जिसे अमेरिका ने मित्र-पक्ष को उधार दे रक्खा है? अमेरिका के महाजनों की जेब पर आ बनी और उन्होंने ऐसी हालत में जो मुनासिब समझा किया। इस बात का खयाल अमेरिका में बढ़ने लगा कि वह लड़ाई में मित्र-पक्ष का साथ दे और अन्त में अमेरिका ने साथ दिया।

आजकल हम अमेरिकन क्रॉज के बारे में बहुत-कुछ सुनते हैं और अखबारों में भी इसकी खूब चर्चा रहती है। यह क्रॉज, जो इंग्लैंड और फ़्रान्स की गर्दन में चक्की की तरह लटका हुआ है और जिसे ये अब अदा नहीं कर सकते, लड़ाई के जमाने में लिया गया था। अगर यह रुपया उस वक्त न मिला होता तो इनकी साख बिल्कुल जाती रहती और शायद अमेरिका इनका साथ भी न देता।

मैं अब यहाँ ठहर जाऊँगा। अगले खत में मैं तुम्हें यह बतलाऊँगा कि लड़ाई के दौरान में क्या हुआ और लड़ाई कैसे खत्म हुई।

: १४६ :

महायुद्ध की गति

१ अप्रैल, १९३३

जब अगस्त १९१४ के शुरू में लड़ाई आरम्भ हुई, सारी दुनिया फ़्रांस की उत्तरी सरहद और बेलजियम की तरफ देखने लगी। जर्मन फ़ौजें आगे बढ़ती जाती थीं और उनके रास्ते में जितनी रुकावटें पड़तीं उन सबको फुचलती जाती थीं। थोड़ी देर के लिए नन्हे-से बेलजियम ने इन्हें रोका, इसपर नाराज होकर इन लोगों ने आतंक पैदा करनेवाली हरकतों से बेलजियन लोगों को डराना चाहा। मित्र-पक्ष ने इन्हीं बातों के आधार पर अत्याचार की कहानियाँ बनाई थीं। जर्मन फ़ौजें पेरिस की तरफ बढ़ीं; फ़्रांस की सेना इनके सामने ठहर न सकी और छोटी-सी ब्रिटिश सेना हटाकर एक तरफ़ करदी गई। लड़ाई शुरू होने के एक महीने के अन्दर ही ऐसा मालूम होता था कि पेरिस की क्रिस्मत का फ़सला होगया। फ़्रांसीसी सरकार अपने दफ्तरों और अपनी क्रीमती चीजों को दक्षिण में बोर्डो को ले जाने की तैयारी करने लगी। कुछ जर्मनों ने समझा कि हमने लड़ाई जीत ली। अगस्त के अखीर में पश्चिमी मोर्चे यानी फ़्रांसीसी मोर्चे पर यह हालत थी।

इसी बीच रूसी फ़ौजें पूर्वी प्रशा पर हमला कर रही थीं। इस बात की कोशिश की गई कि जर्मनों का ध्यान पश्चिमी मोर्चे से हट जाय। फ़्रांस और इंग्लैंड में रूसी

स्टीमरोलर (भाप से चलनेवाला बड़ा बेलनदार इंजिन) के ऊपर बहुत आशायें बांधी गई थीं। यह कहा जाता था कि यह बेलन बेलते-बेलते बर्लिन पहुँचेगा। रूसी सियाहियों के पास काफ़ी अस्त्रशस्त्र नहीं थे और उनके अफ़सर बिल्कुल नालायक थे, और उनके पीछे ज़ार की बेईमान सरकार थी। एकाएक जर्मन लोग रूसियों पर टूट पड़े और एक बहुत बड़ी रूसी सेना को पूर्वी प्रशा की झीलों और दलदलों में फँसाकर बरबाद कर दिया। इस बड़ी जर्मन विजय को 'टैननबर्ग की लड़ाई' कहते हैं; और इस विजय के साथ जिस ख़ास सेनापति का नाम जुड़ गया है वह वान हिण्डनबर्ग था, जो आजकल जर्मन लोकतंत्र का राष्ट्रपति है।

यह बड़ी भारी विजय जरूर थी, लेकिन एक तरह से जर्मन फौजों का इससे बड़ा नुक़सान हुआ। इस विजय को प्राप्त करने के लिए और इस बात से डरकर कि रूसी लोग पूर्व में कुछ बढ़ रहे हैं, जर्मनों ने अपनी कुछ फौज फ्रांस से हटाकर रूस की तरफ़ भेज दी। इसकी वजह से पश्चिमी मोर्चे पर उनका जोर कुछ कम हो गया और फ्रांसीसी फौज ने आगे बढ़नेवाले जर्मनों को पीछे हटा देने की ज़बरदस्त कोशिश की। सितम्बर १९१४ के शुरू में मार्न (Marne) की लड़ाई में उन्होंने जर्मनों को पचास मील पीछे हटा दिया। पेरिस बच गया और फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों को साँस लेने का मौक़ा मिल गया।

जर्मनों ने फिर आगे बढ़ने की कोशिश की और वे क़रीब-क़रीब कानयाव हो चुके थे, लेकिन फिर रोक लिये गये। इसके बाद दोनों फ़ौजें अपनी-अपनी जगह पर डट गईं और खन्दक खोदकर नये किस्म की लड़ाई (Trench warfare) शुरू हुई। एक किस्म की ज़िच-सी होगई थी। यह खन्दकी लड़ाई पश्चिमी मोर्चे पर तीन वर्ष से ज्यादा तक और क़रीब-क़रीब लड़ाई के ख़तम होने तक जारी रही। बड़ी-बड़ी फ़ौजें छछूँदर की तरह ज़मीन में बिल बनाकर रहती थीं और एक-दूसरे को बेदम करने की कोशिश करती थीं। जर्मन और फ्रांसीसी सेनायें इस मोर्चे पर शुरू से ही लाखों की तादाद में रहीं,—और अंग्रेज़ों की भी छोटी-मोटी फ़ौज इस मोर्चे पर तेज़ी से तादाद में बढ़ती गई—यहाँ तक कि इसकी भी तादाद लाखों तक पहुँच गई।

पूर्व के या रूसी मोर्चे पर इससे ज्यादा हलचल रही। रूसी फ़ौजें आस्ट्रियन लोगों की दार-दार शिकस्त देती थीं, लेकिन जर्मनों से हमेशा हार जाया करती थी। इस मोर्चे पर मरने और ज़ख्मी होनेवालों की तादाद बहुत ही ज्यादा थी। यह न समझना कि पश्चिमी मोर्चे पर इस खन्दकी लड़ाई की वजह से कम आदमी पाक आये। आदमियों की डिन्दगी के साथ आदमियों का लारवाही से खेल खेला

१. अब इसकी मूर्त हो चुकी है।

जाता था और दुश्मन के मजबूत मोर्चे पर हमला करने के लिए लाखों आदमी मौत के मुँह में जानबूझकर ढकेल दिये जाते थे और इसका कोई नतीजा नहीं निकलता था।

युद्ध के दूसरे अनेक रंगमंच भी थे। तुर्कों ने स्वेज की नहर पर हमला करना चाहा, लेकिन पीछे हटा दिये गये। मिस्र, जैसा मैंने तुम्हें पहले बताया है, १९१४ के दिसम्बर में ब्रिटिश संरक्षकता में ले लिया गया था। फ़ौरन ही ब्रिटेन ने वहाँ की नई व्यवस्थापक सभा को स्थगित कर दिया और जिन लोगों पर शक था उन्हें जेलखाने में भर दिया। राष्ट्रीय अलखवार दवा दिये गये और पाँच आदमी से ज्यादा एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते थे। मिस्र की 'सेंसर प्रणाली' को लन्दन के टाइम्स ने 'बर्बर कठोरता से भरी हुई' बताया था। इस देश में सारी लड़ाई भर फ़ौजी क़ानून जारी रहा।

ब्रिटेन ने तुर्की के जीर्ण-शीर्ण साम्राज्य के कई कमजोर हिस्सों पर हमला किया। पहले इराक़ पर और फिर फिलस्तीन और सीरिया पर। अरबस्तान में अंग्रेज़ों ने अरबों की राष्ट्रीय भावना से फ़ायदा उठाया और धन और सामग्री की गहरी रिश्वत की मदद से तुर्की के ख़िलाफ़ अरबों में बगावत पैदा कर दी। इस बगावत की ज़िम्मेदारी ख़ासतौर से अरबस्तान में अंग्रेज़ों के एक प्रतिनिधि कर्नल टी० ई० लारेंस की थी। उस वक़्त से इसके बारे में यह मशहूर होगया है कि यह एक रहस्य-पूर्ण यानी भेदों से भरा हुआ व्यक्ति है और एशिया के कितने ही आन्दोलनों के पीछे इसकी साज़िश है।

लेकिन तुर्की के मर्मस्थल पर सीधा हमला १९१५ की फरवरी में शुरू हुआ, जबकि ब्रिटिश जल-सेना ने दर्रे दानियाल में घुसकर कुस्तुनतुनिया पर क़ब्ज़ा करना चाहा। अगर इस बात में ये लोग कामयाब होगये होते, तो इन्होंने लड़ाई में तुर्की का ख़ात्मा ही नहीं कर दिया होता बल्कि पश्चिमी एशिया से जर्मन लोगों का असर भी ख़त्म कर देते। लेकिन ये नाकामयाब रहे। तुर्की ने वहादुरी से लड़ाई की और एक दिलचस्पी की क़ाबिले शौर बात यह है कि इस लड़ाई में सुस्तफ़ा क़माल-पाशा का बहुत बड़ा हाथ रहा। करीब सालभर तक अंग्रेज़ों ने गैलीपोली में यह कोशिश जारी रखी। बाद को बहुत नुक़सान उठाकर ये वहाँ से हट गये।

पश्चिमी और पूर्वी अफ़्रीका के जर्मन-उपनिवेशों पर भी मित्र-पक्ष ने हमला किया। ये उपनिवेश जर्मनी से बिल्कुल अलग थे और इनको कोई मदद नहीं मिल सकती थी। धीरे-धीरे ये पस्त होगये। चीन में क़ियानचान के प्रदेश पर, जिसे जर्मनी ने चीन से हड़प लिया था, जापान ने आसानी से क़ब्ज़ा कर लिया। जापान के सामने कोई रुकावट नहीं थी और सुदूर-पूर्व में कुछ लड़ाई का साज़-बाज़ भी नहीं था। इस-

लिए उसने चीन को डरा-धमका कर तरह-तरह की फायदेमन्द रिआयतों और अधिकारों को हासिल करने में अपना वक्त लगाया।

इटली ने कई महीने तक लड़ाई की गति देखी और यह समझने की कोशिश की कि कौन पक्ष जीतेगा। अखीर में उसने यह निश्चय किया कि जीतने की ज्यादा सम्भावना मित्र पक्ष की है। इसलिए उसने मित्र पक्ष की रिश्वतों को मंजूर कर लिया और एक गुप्त समझौता हो गया। मई १९१५ में इटली वाक्कायदा लड़ाई में, मित्र-पक्ष में, शामिल हो गया। दो वर्ष तक इटैलियन और आस्ट्रियन एक दूसरे के सामने डंटे रहे और कोई नतीजा न निकला। इसके बाद जर्मन लोग आस्ट्रियनों की मदद के लिए आ गये और इटैलियन इनके सामने पस्त हो गये। जर्मन और आस्ट्रियन मिलकर करोड़-करोड़ वेनिस तक पहुँच गये।

अक्टूबर १९१५ में बल्गेरिया जर्मनी से मिल गया। इसीके बाद ही आस्ट्रिया और जर्मनी की संयुक्त सेना ने बल्गेरिया की मदद से सर्बिया को बिल्कुल पस्त कर दिया। सर्बिया का राजा अपनी बची-खुची फ़ौज लेकर अपने देश से भागकर मित्र-पक्ष के जहाजों में जा छिपा और सर्बिया जर्मनों के कब्जे में आ गया।

रुमानिया ने बालकन की लड़ाई में जो ख़त इस्तिथार किया था उससे उसकी यह ख़ास शोहरत हो गई थी कि वह हमेशा मौक़े से फ़ायदा उठाने के घात में रहता है। दो वर्ष तक उसने महायुद्ध की गति देखी और आखिरकार अगस्त १९१६ में, यह मित्र-दल की तरफ़ आ गया। इसे बहुत जल्द ही इस काम की सजा मिल गई। जर्मन फ़ौज इसके ऊपर टूट पड़ी और इसकी दबोच लिया। रुमानिया भी आस्ट्रिया और जर्मनी की मातहतता में आ गया।

इस तरह जर्मनी और आस्ट्रिया ने, जिन्हें मध्य यूरोपियन ताक़तों के नाम से पुकारा जा रहा था, बेलजियम पर, उत्तर पूर्व में फ़्रांस के एक हिस्से पर, पोलैण्ड, सर्बिया और रुमानिया पर क़ब्ज़ा कर लिया। युद्ध के अनेक रंगमंचों पर भी इनकी विजय हुई थी। लेकिन लड़ाई का केन्द्र पश्चिमी मोर्चे और समुद्र पर था, और इन जगहों पर इनकी स्थिति में कोई प्रगति नहीं हो रही थी। इस मोर्चे पर प्रतिद्वन्द्वी फ़ौजें मृत्यु की गोद में खेल रही थीं यानी मरने-मारने के लिए गुथी पड़ी थीं। समुद्र पर मित्र-पक्ष हावी था। लड़ाई की शुरुआत में कुछ जर्मन क्रूज़र इधर-उधर फिरे थे और इन्होंने मित्र-पक्ष के जहाजों की आमद-रफ़्त में दख़ल भी दिया था। इनमें से एक समुद्र 'एमडन' भी था जिसने मदरान पर भी गोले बरसाये थे, लेकिन यह एक लोटी-नी दात थी। मित्रपक्ष समुद्री ताक़तों पर हावी था, और इस घटना की वजह से उनकी इस स्थिति में कोई फ़र्क़ नहीं आया। समुद्र पर क़ब्ज़ा रखने की वजह से

मित्रपक्ष ने इस बात की कोशिश की कि मध्य-यूरोपीय शक्तियों को यानी जर्मन, आस्ट्रिया वगैरा को बाहरी दुनिया से खाने-पीने की सामग्री या दूसरी चीजें बिल्कुल न मिलें। इस रोक-थाम की वजह से जर्मनी और आस्ट्रिया के ऊपर बड़ा भयंकर संकट आ पड़ा क्योंकि भोजन के पदार्थ मुश्किल से मिलने लगे और सारी आबादी भूखों मरने लगी।

इसके जवाब में जर्मनों ने पनडुब्बियों (सबनेरीनों) के जरिये से मित्रपक्ष के जहाजों को डुबोना शुरू किया। यह पनडुब्बी की लड़ाई इतनी कामयाब रही कि इंग्लैंड में भी भोजन की चीजें बहुत कम पहुँचने लगीं और अकाल पड़ने का खतरा हो गया। १९१५ के मई के महीने में एक जर्मन-पनडुब्बी ने लुसीटानिया नाम के एक एटलान्टिक महासागर में चलने वाले विशाल अंग्रेजी जहाज को डुबा दिया। बहुत से आदमी इसीमें डूब गये। बहुत से अमेरिकन भी इसमें डूबे और इसकी वजह से अमेरिका में बहुत नाराजी और गुस्सा पैदा हो गया।

जर्मनी ने इंग्लैंड के ऊपर हवाई जहाज से भी हमला किया। चांदनी रात में बड़े-बड़े जेपलिन हवाई जहाज लन्दन के ऊपर और उन जगहों पर, जहां गोले-बारूद बनते थे, बम फेंकने आते थे। इसके बाद सामान्य हवाई जहाजों ने बम फेंकना शुरू किया। हवाई जहाज की भनाहट का सुना जाना, हवाई जहाजों पर गोला मारने वाली तोपों का दगना और लोगों का तहखानों में अपने बचाव के लिए भागकर घुसना लन्दन के लिए मामूली बात हो गई। शहरी (Civil) जनता पर इस तरह गोला बरसाने के कारण अंग्रेजों में बहुत रोष पैदा हुआ और उनका यह रोष सही था, क्योंकि इस क्रिस्म की गोलावारी बड़ी भयंकर चीज होती है। लेकिन जब अंग्रेजी हवाई जहाज हिन्दुस्तान के उत्तर-पश्चिम की सरहद पर या इराक में बम फेंकते हैं या उस शैतानी ईजाद को, जिसे देर से फूटने वाला बम कहते हैं, गिराते हैं, तो ब्रिटेन में जरा भी रोष पैदा नहीं होता। इसे ये लोग पुलिस का काम कहते हैं और शान्ति के जमाने में भी अकसर इसका प्रयोग करते रहते हैं।

इस तरह महीने-पर-महीने बीतते गये और लड़ाई चलती रही, और जिस तरह से जंगल की आग टिड्डियों को भस्म करती है उसी तरह यह मनुष्यों का भस्म करती रही, और ज्यों-ज्यों दिन बीतते गये यह अधिक विनाशकारी और बर्बर होती गई। जर्मन लोगों ने जहरीली गैस से लड़ना शुरू किया और बहुत जल्द दोनों तरफ से जहरीली गैस इस्तेमाल होने लगी। बम फेंकने के लिए हवाई जहाजों का ज्यादा-से-ज्यादा इस्तेमाल होने लगा। और इसके बाद पहले-पहल अंग्रेजों ने 'टैंक' का इस्तेमाल १. टैंक—लोहे की चादरों से ढकी, सब फौजी सामान से भरी मोटरगाड़ी जिसमें

शुरू किया। टैंक बहुत बड़ी भयंकर मशीन होती है जो हर एक चीज पर रेंग सकती है। मोर्चों पर लाखों आदमी काम आये, और इनके पीछे देश के अन्दर औरतें और बच्चे भूख और दरिद्रता की यातना में पिस गये। जर्मनी और आस्ट्रिया में खास तौर से, नाकेबन्दी की वजह से, लोग घुरी तरह भूखों मरने लगे। सहनशीलता की परीक्षा शुरू होगई। इस मुसीबतों की परीक्षा में कौन पक्ष ज्यादा दिन तक क्रायम रह सकेगा, यही सवाल सामने आ गया। कौन सेना दूसरे को पहले थका देती है, क्या मित्र-पक्ष की नाकेबन्दी की वजह से जर्मन लोगों की हिम्मत टूट जायगी, क्या जर्मन पतङ्गुद्वियों की कारगुजारियों से इंग्लैण्ड भूखों मरने लगेगा और उसका साहस और जीवत खतम हो जायगा? हरेक देश में मुसीबत और बलिदान के बड़े-बड़े उदाहरण दिखाई पड़े। लोग सोचने लगे कि क्या यह सारा भयंकर त्याग और कष्ट फिजूल जायगा? क्या हम उन लोगों के बलिदान को भूल जायें जो मर गये और दुश्मन के सामने सर झुका दें? युद्ध के पहले के दिन बहुत दूर मालूम होने लगे; लड़ाई के कारण भी लोग भूल गये, सिर्फ एक चीज पुरुषों और स्त्रियों के दिमाग में रह गई थी—विजय और बदला लेने की इच्छा।

प्रसिद्ध फ्रेंच कवि एदमाँ रोस्तॉ ने लिखा था :—

Je ne veux que voir la victoire,
Ne me demandez pas : "Après."
Après, je veux bien la nuit noire
Et le sommeil sous les cyprès.

अर्थात् "मैं सिर्फ विजय देखना चाहता हूँ। उसके बाद क्या होगा, यह मुझसे न पूछो। बाद में मैं अंधेरी काली रातें और सरो के वृक्षों के नीचे सोना पसंद करूँगा।"

इस कवि की आशा ज्यों-की-त्यों पूरी हुई। विजय के तीन हफ्ते के अन्दर वह मर गया।

जो लोग किसी सिद्धान्त के लिए शहीद हो चुके हैं उनका आह्वान बड़ा भयंकर होता है। जिसके दिल में जरा-सा भी जोरा है इस आह्वान के सामने कैसे रुक सकता है? लड़ाई के इन आखिरी सालों में हर जगह अन्धकार का राज्य था। लड़ाई में शामिल देशों में हरेक घर रंज और अफ़सोस में डूबा हुआ था। लोग थके हुए थे; उनकी आंखें खुल नहीं थीं; लेकिन वे कर दग मरते थे, निश्चय इसके कि झंझ झंझा मरने। एक निर्दोष अज्ञानर मेजर मैकी की वनई हुई इस प्रभावशाली कविता को पढ़ो पर सोची समझी होती है जिसके कारण यह जैसी नीची जगहों पर भी चल सकती है।

और इसकी कल्पना करो कि लड़ाई के उस अन्धकारमय और संकटपूर्ण जमाने में उसकी क्रोम के पुरुष और स्त्रियों के दिल पर, जिन्होंने इसे पढ़ा होगा, क्या असर पड़ा होगा। याद रखो कि इसी क्रिस्म की कवितायें कई भाषाओं और अनेक मुल्कों में लिखी गई थीं—

We are Dead. Short days ago
We lived, felt down, saw sunset glow,
Loved and were loved, and now we lie
In Flanders Fields.

यानी—

“(आज) हम मुर्दा हैं। पर चन्द दिन पहले हम जीवित थे; उपा का अनुभव करते थे और सूर्यास्त की चमक को देखते थे। प्यार करते थे और प्यार किये जाते थे। और आज हम फ्लैण्डर्स की युद्धभूमि पर पड़े हुए हैं। आज हम मुर्दा हैं।”

Take up our quarrel with the foe :
To you from failing hands we throw
The Torch; be yours to hold it high.
If you break faith with us who die
We shall not sleep though Poppies grow
In Flanders Fields

“दुश्मन के साथ चलनेवाले हमारे इस युद्ध को अब तुम ग्रहण करो। हम अपने इन बेकाम हाथों से यह मशाल तुम्हें सौंपते हैं। अब इसे ऊँचा और प्रज्वलित रखना तुम्हारा काम है। यदि तुमने हम मरने वालों के साथ विश्वासघात किया तो हम कभी सोयेंगे नहीं। (हमारी आत्मा को शान्ति न मिलेगी) चाहे फ्लैण्डर्स के मैदानों में पपी के पीधे भले ही उग आवें।”

१९१६ के अन्त में मित्र-पक्ष कुछ मजबूत होता दिखाई दिया। इनके नये टैंकों ने पश्चिमी मोर्चे पर उन्हें कुछ मजबूती दी थी। जेपलिन हवाई जहाज, जो इंग्लैण्ड पर हमला करते थे टूटने लगे। जर्मन-पनडुब्बियों के होते हुए भी तटस्थ देशों के जहाजों पर काफ़ी खाने का सामान इंग्लैण्ड पहुँच जाता था। सन् १९१६ की मई में उत्तरी समुद्र में एक जहाजी युद्ध हुआ था। इसे जेटलैण्ड की लड़ाई कहते हैं। इस लड़ाई में कुल मिलाकर अंग्रेजों को कामयाबी मिली। इधर जर्मनी की नाकेबन्दी से आस्ट्रिया और जर्मनी के लोग भूखों मरने लगे थे। ऐसा जान पड़ता था कि समय ही मध्य यूरोपीय शक्तियों के ख़िलाफ़ है और फ़ुर्ती से कुछ कर दिखाने की जरूरत मालूम हुई। जर्मनी ने समझौते के लिए भी कुछ इशारा किया था, लेकिन मित्र-पक्ष इसके लिए बिल्कुल तैयार न हुआ। मित्रपक्ष की सरकारें अपनी गुप्त संधियों से अनेक देशों के बँटवारे के लिए बंधी हुई थीं और जब तक पूरी विजय न होजाती, संतुष्ट नहीं हो सकती थीं।

अमेरिका के राष्ट्रपति उडरो विल्सन ने सुलह कराने की कोशिश की थी, लेकिन वह नाकामयाब रहे ।

इस पर जर्मन-नेताओं ने यह निश्चय किया कि अपनी पनडुब्बी का युद्ध तेजी से चलावें और इस तरह से इंग्लैंड को भूखों मार कर उसको नीचा दिखा दें । इस खयाल से इन लोगों ने १९१७ की जनवरी में इस बात का ऐलान किया कि चन्द सपुद्रों में वे तटस्थ जहाज भी डुबा देंगे । यह इसलिए किया गया था कि तटस्थ लोग इंग्लैंड में खाने-पीने का सामान न पहुँचावें । इस ऐलान से अमेरिका बहुत नाराज हुआ । वह इस बात को बरदाश्त नहीं कर सकता था कि उसके जहाज इस तरह डुबो दिये जायें । इसलिए लड़ाई में शामिल हो जाना उसके लिए अनिवार्य होगया । जर्मन-सरकार ने जब हरेक जहाज को पनडुब्बी से डुबाने का अपना निश्चय किया होगा, तब यह बात उसे जरूर मालूम रही होगी । शायद उसका यह खयाल रहा हो कि अब कोई दूसरा चारा नहीं और इस खतरे को उठाना ही पड़ेगा, या उसने यह सोचा हो कि मित्र पक्ष को अमेरिकन पूंजीपति काफी धन दे ही रहे हैं । बहरहाल १९१७ की अप्रैल में अमेरिका ने लड़ाई की घोषणा कर दी और इसके मैदान में आजाने से जर्मनों की हार निश्चित होगई । अमेरिका के पास विस्तृत वसीले थे और जब दूसरी क्रोम थक चुकी थीं इससे एक नई स्थिति पैदा होगई ।

अमेरिका के युद्ध में शामिल होने के पहले एक दूसरी महत्वपूर्ण घटना हो चुकी थी । १५ मार्च १९१७ को रूस की पहली क्रान्ति के कारण जार को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी थी । मैं तुम्हें इस क्रान्ति के बारे में अलग लिखूंगा । मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि इस क्रान्ति की वजह से युद्ध में बड़ा फ़रक पड़ गया । रूस जर्मन शक्तियों के खिलाफ़ बिल्कुल नहीं लड़ सकता था और इसका मतलब यह होगया कि जर्मनी में पूर्वी मोर्चे पर लड़ने की चिन्ता जाती रही । वह अपनी पूर्वी फ़ौजों का ज्यादातर हिस्सा अब पश्चिमी मोर्चे पर भेज सकता था और उन्हें अंग्रेज और फ़्रांसीसियों के खिलाफ़ लड़ सकता था । एक दम से स्थिति जर्मनी के लिए बहुत अनुकूल होगई । अगर उसे रूस की क्रान्ति की खबर उसके होने के छः-सात हफ़्ते पहले मालूम होगई होती तो कितना फ़रक पड़ गया होता ! शायद तब पनडुब्बियों की लड़ाइयों को वह तेज न करता और अमेरिका तटस्थ रहता । रूस के युद्ध-क्षेत्र से बाहर रहने पर और अमेरिका के तटस्थ होते हुए यह बहुत मुमकिन था कि जर्मनी अंग्रेजी और फ़्रांसीसी नेताओं को कुचल डालता । फिर भी जर्मनों की ताकत पश्चिमी मोर्चे में दृढ़ गई और जर्मन पनडुब्बियों ने मित्रपक्ष और तटस्थ देश के जहाजों को ज्यादा नादाद में नष्ट कर डाला ।

रूस की क्रान्ति ने जर्मनी को मदद मिल रही थी, फिर भी जर्मनी में अन्दरूनी

कमजोरी पैदा करने का यह सबसे बड़ा कारण हुआ। पहली क्रान्ति के आठ महीने भी नहीं हुए थे कि दूसरी क्रान्ति हो गई और अधिकार सोवियट और बोलशेविकों के हाथ में आ गया, जिनकी पुकार सुलह की थी। इन लोगों ने सारी लड़नेवाली क्रीमों के सैनिकों और मजदूरों से शान्ति के लिए अपील की और यह बताया कि यह लड़ाई पूँजीपतियों की लड़ाई है, और मजदूरों को इस बात की इजाजत न देनी चाहिए कि वह साम्राज्यवादियों के उद्देशों की पूर्ति के लिए अपने को नष्ट करावें। यह आवाज और यह अपील मोर्चे पर दूसरी क्रीमों के सिपाहियों तक भी पहुँची और इसका बहुत काफ़ी असर हुआ। फ्रांसीसी सेना में कई बलबे हो गये, जिन्हें अधिकारियों ने दबा दिया। जर्मन सिपाहियों पर इससे भी ज्यादा असर हुआ था क्योंकि बहुत-सी जर्मन पलटनों ने क्रान्ति के बाद रूसियों से दोस्ती करली थी। जब ये पलटने पश्चिमी मोर्चे को तब्दील की गई, तब इस नये संदेश को वे अपने साथ ले गई और इसे दूसरी पलटनों में फैलाया। जर्मनी लड़ाई से थका हुआ था और बिल्कुल निरुत्साह हो रहा था। रूस से आये हुए ये बीज ऐसी जमीन पर गिरे जो इनको लेने के लिए तैयार थी। इस तरीके से रूसी क्रान्ति ने जर्मनी को अन्दरूनी तरीके पर कमजोर कर दिया।

लेकिन जर्मनी के फौजी अफसरों ने इन चेतावनियों की तरफ से अपनी आँखें बिल्कुल बन्द करली थीं। इन्होंने सोवियट रूस से सुलह तो की लेकिन उसको दबाकर उसे जर्मनी के साथ एक अपमानजनक समझौता करने को मजबूर किया। सोवियट रूस ने इस समय यही मंजूर कर लिया, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं था और वह हर हालत में सुलह चाहता था। मार्च १९१८ में जर्मन फ़ौज ने पश्चिमी मोर्चे पर अपना आखिरी विशाल प्रयत्न आरम्भ किया। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मोर्चों को तोड़ दिया, अनेक सेनाओं को नष्ट कर डाला और फिर मार्न (Marne) नदी तक पहुँच गई जहाँ से वह ३६ बरस पहले पीछे हटा दी गई थी। यह बड़ा भगीरथ प्रयत्न था लेकिन यह आखिरी प्रयत्न था। इसके बाद जर्मनी परास्त होगया। इसी दरमियान अटलांटिक पार करके अमेरिका की फौजें आ गई और अपने कटु अनुभव के आधार पर पश्चिमी मोर्चे की सारी मित्रपक्ष की सेनायें अंग्रेज, फ्रांसीसी और अमेरिकन एक मुख्य सेनापति की मातहत में कर दी गई ताकि पूरा-पूरा सहयोग हो सके और संगठित तौर पर प्रयत्न किये जा सकें। फ्रेंच मार्शल फ़ोक (Foch) पश्चिम में मित्र-पक्ष की सारी सेनाओं का मुख्य सेनापति बना दिया गया। १९१८ के बीच तक हवा निश्चित तौर से बदल चुकी थी। मित्र-पक्ष के हाथ में ताकत पहुँच चुकी थी और ये लोग बढ़ते गये और जर्मनों को पीछे हटाते गये। अक्टूबर के खतम होने तक लड़ाई का ख़ात्मा हो चुका था और युद्ध बन्द करने की बातचीत होने लगी थी।

४ नवम्बर को कील में जर्मन जल-सेना में ग़दर हो गया। इसके ५ दिन के बाद वालिन में जर्मन-प्रजातन्त्र की घोषणा कर दी गई। उसी दिन यानी ४ नवम्बर को कैसर विलियम द्वितीय ने बड़ी बेइज्जती के साथ और भोंडे तरीके से जर्मनी से निकलकर हालैंड के लिए प्रस्थान किया और उसीके साथ होएनजोलर्न राजवंश भी ख़तम हो गया। चीन के मंचुओं के समान “ये शेर की तरह गरजते हुए दाख़िल हुए थे, लेकिन साँप की पूँछ की तरह शायब होगये।”

११ नवम्बर १९१८ को लड़ाई बन्द हुई। जो सुलह हुई वह अमेरिका के राष्ट्र-पति विलसन की १४ शर्तों (Fourteen Points) पर निर्भर थी। ये १४ शर्तें बहुत हद तक इन सिद्धान्तों पर निर्भर थीं कि छोटे राष्ट्रों को आत्मनिर्णय का अधिकार दिया जाय; निःशस्त्रीकरण हो; कोई गुप्त समझौता न किया जाय; सारी शक्तियाँ रूस को मदद दें और राष्ट्र-संघ बनाया जाय। आगे चलकर हम देखेंगे कि विजेताओं ने कितनी आसानी से इन १४ बातों को भुला दिया।

लड़ाई ख़तम होगई, लेकिन इंग्लैंड की जल-सेना ने जर्मनी की नाकेबन्दी जारी रखी। भूख से तड़पते हुए जर्मनी की स्त्रियों और बच्चों को खाना पहुँचाने की इजाजत नहीं थी। छोटे-छोटे बच्चों के प्रति भी इस आश्चर्यजनक घृणा और प्रतिहिंसा की भावना को मशहूर ब्रिटिश राजनीतिज्ञ, देश सेवक, बड़े-बड़े अख़बार और अपने को उदार दल का समाचारपत्र कहने वाले भी प्रोत्साहन देते थे। उस समय इंग्लैंड के प्रधान सचिव लायड जार्ज उदार दल के थे। लड़ाई का सवा चार वर्ष का इतिहास निर्दयतापूर्ण अत्याचारों से भरा पड़ा है। और फिर भी सुलह के बाद जर्मनी की इस नाकेबन्दी का जारी रखना अपनी शुद्ध निर्दयता में बेमिसाल है। लड़ाई ख़तम हो चुकी थी और सारा मुल्क भूखों मर रहा था। छोटे-छोटे बच्चे भूख से तड़प रहे थे और जान-बूझकर और जबरदस्ती इनको खाने का सामान नहीं पहुँचने दिया जाता था। लड़ाई की वजह से हमारे दिमाग़ किस तरह ख़राब जाते हैं और हमने पागलपन से भरी हुई घृणा किस हद तक सभा जाती है! जर्मनी के पुराने चान्सलर बेस्मैन हॉलदेग ने कहा था—“हमारी सन्तान और हमारी सन्तानों की सन्तान इंग्लैंड की नाकेबन्दी को बाद रखेगी, जिसे इंग्लैंड ने जबरदस्ती हमारे खिलाफ़ जारी कर रखा है और जो बेरहमी में पंजाबिक करी जा सकती है।”

बड़े-बड़े राजनीतिज्ञ और डॉक्टो-डॉक्टो ओहों के आदमी इन नाकेबन्दी को पगन्द मानते थे। लेकिन बेचारा अंग्रेज़ सैनिक, जो अमल में लड़ा था, इस दृश्य को नहीं देख सकता था। राइनलैंड के कोलोन में गसशक्ति के बाद एक अंग्रेज़ी सेना रख दी गई थी, इस सेना के सेनापति ने प्रधान सचिव लायड जार्ज के पास तार भेजा और उनसे

बताया कि "जर्मन स्त्री और बच्चों की तकलीफों को देखकर ब्रिटिश फ़ौज पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है।" लड़ाई बन्द होने के ७ महीने बाद तक इंग्लैण्ड ने जर्मनी की नाकेबन्दी कायम रखी।

कई वर्षों तक लड़ते रहने की वजह से लड़ने वाली क्रोमै जानवर हो गई थीं। बहुत से लोगों के हृदय से सद्भावना खतम हो चुकी थी, और साधारण आदमी आधे बदमाश होगये थे। उद्दण्डता और घटनाओं को जानबूझ कर तोड़-मरोड़ कर बयान करना लोगों के लिए मामूली बात थी और इनका दिल प्रतिहिंसा और घृणा की भावना से भरा हुआ था।

लड़ाई का तलपट क्या था, कोई अभी तक इसे नहीं जानता। हिसाब लगाया जा रहा है। मैं तुम्हें कुछ आँकड़े बताता हूँ जिससे तुम्हें यह मालूम होगा कि आजकल युद्ध का क्या मतलब होता है।

युद्ध में घायलों और मरे हुएों की पूरी संख्या निम्नलिखित आँकी गई है—

मृत सैनिक (जिनका पता है) १,००,००,०००

सैनिक जिनके बारे में समझा जाता है कि मारे गये... ३०,००,०००

शैर-सैनिक जो मारे गये..... १,३०,००,०००

जख्मी..... २,००,००,०००

कैदी..... ३०,००,०००

लड़ाई के अनाथ..... ९०,००,०००

लड़ाई की विधवायें..... ५०,००,०००

देश छोड़कर भागे हुए..... १,००,००,०००

इन विशाल आँकड़ों को देखो और इस बात की कल्पना करने की कोशिश करो कि इनके पीछे कितनी मानुषी यातना छिपी हुई है। इनको जोड़ डालो। सिर्फ मरे हुए और जख्मियों की तादाद ४ करोड़ और ६० लाख होती है जो कि युक्तप्रान्त की सारी आबादी के बराबर है।

और इस लड़ाई में नरक कितना खर्च हुआ, इसका भी हिसाब लगाया जा रहा है। अमेरिकन तख्तीना यह है कि मित्र-पक्ष का ४० अरब ९९ करोड़ ९६ लाख पौंड और जर्मन-पक्ष का १५ अरब १२ करोड़ २३ लाख पौंड खर्च हुआ। दोनों को जोड़ डालो, कुल खर्च ५६ अरब पौंड हुआ। इन आँकड़ों को हम अच्छी तरह से समझ नहीं सकते, क्योंकि हमारी रोज़ाना की ज़िन्दगी से ये बिलकुल परे मालूम होते हैं। इनसे हमें ज्योतिष के आँकड़े याद आ जाते हैं जब हम सूरज या सितारे का पृथ्वी से फ़ासला जानने की कोशिश करते हैं। कोई ताज्जुब की बात नहीं कि लड़ाई में शामिल पुरानी

कौमें, विजयी और पराजित दोनों बराबर ही, लड़ाई के खर्चों के बुरे असर से अभी तक परेशान हैं।

‘युद्ध खत्म करने के लिए युद्ध’, ‘लोकतन्त्र के लिए दुनिया में रास्ता साफ करने के लिए युद्ध’, ‘आत्म निर्णय का युद्ध’ ‘स्वतन्त्रता’ और ‘उच्च आदर्शों का युद्ध’ खतम होगया था। इंग्लैण्ड, फ़्रांस, अमेरिका, इटली और इनके छोटे-मोटे पिछलग्गू (रूस इनसे अलग था) विजयी हुए थे। इन ऊँचे और महान् आदर्शों को क्रियात्मक रूप में कैसे लाया गया, यह हम बाद को देखेंगे। फिलहाल तो हम अंग्रेज़ कवि साउदे की एक कविता उद्धृत करेंगे जो उसने एक पुरानी और दूसरे मौक़े की विजय के बारे में लिखी थी—

“And everybody praised the Duke
Who this great fight did win”

“But what good came of it at last ?”

Quoth little Peterkin.

“Why; that I can not tell”, said he,

“But ’twas a famous victory.”

यानी “हरेक डचूक की, जिसने इस बड़ी लड़ाई में विजय प्राप्त की थी, तारीफ़ कर रहा था। पर छोटे से पेटरकिन ने पूछा कि ‘आखिर इससे फ़ायदा क्या हुआ ?’ उसने कहा—‘क्यों ? यह तो मैं नहीं बता सकता पर यह एक गौरवपूर्ण विजय थी।’

: १५० :

रूस से ज़ारशाही का खात्मा

७ अप्रैल, १९३३

लड़ाई की गति का बयान करते हुए मैंने रूसी क्रान्ति और युद्ध पर उसके प्रभाव का जिक्र किया था। युद्ध पर उसने जो असर डाला वह तो पड़ा ही परंतु संसार के इतिहास में भी यह क्रान्ति अपने क्रिस्म की एक अनोखी और विशाल घटना हुई है। यद्यपि यह अपने क्रिस्म की पहली क्रान्ति थी, पर मुमकिन है कि बहुत दिनों तक यह अपने क्रिस्म की अकेली क्रान्ति न बनी रहे; क्योंकि यह दूसरे देशों के लिए एक क्रिस्म का चैलेंज या चुनौती बन गई है और सारी दुनिया के बहुतेरे क्रान्तिकारियों के सामने एक नमूना पेश कर गई है। इसलिए इसकी गहरी छानबीन करनी चाहिए। निस्सन्देह महा-युद्ध का यही सबसे बड़ा नतीजा था, हालाँकि जिन राजनीतिज्ञों ने और सरकारों ने दुनिया को लड़ाई में धकेला था, वे इसे ज़रा भी नहीं चाहते थे और उन्हें इसका खयाल

भी नहीं था। या यह कहना शायद ज्यादा सही हो, कि इसका जन्म उस आर्थिक और ऐतिहासिक परिस्थिति से हुआ था जो रूस में पाई जाती थी। युद्ध की वजह से पैदा होनेवाली मुसीबतों और नुकसानों ने परिस्थिति को तेजी के साथ संकटपूर्ण बना दिया और क्रान्ति के महापुरुष और अद्भुत वृद्धिवाले लेनिन ने इसका फायदा उठाया।

१९१७ में रूस में असल में दो क्रान्तियाँ हुई—एक मार्च में और दूसरी नवम्बर में। या इस सारे युग को हम क्रान्ति का निरन्तर प्रवाह कह सकते हैं और ये दो तारीखें ऐसी हैं जबकि प्रवाह ऊँची-से-ऊँची सतह पर पहुँच गया था।

मैंने रूस-सम्बन्धी पिछले खत में १९०५ की क्रान्ति का जिक्र किया है। यह क्रान्ति भी लड़ाई और पराजय के समय पैदा हुई थी। इसे बेरहमी के साथ दवा दिया गया और जार की सरकार ने आजादी के साथ निरंकुशता की अपनी जीवन-यात्रा जारी रखी। सब क्रिस्म के आजाद खयालों को खुफिया पुलिस से पता चलाकर यह सरकार दवा देती थी। मार्क्स के अनुयायी और खासकर बोलशेविक कुचल दिये गये और इनके खास-खास आदमी, और औरतें भी, या तो साइबेरिया के मैदानों में भेज दिये गये या उन्होंने विदेशों में जाकर शरण ली। लेकिन इन लोगों की, जो विदेशों में रहते थे, इस छोटी-सी तादाद ने भी अपना प्रचार जारी रखना और लेनिन के नेतृत्व में अध्ययन करते रहे। ये लोग मार्क्स के उसूलों के कट्टर माननेवालों में थे; लेकिन मार्क्स के उसूल जर्मनी और इंग्लैण्ड जैसे उद्योग-प्रधान देशों को नज़र में रखकर बनाये गये थे। रूस अभी तक मध्यकालीन और कृषिप्रधान देश था। बड़े-बड़े शहरों में मामूली व्यवसाय और उद्योग-धंधे थे। लेनिन ने रूस की परिस्थिति को नज़र में रखकर मार्क्स के मुख्य सिद्धान्तों को नई शकल देनी शुरू की। इस विषय पर उसने बहुत काफ़ी लिखा और रूसी निर्वासितों में खूब बहस-मुवाहिदा होता रहा। इस तरह इन लोगों ने अपने को क्रान्ति के उसूलों में पक्का बना लिया। लेनिन का यह विश्वास था कि अगर कोई काम करना हो तो उसे विशेषज्ञों और उस हुनर के जाननेवालों से कराना चाहिए, केवल उत्साहियों और जोशीले लोगों से काम न चलेगा। अगर क्रान्ति की कोशिश करना है तो, उसकी राय थी कि, इस काम के लिए लोगों को अच्छी तरह तालीम देनी चाहिए, और तैयार करना चाहिए ताकि जब काम का वक्त आये उनके दिमाग साफ़ हों और वे जानते हों कि हमें क्या करना है। इसलिए लेनिन और उसके साथियों ने १९०५ के बाद दमन के भयंकर युग को अगले आन्दोलन के लिए अपने को तैयार करने में लगाया।

१९१४ में रूस में शहरी मजदूरवर्ग जगने लगा था और फिर क्रान्तिकारी हो रहा था। बहुत-सी राजनैतिक हड़तालें हुईं। इसके बाद लड़ाई शुरू होगई और

सब लोगों का ध्यान उसीमें लग गया और सबसे आगे बढ़े हुए कार्यकर्त्ता सिपाही बनाकर मोर्चे पर भेज दिये गये। लेनिन और उसके दल ने (ज्यादातर नेता रूस के बाहर निर्वासित थे) लड़ाई का शुरू से ही विरोध किया। और देशों के साम्यवादियों की तरह ये लोग वहाँ नहीं गये। इन्होंने उसे पूँजीवादियों का युद्ध बताया, जिससे मजदूरों को कोई ताल्लुक नहीं था, सिवा इसके कि मजदूर लोग उससे फ़ायदा उठाकर अपनी आज़ादी पा सकते थे।

समर-भूमि में रूसी फ़ौज को बहुत बड़े-बड़े नुकसान हुए। शायद जितनी फ़ौजें लड़ाई में थीं, उनमें सबसे ज्यादा इसीको नुकसान उठाना पड़ा। आम तौर पर फ़ौजी लोग ज्यादा अक्लमन्द नहीं होते तिसपर रूसी सेनापति तो और भी नालायक थे। रूसी सिपाहियों के पास काफ़ी हथियार नहीं थे; अक्सर उनके पास लड़ाई की सामग्री भी नहीं होती थी, और न लड़ने में उनको पीछे से मदद दी जाती थी। ये लोग दुश्मनों पर दौड़ा दिये जाते थे और लाखों की तादाद में काम आजाते थे। इधर पेट्रोग्रेड में, जिसे पहले सेंटपीटर्सबर्ग कहते थे, और दूसरे बड़े शहरों में बेहद मुनाफ़ा हो रहा था और सट्टे से लोग मालामाल हो रहे थे। ये देशभक्त सट्टेवाले और मुनाफ़ा उठानेवाले इस बात की बहुत जोर से चीख़-पुकार मचाते थे, कि लड़ाई अख़ीर तक लड़ी जाय। अगर लड़ाई स्थायी होजाती तो निस्सन्देह इनके बहुत अनुकूल होता; लेकिन सिपाही और मजदूर और किसान, जिनमें से कि सिपाही भरती होते थे, पस्त हो चुके थे, भूखों मर रहे थे और बहुत असन्तुष्ट थे।

ज़ार निकोलस बहुत बेवकूफ़ आदमी था और अपनी स्त्री ज़ारीना के असर में बहुत ज्यादा रहता था, जो कि उसीकी तरह बेवकूफ़ लेकिन उससे ज्यादा दृढ़ निश्चय की स्त्री थी। इन दोनों ने अपने चारों तरफ़ बेवकूफ़ों और बदमाशों को इकट्ठा कर लिया और किसीही हिम्मत नहीं पड़ती थी कि इनपर आक्षेप करे। मामला इस हद तक पहुँचा कि एक घृणित बदमाश, जिसका नाम ग्रीगोरी रासपुटीन था, ज़ारीना का ख़ास आदमी बन गया और ज़ारीना के खरिये से ज़ार के मुँह लग गया। रासपुटीन (रासपुटीन के मानी हैं 'गन्दा कुत्ता') एक ग़रीब किसान था, जो घोड़े चराने के जुर्म में फँस गया था। उसने निश्चय किया कि साधू का वेप बनाना चाहिए और फ़कीरी के लाभदायक पेशे को इस्तिहार करना चाहिए। हिन्दुस्तान की तरह रूस में भी इस ढंग से बहुत आसानी के साथ रुपया पैदा किया जा सकता था। उसने लम्बे-लम्बे बाल बढ़ा लिये और ज्यों-ज्यों उसके बाल बढ़े, त्यों-त्यों उसकी शोहरत भी बढ़ी—यहाँतक कि वह ज़ार के दरबार तक पहुँची। ज़ार और ज़ारीना का लड़का, जो ज़ारविच कहलाता था, किसी इन्टर हमेशा बीमार रहता था। रासपुटीन ने किसी-

न-किसी ढंग से ज़ारीना को यह विश्वास दिला दिया कि वह लड़के को अच्छा कर देगा। उसकी क्रिस्मत जग गई और वह ज़ार और ज़ारीना पर बहुत जल्द हावी होगया। इसीके इशारे पर ऊँची-से-ऊँची नियुक्तियाँ होती थीं। इसका जीवन अत्यन्त पतित था और यह बड़ी-बड़ी रकमों रिश्वत में लिया करता था; फिर भी यह कई वर्षों तक हावी रहा।

हरेक आदमी रासपुटीन से बेज़ार था। नरम दल और उच्च वर्ग के लोगों ने भी शोर मचाना शुरू किया और इस बात की चर्चा होने लगी कि राजमहल के अन्दर क्रान्ति कर दी जाय, यानी दूसरा ज़ार ज़बरदस्ती गद्दी पर बिठा दिया जाय। इसी दरमियान ज़ार निकोलस ने अपनेको अपनी सेना का मुख्य सेनापति बना लिया था और हरेक चीज़ को चौपट कर रहा था। १९१६ के ख़त्म होने के चन्द दिन पहले ज़ार के फ़ुटुम्व के एक आदमी ने रासपुटीन को मार डाला। उसे खाना खाने के लिए बुलाया गया और उससे कहा गया कि तुम अपने को खुद गोली मार लो। रासपुटीन ने इन्कार किया। इसपर उसे गोली मार दी गई। रासपुटीन के क़त्ल का सब लोगों ने स्वागत किया और समझ लिया कि बला टली; लेकिन ज़ार की ख़ुफ़िया पुलिस ने इस घटना के आधार पर बेहद अत्याचार किये।

संकट बढ़ने लगा। पेट्रोग्रेड में अकाल पड़ गया और खाने के लिए बलबे होने लगे; इसके बाद मार्च के शुरू में मज़दूरों की चिर यातना के बीच से आप ही आप क्रान्ति पैदा हुई, जिसकी कोई आशा न थी। मार्च महीने के ५ दिनों में, यानी ८ से १२ मार्च के बीच में, क्रान्ति की विजय रही। यह कोई राजमहल के अन्दर की बात नहीं थी और न यह कोई संगठित क्रान्ति ही थी, जिसकी चोटी के नेताओं ने बाक्रायदा व्यवस्था की हो। यह क्रान्ति नीचे से उभड़ी थी; बहुत ज्यादा सताये हुए मज़दूरों में से और बिना किसी जाहिरा व्यवस्था या नेतृत्व के अन्धों की तरह रास्ता ढटोलते हुए आगे बढ़ी थी। अनेक क्रान्तिकारी दल, जिनमें स्थानीय बोलशेविक भी थे, हक्का-बक्का रह गये और सोचने लगे कि क्रान्ति को किस रास्ते पर ले जायें? जनता ने खुद ही अपना रास्ता निकाल लिया, और जिस समय इन्होंने पेट्रोग्रेड के सिपाहियों को अपनी तरफ़ कर लिया, विजय इनकी होगई। यह क्रान्तिकारी जनता असंगठित भौड़ नहीं थी जो लूट-मार के लिए उतारू हो, जैसे कि पहले के किसानों के बलबे हुआ करते थे। मार्च की इस क्रान्ति के बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका नेतृत्व कारख़ाने के मज़दूरों ने किया जो कि इतिहास में अपने क्रिस्म की पहली चीज़ है, और इन मज़दूरों में यद्यपि उस समय कोई मशहूर नेता नहीं था, बहुत से ऐसे अप्रसिद्ध कार्यकर्त्ता थे, जिन्हें लेनिन के दल में ट्रेनिंग यानी तालीम मिल चुकी थी। लेनिन और दूसरे लोग या तो जेल में थे या जलावतन थे।

दर्जनों कारख़ानों के इन अज्ञात कार्यकर्ताओं ने सारे आन्दोलन को मजबूती दी और उसे निश्चित मार्ग पर चलाया ।

इस जगह पर हमें औद्योगिक जनता (Industrial masses) काम करती हुई दिखाई देती है । किसी दूसरी जगह यह बात नहीं देखी गई थी । रूस एक बिल्कुल खेतिहर मुल्क था और यहाँ कृषि भी मध्यकालीन ढंग से चलाई जाती थी । इस देश में नये ज़माने के उद्योग-धंधे या कल-कारख़ाने बहुत कम थे और जो थे भी वे चन्द शहरों में केन्द्रित थे । पेट्रोग्रेड में बहुत-से कारख़ाने थे और मिल में काम करने वाले मजदूरों की काफ़ी बड़ी आबादी थी । मार्च की क्रान्ति पेट्रोग्रेड के इन्हीं मजदूरों और इस शहर में रखी हुई पलटन का ही काम था ।

८ मार्च को क्रान्ति की पहली गड़गड़ाहट सुनाई दी । स्त्रियों ने सबसे पहले आगे क़दम बढ़ाया । कपड़े की मिलों की स्त्रियाँ, जो मजदूरी करती थीं, जुलूस बनाकर शहरों में फिरीं । दूसरे दिन हड़ताल बढ़ी । बहुत-से मर्द मजदूरों ने काम छोड़ दिया । रोटी के लिए चीख-पुकार शुरू हुई और "निरंकुशता का नाश हो!" का नारा लगाया जाने लगा । जुलूस के इन मजदूरों को पस्त करने के लिए अफ़सरों ने क़ज़्ज़ाकों की फ़ौज भेजी । यही पुराने ज़माने में ज़ारशाही के ख़ास मददगार रहे थे । क़ज़्ज़ाकों ने जनता को इधर-उधर भगा दिया, लेकिन गोली नहीं चलाई । मजदूरों को यह देखकर बड़ी खुशी हुई कि क़ज़्ज़ाक लोग असल में सरकारी नक्काब के पीछे दोस्ती दिखा रहे हैं । फ़ौरन ही जनता का जोश बढ़ गया और उसने क़ज़्ज़ाकों से दोस्ती करने की कोशिश की । लेकिन पुलिस से घृणा रही और उस पर पत्थर फेंके गये । तीसरे दिन यानी १० मार्च को क़ज़्ज़ाकों के साथ दोस्ती की भावना और भी बढ़ गई और यह अफ़वाह फैल गई कि क़ज़्ज़ाकों ने पुलिस पर गोली चलाई है जोकि जनता को गोलियों से मार रही थी । इसके बाद पुलिस सड़कों पर से हट गई । स्त्री कार्यकर्ताओं ने सैनिकों के पास जाकर उनसे जोरदार अपील की और सिपाहियों की संगीनें आसमान की तरफ़ होगई ।

दूसरे दिन यानी ११ मार्च को रविवार था । मजदूर लोग शहर के बीचों-बीच इकट्ठे हुए । पुलिस ने उनपर छिपी हुई जगहों से गोलियाँ चलाई । कुछ फ़ौजी सिपाहियों ने भी जनता पर गोलियाँ चलाई । जनता उस पलटन के बैरक में गई और इस बात की सख्त शिकायत की । फ़ौज के दिल पर असर पड़ा और वह जनता की रक्षा के लिए अपने नानकमिशनट अफ़सरों की मातहत में बाहर निकल आई । यह पलटन गिर-फ़्तार कर ली गई, लेकिन गिरफ़्तारी बहुत देर से हुई । १२ मार्च को और पलटनों में भी ग़दर हो गया और ये लोग अपनी मशीनगन और राइफलें लेकर बाहर निकल

आये। सड़कों पर खूब गोलियाँ चलीं। यह कहना मुश्किल था कि कौन किसको मार रहा है। इसके बाद क्राजी सिपाहियों और मजदूरों ने कुछ मंत्रियों को पकड़ लिया; बाक़ी तो भाग गये थे। इन लोगों ने पुलिस और खुफ़िया पुलिस के आदमियों को गिरफ़्तार कर लिया था। और जेलों से पुराने राजनैतिक कैदियों को भी छोड़ दिया था।

पेट्रोग्रेड में क्रान्ति की विजय रही। इसके बाद शीघ्र ही मास्को में क्रान्ति हुई। गाँव और से यह हालत और हलचल देख रहे थे। धीरे-धीरे किसानों ने भी नई व्यवस्था मंजूर करली, लेकिन उत्साह के साथ नहीं। इनके सामने सिर्फ़ दो सवाल थे; एक तो इन्हें ज़मीन मिल जाय और दूसरे शान्ति रहे।

ज़ार का क्या हुआ ? इस घटनापूर्ण ज़माने में उसकी क्या हालत थी ? वह पेट्रोग्रेड में नहीं था। वह बहुत दूर एक छोटे-से क़स्बे में रह रहा था, जहाँ से मुख्य सेनापति की हैसियत से वह अपनी सेनाओं को हिदायतें देता रहता था। लेकिन उसका ज़माना ख़तम हो चुका था। पके फल की तरह यह टपक पड़ा और किसीने देखा भी नहीं। यह महान् शक्तिशाली ज़ार, रूस का सबसे बड़ा निरंकुश शासक, जिसके सामने लाखों कांपते थे, पवित्र रूस का पिता, इतिहास की रद्दी की टोकरी में ग़ायब हो गया। कितने ताज़्जुब की बात है कि बड़ी-बड़ी प्रणालियाँ, जब उनका ज़माना ख़तम हो जाता है और वह अपना काम कर चुकती हैं, किस तरह ख़तम हो जाती हैं ! जब ज़ार ने सुना कि मजदूरों ने हड़ताल कर दी है और पेट्रोग्रेड में बलवा हुआ है, तो उसने क्राजी क़ानून की घोषणा कर दी। सेनापति ने यह घोषणा तो बाक्लायदा निकाल दी, लेकिन शहर में इसे फैलाने वाला या इसकी नोटिस चिपकाने वाला कोई न मिला। सरकार की मशीन यानी व्यवस्था टुकड़े-टुकड़े हो गई थी। ज़ार ने इन घटनाओं से आँखें बन्द करके पेट्रोग्रेड आने की कोशिश की। लेकिन रेलवे के मजदूरों ने इसकी ट्रेन रास्ते में रोक ली। ज़ारीना ने, जो उस वक़्त पेट्रोग्रेड के बाहर की बस्ती में रह रही थी, ज़ार के नाम एक तार भेजा। यह तार तारघर से वापस आगया और उसके पीछे यह नोट था—“यह आदमी कहाँ है, इसका पता नहीं।”

मोर्चे पर जो सेनापति थे और पेट्रोग्रेड के नरम दल के नेताओं ने इन घटनाओं से डरकर और इस उम्मीद में कि जो कुछ बचे, बचा लेना चाहिए, ज़ार से गद्दी छोड़ने की प्रार्थना की। ज़ार ने गद्दी छोड़ दी और अपनी जगह के लिए अपने एक रिश्तेदार को नामज़द कर दिया। लेकिन अब आगे कोई ज़ार होने वाला नहीं था, रोमनोफ़ का राजवंश तीन सौ बरस के निरंकुश शासन के बाद रूसी रंग-मंच से हमेशा के लिए प्रस्थान कर गया।

उच्च वर्ग के रईस, ज़मींदार, मध्यमवर्ग के ऊपर के दर्जे के आदमियों, यहाँ तक कि सुधारक और उदार दल के आदमियों ने भी मज़दूरों के इस उभार को बहुत भय से देखा। जब इन्होंने यह देखा कि वह सेना, जिसके ऊपर ये भरोसा करते थे, मज़दूरों से मिल गई तो ये बिल्कुल असहाय हो गये। इनको यह निश्चय नहीं था कि विजय किस पक्ष की होगी, क्योंकि यह मुश्किल था कि ज़ार कोई फ़ौज लेकर लड़ाई के मोर्चे पर वापस आये और विद्रोह को दबा दे। इसलिए एक तरफ़ मज़दूरों का डर, दूसरी तरफ़ ज़ार का और इसके अलावा अपनी बचत करने की फ़िक्र से इन लोगों की दशा बहुत दयनीय और मुसीबत की हो गई थी। डूमा यानी पार्लमेण्ट में ज़मींदारों और उच्च वर्ग के लोगों का बोलबाला था। मज़दूर भी इससे कुछ आशा करते थे, लेकिन इस संकट के मौक़े पर नेतृत्व करने के बजाय या कुछ कार्रवाई करने के बजाय, इसके अध्यक्ष और सदस्य बैठे-बैठे काँपते और डरते रहे और यह निश्चय न कर सके कि क्या किया जाय।

इसी दरमियान सोवियट ने रूप धारण करना शुरू किया। मज़दूरों के प्रतिनिधियों के साथ सैनिकों के प्रतिनिधि भी आ गये, और नई सोवियट ने विशाल टाराइड राज-महल का एक हिस्सा अपने क़ब्ज़े में कर लिया। इस राज महल के एक हिस्से में डूमा भी थी। मज़दूरों और सैनिकों को अपनी विजय पर बहुत उत्साह था। लेकिन सवाल यह उठा कि अब किया क्या जाय ? इन्होंने अधिकार तो हासिल कर लिया, लेकिन, इस अधिकार को चलावे कौन ? यह बात इन लोगों की समझ में नहीं आई थी कि सोवियट यानी इनकी पंथायत खुद ही शासन चला सकती हैं। इस लोगों ने यह बात व्यर्थ ही मानली थी कि मध्यमवर्ग को ही शासन करना चाहिए। इसलिए सोवियट की तरफ से डूमा के पास एक डेपूटेशन यानी प्रतिनिधि मण्डल गया और उससे प्रार्थना की कि आप लोग शासन शुरू कीजिए। डूमा के अध्यक्ष और सदस्यों ने यह समझा कि यह डेपूटेशन उन्हें गिरफ़्तार करने आया है। इनके मन में शासन का भार उठाने की कोई इच्छा नहीं थी, और इस काम में जो ख़तरा था उससे ये डरते भी थे। लेकिन ये लोग करें तो क्या करें ? सोवियट के डेपूटेशन ने आग्रह किया और इन लोगों को इन्कार करते हुए डर नालूम हुआ। इसलिए बहुत बे-दिली से और परिणामों से डरते हुए डूमा की एक कमिटी ने शासन की वागडोर हाथ में लेना मंज़ूर किया। लेकिन बाहरी दुनिया को मालूम होता था कि डूमा ही क्रान्ति का संचालन कर रही है। क़ासी अजीब घोटाले की बात थी ! अगर हम किसी कहानी में ऐसी बात पढ़ें तो मुश्किल से यकीन करेंगे। लेकिन घटनायें कल्पनाओं से अकसर अनोखी होती हैं।

डूमा की कमिटी ने जित्त अस्थायी सरकार की रचना की थी, वह बहुत ही संकीर्ण विचार की थी और उसका प्रधान मन्त्री एक 'प्रिंस' या ऊँचे रईसी खानदान का

व्यक्ति था। इसी मकान के दूसरे हिस्से में सोवियट की सभायें होती थीं और वे अस्थायी सरकार के काम में बराबर दस्तन्दाजी करती रहती थीं, लेकिन सोवियट खुद शुरू में एक नरम संस्था थी और बोलशेविक लोग इसके अन्दर मुट्ठी भर थे। इस तरह से दो सरकारें हो गई थीं, एक अस्थायी सरकार और दूसरी सोवियट। इन दोनों के पीछे क्रान्तिकारी जनता थी, जिसने क्रान्ति करके दिखा दी थी और इस क्रान्ति से बड़ी-बड़ी आशाएँ रखती थी। भूखी और लड़ाई से परेशान जनता को नई सरकार ने सिर्फ़ एक बात बताई कि उसे तब तक लड़ाई जारी रखनी चाहिए जबतक जर्मन लोग हार न जाँय। लोग सोचने लगे कि क्या इसी बात के लिए हमने क्रान्ति की थी और ज़ार को निकाला था ?

इसी अवसर पर, १७ अप्रैल को लेनिन रंगमंच पर आ गया। सारी लड़ाई भर यह स्वीज़रलैण्ड में था और जब उसने क्रान्ति की बात सुनी, तो रूस पहुँचने लिए बड़ा उत्सुक होगया। लेकिन पहुँचता कैसे ? अंग्रेज़ और फ़्रान्सीसी अपने मुल्कों से इसे गुज़रने की इजाज़त नहीं देते थे और न जर्मन और आस्ट्रियन ही। आखिरकार अपने मतलब से जर्मन सरकार इस बात पर राज़ी हो गई कि एक बन्द रेल गाडी में उसे स्वीज़रलैण्ड से रूस तक पहुँचा दे। जर्मन लोगों को यह उम्मीद थी और उम्मीद करने की वजह भी थी कि रूस में लेनिन के पहुँच जाने से अस्थायी सरकार और युद्ध की पार्टों कमज़ोर पड़ जायगी, क्योंकि लेनिन लड़ाई के खिलाफ़ था और जर्मन लोग इस बात से फ़ायदा उठाना चाहते थे। इनको यह कल्पना भी नहीं थी कि यह क्रान्तिकारी, जिसको कोई जानता भी नहीं, योरप और दुनिया को हिला देनेवाला है।

लेनिन के दिमाग में कोई शक-शुबहा नहीं था। इसकी आँखें जनता की मनोवृत्ति को समझने में बहुत कुशल थीं। इसका दिमाग चुलझा हुआ था, और यह बदलती हुई स्थिति में अच्छी तरह से सोचे-समझे हुए सिद्धान्तों का प्रयोग कर सकता था। यह दृढ़ निश्चय का आदमी था, जो अपने बनाये हुए रास्ते पर डटा रहता था और तात्कालिक परिणाम की परवाह नहीं करता था। जिस दिन वह आया, उसी दिन उसने बोलशेविक दल को खूब फटकारा, उनकी अकर्मण्यता पर ऐतराज किया और जोरदार वाक्यों में उनका कर्तव्य बताया। इसका भाषण बिजली की तरह चुभ गया और साथ-ही-साथ इसने जान भी पैदा कर दी। इसने कहा था—“हम लोग दशावाज़ नहीं हैं। हम अपनी बुनियाद जनता की जागृति पर ही क़ायम कर सकते हैं। अगर अल्प संख्या में रहना ज़रूरी होगा तो रहेंगे। कुछ समय के लिए नेतृत्व छोड़ देना अच्छा है। अल्प संख्या में रहने से हमें न डरना चाहिए।” इस तरह यह अपने सिद्धान्तों पर अटल रहा और समझौता करने से इन्कार करता

रहा। जो क्रान्ति अभी तक बिना नेता के, बिना राह दिखानेवाले के, चल रही थी, अन्त में सनाथ हो गई। नेता मिल गया, समय ने आदमी पैदा कर दिया।

सवाल यह है कि वह कौन-सा सिद्धान्त का भेद था, जिसकी वजह से इस अवसर पर बोलशेविक लोग मेनशेविकों और दूसरे क्रान्तिकारी दलों से अलग थे? लेनिन के आने के पहले स्थानीय बोलशेविक लोग किस वजह से अकर्मण्य हो रहे थे और सोवियट ने अधिकार पा जाने के बाद इसे पुरानी और संकीर्ण डूमा को सुपुर्द कर देना क्यों मुनासिब समझा? मैं इन सवालों में बहुत गहरा नहीं जा सकता, लेकिन अगर हम १९१७ के रूस और पेट्रोग्रेड के बराबर तब्दील होनेवाले नाटक को समझना चाहते हैं, तो हमें इन सब बातों पर कुछ गौर जरूर करना होगा।

मनुष्य के परिवर्तन और विकास के बारे में कार्लमार्क्स का सिद्धान्त 'इतिहास की भौतिक या पदार्थवादी व्याख्या' कहलाता है। इसके मुताबिक जब पुरानी सामाजिक प्रणाली अपने समय के परे पहुँच जाती है, इसकी जगह पर नये सामाजिक रूप पैदा होते हैं। चीजों की उत्पत्ति के ढंग ने जैसे-जैसे उन्नति की, समाज का आर्थिक और राजनैतिक संगठन भी धीरे-धीरे उसके अनुकूल बनता गया। यह बात इस तरह से हुई कि शोषित वर्ग में और शोषक या शासक वर्ग के बीच बराबर संघर्ष जारी रहा। इससे पश्चिमी योरोप में पुराना सामन्त वर्ग खत्म हो गया और उसकी जगह पर मध्यम वर्ग आ गया। यही वर्ग आज इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी वगैरह देशों में आर्थिक और राजनैतिक ढाँचे को चलाता है। अब इस वर्ग की जगह पर मजदूर वर्ग आयेगा। रूस में सामन्त वर्ग अभी तक हावी था और जिस परिवर्तन की वजह से पश्चिमी योरोप में मध्यम वर्ग हावी हुआ था, वह परिवर्तन रूस में अभी तक नहीं हुआ था। इसलिए मार्क्स के मानने वाले कितने ही लोग यह सोचते थे कि रूस को लाजमी तौर से पहले मध्यम वर्ग के अधिकार में जाना होगा, पार्लमेण्ट की मंजिल से गुजरना होगा और फिर इसके बाद कहीं मजदूरों की प्रजातंत्र की आखिरी मंजिल मिलेगी। इनका खयाल था कि बीच की मंजिल को कूदकर पार नहीं किया जा सकता। लेनिन खुद १९१७ के मार्च की क्रान्ति से पहले मध्यम मार्ग की नीति का मानने वाला था। उसने यह लिखा था कि अगर ज़ार और जमींदारों के खिलाफ मध्यम मार्ग में क्रान्ति करानी है तो किसानों से सहयोग करना चाहिए और मध्यम वर्ग का विरोध न करना चाहिए।

बोलशेविक, मेनशेविक और मार्क्स के सिद्धान्तों के सभी माननेवालों के दिल में यह खयाल जम गया था कि अंग्रेजी या फ्रांसीसी नमूने का मध्यवर्गीय प्रजा सत्तात्मक लोकतन्त्र स्थापन किया जाय। मजदूरों के मजदूर नुमाइन्दे या प्रतिनिधि भी

इसे अनिवार्य समझते थे और इसीलिए सोवियट ने अधिकार को अपने हाथ में रखने की वजाय डूमा के सपुर्द करना मुनासिब समझा। ये लोग जैसा, हम सब लोगों का अकसर हाल होता है, अपने ही सिद्धान्त के गुलाम होगये थे। इन्हें यह नहीं दिखाई पड़ता था कि एक नई स्थिति पैदा होगई है, जिसमें एक दूसरी नीति पर चलने की जरूरत है। कम-से-कम पुरानी नीति को नये साँचे में ढालना चाहिए। जनता नेताओं से कहीं ज्यादा क्रान्तिकारी थी। मेनशेविक लोग, जिनके हाथ में सोवियट थी, यहाँ तक कहते थे कि मजदूर वर्ग को उस समय किसी क्रिस्म का सामाजिक सवाल उठाना ही नहीं चाहिए। इसका तात्कालिक कर्त्तव्य यह होना चाहिए कि राजनैतिक स्वतंत्रता हासिल कर लें। बोलशेविक लोग अपनी घात में थे। संकोच और फूँक-फूँककर क्रदम रखने की नीति के होते हुए भी मार्च की क्रान्ति सफल रही।

लेनिन के आने पर सारी बातें बदल गईं। उसने फौरन ही स्थिति को समझ लिया। सच्चे नेता की अद्भुत बुद्धि उसमें थी। उसने मार्क्स के कार्यक्रम को स्थिति के अनुसार नया रूप देकर सामने रख दिया। अब यह तय हुआ कि मजदूर वर्ग शरीय किसानों के साथ मिलकर पूँजीवाद के खिलाफ लड़ाई करे। बोलशेविक लोगों ने तुरन्त तीन बातों की पुकार शुरू की :—

(१) प्रजासत्तात्मक लोकतन्त्र (२) रियासतों की जल्ती, और (३) मजदूरों के लिए ८ घण्टे का दिन। फौरन ही इन पुकारों की वजह से किसान और मजदूरों के लिए लड़ाई एक असली चीज बन गई। संघर्ष इनके लिए कोई अनिश्चित या खोखला आदर्श नहीं रह गया, बल्कि आशा और जीवन की एक वास्तविक चीज बन गया।

लेनिन ने बोलशेविक लोगों के लिए यह नीति बनाई कि वे मजदूरों के बहुमत को अपने पक्ष में करें और सोवियट पर अपना कब्जा कर लें। इसके बाद सोवियट अस्थायी सरकार से अधिकार छीन ले। लेनिन की यह राय नहीं थी कि फौरन ही दूसरी क्रान्ति शुरू की जाय। उसका आग्रह यह था कि अस्थायी सरकार को उलटने के पहले मजदूरों के बहुमत को अपनी तरफ मिला लेना चाहिए और सोवियट पर कब्जा कर लेना चाहिए। जो लोग अस्थायी सरकार से समझौता करना चाहते थे, वह उनके बहुत सख्त खिलाफ था। उसके मतानुसार यह बात क्रान्ति के साथ दशा करने की थी। वह उन लोगों के भी सख्त खिलाफ था जो सरकार को ठीक वक्त के पहले तोड़ने के लिए उतावले हो रहे थे। उसका कहना था :—

“A moment of action is no time to aim ‘a wee bit too far to the left.’ We look upon that as the greatest crime, disorganisation.”

अर्थात् “काम करने का वक्त बहुत ज्यादा आगे और दूर की गरम बातों पर

लक्ष्य करने में खोना ठीक नहीं है। इसे हम बहुत बड़ा जुर्म और क्रान्ति की ताकतों को छिन्न-भिन्न कर देना समझते हैं।”

इस तरह शान्तिपूर्वक लेकिन न मिटनेवाली कर्म-रेखा की तरह बर्फ का यह टुकड़ा, जिसके अन्दर धधकती हुई आग छिपी हुई थी, अपने निश्चित ध्येय की तरफ बढ़ने लगा।

: १५१ :

बोलशेविक अधिकार छीन लेते हैं

९ अप्रैल, १९३३

क्रान्ति के जमाने में इतिहास बड़े लम्बे क्रदम बढ़ाकर चलता है। ऊपर-ऊपर तेजी के साथ परिवर्तन होते ही हैं, लेकिन इससे भी बड़ा परिवर्तन जनता के हृदय में पैदा हो जाता है। जनता किताबों से बहुत कम सीखती है, क्योंकि उसको किताबी शिक्षा का ज्यादा मौका नहीं मिलता, और किताबें अकसर छिपाती ज्यादा हैं और बताती कम हैं। जनता का स्कूल अनुभव का, ज्यादा कठोर पर ज्यादा सच्चा, स्कूल होता है। लोगों के हार्दिक अभिप्राय पर जो परदा पड़ा रहता है वह क्रान्ति के युग में, ताकत हासिल करने की जिन्दगी और मौत की लड़ाई के बीच हट जाता है, और तब हमें वह असलियत दिखाई दे जाती है, जिस पर समाज की बुनियाद होती है। इसलिए १९१७ के घटनापूर्ण साल में रूस में जनता ने, और खासकर शहर के कारखानों के मजदूरों ने, जो क्रान्ति के बीच में थे, घटनाओं से सबक सीखा और उनमें रोजाना तब्दीलियाँ होती रहीं।

कहीं कोई स्थिरता या समतोल नहीं था। जीवन स्फूर्ति से भरा था और बदल रहा था। जनता और वर्ग अलग-अलग रास्ते पर और जुदी-जुदी दिशाओं में बढ़ रहे थे और एक दूसरे को घसीट रहे थे। ऐसे भी लोग उस वक्त तक पाये जाते थे जो ज़ार की शासन-प्रणाली को फिर से वापस लाने की उम्मीद करते थे और उसके लिए षड्यंत्र रचते थे। लेकिन इस वर्ग का कोई महत्व नहीं था और हम इसकी उपेक्षा कर सकते हैं। असली लड़ाई अस्थायी सरकार और सोवियट के बीच थी; फिर भी सोवियट में ज्यादातर लोग सरकार के साथ सहयोग और समझौता करने के पक्ष में थे। ये समझौता करनेवाले लोग राजसत्ता और शासन की बागडोर हाथ में लेने से डरते थे। सोवियट में एक शख्स ने कहा था—“सरकार की जगह कौन लेगा। हम ? लेकिन हमारे हाथ तो कंपते हैं……” इसी क्रिस्म की आवाज हमें हिन्दुस्तान में भी ऐसे बहुत-से लोगों के मुँह से सुनाई पड़ती है, जिनके हाथ लूले या

बेकाम हो गये हैं, और जिनके दिल थरा गये हैं। लेकिन जब वक्त आता है तब मजबूत हाथ और पक्के दिल के आदमियों की कमी नहीं रहती।

दोनों तरफ़ के समझौता चाहने वाले लोग बचाने की चाहे जितनी कोशिश क्यों न करते, पर अस्थायी सरकार और सोवियट के बीच संघर्ष का होना लाजिमी था। सरकार लड़ाई जारी रख कर मित्र राष्ट्रों को और जायदाद की हिफ़ाजत करके रूसी उच्च या मालिक वर्ग को खुश रखना चाहती थी। सोवियट जनता के सम्पर्क में ज्यादा थी, इसलिए उसने यह देख लिया था कि जनता शान्ति चाहती है, किसान ज़मीन चाहते हैं और मजदूरों की भी बहुत-सी मांगें हैं—जैसे दिन में काम के आठ घण्टे वगैरा। इस तरह सरकार को सोवियट ने बेकार और पस्त कर दिया था और जनता ने सोवियट को, क्योंकि जनता राजनैतिक दलों और उनके नेताओं से कहीं ज्यादा क्रान्तिकारी थी।

इस बात की कोशिश हुई कि सोवियट के ज्यादा अनुकूल सरकार बनाई जाय और एक उग्र परिवर्तनवादी वकील और ज़र्वदस्त भाषण देने वाला राजनीतिज्ञ करेन्की सरकार का प्रधान सदस्य हो गया। उसने एक समझौते की सरकार बनाई, और इस सरकार के लिए सोवियट के मेशेविक लोगों ने, जिनका बहुमत था, प्रतिनिधि भेजे। इसने इस बात की भी सत्त कोशिश की कि जर्मनी पर हमला करके इंग्लैण्ड और फ़्रांस को खुश रखे। लेकिन इस बात में वह नाकामयाब रहा क्योंकि लोग लड़ाई के लिए तैयार न थे।

इसी दरमियान अखिल रूसी सोवियट काँग्रेस के अधिवेशन पेट्रोग्रेड में हो रहे थे और बाद की हरेक काँग्रेस पहले के अधिवेशनों से ज्यादा उग्र होती जाती थी। बोलशेविक मेम्बर ज्यादा से ज्यादा तादाद में चुन कर आते थे और दो बड़े दल यानी मेनशेविक और सोशल रेवोल्यूशनरी यानी सामाजिक क्रान्तिकारी (किसान पार्टी) का बहुमत अब कम हो गया था। ख़ासतौर पर पेट्रोग्रेड के मजदूरों में बोलशेविक लोगों का असर बहुत बढ़ गया। सारे देश में सोवियट बन गये थे और वे तबतक सरकार का हुकम मानने को तैयार नहीं होते थे, जबतक उसपर सोवियट की भी मंजूरी न हो। अस्थायी सरकार के कमज़ोर होने की एक वजह यह भी थी कि रूस में कोई मजबूत मध्यमवर्ग नहीं था।

इधर राजधानी में अधिकार के लिए खींचतान जारी थी, उधर किसानों ने सारा क़ानून अपने हाथ में ले लिया। जैसा मैंने तुम्हें बताया है, ये किसान मार्च की क्रान्ति से बहुत खुश नहीं थे मगर वे इसके खिलाफ़ भी नहीं थे। वे इन्तज़ार कर रहे थे और स्थिति समझ रहे थे। लेकिन बड़ी-बड़ी रियासतों के जमींदारों ने, इस डर से कि उनकी जायदाद जब्त कर ली जायगी, अपनी रियासत को छोटे-छोटे

टुकड़ों में बांट दिया और दिखलाने के लिए दूसरों के नाम कर दिया, जो अपने नाम से इस जायदाद को उनके लिए बनाये रखते। इन लोगों ने अपनी जायदाद का बहुत-सा हिस्सा विदेशियों के हाथ बेच भी डाला। इस तरह उन्होंने अपनी जायदाद बचानी चाही। किसान इस बात को बिल्कुल पसन्द नहीं करते थे और उन्होंने सरकार के सामने यह मांग पेश की कि जमीन की बिक्री क़ानून से रोक दी जाय। सरकार हिचकचाई; सोचने लगी कि क्या किया जाय? वह किसी पार्टी को नाराज करना नहीं चाहती थी। इस पर किसानों ने खुद कार्रवाई करनी शुरू कर दी। अप्रैल के महीने में कुछ किसानों ने अपने जमींदारों को गिरफ्तार करके रियासतों पर क़ब्ज़ा कर लिया और उन्हें आपस में बांट लिया। वे सैनिक, जो मोर्चे से वापस आये थे (और वे किसान ही थे), इस बात में आगे रहे। यह मामला बढ़ता गया, यहाँ तक कि सारी जमीन पर आम तौर पर जनता का क़ब्ज़ा हो गया। जून के महीने में साइबेरिया के मैदानों में कोई बड़े जमींदार नहीं थे, इसलिए किसानों ने गिरजों और मठों से लगी हुई जमीन पर क़ब्ज़ा कर लिया।

नोट करने लायक बात यह है कि बड़ी-बड़ी रियासतों की यह ज़ब्त किसानों ने खुद अपने मन से की और बोलशेविक क्रान्ति के कई महीने पहले यह बात होगई थी। लेनिन की यह राय थी कि संगठित रूप से जमीन किसानों को तुरन्त दे दी जाय। वह इस बात के पक्ष में नहीं था कि अराजकता के ढंग से, जो किसान, जहाँ चाहे मनमानी जमीन ले ले। इस तरह जब कुछ दिन बाद बोलशेविक लोगों के हाथ में सरकार आई, रूस, मौरूसी और दखिलकार किसानों का देश बन चुका था।

लेनिन के आने के ठीक एक महीने बाद एक दूसरा मशहूर निर्वासित शख्स पेट्रोग्रेड आया। इसका नाम ट्राट्स्की था। यह न्यूयार्क से वापस आया था और इसे रास्ते में अंग्रेजों ने रोक रक्खा था। ट्राट्स्की पुराने बोलशेविकों के गिरोह का नहीं था और न वह अब मेनशेविक ही था, लेकिन वह बहुत जल्द लेनिन की तरफ़ आ गया और पेट्रोग्रेड की सोवियट का एक जोरदार नेता बन गया। यह बड़ा अच्छा वक्ता था, बहुत अच्छा लेखक था और इसमें बिजली की बैटरी की तरह ताकत और स्फूर्ति भरी हुई थी। लेनिन के दिल को इससे बड़ी मदद मिली। इसकी आत्म-कथा से, जो 'माई लाइफ़' (मेरा जीवन) नाम से अंग्रेज़ी छपी है, मैं एक लम्बा उद्धरण इस जगह पर दूँगा। इसमें उसने 'माडर्न सर्कस' नाम के मकान में हुई उन सभाओं का ज़ि़क़्र किया है जिनमें उसने भाषण दिया था। यह उद्धरण उसके सिर्फ़ सुन्दर लेख का नमूना ही नहीं है, बल्कि इससे हमारी आंखों के सामने पेट्रोग्रेड के १९१७ के प्रान्तिबारी दिनों की जीती जागती और स्पष्ट तत्त्वों आ जाती है।

“The air, intense with breathing and waiting, fairly exploded with shouts and with the passionate yells peculiar to the Modern Circus. Above and around me was press of elbows, chests and heads. I spoke from out of a warm cavern of human bodies; whenever I stretched out my hands I would touch some one, and a grateful movement in response would give me to understand that I was not to worry about it, not to break off my speech but to keep on. No speaker, no matter how exhausted, could resist the electric tension of that impassioned human throng. They wanted to know, to understand, to find their way. At times it seemed as if I felt, with my lips, the stern inquisitiveness of this crowd that had become merged into a single whole. Then all arguments and words thought out in advance would break and recede under the imperative pressure of sympathy, and other words, other arguments, utterly unexpected by the orator but needed by these people, would emerge in full array from my sub-consciousness. On such occasions I felt as if I was listening to the speaker from the outside, trying to keep pace with his ideas, afraid that, like a somnambulist, he might fall off the edge of the roof at the sound of my conscious reasoning.”

“Such was the Modern Circus. It had its own contours, fiery, tender and frenzied. The infants were peacefully sucking the breasts from which approving or threatening shouts were coming. The whole crowd was like that, like infants clinging with their dry lips to the nipples of the revolution. But this infant matured quickly.”

यानी, “इस सभा का वातावरण लोगों के इन्तजार और साँस लेने की वजह से बहुत गरम था, लेकिन जोशीले नारों से और जयध्वनि से, जो मार्टन सर्कस की एक खासियत थी, यह वातावरण अशान्त हो जाता था। मेरे ऊपर और मेरे चारों तरफ़ घुटनों, सीनों और सरों का जमघट था, और मैं उनसे दबता जाता था। मैं मनुष्य-शरीरों की बनी हुई गुफा की गर्मी से बोल रहा था। जब जब मैं अपने हाथ फैलाता था, कोई-न-कोई छू जाता था। इसके जवाब में उधर से जो हरकत होती थी वह इस बात के लिए मुझे विश्वास दिलाती थी कि मुझे अपना भाषण जारी रखना चाहिए और इसके लिए व्याख्यान को रोकने की कोई जरूरत नहीं। कोई व्याख्यान देने वाला, चाहे वह कितना ही थक क्यों न गया हो, आदमियों की भीड़ की उत्साह से भरी हुई इस बिजली की धारा से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। लोग समझना चाहते थे, जानना चाहते थे, और अपना रास्ता निकालना चाहते थे। सारी भीड़ एक परिपूर्ण चीज़ हो गई थी और इसके कठोर

कौतूहल को कभी-कभी मैं अपने होठों से अनुभव करता था। ऐसी हालत में पहले से सोची हुई तमाम युक्तियाँ, शब्द और विचार खतम हो जाते थे और जनता की सहानुभूति के बोझ के नीचे दब जाते थे। दूसरे शब्द, दूसरी दलीलें, जिन्हें बयान करने की मैं ज़रा भी आशा नहीं रखता था, लेकिन जिन्हें जनता सुनना चाहती थी, मेरे हृदय के अन्दर से जोरों के साथ उबलने लगती थीं। ऐसे अवसरों पर मुझे ऐसा मालूम होता था कि मानों कोई दूसरा आदमी बाहर व्याख्यान दे रहा है और मैं सुन रहा हूँ। ऐसा मालूम होता था कि मानों मैं उसके विचारों के साथ-साथ चलना चाहता हूँ, लेकिन वह डरता था कि अगर कहीं मैंने अपनी बुद्धि से सोची हुई दलीलें पेश कीं तो यह न हो कि यह दूसरा व्याख्यान-दाता सोते में चलने वाले आदमी की तरह छत के नीचे गिर जाय।

“माडर्न सर्कस इस तरह का था। इसकी रूप-रेखा नाजुक मगर पागलपन और उत्साह से अलंकृत थी। बच्चे शान्ति के साथ स्तनों से दूध पी रहे थे जिनसे मंजूरी और धमकी की जोशीली आवाजें आ रही थीं। सारी जनता दुधमुँहे बच्चे के समान क्रान्ति के स्तनों से अपने सूखे होठों से दूध पी रही थी। लेकिन यह बच्चा बहुत तेज़ी के साथ बढ़ गया।”

इस तरह क्रान्ति का हमेशा बदलने वाला नाटक पेट्रोग्रेड में और रूस के दूसरे शहरों और गाँवों में चलने लगा। यह दुधमुँहा बच्चा बढ़ा और बढ़ा हो गया। लड़ाई की भयंकर बोझ की वजह से हर जगह आर्थिक विनाश के चिन्ह दिखाई दे रहे थे; फिर भी मुनाफ़ा उठाने वाले लोग लड़ाई से खूब मुनाफ़ा उठा रहे थे!

सोवियट में और कारखानों में बोलशेविक लोगों का प्रभाव और ताक़त बढ़ती गई। इससे घबड़ाकर करेत्स्की ने उनको दबाने की कोशिश की। लेनिन के खिलाफ़ पहले-पहल बहुत जोरों के साथ आन्दोलन चला और यह कहा जाने लगा कि लेनिन तो जर्मन लोगों का भेजा हुआ आदमी है और वह रूस में उत्पात मचाने के लिए भेजा गया है। लोगों से कहा जाता था कि देखो स्वीज़रलैण्ड से लेनिन बिना जर्मन लोगों की मदद के ही जर्मनी से होकर रूस में कैसे आ सकता है। लेनिन मध्यवर्ग के लोगों में बहुत बदनाम हो गया और वे लोग उसे देशद्रोही समझने लगे। करेत्स्की ने जर्मनी का दूत और देशद्रोही होने का जुर्म लगाकर लेनिन की गिरफ्तारी का वारण्ट निकाला। लेनिन खुद यह चाहता था कि उसपर मुकदमा चले ताकि वह इस अपराध को ग़लत साबित कर सके। लेकिन उसके साथी इस बात से सहमत नहीं हुए और उसे छिप जाने पर मजबूर किया। ट्राट्स्की भी गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन दाद में पेट्रोग्रेड सोवियट के दबाव डालने पर छोड़ दिया गया। बहुत से दूसरे बोलशेविक भी पकड़े गये; उनके अख़बार दबा दिये गये और ऐसे कार्यकर्ताओं के हथियार छीन लिये गये जो बोलशेविकों के प्रति हमदर्दी रखने वाले समझे जाते थे।

इन कार्यकर्त्ताओं का ढंग ज्यादा से ज्यादा गरम और अस्थायी सरकार के लिए खतरनाक होता जाता था और ये इस सरकार के खिलाफ़ बड़े-बड़े प्रदर्शन भी कर चुके थे।

क्रांति के खिलाफ़ एक नया आन्दोलन शुरू हुआ यानी जब प्रतिक्रांति ने सिर उठाया तब इस नाटक में एक नया दृश्य सामने आ गया। एक बूढ़ा जनरल, जिसका नाम कार्नोल्फ़ था, सारी क्रांति को और अस्थायी सरकार को कुचलने के लिए अपनी फ़ौज के साथ राजधानी की ओर बढ़ा। शहर के नजदीक पहुँचते-पहुँचते उसकी सेना गायब हो गई। सिपाही लोग क्रांतिकारियों की तरफ़ चले गये।

घटनायें बहुत तेज़ी से घट रही थीं। सोवियट साफ़-साफ़ सरकार की प्रतिद्वन्द्वी होती जाती थी। अक्सर वह सरकार की आज्ञाओं को रद्द कर देती थी या खिलाफ़ हुक्म निकालती थी। इस समय स्मानली इंस्टिट्यूट में सोवियट का दफ़्तर था और वहीं पेट्रोग्रेड की क्रांति का भी केन्द्र था। इस जगह पहले रईसों की लड़कियों का एक प्राइवेट स्कूल था।

लेनिन पेट्रोग्रेड की सरहद पर आया और बोलशेविकों ने निश्चय किया कि अस्थायी सरकार से सत्ता छीन लेने का व्यय आ गया है। बराबत के सारे प्रबन्ध की जिम्मेदारी ट्राट्स्की को सौंपी गई। एक-एक बात सावधानी से पहले से ही निश्चय कर ली गई और यह भी तय हो गया कि किन-किन महत्व की जगहों पर और कब कब्ज़ा किया जायगा। सातवीं नवम्बर बल्ले की तारीख़ मुक़र्रर हुई। इस दिन सोवियट्स की अखिल रूसी कांग्रेस होने वाली थी, लेनिन ने इसी तारीख़ को मुक़र्रर किया। इसकी जो बजह बताई, वह बहुत दिलचस्प है। उसने कहा:—

“६ नवम्बर की तारीख़ बहुत पहले होगी। शहर के लिए अखिल रूसी आधार का होना ज़रूरी है। ६ तारीख़ को कांग्रेस के सब प्रतिनिधि न आ पाये होंगे। इसके विपरीत अगर तारीख़ मुक़र्रर करें तो बहुत देर हो जायगी, क्योंकि उस तारीख़ तक कांग्रेस संगठित हो जायगी और जनता की किसी भी बड़ी जमात का फुर्ती के साथ एक निश्चित कार्रवाई कर सकना मुश्किल होता है। इसलिए हमें ७ ही तारीख़ को, जिस दिन कांग्रेस का पहला अधिवेशन होगा, क्रांति करनी चाहिए, ताकि हम कांग्रेस से कह सकें कि “लो, अधिकार यह है। इसका जो कुछ करना हो करो।”

इस तरह से क्रांति के स्पष्ट बुद्धि वाले विशेषज्ञ ने कहा था, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि क्रांति की कामयाबी अक्सर छोटी-छोटी महत्वशून्य घटनाओं पर निर्भर होती है।”

१. सात नवम्बर के बारे में यह कहानी एक अमेरिकन पत्रकार ने, जो उस समय पेट्रोग्रेड में था, लिखी है। लेकिन कुछ लोग जो उस समय वहाँ मौजूद थे

७ नवम्बर आई और सोवियट-सिपाहियों ने जाकर सरकारी इमारतों, खासकर तार-घर, टेलीफोन, एक्सचेंज और सरकारी बैंक वगैरा घात और जुगत की जगहों, पर कब्जा कर लिया। किसी ने कोई मुकाबिला नहीं किया। “अस्थायी सरकार हवा में गायब हो गई,” इन शब्दों में एक अंग्रेज प्रतिनिधि ने इंग्लैण्ड को सरकारी रिपोर्ट भेजी थी।

लेनिन नई सरकार का प्रमुख यानी प्रेसीडेण्ट हुआ और ट्राट्स्की बंदेशिक सचिव। दूसरे दिन यानी ८ नवम्बर को लेनिन सोवियट कांग्रेस में शामिल होने के लिए स्मानली इंस्टीट्यूट को गया। शाम का वक्त था। कांग्रेस ने इस नेता का बहुत जोरों के साथ स्वागत किया। रीड नाम के एक अमेरिकन पत्रकार ने, जो इस मौके पर मौजूद था, इस बात का वर्णन किया है कि जब ‘महान लेनिन’ प्लेटफार्म पर आया, वह कैसा दीखता था—

“एक छोटे कद का गठीला व्यक्ति, जिसके कंधों पर एक बड़ा सिर रक्खा हुआ था—बहादुरी और स्फूर्ति से भरा हुआ ! छोटी-छोटी आंखें, गुमठी-सी नाक, चौड़ा मुंह और बड़ी ठुड्डी, मूँछ-दाढ़ी घुटी हुई, पर उसकी पुरानी और आगे मशहूर होने वाली दाढ़ी के छोटे-छोटे बाल निकल रहे थे। फटे-पुराने कपड़े और पैजामा टांगों से ज्यादा लम्बा। इसमें कोई ऐसी प्रभावशाली बात नहीं पाई जाती थी कि कोई भी उसे अपना आदर्श बनावे। पर यह एक आश्चर्यजनक लोकप्रिय नेता था, जो सिर्फ अपनी बुद्धि की वजह से नेता बना था—निलेप, गम्भीर, कट्टर और निस्संग। उसमें कोई दिलचस्प सनक भी नहीं पाई जाती थी। लेकिन इसमें बड़े-बड़े ख्यालों और गहरी बातों को सीधी-सादी ज़बान में समझा सकने और किसी स्थिति का विश्लेषण करके यानी उसे टुकड़े-टुकड़े करके लोगों को समझाने की ताकत थी। और कुशाग्र बुद्धि के साथ-साथ उसमें महान् बौद्धिक साहस भी था।”

साल भर के अन्दर ही यह दूसरी क्रांति हो गई और अभी तक शान्तिपूर्ण बनी रही। शासनाधिकार के बदलने में बहुत कम खून गिरा। मार्च की क्रांति में इससे ज्यादा लड़ाई हुई थी और आदमी मारे गये थे। मार्च की क्रांति आप ही आप और असंगठित रूप से हुई थी। नवम्बर की क्रांति को सोच-विचार कर संगठित किया गया था। इतिहास में यह पहला मौका था जबकि गरीब से गरीब वर्ग के प्रतिनिधि, खासकर मिलों के मजदूर, देश के शासन के प्रमुख बने थे। लेकिन इन लोगों को इतनी आसानी

उसको नहीं मानते। लेनिन छिपे हुए था और उसे डर था कि दूसरे बोलशेविक नेता कहीं समझौता न कर लें और मौके को हाथ से खो दें। इसलिए वह बराबर उनको आगे बढ़ाने के लिए मजबूर करता रहता था। चूंकि ७ तारीख को मामला नार्क हो गया यह कार्रवाई उस वक्त कर ली गई।

से सफलता मिलने वाली नहीं थी। तूफ़ान इनके चारों तरफ़ इकट्ठा हो रहा था और भयंकर वेग के साथ इनके ऊपर फट पड़ने वाला था।

लेनिन को और उसकी नई बोलशेविक सरकार को किस स्थिति का मुकाबिला करना पड़ा ? जर्मन-युद्ध अभी तक जारी था यद्यपि रूसी सेना छिन्न-भिन्न हो चुकी थी और इस सेना के लड़ने की कोई सम्भावना बाक़ी नहीं रह गई थी। सारे देश में अशान्ति फैली हुई थी। सिपाहियों और लुटेरों की टोलियाँ देश भर में फिर-फिर कर मन-माना जो चाहती थीं, करती थीं। आर्थिक ढाँचा टूट चुका था, खाने का सामान कम पड़ गया था और लोग भूखों मर रहे थे। लेनिन के चारों ओर पुरानी प्रणाली के प्रतिनिधि मौजूद थे, जो इस बात के लिए तैयार बैठे थे कि क्रान्ति को कुचल दें। राज्य का संगठन पूँजीपतियों की प्रणाली का था और पुराने सरकारी अफ़सर नई सरकार के साथ सहयोग करने से इनकार करते थे। बंकर या साहूकार लोग रुपया देने को तैयार नहीं थे। यहाँ तक कि तारघर वाले तार नहीं देते थे। इतनी कठिन स्थिति थी कि बहादुर-से-बहादुर आदमी पस्त हो जाय।

लेनिन और उसके साथियों ने ज़ोरों से काम करना शुरू किया। पहली फ़िक्र इस बात की थी कि जर्मनी के साथ सुलह कर ली जाय। उन्होंने फ़ौरन ही लडाई को बन्द कराने का इन्तज़ाम कर लिया। ब्रेस्ट लिटोस्क में दोनों देशों के प्रतिनिधि मिले। जर्मन लोग अच्छी तरह जानते थे कि बोलशेविक लोगों में लड़ने की ताक़त नहीं रही है, इसलिए अपने अभिमान और बेवकूफी की वजह से उन्होंने नें बड़ी अपमान-जनक और सख्त माँगें पेश कर दीं। बोलशेविक लोग हालांकि सुलह करने के लिए बहुत उत्सुक थे लेकिन इन माँगों को देखकर अवाक् रह गये। बहुतों की तो यह राय हुई कि सुलह की शर्तें नामंजूर करदी जायं, लेकिन लेनिन हर हालत में सुलह करने के पक्ष में था। कहते हैं कि ट्राट्स्की को, जो सुलह की इस काफ़्रेंस का एक रूसी प्रतिनिधि था, जर्मन लोगों के एक उत्सव में शाम के कपड़े पहन कर बुलाया गया। वह बहुत घबड़ाया और सोचने लगा कि मजदूरों के प्रतिनिधि के लिए यह कहाँ तक मुनासिब होगा कि बड़े अमीर आदमियों की पोशाक पहन कर जाय। उसने लेनिन को तार दिया और उससे सलाह पूछी। लेनिन ने फ़ौरन ही जवाब दिया—“अगर सुलह के काम में सहायता मिले तो तुम लहंगा पहन कर भी जा सकते हो।”

इधर सोवियट सुलह की शर्तों के लिए बहस-मुबाहिसे कर रही थी, उधर जर्मन लोग पेट्रोग्रेड की तरफ़ बढ़ने लगे और उन्होंने सुलह की शर्तों को पहले से ज्यादा सख्त कर दिया। आख़िर लेनिन की सलाह को सोवियट ने मान लिया और मार्च १९१८ में ब्रेस्ट लिटोस्क के सुलहनामे पर दस्तख़त हो गये, हालाँकि सोवियट इस

सुलहनामे को घृणा की दृष्टि से देखती थी। इस सुलहनामे के आधार पर रूस के राज्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा पश्चिम में जर्मनी ने ले लिया। लेकिन सुलह तो हर हालत में करनी जरूरी थी, क्योंकि जैसा लेनिन कहता था—“क्रौज ने अपने क्रदमों से सुलह के पक्ष में राय डाली है।”

सोवियट ने पहले इस बात की कोशिश की कि महायुद्ध में जितनी शकियाँ फँसी हुई हैं सब से सुलह हो जाय। शासन हाथ में लेने के दूसरे ही दिन उसने सारी दुनिया के साथ सुलह करने की घोषणा निकाली और इस बात को बिल्कुल साफ़ कर दिया कि ज़ार के खुफ़िया अहदनामों के अनुसार जो कुछ अधिकार रूस को मिलते, उसकी यह दावेदार नहीं हैं। उसने यह भी कहा कि कुस्तुनतुनिया तुर्कों के पास रहे और कोई दूसरा देश न छीना जाय। लेकिन सोवियट की तजवीज़ का किसी ने जवाब नहीं दिया क्योंकि लड़ने वाले दोनों दल जीतने की आशा रखते थे और युद्ध के जीते हुए देशों से फ़ायदा उठाना चाहते थे। इसमें शक नहीं की सोवियट की इस तरह तजवीज़ पेश करने की एक मंशा यह भी थी कि उसके सिद्धान्तों का प्रचार हो। वह चाहती थी कि हरेक देश की जनता पर और युद्ध से थके हुए सिपाहियों पर असर पड़ जाय और दूसरे देशों में सामाजिक क्रान्ति पैदा हो जाय, क्योंकि ये लोग संसार भर में क्रान्ति करना चाहते थे और इनका ख़याल था कि इसी तरीक़े से ये अपनी क्रान्ति की रक्षा कर सकेंगे। मैंने तुम्हें इसके पहले बताया है कि फ़्रान्स और जर्मनी की फ़ौजों पर सोवियट के प्रचार का बड़ा असर पड़ा था।

लेनिन ब्रेस्ट लिटोव्स्क के सुलहनामे को एक चन्दरोज़ा मामला समझता था, जो बहुत दिनों तक क़ायम नहीं रह सकता था और यही हुआ भी। ९ महीने बाद ज्योंही जर्मनी को मित्र-पक्ष के लोगों ने पश्चिमी मोर्चे पर हरा दिया, सोवियट ने इस सुलहनामे को मन्सूख़ कर दिया। लेनिन असल में चाहता था कि थके हुए मजदूर और किसानों को, जो फ़ौज में थे, ज़रा-सा आराम और साँस लेने का मौक़ा मिल जाय ताकि वे अपने घरों को वापस जा सकें और अपनी आँखों से देख सकें कि क्रान्ति ने उनके लिए क्या किया है। वह चाहता यह था कि किसान लोग यह समझने लगे कि ज़मीन-दार ख़तम हो गये और ज़मीन उनकी हो गई। वह चाहता था कि मिल के मजदूर भी यह समझने लगे कि उनका शोषण करनेवाले ख़तम हो गये। इससे वे क्रान्ति के लाभ अच्छी तरह समझने लगेंगे और उसकी रक्षा करने के लिए उत्सुक होंगे, साथही वे यह भी समझ जायेंगे कि उनके असली दुश्मन कौन हैं। लेनिन के ऐसे ख़यालात थे, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि गृह-युद्ध आनेवाला है। यह नीति वाद को बहुत सफलतापूर्वक सही साबित हुई। किसान और मजदूर लड़ाई के मैदान से अपने-अपने खेतों और

मिलों को वापस गये। वे लोग न बोलशेविक थे, न साम्यवादी, लेकिन वे क्रान्ति के बड़े कट्टर हिमायती हो गये, क्योंकि वे क्रान्ति की वजह से जो कुछ प्राप्त कर चुके थे, उसे छोड़ना नहीं चाहते थे।

उधर जर्मन लोगों से किसी-न-किसी तरह समझौता करने की कोशिश हो रही थी, उधर बोलशेविक नेताओं ने देश की अन्दरूनी हालत पर ध्यान देना शुरू किया। फ़ौज से निकले हुए अफ़सरों और साहसी ले-भगगुओं की काफ़ी तादाद ऐसी थी जिनके पास मशीनगनों और लड़ाई का सामान था। ये लोग लुटेरेपन का व्यवसाय चला रहे थे। बड़े-बड़े शहरों में दिन दहाड़े गोलियाँ चलाकर लूटमार करते थे। पुराने आतंकवादी दल के कुछ लोग भी थे, जो सोवियट को पसन्द नहीं करते थे और बड़ी परेशानी पैदा कर रहे थे। सोवियट सरकार ने इन सब लुटेरों और दूसरों को ज़ोरों से दबा दिया और पस्त कर दिया।

सोवियट शासन को इससे ज्यादा ख़तरा अनेक सिविल सर्विस के लोगों से यानी पुराने सरकारी नौकरों से हुआ। इनमें से बहुतेरे ऐसे थे, जो बोलशेविकों की मातहतता में या उनसे सहयोग करके किसी तरह भी काम करने को तैयार नहीं थे। लेनिन ने यह सिद्धान्त निश्चित कर दिया कि, जो काम न करे वह खाना भी न खाय, जो काम न करे उसे रोटी न मिले। तमाम सरकारी नौकर, जिन्होंने सहयोग नहीं दिया, फ़ौरन बरखास्त कर दिये गये। बैंकरों ने अपनी तिजोरियाँ खोलने से इन्कार कर दिया। इस पर तिजोरियाँ डाइनामाइट यानी बम से खोल दी गईं। लेकिन पुरानी प्रणाली के सरकारी अफ़सरों के प्रति, जो सहयोग करने से इन्कार करते थे, लेनिन की घृणा का सबसे अच्छा उदाहरण यह है कि जब मुख्य सेनापति ने बोलशेविक सरकार के हुक्म को मानने से इनकार कर दिया, तो वह पाँच मिनट में बरखास्त कर दिया गया। और पाँच मिनट के अन्दर त्राइलेन्को नाम का नौजवान बोलशेविक लेफ्टीनेण्ट प्रमुख सेनापति बना दिया गया!

इन तब्दीलियों के होते हुए भी रूस का पुराना ढाँचा बहुत कुछ ज्यों-का-त्यों बना रहा, किसी विशाल देश को एक दम से समाजवादी बनाना आसान काम नहीं होता और यह सम्भव है कि रूस में परिवर्तन की प्रगति को कई साल लग गये होते अगर घटना ने मजबूरी पैदा न कर दी होती। जिस तरह किसानों ने जमींदारों को भगा दिया था, मजदूरों ने भी कई जगहों पर अपने पुराने मालिकों से नाराज हो कर उनको निकाल दिया और उनके कारख़ानों पर क़ब्ज़ा कर लिया। सोवियट इन कारख़ानों को पुराने पूंजीपतियों को किसी तरह वापस नहीं कर सकती थी इसलिए उसने इन पर क़ब्ज़ा कर लिया। कई जगहों पर इन पूंजीपतियों ने गृह-युद्ध के ज़माने

में, जो बाद को हुआ, अपने कारखानों की मशीनों को तोड़ने की कोशिश की। ऐसी हालत में सोवियट सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा और इन कारखानों की हिफाजत के लिए मिलों पर कब्जा करना पड़ा। इस तरीके से उत्पत्ति के साधनों को पंचायती बनाने की प्रगति में यानी मिलों को सरकारी अधिकार में लाने के काम में खास तौर से तेजी पैदा हो गई, जितनी तेजी कि शायद साधारण स्थिति में नहीं हो सकती थी।

सोवियट शासन के पहले ९ महीनों में रूसी जनता के जीवन में बहुत फरक नहीं आया। बोलशेविकों ने आक्षेपों को भी बरदाश्त किया और गालियां भी सह्यीं। बोलशेविकों के खिलाफ़ अख़बार निकलते रहे। जनता आम तौर से भूखें मरती थी, लेकिन अमीरों के पास अब भी बहुत काफ़ी पैसा व्यसन और शान दिखाने के लिए मौजूद था। होटलों में रात को नाच-गाने होते थे और वहाँ खूब भीड़ लगती थी। घुड़दौड़ और दूसरे खेल-कूद पहले की तरह ही जारी थे। बड़े-बड़े शहरों में बड़े-बड़े अमीर खूब दिखाई देते थे और सोवियट सरकार के पतन की आशा में खुल्लमखुल्ला खुशियाँ मनाते हुए दिखाई देते थे। ये लोग, जोकि जर्मनी के खिलाफ़ लड़ाई जारी रखने में इतनी ज्यादा देश-भक्ति जाहिर करते थे, अब इस बात पर उत्सव करने लगे कि जर्मन लोग पेट्रोग्रेड की तरफ़ बढ़ते चले आ रहे हैं। ये लोग इस आशा में कि जर्मन सेनायें इनकी राजधानी पर कब्जा कर लेंगी, बहुत प्रसन्न थे। विदेशियों के राज्य का डर इनके हृदय में इतना नहीं था, जितनी सामाजिक क्रान्ति की धृणा। यह बात हमेशा होती है, खास तौर से तब, जब मामला वर्गों का होता है। हम हिन्दुस्तान में आज यही देखते हैं। यहाँ भी बहुत-से ऐसे आदमी हैं, जो विदेशी हुकूमत को बेहतर समझते हैं, इस बात के मुक़ाबिले में कि विशेषाधिकार और स्वत्व, जो अब इनको मिले हुए हैं, इनके हाथ से जाते रहें।

जनता का जीवन पहले ही जैसा था और इस समय बोलशेविकों का कोई आतंक भी नहीं था। मास्को का मशहूर नाच बराबर होता था और थियेट्रों में खूब भीड़ लगती थी। जब पेट्रोग्रेड पर जर्मनों के कब्जा कर लेने का खतरा पैदा हुआ, सोवियट सरकार मास्को चली आई। उस समय से मास्को सोवियट की राजधानी रहा है। मित्र पक्ष के राजदूत अभी तक रूस में थे। जब यह अन्देशा हुआ कि पेट्रोग्रेड पर जर्मनों का कब्जा हो जायगा, वे पेट्रोग्रेड से भाग गये और जाकर 'वोलोगडा' में, जो एक छोटा सा क़स्बा है, आराम के साथ मजे में बस गये। वे लोग यहाँ रहते थे और तरह-तरह की अफ़वाहें, जो इनके पास पहुँचती थीं, सुनकर बराबर परेशान और बेचैन रहा करते थे। वे बराबर ट्राट्स्की से पूछते रहते थे कि अफ़वाहें कहाँ तक सही हैं। इन पुराने राजदूतों की इस मानसिक परेशानी से ट्राट्स्की बहुत परेशान हो

गया और इसने बोलगडा के हिज एक्सेलेंसियों की मानसिक बेचैनी को शान्त करने के लिए एक ब्रोमाइड का नुस्खा लिखना चाहा। डाक्टर लोग हिस्टीरिया और बेचैनी से पीड़ित लोगों की मानसिक परेशानी को ठंडा करने के लिए ब्रोमाइड देते हैं।

ऊपर-ऊपर ज़िन्दगी ज़रूर साधारण थी, लेकिन इस जाहिरा शान्ति के नीचे अनेक धारारें अनुकूल और प्रतिकूल बहती थीं। कोई भी इस बात की उम्मीद नहीं करता था और बोलशेविक लोगों को भी इसकी उम्मीद नहीं थी कि वे बहुत दिनों तक क़ायम रह सकेंगे। हरेक आदमी साजिश में लगा था। जर्मन लोगों ने दक्षिण रूस में यूक्रेन में एक रियासत क़ायम कर रखी थी जो इनके हाथ की कठपुतली थी और मुल्ह हो जाने पर भी ये लोग सोवियट को बराबर धमकाते रहते थे। मित्र-पक्ष ज़रूर जर्मनों से नफ़रत करता था, लेकिन वह बोलशेविकों से और भी ज्यादा नफ़रत करता था। अमेरिका के राष्ट्रपति विलसन ने सोवियट कांग्रेस को १९१८ के शुरू में प्रेम-सन्देश भेजा था, लेकिन बाद को मालूम होता है कि वह इस बात पर पछताया और उसने अपने ख़याल बदल दिये। इस तरह से मित्र-पक्ष के लोगों ने निजी तौर पर, क्रान्तिकारी प्रवृत्तियों के विरोध में जो आन्दोलन था उसकी सहायता की और उसको रुपये-पैसे से मदद दी। वे छिपे-छिपे क्रान्तिकारी दल के ख़िलाफ़ काम भी करते थे। विदेशी जासूसों से मास्को भरा पड़ा था। अंग्रेज़ी खुफ़िया पुलिस का ख़ास आदमी, जो ब्रिटेन का सबसे बड़ा जासूस समझा जाता था, सोवियट सरकार को परेशान करने के लिए भेजा गया था। जिन बड़े-बड़े आदमियों को उनकी जायदाद से वंचित कर दिया गया था, वे मित्र-पक्ष के रुपये से क्रान्ति के विरुद्ध बराबर आन्दोलन भड़काते रहते थे।

१९१८ के मध्य के करीब यह हालत थी। सोवियट की जान कच्चे धागे से लटक रही थी।

: १५२ :

सोवियट की विजय

११ अप्रैल, १९३३

जुलाई १९१८ के महीने में रूस की स्थिति में आश्चर्यजनक परिवर्तन हुए। बोलशेविक लोगों पर जो जाल फेंका गया था वह सिकुड़ता जाता था और वे उसमें फँसते जाते थे। दक्षिण में यूक्रेन से जर्मनों की चढ़ाई का डर था और मित्र पक्ष के लोग ज़ेकोस्लोवेकिया के लड़ाई के पुराने क्रैंदियों की एक बड़ी तादाद को इस बात का प्रोत्साहन दे रहे थे कि वह मास्को पर टूट पड़े। फ़्रान्स में सारे पश्चिमी मोर्चे पर महा

युद्ध अभी तक जारी था लेकिन सोवियट रूस में विचित्र दृश्य यह दिखाई देता था कि जर्मन शक्तियाँ और मित्र दल दोनों अलग-अलग एक ही काम में यानी बोलशेविकों को कुचलने में लगे थे। इस स्थान पर हमें फिर यह बात दीख जाती है कि श्रेणी-सम्बन्धी घृणा राष्ट्रीय घृणा से कितनी ज्यादा ताकतवर होती है और राष्ट्रीय घृणा स्वयं काफ़ी विषैली और कटु हुआ करती है। इन शक्तियों ने रूस के खिलाफ़ सरकारी तौर पर युद्ध की घोषणा नहीं की थी, लेकिन सोवियट को परेशान करने के इन्होंने बहुत से तरीक़े निकाल लिये थे, खास कर ऐसे नेताओं को हथियारों से और पैसे से मदद देते थे और उनको प्रोत्साहन दिया करते थे जो क्रान्ति के खिलाफ़ थे। ज़ार से बहुत पुराने सेनापतियों ने सोवियट के खिलाफ़ लड़ाई शुरू कर दी।

ज़ार और उसका कुटुम्ब पूर्वी रूस में यूरल पहाड़ों के नजदीक एक स्थानीय सोवियट की निगरानी में क़ैदी बना कर रक्खे गये थे। ज़ेक सेनाओं के इस प्रदेश की तरफ़ बढ़ने की वजह से स्थानीय सोवियट डर गई। वह घबड़ा गई कि कहीं ज़ार छुड़ा न लिया जाय और क्रान्ति के खिलाफ़ एक बड़ी ताक़त न बन जाय। इसलिए उन्होंने क़ानून को अपनी तबीयत के मुताबिक़ काम में लाकर सारे कुटुम्ब को गोली से मार दिया। इससे मालूम होता है कि सोवियट की केन्द्रीय कमेटी का ज़ार और ज़ार के क़त्ल के में कोई हाथ न था। लेनिन अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से ज़ार के और दया की दृष्टि से उसके कुटुम्ब के क़त्ल के खिलाफ़ था। चूँकि यह हरकत हो चुकी थी, केन्द्रीय सरकार ने इसका समर्थन किया। शायद मित्र-पक्ष की सरकार इस घटना से और भी बिगड़ गई और वह पहले से ज्यादा विरोध करने के लिए तैयार हो गई।

अगस्त के महीने में स्थिति बदतर हो गई और दो घटनायें ऐसी हुईं जिनकी वजह से क्रोध, निराशा और आतंक पैदा हो गया। एक घटना तो यह थी कि लेनिन को मारने की कोशिश की गई और दूसरी यह कि उत्तर रूस में आर्चज़िल पर मित्र पक्ष की फ़ौजें पहुँच गईं। मास्को में बड़ी जोरदार सनसनी फैल गई। मालूम होता था कि बस सोवियट का ख़ात्मा होने वाला है। मास्को को खुद दुश्मनों ने चारों तरफ़ से घेर लिया था। जर्मन, ज़ेक और क्रान्तिकारियों के खिलाफ़ जो दल थे वे इसके चारों ओर पड़े थे। मास्को के चारों तरफ़ सिर्फ़ चन्द ज़िलों में ही सोवियट का राज्य था और मित्र-पक्ष की सेना के उतर पड़ने से इसका भी ख़ात्मा निश्चित हो गया। बोल-शेविकों के पास कोई बड़ी फ़ौज नहीं थी। ब्रेस्ट लिटोस्क के समझौते के अभी सिर्फ़ ५ महीने ही गुजरे थे और पुरानी फ़ौज का ज्यादा हिस्सा खेती-किसानी में लग गया था। मास्को में खुद बहुत से षड्यन्त्र पैदा हो गये थे और बर्जुआ यानी मध्यम वर्ग के लोग खुल्लमखुल्ला खुशियाँ मना रहे थे कि सोवियट का ख़ात्मा होने वाला है।

नौ महीने की उम्र वाले सोवियट प्रजातन्त्र की यह भयंकर दशा थी। बोल-शेविक लोग निराशा और भय में फँस गये और जब इन्होंने देखा कि अब मरना ही है तो सोचा कि लड़ते हुए ही प्राण क्यों न दिये जायें। १२५ वर्ष पहले जिस तरह नये फ़्रान्सीसी प्रजातन्त्र ने किया था वैसे ही ये चारों तरफ़ से घिर गये और रास्ता न पाने वाले जंगली जानवर की तरह वे अपने दुश्मन पर टूट पड़े। न तो क्षमा की बात रही, न दया की। सारे देश में फ़ौजी क़ानून जारी कर दिया गया। और सितम्बर की शुरुआत में केन्द्रीय सोवियट कमेटी ने 'ख़ूनी आतंक' (Red Terror) की घोषणा की। 'सारे देशद्रोहियों का क़त्ल और विदेशी हमला करने वालों के खिलाफ़ निर्दयतापूर्ण युद्ध' यह उनकी पुकार थी। उन्होंने निश्चय किया कि हम अपने दुश्मनों के खिलाफ़ चाहे वह देश के अन्दर के हों या बाहर के, डटकर लड़ेंगे। अब सोवियट का मुक़ाबिला दुनिया से और अपने ही देश के संकीर्ण दल से पड़ गया। 'सैनिक साम्यवाद' का युग आ गया और सारा देश एक क्रिस्म का फ़ौजी कैम्प बन गया। लाल सेना के संगठन के लिए हरेक क्रिस्म की कोशिश की गई और यह काम ट्राट्स्की को सौंपा गया।

यह सितम्बर-अक्टूबर १९१८ की बात है, जबकि पश्चिम में जर्मनों की युद्ध की मशीन टूट रही थी और लड़ाई बन्द करने की चर्चा चल रही थी। प्रेसीडेण्ट विलसन ने अपनी १४ शर्तें पेश कर दी थीं, जिनके बारे में कहा जाता था कि उनमें मित्र-पक्ष का सब मतलब आ गया था। इनमें से एक बात यह थी कि रूस की सारी ज़मीन पर से मित्र-पक्ष की फ़ौजें हटा ली जायें और मित्र-पक्ष की मदद से रूस को अपनी उन्नति का पूरा-पूरा मौक़ा दिया जाय। मित्रपक्ष के लोगों का रूस में हस्तक्षेप करना और वहाँ अपनी फ़ौजों को उतार देना, इस सिद्धान्त पर एक अनुपम टीका कही जा सकती है। बोलशेविक सरकार ने प्रेसीडेण्ट विलसन के पास एक नोट भेजा और जोरों के साथ उनकी १४ शर्तों पर ऐतराज किया। उसने लिखा :—

“आप पोलैण्ड, सर्बिया, बेलजियम और आस्ट्रिया-हंगरी के लोगों की आज़ादी की मांग पेश करते हैं, लेकिन ताज़्जुब यह है कि आपकी मांगों में आयरलैण्ड, मिस्र, हिन्दुस्तान और फिलीपाइन द्वीपों की आज़ादी का कोई ज़िक्र नहीं है।”

११ नवम्बर १९१८ को मित्रपक्ष और जर्मनपक्ष में सुलह हो गई और सुलहनामे पर दस्तख़त भी हो गये, लेकिन रूस में १९१९ और १९२० भर गृह-युद्ध चलता रहा। अकेले दम सोवियट ने बहुत से दुश्मनों का मुक़ाबिला किया। एक वक़्त ऐसा था जब सोवियट के ऊपर सत्रह मुक़्तलिफ़ मोर्चों से हमले हुए थे। इंग्लैण्ड, अमेरिका, फ़्रांस, जापान, इटली, सर्बिया, जेकोस्लोवेकिया, रूमानिया, बालकन स्टेट्स, पोलैण्ड और सैकड़ों रूसी सेनापति, जो क्रान्ति के खिलाफ़ थे, सोवियट पर हमला कर रहे थे और लड़ाई

पूर्वी साइबेरिया से लेकर बाल्टिक और क्रीमिया तक जारी थी। बार-बार यही मालूम होता था कि सोवियट का ख़ात्मा हुआ। मास्को खुद ख़तरों में था और पेट्रोग्रेड दुश्मन के हाथ में जाने ही वाला था। लेकिन सोवियट ने हरेक नाज़ुक मौक़े पर विजय पाई और हरेक विजय के साथ उसकी ताक़त और उसका आत्म-विश्वास बढ़ता गया।

क्रान्तिकारियों के खिलाफ़ दल का एक नेता एडमिरल कोलचक था। वह अपने-को रूस का शासक कहता था। मित्र-दल के लोग उसको शासक मानते थे और उसकी बड़ी मदद करते थे। जनरल ग्रेव्स अमेरिका की सेना के सेनापति थे और कोलचक की सेना को मदद दे रहे थे। उनके कथन से पता चलता है कि एडमिरल कोलचक साइबेरिया में कैसी-कैसी हरकतें करता था। यह अमेरिकन जनरल लिखता है :—

“भयंकर हत्याओं की गई; लेकिन ये हत्याओं, जैसा दुनिया समझती है, बोल-शेविकों ने नहीं कीं। मैं यह सचाई के साथ कह सकता हूँ कि पूर्वी साइबेरिया में अगर बोलशेविकों ने एक हत्या की है तो उनके खिलाफ़ दल ने उसके मुक़ाबिले में सी हत्याओं की है।”

तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि बड़े-बड़े राजनीतिज्ञ बड़े-बड़े राष्ट्रों के मामलात को कितने कम ज्ञान पर चलाते हैं और लड़ाई तथा मुल्ह करते हैं। लायड जार्ज उस वक़्त ब्रिटेन का प्रधान सचिव था और योरप में शायद सबसे ज्यादा प्रभावशाली आदमी उस वक़्त वही था। हाउस आफ़ कामन्स में रूस पर व्याख्यान देते हुए उसने कोलचक और दूसरे सेनापतियों का जिक्र किया। जहाँ उसने जनरल कोलचक का जिक्र किया वहाँ जनरल त्ख़ारकफ़ का भी जिक्र कर दिया। पर त्ख़ारकफ़ कोई जनरल नहीं था। त्ख़ारकफ़ तो एक मशहूर शहर का नाम है, जो यूक्रेन की राजधानी है। भूगोल की प्रारंभिक बातों से इस प्रकार अपरिचित होते हुए भी इन राजनीतिज्ञों ने योरप को टुकड़े-टुकड़े कर दिया और एक नया नक्शा तैयार कर दिया !

मित्र-दल ने भी रूस की नाकेबन्दी की और यह नाकेबन्दी इतनी कामयाब रही कि सन् १९१९ भर रूस विदेशों से न तो कुछ ख़रीद सका, न बेच सका।

इन तमाम बड़ी-बड़ी कठिनाइयों और अनेक शक्तिशाली दुश्मनों के होते हुए भी सोवियट रूस ज़िन्दा रहा और विजयी रहा। इतिहास में यह अत्यन्त आश्चर्यजनक बात हुई है। वह कैसे कामयाब हुआ ? इसमें कोई शक़ नहीं कि अगर मित्रपक्ष संयुक्त रहते और बोलशेविक लोगों को कुचलने पर तुल जाते तो शुरू के दिनों में उन्हें कुचल सकते थे। जर्मनी को हराने के बाद, उनके पास विशाल सेना ख़ाली हो गई थी। लेकिन इन सेनाओं का किसी दूसरी जगह पर और ख़ासकर सोवियट के खिलाफ़ इस्तेमाल करना आसान नहीं था। ये सब सेनाएँ लड़ाई से थक गई थीं और अगर

विदेशों में जाकर फिर लड़ने को कहा जाता तो शायद इन्कार कर देतीं। मजदूरों में इस नवीन रूस के लिए बड़ी हमदर्दी थी और मित्र-दल की सरकारें इस बात से डरती थीं कि अगर सोवियट के खिलाफ खुल्लमखुल्ला लड़ाई छेड़ दी गई तो मुमकिन है देश के अन्दर ही गड़बड़ मच जाय। योरोप क्रान्ति के किनारे पहुँच चुका था। तीसरी बात यह थी कि मित्रदल के लोगों में आपस में भी प्रतिद्वन्द्विता चल रही थी। जब सुलह हुई, इनमें आपस में लड़ाई-झगड़ा शुरू होगया। इन सब बातों की वजह से मित्र-दल बोलशेविकों को खत्म करने के लिए कोई दृढ़ प्रयत्न नहीं कर सका। ये लोग अप्रत्यक्ष रूप से बोलशेविकों का ख़ात्मा करना चाहते थे। कोशिश इनकी यह थी कि कोई दूसरा लड़ाई लड़े जिसे ये रुपये-पैसे से, अस्त्र-शस्त्र से और सलाह-मशविरे से मदद दें। इनको पूरा यकीन था कि सोवियट चल न सकेगी।

इन सब बातों की वजह से सोवियट को निस्सन्देह बहुत मदद मिल गई और उसको अपनेको मजबूत बनाने के लिए वक़्त मिल गया। लेकिन यह ख़याल करना कि बोलशेविकों की विजय बाहर की परिस्थिति की वजह से हुई, बोलशेविकों के साथ अन्याय करना है। विजय की असली वजह तो यह थी कि रूस की जनता में आत्म-विश्वास था, श्रद्धा थी, आत्म-न्याय था और दृढ़ संकल्प था। आश्चर्य की बात तो यह है कि यही रूसी लोग हर जगह पर आलसी, जाहिल, सिद्धान्त-भ्रष्ट और किसी महान् प्रयत्न के लिए अयोग्य समझे जाते थे। आज्ञादी एक क्रिस्म की आदत है और अगर हम बहुत दिनों तक इस आदत से वंचित रहें तो हम इसे भूल जाते हैं। इन जाहिल रूसी किसानों और मजदूरों को बिलकुल मौक़ा नहीं मिलता था कि इस आदत पर अमल कर सकें। लेकिन रूस में उस समय ऐसे क्राबिल नेता पाये जाते थे कि उन्होंने इन असहाय लोगों को एक मजबूत और संगठित क्रौम बना दिया जिसे अपने सिद्धान्तों में पूरा विश्वास और अपने ऊपर पूरा भरोसा था। कोलचक और उसके संगी-साथी हार गये, सिर्फ़ इसलिए नहीं कि बोलशेविक नेताओं में दृढ़ता और योग्यता पाई जाती थी, बल्कि इसलिए कि रूसी कोलचक और उसके साथियों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। ये उन्हें पुरानी प्रणाली का प्रतिनिधि समझते थे जो कि इनके नये पाये हुए अधिकार और हाल में मिली हुई ज़मीन को छीनने के लिए आये थे। इसलिए किसानों ने यह निश्चय किया कि मरते दम तक इन अधिकारों की रक्षा करेंगे।

सबसे ऊपर और ज्यादा अख़्तियार रखनेवाला आदमी लेनिन था। रूसियों के लिए यह शक़्स देवता होगया। उनकी आशाओं और उमंगों का नुमाइन्दा; ऐसा बुद्धिमान जो हरेक परेशानी से निकलने का ढंग जानता था और इसे कोई भी

चीज परेशान नहीं कर सकती थी और न डिगा सकती थी। इसके बाद इस जमाने में ट्राट्स्की समझा जाता था (जो आजकल रूस में बदनाम होगया है)। ट्राट्स्की लेखक और वक्ता था। उसे सेना के संगठन का पहले से कोई अनुभव नहीं था। पर उसने गृहयुद्ध और नाकेबन्दी के होते हुए भी एक बड़ी सेना के संगठन का काम शुरू किया। ट्राट्स्की खतरे की परवा न करनेवाला बड़ा बहादुर आदमी था और लड़ाई में वह अक्सर अपनी जान खतरे में डाल देता था। बुज्दिलों और अनुशासन के खिलाफ़ काम करनेवालों के लिए उसके पास ज़रा भी दया नहीं थी। गृहयुद्ध के एक नाज़ुक मौक़े पर उसने यह आज्ञा निकाली थी :—

“मैं चेतावनी देता हूँ कि अगर फ़ौज का कोई टुकड़ा बग़ैर हुक्म के पीछे हटेगा तो पहले कमीसरी मार दिया जायगा और उसके बाद कमाण्डर। इनकी जगहों पर बहादुर और निर्भीक सिपाही मुक़र्रर किये जायंगे। बुज्दिल, डरपोक और देशद्रोही गोली से न बच सकेंगे। सारी लाल सेना के सामने मैं इस बात का गम्भीरतापूर्वक वादा करता हूँ।”

और उसने अपने वादे को पूरा किया।

ट्राट्स्की ने अक्टूबर १९१९ में एक फ़ौजी हुक्म निकाला था। वह भी बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि उससे जाहिर होता है कि बोलशेविक लोग हमेशा जनता को और पूंजीपति सरकारों को दो चीज मानते रहे और कभी उन्होंने राष्ट्रीय दृष्टिकोण नहीं रखा। हुक्म यह है :—

“But, even to-day, when we are engaged in a bitter fight with Yudenich, the hireling of England, I demand that you never forget that there are two Englands. Besides the England of profits, of violence, bribery and blood-thirstiness, there is the England of labour, of spiritual power, of high ideals of international solidarity. It is the base and dishonest England of the Stock Exchange manipulators that is fighting us. The England of labour and the people is with us.”

अर्थात् “आज भी, जब कि हम इंग्लैण्ड के पिट्टू यूडनिच से कठोर लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम कभी इस बात को न भूलो कि इंग्लैण्ड दो है। एक इंग्लैण्ड है मुनाफ़ाख़ोरों का, जालिमों का, रिश्वत लेनेवालों का, और खून के प्यासों का। दूसरी तरफ़ एक दूसरा इंग्लैण्ड है मजदूरों का, आध्यात्मिक शक्ति का और अन्तर्राष्ट्रीय दृढ़ता के लिए ऊँचे आदर्शों का। जो इंग्लैण्ड हमसे लड़ाई कर रहा है वह शोयर बाज़ार का कमीना, बेईमान इंग्लैण्ड है। जनता का, मजदूरों का इंग्लैण्ड हमारे साथ है।”

जिस दृढ़ता के साथ लाल सेना लड़ाई गई, उसका भन्दाजा नीचे लिखी हुई

घटना से हो सकता है। जिस वक़्त यूज़निच ने पेट्रोग्रेड को घेर लिया और यह शहर उसके हाथ में जाने ही वाला था, उस वक़्त रक्षा-समिति ने एक आज्ञा निकाली—“पेट्रोग्रेड की रक्षा खून का आखिरी क़तरा बहाकर भी करनी चाहिए। ग़ज़भर भी पीछे न हटना चाहिए और शहर के अन्दर दुश्मन आजाय तो शहर की गलियों में भी लड़ाई जारी रखनी चाहिए।”

रूस के मशहूर लेखक मैक्सिम गोर्की ने लिखा है कि लेनिन ने ट्राट्स्की के बारे में एक दफ़ा यह कहा था—“मुझे तुम कोई दूसरा आदमी ऐसा दिखा दो जो साल-भर के अन्दर एक नमूने की सेना संगठित करके दिखा दे और सेना के विशेषज्ञों का सम्मानपात्र भी होजाय। हमें ऐसा आदमी मिला हुआ है; हमारे पास सब कुछ है और चमत्कार अब भी घटित होनेवाले हैं।”

यह लाल सेना दिन-दूनी और रात-चौगुनी तरक्की करती गई। बोलशेविकों के अस्तित्वार पाने के थोड़े ही दिन बाद, दिसम्बर १९१७ में, ४ लाख ३५ हजार आदमी इस सेना में शामिल हो चुके थे। ब्रेस्ट लिटोस्क के बाद इस सेना का बहुत कुछ हिस्सा ज़रूर शायब होगया और उसको नये सिरे से बनाना पड़ा। सन् १९१९ के मध्य में इस सेना में १५ लाख आदमी पहुँच गये थे और सालभर बाद यही सेना ५३ लाख आदमियों की होगई।

ट्राट्स्की रूस का बहुत बड़ा नायक होगया। लेकिन वह इतना सहृदय नहीं था जितना लेनिन था और इसीलिए लोग इसे उतना प्यार नहीं करते थे जितना लेनिन को। लेनिन को छोड़कर उसकी किसी दूसरे पुराने बोलशेविक से नहीं पटती थी। लेनिन के मरने के बाद ही इन लोगों में आपस में झगड़ा होगया और ट्राट्स्की, जो क्रान्ति का वीर पुरुष था और जिसने लाल सेना का निर्माण किया था, रूस से निर्वासित कर दिया गया।

१९१९ के ख़तम होते-होते सोवियट ने निश्चित रूप से गृह-युद्ध में अपने दुश्मनों को नीचा दिखा दिया था; लेकिन लड़ाई एक साल तक और क़ायम रही और नाज़ुक मौक़े आते रहे। १९२० में पोलैण्ड के नये राज्य से रूस की लड़ाई छिड़ गई। जर्मनों की पराजय के बाद पोलैण्ड का नया राज्य बन गया था। लेकिन ये सब लड़ाइयाँ १९२० के ख़तम होते-होते समाप्त होगईं और रूस को कुछ शान्ति मिल गई।

इसी दरमियान अन्दरूनी कठिनाइयाँ बढ़ चुकी थीं। युद्ध, नाकेबन्दी, महामारी और दुष्काल ने देश की बहुत बुरी हालत कर डाली थी। उपज बहुत ज़्यादा घट गई थी, क्योंकि जब प्रतिद्वन्द्वी सेनायें देश को रौंद रही हों, तब न तो किसान खेत जोत सकता है और न मज़दूर मिलों में चीज़ों को बना सकता है। सैनिक साम्यवाद की

वजह से मुल्क किसी-न-किसी तरह ख़तरे से बचा था, लेकिन हरेक को अपनी पेट्री कसनी पड़ी थी और यह काम आगे चलकर बहुत कठिन होगया। किसानों को खेतों से ज्यादा उपज पैदा करने की कोई उत्सुकता नहीं थी, क्योंकि वे कहते थे कि जब राज्य ज्यादा पैदा हुआ अन्न खुद ही लेलेगा तो ज्यादा पैदा करने की परेशानी हम क्यों उठावें ? स्थिति बड़ी कठिन और भयानक होती जाती थी। जहाज़ के सिपाहियों ने पीटर्सबर्ग के क्रारीव क्रांस्टाट में बलवा कर दिया था। पीटर्सबर्ग में भी हड़तालें हुई थीं।

लेनिन ने, जिसमें यह अद्भुत गुण था कि वह सिद्धान्तों को मौजूदा स्थिति के अनुसार ढाल सकता था, फ़ौरन क़दम आगे बढ़ाया। उसने सैनिक साम्यवाद का ख़ात्मा किया और एक नई नीति चलाई, जिसका नाम था 'नई आर्थिक नीति'। इसकी वजह से किसान को पैदा करने और अपने माल को बेचने की ज्यादा आज़ादी मिल गई। इस नीति का अर्थ यह था कि किसी हद तक साम्यवादी सिद्धान्तों के अनुसार ये लोग पीछे हट रहे थे; लेकिन लेनिन ने, यह कहकर कि यह कार्रवाई अल्थायी रूप से की जा रही है, उसे उचित बताया। निस्सन्देह जनता को इसकी वजह से कुछ मदद मिली; लेकिन जल्द ही रूस को एक दूसरी भयंकर आपत्ति का सामना करना पड़ गया। रूस में दुष्काल पड़ा; दक्षिण-पूर्व रूस के बहुत बड़े क्षेत्र में पानी न बरसने की वजह से फसल नष्ट होगई। यह बड़ा भयंकर दुष्काल था और बड़े-से-बड़े दुष्कालों में से एक दुष्काल कहा जा सकता है। लाखों आदमी भूखों मर गये। चूँकि कई सालों की सुतवातिर लड़ाई, गृह-युद्ध, नाकाबन्दी और आर्थिक पतन के बाद यह दुष्काल पड़ा था और सोवियट सरकार को इतना समय नहीं मिला था कि वह शान्ति-पूर्वक अपना कार्यक्रम चला सके, इसलिए मुमकिन था कि इस दुष्काल की वजह से सरकार का ढाँचा बैठ जाता। लेकिन सोवियट जिस प्रकार इसके पहले की आफ़तों को पार कर गई थी, इस आफ़त से भी ज़िन्दा निकल आई। यूरोपियन सरकारों के प्रतिनिधियों की एक कान्फ़्रेंस हुई, जिसमें इस बात पर विचार करना था कि दुष्काल पीड़ितों को क्या मदद दी जाय। इस कान्फ़्रेंस ने यह निश्चय किया कि जबतक सोवियट सरकार इस बात का वादा नहीं करती कि ख़ार के लिये हुए कर्ज़ को अदा करेगी, उस समय तक कोई मदद नहीं दी जा सकती। दया की प्रवृत्ति से महा-जनी की प्रवृत्ति ज्यादा मजबूत निकली और रूसी माताओं की ओर से अपने मरते हुए बच्चों की रक्षा के लिए की हुई अपील को भी किसीने नहीं सुना। लेकिन अमेरिका ने कोई शर्त नहीं की और बड़ी मदद की।

इंग्लैण्ड और दूसरे यूरोपियन देशों ने रूस के दुष्काल में मदद देने से इन्कार कर दिया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे सोवियट का और तरह से

बहिष्कार कर रहे थे । १९२१ की शुरुआत में एक अंग्रेज-रूसी व्यापारिक संधि हुई थी और बहुतसे देशों ने इस उदाहरण का अनुकरण भी किया था और सोवियट के साथ व्यापारिक संधियाँ भी की थीं ।

पूर्वी देशों—जैसे चीन, तुर्की, फारस और अफ़ग़ानिस्तान—के साथ सोवियट की नीति बहुत उदार रही । ज़ार के प्राप्त किये हुए पुराने अधिकारों को उसने छोड़ दिया और बहुत दोस्ताना वर्ताव करने की कोशिश की । यह बात इसलिए की गई थी, क्योंकि उसका सिद्धान्त था कि शोषित और पराधीन जातियों को स्वतंत्रता दी जाय । लेकिन इससे अधिक महत्वपूर्ण अभिप्राय उसका यह था कि सोवियट की अपनी स्थिति मज़बूत होजाय । साम्राज्यवादी राष्ट्र, मसलन इंग्लैंड, सोवियट रूस की उदारता की वजह से अकसर परेशानी में पड़ जाते थे । पूर्वी देश तुलना करने लगते थे, जिसमें इंग्लैंड की और दूसरी क्रोमों की बदनामी होती थी ।

१९१९ में एक दूसरी महत्वपूर्ण घटना हुई, जिसके बारे में मुझे ज़रूर बताना चाहिए । कम्यूनिस्ट पार्टी यानी साम्यवादी दल ने मास्को में 'थर्ड इण्टरनेशनल' (तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय संघ) कायम किया । मैंने तुम्हें पहले के खतों में बताया है कि कार्ल मार्क्स ने 'फर्स्ट इण्टरनेशनल' बनाया था और सेकण्ड इण्टरनेशनल १९१४ में लड़ाई शुरू होने के मौके पर अनेक वीरतापूर्ण शब्दों के बाद ख़तम होगया । बोलशेविकों का कहना था कि पुराने साम्यवादियों और मज़दूरों की पार्टियों ने, जिनसे मिलकर यह 'सेकण्ड इण्टरनेशनल' बना था, मज़दूरों को धोखा दिया, इसलिए इन लोगों ने 'थर्ड इण्टरनेशनल' बनाया, जिसका आदर्श निश्चित रूप से क्रान्तिकारी था । यह इसलिए बनाया गया कि बोलशेविक साम्राज्यवाद और पूँजीवाद के खिलाफ़ और उन मौके से फ़ायदा उठानेवाले साम्यवादियों के खिलाफ़ युद्ध कर सकें जो सड़क के बीच से चलने की नीति को मानते हैं । इस इण्टरनेशनल को 'कामिण्टर्न' कहते हैं, जो कम्यूनिस्ट इण्टरनेशनल का संक्षिप्त है । इसने बहुत देशों में ख़ूब प्रचार किया है । जैसा इसके नाम से जाहिर होता है, यह एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था है, जिसमें अनेक देशों के साम्यवादी दलों के प्रतिनिधि शामिल हैं । लेकिन चूँकि रूस ही एक ऐसा देश है जिसमें कम्यूनिज्म यानी साम्यवाद को विजय मिली है, इस संस्था में यानी कामिण्टर्न में रूसी ज्यादा हैं । 'कामिण्टर्न' दूसरी चीज़ है और सोवियट दूसरी चीज़ है । हालांकि बहुतसे आदमी ऐसे हैं जो दोनों संस्थाओं के प्रमुख समझे जाते हैं । चूँकि 'कामिण्टर्न' एक ऐसी संस्था है जो खुल्लमखुल्ला क्रान्तिकारी साम्यवाद फैलाने के लिए कायम है, साम्राज्यवादी कौमों इसके सख्त खिलाफ़ हैं और अपने देशों में इसके काम को दबाने के लिए हमेशा कोशिश करती हैं ।

सेकण्ड इण्टरनेशनल ('मजदूरों और समाजवादियों की इण्टरनेशनल') को लड़ाई के बाद योरप में फिर से ज़िन्दा किया गया । बहुत हद तक, कम-से-कम सिद्धान्त-रूप में, सेकण्ड और थर्ड इण्टरनेशनल का उद्देश्य एक ही है । लेकिन इनके विचार और इनके काम करने के तरीकों में बहुत भेद है और इनमें आपस में बहुत लड़ाई है । ये अपने दुश्मन पूंजीवाद पर इतना आक्रमण नहीं करते और उससे इतनी लड़ाई-झगड़ा नहीं करते जितना आपस में लड़ते हैं और एक-दूसरे से लड़ाई-झगड़ा करते हैं । 'सेकण्ड इण्टरनेशनल' अब एक शरीफ़ और भले मानुषों की संस्था बन गई है और योरप की सरकारों के मन्त्रिमण्डल के अनेक सदस्य इसके सदस्य हैं । तीसरा इण्टर-नेशनल अभीतक क्रान्तिकारी है और इसलिए अभीतक भले मानुषों की संस्था नहीं बन सका है ।

रूस में गृह-युद्ध के ज़माने में लाल आतंक (Red Terror) और श्वेत आतंक (White Terror) अपनी कठोर निर्दयता के लिए बराबर एक-दूसरे के प्रतिद्वन्द्वी रहे और गालिबन श्वेत आतंक ने इस मामले में लाल आतंक को मात कर दिया । साइबेरिया में कोलचक के अत्याचारों के बारे में अमेरिकन सेनापति के वर्णन से, जिसे मैं पहले दे चुका हूँ, और दूसरे वर्णनों से भी यही नतीजा निकलता है । लेकिन इसमें भी शक नहीं कि लाल आतंक भी बहुत कठोर था और बहुतसे निर्दोष आदमी इसके शिकार हुए । बोलशेविक लोग, जिनपर चारों तरफ़ से हमला हो रहा था और जो चारों तरफ़ जासूसों और षड्यन्त्रों से घिरे हुए थे, ज़रासे शुबह के ऊपर घबरा जाते थे और बड़ी सख्ती से सजा देते थे । बोलशेविकों की राजनैतिक पुलिस, जिसको चेका कहते थे, इस अत्याचार के लिए बदनाम होगई । यह चेका हिन्दुस्तान की खुफ़िया पुलिस की तरह की चीज़ थी, लेकिन इसके अख्तियारात ज्यादा थे ।

यह ख़त लम्बा होता जाता है और इसे ख़त्म करने के पहले मैं तुम्हें लेनिन के बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ । अगस्त १९१८ में, जब उसकी जान लेने की कोशिश की गई थी, उसे गहरी चोट लगी थी । इसपर भी लेनिन ने ज्यादा विश्राम नहीं लिया । वह बहुत ज़ोरों के साथ काम कर रहा था और १९२२ की मई में उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया, जो अनिवार्य था । कुछ दिन आराम करने के बाद उसने फिर काम शुरू कर दिया, लेकिन ज्यादा दिनों तक काम नहीं कर सका । १९२३ में उसका स्वास्थ्य पहले से भी ज्यादा ख़राब होगया और इस बीमारी से वह नहीं बच सका । २१ जनवरी १९२४ को मास्को के नज़दीक उसका प्राणान्त होगया ।

बहुत दिनों तक उसका शरीर मास्को में रक्खा रहा । जाड़े का मौसम था और रासायनिक पदार्थों से शरीर को सुरक्षित रक्खा गया था । सारे रूढ़-भर से और

साइबेरिया के दूर-दराज मैदानों से जन-साधारण के प्रतिनिधि आते थे—किसान और मजदूर मर्द, औरत और बच्चे—और अपने प्यारे कामरेड यानी साथी को, जिसने उन्हें गहरे गड्ढे से बाहर निकाला था और अधिक खुशहाल जिन्दगी की तरफ जाने का रास्ता दिखाया था, अन्तिम सम्मान और आदर देकर चले जाते थे। इन लोगों ने मास्को के सुन्दर रेड स्क्वायर में एक सीधा-सादा और श्रृंगार-शून्य मक़बरा उसके लिए बना दिया है और एक शीशे के बक्स में उसका शरीर अभीतक रक्खा हुआ है। हर शाम को वहाँपर लोगों का ताँता लगा रहता है और लोग चुपचाप उसका दर्शन करके चले जाते हैं। लेनिन को मरे हुए अभी दस वर्ष भी नहीं हुए, फिर भी वह अपनी मातृभूमि रूस में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में एक प्रबल सिद्धान्त बन गया है। ज्यों-ज्यों ज़माना गुज़रता है, लेनिन महत्तर बनता जाता है। वह संसार के अमर लोगों की टोली का एक सदस्य होगया है। पेट्रोग्रेड का नाम लेनिनग्रेड होगया और रूस में क़रीब-क़रीब हर घर में लेनिन के लिए एक कोना मुक़र्रर है या लेनिन की तस्वीर है। लेकिन लेनिन ज़िन्दा है—तस्वीरों और यादगारों के रूप में नहीं, बल्कि उस विशाल कार्य के रूप में, जो उसने करके दिखा दिया। लेनिन ज़िन्दा है करोड़ों मजदूरों के हृदय में, और उसका उदाहरण उनकी जिन्दगी में नई जान फूँकता है, जिसकी वजह से उन्हें बेहतर दिन देखने की आशा है।

यह न समझ लेना कि लेनिन कोई अमानुषी मशीन था जो अपने काम में लगा रहता था और किसी दूसरी बात का ख़याल नहीं करता था। निस्सन्देह वह अपने काम में और अपने जीवन के उद्देश्य में विलकुल तल्लीन था, फिर भी उसे अहंकार नहीं था। वह एक सिद्धान्त की मूर्ति था, फिर भी वह मनुष्य-जैसा था, और सबसे बड़ा मानुषी गुण उसमें यह था कि वह दिल खोलकर हँस सकता था। लॉक हार्ट मास्को में अंग्रेज़ों का एजेण्ट था और उस ज़माने में, जबकि सोवियट खतरे में थी, वह वहीं रहता था। उसने लिखा है कि, चाहे जो हो लेनिन हमेशा हँसमुख दिखाई देता था। “मुझे जितने सार्वजनिक नेताओं से कभी भी मिलने का मौक़ा मिला है उन सबमें लेनिन का स्वभाव मुझे सबसे ज्यादा निर्लेप मालूम हुआ। वह अपनी बातचीत और अपने काम में सरल और स्पष्ट, लम्बी-चौड़ी बातों और दिखावे से नफ़रत करनेवाला था। वह संगीत का प्रेमी था—इतना प्रेमी कि अक्सर वह डरा करता था कि संगीत-प्रेम की वजह से कहीं उसके ऊपर बुरा असर न पड़ जाय और वह अपने काम-काज में मुलायम न हो जाय।”

लेनिन के एक साथी ने, जिसका नाम लूना चास्की था और जो कई वर्षों तक बोलशेविकों के शिक्षा-विभाग का कमीसार यानी मंत्री रह चुका था, लेनिन के बारे

में एक दफ़ा एक अजीब बात कही थी। वह कहता था कि पूंजीपतियों के प्रति लेनिन का व्यवहार बिल्कुल वैसा ही है जैसा हज़रत ईसा का ख़या उधार देनेवालों के प्रति था, जिन्हें उसने मन्दिर से निकाल दिया था। वह कहता था कि अगर हज़रत ईसा आज ज़िन्दा होते तो बोलशेविक होते। ग़ैर-मज़हबी आदमियों के लिए यह उपमा बड़ी आश्चर्यजनक है।

लेनिन ने एक दफ़ा स्त्रियों के बारे में कहा था—“कोई मुल्क आज़ाद नहीं हो सकता, जबकि आधी आबादी रसोईघर में क़ैद रहे”। एक दफ़ा वह कुछ वक्त्रों को खिला रहा था, तब उसने एक बहुत अच्छी बात कही। उसके पुराने दोस्त मैक्सिम गोर्की ने लिखा है कि उसने कहा—“इन लोगों की ज़िन्दगियाँ हम लोगों से ज्यादा आनन्दमय होंगी। इन्हें उन सब बातों का अनुभव नहीं करना पड़ेगा, जिसको हम सह चुके हैं। इनकी ज़िन्दगी में इतनी निर्दयता नहीं पाई जायगी।” निस्सन्देह हम सबको ऐसी ही आशा करनी चाहिए।

मैं इस ख़त को हाल के एक रूसी छन्द को देकर ख़त्म करूँगा। यह कोरस में गाने के लिए है। जिन लोगों ने इस संगीत को सुना है, वे कहते हैं कि इसमें जीवन और शक्ति भरी हुई है और यह गाना क्रान्तिकारी जनता की भावना का प्रतिरूप है। इसके अंग्रेज़ी अनुवाद में भी इस भावना की कुछ पुट आजाती है। इस गाने का नाम ‘अक्तूबर’ है, जिसका मतलब है नवम्बर सन् १७ की बोलशेविक क्रान्ति। उस ज़माने में रूस का पंचांग असंशोधित था और पश्चिमी पंचांग से १३ दिन पीछे था। इस पंचांग के अनुसार मार्च सन् १७ की क्रान्ति फरवरी में हुई थी। इसलिए इसे फरवरी की क्रान्ति कहते हैं और इसी तरह बोलशेविक क्रान्ति, जो नवम्बर सन् १७ की शुरुआत में हुई, अक्टूबर की क्रान्ति कहलाती है। रूस ने अपना पंचांग अव बदल दिया है और संशोधित पंचांग चलाया है; लेकिन ये पुराने नाम अभी तक जारी हैं।

‘अक्टूबर’ गीत का अंग्रेज़ी अनुवाद यह है :

We went, asking for work and for bread,
Our hearts were oppressed with anguish,
The chimneys of the factories pointed toward the sky,
like tired hands without strength to make a fist.
Louder than the common, the silence was broken by the words
of our grief and our pain.
O Lenin! the desire of calloused hands.
We have understood, Lenin, we have understood that our lot is
a struggle ! Struggle ! Struggle !
You led us to the last fight. Struggle !

You gave us the victory of labour.

And no one shall take away from us this victory over ignorance and oppression.

No one ! No one ! Never ! Never !

Let everyone be young and brave in the struggle, because the name of our victory is October !

October ! October !

October is a messenger from the sun.

October is the will of the revolting centuries !

October ! It is a labour, it is a joy and a song.

October ! It is good fortune for the fields and machines !

Here is the banner name of the young generation and Lenin !

अर्थात्, “हम रोटी और काम की भीख मांगते ही जाते थे। हमारे हृदय दुःख से पीड़ित और शिथिल थे। अँगूठा दिखाने की ताकत से हीन हाथों की तरह कारखानों की चिमनियाँ आकाश की तरफ़ इशारा कर रही थीं। हमारे दुःख और दर्द के शब्दों से शान्ति, मामूली तरीक़े की वनिस्वत कहीं ज्यादा, भंग हो रही थी। टूटे हुए हाथों की आकांक्षा-सा ओ लेनिन ! हमने समझ लिया है; लेनिन, हमने समझ लिया है कि हमें लड़ना, लड़ना और लड़ना है। तुमने अंतिम लड़ाई तक हमें पहुँचाया। तुमने हमें श्रमिकों की विजय दी और कोई अज्ञान और अत्याचार पर उस विजय को हमसे छीन नहीं सकता। कोई नहीं ! कोई नहीं ! कभी नहीं ! कभी नहीं ! लड़ाई में, संघर्ष में हरेक को युवा और बहादुर होने दो; क्योंकि हमारी विजय का नाम ‘अक्टूबर’ है। अक्टूबर ! अक्टूबर ! अक्टूबर सूर्य का संदेश-वाहक है। अक्टूबर विद्रोही शताब्दियों का संकल्प है। अक्टूबर ! यह श्रम है, आनन्द है, गान है। अक्टूबर ! यह खेतों और मशीनों का सौभाग्य है। यह युवा पीढ़ी और लेनिन के नाम का झण्डा है।”

: १५३ :

जापान चीन को दबाता है

१४ अप्रैल, १९३३

जिस समय महायुद्ध चल रहा था, सुदूर पूर्व के देशों में कुछ घटनाएँ ऐसी हुईं जिनपर ध्यान देना हमारे लिए ज़रूरी है। इसलिए अब मैं तुम्हें चीन की बात बताऊँगा। चीन के बारे में अपने पिछले ख़त में मैंने तुम्हें चीन में प्रजातंत्र के स्थापित होने की बात बताई थी और उन झगड़ों का भी जिक्र किया था जो इसके बाद हुए। फिर से साम्राज्य क़ायम करने की कोशिशों की गईं। लेकिन वे नाकाम-याब रहीं। प्रजातंत्र भी सारे देश पर अपनी हुकूमत क़ायम करने में नाकामयाब रहा,

या यों कहो कि कोई एक संरकार सारे देश में हुक्मत क्रायम नहीं कर सकी। उस वक्त से अभीतक कोई एक शासन ऐसा नहीं बन सका जिसने सारे चीन पर बेखटके शासन किया हो। कुछ सालों से इस देश में दो मुख्य सरकारें क्रायम रही हैं—दक्षिण में डाक्टर सनयात सेन और उनका राष्ट्रीय दल काउ-मिन-तांग हावी था। उत्तर में युआन-शी-काई सेनापति था और इसके बाद सेनापतियों और सैनिकों का एक ताँता था। इन सैनिक दुस्साहसियों को तूशन कहते थे और हाल के सालों में ये लोग चीन की जान पर आकृत रहे हैं।

चीन इस तरह लगातार अशान्ति और अव्यवस्था की दुःखद अवस्था में रहा और अकसर उत्तर और दक्षिण में या तूशनों में गृह-युद्ध होते रहे। साम्राज्यवादी शक्तियों के लिए बहुत बढ़िया अवसर था। इन्होंने साजिशें शुरू कीं और कभी एक पार्टी या एक तूशन की सहायता करके और कभी दूसरे तूशन को मदद करके आपस की फूट से ये शक्तियाँ क्रायदा उठाने की कोशिश करने लगीं। तुम्हें याद होगा कि अंग्रेजों ने हिन्दुस्तान में भी इसी तरह अपना राज्य क्रायम किया था। यूरोपियन शक्तियों ने इस अवसर से क्रायदा उठाया और एक तूशन को दूसरे तूशन से लड़ाने लगीं। लेकिन सुदूर पूर्व में इनकी ये हरकतें इनकी अपनी खुद की मुसीबतों और महायुद्ध के कारण बहुत जल्द रुक गईं।

लेकिन जापान का यह हाल नहीं हुआ। युद्ध की खास लड़ाई बहुत दूर हो रही थी और जापान ने यह देखा कि चीन में वह अपनी पुरानी कारगुजारियाँ बिल्कुल निर्विघ्न जारी रख सकता है। सच तो यह है कि उस हालत में उसे बहुत अच्छा मौका मिल गया, क्योंकि दूसरी शक्तियाँ और कामों में लगी हुई थीं और हस्तक्षेप नहीं कर सकती थीं। उसने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा सिर्फ इसलिए करदी कि चीन में क्यानचांग में जर्मनों को जो अधिकार मिले हुए थे, वह छीन ले और चीन के अन्दर और आगे बढ़ सके।

चीन के बारे में जापान की नीति पिछले ४० वर्षों से एकसमान रही है। ज्योंही उसकी सेना नये ढंग से संगठित होगई और उसने अपने देश के व्यवसायों की उन्नति करली, उसने यह निश्चय कर लिया कि अब जापान को चीन पर प्रभुत्व जमा लेना चाहिए। उसको फैलने के लिए और अपने व्यवसायों को बढ़ाने के लिए विस्तार की ज़रूरत थी। कोरिया और चीन दोनों ही नजदीक थे और कमजोर थे, मानों अपने शोषण और गुलामी के लिए दुनिया को निमंत्रित कर रहे हों। जापान की पहली कोशिश १८९४-९५ में हुई, जबकि उसने चीन से लड़ाई शुरू की। वह कामयाब हुआ; लेकिन इतना नहीं, जितना चाहता था; क्योंकि यूरोपियन शक्तियों

ने मुख्तारलफ़्त की। फिर १९०४ में रूस के साथ संघर्ष हुआ, जो ज्यादा कठोर था। इसमें भी वह कामयाब रहा और कोरिया और मंचूरिया में मजबूती से जम गया। उसके थोड़े दिन बाद ही कोरिया पर कब्ज़ा कर लिया गया और कोरिया जापानी साम्राज्य का एक अंग बन गया।

मंचूरिया फिर भी चीन का हिस्सा बना रहा। यह देश चीन के तीन पूर्वीय प्रांतों में से है। जापानियों ने इस देश में सिर्फ़ उन सब रियायतों को अपने हाथ में ले लिया जो रूसियों को मिली हुई थीं; उस रेलवे पर भी कब्ज़ा कर लिया, जो रूसियों ने बनाई थी और जिसे उस वक़्त 'चीनी ईस्टर्न रेलवे' कहते थे। इस रेलवे का नाम बदलकर 'दक्षिणी मंचूरियन रेलवे' कर दिया गया। अब जापान ने मंचूरिया को मजबूती से दबोचना शुरू किया। इसी दरमियान चीन के बाक़ी घने बसे हुए हिस्से के लोग इस रेलवे की वजह से इधर झुके और चीनी किसान इस प्रदेश में टूट पड़े। सोयाबीन नाम की चीज़ मंचूरिया में ख़ूब पैदा होती है और इस चीज़ के गुणों की वजह से सारे संसार में इसकी माँग बढ़ी। इससे एक क्रिस्म का तेल भी पैदा होता है। इस सोयाबीन की खेती के लिए बहुत से लोग आकर बसने लगे। इस तरह इधर जापानी लोग ऊपर से मंचूरिया की आर्थिक मशीन पर पूरा-पूरा अधिकार पाने की कोशिश कर रहे थे, उधर चीनी लोग दक्षिण से फटे पड़ते थे और देश में बसते जा रहे थे। पुराने मंचू लोग चीनी किसानों की इस बाढ़ में बिल्कुल डूब गये और अपनी संस्कृति में और दृष्टिकोण में पूरे-पूरे चीनी होगये।

जापान को चीन में प्रजातंत्र का आगमन पसन्द नहीं आया। उसे हरेक चीज़, जिससे चीन को मजबूती मिल सकती थी, नापसन्द थी, और उसकी कूटनीतिज्ञता का सारा उद्देश्य यही था कि कहीं चीन सुसंगठित होकर एक मजबूत राज्य न बन जाय। इसलिए वह एक तूशन की मदद करके दूसरे तूशन के खिलाफ़ उसे लड़ाने में बहुत दिलचस्पी लेता रहा, जिससे देश के अन्दर बदअमनी कायम रहे।

जापान पर या पश्चिमी शक्तियों पर इस बात के लिए दोषारोपण करना सरल है कि उन्होंने इस बात की जान-बूझकर कोशिश की कि चीन में शान्ति न हो सके। दोष उनका ज़रूर है, फिर भी असल वजह चीन की खुद अपनी कमज़ोरी थी, जैसे हिन्दुस्तान में जब-जब अंग्रेज़ी सरकार राष्ट्रीय दल के अन्दर फूट पैदा करने में सफल रही है तब-तब असली कारण राष्ट्रवादियों की कमज़ोरी ही रहा है। सिर्फ़ यह बात कि अंग्रेज़ फूट कराने की इस नीति में सफल हुए, इस बात की परिचायक है कि कम-से-कम इस विषय में ये लोग सबसे आगे बढ़े हुए हैं।

चीन के नवजात प्रजातंत्र के सामने बड़ी-बड़ी भीषण समस्याएँ थीं। सवाल

सिर्फ इतना ही नहीं था कि मृतप्राय शाही सरकार से राजनैतिक सत्ता छीन ली जाय, क्योंकि कोई राजनैतिक सत्ता छीनने को बाक़ी ही नहीं थी। कोई केन्द्रीय शक्ति थी ही नहीं। उसे तो पैदा करना था। पुराना चीन नाम मात्र के लिए साम्राज्य था, वास्तव में वह अनेक स्वशासित क्षेत्रों का समूह था, जो बहुत कमजोरी के साथ आपस में बँधे हुए थे। प्रान्त कोई कम कोई ज्यादा स्वतंत्र थे, और इसी प्रकार क़स्बे और शहर। केन्द्रीय सरकार या सम्राट की हुकूमत लोग मानते थे, लेकिन यह सरकार स्थानीय मामलों में दख़ल नहीं देती थी। कोई यूनिटरी स्टेट यानी ऐसी सरकार नहीं थी जिसके हाथ में सब प्रान्तों को एक शासन में जोड़ने की शक्ति होती और जो सारे देश में एक नीति से हुकूमत चला सकती। राजनैतिक दृष्टिकोण से असल में यह राज्य बड़ी कमजोरी से बँधे हुए प्रदेशों का समूह था, जो पश्चिमी उद्योगों और साम्राज्यवादियों की लालच के सम्पर्क से बिखर रहा था। लोग महसूस करते थे कि अगर चीन को ज़िन्दा रहना है तो उसे एक मज़बूत केन्द्रीय राज्य होना चाहिए, जिससे शासन की प्रणाली सब जगह एक-सी हो। नया प्रजातंत्र इसी किस्म का राज्य क़ायम करना चाहता था। यह एक नई चीज़ थी और इसलिए प्रजातंत्र के सामने यह एक बहुत बड़ी समस्या बन गई। चीन में सड़क, रेलवे और आमदरफ़्त के उपयुक्त साधन नहीं थे। इसकी वजह से उसकी राजनैतिक एकता में बड़ी भारी अड़चन पड़ती थी।

पुराने ज़माने में चीन के लोग राजनैतिक शक्ति को ज्यादा महत्व नहीं देते थे। उनकी सारी विशाल सभ्यता संस्कृति पर निर्भर थी और वह जीवन-यात्रा की कला ऐसे ढंग से सिखाती थी जिस ढंग से पहले कभी नहीं सिखाई गई। चीनी लोग अपनी इस पुरानी संस्कृति में इतने डूबे हुए थे कि जब इनका राजनैतिक और आर्थिक ढाँचा दिखरा तब भी ये अपनी पुरानी संस्कृति के रस्म-रिवाजों से चिपटे रहे। जापान ने जान-बूझकर पश्चिमी सभ्यता और पश्चिमी रंग-ढंग अख़्तियार किया था और फिर भी वह दिल में सामन्तवादी था। चीन सामन्तवादी नहीं था; वह बुद्धिवाद और वैज्ञानिक भावना से परिपूर्ण था। विज्ञान और व्यवसाय में पश्चिम की उन्नति की तरफ़ वह बड़े कौतूहल से देखता था, फिर भी वह उधर नहीं झुका जिधर जापान झुका। इसमें शक नहीं कि चीन के रास्ते में बहुत-सी ऐसी कठिनाइयाँ थीं जो जापान के रास्ते में नहीं थीं। लेकिन चीन के दिल में एक संकोच भी था और वह यह कि कोई बात ऐसी न करो जिससे पुरानी संस्कृति से बिल्कुल नाता टूट जाय। चीन का मिज़ाज फ़िलासफ़ों यानी दार्शनिकों का मिज़ाज था और फ़िलासफ़ लोग तेज़ी से कान नहीं करते। उसके मन में बहुत जोरदार उवाल पैदा होगया था और

है, क्योंकि जिन समस्याओं का उसे मुकाबिला करना था वे केवल राजनैतिक समस्यायें ही नहीं थीं बल्कि आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, शिक्षा-सम्बन्धी और दूसरे प्रकार की भी थीं।

और फिर दूसरी बात यह भी है कि चीन और हिन्दुस्तान ऐसे विशाल देशों के विस्तार की वजह से ही कठिनाइयाँ पैदा होजाती हैं। ये देश महाद्वीप के समान हैं और महाद्वीपों में जो बोल होता है वह इन देशों में भी पाया जाता है। जब कोई हाथी गिर पड़ता है तो उसको उठाने में देर लगती है। विल्ली या कुत्ते की तरह वह कूदकर नहीं बैठ जाता।

जब महायुद्ध शुरू हुआ, जापान तुरन्त मित्र-राष्ट्रों के साथ शामिल होगया और जर्मनी से लड़ाई का ऐलान कर दिया। उसने कियानचान पर कब्जा कर लिया और शांटुंग प्रान्त पर, जिसमें कियानचान स्थित है, अन्दर की तरफ फैलने लगा। इसका मतलब यह था कि जापानी खास चीन पर हमला कर रहे हैं। इसमें जर्मनी के खिलाफ लड़ने का कोई सवाल नहीं था, क्योंकि जर्मनी का इस इलाके से कोई ताल्लुक नहीं था। चीनी सरकार ने नम्रतापूर्वक उनसे चले जाने को कहा। जापानियों ने कहा—‘यह उद्दण्डता है, और झट २१ माँगों का एक सरकारी खरीता पेश कर दिया।

ये ‘२१ माँगों’ मशहूर होगई। मैं यहाँ उन्हें नहीं लिखूँगा। उनका तात्पर्य यह था कि चीन में—खास तौर पर मंचूरिया, मंगोलिया और शांटुंग प्रान्तों में—सब तरह के अधिकार और सुविधायें जापान के सुपुर्द कर दी जायें। इन माँगों को मंजूर कर लेने से चीन अमली तौर पर जापान की एक बस्ती या उपनिवेश होजाता। कमजोर उत्तरी चीनी सरकार ने इन माँगों पर एतराज किया, पर वह ताकतवर जापानी क्राँज के खिलाफ क्या कर सकती थी? और फिर उत्तर की यह चीनी सरकार खुद भी जनता में लोकप्रिय नहीं थी। फिर भी उसने एक काम किया, जिससे मदद मिली। उसने जापानी माँगों को प्रकाशित कर दिया। इससे तुरन्त ही चीन में जबरदस्त विरोध खड़ा हो गया, और दूसरी शक्तियाँ भी, यद्यपि वे लड़ाई में मशगूल थीं, घबरा गईं। अमेरिका ने खास तौर पर विरोध किया। इसका नतीजा यह निकला कि जापान ने कुछ माँगें हटालीं और कुछ में तरमीम करके उन्हें हलका बना दिया और चीनी सरकार को उन्हें मई १९१५ में मंजूर कर लेने पर मजबूर किया। इससे चीन में जापान के खिलाफ जबरदस्त भावना पैदा होगई।

अगस्त १९१७ में, यानी महायुद्ध शुरू होने के तीन वर्ष बाद, चीन मित्र-राष्ट्रों में शामिल होगया और उसने भी जर्मनी के खिलाफ लड़ाई का ऐलान कर

दिया। यह एक हास्यास्पद बात थी, क्योंकि चीन जर्मनी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। उसका मतलब असल में मित्र-राष्ट्रों की सद्भावना प्राप्त करना और यों जापान के भावी खतरों से अपनी रक्षा करना था।

इसके थोड़े ही दिन बाद, नवम्बर १९१७ में, बोलशेविक क्रांति आगई और इसके पश्चात् सारे उत्तरी एशिया में बड़ी अव्यवस्था फैल गई। साइबेरिया सोवियट और सोवियट-विरोधी शक्तियों के बीच एक युद्धभूमि यानी मैदानेजंग बन गया। 'सफ़ेद' रूसी जनरल कोलचक सोवियट के खिलाफ़ साइबेरिया से ही लड़ता था। सोवियट-विजय से घबराकर जापानियों ने साइबेरिया में एक बड़ी फ़ौज भेजी। ब्रिटिश और अमेरिकन फ़ौजें भी वहाँ भेजी गईं। कुछ वक्त के लिए साइबेरिया और मध्य-एशिया से रूस का प्रभाव नष्ट होगया। ब्रिटिश सरकार ने तो इन इलाक़ों से रूस की मर्यादा को एकदम नष्ट कर देने की दिलोजान से कोशिश की। मध्य-एशिया के हृदय काशगार में अंग्रेज़ों ने बोलशेविकों के खिलाफ़ प्रचार करने के लिए एक वेतार के तार का स्टेशन भी खोल दिया।

मंगोलिया में भी सोवियट और सोवियट-विरोधी लोगों में एक खूँखार लड़ाई हुई। १९१५ में, जब महायुद्ध जारी था, जारशाही रूस की मदद से मंगोलिया ने चीन-सरकार से आन्तरिक मामलों में काफ़ी आजादी हासिल करली थी। फिर भी चीन का उत्तपर प्रभुत्व तो था ही और मंगोलिया के वैदेशिक सम्बन्धों की दृष्टि से रूस को भी वहाँ पैर जमाने का मौक़ा मिल गया था। यह एक अजीब व्यवस्था थी। सोवियट राजक्रांति के बाद मंगोलिया में गृह-युद्ध शुरू होगया और तीन वर्ष या उससे भी ज्यादा वक्त तक लड़ने के बाद वहाँ की सोवियट जीत गई। मंगोलिया की वर्तमान स्थिति तो और भी अजीब है। यह सोवियट यूनियन से सम्बद्ध एक स्वतंत्र प्रजातंत्र है, फिर भी, मेरा ख़याल है कि, यह चीन की छत्रछाया को मानता है।

मैंने महायुद्ध के बाद होनेवाले शान्ति-सम्मेलन के बारे में अभीतक नहीं बताया है। उसका ज़िक्र फिर एक दूसरे ही खत में करना पड़ेगा। फिर भी यहाँ मैं इतना कहूँ कि इस कांफ़्रेंस या सम्मेलन में बड़ी ताक़तों ने, जिनसे खासतौर पर इंग्लैंड, फ़्रांस और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का मतलब होता है, तय किया कि चीन का शांटुंग प्रान्त जापान को दे दिया जाय। यों महायुद्ध के फल-स्वरूप उन्हींके मित्र चीन को अपने देश का एक हिस्सा जापान को दे देने को मजबूर किया गया। इसकी वजह युद्ध के जमाने में इंग्लैंड, फ़्रांस और जापान के बीच हुई एक गुप्त संधि थी। कारण कुछ भी रहा हो, चीन के साथ इस तरह की धोखेवाजी को चीनी राष्ट्र ने बहुत नापसन्द किया और चीन के लोगों ने पेंकिंग की सरकार से साफ़-साफ़ कह दिया कि

अगर वह इस मामले में समझौता करेगी तो क्रान्ति हो जायगी। जापानी चीजों के सख्त बहिष्कार की घोषणा कर दी गई और जगह-जगह जापान के खिलाफ दंगे हुए। चीनी सरकार (जिससे मेरा मतलब पेकिंग की उत्तरी सरकार से है, क्योंकि वही प्रधान सरकार थी) ने शांति के संधिपत्र (Peace Treaty) पर दस्तखत करने से इन्कार कर दिया।

दो वर्ष बाद संयुक्तराष्ट्र के वाशिंगटन नगर में एक कान्फ्रेंस हुई, जिसमें शांटुंग का सवाल भी उठा। इस कान्फ्रेंस में वे सब शक्तियाँ शरीक थीं जिनकी सुदूरपूर्व के सवाल में दिलचस्पी थी या स्वार्थ थे और वे अपनी जल-सेनाओं की ताकत पर बहस करने को शामिल हुई थीं। जहाँतक चीन और जापान का ताल्लुक था, १९२२ की इस वाशिंगटन कान्फ्रेंस से कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले। जापान चीन को शांटुंग लौटा देने पर राजी होगया। इस तरह एक सवाल, जो चीनी जनता को हिला रहा था, हल होगया। शक्तियों में दो और महत्वपूर्ण राजीनामे भी हुए।

इनमें से एक अमेरिका, ग्रेटब्रिटेन, जापान और फ्रांस के बीच था और 'फोर-पावर पैक्ट' (चार ताकतों का राजीनामा) के नाम से पुकारा जाता था। इन चारों ताकतों ने प्रशांतमहासागर के अपने अधिकृत स्थानों की सम्मिलित रक्षा का वादा किया, यानी इस बात का वादा किया कि वे एक-दूसरे के इलाकों पर हाथ न डालेंगे। दूसरा राजीनामा 'नाइन पावर ट्रीटी' यानी 'नौ राष्ट्रों की संधि' के नाम से मशहूर हुआ। यह कान्फ्रेंस में शामिल हुए सब राष्ट्रों के बीच था। इसमें ये नौ राष्ट्र थे—संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, बेलजियम, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान, हालैण्ड, पोर्चुगाल और चीन। इस संधि की पहली धारा इन शब्दों के साथ शुरू हुई थी:—

“To respect the sovereignty, the independence and the territorial and administrative integrity of China.....”

अर्थात् “चीन के प्रभुत्व, स्वतंत्रता और प्रादेशिक एवं शासन संबंधी अखंडता या एकता के सम्मान के लिए.....”

मैं तुम्हें 'फोर पावर पैक्ट' और 'नाइन पावर ट्रीटी' के बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि ये दोनों बातें इस वक्त बार-बार हमारे सामने आ रही हैं और अखबारों में अकसर उनका जिक्र किया जाता है। ये दोनों राजीनामे चीन को भावी आक्रमणों से बचाने के लिए थे। वे सहूलियतें हासिल करने और इलाकों को हड़प लेने के पुराने खेल को, जो अबतक शक्तियाँ खेलती रही थीं, बन्द करने की गरज से किये गये थे। पश्चिमी ताकतें महायुद्ध के बाद के अपने ही सवालों को हल करने में मशगूल थीं और उस वक्त चीन में उनकी कोई दिलचस्पी न थी। इसीलिए आत्म-नियंत्रण का

यह आर्डिनेंस पैदा हुआ जिसको लेकर उन्होंने पवित्र शपथ ग्रहण की। जापान भी इस प्रतिज्ञा में शामिल हुआ, यद्यपि यह बात उसकी उस नीति के खिलाफ पड़ती थी जो वह कई वर्षों से चला रहा था। पर बहुत साल नहीं बीते थे कि यह बात स्पष्ट होगई कि सारे राजीनामों और वादों के बावजूद जापान की पुरानी नीति जारी है। अन्तर्राष्ट्रीय पाखण्ड और झूठ का यह एक असाधारण उदाहरण रहा है। जब मैं यह खत लिख रहा हूँ, चीन पर जापान का हमला जारी है। जो कुछ हो रहा है, उसके पार्श्वचित्र को समझाने के लिए ही मैं तुम्हें वॉशिंगटन कान्फ्रेंस तक ले गया था।

वॉशिंगटन कान्फ्रेंस के वक्त के करीब ही साइबेरिया से विदेशी फ़ौजें अन्तिम रूप में हटाई गईं। जापानी सबसे अखीर में गये। तुरंत ही वहाँ सोवियट बन गई और रूस के सोवियट प्रजातंत्र संघ में शामिल होगई।

रूसी सोवियट ने जन्म के कुछ ही दिनों बाद चीनी सरकार को सूचित कर दिया था कि दूसरी साम्राज्यवादी ताकतों के साथ जारशाही रूस को चीन से जो खास सहूलियतें मिली थीं उन सबको वह छोड़ देने को तैयार है। साम्राज्यवाद और साम्यवाद साथ-साथ नहीं चल सकते और इसके अलावा भी सोवियट ने पूर्वी देशों के प्रति, जो पश्चिमी शक्तियों द्वारा बहुत दिनों से शोषित हो रहे थे, जानबूझकर उदारता-पूर्ण नीति इस्तिथार की थी। यह सिर्फ सदाचरण ही नहीं था बल्कि सोवियट रूस के लिए अच्छी और मुनासिब नीति भी थी, क्योंकि इस नीति ने पूर्व में उसके कई मित्र पैदा कर दिये। सहूलियतें छोड़ देने का सोवियट रूस का प्रस्ताव बिना किसी शर्त के था; उसने उसके बदले कोई मांग नहीं की। इतने पर भी चीनी सरकार सोवियट से व्यवहार करने में डरती थी कि कहीं पश्चिमी योरप की शक्तियाँ नाराज न हो जायें। पर आखिरकार रूसी और चीनी प्रतिनिधि मिले और १९२४ में उनके बीच एक राजीनामा हुआ। जब इस राजीनामे का पता चला तो फ़्रांसीसी, अमेरिकन और जापानी सरकारों ने पेकिंग की सरकार के पास अपना विरोध ज़ाहिर किया और पेकिंग सरकार इतनी डर गई कि उसने राजीनामे पर किये हुए अपने प्रतिनिधियों के दस्तखत से इनकार कर दिया। ऐसी बुरी खाई में पेकिंग सरकार पड़ गई थी। इसपर रूसी प्रतिनिधि ने राजीनामे का सारा मस्विदा छाप दिया। इससे बड़ी तनसनी फैली। शक्तियों के सम्पर्क में पहली बार चीन के साथ आदर और सम्मान का व्यवहार किया गया था और उसके अधिकार स्वीकार किये गये थे। यह एक बड़ी शक्ति से उसकी पहली बराबरी की संधि थी। चीनी जनता इससे खुश हुई और सरकार को इसपर दस्तखत करने पड़े। साम्राज्यवादी ताकतों का इसे नापसंद करना लाजिमी था, क्योंकि इन्होंने उन्हें बड़े बुरे रूप में दुनिया के सामने पेश किया। जब

सोवियट रूस ने उदारता के साथ सब सहूलियतें छोड़ दीं, तब वे अपनी सब विशेष सुविधाओं से चिपटी रहीं।

सोवियट सरकार ने डॉ० सनयातसेन की दक्षिणी चीन की सरकार से भी; जिसकी राजधानी कैंटन थी, बातचीत शुरू की और दोनों में एक समझौता हुआ। इस दरमियान एक तरह का हल्का गृह-युद्ध उत्तर और दक्षिण के बीच, और उत्तर के मुस्लिम सिपहसालारों में, जारी था। ये उत्तरी तूशन, या महातूशन जैसा कि कुछ कहे जाते थे, किसी कार्यक्रम या सिद्धान्त के लिए नहीं लड़ते थे; वे अपनी निजी सत्ता के लिए लड़ते थे। कभी-कभी कई मिलकर एक संगठन बना लेते और दूसरे पक्ष से लड़ते थे। पर इनका पक्ष बदलता रहता था और बाहर के लोगों को इन सदा बदलते रहनेवाले संगठनों से बड़ी हैरत होती थी। ये तूशन, या फ़ौजी जांबाज, अपनी निजी फ़ौजें खड़ी करते थे, प्राइवेट टैंक्स लगाते थे और अपनी निजी लड़ाइयाँ जारी रखते थे; और इन सबका बोझ बहुत दिनों से दुःख पानेवाली देवचारी चीनी जनता पर पड़ता था। यह कहा जाता था कि इन बड़े तूशनों में से कुछ के पीछे विदेशी ताकतें थीं। खास तौर पर जापान का नाम लिया जाता था। शंघाई की बड़ी-बड़ी व्यापारिक पेड़ियों से भी उनके पास दौलत और मदद आती थी।

बस एक प्रकाश का स्थान दक्षिण था, जहाँ सनयातसेन की सरकार कायम थी। उसके अपने आदर्श थे, अपनी एक नीति थी, और यह लुटेरों का मामला नहीं था जैसा कि उत्तरी तूशनों की कई सरकारें थीं। १९२४ में काउ-मिन-तांग यानी जनता के दल का प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ और डॉ० सन ने उसके सामने एक मैनीफेस्टो यानी घोषणापत्र पेश किया। इस मैनीफेस्टो में उन्होंने उन सिद्धान्तों को लिखा था, जिनके अनुसार वह राष्ट्र को चलाना चाहते थे। यह मैनीफेस्टो और ये सिद्धान्त तबसे काउ-मिन-तांग का आधार रहे हैं और यह समझा जाता है कि अब भी राष्ट्रीय सरकार की आम नीति उसीके मुताबिक चलाई जाती है।

मार्च १९२५ ई० में, चीन की सेवा में अपनी जिन्दगी गुजारने और चीनी जनता का प्रेमपात्र होने के बाद, डॉ० सनयातसेन की मृत्यु हुई।

युद्ध-काल में भारत

१६ अप्रैल, १९३३

ब्रिटिश साम्राज्य का एक हिस्सा होने के नाते हिन्दुस्तान का महायुद्ध से सीधा ताल्लुक था। पर हिन्दुस्तान के अन्दर या उसके आस-पास कहीं वास्तविक युद्ध नहीं लड़ा जा रहा था। फिर भी महायुद्ध ने हिन्दुस्तान के मामलों पर कई तरह से असर डाला। यह असर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह का था। इसकी वजह से यहाँ बहुतेरी तब्दीलियाँ हुई। मित्र-राष्ट्रों की मदद करने में उसके साधनों का पूरी तरह इस्तेमाल किया गया।

यह हिन्दुस्तान की लड़ाई न थी। हिन्दुस्तान की जर्मन शक्तियों से कोई दुश्मनी न थी, बल्कि तुर्की के साथ तो काफ़ी हमदर्दी भी थी। पर इस मामले में हिन्दुस्तान के लिए कोई चारा न था। वह सिर्फ ब्रिटेन का एक मातहत देश था, इसलिए उसे भी अपने साम्राज्यवादी मालिक के साथ क़तार में खड़ा होने को मजबूर होना पड़ा। इस तरह, देश में काफ़ी विरोध होने के बावजूद, हिन्दुस्तानी सिपाहियों को तुर्कों, मित्रियों और दूसरों के खिलाफ़ लड़ना पड़ा, जिससे एशिया में हिन्दुस्तान का नाम बहुत ही नापसन्द किया जाने लगा और उसकी बड़ी बदनामी हुई।

जैसा मैंने तुम्हें किसी पहले के ख़त में बताया है, महायुद्ध के शुरू में हिन्दुस्तान में राजनीति शिथिल-सी थी। लड़ाई शुरू हो जाने से लोगों का ध्यान राजनीति की तरफ़ से और ज्यादा हट गया और फिर युद्ध के जमाने में जारी किये हुए नियमों, प्रतिबन्धों और दूसरे बन्धनों के कारण वास्तविक राजनैतिक काम बहुत मुश्किल हो गया। युद्ध का जमाना सरकारों के लिए हरेक को दवाने और अपनी मनमानी करने का अक्षर काफ़ी बड़ा बहाना बन जाता है। अगर कोई छूट होती है तो सिर्फ़ खुद उनके लिए होती है; वे जो चाहें कर सकती हैं। सेंसर बैठ जाता है, जो सत्य का गला घोट देता है; अक्षर झूठी बातों का प्रचार करता है और लोगों को अपनी राय जाहिर करने या टीका-टिप्पणी करने से रोकता है। क़रीब-क़रीब हर तरह की क़ौमी कार्रवाई पर नियंत्रण रखने के लिए ख़ास तरह के क़ानून और क़ायदे (रेगुलेशन) बनाये जाते हैं। लड़ाई में शामिल होने या लड़ने वाले सब देशों में ऐसा किया गया और लाजिमी तौर पर हिन्दुस्तान में भी ऐसा ही हुआ। यहाँ 'डिफेंस ऑफ़ इण्डिया ऐक्ट' यानी 'भारत-रक्षा क़ानून' नाम का एक क़ानून पास किया गया। इस तरह युद्ध या उससे सम्बन्ध रखनेवाली दूसरी बातों की सार्वजनिक आलोचना का दरवाज़ा

अच्छी तरह बन्द कर दिया गया। फिर भी इनके पीछे, पार्श्वभूमि में, जर्मन ताकतों और खासकर तुर्की के साथ लोगों की आम हमदर्दी थी। यह कहना शायद ज्यादा सही होगा कि लोग चाहते थे कि ब्रिटेन को मुंह की खानी पड़े। इस तरह की नपुंसक इच्छा उन लोगों के लिए स्वाभाविक थी जो खुद बुरी तरह परत कर दिये गये थे। पर इस इच्छा को सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं किया गया।

ऊपर तो हवा में चारों तरफ़ ब्रिटेन के प्रति वफ़ादारी की आवाज़ थी। ज्यादातर वफ़ादारी का यह शोर-गुल हिन्दुस्तानी राजाओं और उन मध्यम श्रेणी के कुछ लोगों के द्वारा उठता था जो सरकार के सम्पर्क में थे। कुछ हद तक बोरुआ यानी मध्यम वर्ग भी प्रजातंत्र और राष्ट्रों की स्वतंत्रता और आजादी के उन ऐलानों में, जो मित्र-राष्ट्र कर रहे थे, फँस गया था। शायद यह सोचा गया कि ये ऐलान हिन्दुस्तान पर भी लागू होंगे और उम्मीद की जाती थी कि इस वृत्त मुसीबत की घड़ियों में ब्रिटेन को जो मदद दी जायगी उसका वाद में मुनासिब इनाम मिलेगा। कुछ भी हो, हिन्दुस्तान का इस मामले में कोई बस न था और कोई दूसरा आसान रास्ता भी न था, इसलिए उसने भी बुरी चीज़ का अच्छे-से-अच्छा इस्तेमाल करना ही ठीक समझा।

हिन्दुस्तान में ऊपर-ऊपर दिखाई पड़नेवाली इस वफ़ादारी की उन दिनों इंग्लैण्ड में बड़ी तारीफ़ हुई और बार-बार कृतज्ञता भी प्रकट की गई। जिन लोगों के हाथ में सत्ता थी उन्होंने कहा कि इसके बाद इंग्लैण्ड हिन्दुस्तान को 'नये दृष्टिकोण' से देखेगा।

पर हिन्दुस्तान में भी और विदेशों में भी कुछ हिन्दुस्तानी ऐसे थे जिन्होंने 'वफ़ादारी' का यह रुख इस्तिहार नहीं किया। वे, बहुमत की तरह, चुपचाप बैठे भी नहीं रहे। पुरानी आयरिश कहावत के मुताबिक़ उनका विश्वास था कि इंग्लैण्ड की मुसीबत ही उनके देश के लिए सुअवसर है। खास तौर पर जर्मनी और योरप के दूसरे मुल्कों में रहनेवाले कुछ हिन्दुस्तानी बर्लिन में इसलिए इकट्ठे हुए कि इंग्लैण्ड के दुश्मनों को मदद देने के उपाय किये जायें और इसके लिए एक कमेटी भी बनाई। जर्मन सरकार, स्वाभाविक रूप से, हर तरह की मदद हासिल करने को उत्सुक थी। इसलिए उसने इन हिन्दुस्तानी क्रान्तिकारियों का स्वागत किया। बाकायदा एक राजीनामा लिखा गया और उसपर दोनों पक्षों—जर्मन सरकार और हिन्दुस्तानी कमेटी—की तरफ़ से दस्तख़त हुए। इस राजीनामे में और बातों के साथ एक बात यह थी कि हिन्दुस्तानियों ने युद्ध में इस शर्त पर जर्मन सरकार की मदद करने का वादा किया कि फ़तह हासिल होने पर जर्मनी हिन्दुस्तान की आजादी पर जोर देगा। इस हिन्दुस्तानी कमेटी ने सारे युद्ध-काल में जर्मनी की तरफ़ से काम किया। इसने

बाहर लड़ने के लिए भेजी गई हिन्दुस्तानी फ़ौजों में प्रचार किया और इसके काम का क्षेत्र अफ़ग़ानिस्तान और सीमाप्रान्त तक फैल गया था। पर इसके सिवा कि उन्होंने अंग्रेज़ों की परेशानी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया हो, और कुछ ज्यादा ये हिन्दुस्तानी क्रान्तिकारी न कर सके। तमुद्र के रास्ते, हिन्दुस्तान में अस्त्र-शस्त्र भेजने की कोशिश की गई, पर उसे भी अंग्रेज़ों ने नाकामयाब कर दिया। लड़ाई में जर्मनी के हार जाने से इस कमेटी और उसकी उम्मीदों का अपने-आप ख़ात्मा हो गया।

हिन्दुस्तान के अन्दर भी क्रान्तिकारियों की थोड़ी-बहुत कार्रवाई जारी रही और षडयंत्र के भुक्तमों के लिए ख़ास अदालतें—स्पेशल डिव्यूनल्स—बनाई गईं। बहुत-से आदमियों को फाँसी दी गई, और बहुतों को लम्बी सजायें हुईं। उस वक़्त के सज़ा पाये हुए कुछ आदमी आज १७ वर्ष बाद भी जेलों में पड़े हुए हैं !

ज्यों-ज्यों युद्ध आगे बढ़ा, और जगहों की तरह, यहाँ भी कुछ लोगों ने गहरा मुनाफ़ा उठाया। पर ज्यादातर आदमियों का बोझ बढ़ता गया और लोगों में असंतोष भी बढ़ने लगा। लड़ाई के लिए ज्यादा-से-ज्यादा आदमियों की माँग बढ़ती ही जा रही थी और फ़ौज में भरती का काम बड़े जोर से होने लगा। रंगरूट लानेवालों को हर तरह के इनाम और प्रलोभन दिये गये और जमींदारों को अपने काश्तकारों में से तयशुदा तादाद में आदमी देने को मजबूर किया गया। पंजाब में ख़ास तौर पर भरती के मामले में जबरदस्ती का यह तरीक़ा इस्तिस्नान किया गया। हिन्दुस्तान से जितने आदमी फ़ौज में भरती करके लड़ाई के जुदा-जुदा मोर्चों पर लड़ने और दूसरे फ़ौजी मेहनत-मजूरी के कामों पर भेजे गये, उनकी तादाद दस लाख से ज्यादा थी। जिन आदमियों का इन भरतियों से ताल्लुक था, उन्होंने इन जबरदस्ती के तरीक़ों पर बड़ा ऐतराज किया, और ऐसा ख़याल किया जाता है कि पंजाब में महायुद्ध के बाद जो दुर्घटनायें हुईं उनमें एक वजह यह भी थी।

पंजाब पर एक दूसरे तरीक़े से भी असर पड़ा। बहुतेरे पंजाबी और ख़ासकर सिख संयुक्तराष्ट्र अमेरिका के कैलीफ़ोर्निया प्रान्त और पश्चिमी कनाडा के ब्रिटिश कोलम्बिया में जाकर दस्त गये थे। प्रवासियों का ताँता तबतक लगा रहा, जबतक अमेरिकन और कनैडियन अधिकारियों ने उसे रोक नहीं दिया। ऐसे प्रवासियों की राह में दिक्कतें पैदा करने के ख़याल से कनाडा की सरकार ने यह नियम बना दिया कि सिर्फ़ वे ही प्रवासी कनाडा में आ सकेंगे जो एक बन्दरगाह से यहाँके किसी बन्दरगाह तक सीधे आवें और रास्ते में कोई जहाज़ न बदलें। यह नियम हिन्दुस्तानी प्रवासियों को रोकने की गरज से ही बनाया गया था, क्योंकि उनको चीन या जापान में लाज़िमी तौर पर जहाज़ बदलने पड़ते थे। इसपर एक सिख, बाबा गुरुदत्तसिंह,

ने एक पूरा जहाज, जिसका नाम 'कोमागाता मारु' था, सीधे कनाडा भेजने का इन्तजाम किया। वह अपने साथ बहुत बड़ी तादाद में प्रवासियों को कनाडा के 'बैंकुवेर' तक ले गये। इस तरह से उन्होंने कनैडियन कानून की शर्त पूरी कर दी थी, फिर भी कनाडा उन्हें वहाँ आने देना नहीं चाहता था। किसी प्रवासी को वहाँ उतरने नहीं दिया गया। वे लोग उसी जहाज में लौटा दिये गये और वे बड़ी मुसीबत में और गुस्से से भरे हुए हिन्दुस्तान लौटे। कलकत्ता के पास वजवज में पुलिस से एक लड़ाई ही होगई और कई आदमी, खासकर सिख, मारे गये। बाद में इनमें से कई सिखों के पीछे खुफिया पुलिस छाया की तरह लगी और सारे पंजाब में उन्हें दीड़ाती रही। इन लोगों ने भी पंजाब में गुस्ता और असंतोष पैदा किया। 'कोमागाता मारु' की घटना पर सारे हिन्दुस्तान में नाराजी जाहिर की गई।

युद्ध के उन दिनों में होनेवाली सब बातों की जानकारी मुश्किल है, क्योंकि उस ज़माने में 'सेंसर' के कारण बहुतसे समाचार छपने नहीं पाते थे, इसलिए तरह-तरह की बेसिर-पैर की अफवाहें फैला करती थीं। फिर भी यह मालूम है कि सिंगापुर में एक हिन्दुस्तानी रेजीमेण्ट में बगावत होगई थी। इसके अलावा और भी बहुत-सी जगहों में छोटे-मोटे काण्ड हुए।

लड़ाई के लिए आदमी देने और दूसरी तरह की मदद के अलावा हिन्दुस्तान को नक़द धन भी बहुत देना पड़ा। इसे हिन्दुस्तान की तरफ़ से दी जानेवाली 'भेंट' के नाम से पुकारा गया। एक मौक़े पर करोड़ डेढ़ अरब रुपये इस तरह दिये गये और दूसरे मौक़े पर भी एक बहुत बड़ी रक़म दी गई। एक शरीब देश से इस तरह ज़बरदस्ती वसूल किये गये धन को 'भेंट' कहना ब्रिटिश सरकार की मज़ाक़पसन्द तबीयत का एक नमूना है !

अभीतक मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह, जहाँतक हिन्दुस्तान का ताल्लुक है, युद्ध के मामूली नतीजों तक ही महदूद रहा है। पर युद्ध-काल की स्थितियों के कारण इनसे कहीं ज्यादा मौलिक एक परिवर्तन होगया। युद्ध के ज़माने में, और देशों की तरह ही, हिन्दुस्तान का वैदेशिक व्यापार भी अव्यवस्थित होगया। बहुत बड़ी तादाद में जो ब्रिटिश माल हिन्दुस्तान में आता था वह युद्ध के कारण बहुत कम होगया। जर्मन पनडुब्बियाँ भूमध्य महासागर और अटलांटिक महासागर में जहाजों को डुबा रही थीं और इस स्थिति में व्यापार जारी रखना मुमकिन न था। इस तरह हिन्दुस्तान को अपना इंतज़ाम करना पड़ा और अपनी ज़रूरतें पूरी करनी पड़ीं। उसे युद्ध के लिए ज़रूरी बहुत-सी चीज़ें भी सरकार के लिए तैयार करनी पड़ीं। इस तरह हिन्दुस्तानी उद्योग तेज़ी से बढ़ने लगे। इसमें कुछ, कपड़े और जूट की तरह,

पुराने थे और कुछ नये थे। ताता के लोहे और फ़ौलाद के कारख़ाने का, जिसके प्रति अभीतक सरकार ने बड़ी उपेक्षा का बर्ताव किया था, महत्व बहुत बढ़ गया, क्योंकि उसमें युद्ध की सामग्री तैयार की जा सकती थी। उसका संचालन कमोबेश सरकारी नियंत्रण में होता था।

इसलिए युद्ध के वर्षों में हिन्दुस्तान के पूंजीपतियों को, जिनमें अंग्रेज़ और हिन्दुस्तानी दोनों थे, खुला क्षेत्र मिल गया। बाहरी प्रतिद्वंद्विता या लाग-डाँट बहुत कम थी। उन्होंने इस मौक़े का ख़ूब उपयोग किया और ग़रीब हिन्दुस्तानी जनता का पेट काटकर ख़ूब फ़ायदा उठाया। चीज़ों का दाम चढ़ा दिया गया और कल्पना में न आ सकने वाला मुनाफ़ा (डिविडेण्ड) बाँटा गया। लेकिन जिन मजदूरों की मेहनत से यह मुनाफ़ा हुआ, उनकी दुःखजनक स्थिति में बहुत ही थोड़ी तब्दीली हुई। उनकी मजदूरी थोड़ी बढ़ी, पर इस बढ़ती के मुक़ाबिले जिन्दगी की ज़रूरी चीज़ों का दाम कहीं ज्यादा बढ़ गया, इसलिए उनकी हालत पहले से भी ज्यादा ख़राब होगई।

लेकिन पूंजीपति ख़ूब मालदार होते गये और उन्होंने मुनाफ़े से ख़ूब धन जमा किया, जिसे वे फिर उद्योगों में लगाना चाहते थे। पहली बार हिन्दुस्तानी पूंजीपति इतने ताक़तवर हुए कि सरकार पर दबाव डाल सकें। इस दबाव के अलावा घटनाओं के जोर ने भी युद्ध-काल में ब्रिटिश सरकार को हिन्दुस्तानी उद्योगों को मदद देने पर मजबूर किया। देश के बढ़ते हुए उद्योगीकरण यानी कल-कारख़ानों की स्थापना के लिए विदेश से ज्यादा मशीनरी मँगाने की ज़रूरत हुई, क्योंकि ऐसी मशीनरी उस वक़्त हिन्दुस्तान में नहीं बन सकती थी। इस तरह बने हुए माल की जगह इंग्लैण्ड से मशीनरी आने लगी।

इन सब बातों के कारण हिन्दुस्तान में ब्रिटिश नीति में बड़ा परिवर्तन होगया; सौ वर्ष से चली आती हुई पुरानी नीति छोड़नी पड़ी और उसकी जगह नई नीति इस्तिहार करनी पड़ी। ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने अपनेको नई और बदली हुई स्थिति के मुताबिक़ बनाने के लिए अपना चेहरा पूरी तरह तब्दील कर लिया। तुमको मेरी वे बातें याद होंगी जो मैंने हिन्दुस्तान में ब्रिटिश हुकूमत के शुरू के दिनों के बारे में तुम्हें लिखी थीं। पहली अवस्था अठारहवीं सदी की अवस्था थी, जो लूट और यहाँ से नक़्क़द माल उठा लेजाने की अवस्था थी। उसके बाद दूसरी अवस्था आई जब ब्रिटिश हुकूमत ख़ूब मजदूरों के साथ क़ायम होगई। यह अवस्था सौ वर्षों से ज्यादा वक़्त यानी युद्ध तक बनी रही। यह हिन्दुस्तान को कच्चे माल का एक क्षेत्र और ब्रिटेन के बने माल का एक बाज़ार बना रखने के लिए थी। हर तरह से इस देश में बड़-बड़े उद्योगों की स्थापना को अनुत्साहित किया गया और हिन्दुस्तान के आर्थिक

विकास को रोका गया। युद्ध-काल में तीसरी अवस्था आई, जब ब्रिटिश सरकार ने हिन्दुस्तान में बड़े उद्योग-धंधों को प्रोत्साहन दिया; और यह प्रोत्साहन इस बात को जानते हुए दिया गया कि यह कुछ हद तक ब्रिटिश उद्योगों के खिलाफ पड़ेगा। यह साफ़ है कि अगर हिन्दुस्तान के वस्त्र-व्यवसाय को प्रोत्साहन दिया जाय तो लंकाशायर के वस्त्र-व्यवसाय को उसी अंश में धक्का पहुँचेगा, क्योंकि हिन्दुस्तान लंकाशायर का सबसे अच्छा ग्राहक रहा है। तब ब्रिटिश सरकार ने अपनी नीति में ऐसा परिवर्तन क्यों किया, जिससे लंकाशायर और दूसरे ब्रिटिश उद्योग को नुकसान पहुँचे? मैं तुम्हें दिखा ही चुका हूँ कि लड़ाई के कारण किस प्रकार उसके हाथ बँध गये थे। हमें परिवर्तन के इन कारणों पर विस्तार के साथ विचार करना चाहिए :

१. युद्ध-काल की माँगों ने ऐसा करने को मजबूर किया और हिन्दुस्तान में औद्योगीकरण यानी बड़े-बड़े कल-कारखानों को प्रगति दी।

२. इसने हिन्दुस्तानी पूँजीपति वर्ग को बढ़ाया और मजबूत किया। उन्होंने उद्योगों की बढ़ के लिए ज्यादा-से-ज्यादा सहूलियतों की माँग शुरू की। इसने उनकी फालतू दौलत को नये धंधों में लगाने का मौका दिया। अब ब्रिटेन उनकी बिल्कुल उपेक्षा करने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि ऐसा करने से उनके विरोधी हो जाने और बढ़ते हुए उग्र और क्रान्तिकारी विचार के लोगों के मददगार बन जाने की संभावना थी। इसलिए अगर सुमकिन हो तो बढ़ने को कुछ सहूलियतें देकर उनको ब्रिटिश पक्ष में बनाये रखना वाञ्छनीय था।

३. इंग्लैण्ड का पूँजीवादी वर्ग भी अपनी फालतू दौलत को अविकसित देशों में लगाना चाहता था, क्योंकि वहाँ ज्यादा मुनाफ़ा होता था। इंग्लैण्ड में तो कल-कारखानों और उद्योग-धंधों की ऐसी भरमार होगई थी कि वहाँ पूँजी लगाने की सहूलियतें बहुत कम थीं। वहाँ मुनाफ़ा अब उतना ज्यादा नहीं मिलता था और फिर मजदूरों का आन्दोलन वहाँ खूब अच्छी तरह संगठित था, जिससे अकसर मजदूरों के साथ झगड़े खड़े होजाया करते थे। अविकसित देशों में मजदूर कमजोर होता है, इसलिए मजदूरी कम देनी पड़ती है और मुनाफ़ा ज्यादा होता है। लाजिमी तौर पर ब्रिटिश पूँजीपतियों को ब्रिटेन के मातहत अविकसित देशों—जैसे हिन्दुस्तान—में पूँजी लगाना ज्यादा पसंद था। इस तरह ब्रिटिश पूँजी हिन्दुस्तान में आई और इससे और भी औद्योगीकरण हुआ, यानी और भी कल-कारखाने खुले।

४. महायुद्ध के अनुभवों से यह मालूम होगया कि सिर्फ़ बहुत ऊँचे औद्योगिक देश ही प्रभावशाली ढंग से लड़ाई लड़ सकते हैं। ज़ारशाही रूस आखिरकार युद्ध में इसलिए परास्त होगया कि उसका काफ़ी तौर पर औद्योगीकरण नहीं हुआ था और

उसे दूसरे मुल्कों पर निर्भर रहना पड़ा। इंग्लैण्ड को भय है कि आगामी युद्ध सोवियट रुस के साथ होगा और हिन्दुस्तान की सरहद पर लड़ा जायगा। अगर हिन्दुस्तान के पास अपने बड़े-बड़े उद्योग न होंगे तो ब्रिटिश सरकार सरहद पर भलीभाँति लड़ाई न लड़ सकेगी। यह एक बहुत बड़ा खतरा लेना होगा। इसलिए भी हिन्दुस्तान का औद्योगीकरण जरूरी है।

इन कारणों से मजबूर होकर ब्रिटिश नीति में तब्दीली का निश्चय किया गया। ब्रिटेन की बृहत्तर साम्राज्य सम्बन्धी नीति (Larger Imperial Policy) के लिए यह जरूरी था, फिर लंकाशायर और कुछ दूसरे ब्रिटिश उद्योगों को भले ही नुकसान पहुँचे। ब्रिटेन ने तो यह जाहिर किया कि यह परिवर्तन हिन्दुस्तान के प्रति ब्रिटिश सरकार के अत्यधिक प्रेम और उसकी भलाई की इच्छा का परिणाम है। इस नीति का निश्चय कर लेने के बाद ब्रिटेन ने ऐसा उपाय किया कि हिन्दुस्तान के नये उद्योगों का नियंत्रण ब्रिटिश पूंजीपतियों के हाथ में रहे। महरबानी दिखाते हुए हिन्दुस्तानी पूंजीपतियों को छोटा हिस्सेदार बनाया गया।

१९१६ ई० में, जब महायुद्ध चल रहा था, एक 'इंडियन इंडस्ट्रियल कमीशन' नियुक्त किया गया। दो वर्ष बाद इसने रिपोर्ट पेश की जिसमें सिफारिश की गई कि सरकार को उद्योगों को उत्तेजन देना चाहिए और कृषि में नये औद्योगिक तरीकों को चलाना चाहिए। इसने इस बात की भी सिफारिश की कि सारे देश को प्रारम्भिक शिक्षा देने की कोशिश की जानी चाहिए। जैसा कि इंग्लैंड में कारखानों की बढ़ती के शुरू के दिनों में हुआ था, होशियार और कारीगर मजदूर पैदा करने के लिए आम जनता को प्रारम्भिक शिक्षा देना उचित समझा गया।

युद्ध खत्म होने पर इस कमीशन के वाद और भी बहुत-से कमीशन और कमेटियाँ आईं। यह भी सुझाया गया कि बाहरी माल पर कर लगाकर भी हिन्दुस्तानी उद्योगों की रक्षा की जानी चाहिए। इन करों को टैरिफ कहा जाता है। इन सब बातों को हिन्दुस्तानी उद्योगों के पक्ष में एक दड़ी विजय समझा गया। पर जरा ध्यान से परीक्षा करने पर कई मजेदार बातें मालूम हुईं। विदेशी पूंजी को उत्तेजन देने का प्रस्ताव पास किया गया था और विदेशी पूंजी का मतलब असल में ब्रिटिश पूंजी था। वस, इस देश में ब्रिटिश पूंजी का प्रवाह बहने लगा; वह न सिर्फ उसका प्रधान हिस्सा हो गई, बल्कि सब जगह छा गई। बड़े-बड़े उद्योगों में अधिकांश ब्रिटिश पूंजी लगाई गई। इसलिए संरक्षण कर (टैरिफ) और संरक्षण (प्रोटेक्शन) का असल मतलब हिन्दुस्तान में ब्रिटिश पूंजी का संरक्षण होगया। इस तरह हिन्दुस्तान में ब्रिटिश नीति का महान् परिवर्तन ब्रिटिश पूंजीपति के लिए कुछ बँसा बुरा साबित नहीं हुआ।

उसको एक अच्छा संरक्षित बाज़ार मिल गया था, जिसमें वह अपना व्यापार फैला सकता था और मजदूरों को कम मजदूरी देकर खूब मुनाफ़ा उठा सकता था। एक दूसरे तरीक़े पर भी यह उसके लिए मुफीद साबित हुआ। हिन्दुस्तान, चीन, मिस्र और दूसरे ऐसे देशों में जहाँ मजदूरी की दर बहुत नीची थी, अपनी पूंजी लगाने के बाद उसने इंग्लैण्ड के मजदूरों को भी मजदूरी कम करने की धमकी दी। और अगर अंग्रेज़ मजदूर ने मजदूरी में कमी करने की बात का विरोध किया तो पूंजीपति ने कहा कि उसे मजबूर होकर बड़े दुःख के साथ इंग्लैण्ड में अपना कारख़ाना बन्द कर देना पड़ेगा और वह और कहीं दूसरी जगह अपनी पूंजी लगायेगा।

हिन्दुस्तान के उद्योगों पर नियन्त्रण रखने के लिए हिन्दुस्तान की ब्रिटिश सरकार ने और भी कई उपाय किये। यह एक जटिल विषय है और जब मैं इसके बारे में लिखता हूँ तो मुझे ऐसा मालूम होता है कि मैं फिसलती ज़मीन पर हूँ। इसलिए हमें इन बातों पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं। पर एक बात का जिक्र मैं कर देना चाहता हूँ। आधुनिक उद्योग में बैंक बड़ा ज़बरदस्त हिस्सा लेते हैं, क्योंकि बड़े-बड़े व्यापारियों को अक्सर रुपये-सम्बन्धी साख की ज़रूरत पड़ती है। बड़े-से-बड़ा व्यापार भी फेल किया जा सकता है, अगर उसे रुपये उधार मिलने या उसकी साख कायम रखने की सहूलियतें न दी जायें। चूँकि बैंक ही यह 'क्रेडिट' (उधार या साख) दे सकते हैं, इसलिए तुम कल्पना कर सकती हो कि उनके हाथ में कितनी ज़बरदस्त ताक़त होती है। वे किसी व्यवसाय को बना और बिगाड़ सकते हैं। महायुद्ध के बाद ही ब्रिटिश सरकार ने कई बैंकों को मिलाकर 'इम्पीरियल बैंक ऑफ़ इंडिया' के नाम से एक बड़ा बैंक बनाया। यह बैंक पूरे तौर पर सरकार के नियन्त्रण में है और देश के दूसरे छोटे बैंकों पर इसका बहुत काफ़ी नियंत्रण है। इस तरह सरकार हिन्दुस्तानी उद्योगों और व्यापारी पेड़ियों पर अपना काफ़ी क़ब्ज़ा रख सकती है।

हिन्दुस्तानी उद्योगों के लिए अंग्रेज़ लोग जो महान् कार्य कर रहे थे (और हम देख ही चुके हैं कि यह महान् कार्य कैसा था) उसके लिए बतौर इनाम या पुरस्कार उन्होंने अपने माल को तरजीह दिये जाने की माँग की। इसे कभी-कभी 'इम्पीरियल प्रेफ़रेंस' (साम्राज्य के माल को तरजीह देने की नीति) कहा जाता है। इसका मतलब यह था कि अगर हिन्दुस्तानी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए विदेशी माल पर कर या टैरिफ़ लगाना हो तो ब्रिटिश माल पर अपेक्षाकृत कम टैक्स लगाया जाय, या बिल्कुल ही टैक्स न लगाया जाय, जिससे यहाँ के बाज़ार में ब्रिटिश माल को दूसरे विदेशी माल से ज्यादा सुविधायें मिलें। अभी हाल में तरजीह दिये जाने की इस नीति को चलाने में वे कामयाब हुए हैं।

युद्ध-काल में हिन्दुस्तानी पूंजीपति वर्ग और ऊँचे मध्यमवर्ग की बढ़ती हुई ताकत का असर राजनैतिक आन्दोलन पर भी पड़ा। राजनीति युद्ध के पहले या युद्ध के जमाने की शुरुआत की खुमारी से बाहर निकल पड़ी और स्वशासन की माँग की जाने लगी। अपनी लम्बी सजा काटने के बाद लोकमान्य तिलक जेल से बाहर आये। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि उस वक्त राष्ट्रीय महासभा या नेशनल कांग्रेस माडरेट यानी उदार दल के हाथ में थी। उस वक्त वह एक छोटी-सी संस्था थी, जिसका जनता से बहुत कम सम्पर्क था और जिसका बिल्कुल प्रभाव नहीं था। चूँकि अधिक प्रगतिशील राजनीतिज्ञ कांग्रेस में नहीं थे, इसलिए उन्होंने होमरूल लीगों का संगठन किया। ऐसी दो लीगें बनाई गई—एक लोकमान्य तिलक द्वारा, दूसरी श्रीमती एनी बेसेण्ट द्वारा। कुछ वर्षों तक श्रीमती बेसेण्ट ने हिन्दुस्तान की राजनीति में महत्वपूर्ण भाग लिया और उनकी बोलने और किसी बात की वकालत करने की महान् शक्ति ने राजनीति में लोगों की दिलचस्पी बढ़ा दी। सरकार ने उनके प्रचार को इतना खतरनाक समझा कि उन्हें, और उनके दो साथियों को, कुछ महीनों तक नजरबन्द रखा। वह कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्ष हुई। वह कांग्रेस की अध्यक्ष बननेवाली पहली स्त्री थीं। कुछ वर्षों बाद श्रीमती सरोजनी नायडू कांग्रेस की दूसरी महिला-अध्यक्ष हुई थीं।

१९१६ में कांग्रेस के दोनों दलों, माडरेटों और उग्रतावादियों, में समझौता हो-गया और १९१६ में लखनऊ में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ उसमें दोनों शरीक हुए। यह समझौता थोड़े ही समय तक कायम रहा। दो वर्षों के अन्दर ही फिर झगड़ा हो गया और माडरेट, जो अब अपनेको लिबरल यानी उदार-मतवादी कहते हैं, कांग्रेस से अलग हो गये और अभी तक अलग ही हैं।

१९१६ की लखनऊ-कांग्रेस से राष्ट्रीय महासभा का पुनरुत्थान शुरू होता है। तबसे आगे बराबर उसका महत्व और उसकी ताकत बढ़ती गई, और अपने इतिहास में पहली बार वह मध्यमवर्ग एक राष्ट्रीय संगठन बन सका। तब भी इसका आम जनता से कोई ताल्लुक न था और आम लोगों ने तबतक इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली जबतक कि उसमें बापू का आगमन नहीं हुआ। इस तरह माडरेट या उग्रतावादी दोनों, कमोवेश, एक ही यानी मध्यम वर्ग के प्रतिनिधि थे। माडरेट लोग थोड़े-से खुशहाल लोगों और सरकारी नौकरियों के नजदीक रहनेवालों के प्रतिनिधि थे। वे खुद भी ज्यादातर खुशहाल थे और सरकारी नौकरियों में थे या उनके साथ उनके ताल्लुकात थे। उग्रतावादियों के साथ मध्यमवर्ग के ज्यादातर लोगों की हमदर्दी थी और उसमें कितने ही बेकार प्रतिभावान या दुद्धिजीवी लोग थे। ये दुद्धिजीवी (जिन-

से घेरा मतलब बहुत कुछ पढ़े-लिखे लोगों से है) संगठित हुए और इन्हींमें से क्रान्ति-कारियों को भी रंगरूट मिले। माडरेटों और उग्रपंथियों के आदर्श या लक्ष्य में कोई ज्यादा फर्क नहीं था। दोनों ब्रिटिश साम्राज्य के अन्दर स्वशासन की बात करते थे और दोनों उस वक़्त इसका एक हिस्सा भी लेने को तैयार थे। यह जरूर था कि उग्रपंथी माडरेटों की बनिस्वत ज़रा बड़ा हिस्सा माँगते थे और अपनी माँग को जोरदार भाषा में प्रकट करते थे। मुट्ठीभर क्रान्तिकारी जरूर पूरी आजादी चाहते थे, पर उनका कांग्रेस के नेताओं पर बहुत कम प्रभाव था। माडरेटों और उग्रपंथियों में असली फर्क यह था कि पहला अधिपतियों यानी मालदारों (Haves) और उनके सहारे रहनेवाले लोगों का दल था और उग्रपंथियों में ऐसे लोग भी बहुत काफ़ी तादाद में थे जो अपहृत थे और जिनके पास खुशहाल जिन्दगी के जरिये न थे। लाजिमी तौर पर दूसरे दल ने देश के नौजवानों को ज्यादा आकर्षित किया। इन नौजवानों में से ज्यादातर काम की जगह कड़ी भाषा के प्रयोग को ही काफ़ी समझते थे। पर मैं यहाँ यह कह दूँ कि यह जो मैंने एक आम बात बताई है वह दोनों तरफ़ के कई व्यक्तियों पर लागू नहीं होती। उदाहरण के तौर पर गोपालकृष्ण गोखले का नाम लिया जा सकता है, जो माडरेटों के एक बड़े ही योग्य और आत्मत्यागी नेता थे और वह मालदार नहीं थे। उन्होंने लोक-सेवक-समिति (सर्वेण्ट्स ऑफ़ इण्डिया सोसायटी) क़ायम की। पर न तो माडरेटों का, न उग्रपंथियों का, असली शोषित और अपहृत लोगों (Have-nots) यानी मजदूरों और किसानों से कोई ताल्लुक था। हाँ, तिलक आम जनता में जरूर लोकप्रिय थे।

१९१६ की लखनऊ-कांग्रेस हिन्दू-मुस्लिम एकता के कारण भी महत्वपूर्ण थी। कांग्रेस सदा से राष्ट्रीय आधार पर खड़ी थी, पर अमल में वह एक हिन्दू संस्था थी, क्योंकि इसमें ज्यादातर हिन्दू ही थे। युद्ध के कुछ साल पहले, सरकार के बढ़ावा देने पर, शिक्षित मुसलमानों ने आलइंडिया मुस्लिम लीग क़ायम की थी। यह संस्था मुसलमानों को कांग्रेस से अलग रखने के लिए खोली गई थी, पर यह धीरे-धीरे कांग्रेस की तरफ़ बढ़ती गई और लखनऊ में दोनों के बीच, हिन्दुस्तान के भावी विधान के बारे में, एक समझौता होगया। इसे कांग्रेस-लीग योजना कहा जाता था और दूसरी बातों के साथ इसमें मुसलमानों के अल्पमत के लिए स्थान (सीट) सुरक्षित रखने की भी तजवीज़ थी। यह कांग्रेस-लीग योजना दोनों का संयुक्त कार्यक्रम बन गई और देश की माँग के रूप में स्वीकार की गई। इसके ख़यालात मध्यमवर्ग के ख़यालात थे, क्योंकि उस वक़्त मध्यमवर्ग ही राजनैतिक मामलों में दिलचस्पी लेता था। इस योजना के आधार पर आन्दोलन बढ़ता गया।

मुसलमान जो राजनीति में इतनी दिलचस्पी लेने लगे थे और कांग्रेस के साथ मिलकर काम कर रहे थे, उसकी वजह यह थी कि ब्रिटेन के तुर्की के साथ लड़ने से वे खीझ उठे थे। तुर्की के साथ हमदर्दी रखने और जोरों से उसका इजहार करने के कारण दो मुसलमान नेता, मौलाना शौकतअली और मुहम्मदअली, युद्ध के शुरू में ही नजरबन्द कर दिये गये थे। मौलाना अबुलकलाम आज़ाद भी नजरबन्द कर दिये गये थे। उनकी नजरबन्दी की वजह यह थी कि अरब देशों से उनके गहरे ताल्लुकात थे, जहाँ वह अपनी किताबों और लेखों के कारण बड़े लोकप्रिय थे। इन सब बातों से मुसलमानों का खीझना और गुस्सा होना लाजिमी था और वे सरकार से अधिकाधिक दूर हटते गये।

चूँकि हिन्दुस्तान में स्वशासन की माँग बढ़ती गई, ब्रिटिश सरकार ने कई वादे किये और हिन्दुस्तान में जाँच शुरू करदी, जिससे जनता का ध्यान उधर खिंच गया। १९१८ की गरमी के दिनों में उस वक्त के भारत-सचिव और वाइसराय ने एक संयुक्त रिपोर्ट पेश की—जो उनके नामों से 'मांटिगू-चेम्सफर्ड रिपोर्ट' करके मशहूर हुई—जिसमें हिन्दुस्तान में कुछ सुधारों और परिवर्तनों के प्रस्ताव किये गये थे। तुरन्त ही इन प्रस्तावों पर देश में बड़ी बहस छिड़ गई। कांग्रेस ने जोरों के साथ उनका विरोध किया और उन्हें अपर्याप्त यानी नाकाफ़ी बताया। लिबरलों ने उनका स्वागत किया और उन्हींकी वजह से वे कांग्रेस से अलग होगये। कुछ समय पहले से ही वे नये तौर-तरीक़े के कांग्रेसमैनों के साथ तकलीफ़ महसूस कर रहे थे।

जब युद्ध ख़त्म हुआ तब हिन्दुस्तान की यह हालत थी। हर जगह तब्दीलियों का ज़वरदस्त इन्तज़ार था। राजनैतिक 'बैरोमीटर' ऊँचा उठ रहा था और मुलायम, विश्रामदायक, अप्रभावशाली और हिचकिचाहट से भरी हुई कानाफूसियों की जगह उग्रपंथियों की ज्यादा विद्वान्त से भरी हुई, उग्र, सीधी और स्पष्ट चिल्लाहट ले रही थी। पर माडरेट और उग्रपंथी दोनों राजनीति और शासन के बाहरी ढाँचे के बारे में ही बोलते थे; उनकी पीठ पीछे ब्रिटिश साम्राज्यवाद देश के आर्थिक जीवन पर चुपचाप अपना शक्का कायम करता जा रहा था।

१. बैरोमीटर—वायु का भार बतानेवाला यंत्र

योरप का नया नक्शा

२१ अप्रैल, १९२३

थोड़े में महायुद्ध की प्रगति का विचार करने के बाद हम लोगों ने रूस की क्रान्ति की संर की और उसके बाद महायुद्ध के जमाने में हिन्दुस्तान की क्या हालत थी इसपर भी गौर कर लिया। अब हमें फिर 'आर्मिस्टीज' यानी महायुद्ध को बन्द करने के सुलहनामे की तरफ लौट चलना चाहिए और यह देखना चाहिए कि विजयी शक्तियों या राष्ट्रों का वर्ताव कैसा रहा। जर्मनी परस्त होगया था और वेदम पड़ा था। कैसर जर्मनी छोड़कर भाग गया था और प्रजातन्त्र की घोषणा कर दी गई थी। इतने पर भी जर्मन फौज को पूरी तरह से अशक्त या बेकाम कर देने के इत्मीनान के लिए सुलहनामे (Armistice) में बहुतेरी कड़ी शर्तें रखी गई थीं। इनके मुताबिक जर्मन फौज को न सिर्फ उन प्रदेशों से हट जाना पड़ा जिनपर युद्ध के जमाने में हमला करके उसने कब्जा कर लिया था, बल्कि उसे अल्सेस-लॉरेन और राइन तक फैला हुआ जर्मनी का हिस्सा भी खाली कर देना पड़ा। यह शर्तें रखी गई कि मित्र-राष्ट्र राइनलैण्ड यानी कोलोन (Cologne) के इर्द-गिर्द के प्रदेश पर कब्जा कर लेंगे। जर्मनी को अपने बहुतेरे सामरिक या लड़ाकू जहाजों और अपनी सब 'यू' नौकाओं (जर्मनी सबमेरीनें या पनडुब्बियाँ इसी नाम से मशहूर थीं) से हाथ धोना पड़ा। इनके अलावा उसे अपनी हज़ारों तोपें, हवाई जहाज, रेलवे इंजिन, लारियाँ और दूसरी कितनी ही चीजें छोड़ देनी पड़ीं।

उत्तर फ्रांस के काम्पेन वन में, जहाँ उस सुलहनामे पर दस्तखत हुए थे, एक स्मारक है, जिसपर ये वाक्य लिखे हुए हैं :—

"Ici le November 11, 1918, succomba le criminel orgueil de L'Empire Allemand Vaincu par les peuples libres qu'il pretendait asservir."

अर्थात्, "यहां, ११ नवम्बर १९१८ को, आज़ाद क़ौमों (जिन्हें जर्मनी ने गुलाम बनाना चाहा था) द्वारा पराजित जर्मन साम्राज्य के अपराधी अभिमान का अन्त हो गया।"

इसमें कोई शक नहीं कि कम-से-कम ऊपरी तौर पर तो जर्मन साम्राज्य का ख़ात्मा होगया और प्रशा का फ़ौजी ग़ुरुर टूट चुका था। इसके भी पहले रूसी साम्राज्य का अन्त होचुका था और वहाँका रोमनोफ़ राजवंश उस स्टेज से हटा दिया गया था जिसपर वह इतने लम्बे असें तक बदकारियाँ कर रहा था। इस

महायुद्ध से एक तीसरे साम्राज्य और पुराने राजघराने, यानी हैप्सबर्ग खानदान के आस्ट्रिया-हंगरी के साम्राज्य, का भी ख़ात्मा हो गया। लेकिन इसके बाद भी दूसरे कई साम्राज्य बच रहे, क्योंकि वे विजेताओं में से थे और विजय ने उनके गुरुर में कोई कमी नहीं की, न उन लोगों के प्रति, जिन्हें उन्होंने गुलाम बना रखा था, उनमें कुछ ज्यादा उदारता या इंसान का ख़याल ही पैदा किया।

विजयी मित्र-राष्ट्रों ने सन् १९१९ ई० में पेरिस में अपना 'शान्ति-सम्मेलन' (Peace Conference) किया। उनके हाथों पेरिस में दुनिया का भविष्य गढ़ा जाने-वाला था और कई महीनों तक इस मशहूर शहर पर दुनिया की आँखें लगी रहीं। दूर और नज़दीक से सभी तरह के आदमी वहाँ सफ़र करके पहुँचे। अपनेको बहुत महत्वपूर्ण समझनेवाले राजनीतिज्ञ और राजनैतिक आदमी वहाँ जमा हुए; कितने ही कूटनीतिज्ञ, विशेषज्ञ, बड़े-बड़े फ़ौजी आदमी, रुपया लगानेवाले साहूकार, और मुनाफ़ा उठानेवाले लोग वहाँ पहुँच गये। और इन सबके साथ सहायकों, टाइपिस्टों और क्लर्कों की भीड़-की-भीड़ थी। पत्रकारों की जमात तो थी ही। अपनी आज़ादी के लिए लड़नेवाले राष्ट्रों के जैसे आयरलैंड, मिस्र, अरब और दूसरे कितने ही जिनका नाम भी पहले नहीं सुनाई पड़ा था—प्रतिनिधि भी वहाँ पहुँचे थे। पूर्वी योरप के कई राष्ट्रों के प्रतिनिधि भी वहाँ आये थे, जो चाहते थे कि आस्ट्रियन और तुर्कों साम्राज्यों के भग्नावशेष यानी खण्डहरों से अपने लिए अलग राष्ट्रों का निर्माण करें। इनके अलावा बहुत-से लेभगू भी जमा हुए थे। दुनिया का नये ढंग पर बँटवारा होने जा रहा था और गिद्ध इस मौक़े पर चूकना नहीं चाहते थे।

'शान्ति-सम्मेलन' से बड़ी उम्मीदें थीं। लोगों का ख़याल था कि महायुद्ध के भयंकर अनुभव के बाद न्यायपूर्ण और स्थायी शान्ति का कोई उपाय किया जायगा। आम जनता अब भी युद्ध के ज़बरदस्त बोझ को महसूस कर रही थी और मजदूरों में बहुत ज्यादा असंतोष था। जिन्दगी की ज़रूरी चीज़ों के दाम बहुत चढ़ गये थे और इसकी वजह से आम लोगों की मुसीबत बढ़ गई थी। सन् १९१९ ई० में योरप में आनेवाली सामाजिक क्रान्ति के कितने ही चिन्ह साफ़ दिखाई दे रहे थे। रूस का उदाहरण लोगों को ख़ास तौर पर अपनी तरफ़ खींच रहा था।

वर्साई के उस हाल में, जहाँ ठीक अड़तालीस वर्ष पहले जर्मन साम्राज्य का ऐलान किया गया था, होनेवाले शान्ति-सम्मेलन का यह पार्श्वचित्र था। इतने बड़े सम्मेलन का रोज़-बरोज़ मिलना मुश्किल था, इसलिए वह कई कमेटियों में बाँट दिया गया। ये कमेटियाँ अपनी प्राइवेट या गुप्त बैठकें करती थीं और इस चालाकी के परदे के पीछे उनके झगड़े और पड़यन्त्र चलते रहते थे। सम्मेलन

का नियंत्रण मित्र-राष्ट्रों की 'कौंसिल ऑफ़ टेन' (Council of Ten) यानी 'दस की समिति' करती थी, जिसमें दस राष्ट्रों के प्रतिनिधि थे । बाद में वह घटाकर पाँच की कर दी गई, जिसमें संयुक्तराष्ट्र (अमेरिका), ब्रिटेन, फ़्रांस, इटली और जापान दुनिया के पंच महाराष्ट्र (Big Five) थे । कुछ दिनों बाद जापान भी इसमें से निकल गया और सिर्फ़ 'कौंसिल ऑफ़ फ़ोर' यानी चार राष्ट्रों की कौंसिल रह गई । अख़ीर में इटली भी इससे हट गया और सिर्फ़ तीन महाराष्ट्र (Big Three) रह गये—अमेरिका, ब्रिटेन और फ़्रांस । राष्ट्रपति विल्सन, लायड जार्ज और क्लेमैंशो क्रमशः इन तीनों देशों के प्रतिनिधि थे और इन तीन आदमियों के कन्धों पर दुनिया को नये सॉचे में ढालने और उसके भयावने जख्मों को अच्छा करने का महान् कार्य आपड़ा । यह कार्य महापुरुषों और देवताओं के लायक़ था और ये तीनों इनसे कहीं भिन्न या दूसरे ढंग के थे । जिन लोगों के हाथों में ताक़त होती है—जैसे बादशाह, राजनीतिज्ञ, सिपहसालार और इसी तरह के दूसरे लोग—उनका अख़बारवाले इतना ज्यादा विज्ञापन करते और उनकी तारीफ़ का कुछ ऐसा पुल बाँध देते हैं कि आम लोगों को वे विचार और कार्य में असाधारण और देव सरीखे जान पड़ते हैं । उनके चारों ओर एक तरह का प्रकाश का घेरा लोगों को दिखाई पड़ने लगता है और अपने अज्ञान या नावाक़फ़ियत के कारण हम उनमें बहुत-से ऐसे गुणों की कल्पना कर लेते हैं जिनका उनमें नाम-निशान भी नहीं होता । घनिष्ट परिचय में आने या नज़दीक से देखने के बाद वे बहुत मामूली आदमी निकलते हैं । एक मशहूर आस्ट्रियन राजनीतिज्ञ ने एक बार कहा था कि अगर दुनिया को मालूम होजाय कि कितनी कम बुद्धि से उसपर हुकूमत की जाती है तो वह स्तब्ध या हैरतज़दा रह जायगी । इस तरह ये तीन महान् लोग (The Big Three) हालांकि बड़े दीखते थे, पर उनका दृष्टिकोण बहुत संकुचित था और वे अन्तर्राष्ट्रीय मामलों से बेख़बर थे—यहाँ तक कि उन्हें भूगोल का भी ज्ञान न था ।

राष्ट्रपति उडरो विल्सन बड़े लोकप्रिय थे और उनकी चारों तरफ़ बड़ी प्रशंसा हो रही थी । उन्होंने अपने व्याख्यानो और नोटों में इतने खूबसूरत और आदर्श से भरे हुए वाक्यों का प्रयोग किया था कि लोग उन्हें आनेवाली नई आजादी का पैगम्बर समझने लगे । ग्रेटब्रिटेन के प्रधान मंत्री लायड जार्ज ने भी बहुतेरे सुन्दर वाक्यों का इस्तेमाल किया, पर उनको लोग अवसरवादी या मौक़े से अपना मतलब गाँठनेवाला समझते थे । 'शेर' (Tiger) नाम से पुकारे जानेवाले क्लेमैंशो को आदर्शों और लम्बे-चौड़े वाक्यों से कोई मतलब न था । वह तो फ़्रांस के पुराने दुश्मन जर्मनी को हर तरह से कुचलना और अपमानित करना चाहता था, ताकि फिर वह सिर न उठा सके ।

यों ये तीनों एक-दूसरे से लड़ते और एक-दूसरे को अपनी-अपनी तरफ खींचते रहे । इनमें से हरेक पर सम्मेलन में और बाहर से भी न जाने कितने आदमियों का दबाव और जोर पड़ रहा था । फिर इन सबके पीछे सोवियट रूस की छाया फैल रही थी । सम्मेलन में न रूस और न जर्मनी का कोई प्रतिनिधि था, पर सोवियट रूस की हस्ती ही पेरिस में इकट्ठा हुई पूँजीवादी ताकतों के लिए बराबर एक चुनौती-सी थी ।

आखिरकार लायड जार्ज की मदद से क्लेमेशो की जीत हुई । विल्सन जो चीज सबसे ज्यादा चाहता था, वह—एक राष्ट्र-संघ—उसे मिल गई और इस बारे में सबकी मंजूरी मिल जाने पर वह और सब बातों में झुक गया । कई महीनों के तर्क और बहस-मुवाहसे के बाद शान्ति-सम्मेलन में मित्र-राष्ट्र सुल्हनामे के एक मस्विदे पर सहमत हुए और आपस में एकमत हो जाने के बाद उन्होंने जर्मन प्रतिनिधियों को अपना हुक्म या फ़ैसला सुनाने के लिए बुलाया । ४४० धाराओं का यह लम्बा-चौड़ा सुल्ह का मस्विदा जर्मनों के गले ठूस दिया गया और उनसे उसपर दस्तखत करने को कहा गया । उनके साथ कोई तर्क-वितर्क या बहस-मुवाहसा नहीं हुआ और न उन्हें उस मस्विदे में किसी तरह का संशोधन या रद्दोबदल करने का ही मौका दिया गया । यह तो एक ज़बरदस्ती और जोर के बल पर की गई सुल्ह थी; या तो जर्मनों को ज्यों-का-त्यों इसे क़बूल कर लेना था या नामंजूरी का परिणाम भुगतने के लिए तैयार होना था । नये जर्मन प्रजातंत्र के प्रतिनिधियों ने इसका विरोध किया और दी गई अवधि के आखिरी दिन बर्साई की संधि पर दस्तखत किये ।

आस्ट्रिया, हंगरी, बल्गेरिया और तुर्की के साथ मित्र-राष्ट्रों ने अलग-अलग संधियाँ कीं । तुर्की के साथ होनेवाले सुल्हनामे को उस वक़्त के सुल्तान ने तो मान लिया था, पर कमालपाशा और उसके बहादुर साथियों की ज़बरदस्त मुत्सालंक्रत की वजह से वह बाद में नाकामयाब होगया । पर उसकी एक अलग कहानी है, जो मैं किसी दूसरे पत्र में तुम्हें सुनाऊँगा ।

इन सुल्हनामों से क्या तब्दीलियाँ हुईं ? ज्यादातर प्रादेशिक परिवर्तन पूर्वी योरप, पश्चिमी एशिया और अफ़रीका में हुए । अफ़रीका के जर्मन उपनिवेशों को मित्र-राष्ट्रों ने लड़ाई के इनाम के तौर पर हथिया लिया । इसमें इंग्लैण्ड के हाथ में सबसे अच्छे हिस्से आये । ब्रिटेन बहुत दिनों से अफ़रीका के एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपने साम्राज्य का जो सपना देख रहा था वह पूर्वी अफ़रीका में टंगानिका के हाथ आजाने से पूरा होगया, क्योंकि अब उत्तर में मिस्र से लेकर दक्षिण में केप तक ब्रिटेन का ही क़ब्ज़ा था ।

योरप में बहुतेरी तब्दीलियाँ होगईं और बहुत-से नये राज्य या राष्ट्र नक्शे पर आगये । किसी पुराने नक्शे का नये से मुकाबिला करो तो तुम्हें देखते ही इन

तब्दीलियों का पता लग जायगा। कई तब्दीलियाँ तो रूसी क्रान्ति का परिणाम थीं, क्योंकि बहुत-सी क्रौमें, जो रूस की सरहदों पर बसी हुई थीं, सोवियट से अलहदा होगई और उन्होंने अपनी आजादी का ऐलान कर दिया। सोवियट सरकार ने उनके आत्म-निर्णय के अधिकार को मंजूर कर लिया और उनकी स्वतंत्रता में दखल नहीं दिया। योरोप के नये नक्शे को देखो। आस्ट्रिया-हंगरी का बड़ा राज्य एकदम गायब होगया है और उसकी जगह पर कई छोटे देश और राज्य पैदा होगये हैं, जिन्हें 'आस्ट्रियन विरासत वाले राज्य' (Austrian Succession States) कहते हैं। इनमें आस्ट्रिया भी एक है, जो अपने पहले विस्तार का एक छोटा टुकड़ा-सा रह गया है और जिसकी राजधानी वियेना का बड़ा शहर है। इनमें दूसरा देश हंगरी है। यह भी पहले से बहुत छोटा होगया है। तीसरा चेकोस्लोवेकिया है, जिसमें पहले का बोहेमिया शामिल कर दिया गया है। इसके अलावा युगोस्लेविया का, जो हमारा पुराना पर दुःखदाई दोस्त है, एक हिस्सा रह गया है; सर्बिया इस तरह मिट गया है कि पहचाना नहीं जाता। कुछ हिस्से रूमानिया, पोलैण्ड और इटली को मिल गये हैं। मतलब यह कि अच्छी तरह चीर-फाड़ और बांट-बखरा किया गया।

और आगे, उत्तर की तरफ एक और नया राज्य पैदा होगया है। या यों कहना ज्यादा सही होगा कि एक पुराना राज्य फिर से आ गया है। यह पोलैण्ड है। यह प्रशा, रूस और आस्ट्रिया से कई प्रदेश लेकर और उन्हें जोड़कर बनाया गया है। पोलैण्ड को समुद्र तक पहुँचने का रास्ता देने के लिए एक गैरमामूली बात की गई। जर्मनी या प्रशा के दो टुकड़े कर दिये गये और इन दोनों के बीच पोलैण्ड को जमीन का एक टुकड़ा, जिससे होकर वह समुद्र तक जा सकता था, दिया गया। पश्चिमी रूस से पूर्वी प्रशा को जाने में इस टुकड़े को पार करना पड़ता है। इसी टुकड़े के नजदीक डैनज़िग का मशहूर शहर है। इसे एक स्वतंत्र नगर बना दिया गया है। यानी इसपर न जर्मनी का कब्जा है, न पोलैण्ड का; वह खुद ही एक राज्य है और उसपर सीधे राष्ट्र-संघ का नियंत्रण है।

पोलैण्ड के उत्तर में लिथुएनिया, लटविया, इस्टोनिया और फिनलैण्ड के बाल्टिक राज्य हैं। ये सब पुराने ज़ार के साम्राज्य के वारिसों में से हैं। ये छोटे-छोटे राज्य हैं, पर हरेक की संस्कृति और भाषा अलग है। शायद तुमको यह बात दिलचस्प मालूम होगी कि लिथुएनियन लोग आर्य हैं (जैसी कि योरोप में और भी कई क्रौमें हैं) और उनकी भाषा संस्कृत से बहुत मिलती-जुलती है। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है जिसे हिन्दुस्तान में बहुत-से लोग नहीं महसूस करते, और जिससे हमें उन बंधनों की याद आती है जो दूर-दूर की क्रौमों को एक सूत्र में बाँधते हैं।

योरप में सिर्फ एक तब्दीली और हुई; अलसेस-लॉरेन का प्रान्त फ्रान्स को दे दिया गया। कुछ और तब्दीलियाँ भी हुई, पर मैं उनका जिक्र कर तुम्हें तंग न करूँगा। अब तुमने देख लिया है कि इन तब्दीलियों के कारण बहुत-से नये राज्य पैदा होगये, जिनमें से ज्यादातर बिल्कुल छोटे हैं। अब पूर्वी योरप बाल्कन-सा होगया है, इसीलिए अक्सर यह कहा जाता है कि शांति की संधियों ने योरप को 'बाल्कनाइज्ड' (Balkanised) कर दिया या बाल्कन-की-सी शकल में बदल दिया। अब बहुत-सी नई सीमायें या सरहदें पैदा होगई हैं और इन छोटे राज्यों में अक्सर झगडे चलते रहते हैं। यह देखकर हैरत होती है कि वे किस तरह एक-दूसरे से नफरत करते हैं। डैन्यूब नदी की घाटी वाले देशों में खास तौर से यह हालत है। इसकी ज्यादातर जिम्मेदारी मित्र-राष्ट्रों पर है, जिन्होंने योरप का बिल्कुल गलत तरीके पर बँटवारा किया और बहुत-सी नई समस्याएँ पैदा करदीं। बहुतेरी छोटी और कम तादाद वाली क्लौमों पर विदेशी सरकारों का कब्जा है जो उन्हें दबाती और उनपर अत्याचार करती रहती हैं। पोलैण्ड का काफ़ी बड़ा हिस्सा असल में उक्रेन का है और इस हिस्से के गरीब उक्रेनियनों को जबरदस्ती पोलिश बनाने के लिए उनपर तरह-तरह के अत्याचार किये गये हैं। इसी तरह जुगोस्लेविया, रूमानिया और इटली में भी छोटी तादाद वाली विदेशी क्लौमें हैं और उनके साथ बराबर बुरा और भद्दा बर्ताव किया जाता है। दूसरी तरफ़ आस्ट्रिया और हंगरी की हड्डी-हड्डी जुदा करदी गई और उनके अपने लोग उनसे छीन लिये गये हैं। विदेशी हुकूमत में रहनेवाले इन प्रदेशों में राष्ट्रीय आन्दोलनों और झगडों का बराबर खडे होते रहना स्वाभाविक है।

फिर इस नक्शे पर निगाह डालो। तुम देखोगी कि फिनलैंड, इस्टोनिया, लटविया, लिथुएनिया, पोलैण्ड और रूमानिया के राज्यों के सिलसिले के कारण रूस पश्चिमी योरप से एकदम अलहदा होगया है। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है, इन राज्यों में ज्यादातर बर्साई की सुलह से नहीं बनाये गये, बल्कि वे रूसी क्रान्ति के परिणाम थे। जो हो, मित्र-राष्ट्रों ने इनका स्वागत किया और खुशी जाहिर की। इसकी वजह यह थी कि वे रूस को गैरबोलशेवी योरप से अलग करते थे। वे 'स्वच्छता का घेरा' (Cordon Sanitaire जिससे छूत के रोगों को एक जगह से दूसरी जगह फैलने से रोका जाता है) थे, जो बोलशेविज्म के छूत के रोग को रोकने में मददगार हो सकते थे। ये सब बाल्टिक राज्य यानी बाल्टिक समुद्र के आस-पास के राज्य गैरबोलशेवी हैं, वरना वे सोवियट फेडरेशन में शामिल होजाते।

पश्चिमी एशिया में पुराने तुर्की साम्राज्य के कुछ हिस्सों पर यूरोपीय शक्तियों की ललचाई हुई आँखें पड़ीं। महायुद्ध के जमाने में अंग्रेजों ने यह वादा करके तुर्की

के खिलाफ अरबों में व्याप्त करा दी थी कि वे अरबस्तान, फिलस्तीन और सीरिया को मिलाकर एक संयुक्त अरब राष्ट्र का निर्माण करेंगे। जब अरबों से यह वादा किया जा रहा था, तभी इन प्रदेशों को आपस में बाँट लेने की एक गुप्त संधि भी अंग्रेज फ्रांसीसियों से कर रहे थे। यह कोई यश की बात न थी और वर्तमान ब्रिटिश प्रधान मंत्री रैम्से मैकडानल्ड ने इसे 'भद्दे दोरंगीपन' की एक कहानी कहकर पुकारा था। पर यह दस वर्ष पहले की बात है, जब वह मंत्री नहीं थे और कभी-कभी सच बोलने की जुर्रत कर सकते थे।

जब ब्रिटिश सरकार ने न सिर्फ अरबों के साथ किया हुआ वादा तोड़ने की कोशिश की बल्कि फ्रांस से की हुई गुप्त संधि से भी आँखें फेरनी चाहें, तब इसका एक अजीब कारण था। उनके दिमाग में एक महान् मध्यपूर्वी साम्राज्य का स्वप्न पैदा हुआ—ऐसे साम्राज्य का जो हिन्दुस्तान से मिस्र तक फैला हुआ हो। यानी वह बीच के बहुत बड़े हिस्से को हथिया कर हिन्दुस्तान के साम्राज्य को अपने अफ्रीका के राज्य से मिला देना चाहते थे। यह एक बड़ा ही ललचाने वाला और ज़बरदस्त सपना था। फिर भी उसके पूरा होने में उस वक्त कोई ज्यादा दिक्कत मालूम नहीं होती थी। १९१९ के उस जमाने में ब्रिटिश फौजों ने इन सब प्रदेशों—फ़ारस, इराक़, फिलस्तीन, अरबस्तान के कुछ हिस्सों और मिस्र पर क़ब्ज़ा कर रखा था। वे सीरिया से फ्रांस को बाहर रखने की कोशिश कर रही थीं। कुस्तुनतुनिया शहर भी अंग्रेजों के क़ब्ज़े में था। पर १९२०, १९२१ और १९२२ में जो घटनाएँ हुईं उनसे यह सपना टूट गया। ब्रिटिश मंत्रियों की इस महत्वाकांक्षा से भरी योजना को पीछे से सोवियट और आगे से कमालपाशा ने ख़त्म कर दिया।

किन्तु इतने पर भी ब्रिटेन ने पश्चिमी एशिया के कई प्रदेशों—इराक़ और फिलस्तीन—में अपना अधिकार कायम रखा और रिश्वत और दूसरे तरीक़ों का इस्तेमाल करके अरबस्तान में होनेवाली घटनाओं पर भी असर डालने की कोशिश की। सीरिया फ्रांसीसियों के क़ब्ज़े में आ गया। अरब देशों की नई राष्ट्रीयता और आजादी के लिए उनकी लड़ाई के बारे में मैं फिर कभी तुम्हें बताऊंगा।

अब हमें फिर वर्साई की संधि की तरफ़ लौट चलना चाहिए। इस संधि या सुलह ने यह फ़ैसला किया कि जर्मनी युद्ध छेड़ने के लिए कसूरवार है। इस तरह इस सुलहनामे पर दस्तख़त कराके जर्मनों से उनके अपने कसूर को ज़बरदस्ती मनवा लिया गया। ऐसी ज़ोर-ज़बरदस्ती की मंजूरी की कोई ज्यादा क़ीमत नहीं, इससे कटुता पैदा होती है, जैसी कि इस मामले में हुई भी।

जर्मनी को निःशस्त्र होने का भी हुक्म दिया गया। उसे सिर्फ छोटी सेना, ज्यादातर पुलिस के काम के लिए, रखने की अनुमति दी गई। उसे अपना सारा समुद्री बेड़ा मित्र-राष्ट्रों के सुपुर्द कर देना पड़ा। जब जर्मन बेड़ा सौंपने के लिए लेजाया जा रहा था, तब बेड़े के जर्मन अफसरों और आदमियों ने यह तय किया कि अंग्रेजों को सौंपने से अच्छा यही है कि उसे डुबो दिया जाय। यह फ़ैसला उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पर किया; यानी इस फ़ैसले से जर्मन-सरकार का कोई सरोकार न था। इस फ़ैसले के मुताबिक जून १९१९ में 'स्केपाल्फो' पर, जब ब्रिटिश लोग थोड़ी ही दूर रह गये थे और बेड़े पर क़ब्जा करने की तैयारी कर रहे थे, सारा जर्मन बेड़ा अपने ही नाविकों द्वारा डुबा दिया गया।

इसके अलावा युद्ध में मित्र-राष्ट्रों को जो नुक़सान उठाना पड़ा था उसका हर-जाना भी जर्मनी को देना था। इसे रिपेयरेशन या क्षति-पूर्ति कहा जाता था और तबसे यह शब्द योरप के ऊपर छाया-सा लटक रहा है। सुलहनामे में कोई निश्चित रक़म तय नहीं की गई थी, लेकिन उसमें उसका निश्चय करने की तजवीज़ रखी गई थी। इस तरह से मित्र-राष्ट्रों को युद्ध का हरजाना देने की जिम्मेदारी लेना एक बड़ा ज़वर-दस्त मामला था। उस वक़्त जर्मनी एक पराजित और उजड़ा हुआ देश था और अपनी घरेलू ज़िन्दगी को सन्हालने की बड़ी-बड़ी समस्याएँ उसके सामने थीं। उनके अलावा मित्र-राष्ट्रों की क्षति का बोझ उठा लेना एक असम्भव काम था, जिसके पूरा होने की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। पर मित्र-राष्ट्र घृणा और बदले की भावना से भर रहे थे और न सिर्फ़ मांस नौचना चाहते थे बल्कि ज़मीन पर लोटते हुए जर्मनी के खून की आख़री बूंद तक पी जाना चाहते थे। इंग्लैंड में लायड जार्ज ने 'क्रैंसर को फाँसी दे दो' का नारा उठाकर ही पार्लमेण्ट के चुनाव में फतह हासिल की थी और फ़्रांस में तो इससे भी ज्यादा बदले की कटु भावनाएँ थीं।

सुलह की इन धाराओं का सारा मतलब वस यह था कि हर संभव उपाय से जर्मनी को बाँध दिया जाय, उसे निकम्मा कर दिया जाय और ऐसा कर दिया जाय कि फिर वह सिर न उठा सके या मज़बूत न हो सके। उसे पीढ़ियों तक मित्र-राष्ट्रों का आर्थिक गुलाम रखने और उससे हर साल खिराज की शकल में बड़ी-बड़ी रक़में ऐंठते रहने की तजवीज़ की गई थी। इतिहास का यह बिल्कुल साफ़ सबक़ कि किसी बड़ी झोम को लम्बे अर्से तक यों बाँध रखना मुमकिन नहीं है, इन बड़े-बड़े राजनीतिज्ञों के, जिन्होंने प्रतिहिंसा या बदले की इस शान्ति की नींव रखी थी, ध्यान में नहीं आया। आज वे इसके लिए पछता रहे हैं।

अन्त में तुमको मुझे राष्ट्रपति विल्सन की सन्तान उस राष्ट्रसंघ के द्वारे में

भी कुछ बताना चाहिए जिसे वर्साई की सन्धि ने दुनिया के सामने पेश किया। खयाल था कि यह स्वतन्त्र और स्वशासित यानी आजाद और खुदमुख्तार राज्यों का संघ होगा। इसका उद्देश्य न्याय और प्रतिष्ठा के आधार पर परस्पर सम्बन्ध कायम करके भविष्य में युद्धों का प्रतीकार करना और दुनिया की क्रीमों में बौद्धिक और भौतिक सहयोग को बढ़ाना था। उद्देश्य तो बिला किसी शुबहे के तारीफ़ के काबिल था। संघ के हरेक सदस्य-राष्ट्र ने यह मंजूर किया कि वह एक सहयोगी राष्ट्र से तबतक युद्ध न छेड़ेगा जबतक कि शान्तिपूर्ण समझौते की सारी कोशिशें और सम्भावनायें नाकाम साधित न हो जायें और इसके बाद भी नौ महीने धीत जाने के बाद ही युद्ध का सहारा लेगा। यह तजवीज की गई कि अगर कोई सदस्य-राष्ट्र इस प्रतिज्ञा को तोड़ेगा तो और राष्ट्र उससे किसी तरह का आर्थिक सम्बन्ध न रखेंगे। कागज पर लिखा हुआ यह सब बहुत अच्छा लगता है; पर व्यवहार में बात इसके बिलकुल खिलाफ़ हुई। यह याद रखने की बात है कि सिद्धान्त या उसूल में भी संघ ने युद्ध का अन्त करने की कोशिश नहीं की। हाँ, उसने लड़ाई के रास्तों में दिक्कतें पैदा करने की कोशिश जरूर की, ताकि वक्त गुजर जाने और समझौते के प्रयत्नों से युद्ध का जोश-खरोश कम हो जाय। युद्ध के कारणों को दूर करने की उसने कोशिश नहीं की।

राष्ट्र-संघ में एक तो असेम्बली थी, जिसमें सब सदस्य-राष्ट्रों को प्रतिनिधित्व मिला था; दूसरी कौंसिल थी, जिसमें महाशक्तियों के स्थायी प्रतिनिधि होते थे और कुछ प्रतिनिधि असेम्बली द्वारा भी चुने जाते थे। इसका एक सेक्रेटरियट (मंत्रि-कार्यालय) रखा गया, जिसका सदर मुक़ाम, जैसा तुम जानती हो, जेनेवा में है। कामों के दूसरे भी कई विभाग थे। एक अन्तर्राष्ट्रीय मजूर कार्यालय, जो मजूरों के सवालों पर गौर करता था; दूसरा अन्तर्राष्ट्रीय न्याय की स्थायी अदालत (Permanent Court of International Justice), जिसका स्थान हेग में रखा गया; तीसरी बौद्धिक सहयोग के लिए एक कमेटी। राष्ट्रसंघ के साथ ही सब काम शुरू नहीं हुआ; कई काम बाद में बढ़ाये गये।

राष्ट्रसंघ का मूल विधान वर्साई-संधि में शामिल था। इसे ही 'राष्ट्रसंघ का शर्तनामा' (Covenant of the League of Nations) कहते हैं। इस शर्तनामे में यह तजवीज भी थी कि राष्ट्र की रक्षा के लिए जितनी सेना की जरूरत हो उतनी ही रखी जाय और सब राष्ट्र अपनी सेना को घटाकर कम-से-कम कर दें। जर्मनी का निःशस्त्रीकरण (जो ज़बरदस्ती किया गया) इस दिशा में पहला क़दम समझा गया और यह तय हुआ कि दूसरे देश उसका अनुकरण करेंगे। यह भी कहा गया कि किसी

राज्य के हमला करने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जायगी। पर यह स्पष्ट नहीं किया गया कि 'हमला' (Aggression) किसे कहा जायगा। जब दो क्रौमें या राष्ट्र लड़ते हैं तो उनमें से हरेक दूसरे को कसूरवार बताता और उसे आक्रामक या हमला-वार (Aggressor) कहता है।

महत्वपूर्ण मामलों का फैसला राष्ट्रसंघ सर्वसम्मति से ही कर सकता था। इसलिए अगर एक भी सदस्य-राष्ट्र किसी प्रस्ताव के खिलाफ राय दे तो वह गिर जाता था। इसका मतलब यह था कि बहुमत का कोई दबाव नहीं था। इसका यह भी मतलब था कि राष्ट्रीय सरकारें आजाद हैं और करीब-करीब उतनी ही गौर-जिम्मेदार हैं जितनी पहले थीं। राष्ट्रसंघ उनपर किसी महाराष्ट्र की तरह हावी नहीं था। इस तजवीज ने राष्ट्रसंघ को बहुत कमजोर बना दिया और व्यवहार में उसे सिर्फ एक सलाह देनेवाली संस्था का रूप दे दिया।

कोई भी स्वतंत्र राष्ट्र संघ में शामिल हो सकता था, लेकिन चार देश साफ़ तौर पर अलग कर दिये गये थे : जर्मनी, अस्ट्रिया, तुर्की यानी पराजित देश, और बोलशेवी रूस। पर यह तजवीज की गई थी कि बाद में, कुछ शर्तों पर, वे शामिल किये जा सकते हैं। ताज्जुब तो यह है कि हिन्दुस्तान राष्ट्रसंघ के मूल सदस्यों में से एक हुआ। यह संघ के नियम के बिल्कुल खिलाफ़ था, क्योंकि उसके मुताबिक सिर्फ़ आजाद और खुदमुस्तार मुल्क ही सदस्य हो सकते थे। पर 'हिन्दुस्तान' का मतलब हिन्दुस्तान की ब्रिटिश सरकार से था और इस चालाकी से ब्रिटिश सरकार को एक और प्रतिनिधि मिल गया। दूसरी तरफ़ अमेरिका ने, जो एक तरह से राष्ट्रसंघ को जन्म देनेवाला था, इसमें शामिल होने से साफ़ तौर पर इनकार कर दिया। अमेरिकन लोग राष्ट्रपति विल्सन के कामों और यूरोपियन साजिशों व झगड़ों से ऊब गये और उन्होंने इससे अलग ही रहने का फैसला किया।

बहुत-से लोग राष्ट्रसंघ की तरफ़ उत्साह और इस उम्मीद से देख रहे थे कि वह हमारी आजकल की दुनिया के झगड़ों का ख़ात्मा कर देगा, या कम-से-कम उसमें बहुत ज्यादा कमी कर देगा और शान्ति और बहुतायत का युग ले आयगा। संघ को लोकप्रिय बनाने और सवालियों पर अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से गौर करने की आदत डालने के लिए बहुत-से देशों में राष्ट्रसंघ सम्बन्धी संस्थाएँ बनाई गईं। दूसरी तरफ़ बहुत-से लोगों ने संघ को एक बड़ी धोखे और साजिश की ऐसी चीज़ बताया जो बड़ी शक्तियों की स्वार्थ से भरी हुई योजनाओं को पूरा करने के लिए बनाई गई थी। अब हमने इसका कुछ व्यावहारिक अनुभव भी प्राप्त कर लिया है और शायद इसकी उपयोगिता की जाँच करना अब कहीं आसान है। संघ की हस्ती १९२० के नये दिन

(१ जनवरी) से शुरू हुई थी और अवतक इसे सवातेरह वर्ष बीत चुके हैं (में यह अप्रैल १९३३ में लिख रहा हूँ) । इसमें शक नहीं कि एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था के इतिहास में यह कोई लम्बी अवधि नहीं है ; फिर भी संघ को कई तरह से अविश्वसनीय साबित करने के लिए इतना बख्त काफ़ी है । यह ठीक है कि इसने आजकल की जिन्दगी की मुहल्लिफ़ गलियों में अच्छा काम किया है और यही बात कि अन्तर्राष्ट्रीय सवालों पर विचार करने के लिए इसने राष्ट्रों—या यह कहना ज्यादा सही होगा कि उनको सरकारों—को एक जगह जमा किया है, पुराने तरीकों पर एक तरक्की ही है ; पर शान्ति रखने या युद्ध की संभावना को कम करने के अपने असल उद्देश्य को पूरा करने में यह विलकुल नाकामयाब हुआ है ।

राष्ट्रसंघ के बारे में राष्ट्रपति विल्सन का असल मतलब चाहे जो रहा हो, पर इसमें शक नहीं कि महाशक्तियों के, खासकर इंग्लैंड और फ़्रांस के, हाथ में संघ एक अस्त्र या हथियार रहा है । इसका असल काम वर्तमान व्यवस्था को कायम रखना है । यह राष्ट्रों के बीच न्याय और प्रतिष्ठा यानी इन्साफ़ और ईमान की बात करता है, पर यह जाँच नहीं कर करता कि क्या वर्तमान सम्बन्ध इन्साफ़ और ईमानदारी पर कायम हैं ? यह राष्ट्रों के 'घरू या अन्दरूनी मामलों' (Domestic Affairs) में दस्तन्दाजी न करने का ऐलान करता है । किसी साम्राज्यवादी ताक़त के मातहत देश इसके लिए 'अन्दरूनी या घरेलू मामले' हैं । इसलिए जहाँतक संघ का तात्लुक है तहाँतक यह कहा जा सकता है कि वह इन ताक़तों द्वारा इनके साम्राज्यों को सदा मातहत या गुलाम बनाये रखने का समर्थन करता है । इसके सिवा जर्मनी और तुर्की से लिये हुए नये प्रदेश भी मित्र-राष्ट्रों को इसने 'मैण्डेट' यानी 'शासनादेश' के नाम पर सौंप दिये हैं । यह 'मैण्डेट' या 'शासनादेश' शब्द राष्ट्रसंघ की मनोवृत्ति को ठीक-ठीक जाहिर करता है, क्योंकि यह एक नये और खुशनुमा नाम के नीचे पुराने साम्राज्यवादी शोषण के ही सिलसिले को सूचित करता है । मजा तो यह है कि ऐसा समझ लिया गया है कि ये 'मैण्डेट' या 'शासनादेश' इन प्रदेशों की जनता की इच्छा के अनुसार ही दिये गये हैं । इन दुखिया क़ौमों में से कई ने तो इन शासनादेशों के ख़िलाफ़ बगावत भी की है और काफ़ी असें तक ख़ूनी लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं । उन्होंने तबतक इनके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलन्द की है जबतक कि वे बम-वर्षा और तोपों की मार से झुकने को मजबूर नहीं कर दी गई हैं । सम्बन्धित जनता की राय जानने का यह तरीक़ा रहा है !

ख़ूबसूरत लफ़्ज़ और जुमले इस्तेमाल किये गये हैं । साम्राज्यवादी ताक़तें 'मैण्डेट' या 'शासनादेशप्राप्त' इन प्रदेशों के बाशिन्दों की 'द्रुस्ती' रही हैं और संघ

का काम यह देखना रहा है कि ट्रस्ट या थाती की शर्तें पूरी की जा रही हैं या नहीं। सच पूछो तो इससे मामला और बिगड़ गया है। ये शक्तियाँ जो चाहती करती रही हैं, पर ऊपर से उन्होंने पाखंड से भरा हुआ चोंगा पहन रक्खा है और असावधान लोगों के अन्तःकरण को शिथिल और अचेत कर दिया है। जब किसी छोटे राष्ट्र ने संघ का किसी तरह अपमान किया, तब संघ ने कड़ाई से काम लिया और अपनी बेखूबी से उसे सजा देने की कोशिश की है; पर जब किसी बड़ी ताकत ने उसका अपमान किया, तब संघ वहाँसे नज़र हटाकर दूसरी तरफ़ देखने लगा है, या कम-से-कम उसने अपराध की गुस्ता घटाने की कोशिश की है।

इस तरह महाशक्तियों ने संघ पर अपना नियंत्रण रक्खा है, जब स्वार्थ साधने की ज़रूरत हुई तब उसका इस्तेमाल किया है और जब उपेक्षा करने में ही ज्यादा सहूलियत या फ़ायदा मालूम पड़ा तब उसकी उपेक्षा की है। शायद दोष संघ का नहीं था, दोष उस प्रणाली का था जो अपनी प्रकृति के कारण संघ को बरदाश्त करनी पड़ी। साम्राज्यवाद का तत्त्व ही मुक्तलिफ़ ताक़तों के बीच की जबरदस्त प्रतिद्वंद्विता और प्रतियोगिता यानी लाग-डांट है, क्योंकि इनमें से हरेक जहाँतक मुमकिन हो वहाँतक ज्यादा-से-ज्यादा दुनिया का शोषण करना चाहती है। अगर किसी समाज के सदस्य बराबर एक-दूसरे की जेब से धन लूटने की कोशिश करते रहें, या एक-दूसरे का गला काटने के लिए अपने चाकू तेज़ करते रहें, तो उनके बीच कुछ ज्यादा सहयोग की उम्मीद नहीं की जा सकती और न समाज की ज्यादा तेज़ तरक्की की ही आशा की जा सकती है। इसलिए यह कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि जन्मदाताओं और अभिभावकों के जबरदस्त गिरोह के होते हुए भी संघ कमज़ोर और निर्जीव होगया।

वर्साई में सुलह की बहसों के सिलसिले में जापानी सरकार की तरफ़ से यह प्रस्ताव रक्खा गया था कि सुलहनामे में जातीय समानता (Racial Equality) को स्वीकार करने की एक धारा रक्खी जाय पर वह मंज़ूर नहीं किया गया। मगर किसी तरह चीन में कियानचान देकर जापान के आँसू पोछ दिये गये। बृहत्रय (The 'Big Three') ने चीन जैसे कमज़ोर दोस्त के खर्चे पर उदारता दिखाई। इसलिए चीन ने सुलहनामे पर दस्तख़त नहीं किये।

ऐसी वह 'वर्साई की संधि' थी, जिसने 'युद्ध' को ख़त्म करने के लिए लड़े गये 'युद्ध' का ख़ात्मा कर दिया। पिछले चौदह वर्षों का इतिहास इस सन्धि पर एक काली टीका है। प्रसिद्ध अंग्रेज़ राजनीतिज्ञ श्री फिलिप स्नाउडन (अब वाइकौण्ट स्नाउडन) ने, जो कुछ ही दिन पहले तक इंग्लैंड के अर्थसचिव थे, इस सन्धि पर निम्नलिखित टीका की थी :—

“The Treaty should satisfy brigands, imperialists and militarists. It is the death-blow to the hopes of those who expected the end of the war to bring peace. It is not a peace treaty, but a declaration of another war. It is the betrayal of democracy and the fallen in the war. The treaty exposes the true aims of the Allies.”

अर्थात्, “यह सुलहनामा लुटेरों, साम्राज्यवादियों और सैन्यवादियों को संतुष्ट कर सकता है। यह उन लोगों की उम्मीदों पर विजली का गिरना है जो शान्ति के लिए युद्ध का अन्त करने की आशा करते थे। यह शान्ति की संधि नहीं है बल्कि दूसरे युद्ध की घोषणा है। यह प्रजातंत्रवाद और युद्ध में शहीद हुए लोगों के प्रति विश्वासघात है। सन्धि ने मित्र-राष्ट्रों के असली मतलब को साफ़-साफ़ जाहिर कर दिया है।”

प्रकट है कि अपनी घृणा और अभिमान यानी नफ़रत और गुरुर में मित्र-राष्ट्र अपनी सीमा से कहीं आगे बढ़ गये थे। अभीसे वे इसके लिए काफ़ी पछता रहे हैं और सन्धि पर फिर से गौर करने और उसे बदलने की बातचीत भी होने लगी है। पर, शायद, अब बहुत देर हो गई है।

यह ख़त कितना लम्बा होगया !

: १५६ :

महायुद्ध के बाद की दुनिया

२६ अप्रैल, १९३३

अब हम अपने सफ़र की आखिरी मंज़िल में हैं; हम आज यानी वर्तमान की दहलीज पर हैं। हमें महायुद्ध के बाद की दुनिया पर गौर करना है। अब हम अपने ही ज़माने में हैं—या निश्चय ही तुम्हारे ज़माना में ! यह आखिरी मंज़िल है और, जहाँतक वक्त का सवाल है, बहुत छोटी मंज़िल है, पर यह एक मुश्किल सफ़र है। महायुद्ध ख़त्म होने के बाद से इसे सिर्फ़ साढ़े चौदह साल हुए हैं; और हम इतिहास के जिन लम्बे युगों पर विचार कर चुके हैं उनके मुक़ाबिले में यह समय का कितना छोटा टुकड़ा है ? लेकिन हम बिल्कुल इसके साथ गुंथे हुए हैं और इतने नज़दीक से इसके बारे में ठीक राय क़ायम करना बहुत मुश्किल है। हम इसे ठीक तौरपर देखने और अंकित करने की प्रवृत्ति नहीं पैदा कर सकते और न वह स्थिर निष्पक्षता या निस्संगता ही प्राप्त कर सकते हैं जो इतिहास चाहता है। बहुतेरी घटनाओं के बारे में हम बहुत ज्यादा उत्तेजित हैं, इसलिए छोटी बातें हमें बड़ी मालूम पड़ सकती हैं और बड़ी बातों में से कई का हम पूरा महत्त्व समझने से वंचित रह जा सकते हैं। हम वृक्षों की बहु-

तायत में अपनेको खो दे सकते हैं और जंगलों को ठीक तौर पर देखने से वंचित हो सकते हैं।

फिर यह जानने की मुश्किल भी आती है कि हमें घटनाओं के महत्त्व को कैसे नापना चाहिए। हमें इसके लिए किस गज का इस्तेमाल करना चाहिए? यह जाहिर है कि वह बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि हम चीजों और घटनाओं पर किस तरह निगाह डालते हैं। एक दृष्टिकोण से कोई घटना हमें महत्त्वपूर्ण मालूम पड़ सकती है और दूसरी दृष्टि से वही घटना बिल्कुल महत्त्वशून्य और नाचीज मालूम होगी। मुझे भय है कि कुछ सीमा तक मैंने तुमको लिखे हुए अपने खतों में इस सवाल को दर-गुजर किया है; मैंने इसका स्पष्ट और उचित जवाब नहीं दिया है। मेरे सामान्य दृष्टिकोण ने उन सब बातों को रंगीन बना दिया है जिनकी वास्तव मैंने लिखा है। इन्हीं युगों और घटनाओं के बारे में दूसरा आदमी शायद बिल्कुल जुदी बातें लिखता।

इस वक्त मैं इस सवाल की गहराई में नहीं जाना चाहता कि इतिहास के बारे में हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। खुद मेरा दृष्टिकोण हाल के इन वर्षों में बहुत ज्यादा बदल गया है। और जैसे इस और दूसरी चीजों के बारे में अपने खयालात बदले हैं वैसे ही दूसरे बहुत-से लोगों ने बदले हैं। क्योंकि महायुद्ध ने हर चीज और हर आदमी को बुरी तरह झकझोर दिया है। इसने पुरानी दुनिया को पूरी तरह से उलट दिया और तबसे हमारी यह गरीब पुरानी दुनिया, वगैरह कुछ ज्यादा काम-याबी के, फिर से उठने की कोशिश कर रही है। इसने विचारों की सारी प्रणाली को, जिसपर हम बड़े थे, हिला दिया है और आधुनिक समाज और सभ्यता के आधार के बारे में ही हममें शंकाएँ पैदा करदी हैं। हमने नौजवानों का भयंकर संहार देखा; हमने झूठ, हिंसा, पशुता या हैवानियत और विनाश देखा और हैरत में आगये कि यह सभ्यता का ख़ात्मा तो नहीं है। रूस में सोवियट उठ खड़ा हुआ; यह एक नई चीज, एक नई समाज-व्यवस्था और प्राचीन के प्रति एक चुनौती थी। दूसरे भी बहुत-से खयालात हवा में फैल रहे थे। यह विश्रृंखल होने या बिखरने का ज़माना था; यह शंका और प्रश्नों यानी शबहे और सवालों का ज़माना था, जो तेज तब्दीलियों के युग में सदा आता है।

महायुद्ध के बाद के दिनों पर इतिहास की तरह गौर करने में ये सब बातें विष्कृत पेश करती हैं। लेकिन जहाँ हम मुस्तलिफ़्र तरह के विश्वासों और विचारों पर बहस कर सकते, उनकी सचाई पर सवाल उठा सकते और उनमें से किसीको महज इसलिए मानने से इनकार कर सकते हैं कि वे पुराने हैं, वहाँ हम विचारों से खिलवाड़ करने और हमें धरा करना चाहिए, इसके बारे में खूब अच्छी तरह सोचने से छुटकारा पाने

का इसे कोई बहाना नहीं बना सकते। दुनिया के इतिहास में परिवर्तन के ऐसे युग खासतौर पर शरीर और मन से काम लेने का आवाहन करते हैं। ये ऐसे जमाने होते हैं जब जीवन के शुष्क कार्यक्रम में ताजगी आजाती है और साहसिकता हमें पुकारती है और हम सब नई व्यवस्था के निर्माण में अपना हिस्सा ले सकते हैं। ऐसे वक्तों में नौजवानों ने हमेशा प्रधान अभिनय किया है, क्योंकि वे बदलते हुए ख्यालात और हालात के मुताबिक अपनेको उन लोगों की वनिस्वत कहीं ज्यादा आसानी से मोड़ सकते हैं जो बूढ़े या पुराने हैं और अपने प्राचीन विश्वासों में जम गये और कठोर होगये हैं।

शायद यह ज्यादा अच्छा होगा कि हम महायुद्ध के बाद के इस जमाने की ज़रूर विस्तार से परीक्षा करें। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस खत में इस जमाने का सरसरी तौर पर सिंहावलोकन करूँ। नेपोलियन के पतन के बाद के उन्नीसवीं सदी के हमारे सिंहावलोकन की तुम्हें याद होगी। लाज़िमी तौर पर १८१५ ई० की 'वियेना की शान्ति' (The Peace of Vienna) और उसके परिणामों पर ध्यान जाता है और १९१९ ई० की वर्साई की शान्ति और उसके परिणामों के साथ उसकी तुलना करने का मन होता है। वियेना की शान्ति सुखदाई न थी; उसने योरप में आगे होनेवाली लड़ाइयों का बीज बोया। अनुभव से कुछ न सीखने के कारण हमारे राजनीतियों ने वर्साई की शान्ति को उससे भी बुरा बना दिया, जैसा कि हम पिछले खत में देख चुके हैं। महायुद्ध के बाद के वर्षों पर इस कही जाने वाली शान्ति की काली छाया बड़े घने रूप में पड़ती रही है।

तब इन पिछले चौदह वर्षों की बड़ी-बड़ी घटनायें कौन-सी हैं? मेरी समझ से अपने महत्व में सबसे पहली और ध्यान खींचनेवाली घटना सोवियट यूनियन या यू० एस० एस० आर० यानी 'यूनियन आफ़ सोशलिस्ट एण्ड सोवियट रिपब्लिक्स' (समाजवादी एवं सोवियट प्रजातंत्र-संघ) का उदय और संगठन है। मैं उन दिक्कतों में से कुछ का जिक्र तुमसे कर चुका हूँ जो सोवियट रूस को दुनिया में अपनी हस्ती कायम रखने की लड़ाई में वर्दाश्त करनी पड़ी हैं। इन दिक्कतों के बीच भी उसकी विजय इस सदी का एक आश्चर्य है। एशिया में जहाँ-जहाँ पहले का जारशाही साम्राज्य फैला हुआ था वहाँ-वहाँ यानी प्रशान्त महासागर तक फैले हुए साइबेरिया और भारतीय सीमा को छूनेवाले मध्यएशिया में सोवियट शासन-प्रणाली कायम होगई। अलग-अलग सोवियट प्रजातंत्र कायम हुए, पर सब मिलकर एक संघ में शामिल होगये और यही अब यू० एस० एस० आर० है। यह यूनियन या संघ योरप और एशिया के लम्बे-चौड़े हिस्सों में फैला हुआ है, जो अपने क्षेत्रफल में सारी दुनिया के क्षेत्रफल का छठा हिस्सा

है। क्षेत्रफल तो बहुत बड़ा है, पर सिर्फ क्षेत्रफल के बड़े होने का कोई खास मतलब नहीं होता और फिर रूस और उससे भी कहीं ज्यादा मध्यएशिया और साइबेरिया बहुत पिछड़े हुए देश थे। सोवियट ने दूसरा चमत्कार जो किया वह यह था कि उसने इन प्रदेशों के बड़े-बड़े हिस्सों को अपनी नई योजनाओं से कुछ-का-कुछ बना दिया। लिखित इतिहास में किसी जाति की इतनी तेज तरक्की का दूसरा कोई उदाहरण नहीं मिलता। मध्य-एशिया के सबसे ज्यादा पिछड़े हुए देश भी इतनी तेजी से आगे बढ़े हैं कि हम हिन्दुस्तान के वाशिनटों को ईर्ष्या हो सकती है। सबसे ज्यादा उल्लेखनीय तरक्की शिक्षा और उद्योग-धंधों में हुई है। पाँच वर्ष वाली योजना के जरिये, जिसकी अवधि हाल ही में पूरी हुई है, रूस का बड़ी तेजी से उद्योगीकरण हुआ है और बेशुमार कारखाने खड़े होगये हैं। इन सब बातों का जनता पर बड़ा जबरदस्त बोझ पड़ा है और लोगों को अपने आराम की चीजों—यहां तक कि जिन्दगी की जरूरियात का भी त्याग करना पड़ा है, ताकि उनकी आमदनी का ज्यादा हिस्सा प्रथम समाजवादी देश के निर्माण में लगाया जा सके। ज्यादातर बोझ किसानों पर पड़ा है और जब मैं यह खत लिख रहा हूँ तब एक मुसीबत का साल उनके सिर पर दौड़ा आ रहा है।

इस आगे बढ़ते हुए सोवियट प्रदेश और अपनी बराबर बढ़ती हुई मुसीबतों वाले पश्चिमी योरप के बीच का अन्तर बहुत साफ़ और उल्लेखनीय है। अपनी सारी दिक्कतों के साथ अब भी, पश्चिमी योरप रूस से ज्यादा मालदार है। अपने वैभव के लम्बे जमाने में इसने अपने अन्दर बहुत ज्यादा चर्बी बढ़ा ली थी, जिसपर यह कुछ वक़्त तक गुजर कर सकता है। लेकिन हर मुल्क पर कर्ज का जो बोझ है, वसर्दी संधि के मुताबिक जर्मनी से ली जाने वाली हरजाने की रकम, और छोटी-बड़ी ताकतों में सदा चलने वाले झगड़े और लाग-डांट ने ग़रीब योरप की बड़ी घुरी हालत कर दी है। इन कठिनाइयों और मुसीबतों से निकलने का रास्त ढूँढ़ने के लिए एक के बाद एक कांग्रेस होती रही हैं पर कोई रास्ता नहीं निकला है और स्थिति दिन-दिन ख़राब होती जाती है। आज सोवियट रूस की पश्चिमी योरप से तुलना या मुकाबिला करना बहुत बड़ा बोझ सिर पर रखे पर जिन्दगी और स्फूर्ति से भरे हुये एक नौजवान का उस दूरे आदमी से मुकाबला करना है जो उम्र रहते लाजिमी तौर पर ग़रूर के साथ आगे तो चल रहा है पर जिसमें कोई आशा या स्फूर्ति बाकी नहीं रही है।

ऐसा मालूम पड़ता था कि महायुद्ध के बाद संयुक्तराष्ट्र अमेरिका इस छूत से दूध गया है। दस वर्ष तक वह बड़े जोरों से वैभव में बढ़ता और तरक्की करता गया। साहूकारी के धन्ये में इंग्लैण्ड के दबदबे को उसने युद्ध के जमाने में ख़त्म कर दिया था। अब अमेरिका दुनिया का ऋणदाता या साहूकार था और सारी दुनिया उसकी ऋणी

थी। आर्थिक दृष्टि से देखें तो एक तरह से वह सारी दुनिया पर हावी था और वह दुनिया से मिलनेवाले ख़िराज पर आराम के साथ ज़िन्दगी बसर कर सकता था, जैसे कुछ हद तक पहले इंग्लैंड कर चुका था। पर इसमें दो दिक्कतें आ गईं। कर्जदार देश बड़ी दूरी हालत में थे और अपना कर्ज नकद अदा नहीं कर सकते थे। सिर्फ़ एक ही ढंग से वे कर्ज अदा कर सकते थे कि कारखानों में चीज़ें बनायें और उन्हें अमेरिका भेजें। लेकिन अमेरिका इस ख़याल को पसन्द नहीं करता था कि उसके यहाँ विदेशी माल आवे और इसी ख़याल से उसने विदेशी माल को देश के अन्दर आने से रोकने के लिए गहरी चुंगी लगा दी। तब बेचारे कर्जदार देश कर्ज कैसे अदा करते? एक शानदार रास्ता निकाला गया। अमेरिका का जो कर्ज है उसका सूद उसे मिलता रहे इसके लिए (वह कर्जदार देशों को) और कर्ज देगा। यह कर्ज वसूल करने का एक गैर-मामूली तरीका था क्योंकि इसका मतलब तो ऋणदाता या साहूकार का और कर्ज देते जाना और यों कर्ज को बढ़ाना था। यह काफी तौर पर जाहिर होगया कि ज्यादातर कर्जदार देश अपना कर्ज कभी चुका न सकेंगे, तब एकाएक अमेरिका ने कर्ज देना बन्द कर दिया और सारी प्रणाली भरभराकर एकदम से बैठ गई। और एक अजीब बात हुई। अमेरिका, लवालब सोने से भरा हुआ मालदार अमेरिका वेशुमार बेकार श्रमिकों या मजूरों का देश होगया, उद्योग-धंधों के पहिये एकाएक चलने बंद होगये और चारों तरफ़ तबाही फैल गई।

जब मालदार अमेरिका की इतनी बुरी हालत थी तो योरप की हालत का अन्दाज़ आसानी से किया जा सकता है। हरेक देश ने चुंगी की दीवारें या रोक खड़ी करके विदेशी माल को देश के अन्दर आने से रोकने की कोशिश की और 'सिर्फ़ देशी माल ख़रीदो' इसका प्रचार किया। हर देश दूसरे मुल्कों को अपना माल तो बेचना चाहता था पर उनसे ख़रीदना न चाहता था, या कम-से-कम जितना मुमकिन हो उतना ही ख़रीदना चाहता था। ऐसी बातें अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का ख़ात्मा किये बिना ज्यादा दिन तक नहीं चल सकतीं, क्योंकि व्यापार-व्यवसाय तो विनिमय या बदले पर ही चलते हैं। इस नीति को आर्थिक राष्ट्रवाद कहते हैं। यह और उग्र राष्ट्रीयता की दूसरी कितनी ही बातें सभी देशों में फैल गई। ज्यों-ज्यों व्यापार-धन्धे कमजोर पड़ते गये, हर देश की दिक्कतें बढ़ती गईं और बड़ी साम्राज्यवादी ताकतों ने बाहर के अपने साम्राज्यों का ज्यादा-से-ज्यादा शोषण करके और अपने देश में मजूरों की मजूरी में कमी करके किसी तरह काम बनाने की कोशिश की। दुनिया के मुसललिफ़ हिस्सों का शोषण करने की इच्छा और प्रयत्न में प्रतिद्वंद्वी साम्राज्यवादों की एक-दूसरे से ज्यादा टक्कर होने लगी। उधर राष्ट्रसंघ बगुलाभगत की तरह शान्ति

की बातें करता और उसके लिए अमली तौर पर कुछ करता-धरता न था, इधर युद्ध का भूत दिन-दिन नजदीक आता हुआ दिखाई देता था। वस, फिर अनिवार्य दीख पड़नेवाले युद्ध के लिए शक्तियों में गुटबन्दी शुरू होगई।

आज भी, जब मैं यह खत लिख रहा हूँ, हम उस महान् मन्दी के बीच में हैं जिसने विश्व के पूंजीवाद को गिरा दिया है। मामूली हालत में लौटने के लिए ज़ोरों के साथ उपाय ढूँढे जा रहे हैं। मैं नहीं जानता कि कोई उपाय निकलेगा। हो सकता है कि पूंजीवाद अपनी इस आकस्मिक बीमारी से उबरने की कोई दवा ढूँढले, पर इसमें बड़ा शुबहा है कि वह फिर पूरी तरह स्वस्थ या तन्दुरुस्त हो सकेगा। साम्यवादी विश्लेषण अपनेको ठीक साबित करता मालूम पड़ रहा है और पूंजीवाद अपने ही अन्दरूनी विरोधों से ख़त्म हो रहा है और अगर इस बार की मुसीबत उसे न मार सकी तो बाद की दूसरी मुसीबत मार देगी। ताज़्जुब तो यह है कि यद्यपि सब पूंजीवादी देश सोवियट यूनियन से नफ़रत करते हैं, पर उसे गिरा या दबा देने के लिए आपस में एका तक नहीं कर सकते।

इस तरह हम उस महान् युग के ख़ात्मे के नजदीक पहुँच गये जिसमें पूंजीवादी सभ्यता का पश्चिमी योरोप और अमेरिका पर बोलबाला रहा और उसने बाक़ी दुनिया पर भी अपना दबदबा क़ायम रक्खा। महायुद्ध के बाद के पहले दस वर्ष तक यह मालूम पड़ता था कि शायद पूंजीवाद फिर उठ खड़ा हो और एक दूसरे लम्बे युग के लिए ताक़तवर होजाय। पर पिछले तीन वर्षों ने इसे बहुत सन्देहजनक बना दिया है। न सिर्फ़ पूंजीवादी राष्ट्रों की आपसी प्रतिद्वंद्विता या लाग-डॉट ख़तरे की सीमा तक बढ़ गई है बल्कि हर राज्य में श्रेणी-संघर्ष यानी मजदूरों और पूंजीपति स्वामी-वर्ग के, जिसका सरकारों पर नियंत्रण है, बीच कशमकश गहरी होती जाती है। इसलिए बड़ी ताक़तों के बीच राष्ट्रीय युद्ध और हर देश में गृह-युद्ध होने के ख़तरे बढ़ते जाते हैं। ज्यों-ज्यों हालत दुरी होती जाती है, स्वामी-वर्ग उठते हुए मजूरों को कुचलने का आख़िरी प्रयत्न कर रहा है। इसने फ़ैसिज्म की शक्ल इस्तिथार करली है। जहाँ श्रेणी-संघर्ष बहुत जोरदार और ख़तरनाक होगया है और पूंजीपति या स्वामी-वर्ग अपनी विशेष सुविधा की स्थिति से अलग कर दिये जाने के ख़तरे में हैं वहाँ फ़ैसिज्म पैदा होगया है।

महायुद्ध के बाद शीघ्र ही इटली में फ़ैसिज्म शुरू होगया। जब मुसोलिनी के नेतृत्व में फ़ैसिस्टों ने क़ब्ज़ा हासिल किया, तब मजदूर अशान्त और उग्र हो रहे थे। तबसे इटली पर बराबर फ़ैसिस्टों का क़ब्ज़ा है। फ़ैसिज्म का मतलब नंगी स्वेच्छा-चारिता है। यह प्रजातंत्र-प्रणाली की ख़ुलेआम निन्दा करता है। थोड़ा-बहुत फ़ैसिस्ट

तरीका योरप के बहुत-से देशों में फैल गया है और वहाँ डिक्टेटरशिप (किसी एक आदमी या वर्ग का सर्वेसर्वा हो जाना) आम बात हो गई है । सबसे बाद में फैंसिस्ट बननेवाला देश जर्मनी है, जहाँ १९१८ में घोषित कम-उम्र प्रजातंत्र का खात्मा कर दिया गया है और मजदूरों के आन्दोलन को नष्ट कर देने के लिए बिलकुल जंगली तरीकों का इस्तेमाल किया गया है ।

इस तरह योरप में फैंसिज्म और साम्यवाद का सामना है और इसके साथ ही पूंजीवादी ताकतें एक-दूसरे को घूरती हैं और एक-दूसरे से लड़ाई की तैयारी कर रही हैं । फिर पूंजीवाद ऐश्वर्य या बहुतायत और गरीबी का दृश्य साथ-साथ दिखाता है । एक तरफ़ खाना सड़ रहा है, यहाँतक कि फेंका और नष्ट किया जा रहा है, और दूसरी तरफ़ लोग भूखों मर रहे हैं ।

योरप में एक पुराना देश—स्पेन—पिछले कुछ वर्षों के अन्दर प्रजातन्त्र की शक्ल में बदल गया है और उसने अपने हैप्सबर्ग-बोर्बन खानदान के बादशाह को निकाल बाहर किया है । इस तरह इस वक़्त योरप और दुनिया में एक बादशाह कम होगया है ।

मैंने पिछले चौदह वर्षों की तीन प्रधान घटनाओं का वयान तुमसे किया है :— १. सोवियट यूनियन, २. अमेरिका का दुनिया पर आर्थिक नियंत्रण और उसकी वर्तमान विपत्ति, और ३. यूरोपियन उल्लङ्घन । इस जमाने की चौथी मुख्य घटना पूर्वी देशों की पूर्ण जागृति और अपनी आजादी हासिल करने की उनकी ज़बरदस्त कोशिश है । इस युग में दुनिया की राजनीति में पूर्व ने निश्चित रूप से प्रवेश किया है । इन पूर्वी राष्ट्रों या क़ौमों पर दो हिस्सों में गौर किया जा सकता है । एक हिस्से में वे देश हैं जो स्वतन्त्र समझे जाते हैं, और दूसरे में किसी साम्राज्यवादी शक्ति के मातहत औपनिवेशिक या दूसरी तरह के देश शामिल हैं । एशिया और उत्तरी अफ़्रीका के इन सब देशों में राष्ट्रीयता ने बड़ा जोर पकड़ा है और बड़ी ताक़तवर होगई है और आजादी के ख़यालात उग्र यानी ज़बरदस्त होगये हैं । इन सबमें ज़बरदस्त आन्दोलन हुए हैं और कई देशों में तो पश्चिमी साम्राज्यवाद के ख़िलाफ़ बग़ावतें भी हुई हैं । इन देशों में से बहुतों को सोवियट यूनियन से सीधी मदद मिली है और इससे भी ज्यादा महत्व की बात यह है कि उनको अपनी लड़ाई के बड़े ख़तरनाक मौक़ों पर सोवियट यूनियन से नैतिक समर्थन और सहायता मिली है ।

एक गिरे हुए और कमज़ोर राष्ट्र का बड़ा ही उल्लेखनीय पुनर्जन्म हुआ । यह राष्ट्र तुर्की था और इसका ज्यादातर श्रेय मुस्तफ़ा कमालपाशा को है । यह वह बहादुर नेता था जिसने उस वक़्त भी झुकने से इनकार किया, जब सब बातें उसके

खिलाफ़ थीं। उसने अपने देश की न सिर्फ़ आज़ादी हासिल की, बल्कि उसे पूरे तौर पर आधुनिक यानी नये ढंग का बना दिया—यहाँ तक कि कोई पहचान नहीं सकता कि यह वही पुराना तुर्की है। उसने सुलतानियत, खिलाफ़त, स्त्रियों के परदे और बहु-तेरे पुराने रिवाजों का ख़ात्मा कर दिया है। सोवियट का नैतिक और व्यावहारिक समर्थन यानी अमली ताईद उसके लिए बड़ी मददगार साबित हुई। ब्रिटिश प्रभाव से छुटकारा पाने की अपनी कोशिशों में फारस को भी सोवियट से मदद मिली। वहाँ भी रिज़ाख़ाँ नामक एक मज़बूत और ताक़तवर आदमी उठ खड़ा हुआ, और वही अब बादशाह है। इसी अवधि या ज़माने में अफ़ग़ानिस्तान भी पूर्ण स्वतन्त्रता या मुक़म्मल आज़ादी हासिल करने में कामयाब हुआ।

अरबस्तान को छोड़कर और सब अरब देश अब भी विदेशी हुकूमत के नीचे हैं। अरबों की एक कर दिये जाने की माँग अभी तक पूरी नहीं की गई है। अरबस्तान का ज्यादातर हिस्सा सुलतान इब्नसऊद के शासन-तले स्वतन्त्र होगया है। क़ाराज़ पर तो इराक़ भी स्वतन्त्र है, पर असल में वह ब्रिटेन के प्रभाव और नियंत्रण में है। फिलस्तीन और ट्रांसजोर्डन के छोटे राज्य ब्रिटिश शासनादेश में और सीरिया फ़्रांसीसी शासनादेश में है, यानी इन देशों में राष्ट्रसंघ के आदेश से ब्रिटेन और फ़्रांस का शासन है। सीरिया में फ़्रांसीसियों के खिलाफ़ एक ज़बरदस्त और बहादुराना बग़ावत हुई, और वह कुछ हद तक कामयाब भी हुई। मिस्र में भी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ़ बलवे हुए और लम्बे अर्से तक आज़ादी की लड़ाई चलती रही। यह लड़ाई आज भी चल रही है, गोकि मिस्र स्वतन्त्र कहलाता है और ब्रिटेन के हाथ की कठपुतली एक सुलतान वहाँ बादशाहत करता है। उत्तर-अफ़्रीका के सुदूर पश्चिम मोरक्को में भी अब्दुलकरीम के नेतृत्व में आज़ादी के लिए बड़ी बहादुराना लड़ाई हुई। उसने स्पेनवालों को निकाल बाहर करने में कामयाबी हासिल की, पर बाद में फ़्रांसीसियों की पूरी ताक़त ने उसे कुचल दिया।

एशिया और अफ़्रीका में होनेवाली आज़ादी की ये लड़ाइयाँ यह बताती हैं कि पूर्व के सुदूर देशों में कंसे एक ही वक़्त में नई भावना लोगों—स्त्री-पुरुषों—के मन पर असर डाल रही थी। इनके बीच दो देश ऊँचे खड़े हैं, क्योंकि उनका सारी दुनिया के लिए महत्त्व है। ये चीन और हिन्दुस्तान हैं। इन दोनों में से किसी एक में भी एकाएक कोई गहरा परिवर्तन होने से वह दुनिया की सारी बड़ी ताक़तों की प्रणाली पर असर डालता है; दुनिया की राजनीति में उसका ज़बरदस्त नतीजा हुए बिना नहीं रह सकता। इस तरह हम देख सकते हैं कि चीन और हिन्दुस्तान की आज़ादी की लड़ाई सिर्फ़ इन्हीं देशों के दाशिन्यों की राष्ट्रीय या घरू लड़ाई नहीं है। चीन की

सफलता का मतलब एक ताकतवर राष्ट्र का निकलकर मैदान में आना है, जो ताकतों के वर्तमान समतोल में बड़ा फ़र्क पैदा कर देगा और जिससे साम्राज्यवादी ताकतों के चीन के शोषण का अपनेआप खात्मा हो जायगा। इसी तरह हिन्दुस्तान की कामयाबी का मतलब एक ज़बरदस्त और महान् राष्ट्र का रंगमंच पर आना है और इससे तुरन्त ब्रिटिश साम्राज्य का खात्मा होजायगा।

पिछले दस वर्षों में चीन में बहुत-से उतार-चढ़ाव हुए हैं। काउ-मिन-तांग और चीनी साम्यवादियों में जो एका हुआ था वह टूट गया और तबसे चीन 'तूशन' और दूसरी तरह के लुटेरे सरदारों या सिपहसालारों का शिकार रहा है। विदेशी स्वार्थी और हितों ने बराबर उनकी मदद की है, क्योंकि वे चीन में गड़बड़ी क़ायम रखना चाहते हैं और इसीमें उनका फ़ायदा है। पिछले दो वर्षों से तो जापान ने सचमुच चीन पर चढ़ाई ही करदी और उसके कई सूबों पर क़ब्ज़ा कर लिया है। यह अनियमित लड़ाई अभीतक चल रही है। इस बीच चीन के भीतर के कई प्रदेश साम्यवादी होगये हैं और उनमें एक तरह की सोवियट सरकार क़ायम हो गई है।

हिन्दुस्तान में पिछले चौदह वर्ष घटनाओं से भरे रहे हैं। इस ज़माने में एक उग्र पर शान्तिपूर्ण राष्ट्रीयता उठी है। महायुद्ध के बाद जब बड़े-बड़े सुधारों की उम्मीदें लोगों के दिलों में उठ रही थीं, तब हमने पंजाब में फ़ौजी क़ानून (मार्शलला) और जलियाँवाला बाग़ का वह भयानक क्रतलेआम देखा। इसकी खीझ और तुर्की और खिलाफ़त के बारे में मुसलमानों के विरोध से बापू (गांधीजी) के नेतृत्व में १९२० से १९२२ तक का असहयोग-आन्दोलन पैदा हुआ। १९२० के बाद से बापू भारतीय राष्ट्रीयता के एकमात्र असन्दिग्ध नेता रहे हैं, इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। यह हिन्दुस्तान में गांधी-युग रहा है और उनके शान्तिपूर्ण विद्रोह के उपायों ने अपने नयेपन और सामर्थ्य (efficacy) से दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। बीच के विधायक कामों और तैयारी के कुछ वर्षों के बाद १९३० में फिर आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई, जब कांग्रेस ने साफ़-साफ़ पूर्ण स्वतंत्रता या मुकम्मल आज़ादी का ध्येय अपनाया। तबसे हम लोग, बीच की चन्दरोज़ा सुलह के अलावा, सत्याग्रह की लड़ाई, जेलों का भरना और बहुत-सी दूसरी चीज़ें, जिन्हें तुम जानती हो, देखते रहे हैं। इस बीच ब्रिटिश नीति यह रही है कि छोटे-छोटे सुधार देकर अगर मुमकिन हो तो कुछ लोगों को अपनी तरफ़ मिला लिया जाय और राष्ट्रीय आन्दोलन को कुचल दिया जाय। वह नीति अब भी चल रही है, लेकिन फिर भी हमारी लड़ाई असन्दिग्ध रूप से जारी है।

दो वर्ष पहले बरसा में भूखे किसानों की एक बड़ी बगावत हुई और बड़ी

बेहमी के साथ कुचल दी गई। जावा और डचइंडोनेज़ में भी बलवा हुआ। अखबारों से मालूम होता है कि स्याम में भी कुछ उथल-पुथल और तब्दीली हुई है और राजा के अधिकार सीमित कर दिये गये हैं। फ्रांसीसी इण्डोचीन में भी राष्ट्रीयता जग रही है।

इस तरह हम देखते हैं कि सारे पूर्व में राष्ट्रीयता अपनी अभिव्यक्ति के लिए लड़ रही है और कई देशों में इसके साथ साम्यवाद का भी कुछ रंग मिल गया है। इन दोनों यानी राष्ट्रीयता और साम्यवाद के बीच सिवा इसके कोई सामान्य या एकसाँ बात नहीं है कि दोनों साम्राज्यवाद से नफ़रत करते हैं। यूनियन के बाहर और भीतर के सब पूर्वी देशों के प्रति सोवियट रूस की बुद्धिमत्तापूर्ण और उदार नीति के कारण अ-साम्यवादी देशों में से भी कई उसके दोस्त बन गये हैं।

जैसा कि हम देख चुके हैं, आजादी और स्वतंत्रता की तरफ़ हिन्दुस्तान के बढ़ने का मतलब ही ब्रिटिश साम्राज्य का ख़त्म होजाना है। इसमें शक नहीं कि अगर हिन्दुस्तान की इस आजादी की लड़ाई को छोड़ दें तो भी निश्चितरूप से ब्रिटिश साम्राज्य नष्ट होता चला जा रहा है। 'एलिस इन वण्डरलैण्ड' नाम की किताब की चेगायर बिल्ली की तरह यह मिटता जा रहा है; पर मुस्कराहट बची हुई है और यह बहादुराना मुस्कराहट है। एक बड़े राष्ट्र को गिरते हुए देखना बड़ा दुःखायी या करुणापूर्ण होता है। अपने जमाने में इंग्लैण्ड महान् रहा है और उसकी पुरानी ताक़त के सब जरिये एक-एक करके उससे कटते जा रहे हैं। इस वक़्त वह अपनी जमा की हुई दौलत पर जी रहा है और यह दौलत इतनी काफ़ी है कि कुछ दिनों तक यह खेल चल सकता है। अंग्रेज़ों के सामने जो बहुतेरी दिक्कतें हैं उनका सामना करने की हिम्मत का उनमें अभाव नहीं है। साम्राज्यवादी इंग्लैण्ड ऊपर से अपनी वही पुरानी टीन-टाम बनाये रखने की ज़बरदस्त कोशिश कर रहा है—उस बूढ़ी औरत की तरह जो कभी खूबसूरत थी पर अब उसे जवानी को पार किये बहुत दिन हो चुके हैं फिर भी वह पेण्ट और पाउडर की मदद से अपनेको खूबसूरत और नौजवान दिखाने की कोशिश करती है। पर इस शाही औरत के पतन के पीछे मजदूरों और उनका साथ देनेवाले बहुतेरे विद्वानों का एक दूसरा इंग्लैण्ड भी है और भविष्य इन्हीं लोगों का है।

हाज़ के इन वर्षों की एक मुख्य विशेषता स्त्रियों का बहुतेरे क़ानूनी, सामाजिक और परम्परागत दण्डनों से, जिनमें कि वे जकड़ी हुई थीं, छुटकारा है। पश्चिम में महायुद्ध ने इस बात में बड़ी मदद की। पूर्व में भी तुर्की से हिन्दुस्तान और चीन तक स्त्रियाँ जाग उठी हैं और राष्ट्रीय और सामाजिक कामों में बहादुरी के साथ हिस्सा ले रही हैं।

ऐसा यह युग है जिसमें हम रह रहे हैं। हर रोज परिवर्तन, महत्वपूर्ण घटना, राष्ट्रों के झगड़े, पौण्ड और डालर के द्वंद्वयुद्ध, सोवियट पर पूंजीपतियों का क्रोध और सोवियट का उनसे बदला, बढ़ती हुई गरीबी और लाचारी और श्रेणी-संघर्ष यानी मालदारों और गरीब श्रमिकों की कशमकश की खबर आती ही रहती है; और इन सबके ऊपर युद्ध की लगातार बढ़ती हुई काली छाया है।

यह इतिहास का एक उथल-पुथल का जमाना है और ऐसे वक्त में जिन्दा होना और अपना हिस्सा अदा करना—फिर चाहे वह हिस्सा देहरादून-जेल का एकान्त ही क्यों न हो—बड़ी अच्छी और खुशकिस्मती की बात है।

: १५७ :

प्रजातंत्र के लिए आयर्लैंड की लड़ाई

२८ अप्रैल, १९३३

अब हम हाल के वर्षों की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ज़रा तफ़्सील के साथ गौर करेंगे। मैं आयर्लैंड से शुरू करता हूँ। विश्व-इतिहास और विश्व-शक्तियों की दृष्टि से योरोप के सबसे पश्चिम के इस छोटे-से देश का इस समय कोई ज्यादा महत्व नहीं है। पर यह बहादुर और दुर्दमनीय यानी किसी तरह न दबनेवाला देश है और ब्रिटिश साम्राज्य की सारी ताकत इसकी आत्मा को कुचलने या इसे झुकाकर मातहत की कबूल कराने में कामयाब नहीं हुई है। इस वक्त यह भी ब्रिटिश साम्राज्य के विनाश में मदद देनेवाली एक चीज़ है।

आयर्लैंड के बारे में जो पिछला खत मैंने तुम्हें लिखा था उसमें मैंने होमरूल-बिल का जिक्र किया था। यह बिल ब्रिटिश पार्लमेण्ट से ठीक महायुद्ध शुरू होने के पहले पास हुआ था। अल्सटर के प्रोटेस्टेण्ट नेताओं और इंग्लैंड के अनुदार दल ने इसका विरोध किया और इसके खिलाफ़ वाक़ायदा एक बग़ावत का संगठन किया गया। इसपर दक्षिणी आयर्लैंड के बाशिन्दों ने भी ज़रूरत आ पड़ने पर अल्सटर से लड़ने के लिए अपने 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक' दल बनाये। मालूम पड़ता था कि आयर्लैंड में गृह-युद्ध होने ही वाला है। इसी मौक़े पर महायुद्ध आगया और सबका ध्यान बेलजियम और उत्तर-फ़्रांस की युद्ध भूमि की तरफ़ खिंच गया। पार्लमेण्ट के आयरिश नेता युद्ध में अपनी तरफ से मदद देने को तैयार होगये, पर उनका देश इस तरफ से उदासीन था और उसे युद्ध में मदद देने की कोई उत्सुकता न थी। इस बीच अल्सटर के 'बाशियों' को ब्रिटिश सरकार में ऊँचे-ऊँचे ओहदे दिये गये और इससे आयर्लैंड वालों का असन्तोष और ज्यादा बढ़ गया।

आयरलैंड में असन्तोष बढ़ता गया और इसके साथ यह अनुभूति या एहसास भी पैदा हुआ कि इंग्लैंड की लड़ाई में आयरलैंड वालों की कुरबानी न की जाय। जब इंग्लैंड की तरह आयरलैंड में भी अनिवार्यरूप से फ़ौज में शामिल होने का क़ानून (Conscription) बनाने का प्रस्ताव सामने आया (जिसके अनुसार सब स्वस्थ नौजवानों को फ़ौज में शामिल होना पड़ता) तो सारा देश आग-बबूला हो गया और ज़बरदस्त विरोध किया गया। यहाँ-तक कि ज़रूरत पड़ने पर आयरलैंड ने ज़ोर-ज़बरदस्ती से भी उसे रोकने की तैयारी की।

१९१६ के ईस्टर-सप्ताह में डबलिन में एक बगावत होगई और आयरिश प्रजातंत्र का ऐलान कर दिया गया। चन्द दिनों की लड़ाई के बाद अंग्रेज़ों ने इसे कुचल दिया और इस चन्दरोज़ा बगावत में हिस्सा लेने के जुर्म में फ़ौजी क़ानून के मुताबिक़, बाद में, आयरलैंड के कुछ सबसे बहादुर और अच्छे नौजवानों को गोली मार दी गई। यह बगावत, जो 'ईस्टर-विद्रोह' के नाम से मशहूर है, अंग्रेज़ों को चुनौती देने का कोई गंभीर प्रयत्न कहीं कहा जा सकता। असल में यह दुनिया के सामने यह दिखा देने की एक बहादुराना कोशिश थी कि अब भी आयरलैंड प्रजातंत्र का सपना देखता है और अपनी इच्छा से ब्रिटेन की मातहतता क़बूल करने से इन्कार करता है। इस बगावत के पीछे जो बहादुर नौजवान थे उन्होंने दुनिया के सामने यह बात जाहिर करने के लिए जान-बूझकर अपनेको कुरवान कर दिया। वे अच्छी तरह जानते थे कि इस बार की कोशिश में कामयाबी न होगी, पर उम्मीद करते थे कि उनकी कुरबानी बाद में रंग लायगी और आज़ादी को नज़दीक लायगी।

इस बगावत के समय एक आयरिश जर्मनी से आयरलैंड में अस्त्रशस्त्र लाने की कोशिश करता हुआ पकड़ा गया। यह आदमी सर रोजर केसमेण्ट था, जो बहुत दिनों से ब्रिटेन के राजदूत-विभाग में था। लन्दन में केसमेण्ट पर मुक़दमा चला और उसे फाँसी की सज़ा दी गई। अदालत में मुजरिम के कठघरे में खड़े हुए उसने अपना जो बयान पढ़ा, वह बड़ा ही जोशीला और हृदय-स्पर्शी था और उसमें आयरिश आत्मा की उग्र देशभक्ति तड़प रही थी।

बगावत तो असफल हुई, पर उसकी नाकामयाबी में ही उसकी विजय थी। इसके बाद ब्रिटिश सरकार की तरफ़ से जो दमन शुरू हुआ उसने और ख़ासकर नौजवान नेताओं के गिराए जाने की गोली मार दिये जाने के काम ने आयरिश लोगों पर बड़ा गहरा असर डाला। ऊपर से आयरलैंड शान्त दीखता था; पर अन्दर-ही-अन्दर क्रोध की आग भड़क रही थी और बहुत जल्द वह 'सिनफीन' की शैल में सानने आई। सिनफीन-भाषना बड़ी तेज़ी से फैली। शुरू में इसे बहुत कम कामयाबी हुई थी, पर अब यह जंगल की आग की तरह फैल गई।

महायुद्ध खत्म होने के बाद सारे ब्रिटिश टापू में लंदन की पार्लमेण्ट के लिए चुनाव हुए। आयर्लैंड में सिनफीन-दलवालों ने ज्यादातर स्थानों (सीटों) पर कब्जा कर लिया और पुराने नेशनलिस्टों को, जो अंग्रेजों से कुछ सहयोग के तरफदार थे, निकाल बाहर किया। पर सिनफीनों ने ब्रिटिश पार्लमेण्ट की बैठकों में शामिल होने के लिए अपनेको नहीं चुनवाया था। उनकी नीति बिल्कुल जुदा थी; वे असहयोग और बायकाट यानी बहिष्कार में विश्वास रखते थे। इसलिए ये चुने हुए सिनफीनर लंदन की पार्लमेण्ट से दूर ही रहे और उसकी जगह १९१९ में डबलिन में उन्होंने अपनी प्रजातंत्र की असेम्बली बनाली। उन्होंने आयरिश प्रजातंत्र का ऐलान कर दिया और अपनी असेम्बली या धारा-सभा का नाम 'डेल आयरीन' रक्खा। समझा जाता था कि यह सारे आयर्लैंड के लिए है, जिसमें अल्सटर भी शामिल था, पर स्वभावतः अल्सटरवाले इससे अलग रहे। उनका कैथलिक आयर्लैंड से कोई प्रेम न था। 'डेल आयरीन' ने डि वेलरा को अध्यक्ष या राष्ट्रपति और ग्रिफिथ्स को उपाध्यक्ष चुना। उस वक्त नये प्रजातंत्र के ये दोनों अध्यक्ष ब्रिटिश जेलों में थे।

इसके बाद एक असाधारण लड़ाई शुरू हुई। यह लड़ाई आयर्लैंड और इंग्लैंड के बीच होनेवाली पिछली सब लड़ाइयों से बिल्कुल नये और जुदा तरीके की थी। थोड़े-से स्त्री-पुरुषों ने, जिनके साथ उनके देशवालों की हमदर्दी थी, जबरदस्त दिक्कतों के बीच यह लड़ाई लड़ी। एक बहुत बड़ा और संगठित साम्राज्य उनके खिलाफ था। सिनफीन आन्दोलन ऐसा असहयोग था जिसमें हिंसा की पुट थी। इन लोगों ने अंग्रेजी संस्थाओं के बायकाट का प्रचार किया और जहाँ मुमकिन था अपनी संस्थायें खोलीं। मामूली कानूनी अदालतों की जगह इन्होंने पंचायती अदालतें (Arbitration Courts) कायम कीं। गांवों में पुलिस चौकियों के खिलाफ छापा मारने की लड़ाई (Guerilla Warfare) होती रही। सिनफीन क्रांतियों ने जेलों में भूख-हड़ताल करके ब्रिटिश सरकार को बहुत तंग किया। सबसे मशहूर भूख-हड़ताल, जिसने आयर्लैंड को हिला दिया, कार्क के लार्डमेयर टेरेन्स मैक्स्विनी की थी। जब वह जेल में रक्खा गया तो उसने ऐलान किया कि वह जिन्दा या मुरदा होकर जेल से बाहर निकलेगा और खाना छोड़ दिया। ७५ दिनों के अनशन के बाद उसकी मृत्यु हुई और उसका मुरदा शरीर जेल से बाहर लाया गया।

माइकेल कालिन्स सिनफीन बग़ावत का संगठन करनेवालों में एक मशहूर नेता था। सिनफीन चालों से आयर्लैंड में ब्रिटिश सरकार काफ़ी हद तक अव्यवस्थित और लंगडी होगई और गांववाले जिलों में तो उसकी हस्ती भी नाम की ही थी। धीरे-धीरे दोनों तरफ से हिंसा का सहारा लिया जाने लगा और कई बार बदला

लिया गया। आयरलैंड में भेजने के लिए एक खास ब्रिटिश फ़ौजी दल भरती किया गया। इन लोगों को ऊँची तनखाह दी जाती थी और इनमें महायुद्ध की फ़ौजों से बर्खास्त किये हुए खूँवार लोग ही ज्यादा थे। यह फ़ौज अपनी बर्दों के रंग के कारण 'ब्लैक एण्ड टैन' (काली और पीली-भूरी) के नाम से मशहूर हुई। इस फ़ौज ने लोगों को बुरी तरह क़त्ल करना शुरू किया। ये सिपाही अकसर लोगों को सोते हुए ही गोली से मार देते थे। इस तरह का दमन इसलिए किया जाता था कि सिन-फ़्रीन झुककर मातहतता क़बूल कर लेंगे। पर उन्होंने मातहतता क़बूल करने से इन्कार किया और छापे की लड़ाई जारी रखी। इसपर 'ब्लैक और टैन' फ़ौज ने भयंकर बदला लेना शुरू किया। उसके सैनिक गाँव-के-गाँव और शहरों के बड़े-बड़े हिस्से जलाकर खाक कर देते। आयरलैंड एक ऐसा मैदान बन गया जिसमें दोनों दल हिंसा और बरबादी में एक-दूसरे को मात देने की कोशिश करने लगे। एक दल के पीछे एक साम्राज्य की संगठित शक्ति थी और दूसरे के पीछे मुट्ठीभर आदिमियों का फ़ौलादी निश्चय था। १९१९ से अक्टूबर १९२१ तक, दो वर्षों तक, इंग्लैंड-आयरलैंड के बीच यह लड़ाई चलती रही।

इस बीच, १९२० ई० में, ब्रिटिश पार्लमेण्ट ने जल्दी-जल्दी एक नया होमरूल-बिल पास किया। पुराना विधान, जो महायुद्ध शुरू होने के कुछ ही दिन पहले पास हुआ था और जिसने अल्सटर में क़रीब-क़रीब बगावत खड़ी कर दी थी, छोड़ दिया गया। नये बिल ने आयरलैंड को दो हिस्सों में बाँट दिया : अल्सटर या उत्तरी आयरलैंड और बाक़ी देश। इनके लिए अलग-अलग पार्लमेण्टों की व्यवस्था हुई। आयरलैंड एक छोटा देश है और उसे दो हिस्सों में बाँट देने से वे हिस्से बहुत छोटे होगये। उत्तर में अल्सटर में नई पार्लमेण्ट बन गई, पर दक्षिण या बाक़ी आयरलैंड में किसीने होमरूल-बिलानून की तरफ़ ध्यान न दिया। वहाँके लोग तो सिनफ़्रीन बगावत में ही फँसे हुए थे।

अक्टूबर १९२१ ई० में ब्रिटिश मिनिस्टर लायड जार्ज ने सिनफ़्रीन नेताओं से थोड़े दिनों के लिए लड़ाई बन्द करने की अपील की, ताकि समझौते की संभावना के बारे में बातचीत की जा सके। यह बात मान ली गई। इसमें कोई शक़ नहीं कि अगर ब्रिटेन चाहता तो अपने महान् साधनों से सारे देश को दीरान कर देता और अन्त में सिनफ़्रीन-आन्दोलन को कुचल देता; पर अपनी इस दमन-नीति के कारण यह अमेरिका और दूसरे मुल्कों में बहुत बदनाम होता जा रहा था। अमेरिका में रहने-वाले आयरिश लोगों और ब्रिटिश उपनिवेशों से आयरलैंड में आन्दोलन और लड़ाई जारी रखने के लिए खूब धन आ रहा था। पर इसके साथ ही सिनफ़्रीनर भी धक गये थे; उनपर दबा ज़बरदस्त दस्त पड़ रहा था।

इंग्लैण्ड और आयर्लैण्ड के प्रतिनिधि लन्दन में मिले और दो महीनों के बहस-मुवाहसे के बाद दिसम्बर १९२१ ई० में एक अस्थायी या काम-चलाऊ समझौते पर दस्तखत हुए। इसने आयरिश प्रजातन्त्र को तो मंजूर नहीं किया, पर आयर्लैण्ड को एक-दो बातों के अलावा इतनी आजादी दी जितनी उस समय तक किसी भी उपनिवेश को हासिल नहीं थी। इतने पर भी आयरिश प्रतिनिधि इसे मंजूर करने को तैयार न थे और उन्होंने इसे तब मंजूर किया जब इंग्लैण्ड ने साफ़-साफ़ धमकी दी कि यदि इसे मंजूर न किया जायगा तो खौफ़नाक लड़ाई छिड़ जायगी।

आयर्लैण्ड में इस सुलह को लेकर बड़ी चख-चख मची। कुछ इसके पक्ष में थे, दूसरे इसके सख्त खिलाफ थे। इस सवाल पर सिनफीन दल के दो टुकड़े होगये। आखिरकार डेल आयरीन (आयर्लैण्ड की पार्लमेण्ट) ने इस सन्धि को मंजूर किया और आयरिश फ्री स्टेट का, जिसे आयर्लैण्ड में सरकारी तौर पर सावर स्टेट आयरीन (Saorstát Éireann) कहा जाता था, आविर्भाव हुआ। पर इससे सिनफीन-दल के पुराने कार्यकर्ताओं में गृह-युद्ध छिड़ गया। 'डेल आयरीन' के प्रेसीडेंट डि वेलरा इंग्लैण्ड के साथ संधि करने के खिलाफ थे। और भी बहुत-से लोग उनके साथ थे। त्रिफिथ्स, माइकेल कालिन्स और दूसरे लोग उनके पक्ष में थे। कितने ही दिनों तक देश में गृह-युद्ध मचा रहा। जो लोग सन्धि और फ्रीस्टेट के पक्ष में थे उनको विरोधियों को दवाने में ब्रिटिश सरकार ने भी मदद दी। प्रजातन्त्रवादियों ने माइकेल कालिन्स को गोली मार दी, इसी तरह बहुतेरे प्रजातन्त्रवादी नेताओं को फ्रीस्टेटवालों ने भी गोली से मार दिया। जेल प्रजातन्त्रवादियों से भरे हुए थे। यह सब गृह-युद्ध और आपसी नफरत आयर्लैण्ड की आजादी की बहादुराना लड़ाई में एक दुःखपूर्ण वृद्धि थी। अंग्रेजी नीति की विजय हुई। जहाँ उसकी फौजी ताकत बेकाम साबित हुई थी वहाँ अब एक आयरिश अपने ही भाई दूसरे आयरिश से लड़ रहा था और कुछ हद तक इंग्लैंड चुपचाप एक दल की मदद कर रहा था और इस नये झगड़े की तरफ सन्तोष के साथ देख रहा था।

धीरे-धीरे गृह-युद्ध खत्म होगया, पर प्रजातन्त्रवादी फ्रीस्टेट को मंजूर करने को तैयार न हुए। वे प्रजातन्त्रवादी भी जो डेल यानी फ्रीस्टेट की पार्लमेण्ट में चुन लिये गये थे वहाँ जाने को तैयार न थे, क्योंकि वे वफादारी की शपथ, जिसमें बाद-शाह का जिक्र आता था, लेने से इन्कार करते थे। इसलिए डि वेलरा और उनका दल 'डेल' से अलग रहा और फ्रीस्टेट दल ने फ्रीस्टेट के प्रेसीडेंट कासग्रेव के नेतृत्व में प्रजातन्त्रवादियों को कई तरफ से कुचलने की कोशिश की।

आयरिश फ्रीस्टेट के निर्माण से ब्रिटेन की साम्राज्य-राजनीति (Imperial

politics) में बहुत बड़े-बड़े परिणाम निकले। आयरिश सन्धि ने आयरलैंड को कानूनन उससे कहीं ज्यादा स्वतंत्रता दे दी थी जितनी कि उस वक्त और ब्रिटिश उपनिवेशों को हासिल थी। ज्योंही आयरलैंड को यह स्वतंत्रता मिली, दूसरे उपनिवेशों को भी अपनेआप वह स्वतंत्रता मिल गई और औपनिवेशिक मर्यादा के खयाल में तब्दीली हुई। इंग्लैंड और उपनिवेशों के बीच कई इम्पीरियल कांग्रेसें या साम्राज्य-परिषदें हुई और उपनिवेशों में ज्यादा स्वतंत्रता की दिशा में बढ़ने की कितनी ही तब्दीलियाँ हुई। आयरलैंड अपने दृढ़ प्रजातंत्रवादी आन्दोलन के साथ पूर्ण स्वतंत्रता की दिशा में जा रहा था। यही हालत दक्षिण अफ्रीका की थी जहाँ कि बोअर लोगों का बहुमत था। इस तरह उपनिवेशों की स्थिति बदलती और सुधरती जा रही थी—यहाँतक कि उनको ब्रिटिश कामनवेल्थ ऑफ नेशन्स (ब्रिटिश राष्ट्रसंघ) में इंग्लैंड के साथ भाईचारे या एक तरह की बराबरी का दर्जा मिल गया। मुनने में यह अच्छा लगता है और इसमें शुबहा नहीं कि इंग्लैंड की बराबरी के राजनैतिक दर्जे की तरफ यह प्रगति है, पर यह बराबरी व्यावहारिक या अमली की बनिस्बत सैद्धान्तिक ही ज्यादा है। आर्थिक दृष्टि से उपनिवेश ब्रिटेन और ब्रिटिश पूंजी के साथ बँधे हुए हैं और उनपर आर्थिक दबाव डालने के कई तरीके हैं। इसके साथ ज्यों-ज्यों उपनिवेशों का विकास होता जाता है त्यों-त्यों उनके आर्थिक हित इंग्लैंड के आर्थिक हितों से टकराते जाते हैं। इस तरह साम्राज्य धीरे-धीरे कमजोर होता जाता है। साम्राज्य के फट और टूट जाने के खौफ से ही इंग्लैंड ने बन्धनों को ढीला करना और उपनिवेशों की राजनैतिक बराबरी का उसूल संजूर किया। मौके पर इतना आगे बढ़ जाने से उसने बहुत कुछ बचा लिया। पर यह ज्यादा दिन तक काम नहीं दे सकता। उपनिवेशों को इंग्लैंड से अलग रखनेवाली शक्तियाँ अपना काम कर रही हैं; मुख्यतः ये आर्थिक शक्तियाँ हैं और ये शक्तियाँ बराबर साम्राज्य को कमजोर कर रही हैं। इसी कारण और इंग्लैंड के निश्चित पतन के कारण ही मैंने तुमको ब्रिटिश साम्राज्य के नष्ट हो जाने की बात लिखी थी। मगर उपनिवेशों के लिए इंग्लैंड के साथ ज्यादा दिन तक बँधे रहना मुश्किल है—हालांकि उनकी परम्परायें और संस्कृति एक हैं और जाति (Race) भी एक है; तब फिर हिन्दुस्तान के लिए उसके साथ बँधे रहना कितना मुश्किल होगा? क्योंकि हिन्दुस्तान के आर्थिक हितों का तो इंग्लैंड के आर्थिक हितों से सीधा संघर्ष है और इनमें से एक को दूसरे के सामने झुकना ही पड़ेगा। इस तरह स्वतंत्र हिन्दुस्तान के लिए इस बात की संभावना नहीं की जा सकती कि वह इस सम्बन्ध को संजूर करेगा; क्योंकि इसका लाजिमी नतीजा अपनी आर्थिक नीति को ब्रिटेन के हाज़रे में धर देना होगा।

इस तरह ब्रिटिश कामनवेल्थ या आजाद उपनिवेशों का, गरीब और गुलाम हिन्दुस्तान का नहीं, मतलब राजनैतिक दृष्टि से स्वतंत्र इकाइयाँ हैं। पर ये इकाइयाँ भी अभी तक ब्रिटेन के आर्थिक साम्राज्य के मातहत हैं। आयरिश संधि का मतलब ब्रिटिश पूँजी द्वारा, कुछ हद तक, आयरलैंड के शोषण का जारी रहना था और यही असल में प्रजातंत्र के लिए आन्दोलन करने की वजह थी। डि वेलरा और प्रजातंत्रवादी गरीब किसानों, नीचे के मध्यमवर्ग और गरीब बुद्धिशालियों के प्रतिनिधि थे; कासप्रेव और फ्रीस्टेट दलवाले मालदार मध्यमवर्ग और मालदार किसानों के प्रतिनिधि थे और इन दोनों पिछले वर्गों की ब्रिटिश व्यापार में दिलचस्पी थी और ब्रिटिश पूँजी की उनमें दिलचस्पी थी।

कुछ वक्त के बाद डि वेलरा ने अपनी लड़ाई का पेंतरा बदल दिया। वह और उनका दल 'डेल आयरिन' में चुनकर गये और वफ़ादारी की शपथ भी ली। शपथ लेने के साथ उन्होंने इसका भी ऐलान कर दिया कि ऐसा हम महज जावते की खातिर कर रहे हैं और ज्योंही हमारा बहुमत होजायगा, हम इस शपथ को निकाल बाहर करेंगे। दूसरे चुनाव में, १९३२ के शुरू में, डि वेलरा का फ्रीस्टेट पार्लमेण्ट में बहुमत होगया और तुरन्त उसने अपने कार्यक्रम के मुताबिक काम शुरू कर दिया। प्रजातंत्र कायम करने के लिए लड़ाई तो जारी रहनी ही थी, पर अब लड़ाई का तरीका बदल गया था। डि वेलरा ने वफ़ादारी की शपथ को तोड़ देने का प्रस्ताव किया और ब्रिटिश सरकार को यह भी सूचित कर दिया कि अब हम ज़मीन का कोई सालाना भत्ता (Land annuity) नहीं देंगे। मैं समझता हूँ कि मैं तुमको इस भत्ते के बारे में बता चुका हूँ। जब आयरलैंड में बड़े-बड़े ज़मींदारों से ज़मीन ली गई तो उनको अच्छा-खासा मुआवज़ा दिया गया और बाद में थोड़ा-थोड़ा करके यह रक़म उन किसानों से ली जाती थी जिन्होंने कि ज़मीन ली थी। एक पीढ़ी से यह सिलसिला चल रहा था और फिर भी जारी था। डि वेलरा ने कहा कि अब हम कोई रक़म न देंगे।

तुरन्त इसपर इंग्लैंड में एक वावेल मच गया और ब्रिटिश सरकार से संघर्ष हुआ। पहले उसने यह कहकर विरोध किया कि डि वेलरा का वफ़ादारी की शपथ को ख़त्म कर देना १९२१ की आयरिश सन्धि के खिलाफ़ है। डि वेलरा ने कहा कि अगर आयरलैंड और इंग्लैंड बराबर के देश (Sister Nations) हैं, जैसा कि उपनिवेशों के बारे में कहा जाता है, और अगर हरेक को अपना विधान बदलने की आज़ादी है, तब जाहिर है कि आयरलैंड अपने विधान में वफ़ादारी की शपथ रख सकता या उसे निकाल दे सकता है और इस तरह इसमें १९२१ की सन्धि का अब कोई सवाल नहीं उठता। अगर आयरलैंड को यह अधिकार नहीं है तो वह उस हद तक इंग्लैंड के अधीन है।

दूसरी बात यह हुई कि ब्रिटिश सरकार ने सालाना भत्ता बन्द कर देने पर और भी जोरदार विरोध किया और कहा कि यह समझौते और ज़िम्मेदारी को तोड़ना और ज़बरदस्त वादाखिलाफ़ी है। डि वेलरा ने इससे इन्कार कर दिया और इसपर कानूनी बहस-मुबाहसा हुआ, जिससे हमें कोई सरोकार नहीं है। जब इस तरह का कानूनी झगड़ा खड़ा हो तो साफ़ तरीका यह है कि निष्पक्ष पंचायत से मामला तय कर लिया जाय। दोनों दलों ने पंचायती फैसले के लिए रज़ामन्दी जाहिर की; पर एक अजीब दिक्कत पैदा हुई। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि पंचायती बोर्ड (Arbitration Tribunal) में साम्राज्य के अन्दर के ही आदमी होने चाहिए। डि वेलरा ने ऐसे किसी बन्धन को मानने से इन्कार कर दिया; उसने हेग की अन्तर्राष्ट्रीय अदालत (Permanent Court of Justice) या किसी दूसरी पंचायत का, जिसमें विदेशी रखे जा सकें, प्रस्ताव किया। उसने साफ़ कह दिया कि साम्राज्य वालों पर हमारा विश्वास नहीं है। इस प्रस्ताव को ब्रिटिश सरकार ने नामंजूर कर दिया। यह एक बाहियात-सी बात मालूम होती है कि दो सरकारें पंचायत के आदमियों के चुनाव के छोटे-से मसले पर झगड़ बैठें। पर इसके पीछे और भी बहुत-कुछ था जो आँखों से नहीं दिखाई देता। एक तरफ़ प्रजातंत्र की मंजिल तक पहुँचने का आयरिश लोगों का दृढ़ निश्चय था और दूसरी तरफ़ उसे रोकने का ब्रिटेन का पक्का इरादा था।

जब सालाना क्रिस्त देने का वक्त आया और वह नहीं दी गई तो इंग्लैंड ने आयरलैंड के खिलाफ़ एक नई लड़ाई छेड़ दी। यह आर्थिक युद्ध था। इंग्लैंड में आनेवाले आयरिश माल पर इस ख़याल से गहरी चुंगी लगा दी गई कि वह आयरिश किसान, जिसका माल इंग्लैंड आता है, बरबाद होजाय और आयरिश सरकार को समझौता करने के लिए मजबूर करे। जैसी कि इंग्लैंड की आदत है, उसने दूसरे पक्ष को मजबूर करने के लिए अपना सौटा चलाया, पर ऐसे तरीके अब उतने फायदेमन्द नहीं रहे जितने कि पहले थे। आयरिश सरकार ने ब्रिटेन से आयरलैंड में आनेवाले माल पर भारी चुंगी लगाकर इसका बदला लिया। पिछले साल से यह आर्थिक युद्ध जारी है और किसानों और दोनों तरफ़ के उद्योग-धन्धों को इससे बड़ा नुक़सान पहुँचा है। लेकिन अपमानित राष्ट्रीयता और शान दोनों पार्टियों में से किसीके भी झुकने में बाधक है।

कुछ महीने हुए, १९३३ के शुरू में, आयरलैंड में नये चुनाव हुए थे जिससे ब्रिटिश सरकार को और सेंपना पड़ा। डि वेलरा इस बार पहले से भी ज्यादा कामयाब हुआ और उसके पक्ष में पहले से कहीं ज्यादा दह्मन्त था। इससे यह जाहिर होगया कि दबाव डालने की ब्रिटिश नीति कामयाब नहीं हुई। नज़ेदार बात तो यह है कि एक तरफ़ तो ब्रिटिश सरकार झुँड न चुकाने की दजह से आयरिश लोगों को दुरा-

भला कहती थी; पर दूसरी तरफ़ खुद अमेरिका को कर्ज चुकाना नहीं चाहती थी।

इस वक़्त डि वेलरा आयरिश सरकार का प्रधान है और वह अपने देश को क्रम-क्रम प्रजातंत्र की तरफ़ लेजा रहा है। वफ़ादारी की शपथ ख़तम हो चुकी है; सालाना क्रिस्तें बिल्कुल बन्द करदी गई हैं; पुराना गवर्नर-जनरल भी चला गया और डि वेलरा ने अपने दल के एक सदस्य को इस ओहदे पर, जिसका अब कोई महत्व नहीं है, नियुक्त किया है। प्रजातंत्र कायम करने की लड़ाई चल ही रही है, पर अब तरीक़े बदल गये हैं और सदियों पुराना इंग्लैण्ड-आयरलैण्ड का झगड़ा जारी है और आज यह एक आर्थिक युद्ध की शकल में बदल गया है।

आयरलैण्ड जल्द ही प्रजातंत्र हो सकता है। पर रास्ते में एक बड़ी दिक्कत है। डि वेलरा और उसका दल चाहता है कि सारा आयरलैण्ड एक संयुक्त आयरलैण्ड हो और सारे देश का एक प्रजातंत्र, एक केन्द्रीय सरकार हो। इसमें वह अल्सटर को भी शामिल करना चाहता है। आयरलैण्ड इतना छोटा है कि उसका दो हिस्सों में बँट जाना अच्छा नहीं। डि वेलरा के सामने यह बड़ा ज़बरदस्त सवाल है कि अल्सटर को बाक़ी आयरलैण्ड में मिलजाने को कैसे राज़ी किया जाय। ज़ोर-ज़बरदस्ती से यह हो नहीं सकता। १९१४ ई० में जब ब्रिटिश सरकार ने ज़बरदस्ती दोनों को मिलाना चाहा था तो वह कोशिश बगावत में जाकर ख़त्म हुई और फ़्रीस्टेट अल्सटर पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, न ऐसा करने का उसका ख़याल ही है। डि वेलरा की उम्मीद है कि वह अल्सटर की सदिच्छायें यानी दोस्ती हासिल कर सकेगा और यों दोनों में एका हो जायगा। इसमें आशावाद ही ज्यादा है और असलियत कम है, क्योंकि प्रोटेस्टेण्ट अल्सटर का अब भी कैथलिक आयरलैण्ड के प्रति ज़बरदस्त अविश्वास है। हाँ, दोनों का एका तब हो सकता है जब देश के दोनों हिस्सों की सरकारों में मजदूर वर्ग की प्रधानता होजाय, क्योंकि उनमें कोई धार्मिक झगड़ा नहीं होगा।

: १५८ :

नवीन तुर्की का उत्थान

७ मई, १९३३

मैंने कई दिनों से तुम्हें कोई ख़त नहीं लिखा है। और बातों ने मेरा ध्यान खींच लिया था और मेरी ज़िन्दगी के सीधे सिलसिले में ख़लल पड़ गया था। बापू फिर अनशन करने जा रहे हैं—एक लम्बा और भयंकर अनशन, और मेरा मन उड़-उड़कर यरवडा-जेल को जाता है और मैं भविष्य के अन्धकार को भेदकर देखने की कोशिश करता हूँ। पर उससे मुझे यहाँ देहरादून-जेल में कोई मदद नहीं मिलती, इसलिए मुझे

अपने काम पर वापस आ जाना चाहिए और बीती घटनाओं के दीख पड़नेवाले खाँके को तुम्हारे सामने पढ़ने के लिए रखना चाहिए ।

पिछले खत में मैंने प्रजातंत्र के लिए आयरलैंड की बहादुराना लड़ाई की चर्चा की थी । आयरलैंड और तुर्की में कोई खास ताल्लूक तो नहीं है, पर आज मेरे दिमाग में नये तुर्की का खयाल आ गया है, इसलिए मैं उसी के बारे में तुम्हें लिखने जा रहा हूँ । आयरलैंड की तरह इसने भी जबरदस्त दिक्कतों के बीच अपनी आजादी की लड़ाई लड़ी है । हम देख ही चुके हैं कि महायुद्ध के फल-स्वरूप तीन साम्राज्य—रूस, आस्ट्रिया और जर्मनी—खत्म हो गये । तुर्की में हम चौथे बड़े साम्राज्य—उस्मानी साम्राज्य का बिनाश देखते हैं । उस्मान और उसके वारिसों ने ६०० वर्ष पहले इस साम्राज्य की नींव डाली और इसे बनाया था । इस तरह उसका खानदान रूस के रोमनोफों या प्रशा और जर्मनी के हायनज़ालनों से कहीं पुराना था । वह तेरहवीं सदी के शुरू-शुरू के हैप्सबर्गों का समकालिक था और ये दोनों प्राचीन राजवंश एक साथ मिट गये ।

महायुद्ध में जर्मनी के घुटना टेकने के कुछ दिनों पहले ही तुर्की पस्त होगया था और उसने मित्र-राष्ट्रों के साथ एक अलग आर्मिस्टीज (युद्ध बन्द करने की सुलह) की थी । देश क़रीब-क़रीब तहस-नहस हो चुका था, साम्राज्य खत्म होगया था और सरकार की मशीनरी या व्यवस्था टूट चुकी थी । इराक़ और अरब देश अलग हो चुके थे और ज्यादातर मित्र-राष्ट्रों के मातहत थे । खुद कुस्तुनतुनिया पर मित्र-राष्ट्रों का नियंत्रण था और इस बड़े शहर के सामने ही वास्कोरस में, विजयी शक्ति के अभिमान से भरे हुए निशान की तरह ब्रिटिश लड़ाकू जहाज़ लंगर डाले हुए खड़े थे । हर जगह अंग्रेज़ी, फ़्रांसीसी और इटालियन फ़ौजें भरी थीं और चारों तरफ़ ब्रिटिश खुफिया विभाग का जाल बिछा हुआ था । तुर्की क़िले तोड़कर ज़मीन पर गिराये जा रहे थे और जो तुर्की फ़ौज बची थी उससे हथियार रखवा लिये जा रहे थे । अनवरपाशा, तलाअतबेग और दूसरे नौजवान तुर्की नेता दूसरे मुल्कों को भाग गये थे । सुल्तान की गद्दी पर कठपुतली-सा ख़लीफ़ा वहीदउद्दीन बैठा हुआ था, जो इस बीरानी में अपनेको दबाना चाहता था, फिर चाहे उसके देश का कुछ भी हो । कठपुतली-सा दूसरा आदमी, जिसे ब्रिटिश सरकार चाहती थी, वज़ीरआज़न या प्रधान मंत्री बनाया गया और तुर्की पार्लमेण्ट तोड़ दी गई ।

१९१८ के अखीर और १९१९ के शुरू में तुर्की की यह हालत थी । तुर्क धक्-धक् पिलकुल बेदम हो रहे थे और उनकी 'स्प्रिट' कुचल दी गई थी । याद रखो कि उनको फंती भयंकर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था । महायुद्ध के इन चार

वर्षों के पहले वालकन युद्ध हो चुका था और उसके भी पहले इटली से लड़ाई हो चुकी थी; और यह सब उस नौजवान तुर्क आन्दोलन के बाद ही हुआ, जिसने सुलतान अब्दुलमजीद को निकाल दिया था और एक पार्लमेण्ट कायम कर दी थी। तुर्कों ने सदा राजत्व की सहन-शक्ति का परिचय दिया है, पर यह लगातार आठ वर्षों की लड़ाई उनके लिए भी बहुत ज्यादा थी—किसी भी क्रौम के लिए ज्यादा होती। इसलिए उन्होंने सारी उम्मीदें छोड़ दीं और अपनेको क्रिस्मत के भरोसे छोड़कर मित्र-राष्ट्रों के फँसले का इन्तज़ार करने लगे।

इससे दो साल पहले, युद्ध के दरमियान, मित्र-राष्ट्रों ने इटली से एक गुप्त समझौता कर लिया था, जिसमें एशियामाइनर का पश्चिमी हिस्सा और स्मर्ना इटली को देने का वादा किया गया था। इसके पहले, कागज़ पर, कुस्तुनतुनिया रूस की नज़र किया जा चुका था और अरब देशों को आपस में बाँट लेने की बात तय हो चुकी थी। एशियामाइनर इटली को देने के आखिरी गुप्त समझौते पर रूस की रजामन्दी भी ज़रूरी थी, पर इटली की बदक्रिस्मती से ऐसा होने के पहले ही रूस में बोलशेविकों ने अपनी ताकत जमा ली और इसका नतीजा यह हुआ कि वह समझौता मंजूर न हो सका और इटली मित्र-राष्ट्रों पर कुढ़कर रह गया।

ऐसी हालत थी। सुलतान से लेकर नीचे तक सब तुर्क पस्तहिम्मत दिखाई देते थे। आखिरकार 'योरप का रोगी' मर चुका था—कम-से-कम ऐसा मालूम पड़ता था। पर मुट्ठीभर तुर्क ऐसे थे जिन्होंने क्रिस्मत या परिस्थितियों के आगे झुकने से इन्कार किया, फिर चाहे उनका विरोध कितना ही मामूली मालूम हो। कुछ दिनों तक वे चुपचाप काम करते रहे; मित्र-राष्ट्रों के नियंत्रण में जो शस्त्रागार थे उन्हींसे वे अस्त्र-शस्त्र और युद्ध-सामग्री लेते और कालासागर के रास्ते जहाज़ों से उसे अनातोलिया (एशियामाइनर) के अन्दरूनी हिस्से में भेजते रहे। इन गुप्त कार्यकर्ताओं में प्रधान मुस्तफ़ा कमालपाशा था, जिसका नाम मेरे कई खतों में पहले ही आ चुका है।

अंग्रेज़ मुस्तफ़ा कमाल को ज़रा भी नहीं चाहते थे। उनका उसपर सन्देह था और वे उसे गिरफ़्तार करना चाहते थे। सुलतान भी, जो असल में अंग्रेज़ों के हाथ की कठपुतली था, उसे नहीं चाहता था। पर उसने (सुलतान ने) यह ज्यादा अच्छी बात समझी कि उसे (मुस्तफ़ा कमाल को) देश के अन्दर कहीं दूर भेज दिया जाय। इसलिए कमालपाशा पूर्वी अनातोलिया में फ़ौजों का इन्स्पेक्टर जनरल बना दिया गया। सच पूछो तो वहाँ कोई खास फ़ौज निरीक्षण या देखभाल के लिए नहीं थी। और उसके ओहदे का असली मतलब यह था कि वह मित्र-राष्ट्रों की मदद करे और तुर्की सिपाहियों से हथियार ले ले। यह कमाल के लिए बड़ा ही अच्छा मौक़ा था।

वह इस नियुक्ति पर उछल पड़ा और तुरन्त अनातोलिया के लिए रवाना होगया। यह अच्छा ही हुआ कि वह तुरन्त चला गया; क्योंकि उसके जाने के चन्द ही घण्टे बाद सुलतान ने अपना विचार बदल दिया था। एकाएक कमाल का खौफ उसपर सवार होगया और उसने आधी रात के वक्त कमाल को रोकने के लिए अंग्रेजों के पास सन्देश भेजा। पर तबतक चिड़िया उड़ गई थी।

कमालपाशा और मुट्ठीभर दूसरे तुर्कों ने अनातोलिया में राष्ट्रीय प्रतिरोध यानी क्लौमी मुखालफ़त का संगठन करना शुरू किया। शुरू में उन्होंने बहुत धीरे-धीरे और सावधानी से काम किया और वहाँ ठहरी हुई फ़ौज के अफसरों को मिलाने की कोशिश की। ऊपर से वे सुलतान के एजेण्ट की तरह काम करते थे, पर कुस्तुन-तुनिया से आये हुए हुक्मों की कोई परवा न करते थे। घटनायें जिस तरीक़े पर घट रही थीं उससे उन्हें मदद मिल रही थी। काकेशस में अंग्रेजों ने एक आर्मीनियन प्रजातंत्र कायम किया था और उसमें तुर्कों के पूर्वी सूबों को मिला देने का वादा किया था। अब आर्मीनियन प्रजातंत्र सोवियट यूनियन का एक हिस्सा है। आर्मीनियनों और तुर्कों में बड़ी दुश्मनी थी और पहले कितनी ही बार वे एक-दूसरे को क़त्ल कर चुके थे। जबतक तुर्कों के हाथ में ताक़त थी तबतक, और खास तौर से अब्दुलहमीद के वक़्त में, उन्होंने आर्मीनियनों को इस खूँखार खेल में खूब सताया था। इसलिए अब तुर्कों के आर्मीनियनों के मातहत होने का मतलब उनका पूरा विनाश था। इससे उन्होंने लड़ना ही अच्छा समझा। इसलिए अनातोलिया के पूर्वी सूबों के तुर्क कमालपाशा की अपीलों को सुनने के लिए अच्छी तरह तैयार थे।

इस बीच, एक दूसरी और ज्यादा महत्वपूर्ण घटना ने तुर्कों को जगा दिया। १९१९ के शुरू में इटली ने फ़्रांस और इंग्लैण्ड के साथ किये हुए अपने गुप्त समझौते को पूरा करना चाहा, जो अभीतक पूरा नहीं हो सका था। उसने एशियामाइनर में फ़्राँजें भेजनी शुरू कीं। इंग्लैण्ड और फ़्रांस को यह बिल्कुल अच्छा न लगा। वे इस वक़्त इटालियनों को बढ़ाना नहीं चाहते थे। क्या करना चाहिए, इसका फ़ंसला न कर सकने की वजह से उन्होंने यूनानी फ़्राँजों को स्मर्ना पर क़ब्ज़ा कर लेने की इजाज़त दे दी, जिससे इटालियनों के रास्ते में दिक्क़त पेश की जा सके।

यूनानियों को इसके लिए क्यों चुना गया? फ़्रांसीसी और अंग्रेज़ी फ़्राँजें लड़ते-लड़ते थक चुकी थीं और उनमें बशावत के ज़यालात फैल रहे थे। वे चाहती थीं कि जल्द-से-जल्द उन्हें फ़्राँजी काम से छुट्टी दे दी जाय ताकि वे घर जा सकें। यूनानी लोग नज़दोक ही थे और यूनान सरकार एशियामाइनर और कुस्तुनतुनिया को अपने राज्य में मिला लेने और पुराने दिक्क़ण्टियन साम्राज्य को फिर से खड़ा करने का सपना

देख रही थी। दो बड़े योग्य यूनानी उस समय के इंग्लैण्ड के प्रधान मंत्री और मित्र-राष्ट्रों की समिति में बड़े शक्तिमान लायड जार्ज के दोस्तों में से थे। इनमें से एक वेनेज़िलो था जो बीच-बीच में कई बार यूनान का प्रधान मंत्री रह चुका था। दूसरा बड़ा रहस्यमय या भेदिया आदमी है। इस वक़्त वह सर बेसिल ज़हरोफ़ के नाम से मशहूर है, गोकि उसका असली नाम बेसिलोस ज़करिया था। १८७७ में, जब वह बहुत कम उम्र का था, वह बालकन में अस्त्र-शस्त्र बनानेवाली एक ब्रिटिश कम्पनी का एजेण्ट बन गया। जब महायुद्ध ख़त्म हुआ तो वह योरप में और शायद दुनियाभर में सबसे मालदार आदमी था और बड़े-बड़े राजनीतिज्ञ और सरकारें उसका आदर करने में गौरव का अनुभव करते थे। उसे बड़ी-बड़ी अंग्रेज़ी और फ़्रांसीसी उपाधियाँ दी गई थीं; उसके पास बहुत-से अस्त्रवार थे और वह पीछे रहकर सरकारों की नीतियों पर बहुत ज्यादा असर डाला करता था। जनता को उसके बारे में कोई इल्म न था और वह अपनेको शोहरत और प्रचार से दूर रखता था। वह आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय साह-कार या पूंजी लगानेवाले का नमूना था, जो बहुतेरे देशों और प्रभावों के बीच अपनेको बेफ़िक्र और घर-जैसा महसूस करता है और कुछ हद तक विविध प्रजासत्तात्मक देशों की सरकारों पर नियंत्रण या क़ब्ज़ा भी रखता है। ऐसे देशों की जनता अपना शासन आप करने की भावना पर फूलती है, पर उनके पीछे असली ताक़त उस अन्तर्राष्ट्रीय पूंजी की होती है जो जाहिरा तौर पर दिखाई नहीं देती।

ज़हरोफ़ इतना मालदार और ताक़तवर कैसे होगया? उसका काम सब तरह के अस्त्र-शस्त्र यानी लड़ाई का माल बेचना था और यह ख़ास तौरपर बालकन में एक मुनाफे का काम था। पर बहुत-से लोगों का विश्वास है कि शुरू से ही वह ब्रिटिश खुफिया विभाग का आदमी था। इससे उसे व्यापार और राजनीति में बड़ी मदद मिली और बार-बार होनेवाली लड़ाइयों से उसे करोड़ों का फ़ायदा हुआ और यों वह आजकल का एक महान् रहस्यमय 'देव' (Giant) होगया। वह अभीतक ज़िन्दा है, हालांकि इस वक़्त (१९३३ में) उसकी उम्र ८४ वर्ष की होगी। वह माण्टकार्लो में रहता है।

इस बेहद मालदार भेदिया आदमी और वेनेज़िलो ने लायड जार्ज को इस बात पर रजामन्द कर लिया कि एशियामाइनर में यूनानी फ़ौजें भेजी जायें। ज़हरोफ़ ने इसपर पूंजी लगाने का वादा किया। यह उसका ऐसा व्यापार था जिसमें उसे फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि कहा जाता है कि इसमें उसने दस करोड़ डालर खो दिया। यह रक़म उसने तुर्की युद्ध में यूनानियों को दी थी। यह रक़म ४० करोड़ रुपये के बराबर थी, पर इसे देने पर भी ज़हरोफ़ का काम मज्जे से चलता रहा।

की हुई और भी बहुत-सी बातें उन्हें पसंद न आईं । इसलिए छः हफ्ते के बाद उन्होंने अपनी उन्हीं मामूली और भद्दी चालों से काम लेना शुरू किया जो उन्होंने मिस्र और दूसरी जगहों में चली थीं । अंग्रेज सेनापति इस्तम्बोल में घुस गया, शहर पर कब्जा कर लिया, फ़ौजी कानून जारी कर दिया, रऊफ़वेग सहित ४० राष्ट्रीय डेपुटियों को गिरफ़्तार कर लिया और उन्हें माल्टा को निर्वासित यानी जलावतन कर दिया । अंग्रेजों की ये शरीफ़ाना कारगुजारियाँ यह दिखाने के लिए थीं कि 'नेशनल पैक्ट' को मित्र-राष्ट्रों ने मंजूर नहीं किया है ।

फिर तुर्की में खूब उत्तेजना फैली । अब यह काफ़ी तीरपर साफ़ होगया था कि सुलतान अंग्रेजों के हाथ में एक कठपुतली है । बहुत-से तुर्की डेपुटी निकल भागे और अंगोरा पहुँच गये । वहाँ पार्लमेण्ट की बैठक हुई और उसने अपना नाम 'तुर्की की महान् राष्ट्रीय सभा' (Grand National Assembly of Turkey) रक्खा । उसने अपनेको देश की सरकार की शक्ल में घोषित किया और ऐलान कर दिया कि सुलतान और इस्तम्बोल की उसकी सरकार उसी दिन से ख़त्म होगई जिस दिन अंग्रेजों ने शहरपर कब्जा कर लिया ।

सुलतान ने कमालपाशा और दूसरे लोगों को वागी ऐलान किया और उनको फाँसी की सजा का हुक्म देकर इसका बदला लिया । सुलतान ने यह भी सूचित किया कि जो आदमी कमाल और उसके दूसरे साथियों को मार डालेगा, वह एक पवित्र कर्त्तव्य पूरा करेगा और उसे इस दुनिया और दूसरी दुनिया में भी इनाम मिलेगा । याद रखो कि सुलतान ख़लीफ़ा यानी मुसलमानों का धार्मिक नेता भी था और उसके जरिये निकाला हुआ यह मोत का खुला निमंत्रणपत्र बड़ा ख़ौफ़नाक था । कमालपाशा सिर्फ़ एक वागी ही न, था, जिसकी तलाश में सरकारी आदमी पड़े हुए हों, बल्कि दीन को छोड़ देनेवाला आदमी भी था जिसे कोई धर्मान्ध आदमी क़त्ल कर सकता था । सुलतान ने अपनी ताक़त-भर राष्ट्रवादियों को कुचलने के सारे उपाय किये । उसने उनके ख़िलाफ़ 'जिहाद' या धर्म-युद्ध का ऐलान कर दिया और उनसे लड़ने के लिए एक 'ख़लीफ़ों का फ़ौजी दस्ता' बनाया गया । मजहबी आदमी बग़ावत पैदा कर देने के लिए भेजे गये । जगह-जगह बलबे हुए और कुछ वक़्त तक सारे तुर्की में गृह-युद्ध छिड़ गया । यह शहर-शहर और भाई-भाई के बीच बड़ी बुरी लड़ाई थी और दोनों तरफ़ बड़ी बेरहमी से काम लिया गया ।

इस बीच स्मर्ना में यूनानी लोग इस तरह का वर्ताव कर रहे थे मानों वे स्थायी रूप से देश के मालिक हैं और मालिक भी बड़े जंगली हैं । उन्होंने उपजाऊ और हरी-भरी घाटियों और मैदानों को उजाड़ दिया और हजारों गृहहीन तुर्की को

वहाँ से खदेड़ दिया। तुर्कों ने उनका कोई जोरदार मुक़ाबिला नहीं किया, इसलिए वे बढ़ते गये।

राष्ट्रवादियों (नेशनलिस्टों) के लिए ऐसी स्थिति का सामना करना कुछ सुखदायी नहीं था—घर में उनके खिलाफ़ मजहब की ताक़त लिये हुए लड़ा जाने-वाला गृह-युद्ध और उधर उनसे लड़ने के लिए आगे बढ़ते हुए विदेशी आक्रमणकारी। फिर सुलतान और यूनानी दोनों के पीछे मित्र-राष्ट्र थे, जो जर्मनी के ऊपर फतह पाकर सारी दुनिया पर हावी होगये थे। लेकिन कमालपाशा का अपने देशवासियों के प्रति यह नारा था—‘जीतो या नष्ट हो जाओ।’ जब एक अमेरिकन ने उससे पूछा कि राष्ट्रवादी अगर नाकामयाब हुए तो तुम क्या करोगे, तब उसने जवाब दिया—“जो क़ौम ज़िन्दगी और आज़ादी के लिए बड़ी-से-बड़ी और आख़री कुर्बानियाँ करती है वह नाकामयाब नहीं होती। नाकामयाबी का मतलब तो यह है कि क़ौम मर चुकी है।”

अगस्त १९२० में वह सुलहनामा प्रकाशित हुआ जिसे मित्र-राष्ट्रों ने ग़रीब तुर्कों के लिए बनाया था। इसे ‘सेवरे की सन्धि’ कहा गया। यह तुर्की स्वतंत्रता का ख़ात्मा था; आज़ाद राष्ट्र के रूप में तुर्की को मौत की सज़ा दी गई। सिरक़ देश के टुकड़े-टुकड़े ही नहीं कर दिये गये बल्कि खुद इस्तम्बूल में रहकर नियंत्रण रखने के लिए मित्र-राष्ट्रों की तरफ़ से एक कमीशन नियुक्त किया गया। सारे देश में शोक छा गया और हड़ताल और प्रार्थना के साथ राष्ट्रीय शोक का दिन मनाया गया। उस दिन सारे काम बन्द रहे। बाले बार्डों के साथ अल्लवार निकले। पर सुलतान के प्रतिनिधियों ने तो सुलहनामे पर दस्तख़त कर ही दिये थे। हाँ, राष्ट्रवादियों ने उसे हिक्कारत के साथ ठुकरा दिया था और सुलहनामे के प्रकाशित होने का यह नतीजा हुआ कि उनकी ताक़त बढ़ गई और इस गहरी बेइज्जती से अपने देश को बचाने के लिए ज़्यादा-से-ज्यादा तुर्क तैयार होने लगे।

पर इस सुलहनामे की बागी तुर्की पर लागू कौन करता ? मित्र-राष्ट्र खुद ऐसा करने की तैयार न थे। उन्होंने अपनी फ़ौजों को असंगठित कर दिया था और ये सिपाही दड़ी खीस में थे। फिर पश्चिमी योरोप के देशों में वातावरण में अब भी भ्रान्ति और दिद्रोह के ख़यालालत थे। इसके अलावा युद्ध की लूट के बँटवारे के बारे में खुद मित्र-राष्ट्रों में कलह और झगड़े पैदा होगये थे। पूर्व में इंग्लैंड और कुछ हद तक फ़्रांस को एक ख़तरनाक स्थिति का सामना करना था। फ़्रेंच मॅण्डेट या शान्तिनादेश के नीचे सीरिया में ज़बरदस्त असंतोष पैदा होगया था और आगे वहाँ आफ़त खड़ी होने की संभावना थी। मिस्र में एक ख़ूनी दगावत हो चुकी थी, जिसे अंग्रेज़ों ने दबा दिया था। हिन्दुस्तान में १८५७ के ग़दर के बाद पहली नहान् दगावत, यद्यपि यह

शांतिपूर्ण थी, बढ़ रही थी। यह वापू के नेतृत्व में होनेवाला असहयोग-आन्दोलन था, और इसका एक मुख्य आधार खिलाफ़त का सवाल और तुर्की के साथ किया गया बुरा वर्तन था।

इस तरह हम देखते हैं मित्र-राष्ट्र खुद तुर्की पर इस सुलह को ज़बरदस्ती लागू करने की स्थिति में न थे और न वे इसीके लिए तैयार थे कि तुर्की राष्ट्रवादियों द्वारा उसको खुलेआम कुचल दिया जाय। ऐसी हालत में उन्होंने अपने मित्र वेनीज़ेलो और ज़हरोफ़ की तरफ़ देखा और ये दोनों यूनान की तरफ़ से इस काम की ज़िम्मेदारी उठाने के लिए पूरी तरह तैयार थे। किसीको यह उम्मीद नहीं था कि ये शिथिल और गिरे हुए तुर्क ज्यादा तंग करेंगे और एशिया माइनर का इनाम कुछ कम ललचानेवाला न था। और ज्यादा यूनानी फ़ौजें वहाँ भेजी गईं और बड़े पैमाने पर यूनानी-तुर्की युद्ध शुरू हुआ। १९२० के गर्मी और पतझड़ तक तो यूनानियों की जीत होती रही और उन्होंने अपने सामने से तुर्कों को खदेड़ दिया। अपने टूटे-फूटे साधनों से एक ज़बरदस्त और बहादुर फ़ौज तैयार करने की कमालपाशा और उसके साथियों ने रात-दिन कोशिश की। उनको मदद मिली, और वह भी ऐसे मौक़ेपर जबकि उनको उसकी बड़ी ज़रूरत थी। सोवियट रूस ने उनकी अस्त्र-शस्त्र यानी लड़ाई के सामान और धन से मदद की। इंग्लैंड इन दोनों का दुश्मन था।

ज्यों-ज्यों कमाल की ताक़त बढ़ती गई, मित्र-राष्ट्रों को लड़ाई के फ़ैसले या नतीजे के बारे में शक़ होने लगा और उन्होंने सुलह की अच्छी शर्तें पेश कीं। पर ये शर्तें भी इतनी अच्छी न थीं कि कमाल के दल के लोग उन्हें मंज़ूर करते, इसलिए उन्होंने उन्हें ठुकरा दिया। इसपर मित्र-राष्ट्रों ने यूनानी-तुर्की युद्ध से हाथ खींच लिया और अपनी उदासीनता यानी तटस्थता का ऐलान कर दिया। पहले तो उन्होंने यूनानियों को इसमें फँसाया और बाद में उन्हें ख़न्दक में छोड़कर अलग हो रहे। यहाँतक कि फ़्रांस और कुछ हद तक इटली ने खुफ़िया तौर पर तुर्कों से दोस्ती गाँठने की कोशिश की। अंग्रेज़ अब भी थोड़े-बहुत, पर शैर-सरकारी तौर पर, यूनानियों के साथ रहे।

१९२१ की गर्मी के दिनों में यूनानियों ने तुर्कों की राजधानी अंगोरा पर क़ब्ज़ा करने की ज़बरदस्त कोशिश की। वे कस्बे पर क़स्बे क़तल करते और उनपर क़ब्ज़ा जमाते हुए अंगोरा के नज़दीक तक आ पहुँचे, पर आख़िर स़क्रिया नदी पर रोक दिये गये। इस नदी के पास, तीन हफ़्ते तक, दोनों फ़ौजों ने एक-दूसरे का ज़बरदस्त मुक़ाबिला किया; किसीको किसी तरह की छूट या मुग़ालता नहीं दिया गया और दोनों सदियों की चली आती हुई जातीय कटुता के साथ एक-दूसरे से लड़ें। यह लड़ाई

सहन-शक्ति की भयंकर कसौटी बन गई। तुर्क किसी तरह डटे रहे और अन्त में यूनानी पीछे हट गये। जैसा उनका कायदा था, यूनानी फ़ौज पीछे लौटते वक़्त हर चीज़ को, जो उसके रास्ते में पड़ी, आग लगाती और बरबाद करती गई और उसने दो सौ मील तक के उपजाऊ देश को वीरान कर दिया।

सररिया नदी की लड़ाई में तुर्क जीत तो गये, पर यह हलकी जीत थी। यह कोई अन्तिम विजय न थी, फिर भी इसे आधुनिक इतिहास की महत्वपूर्ण और निर्णायक लड़ाइयों में गिना जाता है। इसका मतलब बहाव का उलट जाना था। फिर यह पूर्व और पश्चिम के बीच होनेवाली उन बड़ी लड़ाइयों में से एक थी जिन्होंने पिछले दो हजार वर्षों या ज्यादा समय से एशिया-माइनर की एक-एक इंच मिट्टी को इंसान के खून से सींचा है।

दोनों फ़ौजें बेदम हो रही थीं, इसलिए दोनों सुस्ताने और फिर से अपना संगठन करने के लिए बैठ गई। पर कमालपाशा की किस्मत का सितारा बुलन्द हो रहा था। फ़्रांसीसी सरकार ने अंगोरा के साथ सुलह करली। अंगोरा और सोवियट के साथ भी एक सुलह हो गई थी। फ़्रांस की मंजूरी मुस्तफ़ा कमाल के लिए एक बड़ी नैतिक और भौतिक सहायता थी। इससे सीरिया की सरहदों पर की तुर्की फ़ौजों को यूनान के ख़िलाफ़ लड़ने की छुट्टी मिल गई। ब्रिटिश सरकार अबतक उस कठपुतली सुलतान और ख़त्म हो रही इस्तम्बोल-सरकार का समर्थन कर रही थी और फ़्रांसीसी सुलह से उसे धक्का लगा।

अगस्त १९२२ ई० में, एकाएक पर बड़ी होशियारी से तैयारी करने के बाद, तुर्की फ़ौज ने यूनानियों पर हमला कर दिया और उनको समुद्र में खदेड़ दिया। आठ दिनों के अन्दर यूनानियों को १६० मील पीछे हटना पड़ा; पर पीछे हटते वक़्त भी रास्ते में मिलनेवाले हर तुर्की मर्द, औरत और बच्चे को मारकर उन्होंने अपना बदला लिया। तुर्क भी वैसे ही बेरहम थे और बहुत कम यूनानियों को क़ैदी रखते थे। इन यूनानी क़ैदियों में यूनानी प्रधान सेनापति और उसके स्टाफ़ के लोग थे। यूनानी फ़ौज का ज्यादातर हिस्सा स्मर्ना से समुद्र के रास्ते भाग गया, पर स्मर्ना शहर जला दिया गया।

कमालपाशा ने अपनी फ़ौजों के साथ इस्तम्बोल की तरफ़ बढ़ते हुए अपनी फ़तह जारी रखी। शहर से थोड़ी ही दूर पर, चनक मुक़ाम पर, ब्रिटिश फ़ौजों ने उसे रोक दिया और सितम्बर १९२२ में कुछ दिनों तक तुर्कों और ब्रिटेन के बीच लड़ाई छिड़ने की दात होती रही, पर अंग्रेज़ों ने क़रीब-क़रीब तुर्कों की नारी शर्त मानली और युद्ध बन्द करने की तजवीज़ या सुलहाने (Armistice) पर दस्तख़्त हो गये। इस सुलह-

नामे में मित्र-राष्ट्रों ने वादा किया कि थ्रेस में जितनी भी यूनानी फ़ौज है वह सब देश से हटा दी जायगी। नये तुर्की के पीछे सदा सोवियट रूस का भूत रहा और मित्र-राष्ट्र ऐसी लड़ाई छेड़ना नहीं चाहते थे जिसमें रूस तुर्की की मदद करे।

मुस्तफ़ा कमाल की विजय हुई और १९१९ के मुट्ठीभर वागी महाशक्तियों के प्रतिनिधियों से बराबरी की हैसियत से मिले। इस बहादुर टुकड़ी को बहुतेरी परिस्थितियों से मदद मिली थी, जिनमें युद्ध के बाद की प्रतिक्रिया, मित्र-राष्ट्रों की आपसी फूट या झगड़े, हिन्दुस्तान और मिस्र की विगड़ती हुई हालत में अंग्रेजों का फँस जाना, सोवियट रूस की मदद और अंग्रेजों द्वारा की हुई बेइज्जती ये बातें मुख्य थीं। पर इन सबके ऊपर उनकी विजय का श्रेय उनके फ़ौलादी इरादे, आज़ाद होने के उनके निश्चय और तुर्की किसानों और सिपाहियों की सैनिक यानी लड़ाकू विशेषताओं को ही है।

लुसान में एक शान्ति-सम्मेलन हुआ और कई महीनों तक चलता रहा। इंग्लैंड के घमण्डी और शासनप्रिय प्रतिनिधि लार्ड कर्ज़न और बहरे एवं फूले हुए इस्मतपाशा के बीच अच्छी-खासी पेंतरेवाज़ी हुई। इस्मतपाशा मुस्कराता रहता था और जो कुछ सुनना नहीं चाहता था उसे सुनने से इनकार कर देता था, जिससे कर्ज़न बड़ा चिढ़ता था। कर्ज़न को हिन्दुस्तान के वाइसराय वाले तरीकों से काम लेने की आदत पड़ गई थी; वह यों भी शान-शौकत का आदमी था; इसलिए उसने उन्हीं हाकिमाना तरीकों से काम लिया जिनका बहरे और मुस्कराते हुए इस्मत पर कोई असर नहीं पड़ा। चिढ़कर और झुंझलाकर कर्ज़न लौट आया और सम्मेलन टूट गया। बाद में फिर सम्मेलन हुआ, पर इस बार कर्ज़न की जगह दूसरा ब्रिटिश प्रतिनिधि आया। सिर्फ़ एक को छोड़कर 'नेशनल पैक्ट' में बताई हुई तुर्की की सारी शर्तें मान ली गईं और जुलाई १९२३ में लुसान की सन्धि पर दस्तख़त होगये। इस बार फिर सोवियट रूस के समर्थन और मित्र-राष्ट्रों की आपसी ईर्ष्या से तुर्की को मदद मिली।

कमालपाशा, शाज़ी यानी विजयी, को उन सब बातों में कामयाबी हुई जिनके लिए उसने लड़ाई शुरू की थी। शुरू से ही उसने अपनी कम-से-कम माँगों का ऐलान कर दिया था और विजय की घड़ी में भी उनपर टिका रहा। उसने अरबस्तान, इराक़, फ़िलिस्तीन और सीरिया वगैरा ग़ैरतुर्की मुल्कों पर तुर्की साम्राज्य का ख़याल बिल्कुल छोड़ दिया था। वह सिर्फ़ तुर्की के देश यानी ख़ास तुर्की को आज़ाद करना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि तुर्क दूसरी क़ौमों के बारे में दस्तन्दाजी करें; पर वह यह भी नहीं चाहता था कि तुर्की में किसी तरह का विदेशी दख़ल हो। इस तरह तुर्की एक संयुक्त और एक ही जाति यानी तुर्की का देश बन गया। कुछ वर्षों के बाद,

यूनानियों के प्रस्ताव पर आबादियों का एक गैर-मामूली अदला-बदला हुआ। अनातोलिया में जो यूनानी बच रहे थे वे यूनान भेज दिये गये और बदले में यूनान के तुर्क तुर्की में लाये गये। इस तरह करीब पंद्रह लाख यूनानियों का बदला हुआ। इन यूनानियों और तुर्कों के ज्यादातर कुटुम्ब क्रमशः अनातोलिया और यूनान में पीड़ियों से रहते आये थे। यह क्रांति का अजीब विच्छेद था और इससे तुर्की का आर्थिक जीवन बिल्कुल तितर-बितर होगया, क्योंकि यूनानियों का व्यापार में बहुत ज्यादा हिस्सा था। पर इससे तुर्की और ज्यादा एक-जातीय (Homogenous) होगया। और शायद इस वक़्त यह एशिया या योरप के देशों में सबसे ज्यादा एक-जातीय है।

मैंने ऊपर कहा है कि लुसान-सन्धि से तुर्की की एक के सिवा सब मांगें पूरी हो गईं। यह अपवाद 'दिल्लायत' या इराक़ की सीमा के नजदीक का मोसल प्रदेश था। चूँकि दोनों दल इस सवाल पर एकमत नहीं हो सके, इसलिए यह मामला राष्ट्र-संघ के पास भेज दिया गया। मोसल अपने तेल और खासकर अपनी सैनिक स्थिति के कारण बड़ा महत्वपूर्ण था। मोसल के पहाड़ों पर क़ब्ज़ा होने का मतलब कुछ हद तक तुर्की, इराक़, फारस, यहांतक कि रूस के काकेशस पर भी हावी होना था। ताफ़ तौर पर तुर्की के लिए यह महत्वपूर्ण था। ब्रिटेन के लिए भी यह उतना ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि हिन्दुस्तान को जानेवाले खुशकी और हवाई रास्तों की रक्षा और सोवियट रूस के खिलाफ़ हमला या दबाव करने के लिए यह बहुत ज़रूरी था। अगर तुम नक्शे में देखो तो तुम्हें मालूम होगा कि मोसल कंसी महत्वपूर्ण स्थिति में है। इस सवाल पर राष्ट्र-संघ ने ब्रिटेन के पक्ष में फ़ैसला किया। तुर्की ने उस फ़ैसले को मानने से इनकार कर दिया और फिर लड़ाई की बातचीत होने लगी। उसी वक़्त, दिसम्बर १९२५ ई० में, एक नई रूसी-तुर्की सन्धि हुई थी। पर अंगोरा की सरकार ने अख़ीर में राष्ट्र-संघ का फ़ैसला मान लिया और मोसल इराक़ के नये राज्य में शामिल कर लिया गया। इराक़ वैसे तो स्वतंत्र समझा जाता है, पर असल में यह ब्रिटेन का एक रक्षित या मातहत राज्य है और इसमें ब्रिटिश अधिकारी और सलाहकार भरे हुए हैं।

मुझे अच्छी तरह याद है कि जब ग्यारह साल पहले हम लोगों ने यूनानियों पर मुस्तज़ा क़माल की मर्याद विजय की ख़बर सुनी थी तो हम कितने ख़ुश हुए थे। यह अगस्त १९२२ में हुआ अफ़्रियम क़ुराहिनार का युद्ध था, जब क़माल ने यूनानी मोर्चे को तोड़कर यूनानी फ़ौज को स्मर्ना और समुद्र में ख़देड़ दिया। हमने ने बहुत-से लोग उस वक़्त लखनऊ ज़िला जेल में थे और हम लोगों ने जो कुछ मिला उन्हीं अपनी जेल की दीवारों को सजाकर तुर्की की विजय का जलना मनाया था और शान को रोमनी करने की भी हलकी-सी कोशिश की थी।

मुस्तफ़ा कमाल का अतीत से विच्छेद

८ मई, १९३३

हमने हार के अँधेरे ज़माने से लेकर विजय के दिन तक तुर्कों की किस्मत का मुला-हज़ा किया है और बड़े ताज्जुब के साथ देखा है कि मित्र-राष्ट्रों, खासकर अंग्रेज़ों, ने उनको कुचलने और कमज़ोर कर देने के लिए जिन उपायों का सहारा लिया उनसे तुर्कों पर बिल्कुल उलटा असर पड़ा और उन उपायों ने राष्ट्रवादियों को मजबूत कर दिया और आगे के प्रतिरोध लिए उन्हें फौलादी बना दिया। मित्र-राष्ट्रों की तुर्कों के टुकड़े करने की कोशिश, स्मर्ना में यूनानी फ़ौजों का भेजा जाना, मार्च १९२० का ब्रिटेन का वह आकस्मिक पैतरा, जब राष्ट्रवादी नेता गिरफ़्तार करके जलावतन कर दिये गये, राष्ट्रवादियों के खिलाफ़ अंग्रेज़ों का कठपुतली सुलतान का समर्थन—इन सब बातों ने तुर्कों का गुस्सा और जोश बढ़ाने में मदद की। किसी बहादुर क़ौम को कुचलने और अपमानित करने का लाजमी तौर पर यही नतीजा या असर होता है।

मुस्तफ़ा कमाल और उसके साथियों ने जो फ़तह हासिल की थी, उसका क्या किया? कमालपाशा पुराने रिवाजों से चिपके रहने में विश्वास नहीं रखता था; वह तुर्कों को पूरे तौरपर बदल डालना चाहता था। पर अपनी फ़तह के बाद यद्यपि वह खूब लोकप्रिय था फिर भी उसे बहुत सावधानी से धीरे-धीरे आगे बढ़ना पड़ा, क्योंकि लम्बे ज़माने से चली आ रही परम्परा और धर्म पर खड़े हुए पुराने तरीक़ों को ख़त्म कर देना आसान काम नहीं है। वह सुलतानियत और ख़िलाफ़त दोनों को ख़त्म कर देना चाहता था, पर उसके बहुत-से साथी उससे सहमत न थे और सामान्य तुर्की जनता के ख़यालात भी शायद ऐसी तब्दीली के खिलाफ़ थे। हाँ, कठपुतली सुलतान वहीदउद्दीन को कोई नहीं चाहता था। उसे लोग ऐसा देशद्रोही समझते थे जिसने अपने देश को विदेशियों के हाथ बेच देने की कोशिश की थी और उससे नफ़रत करते थे। बहुत-से लोग एक तरह की वैधानिक सुलतानियत और ख़िलाफ़त चाहते थे और असली सत्ता या ताक़त नेशनल असेम्बली के हाथ में रखने का समर्थन करते थे। कमालपाशा को ऐसा कोई समझौता पसन्द न था; इसलिए वह मौक़े का इन्तज़ार करने लगा।

सदा की तरह अंग्रेज़ों की वजह से वह मौक़ा जल्द आगया। जब लुसान के शान्ति-सम्मेलन की तैयारी हो रही थी तब ब्रिटिश सरकार ने इस्तम्बूल में सुलतान के पास न्यौता भेजा और शान्ति की शर्तें तय करने के लिए अपने प्रतिनिधि भेजने को लिखा और सुलतान से यह अनुरोध भी किया कि यह न्यौता अंगोरा को भी दोहरा दिया जाय। अंगोरा की राष्ट्रीय सरकार के साथ (जिसने लड़ाई जीती थी) इस तरह के

भट्टे बर्ताव और जान-बूझकर कठपुतली सुलतान को आगे बढ़ाने की इस कोशिश ने तुर्की में एक सनसनी पैदा कर दी और तुर्की को क्रोध कर दिया। उन लोगों को यह श्रवण हो गया कि कहीं देशद्रोही सुलतान और अंग्रेजों के बीच फिर कुछ साजिश तो नहीं हो रही है। मुस्तफ़ा कमाल ने मौक़ा देखकर इस ख़याल का फ़ायदा उठा लिया और नवम्बर १९२२ ई० में नेशनल असेम्बली से सुलतानियत को तोड़ देने का फ़ैसला करा लिया। लेकिन खुद ख़िलाफ़त जिन्दा रही और यह ऐलान किया गया कि वह उथमान (उस्मान) घराने के हाथ में रहेगी। इसके बाद ही भूतपूर्व सुलतान वहीदउद्दीन के ख़िलाफ़ भारी देश-द्रोह के जुर्म में मुक़दमा चलाया गया। उसने सार्व-जनिक मुक़दमे का सामना करने की बनिस्बत देश से भाग जाना ही अच्छा समझा। वह एक अंग्रेज़ी एम्बुलेंसकार (मरीजों या घायलों को ढोने वाली मोटर गाड़ी) में छिपकर भाग गया। यह कार उसे एक ब्रिटिश लड़ाकू जहाज तक पहुँचा आई। नेशनल असेम्बली ने उसके चचेरे भाई अब्दुलमजीद को नया ख़लीफ़ा चुना, जो बिना किसी राजनैतिक शक्ति के एक दिखाऊ धर्माध्यक्ष था।

दूसरे साल, १९२३ में, बाक़ायदा तुर्की प्रजातंत्र का ऐलान हुआ और अंगोरा राजधानी बनाई गई। मुस्तफ़ा कमाल राष्ट्रपति चुना गया और उसने सारी ताक़त अपनेमें केन्द्रित कर ली, यानी डिक्टेटर (सर्वेसर्वा) बन गया। असेम्बली उसके आदेशों या हुक्मों का पालन करती थी। अब उसने पहिले पुराने रिवाजों पर हमला करना शुरू किया। वह मजहब के बारे में कुछ ज्यादा शरीफ़ाना सलूक नहीं करता था। बहुत-से लोग, खास तौर पर मजहबी लोग, उसके तरीक़ों और उसकी डिक्टेटरशिप से असंतुष्ट हो गये। ये लोग नये ख़लीफ़ा के, जो खुद एक शान्त और सीधा आदमी था, ईर्द-गिर्द जमा हो गये। कमालपाशा को यह सब पसन्द न आया। उसने ख़लीफ़ा के साथ बहुत हलका बर्ताव किया और अगला बड़ा क़दम बढ़ाने के लिए उचित अवसर का इन्तज़ार करने लगा।

फिर उसे जल्द ही यह मौक़ा मिल गया, और वह कुछ अजीब ढंग से आया। लन्दन से आगाख़ाँ और एक भूतपूर्व हिन्दुस्तानी जज अमीरअली दोनों का संयुक्त पत्र उसे मिला। इन लोगों ने लाखों-करोड़ों हिन्दुस्तानी मुसलमानों के नाम पर बोलने का दावा करते हुए ख़लीफ़ा के साथ किये हुए बर्ताव का विरोध किया और अनुरोध किया कि उसकी मर्यादा की इज्जत की जानी चाहिए और उसके साथ ज्यादा अच्छा बर्ताव किया जाना चाहिए। इन दोनों ने इस ख़त की नक़ल इम्नम्बोल के कई अख़बारों को भी भेज दी और अख़्तली पत्र के अंगोरा पहुँचने के पहले ही नक़ल इन अख़बारों में छप गई। इन ख़त में कोई अनुचित दावा नहीं था; पर कमालपाशा ने इन

मौफ़े को हाथ से जाने देना अच्छा न समझा और इस ख़त को लेकर एक आन्दोलन खड़ा कर दिया। उसने ऐलान किया कि यह तुर्कों में भेद यानी तफ़रका पैदा करने की दूसरी अंग्रेज़ी साजिश है। कहा गया कि आगाख़ाँ अंग्रेज़ों का खास एजेण्ट है; वह इंग्लैण्ड में रहता है, उसकी खास दिलचस्पी अंग्रेज़ी घुड़दौड़ में है और अंग्रेज़ राजनीतिज्ञों से उसका खूब हेलमेल है। वह कट्टर मुसलमान भी नहीं है और मुसलमानों के एक फ़िरक़े का प्रधान है। यह भी कहा गया कि महायुद्ध के ज़माने में अंग्रेज़ों ने पूर्व में पासंग बराबर रखने के लिए एक दूसरे मुलतान—ख़लीफ़ा का रूप देकर उसका उपयोग किया और प्रचार करके उसकी शान और इज्जत बढ़ाई तथा उसे हिन्दुस्तानी मुसलमानों का नेता बनाने की कोशिश इसलिए की कि उन्हें क़ब्ज़े में रखा जा सके। अगर आगाख़ाँ को ख़लीफ़ा से इतनी हमदर्दी थी तो उसने युद्ध के ज़माने में, जब अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ 'जिहाद' या पवित्र ऐलान किया गया था, ख़लीफ़ा का समर्थन क्यों नहीं किया? उस वक़्त उसने ख़लीफ़ा के विरुद्ध अंग्रेज़ों का साथ दिया था।

इस तरह कमालपाशा ने इस संयुक्त पत्र के ऊपर एक तूफ़ान खड़ा कर दिया। लन्दन से यह ख़त भेजते वक़्त इसके लेखकों ने इन नतीजों का ख़याल भी न किया होगा। कमालपाशा ने आगाख़ाँ के बारे में जो बातें कहीं उनसे लोग आगाख़ाँ को अच्छा नहीं समझ सकते थे। जिन ग़रीब इस्तम्बोली सम्पादकों ने इस ख़त को छपा दिया था वे देशद्रोही और इंग्लैण्ड के एजेण्ट बताये गये और उन्हें सज़ा दी गई। इस तरह लोगों में गहरा जोश और दूसरी साजिश का ख़ौफ़ पैदा करके कमालपाशा ने नेशनल असेम्बली में ख़िलाफ़त को तोड़ देने का एक बिल पेश कराया जो उसी रोज़, मार्च १९२४ ई० में, पास होगया। यों आधुनिक रंगमंच से एक पुरानी संस्था या परम्परा, जिसने इतिहास में बहुत बड़ा पार्ट खेला था, ख़त्म होगई। अब कोई 'ईमानदारों का सरदार', कम-से-कम जहाँतक तुर्कों का ताल्लुक था, नहीं रह गया, क्योंकि तुर्की एक दुनियावी राज्य बन गया; यानी राज्य का किसी मज़हब के प्रति कोई आग्रह नहीं रह गया।

कुछ ही वक़्त पहले, जब महायुद्ध के बाद ख़िलाफ़त के प्रति अंग्रेज़ों ने धमकी से भरा ख़त इक़तियार किया था, हिन्दुस्तान में ज़बरदस्त तहरीक हुई थी। सारे देश में ख़िलाफ़त कमेटियाँ बन गई थीं और मुसलमानों के इस आन्दोलन में हिन्दुओं की बड़ी तादाद इस ख़याल से शामिल होगई थी कि ब्रिटिश सरकार इस्लाम के प्रति अन्याय कर रही है। अब तुर्कों ने खुद जान-बूझकर ख़िलाफ़त का ख़ात्मा कर दिया था; इस्लाम बिना ख़लीफ़ा के होगया था। कमालपाशा की यह निश्चित राय थी कि तुर्की को मज़हब की बिना पर अरब देशों या हिन्दुस्तान से कोई रिश्ता नहीं रखना

है। वह अपने देश के लिए या खुद अपने लिए इस्लाम का नेतृत्व नहीं चाहता था। मिस्र और हिन्दुस्तान के लोगों के अनुरोध पर भी उसने खलीफ़ा बनने से इनकार कर दिया था। उसकी नज़र पश्चिम में योरोप की तरफ़ थी और वह चाहता था कि जितनी जल्द मुसलमान हो तुर्की पश्चिमी रंग में रंग जाय। वह पैत-इस्लामी यानी सब मुसलमान देशों का एक संगठन बनाने के ख़याल के बिल्कुल विरुद्ध था। उसके सामने पैत-द्यूरेनियतिज्म यानी द्यूरेन या तुर्क जाति की तरक्की का नया आदर्श था। मतलब यह कि इस्लाम के लम्बे-चौड़े पर शिथिल अन्तर्राष्ट्रीय आदर्श पर उसने शुद्ध राष्ट्रीयता के ज्यादा नज़र और ठोस बन्धनों की तरजीह दी।

मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि अब तुर्की एक-जातीय देश होगया था, और उसमें विदेशी तत्त्व बहुत कम रह गये थे। पर पूर्वी तुर्की में इराक़ और फारस की सरहद पर अब भी एक ग़ैर-तुर्की जाति थी। यह एक तरह की ईरानी ज़बान बोलनेवाली बहुत पुरानी जाति थी जिसे कुर्द कहते थे। कुर्दिस्तान, जिसमें ये लोग रहते थे, कई टुकड़ों में बँटकर तुर्की, फ़ारस, इराक़ और मोसल प्रदेश में मिल गया था। तीस लाख कुर्दों में से करीब आधे अब भी ख़ास तुर्की में थे। १९०८ की नीजवान तुर्क क्रान्ति के बाद ही उनमें नये ढंग का राष्ट्रीय आन्दोलन चल रहा था। वर्साई के शान्ति-सम्मेलन में भी कुर्द प्रतिनिधियों ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता यानी क़ामी आज़ादी की मांग की थी।

१९२५ ई० में तुर्की के कुर्द प्रदेश में एक बड़ा बलबा होगया। यह वही वज़त था जद मोसल के मामले को लेकर इंग्लैण्ड और तुर्की में तनातनी बढ़ रही थी। मोसल खुद ही कुर्द का एक प्रदेश था और उस हिस्से से लगा हुआ था जिसमें बलबा खड़ा हुआ था। तुर्की ने स्वभावतः यह अन्दाज़ लगाया कि इस बलबे के पीछे इंग्लैण्ड का हाथ है और ब्रिटिश एजेंटों ने कमालपाशा के सुधारों के खिलाफ़ कट्टर मजहब़ी कुर्दों को भड़काया है। यह कहना मुमकिन नहीं है कि ब्रिटिश एजेंटों का इस बलबे से कोई ताल्लुक़ था या नहीं, ग़ोकि यह बात स्पष्ट थी कि उस मौक़े पर तुर्की में कुर्द बलबे का ब्रिटिश सरकार ने स्वागत किया। जो हो, इतना तो साफ़ था कि इस बलबे का ज्यादातर ताल्लुक़ मजहब़ी कट्टरता से था और यह भी साफ़ है कि इसमें कुर्द राष्ट्रीयता का भी बड़ा हिस्सा था। संभवतः राष्ट्रीय भाव ही सबसे ज़ोर पर था।

कमालपाशा ने तुरन्त ही आवाज़ दलन्द की कि तुर्की क़ौम ख़तरे में है, क्योंकि कुर्दों के पीछे इंग्लैण्ड का हाथ है। उन्होंने नेशनल असेम्बली से एक क़ानून पास कराया। इन क़ानून में कहा गया था कि बोलबरे या लिखकर लोगों को भड़काने के लिए मजहब़ का इस्तेमाल करना उदरदन्त देश-द्रोह का ज़ुर्म समझा जायगा और उसके लिए

सबसे कड़ी सजा दी जायगी। मस्जिदों में उन मजहबी बातों का पढ़ाना भी बन्द कर दिया गया जिनसे प्रजातंत्र के प्रति लोगों की भक्ति या वफादारी में कुछ फर्क आने की संभावना थी। इसके बाद उसने बड़ी बेरहमी से कुर्दों को कुचल दिया और हजारों की तादाद में उनका फैसला करने के लिए स्वतंत्रता की खास अदालतें (Special Tribunals of Independence) कायम कीं। शेख सईद, डाक्टर फ़ाद और दूसरे बहुत-से कुर्द नेता फांसी पर चढ़ा दिये गये। वे ओठों पर कुर्दिस्तान की आजादी का नाम लेते-लेते मरे।

इस तरह तुर्कों ने, जो कुछ ही दिन पहले अपनी आजादी के लिये लड़ रहे थे, अपनी आजादी की माँग करनेवाले कुर्दों को कुचल दिया। यह अजीब बात है कि कैसे रक्षणात्मक राष्ट्रीयता उग्र और आक्रामक राष्ट्रीयता (Aggressive Nationalism) में तब्दील हो जाती है और किस तरह आजादी की लड़ाई दूसरों को गुलाम बनाने और दूसरों पर प्रभुता कायम करने की शक्ल में बदल जाती है। १९२९ ई० में फिर कुर्दों का एक वलवा हुआ और फिर वह, कम-से-कम उस वक्त, कुचल दिया गया। हमेशा के लिए तो भला कोई उस क्राँम को कैसे कुचल सकता है, जो आजादी की माँग पर डटी हुई है और उसकी क्रीमत चुकाने को तैयार है ?

इसके बाद कमालपाशा ने उन सब लोगों की तरफ नज़र डाली जिन्होंने नेशनल असेम्बली में या उसके बाहर उसकी नीति का विरोध किया था। एक डिक्टेटर की ताक़त या सत्ता की भूख सदा उसके इस्तेमाल के साथ बढ़ती जाती है; वह कभी संतुष्ट या तृप्त नहीं होती, न वह किसी किस्म की मुलालफ़त बरदाश्त कर सकती है। मुस्तफ़ा कमाल ने भी सब तरह के विरोध पर नाराज़गी जाहिर की और इसी वक्त किसी धर्मान्ध द्वारा उसका खून करने की कोशिश से मामला बिल्कुल ख़राब हो गया। स्वतंत्रता की अदालतें सारे तुर्की में घूम-घूमकर उन सब लोगों को सज़ा सज़ा देने लगीं जो शाज़ी पाशा की मुलालफ़त करते थे। यहाँतक कि असेम्बली के बड़े-से-बड़े लोग और कमाल के पुराने नेशनलिस्ट साथी भी, विरोध में होने पर, नहीं बरसो गये। रऊफ़ बेग, जिसे अंग्रेज़ों ने माल्टा को निर्वासित या जलावतन कर दिया था, और जो बाद में तुर्की का प्रधान मंत्री हुआ, अपनी ग़ैरहाज़िरी में ही दण्डित हुआ। बहुत-से दूसरे महत्वपूर्ण नेता और सिपहसालार, जो आजादी की लड़ाई में बहादुरी के साथ लड़े थे, बेइज्जत किये गये और उनको सज़ा दी गई और कुछ फांसी पर चढ़ा दिये गये। उनके ख़िलाफ़ इलज़ाम यह लगाया गया कि उन्होंने राज्य की रक्षा के विरुद्ध कुर्दों के साथ और शायद पुराने दुश्मन इंग्लैंड के साथ भी षड्यंत्र किया था।

सब विरोध को ख़त्म कर देने के बाद मुस्तफ़ा कमाल अब एकमात्र डिक्टेटर था और इस्मतपाशा उसका दाहिना हाथ था। अब उसने अपने कई विचारों को, जो अभी तक उसके दिमाग में भरे हुए थे, अमली शकल देना शुरू किया। उसने बहुत छोटी बात से सुधार शुरू किया पर वह एक नमूने की बात थी। उसने 'फ़ेज' यानी तुर्की टोपी पर हमला किया, जो तुर्की और कुछ हद तक मुसलमानों का प्रतीक या निशान हो गई थी। उसने फ़ौज के साथ बहुत सम्मेलन हुए शुरुआत की। फिर भी वह खुद हैट लगाकर जनता के सामने उपस्थित हुआ, जिससे भीड़ को बड़ी हैरत हुई और उसने 'फ़ेज' पहनने को अपराध करार देकर उसका खात्मा किया। टोपी को इतना ज्यादा महत्व देना महज एक पागलपन मालूम होता है। ज्यादा महत्व की बात यह है कि सिर के अन्दर क्या है, न कि वह जो सिर के ऊपर है। पर कभी-कभी छोटी-छोटी बातें बड़ी बातों का प्रतीक या निशान बन जाती हैं और कमालपाशा ने ग़रीब 'फ़ेज' के रूप में पुराने रिवाज और कट्टरता पर हमला किया। इस सवाल पर दंगे हुए। उन्हें दवा दिया गया और विरोधियों और दंगाइयों को सख्त सज़ायें दी गईं।

पहले पैंतरे में फतह पाने के बाद मुस्तफ़ा कमाल ने आगे एक क़दम और रक्खा। उसने सब मठ और धर्मस्थान बन्द कर दिये या तोड़ दिये और उनका सारा धन राज्य के लिए ज़ब्त कर लिया। जो दरवेश इन स्थानों या मठों में रहते थे उन्हें अपनी रोज़ी के लिए काम और मेहनत करने को कहा गया। यहाँ तक कि उनका खास तरह की पोशाक पहनना भी बन्द कर दिया गया।

इसके भी पहले मुसलमानी मजहबी स्कूल तोड़ दिये गये और उनकी जगह राज्य के ग़ैरमजहबी स्कूल ब्रायम कर दिये गये थे। तुर्की में बहुत-से विदेशी स्कूल-कालेज थे। उनको भी अपनी मजहबी तालीम बन्द करने को मजबूर होना पड़ा। अगर वे इनकार करते तो उन्हें एकदम से बन्द कर दिया जाता। इन विदेशी स्कूलों में तुर्की विषय अनिवार्य कर दिये गये।

क़ानून में भी ऊपर से नीचे तक तब्दीली हुई। अभी तक बहुतेरी बातों में क़ानून क़ुरान की शिक्षाओं पर, जिसे 'शरियत' कहते हैं, आश्रित था। अब स्विस सिविल कोड (स्वीजरलैंड का दीवानी क़ानून), इटालियन पेनल कोड (इटली का दण्ड-विधान) और जर्मन कमर्शल कोड (जर्मनी का व्यापारिक विधान) का ज्यादातर हिस्सा लेकर क़ानून बनाया गया। इसका मतलब व्यक्तिगत क़ानून (Personal law), जिसके मृत्याविक शादी, विरासत वगैरा का काम चलता था, में पूरी तब्दीली हो जाना था। इन बातों के बारे में पुराना इस्लामी क़ानून बदल दिया गया। एकसाथ कई औरतों से शादी करने का रिवाज उखाड़ दिया गया।

दूसरा परिवर्तन, जो पुराने मजहबी रिवाजों के खिलाफ़ गया, इनसान की शकल-सूरत को लेकर ड्राइंग, चित्रकला और मूर्तिकला को बढ़ाना या उत्साहित करना था। इस्लाम इस चीज़ को नहीं मानता। मुस्तफ़ा कमाल ने इस काम के लिए, लड़के-लड़कियों को कला सिखानेवाले स्कूल खोले।

‘नौजवान तुर्क’ आन्दोलन के जमाने से ही तुर्की स्त्रियों ने आजादी की लड़ाई में बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा लिया था। कमालपाशा उनको हर तरह के बन्धनों से छुड़ाकर आजाद करने के लिए बड़े उत्सुक थे। एक ‘नारी-अधिकार रक्षण सभा’ यानी स्त्रियों के हकूक को महफूज रखनेवाली सभा खोली गई और उनके लिए कई कामों या पेशों के दरवाज़े खोल दिये गये। पहले परदा और घूँघट पर जोरदार हमला किया गया और दोनों बड़ी तेज़ी के साथ गायब होगये। स्त्रियों को घूँघट फाड़ फेंकने के लिए सिर्फ़ मौक़ा और सहूलियत देने की ज़रूरत है। कमालपाशा ने उनको यह मौक़ा दिया और वे बाहर निकल आईं। उसने यूरोपियन नाच को बड़ा उत्तेजन दिया। वह न सिर्फ़ खुद इसका शौकीन था बल्कि उसकी समझ से यह औरतों की आजादी और पाश्चात्य सभ्यता का प्रतिनिधित्व था। हँट और नृत्य प्रगति और सभ्यता के नारे बन गये। ये पश्चिम के मामूली प्रतीक थे, पर कम से कम उन्होंने, सतहपर तो ख़ूब काम किया और तुर्की ने अपनी टोपी, अपनी पोशाक और अपनी ज़िन्दगी का तरीक़ा बदल दिया। परदानशीन औरतों की पीढ़ी-की-पीढ़ी चन्द सालों के बीच वकीलों, मास्टर्स, डाक्टरों और जजों में तब्दील होगई। यहाँतक कि इस्तम्बूल की सड़कों पर पुलिस औरतें भी हैं। यह देखने में बड़ा मज़ा आता है कि एक चीज़ दूसरे पर कैसे असर डालती है। लैटिन वर्णमाला को मंज़ूर कर लेने से तुर्की में टाइपराइटरों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ गया और इसका मतलब यह हुआ कि ज्यादा शार्टहैंड टाइपिस्टों की ज़रूरत हुई, जिससे स्त्रियों को भी ज्यादा नौकरियाँ मिलने लगीं।

जहाँ लड़कों को मजहबी मदरसों में रटकर सब कुछ याद कर लेने का पुराना तरीक़ा सिखाया जाता था वहाँ उनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों पर अपना विकास करके आत्मविश्वासी और योग्य नागरिक बनाने पर जोर दिया जाने लगा। एक उल्लेखनीय संस्था ‘शिशु-सप्ताह’ थी। कहा जाता है कि हर साल, एक हफ्ते तक, हरेक सरकारी अधिकारी हटा दिये जाते और उनकी जगह लड़के काम करते और सारे राज्य का इन्तज़ाम लड़कों के ज़रिये चलाया जाता। मैं नहीं जानता कि वह व्यवस्था किस तरीक़े पर की जाती है, पर यह आकर्षक धारणा यानी अपनी तरफ़ खींचनेवाला ख़याल है और मुझे विश्वास है कि कुछ लड़के चाहे कितने ही बेवकूफ़ और अनुभवहीन हों, वे उससे ज्यादा बेवकूफी नहीं कर सकते जितनी हमारे बड़ी उम्र के मनहूस

और बड़े गंभीर तथा पवित्र दिखाई देनेवाले शासक और अधिकारी करते हैं।

एक छोटी-सी, पर तुर्की के शासकों के नये दृष्टिकोण को जाहिर करनेवाली, तब्दीली यह हुई कि सलाम करने के रिवाज को धीरे-धीरे हटा दिया गया। यह कहा गया कि 'हैण्ड शैकिंग' (हाथ मिलाना) स्वागत का ज्यादा सभ्य तरीका है और आगे से उसीको अपनाना चाहिए।

इसके बाद कमालपाशा ने तुर्की भाषा, या जैसा कि वह कहता था उसमें आये हुए विदेशी तत्वों पर एक जबरदस्त हमला किया। तुर्की जवान अरबी लिपि में लिखी जाती थी, जो ऊर्दू या फ़ारसी लिपि से मिलती-जुलती थी। कमालपाशा ने इन दोनों को विदेशी और मुश्किल बताया। ऐसे ही सवाल मध्यएशिया में सोवियट यूनियन के सामने भी पेश हुए थे, क्योंकि कई तातारी क़ौमों की लिपि अरबी या फ़ारसी से ली हुई लिपि थी। १९२४ में सोवियट ने इस सवाल पर विचार करने के लिए बाकू में एक कांग्रेस की और यह तय हुआ कि मध्यएशिया की मुश्किल तातारी जवानों के लिए लैटिन लिपि ग्रहण की जाय। इसका मतलब यह कि जवानें तो वही रहीं पर वे लैटिन या रोमन लिपि में लिखी जाने लगीं। चिन्हों की एक खास प्रणाली निकाली गई, जिससे इन जवानों के खास स्वरों या शब्दों को ठीक तौर से जाहिर किया जा सके। मुस्तफ़ा कमाल का भी ध्यान इस तरीके की तरफ़ गया और उसने इसे सीखा। उसने इसका प्रयोग तुर्की जवान पर किया और इसके पक्ष में व्यक्तिगत रूप से एक जबरदस्त आन्दोलन शुरू कर दिया। कई वर्षों के प्रचार और तालीम के बाद क़ानून के जरिये एक तारीख़ मुक़र्रर कर दी गई जिसके बाद अरबी लिपि का इस्तेमाल क़ानूनन बन्द कर दिया गया और उसकी जगह लैटिन लिपि लाज़िमी या अनिवार्य कर दी गई। अख़बार, किताबों और दूसरी सब चीज़ों का लैटिन लिपि में छपना ज़रूरी होगया। १६ से ४० वर्ष की उम्र के हर व्यक्ति को स्कूल में जाकर लैटिन लिपि सीखनी पड़ी। जो अधिकारी इसे नहीं जानते थे उन्हें बर्खास्त किया जा सकता था। अपनी सज़ा पूरी करने के बाद भी क़दी तब तक न छोड़े जाते जबतक वह नई लिपि सीख न लेते। एक डिप्टेटर, फिर अगर लोकप्रिय हुआ तो, कहीं निकलने का रास्ता नहीं देता। शायद थोड़ी ही सरकारें यों जनता की ज़िन्दगी में इतना ज्यादा दखल देने की हिम्मत करेंगी।

इस तरह तुर्की में लैटिन लिपि क़ायम होगई, पर जल्दी ही दूसरी तब्दीली आई। पता चला कि अरबी और फ़ारसी शब्द इस लिपि में आसानी से नहीं लिखे जा सकते। उनके ज़ास्त स्वर या 'नुअान्स' (nuances) यानी भावों के सूक्ष्म अन्तर इसमें जाहिर नहीं किये जा सकते। शब्द तुर्की शब्द इतने अच्छे या संस्कृत

नहीं थे; वे ज्यादा रूखे, कर्णकटु, सीधे और जोरदार थे और नई लिपि में आसानी से लिखे जा सकते थे। इसलिए यह तय हुआ कि तुर्की ज़बान से अरबी फ़ारसी के शब्द निकाल दिये जायें और उनकी जगह पर शुद्ध तुर्की शब्द रखे जायें। इस फ़सले के पीछे एक राष्ट्रीय कारण भी था। जैसा मैं तुम्हें बता चुका हूँ, कमालपाशा जहाँ तक मुमकिन हो, तुर्की को अरबी और पूर्वी प्रभावों से अलग रखना चाहता था। अरबी और फ़ारसी शब्दों और जुमलों और मुहावरों से भरी हुई पुरानी तुर्की ज़बान शाही उस्मानी दरबार की शानशीकृत से भरी ज़िन्दगी के लिए ठीक हो सकती थी, पर नये जोरदार तुर्की प्रजातंत्र के लिए वह ठीक नहीं समझी गई। इस तरह अच्छे और मँजे हुए शब्द छोड़ दिये गये और विद्वान प्रोफ़ेसर और दूसरे लोग किसानों की ज़बान सीखने और पुरानी तुर्की ज़बान से शब्दों की तलाश करने के लिए गाँवों में गये। अभी तक तब्दीली हो रही है। उत्तरी हिन्दुस्तान में हमारे लिए ऐसी तब्दीली का मतलब पुराने दरबारी जीवन की एक यादगार-सी लखनऊ और दिल्ली की अलंकृत पर बनावटी हिन्दुस्तानी को छोड़कर बहुतेरे ग्रामीण या 'गँदाख़' शब्दों को ग्रहण, करना होगा।

भाषा की इन तब्दीलियों की वजह से शहरों और आदमियों के नामों में भी तब्दीली हुई। जैसा तुम जानती हो, अब कुस्तुनतुनिया इस्तम्बोल हो गया है, अंगोरा अंकारा बन गया है और स्मर्ना अब इस्मीर है। तुर्की में आदमियों के नाम ज्यादातर अरबी से लिये होते हैं। मुस्तफ़ा कमाल खुद एक अरबी नाम हैं। नई प्रवृत्ति शुद्ध तुर्की नाम रखने की चल पड़ी है।

एक और तब्दीली, जिससे आफ़त और मुसीबत आई, यह थी कि नमाज़ और अज़ा भी तुर्की ज़बान में होने का क़ानून बना दिया गया। मुसलमान सदा से नमाज़ मूल अरबी में ही पढ़ते रहे हैं; आज भी हिन्दुस्तान में उसकी यही सूरत है। इसलिए कितने ही मौलवियों और मस्जिदों के मुहाफ़िजों ने कहा कि यह अनुचित है और उन्होंने अरबी में ही नमाज़ पढ़ना जारी रखी। इस सवाल पर कई दंगे हुए और अब भी होते रहते हैं, पर कमालपाशा की मातहत में तुर्की सरकार ने दूसरे विरोधों की तरह इसे भी कुचल दिया है।

पिछले दस वर्षों की इन महान् सामाजिक उथल-पुथल ने जनता की ज़िन्दगी को बिल्कुल बदल दिया है और पुराने रिवाजों और मज़हबी बातों से अलग, एक नई पीढ़ी का विकास हो रहा है। गोकि ये तब्दीलियाँ काफ़ी बड़ी और महत्वपूर्ण हैं, पर उनसे देश के आर्थिक जीवन में कुछ ज्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। सिरे पर की चंद तब्दीलियों के अलावा उसका आधार वही है जो पहले था। कमालपाशा अर्थशास्त्री

नहीं है और न वह उन बड़ी तन्वीलियों के पक्ष में है जो सोवियट रूस में हुई हैं। इसलिए यद्यपि उसकी सोवियट रूस से राजनैतिक दोस्ती है, पर आर्थिक दृष्टि से वह साम्यवाद से दूर रहता है। ऐसा जान पड़ता है कि उसके राजनैतिक और सामाजिक विचार महान् फ्रेंच राज्यक्रान्ति के अध्ययन से बने हैं।

पेशेवर वर्ग को छोड़कर अभी तक तुर्की में कोई जोरदार मध्यमवर्ग नहीं है। यूनानियों और दूसरे विदेशी वर्गों के देश के बाहर भेज दिये जाने से व्यापारिक जीवन कमजोर पड़ गया है। पर तुर्की सरकार अपनी आर्थिक आजादी को क्रूरबान करने की जगह राष्ट्रीय शरीबी और धीरे-धीरे होनेवाले औद्योगिक विकास को कहीं ज्यादा पसंद करती है। चूंकि उसे डर है कि ज्यादा तादाद में विदेशी पूंजी देश में आने से आर्थिक आजादी को क्रूरबान करना पड़ेगा और बाद में उसकी वजह से विदेशों की लूट जारी हो जायगी, इसलिए उसने विदेशियों को उद्योग-व्यवसाय खोलने के मामले में अनुत्साहित किया है। विदेशी माल पर भारी चंगी लगाई गई है। कई उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हो गया है, यानी जनता की तरफ से सरकार उनपर कब्जा रखती और उन्हें चलाती है। रेलवे तेजी से बन रही है।

खेती में कमालपाशा की खासतौर पर दिलचस्पी है, क्योंकि तुर्की किसान तुर्की राष्ट्र और फ्राँज की रोढ़-सा रहा है। नमूने के खेत (माडल फार्म) बनाये गये हैं; ट्रैक्टरों (इंजिन से चलनेवाले बड़े हलों) का प्रचार किया गया है और किसानों की सहयोग-समितियों को उत्तेजन दिया गया है।

आज, बाक्री दुनिया की तरह, तुर्की भी महान् मंदी के चक्कर में फँसा हुआ है और अपनी गुज़र करना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। ग्राजीमुस्तफ़ा कमाल पाशा देश का सर्वेसर्वा बना हुआ है, और यद्यपि कभी-कभी जहाँ-तहाँ बलवे और दंगे हो जाते हैं पर कोई ज्यादा जोरदार विरोध नहीं दिखाई देता है। कमाल १८८० में पैदा हुआ था और इस वक्त भी जीवन के मध्याह्न में है और उसके सामने कई वर्षों का काम फैला हुआ है।

: १६० :

हिन्दुस्तान गांधीजी का अनुसरण करता है

११ मई, १९३३

अब मैं तुम्हें हिन्दुस्तान की हाल की घटनाओं के बारे में कुछ बताऊँगा। स्वभावतः दूसरे मुल्कों में होनेवाली घटनाओं की वनिस्वत इनमें हमारी ज्यादा दिलचस्पी है, और इसलिए मुझे अपने ऊपर नियंत्रण रखना पड़ेगा कि कहीं मैं बहुत ज्यादा

व्योरे की बातों में न चला जाऊँ। हमारी निजी दिलचस्पी के अलावा, जैसा मैं तुम्हें बता चुका हूँ, आज हिन्दुस्तान दुनिया की बड़ी समस्याओं या सवालों में से एक है। यह साम्राज्यवादी हुकूमत का एक नमूनेदार (Typical) और ऊँचे दर्जे का पुराना देश है। ब्रिटिश साम्राज्यवाद का सारा ढाँचा इसपर खड़ा रहा है और इस सफल ब्रिटिश उदाहरण से दूसरे देश भी साम्राज्यवादी दुस्ताहसिकता यानी कमजोर देशों को गुलाम बनाने और उनका शोषण करने के रास्ते पर चलने को ललचे हैं।

मैंने हिन्दुस्तान पर लिखे अपने पिछले खत में तुमसे उन तब्दीलियों का जिक्र किया है जो युद्ध के जमाने में यहाँ हुईं। उसमें मैंने हिन्दुस्तानी उद्योगों और हिन्दुस्तानी पूँजीपति-वर्ग की बढ़ती और हिन्दुस्तानी उद्योगों के प्रति ब्रिटिशनीति के परिवर्तन की बात भी लिखी थी। हिन्दुस्तान से इंग्लैंड पर पड़नेवाला औद्योगिक और व्यापारिक दबाव बढ़ रहा था और राजनैतिक दबाव में भी बढ़ती हो रही थी। सारे पूर्व में एक राजनैतिक जागरण हो रहा था और युद्ध के बाद सारी दुनिया में क्षोभ और बेचैनी फैली हुई थी। हिन्दुस्तान में कभी-कभी हिंसात्मक क्रान्तिकारी घटनाएँ हो जाती थीं। जनता को बड़ी-बड़ी उम्मीदें थीं। ब्रिटिश सरकार खुद समझ रही थी कि कुछ-न-कुछ करना चाहिए। उसने जाँच के बाद राजनैतिक क्षेत्र में कुछ तब्दीली करने की तजवीजों की थीं, जो माण्टेगू-चेल्मसफोर्ड रिपोर्ट में बताई गई थीं। आर्थिक क्षेत्र में उसने बढ़ते हुए मध्यमवर्ग के सामने कुछ टुकड़े फेंक दिये थे, पर इस बात की होशियारी रक्खी थी कि सत्ता और शोषण के किले उसीके हाथ में रहें।

युद्ध के बाद कुछ दिनों तक व्यापार फूलता-फलता रहा और बड़ी भारी समृद्धि का जमाना आया जिसमें लोगों ने, खासकर बंगाल के जूटवालों ने, खूब मुनाफ़ा उठाया। इसमें तो सालाना मुनाफ़े की दर (Dividend) अक्सर सौ फ़ी सदी से भी ऊँची हो जाती थी। चीजों के दाम चढ़ गये और कुछ सीमा तक, पर चीजों के दाम की बढ़ती के मुक़ाबिले कम, मजदूरी की दर भी बढ़ गई। दाम चढ़ जाने से वह मालगुजारी भी बढ़ गई जो काश्तकार ज़मींदार को देता था। इसके बाद मन्दी आई और व्यापार बिगड़ने लगा। उद्योगों में लगे मजदूरों और काश्तकारों की हालत बहुत ख़राब होगई और असन्तोष जोरों से बढ़ने लगा। इस दिन-दिन बिगड़ती हुई हालत की वजह से कारख़ानों में बहुतेरी हड़तालें हुईं। अवध में, जहाँ ताल्लुक़ेदारी प्रणाली में ख़ासतौर से काश्तकारों की हालत बहुत ख़राब थी, क़रीब-क़रीब अपने-आप एक जोरदार किसान-आन्दोलन उठ खड़ा हुआ। पढ़े-लिखे छोटे मध्यमवर्गों में बेकारी बढ़ गई और उनकी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा।

युद्ध के बाद के जमाने के शुरू दिनों की यह आर्थिक पार्श्वभूमि थी, और

अगर तुम इसका खयाल रखो तो बाद की राजनैतिक घटनाओं के समझने में तुम्हें मदद देगी। देश में एक उग्र या सैनिक 'स्प्रिट' थी जो मुह्तलिफ़ सूरतों में अपनेको जाहिर कर रही थी। उद्योग-धंधों में लगे हुए मजूर अपने मजदूर-संघ बना रहे थे और बाद में उन्होंने अखिल-भारतीय मजूर संघ काँग्रेस (All India Trade Union Congress) का संगठन किया। छोटे-छोटे जमींदार और अपनी जमीन पर मिल्कियत रखनेवाले किसान सरकार से असन्तुष्ट थे और राजनैतिक कार्रवाई की तरफ़ झुक रहे थे। काश्तकार भी, चोट खाये हुए कीड़े की तरह, उलटने की कोशिश कर रहे थे और मध्यमवर्ग, खासतौर से उनमें वे लोग जो बेकार थे, निश्चित रूप में राजनीति की तरफ़ और उनमें से मुट्ठीभर क्रान्तिकारी कार्यों की तरफ़ झुक रहे थे। इन हालातों से हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख और दूसरे सब एकसमान प्रभावित हुए थे, क्योंकि आर्थिक स्थितियाँ मजहबों तफ़ावत की तरफ़ बहुत कम ध्यान देती हैं। पर इन बातों के अलावा मुसलमान तुर्की के खिलाफ़ होनेवाली लड़ाई और इस शंका से ज्यादा उत्तेजित हो रहे थे कि कहीं ब्रिटिश सरकार 'जज़ीरत-उल-अरब' और उसके मक्का, मदीना और जरूसलम वगैरा पवित्र शहरों पर क़ब्ज़ा न करले। याद रखो कि जरूसलम यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों—तीनों का तीर्थस्थान है।

हिन्दुस्तान युद्ध के बाद इन्तज़ार कर रहा था। वह खीझ से भरा हुआ बल्कि उग्र था। उसे ज्यादा उम्मीद तो न थी, फिर भी कुछ आस लगी थी। कुछ ही महीनों के अन्दर नई ब्रिटिश नीति के पहले फल, जिनकी तरफ़ लोग बड़ी आस लगाय हुए थे, क्रान्तिकारी आन्दोलन को दबाने के लिए खास क़ानून बनाने की तजवीज़ की सूरत में सामने आगये। ज्यादा आज़ादी की जगह ज्यादा दमन आया। ये बिल एक कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर बनाये गये थे और रालड बिल के नाम से मशहूर हैं। पर बहुत जल्द वे सारे देश में 'काले बिल' (Black Bills) के नाम से पुकारे गये; हर जगह हर हिन्दुस्तानी, यहाँतक कि बहुत ज्यादा माडरेट लोगों द्वारा भी उनकी निन्दा की गई। उनमें सरकार और पुलिस को बहुत ज्यादा अख्तियारात दे दिये गये थे। उनके मुताबिक़ पुलिस को अख्तियार था कि जिससे वह नाराज़ हो या जिसपर उसका शुबहा हो उसे गिरफ़्तार कर सकती, बिना मुकदमा चलाये जेल में रख सकती और खुफ़िया मुकदमा चला सकती थी। उस वक़्त इन बिलों के बारे में एक मशहूर वयान यह था— "न वक़ील, न अर्पील, न दलील।" उधर बिलों की मुख़ालफ़त बढ़ती और जोरदार होती गई, इधर राजनैतिक क्षितिज पर एक नई चीज़, एक छोटा-सा वादल प्रकट हुआ और तेज़ी से बढ़ने और फैलने लगा—यहाँतक कि उसने सारे भारतीय आकाश को ढक लिया।

यह नया तत्त्व—यह वादल मोहनदास करमचन्द गाँधी था। वह युद्ध-काल में दक्षिण अफ़्रीका से हिन्दुस्तान लौटा था और अपने साथियों के साथ साबरमती में एक आश्रम बनाकर रहता था। वह राजनीति से दूर रहता था। यहाँ तक कि उसने युद्ध के लिए सिपाहियों की भरती करने में सरकार की मदद की थी। दक्षिण अफ़्रीका के अपने सत्याग्रह-युद्ध के कारण वह हिन्दुस्तान में अच्छी तरह मशहूर हो चुका था। १९१७ में (में यह सब याददाश्त के सहारे लिख रहा हूँ और मुमकिन है कि तारीखें ग़लत भी हो जायें) उसने बिहार के चम्पारन ज़िले के निलहे गोरों के जुल्म के खिलाफ़ बड़ी कामयाबी के साथ दुखिया और पीड़ित काश्तकारों का नेतृत्व किया था। बाद में उसने गुजरात के खेड़ा ज़िले के किसानों का साथ दिया था। १९१९ ई० के शुरू में वह बड़े जोर से बीमार पड़ा। वह इस बीमारी से उठा ही था कि देश में राउल्ट बिल से कोहराम मच गया। उसने भी इस आम मुल्लाफ़क़त में अपनी आवाज़ मिला दी।

लेकिन उसकी आवाज़ दूसरों से कुछ जुदा थी। यह शान्त और धीमी थी, फिर भी सर्वसाधारण के शोर के ऊपर सुनाई देती थी। यह मुलायम और नम्र थी, फिर भी इसमें कहीं फौलाद (यानी फौलाद जैसा कड़ापन) छिपा हुआ था। यह मीठी और अपील से भरी हुई थी, फिर भी इसमें कोई दृढ़ और डरावनी चीज़ थी। उसमें इस्तेमाल किया हुआ हरेक लफ़्ज़ अर्थ से भरा हुआ था और उसके पीछे एक ज़बर-दस्त सच्चाई मालूम पड़ती थी। शान्ति और मित्रता यानी सुलह और दोस्ती की ज़वान के पीछे शक्ति और क्रिया की काँपती हुई छाया थी और ग़लती के आगे न झुकने का निश्चय था। अब तो हम इस आवाज़ से परिचित होगये हैं; हमने पिछले चौदह वर्षों में कितनी ही बार इसे सुना। पर फरवरी और मार्च १९१९ में यह आवाज़ हमारे लिए नई थी। हम ठीक तरह नहीं जानते थे कि इसका क्या करना चाहिए, पर हम पुलकित हो उठे। निन्दा की हमारी शोरगुल-भरी राजनीति से यह कुछ एक बिल्कुल जुदी चीज़ थी—उस राजनीति से जो सदा विरोध के फिज़ूल और बेअसर प्रस्तावों में, जिनपर कोई ज़्यादा ध्यान न देता था, ख़त्म होती थी। पर यह उससे जुदा चीज़ थी। यह क्रिया की लड़ाई की राजनीति थी, बातचीत और बहस-मुवाहसे की राजनीति नहीं।

बापू ने उन लोगों की एक सत्याग्रह-सभा बनाई जो चुने हुए क़ानून को तोड़ने और उसके लिए जेल जाने को तैयार थे। उस वक़्त यह बिल्कुल नया ख़याल था और हममें से बहुत-से इससे जोश में भर उठे और कितने ही सहमकर पीछे हट गये। आज तो यह (जेल) घटनाओं के लिए मामूली और सामान्य स्थान बन गया है और हममें से बहुतों के लिए हमारी जिन्दगी का एक निश्चित और नियमित हिस्सा बन गया है।

जैसा उनका कायदा है, बापू ने वाइसराय को एक नम्रतापूर्ण अपील और चेतावनी भेजी। जब उन्होंने देखा कि सारे हिन्दुस्तान के विरोध के बावजूद ब्रिटिश सरकार कानून पास करने पर तुली हुई है, तो उन्होंने सारे हिन्दुस्तान में एक शोक-दिवस या मातम का दिन मनाने को कहा। तय हुआ कि उस दिन हड़ताल की जाय; सारे कारबार बंद रहें और सभायें की जायें। बिलों के कानून बन जाने के बाद का पहला रविवार इसके लिए चुना गया। इस दिन सत्याग्रह आन्दोलन की शुरुआत होने वाली थी और यों ६ अप्रैल १९१९ का रविवार सारे देश, शहरों और गाँवों में सत्याग्रह-दिवस के रूप में मनाया गया। यह अपने ढंग का पहला अखिल-भारतीय यानी सारे हिन्दुस्तान में होनेवाला प्रदर्शन था और यह बड़ा शानदार और प्रभावशाली रहा, जिसमें सब तरह के लोगों और जातियों ने हिस्सा लिया। हममें से जिन लोगों ने इस हड़ताल के लिए काम किया था वे इसकी कामयाबी पर हैरत में आ गये। हम लोग सिर्फ शहर के थोड़े लोगों तक पहुँच सके थे, पर हवा में एक नई 'स्पिरिट' आ गई थी और किसी तरह से वह संदेश हमारे विशाल देश के दूर-दूर के गाँवों तक पहुँच गया। पहली मर्तबा गाँववालों और शहरातियों ने बहुत बड़े पैमाने पर एक राजनैतिक प्रदर्शन में हिस्सा लिया।

६ अप्रैल के एक हफ्ते पहले, तारीख के वारे में गलतफहमी होजाने से, दिल्ली ने ३१ मार्च को पड़नेवाले रविवार के दिन ही हड़ताल मनाई थी। वे दिन दिल्ली के हिन्दुओं और मुसलमानों में भाईचारे की मुहब्बत के दिन थे और आर्यसमाज के मशहूर नेता स्वामी श्रद्धानन्द के जामा मस्जिद में बड़ी-बड़ी सभाओं के सामने भाषण देने का पवित्र दृश्य दिखाई पड़ा। ३१ मार्च को पुलिस और फौज ने सड़कों पर जमा जबरदस्त भीड़ को तितर-बितर करने की कोशिश की और उसपर गोलियाँ भी चलादीं, जिससे कई आदमी मारे गये। अपने संन्यासी के वेश में लम्बे और महान् स्वामी श्रद्धानन्द ने, चांदनी चौक में, खुले हुए सीने और न झपकनेवाली आँखों से गुरखों की किरचों का सामना किया। उन्होंने उन गुरखों की किरचों पर फतह हासिल की और इस घटना से सारा हिन्दुस्तान पुलकित हो उठा। पर इसकी 'ट्रेजेडी'—दुःख से भरी बात—यह है कि आठ से कम ही वर्षों बाद अपनी बीमारी में चारपाई पर पड़े-पड़े वह एक धर्मान्ध मुसलमान के हाथों, छुरा भोंककर, मार डाले गये !

६ अप्रैल के उस सत्याग्रह-दिवस के बाद घटनायें तेज़ी से घटीं। जब अमृतसर में १० तारीख को निरस्त्र और नंगे सिर भीड़ पर, जो अपने नेताओं डॉ० किचलू और डॉ० सत्यपाल की गिरफ्तारी पर दुःख प्रकट करने के लिए इकट्ठी हुई थी, फौज ने गोली चलादी और कई आदमी मारे गये, तो एक दंगा होगया। भीड़ ने पाँच

या छः निर्दोष अंग्रेजों को, जो अपने दफ्तरों में बैठे हुए थे, मारकर और उनके बँकों के मकानों को जलाकर इसका पागलपन से भरा हुआ बदला लिया। उसके बाद तो जैसे पंजाब पर एक परदा छा गया। वह बाक़ी हिन्दुस्तान से ज़बरदस्त सेंसर के ज़रिये अलग कर दिया गया; मुश्किल से वहाँकी कोई ख़बर आती थी और लोगों का इस सूबे में जाना या वहाँ से बाहर आना, बड़ा मुश्किल था। वहाँ मार्शलला यानी फ़ौजी क़ानून जारी कर दिया गया था और उसका हाहाकार कई महीनों तक जारी रहा। हफ़्तों और महीनों की हाहाकार-भरी चुप्पी के बाद धीरे-धीरे परदा उठा और उन ख़ौफ़नाक घटनाओं की सच्ची बातें लोगों को मालूम पड़ीं।

मैं यहाँ तुमसे पंजाब के फ़ौजी क़ानून की भयंकरताओं का ज़िक्र न करूँगा। अमृतसर के जलियाँवाला बाग़ में १३ अप्रैल को जो क़त्लेआम हुआ उसे सारी दुनिया जानती है। वहाँ उस मौत के पिंजड़े में, जिससे भागने या बचने का कोई रास्ता न था, हज़ारों आदमी मारे गये और जलमी हुए। अमृतसर लपज़ ही 'क़त्लेआम' का समानार्थवाची होगया है। यह हत्याकाण्ड तो बुरा था ही, पर सारे पंजाब में ऐसी और भी, और इससे भी अधिक लज्जाजनक, बातें हुईं।

इतने वर्षों के बाद भी इस सब बर्बरता और भयंकरता को क्षमा कर देना मुश्किल है, फिर भी इसे समझने में कोई मुश्किल नहीं है। अपनी हुकूमत के तरीक़े या स्वभाव के कारण हिन्दुस्तान में अंग्रेज़ सदा यह महसूस करते हैं कि वे किसी ज्वालामुखी के किनारे पर बैठे हुए हैं। उन्होंने हिन्दुस्तान के दिल व दिमाग़ को बहुत कम समझा है और समझने की कोशिश भी शायद ही कभी की है। वे अपने लम्बे-चौड़े और जटिल संगठन और उसके पीछे की फ़ौजी ताक़त पर विश्वास रखकर अपनी ज़िन्दगी अलग बसर करते रहे हैं। पर उनके सारे विश्वास के पीछे सदा किसी अज्ञात चीज़ का भय है और डेढ़ सौ वर्षों की हुकूमत के बाद भी हिन्दुस्तान उनके लिए एक अज्ञात प्रदेश है। उनके मन में १८५७ के ग़दर की स्मृतियाँ ताज़ा हैं और वे महसूस करते हैं कि जैसे वे एक अजीब, अपरिचित और विरोधी देश में रहते हैं जो किसी भी वक़्त उनपर टूट सकता और उनके टुकड़े-टुकड़े कर दे सकता है। उनके ख़यालात की यह आम बुनियाद है। जब उन्होंने एक ऐसा बड़ा आन्दोलन देश में उठते हुए देखा जो उनके खिलाफ़ था, तो उनकी शंका बढ़ गई। जब १० अप्रैल को अमृतसर में हुए ख़ूनी कारनामों की ख़बर पंजाब के बड़े-बड़े अधिकारियों के पास लाहौर पहुँची तो वे स्थिर न रह सके। उन्होंने समझा कि १८५७ के ग़दर की तरह यह भी बड़े पैमाने पर होनेवाली ख़ूनी बगावत है और सब अंग्रेज़ों की जान ख़तरे में है। उन्हें ख़ून दिखाई दिया और इसलिए उन्होंने जनता पर आतंक पैदा करना चाहा। ज़ालियाँवाला-

बाग का हत्याकाण्ड, फ़ौजी कानून और बाद की घटनायें उनकी इसी मानसिक स्थिति का परिणाम थीं ।

कोई एक डरे हुए आदमी के बुरे बर्ताव को, फिर चाहे उसके डर का कोई वास्तविक कारण न भी हो, समझ सकता है, यद्यपि उसे माफ़ नहीं कर सकता । पर इससे भी ज्यादा हैरत और गुस्सा हिन्दुस्तान को इस बात पर हुआ कि जनरल डायर ने, जो अमृतसर में हुई गोलीबारी और हजारों ज़ख्मी आदमियों के प्रति जंगली उपेक्षा या लापरवाही के लिए जिम्मेदार था, कई महीने बाद भी बड़े अपमानजनक ढंग से अपने किये हुए कामों को ठीक बताया । ज़ख्मी आदमियों के प्रति उसने अपनी उपेक्षा के बारे में कहा—“यह मेरा काम नहीं था ।” इंग्लैंड में कुछ आदमियों और सरकार ने डायर की बड़ी हलकी आलोचना की थी । पर ब्रिटिश शासक-वर्ग का सामान्य रुज़ हाउस ऑफ़ लार्ड्स (पार्लमेण्ट की सरदार सभा) की बहस में दिखाई पड़ा, जिसमें जनरल डायर की प्रशंसा की झड़ी लगा दी गई । इन सब बातों ने हिन्दुस्तान में गुस्से की आग को तेज़ रक्खा और पंजाब के ज़ुल्मों को लेकर सारे देश में कटुता छा गई । सरकार और कांग्रेस दोनों ने जाँच-कमेटियाँ बैठाईं कि वे पता लगावें कि पंजाब में असल में क्या घटनायें हुईं । देश ने उनकी रिपोर्ट का इन्तज़ार किया ।

उस साल से १३ अप्रैल हिन्दुस्तान के लिए राष्ट्रीय दिवस रहा है और ६ अप्रैल से १३ अप्रैल, यानी आठ दिन तक, राष्ट्रीय सप्ताह मनाया जाता है । अब जालियाँ-वाला बाग़ एक राजनैतिक तीर्थ बन गया है । इस वक़्त यह बड़ी ख़बसूरती के साथ बनाया गया बाग़ है और इसकी ज्यादातर पुरानी भयंकरता दूर हो गई है, पर स्मृतियाँ वहाँकी हवा में अब भी छा रही हैं ।

विचित्र संयोग से उस साल, दिसम्बर १९१९ में, कांग्रेस अमृतसर में हुई । दादू इसके सभापति थे और इसके सबसे नन्हे दर्शकों में से एक इन्दिरा प्रियदर्शिनी भी थी ! इस कांग्रेस में कोई महत्वपूर्ण निश्चय नहीं हुआ, क्योंकि जाँच-कमेटियों की रिपोर्ट और नतीजे का इन्तज़ार था । पर यह साफ़ जाहिर था कि कांग्रेस बदल गई है । अब उसका एक सार्वजनिक रूप हो गया था और इसमें एक नई और कुछ पुराने कांग्रेसमैनो के लिए ख़तरनाक या चिन्ता-जनक ताक़त आ गई थी । उसमें लोकमान्य तिलक भी आये थे, जो सदा की तरह किसी तरह का समझौता करने या झुकने के खिलाफ़ थे । यह कांग्रेस में उनका आखिरी आना था, क्योंकि दूसरी कांग्रेस के पहले ही उनकी मृत्यु होनेवाली थी । उसमें वापू थे, जो सर्वसाधारण में लोकप्रिय थे और कांग्रेस और भारतीय राजनीति पर अपने प्रभुत्व के लम्बे युग की शुरुआत कर रहे थे । इस कांग्रेस में जेलों से छूटे हुए वे बहुतेरे नेता आये थे, जिन्हें

फौजी कानून के दिनों में घड़्यंत्र के भयंकर मुकदमों में फँसाकर लम्बी सजायें दी गई थीं पर क्षमादान मिलने से छोड़ दिये गये थे। इनमें मशहूर अलीबन्धु (स्व० मौलाना मुहम्मदअली और शौकतअली) भी थे जो कई वर्षों की नज़रबन्दी के बाद हाल में ही छोड़े गये थे।

दूसरे साल कांग्रेस ने गोता मारा और वापू का असहयोग का कार्यक्रम मंजूर किया। कलकत्ता में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ, जिसमें यह पास हुआ और बाद में नागपुर के सालाना जलसे में पक्के तौर पर स्वीकार किया गया। यह कार्यक्रम पंजाब और खिलाफत के जुल्मों को दूर करने के आधार पर बनाया गया था और बाद में उनके साथ स्वराज्य का प्रश्न भी जोड़ दिया गया। पंजाब के जुल्मों को दूर करने का मतलब वहाँके क्रूरवार अफसरों को सजा देना था। लड़ाई का तरीका बिल्कुल शान्तिपूर्ण—या जैसाकि उसे कहते थे अहिंसात्मक—था और सरकार को उसके शासन और हिन्दुस्तान के शोषण में मदद देने से इनकार करना इसका आधार था। विदेशी सरकार से मिले हुए खिताबों, सरकारी उत्सवों, अदालतों, सरकारी स्कूलों और कालेजों और माण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों के मुताबिक बनी नई कौंसिलों का वायकाट इसमें शामिल था। वकीलों को भी अदालतों का वायकाट करना था। यह तजवीज़ की गई थी कि बाद में दीवानी और फौजी नौकरियों का भी वायकाट किया जायगा और टैक्स देने से इनकार कर दिया जायगा। रचनात्मक काम की दिशा में चर्खा और खादी का प्रचार और सरकारी अदालतों की जगह पंचायतें कायम करना रक्खा गया। और बड़ी महत्वपूर्ण बातें, जिनपर जोर दिया गया, हिन्दू-मुस्लिम एकता और हिन्दुओं के बीच से छुआछूत को दूर करना था।

कांग्रेस ने अपना विधान भी बदल दिया और कुछ काम करनेलायक संस्था बन गई। उसने सर्वसाधारण के लिए अपनी सदस्यता का दरवाज़ा भी खोल दिया।

अभीतक कांग्रेस जो कुछ करती रही थी उससे यह कार्यक्रम बिल्कुल ही जुदा था। बल्कि सारी दुनिया के लिए यह एक नई बात थी, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में जो सत्याग्रह हुआ था उसका द्रष्टिकोण और क्षेत्र बहुत छोटा था। अब इस कार्यक्रम का मतलब कुछ लोगों के लिए—जैसे वकीलों, जिन्हें वकालत छोड़ने को कहा गया था, और विद्यार्थियों, जिन्हें अपने कालेजों का वायकाट करना था, के लिए—तुरन्त बहुत बड़ी क्रूरवानी करना था। इसकी जाँच करना भी मुश्किल था, क्योंकि तुलना के लिए कोई पैमाना न था। इसमें ताज्जुब की बात नहीं कि पुराने और अनुभवी कांग्रेस-नेता इसमें शामिल होने से हिचकिचाये और शंकित हो उठे। उनमें सबसे बड़े नेता लोकमान्य तिलक थे, जिनकी मृत्यु कुछ ही पहले हो चुकी थी। दूसरे बड़े

कांग्रेस-नेताओं में से सिर्फ दादू ने आन्दोलन की शुरुआत में गांधीजी का समर्थन किया। पर औसत कांग्रेसमैन, मामूली आदमी या सर्वसाधारण जनता के उत्साह के बारे में कोई सन्देह न था। बापू जैसे उन्हें बहा या उड़ा ले गये या उनपर कोई जादू कर दिया। सर्वसाधारण ने 'गांधीजी की जय' के नारे से आसमान गुंजाकर अहिंसात्मक असहयोग के नये सिद्धान्त के प्रति अपनी मंजूरी जाहिर की। मुसलमान भी औरों की तरह उत्साह से भर रहे थे। अलीबन्धुओं के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी ने इस प्रोग्राम को कांग्रेस के भी पहले मान लिया था। जल्द ही सर्वसाधारण के उत्साह और आन्दोलन की शुरु की कामयाबियों को देखकर ज्यादातर पुराने कांग्रेस-नेता इसमें आ गये।

मैं इन ख़तों में, इस आन्दोलन के गुण-दोष अर्थात् अच्छाइयों और ख़राबियों, या इसके पीछे के तत्त्वज्ञान की जाँच नहीं कर सकता। यह एक बड़ा पेचीदा सवाल होगा। और शायद इसके जन्मदाता गांधीजी के सिवा दूसरा कोई अच्छी तरह या संतोष-जनक रीति से इसे नहीं कर सकता। फिर भी हमें बाहरी आदमी की निगाह से इसे देखना चाहिए और यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि यह इतनी तेज़ी और कामयाबी के साथ क्यों फैल गया।

विदेशी शोषण में सर्वसाधारण जनता पर पड़नेवाले आर्थिक बोझ या दबाव और दिन-पर-दिन उनकी बिगड़ती हुई हालत और मध्यम वर्गों में बढ़ती हुई बेकारी की चर्चा मैं तुमसे कर चुका हूँ। इसके लिए उपाय क्या था? राष्ट्रीयता के बढ़ने से लोगों का ध्यान राजनैतिक स्वतंत्रता की तरफ़ गया। लोगों ने समझा कि आजादी की सिर्फ़ इसीलिए ज़रूरत नहीं है कि आश्रित और गुलाम होना बेइज्जती और शर्म की बात है; वह सिर्फ़ इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि तिलक के लफ्ज़ों में 'वह हमारा जन्म-सिद्ध अधिकार है और हमें उसे हासिल करना चाहिए', बल्कि अपनी क़ौम या राष्ट्र पर ग्रामी का जो बोझ है उसको कम करने के लिए भी उसकी ज़रूरत है। जाहिर था कि चुपचाप बैठकर इस उम्मीद के साथ उसका इन्तज़ार करने से कि वह अपने-आप आ जायगी, वह नहीं मिल सकती। इसके साथ यह बात भी साफ़ जाहिर थी कि सिर्फ़ विरोध और प्रार्थना करने के तरीक़े, जिसपर कभी कम कभी ज़रा ज्यादा जोश से कांग्रेस अभी तक चल रही थी, एक क़ौम के लिए न सिर्फ़ उसकी मर्यादा या इज्जत के प्रतिकूल थे बल्कि फ़िज़ूल और बेअसर भी थे। इतिहास में ऐसे तरीक़ों से काम-याबी हासिल करने या शासन और सुविधा-प्राप्त वर्ग को अपनी सत्ता छोड़ने पर मजबूर करने की कोई मिसाल न थी। इतिहास ने तो हमें बताया कि गुलाम क़ौमों या वर्गों को उनकी आजादी हिंसात्मक विद्रोह यानी ख़ूनी बलवों और बगावत से ही हासिल हुई है।

पर सशस्त्र विद्रोह का हिन्दुस्तानी क्रोम के लिए कोई सवाल ही न था। हम निरस्त्र थे और हममें से ज्यादातर लोग हथियारों का इस्तेमाल करना भी नहीं जानते थे। इसके अलावा, हिंसात्मक संघर्ष या लड़ाई में ब्रिटिश सरकार या किसी भी राज्य की संगठित शक्ति उससे कहीं ज्यादा थी जितनी उसके खिलाफ खड़ी की गई कोई ताकत होती। फौजों में बलवा हो सकता था। पर निरस्त्र क्रोम बगावत नहीं कर सकती थी और न हथियारबन्द दलों और ताकतों का सामना कर सकती थी। दूसरी तरफ व्यक्तिगत आतंकवाद यानी कुछ अफसरों को बम या पिस्तौल से मार डालना एक दिवालिये का कार्यक्रम था। यह जनता को नैतिक दृष्टि से गिरानेवाला था और यह सोचना महज खामखयाली था कि यह एक जबरदस्त संगठित सरकार को हिला सकता है—फिर व्यक्तियों को वह चाहे कितना ही भयभीत क्यों न कर दे। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है, इस तरह व्यक्तिगत हिंसा रूसी क्रान्तिकारियों को भी छोड़ देनी पड़ी थी।

तब क्या वक़्त था ? रूस अपनी क्रान्ति में कामयाब हो चुका था और उसने मजदूरों का एक प्रजातंत्र कायम कर लिया था। उसका तरीका फौज की मदद से सर्वसाधारण की लड़ाई का तरीका था। पर रूस में भी सोवियटों को कामयाबी उस वक़्त हासिल हुई थी जब महायुद्ध के कारण देश और पुरानी सरकार तहस-नहस हो रही थी और मुत्तलालक़्त के लिए कुछ वक़्त न था। इसके अलावा उस ज़माने में हिन्दुस्तान में बहुत थोड़े लोग रूस या मार्क्सवाद के बारे में कुछ जानते या मजदूरों और किसानों के दृष्टिकोण से कुछ सोचते थे।

इसलिए इन सब तरीकों से हम कहीं न पहुँचते थे और इस बेइज्जती की गुलामी की असह्य हालत से निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता था। जो लोग भावुक थे वे बड़ी जबरदस्त बेचारगी और मायूसी महसूस करते थे। यह वक़्त था जब गांधीजी ने अपना असहयोग का कार्यक्रम पेश किया ! आयरलैंड के सिनफीन की तरह इसने हमें अपने पैरों खड़ा होना और अपनी ताकत का निर्माण करना सिखाया और जाहिर था कि सरकार पर दबाव डालने का यह एक बड़ा प्रभावशाली तरीका है। सरकार हिन्दुस्तानियों के सहयोग, फिर चाहे वह सहयोग अपनी इच्छा से हो या अनिच्छा से हो, पर ही ज्यादातर खड़ी थी और अगर वह सहयोग हटा लिया जाय और बायकाट पर अमल किया जाय तो सैद्धान्तिक दृष्टि से यह बिल्कुल मुमकिन था कि सरकार का सारा ढाँचा बैठ जाय। मगर असहयोग वहाँ तक न पहुँचे तो भी इसमें कोई शुबहा न था कि वह सरकार पर जबरदस्त दबाव डाल सकता और साथ-साथ जनता की ताकत बढ़ा सकता है। यह पूरे तौर पर शान्तिपूर्ण था। फिर भी यह सिर्फ़ एक अप्रतिरोध (Non-Resistance)

नहीं था। सत्याग्रह अन्याय या जुल्म के प्रतिरोध का एक निश्चित, यद्यपि अहिंसात्मक, तरीका था। असल में यह एक शान्तिपूर्ण बग़ावत थी, युद्ध-कला का एक सबसे सभ्य तरीका था, और फिर भी राज्य के लिए ख़तरनाक था। यह सर्व-साधारण के लिए अपनी ताक़त पहचानने और अपने अस्तित्व की रक्षा करने का एक प्रभावशाली रास्ता था और हिन्दुस्तानी जनता या क़ौम की विशेष प्रतिभा के अनुकूल था। यह हमारी स्थिति या बर्ताव को बहुत अच्छा रखता था और विरोधी या दुश्मन को ग़लती में डाल देता था। इसने हमारा वह भय दूर कर दिया था जो हमें कुचल रहा था और हम शासकों से इतनी निडरता से आँखें मिलाकर देखने लगे जैसा हमने कभी न देखा था और उनसे अपने दिल की बातें पूरे तौर पर और साफ़-साफ़ करने लगे। हमारे मन से एक बड़ा बोझ उठ गया और बोलने और काम करने की आशादी ने हमें आत्मविश्वास और शक्ति से भर दिया। फिर शान्तिपूर्ण तरीक़े के कारण वह भयंकर रूप से कटु जातीय और राष्ट्रीय घृणा काफी हद तक रुक गई जो ऐसी लड़ाइयों के साथ हमेशा पैदा होती और बढ़ती है, और इससे आख़री निबटारा आसान हो गया।

इसलिए इसने ताज़ुब की कोई बात नहीं कि असहयोग के इस कार्यक्रम ने, जिसके साथ गाँधीजी का महान् व्यक्तित्व था, देश की कल्पना को ही जगा दिया और उसे आशा से भर दिया। यह फैलता गया और इसके स्पर्श से पुरानी कमज़ोरियाँ दूर होगईं। नई काँग्रेस ने देश के ज्यादातर शक्तिमान तत्त्वों को अपनी तरफ खींच लिया और उसकी ताक़त और मर्यादा बढ़ गई।

इस दरमियान नये माण्डेगू-चेम्सफोर्ड सुधारों के मुताबिक़ नई कौंसिलें और असेम्बलियाँ बन चुकी थीं। माडरेटों ने, जो अब लिबरल नाम से पुकारे जाते हैं, उनका स्वागत किया था और उनमें मिनिस्टरी और दूसरे अधिकार के ओहदों को मंज़ूर कर लिया था। वे अमली तौर पर क़रीब-क़रीब सरकार में ही घुल-मिल गये थे और उनके पीछे जनता का बल न था। काँग्रेस ने इन कौंसिलों का वायकाट किया था, इसलिए देश में उनकी तरफ बहुत कम ध्यान दिया गया। सबकी आँखें बाहर गाँवों और शहरों में होनेवाली लड़ाई की तरफ लगी हुई थीं। पहलीवार बहुत बड़ी तादाद में काँग्रेस-कार्यकर्ता गाँवों में पहुँचे थे। वहाँ काँग्रेस कमेटियाँ कायम की थीं, और गाँव वालों की राजनैतिक जागृति में मदद कर रहे थे।

मामला तूल पकड़ गया था और लाज़िमी तौर पर दिसम्बर १९२१ में भिड़न्त होगई। यह मौक़ा प्रिंस ऑफ़ वेल्स के हिन्दुस्तान आने का था। इस आगमन का काँग्रेस ने वायकाट किया था। सारे हिन्दुस्तान में बहुत बड़ी तादाद में गिरफ्तारियाँ हुईं और

हजारों राजनैतिक कैदियों से जेलें भर गईं। हममें से ज्यादातर लोगों को जेल के अन्दर का पहला अनुभव उसी वक़्त हुआ। यहाँतक कि कांग्रेस के निर्वाचित अध्यक्ष देशबन्धु चित्तरंजन दास भी गिरफ्तार कर लिये गये और अहमदाबाद का कांग्रेस-अधिवेशन उनकी जगह हकीम अजमलखाँ की सदारत में हुआ। पर गाँधीजी उस वक़्त गिरफ्तार नहीं किये गये और आन्दोलन बढ़ता गया। उन लोगों की तादाद जो अपनेको गिरफ्तारी और जेल के लिए पेश कर रहे थे, उससे हमेशा ज्यादा रही जितने कि गिरफ्तार किये जाते थे। चूँकि मशहूर नेता और कार्यकर्ता जेल भेज दिये गये, इसलिए नये, अनुभव-हीन और कभी-कभी अवांछनीय आदमियों ने (यहाँतक कि 'खुफिया पुलिस के आदमियों ने भी!) उनका स्थान ग्रहण किया; इससे कुछ अव्यवस्था और हिंसा भी हुई। १९२२ के शुरू में, युक्तप्रान्त में गोरखपुर के नजदीक चौरी-चौरा में किसानों की एक भीड़ और पुलिस के बीच भिड़न्त होगई। किसानों ने पुलिस चौकी को, जिसके भीतर कुछ पुलिस सिपाही भी थे, जला दिया। बापू को इस और दूसरी चन्द घटनाओं से बहुत दुःख हुआ; क्योंकि इनसे मालूम होता था कि आन्दोलन हिंसात्मक होता जा रहा है। इसलिए, उनकी राय मानकर, कांग्रेस-कार्यसमिति ने असहयोग का क़ानून तोड़नेवाला कार्यक्रम स्थगित कर दिया। इसके थोड़े ही दिनों बाद खुद बापू भी गिरफ्तार कर लिये गये, उनपर मुकदमा चला और उन्हें ६ वर्ष की सज़ा दी गई। यों असहयोग-आन्दोलन की पहली अवस्था ख़त्म हुई।

: १६१ :

उन्नीस सौ बीस के बाद का भारत

१४ मई, १९३३

जब १९२२ ई० में सविनय अवज्ञा स्थगित कर दी गई तब असहयोग-आन्दोलन की पहली अवस्था ख़त्म हुई; पर, उसके स्थगित कर दिए जाने से, बहुत-से कांग्रेस-मैनों को बड़ा असन्तोष हुआ। बहुत बड़ी जागृति होगई थी और क़रीब-क़रीब तीस-हज़ार आदमी क़ानून तोड़ कर जेल गये थे। क्या इन सब बातों का कुछ विचार नहीं करना था और क्या आन्दोलन को एकाएक, बिल्कुल बीच में, उद्देश्य पूरा होने के पहले, सिर्फ इसलिए स्थगित कर देना था कि कुछ जोशीले किसानों ने चौरीचौरा में बुरा बर्ताव किया था? आन्दोलन का उद्देश्य ख़िलाफ़त और पंजाब के जुल्मों और अन्यायों को ठीक करवाना और स्वराज्य हासिल करना था। ख़िलाफ़त का सवाल तुर्की में होनेवाली घटनाओं और कमालपाशा की कारगुजारियों से अपने आप ख़त्म

होगया था। पंजाब का सवाल स्वराज्य के बड़े सवाल में मिल गया था; पर स्वराज्य अब भी बहुत दूर था। दिल्ली और मुहल्लिफ़ सूबों में खिलौने-सी कौंसिलें थीं, जिनका काँग्रेस ने बायकाट किया था। इन कौंसिलों के पास बहुत कम असली ताकत थी; उनके कुछ सदस्य सरकारी अधिकारी थे, कुछ सरकार के नामजद किये हुए थे, और चुने हुए सदस्य भी सीमित मताधिकार यानी थोड़े वोटर्स की राय से चुने गये थे। तब क्या किया जाता? उस वक्त गांधीजी भी जेल में थे।

काँग्रेस ने इस सवाल पर गौर करने के लिए 'सिविल डिसओबिडियंस इनक्वायरी कमेटी' यानी 'सविनय अवज्ञा जाँच समिति' नाम की एक कमेटी नियुक्त की। सारे हिन्दुस्तान का दौरा करने और लम्बे बहस-मुबाहसे के बाद कमेटी ने जो रिपोर्ट पेश की उसकी वजह से काँग्रेस एक-दूसरे का विरोध करनेवाले दो दलों में बँट गई। एक दल जिसे परिवर्तनवादी दल कहा जाता था, असहयोग के बायकाट वाले कार्यक्रम में तब्दीली करने का तरफ़दार था और चाहता था कि कौंसिलों का बायकाट उठा लिया जाय; यानी वे काँग्रेसवालों के नई असेम्बलियों और कौंसिलों में जाने के तरफ़दार थे। उनका कहना था कि काँग्रेसवालों को वहाँ सरकार से सहयोग करने के लिए नहीं बल्कि कौंसिलों के अन्दर से सरकार के काम में अड़ंगा डालने के लिए जाना चाहिए। दूसरा यानी अपरिवर्तनवादी दल इस तब्दीली के खिलाफ़ था। चूँकि शुरू में काँग्रेस में अपरिवर्तनवादियों का बहुमत था, इसलिए कौंसिलों पर कब्ज़ा करने के तरफ़दार दूसरे दल ने काँग्रेस के अन्दर दूसरी एक पार्टी कायम की। इसका नाम 'स्वराज्य दल' रक्खा गया और इसके मुख्य जन्म दाता देशबन्धु चित्तरंजन दास और दादू थे। समय पाकर इस दल का प्रभाव बढ़ गया और उसे काँग्रेस ने स्वीकार कर लिया।

इस स्वराज्य दल को १९२३ के चुनाव में काफ़ी कामयाबी हासिल हुई और सभी कौंसिलों में स्वराजी बड़ी तादाद में चुने गये। पर सरकारी और नामजद सदस्यों की भारी तादाद के कारण बहुत ही कम कौंसिलों में उनका स्पष्ट बहुमत हो सका। इसलिए उन्होंने कौंसिल के अन्दर अपने काम के लिए और दलों से दोस्ती करनी शुरू की। इसका मतलब उन दलों के साथ समझौता और राजनैतिक सौदा हुआ जो ज्यादा नरम थे और उतनी दूर तक जाने को तैयार न थे। इसका मतलब अरुचिकर समझौता और आदर्शों का झुकाना था। इसका मतलब उन स्वराजी सदस्यों का, जो कौंसिलों में गये थे, सर्वसाधारण जनता की आवाज से विछुड़ना भी था, क्योंकि वे अपनी नकली पार्लमेंटों के तौर-तरीकों और छोटी-मोटी चालों में ज्यादा फँसते गये। उन्होंने कुछ जोरदार प्रस्ताव पास किये और साल का वजट पास करने से इन्कार कर दिया। सरकार ने उनके प्रस्तावों की उपेक्षा की और वाइसराय ने

वजट को सर्वोपाय यानी मंजूर कर लिया। ताकत प्रस्तावों और वोटों का विषय नहीं थी, वह दूसरी बातों पर आश्रित थी। स्वराजी प्रस्तावों ने बड़ी हलचल पैदा की; पर यह जाहिर होगया कि उन पर जोर डालने या उन्हें पास कराने के लिए कुछ और भी करना पड़ेगा।

१९२० के बाद के जमाने में हिन्दुस्तान को जो सुखलक्षित ताकतें और आन्दोलन हिला रहे थे, उन्हें समझने की हमें कोशिश करनी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल हिन्दू-मुस्लिम सवाल था। तनातनी बढ़ रही थी और उत्तरी हिन्दुस्तान में मस्जिदों के आगे बाजा बजाने के हक जैसे छोटे सवालों पर कई जगह दंगे हो चुके थे। असह-योग के जमाने की उस दर्शनीय एकता के बाद यह एक अजीब और आकस्मिक परिवर्तन था। यह कैसे होगया और उस एकता का आधार क्या था?

राष्ट्रीय आन्दोलन का आधार मुख्यतः आर्थिक मुसीबत और बेकारी था। इसकी वजह से सभी वर्गों में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक सामान्य भावना और स्वराज्य की स्पष्ट इच्छा पैदा होगई थी। यह विरोधी भाव ही जुदा-जुदा वर्गों के बीच एक मिलानेवाली कड़ी था। इसलिए सबने मिलकर आन्दोलन किया। पर इन विविध वर्गों का उद्देश्य अलग-अलग था। हर जमात के लिए स्वराज्य का एक जुदा अर्थ था—बेकार मध्यम वर्ग नौकरी या धन्धा चाहता था, किसान जमींदार द्वारा थोपे हुए अपने अनेक बोझों से राहत चाहता था, इसी तरह अलग-अलग जमातें अलग-अलग बातें चाहती थीं। मुसलमान इन सवालों पर एक मजहबी जमात की नजर से देखते हुए शामिल हुए थे। खास तौर पर खिलाफत के लिए उनकी जमात-की-जमात आन्दोलन में आ गई थी। यह एक शुद्ध मजहबी सवाल था, जिससे सिर्फ मुसलमानों पर असर पड़ता था। जो मुसलमान नहीं थे उनका इससे कुछ मतलब न था। पर बापू ने इसको ग्रहण किया और दूसरों को भी इसके ग्रहण करने को उत्साहित किया, क्योंकि वह मुसीबत में पड़े भाई की मदद करना अपना फर्ज समझते थे। इससे उन्होंने हिन्दू-मुसलमानों को नजदीक लाने की भी उम्मीद की थी। इस तरह आम तौर पर मुसलमानों का दृष्टिकोण मुस्लिम राष्ट्रीयता या मुस्लिम अन्तर्राष्ट्रीयता का दृष्टिकोण था, सच्ची राष्ट्रीयता का नहीं। हाँ, उस वक्त इन दोनों तरह की राष्ट्रीयताओं के बीच की कशमकश जाहिर नहीं थी।

दूसरी तरफ़ राष्ट्रीयता की हिन्दू धारणा निश्चितरूप से हिन्दू राष्ट्रीयता की भावना थी। इस मामले में हिन्दू राष्ट्रीयता और सच्ची राष्ट्रीयता के बीच ठीक-ठीक रेखा खींचना आसान नहीं था। दोनों एक-दूसरे से घुल-मिल गई थीं, क्योंकि सिर्फ हिन्दुस्तान ही हिन्दुओं का एक देश है और यहाँ उनका बहुमत है। इसलिए हिन्दुओं

के लिए मुसलमानों की बनिस्वत पूर्ण राष्ट्रवादी की शक्ल में जाहिर होना ज्यादा मुमकिन था, हालांकि हरेक अपनी खास तरह की राष्ट्रीयता का हामी था ।

तीसरे वह चीज थी जिसे सच्ची या भारतीय राष्ट्रीयता कहा जा सकता है और जो ऊपर बताई हुई दोनों मजहबी और साम्प्रदायिक राष्ट्रीयताओं से बिल्कुल एक जुदा चीज थी । यह उस तरह की राष्ट्रीयता थी जो पश्चिमी देशों में दिखाई पड़ती है और ठीक-ठीक कहें तो यही एक रूप है जिसे आजकल के अर्थ में राष्ट्रीयता कहा जा सकता है । इस तीसरी जमात में हिन्दू, मुसलमान और दूसरे लोग भी थे । १९२० से १९२२ तक, असहयोग आन्दोलन के जमाने में ये तीनों जमातें या तीनों तरह की राष्ट्रीयताएँ एकसाथ मिल गई थीं । तीनों रास्ते अलग-अलग थे, पर थोड़ी देर के लिए समानान्तर दौड़ रहे थे ।

१९२१ के सामूहिक आन्दोलन से ब्रिटिश सरकार हैरत में आ गई । उसे इसका नोटिस काफ़ी पहले मिल चुका था, पर वह यह नहीं सोच सकी कि इसके साथ क्या सलूक करना चाहिए या इसे कैसे सम्हालना चाहिए । उसने देखा कि वह अपनी गिरफ्तारी और सजा के पुराने सीधे तरीक़े से इसे दबा नहीं सकती, क्योंकि कांग्रेस खुद यही बात (गिरफ्तारी या सजा) चाहती थी । इसलिए उसके खुफिया विभाग ने अन्दर से कांग्रेस को कमजोर करने का तरीक़ा निकाला । पुलिस एजेण्ट और खुफिया विभाग के आदमी कांग्रेस कमेटियों में पहुँचे और झगड़ा पैदा कर दिया । उन्होंने हिंसा को उत्तेजना दी, जिससे असहयोग के शान्तिपूर्ण उपायों में बाधा पड़ी और अव्यवस्था पैदा होगई । इस विचित्र तरह की शान्तिपूर्ण लड़ाई और हिंसा को साथ-साथ चलाना साफ़-साफ़ नामुमकिन था । हरेक दूसरे में दखल डालती थी या दूसरे के काम में दिक्कत पैदा करती थी । सरकारी अधिकारियों और खुफिया विभाग का दूसरा तरीक़ा यह था कि वे साधुओं और फ़कीरों के वेश में अपने खुफिया एजेण्टों को साम्प्रदायिक झगड़े और दंगे खड़े करने को भेजते थे ।

ऐसे उपाय सदा ही उन सरकारों द्वारा किये जाते हैं जो जनता की स्वीकृति के बग़ैर ज़बरदस्ती उसपर हुकूमत करती हैं । साम्राज्यवादी सरकारों का कार-वार उन्हींके भरोसे चलता है । ऐसे उपायों को कामयाबी हासिल होती है, इससे जनता को कमजोरी और पिछड़े होने का ही ज्यादा सबूत मिलता है, सरकार की गुनहगारी का उतना नहीं । दूसरे देश की जनता में भेद पैदा कर देना और उन्हें एक-दूसरे से लड़ाकर और यों कमजोर करके उनका शोषण करना खुद ही यड़प्पन और श्रेष्ठतर या बेहतर संगठन की निशानी है । यह नीति तभी कामयाब हो सकती है जब दूसरे पक्ष में फूट और झगड़े हों । यह कहना कि ब्रिटिश सरकार ने

हिन्दुस्तान में हिन्दू-मुस्लिम सवाल पैदा किया, साफ़तीर पर झूठ होगा; पर उसने इसे कायम रखने या दोनों जातियों के मेल को अनुत्साहित करने की जो लगातार कोशिश की है, उसकी उपेक्षा करना भी ग़लत होगा।

असहयोग-आन्दोलन के स्थगित कर दिये जाने के बाद, १९२२ ई० में, ऐसी साजिशों के लिए ज़मीन अनुकूल थी। एक सख़्त लड़ाई के बाद, जो बिना किसी नतीजे के एकाएक ख़त्म हो गई, उसकी प्रतिक्रिया हो रही थी। तब वे मुदतलिफ़ सड़कें, जो एक-दूसरे के समानान्तर चल रही थीं, एक-दूसरे से दूर होने और भिन्न दिशाओं में जाने लगीं। ख़िलाफ़त का सवाल अब था ही नहीं। हिन्दू और मुसलमान साम्प्रदायिक नेता, जो असहयोग के ज़माने में जनता के सामूहिक उत्साह से दब गये थे, अब मौक़ा देखकर फिर उठ खड़े हुए और सार्वजनिक जीवन में हिस्सा लेने लगे। मध्यमवर्ग के बेकार मुसलमानों ने महसूस किया कि हिन्दुओं ने सब नौकरियों पर क़ब्ज़ा जमा रक्खा है और हमारे रास्ते में कांटें हैं। इसलिए उन्होंने अपने बारे में जुदा बर्ताव करने और हर चीज़ में अलग हिस्सा दिये जाने की माँग की। राजनैतिक दृष्टि से हिन्दू-मुस्लिम सवाल में नौकरियों का झगड़ा और मध्यम श्रेणी का सवाल था। पर इसका असर सर्वसाधारण पर पड़ा।

सब मिलाकर हिन्दू कुछ अच्छी हालत में थे। अंग्रेज़ी तालीम को जल्दी इस्तिफ़ार करने की वजह से ज्यादातर सरकारी ओहदों और कामों पर वही नियुक्त हुए। वे मुसलमानों की बनिस्वत मालदार भी थे। गाँव का बैंकर या साहूकार बनिया था जो छोटे ज़मींदारों और काश्तकारों का शोषण करता था और धीरे-धीरे उन्हें बिल्कुल बेहाल या भिखमंगा कर देता था और तब खुद उनकी ज़मीन पर क़ब्ज़ा कर लेता था। बनिया हिन्दू और मुसलमान काश्तकारों और ज़मीन वालों में कोई भेद नहीं करता और उनका एक-सा ही शोषण करता है, पर उसके मुसलमानों के शोषण ने, ख़ासकर उन सूबों में जिनमें किसान ज्यादातर मुसलमान थे, साम्प्रदायिक खूब इस्तिफ़ार किया। मशीन की बनी चीज़ों ने संभवतः हिन्दुओं की बनिस्वत मुसलमानों पर ज्यादा चोट की, क्योंकि मुसलमानों में कारीगर ज्यादा थे। इन सब बातों ने हिन्दुस्तान की दोनों बड़ी जातियों में कटुता बढ़ाने और उस मुस्लिम राष्ट्रीयता को मजबूत बनाने में मदद की जो देश की बनिस्वत जाति की तरफ़ देखती थी।

साम्प्रदायिक नेताओं की माँगें ऐसी थीं कि सच्ची राष्ट्रीय एकता की सारी उम्मीदों की जड़ पर चोट करती थीं। उन्हींके साम्प्रदायिक तरीक़े पर उनका मुक़ाबिला करने के लिए हिन्दू साम्प्रदायिक संस्था सामने आईं। यद्यपि वे अपनेको सच्चे राष्ट्रवादी—नेशनलिस्ट—कहते थे, पर दरअसल वे उतने ही संकीर्ण और साम्प्रदायिक

ये जितने कि दूसरे । उनकी राष्ट्रीयता हिन्दू छाप की थी । कुछ हद तक मालिक या खुशहाल (Haves) होने के कारण उन्होंने 'सर्वहारा' या साधनहीन (Have-nots) लोगों के साथ अपनी चीजों की शिरकत यानी बँटवारा करना नापसन्द किया । इसमें शक नहीं कि असल में मालदारों (Haves) की तो एक तीसरी ही पार्टी थी और वह शासक शक्ति यानी हुकूमत करनेवाली ताक़त थी । वह टुकड़ों पर की इस लड़ाई का मज़ा लेती और फ़ायदा उठाती थी और असली खाना उसीके हाथ रहता था । संस्था की हैसियत से और सामूहिकरूप में कांग्रेस साम्प्रदायिक संस्थाओं से अलग रही, पर कांग्रेसमैनों में से बहुतों को उनकी छूत लग गई । असली राष्ट्रवादियों—नेशनलिस्टों—ने इस साम्प्रदायिक पागलपन को रोकने की कोशिश की, पर उनको बहुत कम कामयाबी हुई और बड़े-बड़े दंगे हुए ।

इस अंधाधुंधी को बढ़ाने के लिए एक तीसरी तरह की वर्गीय राष्ट्रीयता या फिरक़ेवाराना क़ोमियत उठ खड़ी हुई । यह सिक्ख राष्ट्रीयता थी । गुजरे हुए ज़माने में सिक्खों और हिन्दुओं के बीच का फ़र्क़ बहुत धुंधला था । राष्ट्रीय जागृति ने जानदार सिक्खों को हिला दिया और वे अपनी एक खास और जुदा हस्तीके लिए कोशिश करने लगे । उनमें एक बहुत बड़ी तादाद भूतपूर्व सिपाहियों की थी और इन लोगों ने एक छोटी पर बहुत अच्छी तरह संगठित जाति को, जो हिन्दुस्तान की ज्यादातर जमातों की तरह बातूनी न थी बल्कि क्रियाशील थी, कटोर बना दिया । उनमें से ज्यादातर पंजाब में अपनी ज़मीन के मालिक किसान (जमींदार) थे और क़स्बों के बैंकरों और शहरी स्वार्थों की वजह से उनपर मुसीबत आती थी । अलग वर्ग की सूरत में स्वीकार किये जाने की उनकी माँग के पीछे असली उद्देश्य यह था । शुरू में 'अकाली' आन्दोलन ने मजहबी सवालों या गुस्ठारों की जायदाद पर क़ब्ज़ा करने में दिलचस्पी लेनी शुरू की । अकाली-आन्दोलन नाम इसलिए पड़ा कि सिक्खों में अकाली सबसे क्रियाशील और जोरदार थे । इस सवाल पर सरकार से उनकी भिड़न्त होगई और अमृतसर के नजदीक 'गुरु-का-वाग़' में उन्होंने साहस और सहनशीलता का अद्भुत दृश्य उपस्थित किया । पुलिस ने अकाली जत्थों को बड़ी बुरी तरह मारा, पर उन्होंने एक क्रदम पीछे न हटाया और न पुलिस पर हाथ चलाया । आख़िरकार अकालियों की विजय हुई और गुस्ठारों और मठों पर उनका क़ब्ज़ा होगया । तब वे राजनैतिक क्षेत्र में आये और अपने लिए बड़ी-बड़ी माँगें करने में दूसरे साम्प्रदायिक वर्गों से होड़ करने लगे ।

मुस्लिफ़ जातियों या, जैसा मैंने कहा है, जातीय या वर्गीय राष्ट्रीयताओं की ये संकुचित साम्प्रदायिक भावनाएँ बड़ी दुःखद मालूम पड़ती थीं और सचमुच ही बेसी

थीं। फिर भी वे काफ़ी स्वाभाविक थीं। असहयोग ने हिन्दुस्तान को पूरी तरह से हिला दिया था और इन जातियों या वर्गों की जागृति और हिन्दू, मुसलमान और सिख राष्ट्रीयतायें उसका पहला नतीजा थीं। और भी बहुत-सी छोटी-जमातें थीं जिनमें चेतना पैदा हुई। इनमें 'दलितवर्ग' नाम से पुकारे जानेवाले लोग भी थे। ये लोग एक जमाने से ऊँचे दर्जे के हिन्दुओं के जरिये दबा दिये गये थे और ज्यादातर खेतों में काम करनेवाले बेजमीन मजदूर थे। यह स्वाभाविक था कि जब उनमें चेतना आई तब अपनी बहुतेरी बाधाओं या असमर्थताओं से छुटकारा पाने की ज़बरदस्त इच्छा भी उनमें पैदा हुई और उन हिन्दुओं के प्रति कटुतापूर्ण क्रोध उनमें भर गया जिन्होंने सदियों से उनको दबा रखा था।

हरेक जागृतवर्ग राष्ट्रीयता और देश-भक्ति की तरफ़ अपने ही स्वार्थों की रोशनी में देखता था। एक वर्ग या जाति हमेशा खुदगर्ज होती है, जैसे एक राष्ट्र भी स्वार्थी होता है, यद्यपि जाति या क़ौम में व्यक्ति निःस्वार्थ दृष्टिकोण रख सकते हैं। इस तरह हर वर्ग अपने हिस्से से बहुत ज्यादा चाहता था और संघर्ष का होना लाज़िमी था। एक रुपये को पच्चीस या तीस आनों में तक़सीम करना मुमकिन नहीं है। ज्यों-ज्यों अन्तर्साम्प्रदायिक कटुता बढ़ी, हर वर्ग के ज्यादा जोशीले साम्प्रदायिक नेता आगे आते गये, क्योंकि गुस्से के वक़्त हरेक वर्ग अपना प्रतिनिधि उसी आदमी को चुनता है जो अपने वर्ग की मांगों को सबसे आगे और ऊँची रखता है और दूसरे वर्गों को सबसे ज्यादा गाली दे सकता है। इससे मामला और ख़राब होजाता है। सरकार ने इस कशमकश को बहुत-से तरीक़ों से, खास तौरपर उग्र साम्प्रदायिक नेताओं को उत्साहित करके, बढ़ाया। इस तरह ज़हर फैलता गया और हम ऐसे शैतानी घेरे में फँस गये जिससे निकलने का कोई रास्ता दिखाई न देता था। इसे हिन्दुस्तान में अल्पमत का सवाल कहा जाता था और यह स्वराज्य के लिए एक ज़बरदस्त बाड़ होगया था।

जब ये शक्तियाँ और विनाशक प्रवृत्तियाँ हिन्दुस्तान में बढ़ रही थीं, गाँधीजी घरबड़ा-जेल में बड़े जोर से बीमार पड़ गये और अपेंडिसाइटिज़ के लिए उनका आपरेशन हुआ। १९२४ के शुरू में वह जेल से छोड़ दिये गये। साम्प्रदायिक झगड़ों से वह बड़े दुखी थे और कई महीनों बाद होनेवाले एक दंगे से उनको इतना धक्का लगा कि उन्होंने इक्कीस दिन का अनशन किया। तुम उनके इस अनशन के वक़्त दिल्ली में मौजूद थीं और शायद तुम्हें उसकी याद होगी। शान्ति क़ायम करने के लिए कई एकता-सम्मेलन हुए, पर उनका कोई खास नतीजा न निकला।

इन साम्प्रदायिक झगड़ों और वर्गीय या जातीय राष्ट्रीयताओं का असर यह हुआ कि कांग्रेस और कौंसिलों की स्वराजपार्टी दोनों कमज़ोर होगईं। स्वराज्य का

आदर्श अँधेरे में पड़ गया, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने-अपने वर्ग की भाषा में सोचते और बोलते थे। चूँकि कांग्रेस किसी भी वर्ग की तरफ़दारी करने से अपनेको बचा रही थी, इसलिए उसपर सम्प्रदायवादियों द्वारा हर तरफ़ से हमला हो रहा था। यहाँ-तक कि अखीर में कांग्रेस के कितने ही मशहूर कार्यकर्ता भी साम्प्रदायिक राजनीति में फँस गये। इन दिनों कांग्रेस का खास कार्यक्रम शान्ति के साथ संगठन करना और खादी का था और इसने उसे किसान जनता के सम्पर्क में रक्खा।

असेम्बली और कौंसिलों के स्वराजी या कांग्रेस दल और भी ज्यादा गिर गये। क्योंकि आम जनता का जीवनदायी स्पर्श उनसे छूट गया था। साम्प्रदायिक झगड़े ने उन्हें कमजोर कर दिया, पर कौंसिलों के सदस्यों के सामने सरकार जो बहुत तरह के प्रलोभन बराबर रख रही थी वे उनके लिए इससे भी ज्यादा खतरनाक साबित हुए। उनके सामने न सिर्फ़ मिनिस्टरी और ओहदे थे, बल्कि बेशुमार कमेटियों और कमीशनों की मेम्बरी और सरकारी खर्चों से कभी-कभी योरप की सैर कर आने का प्रलोभन भी था। कांग्रेस ने मिनिस्टरी और दूसरे पदों का बायकाट किया था और वह आखीर तक इस नीति पर डटी रही। पर दूसरे मामलों में इसमें भी कमजोरी आगई और एक क़दम के बाद दूसरा क़दम बढ़ता गया। कौंसिलों के बहुत-से कांग्रेसी सदस्यों ने अपनी स्थिति का, जिसे उन्होंने कांग्रेस की मदद के जरिये हासिल किया था, अपने निजी फ़ायदे के लिए नाजायज़ इस्तेमाल किया। कुछ ने, योरप के मजदूर नेताओं की तरह, उन ऊँचे सरकारी ओहदों तक पहुँचने के लिए इससे सीढ़ी का काम लिया जहाँ से वे कांग्रेस-आन्दोलन को कुचलने में सरकार की मदद करते!

राबर्ट ब्राउनिंग की 'खोया हुआ नेता' (The Lost Leader) नाम की एक छोटी-सी भावपूर्ण कविता है, उसमें से चन्द लाइनें में यहाँ दूँगा :—

Just for a handful of silver he left us,
 Just for a riband to stick in his coat—
 Found the one gift of which fortune bereft us,
 Lost all the others she lets us devote;
 They, with the gold to give, doled him out silver,
 So much was theirs who so little allowed :
 How all our copper had gone for his service !

अर्थात् —“सिर्फ़ चाँदी के चन्द टुकड़ों के लिए उसने हमें छोड़ दिया—
 वस अपने कोट पर (उपाधि या तमगो का) एक फ़ीता लगाने के लिए। उसने सिर्फ़ एक चीज़ पाई, जिससे किस्मत ने हमें महकूम रक्खा था, और उन सबको खो दिया जो उसने (किस्मत ने) हमें उसे अर्पित करने को दी थीं। जिनके पास देने के लिए सोना था उन्होंने उसे चाँदी के टुकड़े दिये; उनके पास बहुत था, पर इतना थोड़ा

दिया। उसकी सेवा के लिए किस तरह सारा ताँवा—सारे पैसे—हमने दे दिया था !”

ऊपर मैंने अपनी साम्प्रदायिक मुसीबतों के बारे में तुमको ज़रा विस्तार से लिखा है, क्योंकि १९२० के बाद की हमारी राजनैतिक जिन्दगी में उनका महत्वपूर्ण भाग रहा है। फिर भी हमें उनके बारे में अतिशयोक्ति या ज्यादा बढ़ाकर बात नहीं करनी चाहिए। आजकल उनको उससे ज्यादा महत्व देने की प्रवृत्ति दिखाई देती है जितना कि देना चाहिए और एक मुसलमान लड़के और हिन्दू लड़के में होनेवाला हरेक झगड़ा साम्प्रदायिक समझ लिया जाता है और हरेक छोटे दंगे का बड़ा प्रचार किया जाता है। हमें याद रखना चाहिए कि हिन्दुस्तान एक बहुत बड़ा देश है और हजारों कस्बों और गांवों में हिन्दू-मुसलमान एक-दूसरे के साथ बड़ी शान्तिपूर्वक रहते हैं और उनके बीच कोई साम्प्रदायिक झगड़ा नहीं है। आमतौर पर इस तरह के झगड़े थोड़े-से शहरों में ही होते हैं, यद्यपि कभी-कभी वे गांवों में भी फैल जाते हैं। यह भी याद रखना चाहिए कि हिन्दुस्तान में साम्प्रदायिक सवाल असल में मध्यम श्रेणी का सवाल है, और चूंकि हमारी राजनीति पर मध्यम वर्ग—कांग्रेस में, कौंसिलों में, अखबारों में, और दूसरे सब तरह के कामों में—हावी है, इसलिए इसको ज्यादा और अनुचित महत्व मिल जाता है। किसान बोलना—अपने को व्यक्त या बाहिर करना—नहीं जानते, अभी हाल के चन्द सालों से ही वे गांवों की कांग्रेस कमेटियों और किसान-सभाओं और इस तरह की दूसरी संस्थाओं में हिस्सा लेने लगे हैं और यों उनकी राजनैतिक हस्ती शुरू ही हुई है। शहरों के, खास तौर पर बड़े-बड़े कारखानों के, मजदूर ज्यादा जागृत हैं और उन्होंने मजदूर-संघ की शक्ल में अपना संगठन भी कर लिया है। पर कारखानों के ये मजदूर, और उनसे भी ज्यादा किसान, मध्यम श्रेणी से आये हुए व्यक्तियों की तरफ ही अपने नेतृत्व और पथ-प्रदर्शन के लिए देखते हैं। अब हमें यह देखना है कि उस जमाने में सर्वसाधारण जनता, किसानों और कारखानों के मजदूरों की क्या हालत थी।

महायुद्ध के कारण भारतीय उद्योगों में जो तेज़ी की तरक्की हुई थी वह शान्ति के बाद भी कुछ वर्षों तक जारी रही। हिन्दुस्तान में ब्रिटिश पूंजी भरने लगी और नये कारखानों और उद्योगों को चलाने के लिए बहुत-सी नई कम्पनियों की रजिस्ट्री हुई। खास तौर पर बड़ी औद्योगिक पेढ़ियों और कारखानों में विदेशी पूंजी लगी थी। इस तरह बड़े उद्योगों पर अमली तौर पर ब्रिटिश पूंजीवादियों का नियंत्रण कायम हो गया था। कुछ साल हुए तब अन्दाज़ लगाया गया था कि हिन्दुस्तान में व्यवसाय करने-वाली कम्पनियों की ८७ प्रतिशत पूंजी ब्रिटिश थी, और संभवतः यह अन्दाज़ भी कम ही है। इस तरह हिन्दुस्तान पर ब्रिटेन का वास्तविक आर्थिक प्रभुत्व या नियंत्रण

बढ़ गया। बड़े-बड़े शहर गाँवों के बल पर नहीं, छोटे शहरों के बल पर, यानी उनकी हानि करके, खड़े हो गये। कपड़े का उद्योग खास तौर पर बढ़ गया और इसी तरह खाने-पीने की चीजों के दामों में भी बढ़ती हुई।

बढ़ते हुए औद्योगीकरण यानी बड़े-बड़े कल-कारखाने की बढ़ती के नये सवालों पर गौर करने के लिए सरकार ने बहुतेरी कमेटियाँ और कमीशन बैठाये। इन कमेटियों और कमीशनों ने सिफ़ारिश की कि विदेशी पूंजी को उत्साहित करना चाहिए। इन्होंने आम तौर पर हिन्दुस्तान में ब्रिटिश औद्योगिक स्वार्थों के प्रति पक्षपात किया। हिन्दुस्तानी उद्योगों की रक्षा के लिए एक टैरिफ़ बोर्ड बनाया गया। पर, जैसा कि मैंने कहा है, इस संरक्षण का मतलब बहुत-से मामलों में हिन्दुस्तान में लगी हुई ब्रिटिश पूंजी का संरक्षण है। इन संरक्षित चीजों का दाम स्वभावतः बाज़ार में बढ़ गया, क्योंकि उनको चुंगी (Duty) देनी पड़ती थी और इससे उस हद तक गुजर-बसर का खर्च बढ़ गया। इस तरह संरक्षण का बोझ असल में सर्वसाधारण जनता या इन चीजों के खरीदारों पर पड़ा और कारखानेदारों को एक संरक्षित बाज़ार मिल गया जिससे प्रतिद्वन्द्विता हटाली गई थी या कम हो गई थी।

कारखानों के बढ़ने से, कुदरती तौर पर, उद्योग-धंधों से मजदूरी कमानेवाले लोगों की तादाद भी बढ़ी। बहुत पहले, १९२२ में, सरकार के अन्दाज से हिन्दुस्तान में इस वर्ग में दो करोड़ आदमी थे। गाँवों के आदमी, जिनके पास ज़मीन नहीं थी और जो बेकार थे, इस वर्ग में शामिल होने के लिए खिंचते गये और उनको शोषण की शर्मनाक हालत को बरदाश्त करना पड़ा। सौ वर्ष पहले, बड़े कारखानों की प्रणाली की शुरुआत के ज़माने में, इंग्लैण्ड में जो हालत थी, वही अब हिन्दुस्तान में थी—रोज़ाना काम का भयंकर लम्बा वक्त, दुःखदाई मजदूरी की दर, नीचे गिराने और तन्दुरुस्ती को नुकसान पहुँचानेवाली जीवन-प्रणाली। कारखानेदारों के वर्ग की निगाह सिर्फ़ एक ही बात पर थी और वह यह कि इस खुशहाली के ज़माने में ज्यादा-से-ज्यादा मुनाफ़ा उठाकर दौलत जमा करली जाय। कुछ साल तक उन्हें इस काम में खूब कामयाबी भी हुई। वे बड़ा ऊँचा मुनाफ़ा उठाते रहे; उधर मजदूरों की हालत वैसी ही ख़राब बनी रही। मजदूरों को इन ऊँचे मुनाफ़ों में, जिन्हें उन्होंने पैदा किया था, कोई हिस्सा न मिलता था; पर बाद में जब खुशहाली और चढ़ती के ज़माने के बाद मन्दो आई और व्यापार ढीला पड़ गया, तब मजदूरों से मजदूरी कम करके इस बदकिस्मती और घाटे में हिस्सा लेने को कहा गया, क्योंकि मजदूरी में कटौती हुए बिना धंधे और उद्योग को मुनाफ़े पर नहीं चलाया जा सकता था और मालिकों के मुनाफ़ा उठाये बिना कोई उद्योग कैसे चल सकता था ?

ज्यों-ज्यों मजदूरों के संगठन यानी मजदूर-संघ बढे, मजूरी की अच्छी हालतों, काम के कम घण्टों और ज्यादा मजदूरी की मांगें भी उनके साथ बढीं। कुछ इससे और कुछ सारी दुनिया की इस मांग के कारण कि मजदूरों के साथ अच्छा सलूक किया जाना चाहिए, सरकार ने कारखाने के मजदूरों की हालत सुधारने के लिए बहुत-से क़ानून पास किये। मैं किसी पिछले ख़त में तुमको फ़ैक्टरी क़ानून के पास होने की बात बता चुका हूँ। इस क़ानून में यह तजवीज़ रखी गई कि १२ से १५ वर्ष तक के लड़के एक दिन में ६ घण्टे से ज्यादा काम न करें। इसी तरह से स्त्रियों और लड़कों के लिए रात को काम करने की भी मनाई थी। वालिग मर्दों और स्त्रियों के लिए ज्यादा-से-ज्यादा ग्यारह घण्टे का दिन या ६० घण्टे का सप्ताह (एक काम का हफ़्ता जो ६ दिनों का होता है) की तजवीज़ थी। वाद की थोड़ी-बहुत तब्दीलियों के साथ यह फ़ैक्टरी क़ानून अभी तक जारी है।

उन दुखिया मजदूरों के संरक्षण के लिए जो खानों में, खास तौर पर कोयले की खानों में, ज़मीन के नीचे काम करते हैं, १९२३ में एक इंडियन माइंस ऐक्ट या 'हिन्दुस्तानी खान क़ानून' पास हुआ। १३ वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ज़मीन के नीचे काम करने की मनाई करदी गई, पर स्त्रियाँ काम करती रहीं—यहाँ तक कि कुल मजूरों में आधी स्त्रियाँ ही थीं। वालिग लोगों के लिए ६ दिन के हफ़्ते का ज्यादा-से-ज्यादा काम यों निश्चित किया गया था—ज़मीन के ऊपर ६० घण्टे और ज़मीन के नीचे काम करने के लिए ५४ घण्टे। मैं समझता हूँ कि एक दिन काम लेने का ज्यादा-से-ज्यादा समय १२ घण्टे है। मैं काम के इन घण्टों की चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि तुमको मजदूरों की हालत का कुछ इल्म होजाय। इसकी मदद से भी तुम्हें उन की हालत का बहुत थोड़ा ही इल्म हो सकता है, क्योंकि उनके बारे में ठीक और पूरे तौर पर विचार बनाने के पहले तुम्हें इसके अलावा मजदूरी की दर, रहन-सहन की हालत वगैरा की जानकारी भी होनी चाहिए। यहाँ हम इन बातों में नहीं जा सकते, पर यह महसूस करने की बात है कि किस तरह लड़कों और लड़कियों, स्त्री और पुरुषों को महज़ थोड़ी मजदूरी के लिए, जो किसी तरह सिर्फ़ उनको ज़िन्दा रखती है, इन कारख़ानों में ग्यारह-ग्यारह घण्टे रोज़ काम करना पड़ता है। कारख़ानों में जिस तरह का मनहूस और उबा देनेवाला काम वे करते हैं वह भयंकर रूप से थका देनेवाला या दिल को गिरा देने वाला होता है। उसमें कोई आनन्द नहीं और जब वे बिल्कुल थके हुए चूर-चूर होकर घर जाते हैं तो सारे कुटुम्ब को छोटी कोठरी, बल्कि माँद में, सफ़ाई और टूटी-पेशाब की सहूलियतों वगैर रहना पड़ता है।

कुछ और भी क़ानून पास हुए, जिनसे मजदूरों को कुछ मदद मिली। १९२३ में

वर्कमेन्स कम्पेनसेशन ऐक्ट (मजदूरों के मुआवजे का क़ानून) पास हुआ, जिसमें दुर्घटनाओं के कारण मजदूर को कुछ मुआवज़ा देने की तज़वीज़ की गई। १९२६ में एक 'ट्रेड यूनियन ऐक्ट' भी पास हुआ जिसमें मजदूर-संघ बनाने और उसकी स्वीकृति के नियम थे। इन दिनों हिन्दुस्तान, और खासकर बम्बई में मजदूर-संघ (ट्रेड यूनियन) आन्दोलन तेज़ी से बढ़ा। एक 'आल इंडिया ट्रेड यूनियन काँग्रेस' बनाई गई, पर चन्द सालों के बाद वह दो टुकड़ों में बँट गई। महायुद्ध और रूसी क्रांति के ज़माने से, सारी दुनिया के मजदूर दो दलों में बँट रहे थे और दो मुख्तलिफ़ दिशाओं में जा रहे थे। पुराने कट्टर और माडरेट मजदूर संघ द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय संघ (सेकेण्ड इंटरनेशनल, जिसके बारे में मैं पहले तुम्हें बता चुका हूँ) में शामिल थे। दूसरी तरफ नया और जोरदार आकर्षण सोवियट रूस और तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय संघ यानी 'थर्ड इंटरनेशनल' का है। इससे हर जगह माडरेट और कारख़ानों के ज़रा अच्छी हालत वाले मजदूर सुरक्षितता और 'सेकण्ड इंटरनेशनल' की तरफ देखते हैं और जो ज्यादा क्रान्तिकारी हैं वे 'थर्ड इंटरनेशनल' की तरफ देखते हैं। यह खिंचावट या रस्साकशी हिन्दुस्तान में भी हुई और १९२९ ई० के अख़ीर में अलगाव होगया। तबसे हिन्दुस्तान में मजदूर-आन्दोलन कमजोर पड़ गया। इन दोनों दलों को एक में मिलाने की कई बार कोशिशें हुई, पर अभीतक उनमें कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई है।

किसानों के बारे में मैं उससे कुछ बहुत ज्यादा यहाँ नहीं बता सकता, जितना पिछले ख़तों में लिख चुका हूँ। उनकी हालत ख़राब होती जाती है और वे साहूकार (ऋणदाता) के कर्ज़ से दिन-दिन ज्यादा दबते जाते हैं। छोटे ज़मींदार, वे किसान जो अपनी ज़मीन के खुद मालिक हैं, और काश्तकार सब रुपया कर्ज़ देनेवाले बनिये और साहूकार के जाल में फँसते जाते हैं। चूँकि कर्ज़ अदा करना नामुमकिन है, इसलिए धीरे-धीरे ज़मीन इस ऋण देनेवाले यानी बनिये या साहूकार के हाथ में चली जाती है और काश्तकार उसका दोहरा गुलाम होजाता है, क्योंकि वही (बनिया) अब उसका ज़मींदार और साहूकार दोनों होजाता है। आम तौर पर यह बनिया ज़मींदार शहर में रहता है और उसके और उसके काश्तकारों के बीच कोई सीधे या गहरे ताल्लुकात नहीं होते। उसकी तो सदा यह कोशिश होती है कि भूखों मरते हुए किसानों से ज्यादा-से-ज्यादा जितना रुपया मिल सके वसूल किया जाय। पुराना ज़मींदार खुद किसानों के बीच रहता था, इसलिए कभी-कभी उनपर दया भी कर देता था। साहूकार ज़मींदार, जो उनसे दूर शहर में रहता है और अपने गुमाशतों या कारिन्दों को रुपया उगाहने के लिए भेजता है, ऐसी कमजोरी शायद ही कभी दिखाता हो।

खेतिहरों पर कितना कर्ज है, इसके मुस्तलिफ़ सरकारी तख्मीने सरकारी कमेटियों ने लगाये हैं। १९३० में यह तख्मीना लगाया गया था कि वरमा को छोड़कर सारे हिन्दुस्तान के कृषिजीवी वर्गों पर कुल कर्ज ८०३ करोड़ यानी ८ अरब ३ करोड़ रुपये का है। इसमें ज़मींदारों और किसानों दोनों के कर्ज शामिल हैं। पिछले तीन वर्षों की आर्थिक मन्दी में यह कर्ज बहुत बढ़ गया होगा।

इस तरह कृषिजीवी (खेती पर गुज़र करनेवाले) वर्ग, छोटे ज़मींदार और काश्तकार, एकसमान दलदल में दिन-दिन ज्यादा नीचे डूबते जा रहे हैं और सिवा इस क्रान्तिकारी तरीक़े के कि आजकल की भूमि-प्रणाली की जड़ को काट दिया जाय, उनके बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। इंग्लैण्ड से खर्चिले कमीशन हिन्दुस्तान आते हैं और स्पेशल ट्रेनों में सारे देश का चक्कर काटते हैं और ऊँची आवाज़ में, ऊपरी और दिखाऊ सुधार के उपाय बताते हैं। हाल के सालों में इस तरह के दो 'रायल कमीशन'—कृषि-कमीशन और मज़दूर-कमीशन—आ चुके हैं। टैक्सों का तरीक़ा कुछ ऐसा है कि सबसे ग़रीब वर्ग पर सबसे ज्यादा बोझ पड़ता है, जिसे वह बर्दाश्त करने में समर्थ नहीं है। फ़ौज, सिविल सर्विस और दूसरे ब्रिटिश जिम्मेदारीवाले महकमों के, जिनसे सर्वसाधारण का कोई फायदा नहीं, खर्च बढ़ते जाते हैं। शिक्षा पर प्रति व्यक्ति करीब ९ पेंस (आठ आना) खर्च है, जबकि ब्रिटेन में २ पौण्ड १५ शिलिंग (करीब ३६ रुपया १० १/२ आना) प्रति व्यक्ति है। इस तरह ब्रिटेन शिक्षा पर प्रति व्यक्ति हमसे ७३ १/२ गुना खर्च करता है।

आबादी पर प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय क्या है, इसका अन्दाज़ लगाने की अकसर कोशिश की गई है। यह एक मुश्किल मामला है और अन्दाज़ में फ़र्क होना स्वाभाविक है। दादाभाई नौरोजी ने १८७० ई० में २० रुपया सालाना प्रति व्यक्ति का अन्दाज़ किया था। हाल के तख्मीने ६७ रुपया प्रति व्यक्ति तक पहुँचे हैं—यहाँ तक कि कुछ अंग्रेज़ों द्वारा सबसे बढ़ाकर बनाये गये तख्मीने भी ११६ रुपये से ज्यादा नहीं जाते। दूसरे देशों से इसका मुकाबिला करना बड़ा दिलचस्प होगा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में प्रति व्यक्ति औसत १,९२५ रुपये का है और सबसे यह और बढ़ गया है; ब्रिटेन में यह १,००० रुपये प्रति व्यक्ति है। कैसा ज़बरदस्त अन्तर है!

भारत में शान्तिपूर्ण विद्रोह

१७ मई, १९३३

हिन्दुस्तान और उसके भूतकाल के बारे में मैंने तुमको बहुतेरे दूसरे मुत्कों की वनिस्वत कहीं ज्यादा खत लिखे हैं; पर भूतकाल अब वर्तमान में मिलता जा रहा है और यह खत, जिसे मैं शुरू कर रहा हूँ, कहानी को आज के हिन्दुस्तान तक पहुँचा देगा। मैं हाल की चन्द्र घटनाओं का जिक्र करूँगा, जो हमारे मन में ताजा हैं। उनके बारे में लिखने का वक्त तो अभी नहीं आया है, क्योंकि अभी कहानी अधूरी ही है। पर सब इतिहास वर्तमान में पहुँचकर एकाएक ही खत्म होजाते हैं और कहानी के बाकी अध्याय भविष्य के गर्भ में छिपे रह जाते हैं। और सच पूछें तो कहानी कभी खत्म नहीं होती; वह आगे चलती ही जाती है।

१९२७ के अखीर में ब्रिटिश सरकार ने ऐलान किया कि वह भावी सुधारों और सरकार के ढाँचे में तब्दीलियों के बारे में जाँच करने के लिए एक कमीशन भेजेगी। सारे राजनैतिक भारत ने इस ऐलान पर गुस्सा और विरोध जाहिर किया। कांग्रेस ने इसका विरोध इसलिए किया कि वह यों समय-समय पर हिन्दुस्तान की स्वतंत्रता की योग्यता की जाँच किये जाने के विचार के ही सख्त खिलाफ थी। हिन्दुस्तान पर जबतक हो सके अपना कब्जा कायम रखने की अंग्रेजों की जो हार्दिक इच्छा है उसपर परदा डालने के खयाल से वे इस वाक्य का प्रयोग करते थे। कांग्रेस ने बहुत पहले से देश के लिए आत्म-निर्णय के अधिकार का दावा किया था—राष्ट्रों के उसी अधिकार का जिसको लेकर मित्र-राष्ट्रों ने महायुद्ध के जमाने में इतना शोर मचाया था। उसने ब्रिटिश पार्लमेण्ट के हिन्दुस्तान के साथ मनमाना वर्ताव करने या उसके भावी भाग्य का अन्तिम निर्णायक होने के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया। इस आधार पर कांग्रेस ने नये पार्लमेण्टरी कमीशन का विरोध किया। हिन्दुस्तान के माडरेट वर्गों ने दूसरे कारणों से कमीशन का विरोध किया, जिसमें खास वजह यह थी कि उसमें कोई हिन्दुस्तानी सदस्य नहीं था। यह एक शुद्ध ब्रिटिश कमीशन था। यद्यपि विरोध के कारण अलग-अलग थे, पर यह बात सच थी कि हिन्दुस्तान के सब वर्गों ने, सबसे अधिक नरम माडरेटों ने भी, मिलकर इसकी, निन्दा की और इसके वायकाट का समर्थन किया।

इसी वक्त के क्रूरिब, दिसम्बर १९२७ में, मद्रास में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ और उसने निश्चय किया कि हिन्दुस्तान का उद्देश्य राष्ट्रीय स्वतंत्रता है। यह

पहला मौका था कि कांग्रेस ने स्वतंत्रता के अपने उद्देश्य का ऐलान किया। उसने साफ़ तौर पर और दृढ़ता के साथ ऐलान किया, फिर भी शायद उस वक्त इस बात पर उसकी पूरे तौर पर दिलजमई नहीं हुई थी। दो वर्ष बाद, लाहौर में, निश्चित रूप से स्वतंत्रता कांग्रेस का ध्येय हुई। यह बात कि मद्रास कांग्रेस स्वतंत्रता के बारे में साफ़-साफ़ कोई निश्चय न कर सकी थी, उसके पास किये हुए एक दूसरे प्रस्ताव से भी जाहिर थी, जिसमें उसने हिन्दुस्तान के दूसरे वर्गों और संस्थाओं को मिल-जुलकर देश के लिए एक विधान बनाने की निमंत्रित किया था। यह जाहिर था कि माडरेट वर्ग या नरम विचारवाले लोग स्वतंत्रता तक जाने को तैयार न थे। इस तरह मद्रास-कांग्रेस ने सर्वदल सम्मेलन (All Parties Conference) को जन्म दिया। यह थोड़े दिनों तक जिन्दा रहा, पर इसकी जिन्दगी क्रियाशील थी।

दूसरे साल, १९२८ में, हिन्दुस्तान में ब्रिटिश कमीशन आया। जैसा कि मैंने बताया है, आमतौर पर इसका वायकाट हुआ और जहाँ-जहाँ यह गया इसके खिलाफ़ जबरदस्त प्रदर्शन हुए। इसके अध्यक्ष के नाम से यह 'साइमन कमीशन' कहलाया और सारे हिन्दुस्तान में 'साइमन लौट जाओ' की ध्वनि गूँज उठी। कई जगह प्रदर्शन करनेवालों पर पुलिस ने लाठियाँ भी चलाईं। लाहौर में लाला लाजपतराय तक को पुलिस ने मारा। चंद महीनों बाद लालाजी की मृत्यु हो गई और डाक्टरों ने संभावना बताई कि पुलिस की मार ने उनकी मृत्यु को नजदीक लाने में मदद की। इन सब बातों से क्रुद्धरती तौर पर देश में बड़ी उत्तेजना और क्रोध छा गया।

इस दरमियान सर्वदल सम्मेलन एक विधान बनाने और साम्प्रदायिक गुट्थी को सुलझाने की कोशिश कर रहा था। उस वक्त हमारे राजनीतिज्ञों को विधान बनाने का काम बड़ा पसन्द था, मानों ताकत हासिल करने के लिए सिर्फ़ एक कागज़ी विधान की ही जरूरत हो! सर्वदल सम्मेलन ने विधान और साम्प्रदायिक सवाल पर अपने प्रस्ताव एक रिपोर्ट की शकल में पेश किये। यह रिपोर्ट नेहरू-रिपोर्ट के नाम से मशहूर है, क्योंकि जिस कमेटी ने रिपोर्ट का मस्विदा तैयार किया उसके चेयरमैन दाढ़ थे।

इस साल की दूसरी उल्लेखनीय घटना गुजरात के वारडोली में सरकार द्वारा मालगुजारी बढ़ा दिये जाने के खिलाफ़ किसानों की एक बड़ी लड़ाई थी। गुजरात में युक्तप्रान्त की तरह बड़ी जमींदारियों की प्रणाली नहीं है; वहाँ जमीन पर मिल्कियत रखनेवाले किसान (Peasant proprietors) हैं। सरदार वल्लभभाई पटेल के नेतृत्व में इन किसानों ने एक बड़ी जबरदस्त लड़ाई लड़ी और भारी फतह हासिल की।

दिसम्बर १९२८ की कलकत्ता-कांग्रेस एक तरह से मद्रास की स्वतंत्रता के निश्चयवाली कांग्रेस से नीचे उतर आई। इसने नेहरू-रिपोर्ट में बताये हुए विधान को

मंजूर किया, जो कि स्वतंत्रता से बहुत कम था। अस्पष्ट रूप से यह ब्रिटिश उपनिवेशों के विधानों से मिलता-जुलता था। पर इसे भी कांग्रेस ने कुछ ही वक्त के लिए मंजूर किया था और सिर्फ एक साल का वक्त रखा था। इसके आधार पर एक साल के अन्दर ब्रिटिश सरकार से राजीनामा न होने पर कांग्रेस फिर स्वतंत्रता के ध्येय पर लौट जायगी, यह तय हुआ। इस तरह कांग्रेस और देश दोनों एक संकट की तरफ बढ़ते जा रहे थे।

मजदूर भी बड़े उत्तेजित हो रहे थे, और कई बड़े औद्योगिक केन्द्रों में मजदूरी घटाने की कोशिश पर बहुत उग्र बनते जा रहे थे। बम्बई में मजदूर वर्ग खास तौर पर अच्छी तरह संगठित था और वहाँ बड़ी-बड़ी हड़तालें हुईं, जिनमें एक लाख या इससे भी ज्यादा मजदूरों ने हिस्सा लिया। समाजवादी, और कुछ हद तक साम्यवादी, खयाल मजदूरों में फैलने लगे और सरकार ने इन क्रान्तिकारी बातों और मजदूरों की बढ़ती हुई ताकत से घबराकर १९२९ के शुरू में एकाएक ३२ मजदूर नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र केस चलाया। यह मुकदमा 'मेरठ केस' के नाम से सारी दुनिया में मशहूर होगया है। पौने चार वर्ष के लम्बे मुकदमे के बाद इसी साल सब अभियुक्तों को लम्बी-लम्बी सजायें हुई हैं। और इसकी आश्चर्यजनक बात तो यह है कि इनमें से किसीपर विद्रोह के अमली काम, यहाँ-तक कि शान्ति-भंग करने के लिए भी, मामला नहीं चलाया गया। उनका जुर्म यह दिखाई देता है कि वे साम्यवादी खयालात रखते और उनके प्रचार की कोशिश करते थे।

आन्दोलन का एक दूसरा रूप और था, जो अन्दर-ही-अन्दर धधक रहा था और कभी-कभी ऊपर भी जाहिर होजाता था। यह उन लोगों की कार्रवाईयाँ थीं जो क्रान्ति को लाने के लिए हिंसा के तरीकों में विश्वास रखते थे। हिंसात्मक उपायों से क्रान्ति लाने के मार्ग में विश्वास करनेवालों का एक तरह का आन्दोलन और था, जो अन्दर-ही-अन्दर सुलग रहा था और कभी-कभी ऊपर भी दिखाई दे जाता था। यह आन्दोलन खास तौर पर बंगाल, कुछ हदतक पंजाब और थोड़ा-बहुत संयुक्तप्रान्त में दिखाई देता था। ब्रिटिश सरकार ने इसे कई तरीकों से दबाने की कोशिश की और बहुत-से षड्यंत्र केस चलाये गये। 'बंगाल आर्डिनेंस' नाम का एक खास क़ानून जारी किया गया। इसके जरिये सरकार को अधिकार दिया गया कि वह जिस किसीको चाहे, सन्देह होने पर, गिरफ्तार कर सके और बिना कोई मुकदमा चलाये जेल में रख सके। इस आर्डिनेंस के जरिये कई सौ बंगाली युवक गिरफ्तार किये और जेल भेजे गये; वे नज़रबन्द कहलाते थे और उनके जेल की कोई अवधि निश्चित नहीं की गई थी। यह ग़ौर

करने के क्राविल मनोरञ्जक बात है कि जब यह असाधारण आर्डिनेंस जारी किया गया तब इंग्लैण्ड में शासन एक मजदूर सरकार के हाथ में था, जो इस आर्डिनेंस के लिए जिम्मेदार थी।

इन क्रान्तिकारियों द्वारा आतंक के बहुत-से काम, ज्यादातर बंगाल में, हुए। इनमें से तीन घटनाओं ने खास तौर पर लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। एक लाहौर में ब्रिटिश पुलिस अफसर को गोली मारने की थी। लोगों का खयाल था कि इसी अफसर ने साइमन कमीशन के खिलाफ हुए प्रदर्शन के वक्त लाला लाजपतराय को पीटा था। दूसरी घटना भगतसिंह और बटुकिश्वरदत्त द्वारा दिल्ली के असेम्बली-भवन में बम फेंकने की थी। इस बम ने बहुत कम नुकसान किया और जान पड़ता है कि शोर मचाने और देश का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए ही यह बम फेंका गया था। तीसरी घटना १९३० में चटगांव में ठीक उस वक्त हुई जब सत्याग्रह-आन्दोलन शुरू हुआ था। यह शस्त्रागार पर बड़े पैमाने पर और साहस से भरा हुआ धावा था और इसमें कुछ कामयाबी भी हुई। सरकार ने इस आन्दोलन को दबाने के लिए जितने भी उपायों की कल्पना की जा सकती थी, उन सबका प्रयोग किया। खुफिया पुलिस और 'मुखविर' रखे गये; बड़ी तादाद में लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनपर षड्यंत्र के मुकदमे चलाये गये; लोगों को नजरबन्द किया गया (कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जो लोग अदालत में छूट जाते हैं वे तुरन्त फिर से गिरफ्तार कर लिये जाते और आर्डिनेंस के मुताबिक नजरबन्द बनाकर रखे जाते हैं); पूर्वी बंगाल के बहुत-से हिस्सों पर अभी तक फ़ौज का कब्जा है और लोग बिना 'आज्ञापत्र' या परवाने के घूम-फिर नहीं सकते, न वाइसकिलों पर चढ़ सकते हैं, न अपने मन की पोशाक ही पहन सकते हैं। पुलिस को खबर न देने के जुर्म में सारे-के-सारे क़स्बों और गाँवों पर भारी जुर्माने किये गये हैं, और जिनपर आतंकवादी होने का शक होता है उनका कुत्तों की तरह पीछा किया जाता है। बहुत समय से यह सब चलता रहा है और अब भी चल रहा है।

१९२९ ई० में लाहौर में जो षड्यंत्र केस चलाया गया था उसमें एक क़दी यतीन्द्रनाथ दास ने जेल के बर्ताव के खिलाफ़ विरोध-स्वरूप भूख-हड़ताल कर दी। यह लड़का अख़ीर तक अपनी बात पर डटा रहा और इकसठवें दिन मर गया। यतीन्द्रनाथदास के आत्म-बलिदान का हिन्दुस्तान पर गहरा असर हुआ। दूसरी घटना, जिसने देश के दिल पर चोट की और उसे व्यथित किया, १९३१ के शुरू में भगतसिंह को दी जाने वाली फांसी थी।

अब मुझे कांग्रेस-राजनीति की तरफ़ लौटना चाहिए। कलकत्ता-कांग्रेस ने एक

वर्ष का जो समय दिया था, वह खत्म हो रहा था। १९२९ के अखीर में ब्रिटिश सरकार ने उन घटनाओं को बढ़ने से रोकने की कोशिश की जिनकी कि चर्चा थी। उसने भावी उन्नति के बारे में एक अस्पष्ट ऐलान किया। उस वक़्त भी कांग्रेस ने सहयोग के लिए हाथ बढ़ाया, अलबत्ता उसमें कुछ शर्तें जरूर थीं। चूँकि ये शर्तें पूरी नहीं की गई इसलिए दिसम्बर १९२९ की लाहौर कांग्रेस ने लाजिमी तौर पर पूर्ण स्वतंत्रता के ध्येय और उसके हासिल करने के लिए लड़ाई लड़ने का फैसला किया। यह निश्चय ३१ दिसम्बर की आधीरात को किया गया, जब पुराना साल और एक साल का दिया हुआ वक़्त खत्म होता था।

इस तरह १९३० का साल आगे आनेवाली घटनाओं की छाया के साथ शुरू हुआ। सत्याग्रह के लिए तैयारियाँ हो रही थीं। फिर असेम्बली और कौंसिलों का बायकाट किया गया और कांग्रेसी सदस्यों ने उनसे इस्तीफ़ा दे दिया। २६ जनवरी को स्वाधीनता की एक खास प्रतिज्ञा सारे देश में, गांवों और शहरों में होनेवाली अगणित सभाओं में ली गई और हर साल उसकी वार्षिक-तिथि 'स्वाधीनता दिवस' के नाम से मनाई जाती है। मार्च में बापू की मशहूर दाँडी-यात्रा शुरू हुई। दाँडी समुद्र के किनारे पर है और वहाँ पहुँचकर उन्होंने नमक-क़ानून तोड़ने का ऐलान किया था। उन्होंने अपनी लड़ाई का आरंभ करने के लिए नमक-क़ानून को इसलिए चुना था कि यह टैक्स गरीबों पर बहुत भारी पड़ता था और इस लिए एक खासतौर पर बुरा टैक्स था।

अप्रैल १९३० के मध्य तक सत्याग्रह-आन्दोलन पूरे जोर पर आ गया था और न सिर्फ़ हर जगह नमक-क़ानून तोड़ा गया, बल्कि और क़ानून भी तोड़े गये। सारे देश में शान्तिपूर्ण बगावत हो गई थी और उसे कुचलने के लिए नये-नये क़ानून और आर्डिनेंस तेज़ी के साथ बनते जा रहे थे। लेकिन इन आर्डिनेंसों पर भी सत्याग्रह होने लगा, यानी लोग उन्हें ही तोड़ने लगे। सामूहिक रूप से यानी झुण्ड-के-झुण्ड आदमियों की गिरफ़्तारियाँ हो रही थीं और पशुतापूर्ण लाठियों की वर्षा एक आम बात होगई थी। इनके अलावा शान्ति भीड़ पर गोलियों का चलना, कांग्रेस कमेटियों का गैरक़ानूनी ऐलान किया जाना, सेंसरशिप, अखबारों का गला दवाना, मारना और जेलों में सज़ा करना जारी था। पर मैं यहाँ उस ज़माने के बारे में ज्यादा कहना नहीं चाहता। एक तरफ़ आर्डिनेंसों का राज्य था, दूसरी तरफ़ उन आर्डिनेंसों को तोड़ने का एक व्यवस्थित और निश्चित प्रयत्न था। इसके साथ विदेशी कपड़े और ब्रिटिश माल का बायकाट भी चल रहा था। करीब एक लाख आदमी जेल गये और कुछ समय तक इस शान्तिपूर्ण पर दृढ़ता के साथ लड़ी जानेवाली लड़ाई ने दुनिया का ध्यान अपनी तरफ़ खींच लिया।

मैं तुम्हारे ध्यान में तीन बातें लाना चाहता हूँ। इनमें पहली पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त की ज्वरदस्त राजनैतिक जागृति थी। लड़ाई के विलकुल शुरू में ही, ४ अप्रैल १९३० ई० को पेशावर में शान्त भीड़ पर जोरों के साथ गोली चलाई गई और सारे सालभर हमारे सीमाप्रान्त के भाइयों ने बड़ी बहादुरी और धीरज के साथ सरकार के पशुतापूर्ण व्यवहारों को वर्दाश्त किया। यह दुगुनी महत्त्वपूर्ण बात थी, क्योंकि सीमाप्रान्त के लोग शान्त स्वभाव के नहीं हुआ करते, ज़रा-सी उत्तेजना की बात पर आग-बबूला हो जाते हैं। इतने पर भी वे शान्त रहे। बंगाल या बंबई के लिए, जिनके पीछे राजनैतिक कार्य का रेकॉर्ड है, लड़ाई में सबसे ज्यादा हिंसा लेना आश्चर्य-जनक नहीं था, पर पठानों जैसे राजनैतिक मैदान में नये आनेवालों के लिए तुरन्त ही सामने आ जाना और ऐसा बहादुराना पार्ट अदा करना एक ताज्जुब की और साथ ही बड़ी ही तारीफ़ की बात थी।

दूसरी उल्लेखनीय बात, जो निश्चय ही इस महान् वर्ष की सबसे प्रधान घटना थी, भारतीय स्त्रियों की अभूतपूर्व जागृति थी। जिस तरह से उनमें से हजारों और लाखों ने अपना घूँघट हटा दिया और अपने सुरक्षित मकानों को छोड़कर अपने भाइयों के साथ-साथ लड़ने के लिए मैदान में आ गईं और अक्सर अपने देश-प्रेम और बहादुरी से अपने आदमियों को शर्मिन्दा कर दिया, वह कुछ ऐसी चीज़ थी कि जिन लोगों ने उसे नहीं देखा वे मुश्किल से ही उसका विश्वास कर सकते हैं।

तीसरी नोट करने लायक बात यह थी कि ज्यों-ज्यों आन्दोलन बढ़ा, किसानों के सवाल का आर्थिक पहलू स्पष्ट रूप से सामने आता गया। १९३० सारी दुनिया में फैली हुई एक बड़ी मन्दी का पहला साल था। यह मन्दी अभी तक जारी है। १९३० में खेती से पैदा होनेवाली चीज़ों का दाम बहुत गिर गया। किसानों पर गाज गिर गया, क्योंकि उनकी आमदनी इन चीज़ों की बिक्री और उससे मिलनेवाले दाम पर ही निर्भर है। इसलिए उनकी इस मुसीबत के साथ करबन्दी का मेल बैठ गया और उनके लिए स्वराज्य कोई दूर का राजनैतिक ध्येय नहीं बल्कि तुरन्त का एक आर्थिक सवाल बन गया। इस तरह उनके लिए आन्दोलन एक नया और ज्यादा परिचित अर्थ लेकर सामने आया और, उसमें ज़मींदार और-काश्तकार के बीच, वर्ग-संघर्ष का एक तत्त्व पैदा हो गया। यह बात ख़ास तौर पर युक्तप्रान्त और पश्चिमी हिन्दुस्तान में थी।

जब हिन्दुस्तान में सत्याग्रह-आन्दोलन फूल-फल रहा था, तब समुद्र के उसपार लन्दन में, ब्रिटिश सरकार बड़ी शान-शौक़त के साथ एक 'राउण्ड टेबुल कांफ़्रेंस (गोल मेज़ परिषद)' कर रही थी। कांफ़्रेंस को इससे कोई सरोकार न था। जितने

हिन्दुस्तानी इसमें गये, सबके सब सरकार के नामजद किये हुए थे। कठपुतलियों या वंजान छायामूर्तियों (परछाई की शक्लों) की तरह वे लंदन के रंगमंच पर कूदते-फाँदते थे और अच्छी तरह महसूस करते थे कि असली लड़ाई हिन्दुस्तान में चल रही है। सरकार ने हिन्दुस्तानियों की कमजोरी दिखाने के लिए बहस में साम्प्रदायिक मसले को सबसे आगे रख दिया; उसने कट्टर साम्प्रदायिक और पश्चाद्गामी लोगों को इस कांफ्रेंस के लिए नामजद करने की होशियारी पहले ही करली थी, जिससे समझौते की कोई संभावना ही न थी।

मार्च १९३१ ई० में कांग्रेस और सरकार के बीच एक 'ट्रूस' या चंदरोजा सुलह इसलिए हुई कि आगे बात-चीत हो सके। सत्याग्रह-आन्दोलन स्थगित कर दिया गया, सत्याग्रह के हजारों कैदी छूटे और आर्डिनेंस उठा लिये गये। फिर भी राजनैतिक कैदियों की एक बड़ी तादाद जेलों में ही रह गई और अब भी है। इनमें १९१४ के षड्यन्त्र, पंजाब के फ़ौजी क़ानून, मेरठ के और दूसरे बहुतेरे षड्यंत्र के मामलों के कैदी थे और बंगाल के नज़रबन्द लोग थे। हिन्दुस्तानी जेलों में इनकी एक स्थायी राजनैतिक आवादी या वस्ती ही बस गई है। जबकि सत्याग्रही कैदी बहुत बड़ी तादाद में एकसाथ आते और जाते हैं, तहाँ दूसरे कैदी बिना किसी विश्राम या भंग के जेल की ज़िन्दगी बिता रहे हैं।

यह देखकर बड़ा मजा आता था कि देहली की सुलह के बाद किस तरह आदमी कांग्रेस की दोस्ती का दम भरता था, यहाँतक कि इनमें वे लोग भी थे जो सदा उस-पर हमला किया करते और उसे गाली दिया करते थे। सत्याग्रह-आन्दोलन ने उनपर असर डाला था और कांग्रेस की ताक़त देखकर वे सोचने लगे कि भविष्य में कांग्रेस के हाथ में ज्यादातर सत्ता होगी। इसलिए वे, जो सदा से ही अवसरवादी थे, कांग्रेस की तरफ़ दौड़े और उसकी खुशामद करने और उसकी तारीफ़ के पुल बाँधने लगे। यह एक दुःखदायी पर सच्ची बात है कि राजनैतिक लड़ाइयों में अकसर यह होता है कि जो वर्ग सबसे ज्यादा क़ुर्बानी करता है उसे सबसे कम मिलता है और जो लोग चुपचाप आराम से अपने घर बैठे हुए होते हैं वे लड़ाई से मिले हुए माल का बँटवारा करने में सबसे आगे आजाते हैं।

सन् १९३१ ई० में बापू कांग्रेस की तरफ़ से दूसरी गोलमेज़ कांफ्रेंस में शरीक होने के लिए लन्दन गये। खुद हिन्दुस्तान में तीन महत्वपूर्ण सवाल उठ खड़े हुए, जिनकी तरफ़ सरकार और कांग्रेस दोनों का ध्यान गया। पहला सवाल बंगाल का था, जहाँ सरकार ने आतंकवाद को मिटाने की आड़ में राजनैतिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ़ बड़ा ही सख्त दमन जारी कर रक्खा था। एक नया और पहले से बहुत ज्यादा सख्त

आर्डिनेंस जारी कर दिया गया और देहली की सुलह के होते हुए भी बंगाल ने नहीं जाना कि शान्ति कैसी होती है ।

दूसरा सवाल सीमाप्रान्त में था, जहाँ राजनैतिक जागृति के कारण लोग अब भी कुछ कार्यक्रम चला रहे थे । खान अब्दुलगफ्फारखां के नेतृत्व में एक बड़ा, अनुशासन से भरा हुआ पर शान्तिपूर्ण संगठन बनता और फैलता जा रहा था । इनको 'खुदाई खिदमतगार' और कभी-कभी 'रेडशर्ट' या लाल कुर्ती दल कहा जाता था । 'रेडशर्ट' इसलिए कि ये एक लाल 'यूनिफार्म' (वर्दी) पहनते थे । किसी समाजवादी या साम्यवादी संस्था से उनका ताल्लुक न था । सरकार इस आन्दोलन को बिल्कुल पसंद न करती थी । वह इससे भयभीत थी, क्योंकि वह एक अच्छे पठान सिपाही या योद्धा की क्रीमत् जानती थी ।

तीसरा सवाल संयुक्तप्रान्त में पैदा हुआ । विश्वव्यापी मंदी और चीजों के दाम गिर जाने से गरीब काश्तकार पर बड़ी मुसीबत आपड़ी । वह अपना लगान नहीं अदा कर सकृता था । उसे कुछ छूट दी गई, पर वह काफ़ी न थी । कांग्रेस ने उसकी तरफ़ से मध्यस्थता की कोशिश की पर उसका कुछ ज्यादा नतीजा न निकला । जब नवम्बर १९३१ ई० में लगान-वसूली का वक़्त आया तो झगड़ा पैदा होगया । कांग्रेस ने काश्तकारों और ज़मींदारों को राय दी कि जबतक छूट का सवाल तय न होजाय, तब तक लगान और मालगुजारी मत दो । यह सत्याग्रह पहले इलाहाबाद से शुरू हुआ । वस, सरकार ने संयुक्तप्रान्त के लिए एक आर्डिनेंस निकाल दिया । यह एक बड़ा ही सख्त और व्यापक आर्डिनेंस था । इसमें जिले के अधिकारियों को हर तरह के काम को कुचल देने, यहाँ तक कि व्यक्तियों की आमदरपत को भी बंद करने का पूरा अख्तियार दिया गया था ।

इस आर्डिनेंस के बाद ही तुरंत सीमाप्रान्त में दो नये विचित्र आर्डिनेंस जारी किये गये और सीमाप्रान्त एवं संयुक्तप्रान्त में प्रमुख कांग्रेसमैनों को गिरफ़्तार कर लिया गया ।

जब बापू साल के आखिरी हफ़्ते में, लंदन से बिना किसी कामयाबी के, लौटे तो उनके सामने यह स्थिति थी । तीन प्रान्तों में आर्डिनेंस राज्य था और उनके कई साथी जेलों में पहुँच चुके थे । एक हफ़्ते के अन्दर फिर कांग्रेस ने सत्याग्रह का ऐलान कर दिया । सरकार ने कांग्रेस कमेटियों और कांग्रेस से हमदर्दी रखनेवाली संस्थाओं को गैरक्रान्ती करार दे दिया ।

यह लड़ाई डेढ़ वर्ष तक चलती रही है और अब भी चल रही है । और इस वक़्त में मैंने जो ये खत तुम्हें लिखे हैं, इसी लड़ाई का एक छोटा और अप्रत्यक्ष परि-

णाम है। यह लड़ाई १९३० की लड़ाई से कहीं ज्यादा सख्त रही है। इसके लिए सरकार ने, पहले के अनुभवों से फ़ायदा उठाकर, अपनेको बड़ी सावधानी से तैयार कर लिया था। क़ानूनी नकाब और क़ानूनी ढांचा ख़त्म कर दिया गया और सर्वव्यापी एवं सर्वभक्षी आर्डिनेंसों के जरिये, मुल्की अफ़सरों के सहारे, देश में ऐसा दमन किया गया जिसे एक तरह का 'मार्शल ला' (फ़ौजी क़ानून) कह सकते हैं। राज्य की असली पाशविक सत्ता ख़ूब साफ़ तौर पर दिखाई पड़ी है। यह बात लाजिमी थी, क्योंकि ज्यों-ज्यों राष्ट्रीय आन्दोलन जोरदार और ताक़तवर बनता जायगा और विदेशी सरकार के आधार के लिए ज्यों-ज्यों ख़तरनाक बनता जायगा त्यों-त्यों सरकारी प्रतिरोध और दमन ज़बरदस्त और भयंकर होता जायगा। ऐसी हालत में धरोहर (Trusteeship) और सद्भावना के पवित्र और नरम वाक्य अलग रख दिये गये और उनकी जगह विदेशी शासन के सच्चे स्तम्भ या रक्षक के रूप में लाठियाँ और किरचें सामने आईं। क़ानून न सिर्फ़ सिर पर बैठे हुए वाइसराय की इच्छा बन गया बल्कि हर छोटा अफ़सर मनमानी करने लगा; क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि वह जो कुछ करेगा उसका उसके ऊपर के अफ़सर समर्थन करेंगे। ख़ासकर ज़ार के ज़माने के रूस की तरह ख़ुफ़िया विभाग और सी० आई० डी० के आदमी सब जगह फैल गये और उनकी ताक़त बढ़ गई। कोई बंधन या रोक नहीं थी और अनियंत्रित सत्ता की भूख सदा उसके इस्तेमाल से बढ़ती जाती है—यहाँ भी बढ़ती गई। एक सरकार जो मुख्यतः अपने ख़ुफ़िया विभाग के सहारे हुकूमत करती है और एक देश जो ऐसी हुकूमत में होता है, दोनों बहुत जल्द भ्रष्ट या पतित होजाते हैं; क्योंकि हरेक ख़ुफ़िया विभाग साज़िश, भेदियों, झूठ, आतंकवाद, उत्तेजक बनावटी बातों, धोखेबाज़ी और दूसरी ऐसी ही बातों पर फूलता-फलता है। पिछले तीन वर्षों में हिन्दुस्तान में छोटे अफ़सरों, पुलिस और सी० आई० डी० को जो बहुत ज्यादा अख़्तियारात दे दिये गये थे और उन्होंने उनका जैसा इस्तेमाल किया था उससे धीरे-धीरे इन महकमों के आदमियों में पशुता आती गई और उनका पतन होता गया। लोगों को जेल जाने से रोकने के लिए तरह-तरह की कोशिशें की गईं और जेल भेजने की जगह उनपर बेरहमी के साथ गहरी मार मारी गई। कोशिश यह थी कि लोग भयभीत होजायें।

मुझे व्योरे की बातों में नहीं जाना चाहिए। इस मौक़े पर सरकार की नीति का एक मनोरंजक पहलू यह रहा है कि संस्थाओं और व्यक्तियों की जायदाद, मकान, मोटरें और बैंक में जमा रुपये ज़ब्त कर लिये जायें। यह कांग्रेस के मध्यमवर्ग के समर्थकों पर चोट करने और उन्हें डरा देने के लिए किया गया। अब व्यक्तिगत धन

या जायदाद की पवित्रता की बात खत्म होगई है। सरकार एक-न-एक वहाने से इसे ज़ब्त कर रही है। इसी तरह हिंसा उसी वक़्त बुरी और अनैतिक बताई जाती है जब कोई वर्तमान स्थिति को बदलने के लिए उसका इस्तेमाल करता है; पर खुद सरकार वर्तमान व्यवस्था की हिफ़ाज़त के लिए सब तरह की बेरहमी से भरी हुई और व्यापक हिंसा से काम लेने में अपनेको बिलकुल उचित और न्यायपूर्ण समझती है !

इन आड़िनैसों में से एक का एक मामूली पर ध्यान देने लायक पहलू यह रहा है कि अपने या अपने साथे में पलनेवाले बच्चों के जुर्मों के लिए माँ-बाप और अभिभावक जिम्मेदार हैं।

जब हिन्दुस्तान में ये सब बातें हो रही हैं, तब ब्रिटिश प्रचार की मशीनरी, जो बहुत दिनों से अपनी क़ाबलियत के लिए मशहूर है, हिन्दुस्तान की खुशहाली और शान्ति की एक सुन्दर तस्वीर दुनिया के सामने खींचने में मशगूल है। खुद हिन्दुस्तान में कोई अख़बार परिणाम के डर से सच्ची बातों को छापने की हिम्मत नहीं करता—यहाँतक कि गिरफ़्तार हुए लोगों के नाम तक छापना एक जुर्म है !

पर हिन्दुस्तान में ब्रिटिश नीति का परदा फाश करनेवाली सबसे खास बात यह रही है कि ब्रिटिश सरकार ने हिन्दुस्तान के सब कट्टर पश्चाद्गामी या प्रतिक्रियावादी वर्गों से मेल करने की कोशिश की। आज ब्रिटिश साम्राज्य उन्नतिशील शक्तियों से लड़ने के लिए सामन्तशाही और प्रतिक्रिया की दूसरी ताकतों पर निर्भर करता है। उसने स्थापित स्वार्थों (Vested Interests) को अपनी मदद के लिए खड़ा करने की कोशिश की है। इस मदद को पाने के लिए उसने इनको (स्थापित स्वार्थ-वालों को) यह बताकर डराया कि अगर हिन्दुस्तान से ब्रिटिश सत्ता हटाली जायगी तो सामाजिक क्रान्ति होजायगी और तुम्हारा क़ात्मा हो जायगा। सामन्तशाही तौर-तरीक़े वाले राजा लोग हिन्दुस्तान में ब्रिटिश हुकूमत की पहली रक्षणात्मक मोर्चाबन्दी (First line of defence) हैं; उसके बाद बड़े-बड़े जमींदारों का वर्ग आता है। चतुराई-भरी चालवाज़ियों से और कट्टर सम्प्रदायवादियों को धकेलकर आगे खड़ा करके अल्पमत के मसले को हिन्दुस्तान की आज़ादी के रास्ते में एक बड़ा रोड़ा बना दिया गया है। अभी हाल में वह ग़ौर करने के क़ाबिल दृश्य दिखाई पड़ा जब मन्दिर-प्रवेश के सवाल पर ब्रिटिश सरकार ने कट्टर मजहबी प्रतिक्रियावादियों के प्रति हर तरह की हमदर्दी और दोस्ती जाहिर की। हर जगह ब्रिटिश सरकार प्रतिक्रिया, संकुचित धर्मोन्माद और भ्रमपूर्ण खुदगर्जी में अपनी मदद ढूँढती है।

सामूहिक आन्दोलन या लड़ाई में एक बड़ी सुविधा होती है। आम जनता को सियासी तालीम देने का यह सबसे अच्छा और तेज़ी का, गो दुखदाई, तरीक़ा है;

क्योंकि आम जनता को 'बड़ी घटनाओं' के लिए तालीम देकर तैयार करना पड़ता है। शान्ति के समय की मामूली राजनैतिक कार्रवाइयाँ—जैसे प्रजासत्तात्मक देशों में होने-वाले चुनाव वगैरा—अक्सर औसत आदमी को भ्रम में डाल देती हैं। उसके सामने भाषणों की धार बहती होती है और हरेक उम्मीदवार हर तरह की अच्छी बातों के करने का वादा करता है जिससे गरीब वोटर या खेत, कारखाने या दुकान में काम करनेवाला आदमी धबरा जाता और भ्रम में पड़ जाता है। उसे एक दल से दूसरे में कोई बहुत ज्यादा और साफ़ फ़र्क़ दिखाई नहीं देता। पर जब एक सामूहिक लड़ाई आती है, या जब क्रान्ति होती है, तब असली स्थिति यों साफ़ दीखती है जैसे बिजली से रोशनी हो उठी हो। ऐसी मुसोबत की घड़ियों में समुदाय, वर्ग या व्यक्ति अपनी वास्तविक अनुभूति या प्रकृति को छिपा नहीं सकते। सत्य बाहर आ जाता है। क्रान्ति का समय न सिर्फ़ चरित्र (Character), साहस, सहनशक्ति, आत्मत्याग और वर्ग-अनुभूति की कसौटी होता है बल्कि वह मुख्तलिफ़ वर्गों और समुदायों के बीच के उस असली संघर्ष को जाहिर कर देता है जो सुन्दर और अस्पष्ट जुमलों के नीचे ढका हुआ होता है।

हिन्दुस्तान में सत्याग्रह की लड़ाई एक राष्ट्रीय या क्रांती लड़ाई रही है, वर्ग-संघर्ष नहीं। यह निश्चित रूप से मध्यम वर्ग का एक आन्दोलन रहा है जिसके पीछे किसानों का बल है। इसलिए यह वर्गों को उस तरह अलग और स्पष्ट नहीं कर सका जिस तरह कोई वर्गीय आन्दोलन करता। फिर भी, इस राष्ट्रीय आन्दोलन में भी, कुछ हद तक वर्गों की मोर्चाबन्दी हुई है। इनमें से कुछ—जैसे सामन्तशाही खयाल के राजा लोग, ताल्लुकदार और बड़े जमींदार—पूरे तौर पर सरकार के साथ बंधे हुए हैं। वे साफ़-साफ़ और जोर से पुकारकर कहते हैं कि वे कौमी आजादी पर अपने वर्ग के हितों को तरजीह देते हैं, या कौमी आजादी तभी चाहिए जब उनके खास अस्तित्वरात को महफूज रखनेवाले सब तरह के संरक्षणों का बंदोबस्त कर दिया जाय। इससे यह साफ़ हो जाता है कि किसी राष्ट्रीय या क्रांती लड़ाई में इनसे किसी तरह मदद की उम्मीद नहीं की जा सकती, हाँ राष्ट्रीय आन्दोलन की मुखालफ़त की उम्मीद जरूर की जा सकती है। इन्होंने निश्चित रूप से अपनेको विदेशी सरकार के साथ मिला दिया है।

कुछ हद तक सभी मालिक वर्ग (Possessing Classes), यानी वे सभी वर्ग जिनके स्थापित स्वार्थ (Vested Interest) होते हैं, किसी भी बड़ी तब्दीली से डरते हैं कि कहीं वह उनके खास अस्तित्वरात या सुविधाओं में दस्तदाजी न करे। बड़े-बड़े बोर्जुआ लोग यानी ऊँचे दर्जे का मध्यमवर्ग विदेशी सरकार को नापसंद

करता है और खुद उसकी जगह लेना चाहता है। कुछ हद तक वह सरकार के प्रति कांग्रेस की चुनौती के साथ हमदर्दी रखता है, क्योंकि इससे उसके फायदे के अनुकूल राजनैतिक परिवर्तन होने की सम्भावना उसे मालूम पड़ती है। पर इसके साथ ही वह सामूहिक जनता और मध्यम वर्ग के छोटे लोगों से भी भय करता है। इसके अलावा उसको यह डर भी है कि कहीं कांग्रेस की विजय से ऐसा सामाजिक परिवर्तन न हो-जाय जो उसको पसन्द न हो। इसलिए ये लोग आम तौर पर मँड़ या हद पर रहते हैं, साफ़-साफ़ किसी तरह शरीक नहीं होते, सरकार और कांग्रेस दोनों की हलकी आलोचना करते हैं और धीरज के साथ उस वक़्त का इन्तज़ार करते हैं जब ये सत्ता के बँटवारे में बड़ा हिस्सा ले सकेंगे। लेकिन सामाजिक क्रान्ति का कोई इशारा किया जाता है, या उनके स्थापित स्वार्थों पर कोई हमला होता है, तब वे गुस्से से लाल होजाते हैं। यह एक गैरमामूली बात है कि लोग अपने खास अस्तित्वभारत और सहूलियतों के बचाव के लिए कितने आग-बबूला हो उठते हैं। इन अस्तित्वभारत पर उनका नैतिक दावा या हक़ जितना ही कमज़ोर होता है, उतना ही वे उनमें दखल दिये जाने पर गुस्सा होते हैं।

अल्पमतों का मसला भी ज्यादातर विशेष समुदायों के स्थापित स्वार्थों का ही सवाल है। बहुतसे लोग हमेशा हिन्दू-मुस्लिम एकता के बारे में राग अलापा करते हैं। यह बात काफी तौर पर साफ़ है कि ऐसा मेल वाञ्छनीय है। पर यह बात भी उतनी ही जाहिर है कि सिर्फ़ इस जुमले को जादू के मन्त्र की तरह दोहराने से कोई फायदा नहीं हो सकता; न किसी तरह जोड़-तोड़ के जरिये किये जाने वाले पैक्टों और समझौतों से ही कोई मदद मिल सकती है। बदकिस्मती से सामने के असली सवालों पर 'हिन्दू-मुस्लिम एकता' जैसे जुमलों से परदा पड़ जाता है। कुछ समुदायों के स्थापित स्वार्थों को अलग छोड़ दें तो गहराई में सवाल असल में आर्थिक है। स्वार्थों के संघर्ष, फिर चाहे वे मुस्लिम जातियों के बीच हों या प्रजासत्तावाद और सामन्तशाही के बीच हों, मुस्कराहटों, आलिंगनों और एक-दूसरे की सचाई के वादों या ऐलानों से दूर नहीं किये जा सकते। अंकगणित या अलजबरा का कोई मसला उसपर मुस्कराने से हल नहीं होता; न एक-दूसरे के खिलाफ़ दो चीज़ों को उनकी परिक्रमा करने से ही एक में मिलाया जा सकता है।

हाल में कांग्रेस-आन्दोलन नीचे के दर्जे के मध्यम वर्ग के ऐसे आन्दोलन में तब-दील होगया है जिसके पीछे छोटे जमींदारों और किसानों की जोरदार मदद है। अब इसमें आम जनता के स्वार्थों का प्रतिनिधित्व करने की प्रवृत्ति पहले से ज्यादा बढ़ गई है और मौलिक और आर्थिक अधिकारों पर एक दिलचस्प प्रस्ताव १९३१ में कराँची-

काँग्रेस ने पास किया था। ज्यों-ज्यों काँग्रेस सामूहिक या आम जनता की तरफ झुकती जाती है त्यों-त्यों बड़े मालिक वर्गों की शंका बढ़ती जाती है और वे इससे दूर हटते जाते हैं, यद्यपि इसका आधार अब भी राष्ट्रीय है।

हिन्दुस्तान में बहुत-से लोगों ने बार-बार जेल जाने की आदत डाल ली है, और कुछ तो जेलों में लगातार कई वर्षों तक बने रहते हैं। दूसरे लोगों के एक समुदाय ने दूसरी आदत पैदा करली है—मेरा मतलब जनता के यानी सरकारी खर्च से गोलमेज कांग्रेस की बैठकों में शामिल होने के लिए हर साल लन्दन जाने की आदत से है। साल-दर-साल वे जाते हैं और बातें ही बातें करते हैं तथा ब्रिटिश सरकार को एक ऐसा विधान बनाने में मदद देते हैं जिसका खास मतलब पीढ़ियों तक हिन्दुस्तान में ब्रिटिश हुकूमत को कायम रखना और हरेक स्थापित स्वार्थ की रक्षा करना है। संघ-राज्य का खयाल ही इसलिए आया कि ब्रिटिश भारत को कब्जे में रखने के लिए सामन्त-प्रथा वाले राजाओं की मदद की जरूरत थी। आर० एच० टाने नाम के एक जहीन अंग्रेज लेखक ने ब्रिटिश मजदूर दल के लिए कार्यक्रम सुझाते हुए लिखा है कि 'गधों की सबसे ज्यादा मुमकिन तादाद को सबसे ज्यादा संभव संख्या में गाजर देना' ("to offer the largest possible number of carrots to the largest possible number of donkeys") दल (मजदूर दल) का काम नहीं है। कोई कल्पना कर सकता है कि लन्दन के विधान-निर्माताओं ने इसे ही अपना खास काम खयाल किया होगा ?

हाल में ही ब्रिटिश सरकार ने हिन्दुस्तान के विधान के लिए अपने प्रस्तावों को एक छोटी किताब की शकल में प्रकाशित किया है, जिसका नाम 'व्हाइटपेपर' है। उसने अपना काम पूरी तरह किया है और उसमें हरेक कल्पना किये जा सकने लायक संरक्षण को शामिल कर लिया गया है जिसे कि आदमी की सूझ सोच और बना सकती है। ये संरक्षण न सिर्फ उसके स्वार्थों की रक्षा के लिए हैं बल्कि हिन्दुस्तान पर उसके सैनिक शासन सम्बन्धी और व्यापारिक (Military, Civil and Commercial) यानी त्रिविध नियंत्रण को और मजबूत करने के लिए हैं। हरेक स्थापित स्वार्थ को महफूज रखा गया है और इंग्लैंड का स्थापित स्वार्थ सबसे बड़ा होने की वजह से उसको सुरक्षित रखने की सबसे जोरदार तजवीज की गई है। यही बात राजाओं, जायदाद पर मालिकी रखनेवाले वर्गों, नौकरियों और ब्रिटिश सरकार के पिछलग्गुओं के बारे में भी है। हरेक स्थापित स्वार्थ के लिए बड़ी दरियादिली से इन्तजाम किया गया है। बदकिस्मती इतनी ही है कि दूसरे के माल पर दिखाई जानेवाली इस उदारता ने हिन्दुस्तान के कमोवेश तंतीस करोड़ वाशिनटों के लिए बहुत कम छोड़ा है। पर उन बेचारों के कोई स्थापित स्वार्थ न थे—सिवाय उनकी जिन्दगी के, जिसकी कोई कीमत नहीं।

ब्रिटिश प्रस्तावों को देखकर इलाहावाद के एक शायर अकबर का, जो कई साल हुए मर गये, एक उर्दू शेर याद आता है। यह शेर उन्होंने १९०३ में लार्ड कर्जन के दिल्ली दरबार के वक्त लिखा था :

महफ़िल उनकी, साक़ी उनका,
आँखें अपनी, बाक़ी उनका।

असली सवाल जन-समूह का शोषण बन्द करने का है और जबतक यह नहीं किया जाता तबतक हिन्दुस्तान में शान्ति कैसे हो सकती है, या हमारी आज़ादी की लड़ाई कैसे ख़त्म हो सकती है ?

इस तरह कहानी चली जा रही है। आज (१७ मई) बापू के अनशन का दसवाँ दिन है। अभीतक वह निवाह लेगये हैं और जान पड़ता है आगे भी बर्दाश्त करलेंगे। वह जेल से छोड़ दिये गये हैं और अनशन के कारण उन्होंने छः हफ़्तों के लिए सत्याग्रह-आन्दोलन को स्थगित कर दिया है। उसके बाद ? कौन जानता है ?

मैंने बरमा की उपेक्षा की है और मुझे उसके बारे में तुम्हें कुछ ज़रूर बताना चाहिए। उसने १९३० या १९३२ के सत्याग्रह-आन्दोलन में हिस्सा नहीं लिया। पर महान् आर्थिक संकट के कारण १९३० और १९३१ में उत्तरी बरमा में किसानों की एक बड़ी बग़ावत होगई। यह बग़ावत अंग्रेज़ों ने बड़ी बर्बरता के साथ दबा दी। इस वक्त ब्रिटिश सरकार बरमा को हिन्दुस्तान से अलग करने की बड़ी ज़ोरों से कोशिश कर रही है और बरमा में इससे बड़ा तहलका मच गया है। ऐसा जान पड़ता है कि वहाँके ज्यादातर लोग हिन्दुस्तान से अलग होना नहीं चाहते।

और ख़ैरवाद हिन्दुस्तान !—फिर मिलेंगे।

: १६३ :

मिस्र की आज़ादी के लिए लड़ाई

२० मई, १९३३

आओ, अब हम मिस्र चलें और बढ़ती हुई राष्ट्रीयता और एक साम्राज्यवादी ताक़त के बीच होनेवाली दूसरी लड़ाई का मुलाहिज़ा करें। हिन्दुस्तान की तरह वहाँ भी यह साम्राज्यवादी शक्ति ब्रिटेन है। मिस्र कई बातों में हिन्दुस्तान से बिल्कुल मुक्तलिफ़ है और वहाँ ब्रिटेन हिन्दुस्तान की बनिस्बत बहुत थोड़े वक्त से रहा है, फिर भी दोनों देशों में बहुत-सी बातें एक-सी हैं। हिन्दुस्तान और मिस्र के राष्ट्रीय आन्दोलनों ने अलग-अलग तरीक़े इस्ति़यार किये, पर मूल में क़ौमी आज़ादी

की प्रेरणा एक ही है और उद्देश्य भी एक ही है। और इन राष्ट्रीय आन्दोलनों को दवाने में साम्राज्यवाद जो ढंग इस्तिथार करता है वह भी दोनों देशों में बहुत-कुछ एक है। इसलिए हम दोनों एक-दूसरे के अनुभवों से बहुत-कुछ सीख सकते हैं। हम हिन्दुस्तान वालों के लिए तो एक खास नसीहत है, क्योंकि हम मिस्र के उदाहरण में देख सकते हैं कि 'स्वतंत्रता' की ब्रिटिश देनों का क्या मतलब होता है और वे कहाँ-तक लेजाती हैं।

सब अरब देशों (अरबस्तान, इराक़, सीरिया, फिलस्तीन) में मिस्र सबसे आगे बढ़ा हुआ है। यह पूर्व और पश्चिम के बीच का राजमार्ग—स्वेज नहर बनने के बाद से जहाज़ों के लिए तिजारत का महान् समुद्री रास्ता—रहा है। पश्चिमी एशिया के किसी देश की बनिस्वत इसका उन्नीसवीं सदी के नये योरप के साथ सबसे ज्यादा सम्पर्क रहा है। दूसरे अरब देशों से बिल्कुल जुदा इसकी एक अलग राष्ट्रीय इकाई है, पर उनके साथ इसका घनिष्ठ सांस्कृतिक सम्बन्ध भी है, क्योंकि इन सबकी जवान, परम्परा और मजहब एक ही हैं। काहिरा (कैरो) के रोज़ाना अख़बार सब अरब देशों को जाते हैं और वहाँ उनका बड़ा प्रभाव है। इन सब देशों में से सबसे पहले राष्ट्रीय आन्दोलन मिस्र में ही शुरू हुआ, इसलिए दूसरे अरब देशों के लिए मिस्री राष्ट्रीयता का एक नमूना बन जाना लाज़िमी था।

मिस्र की बाबत लिखे हुए अपने पिछले ख़त में मैंने अरबीपाशा के नेतृत्व में होनेवाले १८८१-८२ के राष्ट्रीय आन्दोलन का ज़िक्र किया था और यह भी बताया था कि वह ब्रिटेन के ज़रिये किस तरह कुचल दिया गया। मैंने तुमको शुरू के सुधारकों, जमालउद्दीन अफ़ग़ानी और कट्टर इस्लाम पर पश्चिम के नये खयालात के असर की बाबत भी बताया है। इन सुधारकों ने पुराने उसूलों की तरफ़ लौटकर और धर्म की फ़िज़ूलियात यानी सदियों के बीच उसमें मिल गई बहुतेरी बातों को अलग हटाकर ज़माना हाल की तरबूती से इस्लाम का मेल बैठाने की कोशिश की। उन्नतिशील विचार के लोगों ने दूसरा क़दम यह रक्खा कि धर्म को सामाजिक संस्थाओं से अलग कर दिया। पुराने धर्मों का कायदा यह है कि वे हमारी रोज़मर्रा की ज़िन्दगी के हर पहलू को घेर लेते और उसे चलाते हैं। इस तरह हिन्दूधर्म और इस्लाम, अपनी शुद्ध धार्मिक शिक्षाओं से बिल्कुल अलग भी, समाज का विधान बनाते और शादी, विरासत, दीवानी और फ़ौजदारी क़ानून, राजनैतिक संगठन, और दूसरी सब चीज़ों के नियम निर्धारित करते हैं। दूसरे लफ़्ज़ों में वे समाज का एक पूरा ढाँचा निर्धारित करते और उसे धार्मिक स्वीकृति और सत्ता देकर स्थायी बनाने की कोशिश करते हैं। अपनी कठोर वर्ण-व्यवस्था से हिन्दूधर्म इस बारे में सबसे आगे निकल जाता

है। एक सामाजिक ढाँचे को यों धर्म के जरिये स्थायी बना देने से किसी तब्दीली का होना मुश्किल होजाता है। इसलिए दूसरे देशों की तरह मिस्र में भी उन्नतिशील आदमियों ने धर्म को सामाजिक ढाँचे और सामाजिक संस्थाओं से अलग करने की कोशिश की। उन्होंने वजह यह बताई कि पुरानी संस्थायें, जिन्हें धर्म या रिवाज ने पुराने जमाने में लोगों पर लाद दिया था, उस जमाने की हालत में मुनासिब थीं। पर अब हालत बहुत बदल गई है और पुरानी संस्थायें या प्रथायें अब उनके साथ ठीक नहीं बैठतीं। मामूली विवेक से हम समझ सकते हैं कि बैलगाड़ी के लिए बनाया गया एक नियम मोटरकार या रेलगाड़ी के लिए मुनासिब नहीं होसकता।

इन उन्नतिशील आदमियों और सुधारकों ने इस तरह की दलीलें पेश कीं। इस वजह से राज्य और बहुतेरे रिवाजों ने ज्यादा लौकिक या दुनियावी शक्ल इस्तिहार की, यानी वे धर्म से अलग कर लिये गये। जैसा हम देख चुके हैं, यह सिलसिला तुर्की में सबसे ज्यादा दूर तक गया। तुर्की प्रजातंत्र का अध्यक्ष या राष्ट्रपति खुदा के नाम पर ग्रहण की जानेवाली शपथ भी नहीं लेता; वह इसे अपनी इज्जत के नाम पर लेता है। मिस्र में मामला इस हद तक नहीं पहुँचा है, पर दूसरे इस्लामी देशों में यही प्रवृत्ति काम कर रही है। तुर्क, मिस्री, सीरियन, फारसी वगैरा आज धर्म की पुरानी जवान की बनिस्वत राष्ट्रीयता की भाषा में कहीं ज्यादा बोलते हैं। सम्भवतः हिन्दुस्तान के मुसलमानों ने दुनिया के मुसलमानों के किसी बड़े समुदाय की बनिस्वत राष्ट्रीयकरण के इस सिलसिले का सबसे ज्यादा प्रतिरोध किया है और यों वे इस्लामी देशों के अपने धर्मबन्धुओं की बनिस्वत कहीं ज्यादा अनुदार, कट्टर और मजहबी रंग के हैं। यह एक अजीब पर गौर-तलब बात है। नई राष्ट्रीयता और पूँजी-वादी आर्थिक प्रणाली के नीचे पैदा हुए मध्यम वर्गों का विकास अवसर साथ-साथ हुआ है। हिन्दुस्तान के मुसलमान इस बोरजुआ या मध्यम वर्ग का विकास करने में बहुत सुस्त रहे हैं और इस कमी ने राष्ट्रीयता की तरक्की में बाधा डाली है। यह भी मुमकिन है कि हिन्दुस्तान में उनके अल्पमत में होने के खयाल ने उनको इतना भयभीत कर दिया कि वे ज्यादा अनुदार और कट्टर होगये और अपनी पुरानी परम्परा से जकड़कर रह गये और नये खयालात की तरफ से शंकित होगये। इसी तरह की किसी मानसिक अवस्था में वे हिन्दू भी रहे होंगे जो करीब हजार वर्ष पहले, शुरू के इस्लामी हमलों के वक्त अपने खोलों में घुस गये और एक बड़ी सख्त, जातियों में बँटी हुई क्रौम बन गये।

उन्नीसवीं सदी के आखिरी चौथाई हिस्से में और उसके बाद, विदेशी व्यापार बढ़ने के साथ, मिस्र में नई मध्यम श्रेणी पैदा हुई और बढ़ी। इस वर्ग के एक आदमी

सैद जगलूल थे जो 'फेलाह' या किसान कुटुम्ब से इस दर्जे तक बढ़े थे। जब अरबी-पाशा ने १८८१-८२ में अंग्रेजों को चुनौती दी, तब वह एक युवक थे और उन्होंने अरबीपाशा के नेतृत्व में काम किया। तबसे आगे १९२७ में अपनी मौत के वक्त तक, यानी पैंतालीस वर्षों तक, उन्होंने मिस्त्र की आजादी के लिए काम किया और मिस्त्री स्वतंत्रता-आन्दोलन के नेता होगये। वह मिस्त्र के सर्वमान्य नेता थे; किसान, जिनमें से वह उठे थे, उनसे मुहब्बत करते थे और मध्यम श्रेणी, जिसमें वह खुद थे, उन्हें पूजती थी। लेकिन रईस लोगों यानी पुरानी सामन्ती जमींदार श्रेणी ने उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। वे उस बढ़ते हुए मध्यम वर्ग को पसन्द नहीं करते थे जो उनको धीरे-धीरे देश में उनके ऊँचे स्थान से दूर धकेल रहा था। उनकी निगाह में जगलूल एक मामूली खानदान का था, और जगलूल को अपने वर्ग के नेता और प्रतिनिधि की हैसियत से उनके खिलाफ लड़ना पड़ा। हिन्दुस्तान की तरह वहाँ भी अंग्रेजों ने सामन्ती जमींदार वर्ग से अपने लिए मदद लेने की कोशिश की। वहाँ यह वर्ग मिस्त्री की बनिस्वत तुर्की ही ज्यादा था और पुराने शासक सरदारों का नुमाइन्दा था।

इस तरह ब्रिटिश सरकार ने, साम्राज्यवाद के अच्छी तरह परखे हुए और मंजूर-शुदा फैशन के ढंग पर, अपने साथ किसी सामाजिक समुदाय या राजनैतिक दल को मिला रखने की कोशिश की और एक वर्ग या दल को दूसरे वर्ग या दल के खिलाफ खड़ा करके एक राष्ट्रीयता की वृद्धि को रोक दिया। हिन्दुस्तान की तरह वहाँ भी उन्होंने अल्पमत का मसला उठाने की कोशिश की। ईसाई काप्ट लोग मिस्त्र में थोड़ी तादाद में हैं। पर इस कोशिश में वे नाकामयाब रहे। और यह सब भी उन्होंने अपने उसी प्रचलित फैशन में अपने ओठों से पवित्र वाक्यों का उच्चारण करते हुए किया। वे कहते रहे कि जो कुछ हम करते हैं सब तुम्हारे ही फायदे के लिए है; हम तो 'गूंगी जनता' के 'ट्रस्टी' हैं और अगर 'झगड़ा पैदा करनेवाले' और दूसरे लोग, जिनका देश में कुछ भी जोखिम उठाने लायक नहीं है, शान्त रहें तो सब कुछ ठीक होजायगा। मजा तो यह है कि जनता का उपकार करने के इस सिलसिले में अकसर उन्हीं फायदा उठानेवाले लोगों को बड़ी तादाद में गोलियों से भून दिया गया। शायद ऐसा उन्हें दुनिया के दुखों से छुटकारा दिलाने और स्वर्ग की तरफ उनके सफ़र को नजदीक लाने के लिए किया गया होगा !

सारे युद्ध के जमाने में और उसके बाद भी बहुत दिनों तक मिस्त्र में फ़ौजी शासन था। युद्ध के जमाने में वहाँ 'डिस्टामिण्ट ऐक्ट' और 'कांस्त्रिप्शन ऐक्ट' नामी दो क़ानून पास हुए थे। देश ब्रिटिश फौजों से भरा हुआ था। महायुद्ध के शुरू में ही उत्तर पर ब्रिटिश संरक्षण का ऐलान कर दिया गया था।

१९१८ में शान्ति होने के बाद, मित्र के राष्ट्रवादियों ने फिर 'आन्दोलन' शुरू किया और मित्र की आजादी का 'केस' तैयार किया। वे इसे ब्रिटिश सरकार और पेरिस के शान्ति-सम्मेलन के सामने रखना चाहते थे। उस वक़्त मित्र में कोई वास्तविक दल न था। 'वतनी' (स्वदेशवादी) नामका एक दल था, पर इसके सदस्यों की तादाद भी बहुत कम थी। प्रस्ताव यह था कि जगलूलपाशा के नेतृत्व में एक बड़ा डेपुटेशन मित्र की स्वाधीनता की वकालत करने के लिए लंदन और पेरिस जाय और इस डेपुटेशन को राष्ट्रीय रूप देने और उसके पीछे कुछ जोर पैदा करने के लिए एक बड़ी संस्था खोली गई। मित्र की मशहूर 'वपद' पार्टी का जन्म इसी तरह हुआ। 'वपद' का मतलब ही 'डेपुटेशन' है। ब्रिटिश सरकार ने इस डेपुटेशन को लंदन जाने की मंजूरी देने से इन्कार कर दिया और मार्च १९१९ में जगलूल और दूसरे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया।

इसका नतीजा यह हुआ कि एक खूनी क्रान्ति शुरू होगई। कुछ अंग्रेज़ मारे गये और क़ाहिरा (कैरो) के शहर और दूसरे केन्द्रों पर क्रान्तिकारी दल का क़ब्ज़ा होगया। बहुत-सी जगहों में 'सार्वजनिक रक्षा' की 'राष्ट्रीय कमेटियाँ' क़ायम की गईं। इस वगावत में विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी) के विद्यार्थियों ने बड़ा हिस्सा लिया। शुरू की इन कामयाबियों के बाद वगावत बहुत-कुछ दबा दी गई, हालांकि बीच-बीच में अंग्रेज़ अफ़सर मारे जाते रहे। मगर खुली वगावत दबा दी जाने पर भी आन्दोलन को कुचला न जा सका। आन्दोलन ने लड़ाई का ढंग बदल दिया और 'पेंसिव रेसिस्टेंस' या 'शान्त-प्रतिरोध' (यानी एक तरह के सत्याग्रह) का एक दूसरा पहलू इस्तिंयार किया। इसमें इतनी कामयाबी हुई कि ब्रिटिश सरकार को मित्र की मांग पर गौर करने को मजबूर होना पड़ा। लार्ड मिलनर की अध्यक्षता में इंग्लैण्ड से एक कमीशन भेजा गया। मिल्ली राष्ट्रवादियों या नेशनलिस्टों ने इसका बायकाट करने का फ़ैसला किया और इस बायकाट में वे खूब कामयाब हुए। मिलनर-कमीशन के बायकाट में भी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों ने खूब हिस्सा लिया। कमीशन इस राष्ट्रीय विरोध से इतना प्रभावित हुआ कि उसने कुछ बहुत बड़ी सिफारिशें कीं। ब्रिटिश सरकार ने इन सिफारिशों की परवा न की और मित्र में आजादी की लड़ाई जारी रही। १९१९ के शुरू से १९२२ के शुरू यानी तीन वर्ष तक यह लड़ाई चलती रही और मिल्ली स्वतंत्रता 'इस्तक़लाल अल-तत्राम' या पूर्ण से कम पर राज़ी होने को तैयार न थे।

१९१९ में अपनी गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद जगलूलपाशा छोड़ दिये गये थे। दिसम्बर १९२१ में वह फिर गिरफ्तार करके जलावतन कर दिये गये। पर अंग्रेज़ों के लिए इससे मित्र की स्थिति कुछ नहीं सुधरी और उन्हें मिलियों को शान्त करने

के लिए कुछ करने को मजबूर होना पड़ा। यद्यपि जगलूल समझौता न करनेवाले उग्र लोगों में से न थे, फिर भी समझौते की सारी कोशिशें बेकार हुईं। जगलूल उग्र न थे, इसका एक सबूत यह भी है कि एक बार कुछ लोगों ने उनका खून तक करने की कोशिश की। उनका कहना था कि तुम अंग्रेजों के साथ कमजोर समझौता करके अपने देश को धोखा दे रहे हो। पर ब्रिटिश सरकार और मिस्री राष्ट्रवादियों के बीच उस वक्त या बाद में भी समझौता न हो सकने के मौलिक कारण थे। ये वही कारण हैं जो हिन्दुस्तान में भी समझौता होने में बाधक हैं। मिस्री राष्ट्रवादी मिस्र के ब्रिटिश स्वार्थों की उपेक्षा करना नहीं चाहते थे। वे इसपर बातचीत करने और ब्रिटेन के साम्राज्य-व्यापार और सैनिक रास्तों सम्बन्धी विशेष स्वार्थों को एक हद तक मंजूर करने को तैयार थे। पर वे इन सबालों पर तबतक विचार करने को तैयार नहीं थे जबतक कि उनके देश की पूर्ण स्वतंत्रता स्वीकार न करली जाय। फिर इन मसलों पर भी वे उसी हद तक विचार करने को तैयार थे जिस हद तक जाने में उनकी स्वतंत्रता बनी रहे। पर दूसरी तरफ़ इंग्लैण्ड समझता था कि यह तय करना हमारा काम है कि तुमको कितनी आजादी दी जाय और यह आजादी हमारे स्वार्थों के मुआफ़िक़ होगी, क्योंकि उनकी रक्षा करना हमारा पहला फ़र्ज़ है।

इस तरह दोनों के बीच समझौते का कोई सामान्य आधार न था। लेकिन ब्रिटिश सरकार महसूस करती थी कि कुछ-न-कुछ जल्द किया जाना चाहिए इसलिए किसी समझौते या राजीनामे के बग़ैर ही, उसने २८ फरवरी १९२२ को एक ऐलान किया। उसमें उसने कहा कि भविष्य में वह मिस्र को एक 'आजाद खुदमुख्तार राज्य' ("Independent Sovereign State") मानेगी, परन्तु—और यह एक बड़ा परन्तु था—नीचे लिखे चार विषय आगे विचार करने के लिए सुरक्षित रखे गये :—

१. मिस्र में ब्रिटिश साम्राज्य के आमदरपत के मार्गों की रक्षा।
२. प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विदेशी हमलों या दस्तदाजियों के खिलाफ़ मिस्र की रक्षा।
३. मिस्र में फैले हुए विदेशी स्वार्थों और अल्पमत वाली जातियों की रक्षा।
४. सूडान के भविष्य का सवाल।

ये संरक्षण अपने हिन्दुस्तान के संरक्षण-बन्धुओं के साथ कितने एक-से मालूम पड़ते हैं। हम इन्हें यहाँ, अपने देश में, 'सेफगार्ड्स' (संरक्षण) कहते हैं और उनके अण्डे-बच्चे हमारे देश में कहीं ज्यादा हैं। मिस्र में उस वक्त इन संरक्षणों को मंजूर नहीं किया गया और अभीतक मिस्रियों ने इन्हें मंजूर नहीं किया है, क्योंकि यों देखने में तो ये सीधे-सादे और निर्दोष मालूम पड़ते थे पर इनका मतलब यह था कि न घरेलू और न वंदेशिक मामलों में मिस्र को कोई वास्तविक स्वतंत्रता मिलेगी। इस तरह २८ फरवरी १९२२

का मिल की स्वतंत्रता का ऐलान ब्रिटिश सरकार का एकांगी काम था, जिसे मिल ने कभी मंजूर नहीं किया। पिछले ग्यारह वर्षों में मिल में यह बात अच्छी तरह जाहिर होगई है कि संरक्षणों के साथ स्वतंत्रता का भी क्या मतलब हो सकता है।

इस 'स्वतंत्रता' के वावजूद ब्रिटिश अफसरों की देखरेख में और भी डेढ़ साल तक 'मार्शल ला'—फ़ौजी कानून—जारी रहा। यह तब ख़त्म हुआ जब मिल की सरकार ने 'ऐक्ट ऑफ़ इनडेमनिटी' यानी ऐसा क़ानून पास किया जिसके जरिये फ़ौजी शासन के ज़माने में अफसरों द्वारा किये गये ग़ैरक़ानूनी कामों की ज़िम्मेदारी से उन्हें मुक्त कर दिया गया, यानी उन्हें पनाह दीगई।

नये 'स्वतंत्र' मिल को एक बहुत ही प्रतिक्रियात्मक विधान दिया गया, जिसमें वादशाह के हाथ में बड़े अस्तित्वरात थे। यह वादशाह—किंग फ़ुआद—भी बेचारे मिलियों पर ज़बरदस्ती लाद दिया गया। वादशाह फ़ुआद और ब्रिटिश अधिकारियों में ख़ूब मेलजोल था, दोनों राष्ट्रवादियों को नापसन्द करते थे और दोनों जनता की आज़ादी के ख़याल, यहाँतक कि असली पार्लमेण्टरी हुकूमत का भी विरोध करते थे। फ़ुआद खुद अपनेको सरकार समझता था और जो उसके मन में आता वह करता था। उसने पार्लमेण्ट को बर्खास्त कर दिया और अपनी हिफ़ाज़त करने के लिए सदा तैयार ब्रिटिश संगीनों पर विश्वास करके डिक्टेटर की तरह हुकूमत करने लगा।

मिल की स्वतंत्रता के अपने ऐलान के बाद पहला परोपकार का काम जो ब्रिटिश सरकार ने किया वह यह था कि उसने उन अधिकारियों के लिए मुआवज़े की बड़ी-बड़ी रक़मों माँगीं जो नई हुकूमत के कारण 'रिटायर' (अलग) हो रहे थे! इस वक़्त वादशाह फ़ुआद ही मिल की सरकार था और उसने फ़ौरन माँग स्वीकार कर ली और यों पैंसठ लाख पौंड की बड़ी रक़म चुकाई गई—एक बड़े अधिकारी को तो आठ हजार पाँच सौ पौंड मिले! फिर मज़ेदार बात तो यह हुई कि इन अधिकारियों में से कई, जो अलग होने के लिए गहरा मुआवज़ा ले चुके थे, ख़ास कण्ट्राक्ट पर फिर रख लिये गये। याद रखो कि मिल बड़ा देश नहीं है और उसकी आबादी संयुक्तप्रान्त की आबादी की तिहाई से भी कम है।

मिली विधान बड़ी बहादुरी से कहता है कि "सारी सत्ता राष्ट्र से उद्भूत (Emanate) होती है," पर व्यवहार में बात यह है कि जबसे नया विधान जारी किया गया तबसे मिली पार्लमेण्ट के लिए बड़ा बुरा ज़माना आगया है। जहाँतक मैं जानता हूँ (हाल की घटनाओं के बारे में मुझे बिल्कुल ठीक इल्म नहीं है), एक भी पार्लमेण्ट अपनी सामान्य अवधि तक ज़िन्दा नहीं रही। बार-बार वादशाह फ़ुआद के

हाथों उसकी एकाएक मौत होती रही है और यह बादशाह विधान को मुलतवी करके निरंकुश राजा की तरह हुकूमत करता रहा है।

नई पार्लमेण्ट का पहला चुनाव १९२३ में हुआ और जगलूलपाशा और उनके दल ने, जो अब वपद दल के नाम से मशहूर है, सारे देश में हलचल पैदा कर दी। उनको ९० प्रतिशत वोट मिले और २१४ स्थानों में से १७७ पर उन्होंने कब्जा कर लिया। इंग्लैण्ड के साथ समझौता करने की एकबार फिर कोशिश की गई और इसके लिए जगलूल लंदन गये। पर दोनों दृष्टिकोणों में मेल नहीं हो सका और कुछ सवालियों पर समझौते की बातचीत टूट गई। इन सवालियों में से एक सवाल सूडान का था। सूडान मिस्र के दक्षिण में एक देश है। यह मिस्र से बिल्कुल जुदा ढंग का है; यहाँ के वाशिन्डे जुदा हैं और जबान भी जुदी है। इसके ऊँचे क्षेत्रों से नील नदी बहती है। यह नील नदी मिस्र के लिखित इतिहास के शुरू से यानी सात-आठ हजार वर्षों से मिस्र का जीवन-रक्त या सहारा रही है। मिस्र की सारी कृषि और जिन्दगी नील नदी में आनेवाले सालाना सैलाबों—बाढ़ों—के इर्द-गिर्द पनपी है, क्योंकि ये सैलाब अबिसीनिया के ऊँचे प्रदेश से क्रीमती मिट्टी लाते हैं और मिस्र की ऊजड़ जमीन को उपजाऊ बनाते हैं। लार्ड मिलनर (मिलनर कमीशन के—जिसका वायकाट हुआ था—अध्यक्ष) ने नील नदी के बारे में लिखा था :—

“यह खयाल दुःखदाई है कि इस महानद से पानी की नियमित आमदनी, जो मिस्र के लिए सुविधा और खुशहाली का नहीं बल्कि जिन्दगी का सवाल है, सदा खतरे में रहे; और यह तबतक सदा खतरे में रहेगी जबतक कि नदी की उँचाई के स्थान मिस्र के कब्जे में नहीं रहेंगे।”

नदी की धारा के ये ऊँचे स्थान सूडान में हैं, इसलिए सूडान मिस्र के लिए बड़े महत्व का है।

पिछले जमाने में सूडान इंग्लैण्ड और मिस्र के संयुक्त नियंत्रण में समझा जाता था। इसे ‘एंग्लो-इजीप्शियन सूडान’ (अंग्रेजी-मिस्री सूडान) के नाम से पुकारा जाता था और अब भी बहुत-से नकशों और एटलसों में यही नाम है। चूँकि मिस्र पर अमली तौर पर ब्रिटेन की हुकूमत थी, इसलिए स्वार्थों का कोई संघर्ष नहीं था और मिस्र का बहुत-सा रुपया सूडान में खर्च किया गया। यहाँ तक कि १९२४ में लार्ड बर्जन् ने ब्रिटिश पार्लमेण्ट में कहा था कि अगर मिस्र खर्च के लिए धन न दे तो सूडान का दिवाला निकल जाय। लेकिन जब मिस्र छोड़ने के सवाल पर गौर करने के लिए ब्रिटेन को मजबूर होना पड़ा तब उसने सूडान को पकड़ रखना चाहा; दूसरी तरफ़ मिस्रियों ने महसूस किया कि उनकी सारी हस्ती सूडान से बहने वाली नील नदी की धारा की रक्षा पर निर्भर है; इसलिए स्वार्थों में संघर्ष हुआ।

१९२४ ई० में जब ब्रिटिश सरकार और सैद जंगलूलपाशा के बीच सूडान के मसले पर बातचीत हो रही थी, तब कई तरह से सूडान के लोगों ने मिस्र के साथ अपनी मुहब्बत जाहिर की। इसके लिए ब्रिटिश सरकार उनकी छाती पर चढ़ बैठी और मिस्र की सरकार से सलाह-मशविरा किये बिना जो मन में आया किया। मजा यह कि सूडान पर इंग्लैण्ड और मिस्र दोनों का संयुक्त नियन्त्रण था और इसके लिए मिस्र को काफ़ी खर्च करना पड़ता था।

अपनी मिस्री स्वाधीनता की कथित घोषणा में ब्रिटेन ने दूसरी छूट विदेशी स्वार्थों के संरक्षण की रखी थी। ये विदेशी स्वार्थ क्या थे ? मैं उनके बारे में किसी पिछले खत में तुम्हें बता चुका हूँ। जब तुर्की साम्राज्य कमजोर पड़ रहा था, तब महाशक्तियों ने उसपर कई नियम जबरदस्ती लाद दिये थे, जिनके मुताबिक तुर्की में उनके नागरिकों के साथ विशेष व्यवहार किये जाने की तजवीज की गई थी। ये यूरोपियन विदेशी चाहे जो जुर्म करें पर तुर्की अदालतों में उनपर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था। उनका मुकदमा उनके अपने देशों के राजदूतों या राष्ट्रीय प्रतिनिधियों यानी विदेशियों से बनी हुई खास अदालत में होता था। उनको कितने ही टैक्सों से छूट वगैरह की और भी बहुतेरी सहूलियतें दी गई थीं। विदेशियों की ये खास और क़ीमती सहूलियतें कैपिचुलेशंस कहलाती थीं। कैपिचुलेशन का मतलब शत्रु के प्रति आत्म-समर्पण होता है और यह भी मिस्र राष्ट्र का, कुछ हद तक, अपनी स्वाधीनता से झुकना या आत्म-समर्पण करना ही था। चूँकि तुर्की को उन्हें मानना पड़ा, इसलिए तुर्की साम्राज्य के उपनिवेश भी उन्हें मानने को मजबूर हुए। मिस्र तो पूरी तरह ब्रिटेन के क़ब्जे में था और वहाँ तुर्की की सत्ता नाम मात्र की भी नहीं रह गई थी; पर इस मामले में उसे तुर्की साम्राज्य का हिस्सा समझा गया और उसपर भी 'कैपिचुलेशंस' लादे गये। ऐसी अनुकूल स्थिति में शहरों में विदेशी व्यापारियों और पूँजीपतियों की वस्तियाँ बस गईं। यह लाज़िमी था कि वे एक ऐसी प्रथा के तोड़ने का विरोध करते जो हर तरह से उनकी हिफ़ाजत करती और बिना टैक्स दिये उनके मोटे और मालदार होने में मदद देती थी। मिस्र में विदेशी स्थापित स्वार्थ भी थे जिनकी रक्षा की जिम्मेदारी ब्रिटिश सरकार ने ली थी। मिस्र के लिए ऐसी प्रणाली को मानना मुमकिन न था जो न सिर्फ़ स्वाधीनता की विरोधी थी बल्कि जिससे उसकी एक बहुत बड़ी आमदनी मारी जाती थी। अगर सबसे मालदार आदमी टैक्स से बरी होजायें तो फिर सामाजिक अवस्था में किसी तरह के सुधार का कोई काम बड़े पैमाने पर नहीं किया जा सकता। सीधी ब्रिटिश हुकूमत के लम्बे जमाने में अंग्रेजों ने प्रारम्भिक शिक्षा या गाँवों के सुधार और सफ़ाई के लिए कुछ नहीं किया था।

घटनायें इस ढंग पर हुई कि तुर्की, जो 'कैपिचुलेशन' का असली कारण था, कमालपाशा की फ़तह के बाद उनसे छूट गया, पर मिस्र ब्रिटिश संरक्षण में अभीतक उनसे लदा हुआ है। यहाँ मैं यह भी कह दूँ कि चीन भी अभीतक इसी तरह के 'कैपिचुलेशनों' के खिलाफ़ लड़ रहा है। उन्नीसवीं सदी में, कुछ वक्त तक, जापान भी इनका मजा चख चुका था, पर ज्योंही वह ताक़तवर होगया, उसने उन्हें ख़त्म कर दिया।

इस तरह विदेशी स्थापित स्वार्थों का सवाल ब्रिटेन और मिस्र के तस्फ़िये के बीच दूसरा रोड़ा था। स्थापित स्वार्थ सदा ही आजादी के रास्ते में रोड़ा अटकाते हैं।

अपनी सदा की उदारता के साथ ब्रिटिश सरकार ने अल्पमत वाली जातियों की रक्षा करने का भी निश्चय किया था और यह भी फरवरी १९२२ के स्वाधीनता वाले ऐलान में एक संरक्षण था। अल्पमत वाली मुख्य जाति काष्टों की थी। ऐसा ख़याल किया जाता है कि ये लोग पुराने मिस्रियों के वंशज हैं और इस तरह सब तरह के मिस्रियों में से मिस्र के ज्यादा असली बाशिन्दे हैं। वे ईसाई हैं और ईसाई धर्म के शुरू के दिनों से, योरप के ईसाई होने के भी पहले से, ईसाई ही चले आ रहे हैं। अल्पमत वाली जातियों के प्रति ब्रिटेन की इस कृपालुता पर उसका अहसान मानने की जगह काष्टों ने यह अहसानफरामोशी दिखाई कि ब्रिटिश सरकार से साफ़ कह दिया कि हमारे लिए आप तकलीफ़ न करें। फरवरी १९२२ के ब्रिटिश ऐलान के बाद एक बड़ी मीटिंग में काष्ट लोग इकट्ठे हुए और प्रस्ताव किया कि "राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति और क़ौमी एकता के लिए हम सब तरह के अल्पमत के प्रतिनिधित्व और संरक्षणों का त्याग करते हैं।" काष्टों के इस निर्णय की अंग्रेजों ने 'मूर्खतापूर्ण' कहकर आलोचना की। पर बुद्धिमानी या मूर्खता कुछ भी कहो, इसने उनकी रक्षा करने के ब्रिटिश दावे का ख़ात्मा कर दिया और अल्पमत वाली जातियों का सवाल बहस-मुदाहिसे की धीज नहीं रह गया। बल्कि सच पूछें तो काष्टों ने आजादी की लड़ाई में जबरदस्त हिस्सा लिया और वषद दल में जगलूलपाशा के कुछ बहुत ही विश्वासपात्र साथी काष्ट थे।

इन विरोधी दृष्टिकोणों और स्वार्थों के असली संघर्ष के कारण मिस्र, जिसके प्रतिनिधि जगलूलपाशा और उनके साथी थे, और ब्रिटिश सरकार के बीच हो रही १९२४ की समझौते की बातचीत टूट गई थी। इसपर ब्रिटिश सरकार बड़ी नाराज़ हुई। अभीतक वह मिस्र में मनमानी करते रहने की अभ्यस्त होगई थी, इसलिए उसे क़ौरो की नई पार्लमेण्ट और ख़ासकर वषद नेताओं के अडंगे और मुख़ालफ़त पर बड़ी ख़ीज हुई। बस उन्होंने वषद लोगों और मिस्री पार्लमेण्ट को अपने साम्राज्यवादी ढंग पर सयक़ सिखाने का इरादा कर लिया। बहुत जल्द उन्हें मौक़ा भी मिल गया

और जिस सौरमामूली तरीके पर उन्होंने इसका इस्तेमाल किया और इससे फायदा उठाया, उसकी बाबत मैं अगले खत में लिखूंगा। वह महत्वपूर्ण घटना आजकल के साम्राज्यवाद की कारगुजारियों के लिए आईने की तरह है, इसलिए उसपर अलग खत लिखने की जरूरत है।

: १६४ :

अंग्रेजों की छत्रछाया में आज़ादी का तात्पर्य

२२ मई, १९३३

अपने पिछले खत में मैंने तुम्हें बताया था कि १९२४ में मिस्री सरकार, जिसके प्रतिनिधि राष्ट्रवादी थे, और अंग्रेजों के बीच सुलह की बातचीत शुरू होकर टूट गई थी और इससे ब्रिटिश सरकार बड़ी नाराज़ होगई थी। इसके बाद जो उल्लेखनीय घटनायें हुईं उनका बयान करने से पहले मैं तुम्हें यह बता देना चाहता हूँ कि कहने के लिए आज़ाद होते हुए भी मिस्र पर अंग्रेजों का फ़ौजी कब्ज़ा कायम रहा। वहाँ सिर्फ़ अंग्रेजी फ़ौज रखी ही नहीं गई थी, बल्कि मिस्र की फ़ौज भी अंग्रेजों के ही नियंत्रण में थी। उसका अध्यक्ष 'फ़ौज के सरदार' के ख़िताबवाला एक अंग्रेज था। पुलिस के बड़े-बड़े अफ़सर भी अंग्रेज ही थे, और मिस्र में विदेशियों की रक्षा करने का बहाना बताकर ब्रिटिश सरकार अर्थ, न्याय और आन्तरिक महकमों पर भी नियंत्रण रखती थी। ग़रज़ यह कि, मिस्री शासन के हरेक महत्वपूर्ण काम पर अंग्रेजों का ही नियंत्रण था। स्वभावतः ही, मिस्रवासी इस बात पर ज़ोर देते थे कि अंग्रेजों को यह नियंत्रण हटा लेना चाहिए।

१९ नवम्बर १९२४ ई० को एक अंग्रेज सर ली स्टाक, जो 'मिस्री फ़ौज के सरदार' के पद पर था और जो सूडान का भी गवर्नर-जनरल था, कुछ मिस्रियों द्वारा क़त्ल कर दिया गया। कुदरती तौर पर इससे मिस्र के और इंग्लैण्ड के अंग्रेजों को बड़ा रंज पहुँचा। इससे मिस्र के राष्ट्रवादी दल वफ़द के नेताओं को तो और भी ज्यादा रंज हुआ, क्योंकि वे जानते थे कि इसके फलस्वरूप उनपर हमला किया जायगा। और यह हमला काफ़ी जल्दी सामने आगया। तीन ही दिन के अन्दर, २२ नवम्बर को, मिस्र के ब्रिटिश हाई कमिश्नर लार्ड एलेनबी ने मिस्री सरकार को एक चुनौती दी, जिसमें नीचे लिखी मांगें फौरन पूरी करने को कहा गया :—

१. माफ़ी माँगी जाय,
२. मुजरिमों को सज़ा दी जाय,
३. सब राजनैतिक प्रदर्शन बन्द कर दिये जायँ,

४. ५ लाख पौण्ड हर्जाना दिया जाय,

५. सूडान से २४ घंटे में तमाम मिस्री फ़ौजें हटा ली जायँ,

६. मिस्र के हित की दृष्टि से सूडान में आवपाशी के रकबे पर जो प्रतिबन्ध लगाया गया था वह हटा दिया जाय,

७. मिस्र में सब विदेशियों की रक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार ने जो अधिकार हासिल कर लिया है, उसका आगे कोई विरोध न किया जाय। (इसमें इस बात का खास तौर से इशारा था कि अर्थ, न्याय और आन्तरिक महकमों में ब्रिटिश सत्ता कायम रखी जाय।)

इन सात मांगों पर कुछ गौर किया जाना चाहिए। चूँकि कुछ लोगों ने सर ली स्ट्राक को क़त्ल कर दिया था, ब्रिटिश सरकार फ़ौरन, जाँच की सम्भावना के बिना ही, कुल मिस्री सरकार यानी कुल मिस्री क़ौम के साथ मुजरिम का-सा बर्ताव करने लगी। इसके अलावा इस सारे मामले से उसने खासा आर्थिक लाभ भी उठाया, और सबसे ज्यादा गौर करने की बात यह है कि उसने इस मौक़े का फ़ायदा उठाकर उन सब बातों का ज़वरन तसफ़िया करना चाहा जिनकी बावत उसमें और मिस्री सरकार में मतभेद था और जिनके बारे में कुछ ही महीने पहले लन्दन में सुलह की बातचीत शुरू होकर टूट चुकी थी। फिर उसने इतना ही काफ़ी न समझकर यह भी कहा कि सब राजनैतिक प्रदर्शन निषिद्ध कर दिये जायँ ताकि मुल्क के सामान्य सार्वजनिक जीवन का प्रवाह ही बन्द होजाय।

उस क़त्ल के कारण इतनी मांगों का पेश किया जाना तो एक बड़ी असाधारण बात थी और एक क़त्ल से ब्रिटिश लोगों के लिए इतना फ़ायदा उठाना तो एक बड़े तेज और उपजाऊ दिमाग़ का ही काम था। और इसमें ज्यादा ताज्जुब की बात एक यह भी थी कि अपराध और क़त्ल को रोकने के लिए खास तौर पर ज़िम्मेदार समझे जाने लायक़ दो बड़े अफ़सर (जो नाममात्र को मिस्री सरकार के मातहत थे), यानी काहिरा की पुलिस का अध्यक्ष और सार्वजनिक रक्षा के यूरोपीय विभाग (European Department of Public Safety) का डायरेक्टर जेनरल, अंग्रेज ही थे। क़त्ल के लिए उनको किसी ने ज़िम्मेदार नहीं समझा। लेकिन बेचारे मिस्री शासक-मण्डल पर, जिसने कि क़त्ल के बाद फ़ौरन सख़्त रंज और अफ़सोस ज़ाहिर कर दिया था, ब्रिटिश सरकार का भारी लेकिन बेरहमी से सोचा हुआ और फ़ायदेमन्द गुस्ता दिखाया गया।

मिस्री सरकार ने हद दर्जे की नम्रता प्रकट की। ज़ग़लूलपाशा ने चुनौती की प्ररीब-क़रीब सनी शर्तें मान लीं, और २४ घण्टे में ५ लाख पौण्ड का हर्जाना भी अदा कर दिया। तिरुँ सूडान के बारे में मिस्री सरकार ने कहा कि वह अपना हक़ नहीं छोड़ सकती। लेकिन इतनी नम्रता और मुआफ़ी भी लार्ड एलेनबी के लिए काफ़ी न

थी, और चूँकि सूडान-संबंधी शर्तें मानी नहीं गई थीं, इसलिए अंग्रेजों की तरफ से उसने सिकन्दरिया (एलेजेंड्रिया) के कस्टम्स हाउस यानी चुंगीघर पर जबरन कब्जा कर लिया, और इस तरह चुंगी की आमदनी पर नियन्त्रण प्राप्त कर लिया। फिर, मिस्रवासियों के विरोध करने पर भी, उसने सूडान में इन शर्तों को लागू कर दिया और सूडान को ब्रिटिश वस्ती बना डाला। सूडान में फ्रीज की बग़ावतें भी हुईं, लेकिन उन्हें बेहद सख्ती के साथ दबा दिया गया।

अंग्रेजों की इस कार्रवाई के खिलाफ ज़ग़लूलपाशा और उनकी सरकार ने फ़ौरन इस्तीफ़ा दे दिया, और नवम्बर १९२४ के उसी महीने में शाह फ़ुआद ने पार्लमेण्ट तोड़ दी। इस तरह अंग्रेज लोग ज़ग़लूल और उसके दल 'वफ़द' को उसके पद से निकाल बाहर करने और, कम-से-कम उस वक़्त के लिए ही सही, पार्लमेण्ट को ख़त्म कर देने में कामयाब हो गये। उन्होंने सूडान को अपने राज्य में मिला लिया, और इस तरह सूडान में नील नदी के पानी के नियन्त्रण द्वारा मिस्र का सरलता से गला घोटने की ताक़त हासिल कर ली।

मिस्र की दुखिया पार्लमेण्ट ने एक खेदजनक घटना का साम्राज्यवादी लाभ के लिए दुरुपयोग करने के खिलाफ़ राष्ट्र-संघ में अपील की। लेकिन बड़ी शक्तियों के खिलाफ़ शिकायतों के बारे में तो राष्ट्रसंघ न कुछ सुन सकता है, न देख सकता है।

उस वक़्त से आज तक मिस्र में एक तरफ़ वफ़ददल, जो कि लगभग सारे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, और दूसरी तरफ़ शाह फ़ुआद और ब्रिटिश हाई कमिश्नर के गुट के बीच, जिनका समर्थन अन्य विदेशी स्वार्थी और राज-दरबार के पिछलग्गू करते हैं, लगातार एक कशमकश चली आ रही है। ज्यादातर देश का शासन, राज्य-विधान के विरुद्ध भी डिक्टेटरशाहियों द्वारा चलता रहा है, जिसमें शाह फ़ुआद स्वेच्छाचारी बादशाह की तरह काम करता रहा है। जब कभी पार्लमेण्ट की बैठक होजाने दी गई, तभी फ़ौरन उससे यह जाहिर होगया कि वफ़ददल के साथ क्ररीब-क्ररीब सारा राष्ट्र है, और इसीलिए वह तोड़ दी गई। फ़ुआद की मदद पर अगर अंग्रेज और उनके नियन्त्रण में फ़ौज और पुलिस न होती, तो शायद वह इस तरह का अमल न कर सकता। 'आजाद' मिस्र के साथ लगभग वैसा ही बर्ताव किया जाता है जैसा कि हिन्दुस्तान में किसी देशी रियासत के साथ, जहाँकि असली सत्ता यानी अंग्रेज रेज़िडेंट के इशारों के मुताबिक़ कार्य चलता है।

नवम्बर १९२४ ई० में पार्लमेण्ट तोड़ दी गई। मार्च १९२५ में नई पार्लमेण्ट की बैठक हुई। इसमें वफ़ददल का भारी बहुमत था, और उसने फ़ौरन ज़ग़लूलपाशा को चैंस्लर आफ़ डेप्युटीज के प्रधान-पद के लिए चुन लिया। यह बात न तो अंग्रेजों

को और न शाह फ़ुआद को अच्छी लगी, और इसलिए उसी दिन इस एक दिन की बिल्कुल नई पार्लमेण्ट को तोड़ दिया गया। इसके पूरे एक साल बाद तक, विधान के खिलाफ़ भी, पार्लमेण्ट नहीं बनाई गई और फ़ुआद डिक्टेटर की तरह हुकूमत करता रहा। हाँ, उसके पीछे असली ताक़त थी ब्रिटिश कमिश्नर। सारे देश ने इसपर नाराज़गी जाहिर की, और शाह फ़ुआद और अंग्रेजों के इस गृष्ट का विरोध करने के लिए सैद ज़ग़लूल सब दलों को एक करलेने में कामयाब हुए। नवम्बर १९२५ में सरकारी निषेधाज्ञा की परवा न करते हुए पार्लमेण्ट के मेम्बरों की एक बैठक भी हुई। पार्लमेण्ट-भवन पर तो सैनिकों का क़ब्ज़ा था, इसलिए मेम्बरों को अपनी मीटिंग दूसरी जगह करनी पड़ी।

इस पर फ़ुआद ने अपने महल से एक हुक्मनामा जारी करके सारे विधान को ही बदल डालने की कोशिश की। उसकी मंशा यह थी कि विधान को अधिक अनुदार बना दिया जाय, ताकि पार्लमेण्टों पर ज्यादा आसानी से नियन्त्रण रखा जा सके और अधिकांश ज़ग़लूली लोगों का आना बन्द हो जाय। लेकिन इसके खिलाफ़ जबरदस्त पुकार उठी, और यह जाहिर होगया कि नये तरीक़े के चुनावों का पूरा बहिष्कार किया जायगा। इसपर शाह फ़ुआद को झुकना पड़ा, और पुराने तरीक़े के मुताबिक़ ही चुनाव हुए। नतीजा था ज़ग़लूल के दल का भारी बहुमत, १४ के विरुद्ध २००। इससे ज्यादा इस बात का क्या सबूत हो सकता था कि राष्ट्र पर ज़ग़लूल का कितना असर है और मिला क्या चाहता है? इतना होने पर भी ब्रिटिश कमिश्नर ने (जो कि हिन्दुस्तान के एक भूतपूर्व गवर्नर लार्ड लायड थे) कहा कि उसे ज़ग़लूल के प्रधान मंत्री बनने पर ऐतराज़ है; और इसलिए दूसरा व्यक्ति मुकर्रर किया गया। यह समझना ज़रा मुश्किल है कि अंग्रेजों को इस मामले में दख़ल देने से क्या सरोकार था। फिर भी नई सरकार पर ज्यादातर ज़ग़लूल के दल का ही नियन्त्रण था और बहुत नरम होने की कोशिश करने पर भी वे लोग अक्सर लार्ड लायड के संघर्ष में आजाते थे, जो कि बड़ा सख़्त और ज़ालिम आदमी था और अक्सर उन्हें अंग्रेज़ी जंगी जहाज़ों की धमकी दिया करता था।

ब्रिटेन से समझौता करने की दूसरी कोशिश १९२७ ई० में की गई, लेकिन शाह फ़ुआद का नरम-से-नरम प्रधान मन्त्री भी ब्रिटेन की शर्तों को देखकर ताज़्जुब में पड़ गया। सिर्फ़ क़ाग़ज़ी आजादी के दिखावे के अन्दर उनका असली मज़सद था मिला को अंग्रेज़ी संरक्षण में रखना। इसलिए मुल्ह की बातचीत फिर नाकामयाब रही।

जब ये समझौते की बातें चल रही थीं, तब, २३ अगस्त १९२७ को, सत्तर वर्ष की उम्र में, मिला के महान नेता सैद ज़ग़लूलपाशा की मृत्यु होगई। वह तो मर

गये; परन्तु उनकी स्मृति मिस्र में एक शानदार और कीमती विरासत की तरह अब भी ज़िन्दा है और जनता को स्फूर्ति प्रदान करती रहती है। उनकी पत्नी श्रीमती सक्रिया जगलूल अब भी जीवित है। राष्ट्र उनसे प्रेम और उनका आदर करता है। उसने उन्हें 'राष्ट्र की माता' की पदवी दे दी है और उनका मकान, जो 'पीपल्स हाउस' (जनता का मकान) कहलाता है, एक असें से मिस्र के राष्ट्रवादियों का प्रधान केन्द्र है।

जगलूल के बाद मुस्तफ़ा नहसपाशा 'वफ़द' का नेता बना। बाद में मार्च १९२८ में वह प्रधान मन्त्री बना। उसने नागरिक स्वतन्त्रता और जनता के शस्त्र रखने के अधिकार के बारे में कुछ सीधे-सादे आन्तरिक सुधार करने की कोशिश की। मार्शल-ला के जमाने में इन अधिकारों को अंग्रेजों ने कम कर दिया था। ज्योंही मिस्र की पार्लमेण्ट ने इस सवाल पर गौर करना शुरू किया त्योंही इंग्लैण्ड से धमकियाँ आई कि ऐसा न किया जाय। यह अजीब बात है कि एक बिल्कुल घरेलू मामले में इंग्लैण्ड इस तरह दखल दे। लेकिन अपने पुराने तरीक़े के अनुसार लार्ड लायड ने एक चुनौती पेश कर दी, और माल्टा से ब्रिटिश जंगी जहाज सनसनाते हुए एलेग्ज़ेण्ड्रिया (सिकन्दरिया) के बन्दरगाह में चले आये। नहसपाशा कुछ झुक गया, और उसने इन कानूनों पर विचार कुछ महीने बाद अगले अधिवेशन के लिए स्थगित करना मंजूर कर लिया।

लेकिन अगला अधिवेशन तो होना ही न था। प्रतिक्रिया और साम्राज्यवाद के प्रतिनिधि ने, शाह फ़ुआद और ब्रिटिश कमिश्नर ने, ऐसी योजना की कि आगे पार्लमेण्ट को शरारत करने का मौक़ा ही न मिले। एक अजीब ढंग की साजिश की गई। नहसपाशा अपने उच्च चरित्र और रिश्तत न लेने के लिए खास तौर पर मशहूर था। अचानक एक पत्र के आधार पर, जो बाद में जाली साबित हुआ, नहसपाशा और वफ़द के एक काफ़्टिक नेता पर रिश्ततख़ोरी का इलज़ाम लगाया गया। अदालती क्षेत्रों और अंग्रेजों द्वारा ज़बरदस्त प्रचार किया गया। मिस्र में ही नहीं बल्कि विदेशों में और ब्रिटिश एजेंसियों और अख़बारों के संवाददाताओं ने इस झूठे इलज़ाम को फैलाया। इस इलज़ाम की आड़ लेकर शाह फ़ुआद ने नहसपाशा से प्रधानमन्त्रित्व से इस्तीफ़ा दे देने को कहा। लेकिन उसने ऐसा करने से इन्कार कर दिया, और इसपर उसे फ़ुआद ने बरखास्त कर दिया। लायड-फ़ुआद साजिश की अगली योजना अब अमल में लाई गई। 'सहसा राजनैतिक परिवर्तन' किया गया, और एक खास हुक्मनामा निकालकर शाह ने पार्लमेण्ट को मौकूफ़ कर दिया और विधान को बदल दिया। विधान में जो धारायें अख़बारों की आजादी और दूसरी नागरिक स्वतन्त्रताओं के बारे में प्राचीन मिस्रियों के ईसाई वंशजों को 'काफ़्ट' कहते हैं।

में थीं, उन्हें हटा दिया गया और डिक्टेटरशाही घोषित कर दी गई। अंग्रेजी अखबारों और मिस्र के यूरोपियनों ने बड़ी खुशियाँ मनाई।

डिक्टेटरशाही के होते हुए भी पार्लमेण्ट के मेम्बरों ने अपनी बैठक की और नई सरकार को गैरकानूनी ऐलान कर दिया। लेकिन लायड और फुआद ने इन मामलों की कोई चिन्ता न की। 'इन्साफ़ और अमन' का काम इतना ही होता है कि वह प्रतिक्रिया और साम्राज्यवाद का समर्थन करे, यह नहीं कि उनके विरुद्ध हथियार बन सके।

सरकारी दबाव के बावजूद, नहसपाशा के खिलाफ़ सरकार का मुकदमा बुरी तरह गिर गया। उसपर लगाये हुए इलजाम झूठे साबित हुए और सरकार ने (उसकी ईमानदारी और उदारता कितनी आश्चर्यजनक थी!) हुक्म जारी कर दिया कि इस मुकदमे का फ़ैसला कोई अख़बार न छापे! लेकिन ख़बर तो फ़ौरन फैल ही गई, और हर जगह लोगों को बड़ी खुशी हुई।

इस डिक्टेटरशाही ने, जिसकी पीठ पर लायड और ब्रिटिश फ़्रीज थी, 'वफ़द' दल यानी मिस्री राष्ट्रीयता को कुचल देने और तबाह कर देने की सख्त कोशिश की। एक नियमित आतंकवाद और समाचारों पर पूरा सेंसर क़ायम होगया। इसके बावजूद राष्ट्रीयता के बड़े-बड़े प्रदर्शन हुए, जिनमें स्त्रियों ने ज़ास हिस्सा लिया। एक हफ़्ते तक हड़ताल हुई, जिसमें वकीलों वग़ैरा ने भी हिस्सा लिया, लेकिन सेंसर के कारण अख़बार उसकी ख़बर भी न छाप सके।

इस तरह १९२८ का वर्ष तूफ़ान और मुसीबत में ही गुज़रा। वर्ष के अख़ीर हिस्से में इंग्लैंड में राजनैतिक परिवर्तन हुआ और उसका असर फ़ौरन मिस्र पर भी पड़ा। वहाँ मजदूर-दल की सरकार क़ायम होगई थी, और उसने शुरू में ही एक काम यह भी किया कि लायड को वापस बुला लिया, जो कि ब्रिटिश सरकार के लिए भी असह्य बन गया था। लायड के हटजाने से कुछ वक़्त के लिए फ़ुआद-अंग्रेज़ गुट टूट गया। अंग्रेज़ों की मदद के वग़ैर फ़ुआद कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए उसने दिसम्बर १९२८ में पार्लमेण्ट के नये चुनाव होने दिये। फिर भी 'वफ़द' दल का क़रीब-क़रीब सब जगहों पर क़ब्ज़ा होगया।

अंग्रेज़ों की मजदूर-सरकार ने मिस्र से सुलह की बातचीत फिर शुरू की, और इस काम के लिए १९२९ में नहसपाशा लन्दन गया। इस बार मजदूर-सरकार अपनी पहले की सरकारों से कुछ क़दम आगे बढ़ी और तीनों प्रतिवन्दों पर नहसपाशा का दृष्टिकोण मंज़ूर कर लिया गया। लेकिन चौथी बात—सूडान—की दावत एकमत न हो सका। सुलह की बातचीत टूट गई। मगर इस बार पहले की बनिस्बत ज्यादा एकमत हो सका, और दोनों पक्ष एक-दूसरे के प्रति अधिक मित्रतापूर्ण रहे, और दोनों

ने आगे फिर बहस करने का वादा किया। नहसपाशा और 'वपद' के लिए तो कुल मिलाकर यह एक कामयाबी ही थी, लेकिन मिस्र के ब्रिटिश और दूसरे विदेशी व्यापारियों और पूंजी लगानेवालों ने इस बात को बिल्कुल पसन्द नहीं किया। शाह फ़ुआद को भी यह बात अच्छी न लगी। कुछ महीने बाद, जून १९३० में, शाह और पार्लमेण्ट में झगड़ा होगया, और नहसपाशा ने प्रधानमंत्रित्व से इस्तीफ़ा दे दिया।

इस झगड़े के असें में फ़ुआद ने फिर अपने शासन-काल में तीसरी बार डिक्टेटरशाही चलाई। पार्लमेण्ट तोड़ दी गई, 'वपद'दल के अख़्तियार बन्द कर दिये गये, और आमतौर पर बड़ी सत्ती शुरू होगई। पार्लमेण्ट की दोनों उप-सभाओं, चैम्बर और सिनेट, के सभी सदस्यों ने सरकार की परवा न की, और पार्लमेण्ट-भवन में ज़बरदस्ती घुसकर वहाँ एक अधिवेशन कर डाला। वहाँ, २३ जून १९३० को, उन्होंने विधान के प्रति वफ़ादार रहने की शपथ गंभीरतापूर्वक ली, और क़सम खाई कि हम अपनी सारी ताक़त लगाकर भी उसकी रक्षा करेंगे। देशभर में बड़े-बड़े प्रदर्शन किये गये। इन प्रदर्शनों को फ़ौजों द्वारा भंग किया गया, और बहुत-सा खून वहाया गया। ख़ुद नहसपाशा के भी चोटें आईं। इस तरह कुछ मुद्ठीभर बड़े और मालदार लोगों को छोड़कर, जो शाह के पिछलग्गू थे, सारा राष्ट्र जिस डिक्टेटरशाही के खिलाफ़ था, उसकी हिफ़ाज़त फ़ौज और पुलिस और उसके अंग्रेज़ अफ़सरों ने की। वपिदियों के अलावा दूसरे नरम और लिबरल लोगों ने भी, जोकि हिन्दुस्तान की तरह जनता की तरफ़ से होनेवाले हर तेज़ काम से अपना विरोध जाहिर करते रहते थे, इस डिक्टेटरशाही के खिलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद की।

बाद में, उसी साल, सन् १९३० में, शाह ने एक हुक्मनामा निकाला जिसके जरिये एक नये विधान का ऐलान किया गया, जिसमें उसने पार्लमेण्ट के अधिकार कम कर दिये और अपने बढ़ा लिये। ऐसा काम कर लेना कितना आसान था ! सिर्फ़ एक ऐलान कर दिया गया और काम होगया, क्योंकि शाह के पीछे एक साम्राज्यवादी ताक़त की कठोर मूर्ति छिपी हुई थी।

मैंने मिस्र के १९२२ से १९३० तक के इन नौ वर्षों की कहानी तुमसे कुछ विस्तार में कही है, क्योंकि मुझे यह एक बड़ी ग़ैर-मामूली कहानी मालूम हुई है। अंग्रेज़ों के फरवरी १९२२ के ऐलान के मुताबिक, ये वर्ष मिस्र की 'आजादी' के वर्ष थे। मिस्री लोग क्या चाहते थे इसमें भी कोई शंका नहीं हो सकती थी। जब कभी उन्हें अवसर दिया गया तभी उन्होंने मुस्लिम और काष्ट, इन दोनों धर्म के लोगों ने, भारी बहुमत से वपिदियों को ही चुना। लेकिन चूँकि वे यही चाहते थे कि राष्ट्र का अर्थ-शोषण करने की विदेशियों की, खासकर ब्रिटिश लोगों की, ताक़त कम करदी जाय,

इसलिए इन सब विदेशी स्थापित स्वार्थों ने हर तरह से, जोर और जबरदस्ती से, जालसाजी और षड्यन्त्र से, उनका विरोध किया, और अपने हुक्मों को पूरा करने के लिए अपना एक आज्ञाकारी शाह खड़ा कर दिया।

वफ़द-आन्दोलन एक विशुद्ध राष्ट्रवादी मध्यमवर्गीय आन्दोलन रहा है। वह क़ौमी आजादी के लिए लड़ा, लेकिन उसने सामाजिक समस्याओं में दखल नहीं दिया। जब कभी पार्लमेण्ट ने कुछ भी कार्य किया, तब-तब उसने तालीम व दूसरे महकमों में कुछ अच्छा ही काम कर दिखाया। दरहकीकत, राष्ट्रीय लड़ाई चलते हुए भी, इस थोड़े-से असें में पार्लमेण्ट ने इतना काम किया जितना कि पिछले चालीस सालों में ब्रिटिश हुकूमत ने नहीं किया था। वफ़द-दल किसानों में भी लोकप्रिय है, जैसा कि चुनावों और बड़े-बड़े प्रदर्शनों से जाहिर होजाता है। लेकिन फिर भी, चूँकि यह आन्दोलन त्रास तौर पर मध्यम-वर्गीय आन्दोलन है, उसने आम जनता को इतना नहीं उठाया है जितना कि सामाजिक परिवर्तन का उद्देश्य रखनेवाला कोई आन्दोलन उठा सकता था।

मैंने यह कहानी १९३० के अख़ीर तक पहुँचा दी है। बाद में भी राष्ट्रवादियों और शाह में कशनकश चलती रही, लेकिन ठीक तौर पर मुझे मालूम नहीं है कि पिछले वर्षों में क्या-क्या हुआ। जबसे मैं जेल में हूँ तबसे अख़बारों में तो मिस्त्र का शायद ही कहीं जिक्र आता हो। शायद इसका मतलब यही है कि डिक्टेटरशाही चल रही है, और उसके साथ उसका लँगोटिया यार सेन्सर भी। इस बात का कि इंग्लैण्ड में अनुदार-दल की हुकूमत है, जो कि अपने साम्राज्यवाद पर अभिमान करता है, अर्थ यही है कि मिस्त्र में अंग्रेजों की दमन करने की सख्त नीति होनी चाहिए। इस हालत में शाह फ़ुआद दुःखी मिस्त्री लोगों की परवा न करते हुए फ़िलहाल तो काम जारी रख सकता है।

इस प्रकार ख़त को ख़त्म करने से पहले मैं स्त्रियों के आन्दोलन के बारे में भी कुछ कहना जरूरी समझता हूँ। सारे अरब देशों में, शायद खुद अरब को छोड़कर, स्त्रियों में दड़ी भारी जागृति होगई है। दूसरे कई मामलों की तरह इस मामले में भी मिस्त्र इराक़ या सीरिया या फिलस्तीन से आगे बढ़ा हुआ है। लेकिन इन सब देशों में स्त्रियों का एक संगठित आन्दोलन है, और जुलाई १९३० में अरब स्त्रियों की पहली कांग्रेस दमिस्क में हुई। उन्होंने राजनैतिक मामलों की वनिस्वत संस्कृतिक और सामाजिक प्रगति पर ज्यादा जोर दिया। उन्होंने अरबी स्वदेशीवाद की घोषणा की है। मिस्त्र में स्त्रियाँ राजनीति की तरफ़ ज्यादा झुकी हैं। वे राजनैतिक प्रदर्शनों में हिस्सा लेती हैं और उनका एक मजदूत स्त्री-भताधिकार-संघ भी है। वे विवाह-

क्रान्त का अपने हक में सुधार और व्यवसाय आदि में समान अवसर चाहती हैं। मुस्लिम और ईसाई स्त्रियाँ एक-दूसरे से पूरी तरह सहयोग करती हैं। दुरके की आदत सब जगह, खासकर मिस्र में, घट रही है। तुर्की की तरह दुर्का बिलकुल गायब तो नहीं होगया है, लेकिन टूटता जा रहा है।

: १६५ :

पश्चिमी एशिया का विश्व-राजनीति में पुनः प्रवेश

२५ मई, १९३३

एक छोटी-सी जलधारा ही मिस्र और अफ़रीका को पश्चिमी एशिया से अलग करती है। अब इस स्वेज़ नहर को हम पार करें और अरब, फिलिस्तीन, सीरिया और इराक़—जो कि सभी अरब-देश हैं—और उनसे ज़रा आगे ईरान पर एक नज़र डालें। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, इतिहास में पश्चिमी एशिया का एक ज़बरदस्त हिस्सा रहा है और अक्सर यह दुनिया की घटनाओं की धुरी रहा है। इसके बाद कई सौ वर्षों का एक ऐसा ज़माना आया, जब यह प्रदेश महत्वपूर्ण नहीं रहा। यह एक खाई या गड़हिया-सा बन गया; जीवन की धारा इसके पास से हरहराती हुई निकल गई, लेकिन इसकी शान्त सतह पर उससे कोई हलकी-सी लहर तक पैदा न हुई। और अब हम एक दूसरी तब्दीली देख रहे हैं जो 'मध्य-पूर्व' के देशों को फिर संसार की रंगभूमि पर लाती है। पूर्व और पश्चिम को जोड़नेवाला राजमार्ग अब फिर इन्हीं देशों में से होकर गुज़रने लगा है। इस बात की तरफ़ हमारा ध्यान जाना चाहिए।

जब कभी मैं पश्चिमी एशिया का विचार करने लगता हूँ तो मुझे भूतकाल में डूब जाने का अंदेशा रहता है। मेरे दिमाग में प्राचीन काल के इतने चित्र भर जाते हैं कि मैं उनके आकर्षण को रोक नहीं सकता। लेकिन अब मैं अपने आप को इन आकर्षणों में न फँसने दूँगा। फिर भी मैं तुम्हें यह याद दिलाना ज़रूरी समझता हूँ, ताकि तुम भूल न जाओ कि इतिहास के बिलकुल प्रारम्भ से ही कई हजार वर्षों तक दुनिया के इस हिस्से का बड़ा भारी महत्व रहा है। इतिहास में सात हजार वर्ष पहले प्राचीन चैल्डिया का धुंधला चित्र दिखाई देता है। यहाँ आजकल का इराक़ है। इसके बाद बेबीलोन का चित्र आता है और बेबीलोन वालों के बाद क्रूर असीरियन नज़र आते हैं जिनकी महान् राजधानी निनैवा में थी। फिर असीरियन लोगों की भी हटने की वारी आजाती है, और ईरान से एक नया राजवंश और नई जाति आजाती है, जो हिन्दुस्तान की सरहद से मिस्र तक सारे 'मध्य-पूर्व' को अपनी मर्जी के मुताबिक

नचाती हैं। ये लोग ईरान के अकेमेनीद थे, जिनकी राजधानी परसीपोलिस थी। इन्हींमें से 'महान् नरेश' माइरस, डेरियस (दारा) और जरक्सीज पैदा हुए, जिन्होंने छोटे यूनान पर हावी होने की कोशिश की, लेकिन उसे जीत न सके। बाद में इन्हें यूनान बल्कि मेसीडोनिया के एक लाल सिकन्दर के हाथों शिकस्त खानी पड़ी। सिकन्दर की जिन्दगी में एक अजीब घटना यह हुई कि इस एशिया और योरप की सन्धि-भूमि में उसने वह योजना की, जिसे इन दोनों महाद्वीपों का 'विवाह' कहा जाता है। उसने खुद ईरानी बादशाह की लड़की से विवाह किया (हालांकि उसकी कुछ पत्नियाँ पहले से मौजूद थीं) और उसके हजारों अफसरों और सिपाहियों ने भी ईरानी कन्याओं से विवाह किये।

सिकन्दर के बाद मध्य-पूर्व में, हिन्दुस्तानी सरहद से लेकर मिस्र तक, कई सदियों तक यूनानी संस्कृति प्रधान रही। इसी जमाने में रोम की शक्ति का उदय हुआ और वह एशिया की तरफ फैलने लगी। सासानियों के नये ईरानी साम्राज्य ने उसकी बढ़ती को रोक दिया। पूर्वी साम्राज्य के भी दो टुकड़े होगये, पश्चिमी साम्राज्य और पूर्वीय साम्राज्य, और पूर्वी साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया होगई। पश्चिमी एशिया के इन मैदानों पर पूर्व और पश्चिम की पुरानी कशमकश चलती रही, और इसमें खास हिस्सा लेनेवाले थे एक तो कुस्तुनतुनिया का विजेण्टाइन साम्राज्य और दूसरा ईरानी सासानी साम्राज्य। और इसी सारे जमाने में जनता के बड़े-बड़े कारवान ऊँटों पर व्यापारिक चीजें लाद कर इन मैदानों में पूर्व से पश्चिम को और पश्चिम से पूर्व को आया-जाया करते थे, क्योंकि 'मध्य-पूर्व' उस युग में संसार का एक बड़ा भारी राजमार्ग था।

पश्चिमी एशिया के इन प्रदेशों में तीन महान् धर्मों का जन्म हुआ था—यहूदी-धर्म, जरथुस्त्रधर्म (जो मौजूदा पारसियों का धर्म है), और ईसाई-धर्म। अब अरब के रेगिस्तान में एक चौथा धर्म और पैदा हुआ, जो जल्दी ही दुनिया के इस हिस्से में इन सब धर्मों पर हावी होगया। इसके बाद हमें बाग़दाद का अरब साम्राज्य और पुराने संपर्क का एक नया रूप, विजेण्टाइन के विरुद्ध अरब लोगों का युद्ध, नज़र आता है। फिर लम्बे और शानदार कारनामों के बाद अरब-संस्कृति भी मन्द पड़ जाती है। और सेलजूक तुर्क आगे आजाते हैं, और अन्त में मंगोल चंगेजखाँ के वारिसों द्वारा वह बिल्कुल दबा दी जाती है।

लेकिन मंगोलों के पश्चिम में आने से पहले ही, एशिया के पश्चिमी किनारों पर ईसाई पश्चिम और मुस्लिम पूर्व के दरमियान ख़ौफ़नाक लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी थी। ये क्रूसेड के युद्धों के नाम से मशहूर हैं, जो बीच-बीच में बन्द होकर टाई

सौ वर्ष तक, यानी क़रीब तेरहवीं सदी के मध्य तक, जारी रहे। ये युद्ध धर्म-युद्ध समझे जाते हैं, और असल में थे भी। लेकिन इन युद्धों के लिए धर्म कारण की बनिस्बत बहाना ही ज्यादा था। उस ज़माने में योरप के लोग पूर्व की बनिस्बत पिछड़े हुए थे। वह योरप का अन्धकारयुग था। लेकिन योरप जागता जा रहा था, और आगे बढ़ा हुआ और सभ्य पूर्व उसे चुम्बक की तरह खींचता जा रहा था। पूर्व की तरफ़ की इस खिंचावट ने कई शकलें इख़्तियार कीं, और इसमें क्रूसेड की लड़ाई सबसे महत्वपूर्ण थी। इन युद्धों के फलस्वरूप योरप ने पश्चिमी एशियाई देशों से बहुत बातें सीखीं। उसने बहुत-सी ललित कलायें, कारीगरियाँ और विलास की आदतें सीखीं, और अधिक महत्वपूर्ण बात जो सीखीं वे थीं कार्य और विचार की वैज्ञानिक पद्धतियाँ।

क्रूसेड की लड़ाइयाँ अभी ख़त्म भी न होने पाई थीं कि पश्चिमी एशिया पर मंगोल लोग आ दूटे, जो अपने साथ विनाश और बरबादी लेकर आये। लेकिन हमें मंगोलों को बिल्कुल विनाशक ही नहीं समझना चाहिए। चीन से रूस तक भारी तादाद में जाने की उनकी हलचल ने दूर-दूर की जातियों में आपसी ताल्लुकात कायम कर दिये और व्यापार और समागम को प्रोत्साहित किया। उनके महान् साम्राज्य में कारवानों के पुराने रास्ते मुसाफ़िरी के लिए महफूज़ होगये, और सिर्फ़ व्यापारी ही नहीं बल्कि राजनीतिज्ञ, धर्म-प्रचारक और दूसरे लोग भी बड़ी लम्बी यात्राओं पर आने-जाने लगे। 'मध्य-पूर्व' संसार के इन प्राचीन राजमार्गों की सीध में पड़ता था। यही एशिया और योरप को जोड़नेवाली कड़ी थी।

तुम्हें शायद याद होगा कि मंगोलों के ज़माने में ही मार्कोपोलो अपने निवास-स्थान वेनिस से बड़ी लम्बी यात्रा करके एशिया में से गुज़रता हुआ चीन पहुँचा था। हमें उसकी लिखी हुई, या यों कहो कि लिखाई हुई, एक किताब मिलती है, जिसमें उसने अपनी यात्रा का हाल बताया है और इसीलिए हम उसका नाम जानते हैं। और भी कई लोगों ने ऐसी ही लम्बी यात्रायें की होंगी, लेकिन उन्होंने उनके बारे में कुछ लिखा नहीं, और अगर लिखा भी होगा तो उनकी किताबें नष्ट होगई होंगी, क्योंकि उस ज़माने में किताबें हाथ से लिखी जाती थीं। उस युग में एक देश से दूसरे देश में कारवान हमेशा आते-जाते रहते थे, और हालाँकि उनका ख़ास काम व्यापार था, लेकिन उनके साथ कई लोग दौलत पैदा करने या साहसी काम करने के लिए भी चले जाते थे। पुराने ज़माने का एक और यात्री है जो मार्कोपोलो जैसा ही है। इसका नाम था इब्न-बतूता। यह एक अरब था, जिसका जन्म चौदहवीं सदी के शुरू में मोरक्को के टैंज़िंजर नामक स्थान पर हुआ था। इस तरह वह मार्कोपोलो से

एक ही पीढ़ी बाद हुआ। मेरा खयाल है कि मैंने इसका जिक्र अपने पिछले खतों में कहीं किया है। उस वक्त मैंने उसकी यात्राओं की पुस्तक नहीं पढ़ी थीं। हाल में ही मैंने यह किताब पढ़ली है, और पढ़ते वक्त मैं उसके भ्रमण-प्रेम को, जिसे जर्मन लोग भ्रमण-पिपासा यानी सैलानीपन कहते हैं, देखकर दंग रह गया। इक्कीस वर्ष की छोटी-सी उम्र में वह इस विस्तृत दुनिया के लम्बे सफ़र के लिए निकल पड़ा, और उसके पास सिवा अपनी बुद्धिमत्ता और एक मुसलमान काजी से पाई हुई तालीम के और कुछ न था। मोरक्को से सारा उत्तरी अफ़्रीका पार करके वह मिस्र पहुँचा, और फिर अरब, सीरिया और ईरान को गया। फिर उसने अनातोलिया (तुर्की), दक्षिणी रूस (जो 'सुनहरे कबीलों' के मंगोल खानों के अधीन था), और क्रुस्तुनुनिया (जो उस समय भी विजेण्टियम की राजधानी थी) और एशिया और हिन्दुस्तान के सफ़र किये। उसने हिन्दुस्तान को उत्तर से दक्षिण तक पार किया, मलाबार और लंका गया, और वहाँ से चीन पहुँचा। लौटने पर वह अफ़्रीका के आसपास सफ़र करता रहा, और सहारा का रेगिस्तान भी पार किया! यह भ्रमण का इतना बड़ा रिकार्ड है कि आजकल की हमारी तमाम सहूलियतें होते हुए भी इस ज़माने में काफ़ी दुर्लभ है। चौदहवीं सदी के पहले आधे हिस्से के बारे में तो यह आश्चर्यजनक रूप से हमारी आँखें खोल देता है। इससे पता लगता है कि उस ज़माने में सफ़र करने का कैसा आम रिवाज था। कुछ भी हो, इन्न-वतूता सभी युगों के महान् यात्रियों में गिना जाना चाहिए।

इन्न-वतूता की किताब में जहाँ-जहाँ वह गया वहाँ-वहाँके लोगों और देशों के बारे में बड़े दिलचस्प बयान हैं। उस ज़माने में मिस्र दौलतमन्द था, क्योंकि पश्चिम के साथ होनेवाली सारी हिन्दुस्तानी तिजारात उसके अन्दर से गुज़रती थी, और यह बड़े मुनाफ़े का व्यापार था। इन्हीं मुनाफ़ों से काहिरा एक बड़ा शहर बना हुआ था, जिसमें सुन्दर-सुन्दर स्मारक थे। इन्न-वतूता कहता है कि हिन्दुस्तान में जातियाँ थीं, 'सती-प्रथा' थी, और 'पान-नुपारी' देने का रिवाज था। वह बताता है कि हिन्दुस्तानी व्यापारी विदेशी बन्दरगाहों में जाकर भारी व्यापार करते थे, और समुद्रों पर हिन्दुस्तानी जहाज़ आया-जाया करते थे। वह खास तौर पर देखता है और बयान करता है कि सुन्दर स्त्रियाँ कहीं-कहीं हैं, और उनकी वेश-भूषा, उनके गंध और उनके आभूषण कैसे हैं। वह दिल्ली के बारे में लिखता है कि यह "हिन्दुस्तान की राजधानी है; बड़ा भारी और शानदार शहर है, जहाँ सुन्दरता और शक्ति आकर इकट्ठी होगई है।" यह पागल सुलतान मुहम्मद तुग़लक़ का ज़माना था, जिसने कि गुस्ते में आकर अपनी राजधानी दिल्ली से दक्षिण के दौलताबाद को तब्दील कर दी थी, और इस

तब इस "बड़े भारी और शानदार शहर" को एक रेगिस्तान—"थोड़ेसे निवासियों के सिवा, सारा खाली और वीरान"—बना दिया था, और ये थोड़े-से निवासी भी बहुत बाद में चुपचाप आकर रहने लगे थे।

मैंने इन्-बतूता का सरसरी तौर पर ही बयान करने की कोशिश की है। पुराने जमाने की ये भ्रमण-कहानियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं।

इस तरह हम देखते हैं कि चौदहवीं सदी तक 'मध्य-पूर्वी' या पश्चिमी एशिया का दुनिया के मामलों में बड़ा हिस्सा था, और वह पूर्व और पश्चिम को जोड़नेवाली खास कड़ी थी। लेकिन इसके अगले सौ वर्षों में हालत बदल गई। उस्मानी तुर्कों ने क्रुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया और वे मध्य-पूर्व के इन सारे देशों में, और भिन्न-भिन्न में भी, फैल गये। उन्होंने योरप के साथ होनेवाले व्यापार की तरक्की नहीं की। शायद इसका एक सबब यह भी था कि यह व्यापार उनके भूमध्यसागर के प्रतिस्पर्धी वेनिस और जिनोवा-वासियों के हाथ में था। व्यापार का रास्ता भी बदल गया, क्योंकि अब नये समुद्री रास्ते खोज निकाले गये थे और उन्होंने कारवान के पुराने खुशकी रास्तों की जगह लेली थी। इस तरह पश्चिमी एशिया में से गुजरनेवाले इन रास्तों का, जिन्होंने कई हजार वर्षों तक बड़ा काम दिया था, इस्तेमाल बन्द होगया, और जिन देशों में से वे गुजरते थे वे भी रंग-भूमि के केन्द्र से दूर जा पड़े।

सोलहवीं सदी के शुरु से उन्नीसवीं सदी के अखीर यानी करीब चार सौ वर्ष तक, समुद्री रास्ते बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहे और वे खुशकी के रास्तों पर हावी होगये—खासकर वहाँ जहाँ रेलें नहीं थीं। और पश्चिमी एशिया में तो रेलें थीं ही कहाँ? महायुद्ध से कुछ पहले क्रुस्तुनतुनिया से बगदाद तक रेल बनाने की एक योजना बनाई गई थी, जिसका समर्थन जर्मन सरकार करती थी। दूसरी ताकतें जर्मनी की इस योजना से बहुत जलती थीं, क्योंकि इससे मध्य-पूर्व में जर्मन प्रभाव बढ़ने की संभावना थी। लेकिन इसी बीच युद्ध आ गया।

१९१८ में जब महामुद्ध खत्म हुआ, तो पश्चिमी एशिया में ब्रिटेन ही सबसे जबरदस्त ताकत थी और, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, थोड़े समय तक तो ब्रिटिश राजनीतिज्ञों की चकित आँखों के आगे हिन्दुस्तान से लेकर तुर्की तक एक बड़े मध्य-पूर्वीय साम्राज्य का सुन्दर सपना दिखाई देता रहा। लेकिन वह पूरा न हो सका। बोल्शेविक रूस और कमालपाशा और दूसरे कारणों ने उस सपने के पूरा होने में बाधा डालदी। फिर भी इंग्लैण्ड एक काफ़ी बड़े टुकड़े पर तो कब्जा जमाये ही रहा। इराक़ और फ़िलस्तीन ब्रिटिश नियन्त्रण में हैं (हालांकि भिन्न की तरह इराक़ भी आजाद समझा जाता है); सीरिया फ़्रांसीसियों के मातहत है; ईरान

और अरब बहुत कुछ आजाद देश हैं। इस तरह हालाँकि ब्रिटिश लोग अपनी बड़ी महत्वाकांक्षा को पूरा न कर सके, फिर भी वे हिन्दुस्तान को जानेवाले रास्तों पर कब्जा रखने की अपनी पुरानी नीति पर जमे रहने में कामयाब रहे। इसी उद्देश्य से ब्रिटिश फ़ौजों ने महायुद्ध के ज़माने में मेसोपोटामिया और फ़िलस्तीन में लड़ाइयाँ लड़ी थीं और तुर्की के खिलाफ़ अरबी बगावत को प्रोत्साहन और मदद दी थी। इसी कारण इंग्लैण्ड और तुर्की में युद्ध के बाद मोसल की बाबत बड़ा झगड़ा खड़ा हो गया था। और इंग्लैण्ड और सोवियट रूस के मन-मुटाव का भी यही खास कारण है, क्योंकि इंग्लैण्ड इस ख़याल से नफ़रत करता है कि रूस जैसी बड़ी ताक़त हिन्दुस्तान के रास्ते के पड़ौस में ही रहे।

महायुद्ध से पहले जिन दो रेलवे लाइनों बग़दाद-रेलवे और हेजाज़-रेलवे—की बाबत इतना झगड़ा था, वे अब बन चुकी हैं—बग़दाद-रेलवे भूमध्यसागर और योरप को बग़दाद से जोड़ती है। हेजाज़-रेलवे अरब के मदीना शहर को बग़दाद-रेलवे से अलप्पो पर मिलाती है। (हेजाज़, जिसमें इस्लाम के पवित्र नगर मक्का और मदीना हैं, अरबस्तान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है।) इस तरह पश्चिमी एशिया के कई महत्वपूर्ण शहर रेल के जरिये योरप और मिस्र से जुड़ गये हैं और उन तक पहुँचना आसान होगया है। अलप्पो का शहर एक महत्वपूर्ण रेलवे-जंक्शन बनता जा रहा है, क्योंकि तीन महाद्वीपों की रेलें—योरप से आने वाली लाइन, एशिया से बग़दाद होकर आनेवाली लाइन और अफ़्रीका से काहिरा होकर आनेवाली लाइन—वहीं आकर इकट्ठी होनेवाली हैं। ब्रिटिश नीति का उद्देश्य बड़े अरसे से एशिया और अफ़्रीका के इन रास्तों पर नियन्त्रण करना रहा है। एशियाई मार्ग अगर बग़दाद से आगे बढ़ा दिया जाय तो हिन्दुस्तान तक पहुँच सकता है। अफ़्रीकन मार्ग अफ़्रीका महाद्वीप के आर-पार कैरो से दक्षिण में केपटाउन तक जायगा ही। केपटाउन से काहिरा तक खिंची हुई रेलवे की पूर्ण लाल रेखा का स्वप्न ब्रिटिश साम्राज्यवादी बहुत समय से देख रहे हैं, और अब वह पूर्ण होने के करीब आ पहुँचा है—‘पूर्णलाल’ का अर्थ यह है कि वह सारे रास्ते भर अंग्रेज़ी इलाक़े में से गुज़रती हुई जाय, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य ने नक़शे में लाल रंग पर अपना एकाधिकार कर लिया है।

लेकिन, पता नहीं भविष्य में ये बातें पूरी हों या न हों, क्योंकि अब मोटर-कारों और हवाईजहाज़ों के रूप में रेलवे के ज़बरदस्त दुश्मन खड़े होगये हैं। यह भी मुमकिन है कि इन स्वप्नों के पूरे होने से पहले ही खुद ब्रिटिश साम्राज्य ही ख़तम होजाय। इस बीच, यह याद रखने लायक़ है कि पश्चिमी एशिया में बग़दाद और हेजाज़ की इन दोनों, नई रेलों पर ज्यादातर अंग्रेज़ों का ही नियन्त्रण है, और

वे अपने नियन्त्रण के अधीन, हिन्दुस्तान के लिए नया और छोटा रास्ता खोलने की ब्रिटिश नीति का उद्देश्य पूरा करती हैं। बरादाद-रेलवे का एक हिस्सा सीरिया में से गुजरता है, जो फ्रांसीसियों के नियन्त्रण में है। फ्रांस की इस अधीनता को बुरा समझकर, ब्रिटिश अब उसकी जगह एक नई लाइन फिलिस्तीन में से बनाना चाहते हैं। एक और छोटी-सी रेलवे अरबिस्तान में लालसागर के बन्दरगाह, जद्दाह और मक्का के बीच बन रही है। इससे हर साल लाखों की तादाद में मक्का जानेवाले यात्रियों को बड़ा आराम होजायगा।

इन रेलों के बारे में, जोकि पश्चिमी एशिया को संसार के लिए खोल रही हैं, इतना बयान किया गया। लेकिन अपने उद्देश्य को पूरा करने से पहले ही इन रेलों का महत्व कुछ कम हो रहा है, क्योंकि उनकी जगह मोटरकारों और हवाईजहाज आ रहे हैं। मोटरकार बहुत जल्दी रेगिस्तान के अनुकूल बन गई हैं, और जिन कारवानी रास्तों से पहले हजारों वर्ष तक धैर्यशाली ऊँट धीरे-धीरे चलते रहे हैं उन्हींपर वह अब सरपट दौड़ी जाती है। रेल बड़ी खर्चीली चीज है और उसके बनाने में बहुत लगता है। लेकिन मोटर में खर्च कम लगता है, और जब जरूरत हो तभी वह चलाई जा सकती है। लेकिन मोटर-कारों और लारियाँ आम तौर पर ज्यादा दूरी तक काम नहीं देती। वे अपेक्षाकृत छोटे रकबों में, ज्यादा-से-ज्यादा एक सौ मील तक, आती-जाती हैं।

ज्यादा दूरी के लिए तो हवाई जहाज है ही। इसमें भी रेल से कम खर्च पड़ता है और उससे कहीं ज्यादा तेज चलता है। इसके लिए सड़क या रास्ता बनाना नहीं पड़ता। इसमें संदेह नहीं हो सकता कि सवारियाँ या माल लाने-लेजाने के लिए अब वायुयानों का उपयोग तेजी से बढ़ता जायगा। अबतक भी बहुत भारी तरक्की हो चुकी है, और एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक बड़े-बड़े जहाज नियमित रूप से जाते रहते हैं। पश्चिमी एशिया फिर इन महान् वायु-मार्गों का सम्मेलन-स्थान बन रहा है, और बरादाद खासतौर पर इन सब का केन्द्र है। अब तो ब्रिटिश इम्पीरियल एयरवेज नामक कम्पनी के नियमित साप्ताहिक हवाई जहाज योरप को पार करते हुए बरादाद आया करते हैं और वहाँसे हिन्दुस्तान आते हैं। आजकल वे कराची पर रुक जाते हैं, लेकिन उनका सम्बन्ध दिल्ली और बम्बई और मद्रास को जानेवाली हवाई सरविसों से है। यह तजवीज भी की जा रही है कि इन हवाई जहाजों के सिलसिले को कलकत्ता, रंगून और सिंगापुर तक बढ़ाया जाय, और वहाँसे एक शाखा हांगकांग जाय और दूसरी फूटकर आस्ट्रेलिया चली जाय।

ब्रिटिश हवाई मार्ग की एक दूसरी योजना है लंदन से काहिरा तक, और वहाँ

से आगे पूर्वी अफ्रीका होते हुए केपटाउन तक (मुझे मालूम नहीं कि आजकल यह मार्ग जारी होगया है या नहीं) । यह सारा रास्ता भी क़रीब-क़रीब ब्रिटिश इलाक़े में से होकर ही जायगा । इस तरह तुम्हें मालूम होगा कि अंग्रेज़ों की हवाई योजनाएँ कल्पना में बहुत बड़ी-बड़ी हैं । उनका फैलाव योरप, एशिया और अफ्रीका तीनों महाद्वीपों में और आस्ट्रेलिया तक है । यह सब उनके साम्राज्य के कारण जरूरी होगया है । पहले ज़माने में उनके लिए समुद्री ताक़त जरूरी थी, और उन्होंने समुद्रों पर बहुत अर्से तक क़ब्ज़ा रक्खा । लेकिन अब तो समुद्री ताक़त का महत्व बहुत कम होगया है । आजकल इंग्लैंड के टापू की रक्षा समुद्री ताक़त से भी निश्चित नहीं रही । क्योंकि हवाई जहाज़ों के लिए तो समुद्रों को पार करना और बसों से शहरों और कारख़ानों को बरबाद कर देना बड़ा ही आसान है । अगर खुद इंग्लैंड पर हवाई हमले का ख़तरा रहता है, तो बड़े भारी फ़ैले हुए साम्राज्य पर तो और भी ख़तरा होना चाहिए । इसीलिए हवाई ताक़त का महत्व होगया है । हर बड़ी ताक़त अब हवा में प्रबल बनने की इच्छा कर रही है, और पुरानी समुद्री प्रतिस्पर्धा के स्थान पर अब हवाई प्रतिस्पर्धा होने लगी है । हर देश शान्ति-कालीन हवाई सफ़र को प्रोत्साहन और सहायता दे रहा है, क्योंकि इससे सुशिक्षित हवाई जहाज़-चालकों का एक दल तैयार हो-जाता है, जो युद्ध के वक़्त में भी काम दे सकेगा । इसे फ़ौजी वायु-यात्रा, जिसका ताल्लुक सिर्फ़ लड़ाई करने और बम फेंकने से ही होता है, न कहकर मुल्की या 'सिविल' वायु-यात्रा कहते हैं । सच तो यह है कि जब भी संकट आये, शान्तिकालीन सफ़री हवाई जहाज़ों में युद्ध-सम्बन्धी चीज़ें जोड़कर उन्हें बड़ी आसानी से लड़ाई के लायक बनाया जा सकता है ।

'सिविल' या मुल्की वायु-यात्रा की तरक्की के लिए जिस तरह ब्रिटेन की बड़ी-बड़ी योजनायें हैं, उसी तरह दूसरी साम्राज्यवादी शक्तियों की भी हैं । फ़्रांसीसी हवाई जहाज़ पेरिस-मार्सलीज़ या मर्सई-वेरत से जाते हैं, बग़दाद पहुँचते हैं, और वहाँसे हिन्दुस्तान और इंडो-चाइना के सैगोन नगर को जाते हैं । फ़्रांस की दूसरी हवाई सरविसें भूमध्यसागर और सहारा रेगिस्तान के उत्तपार भी जाती हैं । हालैंड की भी एक नियमित सरविस एम्स्टर्डम से जावा के बटेविया शहर जाती है, जो बग़दाद और हिन्दुस्तान में से गुज़रती है । मेरा ख़याल है कि शायद तुमने इलाहाबाद के पास दमरौली में उनके दड़े-बड़े हवाई जहाज़ देखे होंगे, क्योंकि हिन्दुस्तान में से गुज़रनेवाली ये बड़ी-बड़ी सरविसें ज़्यादातर सभी इलाहाबाद होकर जाती हैं ।

मुझे इस ख़त में इस वक़्त दुनिया में चलनेवाली तमाम हवाई सरविसों की फ़ेहरिस्त नहीं देना है । आजकल तो ऐसी सैकड़ों सरविसें चल रही हैं, और योरप

और उत्तरी अमेरिका में तो कोई भी क़रीब-क़रीब सभी जगह हवाई जहाज़ से जा सकता है। मैं यहाँ तुम्हारा ध्यान इस बात की तरफ़ खींच रहा हूँ कि पश्चिमी एशिया, जहाँ कि कई लम्बी-लम्बी हवाई लाइनें आकर मिलती हैं, अचानक हवाई यात्रा के क्षेत्र के रूप में कितना महत्वपूर्ण बन गया है। तुम देखोगी कि कितने हवाई मार्ग आकर बग़दाद में मिलते हैं। और भी कई लाइनें हैं जिनका मैंने ज़िक्र नहीं किया है, मसलन, मास्को से एक लाइन बाकू जाती है, वहाँसे बग़दाद जाती है, और फिर ईरान के तेहरान नगर को जाती है। इन सब बातों के सबब से, पश्चिमी एशिया फिर संसार की राजनीति में निश्चित रूप से दाख़िल होजाता है, और अन्तर्महाद्वीपीय मामलों की एक धुरी बन जाता है। इसका यह भी अर्थ है कि वह बड़ी-बड़ी शक्तियों के झगड़े और संघर्ष का स्थान बन गया है, क्योंकि उनके स्वार्थ एक-दूसरे से टकराते हैं और हरेक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करता है। हवा में भी वे 'न अपने काम में लें, न पराये काम आने दें' वाली नीति पर चलते हैं, और अपने प्रदेशों पर से अपने प्रतिस्पर्धियों को उड़ने से रोकते हैं। राष्ट्रीयता का यह रूप कभी-कभी हवाई राष्ट्रीयता कहलाता है। इस तरह ईराक़ सरकार, जिसका अर्थ है ईराक़ का नियन्त्रण करनेवाले अंग्रेज़, मशहूर जर्मन हवाई कम्पनी, जंकर्स को अपने हवाई जहाज़ इराक़ पर से नहीं लेजाने देती। और, इस कारण ईरानी सरकार, जो जंकर्स के प्रति अधिक मित्रता रखती है, ब्रिटिश इम्पीरियल एयरवेज़ को अपने प्रदेश पर से उड़ने की इजाज़त नहीं देती। कहीं-कहीं ये दिक्कतें आपस में समझौते करके हल होजाती हैं, लेकिन इनकी तह में जो प्रतियोगिता है वह चलती रहती है।

हवाई ताक़त और आमदरपत के बढ़ते हुए महत्व और साथ ही समुद्री ताक़त के घटते हुए महत्व के कारण देश-रक्षा के पुराने तरीक़ों में बड़ा भारी फ़र्क़ पड़ गया है। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, जिस बात की इंग्लैंड को हमेशा चिन्ता रही है और जिसको लक्ष्य में रखकर उसकी सारी नीति बनती बिगड़ती रही है, वह है अपने हिन्दुस्तानी साम्राज्य की रक्षा की समस्या। इसके लिए उसने समुद्री ताक़त का सहारा लिया, और इसीलिए ठीक-ठीक जगहों पर स्थित बन्दरगाह और कोयला लेने के स्थान उसके लिए महत्वपूर्ण रहे, ताकि उसका समुद्री बेड़ा आसानी से सब जगह आ-जा सके। लेकिन अगर अब हवाई मार्गों पर ज्यादा दारोमदार रखना है तो इन कोयला लेने के स्थानों का अब ज्यादा उपयोग नहीं है। इस तरह अदन जैसे बन्दरगाह का, जो समुद्री महत्व के जमाने में हिन्दुस्तान की रक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था, हवाई जहाज़ के आजाने के सबब से अब वह महत्व नहीं रहा। अब जिस बात की ज़रूरत है, वह है हवाई बन्दरगाह, अर्थात् बड़े-बड़े हवाईस्टेशन और हवाईजहाज़ों के

लिए तेल की प्रचुर मात्रा। अगर हम इस बात को याद रखेंगे तो मध्य-पूर्व आदि में अंग्रेजों और दूसरी शक्तियों की कार्रवाइयों की आधारभूत नीति को भी बहुत कुछ समझ सकेंगे।

मोसल में, हिन्दुस्तान को जानेवाले इस नये राज-मार्ग पर उसके स्थित होने के अलावा, तेल भी है। इराक़ में भी तेल है और, जैसा कि हम देख चुके हैं, वह हवाई लाइनों का मानों हृदय-स्थान है। इस तरह यह आसानी से समझा जा सकता है कि अंग्रेजों के लिए इराक़ पर नियन्त्रण रखना कितना जरूरी है। ईरान में भी तेल के कई क्षेत्र हैं, और इनमें 'एंग्लो-पर्सियन ऑयल कम्पनी' नाम की एक अंग्रेजी कम्पनी बहुत असें से काम करती रही है, जिसमें ब्रिटिश सरकार के भी कई हिस्से हैं। ईरान में इस कम्पनी का कारोबार ही सबसे बड़ा कारोबार है, और उसी का देश पर प्रभुत्व है। मेरा खयाल है कि एक पिछले खत में मैंने तुम्हें ईरान की नई तथा उग्र राष्ट्रीयता और इस ऑयल-कम्पनी, जिसका अर्थ है ब्रिटिश-सरकार, के बीच होनेवाले संघर्ष का हाल लिखा था। ईरानी सरकार ने पुराने इजाजतनामे को, इस आधार पर कि वह उसके हक़ में न्यायोचित नहीं है, रद्द कर दिया। यह मामला राष्ट्रसंघ के सामने लाया गया, और हाल में ही एक समझौता होगया है, जिसके अनुसार कम्पनी को ईरान एक नया ठेका दे रहा है। इस ठेके के मुताबिक़ ईरान को मुनाफ़े में से ज्यादा बड़ा और निश्चित हिस्सा मिलेगा।

तेल या पेट्रोल का महत्व बढ़ रहा है, क्योंकि वह सिर्फ़ हवाई जहाजों और मोटर-गाड़ियों में ही काम नहीं आता बल्कि उसे कई समुद्री-जहाज भी इस्तेमाल करते हैं। इसलिए साम्राज्यवादी नीतियों के निर्माण में उसका बड़ा हिस्सा रहता है, जो बड़ा चिपकनेवाला, फिसलनेवाला और मलिनतापूर्ण होता है। वास्तव में आजकल के साम्राज्यवाद को कभी-कभी 'तेल साम्राज्यवाद' भी कहते हैं।

इस खत में हमने कुछ ऐसे कारणों पर गौर किया है जिन्होंने 'मध्य-पूर्व' को एक नया महत्व दे दिया है, और उसे संसार की राजनीति के भँवर में लाकर डाल दिया है। लेकिन इन सब बातों की तह में हैं सारे एशिया की राष्ट्रीय जागृति, और इसका जहाँतक पश्चिमी एशिया से सम्बन्ध है वहाँतक इसपर हम अगले पत्र में विचार करेंगे। हमने तुर्की का भी अध्ययन कर लिया और मिस्र का भी। पश्चिमी एशिया में इन दो देशों ने अपने पड़ोसियों के लिए मिसाल क़ायम करदी है।

मैं उम्मीद करता हूँ कि इस खत को पढ़ते वक्त तुम एक नक्शा या एटलस अपने पास रख लोगी, जिससे तुम्हें नई रेलवे-लाइन और हवाई मार्ग मालूम हो सकेंगे। हमारे लिए इनमें एक खास दिलचस्पी भी है, क्योंकि ये हमारे हिन्दुस्तान

से योरप जानेवाले रास्ते पर पड़ते हैं, और बहुत मुमकिन है कि किसी दिन हमें भी उनपर से गुजरना पड़े। पुरानी समुद्री यात्रा तो बहुत ही धीमी और गुजरे जमाने की मालूम होती है, अब तो हवाई यात्रायें ही दिल को लुभा रही हैं।

: १६६ :

अरब देश—सीरिया

२८ मई, १९३३

हम देख चुके हैं कि जिन देशों में प्रायः एक ही सामान्य भाषा और परम्परा होती है, वहाँके लोगों के समूहों को आपस में मिलाने और मजबूत बनाने की राष्ट्रीयता में बड़ी ताकत होती है। यह राष्ट्रीयता जहाँ किसी एक वर्ग को मिलाकर एक करती है, वहाँ उसे दूसरे समूहों से अलग करके और दूर भी कर देती है। राष्ट्रीयता ने फ़्रान्स को एक मजबूत ठोस अलग राष्ट्र बना दिया है, जो खुद तो बहुत अच्छी तरह संगठित है लेकिन बाक़ी दुनिया को अपनेसे बिल्कुल अलहदा समझता है। इसी तरह राष्ट्रीयता के कारण भिन्न-भिन्न जर्मन देश मिलकर एक जबरदस्त जर्मन-राष्ट्र बन गये हैं। लेकिन फ़्रान्स और जर्मनी के इसी तरह अलग-अलग संगठित होने के कारण ही वे एक-दूसरे से और भी ज्यादा दूर हो गये हैं।

किसी ऐसे देश में तो जहाँ कई जुदा-जुदा जातीय दल रहते हैं, राष्ट्रीयता देश को मजबूत और सुसंगठित करने के बजाय प्रायः असंगठित कर देती है, उसे दरअसल कमजोर और उसके टुकड़े-टुकड़े कर देती है। महायुद्ध से पहले आस्ट्रो-हंगेरियन साम्राज्य कई जातीयताओं का एक ऐसा ही देश था, जहाँ जर्मन-आस्ट्रियन और हंगेरियन ये दो जातियाँ तो प्रधान थीं और बाक़ी सब इनके अधीन थीं। इसलिए जब राष्ट्रीयता ने इन सब क़ौमों में अलग-अलग नया जीवन डाला और इसके साथ उनमें आजाद होने की इच्छा पैदा हुई तो उससे आस्ट्रिया-हंगरी कमजोर होगया। महायुद्ध से मामला और भी ख़राब होगया, और जब महायुद्ध के बाद हार होगई तो सारा देश छोटे-छोटे टुकड़ों में बंट गया और हर क़ौमो गिरोह ने अपना छोटा-सा अलग राष्ट्र बना लिया। (यह बंटवारा कोई भला या युक्तिसंगत नहीं था, लेकिन इस विषय में अभी यहाँ हमें विचार नहीं करना है।) परन्तु करारी हार होने पर भी, जर्मनी के टुकड़े नहीं हुए। वह राष्ट्रीयता की जबरदस्त प्रेरणा के कारण, मुसीबत में भी एक और संगठित बना रहा।

आस्ट्रिया-हंगरी की तरह ही, महायुद्ध के पहले तुर्की साम्राज्य भी कई जातीयता-

ओं का एक मजमा था। बालकन जातियों के अलावा उसमें अरब और आरमीनियन वगैरा जातियाँ भी शामिल थीं। इसलिए इस साम्राज्य में भी राष्ट्रीयता एक विश्रृंखल-कारी शक्ति यानी टुकड़े करनेवाली ताकत साबित हुई। सबसे पहले उसका बालकन जातियों पर असर पड़ा, और उन्नीसवीं सदी में लगातार, पहले ग्रीस से और फिर एक के बाद एक दूसरी जातियों से तुर्की को हमेशा लड़ाई करनी पड़ी। 'बड़ी शक्तियों' और खासकर जारशाही रूस ने इस उठती हुई राष्ट्रीयता से फ़ायदा उठाने की कोशिश की और उसके साथ साजिश की। उन्होंने उस्मानी साम्राज्य पर चोट पहुँचाने और उसे कमजोर करने के लिए आरमीनियन क्रौम को अपना हथियार भी बनाया, और इसीसे तुर्की हुकूमत और आरमीनियनों में बार-बार संघर्ष हुआ, जिसमें कई बार क़त्ले-आम भी हुए। 'बड़ी शक्तियों' ने इन आरमीनियनों का दुरुपयोग किया और प्रचार-कार्य में उनका इस्तेमाल किया, लेकिन महायुद्ध के बाद जब उनका और कोई उपयोग न रहा तो उन्हें उनकी क्रिस्मत पर छोड़ दिया गया। बाद में आरमीनिया, जो तुर्की के पूर्व में है और काले सागर से लगा हुआ है, सोवियट-प्रजातन्त्र बन गया और रूसी सोवियट यूनियन में शामिल होगया।

तुर्की साम्राज्य के अरबी हिस्सों को जागृत होने में ज्यादा समय लगा, हालाँकि अरबों और तुर्कों में कभी कोई मुहब्बत नहीं रही थी। पहले तो उनमें संस्कृति-सम्बन्धी जागृति हुई और अरबी भाषा और साहित्य का पुनरुद्धार हुआ। इस जागृति की शुरुआत सीरिया में उन्नीसवीं सदी के मध्य के लगभग हुई, और फिर यह मिस्र और अरबी बोलनेवाले दूसरी देशों में फैल गई। तुर्की की १९०८ की 'युवक तुर्क' क्रान्ति, और मुलतान अब्दुलहमीद के पतन के बाद राजनैतिक आन्दोलन उठ खड़े हुए। मुस्लिम और ईसाई दोनों धर्म के अरबों में क़ौमी खयालात फैल गये, और अरब देशों को तुर्की हुकूमत से आज़ाद करने और उन्हें एक नये राज्य के रूप में बनाने का विचार पैदा हो गया। मिस्र हालाँकि अरबी-भाषी देश था, लेकिन वह राजनैतिक रूप से बहुत-कुछ अलग था, और इस नये अरब-राज्य में, जिसमें अरबिस्तान, सीरिया, फिलस्तीन और इराक़ को शामिल करने का विचार था, उसके शामिल होने की उम्मीद नहीं थी। अरब यह भी चाहते थे कि ख़िलाफ़त को उस्मानी मुलतान के पास से हटाकर किसी अरब वंश में ले आया जाय, ताकि वे इस्लाम का धार्मिक नेतृत्व भी फिर प्राप्त कर सकें। यह काम भी धार्मिक दृष्टि की बनिस्वत क़ौमी दृष्टिकोण से अधिक देखा जाता था, क्योंकि इससे अख़ीर में अरबों का महत्व और गौरव ही बढ़ता और सीरिया के ईसाई अरब भी इसके पक्ष में थे।

ब्रिटेन ने इस अरब राष्ट्रवादी आन्दोलन के साथ महायुद्ध से भी पहले साजिश

करनी शुरू कर दी। महायुद्ध के जमाने में एक महान् अरब राज्य बनवा देने के बड़े-बड़े वादे किये गये और मक्का का शरीफ हुसैन, इस उम्मीद से कि वह एक बड़ा बादशाह बन जायगा और फिर खलीफ़ा भी उसकी खुशामद करता फिरेगा, अंग्रेजों के साथ हो गया और उसने तुर्कों के खिलाफ़ अरब-विद्रोह खड़ा कर दिया। सीरिया के मुसलमान और ईसाई दोनों तरह के अरबों ने हुसैन की इस वगावत का समर्थन किया और उनके कई नेताओं को इसके लिए अपनी जानें देनी पड़ीं, क्योंकि तुर्कों ने उनको फांसी पर चढ़ा दिया। दमिश्क और बेरूत में ६ मई को उन्हें फांसियाँ हुईं, और यह दिवस सीरिया में राष्ट्रीय शहीदों की यादगार में अब भी मनाया जाता है।

अंग्रेजों की माली इमदाद से, और खासकर अंग्रेजों के खुफ़िया महकमे के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के सहयोग से, जिसका नाम कर्नल लॉरेन्स था, अरब विद्रोह कामयाब होगया। महायुद्ध के ख़त्म होने के वक़्त तक तुर्कों के क़रीब-क़रीब सभी अरब-प्रदेश अंग्रेजी नियन्त्रण में आगये। तुर्की साम्राज्य टुकड़े-टुकड़े होगया। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि तुर्की की आज़ादी की लड़ाई में मुस्तफ़ा कमालपाशा ने कुर्दिस्तान के एक छोटे-से हिस्से के सिवा शेर-तुर्क प्रदेशों पर क़ब्ज़ा ज़माने का उद्देश्य कभी नहीं रक्खा। बड़ी अक्लमन्दी से उसने सिर्फ़ तुर्कों की ही रक्षा की।

महायुद्ध के बाद इन अरब देशों के भविष्य का फ़ैसला होना था। विजयी मित्र-राष्ट्रों यानी अंग्रेज और फ़्रांसीसियों ने ईमानदारी के साथ ऐलान किया कि इन देशों के बारे में उनका उद्देश्य यह है कि इन "जातियों को, जो अभी तक तुर्कों द्वारा पीड़ित थीं, पूर्ण और निश्चित रूप से मुक्त किया जाय, और यहाँके वाशिनदे खुद अपनी स्वतंत्र इच्छा से जैसे राष्ट्रीय शासन और शासक-मण्डल चाहें वैसे क़ायम कर दिये जायें।" इन दोनों राष्ट्रों ने इस ऊँचे उद्देश्य की पूर्ति इस तरह शुरू की कि इन अरब देशों के ज्यादातर हिस्से को खुद ही आपस में बाँट लिया। फ़्रांस और इंग्लैंड को मॅण्डेट (शासनादेश) दिये गये। मॅण्डेटों का हासिल करना राष्ट्र-संघ के आशीर्वाद के साथ साम्राज्यवादी ताक़तों के द्वारा नया इलाक़ा हासिल करने का ही एक नया तरीक़ा था। फ़्रांस को सीरिया और इंग्लैंड को फ़िलिस्तीन और इराक़ मिला; और हेज़ाज़, जो अरबस्तान का सबसे महत्त्वपूर्ण हिस्सा था, अंग्रेजों के आश्रित मक्का के शरीफ़ हुसैन के अधीन रक्खा गया। इस तरह, एक ही बड़ा अरब-राज्य बनाने के वादों के खिलाफ़, इन अरब प्रदेशों को अलग-अलग हिस्सों में बाँटकर अलग-अलग मॅण्डेटों की शक्ल में बना दिया गया और सिर्फ़ हेज़ाज़ ही एक अलग राज्य बनाया गया जो ज़ाहिरा आज़ाद रहा लेकिन दरअसल अंग्रेजों के अधीन था। अरबों को अपने सारे प्रदेश के इस तरह टुकड़े किये जाने से बड़ी निराशा हुई, और उन्होंने इन हिस्सों

को अन्तिम मानने से इनकार कर दिया। लेकिन उनकी क्रिस्मत में तो अभी और भी आश्चर्य और निराशा की बातें आनेवाली थीं, क्योंकि उनपर ज्यादा आसानी से हुकूमत कर सकने के लिए साम्राज्यवाद की पुरानी भेद-नीति हरेक मँण्डेट के अन्दर भी बरती जाने लगी। अब इनमें से हरेक देश पर अलग-अलग विचार करना आसान होगा। इसलिए मैं पहले फ्रेंच मँण्डेट वाले सीरिया को लेता हूँ।

१९२० के शुरू में अंग्रेजों की मदद से सीरिया में हेजाज के शाह हुसैन के पुत्र अमीर फ़ैसल के अधीन एक अरब सरकार खड़ी की गई। एक सीरियन राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और उसने संयुक्त सीरिया के लिए एक प्रजातन्त्रीय विधान पारित किया। लेकिन यह तो चन्द दिनों का दिखावा ही था। १९२० की गरमी के दिनों में फ़्रांसीसी लोग अपनी जेब में राष्ट्र-संघ की तरफ़ से सीरिया का मँण्डेट लेकर आगये, और उन्होंने फ़ैसल को निकाल बाहर किया और देश पर जबरदस्ती कब्ज़ा कर लिया। कुल मिलाकर भी सीरिया एक छोटा-सा देश है, जिसकी आबादी ३० लाख से भी कम है। लेकिन वह फ़्रांसीसियों के लिए बरों का छत्ता बन गया। मुसलमान और ईसाई दोनों तरह के सीरियन अरबों ने आजाद होने का पक्का इरादा कर लिया, और दूसरी ताक़त के आगे आसानी से सिर झुकाने से इन्कार कर दिया। वहाँ हमेशा झगड़ा और मुकामी बगावतें होती ही रहीं, और फ़्रांसीसी हुकूमत चलाने के लिए बड़ी भारी फ़्रांसीसी फ़ौज की जरूरत पड़ी। इसके बाद फ्रेंच सरकार ने साम्राज्यवाद की वही फूट डालने की चाल चलने की कोशिश की, और देश को और भी छोटी-छोटी रियासतों में बाँटकर और धार्मिक अल्पसंख्यक भेद-भावों को महत्त्व देकर सीरियन राष्ट्रीयता को कमजोर करना चाहा। “शासन करने के लिए अलग-अलग बाँटना” यह नीति जान-बूझकर इस्तिस्नान की गई, और क़रीब-क़रीब सरकारी तौर पर जाहिर कर दी गई।

हालाँकि सीरिया छोटा-सा देश था, लेकिन उसे पाँच अलग-अलग राज्यों में बाँटा गया। पश्चिम के समुद्री किनारे पर और लेबेनन पहाड़ के पास लेबेनन राज्य बनाया गया। यहाँ के ज्यादातर वाशिन्डे मॅरोनाइट नामक ईसाई सम्प्रदाय के थे, और सीरियन अरबों के खिलाफ़ उन्हें अपनी तरफ़ मिला लेने के लिए फ़्रांसीसियों ने उन्हें एक खास दर्जा दे दिया।

लेबेनन के उत्तर में समुद्र के ही किनारे पहाड़ों के दरमियान एक और छोटा-सा राज्य बनाया गया, जहाँ कि अलावी नाम के मुसलमान रहते थे। इससे भी उत्तर में एलेक्जेंड्रेटा नामक एक तीसरा राज्य बनाया गया। यह राज्य तुर्की से लगा हुआ था और इसमें तुर्की भाषा बोलनेवाले लोग ज्यादा थे।

इस तरह देश के बाकी हिस्से, खास सीरिया प्रदेश के कुछ उपजाऊ जिले, चले गये और इससे भी दुरी बात यह हुई कि उसका समुद्र से ताल्लुक बिलकुल टूट गया। हजारों वर्षों से सीरिया की गिनती भूमध्य-सागर के महान् देशों में थी, लेकिन अब वह पुराना सम्बन्ध तोड़ दिया गया और उसे कठोर मरुभूमि से अपना नाता जोड़ना पड़ा। इस खास सीरिया प्रदेश में से भी एक और पहाड़ी टुकड़ा काटकर जबल-अद-द्रुज़ नामक एक अलग राज्य बना दिया गया, जहाँ कि द्रुज़ फिरक़े के लोग रहते थे।

शुरू से ही सीरियन लोग फ़्रेंच "मैण्डेट" के खिलाफ़ थे। पहले ही संघर्ष और बड़े-बड़े प्रदर्शन हुए थे, जिनमें अरब स्त्रियों ने भी हिस्सा लिया था और जिन्हें फ़्रांसीसियों ने बड़ी सत्ता से कुचला था। देश के छोटे-छोटे टुकड़े करने और जान-बूझकर धार्मिक और अल्पसंख्यक समस्याएँ खड़ी करने की कोशिश से तो मामला और बिगड़ गया और असन्तोष बढ़ गया। इसे दबाने के लिए जिस तरह हिन्दुस्तान में अंग्रेज़ों ने किया है उसी तरह फ़्रांसीसियों ने भी व्यक्तिगत और राजनैतिक आजादी छीन ली और सारे देश में खुफिया महकमे के लोग फैला दिये गये। उन्होंने ऐसे 'राजभक्त' सीरियनों को अफ़सर मुकर्रर किया, जिनका लोगों पर कुछ भी असर नहीं था और जिन्हें उनके देशवासी आमतौर पर देशद्रोही समझते थे। ये बातें अधिक-से-अधिक ईमानदारी की नीयत से की गईं, और फ़्रांसीसियों ने ऐलान किया कि वे 'सीरियनों को राजनैतिक अनुभव और आजादी की तालीम देना अपना फ़र्ज़ समझते हैं'— हिन्दुस्तान में भी तो इस तरह के वाक्यों से लोग परिचित हैं।

मामला खासकर जबल-अद-द्रुज़ के लड़ाकू और जंगली लोगों में (जो कि हमारे उत्तर-पश्चिमी सरहदी जातियों जैसे ही हैं) बढ़ता गया। इन द्रुज़ लोगों के नेताओं के साथ फ़्रांसीसी गवर्नर ने एक भद्दी चालाकी की। उसने उन्हें बुलाया और फिर उन्हें वहीं कैद कर लिया और ज़ामिनों की तरह पकड़ रक्खा। यह वाक़्या १९२५ के गरमी के दिनों में हुआ और फौरन ही जबल-अद-द्रुज़ में एक बगावत खड़ी होगई। यह मुक़ामी बगावत जल्द ही सारे देश में फैल गई और सीरियन आजादी और एकता के लिए एक व्यापक विद्रोह बन गई।

सीरियन आजादी की यह लड़ाई एक उल्लेखनीय बात थी। एक छोटा-सा देश, जो हिन्दुस्तान के दो या तीन जिलों के बराबर था, फ़्रांस के खिलाफ़, जो कि उस वक़्त संसार की सबसे बड़ी सैनिक शक्ति थी, लड़ने को तैयार होगया। सीरियन लोग फ़्रांस की बड़ी-बड़ी और सुसज्जित फौजों के आगे बाक़ायदा मुक़ाबिले की लड़ाई तो लड़ ही नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने उनका देहाती इलाक़ों पर क़ब्ज़ा बनाये रखना मुश्किल कर दिया। सिर्फ़ बड़े-बड़े क़स्बे ही फ़्रांसीसियों के अधिकार में थे और उन-

पर भी अक्सर सीरियन लोग हमला कर देते थे। फ्रांसीसियों ने बहुत लोगों को गोलियों से उड़ाकर और कितने ही गांवों को जलाकर आम लोगों को भयभीत करने की पूरी कोशिश की। अक्टूबर १९२५ में प्रसिद्ध पुराने शहर दमिश्क पर भी बम-वर्षा की गई और उसे बहुत-कुछ बरबाद कर दिया गया। सारा सीरिया फौजी छावनी बन गया था। इतने पर भी दो साल तक विद्रोह दब न सका। आखिर वह फ्रांस की महान् सैनिक मशीन से कुचल दिया गया। लेकिन सीरियनों के महान् बलिदान बेकार नहीं गये। उन्होंने आज़ाद होने के अपने हक़ को क़ायम किया और दुनिया को मालूम होगया कि उनमें भी कितनी वृद्धता मौजूद है।

यह बात ध्यान देने योग्य है कि फ्रांसीसियों ने इस विद्रोह को मजहबी रंग देना और दूजों से ईसाइयों को लड़ाना चाहा, मगर सीरियनों ने यह बिल्कुल साफ़ जाहिर कर दिया कि वे क़ौमी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, न कि किसी मजहबी उद्देश्य के लिए। विद्रोह के बिल्कुल शुरू में दूज प्रदेश में एक अस्थायी सरकार क़ायम करली गई, और इस सरकार ने लोगों से आज़ादी की लड़ाई में शामिल होने और “एक और अखण्ड सीरिया की मुकम्मल आज़ादी हासिल करने का विधान बनाने के वास्ते कान्स्टीट्यूएण्ट एसेम्बली का स्वतन्त्र चुनाव करने, देश पर कब्ज़ा जमानेवाली विदेशी फ़ौजों के हटाये जाने, स्वरक्षा के लिए राष्ट्रीय फ़ौज बनाने, और फ़्रान्स की क्रान्ति तथा ‘मनुष्यों के अधिकार’ के सिद्धान्तों को प्रयोग में लाने के लिए” अपील निकाली। इस तरह, फ्रांस की सरकार और फ़ौज ने एक ऐसी जाति को दबा देने की कोशिश की जो फ्रेंच-क्रान्ति के उसूलों और उसके ऐलान किये हुए हक़ों के लिए ही खड़ी हुई थी !

१९२८ के शुरू में सीरिया में मार्शल-ला यानी फौजी क़ानून ख़त्म होगया, और प्रेस पर से सेन्सरशिप भी हट गई। कई राजनैतिक क़ैदी छोड़ दिये गये। राष्ट्रवादियों की मांग के मुताबिक़ विधान तैयार करने के लिए एक ‘कान्स्टीट्यूएण्ट एसेम्बली’ बुलाई गई। लेकिन फ़्रान्सीसियों ने (आजकल जैसा कि हिन्दुस्तान में किया गया है) अलग-अलग धार्मिक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था करके झगड़े की जड़ डाल दी। मुसलमानों, ग्रीक कैथलिकों, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स मतवालों और यहूदियों के लिए बिल्कुल अलग-अलग क्षेत्र बना दिये गये, और हर वोटर को अपने धर्मवालों को ही वोट देने के लिए मजबूर किया गया। दमिश्क में एक अजीब और आँखें खोल देने-वाली परिस्थिति पैदा होगई। वहाँ राष्ट्रवादियों का नेता एक प्रोटेस्टेंट ईसाई था। प्रोटेस्टेंट होने के कारण वह किसी भी विशेष निर्वाचन-क्षेत्र में नहीं आता था, और हालांकि वह दमिश्क का एक सबसे ज्यादा लोकप्रिय व्यक्ति था, लेकिन फिर भी चुनाव

न जा सका। मुसलमानों ने, जिनकी दस सीटें थीं, एक सीट छोड़ देनी चाही, ताकि वह प्रोटेस्टेंटों को दी जासके, परन्तु फ्रांसीसी सरकार ने इसे नहीं माना।

फ्रांसीसियों की इन तमाम कोशिशों के बावजूद, कान्स्टीट्यूएण्ट एसेम्बली पर राष्ट्रवादियों का ही नियन्त्रण रहा, और उन्होंने एक आजाद और सर्वोपरि राज्य का विधान तैयार कर डाला। विधान में सीरिया को एक प्रजातन्त्र बनाया गया, जिसमें सारी सत्ता का उद्गम जनता से रखा गया। इस प्रस्तावित विधान में फ्रांसीसियों या उनके मण्डेट का कहीं जिक्र तक नहीं था। इसपर फ्रांसीसियों ने एतराज किया, लेकिन एसेम्बली भी बिल्कुल न झुकी, और कई महीनों तक खींचा-तानी चलती रही। आखिरकार फ्रेञ्च हार्ड कमिशनर ने यह तजवीज की कि विधान का सारा मस्विदा मंजूर कर लिया जाय, सिर्फ़ उसमें एक ऐसी धारा रख दी जाय कि जबतक मण्डेट-शासन चलेगा तबतक विधान की किसी भी धारा का ऐसा प्रयोग न किया जायगा जो मण्डेट के अनुसार फ़्रान्स की जिम्मेदारियों के खिलाफ़ पड़े। यह बड़ी गोलमोल बात थी, फिर भी इसमें फ़्रांस को बहुत झुकना पड़ा। लेकिन कान्स्टीट्यूएण्ट एसेम्बली ने इसको भी मंजूर नहीं किया। इसपर मई १९३० में फ़्रेंच सरकार ने इस एसेम्बली को ही वरत्तास्त कर दिया, और साथ ही संक्रमण-काल (बीच का समय) सम्बन्धी अपनी प्रस्तावित धारा जोड़कर उसके बनाये हुए विधान का ऐलान कर दिया।

इस तरह सीरिया प्रदेश जो कुछ चाहता था वह अधिकांश उसे मिल गया, फिर भी उसने अपनी किसी भी माँग को न तो कम किया, न उसपर समझौता किया। दो बातें बाक़ी रहीं : एक तो मण्डेट-शासन का अन्त होना, जिसके साथ संक्रमण-कालीन धारा भी चली जायगी, और दूसरे सारे सीरिया के एकीकरण का बड़ा सवाल। इसके सिवा, आजकल जो विधान चल रहा है, वह बड़ा प्रगतिशील है और पूरी तौर पर आजाद देश के लायक़ बनाया गया है। महान् विद्रोह के समय नें सीरियनों ने अपने को बहादुर और मजबूत लड़ाका साबित कर दिया। उसके बाद सन्धि-चर्चा में भी उन्होंने अपनेको दृढ़ और निश्चित माँगें रखनेवाला साबित किया, और उन्होंने पूरी आजादी की माँग को ज़रा भी संशोधित या कम करने से इन्कार कर दिया। अख़बारों की ख़बरों से मालूम होता है कि सीरियन राष्ट्रवादियों और फ्रांसीसी सरकार के बीच जल्द ही कोई समझौता होनेवाला है। अख़बारों की बयान की हुई बातों पर यकीन तो नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं तुम पर ही छोड़ता हूँ कि तुम इस समझौते का जितना मुनासिब हो उतना ही महत्व समझना। यह उचित भी मालूम होता है। १९३४ के अख़ीर में सीरिया प्रदेश तथा अलावियों और द्रुज़ों पर से

फ्रान्सीसी मँण्डेट के ख़त्म होने और इन तीनों हिस्सों के एकीकरण के आधार पर यह समझौता होनेवाला है। इस तरह अब तीनों हिस्सों को मिलाकर एक ही राज्य बन जायगा, लेकिन अलावियों और द्रुज़ों को भी बहुत ज्यादा आज़ादी रहेगी। इस राज्य में अभी लेबेनन शामिल न होगा। वह बीस वर्ष के लिए और भी फ्रान्स के संरक्षण में रहेगा। उसके बाद लेबेनीज़ प्रजातन्त्र के लोग वोटों द्वारा सीरिया के साथ मिल जाने के सवाल का फ़ैसला करेंगे।

: १६७ :

फ़िलस्तीन और ट्रान्स-जोर्डन

२९ मई, १९३३

सीरिया से लगा हुआ ही फ़िलस्तीन है, जिसकी बावत ब्रिटिश सरकार के पास राष्ट्र-संघ का मँण्डेट (शासनादेश) है। यह और भी छोटा देश है। इसकी आबादी दस लाख से भी कम है, लेकिन इसके पुराने इतिहास और ताल्लुकात की वजह से इसकी तरफ़ लोगों का ध्यान बहुत जाता है; क्योंकि यह यहूदियों के लिए, ईसाइयों के लिए, और किसी हद तक मुसलमानों तक के लिए भी एक पवित्र भूमि है। यहाँके बाशिन्दे ज्यादातर मुसलमान अरब हैं, और वे आज़ादी की और सीरिया के अपने अरब-बन्धुओं के साथ मिल जाने की माँग करते हैं। लेकिन ब्रिटिश नीति ने यहाँ एक ख़ास—यहूदियों की—अल्पसंख्यक समस्या पैदा कर दी है। यहूदी लोग अंग्रेज़ों का साथ देते हैं और फिलस्तीन की आज़ादी का विरोध करते हैं, क्योंकि उन्हें अंदेशा है कि इसका अर्थ होगा अरबों का शासन। ये दोनों एक-दूसरे के ख़िलाफ़ जाने-वाले रास्ते हैं और, जैसा होना लाज़िमी है, संघर्ष होते ही रहते हैं। अरबों की तादाद ज्यादा है; यही उनकी ताक़त है। दूसरी तरफ़ यहूदी बहुत मालदार हैं और सारी दुनिया में उनका अच्छा संगठन है। इसलिए इंग्लैण्ड अरब राष्ट्रीयता के मुक़ाबिले में यहूदी धार्मिक राष्ट्रीयता को बढ़ावा देता है और दिखाता है कि दोनों का बीच-बचाव करने और शान्ति कायम रखने के लिए उसका वहाँ बना रहना ज़रूरी है। यह वही पुराना तमाशा है जो साम्राज्यवाद के अधीन दूसरे देशों में हम देख चुके हैं। कितना आश्चर्य है कि बार-बार वही दोहराया जाता है !

यहूदी बड़े राजब के लोग हैं। मूलतः फिलस्तीन में वे एक छोटी-सी जाति अथवा कई छोटी-छोटी जातियों के रूप में रहते थे, और उनकी शुरु की कहानी बाइबिल के ओल्ड टेस्टामेण्ट यानी प्राचीन धर्मपुस्तक में लिखी हुई है। वे बड़े मज़हब थे,

अपने आपको परमात्मा के खास पसन्द किये हुए लोग मानते थे । लेकिन ऐसी झूठी मान्यतायें दुनिया की करीब-करीब सभी जातियों में रही हैं । वे बार-बार हराये गये, दबाये गये, और गुलाम बनाये गये । अंग्रेजी की कुछ सबसे सुन्दर और दिल हिला देनेवाली कवितायें तो यहूदियों के गाने और रोने की हैं । ये कवितायें वाइबिल के प्रमाणित अनुवाद में दी हुई हैं । मेरा खयाल है कि मूल हिब्रू भाषा में तो वे इतनी ही या इससे भी सुन्दर होंगी । मैं ओल्ड टेस्टामेन्ट के एक भजन की कुछ पंक्तियों का अनुवाद यहाँ देता हूँ :—

By the waters of Babylon we sat down and wept :
when we remembered thee, O Sion !

As for our harps we hanged them up :
upon the trees that are therein.

For they that led us away captive required of us then
a song, and melody, in our heaviness :

Sing us one of the songs of Sion.

How shall we sing the Lord's song : in a strange land ?

If I forget thee, O Jerusalem :

let my right hand forget her cunning.

If I do not remember thee, let my tongue cleave to
the roof of my mouth : yea, if I prefer
not Jerusalem in my mirth.

अर्थात्, “ऐ ज़ियोन ! जब हमें तेरा स्मरण आया, तो हम बेबीलोन नदी के तट पर बैठ गये और खूब रोये ।

अपनी वीणाओं को तो हम वहीं के वृक्षों पर लटका आये ।

क्योंकि, जो हमें वन्दी बनाकर ले गये वे हमारे शोक में हमसे कहते थे कि हमें कोई गीत, कोई राग, सुनाओ । हमें ज़ियोन का गाना सुनाओ ।

हम प्रभु का गीत, एक विराने देश में, कैसे गावें ?

ऐ जेरूसलम ! यदि मैं तुझे भुलाऊँ तो अपने दाहिने हाथ की सारी कुशलता को भूल जाऊँ ।

यदि मैं तेरा नाम लेना भुलाऊँ तो मेरी जिह्वा तालु से चिपकी रह जाय, यदि मैं अपने आनन्द में सबसे अधिक जेरूसलम को न चाहूँ ।”

ये यहूदी अन्त में सारी दुनिया में जहाँ-तहाँ बिखर गये । उनका कोई देश या राष्ट्र न था, और जहाँ कहीं वे जाते वहीं उनके साथ परदेशियों का-सा बुरा बर्ताव किया जाता था । उन्हें सबसे अलग शहर के खास हिस्सों में, जो ‘घेटो’ लहलाते थे, बसाया जाता था, ताकि वे दूसरे लोगों को अपवित्र न कर दें । कहीं-कहीं उनके लिए खास पोशाक मुक़र्रर करदी जाती थी । उनका अपमान किया जाता था, उन्हें अपशब्द

कहे जाते थे, यातनायें दी जाती थीं, और सरे-आम क़त्ल कर दिया जाता था। 'यहूदी' शब्द ही एक गाली बन गई थी, जिसका अर्थ था कंजूस और मक्खी-चूस साहूकार। इतना होने पर भी यह अद्भुत जाति न सिर्फ़ ज़िन्दा रही, बल्कि अपनी जातीय और सांस्कृतिक विशेषताओं की भी रक्षा की, ख़ूब फूली-फली और अपने अन्दर से अनेक महान् पुरुषों को पैदा किया। आज वैज्ञानिकों, राजनीतिज्ञों, साहित्य-कारों, धनपतियों और व्यापारियों में वे सबसे आगे बढ़े हुए माने जाते हैं। और सबसे बड़े साम्यवादी और कम्युनिस्ट तक यहूदी हुए हैं। लेकिन ज्यादातर यहूदी तो मालदार नहीं हैं। पूर्वी योरोप के शहरों में उनकी तादाद ज्यादा है, और समय-समय पर उनको 'पोशो' यानी क़त्लेआम भी वर्दश्त करने पड़ते हैं। वतन या राष्ट्र से महरूम इस जाति ने, ख़ासकर ग़रीब यहूदियों ने, पुराने जेरुसलेम के, जो उन्हें किसी समय की वास्तविकता से महान् और वैभव-पूर्ण दिखाई देता है, स्वप्न देखना कभी न छोड़ा। जेरुसलेम को वे 'ज़ियोन' कहते हैं, जो एक प्रकार का स्वर्ग है, और 'ज़ियोनिज़्म' वह भूतकाल की प्रेरणा है जो उन्हें जेरुसलम और फ़िलस्तीन की तरफ़ आकर्षित करती रहती है।

उन्नीसवीं सदी के अन्त के लगभग इस 'ज़ियोनिस्ट' आन्दोलन ने धीरे-धीरे उपनिवेश बनने की शकल इख़्तियार की और कई यहूदी फ़िलस्तीन में बसने पहुँच गये। हिब्रू भाषा का पुनरुद्धार भी शुरू हुआ। महायुद्ध के ज़माने में अंग्रेज़ी फ़ौजों ने फ़िलस्तीन पर हमला किया, और जब वे जेरुसलम की तरफ़ बढ़ रही थीं तब ब्रिटिश सरकार ने नवम्बर १९१७ में बालफ़ोर-घोषणा नाम की एक घोषणा प्रकाशित की। उन्होंने जाहिर किया कि उनका इरादा है कि फ़िलस्तीन में एक 'यहूदी वतन' (ज़्यूइश नेशनल होम) क़ायम किया जाय। शायद यह ऐलान अन्तर्राष्ट्रीय यहूदी समाज की सद्भावना हासिल करने के लिए निकाला गया, और आर्थिक दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण था। यहूदियों ने इसका स्वागत किया। लेकिन इसमें एक छोटी-सी बाधा थी। एक बात की तरफ़, जो ग़ैर-ज़रूरी न थी, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। फ़िलस्तीन कोई वीरान या ग़ैरआबाद प्रदेश न था। यह तो पहले ही किसी-न-किसी का वतन था। इसलिए ब्रिटिश सरकार का यह उदारतापूर्ण प्रयत्न फ़िलस्तीन में पहले से बसे हुए लोगों को मुक़्तान पहुँचानेवाला था और इन लोगों ने, जिनमें अरब, ग़ैर-अरब, मुसलमान, ईसाई, असल में हर तरह के ग़ैर-यहूदी शामिल थे, इस ऐलान का जोरदार विरोध किया। इन लोगों ने महसूस किया कि हर काम में यहूदी उनका मुकाबिला करेंगे और अपनी बेशुमार दौलत के बल से देश के आर्थिक स्वामी बन जायेंगे। उन्हें अन्देशा था कि यहूदी उनके मूंह की रोटी और किसानों की ज़मीन छीन लेंगे।

पिछले बारह वर्ष की फ़िलस्तीन की कहानी अरबों और यहूदियों के कशमकश की कहानी है, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने मोक्के के मुताबिक़ कभी इधर और कभी उधर हिस्सा लिया, लेकिन वह आम तौर पर यहूदियों का ही साथ देती रही। इस देश के साथ ऐसा वर्त्ताव किया मानों यह स्वशासन-हीन अंग्रेज़ी वस्ती हो। अरब, जिनके साथ ईसाई और दूसरे गैर-यहूदी लोग भी हैं, आत्म-निर्णय और पूर्ण स्वाधीनता की मांग हमेशा करते रहे। उन्होंने बड़े जोर से मैण्डेट का और नये प्रकार से बसनेवालों का इस सबब से विरोध किया है कि वहाँ अब और लोगों की गुंजाइश नहीं है। ज्यों-ज्यों बाहर से यहूदी आते गये, त्यों-त्यों उनका अन्देशा और गुस्सा बढ़ता गया। उन्होंने (अरबों ने) बताया कि “ज़ियोनिज़्म में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का स्वार्थ भी मिला हुआ है। ज़ियोनिस्ट आन्दोलन के ज़िम्मेदार नेतों ने हमेशा कहा है कि एक मज़बूत ‘यहूदी वतन’ बन जाने पर वह हिन्दुस्तान के मार्ग की हिफ़ाज़त करने के लिए अंग्रेज़ों के वास्ते बड़ा लाभप्रद होगा, क्योंकि वह अरब राष्ट्रीय आकांक्षाओं का विरोध करने-वाली एक ताक़त होगी।” कौसी अजीब-अजीब जगहों में भी हिन्दुस्तान आ खड़ा होता है !

अरब कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग करने और एक लेजिस्लेटिव कौंसिल का, जिसे अंग्रेज़ खड़ी कर रहे थे, बहिष्कार करने का फैसला किया। यह बहिष्कार बहुत कामयाब हुआ और कौंसिल न बन सकी। एक ख़ास तरह के असहयोग की नीति कई साल तक चलती रही। फिर वह किसी हद तक कमजोर पड़ गई और कुछ दल अंग्रेज़ों को आंशिक सहयोग देने लगे। फिर भी अंग्रेज़ चुनी हुई कौंसिल न बना सके, और हाईकमिशनर ही सर्वशक्तिमान सुलतान की तरह हुकूमत करता रहा।

१९२८ में अरब कांग्रेस में भिन्न-भिन्न दल फिर मिलकर एक हो गये और उन्होंने ‘अधिकार के रूप में’ प्रजातन्त्रीय तरीक़े की हुकूमत की मांग की। उन्होंने बड़ी बहादुरी से यह भी कह दिया कि “फ़िलस्तीन के लोग मौजूदा एकतन्त्री कालोनियल शासन-प्रणाली को न तो मान सकते हैं और न मानेंगे।” अरबी राष्ट्रियता की इस नई लहर में एक मज़ेदार बात यह भी थी कि आर्थिक सवालों पर जोर दिया गया। स्थिति की असलियत के ज्यादा-से-ज्यादा ठीक तौर पर समझे जाने का यह हमेशा एक चिन्ह होता है।

अगस्त १९२९ में अरबों और यहूदियों के कई बड़े-बड़े दंगे हुए। असली सबब तो था यहूदियों की बढ़ती हुई दौलत और तादाद के कारण अरबों की कटुता और भय तथा अरबों की आज़ादी की मांग का यहूदियों द्वारा विरोध किया जाना। लेकिन

तात्कालिक कारण था एक दीवार की, जिसे 'वेलिंग वाल' (रोने की दीवार) कहते हैं, वास्तव झगड़ा। यह उस दीवार का हिस्सा है जो पुराने जमाने में हेरोड के मन्दिर के चारों ओर बनी हुई थी और इसलिए इसे यहूदी पवित्र मानते हैं, क्योंकि यह उस समय की यादगार है जब उनकी जाति महान् थी। बाद में यहीं एक मस्जिद बना ली गई और यह दीवार उसका एक हिस्सा बन गई। यहूदी इस दीवार के पास अपनी प्रार्थना करते हैं, खासकर अपने रोदनो को ऊँची आवाज से पढ़ते हैं, इसलिए इसका नाम 'रोने की दीवार' पड़ गया। मुसलमान अपनी एक सबसे प्रसिद्ध मस्जिद के हिस्से पर इस प्रकार रोने पर एतराज करते हैं।

दंगे के दवा दिये जाने के बाद झगड़ा दूसरी शक्तों में चलता रहा, और अजीब बात यह थी कि अरबों को फ़िलस्तीन के सब ईसाई सम्प्रदायों का पूरा समर्थन प्राप्त था। हड़तालों और बड़े-बड़े प्रदर्शनों में मुसलमान और ईसाई दोनों शामिल हुए। स्त्रियों तक ने इसमें बड़ा हिस्सा लिया। इससे जाहिर होता है कि असली झगड़ा धार्मिक नहीं था, बल्कि नये आनेवालों और पुराने रहनेवालों के बीच एक आर्थिक संघर्ष था। अपने मण्डेट-सम्बन्धी कर्तव्यों को पूरा न कर सकने और खासकर १९२९ के दंगों को न रोक सकने के कारण राष्ट्र-संघ ने ब्रिटिश हुकूमत की बड़ी आलोचना की।

इस तरह फ़िलस्तीन अब भी क़रीब-क़रीब एक अंग्रेज़ कालोनी यानी वस्ती है, और कई बातों में तो कालोनी से भी खराब है, और अंग्रेज़ लोग अरबों से यहूदियों को लड़ाकर इस हालत को जारी रख रहे हैं। उसमें ब्रिटिश अफ़सर ही भरे हुए हैं, सारे ऊँचे ओहदों पर वही हैं। अंग्रेज़ों के मातहत मुल्कों की आम हालत के मुआफ़िक वहाँ भी तालीम की बहुत कम कोशिश की गई है, हालाँकि अरबों को तालीम की ज़बरदस्त ख़ाहिश है। यहूदियों के बड़े-बड़े आर्थिक साधन होने के कारण, उनके पास अच्छे-अच्छे स्कूल और कालेज हैं। यहूदी आबादी मुसलिम आबादी के चौथाई हिस्से के क़रीब तो हो चुकी है, और उनकी माली ताक़त तो इससे भी कहीं ज्यादा है। वे उस दिन के इन्तज़ार में हैं जब फ़िलस्तीन में उनकी ही तूती बोलेगी। क़ौमी आज़ादी और प्रजातांत्रिक शासन की लड़ाई में अरबों ने उनका सहयोग पाने की कोशिश की, लेकिन इन बातों से उन्होंने इन्कार कर दिया। उन्होंने हुकूमत करनेवाली विदेशी ताक़त का साथ देना पसन्द किया है, और उसे अधिकांश जनता को आज़ादी न देने में मदद पहुँचाई है। फिर आश्चर्य नहीं कि यह अधिकांश जनता, जिसमें खासकर अरब हैं और ईसाई भी शामिल हैं, यहूदियों के इस ख़त पर घुरी तरह नाराज़ है।

फ़िलस्तीन से लगा हुआ, ट्रान्स-जोर्डन नदी के उत्तर-पूरब एक और छोटा-सा राज्य है जिसको अंग्रेज़ों ने महायुद्ध के बाद पैदा किया है। इसे ट्रान्स-जोर्डन कहते

हैं। यह एक छोटा-सा रकबा है, जो रेगिस्तान की हृद से मिला हुआ और सीरिया और अरब के बीच में स्थित है। इस राज्य की पूरी आबादी करीब तीन लाख है, जो कि आजकल के किसी शहर के भी मुश्किल से बराबर है ! ब्रिटिश सरकार इसको आसानी से फिलिस्तीन के साथ मिला सकती थी, लेकिन साम्राज्यवादी नीति मिलाने के बजाय जुदा करना ज्यादा पसन्द करती है। यह राज्य हिन्दुस्तान को जानेवाले जमीन के और हवाई मार्ग के लिए महत्वपूर्ण है। यह रेगिस्तान और उपजाऊ प्रदेशों के बीच में एक लाभदायक सरहदी राज्य है, जो पश्चिम में समुद्र तक पहुँचने का रास्ता है।

हालाँकि यह राज्य छोटा ही है, लेकिन यहाँ भी वही घटनाएँ हुईं जो पास के बड़े देशों में हुई थीं। यहाँ भी जनता की तरफ से प्रजातंत्री पार्लमेण्ट की मांग हुई, जो मंजूर नहीं की गई। प्रदर्शन दबा दिये गये। सेन्सरशिप, नेताओं की जलावतनी, सरकारी कार्यों का बहिष्कार वगैरा सब बातें हुईं। अंग्रेजों ने अमीर अब्दुल्ला को (जो हेजाज के शाह हुसैन का एक पुत्र और फ्रंसल का भाई है) बड़ी चतुराई से ट्रान्स-जोर्डन का शाह बना दिया है। वह बिल्कुल अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली है। लेकिन वह जनता की आँखों से अंग्रेजों को छिपाने के लिए परदे का काम देता है। जो कुछ होता है, अधिकांश बुराई उसीके सिर पर पड़ती है, और वह बहुत ही अप्रिय है। अब्दुल्ला के हाथ में ट्रान्स-जोर्डन का राज्य असल में ऐसा ही है जैसा हमारे हिन्दुस्तान में कई छोटे-छोटे देशी राज्य हैं।

उसूलन तो यह राज्य आजाद है, लेकिन १९२८ के एक सुलहनामे के जरिये फ्रौजी और दूसरी सब तरह की सहूलियतें ब्रिटेन को दे दी गई हैं। ट्रान्स-जोर्डन दर-असल ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गया है। यह एक नई किस्म की आजादी का छोटे पैमाने पर नमूना है, जो अंग्रेजों की छत्रछाया में रहती है। इस सुलहनामे और आमतौर पर इस सारी स्थिति को मुसलिम और ईसाई जनता बिल्कुल नापसन्द करती है। सुलहनामे के खिलाफ होनेवाले आन्दोलन को दबा दिया गया, जिन अखबारों ने उसका समर्थन किया उन्तक का निषेध कर दिया गया, और, जैसा कि मैं ऊपर कह चुका हूँ, नेताओं को जलावतन कर दिया गया। इसपर विरोध और भी बढ़ा, और एक राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और उसने एक राष्ट्रीय इकरार-नामा मंजूर किया और सुलहनामे की निन्दा की। जब नये चुनाव के लिए वोटों यानी मतदाताओं की फेहरिस्त तैयार की जा रही थी तो जनता के भारी बहुमत ने उसका बहिष्कार किया। लेकिन अब्दुल्ला और अंग्रेजों ने फिर भी सुलहनामे की दिखावटी ताईद के लिए कुछ समर्थक इकट्ठे कर ही लिये।

१९२९ के फ़िलिस्तीन के झगड़ों के दिनों में अंग्रेजों और बालफ़ोर-घोषणा के खिलाफ़ ट्रान्स-जोर्डन में भी बड़े-बड़े प्रदर्शन हुए ।

मैं तुम्हें मुख्तलिफ़ देशों की घटनाओं की महत्वपूर्ण बातों को विस्तार से लिखता जाता हूँ, और ऐसा मालूम होता है कि एक ही कहानी बार-बार दोहराई जा रही है । मैं यह इसलिए लिखता हूँ कि तुम अनुभव करलो कि यह बात नहीं है कि हम सब लोगों को अपने-अपने देश में अपनी अलग-अलग समस्याओं को निपटाना है, जैसा कि हम कभी-कभी सोचने लगते हैं । बल्कि हम सबको दुनिया के बड़े सवालों को हल करना है और शक्तियों का सामना करना है । हमें उस संघर्ष में से गुजरना है, जिसमें एक तरफ़ तो पूर्व के सभी देशों की उठती हुई राष्ट्रीयता है और दूसरी ओर उसे दबानेवाले साम्राज्यवाद की वही बार-बार दुहराई जानेवाली चालें हैं । जैसे-जैसे राष्ट्रीयता पैदा होती और बढ़ती जाती है वैसे-ही-वैसे साम्राज्यवाद की चालों में हलकी-सी तब्दीलियाँ होती जाती हैं; लोगों को संतुष्ट करने और बाहरी ढाँचे के मामलों में झुक जाने की थोड़ी-सी दिखावटी कोशिशें की जाती हैं । इस बीच भिन्न-भिन्न देशों में जैसे-जैसे यह राष्ट्रीय लड़ाई आगे बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे हर देश में सामाजिक लड़ाई यानी भिन्न-भिन्न वर्गों की आपसी कशमकश भी साफ़ जाहिर होती जाती है, और सामन्त और किसी हद तक सम्पत्तिशाली वर्ग भी साम्राज्यवादी शक्ति की तरफ़ ज्यादा-ज्यादा मिलते जाते हैं ।

: १६८ :

अरब—मध्य-युग से सहसा प्रगति

३ जून, १९३३

मैं तुम्हें अरब देशों का हाल लिखता रहा हूँ, लेकिन अभी तक मैंने तुम्हें खास अरब यानी अरबिस्तान के बारे में कुछ नहीं लिखा, जोकि अरबी भाषा और संस्कृति का उद्गम है और इस्लाम की जन्मभूमि है । हालाँकि वह अरब सभ्यता का उद्गम-स्थान था, लेकिन वह पिछड़ा हुआ और मध्ययुगीन ही बना रहा, और हमारी आधुनिक सभ्यता की कसौटियों के मुताबिक नज़दीक के अरब देश—मिस्र, सीरिया फ़िलिस्तीन और इराक़—इससे बहुत ज्यादा आगे बढ़ गये । अरब एक बड़ा भारी देश है । फ़लाव और रक़बे में वह हिन्दुस्तान के दो-तिहाई के करीब है । लेकिन उसकी आबादी सिर्फ़ ४० या ५० लाख ही है जो हिन्दुस्तान की आबादी का ७०वां या ८०वां हिस्सा है । इससे जाहिर होता है कि वहाँ आबादी घनी नहीं है । दरअसल

उसके ज्यादातर हिस्से में तो रेगिस्तान है, और इसी सबब से पुराने जमाने के लालची बहादुरों की निगाह उसपर नहीं पड़ी और वह तब्दील होते हुए जमाने में बगैर रेल, तार और टेलीफोन के मध्ययुग के निशान-सा बना रहा। उसमें ज्यादातर घूमने-फिरने वाले खानाबदोश फिरके, जिन्हें बंदाऊन कहते हैं, बसते थे। ये लोग रेगिस्तान में एक सिरे से दूसरे सिरे तक 'रेगिस्तान के जहाजों' यानी अपने तेज ऊंटों और अपने खूबसूरत अरबी घोड़ों पर, जो दुनियाभर में मशहूर हैं, सफ़र किया करते थे। उनकी जिन्दगी का वही पुराना ढंग था जिसमें कुटुम्ब का बड़ा-बूढ़ा अगुआ होता था और सब उसका कहना मानकर चलते थे। हजार वर्ष में भी उनकी हालत में कोई खास तब्दीली नहीं हुई थी। लेकिन महायुद्ध ने जिस तरह और भी कई चीजों को तब्दील कर दिया इसी तरह इस सबको भी बदल दिया।

अगर तुम नक़्शे को देखोगी तो तुम्हें मालूम होगा कि अरब यानी अरबिस्तान का महान् प्रायद्वीप, लाल समुद्र और ईरान की खाड़ी के बीच में है। उसके दक्षिण में अरब सागर है, और उत्तर में फ़िलस्तीन और ट्रान्स-जोर्डन और सीरिया का रेगिस्तान है, और उत्तर-पूर्व की तरफ़ इराक़ की हरी और उपजाऊ तराई है। पश्चिमी किनारे पर लाल समुद्र से लगा हुआ हेजाज़ का प्रदेश है, जो इस्लाम का जन्म-स्थान है और जिसमें मक्का और मदीना के पवित्र नगर हैं और जद्दाह का बन्दरगाह है, जहाँ हर साल मक्का को जानेवाले हजारों यात्री उतरा करते हैं। अरब के बीच में और पूर्व में ईरान की खाड़ी तक फैला हुआ नज्द प्रदेश है। हेजाज़ और नज्द यही दोनों अरबिस्तान के खास हिस्से हैं। दक्षिण-पश्चिम में यमन है, जिसे पुराने रोमन जमाने से अरेबिया फ़ेलिक्स यानी खुशकिस्मत अरबिस्तान कहा जाता है, क्योंकि दूसरे रेगिस्तान और बंजर हिस्से के मुक़ाबिले में यह उपजाऊ रहा है। कुदरती तौर पर इस हिस्से में आबादी घनी होनी चाहिए। अरब के दक्षिण-पश्चिमी सिरे के ऊपर अदन है, जो अंग्रेज़ों के कब्ज़े में है और जहाँ पूर्व और पश्चिम के बीच आने-जाने वाले जहाज़ ठहरा करते हैं।

महायुद्ध से पहले क़रीब-क़रीब सारा ही देश तुर्की शासन में था या तुर्की हुकूमत को तस्लीम करता था। लेकिन नज्द में अमीर इब्नसऊद धीरे-धीरे आज़ाद बनता जा रहा था और इलाक़े पर इलाक़ा सर करता हुआ ईरान की खाड़ी की तरफ़ बढ़ रहा था। यह बात महायुद्ध के पहले के कुछ वर्षों की है। इब्नसऊद मुसलमानों की एक खास क़ौम या फ़िरक़े का, जिसे वहाबी कहते हैं और जिसको अठारहवीं सदी में अब्दुलवहाब ने क़ायम किया था, सरदार था। वहाबी असल में इस्लाम का एक सुधारक दल था, जैसाकि ईसाइयों में प्यूरिटन मत है। वहाबी लोग कई रीति-रिवाजों

के और पीर-पूजा के खिलाफ थे, जो मुसलमानों में मक्कबरोँ और धार्मिक लोगों के स्मारकों की पूजा के रूप में बहुत फैल गई थी। वहाबी लोग इसे बुतपरस्ती कहा करते थे, जैसे कि योरप के प्यूरिटन लोग रोमन कैथलिकों को, जो सन्तों की मूर्तियों और स्मारकों को पूजते थे, मूर्तिपूजक कहा करते थे। इस तरह राजनैतिक विरोध के अलावा, वहाबियों और अरब के दूसरे मुस्लिम फ़िरक़ों में मजहबी झगड़ा भी था।

महायुद्ध के जमाने में अरब में ब्रिटिश साजिशों ने जोर पकड़ा, और मुहम्मद-लिफ़ अरब सरदारों को मदद और रिश्तत देने के लिए ब्रिटेन और हिन्दुस्तान का रुपया पानी की तरह बहाया गया। उनसे जितने किस्म के भी वादे हो सकते हैं सभी किये गये, और उन्हें तुर्की के खिलाफ़ बगावत करने के लिए भड़काया गया। कभी-कभी सरदार एक-दूसरे से लड़ते थे और दोनों को अंग्रेज़ों से मदद मिलती थी! अंग्रेज़ लोग मक्का के शरीफ़ हुसैन के जरिये अरब-विद्रोह का झंडा उठवाने में कामयाब होगये। हुसैन का महत्व इस बात से था कि वह पैगम्बर मुहम्मद साहब के ख़ानदान में था, और इसलिए उसकी बड़ी इज्जत थी। अंग्रेज़ों ने हुसैन से वादा किया कि वे उसे सारे अरब के संयुक्त राज्य का बादशाह बना देंगे।

लेकिन इब्नसऊद ज्यादा होशियार था। उसने अंग्रेज़ों से अपने-आपको खुद-मुहम्मद बादशाह तसलीम करवा लिया। उसने ५,००० पौण्ड या ७०,००० रुपया माहवार की रक़म लेना मंज़ूर कर लिया और तटस्थ रहने का वादा कर दिया। इस तरह जबकि दूसरे लोग लड़ते रहे, वह अपनी स्थिति को मजबूत और संगठित बनाता रहा, और उसमें किसी हद तक अंग्रेज़ों के रुपये की भी मदद रही। इस्लामी मुल्कों में, हिन्दुस्तान में भी, शरीफ़ हुसैन अप्रिय होता जा रहा था, क्योंकि उसने तुर्की के सुलतान के खिलाफ़, जो कि उस वक़्त ख़लीफ़ा भी था, बगावत की थी। इब्नसऊद ने तटस्थ रहकर बदलती हुई परिस्थितियों का पूरा फ़ायदा उठाया, और धीरे-धीरे इस्लाम का एक ताक़तवर आदमी होने का नाम पा लिया।

दक्षिण में यमन था। यमन का इमाम या शासक युद्ध के जमाने में हमेशा तुर्कों का वफ़ादार रहा। लेकिन वह लड़ाई की जगह से अलग जा पड़ा था और कोई ज्यादा मदद न पहुँचा सकता था। तुर्कों की हार के बाद वह खुदमुहम्मद होगया। यमन भी एक स्वतन्त्र राज्य है।

महायुद्ध के अख़ीर में अरब इंग्लैण्ड के ही हाथों में था, और इंग्लैण्ड हुसैन और इब्नसऊद दोनों को अपने हथियार की तरह से इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इब्नसऊद में इतनी होशियारी थी कि वह उनकी कठपुतली न बना। परन्तु शरीफ़ हुसैन के ख़ानदान की शान अचानक ही बहुत बढ़ गई, क्योंकि

उसकी पीठ पर अंग्रेजों की ताकत थी। खुद हुसैन हेजाज का बादशाह बना; उसका एक लड़का फ़ैज़ल सीरिया का शासक बना; और दूसरे लड़के अब्दुल्ला को अंग्रेजों ने ट्रान्स-जोर्डन नामक नये राज्य का शासक बना दिया। मगर यह शान चन्द दिन ही क़ायम रही, क्योंकि, जैसाकि पहले बयान किया जा चुका है, फ़ैज़ल को सीरिया से फ़्रांसीसियों ने भगा दिया, और हुसैन की बादशाहत इब्नसऊद के वहावियों की चढ़ाई के सामने ख़त्म होगई। फ़ैज़ल फिर बेकारों में शामिल होगया और उसे अंग्रेजों ने इराक़ की हुकूमत दे दी, जहाँकि वह अब भी अंग्रेजों की मेहरबानी से शाह बना हुआ शासन कर रहा है।

उस थोड़े-से असें में, जबकि हुसैन हेजाज का बादशाह था, अंगोरा की तुर्की पार्लमेण्ट ने १९२४ में ख़िलाफ़त को मिटा दिया। अब कोई ख़लीफ़ा न रहा। इसलिए हुसैन बड़ी भारी हिम्मत करके ख़ाली तख़्त पर खुद जा कूदा, और उसने अपनेआपको इस्लाम का ख़लीफ़ा ऐलान कर दिया। इब्नसऊद ने देखा कि बस उसके लिए यही अच्छा मौक़ा है और उसने अरब राष्ट्रीयता और मुस्लिम अन्तर्राष्ट्रीयता के सामने हुसैन की मुख़ालफ़त की। वह एक महत्वाकांक्षी अनधिकारी के मुक़ाबिले में इस्लाम का हिमायती बन गया, और बड़े कुशलतापूर्ण प्रचार की मदद से उसने दूसरे देशों के मुसलमानों की सद्भावना प्राप्त करली। हिन्दुस्तान की ख़िलाफ़त कमेटी ने भी उसके पास अपनी सद्विचारों भेजीं। अंग्रेजों ने भी हवा का रज़ देखकर, यह महसूस करके कि जिस व्यक्ति की वे अबतक हिमायत करते रहे वह कामयाब न होगा, चुपचाप हुसैन का साथ छोड़ दिया। उन्होंने रुपया देना बन्द कर दिया और एक मजबूत और चढ़ाई करते हुए दुश्मन के सामने बेचारा हुसैन, जिसके साथ इतने वादे किये गये थे, अकेला लाचार और असहाय छोड़ दिया गया।

कुछ ही महीनों में, अक्टूबर १९२४ में, वहावी मक्का में दाख़िल होगये, और उन्होंने अपने कट्टरमत के अनुसार कुछ मक्कवरों को बर्बाद कर दिया। इस बर्बादी की वजह से मुसलमानी मुल्कों में बहुत अंदेशा फैल गया। हिन्दुस्तान में भी इसका बड़ा विरोध किया गया। दूसरे साल मदीना और जद्दाह भी इब्न-सऊद के हाथ में आगये, और हुसैन और उसका ख़ानदान हेजाज से निकाल दिया गया। १९२६ के शुरू में इब्नसऊद ने अपनेको हेजाज का बादशाह घोषित कर दिया। अपनी नई स्थिति को मजबूत बनाने और बाहर के मुसलमानों की सद्भावना बनाये रखने के लिए उसने जून १९२६ में मक्का में सारे दुनिया के मुसलमानों की काँग्रेस बुलाई, जिसमें उसने दूसरे देशों के प्रतिनिधियों को भी बुलाया। उसे ख़लीफ़ा बनने की कोई इच्छा न थी, और उसके वहावी-मत के बहुत-से मुसलमान उसे किसी तरह भी ख़लीफ़ा नहीं मान

सकते थे। मिस्त्र का शाह फुआद, जिसके राष्ट्र-विरोधी और स्वेच्छाचारी कारनामों पर हम पहले गौर कर चुके हैं, खलीफ़ा बनने को बहुत इच्छुक था, लेकिन उसे कोई नहीं चाहता था—खुद मिस्त्र-वासी भी नहीं चाहते थे। शिकस्त खाने के बाद, हुसैन ने भी खलीफ़ा होने का अपना दावा छोड़ दिया।

मक्का की इस्लामी काँग्रेस ने कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं किये, और शायद उसकी गरज भी यह नहीं थी कि उसमें कोई महत्वपूर्ण बात हो। वह तो इब्नसऊद की अपनी स्थिति को, खासकर बाहरी ताक़तों के सामने, मज़बूत बनाने की तरकीब थी। खिलाफ़त कमेटी के हिन्दुस्तानी प्रतिनिधि, जिनमें मेरे ख़याल से मौलाना नुहम्मद-अली भी शामिल थे, इब्नसऊद से निराश और नाराज़ होकर लौटे। लेकिन उसपर इसका कोई असर न पड़ा। उसने हिन्दुस्तान की खिलाफ़त कमेटी का उपयोग कर लिया था, जब कि उसे उसकी ज़रूरत थी। अब तो उसकी सद्भावना के बग़ैर भी उसका काम चल सकता था।

इब्नसऊद सिपाही और योद्धा की हैसियत से तो कामयाब हो ही गया था; अब वह उससे भी मुश्किल काम में यानी अपनेको आजकल के हालात के मुताबिक़ बनाने में लग गया। यह तरक्की पुराने ढंग के खानदानी समाज से एकाएक आजकल की दुनिया में छलाँग मारकर आजाने के बराबर हुई। मालूम होता है कि इस काम में भी इब्नसऊद को काफ़ी कामयाबी मिली है, और उसने इस तरह साबित कर दिया है कि वह दूरदर्शी राजनीतिज्ञ है।

उसकी पहली कामयाबी खानाजंगी यानी अन्दरूनी झगड़ों में हुई। बहुत ही थोड़े अर्से में कारवान और सफ़र के रास्ते बिल्कुल सुरक्षित होगये। यह एक बड़ी फ़तहयाबी थी, और कुदरती तौर पर बहुत-से यात्रियों ने, जिन्हें कि अभीतक रास्तोंमें राहज़नी और लूट का अकसर सामना करना पड़ता था, इसे बहुत पसन्द किया।

इससे भी आश्चर्यजनक सफलता थी—धूमते-फिरते रहनेवाले बदायूनों को बसा देना। उसने इनका बसाना हेजाज़ जीतने से भी पहले शुरू कर रखा था, और इस तरह उसने एक आधुनिक राज्य की नींव डाल दी। इन न टिकनेवाले घुमक्कड़ और आज़ादी-पसन्द बदायूनों को बसाना आसान काम नहीं है, लेकिन इसमें इब्नसऊद को बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। राज्य का इन्तज़ाम कई बातों में सुधरा है, और हवाई जहाज़ और मोटरें और टेलीफ़ोन और आधुनिक सभ्यता के कई दूसरे निशान दिखाई देने लगे हैं। लेकिन मध्ययुग से आधुनिक युग में छलाँग मारना आसान काम नहीं है, और सबसे ज़्यादा कठिनाई लोगों के ख़यालात बदलने में आती है।

यह नई तरक्की और तब्दीली बहुत-से अरबों को पसन्द नहीं आई; पश्चिम की नई गढ़ी हुई मशीनें, उनके एंजिन और मोटरें और हवाई-जहाज उन्हें शैतान के आविष्कार मालूम हुए। उन्होंने इन नई बातों का विरोध किया, और १९२९ में उन्होंने इन्सऊद के खिलाफ बशावत भी कर दी। इन्सऊद ने उन्हें चतुराई और दलीलों से अपनी तरफ़ मिलाने की कोशिश की, और कइयों को मिलाने में कामयाब भी हुआ। कुछ लोगों ने बशावत जारी रखी और इन्सऊद के जरिये पस्त कर दिये गये।

इसके बाद इन्सऊद के सामने एक दिक्कत और आई, लेकिन यह दिक्कत तो सारी दुनिया के ही सामने आई थी। १९३० से सभी जगह व्यापार में भारी मन्दी आ गई है। पश्चिम के बड़े-बड़े औद्योगिक देशों ने इसको सबसे ज्यादा महसूस किया है, और इसके बढ़ते हुए जाल से निकलने के लिए अब भी पैर पीट रहे हैं। संसार के व्यापार से अरब का कोई वास्ता नहीं है, लेकिन वहाँ मन्दी का अनुभव दूसरी तरह से हुआ। इन्सऊद की आमदनी का खास ज़रिया हर साल मक्का आनेवाले यात्रियों की तादाद थी। विदेशों से हर साल करीब एक लाख यात्री मक्का आया करते थे। १९३० में यह तादाद घटकर चालीस हजार रह गई, और घटती अब भी जारी है। इसका नतीजा यह हुआ कि राज्य की आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल उलट-पुलट होगई, और अरब के कई हिस्सों में बड़ी ही दुर्दशा पैदा होगई। कहा जाता है कि कई प्रदेशों की हालत तो इतनी बुरी है कि तुर्की हुकूमत के ख़राब-से-ख़राब ज़माने में भी वैसी नहीं हुई थी। रुपये की कमी से इन्सऊद का हाथ तंग होगया और उसकी कई सुधार-योजनायें बन्द होगई। वह विदेशियों को उद्योग और व्यापार-सम्बन्धी सुविधायें नहीं देना चाहता था, क्योंकि उसका यह अन्देशा सही था कि अगर विदेशी लोग देश के औद्योगिक साधनों को काम में लायेंगे तो उससे विदेशी असर बढ़ेगा, और फिर इससे विदेशी दस्तन्दाजी होगी और अपनी आज़ादी में कमी आयगी। उसका अन्देशा बिल्कुल ठीक था, क्योंकि ज्यादातर जिन तकलीफों को औपनिवेशिक और गुलाम देशों ने वर्दाश्त किया है वे विदेशी उद्योग-विस्तार से ही पैदा हुई हैं। इन्सऊद ने कुछ तरक्की और खुशहाली होने लेकिन आज़ादी के मिटने की बनिस्बत आज़ादी को ज्यादा पसन्द किया।

फिर भी मन्दी की मजबूरी से इन्सऊद को अपनी नीति में थोड़ा सुधार करना पड़ा है, और अब वह विदेशियों को कुछ सहूलियतें देने को तैयार है। लेकिन इस स्थिति में भी वह अपनी आज़ादी को महफूज़ रखने का खयाल रखता है, और इसके लिए शर्तें तय कर दी गई हैं। इस तरह पहली सहूलियत जद्दाह बन्दरगाह और मक्का के बीच रेल बनाने के लिए एक हिन्दुस्तानी मुस्लिम पंजीपति दल को दी जाने

वाली हैं। अरब में यह रेल एक बड़ी भारी चीज़ होगी, क्योंकि इससे वार्षिक यात्राओं में कान्ति होजायगी। इससे सिर्फ़ यात्रियों को ही फ़ायदा न पहुँचेगा, बल्कि अरब लोगों के दृष्टिकोण को आधुनिक बनाने में भी मदद मिलेगी। उम्मीद है कि रेल दो साल में यानी १९३५ की वसन्त ऋतु से चलने लगेगी।

किसी पिछले ख़त में मैं लिख चुका हूँ कि अरब में एक रेलवे तो पहले से ही मौजूद है, जो हेजाज़ रेलवे कहलाती है और मदीना को सीरिया के अलप्पो नामक स्थान पर बग़दाद रेलवे से जोड़ती है।

इस ख़त के शुरू के हिस्से में मैंने ज़िक्र किया है कि दक्षिण-पश्चिम में यमन का नाम 'अरेबिया फ़ेलिक्स' था। वास्तव में यह नाम तो दक्षिणी अरब के एक बड़े हिस्से को भी दिया गया था, जो करीब-करीब ईरान की खाड़ी तक फैला हुआ था। लेकिन इस प्रदेश के लिए यह नाम बिल्कुल ग़ैरमौजू है, क्योंकि यह तो एक भद्दा-सा रेगिस्तान है। शायद पुराने ज़माने में इसे लोग काफ़ी तौर पर जानते नहीं थे और इसलिए यह ग़लती होगई। हालतक तो यह एक अज्ञात प्रदेश था, दुनिया की सतह पर की उन थोड़ी-सी जगहों में से एक था जिनकी नाप होकर नक्शा भी नहीं बना है। सिर्फ़ तीन साल पहले, पहली मर्तबा, एक अंग्रेज़ अन्वेषणकारी ने इसको पार किया है।

: १६६ :

इराक़ और आसमान से बम-वर्षा

७ जून, १९३३

अब एक अरब देश और रहता है, जिसपर हमें विचार करना है। यह देश है इराक़ या मेसोपोटामिया—टाइग्रिस (दज्जला) और यूफ़्रेटीज (फ़ुरात) नदियों के बीच का सम्पन्न और उपजाऊ प्रदेश; पुराने किस्से-कहानियों, बग़दाद, और हारून-ल-रशीद और अल्लिफ़ लैला की भूमि। यह ईरान और अरबी रेगिस्तान के बीच में स्थित है। दक्षिण में इसका ख़ास बन्दरगाह बसरा है, जो कि ईरान की खाड़ी से कुछ दूर नदी के ऊपर है। उत्तर में यह तुर्की की हद से लगा हुआ है। इराक़ और तुर्की दोनों कुर्दिस्तान में आ मिले हैं, जहाँ कि कुर्द जाति बसती है। अधिकांश कुर्द लोग तो अब तुर्की में हैं, और मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ कि वे तुर्की से अपनी आजादी के लिए लड़े थे। लेकिन ईरान में भी कुछ कुर्द लोग हैं और उनका वहाँ भी एक छोटी तादादवाला पर महत्वपूर्ण समाज है। मोसल, जिसकी बाबत बहुत अनेक तुर्की

और इंग्लैण्ड में झगड़ा चलता रहा था, अब इराक़ के इस उत्तरी कुर्दिश प्रदेश में ही है। इसका अर्थ है कि वह अंग्रेज़ों के नियन्त्रण में है। मोसल के नज़दीक ही असीरियनों के प्राचीन नगर निनेव के खंडहर हैं।

इराक़ उन देशों में से एक था जिनके लिए इंग्लैण्ड को राष्ट्र-संघ से 'मैण्डेट' मिला था। 'मैण्डेट' का अर्थ राष्ट्र-संघ की पवित्र भाषा में है : राष्ट्र-संघ की तरफ़ से सभ्यता की 'पवित्र धरोहर' (ट्रस्ट)। मूल उद्देश्य यह था कि 'मैण्डेट' वाले देशों के वाशिन्डे अभी इतने बढ़े हुए नहीं हैं, या इस लायक नहीं हैं, कि वे अपने हितों को खुद सम्हाल सकें, इसलिए बड़ी शक्तियाँ इस काम में उनको मदद दें। शायद इसकी मिसाल यह होसकेगी कि कुछ गायों या हिरनों के हितों की हिफाज़त के लिए किसी शेर को मुकर्रर किया जाय। यह मान लिया गया था कि ये 'मैण्डेट' वहाँके निवासियों के कहने से दिये गये हैं। पश्चिमी एशिया में तुर्की हुकूमत से आजाद किये हुए मुल्कों के मैण्डेट इंग्लैण्ड और फ़्रान्स के हिस्से में आये। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, इन दोनों देशों की सरकारों ने ऐलान किया कि उनका एकमात्र यही उद्देश्य है कि "वहाँकी जातियों को मुकम्मल और यक़ीनी तौर पर सभ्य बनाना" और वहाँ ऐसी राष्ट्रीय सरकारें और व्यवस्थापक-मण्डल क़ायम करना जिनकी हस्ती वहाँ के असली वाशिन्दों की अपनी इच्छा और पसन्द पर मुनहसर या निर्भर हो।" इस उच्च उद्देश्य को हासिल करने के लिए पिछले बारह वर्षों में जो-जो काम किये गये वे हम सीरिया, फिलस्तीन और ट्रान्स-जोर्डन के विषय में मुत्तसर तौर पर देख ही चुके हैं। वहाँ बार-बार गड़बड़ी हुई, असहयोग हुआ और वहिष्कार हुआ। उस वक़्त लोगों की प्रेरणा और दिना किसी दबाव की उनकी पसंदगी को बढ़ावा देने के लिए उन्हें गोलियों से मारा गया, उनके नेताओं को सज़ायें दी गईं और जलावतन किया गया, उनके अख़बारों का दमन किया गया, उनके शहरों और गाँवों को बर्बाद किया गया और अबसर फौजी कानून तक जारी किया गया। इन घटनाओं में नई बात कोई नहीं है। इतिहास के बिलकुल शुरू से ही साम्राज्यवादी शक्तियाँ ज़बरदस्ती से काम लेती और विनाश और आतंक फैलाती रही हैं। नये ढंग के साम्राज्यवाद में नई बात यह है कि वह अपने आतंक और लूट को 'ट्रस्टीशिप', 'जनता का हित', 'पिछड़ी हुई जातियों को स्वायत्त-शासन की तालीम देना' वगैरह बड़े-बड़े जुमलों के परदे में छिपाने की कोशिश करता है। वे लोगों पर गोली चलाते हैं, मारते हैं और बर्बाद करते हैं—सिर्फ़ उन्हीं मरनेवाले लोगों की भलाई के लिए ! यह पाखण्ड शायद तरक्की की निशानी हो, क्योंकि भलाई के लिए पाखण्ड करना ही पड़ता है; और इससे जाहिर होता है कि सचाई पसन्द नहीं की जाती और इसलिए उसे इन पसन्द आनेवाले और बहलाने

वाले वाक्यों में ढक दिया जाता है, और इस तरह उसे छिपा दिया जाता है। लेकिन कभी-कभी यह साधुता-प्रदर्शक पाखण्ड नंगी सचाई से बहुत बुरा लगता है

अब हम इस बात पर गौर करते हैं कि इराक़ में लोगों की इच्छाओं पर किस तरह अमल किया गया, और ब्रिटिश मण्डेट में यह देश किस तरह आजादी की तरफ़ बढ़ता चला गया। महायुद्ध के दौरान में अंग्रेज़ों ने इराक़ को—या, जिस नाम से वह उस वक़्त मशहूर था, मेसपॉट को—तुर्की के खिलाफ़ अपनी कारगुजारियों का खास मुक़ाम बना लिया था। उन्होंने इस देश में अंग्रेज़ी और हिन्दुस्तानी फौजों की भर-मार करदी थी। उन्हें १९१६ में एक बड़ी शिकस्त मिली, जबकि कुतलअमारा में जनरल टाउनशेण्ड की मातहतों में एक ब्रिटिश फौज को तुर्कों के सामने हार खानी और शरण लेनी पड़ी। सारे मेसोपोटामियन युद्ध में भयंकर फ़िज़ूलखर्ची और बर्द-इन्तज़ामी रही, और चूँकि भारत-सरकार इसके लिए ज्यादातर ज़िम्मेदार थी इसलिए उसे अपनी नालायकी और बेवकूफी के बारे में बहुत सख़्त बातें बर्दाश्त करनी पड़ीं। फिर भी, अख़ीर में अंग्रेज़ों के बढ़े हुए साधनों का नतीजा निकला ही और उन्होंने तुर्कों को उत्तर में खदेड़ दिया और बाद में वे क़रीब-क़रीब मोसल तक जा पहुँचे। महायुद्ध के अख़ीर में सारा इराक़ अंग्रेज़ों के फ़ौजी कब्ज़े में था।

इंग्लैण्ड को इराक़ का मण्डेट मिलने का पहला असर १९२० के शुरू में जाहिर हुआ। इसके खिलाफ़ जबरदस्त विरोध किया गया, जो बढ़ते-बढ़ते दंगे-फसाद की शक्ल में जाहिर हुआ, और दंगों ने बगावत की शक्ल इख्तियार करली, जोकि सारे देश में फैल गई। यह एक अजीब और मजेदार बात है कि १९२० के इस पहले आधे हिस्से में क़रीब-क़रीब एकसाथ ही तुर्की, मिस्र, सीरिया, फिलस्तीन, इराक़ और ईरान में गड़बड़ी हुई थी। हिन्दुस्तान में भी उन्हीं दिनों असहयोग की चर्चा थी। इराक़ की बगावत को अन्त में, खासकर हिन्दुस्तान की फ़ौज की मदद से, दबा दिया गया। बहुत असें से हिन्दुस्तान की फ़ौजों का यह काम रहा है कि वे ब्रिटिश साम्राज्यवाद का गन्दा काम किया करती हैं, और इस कारण मध्य-पूर्व और दूसरे मुल्कों में हमारे देश की काफ़ी बदनामी होगई है।

अंग्रेज़ों ने इराक़ की बगावत को कुछ तो जोर-जबरदस्ती से और कुछ भविष्य में आजादी देने के वादों से दबा दिया। उन्होंने अरब मन्त्रियों की एक अस्थायी सरकार तैयार की, लेकिन हर मन्त्री के साथ एक अंग्रेज़ सलाहकार था जोकि असली ताक़त रखता था। मगर ये फालतू और नामजद मन्त्री भी इतने तेज़ थे कि अंग्रेज़ों को पसन्द न आये। अंग्रेज़ों की योजना यह थी कि इराक़ दिलकुल उनके हुक्म के

मुताबिक अमल करे, पर कुछ मन्त्रियों ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया। इसलिए अप्रैल १९२१ में अंग्रेजों ने मुख्य मंत्री सैयद तालिबशाह को, जो कि उनमें सबसे ज्यादा लायक था, गिरफ्तार करके जलावतन कर दिया, और इस तरह मुल्क को आजादी के वास्ते तैयार करने के लिए यह दूसरा क्रदम उठाया गया। १९२१ की गर्मियों में अंग्रेज हेजाज के शाह हुसैन के लड़के फ़ैज़ल को ले आये, और उसे इराकियों के सामने उनके भावी बादशाह के रूप में पेश किया गया। तुम्हें याद होगा कि उन दिनों फ़ैज़ल बेकार था, क्योंकि उसकी सीरिया वाली कारगुजारी फ़्रान्सीसी हमले के आगे असफल हो चुकी थी। वह अंग्रेजों का एक अच्छा दोस्त था, और उसने महायुद्ध में तुर्की के खिलाफ़ उठनेवाले अरब विद्रोह में सबसे ज्यादा हिस्सा लिया था। इसलिए यह मुमकिन था कि स्थानीय मन्त्री अंग्रेजों की योजनाओं के जितने मुआफ़िक़ हो पाये थे, उससे वह ज्यादा मुआफ़िक़ होता। 'प्रतिष्ठित' लोगों यानी मध्य दर्जे के मालदार लोगों और दूसरे प्रमुख व्यक्तियों ने इस शर्त पर फ़ैज़ल को अपना बादशाह बना लेना मंजूर कर लिया कि हुक्मत वैधानिक हो और उसके साथ प्रजातन्त्रवादी पार्लमेण्ट हो। उनके हाथ में कुछ था तो नहीं, लेकिन चाहते थे कि एक सच्ची पार्लमेण्ट बने, और चूँकि फ़ैज़ल बादशाह बनने ही वाला था इसलिए उन्होंने पार्लमेण्ट बनने की यह एक शर्त रखदी। आम तौर पर लोगों की राय नहीं ली गई। इस तरह अगस्त १९२१ में फ़ैज़ल बादशाह बन गया।

लेकिन इससे समस्या हल नहीं होती थी, क्योंकि इराकी लोग ब्रिटिश मण्डल के बहुत खिलाफ़ थे और मुकम्मल आजादी हासिल करके दूसरे अरब देशों के साथ मिल जाना चाहते थे। आन्दोलन और प्रदर्शन जारी रहे, और एक साल बाद अगस्त १९२२ में मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया। तब अंग्रेज अधिकारियों ने इराकियों को आजादी का एक सबक और पढ़ाया। ब्रिटिश हाइकमिशनर सर पर्सी काक्स ने बादशाह की (जो उस समय बीमार था) मंत्रि-मण्डल की, और इराक़ को जिस तरह की भी कौंसिल दी गई थी उस सबकी सत्ता का ख़ात्मा कर दिया, और शासन के पूरे अख़्तियारात खुद ले लिये। दरहक़ीक़त, वह खुद-मुख्तार डिक्टेटर बन गया, और उसने जैसा मन में आया वैसा जबरदस्ती किया और गड़बड़ी को अंग्रेजी फ़ौज और ख़ासकर ब्रिटिश हवाई फ़ौज की मदद से दबा दिया। वही पुराना क्रिस्ता जो कि थोड़े-थोड़े फ़र्क़ से हिन्दुस्तान, मिस्र, सीरिया वगैरह में हुआ, यहाँ भी दोहराया गया। राष्ट्रीय अख़बार रोक दिये गये, पार्टियाँ तोड़ दी गईं, नेता जलावतन कर दिये गये और अंग्रेजी हवाई जहाज़ों ने बमों के ज़रिये ब्रिटिश साम्राज्य की ताक़त को क़ायम कर दिया।

लेकिन फिर भी इससे समस्या का हल न हुआ। कुछ महीनों के बाद सर परसी कावस ने बादशाह और मंत्रि-मंडल को फिर काम करने का जाहिरा मौक़ा दिया, और इन लोगों से ब्रिटेन के साथ एक सुलह मंजूर करवाली। फिर आश्वासन दिये गये कि इंग्लैंड इराक को आज़ादी हासिल करने में मदद देगा और राष्ट्र-संघ का मेम्बर भी बनवा देगा। इन सुन्दर और तसल्ली देनेवाले वादों के परदे में यह ठोस वाक़या छिपा हुआ था कि इराक़-सरकार को इस बात के लिए राजी कर लिया गया कि वह अंग्रेज़ अफ़सरों या अंग्रेज़ों के पसन्द किये हुए अफ़सरों की मदद से हुकूमत को चलावे। अक्टूबर १९२२ की इस सुलह की, जो कि लोगों की इच्छा के खिलाफ़ हुई, जनता ने निन्दा की। जनता ने कहा कि अरब मंत्रिमण्डल तो एक धोखा है, और असली ताक़त फिर भी अंग्रेज़ अफ़सरों के हाथों में है। नेताओं ने नैशनल कान्स्टीट्यूएण्ट एसेम्बली का, जो कि भावी विधान तैयार करने के लिए बुलाई गई थी, बहिष्कार करने का फ़ैसला किया। यह असहयोग कामयाब हुआ और असेम्बली की बैठक न हो सकी। टैक्स वसूल करने में भी बड़ी गड़बड़ी और दिक्कतें पैदा हो गईं।

एक वर्ष से भी ज्यादा असें तक, १९२३ के तमाम साल, ये झगड़े चलते रहे। आख़िरकार इराक़ के हक़ में कुछ तब्दीलियाँ सन्धि में करदी गईं और आन्दोलन खड़ा करनेवाले ख़ास नेताओं को जलावतन कर दिया गया। फलतः आन्दोलन धीमा पड़ गया, और १९२४ के शुरू में कान्स्टीट्यूएण्ट एसेम्बली का चुनाव हो सका। इस एसेम्बली ने भी ब्रिटिश सुलहनामे का विरोध किया। इसपर अंग्रेज़ों पर भारी दबाव डलवाया, और आख़िरकार एक-तिहाई से कुछ ज्यादा मेम्बरों ने सन्धि पर मंजूरी दे दी; लेकिन बहुत-से सदस्य तो इस अधिवेशन में आये तक नहीं थे।

कान्स्टीट्यूएण्ट एसेम्बली ने इराक़ के लिए एक नया विधान तैयार किया। कागज़ पर लिखा हुआ तो वह अच्छा ही मालूम हुआ, क्योंकि उसमें यह तय कर दिया गया कि इराक़ एक ख़ुद-मुख्तार आज़ाद राज्य है जिसमें कि पुश्तैनी वैधानिक बादशाहत रहेगी और पार्लमेण्टरी ढंग का शासन होगा; लेकिन पार्लमेण्ट की दो मजलिसों में से एक की, यानी सिनेट की, नामज़दगी बादशाह पर रक्खी गई। इस तरह बादशाह के हाथ में बड़ी ताक़त रही, और बादशाह की पीठ पर थे अंग्रेज़ अफ़सर जो कि सभी महत्व-पूर्ण ओहदों पर क़ायम थे। यह विधान मार्च १९२५ से अमल में आया, और कुछ वर्षों तक नई पार्लमेण्ट काम करती रही, लेकिन मण्डेट की मुख़ालिफ़त फिर भी जारी रही। अधिकांश समय तो लोगों का ध्यान मोसल के मामले में इंग्लैंड और तुर्की के झगड़े पर लगा रहा, क्योंकि इस प्रदेश का दावेदार इराक़ भी था। आख़िरकार जून १९२६ में इंग्लैंड, इराक़ और तुर्की के बीच एक सम्मिलित सन्धि होकर इस मामले

का फ़ैसला हो गया। मोसल इराक़ को मिल गया, और चूँकि इराक़ खुद ब्रिटिश साम्राज्य की छाया में था इसलिए अंग्रेज़ों के स्वार्थ भी सुरक्षित रहे।

जून १९३० में, ब्रिटेन और इराक़ में एक और दोस्ताना मुलह हुई। इसके जरिये भी, अन्दरूनी और बाहरी मामलों में इराक़ की मुकम्मिल आजादी को तस्लीम किया गया। लेकिन शर्तें और शर्कावटें ऐसी रखी गईं जिनसे कि यह आजादी गुलामी में तब्दील हो जाती थी। मोसलन हिन्दुस्तान को जानेवाले रास्तों की, जिसे सन्धि में 'ज़रूरी आमद-रफ्त' कहा गया है, हिफाज़त के लिए इराक़ इंग्लैंड को हवाई-अड्डों के लिए जगह देगा। ब्रिटेन मोसल और दूसरी जगहों पर भी अपनी फ़ौजें रखेगा। इराक़ फ़ौजी तालीम के लिए सिर्फ़ अंग्रेज़ शिक्षक ही रख सकेगा और इराक़ी फ़ौज में अंग्रेज़ अफ़सर सलाहकार की हैसियत से मुलाज़िम रहेंगे। हथियार, गोला-बारूद, हवाई जहाज़ वगैरा सिर्फ़ इंग्लैंड से लिये जायेंगे। युद्ध छिड़ने पर, दुश्मन से जंगी तैयारियाँ करने के लिए, अंग्रेज़ों को देश में सब तरह के सुभीते कर दिये जायेंगे। इस तरह मोसल के पास के मोर्चे से इंग्लैंड बड़ी आसानी से तुर्की, ईरान या आज़र-बाय-जान के सोवियट पर हमला कर सकता है।

इस सन्धि के बाद १९३१ में ब्रिटेन और इराक़ के बीच एक जुडीशियल सन्धि भी हुई, जिसके जरिये इराक़ ने एक अंग्रेज़ जुडीशियल सलाहकार, (अपील की अदालत का अंग्रेज़ प्रेसीडेण्ट) और बग़दाद, बसरा, मोसल और दूसरी जगहों में अंग्रेज़ प्रेसीडेण्ट रखना मंज़ूर कर लिया।

इन शर्तों के अलावा भी मालूम होता है कि अंग्रेज़ अफ़सर और भी कई ऊँचे ओहदों पर हैं। नतीजा यह है कि यह 'आजाद' मुल्क दरहक़ीक़त इंग्लैंड का एक मातहत मुल्क बन गया है। १९३० की संधि, जिसके जरिये से यह सब हुआ है, पच्चीस साल के लिए है।

१९२५ में नये विधान के मंज़ूर होने के बाद हालाँकि नई पार्लमेण्ट काम करने लगी, लेकिन लोग संतुष्ट नहीं थे और बाहरी प्रदेशों में कभी-कभी झगड़े होजाते थे। ऐसा खासकर कुदिश इलाके में होता था, जहाँ कि बार-बार अशान्ति खड़ी हो जाती थी, और जिसे ब्रिटिश हवाई फ़ौज ने बम-वर्षा और सारे गाँव की तबाही की कारगुजारियों के जरिये दबा दिया। १९३० की संधि के बाद इराक़ के ब्रिटिश सरपरस्ती में राष्ट्र-संघ में शामिल किये जाने का सवाल खड़ा हुआ। लेकिन देश में तो शान्ति नहीं थी, और झगड़े होते ही रहते थे। इससे न तो मैण्डेटरी-शक्ति इंग्लैंड की नेकनामी होती थी, और न बादशाह फ़ैज़ल की हुकूमत की ही नामवरी होती थी, क्योंकि बग़दादियों से काफ़ी सबूत मिलता था कि अंग्रेज़ों द्वारा ज़बरदस्ती लादी हुई

सरकार से लोग संतुष्ट नहीं हैं। यह बहुत ही अवाञ्छनीय समझा गया कि राष्ट्र-संघ के सामने ये बातें आवें, इसलिए इन झगड़ों को बल और आतंक से खत्म कर देने की खास कोशिश की गई। इस काम के लिए अंग्रेजी हवाई फ़ौज का इस्तेमाल किया गया। शान्ति और व्यवस्था कायम करने की उसकी कोशिश का नतीजा किसी हद तक एक मशहूर अंग्रेज़ अफसर के वयान से समझा जा सकता है। ८ जून १९३२ को, लंदन में रायल एशियन सोसायटी की सालगिरह के जलसे पर व्याख्यान देते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल सर आरनल्ड विल्सन ने जिक्र किया है कि किस तरह :—

“आग ० ए० एफ० यानी रायल एयर फ़ोर्स ने (जेनेवा की घोषणाओं के विरुद्ध भी) पिछले दस सालों में, और खासकर पिछले छः महीनों में, कुर्दिश जनता पर निरन्तर बम-वर्षा की है। बग़वाद किये हुए गाँव, मरे हुए पशु, अंग-भंग की हुई म्त्रियाँ और बच्चे, ‘टाइम्स’ के विशेष संवाद-दाता के शब्दों में, ये सब इसके सुबूत हैं कि मभ्यता का एक ही माँचा सब जगह फैला हुआ है।”

यह जानकर कि गाँव के लोग हवाई जहाज़ को आता देखकर अक्सर भाग जाते हैं और इतने विनोद-प्रिय नहीं हैं कि बमों द्वारा मारे जाने तक ठहरे रहें, एक नये क्रिस्म का बम भी, जिसे कुछ देर बाद फूटनेवाला बम कहते हैं, इस्तेमाल किया गया। यह गिरते ही फूटता न था बल्कि इस तरह बनाया गया था कि कुछ वक्त बाद फूटा करता था। यह राक्षसी युक्ति इसलिए की गई कि गाँववाले हवाई जहाज़ों के जाने के बाद फिर अपनी झोंपड़ियों में लौट आयें और फिर बमों के फटने से घायल हो जायें। जो मर जाते थे वे तो खुश-क्रिस्मत थे, लेकिन जिनके अंग-भंग हो जाते थे, जिनके हाथ पैर टूट जाते थे, या जिन्हें और किसी जगह सख्त चोटें लगती थीं, वे बहुत ज्यादा बद-क्रिस्मत थे, क्योंकि उन दूर के देहातों में कोई भी डाक्टरों मदद नहीं मिल सकती थी।

इस तरह शान्ति और व्यवस्था फिर कायम होगई, और इराक़ की सरकार ने राष्ट्र-संघ के सामने ब्रिटिश सरपरस्ती में अपनेआपको पेश किया और उसे मेम्बर बना लिया गया। यह बिल्कुल ठीक हो कहा गया है कि ‘बम मार-मार कर’ इराक़ को राष्ट्र-संघ में दाखिल कर दिया गया।

इराक़ के राष्ट्र-संघ का सदस्य बन जाने पर ब्रिटिश मॅण्डेट खत्म होगया। उसकी जगह अब १९३० की संधि आगई, जिससे कि राज्य पर अंग्रेज़ों का अमली दबाव कायम होगया है। इस स्थिति से असन्तोष अब भी जारी है, क्योंकि इराक़ के लोग पूरी आज़ादी और अरब राष्ट्रों की एकता चाहते हैं। राष्ट्र-संघ की मेम्बरी में उनकी थोड़ी दडी दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि पूर्व की अधिकांश दूसरी क़ाओं की तरह

वे समझते हैं कि राष्ट्र-संघ तो बड़ी-बड़ी यूरोपियन शक्तियों के हाथ में एक हथियार है जिससे वे अपने औपनिवेशिक या दूसरे स्वार्थ सिद्ध करती रहती हैं।

अधिक अमली आजादी की माँग इतनी ज़बरदस्त है कि बादशाह फ़ैज़ल तक को उसपर अंग्रेज़ों के सामने जोर देना पड़ा है। जिस समय में यह ख़त लिख रहा हूँ, अख़बारों में यह ख़बर छपी है कि वह कुछ ही दिनों में सरकारी काम से इंग्लैंड जा रहा है। मुमकिन है कि इराक़ और इंग्लैंड के ताल्लुकात के सवाल पर फिर से बहस हो और इराक़ कुछ छोटे-मोटे फ़ायदे हासिल कर सके। जबतक कि फ़ौजी और ख़ास मोर्चेबन्दी सम्बन्धी नियन्त्रण इंग्लैंड के हाथ में रहते हैं तबतक वह महत्वशून्य छोटे-छोटे मामलों में झुक भी सकता है, ताकि वह उदार-हृदय मालूम हो सके और शायद उससे दूसरे पक्ष की सद्भावना भी हासिल कर सके। जब अगला महायुद्ध आयगा, तो इराक़ सम्भवतः एक महत्वपूर्ण केन्द्र बनेगा।

अब हम अरब राष्ट्रों पर सरसरी नज़र डाल चुके हैं। तुमने देखा होगा कि महायुद्ध के बाद ये सब हिन्दुस्तान और पूर्व के दूसरे देशों की तरह राष्ट्रीयता की लहरों से जोरों के साथ हिल उठे थे। मानों विजली की एक लहर इन सब में एक-साथ दौड़ गई हो। दूसरी उल्लेखनीय बात है सबका एक ही तरह के उपाय काम में लाना। इन में से कई देशों में बग़ावतें और हिंसात्मक विद्रोह हुए, लेकिन वे असहयोग और बहिष्कार की नीति की तरफ़ ही ज्यादा झुकते गये। इसमें शक नहीं कि मुकाबिला करने के इस उपाय का रिवाज पहलेपहल १९२० में हिन्दुस्तान ने ही डाला था, जबकि कांग्रेस ने बापू का नेतृत्व ग्रहण किया। मेरा यह मतलब नहीं कि ये दूसरे देश बापू की उसके पक्ष में दी हुई मुख्य दलीलों को भी मानते थे। लेकिन फिर भी असहयोग और कौन्सिलों के बहिष्कार का ख़याल हिन्दुस्तान से ही पूर्व के दूसरे देशों में फैला है, और यह उपाय आजादी की लड़ाई में घर कर गया है और उसपर अक्सर अमल होता है।

साम्राज्यवादी नियन्त्रण अमल में लाते वक़्त इंग्लैंड और फ़्रान्स किस तरह परस्पर जुदा-जुदा उपायों को काम में लाते हैं, यह जानना बड़ा दिलचस्प है और इसपर मैं तुम्हारा ध्यान खींचना चाहता हूँ। इंग्लैंड अपने सभी मातहत मुल्कों में जागीरदारों, ज़मींदारों और सबसे अनुदार और पिछड़े हुए वर्गों से मेल करने की कोशिश करता है। यह बात हिन्दुस्तान में, मिस्र में और दूसरी जगहों में देखी गई है। वह अपने मातहत देशों में डगमगाती हुई राजगद्दियाँ पैदा कर देता है, उनपर प्रगति-विरोधी शासकों को बिठा देता है, और अच्छी तरह जानता है कि वे उसका समर्थन करेंगे। उसने मिस्र में फ़ुआद, इराक़ में फ़ैज़ल, ट्रान्स-जोर्डन में अब्दुल्ला को

गद्दी पर बिठाया, और हेजाज में भी हुसैन को गद्दी पर बैठाने की कोशिश की। दूसरी तरफ़ फ़्रांस चूँकि खुद एक नमूनेदार मध्यमवर्गीय देश है, इसलिए वह अपने मातहत देशों के कुछ मध्यमवर्गीय भागों, उठते हुए व्यापारी वर्गों, द्वारा समर्थन प्राप्त करने की कोशिश करता है। मसलन, सीरिया में उसने ईसाई मध्यमवर्गीयों का समर्थन प्राप्त करना चाहा था। इंग्लैण्ड और फ़्रान्स दोनों ही अपने सब मातहत देशों में अपना विरोध करनेवाली राष्ट्रीयता को कमजोर करने के लिए उसे टुकड़े-टुकड़े करने, फूट डालने, अल्पसंख्यक, जातीय और मजहबी सवाल को पैदा करने की नीति का सहारा लेते हैं। लेकिन सारे पूर्वी देशों में राष्ट्रीयता इन सब भेद-भावों को धीरे-धीरे पार कर रही है, और इस कार्य में वह 'मध्य-पूर्व' के अरब देशों में ही शायद सबसे ज्यादा कामयाब हुई है, जहाँ कि मजहबी फिरफ़े अब राष्ट्रीयता के आदर्श के सामने कमजोर पड़ते जा रहे हैं।

मैंने ऊपर तुम्हें बताया है कि इराक़ में ब्रिटिश आर० ए० एफ० (रायल एयर फ़ोर्स) ने किस तरह काम लिया गया। पिछले दस-बारह साल से ब्रिटिश सरकार की यह निश्चित नीति हो गई है कि वह अपने नाम के आज़ाद पर असल में आधे-मातहत देशों में जिसे 'पुलिस-कार्य' कहा जाता है, वह करने के लिए हवाईजहाज़ों का इस्तेमाल करने लगी है। यह ख़ासकर वहीं किया जाता है जहाँ किसी हद तक स्वायत्त शासन दिया जाता है, और शासक-मण्डल ज्यादातर उसी देश का होता है। इन देशों में अब क़ब्ज़ा जमानेवाली सेनायें नहीं रखी जाती, या उन्हें बहुत कम कर दिया गया है। इसके कई फ़ायदे हैं। बहुत-सा रुपया बच जाता है, और उस देश पर फ़ौजी क़ब्ज़ा ज़ाहिरा कम दिखाई देता है। साथ ही हवाईजहाज़ों और बमों के द्वारा स्थिति पर उनका पूरा क़ाबू रहता है। इस तरह मातहत इलाक़ों में हवाई जहाज़ों से बम-वर्षा का उपयोग बहुत बढ़ गया है, और दूसरी ताक़तों की बनिस्वत शायद अंग्रेज़ ही इस उपाय को ज्यादा काम में लाते हैं। मैंने इराक़ का हाल तो बता ही दिया। यही कहानी हिन्दुस्तान की उत्तर-पश्चिमी सरहद के बारे में भी दोहराई जा सकती है, जहाँ कि हवाई बम-वर्षा अक्सर होनेवाली बात होगई है।

मुमकिन है, फ़ौज भेजने के पुराने तरीक़े की बनिस्वत यह तरीक़ा ज्यादा सस्ता और ज्यादा कारगर हो। लेकिन यह बहुत ही बेरहम और भयंकर तरीक़ा है। असल में पूरे-पूरे गाँवों पर बम बरसाना, ख़ासकर देर से फूटनेवाले बम बरसाना और गुनहगारों और बेग़ुनाहों को एक-साथ मार डालने से ज्यादा घृणित और जंगली काम की कल्पना करना भी मुश्किल है। इस तरीक़े से दूसरे देश पर हमला करना भी बड़ा आसान हो जाता है। इसलिए इसके ज़िलाज़ ख़ूब चीख़-पुकार उठी

हैं, और जिनेवा में राष्ट्र-संघ में निरस्त्र जनता पर हवाई हमला करने के खिलाफ बड़े-बड़े भाषण दिये जाते हैं। पिछले साल (जुलाई १९३२ में) राष्ट्र-संघ की या राष्ट्र-संघ की निःशस्त्रीकरण कांग्रेस की मीटिंग में अंग्रेज प्रतिनिधि सर जान साइमन भी इस आम मुद्दालिफ्त में शामिल होगये थे, और उन्होंने कहा था कि यह 'बिल्कुल पूरी तरह से' बन्द कर दिया जाना चाहिए। लेकिन ताज्जुब है कि जो प्रस्ताव पास हुआ उसमें 'देशी गांवों' पर बम बरसाने की छूट कर दी गई !

सिर्फ एक हफ्ता पहले (२९ मई १९३३ को) जिनेवा में निःशस्त्रीकरण कांग्रेस में इस मामले पर फिर बहस हुई, और ख़तर के एक तार में लिखा है कि "जब अंग्रेजों ने तजवीज की कि मातहत देशों में सिर्फ पुलिस-कार्य के लिए ही हवाई-जहाज का इस्तेमाल किया जाय,तो इस पर बड़ी भारी मुद्दालिफ्त हुई।" मालूम होता है कि दूसरे सब देशों ने, जिनमें यूनाइटेड स्टेट्स भी शामिल हैं, हवाई बम-बर्पा को बिल्कुल बन्द कर देने पर जोर दिया। लेकिन ब्रिटिश सरकार मानने से इन्कार कर देती है और इस मामले पर निःशस्त्रीकरण कांग्रेस के टूट जाने की नौबत लाने को भी तैयार है। इस बात पर ब्रिटेन सारी दुनिया के खिलाफ़ है। लेकिन इसमें शक नहीं कि किसी-न-किसी दूसरी साम्राज्यवादी शक्ति का गुप्त समर्थन उसे प्राप्त है।

: १७० :

अफ़ग़ानिस्तान और एशिया के कुछ अन्य देश

८ जून, १९३३

इराक़ के पूर्व में ईरान या फ़ारस है, और ईरान के पूर्व में अफ़ग़ानिस्तान है। ईरान और अफ़ग़ानिस्तान दोनों ही हिन्दुस्तान के पड़ोसी हैं, क्योंकि ईरानी सरहद हिन्दुस्तान से बलोचिस्तान में कईसौ मील तक मिली हुई है, और अफ़ग़ानिस्तान और हिन्दुस्तान की सरहद भी बलोचिस्तान की बिल्कुल पश्चिमी नोक से हिन्दूकुश के उत्तरी पर्वत तक, जहाँतक कि हिन्दुस्तान अपने बर्फ़ से ढके हुए मस्तक को मध्य-एशिया की छाती पर रखे हुए है और सोवियट के मुत्कों की तरफ़ झाँक रहा है, करीब एक हजार मील तक साथ-साथ चली गई है। ये तीनों देश पड़ोसी ही नहीं हैं। बल्कि इनकी नस्ल भी एक ही है, क्योंकि इन सब में प्राचीन आर्य नस्ल की ही प्रधानता है। और संस्कृति की दृष्टि से भी, जैसा कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ, पिछले जमाने में इन सबमें एकसी बातें थीं। अभी हालतक उत्तरी हिन्दुस्तान में आलिमों की ज़बान फ़ारसी ही थी, और

अब भी वह खासकर मुसलमानों में लोकप्रिय है। अफ़ग़ानिस्तान में आज भी फ़ारसी ही सरकारी भाषा है, हालाँकि अफ़ग़ानिस्तान की आम ज़बान पश्तो है।

ईरान के बारे में अपने पिछले ख़तों में जितना लिख चुका हूँ उससे ज्यादा लिखना नहीं चाहता। लेकिन अफ़ग़ानिस्तान में हाल में जो घटनायें हुई हैं उनका कुछ ब़ि़क़ करना ज़रूरी है। अफ़ग़ानिस्तान का इतिहास तो हिन्दुस्तान के इतिहास का करीब-करीब एक हिस्सा ही है। असल में बहुत अर्से तक अफ़ग़ानिस्तान हिन्दुस्तान का ही एक भाग था। अलहदा होने के बाद, और खासकर पिछले सौ-सवासी साल से, वह रूस और इंग्लैण्ड इन दो बड़े साम्राज्यों के बीच एक मध्यवर्ती राज्य बन गया है। रूसी साम्राज्य मिट चुका है, और उसकी जगह सोवियट यूनियन क़ायम होगया है, लेकिन अफ़ग़ानिस्तान अब भी उसी तरह मध्यवर्ती स्थिति में है, जहाँ कि अंग्रेज़ और रूसी दोनों प्रधानता हासिल करने के लिए साजिश करते रहते हैं। उन्नीसवीं सदी में इन साजिशों ने बढ़कर इंग्लैण्ड और अफ़ग़ानिस्तान के बीच जंग की सूरत इख़्तियार कर-ली थी, जिसमें अंग्रेज़ों को कई बार नुक़सान उठाना पड़ा, लेकिन आख़िरकार इंग्लैण्ड की प्रधानता क़ायम होगई। अफ़ग़ानी राजघराने के कई आदमी अब भी नज़रबन्द की तरह उत्तर हिन्दुस्तान में जगह-जगह रखे हुए हैं, और हमें इस बात की याद दिलाते हैं कि किस तरह इंग्लैण्ड अफ़ग़ानिस्तान में दस्तंदाज़ी किया करता था। ऐसे अमीर जो अंग्रेज़ों के दोस्त थे, हुकूमत करने लगे और अफ़ग़ानिस्तान की पर-राष्ट्रीय नीति निश्चित रूप से अंग्रेज़ों के दबाव में होगई। लेकिन ये अमीर कितना भी दोस्ताना वर्ताव रखते हों तो भी उनपर पूरा यक़ीन नहीं किया जा सकता था, और हर साल अंग्रेज़ उन्हें ख़ुश करने और अपने अधीन बनाये रखने के लिए बहुत-सा रुपया दिया करते थे। अमीर अब्दुर्रहमान इसी किस्म का आदमी था। इसकी लम्बी हुकूमत १९०१ में ख़त्म हुई। उसके बाद हवीदुल्ला अमीर हुआ, और वह भी अंग्रेज़ों से अच्छे ताल्लुक़ात रखता था।

अफ़ग़ानिस्तान जो अंग्रेज़ों का मुहताज बन गया, उसकी एक वज़ह थी उसकी स्थिति। नज़्द से तुम देख सकोगी कि बलोचिस्तान के बीच में आने से उसका समुद्र से ताल्लुक़ टूट गया है। कोई ऐसा भूकान हो जिसमें आम सड़क पर पहुँचने के लिए किसी दूसरे की ज़मीन में से गुज़रे बिना रास्ता न हो, तो वह कितनी तकलीफ़देह हालत होगी? ऐसी ही हालत अफ़ग़ानिस्तान की है। बाहरी दुनिया तक पहुँचने का उसका सबसे आसान रास्ता हिन्दुस्तान में से था। उन दिनों हिन्दुस्तान के उत्तर में रूसी इलाक़े में आमद-रफ़्त के कोई अच्छे साधन न थे। मेरा ख़याल है कि हाल में सोवियट सरकार ने रेल बनाकर और हवाई जहाज़ और मोटर-मरदमों को प्रोत्सा-

हित करके दोनों तरह से इन साधनों को उन्नत कर लिया है। इस तरह जब हिन्दुस्तान ही अफ़ग़ानिस्तान के लिए दुनिया पर निगाह डालने की सिर्फ़ एक बाहरी खिड़की थी, तो ब्रिटिश सरकार कई तरीकों से दबाव डालकर इसका फ़ायदा उठा सकती थी। समुद्र तक पहुँचने की अफ़ग़ानिस्तान की यह दिक्कत अब भी उस देश के सामने एक बड़ा सवाल है।

१९१९ के शुरू में अफ़ग़ानी राज-दरबार के अन्दरूनी झगड़े और षड़यंत्र बाहर जाहिर होगये, और राजमहल में एक के बाद एक दो क्रांतियाँ जल्दी-जल्दी होगईं। में ठीक नहीं जानता कि परदे की ओट में क्या-क्या घटनायें हुईं, या इनके लिए कौन ज़िम्मेदार था। किसी ने पहले अमीर हवीबुल्ला का क़त्ल कर दिया, और उसके बाद उसका भाई नसरुल्ला अमीर हुआ। लेकिन बहुत जल्द ही नसरुल्ला हटा दिया गया और अमानुल्ला, जो कि हवीबुल्ला के छोटे लड़कों में से एक था, अमीर बन गया। उसने इसके बाद ही मई १९१९ में हिन्दुस्तान पर चढ़ाई कर दी। इसके लिए उस वक़्त तात्कालिक कारण क्या था, या किसने पहले झगड़ा शुरू किया, यह मुझे मालूम नहीं है। शायद अमानुल्ला को यह बुरा लगा कि वह किसी तरह भी अंग्रेज़ों के मात-हत रहे। वह अपने देश की पूरी आज़ादी क़ायम करना चाहता था। शायद उसने यह भी समझा कि इसके लिए मौक़ा भी अच्छा है। तुम्हें याद होगा कि उन्हीं दिनों पंजाब में फ़ौजी क़ानून जारी था, हिन्दुस्तान में आम बेचैनी थी और ख़िलाफ़त के सवाल पर मुसलमानों में आन्दोलन बढ़ रहा था। कारण और प्रलोभन कुछ भी रहे हों, अफ़ग़ानियों की अंग्रेज़ों से लड़ाई होगई। लेकिन यह लड़ाई बहुत थोड़े असें तक चली, और बहुत कम हुई। फ़ौजी ताक़त में तो हिन्दुस्तान के अंग्रेज़ अमानुल्ला से बहुत ज्यादा मज़बूत थे, लेकिन उनकी तबीयत लड़ाई की नहीं थी, और कुछ घटनायें होने पर ही उन्होंने अफ़ग़ानिस्तान से सुलह करली। नतीजा यह हुआ कि अफ़ग़ानिस्तान पूरी तरह से आज़ाद मुल्क तस्लीम कर लिया गया, और विदेशों से अपने ताल्लुक़ात क़ायम करने में उसे पूरी आज़ादी मिल गई। इस तरह अमानुल्ला ने अपना मक़सद हासिल कर लिया, और योरोप और एशिया में उसकी इज़्ज़त बहुत बढ़ गई। लाज़िमी तौर पर अंग्रेज़ उसे अच्छा नहीं समझते थे।

अपने देश में एक नई नीति जारी करने के कारण तो अमानुल्ला की तरफ़ लोगों का और भी ज्यादा ध्यान जाने लगा। यह नीति थी पश्चिमी ढंग के सुधार बड़ी तेज़ी से करना, जिसे अफ़ग़ानिस्तान का पश्चिमीकरण कहते हैं। इस काम में उसकी पत्नी बेगम सुरैया ने उसे बड़ी मदद दी। उसकी कुछ तालीम योरोप में हुई थी, और स्त्रियों का बुरक़े में बन्द रहना उसे बड़ा खटकता था। इस तरह एक बहुत ही पिछड़े

हुए देश को थोड़े-से वक्त में तब्दील कर देने, अफ़ग़ानों को पुराने रास्ते से धक्का मारकर और खदेड़कर नये रास्ते पर चलाने का आश्चर्यजनक कार्य शुरू होगया। स्पष्टतः अमानुल्ला का आदर्श कमालपाशा ही था, और उसने कई बातों में—अफ़ग़ानों को कोट, पेण्ट और यूरोपियन हैट पहनाने और दाढ़ी साफ़ करवाने तक में—उसकी नक़ल करने की कोशिश की। लेकिन अमानुल्ला में मुस्तफ़ा कमाल की-सी दृढ़ता और योग्यता न थी। कमालपाशा ने अपने बड़े-बड़े सुधार करने से पहले अपने देश में और बाहर के देशों में अपनी ताक़त बिल्कुल महफूज़ और मजबूत करली थी। उसके साथ एक जोरदार और अच्छी फ़ौज़ थी, और अपनी जनता में उसकी ज़बरदस्त इज्जत थी। अमानुल्ला इन सब बातों का ख़याल न करके आगे बढ़ गया। उसका काम ज्यादा मुश्किल भी था, क्योंकि तुर्कों की बनिस्बत अफ़ग़ानी लोग ज्यादा पिछड़े हुए थे।

लेकिन घटना हो जाने के बाद तो समझदारी आना आसान होता ही है। अमानुल्ला के उन शुरू के वर्षों में, वह सब बातों में कामयाब ही होता नज़र आता था। उसने कई अफ़ग़ान लड़के और लड़कियों को तालीम हासिल करने के लिए योरोप भिजवाया। अपने शासन में उसने कई सुधार शुरू किये और उसने अपनी अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति अपने पड़ोसियों और तुर्कों के साथ सुलह करके मजबूत करली। सोवियट रूस ने चीन से तुर्कों तक सारे पूर्वी देशों के साथ उदार और दोस्ताना नीति जान-बूझकर इस्तियार कर रखी थी, और इस सोवियट दोस्ती और मदद की वजह से विदेशी दवाव से तुर्कों और ईरान के छूटने में बड़ी मदद मिली थी। और जिस आसानी से अमानुल्ला ने १९१९ में इंग्लैण्ड के साथ अपने छोटे-से जंग में अपना मक़सद हासिल कर लिया था, उसमें भी यही एक महत्वपूर्ण कारण रहा होगा। बाद के वर्षों में सोवियट रूस, तुर्कों, ईरान और अफ़ग़ानिस्तान इन चार शक्तियों में बहुत-सी सन्धियाँ और सुलहनामे हुए। इन सबमें, या किसी तीन में, एकसाथ कोई सन्धि नहीं हुई। हर शक्ति ने दूसरी तीन शक्तियों से अपनी-अपनी जुदा, लेकिन क़रीब-क़रीब एक-सी, सन्धि की। इस तरह 'मध्य-पूर्व' में सन्धियों का एक जाल-सा खड़ा होगया, जिसने इन सब देशों को मजबूत कर दिया। मैं नीचे इन सन्धियों की सिर्फ़ तारीख़दार फ़ेहरिस्त दे देता हूँ :—

तुर्क-अफ़ग़ान सन्धि	१९ फ़रवरी १९२१
सोवियट-तुर्की "	१७ दिसम्बर १९२५
तुर्की-ईरानी "	२२ अप्रैल १९२६
सोवियट-अफ़ग़ान "	३१ अगस्त १९२६
सोवियट-ईरानी "	१ अक्टूबर १९२७
ईरानी-अफ़ग़ानी "	२८ नवम्बर १९२७

ये सन्धियाँ सोवियट राजनीतिज्ञों की कामयाबी का सबूत थीं, और इनसे 'मध्य-पूर्व' में अंग्रेजों के प्रभाव को गहरा धक्का लगा। यह कहने की तो जरूरत ही नहीं कि ब्रिटिश सरकार ने इन्हें बहुत नापसन्द किया, और खासकर अमानुल्ला के सोवियट रूस की तरफ दोस्ती और झुकाव को तो उसने बहुत ज्यादा नापसन्द किया।

१९२८ के शुरू में अमानुल्ला और रानी सुरैया योरप का एक बड़ा दौरा करने के लिए अफ़ग़ानिस्तान से रवाना हुए। वे योरप की कई राजधानियों में—रोम, पेरिस, लन्दन, मास्को—गये, और सब जगह उनका बड़ा स्वागत हुआ। ये सभी देश व्यापार और राजनैतिक उद्देश्यों के लिए अमानुल्ला की सद्भावना प्राप्त करने को उत्सुक थे। उसे क़ीमती तोहफ़े भी भेंट किये गये। लेकिन उसने बड़ी राजनैतिक होशियारी से काम लिया, और किसीसे कोई खास वादा नहीं किया। लौटते वक़्त वह तुर्की और ईरान भी होता आया।

उसके लम्बे दौरे की तरफ़ बहुत लोगों का ध्यान गया। इससे अमानुल्ला की इज्जत बढ़ गई, और इससे दुनिया में अफ़ग़ानिस्तान का महत्व भी बहुत बढ़ गया। लेकिन खुद अफ़ग़ानिस्तान के अन्दर हाल अच्छा न था। एक ऐसे समय, जब कि पुराने तौर-तरीक़े और ज़िन्दगी को पलट देनेवाली बड़ी-बड़ी तब्दीलियाँ हो रही थीं, उसके बीच में अपने देश को छोड़ जाने में अमानुल्ला ने बड़ी भारी जोखिम उठाई थी। मुस्तफ़ा क़माल ने यह जोखिम कभी नहीं उठाई। अमानुल्ला की लम्बी शरहाज़री में सारे प्रगति-विरोधी लोग और शक्तियाँ, जो उसके खिलाफ़ थीं, धीरे-धीरे सामने आगई। हर तरह की साज़िश की गई और उसको बदनाम करने के लिए हर तरह की अफ़वाहें फैलाई गईं। इस अमानुल्ला-विरोधी प्रचार के लिए, न जाने किस तरफ़ से, रुपये की बाढ़-सी आगई। मालूम होता है कि बहुत-से मुल्ला लोगों को इस काम के लिए रुपया दिया गया था और वे सारे देश में अमानुल्ला को काफ़िर, दीन का दुश्मन, घोषित करते फिरते थे। रानी सुरैया की अजीब-अजीब तस्वीरें, जिनमें वह यूरोपियन ढंग की रात की पोशाक या और कोई लापरवाही में पहनी हुई पोशाक में नज़र आती थी, हज़ारों की तादाद में देहातों में बाँटी गई थीं—यह दिखाने के लिए कि वह किस अनुचित प्रकार के कपड़े पहनती है। इस व्यापक और ख़र्चीले प्रचार का करनेवाला कौन था? अफ़ग़ानियों के पास तो न इतना रुपया था, और न इतनी तालीम थी। उनपर इसका ख़ूब असर हो सकता था। मध्य-पूर्व और योरप में यह आम तौर पर माना जाता था और कहा जाता था कि इस प्रचार में शिटिश खुफ़िया महक़मे का हाथ था। ऐसी बातों का साबित होना मुश्किल होता है, और इस काम से अंग्रेजों का ताल्लुक़ बताने के लिए कोई खास सबूत नहीं मिलता, हालाँकि यह कहा

गया है कि अफ़ग़ान वाग़ियों के पास अंग्रेज़ी रायफ़्लें थीं। लेकिन यह तो काफ़ी जाहिर था कि अमानुल्ला को अफ़ग़ानिस्तान में कमज़ोर कर देने में इंग्लैण्ड की दिलचस्पी थी।

जिस वक़्त अफ़ग़ानिस्तान में अमानुल्ला की जड़ें उखाड़ी जा रही थीं, उस वक़्त वह योरप की राजधानियों में शानदार स्वागतों का आनन्द ले रहा था। वह अपने सुधारों के प्रति नया उत्साह लेकर नये विचारों से भरा हुआ और कमालपाशा से, जिससे वह अंगोरा में मिला था, और भी ज्यादा प्रभावित होकर अपने देश को लौटा। वह इन सुधारों को और भी आगे बढ़ाने के लिए फ़ौरन जुट पड़ा। उसने सरदारों के ख़िताबत बन्द कर दिये, और मज़हबी मुखियों के इस्तिथारात भी कम करने की कोशिश की। उसने शासन चलाने के लिए मंत्रियों की एक कौंसिल बनाने की भी कोशिश की, और इस तरह से अपनी स्वेच्छातन्त्री शक्तियों को भी कम कर लिया। मंत्रियों की आज्ञादी का काम भी धीरे-धीरे आगे बढ़ाया गया।

अचानक दबी हुई आग़ भड़क उठी, और १९२८ के ख़तम होने के कुछ पहले बगावत चमकने लगी। एक मामूली भिश्ती बच्चा-ए-सक्का के नेतृत्व में विद्रोह फैला और १९२९ में वह कामयाब होगया। अमानुल्ला और उसकी बेगम भाग गये, और भिश्ती अमीर बन गया। पाँच महीने तक बच्चा-ए-सक्का काबुल में हुकूमत करता रहा; बाद में वह अमानुल्ला के एक सेनापति नादिरखाँ द्वारा हटा दिया गया। नादिरखाँ ने खुद अपनी तरकीब से काम लिया, और जब वह कामयाब होगया तो नादिरशाह के नाम से खुद ही शासक बन बैठा। पिछले साढ़े तीन साल से नादिरशाह ही अफ़ग़ानिस्तान का बादशाह है, लेकिन इस दरमियान और झगड़े बराबर बने ही रहे, और अब भी बने हैं। जाहिर है कि वह अमानुल्ला की वनिस्वत इंग्लैण्ड से ज्यादा दोस्ताना ताल्लुक रखता है।

अफ़ग़ानिस्तान में अब भी अमनो-अमान नहीं है, और साज़िश की अफ़वाहें अक्सर आती ही रहती हैं। इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं है, क्योंकि दो ताक़तवर विरोधियों के बीच में मध्यवर्ती राज्य होने की सज़ा तो उस देश को भुगतनी ही चाहिए। इस वक़्त अमानुल्ला और भूतपूर्व रानी सुरैया रोम में रह रहे हैं। दुनिया में भागे हुए राज-वंशों की भरमार होती जा रही है।

आज सुबह के अख़बार की एक ख़बर से जाहिर होता है कि अफ़ग़ानिस्तान में शान्ति नहीं है। दो दिन पहले, ६ जून १९३३ को, बर्लिन के अफ़ग़ान राजदूत को, एक अफ़ग़ान विद्यार्थी ने 'आज़ादी की खातिर' का नारा लगाकर गोली से मार दिया। यह मंत्री नादिरशाह का भाई था।

मैंने अफ़ग़ानिस्तान का और पश्चिमी और दक्षिणी एशिया का भी पूरा दयान

कर दिया है। अब मैं एशिया के दक्षिण-पूर्वी कोने की हाल की कुछ घटनाओं का थोड़ा हाल बयान करूँगा और फिर इस खत को खत्म कर दूँगा। इस हिस्से की वाबत में तुम्हें ज्यादा नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे खुद भी बहुत कम मालूम है।

बरमा के पूर्व में स्याम है, जो दुनिया के इस हिस्से में सिर्फ एक ही देश है जो अपनी आजादी को कायम रख सका है। वह एक तरफ़ ब्रिटिश बरमा और दूसरी तरफ़ फ्रेञ्च-इंडोचायना के बीच में जकड़ा हुआ है। इस देश में पुराने भारतीय स्मारक-चिन्हों की भरमार है, और उसकी परम्पराओं और संस्कृति और रीति-रिवाजों पर आज भी हिन्दुस्तान का असर दिखाई देता है। हाल तक वहाँ राजा का मनमाना शासन था, और समाज ज्यादातर सामन्तशाही की हालत में था। हाँ, साथ-ही-साथ छोटा-सा मध्यमवर्ग भी बढ़ रहा था। मेरे खयाल से राजाओं का खिताब अक्सर राम होता था, जिस शब्द से कि हमें फिर हिन्दुस्तान की याद आने लगती है। इस तरह उनमें राम प्रथम, राम द्वितीय इत्यादि राजा हुए थे। महायुद्ध के जमाने में स्याम मित्र-दल के साथ होगया, जबकि मित्र-दल की जीत साफ़ जाहिर होने लगी थी, और बाद में वह राष्ट्र-संघ का भी सदस्य बन गया।

जून १९३२ में बंकोक के, जोकि स्याम की राजधानी है, राजमहल में एक क्रान्ति हुई, और बताया गया कि कुछ नौजवान स्यामी अफसरों और दूसरे लोगों ने, जोकि एक शासन-विधान की मांग करते थे, राजा और उसके परिवार और मुख्य मन्त्रियों को गिरफ्तार कर लिया है। राजा ने किसी तरह के एक शासन-विधान को, जिसमें उसके अख्तियारात महदूद कर दिये गये थे, मान लिया और एक पीपल्स असेम्बली यानी जनता की कौंसिल कायम होगई। मुझे ठीक-ठीक मालूम नहीं है कि क्या-क्या बातें हुई, लेकिन मालूम होता है कि जिस तरह नौजवान तुर्कों और सुल्तान अब्दुलहमीद के मामले में अचानक फ़ौजी कार्रवाई की गई थी, इसी तरह की कोई अचानक फ़ौजी कार्रवाई अमल में आई होगी। बेशक इस फ़ौजी कार्रवाई के पीछे जनता की दुर्दशा छिपी हुई थी। फिर भी यह क्रान्ति जनता की आम उथल-पुथल नहीं मालूम हुई। राजा के जल्दी मान जाने से संकट-काल खत्म होगया। मालूम होता है कि राजा ने इस तब्दीली की मंजूरी दिल से नहीं दी थी। अप्रैल १९३३ में उसी राजा प्रजाधिपक ने इस कारण से अचानक एसेम्बली तोड़ दी कि उसके कुछ सदस्य साम्यवाद की हिमायत कर रहे हैं। इतनी दूर से अधिक समाचार के अभाव में इस वाबत कोई भी फ़ैसला करना मुश्किल है। फिर भी, मालूम होता है कि राजा सिर्फ किसी बहाने की तलाश में था, जिससे वह एसेम्बली को खत्म करदे और अपनी स्वेच्छाचारी शक्ति को फिर ग्रहण कर ले। शायद उसे ऐसी हर बात जो उसके अख्तिय-

यारात को महदूद करे, साम्यवाद से भरी हुई ही दिखाई देती हो। यह भी बिल्कुल मुमकिन है कि स्याम में किसी हद तक साम्यवाद फैल गया हो, जैसा कि वह चीन के कुछ हिस्सों में काफ़ी मजबूत है। लेकिन ज्यादा मुमकिन बात यह है कि स्याम में साम्यवादी रंग लिये हुए मध्यवर्गीय राष्ट्रीयता पैदा होगई हो, और वहाँकी पुरानी सामन्ती समाज-व्यवस्था पर हमला कर रही हो। सबसे ताज़ी ख़बर यह है कि एक ओर 'शान्तिपूर्ण क्रान्ति' होगई है, और फ़ौजी अफ़सरों के अगुआ-दल ने फिर जोर पकड़ लिया है, और ऐसेम्बली को फिर से क़ायम करने का आग्रह किया है।

स्याम के पूर्व फ़्रेञ्च इण्डो-चायना में भी राष्ट्रीयता फैली है, और उसकी ताक़त बढ़ती जा रही है। राष्ट्रवादी आन्दोलन को दवाने के लिए फ़्रेञ्च सरकार ने भी कई पद्धन्त्र के मुक़दमे चलाये हैं और बहुत-से लोगों को लम्बी-लम्बी सजायें दी हैं। मार्च १९३३ में जिनेवा की एक निःशस्त्रीकरण कान्फ़रेंस में फ़्रेञ्च प्रतिनिधि मो० सारीत ने एक बड़े भेद की बात कही थी। यह प्रतिनिधि खुद फ़्रेञ्च इण्डो-चायना का गवर्नर रह चुका था। उसने ज़िक्र किया कि "मातहत देशों में राष्ट्रीयता बढ़ रही है, और उनपर हुकूमत करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है।" उसने फ़्रेञ्च इण्डो-चायना की मिसाल दी कि जब वह वहाँका गवर्नर था तो व्यवस्था क़ायम रखने के लिए सिर्फ़ १,५०० आदमी थे, लेकिन अब वहाँ १०,००० आदमियों की ज़रूरत होती है।

अख़ीर में डच ईस्ट-इंडीज़ के अन्तर्गत जावा का भी ज़िक्र कर देना मुनासिब होगा, जोकि अपनी शकर और रबर के लिए मशहूर है, और साथ ही कारख़ानेदारों के खेतों पर काम करनेवाले लोगों का बुरी तरह खून चूसने के लिए भी मशहूर है। राष्ट्रीयता की बढ़ती के साथ, हिन्दुस्तान की तरह, थोड़ा-सा राजनैतिक सुधार और और बहुत-सा दमन भी आया। १९२७ में डच सत्ता के ख़िलाफ़ बग़ावत होगई थी जो काफ़ी बेरहमी के साथ दबा दी गई थी। डच सरकार उसे साम्यवादी बग़ावत बताती थी, हालांकि उसके सारे बयान से वह साम्यवादी की बनिस्बत क़ौमी ही ज्यादा मालूम होती थी। इसमें शक नहीं कि पूर्व के तमाम मुल्कों में साम्यवाद भी बढ़ रहा है; लेकिन गिनती के ख़याल से अब भी वह महत्व-शून्य है। उसकी ताक़त इस बात से है कि उसकी तरफ़ लायक़ कुरबानी करनेवाले और तेज़ स्वभाव के नौजवान रत्नी और पुरुष खिंचते हैं।

कुछ महीने पहले जावा के नजदीक़ के नमुद्री हिस्से में एक अजीब घटना हुई। एक डच जंगी जहाज़ के नाविकों ने बेतन-कटौती के विरोध में जहाज़ पर अपना बग़ा जमा लिया और उसे लेकर चल दिये। उन्होंने किसी चीज़ का नुक़सान नहीं

किया, और यह भी साफ़ जाहिर कर दिया कि वे सिर्फ़ अपने वेतनों की वास्तविक विरोध कर रहे हैं। वह एक तरह की उग्र हड़ताल थी। इसपर डच हवाई जहाजों ने इस जंगी जहाज पर बम बरसाये, कई नाविकों को मार दिया, और इस तरह उस पर क़ब्ज़ा पा लिया।

अब हम एशिया को छोड़ देते हैं, जहाँ कि राष्ट्रीयता और साम्राज्यवाद के बीच लगातार संघर्ष के बाद संघर्ष होते ही जाते हैं, और योरोप पर आते हैं, क्योंकि योरोप भी हमारा ध्यान खींच रहा है। हमने महायुद्ध के बाद के योरोप पर विचार नहीं किया है, और तुम्हें याद रखना चाहिए कि अब भी योरोप की परिस्थितियों में ही संसार की परिस्थितियों की चाबी है। इसलिए हमारे अगले कुछ ख़त योरोप के बारे में ही होंगे।

एशिया के दो हिस्सों, दो बड़े-बड़े हिस्सों, पर ग़ौर करना अभी बाक़ी है— एक तो चीन का प्रदेश, और दूसरा उत्तर में सोवियट प्रदेश। कुछ समय बाद हम उन-पर फिर पहुँचेंगे।

: १७१ :

वह क्रान्ति जो होते-होते रह गई

१३ जून, १९३३

जी० के० चेस्टरटन ने, जो कि आजकल अंग्रेज़ी के एक मशहूर लेखक हैं, कहीं लिखा है कि इंग्लैंड में उन्नीसवीं सदी की सबसे बड़ी घटना वह क्रान्ति है जो कि नहीं हुई या होते-होते रह गई। तुम्हें याद होगा कि उन्नीसवीं सदी में कई मौक़ों पर इंग्लैंड क्रान्ति के किनारे तक आगया था, यानी ऐसी सामाजिक क्रान्ति होने ही वाली थी जिसे निचले वर्ग के लोग और श्रमिक मिलकर करते। लेकिन हर बार आख़री वक़्त पर शासकवर्ग झुक जाते थे, पार्लमेण्टरी ढाँचे के ही अन्दर वोट का अधिकार बढ़ाकर ऊपरी तौर पर कुछ हिस्सा बाँट देते थे, और बाहर की साम्राज्यवादी लूट के लाभों में से भी थोड़ा हिस्सा दे देते थे, और इस तरह आनेवाली क्रान्ति को दबा रखते थे। वे ऐसा इसलिए कर सके कि बाहर उनका साम्राज्य बढ़ रहा था, और उससे उन्हें धन मिल रहा था। इसलिए इंग्लैंड में क्रान्ति नहीं हुई, लेकिन उसका साया अक्सर देश पर छा जाता था, और क्रान्ति के भय से घटनाओं पर असर पड़ता था। इस तरह वह बात, जो असल में हुई नहीं, पिछली सदी की सबसे बड़ी घटना कही जाती है।

इसी तरह, शायद, यह कहा जा सकता है कि पश्चिमी योरोप में महायुद्ध के

वाद सबसे बड़ी घटना वह क्रान्ति थी जो कि नहीं हुई। जिन परिस्थितियों ने रूस में बोलशेविक क्रान्ति पैदा कर दी, वे, चाहे कुछ कम अंश में ही सही, मध्य और पश्चिमी योरोप में भी मौजूद थीं। रूस और पश्चिम के औद्योगिक देशों—इंग्लैंड, जर्मनी, फ़्रान्स वगैरा—में फ़र्क यह था कि रूस में मजबूत मध्यम-वर्गीय समाज नहीं था। असल में मार्क्स के उसूल के मुताबिक तो उम्मीद यही थी कि श्रमिकों की क्रान्ति पहले इन्हीं उन्नत औद्योगिक देशों में होगी, न कि पिछड़े हुए रूस में। लेकिन महायुद्ध ने ज़ारशाही के पुराने सड़े हुए ढाँचे को चकनाचूर कर दिया, और सिर्फ़ इसलिए कि वहाँ बीच में आजाने और पश्चिमी ढंग की पार्लमेण्ट द्वारा शासन पर नियंत्रण करने के लिए कोई मजबूत मध्यम-वर्ग नहीं था, मजदूरों के सोवियटों ने सत्ता पर क़ब्ज़ा जमा लिया। इसलिए यह एक क़ाफ़ी आश्चर्यजनक बात हुई कि रूस का पिछड़ापन ही, उसकी कमजोरी का कारण ही, उसके लिए उससे भी उन्नत देशों की वनिस्वत बड़ा क़दम उठाने का सबब बन गया। लेनिन के नेतृत्व में बोलशेविकों ने यह क़दम उठाया, लेकिन वे किसी धोखे में नहीं थे। वे जानते थे कि रूस पिछड़ा हुआ है और उसे आगे बढ़े हुए देशों के बराबर होने में वक़्त लगेगा। उन्हें उम्मीद थी कि श्रमिकों का प्रजातंत्र क़ायम रखने की उनकी मिसाल से योरोप के दूसरे मुल्कों के मजदूर भी अपनी-अपनी मौजूदा हुकूमतों के खिलाफ़ बगावत करने में उत्साहित होंगे। उन्होंने महसूस किया कि योरोप में सार्वत्रिक सामाजिक क्रान्ति होने से ही उनके बचे रहने की उम्मीद है। वरना, बाक़ी पूँजीवादी दुनिया तो रूस की नई सोवियट सरकार को कुचल ही देगी।

इसी आशा और विश्वास से अपनी क्रान्ति के शुरू में उन्होंने संसार-भर के मजदूरों के नाम अपनी अपीलें निकालीं। उन्होंने दूसरे देशों को जीतकर दबा लेने की योजनाओं की निन्दा की। उन्होंने कहा कि ज़ारशाही रूस और इंग्लैंड व फ़्रान्स के बीच जो गुप्त सन्धियाँ हुई हैं उनके आधार पर वे अपना कोई दावा नहीं करेंगे। और साफ़ ज़ाहिर कर दिया कि कुस्तुनतुनिया तुर्कों के ही पास रहना चाहिए। उन्होंने पूर्वी देशों को और ज़ारशाही साम्राज्य की कितनी ही पामाल क़ौमों को उदार से उदार शर्तें दीं। और सबसे बड़ी बात यह थी कि वे दुनियाभर के मजदूरों के हिमायती बन गये, और उन्होंने हर जगह के मजदूरों को प्रेरणा दी कि वे उनकी मिसाल पर अमल करें और साम्यवादी प्रजातंत्र क़ायम कर लें। राष्ट्रीयता और रूस के राष्ट्र का उनके लिए इसके सिवा और कोई अर्थ न था कि दुनिया के उन हिस्से में ही इतिहास में पहली बार श्रमिकों की सरकार क़ायम हुई थी। जर्मन और मित्र-राष्ट्रों की सरकारों ने बोलशेविक अपीलें का दमन किया, लेकिन फिर भी वे कई लड़ाई के मोर्चों और कार-स्तानों के प्रदेशों में पहुँच ही गईं। हर जगह उनका बाक़ी अमर हुआ, और ग्राम्नीमी

फ़ौज में फूट होती दिखाई दी। जर्मन फ़ौजों और मजदूरों पर तो और भी ज्यादा असर हुआ। जर्मनी और आस्ट्रिया और हंगरी—इन हारे हुए मुल्कों में बलबे और बगावतें भी हुईं, और कई महीनों या साल-दो साल तक तो योरोप में एक ज़बरदस्त सामाजिक क्रान्ति का अन्देशा बना ही रहा। हारे हुए मुल्कों की बनिस्वत जीते हुए मित्र-राष्ट्रों की हालत कुछ अच्छी थी, क्योंकि कामयाबी के सबब से उनमें हारी हुई शक्तियों से बसूल करके अपना कुछ नुक़सान पूरा कर लेने की हिम्मत और उम्मीदें पैदा होगई थीं (जो कि बाद की घटनाओं से काफ़ी झूठी साबित हुईं)। लेकिन मित्र-राष्ट्रों में भी क्रान्ति का वातावरण था। असल में सारे योरोप और एशिया का वातावरण असन्तोष से पूरी तरह भरा हुआ था, और सतह के नीचे क्रान्ति की आग सुलग और गड़गड़ा रही थी और अक्सर भभक उठना भी चाहती थी। लेकिन योरोप और एशिया में असन्तोष के और जो वर्ग क्रान्ति करना चाहते थे उनके प्रकारों में भेद था। एशिया में पश्चिमी साम्राज्यवाद के खिलाफ़ उठनेवाली क़ौमी बगावतों में मध्यम वर्ग आगे रहा; और योरोप में श्रमिक वर्गों ने चाहा कि मौजूदा पूंजीवादी समाज-व्यवस्था को उलट दें और मध्यम-वर्गों से सत्ता छीन लें।

इन गड़गड़ाहटों और अन्देशों के होने पर भी, मध्य या पश्चिमी योरोप में रूस की तरह की कोई क्रान्ति नहीं हुई। पुरानी समाज-व्यवस्था उसपर होनेवाले हमलों को बर्दाश्त कर लेने की ताक़त रखती थी, लेकिन वह इन हमलों से इतनी काफ़ी कमज़ोर होगई और डर गई कि उससे सोवियट रूस बच गया। अगर पीछे की तरफ़ से यह ज़बरदस्त मदद न मिली होती तो यह बिलकुल मुमकिन था कि १९१९ या १९२० में साम्राज्यवादी शक्तियों के सामने सोवियट नष्ट होजाता। पर महायुद्ध के बाद धीरे-धीरे जैसे-जैसे साल गुज़रते गये, स्थिति किसी हद तक शान्त होती गई। राजवादियों और सामन्त-ज़मींदारों यानी प्रगति-विरोधी रुढ़िवादियों और नरम साम्यवादी या सोशल डिमोक्रेट लोगों के बीच एक अजीब तरह का मेल होगया, और इन्होंने मिलकर क्रान्ति-कारी तत्त्वों को दबा दिया। असल में यह एक अजीब मेल था, क्योंकि सोशल डिमोक्रेट कहा करते थे कि हम मार्क्सवाद और श्रमिकों की सरकार में विश्वास रखते हैं। इस तरह जाहिरा तो उनके आदर्श वही थे जो कि सोवियटों और कम्यूनिस्टों यानी साम्यवादियों के थे। फिर भी ये सोशल डिमोक्रेट लोग पूंजीवादियों से भी ज्यादा कम्यूनिस्टों से डरते थे, और कम्यूनिस्टों को कुचलने के लिए पूंजीवादियों से मिल गये। या यह भी मुमकिन है कि वे पूंजीवादियों से इतना डरते थे कि उनके खिलाफ़ होने की हिम्मत नहीं कर सकते थे; उन्होंने शान्तिपूर्ण और पार्लमेण्टरी पद्धति से अपनी स्थिति मजबूत करने और यों अप्रत्यक्ष रूप से साम्यवाद ले आने की उम्मीद की। उनके इरादे कुछ भी रहे

हों, उन्होंने क्रान्तिकारी भावना को कुचलने में प्रगति-विरोधी तत्त्वों को मदद पहुँचाई, और इस तरह योरप के कई देशों में असल में प्रति-क्रान्ति करवा दी। अपना दाव पड़ने पर इस प्रति-क्रान्ति ने इन्हीं सोशल डिमोक्रेटिक पार्टियों को कुचल दिया, और फिर तो नई और उग्र साम्यवाद-विरोधी शक्तियों के हाथ में सत्ता आ गई। मोटे तौर पर, पिछले चौदह वर्षों में, जबसे कि महायुद्ध खत्म हुआ है, योरप की घटनायें इसी ढंग से हुई हैं।

लेकिन झगड़ा अभी खत्म नहीं हुआ है, और साम्यवाद और पूंजीवाद, इन दो एक-दूसरे के खिलाफ ताकतों के बीच लड़ाई चल रही है। इन दोनों में दायमी समझौता कभी नहीं हो सकता, हालांकि दोनों में अस्थायी समझौते और सन्धियाँ हुई हैं और आगे भी हो सकती हैं। रूस और साम्यवाद दुनिया के एक ध्रुव पर हैं, तो पश्चिमी योरप और अमेरिका के बड़े-बड़े पूंजीवादी देश दूसरे ध्रुव पर खड़े हैं। दोनों के बीच में लिबरल, माडरेट, और मध्य दल के लोग अब सभी जगह कम होते जा रहे हैं। संघर्ष और असंतोष तो असल में सत्ता-व्यापी सम्पूर्ण आर्थिक उलट-पुलट और बढ़ती हुई दुर्दशा के कारण पैदा हुआ है, और जबतक इसमें संतोषजनक सुव्यवस्था फिर से स्थापन न होजाय तब तक यह कशमकश जारी ही रहेगी।

महायुद्ध के बाद से जो अनेक असफल क्रान्तियाँ हुई हैं, उनमें जर्मनी की क्रान्ति सबसे ज्यादा दिलचस्प और अंदरूनी बातों पर रोशनी डालने वाली है; इसलिए उसका थोड़ा-सा जिक्र मैं करता हूँ। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि जब महायुद्ध आया तो सारे यूरोपियन देशों के साम्यवादी अपने आदर्शों और वादों के पक्के न रह सके। वे अपने-अपने देश की जबरदस्त राष्ट्रीयता की लहरों में बह गये, और जंग की जबरदस्त खूनी प्यास में समाजवाद के अन्तर्राष्ट्रीय आदर्श को भूल गये। महायुद्ध के शुरू होने के तारीख ही, ३० जुलाई १९१४ को, जर्मनी की सोशल डिमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं ने ऐलान किया था कि हैप्सबर्ग खानदान की साम्राज्यवादी योजनाओं के ख़ातिर वे "किसी भी जर्मन सिपाही का एक बूंद खून भी दहाये जाने के खिलाफ हैं।" (उस वक़्त आस्ट्रिया के आर्क ड्यूक फ्रैंज फर्डिनेण्ड के क्रतल के मामले में आस्ट्रिया और सर्बिया के बीच झगड़ा था।) पाँच दिन के बाद ही उनके दल ने युद्ध का समर्थन किया, और ऐसा ही दूसरे देशों के सोशल डिमोक्रेटिक दलों ने भी किया। और आस्ट्रिया के समाजवादियों के नेता ने तो पोलैण्ड और सर्बिया को आन्ट्रियन साम्राज्य के मातहत कर लेने तक की बातें कह डालीं, और कहा कि इस काम की गिनती दूसरे देश को जबरदस्ती अपने राज्य में मिला लेने से नहीं की जा सकती।

१९१८ के शुरू में योरप के मजदूरों के नाम निवाली हुई दोलनोदक अपीलों

का जर्मन मजदूरों पर काफ़ी असर हुआ, और युद्ध-सामग्री तैयार करनेवाले कारख़ानों में बड़ी-बड़ी हड़तालें हुईं। इससे जर्मनी की साम्राज्यवादी सरकार के लिए बड़ी गंभीर परिस्थिति पैदा होगई, और मुमकिन था कि उसका सर्वनाश भी होजाता। इसपर समाजवादी नेताओं ने हड़ताल कमेटी में शामिल होकर, और अन्दर से हड़ताल तोड़कर, परिस्थिति को बचा लिया।

४ नवम्बर १९१८ को उत्तर-जर्मनी के कील बन्दरगाह की नौ-सेना में बगावत होगई। जर्मन नौ-सेना के बड़े-बड़े जंगी जहाज़ों को बाहर जाने का हुक्म दिया गया, लेकिन नाविकों और आगवालों ने बाहर जाने से इन्कार कर दिया। जो फ़ौजें उन्हें दवाने के लिए भेजी गई थीं, वे भी उनसे मिल गईं और उन्हींके साथ होगई। अफ़सर अपने पदों से हटा दिये गये या गिरफ़्तार कर लिये गये, और मजदूरों और सैनिकों की कौंसिलें (सोवियटें) क़ायम करली गईं। ये सब बातें रूस की सोवियट क्रान्ति के शुरू की घटनाओं की-सी ही थीं, और ऐसा मालूम होने लगा कि ये सारे जर्मन में फैल जायेंगी। फ़ौरन ही कील में सोशल डिमोक्रेटिक नेता जा पहुँचे और वे नाविकों और सैनिकों के ध्यान को दूसरी बातों में लगाने में कामयाब हुए। लेकिन ये नाविक अपने हथियार लेकर कील से रवाना होगये, और सारे देश में बगावत के बीज लेकर फैल गये।

क्रान्तिकारी आन्दोलन फैलता जा रहा था। बवेरिया (दक्षिण-जर्मनी) में एक प्रजातन्त्र की घोषणा करदी गई। फिर भी क़ैसर तो चिपटा ही रहा। ९ नवम्बर को बर्लिन में एक आम हड़ताल शुरू होगई। सारा काम-काज बन्द होगया, और कुछ हिंसा भी न हुई, क्योंकि शहर की सारी फ़ौज क्रान्तिकारियों की तरफ जा मिली। पुरानी व्यवस्था जाहिरा तो नष्ट होगई थी, और सवाल यह था कि अब इसकी जगह क्या होगा ? कुछ साम्यवादी नेता सोवियट या प्रजातन्त्र का ऐलान करने ही वाले थे कि एक सोशल डिमोक्रेटिक नेता ने उनसे भी पहले पार्लमेण्टरी ढंग के प्रजातन्त्र का ऐलान कर दिया।

इस तरह जर्मन प्रजातन्त्र क़ायम हुआ। लेकिन वह तो सिर्फ़ नाम का प्रजातन्त्र था, क्योंकि असल में किसी चीज़ में भी तब्दीली नहीं हुई थी। सोशल डिमोक्रेटों ने, जिनके हाथ में सारी परिस्थिति थी, क़रीब-क़रीब हर बात को पहले की तरह ही रखा। उन्होंने मन्त्रित्व वग़ैरा के कुछ ऊँचे ओहदे लेलिये, लेकिन फ़ौज, सिविल सर्विस और अदालतों के अफ़सर और कर्मचारी वही रहे और सारा शासन उसी तरह का रहा जैसा कि क़ैसर के ज़माने में था। इस तरह, जैसा कि हाल की छपी एक किताब का नाम है, “क़ैसर चला गया, लेकिन उसके जनरल बने रहे।” क्रान्तियाँ इस

तरह से पैदा या मजबूत नहीं होतीं। किसी राष्ट्र की क्रान्ति में तो उसका राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक ढाँचा ही बदल जाना चाहिए। यह उम्मीद करना कि, जब क्रान्ति के दुश्मनों के हाथ में सत्ता छोड़ दी जायगी तो वह क्रान्ति टिकी रहेगी, बेमानी है; लेकिन जर्मन सोशल डिमोक्रेटों ने ठीक यही बात की, और उन्होंने क्रान्ति के विरोधियों को उसके नाश के लिए तैयारी और संगठन करने के पूरे मौक़े दे दिये। जर्मनी में पुराने सेनावादियों और फ़ौजी अफ़सरों का दबदबा बना रहा।

नई सोशल डिमोक्रेटिक सरकार को यह पसंद न आया कि कील के नाविक सारे देश में घूम-घूमकर क्रान्तिकारी विचार फैलाते रहें। उसने इन नाविकों को बर्लिन में दवाने की कोशिश की, और जनवरी १९१९ के शुरू में बड़े झगड़े हुए और खून-खराबी भी हुई। इसपर जर्मन साम्यवादियों ने सोवियट सरकार कायम करने की कोशिश की, और शहर की आम जनता से मदद माँगी। उन्हें जनता से कुछ मदद मिली, और उन्होंने सरकारी इमारतों पर कब्ज़ा कर लिया—और जर्मनी में एक हफ़्ते तक, जिसे बर्लिन में 'लाल हफ़्ता' कहा जाता है, शहर की सत्ता उन्हींके हाथों में दिखाई दी। लेकिन जनता ने काफ़ी साथ नहीं दिया, क्योंकि ज्यादातर लोग भौचक्के-से थे, और उन्हें समझ नहीं आता था कि क्या करना चाहिए। बर्लिन के सिपाही भी भौचक्के-से होगये, और तटस्थ रहे। चूँकि इन सिपाहियों पर यकीन नहीं किया जा सकता, इसलिए सोशल डिमोक्रेटों ने खास तौर पर कुछ विशेष स्वयंसेवक भर्ती कर लिये, और उनकी मदद से साम्यवादी बगावत को दबा दिया। लड़ाई बड़ी बेरहमी से हुई, और किसीको माफ़ नहीं किया गया। लड़ाई ख़त्म होने के कुछ दिन बाद दो साम्यवादी नेता कार्ल लेबकनेस्ट (Liebknecht) और रोज़ा लक्ज़ेम्बर्ग अपनी छिपने की जगहों पर तलाश कर लिये गये, और कुछ लोगों के ज़रिये बेरहमी से क़त्ल कर दिये गये। इस क़त्ल से और बाद में क्रांतियों के मुक़दमे में बरी हो जाने से, साम्यवादियों और सोशल डिमोक्रेटों के बीच बड़ी कटुता पैदा हो गई। कार्ल लेबकनेस्ट विल्हेल्म लेबकनेस्ट का पुत्र था, जोकि उन्नीसवीं सदी का मशहूर साम्यवादी लड़ाका था और जिसका नाम मेरे एक पिछले ख़त में आया है। रोज़ा लक्ज़ेम्बर्ग भी एक पुराना काम करनेवाला था और लेनिन का बड़ा दोस्त था—और सचाई यह थी कि जिस साम्यवादी बगावत के कारण लेबकनेस्ट और लक्ज़ेम्बर्ग की मृत्यु हुई, उसके ये दोनों खिलाफ़ थे।

साम्यवादी लोग सोशल डिमोक्रेटिक प्रजातंत्र द्वारा कुचल दिये गये, और इसके बाद पॉलन ही केसर नाम के स्थान पर प्रजातंत्र के लिए एक शासन-विधान तैयार किया गया। इसलिए उसे केसर-विधान कहते हैं। तीन महीने के अन्दर ही प्रजातंत्र में नई

तब्दीली होने का अन्देशा हुआ। इस बार यह अन्देशा दूसरी ही तरफ़ से खड़ा हुआ। प्रगति-विरोधियों ने प्रति-क्रान्ति कर डालनी चाही, और उसमें पुराने जनरल खास तौर पर हिस्सा ले रहे थे। यह विद्रोह 'कैप पुश' कहलाता है। कैप नेता का नाम था, और पुश जर्मन भाषा में ऐसे विद्रोह को कहते हैं। सोशल डिमोक्रेटिक सरकार के लोग वॉलिन से भाग गये, लेकिन वॉलिन के मजदूरों ने अचानक आम हड़ताल करके, जिससे कि शहर का सारा कामकाज बन्द हो गया, इस 'पुश' का खात्मा कर दिया। संगठित मजदूरों के सामने कैप और उसके दोस्तों को भाग जाना पड़ा, और सोशल डिमोक्रेटिक नेता फिर हुकूमत करने आगये। उन्होंने साम्यवादियों के साथ जिस तरह का वर्ताव किया था, उसके मुकाबिले कैप-दल के वागियों के साथ सरकार ने बड़ी नरमी दिखाई। इनमें से कई लोग पेंशन पानेवाले अफ़सर थे, और विद्रोह करने पर भी उनकी पेंशनें जारी रहीं।

इसी तरह का क्रान्ति-विरोधी 'पुश' या विद्रोह बवेरिया में भी संगठित हुआ। वह भी नाकामयाब रहा। लेकिन उसमें सबसे बड़ी दिलचस्पी की बात यह है कि उसका संगठन करनेवाला एक छोटा-सा आस्ट्रियन अफ़सर हिटलर था, जो आज जर्मनी का डिक्टेटर है।

इस सबका नतीजा यह हुआ कि हालांकि जर्मन प्रजातन्त्र नाम के लिए चलता रहा, लेकिन वह दिन-ब-दिन कमजोर होता गया। समाजवादियों, सोशल डिमोक्रेटों और साम्यवादियों के बीच फूट होने से, प्रगति-विरोधी लोग, जो खुल्लम-खुल्ला प्रजातन्त्र की निन्दा करते थे, ज्यादा-ज्यादा संगठित और उग्र होते गये। बड़े-बड़े भूस्वामियों ने—जो जर्मनी में 'जंकर' कहलाते हैं—और बड़े-बड़े कारखानेदारों ने धीरे-धीरे उन थोड़े-से समाजवादी तत्त्वों को भी शासक-मण्डल में से निकाल दिया जो कि उसमें बाक़ी रहे थे। वर्साई की सन्धि से जर्मन लोगों को बड़ा धक्का लगा और प्रगति-विरोधियों ने अपने लाभ के लिए उसका दुरुपयोग किया। इस संधि के मुताबिक जर्मनी को अपने हथियार त्याग देने पड़े और अपनी बड़ी फ़ौज छोड़नी पड़ी। उसे सिर्फ़ एक लाख छोटी-सी फ़ौज रखने की ही इजाजत मिली। नतीजा यह हुआ कि दिखाने के लिए तो निःशस्त्रीकरण हुआ, लेकिन बहुत-से हथियार छिपा दिये गये। बड़ी-बड़ी खानगी फ़ौजें यानी मुख्तलिफ़ पार्टियों के स्वयंसेवक 'स्टील हेलमेट' कहलाते थे; साम्यवादी मजदूरों के स्वयं-सेवक 'रेड-फ़्रण्ट' कहे जाते थे, और कुछ समय बाद हिटलर के अनुयाइयों ने 'नाज़ी सेना' के नाम से दल बनाया।

जर्मनी में महायुद्ध के बाद के कुछ वर्षों में क्या-क्या हुआ, यह मैंने तुम्हें काफ़ी बता दिया है, और इससे ज्यादा भी मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि किस तरह क्रान्ति वातावरण में भर गई थी, और प्रति-क्रान्ति के साथ लड़ी थी। जर्मनी के मुख्तलिफ़ हिस्सों

में, ववेरिया और सैंक्सनी में भी, बलबे हुए थे। आस्ट्रिया में भी, जिसे कि संधि ने अपने पहले आकार से बहुत छोटा बना दिया था, बहुत-कुछ ऐसी ही हालतें रहीं। यह छोटा-सा देश, जिसको बड़ी भारी राजधानी वियेना है, भाषा और संस्कृति में बिल्कुल जर्मन था। यह १२ नवम्बर १९१८ को, अस्थायी संधि के दूसरे दिन, प्रजातन्त्र बन गया था। यह जर्मनी का हिस्सा बनना चाहता था, लेकिन मित्र-राष्ट्रों ने इसकी सख्त मनाई कर दी, हालांकि जाहिरा तौर पर ऐसा करना बिल्कुल स्वाभाविक था। आस्ट्रिया और जर्मनी की इस प्रस्तावित एकता को जर्मन भाषा में 'एन्गलस' कहते हैं और यह आजकल की समस्याओं में से एक है। आस्ट्रिया की एक समस्या टिरोल या टायरोल के बारे में भी है, जिसका एक हिस्सा, जिसमें जर्मन-आस्ट्रियन लोग रहते हैं, इटली ने दबा लिया है।

जर्मनी की तरह आस्ट्रिया में भी पहले तो सोशल डिमोक्रेटों के ही हाथ में सत्ता थी, लेकिन वे इतने डरे हुए थे और अपने अन्दर उनको इतना कम विश्वास था कि मध्यम-वर्गीय दलों से समझौते की नीति पर चलने लगे। नतीजा यह हुआ कि सोशल डिमोक्रेट बहुत कमजोर होगये और शासन दूसरों के हाथ में चला गया। जर्मनी की तरह ही यहाँ भी प्राइवेट फ़ौजें खड़ी हुईं, और आखिरकार एक प्रगति-विरोधी डिक्टेटरशाही क़ायम होगई। बहुत वक़्त तक तो वियेना के समाजवादी शहर और देहात के दक्षिणानूसी विचार के किसानों के बीच संघर्ष चलता रहा। वियेना की समाजवादी म्युनिसिपैलिटी मजदूरों के लिए अच्छे-अच्छे मकान बनवाने और दूसरी योजनाओं के लिए मशहूर होगई।

हंगरी में ३ अक्टूबर १९१८ को, महायुद्ध ख़त्म होने के पाँच हफ़्ते पहले ही, एक क्रान्ति होगई थी। नवम्बर में प्रजातन्त्र की घोषणा करदी गई। चार महीने बाद, मार्च १९१९ में, एक दूसरी क्रान्ति होगई। यह बेलाकून नाम के एक साम्यवादी नेता थे, जो पहले लेनिन का साथी रह चुका था, नेतृत्व में एक सोवियट क्रान्ति थी। एक सोवियट-सरकार भी क़ायम होगई और कई महीनों तक उसीकी सत्ता रही। इसपर देश के अनुदार और प्रगति-विरोधी लोगों ने अपनी मदद के लिए एक रुमानियन फ़ौज को बुलाया। रुमानियन लोग बड़ी खुशी से आगये। उन्होंने बेलाकून की सरकार को कुचलने में मदद दी और फिर वे देश को लूटने में लग गये। वे वहाँसे तभी गये, जब कि मित्र-राष्ट्रों ने उनके खिलाफ़ कार्रवाई करने की धमकी दी। ज्योंही रुमानियन चले गये, त्योंही हंगरी के अनुदार लोगों ने देश के तमाम उदार या उन्नत विचार के लोगों पर आतंक जमाने के लिए, ताकि वे क्रान्ति के लिए फिर होशियार न करें, एक प्राइवेट फ़ौज या स्वयंसेवक-दल संगठित कर लिया। इन तरह १९१९ में हंगरी में वह उमाना शुरू

हुआ जो 'सफ़ेद आतंक' (White Terror) कहलाता है और जो महायुद्ध के बाद के इतिहास के सबसे ज्यादा खूनी हिस्सों में से एक माना जाता है। हंगरी में कुछ अब भी सामन्तशाही है, और ये सामन्त जमींदार बड़े-बड़े कारखानेदारों के साथ, जिन्होंने महायुद्ध के जमाने में बड़ी दौलत पैदा करली थी, मिल गये, और उन्होंने न सिर्फ़ साम्यवादियों को बल्कि आम तौर पर मजदूरों, सोशल डिमोक्रेटों, उदार और शान्तिवादी लोगों और यहूदियों तक को क़त्ल किया और उनपर आतंक फैला दिया। तभीसे हंगरी में एक प्रगति-विरोधी डिक्टेटरशाही कायम है। वहाँ दिखाने के लिए एक पार्लमेण्ट है, लेकिन चुनाव की पाँचियाँ खुली हुई पड़ती हैं, यानी पार्लमेण्ट के मेम्बरों का चुनाव जाहिरा तौर पर होता है और पुलिस और फ़ौज इस बात की कोशिश करती है कि डिक्टेटरशाही जिन्हें पसन्द करती या चाहती है सिर्फ़ वे ही लोग चुने जावें। राजनैतिक सवालों पर सार्वजनिक सभायें होने नहीं दी जातीं।

इस ख़त में मैंने मध्य-योरप की महायुद्ध के बाद की घटनाओं पर और युद्ध और हार और रूसी क्रान्ति के उन देशों पर होनेवाले परिणामों पर, जो पहले 'मध्य-योरप की शक्तियाँ' कहलाते थे, विचार किया है। युद्ध के आश्चर्यजनक आर्थिक परिणाम, और उनसे पूँजीवाद मौजूदा दुर्दशा में कैसे आ गया है, इसका हाल हमें अलग ही देखना होगा। इस ख़त में मैंने जो कुछ लिखा है उसका मतलब यही है कि महायुद्ध के बाद के उन दिनों में योरप में क्रान्ति आती हुई दिखाई देती थी। इस बात से सोवियट रूस को बड़ी मदद मिली, क्योंकि किसी भी बड़ी साम्राज्यवादी शक्ति को अपने मजदूर-वर्ग पर बुरा असर पैदा होने के अन्देश से उसपर पूरे दिल से हमला करने की हिम्मत नहीं हुई। फिर भी क्रान्ति हुई नहीं, सिर्फ़ कहीं-कहीं छोटे-छोटे प्रयत्न हुए जो कुचल दिये गये। इस सामाजिक क्रान्ति के कुचलने और रोकने में सोशल डिमोक्रेटों ने सबसे ज्यादा हिस्सा लिया, हालाँकि उनका सारा दल इसी तरह की सामाजिक क्रान्ति के उसूल पर कायम हुआ था। मालूम होता है कि ये सोशल डिमोक्रेट समझते थे या उम्मीद करते थे कि पूँजीवाद खुद ही अपनी मौत मर जायगा। इसलिए जोर से उसपर हमला करने के बजाय उन्होंने उसे कम-से-कम उस वक़्त तो बचे रहने में मदद दी। या यह भी मुमकिन है कि उनकी बड़ी भारी और मालदार पार्टी-मशीन इतने आराम में थी, या मौजूदा समाज-व्यवस्था में ही इतनी फँसी हुई थी, कि वह सामाजिक उथल-पुथल की जोखिम उठाना नहीं चाहती थी। उन्होंने बीच का रास्ता इख़्तियार करने की कोशिश की। लेकिन नतीजा यह हुआ कि उन्होंने सारा काम बिगाड़ दिया और हाथ में जो कुछ था वह भी खो दिया। जर्मनी की हाल की घटनाओं ने इस बात को और भी ज्यादा साफ़ कर दिया है।

महायुद्ध के बाद एक और बात जो जोर पकड़ती गई, वह है बल-प्रयोग की मनोवृत्ति का पैदा होना। यह ताज्जुब की बात है कि जब हिन्दुस्तान में अहिंसा का सन्देश फैलाया जा रहा था, उन्हीं दिनों दुनिया में क़रीब-क़रीब सभी जगह हिंसा—नग्न और निर्लज्ज हिंसा—ही अमल में आ रही थी और उसका गौरव बढ़ाया जा रहा था। इसका कारण था ज्यादातर तो महायुद्ध और बाद में मुस्लिफ़ वर्गों के स्वार्थों की टक्कर। ज्यों-ज्यों मुस्लिफ़ वर्गों के स्वार्थ ज्यादा-ज्यादा एक-दूसरे से टकराते गये और उनमें स्पष्टता और गहराई आती गई, त्यों-त्यों हिंसा बढ़ती गई। उदार सिद्धान्त क़रीब-क़रीब मिट गये, और उन्नीसवीं सदी का प्रजातन्त्रवाद नापसन्द किया जाने लगा। डिक्टेटर लोग मैदान में आगये।

मैंने इस ख़त में हारी हुई शक्तियों के बारे में लिखा है। जीतनेवाली शक्तियों को भी ऐसी ही तकलीफ़ें उठानी पड़ीं, हालांकि मध्य-योरप के समान उयल-पुयल या बलवे इंग्लैण्ड और फ़्रांस में नहीं हुए। इटली में एक ख़ास ढंग की उयल-पुयल हुई, जिसके अजीब ही नतीजे हुए। उनका बयान भी अलग किया जाना चाहिए।

: १७२ :

पुराने क़र्ज़ चुकाने की नई तरकीब

१५ जून, १९३३

इस तरह हम देखते हैं कि महायुद्ध के बाद योरप और दरअसल किसी हद तक सारा संसार एक उबलती हुई कढ़ाई की हालत में था। वर्साई की और दूसरी संधियों से मामले नहीं सुधरे। योरप के नये नक्शे से पोल और ज़ेक और बाल्टिक जातियों को आज़ाद बनाकर कुछ पुरानी राष्ट्रीय समस्याएँ सुलझाई गईं। लेकिन इसके साथ ही आस्ट्रियन टिरोला या टायरल को इटली के मातहत करने, यूक्रेन के एक हिस्से को पोलैण्ड को दे देने, और पूर्वी योरप में और भी कुछ दुःखदाई मुल्की बटवारा करने के कारण कई नई-नई राष्ट्रीय समस्याएँ खड़ी भी होगईं। सबसे अजीब और चिढ़ पैदा करनेवाली पोलिश कॉरीडर और डेनज़िग की व्यवस्था थी। योरप के मध्य और पूर्व में कई नये छोटे-छोटे राज्य बना दिये गये, जिसके मानी हुए सरहदों, चुंगी की हदबन्दियों और आपसी नफ़रतों में बढ़ि।

१९१९ की इन संधियों के अलावा भी रुमानिया ने किसी तरह बेमारोविया प्रदेश ले लिया, जोकि पहले दक्षिण-पश्चिम रून का हिस्सा था। तबसे लगातार इस प्रदेश की दावत नोबियट और रुमानिया में झगड़ा और दलीलबाज़ी होनी रही है। बेमारोविया 'नीपर का एल्नेम-लॉर्गेन' कहलाने लगा है।

मुल्की तब्दीलियों से भी बड़ा सवाल मुआवजे (रिपेयरेशनस्) का था, यानी उस रुपये का जो महायुद्ध के खर्चों और नुकसानों के बदले में हारा हुआ जर्मनी जीतने-वाले मित्र-राष्ट्रों को अदा करे। वसर्ई की सन्धि में इसकी कोई निश्चित रकम मुक्रर नहीं की गई थी, लेकिन बाद की कान्फरेन्सों में मुआवजे की रकम ६,६०,००,००,००० पौण्ड मुक्रर की गई, जो सालाना क्रिस्तों में देनी थी। इतनी बड़ी रकम किसी देश के लिए भी देना मुश्किल था, और हारा और थका हुआ जर्मनी तो इसे देने के और भी ज्यादा नाकाबिल था। जर्मनी ने इसका विरोध किया, लेकिन देकार हुआ, और फिर जब कोई चारा न रहा तो उसने यूनाइटेड स्टेट्स यानी संयुक्तराष्ट्र अमेरिका से उधार लेकर दो-तीन क्रिस्तें अदा कीं। कुछ वक़्त गुज़ारने और फिर सारे सवाल पर फिर से ग़ौर करवाने के लिए ही उसने ऐसा किया। उसे और ज्यादातर दूसरे मुल्कों पर भी यह जाहिर होगया था कि पीढ़ियों तक बड़ी-बड़ी रकमें वह देता नहीं जा सकता था।

बहुत जल्दी ही जर्मनी की आर्थिक व्यवस्था टूट गई, और सरकार के पास न तो बाहरी ऋजों, जैसे मुआवजा वग़ैरा, और न अन्दरूनी देनदारियां तक पूरी करने के लिए काफ़ी धन रहा। दूसरे देशों को अदायगी सुवर्ण में करनी पड़ती थी। जब अदायगियां मुक्रर तारीखों पर न हो सकीं, तो वादा-खिलाफ़ी हुई। फिर भी जर्मनी के अन्दर तो सरकार करेंसी नोटों की शक्ल में अदायगी कर सकती थी, और इसलिए उसने अधिकाधिक कागज़ी नोट छाप लेने की तरकीब चलाई। कागज़ के नोट छाप लेने से धन पैदा नहीं होता; सिर्फ़ साख़ या अदायगी की ज़िम्मेदारी का विश्वास पैदा होता है। लोग कागज़ के नोटों का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि उन्हें मालूम है, अगर वे चाहें तो उनके बदले में उन्हें सोना या चांदी मिल सकता है। इन नोटों के लिए बैंकों में हमेशा किसी क़दर सोना रक्खा रहता है, जिससे कि नोटों की क़ीमत बनी रहे। इस तरह कागज़ी रुपये से बड़ा उपयोगी काम निकलता है, क्योंकि इससे रोज़ाना लेन-देन में सोना लगने से बच जाता है और साख़ भी बढ़ जाती है। लेकिन अगर कोई सरकार इस बात का ख़याल न करे कि बैंकों में कितना सोना है और कागज़ी रुपया छापती और बेहद नोट जारी करती चली जाय तो इस कागज़ी रुपये की क़ीमत ज़रूर गिरेगी। नोट जितना ज्यादा छपता जायगा, उतनी ही उसकी क़ीमत घटेगी और देनदारी की साख़ का कार्य भी वह उतना ही कम करेगा। इस व्यवस्था को 'इनफ़्लेशन' कहते हैं। १९२२ और १९२३ में जर्मनी में ठीक यही बात हुई। जर्मन सरकार को अपने खर्चों के लिए जैसे-जैसे ज्यादा रुपये की ज़रूरत होती गई, वैसे-वैसे वह ज्यादा-से-ज्यादा नोट छापती गई। इससे हर चीज़ के दाम चढ़ गये, लेकिन पौण्ड, डालर

या फ्रांक के मुकाबिले में खुद जर्मन मार्क की कीमत घट गई। इसलिए सरकार को और मार्क छापने पड़े, और फिर इससे मार्क की कीमत और भी गिरी। यह अव्यवस्था बहुत ज्यादा बढ़ गई, यहाँ तक कि एक डालर या पाउण्ड की कीमत अरबों कागज़ी मार्क होगई। असल में कागज़ी मार्क का कोई मूल्य ही नहीं रहा। लिफ्राफ़े पर लगाने के लिए एक टिकट की कीमत दस लाख कागज़ी मार्क होगई ! दूसरी चीज़ों के दाम भी इसी हिसाब से कम या ज्यादा थे, और हमेशा बदलते भी रहते थे।

जर्मनी का यह 'इन्फ़्लेशन' और मार्क की कीमत में आश्चर्यजनक गिरावट अपने-आप ही नहीं होगये थे। यह जर्मन सरकार ने आर्थिक कठिनाइयों में से निकलने के लिए जान-बूझकर किया था, और बहुत काफ़ी दूर तक वह कठिनाइयों में से निकल भी गई; क्योंकि सरकार ने और म्यूनिसिपैलिटियों ने और दूसरे कर्जदारों ने जर्मनी के अपने अन्दरूनी कर्ज आसानी से मूल्यहीन कागज़ी मार्कों द्वारा चुका दिये। बेशक वे इस तरह बाहरी देशों के कर्जों को नहीं चुका सकते थे, क्योंकि वहाँका कोई भी आदमी उनके कागज़ी रुपये को नहीं ले सकता था। जर्मनी में तो वे क़ानून के जरिये भी ऐसी अदायगी को मंज़ूर करवा सकते थे। इस तरह सरकार और हर कर्जदार कर्ज के दुःखदायी बोझ से छूट गया। लेकिन ऐसा करने में बड़ी ज़बरदस्त मुसीबतें उठानी पड़ीं। इन्फ़्लेशन के इस असर में सभी लोगों ने तकलीफ़ें उठाई; लेकिन सबसे ज्यादा मुसीबत मध्यमवर्गों को हुई, क्योंकि उन्हें ज्यादातर निश्चित तनखाहें मिलती थीं, या दूसरी किसी तरह की आमदनी भी निश्चित ही थी। बेशक ज्यों-ज्यों मार्क गिरता गया त्यों-त्यों इनकी तनखाहें बढ़ती गई, लेकिन जिस रफ़्तार से मार्क गिरता था उसके मुताबिक ही उनकी तनखाहें नहीं बढ़ पाती थीं। निचले मध्यमवर्ग तो इस इन्फ़्लेशन से क़रीब-क़रीब मिट ही गये, और जब हम जर्मनी में बाद के वर्षों में होनेवाली खास-खास घटनाओं पर विचार करेंगे तो हमें इस बात को याद रखना होगा। क्योंकि फिर तो इन असंतुष्ट वर्गहीन (Declassed) मध्यमवर्गों की एक ज़बरदस्त असंतुष्ट सेना बन गई, जिनसे बड़ी-बड़ी आन्दोलनकारी संभावनाये थीं। वे प्रमुख दलों के साथ बननेवाली प्राइवेट फ़्रोंज़ों में दाख़िल होगये और ज्यादातर हिटलर के नये दल नैशनल सोशलिस्ट या नाज़ी पार्टी में चले गये।

पुराना मार्क, जो कि अब बिल्कुल भी काम का न रहा था, मंख़ु कर दिया गया, और नये नोट, जिन्हें 'रेप्टेन मार्क' कहने थे, चालू किये गये। इनमें 'इन्फ़्लेशन' नहीं किया गया, और ये अपने सोने की कीमत के बराबर होने थे। इस तरह जर्मनी अपने निचले मध्यम वर्गों का सफ़ाया करके फिर स्थायी मुद्रा-प्रणाली पर लौट आया।

जर्मनी की आर्थिक मुसीबतों के बड़े-बड़े अन्तर्राष्ट्रीय परिणाम हुए। मित्र-राष्ट्रों

को दिये जानेवाले मुआवजे की किस्त चूक गई। यह मुआवजा इन मित्र-राष्ट्रों के बीच बांट लिया जाता था, और सबसे ज्यादा हिस्सा फ्रांस को मिलता था। रूस उसमें से कुछ भी नहीं लेता था। असल में, उसमें अगर उसका कोई हक रहा भी हो तो वह भी उसने छोड़ दिया था। जर्मनी की तरफ से जब किस्त की अदायगी न हुई तो फ्रांस और बेलजियम ने जर्मनी के रूर प्रदेश पर फौजी कब्जा कर लिया। मित्र-राष्ट्रों के पास वर्साई-सन्धि के मुताबिक राइनलैण्ड पहले से ही था। जनवरी १९२३ में फ्रांस और बेलजियम ने एक और हिस्से पर कब्जा कर लिया (इंग्लैण्ड ने इस काम में शरीक होने से इन्कार कर दिया)। यह रूर प्रदेश राइनलैण्ड के पास ही है और इसमें बहुत अच्छी-अच्छी कोयले की खानें और कारखाने हैं। फ्रांसीसी चाहते थे कि कोयला वगैरा जो माल वहाँ पैदा होता है उसपर कब्जा करके वे अपनी रकम अदा कर लें। लेकिन इसमें एक कठिनाई आ गई। जर्मन सरकार ने फ्रांस के इस कब्जे का विरोध निष्क्रिय प्रतिरोध या सत्याग्रह के जरिये करने का फैसला किया, और उसने रूर के खान-मालिकों और मजदूरों से कह दिया कि वे काम बन्द कर दें और फ्रांसीसियों को किसी तरह भी मदद न दें। उसने खान-मालिकों और कारखाने-दारों को उनके किये गये नुकसान के एवज में लाखों मार्क भी दिये। नौ या दस महीनों के बाद, जिनमें फ्रांस और जर्मनी दोनों को बहुत खर्च उठाने पड़े, जर्मन सरकार ने निष्क्रिय प्रतिरोध हटा लिया और उस प्रदेश में खानों और कारखानों के चलाने में फ्रांस से सहयोग करना शुरू कर दिया। १९२५ में फ्रेञ्च और बेलजियनों ने रूर को छोड़ दिया।

रूर में जर्मनी का निष्क्रिय प्रतिरोध टूट गया, लेकिन उसने जाहिर कर दिया कि मुआवजे के सवाल पर फिर से शीर होना चाहिए और किस्तों की रकम ज्यादा समझदारी से मुक़र्रर की जानी चाहिए। इसलिए एक के बाद एक जल्दी-जल्दी कई कान्फ़रेंसें हुईं और कमीशन मुक़र्रर हुए, और एक के बाद एक कई योजनायें निकाली गईं। १९२४ में डाज़-योजना बनी, और पाँच साल बाद १९२९ में यंग-योजना बनी, और तीन साल बाद १९३२ में सभीने यह मान लिया कि और किस्तें नहीं दी जा सकती हैं, और उसका ख़याल ही छोड़ दिया गया।

१९२४ के बाद इन कुछ वर्षों तक जर्मनी ने मुआवजे की बाकायदा किस्तें अदा कीं। लेकिन जब जर्मनी के पास धन नहीं था और वह दीवालिया-सा हो रहा था, तो यह बात किस तरह हो सकी? यह अदायगियाँ अमेरिका से उधार लेकर की गईं। मित्र-राष्ट्रों (इंग्लैण्ड, फ़्रान्स, इटली वगैरा) को अमेरिका को रुपया देना था जोकि उन्होंने महायुद्ध के जमाने में उधार लिया था; और जर्मनी को मुआवजे की

शकल में रुपया मित्र-राष्ट्रों को देना था। इसलिए अमेरिका ने जर्मनी को उधार दिया, और जर्मनी मित्र-राष्ट्रों को दे सका, ताकि अन्त में मित्र-राष्ट्र भी अमेरिका को अदायगी कर सकें। यह एक बड़ा मजेदार फ़ैसला था, जिससे कि हरेक संतुष्ट नज़र आता था ! दरअसल, इसके सिवा बसूली करने की और कोई सूरत ही नहीं थी। हाँ, यह उधारी और अदायगी का सारा चक्कर एक बात पर निर्भर था—अमेरिका जर्मनी को उधार देता चला जाय। अगर यह बन्द होजाता है तो सारी व्यवस्था टूट जाती है।

इन उधारियों और अदायगियों में नक़द धन का वास्तविक लेना और देना नहीं होता था; क़ागज़ी जमा-ख़र्च होजाता था। अमेरिका जर्मनी के नामे एक खास रक़म लिख देता था, जर्मनी इसे मित्र-राष्ट्रों के नामे बदलवा देता था, और मित्र-राष्ट्र फिर उसे ही अमेरिका के नामे बदलवा देते थे। वास्तविक धन कहीं न जाता था, न आता था, सिर्फ़ हिसाब के काग़ज़ों में कई इन्दराज होजाया करते थे। अमेरिका ग़रीब मुल्कों को, जो अपने पिछले कर्ज़ों का सूद भी न चुका सकते थे, रुपया क्यों उधार देता गया ? अमेरिका ने उधार इसलिए दिया कि किसी तरह इनका काम चलता रहे, और वे दीवालिया न हों, क्योंकि अमेरिका को योरोप के एकदम बर्बाद हो जाने का डर था, जिससे कि सारा क़र्ज़ा मारा जाता। इसलिए समझदार ऋणदाता या साहूकार की तरह, अमेरिका ने अपने कर्ज़दारों को जिन्दा और उनका काम चालू रखवा। लेकिन कुछ वर्षों के बाद अमेरिका इस लगातार ऋण देने की नीति से तंग आगया और उसने देना बन्द कर दिया। फ़ौरन ही मुआवज़े और क़र्ज़ों की सारी इमारत गिर पड़ी, किस्ते रुक गई और योरोप और अमेरिका के सारे राष्ट्र एक ऐसी दलदल में फँस गये, जिसमें पड़े वे अब भी तड़फड़ा रहे हैं। इसके बारे में मैं बाद में कुछ और कहूँगा।

इस तरह महायुद्ध के बाद मुआवज़े की समस्या ने योरोप को दस-बारह साल से भी ज्यादा फँसाये रक्खा। इसके साथ ही महायुद्ध के क़र्ज़ों यानी जर्मनी के अलावा दूसरे देशों के क़र्ज़ों का भी सवाल था। ज़ेता कि मैं महायुद्ध की वास्तव लिखे हुए ख़त में तुम्हें बता चुका हूँ, शुरू के दिनों में इंग्लैंड और फ़्रांस अपने छोटे-छोटे मित्र-देशों को युद्ध के लिए रुपया उधार देते थे। इसके बाद फ़्रांस के डरिये ख़त्म होगये, और उसने उधार देना बन्द कर दिया। लेकिन इंग्लैंड देता रहा। बाद में आर्थिक दृष्टि से इंग्लैंड भी दिगड़ गया, और ज्यादा उधार नहीं दे सका। सिर्फ़ अमेरिका ही दे सकता था, और उसने दड़ी फ़ैसली यानी उधारता ने कर्ज़ा दिया, जिनमें उनका और इंग्लैंड, फ़्रांस और दूसरे मित्र-राष्ट्रों का भी क़ादर था। इन तरह महायुद्ध ख़त्म

होने पर कुछ देशों पर फ्रांस का कर्जा हो गया था, कई पर इंग्लैण्ड का कर्जा हो गया था, और सारे मित्र-राष्ट्रों पर अमेरिका का बड़ा भारी कर्जा हो गया था। अमेरिका ही एक ऐसा देश था जिसपर दूसरे किसीका ऋण न था। उस वक़्त वह एक बड़ा भारी साहूकार देश बन गया था। वह इंग्लैण्ड के पुराने स्थान पर पहुँच गया; और संसार का साहूकार बन गया। कुछ आँकड़े देने से यह बात और भी साफ़ होजायगी। महायुद्ध के पहले अमेरिका एक ऋणी देश था, उसपर दूसरे देशों का ३ अरब डालर कर्जा था, महायुद्ध के समाप्त होने के वक़्त तक यह कर्जा मिट गया था, और इसके बजाय अमेरिका ने ही बहुत बड़ी-बड़ी रकम उधार दे दी थीं। १९२६ में अमेरिका ऋण-दाता देश हो गया, और उसका दिया हुआ कर्जा २५ अरब डालर तक पहुँच गया।

युद्ध के ये कर्जें कर्जदार मुल्कों—इंग्लैण्ड, फ़्रान्स, इटली वगैरा—पर बहुत ज्यादा बोझ-से थे, क्योंकि ये सब सरकारी कर्जें थे, जिनके लिए सरकारें जिम्मेदार थीं। उन्होंने अमेरिका से खास रियायती शर्तें प्राप्त करने की कोशिश की, और उन्हें कुछ सहूलियतें मिल भी गईं, लेकिन फिर भी बोझ तो बना ही रहा। जबतक जर्मनी मुआवजे की रकम देता रहा, तबतक तो ये कर्जदार मुल्क अमेरिका को वही रकम (जो असल में अमेरिका का दिया हुआ कर्जा ही था) तब्दील करके देते रहे। लेकिन जब मुआवजे मिलना अनियमित हो गया या बन्द हो गया, तो कर्जा चुकाना मुश्किल हो गया। योरोप के कर्जदार देशों ने कोशिश की कि मुआवजे और युद्ध के कर्जों का ताल्लुक कायम कर दिया जाय। उन्होंने कहा कि दोनों बातों पर साथ-साथ विचार किया जाना चाहिए, और अगर यह बन्द हो जाता है तो वह भी अपनेआप बन्द होजाना चाहिए; लेकिन अमेरिका ने इन दोनों बातों को एक मानने से इन्कार कर दिया। उसने कहा कि मैंने तो रुपया दिया है, मुझे अपना वह रुपया मिलना चाहिए, और इससे मुझे कोई मतलब नहीं कि जर्मनी से मुआवजा मिलता है या नहीं, जिसका कि आधार ही दूसरा है। योरोप में अमेरिका के इस रुख पर बड़ी नाराज़गी जाहिर की गई और उसे बहुत बुरा-भला कहा गया। कहा कि वह शायलाक जैसा लोभी बनिया है, कि जिसने अपने कर्जदार का पूरा एक पौंड मांस-काटकर लेने का हठ किया था। खासकर फ़्रान्स में यह कहा गया कि यह युद्ध सबके साझे का काम था, जिसके लिए कि कर्जा लिया गया था, इसलिए कर्जों को साधारण ऋण के समान न समझना चाहिए। और दूसरी तरफ़ अमेरिकन लोगों में महायुद्ध के बाद योरोप में होनेवाले झगड़ों और साजिशों से बड़ी नफ़रत पैदा होगई थी। उन्होंने देखा कि अब भी फ़्रान्स और इंग्लैण्ड और इटली अपनी-अपनी क़ौजों और नौसेनाओं पर भारी-भारी रकम खर्च करते जा रहे

उन्नीस सौ बीस के बाद के दस वर्षों की अमेरिकन सम्पन्नता के आँकड़े मैंने इसलिए दिये हैं कि तुम्हें मालूम हो जाय कि आजकल की औद्योगिक सभ्यता ने एक देश को हिन्दुस्तान और चीन जैसे पिछड़े हुए अनौद्योगिक देशों के मुकाबिले में कितना ज्यादा मालदार बना दिया, और तुम यह भी देख लो कि इस सम्पन्नता के मुकाबिले में अमेरिका में वाद का संकट और सर्वनाश कितना बड़ा आया, जिसका कि मैं आगे बयान करूँगा ।

संकट-काल तो बाद में आया । ठीक १९२९ तक तो यही दिखाई दिया कि योरप और एशिया जिन बुराइयों में फँस गये हैं उनसे अमेरिका बचा हुआ है । हारी हुई शक्तियों का हाल खराब था । मैंने तुम्हें जर्मनी को तक्रलीफों का कुछ हाल बता ही दिया है । मध्य-योरप के ज्यादातर छोटे देश, खास तौर पर आस्ट्रिया, तो और भी बुरी दशा में थे । आस्ट्रिया को भी 'इन्फ्लेशन' की मुसीबतें उठानी पड़ीं, और पोलैण्ड को भी । फिर इन दोनों को ही अपनी करेंसी या मुद्रा-प्रणाली बदलनी पड़ी ।

लेकिन ये मुसीबतें सिर्फ हारे हुए देशों तक ही महद्द नहीं थीं, बल्कि जीतने वाले देशों पर भी धीरे-धीरे आगई । यह बात हमेशा मानी जाती थी कि कर्जदार होना अच्छा नहीं है । अब एक नया और अजीब ही तजुर्बा हुआ; वह यह कि ऋणदाता होना भी अच्छा नहीं है । क्योंकि विजयी शक्तियाँ, जिनका मुआवजा जर्मनी को चुकाना था, इस मुआवजे के सबब से बड़ी कठिनाइयों में पड़ गईं, और जब उसकी वसूली करने लगीं तो वे और भी ज्यादा मुसीबत में पड़ीं । इस बाबत मैं अगले खत में लिखूँगा ।

: १७३ :

मुद्रा की गड़बड़ी

१६ जून, १९३३

महायुद्ध के बाद के जमाने में एक बड़ी उल्लेखनीय बात मुद्रा यानी सिक्कों, नोटों आदि की गड़बड़ी हुई । महायुद्ध के पहले हर देश में मुद्रा की बहुत कुछ निश्चित क्रोमत हुआ करती थी । हर मुल्क की अपनी अलग-अलग प्रचलित मुद्रा थी—जैसे हिन्दुस्तान में रुपया, इंग्लैण्ड में पौण्ड, अमेरिका में डालर, फ्रांस में फ्रांक, जर्मनी में मार्क, रूस में रूबल, इटली में लीरा, वगैरा; और इन मुलतलिफ़ सिक्कों का भी आपस में एक निश्चित सम्बन्ध होता था । वे एक-दूसरे से अन्तर्राष्ट्रीय 'गोल्ड स्टैण्डर्ड' (स्वर्ण-मान) द्वारा सम्बन्धित थे, यानी हर देश के प्रचलित सिक्के की सोने में एक

हैं। १९२६ में अमेरिका की लगी हुई पूंजी सवा चार अरब डालर थी। तीन साल बाद, १९२९ में, वह साढ़े पाँच अरब से ज्यादा होगई।

इस तरह महायुद्ध के बाद के इन वर्षों में अमेरिका देशक सारी दुनिया का सहूँकार बन गया। वह धनी था, सम्पन्न था, और दीलत से फटा पड़ता था। वह सारी दुनिया पर हावी था, और उसके निवासी कुछ-कुछ घृणा के साथ योरप को और एशिया को तो और भी ज्यादा, बूढ़ा और झगड़ालू महाद्वीप समझते थे। १९२० से १९२९ तक की ज़बरदस्त खुशहाली के उन दिनों में अमेरिका के धन की ज़रूरत कल्पना करो। १९१२ से १९२७ तक के पंद्रह वर्षों में अमेरिका का सारा राष्ट्रीय धन १,८७,२३,९०,००,००० डालर से बढ़कर ४,००,००,००,००,००० डालर होगया। १९२७ में उसकी आबादी ११७० लाख के करीब थी और हर आदमी पर ३,४२८ डालर धन का औसत पड़ता था। प्रगति इतनी तेज़ी से हुई है कि ये आँकड़े हर साल बदल जाते हैं। एक पिछले खत में, हिन्दुस्तान और दूसरे देशों की राष्ट्रीय आय का मुक़ाबिला करते हुए, मैंने अमेरिका का आँकड़ा बहुत नीचा दिया था। वह आँकड़ा सालाना आमदनी का था, न कि धन का, और शायद वह किसी पिछले साल का था। १९२७ का आँकड़ा जो ऊपर दिया गया है, वह अमेरिका के प्रेसीडेंट कूलिज़ के नवम्बर १९२६ के एक वक्तव्य पर से लिया गया है।

कुछ और आँकड़े भी तुम्हें दिलचस्प मालूम होंगे। वे सब १९२७ के हैं। संयुक्तराष्ट्र अमेरिका में कुटुम्बों की तादाद २७० लाख थी। उनकी मिल्कियत में १,५९,२३,००० बिजलीदार मकान थे, और १,७७,८०,००० टेलीफ़ोन व्यवहार में आते थे। १,९२,३७,१७१ मोटर-कारें चलती थीं, और यह तादाद सारी दुनिया की तादाद का ८१ फीसदी थी। अमेरिका ने सारे संसार की ८७ फीसदी मोटर-गाड़ियाँ बनाईं, दुनिया का ७१ फीसदी पेट्रोलियम तैयार किया, और दुनिया का ४३ फीसदी कोयला निकाला। इसपर भी उसकी आबादी संसार की आबादी की ६ फीसदी ही थी। इस तरह आम रहन-सहन का दर्जा बहुत ऊँचा था, और फिर भी जितना ऊँचा होना मुमकिन था उतना नहीं था, क्योंकि धन तो कुछ ही अरबपतियों और ख़रबपतियों के हाथों में केन्द्रित था। ये 'बड़े-बड़े व्यापारी' (Big Business) ही सारी दुनिया पर हुकूमत करते थे। उन्हींकी मर्जी से प्रेसीडेंट यानी राष्ट्रपति चुना जाता था, वे ही क़ानूनों के बनानेवाले थे, और अवसर वही क़ानूनों को तोड़ा भी करते थे। इन बड़े व्यापारियों में बड़ी भयंकर रिश्ततख़ोरी जारी थी, लेकिन अमेरिका में जबतक आम तौर पर सम्पन्नता या खुशहाली रही तबतक उन्होंने इसकी कोई परवा नहीं की।

आई। क्योंकि औद्योगिक तरक्की का अर्थ था बहुत ही पेचीदा और नाजुक अन्तर्राष्ट्रीय ढाँचा। जाहिर है कि तिब्बत जैसे पिछड़े हुए और दुनिया से अलग रहनेवाले देश पर तो मार्क या पौण्ड के उतार-चढ़ाव का कोई असर न होगा, लेकिन डालर की क्रीमत के गिरने से जापान में फ़ौरन गड़बड़ी पड़ जायगी।

इसके अलावा, हर औद्योगिक देश में हरेक वर्ग के हित जुदा-जुदा थे। इस तरह, कुछ वर्ग तो सस्ती मुद्रा और इन्फ़्लेशन (हाँ, जर्मनी की तरह इन्फ़्लेशन नहीं) चाहते थे, लेकिन कुछ वर्ग इससे बिल्कुल उलटी बात, डिफ़्लेशन यानी मुद्रा का ऊँचा स्वर्ण-मूल्य चाहते थे। मसलन, ऋणदाता बैंकर वगैरा इस राय के थे कि मुद्रा की क्रीमत ऊँची रहे, क्योंकि उन्हें लोगों से धन लेना था, और ऋणी लोग कुदरती तौर पर यह चाहते थे कि ऋजें चुकाने के लिए मुद्रा सस्ती रहे। कारख़ानेदार और माल तैयार करनेवाले सस्ती मुद्रा के तरफ़दार थे। क्योंकि वह आम तौर पर बैंकरों के ऋजदार थे, और उससे भी बड़ा कारण यह था कि इससे विदेश में उनके माल बिकने में मदद मिलती थी। अगर ब्रिटेन में मुद्रा सस्ती हो तो, इसका मतलब यह होगा कि विदेशियों में ब्रिटिश माल की क्रीमत जर्मन या अमेरिकन या दूसरे देशों के माल से कम होगी और इससे ब्रिटेन के कारख़ानेदारों को फ़ायदा होगा और उनका माल ज्यादा बिकेगा। इस तरह तुम्हें मालूम होगा कि जुदा-जुदा वर्ग अपना-अपना मतलब साधना चाहते थे, और खास रस्साकशी कारख़ानेदारों और बैंकरों के बीच में थी। मैं इस बात को ज्यादा-से-ज्यादा आसान बनाकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दरअसल, इसमें बहुत-से पेचीदा कारण शामिल थे।

फ़्रांस और इटली में 'इन्फ़्लेशन' हुआ, और फ़्रांक और लीरा का भाव गिर गया। पहले एक पाउण्ड स्टर्लिंग के (जो कि ब्रिटिश पौण्ड का नाम है) लगभग २५ फ़्रांक मिला करते थे। फिर भाव के गिरने से एक पाउण्ड के २७५ फ़्रांक तक हो गये। आख़िरकार उसका भाव एक पाउण्ड के १२० फ़्रांक के करीब मुक़र्रर कर दिया गया।

महायुद्ध के बाद जब अमेरिका ने इंग्लैण्ड की मदद करना बन्द कर दिया, तो पौण्ड की क्रीमत कुछ गिर गई। उस वक़्त इंग्लैण्ड के सामने कठिनाई खड़ी हो गई। क्या उसे मुनासिब था कि वह पाउण्ड की क्रीमत की इस कुदरती गिरावट को मंज़ूर करले, और पौण्ड की यह नई क्रीमत ही मुक़र्रर करदे? इससे माल तो सस्ता होजाता और कारख़ानों को मदद भी पहुँचती, लेकिन बैंकरों और ऋणदाताओं को नुक़सान होता। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि इससे दुनिया के आर्थिक केन्द्र के रूप में लन्दन की जो स्थिति थी वह मिट जाती। फिर तो इस स्थिति में

निश्चित यानी तयशुदा क्रीमत होती थी। हर देश की सीमा में उसकी प्रचलित मुद्रा ठीक समझी जाती थी, लेकिन उसके बाहर नहीं। दो भिन्न-भिन्न प्रचलित मुद्राओं का सम्बन्ध जोड़नेवाली चीज थी सोना, और इस तरह अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन सोने की शक्ल में हुआ करते थे। जबतक कि प्रचलित मुद्राओं का निश्चित स्वर्ण-मूल्य रहा तबतक उनमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ सका, क्योंकि जहाँतक मूल्य या क्रीमत का ताल्लुक है वहाँतक सोना एक काफ़ी स्थायी धातु है—यानी ऐसी धातु है जिसमें मूल्य सम्बन्धी उतार-चढ़ाव बहुत कम होता है।

लेकिन महायुद्ध-काल की जरूरियात से मजबूर होकर युद्ध करनेवाली सरकारों को यह स्वर्ण-मान (गोल्ड स्टैंडर्ड) छोड़ना पड़ा, और इस तरह उन्होंने अपनी प्रचलित मुद्राओं को सस्ता बना दिया। किसी हदतक 'इन्फ्लेशन' भी किया गया। इससे व्यापार चलाने में तो मदद मिली, लेकिन मुह्तलिफ़ देशों की प्रचलित मुद्राओं या सिक्कों के बारे में उलट-फेर जरूर होगया। महायुद्ध के जमाने में दुनिया दो विरोधी पक्षों में बँट गई थी—एक मित्र-राष्ट्रों का पक्ष और दूसरा जर्मन पक्ष; और हर पक्ष के अन्दर आपसी सहयोग और संगठन था, और हरेक बात युद्ध को मद्देजर रखकर की जाती थी। दिक्कतें तो महायुद्ध के बाद पैदा हुईं, और बदलते हुए माली हालात और क्रीमों के आपसी अविश्वासों का नतीजा यह हुआ कि मुह्तलिफ़ प्रचलित मुद्राओं में गड़बड़ी पड़ गई। आजकल की सारी अर्थ-व्यवस्था ज्यादातर साख (क्रेडिट) पर चल रही है। बैंक-नोट और चेक दोनों ही वास्तविक धन नहीं, सिर्फ़ अदायगी के वादे हैं, लेकिन उन्हें वास्तविक धन के तौर पर मंजूर कर लिया जाता है। साख हमारे विश्वास पर कायम है, और अगर विश्वास हट जाता है तो उसके साथ साख (क्रेडिट) भी चली जाती है। पिछले दस-बारह वर्षों में मुद्रा-व्यवस्था में इतनी ज्यादा गड़बड़ी होने का यह भी एक कारण है। क्योंकि योरप की कठिनाई से भरी परिस्थितियों ने सारे विश्वास को हिला दिया है। आज की दुनिया परस्पराधीन भी है, हरेक हिस्से का दूसरे हिस्से से बड़ा गहरा ताल्लुक है, और हमेशा ही अनेक अन्तर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियाँ चलती रहती हैं। इसका मतलब यह है कि एक देश की गड़बड़ी का दूसरे देशों पर फ़ौरन असर पड़ता है। अगर जर्मनी का मार्क गिरता है, या जर्मन बैंक फ़ेल होजाता है, तो उससे लन्दन और पेरिस और न्यूयार्क के लोग भी कई तरह से गड़बड़ी में पड़ जाते हैं।

इन और दूसरे कारणों से, जिन्हें बतलाकर मैं तुम्हें हैरान नहीं करूँगा, क़रीब-क़रीब तमाम मुल्कों में मुद्रा या धन के बारे में दिक्कतें पैदा होगईं, और अक्सर जो मुल्क उद्योग-धन्धों में जितना ज्यादा बढ़ा हुआ था उतनी ही ज्यादा उसपर मुसीबत

महाद्वीप और अमेरिका के बड़े-बड़े और ज्यादा अच्छी तरह संगठित गिरोहों का आसानी से मुकाबिला नहीं कर सकता था ।

चूँकि कोयले के उद्योग की हालत दिन-ब-दिन गिरती गई, इसलिए खानों के मालिकों ने मजदूरों की मजदूरी घटाने का फैसला किया । खानों के मजदूरों ने इसकी सख्त मुखालफ़त की, और इसमें उन्हें दूसरे उद्योगों के मजदूरों का समर्थन भी प्राप्त होगया । खान के मजदूरों के वास्ते ब्रिटेन का सारा मजदूर-संगठन लड़ाई लड़ने को तैयार होगया, और एक 'युद्ध-समिति' बन गई । इससे पहले तीन बड़े-बड़े मजदूर-संघों—खान मजदूरों, रेलवे मजदूरों और ट्रान्सपोर्ट मजदूरों—के बीच एक मजबूत त्रिगुट या संगठन बना था, जिसमें कि कई लाख सुसंगठित और सीखे हुए मजदूर शामिल थे । मजदूरों के इस तेज़ रुख़ से सरकार डर-सी गई, और उसने खान-मालिकों को धन की मदद देकर उस संकट को आगे के लिए टाल दिया । यह मदद इसलिए दी गई कि वे एक साल तक पुराने दर से मजदूरों को मजदूरी दे सकें । एक जाँच-कमीशन भी मुकर्रर किया गया । लेकिन इस सारी कार्रवाई का भी कोई नतीजा न निकला, और दूसरे साल १९२६ में जब मालिकों ने फिर मजदूरी घटानी चाही तो संकट-काल आ खड़ा हुआ । इस बार सरकार मजदूरों से लड़ने को तैयार थी; क्योंकि उसने पिछले महीनों में इसके लिए हर तरह की तैयारी करली थी ।

कोयले की खानों के मालिकों ने मजदूरों के लिए काम बन्द कर देने का निश्चय किया, क्योंकि मजदूरों ने मजदूरी में कमी करना मंजूर नहीं किया । इससे इंग्लैण्ड में फ़ौरन एक आम हड़ताल होगई, जो कि ट्रेड-यूनियन कांग्रेस की तरफ़ से की गई थी । ट्रेड-यूनियन कांग्रेस की इस आज्ञा का ख़ूब अच्छी तरह पालन किया गया, और देशभर के तमाम संगठित मजदूरों ने काम बन्द कर दिया । देश का करीब-करीब सब काम-काज बन्द होगया । रेलें नहीं चलती थीं, अख़बार नहीं छपते थे, और बहुत-से दूसरे कार्य बन्द होगये । सरकार ने स्वयंसेवकों की मदद से कुछ जरूरी कारोबार जारी रखे । आम हड़ताल ठीक आधी रात यानी ३-४ मई १९२६ को शुरू हुई । दस दिन के बाद ट्रेड-यूनियन कांग्रेस के नरम नेताओं ने, जिन्हें इस तरह की क्रान्तिकारी हड़ताल से कोई मुहब्बत न थी, इस वहाने पर अचानक उसे बन्द करवा दिया कि उनसे कोई अनिश्चित-सा वादा कर दिया गया है । खानों के मजदूर मुसीबत में अकेले रह गये, लेकिन फिर भी, उगमगाते हुए भी वे कई महीनों तक अपनी लड़ाई लड़ते रहे । भूख से मजबूर किये जाकर आख़िर वे हरा दिये गये । यह एक महत्वपूर्ण हार थी—न सिर्फ़ खान-मजदूरों के लिए, बल्कि आम तौर पर सभी ब्रिटिश मजदूरों के लिए । कई जगहों पर मजदूरियाँ घटाई गई, कुछ उद्योगों में काम के

न्यूयार्क आजाता, और ऐसा होने पर क़र्ज़ा चाहनेवाले लोग लन्दन के बजाय न्यूयार्क ही जाते। दूसरा रास्ता यह था कि जोर लगाकर पाउण्ड को ही उसकी पहली क़ीमत पर पहुँचा दिया जाता। इससे पाउण्ड की इज्जत भी बढ़ जाती और लन्दन दुनिया का आर्थिक नेता भी बना रहता। लेकिन उद्योग-धन्धों को नुक़सान होता और, ज़ैसा कि हुआ, और भी कई अवाञ्छनीय बातें होतीं।

ब्रिटिश सरकार ने १९२५ में दूसरा मार्ग ही पसन्द किया, और पाउण्ड को बढ़ाकर उसकी पहली क़ीमत पर कर दिया। इस तरह उसने किसी हद तक अपने उद्योग-धन्धों को अपने बँकरो के लिए क़ुर्बान कर दिया। असली सवाल उसके सामने और भी बड़ा था, क्योंकि उससे उसके साम्राज्य के जारी रहने पर ख़ास असर पड़ता था। अगर लन्दन दुनिया के आर्थिक नेतृत्व को खो देता है, तो साम्राज्य के मुत्तलिफ़ हिस्से फिर उसके नेतृत्व या मदद की इवाहिश न करेंगे, और धीरे-धीरे साम्राज्य टुकड़े-टुकड़े और तबाह होजायगा। इसलिए यह सवाल साम्राज्य की नीति का, सवाल बन गया, और ब्रिटेन के कारख़ानों और उस वक़्त के अन्दरूनी हितों की क़ुर्बानी करके भी इस व्यापक साम्राज्यवाद की ही जीत हुई। तुम्हें याद होगा कि इसी तरह साम्राज्य-सम्बन्धी कारणों से ही महायुद्ध के बाद लंकाशायर और ब्रिटिश कारख़ानों को कुछ नुक़सान पहुँचाकर भी ब्रिटेन ने हिन्दुस्तान में बड़े-बड़े कल-कारख़ानों और उद्योग-धन्धों को बढ़ाने का विचार किया था।

इस तरह ब्रिटेन ने अपना नेतृत्व और साम्राज्य बनाये रखने के लिए एक ज़बरदस्त कोशिश की, लेकिन यह कोशिश बड़ी महँगी पड़ी और उसका नाकामयाब होना लाज़िमी था। ब्रिटिश सरकार या कोई भी दूसरी सरकार आर्थिक व्यवस्था की अनिवार्य भावी घटनाओं पर क़ाबू नहीं रख सकती थी। अतः कुछ वक़्त के लिए तो पाउण्ड ने अपना पुराना दवदबा फिर हासिल कर लिया, लेकिन इससे उद्योग-धन्धे धीरे-धीरे बिगड़ने लगे। बेकारी बढ़ने लगी, और ख़ासकर कोयले के धन्धे में तो बड़ी कठिनाई आई। इसकी ख़ास वजह थी पौण्ड का डिफ़्लेशन (जोकि उसका स्वर्ण-मूल्य बढ़ाने का नाम था)। कुछ दूसरे कारण भी थे। मुआवज़े की अदायगी में जर्मनी का कुछ कोयला भी ले लिया गया था, और इसका मतलब यह था कि ब्रिटेन के कोयले की ज़रूरत कम होगई, जिसका नतीजा यह हुआ कि कोयले की खानों में ज्यादा बेकारी होगई। इस तरह ऋणदाता और विजयी देशों ने भी महसूस कर लिया कि हारे हुए देश से इस तरह का ख़िराज हासिल करना भी कोई बिल्कुल सुख-ही-मुख की बात नहीं है। ब्रिटेन के कोयले के उद्योग की व्यवस्था भी बहुत ख़राब थी। यह उद्योग सैकड़ों छोटी-छोटी कम्पनियों में बँटा हुआ था, और योरप

अब ख़त्म ही होना चाहता है, दोष है। वे रूस की मिसाल देकर कहा करते थे कि हालाँकि वहाँ बहुत-सी दूसरी गड़बड़ी और तकलीफ़ें हैं, लेकिन बेकारी नहीं है।

ये सवाल कुछ पेचीदा हैं, और इन इनसानी मुसीबतों की दवा क्या है, इस बात डाक्टरों और पण्डितों की भी जुदा-जुदा रायें हैं। फिर भी हम उनपर ग़ौर तो करेंगे ही और उनकी कुछ खास विशेषताओं की जाँच भी करेंगे।

आजकल की सारी दुनिया एक ही सम्पूर्ण इकाई बनती जा रही है, और बहुत हद तक बन भी चुकी है। इसका मतलब यह है कि जीवन, प्रवृत्तियाँ, उत्पत्ति, विभाजन, ख़पत वग़ैरा सभी अन्तर्राष्ट्रीय और संसार-व्यापी बन रहे हैं और यह प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। व्यापार, उद्योग-धंधे, मुद्रा-प्रणाली भी ज्यादातर अन्तर्राष्ट्रीय हो रही हैं। मुस्लिम मुल्कों में गहरे नज़दीकी ताल्लुकात हैं, वे एक-दूसरे पर निर्भर हैं, और एक देश की घटना का दूसरे देश पर असर पड़ता है। इस सारी अन्तर्राष्ट्रीयता के होते हुए भी, सरकारें और उनकी नीतियाँ अब भी संकुचित रूप से राष्ट्रीय ही हैं। वल्कि महायुद्ध के बाद के वर्षों में यह संकुचित राष्ट्रीयता और भी ख़राब और उग्र होगई है, और वही आज दुनिया में सबसे ज़बरदस्त चीज़ बन गई है। नतीजा यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं और सरकारों की राष्ट्रीय नीतियों के बीच संघर्ष चलता रहता है। संसार की अन्तर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियों को तुम एक ऐसी नदी मान लो, जो समुद्र की तरफ़ बहती हुई जा रही है, और राष्ट्रीय नीतियाँ मानों उस नदी को रोकने, बाँधने, दिशा बदलने और उलटा बहाने तक की कोशिशों के समान हैं। जाहिर है कि नदी उलटी नहीं बहाई जा सकती, और न रुक ही सकती है। लेकिन मुमकिन है कि कहीं-कहीं उसके रुक में थोड़ी-सी तब्दीली हो सके, या बाँध भर जाय और उसके ऊपर से पानी बहने लगे। इस तरह आजकल की यह राष्ट्रीयता नदी के नियमित बहाव में बाधा डाल रही है, और कहीं बाढ़ें पैदा कर रही है, कहीं नदी-प्रवाह से झीलें बना रही हैं, और कहीं सड़नेवाली तलैयाँ पैदा कर रही हैं, लेकिन वह नदी की आखिरी मंजिल को कभी रोक न सकेगी।

इस तरह व्यापार और आर्थिक क्षेत्र में 'आर्थिक राष्ट्रीयता' कही जानेवाली चीज़ पैदा होगई है। इसका मतलब यह है कि हरेक देश को जितना माल वह ख़रीदे उससे ज्यादा बेचना चाहिए, और जितना माल वह ख़ुद खपा सके उससे ज्यादा पैदा करना चाहिए। हरेक मुल्क अपना माल बेचना चाहता है, लेकिन ख़रीदेगा कौन ? बिक्री के लिए ज़रूरी है कि एक बेचनेवाला हो और एक ख़रीदनेवाला हो। ऐसी दुनिया हो ही नहीं सकती जिसमें सिर्फ़ बेचनेवाले ही हों। लेकिन आर्थिक राष्ट्रीयता का आधार यही है। हर मुल्क आयात-निर्यात करों की दीवारें यानी आर्थिक बाधाएँ खड़ी करता है, जिससे

घण्टे बढ़ाये गये, और मजदूरों की रहन-सहन का दर्जा नीचे गिर गया। सरकार ने अपनी जीत का फायदा उठाया, और मजदूरों को कमजोर करने के लिए और खास-कर भविष्य में कोई भी आम हड़ताल न होने देने के लिए नये क़ानून बना दिये। १९२६ की यह आम हड़ताल इसलिए नाकामयाब हुई कि मजदूरों के नेताओं में अनिश्चितता और कमजोरी थी, और वे उसके लिए तैयार न थे। असल में उनका सारा मक़सद उसको टालना ही था, और जब वे ऐसा न कर सके तो उन्होंने पहला मौक़ा हाथ आते ही उसे ख़त्म कर दिया। दूसरी तरफ़ सरकार पूरी तरह तैयार थी और उसे मध्यम वर्गों का सहयोग भी प्राप्त हुआ।

इंग्लैण्ड की आम हड़ताल और कोयले के उद्योगों की लम्बी काम-बन्दी से सोवियट रूस में बड़ी दिलचस्पी पैदा होगई थी, और रूस की ट्रेड-यूनियनों ने बहुत बड़ी-बड़ी रक़मों, जो कि रूस के मजदूरों ने चन्दा करके इकट्ठा की थीं, इंग्लैण्ड के ख़ान-मजदूरों की मदद के लिए भेजीं।

उस वक़्त के लिए तो इंग्लैण्ड में मजदूर दवा दिये गये, लेकिन किसी उद्योग की गिरावट और बेकारी की बढ़ती का यह कोई हल न था। बेकारी से मजदूरों में आम तौर पर मुसीबत आई; इससे राज्य पर भी एक बड़ा बोझ होगया, क्योंकि कई देशों में बेकारी का बीमा करने का एक तरीक़ा पैदा हो चुका था। यह मान लिया गया था कि राज्य का फ़र्ज़ है कि वह ऐसे मजदूरों का भरण-पोषण करे जो वग़ैर अपने किसी कसूर के बेकार हों। सरकार के पास नाम दर्ज करानेवाले ऐसे बेकारों को कुछ मदद दी जाती थी, जिसे 'डोल' कहते थे। इस कारण सरकार और स्थानीय संस्थाओं को बड़ी-बड़ी रक़मों खर्च करनी पड़ती थीं।

यह सब क्यों हो रहा था? उद्योग-धंधे क्यों गिरते जा रहे थे? व्यापार क्यों कम हो रहा था? बेकारी क्यों बढ़ रही थी? सिर्फ़ इंग्लैण्ड में ही नहीं बल्कि क़रीब-क़रीब सभी मुल्कों में हालत क्यों ख़राब होती जा रही थी? राजनीतिज्ञ और शासक लोगों ने हालत सुधारने की जाहिरा ख़ूब इच्छा की, कांग्रेस पर कांग्रेस की गई, लेकिन उन्हें कोई कामयाबी न मिली। यह बात नहीं थी कि भूकम्प या बाढ़ या अनावृष्टि जैसी कोई कुदरती मुसीबत आगई हो, जिससे कि अकाल और तकलीफ़ें पैदा होगई हों। दुनिया बहुत-कुछ पहले की ही तरह चल रही थी। असल में भोजन और कारख़ाने और हर तरह के ज़रूरी पदार्थ पहले से मित्रदार और तादाद में ज़्यादा ही होगये थे, फिर भी मानव जाति के कष्ट बढ़ गये। जाहिर था कि कोई-न-कोई बुनियादी ख़राबी होगई है, जिससे कि यह उलटा नतीजा निकला। समाज में कहीं-न-कहीं भयंकर कुप्रबन्ध मौजूद था। समाजवादियों और साम्यवादियों ने बताया कि यह सब पूंजीवाद का ही, जो कि

उनका नुकसान होता है। यह भी इस बात की एक वजह है कि क्यों आयात-निर्यात कर एकबार शुरू होजाने पर बने ही रहते हैं, और क्यों आर्थिक राष्ट्रीयता दुनिया में चल रही है, हालांकि ज्यादातर लोग मान चुके हैं कि इससे सबका नुकसान है। स्थापित स्वार्थों के एक बार पैदा होजाने पर उनका ख़ात्मा करना आसान नहीं है, और किसी अकेले राष्ट्र का ऐसे मामले में आगे बढ़ना तो और भी कम आसान है। अगर सभी देश एकसाथ मिलकर आयात-निर्यात करों को ख़त्म कर दें या बहुत हद तक घटा दें, तो शायद ऐसा हो भी सके। इसमें भी कठिनाइयाँ होंगी। ऐसा करने से औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए देशों को नुकसान पहुँचेगा, क्योंकि वे उन्नत देशों का बराबरी के आधार पर मुक़ाबिला नहीं कर सकेंगे। नये उद्योग-धंधे तो अक्सर संरक्षणात्मक कर के साथे में ही खड़े होते हैं।

आर्थिक राष्ट्रीयता से राष्ट्रों में आपसी व्यापार कम होता है और रुकता है। इस तरह संसार-व्यापी बाज़ार के खुलने में हानि होती है। हर राष्ट्र एकाधिकार का क्षेत्र बन जाता है, और उसका बाज़ार संरक्षित होजाता है; यानी खुला बाज़ार नहीं रह पाता। हर राष्ट्र के अन्दर भी एकाधिकार (मोनोपली) बढ़ जाते हैं, और खुला और उन्मुक्त बाज़ार घायब होने लगता है। बड़े-बड़े ट्रस्ट (व्यापारियों के समूह), बड़ी-बड़ी दूकानें और बड़े-बड़े कारख़ाने छोटे उत्पादकों और दूकानदारों को निगल जाते हैं, और इस तरह प्रतियोगिता को ही ख़त्म कर देते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान और दूसरे औद्योगिक देशों में ये राष्ट्रीय एकाधिकार रखनेवाले ट्रस्ट या कम्पनियाँ भयंकर गति से बढ़ गई हैं, और इस तरह ताक़त थोड़े-से ही लोगों के हाथों में जमा होगई है। पेट्रोल, साबुन, रासायनिक चीज़ें, शस्त्रास्त्र, लोहा, बैंकिंग, और दूसरी भी अनेक वस्तुओं में एकाधिकार क़ायम होगये हैं। इस सबका एक अजीब नतीजा होता है। वह विज्ञान की तरक्की और पूंजीवाद की बढ़ती का अनिवार्य यानी कुदरती नतीजा है, लेकिन वह इस पूंजीवाद की जड़ को ही काटता है। क्योंकि पूंजीवाद संसार-व्यापी बाज़ार और खुले बाज़ार के साथ ही शुरू हुआ था। प्रतियोगिता ही पूंजीवाद की जान थी। अगर संसार-व्यापी बाज़ार मिट जाता है और राष्ट्रीय सीमाओं के अन्दर भी खुले बाज़ार की प्रतियोगिता मिट जाती है तो समाज के इस पुराने पूंजीवादी ढाँचे की बुनियाद ही हट जाती है। यह तो दूसरी बात है कि अब इसकी जगह पर कौन-सी समाज-व्यवस्था आयगी, लेकिन मालूम होता है कि पुरानी समाज-व्यवस्था इन एक-दूसरे की विरोधी प्रवृत्तियों को रखती हुई ज्यादा दिन चल नहीं सकती।

विज्ञान और औद्योगिक प्रगति मौजूदा सामाजिक प्रणाली से बहुत आगे पहुँच चुकी है। वे भोजन और ज़िन्दगी की अच्छी चीज़ें बहुत ज्यादा पैदा करती हैं और

विदेशी माल न आसके, और साथ ही वह अपना विदेशी व्यापार भी बढ़ाना चाहता है। आयात-निर्यात कर की ये दीवारें अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को, जिसके आधार पर आजकल की दुनिया बनी है, रोकती हैं और मार देती हैं। जैसे-जैसे व्यापार कम होता जाता है, उद्योग-धंधों को नुकसान होता है और बेकारी बढ़ती है। इसका नतीजा यह होता है कि विदेशी माल को, जिससे स्वदेश के उद्योग-धंधों में रुकावट पड़ने का खयाल किया जाता है, रोकने के लिए और भी ज़बरदस्त कोशिश की जाती है, और आयात-निर्यात करों की दीवारें और भी ऊँची कर दी जाती हैं। इससे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को और ज्यादा नुकसान पहुँचता है और यह दुःखदाई चक्कर चलता रहता है।

आजकल की औद्योगिक दुनिया असल में राष्ट्रीयता के दर्जे से आगे बढ़ चुकी है। माल की उत्पत्ति और विभाजन की सारी प्रणाली सरकारों और देशों के राष्ट्रीय ढाँचों के साथ मेल नहीं खाती। भीतरी वस्तु अब अपने ऊपरी छिलके से ज्यादा बढ़ने लगी है, और छिलका तड़कने लगा है।

इन आयात-निर्यात करों और व्यापारिक बाधाओं से हर देश के सिर्फ कुछ वर्गों को ही असल में फ़ायदा पहुँचता है, लेकिन चूँकि ये वर्ग ही अपने-अपने देशों पर हावी हैं इसलिए वे ही देश की नीति को बनाया-बिगाड़ा करते हैं। इसलिए हर देश दूसरे देशों से बढ़ने की कोशिश करता है, और नतीजा यह होता है कि सभीको नुकसान पहुँचता है, और राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धायें और घृणायें यानी क्रौमी लाग-डॉट और नफ़रत बढ़ती जाती हैं। आपसी मतभेदों को काफ़्रोंसें करके मिटाने की बार-बार कोशिशें की जाती हैं, और जुदा-जुदा देशों के प्रतिनिधि ऊँची-से-ऊँची सद्विच्छा प्रकट करते हैं, लेकिन कामयाबी उनके पास तक भी नहीं फटकती। क्या इससे तुम्हें हिन्दुस्तान के साम्प्रदायिक सवाल यानी हिन्दू-मुस्लिम-सिख समस्याओं को हल करने की कोशिशों की याद नहीं आती? शायद दोनों ही मामलों में नाकामयाबी का कारण यह है कि धारणायें ग़लत बनावली गई हैं, हेतु ग़लत समझे गये हैं, और साथ ही उद्देश्य भी ग़लत रखे जाते हैं।

जो वर्ग इन आयात-निर्यात करों से और आर्थिक राष्ट्रीयता को बढ़ानेवाले दूसरे तरीक़ों से—मसलन राज्य की तरफ़ से विशेष आर्थिक सहायता, रेल-किराये की खास दरों वगैरा से—फ़ायदा उठाते हैं वे मिलिक्यतदार और कारख़ानेदार वर्ग ही हैं, जिन्हें कि संरक्षण-प्राप्त स्वदेशी बाज़ारों से लाभ होता है। इस तरह संरक्षण और आयात-निर्यात करों के साये में स्थापित स्वार्थ निर्मित होजाते हैं, और सभी स्थापित स्वार्थों की तरह वे भी बड़े जोर के साथ हर ऐसी तब्दीली की मुज़ाहिदा करते हैं जिसे

दिखलाकर कि अदृष्ट शक्तियों से उनका सम्बन्ध है, अपनी इच्छा के मुताबिक अज्ञान जनता को चलाया करते थे। आजकल धर्माधीशों की ताकत बहुत कम होगई है, और औद्योगिक देशों में तो करोड़-करोड़ बिलकुल ही नहीं रही। धर्माधीशों की जगह अब विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री और बैंकर और ऐसे ही दूसरे लोग पैदा होगये हैं, जो गूढ़ भाषा में, जिसमें ज्यादातर शब्द पारिभाषिक होते हैं, बात करते हैं, जिसे मामूली लोगों का समझना मुश्किल होता है। इस तरह औसत आदमी को इन सवालों को तय करने का काम इन विशेषज्ञों पर छोड़ देना पड़ता है। लेकिन विशेषज्ञ लोग, जान में या अनजान में, शासकवर्गों के ही साथ जुड़ जाते हैं, और उनके ही हितों को फायदा पहुँचाते हैं। फिर विशेषज्ञों में मतभेद भी होता है।

इसलिए यह अच्छा है कि हम सब इन आर्थिक सवालों को, जो आजकल राजनीति और दूसरी भी सारी बातों पर हावी मालूम होते हैं, कुछ-कुछ समझ लेने की कोशिश करें। इन्सान को कई तरह से वर्गों और श्रेणियों में बाँटा जा सकता है। एक बँटवारा इस तरह भी हो सकता है कि इन्सान दो श्रेणी के हैं : एक तो जमाने की लहर के साथ बहनेवाले, जिनकी अपनी कोई इच्छा-शक्ति नहीं होती और जो पानी की सतह पर पड़े हुए तिनके की तरह अपनेआपको इधर-उधर बह जाने देते हैं, और दूसरे वे लोग जो जिन्दगी में जोरदार अभिनय करते हैं और परिस्थिति पर असर डालते हैं। दूसरे वर्ग के लोगों के लिए ज्ञान और समझ जरूरी है; क्योंकि कोई भी कारगर काम इनके आधार पर ही हो सकता है। सिर्फ़ सद्भावना या सविच्छाओं से ही काम नहीं चल सकता। जब कभी कोई क्रुदरती मुसीबत या महामारी या सूखा पड़ जाता है या और कोई भी कष्ट आजाता है तो सिर्फ़ हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि योरप में भी अक्सर देखा जाता है कि लोग कष्ट दूर करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। अगर ईश्वर की प्रार्थना से उनकी आत्मा को तसल्ली मिलती है और विद्वान्त और हिम्मत पैदा होती है तो वह अच्छी चीज़ है और उसपर किसीको एतराज करने की जरूरत नहीं। लेकिन प्रार्थना से महामारी मिट जायगी, इस ख्याल के बदले अब यह वैज्ञानिक विचार पैदा होता जा रहा है कि बीमारियों के मूल कारणों को सफ़ाई और दूसरे तरीकों से दूर करना चाहिए। अगर कारखाने की मशीनों में कोई टूट-फूट होजाय, या गाड़ी के टायर में सूराख होजाय, तो ऐसा नहीं देखा जायगा कि लोग बैठे रहें या प्रार्थना करते रहें और सिर्फ़ आशा, सदिच्छा या प्रार्थना करते रहें, कि वह टूट-फूट अपने-आप दुरुस्त हो जाय, या सूराख खुद जुड़ जाय। वे काम करना और मशीन और टायर को सुधारना शुरू कर देते हैं, और फ़ौरन ही मशीन फिर चलने लगती है और गाड़ी सड़क पर दौड़ने लगती है।

पूँजीवाद यह नहीं जानता कि इन चीजों का क्या उपयोग किया जाय ! बल्कि वह अक्सर इन चीजों को बर्बाद करने या उनकी उत्पत्ति कम करने लगता है । और इस तरह हम यह असाधारण दृश्य देखते हैं कि प्रचुरता और दरिद्रता यानी खुशहाली और गरीबी साथ-ही-साथ मौजूद हैं । अगर आधुनिक विज्ञान और उत्पत्ति के साधनों के लायक यह पूँजीवाद नहीं है, तो कोई दूसरा तरीका ढूँढ़ना होगा जो विज्ञान के ज्यादा अनुकूल हो । वरना, दूसरा रास्ता यह है कि विज्ञान का ही गला घोट दिया जाय और उसे आगे बढ़ने से रोक दिया जाय । लेकिन ऐसा करना तो बेवकूफी होगी, और, कुछ भी हो, उसका तो खयाल करना ही मुश्किल है ।

जब आर्थिक राष्ट्रीयता मौजूद है, जब एकाधिकारों और क्रांती लागू-डांट की बढ़ती हो रही है, और जब दम तोड़ते हुए पूँजीवाद के दूसरे दोष मौजूद हैं, तो सारी दुनिया में गड़बड़ी मची हो तो इसमें ताज्जुब की बात कौन-सी है ? आजकल का साम्राज्यवाद खुद भी इस पूँजीवाद का एक रूप है, क्योंकि हर साम्राज्यवादी ताकत दूसरी जातियों का खून चूसकर अपने क्रांती सवालों को हल करना चाहती है । इससे फिर साम्राज्यवादी ताकतों में लागू-डांट और कशमकश पैदा होती है । आजकल इस उलटी दुनिया में हर बात का नतीजा संघर्ष ही होता है !

मैंने तुम्हें यह बताते हुए इस खत को शुरू किया था कि महायुद्ध के बाद मुद्रा-प्रणाली में अजीब गड़बड़ी पैदा होगई थी । क्या हम मुद्रा-प्रणाली को दोष दे सकते हैं, जबकि और भी तमाम बातों में बेहद गड़बड़ी हो गई है ?

: १७४ :

दाँव और घात

१८ जून, १९३३

मेरे पिछले दो खत आर्थिक और मुद्रा-सम्बन्धी सवालों की बाबत थे । ये विषय बड़े रहस्यपूर्ण यानी भेद से भरे हुए और समझने में कठिन माने जाते हैं । यह तो सच है कि वे आसान नहीं हैं, और उनपर बहुत ज्यादा गौर करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन फिर भी वे बहुत भयंकर नहीं हैं और उन विषयों की बाबत रहस्यपूर्णता का वातावरण बन जाने के लिए कुछ हदतक अर्थशास्त्री और विशेषज्ञ लोग भी जिम्मेदार हैं । पुराने जमाने में रहस्यपूर्ण बातों का ठेका धर्माधीशों के पास रहता था, और वे तरह-तरह के क्रायदों और रस्म-रिवाजों के जरिये, जो अक्सर किसी ऐसी पुरानी ज़बान में पूरी की जाती थीं जिन्हें कोई नहीं समझता था, और यह

ज्यादा नज़र आता था, और फ़्रांस विजय की भावना को खास तौर पर जाहिर करता था। कुदरती तौर पर हारे हुए मुल्क सुलहनामों की कई शर्तों से असन्तुष्ट थे, और हालाँकि वे कुछ नहीं कर सकते थे फिर भी भविष्य में तब्दीली के सपने देखा करते थे। आस्ट्रिया और हंगरी बड़ी मुसीबत में थे; उनकी हालत और भी बिगड़ती हुई मालूम होती थी। दूसरी तरफ़, युगोस्लेविया सर्बिया का ही बढ़ा हुआ रूप था, और वह कई बेमेल वर्गों और जातियों का एक समूह बन गया था। उसके मुख्तलिफ़ हिस्सों को एक-दूसरे से ऊब उठने और आपस में जुदा हो जाने की प्रवृत्ति से भर जाने में ज्यादा वक़्त न लगा। खासकर क्रोशिया में (जो अब युगोस्लेविया का एक सूबा है) आजादी का एक जोरदार आन्दोलन चल रहा है, और इसे सर्बियन सरकार ने जोर-जबरदस्ती से दबाने की कोशिश की है। पोलैण्ड नक़शे पर अब काफ़ी बड़ा होगया है, लेकिन उसके साम्राज्यवादी लोग दक्षिण में काले समुद्र तक फैल जाने के और इस तरह सन् १७७२ की पुरानी पोलिश सरहद फिर से क़ायम करने के ग़ैरमामूली सपने देखते हैं। आजकल तो पोलैण्ड में रूसी यूक्रेन का एक हिस्सा भी शामिल है। इसे तरह-तरह के जुल्म, मौत की सज़ाओं, और बर्बरतापूर्ण दमन के आतंक से 'शान्त करने' या 'पोलिश बनाने' की कोशिश कीगई है, और अब भी की जा रही है। ये आग के कुछ छोटे-छोटे-से ढेर हैं जो पूर्वीय योरप में सुलग रहे हैं। इनका महत्व इस कारण है कि इस आग के ज्यादा बढ़ जाने का अन्देश है।

राजनैतिक रूप में, और उपयोगिता की दृष्टि से भी, महायुद्ध के बाद के ज़माने में योरप में फ़्रांस ही प्रमुख राष्ट्र होगया था। वह जो कुछ चाहता था, प्रदेश या राज्य के रूप में और मुआवज़े के इकरार की शक़ल में उसे ज्यादातर मिल गया था, लेकिन फिर भी वह सुखी न था। एक बड़ी दहशत हमेशा उसके सिर पर सवार थी, कि कहीं जर्मनी फिर उससे लड़ने लायक़ मज़बूत न बन जाय, और कहीं उसे हरा न दे। इस दहशत का खास सबब यह था कि जर्मनी की आबादी उससे बहुत ज्यादा थी। फ़्रांस का मुल्क असल में जर्मनी से बड़ा है, और शायद उपजाऊ भी ज्यादा है। फिर भी फ़्रान्स की आबादी ४१० लाख से कम है, और स्थायी-सी है। लेकिन जर्मनी की आबादी ६२० लाख से ज्यादा है, और बढ़ती जा रही है। जर्मन लोग हमलावर और लड़ाकू भी मशहूर हैं और इसी पीढ़ी के सामने वे दो बार फ़्रांस पर हमला भी कर चुके हैं।

इसलिए फ़्रांस पर जर्मनी द्वारा बदला लिये जाने का भय हमेशा सवार रहा, और उसकी सारी नीति की बुनियाद और खास उसूल 'सुरक्षितता' यानी उसने जो कुछ हासिल कर लिया है उसे बनाये और बचाये रखने की सुरक्षितता ही रहा है।

इसी तरह मानवीय और सामाजिक मशीन में भी सदिच्छा के अलावा हमें उसकी अच्छी वाक्फ़ियत और उसकी ताक़तों का ज्ञान होना चाहिए। यह ज्ञान निश्चित तो प्रायः नहीं होता, क्योंकि उसका ताल्लुक मनुष्य की इच्छाओं, आकांक्षाओं, रुचि-अरुचियों और आवश्यकताओं-जैसी अनिश्चित चीज़ों से होता है, और जब आम लोगों या तमाम समाज या मुहल्लतल्लिफ़ वर्गों के मनुष्यों का हम विचार करते हैं तो ये चीज़ें और अनिश्चित होजाती हैं। लेकिन अध्ययन और अनुभव और निरीक्षण से इस अनिश्चित गिरोह या जमघट में भी धीरे-धीरे व्यवस्था आने लगती है, और ज्ञान बढ़ता है, और उसके साथ अपनी परिस्थिति को बनाने या सम्हालने की हमारी योग्यता भी बढ़ती है।

अब मैं महायुद्ध के बाद के इन वर्षों में योरप के राजनैतिक पहलू के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। पहली बात, जो खास तौर पर दिखाई देती है, यह है कि महाद्वीप यानी योरप इन तीन हिस्सों में बँट गया था—महायुद्ध में जीतनेवाले राष्ट्र, महायुद्ध में हारनेवाले राष्ट्र, और सोवियट रूस। नार्वे, स्वीडन, हालैण्ड और स्वीज़रलैण्ड-जैसे भी कुछ छोटे-छोटे देश थे जो इन तीनों हिस्सों में से किसीमें भी न आते थे, लेकिन बृहत्तर राजनैतिक दृष्टिकोण से उनका कोई खास महत्त्व नहीं था। हाँ, सोवियट रूस श्रमिकों की सरकार बनाकर अकेला अलग ही था, और विजयी शक्तियों को हमेशा खटकता रहता था। यह खटक सिर्फ़ इसलिए नहीं थी कि उसकी शासन-प्रणाली ऐसी थी जिससे कि दूसरे देशों के श्रमिकों को क्रान्ति की प्रेरणा मिलती थी, बल्कि इसलिए भी थी कि वह विजयी शक्तियों की पूर्व-देशीय योजनाओं में अडंगा डालता था। मैंने तुम्हें रूस में विदेशी ताक़तों की लड़ाइयों का हाल पहले बताया है, जिनमें कि सन् १९१९ और १९२० में इन विजयी राष्ट्रों में से ज्यादातर राष्ट्रों ने सोवियट शासन को कुचल डालने की कोशिश की थी। फिर भी सोवियट रूस तो ज़िन्दा ही रहा, और योरप की साम्राज्यवादी ताक़तों को उसकी हस्ती बर्दाश्त करनी पड़ी, लेकिन यह भी किया उन्होंने कम-से-कम सदिच्छा या गौरव के साथ ही। खासकर इंग्लैण्ड और रूस की पुरानी लाग-डांट, जोकि ज़ारशाही ज़माने से चली आ रही थी, फिर भी जारी रही, और उससे कई बार ऐसी सनसनी, अन्देशे और वाक्आत पैदा होजाते थे, जिनसे लड़ाई छिड़ जाने का डर होजाता था। सोवियट-रूस को विश्वास होगया था कि इंग्लैण्ड उसके खिलाफ़ हमेशा साजिश करता रहता है और योरप में सोवियट-विरोधी संगठन खड़ा कर रहा है। कई बार लड़ाई का ख़ौफ़ भी पैदा होजाता था।

पश्चिमी और मध्य योरप में जीते और हारे हुए देशों के बीच का फ़र्क़ बहुत

महायुद्ध के बाद के वर्षों में ब्रिटिश साम्राज्य में उसके छिन्न-भिन्न होने की भी कुछ प्रवृत्तियाँ नज़र आईं। दूसरे ख़तों में भी मैंने इस सवाल के कुछ पहलुओं पर बहस की है। यहाँ मैं सिर्फ़ एक पहलू का ज़िक्र करूँगा। आस्ट्रेलिया और कनाडा दोनों ही अमेरिका के सांस्कृतिक और आर्थिक प्रभाव में अधिक-अधिक आने लगे थे, और इन तीनों देशों में जो एक सामान्य बात थी वह है—जापानियों से, खासकर जापानियों के अपने देश में बसने से, नाराज़ी। आस्ट्रेलिया को तो इससे खास ख़तरा है, क्योंकि उसमें ग़ैर-आबाद जगह बहुत पड़ी है और जापान दूर नहीं है और उसकी आबादी भी बहुत बढ़ती जा रही है। न तो इंग्लैंड के ये दोनों उपनिवेश और न संयुक्तराष्ट्र अमेरिका ही इंग्लैंड की जापान से दोस्ती पसन्द करते थे। इंग्लैंड अमेरिका को खुश रखना चाहता था, क्योंकि ऋणदाता की हैसियत से और दूसरी तरह भी अमेरिका दुनिया में प्रमुख होता जाता था, और साथ ही वह अपना साम्राज्य भी जबतक चल सके तबतक चलाये रखना चाहता था। इसलिए उसने १९२२ में वाशिंगटन कान्फ़रेन्स में जापान की दोस्ती को क्रूरबान कर दिया। मैंने चीन पर जो पिछला ख़त लिखा था उसमें तुम्हें इस कान्फ़्रेस की बाबत लिखा था। वहींपर चार राष्ट्रों का समझौता (Four Power Agreement) और नौ राष्ट्रों की सन्धि (Nine Power Treaty) हुई थी। इन सन्धियों का चीन और पैसिफ़िक समुद्र-तट से ताल्लुक था, लेकिन सोवियट रूस को, जिसका इनसे जीवन-मरण का सम्बन्ध था, उसके विरोध करने पर भी बुलाया नहीं गया।

इस वाशिंगटन कान्फ़रेन्स से इंग्लैंड की पूर्वाय नीति में फ़र्क़ शुरू होता है। अभीतक तो इंग्लैंड 'सुदूर-पूर्व' (Far East) में, और ज़रूरत हो तो हिन्दुस्तान में भी, जापान से मदद लेने का भरोसा रखता था। लेकिन अब दुनिया के मामलों में 'सुदूर-पूर्व' एक बड़ा ज़रूरी हिस्सा बनता जा रहा था, और वहाँ मुसलिम मुल्कों के स्वार्थों में कशमकश भी थी। चीन उठ रहा था, या उठता-सा दिखाई देता था, और जापान और अमेरिका एक-दूसरे के ज्यादा ख़िलाफ़ होते जा रहे थे। कई लोगों का ख़याल था कि अगला महायुद्ध खासकर पैसिफ़िक (प्रशान्त) महासागर में होगा। जापान और अमेरिका दोनों के बीच ये इंग्लैंड अमेरिका के पक्ष में ढल गया, बल्कि यह कहना ज्यादा सही होगा कि उसने जापान का पक्ष छोड़ दिया। उसकी नीति थी वग़ैर निश्चित इक़रार किये हुए ताक़तवर और दौलतमन्द अमेरिका से दोस्ती ज़रूर बनाये रखना। जापानी दोस्ती ख़त्म कर देने के बाद इंग्लैंड ने 'सुदूर-पूर्व' के भावी संभावित युद्ध के लिए तैयारी शुरू कर दी। उसने सिंगापुर में बहुत बड़े और खर्चीले 'डाक' बनवाये, और इस मुक़ाम को जहाज़ी बेड़े का ज़वरदस्त अड्डा बना दिया। इस जगह से

फ्रांस की सैनिक प्रमुखता के ही सब से वे सब देश दबे रहते थे, जो वर्साई की सन्धि से असन्तुष्ट थे, क्योंकि इस सन्धि को बनाये रखना फ्रांस की सुरक्षितता के लिए जरूरी समझा जाता था। अपनी स्थिति को और भी मजबूत करने के लिए फ्रांस ने ऐसे राष्ट्रों का एक गुट बना लिया जो वर्साई-सन्धि को बनाये रखने में दिलचस्पी लेते थे। ये देश थे—बेल्जियम, पोलैण्ड, जेकोस्लोवेकिया, रूमानिया और युगोस्लेविया।

इस तरह फ्रांस ने योरोप में अपना नेतृत्व कायम कर लिया। यह इंग्लैण्ड को पसन्द न आया, क्योंकि इंग्लैण्ड नहीं चाहता कि उसके सिवा कोई दूसरी ताकत योरोप में हावी होजाय। इंग्लैण्ड के दिल में अपने दोस्त फ्रांस के लिए जो मुहब्बत और मित्रता थी उसमें बड़ी कमी आगई; इंग्लैण्ड के अखबारों में फ्रांस को खुदगर्ज और संगदिल कहा जाने लगा, और पुराने दुश्मन जर्मनी के लिए मित्रतापूर्ण शब्द इस्तेमाल किये जाने लगे। इंग्लैण्ड के लोग कहने लगे कि इंसान को पुरानी बातों को भूल जाना और माफ़ कर देना चाहिए, और लड़ाई के दिनों को याद कर शान्ति के दिनों में वर्तव नहीं करना चाहिए। ये फैसी ऊँची भावनाएँ थीं! और अंग्रेजी दृष्टिकोण से तो दोहरी प्रसंसनीय थीं, क्योंकि ये अंग्रेजी नीति से मेल भी खा जाती थीं। एक इटैलियन राजनीतिज्ञ काउण्ट स्फ़ोरजा ने कहा है कि “ब्रिटिश जाति को दयालु ईश्वर ने यह महान् वरदान दे रखा है कि इंग्लैण्ड को जिस बात में कोई राजनैतिक फ़ायदा होता हो, या ब्रिटिश सरकार जो कोई राजनैतिक कार्रवाई करे, उसे सभी वर्ग ऊँचे-से-ऊँचे नैतिक कारणों से उचित सिद्ध करें।”

१९२२ के शुरू से यूरोपियन राजनीति में इंग्लैण्ड और फ्रांस की कशमकश एक स्थायी चीज़ होगई है, और वह तबसे चल ही रही है। जाहिरा तौर पर तो दोनों तरफ़ के लोग आपस में हँसकर मिलते हैं, शिष्टता के शब्द कहते हैं; और उनके राजनीतिज्ञ और प्रधानमन्त्री अवसर मिला करते और साथ-साथ फोटो भी खिचवाते हैं; लेकिन दोनों सरकारें अवसर एक-दूसरे से भिन्न दिशाओं में ही जाती हैं। १९२२ में जब जर्मनी अपनी क्रिस्त की अदायगी न कर सका, तो इंग्लैण्ड 'रूर' प्रदेश पर मित्र-राष्ट्रों के दखल करलेने के हक्क में न था। लेकिन फ्रांस ने इंग्लैण्ड की परवा न करते हुए अपनी मर्जी के मुताबिक़ अमल किया। इंग्लैण्ड ने इसमें कोई हिस्सा न लिया।

एक और पुराना मित्र फ्रांस से अलग होगया, और दोनों देशों में हमेशा कशमकश होने लगी। इसका कारण था १९२२ में मुसोलिनी का सत्ता प्राप्त कर लेना, और उसकी साम्राज्यवादी आकांक्षायें, जिनमें फ्रांस बाधा डालता था। मुसोलिनी और फैसिज्म का हाल में तुम्हें अपने अगले ख़त में बताऊंगा।

मान लेने से इन्कार कर दिया। हाँ, उसने यह वादा किया कि इसको बदलवाने के लिए वह सिर्फ़ शान्तिपूर्ण उपाय ही काम में लायगा। अगर एक भी फ़रीक़ समझौते को भंग करे तो बाक़ी सबने मिलकर उसका मुक़ाबिला करने का इक़रार किया।

लोकानों की सन्धि अंग्रेज़ी नीति की सफलता थी। इस सन्धि से ब्रिटेन किसी हद तक फ़्रांस और जर्मनी के बीच पंच बन गया, और इससे जर्मनी रूस से भी अलग कर लिया गया। लोकानों का खास महत्व इस बात में है कि इसमें पश्चिमी योरप के राष्ट्र एक सोवियट-विरोधी गुट की शक्ल में आगये। इससे रूस भयभीत होगया और कुछ ही महीनों में उसने तुर्की के साथ सन्धि करके इसका जवाब दे दिया। यह रूसी-तुर्की सन्धि दिसम्बर १९२५ में, मोसल के ख़िलाफ़ राष्ट्र-संघ द्वारा फ़ैसला होने के, जो कि तुर्की के ख़िलाफ़ था, ठीक दो दिन बाद ही हुई। सितम्बर १९२६ में (जब कि हम लोग इत्तफ़ाक़ से जेनेवा में थे और तुम इकोल इन्टरनेशनल में अपने छोटे-छोटे पैरों से चलकर पहुँच जाया करती थीं) जर्मनी राष्ट्र-संघ में दाख़िल होगया। लोग आपस में खूब गले मिले, हाथ मिलाये, और राष्ट्र-संघ के सभी लोगों ने प्रसन्नता की मुस्कराहट से एक-दूसरे को बधाई दी।

इस तरह यूरोपियन राष्ट्रों में, जो अक्सर अपनी आन्तरिक नीतियों से प्रभावित रहते थे, एक-दूसरे के ख़िलाफ़ दाँव और घात चलते रहे। इंग्लैण्ड में दिसम्बर १९२३ में आम चुनाव हुआ और उसमें अनुदार दल की हार हुई, और पार्लमेण्ट में मज़दूर दल ने, हालाँकि उसका साफ़ बहुमत न था, पहली बार मन्त्रि-मण्डल बनाया। रैम्जे मैकडानलड प्रधानमन्त्री हुआ। यह सरकार सिर्फ़ साढ़े नौ महीने ही जिन्दा रही। फिर भी इस असें में उसने सोवियट रूस से समझौता कर लिया, और दोनों देशों में राजनैतिक और व्यापारिक ताल्लुकात कायम कर लिये गये। अनुदार लोग सोवियट राज्यों को ज़रा भी मानने के ख़िलाफ़ थे, और ब्रिटेन के अगले आम चुनाव में, जो कि पिछले चुनाव के एक साल के अन्दर हुआ, रूस का बहुत ज़्यादा ज़िक्र आया। इसका कारण यह था कि अनुदार लोगों ने चुनाव में एक खास पत्र को, जो जिनोवीर पत्र के नाम से मशहूर है, अपना खास मोहरा बना लिया था। मैं अब भूल गया हूँ कि इस पत्र में क्या लिखा था, लेकिन स्पष्टतः उसमें कोई साजिश करने की बात सूचित की गई थी, और बताया गया था कि इंग्लैण्ड में खुफ़िया तौर से कुछ कार्रवाइयाँ करनी चाहिए। जिनोवीर सोवियट सरकार का एक प्रमुख बोलशेविक था। उसने उस ख़त से बिलकुल इन्कार किया और कहा कि वह बनावटी होगा। फिर भी अनुदार लोगों ने उस पत्र का पूरा दुरुपयोग किया, और कुछ-कुछ उसकी मदद से ही चुनाव जीत लिया। अब एक अनुदार सरकार कायम हुई और प्रधानमन्त्री स्टैनली बाल्डविन बना। इस सर-

इंग्लैण्ड हिन्द-महासागर और प्रशान्त महासागर के बीच होनेवाले आवागमन पर नियन्त्रण रख सकता है। एक तरफ तो वह हिन्दुस्तान और बरमा पर हावी रह सकता है, और दूसरी तरफ फ्रांस और हालैण्ड के मातहत देशों पर भी हावी हो सकता है; और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह प्रशान्त महासागर के युद्ध में कारगर और जबरदस्त हिस्सा ले सकता है, चाहे वह जापान के खिलाफ हो या और किसी ताकत के खिलाफ हो।

१९२२ में वाशिंगटन में इंग्लैण्ड और जापान का गुट टूट जाने से जापान अकेला रह गया। मजबूरन जापानियों को रूस की तरफ नजर दौड़ानी पड़ी, और वे सोवियट राज्यों से अच्छे ताल्लुकात कायम करने लगे। तीन साल बाद, जनवरी १९२५ में, जापान और सोवियट यूनियन के बीच एक सन्धि होगई।

महायुद्ध के बाद कुछ साल तक जर्मनी के साथ विजयी शक्तियों ने जाति-वहिष्कृत का-सा बर्ताव किया। इन शक्तियों से ज्यादा हमदर्दी न पाकर, और इन्हें कुछ डरा देने की निगाह से, वह सोवियट रूस की तरफ मुड़ा और उससे अप्रैल १९२२ में एक सन्धि—रेपेलो की सन्धि—करली। सन्धि की बातचीत गुप्त रूप से की गई थी, और इसलिए जब सन्धि प्रकाशित की गई तो मित्र-राष्ट्रों को धक्का-सा लगा। तत्सक ब्रिटिश सरकार तो बहुत घबरा गई, क्योंकि इंग्लैण्ड के शासक-वर्ग सोवियट सरकार को बहुत ज्यादा नापसन्द करते थे। दरअसल इसी अनुभव ने कि अगर जर्मनी के साथ अच्छा बर्ताव न किया गया और उसे मनाया न गया तो वह रूस से मिल जायगा, जर्मनी के प्रति अंग्रेजों की नीति में तब्दीली पैदा करदी। वे जर्मनी की तकलीफों को खूब महसूस करने लगे, और उन्होंने कई तरह से गैर-सरकारी तरीके पर जर्मनी को मदद पहुँचाने की इच्छा प्रकट की। वे रूस-प्रदेश की दखलयाबी से भी दूर रहे। यह सब कुछ जर्मनी की मुहब्बत के सबब से नहीं किया गया, बल्कि इस त्वाहिश से किया गया कि जर्मनी रूस से अलग बना रहे, और सोवियट-विरोधी गुट में शामिल रहे। कुछ साल तक अंग्रेजों की नीति की यही कसौटी रही, और १९२५ में लोकानों में उन्हें काम-याबी भी मिल गई। लोकानों में राष्ट्रों की एक कान्फरेन्स की गई, और महायुद्ध के बाद पहली बार विजयी शक्तियों और जर्मनी में कुछ बातों में असली मेल हुआ, जो कि निस्सन्देह एक सुलहनामे की शकल में लिख लिया गया। पूरा मेल तो हुआ ही नहीं था; मुआवजे का जबरदस्त सवाल और दूसरे सवाल बाक़ी ही रहे। लेकिन एक अच्छी शुरुआत होगई थी और कई आपसी आश्वासन और वादे किये गये। जर्मनी ने वर्साई-सन्धि में बताई हुई अपनी पश्चिम की फ्रेंच सीमा को मंजूर कर लिया; लेकिन पूर्वीय सीमा को, और उसके साथ समुद्र से मिले हुए पोलैण्ड के करडोर को, उसने तयशुदा

शक्तियों ने चीन की सरकारों से ऐसी कार्रवाई करवाई, जिससे कि रूस को युद्ध में पड़ना पड़े। लेकिन रूस ने लड़ाई न की। एक महीने बाद, मई १९२७ में, एक और गैरमामूली हमला रूसी व्यापारी कार्यालयों पर किया गया, और इस बार यह लन्दन में हुआ। यह 'आरकस-रेड' कहलाता है, क्योंकि इंग्लैण्ड में रूस की सरकारी व्यापारी कम्पनी का नाम 'आरकस' था। यह भी दूसरे राष्ट्र का एक बड़ा भारी और, जैसा कि घटना से साबित हुआ, एक बिल्कुल अनुचित अपमान था। इसके बाद फौरन ही दोनों देशों में राजनैतिक और व्यापारिक सम्बन्ध टूट गये। इसके अगले माह जून में बारसा में पोलैण्ड में रहनेवाले सोवियट राजदूत का कत्ल कर दिया गया। (चार साल पहले लोसेन में रोम का सोवियट राजदूत मार दिया गया था।) इन सब वाक्यात के एक-के-बाद-एक जल्दी-जल्दी होने से रूस के लोगों को डर हो गया, और उन्हें पूरी उम्मीद होगई कि साम्राज्यवादी राष्ट्र सब मिलकर उनपर हमला करेंगे। रूस में युद्ध का ज़बरदस्त आतंक फैल गया और पश्चिमी योरप के कई देशों में मजदूरों ने रूस के पक्ष में, और नज़र आनेवाले युद्ध के खिलाफ़, प्रदर्शन किये। लेकिन यह डर निकल गया और युद्ध नहीं हुआ।

उसी साल, १९२७ में, रूस ने बड़े पैमाने पर बोलशेविक क्रान्ति का दसवाँ वार्षिकोत्सव मनाया। उस वक़्त इंग्लैण्ड और फ्रांस रूस के बहुत खिलाफ़ थे, लेकिन पूर्वोक्त देशों से रूस की दोस्ती का इजहार इसी बात से होता था कि उस उत्सव में ईरान, तुर्की, अफ़ग़ानिस्तान और मंगोलिया से आये हुए सरकारी प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था।

जब योरप और दूसरे स्थानों पर ये सनसनियाँ और युद्ध की तैयारियाँ चल रही थीं, उसी वक़्त निःशस्त्रीकरण के बारे में बहुत-सी बातचीत भी हो रही थी। राष्ट्र-संघ के कनेनेण्ट (इक्करारनामे) में यह बात लिखी हुई थी कि "इस संघ के मेम्बर मानते हैं कि शान्ति कायम रखने के लिए ज़रूरी है कि अपने-अपने राष्ट्र की सुरक्षितता रखते हुए हरेक राष्ट्र के शस्त्रास्त्रों में ज्यादा-से-ज्यादा कमी की जाय, और अन्तर्राष्ट्रीय कर्तव्यों पर सब एकसाथ मिलकर अमल करें।" इस ऊँचे उद्देश्य को लिख देने के अलावा राष्ट्र-संघ ने उस वक़्त और कुछ नहीं किया, लेकिन उसने अपनी कौंसिल को हिदायत दी कि वह इस मामले में आगे कार्रवाई करे। जर्मनी और दूसरी हारी हुई ताकतें तो संधियों के मुताबिक़ निःशस्त्र कर ही दी गई थीं। जीतने वाले मुल्कों ने वादा किया था कि हम भी इसके बाद अपना निःशस्त्रीकरण कर देंगे, लेकिन बार-बार कान्फ़रेन्स करने के बाद भी कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। यह कोई ताज्ज़ुब की भी बात नहीं थी, क्योंकि हर राष्ट्र ऐसा निःशस्त्रीकरण चाहता था

कार से बार-बार कहा गया कि वह जिनोवीर पत्र की सचाई या झूठ की जाँच कराये; लेकिन उसने ऐसा करने से इन्कार कर दिया। बर्लिन में वाद के रहस्योद्घाटन से मालूम हुआ कि वह एक जाली खत था, जो एक 'सफ़ेद' रूसी व्यक्ति यानी एक बोलशेविक-विरोधी प्रवासी रूसी ने बनाया था। लेकिन इस जालसाजी ने इंग्लैंड में अपना काम पूरा कर दिया, और एक सरकार को हटाकर दूसरी क़ायम कर दी। ऐसी छोटी-छोटी घटनाओं से अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर असर पड़ जाया करता है !

नई अनुदार सरकार ने रूस से फ़ौरन ताल्लुकात नहीं तोड़े। वह उससे जाहिरा तौर पर सम्बन्ध बनाये रही, लेकिन व्यवहार में हमेशा नाराज़गी जाहिर करती और नुक़स निकालती रही और इसमें शक़ नहीं कि अन्दर-ही-अन्दर बहुत-सी साज़िशें भी होती रहीं। जिस उदारता से रूस के मज़दूरों ने १९२६ की ब्रिटिश खान-मज़दूरों की बड़ी लड़ाई में मदद पहुँचाई, उससे तो वाल्डविन की सरकार बहुत ज्यादा खीझ गई। वाद में उसी साल एक नई बातें, जो कि इस बार 'सुदूर पूर्व' में हुई, उसे और भी गुस्सा आया। अचानक चीन में एक मज़बूत संयुक्त राष्ट्रीय सरकार पैदा होगई, और सोवियट सरकार से उसकी बड़ी गहरी दोस्ती मालूम हुई। कई नहीनों तक चीन में अंग्रेज़ बड़ी मुश्किलों में रहे, और उन्हें अपने रीब और दबदबे में होनेवाली कमी को बर्दाश्त करना पड़ा, साथ ही और भी कई ऐसे काम करने पड़े जिन्हें वे नापसन्द करते थे। इसके बाद चीन के आन्दोलन में, कुछ समय की कामयाबी के बाद, फूट पड़ गई और वह टुकड़ों में बँट गया। जनरलों यानी सेनापतियों ने आन्दोलन के उग्र विचार वाले व्यक्तियों का क़त्ले-आम किया या उन्हें निकाल दिया, और शंघाई के विदेशी बैंकरों का सहारा लेना ही ज्यादा पसन्द किया। यह अन्तर्राष्ट्रीय कार्यों में रूस की एक बड़ी हार थी और इससे चीन में तथा दूसरे देशों में रूस की इज्जत बहुत कम होगई। इंग्लैंड के लिए यह एक जीत थी, और उसने सोवियट को हार का और भी अनुभव कराकर इस मौक़े को और भी अच्छा बनाने की कोशिश की। सोवियट-विरोधी गुट फिर संगठित किया गया और रूस को चारों तरफ़ से घेर लेने की कोशिश की गई।

क़रीब १९२७ के बीच में दुनिया के मुहत्तलिफ़ हिस्सों में कई जगह सोवियट के खिलाफ़ कार्रवाई की गई। अप्रैल १९२७ में एक ही दिन पेकिंग के सोवियट राज-दूतावास पर और शंघाई के सोवियट प्रतिनिधि के स्थान पर हमले किये गये। इन प्रदेशों पर चीन की दो जुदा-जुदा सरकारों का नियन्त्रण था, लेकिन इस मामले में दोनों ने एक साथ कार्रवाई की। राजदूतावास पर हमला होना और राजदूत का अपमान होना एक बड़ी ग़ैर-मामूली बात होती है; क़रीब-क़रीब लाज़िमी तौर पर इससे युद्ध छिड़ जाता है। रूस का विश्वास था कि इंग्लैंड और दूसरी सोवियट-विरोधी

शुरू में खयाल यह था कि सिर्फ़ फ़्रांस और अमेरिका के बीच एक इकरारनामा हो-
जाय; लेकिन वह बढ़ गया, और आखिरकार इसमें संसार के क़रीब-क़रीब सभी राष्ट्र
शामिल होगये। अगस्त १९२८ में पेरिस में इस इकरारनामे पर दस्तख़त हुए, इसलिए
यह १९२८ का पेरिस का इकरारनामा, या केलाग-ब्रियाँद इकरारनामा, या सिर्फ़ केलाग
इकरारनामा कहलाता है। केलाग अमेरिका का राजमंत्री (Secretary of State)
था जिसने इस मामले में नेतृत्व किया था, और एरिस्टाइड ब्रियाँद फ़्रांस का परराष्ट्र-
सचिव था। इस इकरारनामे में एक छोटा-सा मजमून था, जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय बहस-
तलब मामलों को हल करने के लिए युद्ध से काम लेने की निन्दा की गई थी और
इकरारनामे पर दस्तख़त करनेवालों ने आपसी बर्ताव में युद्ध की नीति छोड़ देना मंजूर
किया था। ये शब्द, जो क़रीब-क़रीब उस इकरारनामे के ही शब्द हैं, सुनने में बड़े
सुन्दर हैं, और अगर इनको सचाई से लिखा गया होता तो इनसे युद्ध ही ख़त्म हो
सकता था। लेकिन फ़ौरन ही यह जाहिर होगया कि इकरारनामा करनेवाली शक्तियाँ
कितनी झूठी हैं। फ़्रांसीसियों और अंग्रेज़ों ने, और ख़ासकर अंग्रेज़ों ने, दस्तख़त करने
से पहले कई संरक्षण रख लिये, जिससे कि उनके लिए इकरारनामा न होने के बराबर
ही होगया। ब्रिटिश सरकार ने इकरारनामे से उन सब जंगी कार्रवाइयों की छूट
लेली जो उसे साम्राज्य के हित के लिए करनी पड़ेंगी। इसका मतलब यह हुआ कि
वह जब चाहे तब युद्ध कर सकेगी। उसने अपने अधिकार और प्रभाव के क्षेत्रों पर
एक तरह से अंग्रेज़ी 'मनरो-सिद्धान्त' की घोषणा करदी।

जब आम लोगों के सामने युद्ध को 'ग़ैर-क्रान्तूनी' बनाया जा रहा था, उसी वक़्त
१९२८ में इंग्लैण्ड और फ़्रांस के बीच एक गुप्त नौसेना-सम्बन्धी समझौता हुआ। यह
बात किसी तरह जाहिर होगई, और इससे योरप और अमेरिका को बड़ा रंज पहुँचा।
इससे परदे की ओट में होनेवाले मामलों की असली हालत का काफ़ी पता लगता है।

सोवियट यूनियन ने केलाग-इकरारनामे को मंजूर किया, और उसपर दस्तख़त
कर दिये। उसके ऐसा करने का असली सबब यह था कि इस तरह, कुछ हद तक ही
सही, वह इस इकरारनामे की आड़ लेकर सोवियट पर हमला करनेवाले गुट का बनना
रोक देना चाहता था। इकरारनामे में अंग्रेज़ों के संरक्षण ख़ासकर सोवियट के ख़िलाफ़
ही रक्खे हुए मालूम होते हैं। इकरारनामे पर दस्तख़त करते वक़्त रूस ने इंग्लैण्ड और
फ़्रांस के इन संरक्षणों पर ज़बरदस्त एतराज किया।

रूस युद्ध को टालने का इतना इच्छुक था कि उसने अपने पड़ोसियों पोलैण्ड,
रुमानिया, इस्थोनिया, लटविया, तुर्की और ईरान से शान्ति रखने के बारे में एक
ख़ास सुलह करके अपने बचाव की और भी पेशबन्दी करली। इस सुलहनामे पर १९

जिसके हो जाने पर वह दूसरे राष्ट्रों की वनिस्वत जोरदार बना रहे; और इसे कोई भी दूसरा राष्ट्र मंजूर न करता था। फ्रांसीसी हमेशा इस मांग पर अड़े कि निःशस्त्रीकरण से पहले सुरक्षितता होजानी चाहिए।

बड़ी शक्तियों में से न तो अमेरिका और न सोवियट यूनियन ही राष्ट्र-संघ के मेम्बर थे। दरअसल सोवियट यूनियन तो समझता था कि राष्ट्र-संघ एक मुक्काविले का और विरोधी प्रदर्शन है, सोवियट यूनियन के खिलाफ खड़ा किया हुआ पूंजीवादी ताकतों का गिरोह है। सोवियट यूनियन ही खुद एक राष्ट्र-संघ समझा जाता था (जैसा कि ब्रिटिश साम्राज्य को भी बताया जाता है), क्योंकि उसमें भी कई प्रजातंत्र संघ-रूप में शामिल थे। पूर्वोक्त जातियाँ भी राष्ट्र-संघ को सन्देह की निगाह से देखती थीं, और उसे साम्राज्यवादी शक्तियों का एक हथियार मानती थीं। फिर भी अमेरिका, रूस और क़रीब-क़रीब सभी मुल्कों ने राष्ट्र-संघ की कान्फ़रेन्सों में निःशस्त्रीकरण पर विचार करने में हिस्सा लिया। १९२६ में या शायद १९२७ के शुरू में राष्ट्र-संघ ने एक 'प्रिपेयरेटरी कमीशन' मुक़रर किया, जिसका काम था निःशस्त्रीकरण के मामले में एक बड़ा विश्व-सम्मेलन बुलाने के लिए ज़मीन तैयार करना। इस कमीशन ने कितनी ही योजनाओं पर, एक-के-बाद-एक, विचार कर डाला, लेकिन उसका सिल-सिला ख़तम ही न हुआ और नतीजा कुछ न निकला। सोवियट की तरफ़ से निःशस्त्रीकरण की कई मौलिक तजवीज़ें पेश की गईं, लेकिन चूँकि यह समझा गया कि उनसे बहुत ही ज्यादा निःशस्त्रीकरण हो जायगा इसलिए उनको अव्यावहारिक मान लिया गया। पिछले साल यही 'प्रिपेयरेटरी कमीशन' विश्व-निःशस्त्रीकरण-सम्मेलन में मिल गया, और इसकी बैठकें अब महीनों से होती चली आ रही हैं और बातचीत का ख़ात्मा ही नहीं होता है—यहाँतक लोग भी क़रीब-क़रीब भूल गये हैं कि जिनेवा में ऐसी कोई चीज़ मौजूद है !

अमेरिका ने निःशस्त्रीकरण की इन बहसों में सिर्फ़ हिस्सा ही नहीं लिया, बल्कि संसार में अपनी सबसे ज़बरदस्त आर्थिक स्थिति के कारण योरप और यूरोपियन मामलों में उसकी दिलचस्पी भी बढ़ गई। सारा योरप उसका कर्ज़दार था, और वह यूरोपियन मुल्कों को फिर एक-दूसरे का गला काटने से रोकना चाहता था; क्योंकि उच्च उद्देश्यों के अलावा भी, अगर ये सब फिर लड़ने लगे तो उसके क़र्ज़ों और व्यापार का क्या हाल होगा ? निःशस्त्रीकरण की बहसों से जब जल्दी कोई नतीजा न निकला तो, १९२८ में, फ्रांस और अमेरिका की सरकारों के बीच बातचीत होकर शान्ति-रक्षा में सहायक होनेवाली एक नई तजवीज़ निकली। इस तजवीज़ में बड़ी हिम्मत के साथ यह कोशिश की गई कि 'युद्ध' ही 'शैर-क़ानूनी' बना दिया जाय।

महायुद्ध शुरू होने से पहले भी इटली घोर आर्थिक संकट में फँस गया था। १९११-१२ में वह तुर्की के साथ युद्ध में जीत तो गया था और उत्तरी अफ़्रीका का त्रिपोली प्रदेश मिल जाने से इटली के साम्राज्यवादी खुश भी बहुत हुए थे, मगर इस छोटी-सी लड़ाई से इटली की भीतरी भलाई बहुत नहीं हुई थी और उसकी आर्थिक हालत नहीं सुधरी थी। वस्तु अवस्था और भी बुरी होगई थी और १९१४ में, जबकि महायुद्ध छिड़ता ही दिखाई देता था, इटली क्रान्ति के दरवाजे पर खड़ा था। कारखानों में बड़ी-बड़ी हड़तालें हो रही थीं। नरम दल के समाजवादी नेता हड़तालों को दबाकर बड़ी मुश्किल से मजदूरों को आगे बढ़ने से रोक पाये थे। उसके बाद ही महायुद्ध शुरू होगया। इटली ने अपने जर्मन मित्रों का साथ देने से इन्कार कर दिया, उसने दोनों तरफ़ से ज्यादा-से-ज्यादा रियायतें हासिल करने के लिए अपनी निरपेक्षता या उदासीनता का फ़ायदा उठाने की कोशिश की। इस तरह ऊँची-से-ऊँची बोली बोलनेवाले को अपनी सहायता बेचने की वृत्ति शोभास्पद तो नहीं थी, परन्तु राष्ट्रों के हृदय नहीं होता और उनके व्यवहार के तरीके अलग ही होते हैं। यही व्यवहार अगर व्यक्ति करें तो उन्हें शर्म के मारे सिर नीचा करना पड़े। रिश्वत देने के लिए मित्र-राष्ट्रों यानी इंग्लैंड और फ़्रांस की स्थिति ज्यादा अनुकूल थी। उन्होंने नक़द रुपया भी दिया और आगे चलकर इलाक़ा देने का वचन भी दिया। इस कारण इटली मित्र-राष्ट्रों की तरफ़ होकर १९१५ की मई में लड़ाई में शामिल हुआ। मेरा खयाल है, मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि कुछ समय बाद एक गुप्त सन्धि के द्वारा इटली को स्मर्ना और छोटे एशिया का एक हिस्सा देने की बात हुई थी। मगर इस सन्धि के पक्की होने से पहले ही रूस में बोलशेविक क्रान्ति होगई और यह सारा खेल बिगड़ गया। इटली को यह भी एक शिकायत थी और पेरिस की शान्ति-परिषद में इस बात पर असन्तोष रहा कि इटली के हक्कों की उपेक्षा की गई। वहाँके साम्राज्यवादियों और अमीरों को आदा था कि नये-नये देश इटली के अधिकार में आयेंगे और वे उनका शोषण करके अपने देश के आर्थिक भार को हलका कर सकेंगे।

महायुद्ध के बाद इटली की हालत बहुत खराब होगई थी और वह किसी भी दूसरे मित्र-राष्ट्र से अधिक थक गया था। वहाँकी आर्थिक व्यवस्था छिन्न-भिन्न होती दीखती थी और समाजवाद और साम्यवाद के हामियों की तादाद बढ़ रही थी। उनके सामने रूस का बोलशेविक उदाहरण तो था ही। एक तरफ़ कारखानों के मजदूर आर्थिक अवस्था से कष्ट पा रहे थे, दूसरी तरफ़ सिपाही बड़ी तादाद में फ़ौज से खारिज होकर मारे-मारे बेकार फिर रहे थे। उपद्रव होने लगे और मध्यमवर्ग के नेता इन सैनिकों को मजदूरों की बढ़ती हुई ताक़त का मुकाबिला करने के लिए संग-

फरवरी १९२९ को, फेलाग-इकरारनामे के अन्तर्राष्ट्रीय कानून बन जाने के छः महीने पहले, दस्तखत हुए ।

इस तरह आपस में लड़नेवाली और भरभराकर गिरनेवाली दुनिया के ढाँचे को आखिरी कोशिशों से बचाने के लिए ये इकरारनामे और मुलहनामे होते गये, मानों इस तरह के इकरारनामों या ऊपरी पैवन्दों से अन्दर गहरी बँधी हुई बीमारी का इलाज हो सकता हो । यह १९२० और १९२९ के बीच का जमाना था, जब कि योरप के देशों में अक्सर समाजवादी या सोशल डिमोक्रेट लोग राज्याधिकारी थे । जितना ज्यादा उन्हें राज्याधिकार और सत्ता मिलती गई, उतना ही ज्यादा वे पूंजीवादी ढाँचे के अन्दर अपनेआपको मिलाते गये । दर-हक़ीक़त वे पूंजीवाद के सबसे अच्छे रक्षक बन गये, और अक्सर ज्यादा-से-ज्यादा अनुदार या प्रगति-विरोधी व्यक्ति के समान उग्र साम्राज्यवादी बन गये । महायुद्ध के बाद के जोश से भरे हुए कुछ क्रान्तिकारी वर्गों के पश्चात्, योरप की दुनिया किसी हद तक ठण्डी पड़ गई । मालूम होता था कि फिर कुछ वक़्त के लिए पूंजीवाद ने अपनेआपको परिस्थितियों के मुताबिक़ बना लिया, और कहीं भी जल्दी कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन होने की सम्भावना नज़र नहीं आती थी ।

सन् १९२९ में योरप का ऐसा हाल था ।

: १७५ :

मुसोलिनी और इटली का फ़ैसिज्म

२१ जून, १९३३

हमारी योरप की कहानी की रूपरेखा १९२९ या चार वर्ष पहले तक आ पहुँची है । परन्तु एक महत्वपूर्ण अध्याय अबतक अछूता ही रहा है । इसका बयान करने के लिए मुझे ज़रा पीछे जाना पड़ेगा । इसका ताल्लुक़ महासमर के बाद की इटली की घटनाओं से है । इन घटनाओं का महत्व इसलिए नहीं है कि उनसे हमें इटली के हालात मालूम होते हैं, बल्कि इसलिए है कि वे नये ढंग की घटनायें हैं और उनसे दुनियाभर में होनेवाली एक नई प्रवृत्ति और कशमकश की सूचना मिलती है । इस तरह इनका महत्व राष्ट्रीय ही नहीं है, बल्कि उससे भी अधिक है । इसीलिए मैंने इन्हें अलग पत्र के लिए रख छोड़ा था । इसलिए, इस ख़त में मुसोलिनी का हाल होगा और इटली में फ़ैसिज्म का जोर कैसे बढ़ा, इसका ज़िक्र होगा । मुसोलिनी इस वक़्त दुनिया के बड़े-से-बड़े आदमियों में एक है ।

थे और इनका मुख्य काम था मौक़ा पाकर समाजवादियों, उग्र सुधारकों और उनकी संस्थाओं पर हमला करना। इस तरह से कभी ये किसी समाजवादी पत्र के छापेखाने को नष्ट करते तो कभी किसी समाजवादी नियन्त्रण वाली म्यूनिसिपैलिटी या सहयोग-समिति पर हमला करते। बड़े-बड़े कारख़ानेदार और अमीर लोग मजदूर-आन्दोलन और समाजवाद के विरोध में आम तौर पर इन सैनिक दलों को अपने रुपये और प्रभाव की 'सहायता देने लगे। सरकार ने उनकी ओर से आँखें बन्द करलीं। वह समाजवादी दल की शक्ति को नष्ट करना चाहती थी।

इन लड़ाकू दलों या, संक्षेप में कहें तो, फ़ैसिस्टों को संगठित करनेवाला यह बेनिटो मुसोलिनी कौन था ? उस वक़्त तो वह जवान था। (अब उसकी उम्र पचास वर्ष के करीब है। १८८३ में वह पैदा हुआ था।) उसका जीवन बड़ा रंग-बिरंगा और दिलचस्प रहा था। उसका पिता लुहार था और समाजवादी था। इसलिए बेनिटो समाजवादी संस्कृति लेकर बड़ा हुआ। शुरू जवानी में ही वह बड़ा गरम आन्दोलनकारी होगया था और क्रान्तिकारी प्रचार-कार्य के कारण उसे स्वीज़रलैण्ड की नई रियासतों से निकाल दिया गया था। नरम समाजवादी नेताओं पर उसकी नरमी के कारण उसने दुरी तरह हमले किये। राज्य के ख़िलाफ़ बम और दूसरे आतंकवादी साधनों का वह खुला समर्थन करता था। तुर्की के साथ इटली की जो लड़ाई हुई उसकी अधिकांश समाजवादी नेताओं ने ताईद की थी। मगर मुसोलिनी की बात दूसरी थी। उसने लड़ाई का विरोध किया और इस सिलसिले में कई हिंसा के कामों पर उसे कुछ मास की क़ैद भी भोगनी पड़ी। लड़ाई का समर्थन करनेवाले नरम समाजवादी नेताओं का उसने घोर विरोध किया और उन्हें समाजवादी दल से निकलवाकर छोड़ा। मिलान से निकलनेवाले समाजवादी दैनिक पत्र 'अवन्ती' का वह सम्पादक बन गया और उसमें नित्य मजदूरों को हिंसा का मुक़ाबिला हिंसा से करने की सलाह देता रहा। हिंसा के इस उत्तेजन पर नरम मार्क्सवादी नेताओं को जोरदार आपत्ति थी।

इतने ही में महायुद्ध आ पहुँचा। कुछ महीनों तक मुसोलिनी युद्ध के ख़िलाफ़ और इटली के तटस्थ रहने के पक्ष में रहा। फिर अचानक उसने अपना विचार या अपने विचारों को जाहिर करने का ढंग बदल दिया और एलान कर दिया कि इटली को मित्र-राष्ट्रों के साथ शरीक होजाना चाहिए। वह समाजवादी पत्र को छोड़कर इस नई नीति का प्रचार करनेवाले एक नये पत्र का सम्पादन करने लगा। वह समाजवादी दल से निकाल दिया गया। आगे चलकर वह साधारण सिपाहियों में भरती होगया, और इटली की तरफ़ से लड़ाई के मोर्चे पर लड़ता हुआ घायल हुआ।

लड़ाई के बाद मुसोलिनी ने अपनेको समाजवादी कहना बन्द कर दिया।

ठित करने लगे। १९२० के गरमी के दिनों में स्थिति विकट हो गई। धातु के कारखानों के मजदूरों ने ज्यादा मजदूरी की मांग की। इनकी सभा में ५ लाख सदस्य थे। यह मांग मंजूर नहीं हुई और मजदूरों ने हड़ताल करने का निश्चय कर लिया। उन्होंने हड़ताल का एक नया ही तरीका निकाला। यानी मजदूर अपने-अपने कारखानों में पहुँचे और न खुद काम किया और न किसीको करने दिया। संघवादी समाजवादियों (Syndicalists) का यही कार्यक्रम था और फ्रांस का मजदूर-आन्दोलन बहुत असें से इसका समर्थक था। इस अडंगेवाजी का जवाब मालिकों ने यह दिया कि उन्होंने कारखाने बन्द कर दिये। इसपर मजदूरों ने कारखानों पर कब्जा करके उन्हें समाजवादी ढंग पर चलाने की कोशिश की।

मजदूरों की यह कार्रवाई निश्चित रूप से क्रान्तिकारी थी। अगर वे इसपर डटे रहते, तो या तो सामाजिक क्रान्ति हुए बिना न रहती या वे नाकामयाब होते। बहुत दिनों तक कोई बीच की हालत कायम नहीं रह सकती थी। उस वक्त इटली में समाजवादी दल बड़ा प्रबल था। मजदूर-संघों पर तो उसका नियन्त्रण था ही, तीस-हजार म्युनिसिपैलिटियाँ भी उसके फावू में थीं और पार्लमेण्ट में उसके १५० यानी एक-तिहाई सदस्य थे। अगर किसी दल में जोर हो, उसकी जड़ जमी हुई हो, जाय-दाद उसके पास हो और बहुत-से सरकारी पद उसके हाथ में हों, तो वह अक्सर क्रान्तिकारी नहीं होता। फिर भी इटली के समाजवादी दल और उसके नरम सदस्यों तक ने कारखानों पर अधिकार कर लेने की मजदूरों की कार्रवाई का समर्थन किया। मगर इतनी-सी बात करके इस दल ने और कुछ नहीं किया। वह पीछे हटना तो नहीं चाहता था, मगर उसमें आगे बढ़ने का साहस भी नहीं था। उसने कम-से-कम विरोध का बीचवाला रास्ता पसन्द किया। उसका वही हाल हुआ जो सब हिचकिचाहट से भरे हुए और अनिश्चयी लोगों का हुआ करता है। वे ठीक समय पर कोई निर्णय नहीं कर पाये, समय उन्हें छोड़कर आगे निकल गया, और वे कहीं के न रहे। उग्र सुधारकों और मजदूर नेताओं की हिचकिचाहट के कारण आखिर कारखानों पर से मजदूरों का कब्जा जाता रहा।

इससे मालिक वर्ग का हौसला बहुत बढ़ गया। उन्होंने देख लिया कि मजदूरों और उनके नेताओं की जितनी ताकत वे समझते थे उतनी नहीं है। अब उन्होंने मजदूर-आन्दोलन और समाजवादी दल से बदला लेने और उन्हें तहस-नहस कर देने की योजना बनाई। १९१९ में फ़ौजों से खारिज हुए सिपाहियों के कुछ स्वयंसेवक-दल बेनिटो मुसोलिनी ने बनाये थे। मालिक वर्ग का ध्यान इनकी तरफ़ गया। ये लड़ाकू दल या फैसिस्ट (जो इटालियन के Fasci di Combattimenti से बना है) कहलाते

इस तरह जब समाजवादी नेता शंका, संकोच और आपस के झगड़ों में लगे रहे और उनके दल में फूट होती रही उस समय फ़ैसिस्टों का जोर खूब बढ़ता गया। नियमित सेना का फ़ैसिज्म के प्रति बड़ा दोस्ताना रुख था और मुसोलिनी ने सेनापतियों को अपनी तरफ़ मिला लिया था। मुसोलिनी का यह बड़े मार्क के काम था कि उसने ऐसे मुत्तलिफ़ और विरोधी तत्त्वों को अपने साथ करके ऐक्य-सूत्र में बाँध रक्खा और अपने अनुयायियों के हर समूह का यह विश्वास जमा दिया कि फ़ैसिज्म खास तौर पर उसी-का हिमायती है। धनवान फ़ैसिस्ट यह समझने लगे कि मुसोलिनी उनकी सम्पत्ति का रक्षक है और पूंजीवाद के खिलाफ़ वह जो भाषण करता और नारे लगाता है वे ख़ाली सर्वसाधारण को धोखा देने की बातें हैं। ग़रीब फ़ैसिस्ट यह मानने लगे कि फ़ैसिज्म में असली चीज़ तो यह पूंजीवाद का विरोध ही है और बाक़ी बातें अमीरों को खुश करने भर के लिए हैं। इस तरह मुसोलिनी इन दोनों वर्गों से काम निकालने लगा। एक दिन वह अमीरों के हक़ में बोलता तो दूसरे ही दिन ग़रीबों के पक्ष में भाषण देता। मगर असल में वह सम्पत्तिशाली वर्ग का हिमायती था, क्योंकि वे उसे आर्थिक सहायता देते थे और यह इसलिए कि वे अपने चिर-शत्रु समाजवाद और मज़दूर-आन्दोलन की शक्ति को नष्ट करने पर तुले हुए थे।

अन्त में १९२२ के अक्टूबर में फ़ैसिस्टों की टुकड़ियों ने नियमित सेनानायकों के नेतृत्व में रोम पर धावा बोल दिया। प्रधानमन्त्री ने अबतक फ़ैसिस्टों के कार्यों को सहन किया था। अब उसे भी फ़ौजी क़ानून की घोषणा करनी पड़ी। परन्तु अब क्या था; देर बहुत हो चुकी थी और खुद वादशाह भी मुसोलिनी की तरफ़ होगया था। उसने फ़ौजी क़ानून की आज्ञा रद करदी, अपने प्रधानमन्त्री का इस्तीफ़ा मंज़ूर कर लिया और मुसोलिनी को प्रधानमन्त्री बनने और मन्त्रिमण्डल बनाने के लिए आमंत्रण दिया। ३० अक्टूबर १९२२ को फ़ैसिस्ट सेना रोम पहुँची और उसी दिन मुसोलिनी प्रधानमन्त्री बनने के लिए मिलान से रेल द्वारा आ पहुँचा।

फ़ैसिज्म की विजय हुई और सत्ता मुसोलिनी के हाथ में आगई। परन्तु उसका पक्ष क्या था ? वह किस नीति और कार्यक्रम का समर्थक था ? आम तौर पर बड़े आन्दोलनों का निर्माण किसी स्पष्ट विचार-धारा पर होता है और ये विचार कुछ निश्चित सिद्धान्तों पर निर्भर होते हैं, और उनका निश्चित ध्येय और कार्यक्रम होता है। फ़ैसिज्म में यह अद्वितीय गुण है कि न उसके कोई निश्चित सिद्धान्त हैं, न विचार-धारा और तत्त्व-ज्ञान। हाँ, समाजवाद, साम्यवाद और उदार विचारों का विरोध ही एक तत्त्व-ज्ञान समझ लिया जाय तो बात दूसरी है। १९२० में यानी फ़ैसिस्ट दलों के बनने के एक वर्ष बाद मुसोलिनी ने घोषणा की थी कि फ़ैसिस्ट लोग—

उसका पुराना दल उसे नापसन्द करता था और मजदूरवर्ग पर उसका कोई प्रभाव नहीं रहा। वह इधर का रहा न उधर का। उसने शान्तिवाद और समाजवाद के साथ-साथ पूंजीवादी शासन की भी निन्दा करनी शुरू कर दी। वह हर क्रिस्म के राज्य की बुराई करने लगा, और अपनेको व्यक्तिवादी बताकर अराजकता की तारीफ करने लगा। ये तो बातें हुईं उसके लिखने की। अब उसने जो किया वह भी सुन लो। १९१९ में उसने फ़ैसिज्म की स्थापना की और अपने लड़ाकू दलों में बेकार सैनिकों को भरती करना शुरू कर दिया। इन दलों का धर्म हिंसा था और सरकार के तटस्थ रहने से इनका होसला और उत्पात बढ़ता गया। कभी-कभी शहरों में मजदूर-वर्ग ने इनकी वाक्यावदा भिड़न्त होजाती थी और वे इन्हें मार भगाते थे। परन्तु समाजवादी नेता मजदूरों की इस लड़ाकू वृत्ति के खिलाफ़ थे। वे उन्हें धीरज और शान्ति से फ़ैसिस्ट खतरे का मुक़ाबिला करने की सलाह देते थे। उन्हें उम्मीद थी कि फ़ैसिज्म इस तरह अपनी मौत आप मर जायगा। पर फ़ैसिस्ट दलों की ताक़त बढ़ती गई। बढ़ती भी क्यों नहीं, जब अमीरों के रुपये की उन्हें मदद थी, सरकार उनके काम में दख़ल नहीं देती थी और सर्व-साधारण में जो विरोध-भावना थी वह सब नष्ट होचुकी थी। नीचेत यहाँतक पहुँची कि मजदूरों के एकमात्र हथियार हड़ताल का भी प्रयोग फ़ैसिस्टों की हिंसा को रोकने के लिए नहीं किया गया।

मुसोलिनी के नेतृत्व में फ़ैसिस्टों ने दो विरोधी विचार-धाराओं का मेल साधा। प्रथम तो वे समाजवाद और साम्यवाद के कट्टर शत्रु थे। इससे उन्हें पूंजीपतियों की सहायता मिल गई। दूसरे मुसोलिनी पुराना समाजवादी आन्दोलक और क्रान्तिकारी था और उसकी जवान पर अनेक पूंजी-विरोधी नारे रहते थे। ये शरीबों को पसन्द आते थे। आन्दोलन के विशेषज्ञ साम्यवादियों से उसने यह कला भी ख़ूब अच्छी तरह सीख ली थी। इस तरह फ़ैसिज्म एक अजीब खिचड़ी बन गया था और उसका अलग-अलग तरह से अर्थ लगाया जा सकता था। असल में तो यह पूंजीपतियों का आन्दोलन था, परन्तु इसके कई रणनाद पूंजीवाद के लिए ख़तरनाक भी थे। इस तरह इसमें तरह-तरह के लोग शामिल होगये। मध्यमवर्ग—खासकर निम्न श्रेणी के मध्यमवर्ग के बेकार लोग इसके स्तम्भ थे। ज्यों-ज्यों इसकी ताक़त बढ़ती गई त्यों-त्यों बेकार और साधारण मजदूर, जिनके संघ नहीं बने थे, फ़ैसिस्ट दल की ओर आकर्षित होने लगे। सफलता का लोहा सभी मानते हैं। फ़ैसिस्टों ने दूकानदारों से ज़बरदस्ती भाव कम करवाके शरीबों का सद्भाव प्राप्त कर लिया। और मनचले लोग तो वैसे ही फ़ैसिस्ट झण्डे के नीचे बहुत-से आगये। लेकिन यह सब कुछ होने पर भी फ़ैसिज्म एक अल्पसंख्यक आन्दोलन ही रहा।

सत्ता के यह हरगिज अनुकूल नहीं पड़ सकता। उनका नेता मुसोलिनी इल ड्यूस अर्थात् सर्वेसर्वा बन गया। उनकी वर्दी काली कुर्ती होने के कारण वे काली कुर्ती वालों के नाम से प्रसिद्ध होगये।

फ़ैसिस्ट लोगों का यदि कोई रचनात्मक कार्य-क्रम था तो वह सिर्फ सत्ता हासिल कर लेना था। इस कारण मुसोलिनी के प्रधानमन्त्री बन जाने पर उनकी यह मुराद पूरी होगई। इसके बाद वह अपने विरोधियों को पीसकर अपनी स्थिति मज़बूत करने के काम में लग गया। हिंसा और आतंकवाद का असाधारण चक्र शुरू हुआ। इतिहास में हिंसा एक साधारण-सी बात रही है, परन्तु आम तौर पर इसे एक आवश्यक बुराई समझा गया है और इसके लिए व्हाने ढूँढे गये और सज़ा दी जाती रही है। मगर फ़ैसिज्म को हिंसा के बारे में ऐसा कोई क्षमा-याचना का-सा ढंग इस्तिहार करने की ज़रूरत मालूम नहीं देती। इन लोगों के लिए तो यह एक मानी हुई और तारीफ़ की चीज़ है। वे विरोध न होने की हालत में भी हिंसा करते हैं, पार्लमेण्ट में विरोधी सदस्यों को इन लोगों ने पीट-पीटकर भयभीत कर दिया और विधान को बिल्कुल बदल देनेवाला एक नया क़ानून ज़बरदस्ती पास करवा लिया। इस तरह मुसोलिनी के पक्ष में भारी बहुमत प्राप्त किया गया।

यह आश्चर्य की बात है कि जब फ़ैसिस्ट लोगों के हाथ में सबमुच सत्ता आगई और पुलिस और राज की सारी शक्ति पर उनका अधिकार जम गया तब भी उनकी ग़ैर-क़ानूनी हिंसा जारी रही। परन्तु वह जारी रही और उन्हें कोई रोकनेवाला भी नहीं रहा। सरकारी पुलिस तो दखल ही क्यों देती? लोगों की हत्याएँ हुई, उन्हें मारा-पीटा और अन्य शारीरिक यातनाएँ दी गई और उनकी सम्पत्ति नष्ट करदी गई। ये फ़ैसिस्ट एक ख़ास तरीक़े का व्यापक प्रयोग करते थे। उनके विरोध का साहस करने-वालों को वे अण्डी के तेल की भारी-भारी खुराकें पिला देते थे।

१९२४ में गियाकोमो मेटिमोरी नामक समाजवादी नेता की हत्या की गई। यह पार्लमेण्ट का सदस्य था। इससे घोरप-भर में बड़ी सनसनी फैली। इसने थोड़े दिन पहले ही चुनाव में फ़ैसिस्ट तरीक़ों पर भाषण देकर उनकी आलोचना की थी। उसके कुछ ही समय बाद उसकी हत्या करदी गई। दिखावे के लिए हत्यारों पर मुक़दमा चलाया गया; परन्तु वे प्रायः बिना सज़ा के ही छूट गये। उदार दल के नरम नेता अमेण्डोला की मृत्यु मार के कारण हुई। भूतपूर्व उदार प्रधानमन्त्री निटो मुश्किल से जान बचाकर इटली से भागा; मगर उसका घर नष्ट कर दिया गया। ये थोड़े-से उदाहरण तो ऐसे हैं जिनपर संसार-भर का ध्यान गया। वैसे इनकी हिंसा तो लगातार और व्यापक रूप में जारी रही। यह हिंसा दमन के क़ानूनी उपायों से अलग थी। यह

“किसी भी तरह के निश्चित सिद्धान्तों के बन्धन से मुक्त हैं। उनके सामने एक ही ध्येय है। वह है इटली-निवासियों का भावी हित। इस ध्येय की ओर वे अविश्रान्त गति से बढ़ रहे हैं।”

यह तो कोई निश्चित नीति नहीं हुई, क्योंकि अपने देशबन्धुओं की भलाई का दावा करने को तो सभी तैयार होते हैं। १९२२ में, यानी रोम के लिए कूच करने के ठीक एक महीने पहले, मुसोलिनी ने कहा था, “हमारा कार्य-क्रम बहुत सीधा-सादा है। हम इटली पर शासन करना चाहते हैं।” कितनी साफ़ बात है ?

हाल ही में इटली के एक विश्वकोष में फ़ैसिज्म की उत्पत्ति पर एक लेख लिख-कर मुसोलिनी ने यह बात और भी स्पष्ट कर दी है। उसमें वह कहता है कि जब वह रोम के लिए रवाना हुआ था, उस वक़्त उसके दिमाग़ में आगे के लिए कोई निश्चित योजना नहीं थी। उसके मन पर पुराने समाजवादी संस्कार थे। विकट राज-नैतिक स्थिति के मौक़े पर कुछ कर गुज़रने की उसके जी में प्रबल लालसा थी। वस इसीसे प्रेरित होकर उसने बीड़ा उठा लिया।

फ़ैसिज्म और साम्यवाद (Communism) में परस्पर कट्टर विरोध है, परन्तु इनकी कुछ कार्यवाइयाँ मिलती-जुलती हैं। वैसे जहाँतक सिद्धान्तों और विचारों का सम्बन्ध है, इसमें ज़मीन-आसमान का फ़र्क़ है। हम देख चुके हैं कि फ़ैसिज्म के कोई आधार-भूत सिद्धान्त नहीं हैं। उसकी शुरुआत ही ख़ाली मस्तिष्क से हुई है। इसके विपरीत साम्यवाद या मार्क्सवाद एक पेचीदा आर्थिक मत और ऐतिहासिक दृष्टिकोण है। उसके लिए कठोर-से-कठोर मानसिक अनुशासन की ज़रूरत है।

हालाँकि फ़ैसिज्म के कोई सिद्धान्त या आदर्श नहीं हैं, फिर भी हिंसा और आतंकवाद का उसका एक निश्चित विधि-विधान है और अतीत काल के बारे में उसका एक ख़ास दृष्टिकोण है। इससे हमें फ़ैसिज्म को समझने में थोड़ी मदद मिल जाती है। उसका संकेत-चिन्ह एक पुराना रोमन साम्राज्य का निशान है जो रोम के सम्राटों और हाकिमों के आगे-आगे चलता था। यह छड़ियों का एक गट्टा होता था और उसके बीच में एक कुल्हाड़ा रहता था। रोमन भाषा में उन छड़ियों को *Fasces* कहते थे और इसी से *Fascismo* शब्द बना। फ़ैसिस्ट संगठन भी पुराने रोमन नमूने पर बना है। नाम तक पुराने ही काम में लाये जा रहे हैं। फ़ैसिस्ट सलामी फ़ैसिस्टा कहलाती है। यह भी वही आगे बढ़ाकर ऊँचे किये हाथों की पुरानी रोमन सलामी है। इस प्रकार फ़ैसिस्टों की नज़र प्रेरणा के लिए भी साम्राज्यवादी रोम पर ही गई है। उनका दृष्टिकोण साम्राज्यवादी है। उनका ‘मोटो’ या आदर्शवाक्य है—“चर्चा नहीं, केवल आज्ञा पालन।” यह आदर्श शायद सेना के लिए तो ठीक है, परन्तु लोक-

शाही नगर सुन्दर बनाया जा रहा है और सुधार की कई बड़ी-बड़ी योजनायें हाथ में ली गई हैं। मुसोलिनी के कल्पना-जगत् में नये रोमन साम्राज्य के स्वप्न नाच रहे हैं।

पोप और इटली की सरकार में प्राचीन काल से झगड़ा था। वह १९२९ में ख़त्म होगया। मुसोलिनी और पोप के प्रतिनिधि के बीच समझौता होगया। जबसे १८७१ में इटली राज्य ने रोम को अपनी राजधानी बनाया था तभीसे पोप ने इसे स्वीकार नहीं किया था और रोम पर अपनी सर्वोपरि सत्ता छोड़ने से इन्कार किया था। इसीलिए पोप लोगों ने यह नीति ग्रहण करली थी कि पोप निर्वाचित होते ही वे रोम के अपने विशाल बैटिकन महल में चले जाते और फिर कभी इटली की भूमि पर नहीं निकलते। वे स्वेच्छा से क़ैदी बनकर रहते थे। १९२९ के समझौते से रोम का यह छोटा-सा बैटिकन इलाक़ा एक स्वतंत्र और सम्पूर्ण सत्ताधारी राज्य मान लिया गया। पोप इस राज्य का निरंकुश शासक है और इसके नागरिकों की संख्या ५०० के करीब है। इस राज्य की अपनी अदालतें, सिक्का, डाक के टिकट और सार्वजनिक सेवा के विभाग हैं। इसकी छोटी-सी रेलवे दुनिया में सबसे महंगी है। अब पोप क़ैदी की तरह नहीं रहता। वह कभी-कभी बैटिकन से बाहर आता है। पोप के साथ सन्धि करके मुसोलिनी कैथलिक सम्प्रदाय के ईसाइयों में लोकप्रिय होगया। फ़ैसिस्ट हिंसा का ग़ैरक़ानूनी स्वरूप करीब एक साल तक बड़ा उग्र रहा और बाद में भी १९२६ तक कुछ-कुछ बना रहा। १९२६ में राजनैतिक विरोधियों से निपटने के लिए 'असाधारण क़ानून' बना दिये गये। इनसे राज्य को बड़े अधिकार मिल गये और ग़ैर-क़ानूनी कार्रवाई अनावश्यक होगई। वे क़ानून कुछ ऐसे ही थे जैसे वे आर्डिनेंस और उनपर बने हुए क़ानून हैं जिनकी हम भारतवासियों पर इतनी वर्षा हुई है। इन 'असाधारण क़ानूनों' के अनुसार लोगों को सजायें दी जा रही हैं, जेल भेजा जा रहा है और बड़ी तादाद में देश-निकाले दिये जा रहे हैं। सरकारी अंकों के अनुसार १९२६ के नवम्बर और १९३२ के अक्टूबर के बीच में १०,०४४ आदमियों को विशेष अदालतों के सामने पेश किया गया था। पोंज़ा, वेण्टोलीन और ट्रिमटी नामक तीन द्वीप इन निर्वासितों के लिए अलग ही सुरक्षित कर दिये गये हैं। कहा जाता है कि वहाँ की हालत बहुत ख़राब है। इस बीच में दमन और गिरफ़्तारियाँ तो जारी हैं ही। अभी हाल ही की यानी १९३३ के मार्च मास की बात है कि मिलान नगर और उत्तरी प्रदेशों में बहुत लोग गिरफ़्तार किये गये थे। रोम पर फ़ैसिस्टों की कूच का पिछले साल दसवाँ वार्षिकोत्सव था। उस अवसर पर आम माफ़ी दी गई थी और बहुत-से मामूली और थोड़े-से राजनैतिक क़ैदी छोड़े गये थे। मगर प्रमुख और लम्बी मियाद के राजनैतिक क़ैदी नहीं छोड़े गये।

कोई भड़की हुई भीड़ की हिंसा भी नहीं थी। यह तो जान-बूझकर संगठित रूप में की गई वाकायदा हिंसा थी। इसके शिकार सभी विरोधी होते थे। समाजवादी और साम्यवादी ही नहीं, उदार दल के शान्त और नरम-से-नरम आदमी भी नहीं बचते थे। मुसोलिनी की आज्ञा थी कि विरोधियों का जीना कठिन या 'असंभव' बना दिया जाय; कोई दूसरा दल, संगठन या संस्था जीवित न रहने पावे; जो कुछ हो फ़ैसिस्ट हो; सभी नौकरियाँ भी फ़ैसिस्टों को ही मिलें। इसकी तामील भी सचाई के साथ होती थी।

मुसोलिनी इटली का सर्वशक्तिमान विधाता और सर्वेसर्वा होगया। वह प्रधान-मंत्री ही नहीं, साथ ही वंदेशिक, गृह, औपनिवेशिक, युद्ध, जलसेना और श्रमजीवी विभागों का मंत्री भी बन बैठा। एक तरह से सारा मंत्रि-मण्डल ही वह था। बेचारा बादशाह कोने में धिठा दिया गया। उसका कभी नाम ही सुनाई नहीं देता। पार्लमेण्ट भी धीरे-धीरे एक तरफ़ धकेल दी गई और छायागात्र रह गई। फ़ैसिस्ट महापरिषद् (फ़ैसिस्ट ग्रैंड कौंसिल) का ही बोलवाला होगया और परिषद् में मुसोलिनी की तूती बोलने लगी।

मुसोलिनी ने शुरू-शुरू में विदेशी मामलों पर जो भाषण दिये उनसे योरप में बड़ा आश्चर्य और भय फैला। वे भाषण असाधारण ढंग के थे। वे शोखी और धमकियों से भरे थे। उनमें राजनीतियों की-सी चिकनी-चुपड़ी बातें ज़रा भी नहीं थीं। ऐसा मालूम होता था मानो वह सदा लड़ाई के लिए तुला बैठा हो। वह इटली के साम्राज्यवादी भाग्य की ओर इटली के असंख्य वायुयानों के आकाश में छा जाने की बातें करता था; और उसने कई बार अपने पड़ोसी फ़्रान्स को खुली धमकियाँ दीं। अवश्य ही फ़्रान्स इटली से कहीं अधिक बलवान था। मगर लड़ने की किसीकी इच्छा नहीं थी, इसलिए मुसोलिनी की ये सब बातें बर्दाश्त करली जाती थीं। राष्ट्रसंघ को मुसोलिनी ने अपने व्यंग और तिरस्कार का खास तौर पर निशाना बनाया। दिल्लगी तो यह थी कि इटली खुद राष्ट्रसंघ का सदस्य था। एक अवसर पर तो मुसोलिनी ने बहुत बुरी तरह आगे बढ़कर उसका मान भंग किया। फिर भी राष्ट्रसंघ और दूसरी शक्तियाँ इसे पी गईं। परन्तु जैसे-जैसे समय बीतता गया वैसे-वैसे मुसोलिनी के भाषणों की उत्तेजना भी कम पड़ती गई। उसका रवैया नरम हो गया है और अब वह भी दूसरे शान्त राजनीतियों की तरह ही शान्ति और निःशस्त्रीकरण की बातें करता है। निरंकुश शासकों की सत्ता पशुबल पर निर्भर होती है; इस कारण युद्ध उनके लिए सदा ख़तरनाक होते हैं।

पिछले दस साल में इटली में बहुत-से बाहरी परिवर्तन हुए हैं और यात्रियों के दिल पर वहाँ व्यवस्था और समय की पावन्दी देखकर अच्छा असर पड़ता है। रोम का

मोरक्को के छोटे-बड़े दो हिस्से करके फ़्रांस और स्पेन ने उन्हें अपने-अपने प्रभाव-क्षेत्रों में बाँट लिया था। १९२१ में मोरक्को के रीफ़ लोगों में अब्दुलकरीम नाम का एक योग्य नेता स्पेनिश शासन के खिलाफ़ खड़ा हुआ। उसने बड़ी क़ाबलियत और बहादुरी का सबूत दिया और स्पेनिश फ़ौजों को बार-बार हराया। इससे स्पेन की भीतरी स्थिति विकट होगई। राजा और सेनानायक दोनों विधान और पार्लमेण्ट का ख़ात्मा करके निरंकुश शासन क़ायम करना चाहते थे। इस बात पर वे दोनों सहमत थे, लेकिन सर्वेसर्वा कौन बने इस बात पर उनमें मतभेद था। राजा खुद सर्वसत्ताधारी या निरंकुश शासक बनना चाहता था और फ़ौज के लोग सैनिक-शाही क़ायम करना चाहते थे। १९२३ के सितम्बर में फ़ौज ने बग़ावत कर दी। इससे मामला फ़ौज के हक़ में तय हो गया और सेनापति प्राइमो दि रिवेरा सर्वेसर्वा बन गया। उसने पार्लमेण्ट को मुअत्तल करके पशुबल के ज़रिये यानी फ़ौज के सहारे हुकूमत करनी शुरू कर दी। फिर भी रीफ़ों के खिलाफ़ मोरक्को वाली मुहिम कामयाब नहीं हुई और अब्दुलकरीम आगे बढ़-बढ़कर स्पेन की सत्ता का तिरस्कार करता रहा। स्पेनिश सरकार ने उसके सामने अनुकूल शर्तें पेश कीं, मगर उसने उन्हें मंज़ूर नहीं किया। वह बराबर मुकम्मल आज़ादी का दावेदार रहा। मुमकिन है कि अकेली स्पेनिश सरकार उसे दवा देने में कामयाब न होती। फ़्रान्स का मोरक्को में बड़ा स्वार्थ था। १९२५ में उसने दख़ल देने का फ़ैसला किया और अपने विशाल साधन अब्दुलकरीम के खिलाफ़ लगा दिये। १९२६ के मध्य में अब्दुलकरीम की हार हुई, फ़्रांस वालों के आगे उसने हाथियार डाल दिये और उसकी लम्बी और वीरतापूर्ण लड़ाई ख़त्म हुई।

इस बीच स्पेन में प्राइमो दि रिवेरा की तानाशाही जारी रही। उसके मामूली लवाज़मात यानी फ़ौजी ज़बरदस्ती, ख़बरों पर पाबन्दी, दमन और कभी-कभी फ़ौजी क़ानून भी साथ रहे। याद रहे कि यह तानाशाही मुसोलिनी की तानाशाही से जुदा ढंग की थी। इसका आधार सिर्फ़ सेना पर था और इटली में जनता के कुछ वर्गों का सहारा था। ज्योंही ही सेना प्राइमो दि रिवेरा से ऊँची कि और कोई उसकी मदद करनेवाला ही नहीं रहा। १९३० के शुरू में ही राजा ने प्राइमो को ख़र्खास्त कर दिया। उसी साल क्रान्ति भी हुई थी और वह दवा भी दी गई थी। मगर प्रजातन्त्र और क्रान्ति की भावना इतनी व्यापक होगई थी कि उसे दबाकर रखना असंभव था। १९३१ में प्रजातन्त्रवादियों ने म्यूनिसिपल चुनाव में अपने भारी बल का परिचय दिया और उसके थोड़े ही दिन बाद राजा अलफ़्रेंज़ो ने गद्दी छोड़कर देश से भाग जाने में ही बुद्धिमानी समझी। अत्यायी सरकार क़ायम होगई और स्पेन में योरप की सबसे नई प्रजातन्त्र शासन-प्रणाली का जन्म हुआ। अबतक स्पेन निरंकुश राजतन्त्र और धार्मिक

इन लगातार गिरफ्तारियों से जाहिर है कि इस सारे दमन के बावजूद देश में गुप्त और क्रान्तिकारी विरोध मौजूद है। उसकी शक्ति कितनी है, यह कह सकना कठिन है। वैसे जाहिरा तो यही मालूम होता है कि मुसोलिनी ही सर्वेसर्वा है और उसकी जड़ खूब मजबूत जम गई है। परन्तु आर्थिक तौल बढ़ता जा रहा है और देश की माली हालत फिर बहुत खराब होगई है। मगर यह बात तो आज क़रीब-क़रीब सभी देशों के लिए कही जा सकती है।

: १७६ :

लोकसत्ता और निरंकुश शासन

२२ जून, १९३३

बेनिटो मुसोलिनी ने अपनेको इटली का सर्वेसर्वा (डिक्टेटर) क्या बना लिया, उसके उदाहरण की बीमारी योरप-भर में फैलती देखने लगी। उसने कहा—“योरप के हर देश में सिंहासन खाली पड़ा है। कोई योग्य पुरुष उसपर क़ब्ज़ा करले, इसीकी देर है।” कई मुल्कों में निरंकुश शासन क़ायम होगये। पार्लमेण्ट या तो तोड़ दी गई या उन्हें ज़बरदस्ती सर्वसत्ताधारियों (डिक्टेटरों) की इच्छाओं के अनुकूल बना लिया गया। स्पेन की मिसाल ध्यान देने लायक है।

स्पेन महासमर में नहीं पड़ा था। उसने लड़ाकू राष्ट्रों को माल बेच-बेचकर खूब धन कमाया। लेकिन उसके अपने झगड़े तो थे ही और वह औद्योगिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ देश था। एक समय था, जब अमेरिका और पूर्वी देशों का धन उसके यहाँ बहकर आता था और योरप में उसका दर्जा बहुत ऊँचा था। लेकिन वह ज़माना कभी का बीत चुका था। अब तो योरप में उसकी महत्वपूर्ण शक्ति भी नहीं समझी जाती थी। उसकी पार्लमेण्ट कमज़ोर-सी संस्था थी। उसे कोर्टे कहते थे। रोमन पादरियों का जोर था। उद्योग-धंधों में पिछड़े हुए योरप के दूसरे देशों में जो बात हुई, वही स्पेन में भी हुई। जर्मनी और इंग्लैंड के ठोस भाक्सवाद और नरम समाजवाद की अपेक्षा वहाँ संघवाद और अराजकतावाद का प्रचार ज्यादा हुआ। जब १९१७ में रूस के बोलशेविक सत्ता के लिए जूझ रहे थे उस वक़्त स्पेन के मजदूरों और उग्र सुधारकों ने व्यापक हड़ताल करके लोकसत्तात्मक प्रजातन्त्र क़ायम करने की कोशिश की। बादशाह की सरकार और सेना ने मिलकर इस हड़ताल और सारे आन्दोलन को कुचल दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि देश में सेना की सत्ता सर्वोपरि होगई। बादशाह भी फ़ौज का सहारा पाकर पहले से ज़रा अधिक स्वतन्त्र और स्वेच्छाचारी होगया।

की हुई—साम्यवादियों की, फ्रैंसिस्टों की और सेना की। सैनिक तानाशाही में कोई खास बात नहीं है। वह पुराने जमाने से चली आई है। साम्यवादी और फ्रैंसिस्ट तानाशाहियाँ इतिहास में नई चीज हैं और हमारे अपने समय की खास उपज हैं।

इन तानाशाहियों के बारे में सबसे मार्क की बात यह है कि ये लोकसत्ता और प्रतिनिधि-शासन के बिल्कुल खिलाफ हैं। तुम्हें याद होगा, मैंने तुम्हें बताया है कि उन्नीसवीं सदी लोकसत्ता की सदी थी। उस सदी में फ़्रांस की राज्यक्रान्ति की दी हुई मनुष्य के अधिकारों-सम्बन्धी विचार-धारा ने उन्नत लोगों के मस्तिष्क पर शासन किया था और व्यक्ति-स्वातंत्र्य का ध्येय सर्वमान्य हो गया था। इसीमें से योरप के ज्यादातर देशों में—कहीं कम कहीं ज्यादा—प्रतिनिधि-शासन का विकास हुआ। इसमें आर्थिक क्षेत्र में दखल न डालने और जो कुछ चल रहा है वही चलने देने का उसूल चल गया। बीसवीं सदी ने, या यूँ कहो कि महासमर के बाद के सालों ने, उन्नीसवीं सदी की इस महान् परम्परा का अन्त कर दिया और अब नियमित लोक-सत्ता की कल्पना का आदर बहुत ही थोड़े लोगों में रह गया है। लोकसत्ता के इस पतन के साथ उदार कहलानेवाले समूहों का भी सब जगह एकसा हाल हुआ और अब उनकी गिनती सबल शक्तियों में नहीं रही।

लोकसत्ता की टीका और विरोध साम्यवादियों और फ्रैंसिस्टों दोनों ने किया है, मगर दोनों की दलीलें बिल्कुल जुदा-जुदा हैं। जिन देशों में साम्यवाद या फ्रैंसिज्म किसीका भी जोर नहीं है, उनमें भी लोकसत्ता की पहले जैसी क्रूर नहीं रही। पार्ल-मेण्ट की पहलेवाली बात जाती रही और अब उसकी बहुत इज्जत नहीं है। शासन विभाग के मुखियाओं को बड़े इस्तिथारात दे दिये जाते हैं और वे पार्लमेण्ट से पूछे बिना जो ठीक समझते हैं कर डालते हैं। इसकी एक वजह तो यह है कि आजकल का वक़्त बड़ा नाजुक है। इसमें तुरन्त कार्रवाई करने की जरूरत पड़ती रहती है और प्रतिनिधि-सभायें जल्दी कार्रवाई नहीं कर सकतीं। जर्मनी ने हाल ही में अपनी पार्ल-मेण्ट को बिल्कुल धता बता दिया है और अब वहाँ फ्रैंसिस्ट शासन का बुरे-से-बुरा रूप प्रकट हो रहा है। अमेरिका के संयुक्त राष्ट्र के प्रधान के हाथों में सदा ही बड़े अधिकार रहे हैं और इस साल वे और भी बढ़ा दिये गये हैं। इस वक़्त तो सिर्फ़ इंग्लैण्ड और फ़्रांस ही दो बड़े देश रह गये हैं जहाँ जाहिरा तौर पर पार्लमेण्ट पहले की तरह काम कर रही है। उनकी मनमानी उनके मातहत देशों और उपनिवेशों में होती है। अंग्रेजों का फ्रैंसिज्म हिन्दुस्तान में और फ़्रांस का इण्डो-चीन में 'शान्ति-स्थापन' का काम कर रहा है! मगर लन्दन और पेरिस में भी पार्लमेण्ट खोखली होती जा रही है। पिछले ही महीने उदार दल के एक प्रमुख अंग्रेज ने कहा था :—

शासन का प्रतीक बना हुआ था। अब उसने राजा अलफ्रेड्सो को मुजरिम करार दिया और चर्च यानी धर्म-संस्था के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी।

मगर मैं तो तुम्हें सर्वसत्ताधारियों (डिक्टेटरों) का हाल कह रहा था। इटली और स्पेन के सिवाय जिन दूसरे देशों ने लोकसत्तात्माक शासन-प्रणाली को छोड़कर निरंकुश शासन स्थापित कर लिये थे, वे ये हैं—पोलैण्ड, यूगोस्लाविया, यूनान, बल्गेरिया, पुर्तगाल, हंगरी और आस्ट्रिया। पोलैण्ड में सेना पर अधिकार होने के कारण पिलसूडस्की सर्व-सत्ताधारी यानी डिक्टेटर बन गया था। यह ज़ार के जमाने का पुराना समाजवादी था। पोलैण्ड की पार्लमेण्ट के सदस्यों को यह ऐसी बुरी-बुरी सुनाया करता था कि आश्चर्य होता था। कभी-कभी तो वे सचमुच गिरफ्तार करके भेज दिये जाते थे। यूगोस्लाविया में खुद राजा सर्वोच्च हैं। कहते हैं कि इस देश में कहीं-कहीं तुर्कों के शासन से भी अधिक खराब हालत और जुल्म हैं।

मैंने जिन मुल्कों का जिक्र किया है उन सब में शायद अब खुली तानाशाही नहीं है। उनके जल्दी-जल्दी होनेवाले परिवर्तनों से वाक़िफ़ रहना मुश्किल है। कभी-कभी उनकी पार्लमेण्टों की थोड़ी देर के लिए नौद खुल जाती है और उन्हें काम करने दिया जाता है। कभी-कभी, जैसा बल्गेरिया में हाल ही में हुआ, सत्ताधारी सरकार जिन सदस्यों को नापसन्द करती है उनके समूह-के-समूह को गिरफ्तार करके पार्लमेण्ट से उन्हें निकाल देती है। साम्यवादी लोग आम तौर पर इस गुस्से के शिकार होते हैं। पीछे से और दलों के सदस्य जैसे-तैसे अपना काम चलाते हैं। ये देश सदा ही या तो सर्व-सत्ताधारियों यानी डिक्टेटरों के मातहत रहते हैं या इनकी हालत क़रीब-क़रीब ऐसी ही रहती है। व्यक्तियों या छोटे-छोटे समूहों की इन सरकारों का आधार पशुबल होता है और उन्हें लगातार विरोधियों के दमन, हत्या, सख्त पाबन्दियों और क़ैद का तथा गुप्तचरों के जाल का सहारा ढूँढना पड़ता है।

योरप के बाहर भी तानाशाहियों का उदय हुआ। मैं तुम्हें तुर्की और कमाल-पाशा का हाल पहले ही बता चुका हूँ। दक्षिण अमेरिका में कई सर्वसत्ताधारी थे, लेकिन वहाँके लिए यह संस्था पुरानी हो चुकी थी, क्योंकि दक्षिणी अमेरिका के प्रजातंत्रों ने लोकसत्ता के विधि विधानों को कभी अच्छी नज़र से नहीं देखा।

तानाशाहियों की इस सूची में मैंने सोवियट यूनियन को शामिल नहीं किया है, क्योंकि वहाँकी तानाशाही है तो उतनी ही निर्दय जितनी और देशों की है मगर वह एक मुहल्लिफ़ क्रिस्म की है। वहाँ किसी व्यक्ति या छोटे-से समूह का बोलबाला नहीं है, बल्कि एक ऐसे सुसंगठित राजनैतिक दल का है जिसका मुख्य आधार मजदूरों पर है। वे इसे 'ग़रीबों का सर्वाधिकार' कहते हैं। इस तरह तानाशाही तीन क्रिस्म

करने के लिए एक बीच का ऐसा समय जरूरी है जिसमें सारी सत्ता शरीरों के हाथ में रहे और पूंजीवादी और अमीर वर्ग इस तरह दबाकर रखे जायें कि वे मजदूरों के राज्य के खिलाफ़ पड़यंत्र न रच सकें। इस तरह की सर्वोपरि सत्ता सोवियट यूनियन में है। उसमें सारे मजदूर, किसान और काम करनेवाले वर्गों का प्रतिनिधित्व है। इस तरह इस तानाशाही में ९० या ९५ फ़ीसदी लोगों की बाक़ी के ५ या १० फ़ीसदी लोगों पर हुकूमत होती है। यह तो हुई सिद्धान्त की बात। व्यवहार में साम्यवादी दल का नियंत्रण सोवियट पंचायतों पर है और साम्यवादी दल पर शासकों के गुट का अधिकार है। और जहाँतक ख़बरों पर पाबन्दी और विचार या कार्य की आज़ादी का ताल्लुक है, वहाँतक यह तानाशाही भी उतनी ही कड़ी है जितनी और किसी तरह की तानाशाही होसकती है। परन्तु चूँकि इसका आधार श्रमजीवियों का सद्भाव है, इसलिए उन्हें साथ रखना इसके लिए जरूरी है। और आख़री बात यह है कि इसमें मजदूरों का या किसी एक वर्ग का दूसरे वर्ग के लाभ के लिए शोषण नहीं होता। कोई शोषक वर्ग बाक़ी ही नहीं रहता। अगर कोई शोषण करता है तो वह राज्य ही करता है और वह सबकी भलाई के लिए करता है। यह याद रखने की बात है कि रूस में कभी लोकसत्तात्मक शासन नहीं रहा। वह तो १९१७ में निरंकुश राजतंत्र से एकदम छलांग मारकर साम्यवाद में पहुँच गया।

फ़्रैंसिस्ट दृष्टिकोण इससे बिल्कुल भिन्न है। मैं तुम्हें पिछले ख़त में बता चुका हूँ कि यह जान सकना आसान नहीं है कि फ़्रैंसिस्टों के क्या उसूल हैं। उनके कोई निश्चित उसूल मालूम नहीं होते। मगर इसमें कोई शक़ नहीं कि लोकसत्ता के वे खिलाफ़ हैं। हाँ, लोकसत्ता का उनका विरोध और कम्यूनिस्टों (साम्यवादियों) का विरोध बिल्कुल जुदा है। साम्यवादी लोकसत्ता के खिलाफ़ इसलिए हैं कि यह असली चीज़ नहीं है, बनावटी चीज़ है। फ़्रैंसिस्ट लोकसत्ता के सिद्धान्त और विचार के ही खिलाफ़ हैं। वे अपनी पूरी ताक़त के साथ लोकसत्ता की निन्दा करते हैं। मुसोलिनी ने उसे 'सड़ी हुई लाश' की पदवी दी है। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के विचार से भी फ़्रैंसिस्टों को उतनी ही नफ़रत है। उनके ख़याल से राज्य ही सब कुछ है, व्यक्ति की कोई गिनती वहीं। (साम्यवादी भी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को बहुत महत्व नहीं देते)। उन्नीसवीं सदी की उदार लोकसत्ता का पुजारी बेचारा मैज़िनी आज जिन्दा होता तो वह अपने देश-बन्धु मुसोलिनी से क्या कहता !

साम्यवादियों और फ़्रैंसिस्टों को ही नहीं, और बहुत-से लोगों को भी, जिन्होंने वर्तमान युग के झगड़ों पर विचार किया है, इस पुराने विचार से असन्तोष होगया है कि मताधिकार दे देने का ही नाम लोकसत्ता है। लोकसत्ता का अर्थ है

“हमारी प्रतिनिधि संस्था पार्लमेण्ट तेजी के साथ एक शासन-समूह के हाथ का खिलाती बनती जा रही है और उसके हुकों का पालन भग्न कर देना उसका काम रह गया है। इस समूह का चुनाव एक अपूर्ण और भद्दे निर्वाचन-यन्त्र के द्वारा होता है।”

इस तरह उन्नीसवीं सदी की लोकसत्ताओं और पार्लमेण्टों का असर सभी जगह कम हो रहा है। कुछ देशों में तो इन्हें खुले और बहुत भद्दे ढंग से रद्द कर दिया गया है और कुछ देशों में उनका कोई अर्थ नहीं रह गया है। वे धीरे-धीरे एक गम्भीर और थोड़ा तमाशा होती जा रही हैं। एक इतिहासकार ने पार्लमेण्टों के इस पतन की तुलना उन्नीसवीं सदी के राजाशाही के पतन से की है। इस लेखक के मत से पार्लमेण्टें भी उसी तरह निबल और दिखावटी चीजें हो जायेंगी और होती जा रही हैं; वे दीखने में बड़ी और महत्वपूर्ण रहेंगी, मगर उनका अर्थ कुछ भी नहीं रहेगा—जिस तरह कि इंग्लैण्ड और दूसरे देशों में राजा की असली सत्ता जाती रही और वह सिर्फ प्रदर्शन के लिए बंध शासक मात्र रह गया।

यह सब क्यों हुआ ? जिस लोकसत्ता का आदर्श असंख्य मनुष्यों को सौ वर्ष से भी अधिक प्रेरणा देता रहा और जिसपर हजारों ने अपने प्राण निछावर कर दिये, वह आज इतनी नापसन्द क्यों होगई ? ऐसे परिवर्तन काफ़ी कारणों के बिना तो हुआ नहीं करते। उनका आधार अस्थिरचित्त जनता की सनक भी नहीं होता। अवश्य ही जीवन की आधुनिक परिस्थिति में कोई बात ऐसी है जो उन्नीसवीं सदी की नियमित लोकसत्ता के साथ मेल नहीं खाती। यह विषय दिलचस्प और पेचीदा है। मैं इसपर यहाँ विस्तार से तो नहीं कह सकता, मगर दो-एक बातें तुम्हारे विचार के लिए रखता हूँ।

मैंने पिछले पैसे में लोकसत्ता का जिक्र करते वक़्त ‘नियमित’ शब्द काम में लिया है। साम्यवादियों का कहना है कि वह सच्ची लोकसत्ता नहीं थी। वह सिर्फ लोकसत्ता का परदा था जिसके नीचे यह सत्य छिपा रहता था कि एक वर्ग दूसरे वर्गों पर हुकूमत कर रहा है। उनके कहने के मुताबिक़ लोकसत्ता पूंजीवादी वर्ग की सर्वोपरि सत्ता के लिए परदे का काम देती थी। उनकी राय में यह धनिक-राज्य था। सर्वसाधारण को जो मताधिकार मिला था, और जिसकी इतनी बड़ाई की गई है, उससे उन्हें चार-पाँच वर्षों में एक बार इतना-सा कहने का हक़ मिला था कि ‘अ’ उनपर राज्य करे और उनका शोषण करे या ‘ब’ करे। हर हालत में अमीर शरीरों का खून चूसते रहे। सच्ची लोकसत्ता तभी कायम हो सकती है जब यह वर्ग-राज्य और शोषण न रहे और सिर्फ एक ही वर्ग बाक़ी रह जाय। परन्तु ऐसे समाजवादी शासन का विकास

व्यक्तित्व के द्वारा नहीं करना चाहिए। यह लोकसत्तात्मक ढंग है। उन्हें विकास फ़ैसिस्ट तरीक़े पर करना चाहिए और संसार की अत्म-चेतना के रूप में यानी अपने अहं के विकसित रूप में करना चाहिए। (इसका क्या अर्थ हुआ, यह मेरी समझ में खाक भी नहीं आया)। इस तरह इस दृष्टिबिन्दु में व्यक्तित्व और स्वातंत्र्य का कोई स्थान नहीं। इसके अनुसार सच्चा व्यक्तित्व और व्यक्ति-स्वातंत्र्य वही है जो मनुष्य अपनेको किसी दूसरी चीज़ यानी राज्य में विलीन करके प्राप्त करता है।'

“कुटुम्ब, राज्य और आत्मा में मिल जाने से मेरा व्यक्तित्व मिटता नहीं है बल्कि ऊँचा उठता है, मज़बूत होता और बढ़ता है।”

जेण्टाइल फिर कहता है:—

“शक्ति किसी भी तरह की हो, यदि उससे संकल्प पर असर पड़ता है तो वह नैतिक शक्ति ही है, उसके पक्ष में दलील चाहे उपदेश की दी जाय या डण्डे की।”

इससे हम समझ सकते हैं कि भारत में जब सरकार लाठी-चार्ज करवाती है तो कितने नैतिकबल को काम में लेती है!

ये सब बातें तो ऐसी हैं कि जो चीज़ हो चुकी हो उसका अर्थ खास तरह से लगाया जाय या उसे न्याय्य सिद्ध किया जाय। यह भी कहा जाता है कि फ़ैसिज्म का उद्देश्य 'सामूहिक राज्य' (Corporate State) की स्थापना करना है। मेरा अनुमान है कि ऐसे राज्य में सब लोग सामूहिक भलाई के लिए मिल-जुलकर काम करते हैं। परन्तु अभी तक इटली में या और कहीं भी ऐसा राज्य प्रकट नहीं हुआ है। इटली में भी और पूँजीवादी देशों की तरह ही पूँजीवाद मजे से अपना काम कर रहा है।

चूँकि फ़ैसिज्म और मुल्कों में भी फैल गया है, इससे जाहिर है कि यह इटली की ही कोई विशेषता नहीं है, बल्कि एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी देश में खास तरह के आर्थिक और सामाजिक हालात होने पर पैदा होसकती है। जब कभी मजदूरों का बल बढ़ता है और वे सचमुच पूँजीवादी राज्य के लिए ख़तरनाक होजाते हैं, तो पूँजीवादी वर्ग का अपने बचाव की कोशिश करना स्वाभाविक है। आम तौर पर मजदूरों की तरफ़ से ऐसा ख़तरा भयंकर आर्थिक संकट के अवसरों पर ही पैदा होता है। अगर सम्पन्न और शासक वर्ग उस वक़्त पुलिस और फ़ौज की मदद लेकर मामूली लोकसत्तात्मक साधनों से मजदूरों को नहीं दबा सकते हैं, तो वे फ़ैसिस्ट तरीक़े का सहारा लेते हैं। यह इस तरह कि एक लोकप्रिय सार्वजनिक आन्दोलन खड़ कर दिया जाता है; उसमें कुछ रणनाद या नारे तो सर्वसाधारण को पसन्द आनेवाले रख दिये जाते हैं, पर वह आन्दोलन सम्पत्तिशाली वर्ग की रक्षा के ही लिए होता है। इस आन्दोलन की रीढ़ नीचे दर्जे का मध्यमवर्ग होता है, क्योंकि इसमें बेकारों की तादाद बहुत होती है। इन

समानता, और समानता के समाज में ही लोकसत्ता फल-फूल सकती है। यह स्पष्ट है कि सबको मताधिकार दे देने से ही समानता का समाज कायम नहीं होजाता। वयस्क-मताधिकार यानी सब बालिश स्त्री-पुरुषों को राय देने का हक दे देने या ऐसी ही और कुछ बातें होजाने पर भी आज भयंकर असमानता मौजूद है। इसलिए लोकसत्ता को मौला देना हो तो समानता का समाज कायम होना लाजिमी है। इस तर्क से कई तरह के दूसरे आदर्शों और साधनों का सवाल खड़ा होजाता है। परन्तु यह बात सभी लोग निर्विवाद रूप से मानते हैं कि आजकल की पार्लमेण्टें बहुत ही असन्तोषजनक हैं।

फ्रांसिज्म को जरा और गहरी नज़र से देखें और मालूम करें कि यह क्या है। इसे हिंसा पर गर्व और शान्तिप्रियता से नफ़रत है। इटली के विश्वकोष में मुसोलिनी ने लिखा है :—

“फ्रांसिज्म का न तो शाश्वत शान्ति की आवश्यकता में विश्वास है और न उसकी उपयोगिता में। शान्तिवाद में जड़ोजहद से बचने की वृत्ति छिपी हुई है। वह मूलतः कायरता ही है। इसलिए फ्रांसिज्म क्रुर्वानी के मुक्ताविले में अमन को ठुकराता है। युद्ध और सिर्फ़ युद्ध से ही मनुष्य की शक्तियों की अधिक-से-अधिक जोरआज-माई होती है और उसको स्वीकार करने का साहस करनेवाली जातियों के सिर पर ही उच्चता का सेहरा बँधता है। और सब तरह की परीक्षाएँ नक़ली होती हैं। वे मनुष्य के सामने जीवन या मरण के चुनाव का सवाल पेश नहीं करतीं।”

फ्रांसिज्म उत्कट राष्ट्रवादी और साम्यवाद अन्तर्राष्ट्रीय है। फ्रांसिज्म अन्तर्राष्ट्रीयता का विरोध करता है। उसने राज्य को एक देवता बना दिया है। इस देवता के चरणों में व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों की बलि चढ़नी ही चाहिए। उसके लिए अपने देश के सिवा और सब मुल्क शैर हैं और करीब-करीब दुश्मन जैसे हैं। यहूदियों को विदेशी समझकर आमतौर पर सताया जाता है। फ्रांसिज्म में भले ही कुछ धनिक-विरोधी नारों और क्रान्तिकारी साधनों का स्थान हो, परन्तु उसका सम्पत्तिशाली और प्रतिगामी वर्गों से गठबन्धन जरूर है।

ये फ्रांसिज्म की कुछ सूरतें हैं। उसका कोई तत्त्वज्ञान हो तो उसे समझ सकना कठिन है। हम देख चुके हैं कि इसका आरम्भ सत्ता की लालसा के साथ हुआ है। जब कामयाबी मिल गई, तब उसका तत्त्वज्ञान बनाने की कोशिश की गई। तुम चक्कर में तो पड़ोगी मगर तुम्हें फ्रांसिज्म की कल्पना हो जायगी, इसलिए एक प्रसिद्ध फ्रांसिस्ट तत्त्ववेत्ता का उद्धरण दूंगा। उसका नाम जियोवानी जेण्टाइल है। यह फ्रांसिज्म का अधिकार-प्राप्त तत्त्ववेत्ता माना जाता है और फ्रांसिस्ट सरकार का एक मंत्री भी रह चुका है। जेण्टाइल का कहना है कि ‘लोगों को अपना आत्मानुभव या विकास अपने

चीन की क्रान्ति और प्रति-क्रान्ति

२६ जून, १९३३

अब हम योरोप और उसके असन्तोष को छोड़कर उससे भी बड़े उपद्रव के क्षेत्र, तुर्क पूर्व, चीन और जापान में चलें। चीन पर लिखे हुए अपने पिछले खत में मैंने तुम्हें बताया था कि इस युवा प्रजातन्त्र को कितनी मुश्किलें पेश आई हैं। यह प्रजातन्त्र संसार की अत्यन्त प्राचीन और महत्त्वपूर्ण संस्कृति की भूमि में स्थापित हुआ। उस वक्त देश तहस-नहस होता दिखाई दे रहा था और तूशन और महातूशन नाम से पुकारे जानेवाले बेउसूल सेनानायकों की ताकत बढ़ रही थी। ये लोग हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। इन्हें अक्सर साम्राज्यवादी राष्ट्रों की तरफ से उत्साह और सहायता दी जाती थी, क्योंकि इन राष्ट्रों का स्वार्थ इसीमें था कि चीन दुर्बल हो और आपस में लड़ता रहे। इन तूशनों के कोई उसूल नहीं थे। उनमें से हरेक अपनी-अपनी बड़ाई चाहता था और वहाँ जो छोटे-छोटे गृह-युद्ध चलते रहते थे उनमें वे कभी इस तरफ हो जाते थे और कभी उस तरफ। उनके और उनकी सेनाओं के गुजर का भार अभागों किसानों पर पड़ता था। मैं तुम्हें यह भी बता चुका हूँ कि चीन के महान् नेता डॉक्टर सनयातसेन ने दक्षिणी चीन में कैंप्टन नगर में राष्ट्रीय सरकार संगठित की थी। इस महापुरुष ने जीवन-भर चीन की आजादी के लिए कोशिश की थी।

सारे देश पर विदेशी पूँजीवादी राष्ट्रों के आर्थिक स्वार्थों का प्रभाव था। ये शंघाई और हांगकांग वगैरह बड़े-बड़े बन्दरगाहवाले शहरों में बैठकर चीन के सारे विदेशी व्यापार का नियंत्रण करते थे। डॉक्टर सन ने बिल्कुल सच कहा था कि आर्थिक दृष्टि से चीन इन राष्ट्रों का उपनिवेश है। एक मालिक का होना ही कम बुरी बात नहीं होती। कई मालिकों का होना कभी-कभी उससे भी बुरी बात है। डॉक्टर सन ने देश का औद्योगिक विकास करने और अपने घर का सुधार करने के लिए विदेशों की सहायता लेने की कोशिश की थी। अमेरिका और ब्रिटेन से खास उम्मीदें थीं, मगर दोनों ने या और भी किसी साम्राज्यवादी राष्ट्र ने सहायता नहीं दी। चीन के शोषण में सबका स्वार्थ था। वे उसकी भलाई या बल-वृद्धि नहीं चाहते थे। तब १९२४ में डॉक्टर सन ने रूस की तरफ नज़र डाली।

चीन के विद्यार्थियों और शिक्षित वर्ग में गुप्त रूप से पर तेज़ी के साथ साम्यवाद बढ़ रहा था। १९२० में एक साम्यवादी दल बन चुका था और वह गुप्त समिति के रूप में काम कर रहा, क्योंकि वहाँ की मुक्तलिफ़ सरकारों ने उसे खुले तौर पर तो

नारों से और अपनी हालत सुधारने की उम्मीदों से आकर्षित होकर बहुत-से राजनैतिक विचारों में पिछड़े हुए और असंगठित मजदूर भी शामिल होजाते हैं। ऐसे आन्दोलन को बड़े-बड़े अमीरों से रुपये की मदद मिलती है, क्योंकि उन्हें इससे फ़ायदा होने की उम्मीद होती है। देश की पूंजीवादी सरकार इस आन्दोलन के हिंसा-धर्म और हिंसा-कार्य को जानते और देखते हुए भी इसलिए सहन कर लेती है कि यह उसके समान-शत्रु—समाजवादी मजदूर आन्दोलन—से लोहा लेता है। फ़्रैंसिज्म दल के रूप में भी और देश की सरकार बन जाने पर और भी प्रबल होकर मजदूरों के संगठन का नाश करता है और सब विरोधियों को भयभीत रखता है।

इस तरह फ़्रैंसिज्म का उदय उस वक़्त होता है जब बढ़ते हुए समाजवाद और जमे हुए पूंजीवाद में वर्ग-युद्ध तीव्र और भयंकर होजाता है। यह सामाजिक संघर्ष किसी ग़लतफ़हमी से पैदा नहीं होता, बल्कि हमारे वर्तमान समाज के स्वाभाविक विरोधी हितों और संघर्षों को अच्छी तरह समझने के कारण होता है। इन संघर्षों की उपेक्षा करने से ये नहीं मिटते। जिन लोगों को वर्तमान व्यवस्था से कष्ट होता है वे ज्यों-ज्यों इस हित-विरोध को समझते जाते हैं त्यों-त्यों उनमें अपने हिस्से से वंचित रहने पर अधिक गुस्सा पैदा होता है। जिनके पास सब कुछ है वे कुछ भी छोड़ने को तैयार नहीं होते। वस इसीसे संघर्ष तीव्र होजाता है। जबतक पूंजीवाद अपनी सत्ता कायम रखने के लिए लोकसत्तात्मक संस्थाओं के साधन काम में ले सकता है, तबतक लोक-सत्ता को कायम रहने दिया जाता है। जब यह सम्भव नहीं रहता, तब पूंजीवाद लोक-सत्ता को परे फेंक देता है और हिंसा और आतंकवाद का खुला फ़्रैंसिस्ट तरीक़ा इस्ति-यार कर लेता है।

शायद रूस के सिवा योरोप के सभी देशों में फ़्रैंसिज्म थोड़े-बहुत प्रमाण में मौजूद है। इसकी सबसे ताज़ा जीत जर्मनी में हुई है। इंग्लैण्ड में भी शासकवर्ग में फ़्रैंसिस्ट विचार फैल रहे हैं और उनका प्रयोग हम हिन्दुस्तान में तो अक्सर देखते ही हैं। संसार की रंग-भूमि पर आज फ़्रैंसिज्म पूंजीवाद का अन्तिम अस्त्र बनकर साम्यवाद से जुझ रहा है।

परन्तु फ़्रैंसिज्म की और बातें जाने दें तो भी उससे संसार को सतानेवाली आर्थिक समस्याओं का भी कोई हल नहीं मिलता। इसका तीव्र राष्ट्रवाद संसार की एक-दूसरे पर निर्भर रहने की वृत्ति के विरुद्ध पड़ता है और पूंजीवाद के पतन से उत्पन्न होने-वाली समस्याएँ बढ़ती हैं। दूसरे देशों के प्रति इसकी जो आक्रमणकारी मनोवृत्ति है उससे राष्ट्रों में परस्पर संघर्ष पैदा होता है और इससे अक्सर युद्ध की नौबत आ जाती है।

जमींदारी बनती है तो वारिसों में बँटकर उसके जल्दी ही छोटे-छोटे हिस्से होजाते हैं। करीब-करीब आधे किसानों के अपने खेत हैं और आधे जमींदारों की जमीन जोतते हैं। इस तरह चीन छोटे-छोटे बेशुमार किसानों का देश है। सैकड़ों वर्षों से चीनी किसानों को यह श्रेय है कि वे जमीन में से अधिक-से-अधिक सार निकाल लेते हैं। उनके खेत इतने छोटे हैं कि उन्हें मजबूर होकर ऐसा करना पड़ता है। वे अपनी विलक्षण सूझ काम में लाते हैं और भयंकर परिश्रम करते हैं। मेहनत बचाने की कृषि की आधुनिक सुविधायें उनके पास नहीं हैं। वर्ना जितना फल उन्हें मिलता है उसके लिए इतनी कठोर मेहनत न करनी पड़ती।

इस सारी सूझ और कड़ी मेहनत के बावजूद लगभग आधे किसानों का आमद-खर्च बराबर नहीं होता था और वे अपनी छोटी-छोटी उम्मीदें यही आधेपेट गुजार देते थे। हिन्दुस्तान के बेशुमार किसानों का भी यही हाल होता है। चीनी किसान सदा ही नंगे-भूखे-से रहते थे और जब अकाल और बाढ़ का संकट आता तो लाखों बेमौत मर जाते। बोरोडीन की सूचना पर डॉक्टर सन की सरकार ने किसानों और मजदूरों की मुसीबत दूर करने के लिए कानून बनाये, लगान पौना कर दिया गया, मजदूरों के लिए आठ घण्टे की मेहनत और जीवन-निर्वाह के योग्य मजदूरी मुकर्रर की गई और किसान-संघ स्थापित किये गये। स्वभावतः इन सुधारों का सर्वसाधारण ने स्वागत किया और उनके दिल उत्साह से भर गये, वे नये संघों में धड़ाधड़ शामिल होगये और कॅण्टन-सरकार की मदद के लिए खड़े होगये।

इस तरह कॅण्टन ने अपनी शक्ति मजबूत करके उत्तर के तूशनों से भिड़न्त करने की तैयारी करली। एक फ़ौजी कालेज खोल दिया गया और सेना का निर्माण किया गया। कॅण्टन में ही नहीं, सारे चीन में और कुछ हद तक पूर्व-भर में एक दिलचस्प घटना यह होरही है कि धार्मिक सत्ता का स्थान भौतिक सत्ता लेती जा रही है। संकुचित अर्थ में तो चीन कभी धार्मिक देश नहीं रहा। अब वह और भी भौतिक होगया है। पहले शिक्षा धार्मिक थी, अब भौतिक करदी गई है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि चीन के बहुत-से प्राचीन मन्दिर अब सार्वजनिक उपयोग के काम में लाये जा रहे हैं। कॅण्टन के एक मशहूर और पुराने मन्दिर में आजकल पुलिस को तालीम दी जाती है। दूसरे स्थान पर मन्दिरों को बदलकर तरकारी के बाजार बना दिये गये हैं। धार्मिक अन्ध-विश्वास को दूर करने के लिए संस्थायें बन गई हैं। वे प्रचार-कार्य करती हैं।

डॉक्टर सनयातसेन १९२५ के मार्च में मर गये, मगर कॅण्टन-सरकार की ताकत बढ़ती गई। बोरोडीन उसका सलाहकार बना रहा। थोड़े समय बाद कुछ घटनायें

काम करने नहीं दिया। डॉक्टर सन साम्यवाद से दूर ही रहते थे। उनके मशहूर 'जनता के तीन उद्गारों' से मालूम होता है कि वे नरम समाजवादी थे। मगर उनपर इस बात की अच्छी छाप पड़ी कि सोवियट रूस का चीन और दूसरे पूर्वी राष्ट्रों के साथ उदार और अच्छा वर्ताव है। उन्होंने रूस के साथ दोस्ताना ताल्लुकात पैदा कर लिये और कुछ रूसी सलाहकार रख लिये। इनमें से बोरोडीन ज्यादा मशहूर था। वह एक निहायत क्राविल बोलशेविक था। बोरोडीन कैण्टन के राष्ट्रीय दल काउ-मिन-तांग के लिए एक ज़बरदस्त मददगार साबित हुआ। उसने चीन में एक ऐसे बलशाली राष्ट्रीय दल के निर्माण और संगठन के लिए परिश्रम किया जिसकी पीठ पर सर्वसाधारण का सहारा हो। उसने बिल्कुल साम्यवादी ढंग पर ही काम करने की कोशिश नहीं की। उसने दल की राष्ट्रीय बुनियाद क़ायम रखी, मगर काउ-मिन-तांग में साम्यवादियों के लिए भरती होने का दरवाज़ा खुलवा दिया। इस तरह राष्ट्रीय काउ-मिन-तांग और साम्यवादीदलों में एक तरह का बेज़ावता मेल होगया। काउ-मिन-तांग के बहुत-से अनुदार और धनी सदस्यों को साम्यवादियों का यह सम्पर्क पसन्द नहीं था। उधर बहुत-से साम्यवादियों को भी यह अच्छा नहीं लगता था। इसका कारण यह था कि उन्हें अपना कार्यक्रम नरम बनाना पड़ता था और बहुत-सी ऐसी बातें करने से बाज़ रहना पड़ता था जो वे दूसरी सूरत में करते। यह मेल बहुत दिन नहीं टिका। हम देखेंगे कि यह एक नाज़ुक मौक़े पर टूटा और उससे चीन पर बड़ी विपत्ति आई। जिन दो या अधिक वर्गों के स्वार्थ आपस में टकराते हों उन्हें एक ही दल में मिलाकर रखना हमेशा मुश्किल होता है। परन्तु जबतक यह मेल क़ायम रहा तबतक ख़ूब कामयाब हुआ और काउ-मिन-तांग और कैण्टन सरकार का बल बढ़ता गया। किसान-सभाओं और मज़दूर-संघों को प्रोत्साहन दिया गया और उनका तेज़ी से विस्तार हुआ। आम जनता की इसी मदद से कैण्टन की काउ-मिन-तांग की सच्ची सत्ता प्राप्त हुई। इसीसे ज़मीन के मालिक नेताओं के कान खड़े हुए और आगे चलकर उन्हें दल को तहस-नहस करने की प्रेरणा मिली।

बहुत बातों में ज़बरदस्त फ़र्क़ होते हुए भी चीन और भारत की स्थिति में बड़ी समानता है। चीन असल में कृषि-प्रधान देश है। वहाँ बेशुमार किसान हैं। पूंजीवादी उद्योग सिर्फ़ छः-सात बड़े-बड़े शहरों में ही हैं और विदेशियों के हाथों में हैं। करोड़ों किसान क़र्ज़ के भयंकर बोझ से पिसे जा रहे हैं। लगान की दर बहुत ऊँची है और हिन्दुस्तान की तरह वहाँ भी किसानों को कई महीने मजबूरन बेकार रहना पड़ता है। उन दिनों खेतों में बहुत कम काम रहता है। इस तरह इस ख़ाली समय को भरने और उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए गृह-उद्योगों की ज़रूरत है। अब तो वहाँ बहुत-से गृह-उद्योग हो भी गये हैं। वहाँ बड़ी-बड़ी ज़मींदारियाँ बहुत कम हैं। जब कोई बड़ी

और उसे हर तरह मदद दी। कैंपटन की सेना के खिलाफ लड़ने के लिए जो फ़ौजें भेजी जातीं वे शायद ही कभी लड़तीं और अक्सर सब सामान-सहित उसमें आकर मिल जातीं। १९२६ का साल खत्म होने से पहले राष्ट्रवादियों ने आधा चीन पार कर लिया और यांगत्सी नदी पर हूँकन का बड़ा शहर ले लिया। उन्होंने अपनी राजधानी कैंपटन से हटाकर हूँकन में करली और उसका नाम बदल कर वूहन रख लिया। उत्तरी सेनापतियों को पस्त करके भगा दिया गया। साम्राज्यवादी सत्ताओं की अकस्मात् आंख खुली। उन्हें बुरा तो लगा; परन्तु उन्होंने देख लिया कि एक नवीन और आक्रमणकारी राष्ट्रवादी चीन सामने खड़ा है, जो समानता का दावा करता है और धमकी में आने से इन्कार करता है।

१९२७ के शुरू में राष्ट्रवादियों ने हूँकन की ब्रिटिश रियायती बस्ती पर कब्जा करने की कोशिश की। इसपर चीनियों और अंग्रेजों में संघर्ष हो गया। अगर इस तरह का उत्तेजनापूर्ण रख चीनी लोग पहले कभी इस्तिहार करते तो लड़ाई छिड़ जाती और ब्रिटिश सरकार उन्हें कुचल डालती। इतना ही नहीं, वह उन्हें डरा-धमकाकर हर्जाने और रियायतें वसूल करती। १८४० के अफ़ीम के युद्ध से अबतक सदा यही रिवाज चला आता था, यह हम देख चुके हैं। मगर अब जमाना बदल गया था और अंग्रेजों के मुक़ाबिले में नई तरह का चीन खड़ा था। इसलिए तुरन्त और पहली ही बार अंग्रेजों की नीति बदली और नवीन चीन के प्रति उन्होंने नरम रख इस्तिहार किया। हूँकन की बस्ती का मामला छोटा-सा था और आसानी से तय हो सकता था। परन्तु उससे थोड़ी ही दूर पर और राष्ट्रवादियों की कूच के रास्ते में ही शंघाई का बड़ा बन्दरगाह था। चीन में विदेशियों के अधिकार में यह सबसे बड़ा और कीमती रियायती क्षेत्र था। शंघाई की क्रिस्मत के साथ विदेशियों के बड़े-बड़े स्वार्थ लगे हुए थे। वह शहर—नहीं, उसका रियायती भाग—विदेशी नियंत्रण में था और क़रीब-क़रीब चीनी सरकार की सत्ता से स्वतंत्र था। जब चीन की राष्ट्रीय सेना शंघाई के क़रीब पहुँचने लगी, तो शंघाई के इन विदेशियों और उनकी सरकारों को बड़ी चिन्ता हुई और उनकी सेना और लड़ाकू जहाज़ शीघ्र उस बन्दर पर पहुँच गये। १९२७ के शुरू जनवरी में ब्रिटिश सरकार ने खासतौर पर बड़ी-सी सेना शंघाई भेज दी। इसमें हिन्दुस्तानी सिपाही भी थे।

उस वक़्त हूँकन या वूहन में क़ायम राष्ट्रीय सरकार के सामने एक मुश्किल समस्या पैदा होगई—आगे बढ़ा जाय या न बढ़ा जाय, और शंघाई को ले लिया जाय या नहीं? उन्हें अबतक आसानी से जो कामयाबी मिली थी उससे उनका हौसला बढ़ गया था और उनमें उत्साह भर गया था। शंघाई या भी अत्यन्त आकर्षक

ऐसी हुई जिनसे चीन-निवासी विदेशी पूंजीपतियों और खास तौर पर अंग्रेजों के खिलाफ गुस्से से भर गये। शंघाई की मिलों में हड़तालें हुई थीं और १९२५ की मई में एक प्रदर्शन में एक मजदूर मारा गया। उसकी स्मृति में एक विशाल सामूहिक प्रार्थना का आयोजन किया गया था। उस अवसर पर विद्यार्थियों और मजदूरों ने साम्राज्य-विरोधी प्रदर्शन किये। एक अंग्रेज पुलिस अफसर ने अपने मातहत सिक्ख सिपाहियों को इस भीड़ पर गोली चलाने का हुक्म दिया। हुक्म मारने के लिए गोली चलाने का था। कई छात्र मारे गये। इससे चीन-भर में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्से की आग भभक उठी। बाद की एक घटना ने स्थिति को और भी बिगाड़ दिया। यह घटना १९२५ के जून में कॅण्टन की शमीन नामक विदेशी बस्ती में हुई। वहाँ मुख्यतः चीनी विद्यार्थियों की भीड़ पर मशीनगन चला दी गई। ५२ आदमी मारे गये और बहुत-से घायल हुए। इस घटना को 'शमीन का हत्या-काण्ड' नाम दिया गया और इसके लिए मुख्यतः अंग्रेजों को दोषी ठहराया गया। कॅण्टन में ब्रिटिश माल के राज-नैतिक बहिष्कार की घोषणा कर दी गई और कई महीने तक हांगकांग का व्यापार बन्द कर दिया गया। इससे अंग्रेज व्यवसायियों और ब्रिटिश सरकार को बड़ा नुकसान हुआ। तुम्हें शायद मालूम है कि हांगकांग दक्षिण चीन में अंग्रेजों का इलाका है। यह कॅण्टन के पास ही है और यहाँसे बहुत बड़ा व्यापार होता है।

डॉक्टर सन की मृत्यु के बाद कॅण्टन-सरकार के दाहिने और बायें अंगों यानी नरम और गरम दलों में लगातार फशमकश रही। कभी एक पक्ष के हाथ में सत्ता आजाती तो कभी दूसरे के हाथ में। १९२६ के मध्य में नरम दली च्यांग-काई-शेक प्रधान सेनापति बना और उसने साम्यवादियों को धकेल बाहर करना शुरू कर दिया। फिर भी दोनों बल किसी तरह एक हद तक साथ-साथ काम करते रहे। उनके दिलों में परस्पर अविश्वास जरूर था। उसके बाद कॅण्टन की सेना का तूशनों से लड़ने और उन्हें निकाल बाहर करने के लिए उत्तर की तरफ बढ़ना शुरू हुआ। उसका उद्देश्य सारे देश में एक राष्ट्रीय सरकार कायम करना था। यह कूच एक असाधारण घटना थी और शीघ्र ही सारे संसार का ध्यान उसकी तरफ खिंच गया। असल में लड़ाई भी बहुत कम हुई और दक्षिण की सेना फ़तह-पर-फ़तह हासिल करती हुई तेज़ी से आगे बढ़ती गई। उत्तर वालों में फूट थी, लेकिन दक्षिण वालों की असली ताकत इस बात में थी कि किसान और मजदूर उन्हें चाहते थे। उनकी फ़ौज के आगे-आगे प्रचारकों और आन्दोलकों की टुकड़ी चलती थी और वह किसानों और मजदूरों के संघ संगठित कर-करके उन्हें समझाती थी कि कॅण्टन-सरकार के मातहत होने पर उन्हें क्या-क्या लाभ होंगे। इसलिए नगर और गाँव दोनों ने बढ़ती हुई फ़ौज का स्वागत किया

और नरम अंगों में फूट हुई। इससे राष्ट्रीय विजय का अन्त होगया और चीन पर विपत्ति आगई। क्रान्ति खत्म हुई और प्रति-क्रान्ति शुरू होगई।

च्यांग-काई-शेक ने हैकन-सरकार के बहुत-से मन्त्रियों की इच्छा के खिलाफ़ शंघाई पर कूच किया था। इसलिए दोनों दल एक-दूसरे के खिलाफ़ साजिश करने लगे। हैकनवालों ने सेना पर च्यांग का प्रभाव घटाने और उससे पिण्ड छुड़ाने की कोशिश की। च्यांग ने नानकिंग में दूसरी सरकार कायम करली। यह सब शंघाई की विजय के थोड़े दिन बाद ही होगया। हैकन की अपनी ही सरकार से विद्रोह करके अब च्यांग ने अपना स्वरूप पूरी तरह प्रकट कर दिया और साम्यवादियों, उग्रदलवालों और संघवाले मजदूरों पर हल्ला बोल दिया। जिन मजदूरों की बदौलत वह शंघाई पर इतनी आसानी से क़ब्ज़ा कर पाया था और जिन्होंने खुशी से पागल होकर उसका स्वागत किया था, उन्हींको अब उसने चुन-चुनकर सताया और कुचल दिया। बहुत लोगों को गोली या तलवार से मार दिया गया और हज़ारों को गिरफ़्तार करके जेलख़ाने भेज दिया गया। लोगों की धारणा यह थी कि राष्ट्रवादी शंघाई में स्वतन्त्रता की धारा बहायेंगे; और हुआ यह कि खून की नदियाँ बह निकलीं।

१९२७ के अप्रैल मास के इन्हीं दिनों में एक ही रोज़ पेकिंग और शंघाई के सोवियट दूतावासों की एकसाथ तलाशियाँ हुईं। यह साफ़ जाहिर था कि च्यांग-काई-शेक उत्तरी सेनानायक चैंग सोलिन से मिलकर कार्रवाई कर रहा है। वैसे इन दोनों में लड़ाई समझी जाती थी। पेकिंग और शंघाई दोनों में साम्यवादियों और प्रगति-शील मजदूरों का 'सफ़ाया' किया गया। साम्राज्यवादी सत्ताओं ने तो इन घटनाओं का स्वागत किया ही। उन्हें यह काम इसलिए पसन्द था कि इससे चीनी राष्ट्रवादियों की एकता भंग होकर उनका बल क्षीण होता था। यह बहुत मुमकिन है कि उस वक़्त च्यांग-काई-शेक का शंघाई-स्थित विदेशी राष्ट्रों से ख़ुफ़िया ताल्लुक हो। आगे चलकर तो इसमें कोई शक नहीं रहा कि उसने उनका सहयोग चाहा था। तुम्हें याद होगा कि लगभग उसी समय, यानी १९२७ के मई में, ब्रिटिश सरकार ने लन्दन के सोवियट भवन की तलाशी ली थी और फिर रूस के साथ ताल्लुकात तोड़ दिये थे।

इस तरह एक-दो महीने के अन्दर ही चीन का सारा नक्शा बदल गया। जो काऊ-मिन-तांग ऐष्य और विजय की पताका फहराता हुआ चीनी राष्ट्र का प्रतिनिधि था और सफलता का सेहरा सिर पर बांधे हुए विदेशी सत्ताओं के सम्मुख खड़ा हुआ था, वही काऊ-मिन-तांग अब तहत-नहत होगया था, उसके निम्न-निम्न अंग आपस में लड़ रहे थे, और जिन मजदूरों और किसानों ने उसे जीवन और बल दिया था वे ही अब

पुरस्कार । उधर वे केवल आगे बढ़ ही रहे थे और ५०० मील से भी ज्यादा लम्बा-चौड़ा इलाका पार कर आये थे, मगर उन्होंने वहाँ अपनी हालत मजबूत बनाने का उपाय नहीं किया था । इस हालत में अगर वे शंघाई पर हमला कर देते तो विदेशी सत्ताओं से भिड़कर मुश्किलों में फँस जाते । मुमकिन है इससे उन्होंने जो कुछ हासिल किया था वह भी ख़तरे में पड़ जाता । बोरोडीन ने सावधानी से चलने और स्थिति को मजबूत कर लेने की सलाह दी । उसकी राय यह थी कि राष्ट्रवादियों को शंघाई से अलग ही रहना चाहिए और चीन के दक्षिणी आधे भाग में, जहाँ उनका अधिकार कायम हो चुका था, अपनी स्थिति दृढ़ कर लेनी चाहिए । इस बीच में उत्तर में प्रचार-कार्य के जरिये ज़मीन तैयार करनी चाहिए । उसे उम्मीद थी कि बहुत जल्दी यानी एकाध वर्ष में ही सारा चीन राष्ट्रवाद के आगमन का स्वागत करेगा । उस वक़्त शंघाई को लेलेने, पेंकिंग पर कूच करने और विदेशी साम्राज्यवादी शक्तियों का सामना करने का मौका मिलेगा । क्रान्तिकारी होकर भी बोरोडीन ने यह सावधानी की सलाह दी, क्योंकि वह अनुभवी था और परिस्थिति विशेष को पैदा करनेवाले भिन्न-भिन्न तत्त्वों को समझ सकता था । परन्तु काउ-मिन-तांग के दाहिने अंग के नेताओं ने और खास तौर पर प्रधान सेनापति च्यांग-काई-शेक ने शंघाई की तरफ़ कूच करने पर जोर दिया । शंघाई को लेलेने की इस इच्छा का असली कारण आगे चलकर उस वक़्त जाहिर हुआ जब काउ-मिन-तांग के बिखरकर दो टुकड़े हो गये । इन दाहिने अंग के नेताओं को किसान और मजदूर-संघों की बढ़ती हुई ताक़त पसन्द न थी । बहुत-से सेनानायक खुद भू-स्वामी थे । इसलिए उन्होंने इन संघों को कुचल देने का फ़ौसला कर लिया, भले ही इसमें दल के दो टुकड़े हो जायें और राष्ट्रवादी पक्ष कमज़ोर हो जाय । शंघाई बड़े-बड़े चीनी अमीरों का महत्वपूर्ण केन्द्र था । दाहिने अंग के यानी प्रतिगामी सेनानायकों को यह विश्वास था कि ये अमीर उन्हें अपने दल के प्रगतिशील अंग और खासतौर पर साम्यवादियों से लड़ने में रुपये-पैसे की और दूसरी मदद देंगे । वे यह भी जानते थे कि ऐसी लड़ाई में उन्हें शंघाई के विदेशी साहूकारों और कारख़ानेदारों से भी मदद मिलेगी ।

इसलिए उन्होंने शंघाई पर कूच कर दी । १९२७ के १२ मार्च को शहर का चीनी हिस्सा उनके हाथ आ भी गया । विदेशी बस्ती पर उन्होंने हमला नहीं किया । शंघाई का यह पतन हुआ भी बहुत लड़ाई के बिना ही । विरोधी सेनायें राष्ट्रवादियों में जा मिलीं और राष्ट्रवादियों के पक्ष में मजदूरों की आम हड़ताल हो जाने से शंघाई की तत्कालीन सरकार का पूरी तरह पतन हो गया । दो दिन बाद नान्किंग का बड़ा शहर भी राष्ट्रीय सेना के कब्ज़े में आ गया । इसके बाद ही काउ-मिन-तांग दल के उग्र

का बोझ किसानों पर भयंकर होगया। बेशुमार सिपाही काम की तलाश में देहातों में आबारा फिरने और काम न मिलने पर अक्सर लूटमार करने लगे।

१९२७ के दिसम्बर में नान्किंग-सरकार और सोवियट रूस के सम्बन्ध टूट गये और साम्राज्यवादी सत्ताओं की शह पाकर नान्किंग ने आगे बढ़कर सोवियट का विरोध करने की वृत्ति धारण करली। अगर रूस बराबर युद्ध को टालता न रहता तो १९२७ में ही चीन से उसकी जंग छिड़ जाती। १९२९ में चीन ने फिर आक्रमणकारी ढंग इख्तियार किया। इस बार मंचूरिया में ऐसा हुआ। वहाँके सोवियट दूतावास की तलाशी ली गई और चीनी पूर्वी रेलवे के रूसी कर्मचारियों को बरखास्त कर दिया गया। यह रेलवे अधिकांश में रूसी सम्पत्ति थी और सोवियट सरकार ने चीनियों के खिलाफ़ तुरन्त कार्रवाई की। कुछ महीनों तक एक तरह का जंग रहा। उसके बाद सरकार ने पुरानी व्यवस्था फिर से क़ायम करने की रूसी माँग स्वीकार करली।

मंचूरिया से और उसके बीच में होकर निकली हुई रेलवे से कई बार अन्तर्राष्ट्रीय पेचीदगियाँ पैदा हुई हैं, क्योंकि वहाँ बहुत-से, और खासकर चीन, जापान और रूस के, स्वार्थ टकराते हैं। पिछले दो वर्षों में दुनियाभर के नाराज होने पर भी जापान ने उसपर पूरा नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की और उसमें वह प्रायः सफल भी हो गया है। इसका हाल अगले खत में बताऊंगा।

मैंने ऊपर जिक्र किया है कि चीन के कुछ हिस्सों में साम्यवादी सरकार क़ायम हुई है। यह सरकार आज भी मौजूद है। हाँ, यह स्पष्ट नहीं है कि इसका बल कितना है और इसका अधिकार कितने विस्तार में है। मालूम होता है दक्षिण के क्वांटंग प्रान्त के हेफ़ंग जिले में १९२७ के नवम्बर में पहलेपहल साम्यवादी शासन क़ायम हुआ था। यह 'हेफ़ंग सोवियट प्रजातन्त्र' कहलाया। इसका विकास अलग-अलग किसान-संघों में से हुआ था। चीन के भीतरी भागों में सोवियट इलाक़ा बढ़ता गया और १९३२ के मध्य तक असली चीन का छठा भाग उसमें शामिल होगया। इसका विस्तार २,५०,००० वर्गमील और जन-संख्या ५ करोड़ होगई। इस इलाक़े पर साम्यवादी दल का सम्पूर्ण अधिकार है और कहते हैं वहाँ अनुशासन का भी अच्छा पालन होता है। उन लोगों ने चार लाख आदमियों की लाल सेना बनाली है और उसके सहायक अंगों में लड़के और लड़कियाँ भी शामिल होगये हैं। नान्किंग और कैंप्टन दोनों सरकारों ने इन चीनी सोवियटों को कुचलने में कोई कसर नहीं रखी है, मगर अभीतक उन्हें सफलता नहीं मिली। इसका एक कारण तो यह है कि कम्यूनिस्ट इलाक़ा भीतरी भागों में है और वहाँ आवागमन के साधन अच्छे न होने के कारण वह दुर्गम है। दूसरा कारण यह है कि काउ-मिन-तांग का प्रभाव तो

सताये और मारे जाते थे। शंघाई के विदेशी स्वार्थी को फिर सुख की सांस लेने का मौका मिला। वे बड़े कृपा-पूर्ण हाथों से एक समूह को दूसरे के खिलाफ मदद देने लगे। मजदूरों को भड़काने और सताने का लाभदायक और सुखद मनोरंजन वे खास तौर पर करने लगे। शंघाई ही क्या, चीन भर के कारखानों के मजदूरों का मालिक लोग भयंकर शोषण करते थे और उनका जीवन और रहन-सहन अत्यन्त दुःखी था। संगठन से उन्हें बल मिला था और मालिकों को मजबूर होकर उनकी मजदूरी बढ़ानी पड़ी थी। इस कारण कारखानेदारों को—भले ही वे यूरोपियन हों या जापानी और चीनी हों—मजदूर-संघ नहीं मुहाते थे।

चीन में घटना-चक्र जिस तरह चल पड़ा उसपर मास्को में वीरोडीन की कड़ी टीका हुई और १९२७ के जुलाई में वह रुस चला गया। उसके जाते ही हूंकन के काउ-मिन-तांग दल का उग्र पक्ष छिन्न-भिन्न हो गया। अब काउ-मिन-तांग पर नानकिंग-सरकार का पूरा नियंत्रण हो गया और साम्यवादियों के खिलाफ खास तौर पर, और वैसे सभी उग्र दलवालों और मजदूर नेताओं के खिलाफ, लड़ाई जारी रही। इस अवसर पर जो लोग चीन छोड़कर चले गये, या जिन्हें निकाल दिया गया, उनमें से महान नेता सनयातसेन की आदरणीया विधवा श्रीमती सन भी थीं। उन्होंने दुःखित होकर घोषणा की कि सेनावादियों और दूसरे लोगों ने चीन की स्वतन्त्रता के लिए किया गया उनके पतिदेव का महान् कार्य नष्ट कर दिया। फिर भी ये सेनावादी डाक्टर सन के उसूलों की ही दुहाई देते रहे।

चीन फिर सेनानायकों की आपसी लड़ाइयों की भूल-भुलैया में फँस गया। कैंटन ने नानकिंग-सरकार से अलग होकर दक्षिण में अपनी स्वतन्त्र सरकार कायम कर ली। १९२८ में पेकिंग नानकिंग-सरकार के हाथ पड़ गया। उसका नाम बदलकर पीपिंग रख दिया गया। इसका अर्थ 'उत्तरी शान्ति' है और पेकिंग का अर्थ 'उत्तरी राजधानी' है। मगर अब वह राजधानी तो रहा नहीं।

पेकिंग के पतन के बाद—हाँ, अब तो हमें उसे पीपिंग कहना चाहिए—देश के मुक्तलिफ़ हिस्सों में गृह-युद्ध जारी रहा। कैंटन में तो अलग सरकार बन ही गई थी। उत्तर में भी भिन्न-भिन्न सेनानायक अपनी मनमानी करते, परस्पर लड़ते रहते और कभी-कभी थोड़े दिन के लिए आपस में मुलह कर लेते थे। कहने को कैंटन के सिवा सारे चीन में नानकिंग की राष्ट्रीय सरकार का शासन था; मगर कई इलाक़े उसकी हुकूमत के बाहर थे। उनमें से उल्लेखनीय एक बड़ा भीतरी प्रदेश था। वहाँ साम्यवादी शासन कायम हो गया था। नानकिंग-सरकार का मुख्य आधार, आर्थिक सहायता के लिए, शंघाई के कोठी वालों पर था। अलग-अलग सेनानायकों की बड़ी-बड़ी सेनाओं

सरदार रहें। धर्म, शिक्षा और सभी बातों में यही ध्यान रक्खा गया है। धर्म-विभाग सरकारी नियन्त्रण में है, मन्दिरों और धर्म-स्थानों पर सरकारी अफसरों का सीधा कब्जा है और पुजारी सरकारी नौकर हैं। इस तरह मन्दिरों और स्कूलों के जरिये प्रचार का एक जबरदस्त हथियार काम में लाया जा रहा है। वह लोगों को न सिर्फ देशभक्ति की शिक्षा देता रहता है, बल्कि उन्हें यह भी सिखाता रहता है कि सम्राट् दैवी पुरुष है और उसकी आज्ञा का पालन हर हालत में होता चाहिए। पुरानी वीर परम्परा से मिलते-जुलते अर्थ का जापानी शब्द 'बुशीदो' है। इसका अर्थ एक प्रकार की वंश-भक्ति है। इसी कल्पना का विस्तार करके उसे राज्य-भर पर लागू कर दिया गया है और सबसे ऊपर सम्राट् से इसका नाता जोड़ दिया गया है। असल में सम्राट् एक प्रतीक है और उसके नाम पर बड़े-बड़े भूस्वामी और सैनिक वर्ग शासन-सत्ता का संचालन करते हैं। उद्योगवाद के कारण जापान में एक अमीर वर्ग पैदा हुआ है, मगर बड़े-बड़े कारखानेदार भूस्वामियों में से ही बन गये हैं और इस कारण शक्ति एक अमीर वर्ग के हाथ में जाने की नीवत नहीं आई। नतीजा यह हुआ है कि जापान में थोड़े-से बलशाली परिवारों का देश के उद्योग और राजनीति दोनों पर एकाधिकार कायम होगया है।

जापान में बहुत जमाने से बौद्ध धर्म लोकप्रिय रहा है, लेकिन शिण्टो मत राष्ट्रीय धर्म अधिक है और वह पूर्वजों की पूजा पर जोर देता है। इस पूजा में राष्ट्र के पुराने सम्राटों और वीर पुरुषों की और खास तौर पर उन लोगों की पूजा शामिल है जो लड़ाई में मारे गये हों। इस तरह शिण्टो धर्म देश-प्रेम और सम्राट्-भक्ति के भावों का प्रचार करने के लिए एक जबरदस्त और कारगर हथियार बन गया है। जापानी लोगों का विलक्षण देश-प्रेम और अपने वतन के लिए कुर्बानी करने की उनकी तैयारी मशहूर है। मगर यह बात बहुत लोग नहीं जानते कि यह देश-प्रेम बहुत आक्रमणकारी और विश्वव्यापी साम्राज्य के सपने देखनेवाला है। १९१५ के करीब जापान में एक नया सम्प्रदाय निकला। यह 'ओमोतो क्यो' कहलाता है और इसका प्रचार देशभर में बड़ी तेजी से होगया। इस सम्प्रदाय का खास उसूल यह है कि जापान सारी दुनिया का शासक हो और सम्राट् उसका प्रमुख सत्ताधारी। इस सम्प्रदाय की तरफ से कहा गया था कि—

“हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि जापान का सम्राट् सारे संसार का शासक बन जाय, क्योंकि संसार में वही ऐसा शासक है जिसमें सबसे प्राचीन स्वर्गवासी पूर्वज से घिरासत में मिली हुई आध्यात्मिक लक्ष्य के प्रचार की भावना बाक़ी है।”

हम देख चुके हैं कि महायुद्ध के समय जापान ने चीन को डरा-धमकाकर उससे

जल्दी-जल्दी नष्ट हो रहा है और सोवियटों की लोकप्रियता और ताकत बढ़ रही है। साम्यवाद के लिए कहा जाता है कि वह उद्योग-प्रधान देशों में ही फलता-फूलता है, और ये चीनी सोवियट प्रजातन्त्र ठहरे बहुत पिछड़े हुए और दुनिया से अलग-थलग। फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि ये चीन के भविष्य का निर्माण करने में महत्वपूर्ण काम करेंगे। आज भी इनके अधिकार में बहुत बड़ा प्रदेश है। वह क़रीब-क़रीब संयुक्तप्रान्त, दिल्ली, पंजाब, और सीमाप्रान्त के सम्मिलित इलाक़े के बराबर है; यानी बनारस से पेशावर तक उसका विस्तार हो सकता है। आबादी भी संयुक्तप्रान्त से अधिक है।

आज मेरी गिरफ़्तारी को अठारह महीने होगये ! पूरा डेढ़ वर्ष निकल गया !

: १७८ :

जापान सारी दुनिया को अँगूठा दिखाता है

२९ जून, १९३३

हम चीन के अंग-भंग की दुःखद कहानी सुन चुके हैं। हमने यह भी देख लिया कि किस तरह क्रान्ति पहले तो विजयी हुई और फिर अचानक वह वेदम होगई और भयंकर प्रति-क्रान्ति यानी क्रान्ति के खिलाफ़ होनेवाली प्रतिक्रिया उसे निगल गई। पर कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। अभी और बाक़ी है। जिस वक़्त यह लिख रहा हूँ, उस वक़्त भी चीन के अंग-भंग का सिलसिला जारी है। क्रान्ति के असफल होने की वजह यह थी कि राष्ट्रीयता के बन्धनों में जितना बल था उससे ज्यादा ताक़त वर्ग-भावना के स्वार्थ और संघर्ष में थी। अमोरों और भूस्वामियों ने किसानों और मजदूरों की प्रधानता कायम होने से राष्ट्रीय आन्दोलन की कमर तोड़ देना अच्छा समझा। हिन्दु-स्तान में भी हमें आज यही बात दूसरी शक्ल में होती हुई नज़र आ रही है।

चीन के लिए भीतरी झगड़े तो थे ही, अब उसको एक विदेशी दुश्मन के संकल्प-पूर्ण आक्रमण का सामना भी करना था। यह दुश्मन जापान था और वह चीन की कमज़ोरी और दूसरे राष्ट्रों के और-और झंझटों में फँसे रहने से फ़ायदा उठाने पर तुला हुआ था।

जापान आधुनिक उद्योगवाद और मध्यकालीन सामन्तशाही का और प्रतिनिधि-शासन तथा स्वेच्छाचार एवं सैनिक नियंत्रण की खिचड़ी का एक अजीब नमूना है। भूस्वामी, शासकों और सैनिकवर्ग ने मिलकर इरादतन वहाँ ऐसा ख़ानदानी राज्य बनाने की कोशिश की है जिसमें सम्राट् सर्वोपरि अधिकारी और वे उसके सामन्त या

वर्तमान व्यवस्था की ऐसी सारी बातों का खात्मा हो। जापान में सत्ताधारी पूँजीपति-वर्ग लोगों का अधिकाधिक शोषण कर रहा था, उनके कष्ट दिन-दिन बढ़ रहे थे और इसलिए वहाँ भी साम्यवाद फैल रहा था। आबादी तेजी से बढ़ रही थी। अमेरिका, कनाडा और आस्ट्रेलिया के वीरान जंगलों में भी जाकर जापानी लोग बस नहीं सकते थे। उनके लिये दरवाजा बन्द कर दिया गया था। चीन पास में था, मगर वहाँ पहले ही आबादी ज्यादा थी। कुछ लोग कोरिया और मंचूरिया में जा बसे थे। जापान के अपने खास झगड़े तो थे ही, दुनियाभर उद्योगवाद और व्यापार की मंदी के कारण जो कष्ट अनुभव कर रही थी उसका उसे भी सामना करना पड़ा। जब उसकी भीतरी परिस्थिति गम्भीर होने लगी, तो साम्यवादी और सभी उग्र विचारों का दमन शुरू होगया। १९२५ में एक 'शान्तिर-रक्षा क़ानून' पास हुआ। उसकी भाषा रोचक है, इसलिए इस क़ानून की पहली क़लम उद्धृत करता हूँ। वह यों है :—

“जिन्होंने राष्ट्र के विधान को बदलने या व्यक्तिगत सम्पत्ति की प्रणाली को मिटाने की ग़र्ज़ से कोई मण्डल या पञ्चायत मंगठित की है या जो उसके उद्देश्य को पूरी तरह जानकर उसमें शामिल हुए हैं, उन्हें मौत से लगाकर पाँच वर्ष क़ैद तक की मज़ा दी जायगी।”

यह क़ानून कितना ज्यादा सख्त है कि इसमें न सिर्फ़ साम्यवाद की ही बल्कि सभी तरह के समाजवादी, उग्र या वैध सुधारों तक की मनाई करदी गई है। इससे यह अन्दाज़ लगाया जा सकता है कि साम्यवाद के बढ़ने से जापानी सरकार कितनी डरी हुई है।

मगर साम्यवाद तो सामाजिक परिस्थिति से पैदा होनेवाले व्यापक दुखों का परिणाम है। जबतक इस परिस्थिति में सुधार नहीं होता तबतक सिर्फ़ दमन से काम नहीं चल सकता। इस वक़्त जापान में लोगों को भयंकर कष्ट है। चीन और हिन्दुस्तान की तरह वहाँ भी किसान क़र्ज़ के भारी बोझ से कुचले जा रहे हैं। ज़बरदस्त प्रॉजी ख़र्च और लड़ाई की ज़रूरियात की वज़ह से वहाँ टैक्स का बोझ खास तौर पर भारी है। ऐसी ख़बरें भी आती हैं कि भूखों मरते हुए किसान घास और जड़े खाकर गुज़र कर रहे हैं और अपने बच्चों तक को बेच रहे हैं। बेकारी के कारण मध्यमवर्ग का भी बुरा हाल है और खुदकुशी बढ़ रही है।

साम्यवाद के विरोध का तिलतिला बड़े पैमाने पर १९२८ के आरम्भ में शुरू हुआ। उस वक़्त एक रात में एक हजार से ज्यादा गिरफ़्तारियाँ हुईं, मगर अख़बारों को एक महीने तक यह ख़बर छापने की इजाज़त नहीं मिली। तबसे पुलिस की तरफ़ से तलाशियाँ और बहुत ज्यादा तादाद में घर-घर-घर का ताँता-सा बँधा हुआ है।

अपनी इष्कीस माँगें पूरी कराने की कोशिश की थी। इसपर अमेरिका और योरोप में बड़ा शोर मचने से वह जितना चाहता था उतना सब तो उसे नहीं मिला, मगर बहुत कुछ मिल गया। युद्ध के बाद जार का साम्राज्य टूट गया और जापान ने देखा कि एशिया में हाथ-पैर फैलाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। उसकी फ़ौज साइबेरिया में घुस गई और उसके एजेण्ट ठेठ मध्य-एशिया में समरकन्द और बुखारा तक जा पहुँचे। मगर सोवियट रूस के सम्बल जाने से, और कुछ अमेरिका के विरोध और अविश्वास के कारण, जापान के मसूवे पूरे नहीं हुए। यह सदा याद रखने की बात है कि जापान और अमेरिका में जरा भी प्रेम नहीं है। वे एक-दूसरे से बड़ी नफ़रत करते हैं और प्रशान्त महासागर के आर-पार से एक-दूसरे को सशंक दृष्टि से देखते रहते हैं। १९२२ की वाशिंगटन-परिषद् से जापान की महत्वाकांक्षाओं पर पानी फिर गया और अमेरिका की राजनीति सफल होगई। इस परिषद् में जापान-सहित नौ राष्ट्रों ने चीन की अखण्डता का आदर करने की प्रतिज्ञा की। इसका यह अर्थ था कि जापान को चीन में फैलने की सारी आशायें छोड़नी होंगी। इस परिषद् में इंग्लैंड और जापान की संधि भी खत्म हुई और सुदूर पूर्व में जापान अकेला रह गया। ब्रिटिश सरकार ने सिंगापुर में एक जवरदस्त समुद्री क़िला बनाना शुरू कर दिया। यह साफ़ तौर पर जापान के लिए ख़तरनाक है। १९२४ में अमेरिका ने जापानियों के ख़िलाफ़ आयात-क़ानून पास किया। वह अपने यहाँ जापानी मजदूरों को नहीं आने देना चाहता था। इस जातीय भेद-भाव से जापान में बहुत और सारे पूर्व में कुछ-कुछ, रोष पैदा हुआ। मगर जापान अमेरिका का कुछ बिगाड़ नहीं सका। इस तरह अकेला पड़ जाने और चारों तरफ़ दुश्मनों से घिर जाने पर जापान की नज़र रूस पर गई और १९२५ के जनवरी में उसके साथ सुलह होगई।

इसी बीच में जापान पर जो महान् विपत्ति आई और उसे बहुत कमज़ोर कर गई, उसका हाल तुम्हें अवश्य बताऊंगा। १९२३ के १ सितम्बर को वहाँ एक भयंकर भूकम्प आया और उसके साथ-साथ राजधानी टोकियो के विशाल नगर में तूफ़ान भी आया और आग भी लगी। यह विशाल नगर नष्ट होगया और योकोहामा बन्दर भी नेस्तनाबूद होगया। एक लाख से ऊपर आदमी मारे गये और बहुत भारी नुक़सान हुआ। जापानी लोगों ने इस विपत्ति का सामना साहस और दृढ़ता के साथ किया और पुराने टोकियो के खण्डहरों पर उन्होंने नया शहर खड़ा कर लिया।

जापान ने रूस के साथ अपनी कठिनाइयों की वजह से सुलह की थी। लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि उसने साम्यवाद का समर्थन किया हो। साम्यवाद का अर्थ ही यह है कि सम्राट-पूजा, सामन्तशाही, शासकवर्ग द्वारा गरीबों का शोषण और

नौ राष्ट्रों की सन्धि का हाल बताया था। यह सुलह या सन्धि खास तौर पर पश्चिमी राष्ट्रों की सूचना पर चीन में जापानियों के हथकण्डे रोकने के लिए हुई थी। साफ़ और असंदिग्ध शब्दों में जापान-सहित नवों राष्ट्रों ने 'चीन की सत्ता, स्वाधीनता और उसकी भूमि एवं शासन-संबंधी अखण्डता का आदर करना' मंजूर किया था।

कुछ वर्ष तक जापान ने कुछ नहीं किया। लेकिन परदे की आड़ में कुछ चीनी सेनापतियों या तूशनों को गृह-युद्ध जारी रखकर चीन को कमजोर करने में रुपये-पैसे की और दूसरी मदद करता रहा। उसने चंग सोलिन की खास तौर पर मदद की। इसका मंचूरिया और पेकिंग में भी बोलबाला था और जबतक दक्षिण के राष्ट्र-वादियों की विजय न हुई तबतक उसीका बोलबाला रहा। १९३१ में जापानी सरकार ने मंचूरिया में खुले तौर पर आक्रमणकारी र्वैया इख्तियार कर लिया। इसकी वजह यह भी हो सकती है कि जापान की भीतरी आर्थिक हालत बहुत खराब हो चली थी और इसलिए सरकार मजबूर होकर विदेश में ऐसा काम कर रही थी, जिससे लोगों का ध्यान बँट जाय और घर की खींचतान कुछ कम हो जाय, या सैनिक दल का शासन में बहुत जोर बढ़ गया हो या यह ख्याल होगया हो कि दूसरे सब राष्ट्रों को तो अपने-अपने झगड़ों और व्यापारिक मन्दी की चिन्ता है, इसलिए कोई बोलनेवाला नहीं है। शायद इन सभी कारणों से प्रेरित होकर जापान ने इतनी खतरनाक कार्रवाई की हो। इस कार्रवाई से १९२२ की नौ राष्ट्रों की संधि तो टूटती ही थी, यह बात राष्ट्र-संघ के नियमों के भी खिलाफ़ थी, क्योंकि चीन और जापान दोनों ही राष्ट्र-संघ के सदस्य थे और उसकी मंजूरी के बिना एक-दूसरे पर हमला नहीं कर सकते थे, और १९१८ में युद्ध को शर-क़ानूनी कर देने के लिए पेरिस में जो केलाग-संधि हुई थी उसका भी साफ़ तौर पर भंग होता था। चीन के खिलाफ़ लड़ाई की कार्रवाइयां करके जापान ने जान-बूझकर ये अहदनामे और वादे तोड़ डाले और संसार-भर का विरोध मोल ले लिया।

अलबत्ता उसने यह बात साफ़ लपटों में नहीं कही। जापानी सरकार ने कुछ ऐसे कमजोर और झूठे बहाने बनाये कि मंचूरिया में डाकुओं का उपद्रव है और वहाँ ऐसी छोटी-मोटी घटनायें होगई हैं कि व्यवस्था और जापानी हितों की रक्षा के लिए मजबूर होकर फ़ौज भेजनी पड़ी है। साफ़ तौर पर लड़ाई का ऐलान नहीं किया गया, फिर भी जापानियों की तरफ़ से मंचूरिया पर हमला होगया। इससे चीनी लोग बड़े नाराज़ हुए। चीनी सरकार ने नाराज़गी जाहिर की, और राष्ट्र-संघ और दूसरे राष्ट्रों से फ़रियाद की, मगर किनीने कोई ध्यान नहीं दिया। सभी देश अपने-अपने झगड़ों के सारे तंग थे। जापान का विरोध करके नई इल्लत कौन मोल ले ? यह भी मुम-

सबसे बड़ा धावा पिछले साल यानी १९३२ के अक्टूबर में हुआ। उस वक़्त २२५० आदमी पकड़े गये। इनमें से ज्यादातर आदमी मजदूर नहीं, बल्कि विद्यार्थी और शिक्षक हैं। इनमें सैकड़ों स्नातक यानी ग्रेजुएट और स्त्रियाँ हैं। यह बात अजीब-सी मालूम होती है कि जापान में बहुत-से मालदार युवकों का साम्यवाद की तरफ़ झुकाव हुआ है। पिछले दिनों एक बैंक भी लूटा गया है। यह साम्यवादियों का काम बताया जाता है और उन्होंने पुराने, रूसी और पोलिश 'भूतपूर्व मालिकों' (ex-proprietors) की नफ़ल की है। पुलिस साम्यवाद और उग्र विचारों को दवाने में इतनी मशगूल रहती है कि उसे मामूली मुजरिमों के लिये बहुत कम वक़्त मिलता है। वहाँ भी हिन्दुस्तान की तरह उदात्त विचारक अपराधियों से ज्यादा ख़ौफ़नाक समझे जाते हैं। हिन्दुस्तान में मेरठ-पड़यन्त्र का मामला चला, कुछ जापानी साम्यवादियों के मुक़दमे भी वैसे ही बरसों तक चलते रहे हैं।

मैंने जापान के ये सब हालात तुम्हें इसलिए बता दिये हैं कि जापान ने मंचूरिया में जो करतूत की है उसकी भूमिका या ज़मीन के बारे में तुम्हें कुछ अन्दाज़ होजाय। अब मैं उस करतूत का कुछ हाल सुनाता हूँ।

पिछले छतों में मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि जापान ने एशिया महाद्वीप की ज़मीन पर पहले कोरिया और फिर मंचूरिया में पैर जमाने की लगातार कोशिश की। १८९४ में चीन के ओर दस वर्ष बाद रूस के साथ जापान की जो लड़ाइयाँ हुई उन दोनों का यही मतलब था। जापान को कामयाबी मिली, और वह एक-एक क़दम आगे बढ़ता गया। कोरिया को उसने अपनेमें मिलाकर जापानी साम्राज्य का अंग ही बना लिया। रूस ने मंचूरिया के आरपार चीन की पूर्वी रेलवे बनाई थी। उसका एक हिस्सा जापान के नियन्त्रण में आ गया और उसका नाम दक्षिण मंचूरिया रेलवे रख दिया गया। इन सब तब्दीलियों के होते हुए भी सारे मंचूरिया पर चीन की ही हुकूमत थी और रेलवे के कारण चीनी लोग आ-आकर बड़ी तादाद में वहाँ बसते रहे। असल में ऐसा माना जाता है कि दुनिया के इतिहास में जितने जितने लोग इस तरह चीन के उत्तर-पूर्व के प्रान्तों में आकर बसे, उतने और कम ही स्थानों पर बसे हैं। १९२३ से १९२९ तक सात वर्ष के भीतर २५ लाख चीनियों ने देश-त्याग दिया। मंचूरिया की आबादी अब तीन करोड़ है और इनमें से ९५ फ़ीसदी चीनी हैं। इस तरह तीनों प्रान्त पूरी तरह चीनी हैं। बाक़ी ५ फ़ीसदी रूसी, मंगोली ख़ानाबदोश, कोरियन और जापानी हैं। पुराने मंचू लोग चीनियों में मिल गये हैं और अपनी भाषा तक भूल बैठे हैं।

तुम्हें याद होगा कि मैंने तुम्हें १९२२ में वाशिंगटन कान्फ़रेन्स के मौक़े पर हुई

पास न बहुत सामान था, न बड़ी तोपें। उसकी बर्दी भी रही-सी थी। चीन के कड़ाके के जाड़े से बचने के लिए उसके पास पूरे कपड़े भी नहीं थे। उसमें बहुत-से पन्द्रह-सोलह वर्ष के और कुछ सिर्फ बारह-बारह वर्ष के लड़के भी थे। इस बेसामान फ़ौज ने च्यांग-काई-शेक के हुक्म के खिलाफ़ जापानियों से लड़ने और उन्हें रोक रखने का फ़सला किया। १९३२ के जनवरी और फ़रवरी में दो हफ़्ते तक नानकिंग-सरकार की मदद के बिना ये लोग लड़ते रहे। वे लड़े भी इस विलक्षण वीरता से कि कहीं अधिक सबल और सुसज्जित जापानी सेना को रुक जाना पड़ा। इससे खुद उन्हें भी ताज्जुब हुआ। जापानियों को ही नहीं, बल्कि विदेशी राष्ट्रों और खुद चीन-निवासियों को भी ताज्जुब हुआ। जब ये लोग दो हफ़्ते तक किसी की मदद के बिना लड़ते रहे और सब से उन्हें शाबाशियाँ दी जा रही थीं, तब कहीं बचाव में मदद करने के लिए चियांग-काई-शेक ने थोड़े-से सिपाही भेजे।

उन्नीसवें कूच की सेना ने इतिहास बना दिया और संसार-भर में नाम कमा लिया। उसकी स्वदेश-रक्षा ने जापान की योजनाओं को अस्त-व्यस्त कर दिया। इधर पश्चिमी राष्ट्रों को भी शंघाई में अपने स्वार्थों की चिन्ता थी। इसलिए शंघाई क्षेत्र से जापानी सेना धीरे-धीरे हटाली गई और जहाजों में भर-भरकर वापस भेज दी गई। यह उल्लेखनीय बात है कि इन पश्चिमी राष्ट्रों को चापेई जैसे हजारों आहुतियाँ लेने-वाले मनमाने हत्याकाण्डों और पवित्र राष्ट्रीय संधियों और अन्तर्राष्ट्रीय नियमों के भंग होने का इतना ख़याल नहीं था जितना अपने माली और दूसरे स्वार्थों का ख़याल था। इस मामले की राष्ट्र-संघ से कई बार फ़रियाद की गई, मगर वह किसी-न-किसी बहाने से इसे हमेशा टालता रहा। संघ के लिए यह कोई महत्त्व की बात ही न थी कि सचमुच लड़ाई हो रही है और हजारों आदमी मारे जा चुके हैं और मारे जा रहे हैं। कहा यह गया कि चूंकि सरकारी तौर पर लड़ाई का ऐलान नहीं किया गया, इसलिए वास्तविक युद्ध हुआ ही नहीं। संघ की इस कमजोरी और जीती मक्खी निगल जाने की कार्रवाई से उसकी प्रतिष्ठा और कीर्ति को बड़ा धक्का लगा। अलबत्ता इसकी जिम्मेदारी कुछ बड़े राष्ट्रों के सिर पर थी। इंग्लैंड ने तो संघ में ख़ास तौर पर जापान का पक्ष लिया। आखिरकार संघ ने लॉर्ड लिटन की अध्यक्षता में मंचूरिया के मामले की जांच के लिए एक कमीशन मुक़रर किया। इसे राष्ट्रों ने तुरन्त मंजूर कर लिया। क्योंकि इसका अर्थ था कई मास तक निर्णय स्थगित रखना। मंचूरिया बहुत दूर था और कमीशन को वहाँ जाकर जांच करने और रिपोर्ट लिखने में मुद्दत लगती। शायद मामला हवा में ही उड़ जाता।

जापानी शंघाई से तो हट गये, पर अब उन्होंने मंचूरिया की तरफ़ ज्यादा ध्यान

फिन है कि कुछ राष्ट्रों ने—खास तौरपर इंग्लैण्ड ने—जापान से खुफिया समझौता कर लिया हो। चीन की अनियमित सेना ने जापान को मंचूरिया में खूब दिक्कत किया। फिर भी यह नहीं माना गया कि दोनों देशों में युद्ध है ! जापान को अधिक दिक्कत तो चीन के जापानी माल के बड़े बहिष्कार-आन्दोलन से हुई।

१९३२ की जनवरी में जापानी फ़ौज शंघाई के पास चीन की ज़मीन पर जा धमकी और वहाँ उसने आधुनिक समय का एक बड़ा ही दर्दनाक क़त्लेआम कर डाला। उसने पश्चिमी राष्ट्रों के डर से विदेशी वस्तियों को तो छोड़ दिया और घनी आवादी के चीनी मुहल्लों पर हमला किया। शंघाई के पास एक बड़े इलाक़े पर बम और गोले बरसाये गये। मेरे ख़याल से उस इलाक़े का नाम चेपेई था। वह बिल्कुल तहस-नहस कर दिया गया, हजारों मारे गये और बेशुमार लोग बेघर-बार होगये। याद रहे कि यह लड़ाई किसी फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं थी। यह तो बेगुनाह और निःशस्त्र लोगों पर बम-बर्षा थी। इस 'वीरतापूर्ण' कार्रवाई का ज़िम्मेदार एक जापानी जल-सेनापति था। पूछने पर उसने कहा कि जापान का यह निर्णय दयापूर्ण है कि "निःशस्त्र लोगों पर अन्धाधुन्ध बम-बर्षा सिर्फ़ दो ही दिन और की जाय।" शंघाई में लंदन के 'टाइम्स' पत्र का जो संवाददाता था वह जापान का हिमायती था, मगर उसके दिल पर भी इस घटना से इतनी चोट पहुँची कि उसने इसे चीनियों का जापानियों के हाथों 'क़त्ले-आम' बताया। चीनियों के भाव इस घटना पर क्या हुए होंगे, इसका तो अन्दाज़ आसानी से लगाया जा सकता है। समूचे चीन में क्रोध और आतंक की लहर दौड़ गई और ऐसा मालूम हुआ कि इस जंगली विदेशी हमले के सामने देश के मुत्तलिफ़ और एक-दूसरे के विरोधी सेनानायक और शासक आपस के ईर्ष्या-द्वेष को भूल गये हैं। सबके मिलकर जापान का मुक़ाबिला करने की चर्चा चली और चीन के भतरी प्रदेश की साम्यवादी सरकार ने भी नानकिंग सरकार को अपनी सेवार्यें पेश कीं। फिर भी ताज्जुब की बात यह हुई कि नानकिंग या उसके नेता चियांग-काई-शेक ने बढ़ती हुई जापानी फ़ौज की तरफ़ शंघाई की रक्षा करने के लिए चिट्ठी उँगली भी नहीं उठाई। नानकिंग ने इतना-सा किया कि राष्ट्रसंघ के पास अपनी विरोध-सूचना भेज दी। उसने जापानियों का सम्मिलित विरोध संगठित करने की कोशिश तक नहीं की। मालूम होता है वह बातें भले ही बड़ी-बड़ी बनाता हो, लेकिन उसके जी में मुक़ाबिला करने की इच्छा ही नहीं थी, हालांकि देश क्रोध के मारे लाल पीला हो रहा था।

इसके बाद ही दक्षिण से चलकर एक अजीब-सी सेना शंघाई के मैदान में आ पहुँची। यह उन्नीसवीं कूचवाली सेना कहलाती थी। इसमें कैप्टन के लोग ही थे, मगर यह न तो कैप्टन सरकार के ताबे में थी और न नानकिंग के। इस भद्दी-सी फ़ौज के

इस नये हमले और नये दिन के हत्याकाण्ड से संघ की नौद खुली और छोटे राष्ट्रों के संघ ने एक प्रस्ताव द्वारा लिटन-रिपोर्ट को मंजूर किया और जापान की निन्दा की। जापान ने इसको ज़रा भी परवा नहीं की। (क्या वह नहीं जानता था कि इंग्लैण्ड और कुछ दूसरे राष्ट्र चुपके-चुपके उसकी पीठ ठोक रहे थे ?) जापान राष्ट्र-संघ में से निकल गया। संघ से इस्तीफा देकर जापान चुपचाप पीपिंग की तरफ बढ़ता गया। उसका किसीने मुकाबिला नहीं किया। ऐसा मालूम होता है कि यह सब पहले से गढ़ा-गढ़ाया खेल था। क्रूरिब एक महीने पहले जब जापान की फ़ौज पीपिंग के दरवाज़े पर पहुँच गई तब अचानक यह ऐलान हुआ कि ३१ मई १९३३ ई० को चीन और जापान में लड़ाई बन्द होने की सुलह होगई है। सारा मामला रहस्यपूर्ण मालूम होता है और अभी-तक कोई निश्चित बात मालूम नहीं होपाई है। लेकिन इतना दीखता है कि जापानी सरकार की विजय होगई और नान्किंग-सरकार ने, चाहे कमजोरी से या जान-बूझकर, उस विजय को स्वीकार कर लिया है। जापानी हमले के प्रति नान्किंग-सरकार और काउ-मिन-तांग दल ने जिस दयनीय उपेक्षा का परिचय दिया, उसके बाद अगर चीन में उनकी लोकप्रियता बुरी तरह घट रही हो तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं।

मैं मंचूरिया के विषय में बहुत कह गया। वह महत्वपूर्ण है, क्योंकि चीन के भविष्य पर उसका असर पड़ता है। लेकिन इस बात से उसका महत्व और भी ज्यादा होगया है कि उससे राष्ट्र-संघ की क़लई खुल गई और यह साबित होगया कि अन्तर्राष्ट्रीय अन्याय के प्रमाणित होने पर भी संघ कुछ नहीं कर सकता और इसलिए वह एक बिलकुल निकम्मी चीज़ है। इससे बड़े-बड़े यूरोपियन राष्ट्रों की दुरंगी चालों और साजिशों का भी भण्डाफोड़ होगया। इस खास मामले में संघ का सदस्य न होते हुए भी अमेरिका ने जापान के ख़िलाफ़ कड़ा रुख़ इस्तिहार करने की कोशिश की और लड़ाई पर उतारू-सा होगया। मगर इंग्लैण्ड और दूसरे राष्ट्रों ने गुप्त रूप से जापान का जो समर्थन कर दिया, उससे अमेरिका के रुख़ का कोई असर नहीं हुआ और वह भी जापान के विरोध में अकेला पड़ जाने के डर से अधिक सावधान होगया। संघ ने जापान की साधुतापूर्ण भर्त्सना यानी शरीफ़ाना डाँट-डपट करदी है। उम्मीद तो यह रखी गई थी कि इसके साथ-साथ कोई सम्मिलित कार्रवाई भी की जायगी। लेकिन हुआ कुछ भी नहीं, और न आगे कुछ होना-जाना है। मंचूकुओ के कठपुतली राज्य को राष्ट्र-संघ के सदस्यों ने मंजूर नहीं किया, मगर यह नामंजूरी भी खिलवाड़-सी होती जा रही है।

राष्ट्र-संघ ने जापान की निन्दा करदी, तब भी ब्रिटिश मंत्री और राजदूत आगे बढ़-बढ़कर जापान के कार्य को उचित बताते रहते हैं। रुम के प्रति इंग्लैण्ड का

देना शुरू कर दिया। उन्होंने एक नाममात्र की सरकार कायम करके ऐलान कर दिया कि मंचूरिया ने आत्म-निर्णय के अधिकार से काम लिया है। इस नई कठपुतली का नाम मंचूकुओ रखा गया और चीन के पुराने मंचू राजवंश के एक जर्जर युवक को नये राज्य का राजा बना दिया गया। वैसे यह सब सिर्फ एक तमाशा था और असली शासक जापान था। सब लोग जानते थे कि जापानी फ़ौज हटा ली जाय तो मंचूकुओ राज्य का एक दिन में ढेर हो जाय।

जापानियों को मंचूरिया में दिक्कत पेश आई, क्योंकि चीनी स्वयंसेनिकों के दल उनसे बराबर लड़ते रहे। इन टुकड़ियों को जापानी लोग 'डाकू' कहते हैं। जापानियों ने स्थानीय चीनियों को भर्ती करके मंचूकुओ की सेना बनाई और उसे शिक्षित और सुसज्जित किया। जब उसे डाकुओं से लड़ने भेजा गया तो वह सारा नये ढंग का सामान लेकर डाकुओं में जा मिली। इस सदा चलते रहने वाली जंग के मारे मंचूरिया का बुरा हाल है। फ़सलें बोई नहीं जाती और सोयाबीन का व्यापार मर रहा है।

कई महीनों की जांच-पड़ताल के बाद लिटन-कमीशन ने राष्ट्र-संघ के सामने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। यह बड़ी सावधानी, संयम और विवेकपूर्वक लिखी गई थी पर इसमें जापान की पेट भरकर निन्दा की गई थी। इससे ब्रिटिश सरकार बड़ी परेशान हुई, क्योंकि वह जापान की रक्षा करने पर तुली हुई थी। अन्त में संघ के सामने यह सवाल पेश हुआ। इंग्लैंड से अमेरिका का रवैया जुदा ही था। वह जापान के बहुत खिलाफ़ था। अमेरिका ने ऐलान किया कि जापान मंचूरिया में या और कहीं भी जबर-दस्ती कोई परिवर्तन करेगा तो अमेरिका उसे मंजूर नहीं करेगा। अमेरिका के इस सख्त रवये के बावजूद इंग्लैंड ने और कुछ फ़्रांस, इटली और जर्मनी ने जापान का समर्थन किया। यह कहा जा चुका है कि इस और दूसरे मामलों में ब्रिटेन ने जापान के साथ खुफ़िया समझौता कर रखा है।

जिस वक़्त संघ निर्णय को टालने में कोई कसर नहीं रख रहा था उसी वक़्त जापान ने एक नया काम किया। १९३३ के नये दिन की बात है। जापानी फ़ौज एका-एक चीन में जा धमकी और उसने शनहेकवान नगर पर हमला कर दिया। यह शहर चीन की बड़ी दीवार की तरफ़ है। बड़ी-बड़ी तोपों और नाशक जहाज़ों से गोले और वायुयानों से बम बरसाये गये। यह पूरी तरह नये ढंग का हमला था और शनहेकवान जलकर खाक हो गया। बहुत तादाद में उसके निवासी हताहत हुए। इसके बाद जापानी सेना बढ़ती हुई चीन के जेहोल प्रान्त में घुसकर पीपिंग के पास पहुँच गई। बहाना यह किया गया कि 'डाकू' लोग जेहोल को केन्द्र बनाकर वहाँसे मंचूकुओ पर हमले किया करते थे। किसी-न-किसी तरह जेहोल मंचूकुओ में शामिल कर लिया गया।

दिया है। अब मैं सुदूर पूर्व से विदा लेता हूँ। मगर इसे खत्म करने से पहले मैं तुम्हें छोटे-से कोरिया देश की याद दिला देना चाहता हूँ (वैसे यह इतना छोटा तो नहीं है)। जापानी उस देश के स्वामी हैं, मगर वह अभी तक आजादी के सपने देखता है और उसके लिए कोशिश भी करता है। (कोरिया के बाहर तो!) 'कोरिया की अस्थायी प्रजातन्त्र सरकार' भी है।

: १७६ :

समाजवादी सोवियट प्रजातंत्र संघ

७ जुलाई, १९३३

अब जरा सोवियट पंचायतों की भूमि रूस में लौट चलें और उसकी कहानी जहाँ छोड़ी थी वहाँसे फिर आगे बढ़ायें। हम १९२४ की जनवरी तक पहुँच गये थे, जबकि क्रान्ति के प्रवर्तक और नेता लेनिन का देहान्त हुआ था। उसके बाद दूसरे देशों की बाबत मैंने जो बहुत-से खत तुम्हें लिखे हैं उनमें रूस का जिक्र बार-बार आया है। योरोप की समस्याओं या हिन्दुस्तानी सरहद, सुदूर पूर्व, चीन और जापान, तुर्की और ईरान पर विचार करते वक्त बीच-बीच में रूस से ताल्लुक पड़ता रहा है। यह बात तुम्हें साफ़ दिखाई देने लगी होगी कि एक राष्ट्र की राजनीति और अर्थनीति को दूसरे देश की राजनीति और अर्थनीति से अलग रखना बहुत मुश्किल ही नहीं, असल में शर-मुमकिन है। पिछले वर्षों में राष्ट्रों के आपस के ताल्लुकात इतने गहरे होचले हैं और वे एक-दूसरे पर इतने निर्भर रहने लगे हैं कि दुनिया कई बातों में एक होगई है। हमारे स्कूल-कालेजों की वही पुरानी रफ़्तार है। राष्ट्रीय इतिहास की पुस्तकों में अब भी पुराने ढंग पर ख़ास देशों का ही हाल रहता है। लेकिन इतिहास अब अन्तर्राष्ट्रीय विषय यानी दुनिया-भर का इतिहास होचला है। अब उसे एक देश के बारे में समझने के लिए भी समूचे संसार पर नज़र रखकर देखना पड़ेगा।

योरोप और एशिया में सोवियट संघ का लम्बा-चौड़ा प्रदेश पूँजीवादी संसार से अलग ही है। फिर भी वह हर जगह इस दूसरी दुनिया के सम्पर्क में और अनेक बार संपर्क में आता है। पिछले ख़तों में मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि सोवियट नीति पूर्व के देशों के प्रति उदार है। उसने तुर्की, ईरान और अफ़ग़ानिस्तान को मदद दी और चीन के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित कर लिये। ये सम्बन्ध बाद में एकाएक टूट गये। मैं तुम्हें यह भी कह चुका हूँ कि किस तरह आर्कम पर घावा हुआ और जिनो-दोर पत्र से ब्रिटेन के आम चुनाव पर असर पड़ा, हालाँकि बाद में वह ख़त बनावटी

व्यवहार इससे बिल्कुल उलटा है। करीब दो महीने हुए कि रूस में गुप्तचरों के अपराध पर कुछ अंग्रेज इंजीनियरों पर मुकदमा चलाया गया था। कुछ छोड़ दिये गये और दो को हलकी-हलकी क़ैद की सज़ा दी गई। इसपर बड़ा वावला मचा और ब्रिटिश सरकार ने रूसी माल को ब्रिटेन में आने से रोक दिया। रूस ने भी अंग्रेजी माल के आने की मनाई करके इसका मुनासिब जवाब दिया।

इस तरह कम-से-कम अभी तो चीन के हाथ से मंचूरिया जाता रहा। मंगोलिया सोवियट देश है। उसकी रूसी सोवियट-संघ से दोस्ती है। तिब्बत अब आज़ाद हो गया। असली चीन में अब कम-से-कम तीन सरकार हैं। मुख्य सरकार नान्किंग में है, दूसरी दक्षिण में क़ैण्टन में है, और तीसरी अन्दरूनी इलाक़े की साम्यवादी सरकार है। इनके अलावा अनेक सेनापति और त़ूशन हैं। वे मनमानी करते और कभी इस दल के और कभी उस दल के साथ मिलते रहते हैं। उत्तर में बड़ी दीवार से लगाकर लग-भग पीपिंग तक जापान मुंह बाये बैठा है। बड़े-बड़े बन्दरगाहों पर विदेशियों का क़ब्ज़ा है। उनकी बड़ी-बड़ी रियायती बस्तियां हैं और वे बड़े-बड़े भीतरी प्रदेशों के व्यापार पर अपना अधिकार रखते हैं। सोवियट और साम्यवादी इलाक़े को छोड़कर, देश पर विदेशियों का आर्थिक प्रभाव और प्रभुत्व और भी ज्यादा है।

एक और बड़ा प्रान्त चीन से अलग होता दीख रहा है। यह सिंकियांग अथवा चीनी तुर्किस्तान है और तिब्बत और साइबेरिया के बीच में है। इस प्रान्त के यारक़न्द और काशगर नगरों को, काशमीर के श्रीनगर से लद्दाख़ प्रान्त के लेह नगर होकर, फारवान नियमित रूप से जाते रहते हैं। दो-तीन मास से ख़बरें आ रही हैं कि सिंकियांग के तुर्कों ने विद्रोह कर दिया है और यारक़न्द और काशगर पर क़ब्ज़ा कर लिया है। अंग्रेज ऐसा संकेत करते रहते हैं कि इस विद्रोह के पीछे सोवियट रूस का हाथ है। दूसरी ओर, समाचार भेजने वाली सोवियट संस्थाओं ने खुले तौर पर कहा है कि यह विद्रोह कुछ ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के प्रोत्साहन से हुआ है। उनका उद्देश्य यह बताया जाता है कि मंचूकुओं की तरह सिंकियांग भी चीन और रूस के बीच में एक निरपेक्ष राज्य बन जाय। जिस अंग्रेज अफ़सर ने सिंकियांग में यह विद्रोह संगठित किया है उसका नाम तक प्रकाशित किया गया है। कहा नहीं जा सकता कि सच्ची बात क्या है, मगर यह निश्चित समझ लेना चाहिए कि ब्रिटिश और सोवियट दोनों सरकारें सिंकियांग में षड़यंत्र रच रही हैं। मुमकिन है यह विद्रोह राष्ट्रीय हो, क्योंकि वहाँके मुसलमान तुर्कों पर धार्मिक भावों से राष्ट्रीय भावों का असर ज्यादा है। मालूम होता है, चीनी तुर्किस्तान में प्रजातंत्र की घोषणा होगई है।

इस ख़त के साथ मैंने चीन और जापान की कहानी को आज के दिन तक पहुँचा

बड़े प्रमाण में क्रीमती मशीनें खरीदने को तैयार हो। रूस-जैसे कृषि-प्रधान देश और जर्मनी, इंग्लैंड और अमेरिका जैसे उद्योग-प्रधान देशों में व्यापार होने से दोनों ही पक्ष का फायदा था, क्योंकि रूस को यंत्रों की जरूरत थी और उसके बदले में वह सस्ते खाद्य पदार्थ और कच्चा माल देसकता था।

आखिरकार साम्यवाद की घृणा से थैली का जोर ज्यादा ताकतवर साबित हुआ और करीब-करीब सभी देशों ने सोवियट सरकार को मान लिया और बहुतों ने तो उसके साथ सन्धियाँ भी कर लीं। अमेरिका ही एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जिसने अबतक सोवियट को स्वीकार नहीं किया है। आजतक भी उनके आपस में राजनैतिक संबंध नहीं हैं, हालाँकि उनके कायम होजाने की जल्दी ही उम्मीद है। फिर भी रूस और अमेरिका में व्यापार होता रहा है।

इस तरह सोवियट ने ज्यादातर पूँजीवादी और साम्राज्यवादी राष्ट्रों के साथ ताल्लुकात कायम कर लिये। एक हद तक, उसने इनके आपसी ईर्ष्या-द्वेष से फायदा भी उठाया। यह फायदा उसने उस समय भी उठाया जब १९२२ में पराजित जर्मनी ने उसके साथ सन्धि की थी। मगर यह समझौता बड़ा ही नापायदार था और पूँजीवाद और साम्यवाद की दो प्रणालियों में मौलिक विरोध था। औपनिवेशिक देशों की गुलाम रियाया और कारखानों के मजदूर दोनों ही दलित और शोषित वर्ग में थे। बोल्शेविक सदा इन लोगों को शोषकों से बचाव करने के लिए भड़काते रहते थे। यह काम वे सरकारी तौर पर नहीं करते थे, बल्कि कोमिन्टर्न नाम की अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवादी संस्था के द्वारा करते थे। उधर साम्राज्यवादी राष्ट्र और खासकर इंग्लैंड सोवियट की हस्ती मिटाने के लिए बराबर साजिश करते रहते थे। इसलिए झगड़ा तो होता ही; और बार-बार झगड़ा होने से राजनैतिक सम्बन्ध-विच्छेद होने और लड़ाई की खबरें उड़ने की नौबत भी आई। तुम्हें याद होगा कि १९२७ में आर्थर्स के धावे और तलाशी के बाद रूस के ताल्लुकात इंग्लैंड से टूट गये थे। असल बात तो यह है कि पिछले साढ़े पन्द्रह वर्षों में, जबसे सोवियट का जन्म हुआ है तभीसे, इंग्लैंड और रूस में कशमकश रही है। इसका कारण भी आत्तानी से समझा जा सकता है। इंग्लैंड सबसे बड़ा साम्राज्यवादी राष्ट्र है और रूस एक ऐसी कल्पना सामने रखता है जो साम्राज्यवाद की जड़ ही काट डालना चाहती है। मगर इन विरोधी देशों के बीच में और भी एक चीज है। ज़ार के ज़माने से ही रूस और इंग्लैंड में पीढ़ियों से दुश्मनी चली आती है।

इंग्लैंड और दूसरे पूँजीवादी देशों में आज सोवियट सेना का इतना भय नहीं है जितना सोवियट बिचारों और साम्यवादी प्रचार का है। यह है तो अप्रत्यक्ष चीज,

निकला। म. तुम्हें सोवियट देश के बीच में लेचलकर यह दिखाना चाहता हूँ कि वहाँ जो अद्भुत और मनोहर सामाजिक प्रयोग हो रहा है उसकी प्रगति कैसी है।

१९१७ से १९२१ तक क्रान्ति के बाद के पहले चार वर्ष क्रान्ति की रक्षा में बहुतेरे दुश्मनों से लड़ने में बीते। यह जमाना बड़े जोश और नाटक की-सी तब्दीलियों का था। उसमें लड़ाई और वसावत, गृह-युद्ध, भूख और मौत की भरमार थी। इस अन्धकार में यह रोशनी भी थी कि आम जनता में जिहादी या धर्म के के लिए लड़ने-जैसा जोश था और आदर्श की रक्षा में उसने रंग-मामूली बहादुरी दिखाई थी। लोगों को तुरन्त किसी फल की उम्मीद नहीं थी, मगर उनके हृदय भावी आशाओं और नतीजों के भाव से भरे हुए थे। इनके कारण वे सारे भयंकर कष्ट सह लेते थे और थोड़ी देर के लिए यह भी भूल जाते थे कि उनके पेट में अन्न नहीं पड़ रहा है। यह 'सैनिक साम्यवाद' का जमाना था।

इसके बाद जब १९२१ में लेनिन ने नई अर्थनीति जारी की, तब थोड़ा आराम मिला। यह नीति साम्यवाद से पीछे हटकर देश के पूँजीपति वर्ग से समझौता करने की थी। इसका यह अर्थ नहीं था कि बोलशेविक नेताओं ने अपना ध्येय बदल दिया है। इसका मतलब इतना ही था कि आराम लेने और ताजा होने के लिए वे एक क्रम पीछे हट गये थे, ताकि फिर बाद में वे कई क्रम आगे बढ़ने के क़ाबिल हो जायें। इस तरह सोवियट ने जमकर एक ऐसे राष्ट्र की रचना का बहुत बड़ा काम अपने हाथ में लिया, जिसका बहुत कुछ नाश हो चुका था। निर्माण के इस काम में उन्हें रेलवे इंजिनों और गाड़ियों, मोटर के छकड़ों, हलों और कारख़ानों के सामान की और यंत्रों की जरूरत थी। यह सब उन्हें विदेशों से ख़रीदना पड़ा और उसके लिए उनके पास रुपया बहुत कम था। इसलिए उन्होंने विदेशों से कर्ज़ लेने की कोशिश की, ताकि वे ख़रीद के माल की क़ीमत हलफ़ी क्रिस्तों में चुका सकें। मगर कर्ज़ तो तब मिले जब इन देशों से बोल-चाल का भी वास्ता हो। वे तो सरकारी तौर पर एक-दूसरे को मानते तक न थे। इसलिए सोवियट रूस को इस बात की बड़ी फ़िक्र थी कि किसी तरह बड़े राष्ट्र उसे मान लें। लेकिन इन बड़ी-बड़ी साम्राज्यवादी सत्ताओं को बोलशेविकों और उनके सारे कामों से नफ़रत थी। उनके ख़याल से साम्यवाद इतनी बुरी वस्तु थी जिसका दमन करना ही उचित था। वस्तुन्दाजी और लड़ाई करा-कराके वे उसे कुचलने की कोशिश भी भरसक कर चुकी थीं। मगर उन्हें कामयाबी नहीं मिली। उनका बस चलता तो वे सोवियट के साथ कोई सरोकार न रखतीं। मगर जिस सरकार के क़ब्ज़े में समूची दुनिया का छठा हिस्सा हो उसकी उपेक्षा करना मुश्किल है। इससे भी ज्यादा मुश्किल है एक ऐसे अच्छे ग्राहक की उपेक्षा करना जो बहुत

क्रान्तिकारी फ्रांस ने न सिर्फ पुराने शासकों की विदेशों के साथ की हुई संधियाँ ही फाड़ फेंकीं, बल्कि राष्ट्रीय ऋण भी रद्द कर दिया ।”

इस तरह ऋज अदा न करने का औचित्य साबित कर देने पर भी, सोवियट सरकार दूसरे राष्ट्रों से राजीनामा करने के लिए इतनी उत्सुक थी कि वह ऋज के सवाल पर भी उनसे चर्चा करने के लिए पूरी तरह तैयार होगई। मगर उसने यह शर्त रखी कि यह चर्चा उसी वक्त हो सकती है जब विदेशी सरकार सोवियट को बिना शर्त के मान ले। असल बात तो यह है कि सोवियट ने इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका को ऋज चुकाने के बहुत आश्वासन दिये, मगर इन पूँजीवादी राष्ट्रों को रूस के साथ समझौता करने की बहुत उत्सुकता नहीं थी।

ब्रिटिश दावे के मुक़ाबिले में सोवियट ने बड़ा मजबूत दावा पेश किया। रूस पर अंग्रेजों का सारा दावा सरकारी और युद्ध के ऋण, रेलवे के हिस्सों और व्यापारिक पूँजी के रूप में ८४ करोड़ पौण्ड का था। बोलशेविकों के दुश्मनों को रूसी गृहयुद्ध में ब्रिटेन और ब्रिटिश सेना ने मदद दी थी। उससे जो हानि हुई थी उसके हिस्से का दावा रूस ने ब्रिटेन पर किया। गृहयुद्ध में रूस की सारी हानि चार अरब छः करोड़ बहत्तर लाख छब्बीस हजार चालीस पौण्ड क़ती गई थी। इसमें ब्रिटेन का हिस्सा दो अरब पौण्ड के करीब था। इस तरह ब्रिटेन के दावे से रूस का दावा अढ़ाई गुना था।

बोलशेविकों का यह दावा कमजोर भी नहीं था। उन्होंने ‘अलाबामा’ नामक जहाज की मशहूर नज़ीर पेश की थी। उन्नीसवीं सदी में अमेरिका में जो गृहयुद्ध हुआ था उसीके सिलसिले में दक्षिणी राज्यों के लिए यह जहाज इंग्लैंड में बना था। यह जहाज गृह-युद्ध छिड़ने के बाद लिवरपूल से रवाना हुआ था और इसने उत्तरी राज्यों की जहाज़ी यात्रा और व्यापार को बहुत नुक़सान पहुँचाया था। इंग्लैंड और अमेरिका में लड़ाई होते-होते बच गई। संयुक्त राष्ट्र की सरकार ने दावा किया कि युद्ध के ज़माने में लड़ाई का जहाज दक्षिणी राज्यों को सौंपने का इंग्लैंड को कोई हक़ न था और इसलिए जितना नुक़सान हुआ वह उसे मिलना चाहिए। मामला एंजायत में डाला गया और अन्त में इंग्लैंड से अमेरिका को ३८,८९,१६६ पौण्ड हज़ाने के दिलवाये गये।

रूस के गृह-युद्ध में इंग्लैंड का हिस्सा कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण और अस्तर डालने-डाला था। जिस एक लड़ाकू जहाज के देने पर उसे इतना भारी हज़ाना चुकाना पड़ा उससे तो यह बहुत ज्यादा था। सोवियट की तरफ़ से सरकारी तौर पर बताया गया है कि रूस के विदेशी हस्तक्षेप की लड़ाइयों में साढ़े तेरह लाख आदमी मारे गये।

रूस के पुराने ऋज के सवाल का आखिरी फैसला नहीं हुआ, मगर ज्यों-ज्यों समय बीतता जा रहा है त्यों-त्यों उनका महत्त्व अपनेआप घटता जा रहा है।

मगर जोरदार और खतरनाक बहुत है। इसका प्रतीकार करने के लिए रूस के खिलाफ लगातार और बहुत कुछ झूठा प्रचार किया जाता है और सोवियट की दुष्टता की अजीब-अजीब कहानियाँ फैलाई जाती हैं। सोवियट नेताओं के लिए ब्रिटिश राजनीतिज्ञ ऐसी ज़यान काम में लगे हैं जो उन्होंने लड़ाई के वक़्त में दुश्मन के लिए भले ही ली हो, मगर और कभी किसीके लिए नहीं प्रयोग की। लॉर्ड बर्कनहेड ने सोवियट राजनीतिज्ञों को ऐसे वक़्त में 'हत्यारों का गुट' और 'मुट्ठीभर मोटे मंडक' बताया था, जब इन दोनों देशों में कोई लड़ाई न थी, बल्कि दोनों में परस्पर राजनैतिक सम्बन्ध थे। इन बातों से यह जाहिर है कि सोवियट और साम्राज्यवादी राष्ट्रों में सच्ची दोस्ती नहीं हो सकती। उनमें मौलिक भेद है। महायुद्ध के विजेता और पराजित राष्ट्रों में मेल हो सकता है, मगर साम्यवादियों और पूंजीवादियों में नहीं हो सकता। इन दोनों में अगर मेल हो सकता है तो वह अस्थायी ही हो सकता है। वह सिर्फ़ थोड़े वक़्त के लिए लड़ाई बन्द कर देने का निश्चय है।

सोवियट रूस और साम्राज्यवादी राष्ट्रों के झगड़े की जड़ बार-बार यह बताई जाती है कि रूस ने विदेशों का क़र्ज़ चुकाने से इन्कार कर दिया। आजकल तो यह ज़िन्दा सवाल नहीं रहा, क्योंकि इन चुरे दिनों में तो क़रीब-क़रीब सभी देशों ने क़र्ज़ नहीं चुकाया है। फिर भी यह सवाल समय-समय पर खड़ा होता रहता है। बोलशेविकों के हाथ में सत्ता आई, उसके थोड़े ही दिन बाद उन्होंने दूसरे देशों से लिया हुआ ज़ार के समय का क़र्ज़ रद्द कर दिया। वैसे तो १९०५ की असफल क्रान्ति के समय ही इस नीति का ऐलान कर दिया गया था। उन्होंने अपने उसूल की सचाई का यह सबूत दिया कि चीन वगैरा पूर्वी देशों में वे जो रुपया मांगते थे उसका दावा छोड़ दिया। महायुद्ध के हज़ानों की रक़म में से भी उन्होंने अपना हिस्सा छोड़ दिया। १९२२ में मित्र-राष्ट्रों ने इस क़र्ज़ के बारे में एक माग-पत्र (Memorandum) दिया, जिसके जवाब में सोवियट सरकार ने उन्हें याद दिलाया कि भूतकाल में कितने पूंजीवादी राष्ट्रों ने अपने क़र्ज़ रद्द कर दिये और विदेशियों की सम्पत्ति ज़ब्त कर ली थी। "जो सरकारें और प्रणालियाँ क्रान्तियों से पैदा होती हैं वे पिछले शासनों की ज़िम्मेदारियों को निभाने के लिए बँधी हुई नहीं हैं।" सोवियट सरकार ने मित्र-राष्ट्रों में से फ़्रांस को खास तौर पर स्मरण दिलाया कि उसने अपनी महान् क्रान्ति के समय क्या किया था।

"फ़्रांस की उस राष्ट्रीय परिपद् ने, जिसका फ़्रांस आज उचित उत्तराधिकारी होने का दावा करता है, २२ दिसम्बर १७९२ को ऐलान किया था कि अत्याचारियों की संधियों से जनता की सत्ता बँधी हुई नहीं है। इस घोषणा के अनुसार

कारण यही था कि यह संघर्ष कम किया जा सके। इसलिए किसानों को खानगी व्यापार करने की भी सुविधा दी गई।

विजली के प्रचार की योजना पर लेनिन का इतना ज्यादा जोर था कि उसका बनाया हुआ एक सूत्र (फार्मूला) मशहूर होगया। उसने कहा था कि “विजली और सोवियट पंचायतें मिलकर समाजवाद के बराबर हैं”। लेनिन की मौत के बाद भी विजली का प्रचार बड़ी तेजी से जारी रहा। किसानों पर असर डालने और खेती के तरीकों का सुधार करने के लिए दूसरा उपाय यह किया गया कि हल चलाने और दूसरे कामों के लिए भारी एंजिनों से काम लेना शुरू किया गया। ये यंत्र अमेरिका की फ़ोर्ड कम्पनी से लिये गये थे। रूस में मोटर से चलनेवाले यंत्र बनाने का बड़ा कारख़ाना क़ायम करने का ठेका भी सोवियट सरकार ने फ़ोर्ड कम्पनी को दिया। इस कारख़ाने में हर साल एक-एक लाख मोटरें तैयार हो सकती थीं। यह कारख़ाना ख़ासकर बोझा ढोने और हल चलाने के एंजिन बनाने के लिए ही था।

दूसरा काम, जिससे सोवियट और विदेशी स्वार्थों का संघर्ष हुआ, यह था कि रूस ने भी तेल और पेट्रोल निकालना और विदेशों में बेचना शुरू कर दिया। कोह-काफ़ के आज़रबैजान और ज़्याज़िया प्रदेशों में तेल बहुतायत से पाया जाता है। शायद यह उसी बड़े तेल-क्षेत्र का भाग है जो ईरान, मोसल और इराक़ तक फैला हुआ है। काल्पियन समुद्र पर बाकू नगर तो दक्षिणी रूस का बड़ा तेल-नगर है। रूस वालों ने बड़ी-बड़ी तेल की कम्पनियों से सस्ते भाव पर विदेशों में तेल और पेट्रोल बेचना शुरू कर दिया। अमेरिका की स्टैंडर्ड ऑयल कम्पनी, एंग्लोपर्सियन, रॉयल डचशेल कम्पनी और दूसरी कम्पनियाँ बड़ी ताक़तवर हैं और दुनिया-भर को तेल पहुँचाने का इनको एकाधिकार-सा मिला हुआ है। सोवियट के सस्ते भावों पर तेल और पेट्रोल बेचने से उन्हें बड़ा नुक़सान हुआ और गुस्सा आया। उन्होंने इसी तेल को ‘चोरी का तेल’ कह-कार सोवियट के खिलाफ़ आन्दोलन शुरू कर दिया, क्योंकि रूस ने कोहकाफ़ के तेल के कुछेक उनके पुराने पूँजीवादी मालिकों से छीन लिये थे। लेकिन थोड़े दिन बाद इन कम्पनियों ने इस ‘चोरों के तेल’ के साथ समझौता कर लिया।

मैंने इस ख़त में और दूसरे ख़तों में जगह-जगह पर ‘सोवियट’ या ‘सोवियटों’ का ज़िक्र किया है। कभी-कभी इसका भी ज़िक्र किया है कि ‘रूस’ ने यह किया और ‘रूस’ ने वह किया। इन सारे लफ़्ज़ों का इस्तेमाल मैंने उरा आज़ादी के साथ किया है और एक ही अर्थ में किया है। अब मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि यह चीज़ क्या थी और क्या है। तुम यह तो ज़रूर जानती हो कि दोलशेदिक़ त्रांज़ि के बाद, १९१७ के नवम्बर में, पेट्रोग्राड में सोवियट प्रजातन्त्र का ऐलान किया गया था। उरा का

इस बीच बड़े-बड़े पूंजीवादी और साम्राज्यवादी देश इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और इटली वही बात कर रहे हैं जिसपर वे रूस से इतने विगड़े थे। यह सही है कि वे न तो क्रूर रव करते हैं और न पूंजीवादी प्रणाली के आधार का विरोध करते हैं। वे तो सिर्फ रुपया चुराते नहीं।

रूस को ताज़ा होने के लिए समय की ज़रूरत थी और समाजवादी ढंग पर एक लम्बे-चौड़े देश के निर्माण के महान् कार्य में उसकी सारी शक्ति लगी हुई थी, इसलिए सोवियट नीति यह थी कि किसी भी तरह शान्ति रखी जाय। दूसरे देशों में समाजवादी क्रान्ति होने की निकट-भविष्य में सम्भावना नहीं दिखाई देती थी, इस कारण फिलहाल 'विश्व-क्रान्ति' का खयाल धुंधला पड़ गया था। पूर्वी देशों में शासन-प्रणाली पूंजीवादी थी, फिर रूस ने उनके साथ दोस्ती और सहयोग की नीति अपनाई। मैंने तुम्हें बताया है कि रूस, तुर्की, ईरान और अफ़ग़ानिस्तान में आपसी संधियों का जाल बिछ गया था। सभी को बड़े-बड़े साम्राज्यवादी देशों से एक-सा ही खौफ़ और नफ़रत थी, इसलिए वे सब मिल गये।

१९२१ में लेनिन ने जिस नई अर्थ-नीति की शुरुआत की थी उसका मतलब यह था कि मध्यवर्ग के किसान भूमि के समाजवादी विभाजन से सहमत होजायें। वहाँके मालदार किसानों को 'कुलक' कहते हैं। कुलक शब्द का अर्थ मुक़ा है। इन लोगों को प्रोत्साहन नहीं दिया गया, क्योंकि ये भी छोटे-छोटे पूंजीपति ही थे और भूमि के समाजवादी विभाजन का विरोध करते थे। लेनिन ने गाँवों में बिजली के प्रचार की भी बड़ी भारी योजना जारी की। बिजली के बड़े-बड़े यंत्र वहाँ लगाये गये। इसका मतलब हर तरह किसानों की मदद करना और देश को उद्योग-प्रधान बनाने के लिए रास्ता साफ़ करना था। सबसे बड़ा उद्देश्य यह था कि किसानों में उद्योगवादी मनोवृत्ति पैदा होजाय और शहरी मज़दूरों के वे ज्यादा नज़दीक आजायें। जिन गाँवों में बिजली की रोशनी लग गई और जिनकी खेती का ज्यादातर काम बिजली के जोर से होने लग गया, वहाँके किसान पुराना ढर्रा और अन्ध-विश्वास छोड़कर नये ढंग पर विचार करने लगे। शहरों और गाँवों के, शहरियों और देहातियों के स्वार्थों में सदा संघर्ष होता है। शहरी मज़दूर चाहता है कि गाँवों से तो उसे खाद्य सामग्री और कच्चा माल सस्ता मिले और वह जो माल कारख़ानों में बनाता है उसकी कीमत ऊँची मिले। उधर किसान चाहता है कि शहर से औज़ार और पक्का माल तो सस्ते भावों पर मिले और उसकी पैदा की हुई खाद्य सामग्री और कच्चे माल की कीमत ज्यादा-से-ज्यादा मिले। चार वर्ष के सैनिक साम्यवाद के कारण यह संघर्ष बहुत तीव्र हो रहा था। नई अर्थ-नीति के जारी करने का मुख्य

(२) सफ़ेद रूसी समाजवादी सोवियट प्रजातन्त्र ।

(३) उक्रेन समाजवादी सोवियट प्रजातन्त्र ।

(४) काफ़ के पार का समाजवादी सोवियट प्रजातन्त्र (Trans-Caucasian Socialist Federative Soviet Republic) ।

(५) तुर्कमीनिस्तान या तुर्कमीन समाजवादी सोवियट प्रजातन्त्र ।

(६) उजबक समाजवादी सोवियट प्रजातन्त्र ।

(७) ताजीकिस्तान या ताजिक समाजवादी सोवियट प्रजातन्त्र ।

मंगोलिया का भी सोवियट संघ से कुछ-न-कुछ सम्बन्ध है ।

इस तरह सोवियट संघ कई प्रजातन्त्रों का समूह है । इन अंगभूत प्रजातन्त्रों में से कुछ खुद भी संघ हैं । इस तरह रूसी प्रजातन्त्र बारह स्वशासन-भोगी प्रजातन्त्रों का संघ है । और क्राफ़ के पार का प्रजातन्त्र आज़रबैजान, ज्यार्जिया और आर्मीनिया के तीन प्रजातन्त्रों का संघ है । इन परस्पर-सम्बन्धित और एक-दूसरे पर निर्भर प्रजातन्त्रों के अलावा इनके भीतर बहुत-से 'राष्ट्रीय' और 'स्वशासन-भोगी' प्रदेश हैं । हर जगह इतने स्वशासन को जारी रखने का उद्देश्य यह है कि प्रत्येक जाति को अपनी संस्कृति और भाषा की रक्षा करने और ज्यादा-से-ज्यादा आज़ादी भोगने का मौक़ा मिले । कोशिश यह की गई है कि जहाँतक हो सके किसी एक राष्ट्रीय या जातीय समूह का दूसरे पर प्रभुत्व न रह सके । अल्पसंख्यक जातियों की समस्या को सोवियट ने जिस तरह हल किया है वह हमारे लिए दिलचस्पी की चीज़ है, क्योंकि हमारे सामने भी यह मुश्किल सवाल है । हमसे सोवियट की कठिनाइयाँ कहीं ज्यादा थीं, क्योंकि उन्हें १८२ मुस्लिम जातियों से निपटना था । लेकिन उन्होंने इस मसले को बहुत-सफलतापूर्वक हल किया है । उन्होंने बहुत आगे बढ़कर हरेक अलग जाति को मान लिया और उन्हें अपना काम और शिक्षा अपनी-अपनी भाषा में करने का उत्साह दिलाया । यह बात अलग-अलग अल्प-संख्यक जातियों की अलग होने की वृत्ति को खुश करने के लिए ही नहीं की गई, बल्कि यह अनुभव करके की गई कि देशी भाषा के जरिये ही सर्वसाधारण में सच्ची शिक्षा और संस्कृति की प्रगति होसकती है । इस नीति का नतीजा भी बहुत अच्छा निकला है ।

इस तरह संघ में एक ही तरह की पद्धति जारी नहीं की गई है, फिर भी उसके मुस्लिम हिस्से एक-दूसरे के इतने ज्यादा नज़दीक आते जा रहे हैं जितने ज़ार के बेमिदत राज्य में भी वे कभी नहीं आये थे । इसका कारण यह है कि उनके आदर्श समान हैं और वे सब मिलकर एक ही बड़ा काम कर रहे हैं । संघ के प्रत्येक प्रजातन्त्र को जब चाहे संघ से अलग होने का हक़ है, मगर ऐसा होने की नौबत शायद ही

साम्राज्य कोई एकरस राष्ट्रीय राज्य न था। खास रूस का योरोप और एशिया की बहुत-सी जातियों पर प्राधान्य था। इन जातियों की तादाद करीब दो सी थी और उनमें आपस में बड़ा भारी कर्कश था। जार के जमाने में उनके साथ गुलाम रियाया का-सा वर्ताव होता था और कमोवेश उनकी भाषाओं और संस्कृतियों का भी दमन किया जाता था। मध्य-एशिया के पिछड़े हुए लोगों के सुधार के लिए प्रायः कुछ नहीं किया गया। यहूदियों का कोई खास प्रदेश नहीं था और अल्प-संख्यक जातियों में सबसे बुरा वर्ताव उनके साथ होता था। यहूदियों के हत्याकाण्ड बुरी तरह मशहूर होगये थे। इन हत्याओं को 'पैग्रो' कहते थे। इस कारण इन पीड़ित जातियों के बहुत-से लोग रूसी क्रान्ति में शामिल हुए; लेकिन उनकी खास दिलचस्पी राष्ट्रीय क्रान्ति में थी, सामाजिक क्रान्तियों में नहीं थी। १९१७ के फरवरी महीने की क्रान्ति के बाद जो अस्थायी सरकार बनी उसने इन जातियों से बहुत-से वादे किये, मगर उसने किया-धरा कुछ नहीं। उधर लेनिन ने बोलशेविक दल के शुरू जमाने से ही इस बात पर जोर दिया था कि हरेक जाति को अपने भाग्य-निर्णय का पूरा हक दिया जाय, यहाँतक कि वे चाहें तो बिल्कुल अलग और स्वतन्त्र भी होजायें। यह पुराने बोलशेविक कार्यक्रम का अंग था। क्रान्ति के बाद बोलशेविकों ने देश की शासन-सत्ता हाथ में आते ही आत्म-निर्णय के इस उसूल में अपना विश्वास दुहराया।

गृह-युद्ध के समय ही जार का साम्राज्य चूर-चूर होगया था और थोड़े दिन तक सोवियट प्रजातन्त्र के नियन्त्रण में मास्को और लेनिनग्रेड के चारों ओर छोटा-सा इलाका रह गया। पश्चिमी राष्ट्रों का प्रोत्साहन पाकर बाल्टिक समुद्र से लगी हुई कई जातियाँ, अर्थात् फ़िनलैण्ड, एस्टोनिया, लटविया, और लिथुएनिया, स्वाधीन राज्य बन गईं। इसी तरह पोलैण्ड भी स्वाधीन बन गया। जब रूसी सोवियट की गृह-युद्ध में विजय हुई और विदेशी सेनायें अपने-अपने घर गईं तब साइबेरिया और मध्यएशिया में अलग-अलग और स्वाधीन सोवियट सरकारें बन गईं। इन सरकारों के समान उद्देश्य थे, इसलिए उनकी आपस में गहरी दोस्ती होना लाजिमी था। १९२३ में उन्होंने मिलकर सोवियट संघ बना लिया। इसका पूरा और सरकारी नाम समाजवादी सोवियट प्रजातंत्र संघ (Union of Socialist and Soviet Republics) है। अंग्रेजी में इसे संक्षेप में U. S. S. R. (यू० एस० एस० आर०) भी कहते हैं।

१९२३ से संघ के प्रजातन्त्रों की संख्या में कुछ परिवर्तन हुए हैं, क्योंकि एक-दो प्रजातन्त्रों के टुकड़े होगये हैं। मैं समझता हूँ आजकल संघ में ७ प्रजातन्त्र हैं :—

(१) रूस (Russian Socialist Federative Soviet Republic) जिसे संक्षेप में आर० एस० एफ० एस० आर० कहते हैं।

उसीने ज़बरदस्त मुश्किलात के बावजूद लाल सेना बनाई थी। इसी सेना ने गृह-युद्ध में और विदेशी दस्तगिरी के खिलाफ़ फ़तह हासिल की थी। फिर भी ट्राट्स्की बोल-शेविक दल में नया-ही-नया आया था और लेनिन को छोड़कर पुराने बोलशेविक न उसे बहुत चाहते थे और न उसपर विश्वास करते थे। इन पुराने बोलशेविकों में से स्टालिन साम्यवादी दल का प्रधानमंत्री बन गया था और उस हैसियत से रूस का प्रधान और बड़ा ही ताक़तवर संगठन उसके हाथ में था। ट्राट्स्की और स्टालिन में बनती न थी। वे एक-दूसरे से नफ़रत करते थे और किसी भी बात में मेल नहीं खाते थे। ट्राट्स्की प्रतिभाशाली लेखक और वक्ता था और उसने अपनी महान् संगठन और कार्य-शक्ति का भी सबूत दे दिया था। वह बड़ी तेज़ अक्ल का रौशन-दिमाग़ आदमी था। वह क्रान्ति के उसूलों का विकास करता रहता और विरोधियों पर चाबुक और बिच्छू के डंक की तरह चुभनेवाले वाग्बाण चलाया करता था। उसके सामने स्टालिन मामूली आदमी लगता था। वह शान्त, सरल और मामूली अक्ल वाला आदमी था। फिर भी वह एक बड़ा संगठनकर्ता, एक वीर योद्धा और क्रौलादी इरादों रखनेवाला यानी दृढ़-संकल्प वाला आदमी था। अब तो वह ‘क्रौलाद का आदमी’ कहलाने भी लगा है। इन दोनों बड़ी हस्तियों के लिए साम्यवादी दल में एकसाथ गुंजाइश नहीं थी।

स्टालिन और ट्राट्स्की का संघर्ष व्यक्तिगत ही नहीं था, उससे ज्यादा और कुछ भी था। क्रान्ति के विकास के बारे में दोनों की नीति और साधन अलग-अलग थे। ट्राट्स्की ने क्रान्ति के बहुत वर्ष पहले से ही ‘स्थायी क्रान्ति’ के उसूल गढ़ रखे थे। उनके मुताबिक़ किसी एक देश के लिए पूरे समाजवाद की स्थापना करना मुमकिन नहीं, भले ही उस देश की स्थिति कितनी ही अच्छी और अनुकूल हो। सच्चा समाजवाद विश्व-क्रान्ति के बाद ही आ सकता है, क्योंकि उसी वक़्त किसानों को पूरा समाजवादी बनाया जा सकता है। आर्थिक विकास में समाजवाद पूंजीवाद के बाद की दूसरी ही ऊँची मंजिल है। जब पूंजीवाद अन्तर्राष्ट्रीय होगया, तभी वह बैठ गया। आज अधिकांश जगत् में हम यही होता देख रहे हैं। इस अन्तर्राष्ट्रीय रचना का काम समाजवाद ही सफलतापूर्वक कर सकता है। इसीलिए समाजवाद अनिवार्य है। मार्क्स का यही उसूल है। लेकिन समाजवाद को एक ही देश यानी राष्ट्रीय रूप में ही अमल में लाने की कोशिश की जायगी तो उसका अर्थ पीछे हटकर नीची आर्थिक सीढ़ी पर उतरना होगा। अन्तर्राष्ट्रीयता उन्नति मात्र की उल्लरी बुनियाद है और इसमें सामाजिक उन्नति भी शामिल है। अन्तर्राष्ट्रीयता से पीछे हटना न संभव है और न वाञ्छनीय या मुनासिब ही है। इसलिए ट्राट्स्की के मत से सोवियट संघ जैसे बड़े किन्तु अकेले देश में समाजवाद का निर्माण कर सकना आर्थिक दृष्टि से असम्भव है। कितनी ही बातें ऐसी हैं जिनमें

आये, क्योंकि पूंजीवादी संसार के विरोध के सामने समाजवादी प्रजातन्त्रों के संघ में शामिल रहने में उन्हें बहुत बड़े-बड़े फायदे हैं।

अवश्य ही इस संघ का प्रधान प्रजातन्त्र रूसी प्रजातन्त्र है। यह लेनिनग्रेड से ठेठ साइबेरिया तक देश के आर-पार फैला हुआ है। सफ़ेद रूस पोलैण्ड से लगा हुआ है। उक्रेन काले समुद्र के किनारे-किनारे दक्षिण में है। यह रूस का अन्न-भण्डार है। कोह फ़ाफ़ के पार वाला प्रजातन्त्र, जैसा इसके नाम से ही जाहिर है, फ़ाफ़ पहाड़ के उसपार कैस्पियन और काले समुद्र के बीच में है। इस प्रजातन्त्र में आर्मीनिया भी शामिल है। यह मुद्दतों तक तुर्कों और आर्मीनियों के भयंकर हत्याकाण्ड की रंगस्थली रहा है। अब सोवियट प्रजातन्त्र बन जाने से यहाँके लोग शान्तिपूर्ण कामों में लग गये दीखते हैं। कैस्पियन समुद्र की दूसरी ओर तुर्कमनीस्तान, उजबकिस्तान और ताजकिस्तान नामक तीन मध्य-एशियाई प्रजातन्त्र हैं। उजबकिस्तान में बुखारा और समरकन्द के मशहूर शहर हैं। ताजकिस्तान अफ़ग़ानिस्तान के ठीक उत्तर में है और यह हिन्दुस्तान के सबसे पास का सोवियट इलाक़ा है।

मध्य-एशिया के साथ बहुत पुराने जमाने से हमारे ताल्लुकात रहे हैं, इसलिए इन मध्य एशियाई प्रजातन्त्रों के साथ हमारी ख़ास दिलचस्पी है। पिछले चन्द सालों में उन्होंने जो उल्लेखनीय प्रगति करली है उसके कारण वे और भी आकर्षक होगये हैं। ज़ारशाही में वे बहुत पिछड़े हुए और अन्धविश्वासी देश थे। उनमें शिक्षा का प्रचार बहुत कम था और उनकी स्त्रियाँ क़रीब-क़रीब परदे में रहती थीं। लेकिन अब वे बहुत बातों में हिन्दुस्तान से आगे हैं।

: १८० :

‘पायाटिलेटका’ अथवा रूस की पंचवर्षीय योजना

९ जुलाई, १९३३

जबतक लेनिन जिया वही सोवियट रूस का एकमात्र नेता रहा। उसके आख़री फ़ैसले के सामने सब झुक जाते थे। जब कभी संघर्ष होता तो उसकी बात क़ानून की तरह मान ली जाती थी और साम्यवादी दल के आपसी झगड़े पलभर में मिटा देती थी। उसकी मृत्यु के बाद विपत्ति का आना लाज़िमी था, क्योंकि प्रतिस्पर्धी यानी मुत्तालिफ़ ग़िरोह और शक्तियाँ प्रभुत्व के लिए आपस में लड़ने लगीं। लेनिन के बाद बाहर की दुनिया की ओर कुछ हद तक रूस की नज़र में भी ट्राट्स्की बोलशेविकों में प्रधान आदमी था। ट्राट्स्की ने ही अक्टूबर की क्रान्ति में प्रमुख भाग लिया था और

इस तरह इन दो बड़े आदमियों का बड़ा झगड़ा खत्म हुआ और जिस रंग-मंच पर ट्राट्स्की ने इतनी वीरता और तेजस्विता का अभिनय किया था वहाँसे उसे हटा दिया गया। जिस सोवियट संघ का वह एक प्रधान निर्माणकर्त्ता था उसको छोड़कर उसे जाना पड़ा। इस जबरदस्त हस्ती से करीब-करीब सभी पूंजीवादी देश भयभीत थे। उन्होंने उसे अपने यहाँ नहीं आने दिया। दूसरे यूरोपियन देशों की तरह इंग्लैण्ड ने भी उसे घुसने की इजाजत नहीं दी। अन्त में उसे तुर्की में शरण मिली और वह आज-कल प्रिकिपो में रहता है। मैं समझता हूँ यह इस्तम्बोल से आगे एक छोटा-सा टापू है। पद और दूसरे काम-काज की जिम्मेवारियों और झंझटों से छूटकर अब वह लिखने-पढ़ने के काम में लग सकता है। उसके ऐसा करने से परिणाम भी सुन्दर निकला है। उसका नया ग्रंथ *History of the Russian Revolution* (रूस की क्रान्ति का इतिहास) है। अभी उसकी उम्र भी बहुत नहीं है। वह कोई पचास-पचपन वर्ष का होगा। संभव है भविष्य के गर्भ में उसके लिए बहुत काम रक्खा हो। आगे चलकर उसका कुछ भी हो, संसार के इतिहास में उसके लिए एक कोना सुरक्षित है; और जिस संघर्ष के साथ सोवियट रूस में उसकी हस्ती मिट गई वह एक दुःखान्त नाटक तो है, लेकिन इससे उसके प्रतिभाशाली और अद्वितीय जीवन में कला का स्पर्श होगया। प्रिकिपो में बैठकर वह कड़ी भाषा में स्टालिन और उसके साथियों की टीका करता रहता है और संसार के अनेक भागों में नियमित ट्राट्स्की-दल खड़ा होगया है। साम्यवाद का यह अंग सत्ताधारी साम्यवादी दल को पसन्द नहीं है, क्योंकि वह साम्यवादी अन्तर्राष्ट्रीय परिषद् की आज्ञा मानता है और परिषद् पर स्टालिन का प्रभुत्व है।

ट्राट्स्की का निपटारा करके स्टालिन ने असाधारण साहस के साथ कृषि-संबंधी अपनी नई नीति के काम को हाथ में लिया। उसके सामने बड़ी कठिन परिस्थिति थी। पढ़े-लिखों में बेकारी और मुसीबत थी और मजदूरों में भी हड़तालें हो चुकी थीं। उसने कुलकों यानी मालदार किसानों पर भारी कर लगाये और यह रुपया सम्मिलित खेती के निर्माण में खर्च किया। सम्मिलित खेती का यह मतलब है कि छोटे-छोटे बहुतेरे किसान सहयोग के तरीके पर बड़ी-बड़ी खेतियाँ करते हैं और उसका मुनाफ़ा आपस में बाँट लेते हैं। सम्पन्न किसानों ने इस नीति का विरोध किया और वे सोवियट सरकार से बहुत बिगड़े। उन्हें यह डर था कि उनके मवेशी और खेतों का सामान उनके बरिद्र पड़ोसियों के मवेशियों और सामान के साथ मिला दिया जायगा। इस डर के मारे उन्होंने सचमुच पशु-धन नष्ट कर दिया। इतने ज्यादा मवेशी मारे गये कि अगले साल खाने-पीने की चीजों की, माँस की, और दूध भस्करन वगैरा की बहुत ज्यादा कमी रही।

सोवियट को पश्चिमी योरप के उद्योगवादी देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। यह तो शहर और गाँव के सहयोग की-सी बात हुई। उद्योगवादी पश्चिम को शहर समझ लिया जाय; और रूस को अधिकांश में गाँव मान लिया जाय। राजनैतिक दृष्टि से भी ट्राट्स्की की राय में पूँजीवादी वातावरण के बीच में अकेला समाजवादी देश बहुत दिनों तक ज़िन्दा नहीं रह सकता। दोनों में ज़रा भी मेल नहीं होसकता। हम देख चुके हैं कि यह बात कितनी सच है। या तो पूँजीवादी राष्ट्र उस समाजवादी देश को कुचल देंगे या पूँजीवादी देशों में सामाजिक क्रान्तियाँ होकर सब जगह समाजवाद क़ायम हो जायगा। अलबत्ता कुछ समय या कुछ वर्षों तक दोनों साय-साय रह सकते हैं, मगर उनका समतोल स्थिर नहीं होगा।

बहुत हद तक यही ख़याल क्रान्ति के पहले और पीछे सभी बोलशेविक नेताओं का रहा है। वे बड़े अधीर होकर विश्व-क्रान्ति या कम-से-कम कुछ यूरोपियन देशों में क्रान्ति की वाट देखते रहे। महीनों तक योरप की हवा में गर्जना होती रही, मगर तूफ़ान वर्षा हुए बिना ही निकल गया। रूस अपनी पंचवर्षीय योजना में लग गया और साधारण जीवन बिताने लगा। ट्राट्स्की ने इसपर ख़तरे की घण्टी बजाई। उसने चेतावनी दी कि अगर विश्व-क्रान्ति के उद्देश्य से उग्र नीति काम में नहीं ली गई तो रूस की क्रान्ति भी जोखिम में पड़ जायगी। इस चेतावनी का नतीजा यह हुआ कि ट्राट्स्की और स्टालिन में ज़बरदस्त द्वन्द्व-युद्ध छिड़ गया और इस टक्कर ने कुछ वर्षों तक बराबर साम्यवादी दल को हिला रक्खा। दल की सत्ता स्टालिन के हाथ में थी, इसलिए उसकी पूरी जीत हुई। ट्राट्स्की और उसके हिमायती क्रान्ति के दुश्मन समझे गये और दल में से निकाल दिये गये। ट्राट्स्की को पहले तो साइबेरिया भेजा गया और फिर संघ के बाहर निर्वासित कर दिया गया।

स्टालिन और ट्राट्स्की में जल्दी ही भिड़न्त होने का कारण यह था कि स्टालिन ने किसानों को समाजवाद के पक्ष में करने के लिए कृषि के बारे में उग्र नीति जारी करने का प्रस्ताव किया। यों दूसरे देशों में क्या हो रहा है इसका ख़याल न करके अकेले रूस में समाजवाद का निर्माण करने की कोशिश थी। ट्राट्स्की ने इसे मंजूर नहीं किया। वह अपने 'स्थायी क्रान्ति' के उसूल पर डटा रहा। उसका कहना था कि इसके बिना किसान पूरी तरह समाजवादी नहीं बन सकते। असल बात यह थी कि स्टालिन ने भी ट्राट्स्की की बहुत-सी सूचनाओं पर अमल तो किया, मगर किया उसने अपने ढंग से, ट्राट्स्की के ढंग पर नहीं। इसके बारे में ट्राट्स्की ने अपने आत्म-चरित्र में लिखा है: "राजनीति में निर्णायक यही बात नहीं होती कि वस्तु क्या है, बल्कि यह होती है वह कैसे की जाती है और कौन करता है।"

में एक भी कमजोर या पिछड़ी कड़ी से देर होने या सारा सिलसिला बन्द हो जाने की सम्भावना थी। लेकिन पूँजीवादी देशों की अपेक्षा रूस को एक बड़ी सुविधा थी। पूँजीवाद में ये सारे काम व्यक्तियों की इच्छा और संयोग पर निर्भर रहते हैं और लाग-डांट के कारण प्रयत्न बेकार भी बहुत होते हैं। अलग-अलग पदार्थ पैदा करनेवाले मूलतः व्यक्तिगत क्रिस्म के मजदूरों में कोई सहयोग नहीं होता। संयोग से बाज़ार में आकर खरीदारी या बिक्री करनेवालों के बीच में कुछ सहयोग होजाता है। सार यह है कि बड़े पैमाने पर और योजना के अनुसार काम नहीं होता। अलग-अलग व्यापारी या कम्पनियाँ अपने भावी कामों की योजनाएँ बना सकती हैं और बनाती हैं, मगर इन व्यक्तिगत योजनाओं में दूसरों से बाज़ी मार लेजाने की सम्भावना ही रहती है। राष्ट्रीय दृष्टि से इसका नतीजा उलटा ही होता है। इसका अर्थ यह होता है कि विपुलता और अभाव, सम्पन्नता और विपन्नता साथ-साथ रहते हैं। सोवियट सरकार को यह सुविधा थी कि देशभर के भिन्न-भिन्न उद्योगों और प्रवृत्तियों पर उसका नियन्त्रण था। इसलिए वह हरेक प्रवृत्ति को उचित स्थान देकर एक ही योजना बना सकी और उसको अमल में ला सकी। इसमें शक्ति नष्ट होने की भी गुंजाइश नहीं रहती। सिर्फ़ हिसाब लगाने या काम चलाने या काम चलाने में जो भूलें होजाती हैं उन्हींसे जो हानि होती है सो होती है। ये भूलें भी अलग-अलग आदमियों के हाथ में नियन्त्रण होने की हालत में ज्यादा होती हैं और सारा नियन्त्रण एक ही जगह से होने में कम होती हैं।

पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य सोवियट-संघ में उद्योगवाद की जड़ मजबूत करना था। कल्पना यह नहीं थी कि कपड़ा वगैरा जैसी सबकी जरूरत की चीजें बनाने के कुछ कारखाने खोल दिये जायें। हिन्दुस्तान की तरह बाहर से मशीनें मंगाकर लगा लेना तो आसान था। खपत का भाल बनाने के इन कारखानों को ‘हलके उद्योग’ कहते हैं। इन हलके उद्योगों का दारोमदार ‘भारी उद्योगों’ पर होता है। लोहा, फौलाद और यंत्र बनाने के कारखाने भारी उद्योग कहलाते हैं। ये छोटे उद्योगों के लिए यंत्र, सामान और एंजिन वगैरा तैयार करते हैं। सोवियट सरकार ने बहुत दूर की सोचकर पंचवर्षीय योजना में इन आधार-भूत या बड़े कारखानों पर सारी शक्ति लगाने का निश्चय किया। इस तरह उद्योगवादी बुनियाद मजबूत होजायगी और वाद में छोटे-छोटे उद्योग भी सरलता से खड़े हो सकेंगे। बड़े कारखानों से रूस को यंत्रों और लड़ाई के सामान के लिए भी दूसरे देशों के मुँह की ओर नहीं देखना पड़ेगा।

मौजूदा परिस्थिति में रूस के लिए बड़े-बड़े उद्योग पसन्द करना ही ठीक था, मगर इससे लोगों को प्रयत्न भी बहुत अधिक करना पड़ा और कष्ट भी खूब सहने

इस बात की स्टालिन को आशा नहीं थी, मगर वह जी कड़ा करके अपने कार्यक्रम पर अटल रहा। इतना ही नहीं, उसने कार्यक्रम को बढ़ाया और उसे सारे देश के लिए कृषि और उद्योग दोनों के एक बलशाली आयोजन के रूप में बदल दिया। किसान को उद्योग के निकट लाना था और इसके लिए राज्य की ओर से नमूने के बड़े-बड़े और सम्मिलित खेत कायम करना था। बड़े-बड़े कारखाने खोलकर पानी से, बिजली निकालने के यंत्र लगाकर, खानों का काम और इसी तरह के अनेक दूसरे काम जारी करके देश-भर को उद्योगवादी बनाना था। साथ ही शिक्षा, विज्ञान, सहयोगी खरीद-फरोकत, लाखों मजदूरों के लिए मकान बनवाने और सब तरह उनके रहन-सहन का तरीका ऊँचा करने वगैरा के काम हाथ में लेने थे। यही मशहूर 'पंच-वर्षीय योजना' थी। इसी लोग इसे 'पायाटिलेटका' कहते हैं। यह कार्यक्रम इतना विशाल, उच्चाकांक्षापूर्ण और कठिन था कि किसी धनी और उन्नत देश के लिए भी एक पीढ़ी में पूरा होना मुश्किल था। रूस जैसे पिछड़े हुए और गरीब मुल्क के लिए इसे हाथ में लेना तो हृदय दर्जों की बेवकूफी ही मालूम होती थी।

यह पंचवर्षीय योजना बहुत ध्यानपूर्वक विचार और खोज के बाद बनी थी, वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने सारे देश की स्थिति की जाँच की थी और बहुत-से विशेषज्ञों ने इस समस्या पर चर्चा करली थी कि कार्यक्रम के एक भाग का दूसरे के साथ कैसे मेल बिठाया जाय। सच्ची कठिनाई इस मेल बिठाने के काम में आई थी। अगर कारखाने के लिए कच्चे माल का अभाव हो तो बड़ा सारा कारखाना खोल देने के मानी ही क्या? अगर कच्चा माल मिल भी जाय तो उसे कारखाने में पहुँचा देने का इन्तजाम होना चाहिए। इस तरह दुलाई की समस्या हल करनी पड़ती है, उसके लिए रेलवे बनानी पड़ती है। रेलवे के लिए कोयला चाहिए और उसके लिए खानें चलाना आवश्यक है। खुद कारखाने को चलाने के लिए कोई शक्ति चाहिए। यह शक्ति जुटाने के लिए बड़ी-बड़ी नदियों को बाँधकर उनके पानी से बिजली पैदा की गई और यह बिजली तारों के जरिये कारखानों और खेतों में पहुँचाई गई और शहरों और गाँवों में रोशनी के लिए इस्तेमाल की गई। फिर इन सब कामों के लिए इंजीनियरों, मिस्त्रियों और कुशल मजदूरों की जरूरत होती है और थोड़े-से समय में बीसों हजार स्त्री-पुरुषों को तालीम दे देना हँसी-खेल नहीं है। हजारों की तादाद में खेतों पर काम करने के लिए भारी-भारी एंजिन भेज तो दिये जायें, मगर उन्हें चलाये कौन?

ये थोड़े-से उदाहरण तुम्हें इस बात की कल्पना करने के लिए दे दिये हैं कि पंचवर्षीय योजना से कैसी-कैसी घबरा देनेवाली और पेचीदा समस्यायें पैदा हुई होंगी। इसमें एक-एक भूल से दूरवर्ती परिणाम निकल सकते थे। कार्य की श्रृंखला

को ही पहलेपहल मिला है कि उसने राष्ट्र की सारी शक्ति नाश के नहीं निर्माण के शान्तिपूर्ण प्रयत्न में, यानी एक पिछड़े हुए देश का औद्योगिक उत्थान करने और उसे समाजवाद के ढाँचे में ढालने के काम में, लगादी। मगर कष्ट भी लोगों को और खास तौर पर उच्च और मध्यमवर्ग के किसानों को बहुत ही हुआ और कई बार ऐसा मालूम होने लगता था कि यह सारी विशाल योजना बैठ जायगी और शायद अपने साथ-साथ सोवियट सरकार को भी ले डूबेगी। ऐसी अवस्था में टिके रहना और-मामूली हिम्मत का ही काम था। बड़े-बड़े बोलशेविकों ने विचार किया कि कृषि-संबंधी कार्य-क्रम का भार और उससे होनेवाला कष्ट असहनीय है और लोगों को आराम मिलना चाहिए। मगर स्टालिन का यह खयाल नहीं था। वह जी कड़ा करके चुपचाप अड़ा रहा। वह बात करना नहीं जानता था। सार्वजनिक भाषण वह शायद ही कभी देता था। वह ऐसा दीखता था मानों भाग्य की अटल रेखाएँ लोहे की मूर्ति बनकर एक निश्चित लक्ष्य की ओर बढ़ रही हैं। उसके इस साहस और वृद्ध संकल्प की छूत उसके साम्यवादी दल के सदस्यों और दूसरे कार्यकर्ताओं को भी लगी।

पंचवर्षीय योजना के पक्ष में लोगों का जोश कायम रखने और उन्हें अपने प्रयत्न में लगा रखने के लिए लगातार प्रचार-कार्य किया गया। पानी से बिजली निकालने के बड़े-बड़े कारखानों, बाँधों, पुलों, पुतलीघरों और सामूहिक खेतों के बनाने में जनता ने खूब दिलचस्पी ली। इंजीनियरिंग सबसे लोकप्रिय धन्धा होगया और इंजीनियरिंग के बड़े-बड़े सफल कार्यों की वैज्ञानिक तफ़्सील से अख़बार भरे रहने लगे। जंगल और मरुभूमियाँ आबाद होगईं और एक-एक बड़े कारखाने के आसपास बड़ा और नया शहर खड़ा होगया। नई सड़कें, नई नहरें और नई रेलवे बन गईं। रेलें ज्यादातर बिजली की थीं। हवाई जहाजों के जरिये आने-जाने की प्रणाली का विकास होगया। रासायनिक पदार्थों, युद्ध-सामग्री और औजारों के उद्योग कायम होगये और सोवियट-संघ भारी एंजिन, मोटरें, रेल के डब्बे, हवाई जहाज और पनचक्कियाँ सब बनाने लग गया। बिजली का दूर-दूर तक प्रचार होगया और रेडियो आम तौर पर काम में आने लगा। बेकारी का नाम-निशान भी नहीं रहा, क्योंकि निर्माण-कार्य और दूसरा काम इतना था कि उसमें जितने मजदूर मिल सकते थे वे सब लग गये। बहुत-से योग्य इंजीनियर विदेशों से आये। उनका स्वागत किया गया। याद रहे कि यह बात उन दिनों की है जब सारे पश्चिमी योरप और अमेरिका में मन्दी छाई हुई थी और बेकारों की तादाद बुरी तरह बढ़ गई थी।

मगर पंचवर्षीय योजना के काम में कोई दिक्कत न आई हो, सो बात नहीं थी। कई बार बड़ा सगड़ा खड़ा होजाता था, सहयोग की भी कमी होजाती और प्रतिक्रिया

पड़े। बड़े उद्योगों पर छोटे उद्योगों से बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ता है और इससे भी बड़ा अन्तर यह है कि बड़े उद्योगों से बहुत देर में मुनाफा होता है। कपड़े का कारखाना खोलते ही कपड़ा तैयार होने लगता है और वह तुरन्त बिक सकता है। यही हाल दूसरे छोटे कारखानों का है जो खपत की चीजें बनाते हैं। मगर, लोहे या फ़ीलाव के कारखाने में तो फ़ीलाव की पटरी या एंजिन ही बन सकते हैं। ये जब-तक रेलवे न बन जाय तबतक न खप सकते हैं, न काम आ सकते हैं। इसमें समय लगता है और तबतक बहुत-सा रुपया उस व्यवसाय में रुका रहता है और उतना ही देश दरिद्र रहता है।

इस कारण रूस के लिए इतनी ज्यादा तेज़ी के साथ बड़े-बड़े कारखानों का बनाना बड़ी भारी क़ुर्यानी थी। यह सारी रचना, ये सारे यंत्र बाहर से आये थे, उनकी क़ीमत चुकानी पड़ी थी और वह भी सोना-चांदी के रूप में। इसकी व्यवस्था कैसे की गई? सोवियट-संघ के निवासियों ने अपने पेट पर पट्टी बांध ली—आधे भूखे रहे, और बाहरवालों को चुकाने के लिए ज़रूरी चीजों से भी अपनेको वंचित रक्खा। उन्होंने अपने खाद्य-पदार्थ बाहर भेजे और उनके मूल्य से यंत्रों के दाम चुकाये। गेहूँ, फ़ंगरान, जौ, गल्ला, तरकारी, फल, अण्डे मक्खन, मांस, पक्षी, शहद, मछली, शकर, तेल, मिठाइयाँ आदि जो भी चीजें बिक सकती थीं वे सब बिकने को भेज दीं। इन चीजों के भेजने का अर्थ यह था कि उन्होंने इनके बिना काम चलाया। रूसियों को मक्खन मिला ही नहीं या बहुत कम मिला, क्योंकि वह यंत्रों की क़ीमत में बाहर चला जाता था। यही हाल और बहुत-से माल का हुआ।

यह प्रबल प्रयत्न पंचवर्षीय योजना के रूप में १९२९ में शुरू हुआ। क्रान्ति की भावना फिर फैल गई, आदर्श की पुकार पर सर्वसाधारण के दिल हिल गये और उन्होंने इस नवीन संग्राम में अपनी सारी शक्ति लगा दी। यह संग्राम किसी विदेशी या भीतरी दुश्मन के खिलाफ़ नहीं था। यह लड़ाई रूस की पिछड़ी हुई हालत के, पूँजीवाद के अवशेष के और नीचे रहन-सहन के ढंग के खिलाफ़ थी। लोगों ने फिर से उत्साहपूर्वक त्याग करना बर्दाश्त किया और फ़कीरों की-सी सख्त जिन्दगी बिताई। उन्होंने महान् भविष्य के संकेत पर वर्तमान का बलिदान कर दिया। करते भी क्यों नहीं? उन्हींको तो उसके निर्माण का गर्व और श्रेय था।

एक काम को पूरा करने में राष्ट्रों ने पहले भी अपनी सारी शक्तियाँ लगाई हैं, मगर यह बात युद्ध-काल में ही हुई है। महासमर के समय जर्मनी, इंग्लैंड और फ़्रांस के जीवन का एक ही लक्ष्य था; और वह था लड़ाई में जीतना। इस उद्देश्य के सामने और सब बातें गौण हो गई थीं। मगर यह श्रेय इतिहास में सोवियट रूस

सोवियट संघ की कठिनाइयाँ, असफलतायें और सफलतायें

११ जुलाई, १९३३

सोवियट रूस ने पंचवर्षीय योजना बनाकर एक बड़ा भारी काम हाथ में लिया था। यह योजना अकेले ही कई क्रान्तियों के बराबर थी। इसमें खेती और उद्योग दोनों की क्रान्तियाँ शामिल थीं। पुराने ढंग से छोटे पैमाने पर खेती करनेवाले किसानों में बड़े पैमाने पर सामूहिक और यन्त्रों द्वारा खेती का तरीका चला देना और रूस जैसे उद्योगहीन देश को इस तेजी से उद्योगवादी बना देना क्रान्ति से क्या कम है ? मगर योजना के बारे में सबसे दिलचस्प बात थी वह भावना जो उसके पीछे काम कर रही थी, क्योंकि यह भावना राजनीति और उद्योग दोनों के लिए नई है। यह भावना विज्ञान की भावना है। इसमें समाज-रचना के काम में सोच-समझकर वैज्ञानिक तरीके इस्तेमाल करने की कोशिश है। ऐसी बात किसी उन्नत-से-उन्नत देश में भी पहले नहीं हुई थी। इस तरह मानवीय और सामाजिक मामलों में विज्ञान के साधनों का उपयोग करना ही सोवियट योजना की बड़ी भारी खासियत है। यही वजह है कि सारी दुनिया इस वक्त योजना बनाने की चर्चा कर रही है, मगर जब पूंजीवाद जैसी सामाजिक व्यवस्था का आधार ही स्पर्धा यानी लाग-डांट और मालदारों के स्वार्थों की रक्षा है तो उसमें कोई भी सफल योजना बनाना कठिन है। इसलिए योजना बनाने और पूंजीवादी देशों में सहयोग कायम करने की कोरी बातें ही होकर रह जाती हैं।

मगर मैं तुम्हें कह चुका हूँ कि पंचवर्षीय योजना से कष्ट, कठिनाई और गड़बड़ बहुत हुई। लोगों को इसकी भयंकर क्रीमत चुकानी पड़ी। ज्यादातर लोगों ने यह क्रीमत खुशी-खुशी चुकाई और उज्ज्वल भविष्य की उम्मीद में क्रूरबानी की और कष्ट सह लिये। कुछ लोगों ने यह क्रीमत मन से नहीं, बल्कि सोवियट सरकार के दबाव से चुकाई। जिनको सबसे ज्यादा तकलीफ हुई उनमें कुलक या मालदार किसान भी थे। उनके पास दौलत ज्यादा थी और उनका खास असर था। इसलिए नई योजना से उनका मेल नहीं बैठता। वे समाज के पूंजीवादी अंग थे और इस कारण वे सामूहिक खेती का समाजवादी ढंग पर विकास होने में बाधक थे। अक्सर वे इस समूहवाद का विरोध करते थे, कभी-कभी गिरोहों में घुसकर उन्हें भीतर से कमजोर करते थे या उनसे नाजायज फ़ायदा उठाने की कोशिश करते थे। सोवियट सरकार ने उनपर हथौड़े बरसाये। सरकार ने मध्यमवर्ग के बहुत-से आदमियों पर भी बड़ी सख्तियाँ कीं, क्योंकि उनपर दुश्मन की तरफ़ से जासूसी और गुप्त विरोध करने का शक था। इस सन्देह

और हानि भी होजाती थी। लेकिन इन सब बातों के होते हुए भी काम का जोश बढ़ता गया और हमेशा ज्यादा-से-ज्यादा काम की मांग बनी रही। फिर तो यह आवाज आने लगी कि पाँच वर्ष की योजना चार ही वर्ष में पूरी हो, मानों इस विलक्षण कार्यक्रम के पूरा करने के लिए पाँच वर्ष का समय थोड़ा नहीं था। योजना जाते से ३१ दिसम्बर १९३२ को यानी चार वर्ष के अखीर में पूरी हुई; और १९३३ की प्रथम जनवरी से यानी तुरन्त ही दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू होगई।

पंचवर्षीय योजना की चर्चा करते समय कुछ लोग तो इसे बड़ी भारी कामयाबी बताते हैं और कुछ कहते हैं यह नाकामयाब रही। कहां-कहां नाकामयाबी रही, यह बताना आसान है; क्योंकि कई बातों में लोगों की आशायें पूरी नहीं हुईं। आज रूस में बहुत बातों में भयंकर विपमता है। मुख्य अभाव कुशल और तालीमयाप्त कार्यकर्त्ताओं का है। कारखाने अधिक और उन्हें चलाने के लिए योग्य इंजीनियर थोड़े हैं। भोजनालय और पाकशालायें ज्यादा और होशियार रसोइये कम हैं। यह बेहिसाब हालत अवश्य ही थोड़े समय बाद नहीं रहेगी, या कम-तो हो ही जायगी। एक बात साफ है कि पंचवर्षीय योजना ने रूस की बिल्कुल कायापलट करदी है। सामन्तशाही से निकलकर वह एकदम उन्नत उद्योगवादी देश होगया है। संस्कृति की भी आश्चर्यजनक प्रगति हुई है। समाज की सेवा के साधन, स्वास्थ्य-रक्षा के उपाय और आकस्मिक घटना का बीमा आदि की व्यवस्था संसार-भर से अधिक व्यापक और उन्नत ढंग की हैं। मुसीबत और गरीबी होते हुए भी बेकारी और भूख का भयंकर भत जो दूसरे देशों के मजदूरों पर सवार है उसका रूस से काला मुंह होगया है। लोगों की आर्थिक निश्चिन्तता की नई अनुभूति होरही है।

पंचवर्षीय योजना की सफलता-असफलता की दलीलों में कोई सार नहीं है। उसका अमली उत्तर तो सोवियट-संघ की आज की हालत से मिल जाता है। दूसरा जवाब यह भी है कि इस योजना ने संसार-भर के दिमाग पर अपनी छाप बिठाई है। अब सभी तीन वर्ष, पाँच वर्ष और दस वर्ष की योजनाओं की बात करते हैं। यहाँ तक कि आम तौर पर समय के एक पीढ़ी पीछे रहनेवाले भारतीय गवर्नरों को भी योजनाओं की बात करने का चस्का लग गया है। सोवियट ने इस शब्द में जादू भर दिया है।

१९१७ में आबादी थी	१३ करोड़
१९२६ " " "	१४ करोड़ ९० लाख
१९२९ " " "	१५ करोड़ ४० "
१९३० " " "	१५ करोड़ ८० "
१९३३ " (वसन्त ऋतु का अनुमान)	१६ करोड़ ५० "

इस तरह १५ वर्ष से ज़रा ज्यादा समय में ३॥ करोड़ आदमी बढ़ गये। २६ फ़ी सदी वृद्धि एक सैरमामूली बात है।

वैसे सारे सोवियट संघ की ही आबादी बढ़ी, मगर शहरों में विशेष वृद्धि हुई। पुराने नगर और भी बड़े बन गये और मरुभूमि में नये-नये कारख़ानों के नगर खड़े होगये। पंचवर्षीय योजना में बड़े-बड़े उद्योग-धन्धों का निर्माण हुआ। उनमें काम बहुत था। इससे आकर्षित होकर बेशुमार किसान अपने गाँव छोड़-छोड़कर शहरों में जा पहुँचे। रुस-भर में १९१७ में एक लाख या उससे अधिक आबादी के २४ शहर थे। १९२६ में इनकी संख्या ३१ और १९३३ में ५० से ऊपर होगई। पंद्रह साल के भीतर सोवियट ने १०० से ऊपर उद्योग-नगर बना दिये। १९१३ से १९३२ के बीच में मास्को की आबादी १६ लाख से ३२ लाख यानी दुगुनी होगई। लेनिनग्रेड में भी दस लाख आदमी बढ़ गये और वहाँ तीस लाख की संख्या पूरी होगई। काफ़ के पार बाकू नगर की आबादी भी ३,३४,००० से बढ़कर ६,६०,००० यानी दुगुनी होगई। १९१३ से १९३२ तक शहरों की आबादी २ करोड़ से ३॥ करोड़ होगई।

जब किसान शहर में जाकर मजदूर बन जाता है तो वह अपने गाँव में था उस वक्त की तरह अन्न पैदा करनेवाला नहीं रहता। कारख़ाने में काम करके वह पक्का माल या औज़ार बना सकता है, मगर जहाँतक खाद्य पदार्थों का ताल्लुक है वह खर्च करनेवाला ही होजाता है। इस तरह गाँवों से उठ-उठकर बहुत-से किसानों के शहरों में चले जाने का मतलब यह हुआ कि जो अन्न पैदा करते थे वे ही उसे खर्च करनेवाले बन गये। भोजन के मसले को इस बात ने और भी पेचीदा बना दिया।

एक बात और भी थी। देश के बढ़ते हुए उद्योग के लिए कारख़ानों को अधिकाधिक कच्चे माल की ज़रूरत हुई। इस तरह कपड़े के कारख़ानों में रुई की ज़रूरत हुई। इसलिए अनेक प्रदेशों में अनाज के वजाय रुई और दूसरा कच्चा माल बोया गया। इससे भी अन्न की कमी बढ़ी।

सोवियट संघ की आबादी का इतना ज्यादा बढ़ना खुद ही खुशहाली का बढ़िया सबूत था। अमेरिका की तरह इसका कारण लोगों का बाहर से आकर बसना नहीं था। इससे जाहिर होता था कि लोगों को कष्ट और असुविधा होते हुए भी भूखों

के कारण, जो शायद कुछ मामलों में सच्चा था, बहुत-से इंजीनियरों को सजायें देकर जेल में भेज दिया गया। चूंकि बहुत-सी हाथ में ली हुई बड़ी-बड़ी योजनाओं में इंजीनियरों की तास जरूरत थी, इसलिए इस कार्रवाई से पंचवर्षीय योजना को भी धक्का पहुंचा।

विषमता तो क़रीब-क़रीब सभी जगह थी। दुलाई की व्यवस्था ठीक न होने से अक्सर कारख़ानों और खेतों में पैदा हुए माल को वहीं पड़े-पड़े इन्तज़ार करना पड़ता था। इससे सब जगह काम में गड़बड़ होती थी। सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि योग्य विशेषज्ञों और इंजीनियरों की कमी थी।

इस पंचवर्षीय योजना के समय संसार में, या यूँ कहो कि पूँजीवादी संसार में, ऐसी मन्दी छाई हुई थी जैसी पहले कभी नहीं हुई। व्यापार बंठता जा रहा था, कारख़ाने बन्द हो रहे थे और बेकारी बढ़ रही थी। अनाज और कच्चे माल की क़ीमत दुरी तरह घट जाने से दुनियाभर के किसानों में त्राहि-त्राहि मची हुई थी। यह अजीब बात मालूम होती थी कि जब और सब जगह यह बेकारी और बेरोज़गारी फैली हुई थी उस वक़्त सोवियट संघ में दिन-रात काम-धन्धे की धूम मची हुई थी। ऐसा मालूम होता था कि दुनिया की मन्दी का उसपर कोई असर ही नहीं है। उसकी अर्थ-व्यवस्था ही बिल्कुल जुदा थी। मगर मन्दी के असर से सोवियट भी बच नहीं सका। यह असर चुपके-चुपके और अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। इससे सोवियट की कठिनाइयाँ बहुत बढ़ गईं। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि सोवियट बाहर से मशीनें मोल ले रहा था और उनकी क़ीमत उसे खेती की पैदावार विदेशों को बेचकर चुकानी पड़ती थी। चूंकि खाद्य पदार्थों का भाव संसार के बाज़ारों में गिर गया था, इसलिए सोवियट को भी अपने निर्यात माल की क़ीमत थोड़ी मिलती थी। मगर खरीदी हुई मशीनरी के दाम चुकाने को तो उसे पूरा सोना ही देना पड़ता था। इसलिए अधिकाधिक अन्न बाहर भेजना पड़ता था। इस तरह दुनिया की व्यापारिक मन्दी और भावों की कमी से सोवियट को भी नुक़सान हुआ और उसने जो हिसाब लगा रक्खा था उसमें बहुत-सी गड़बड़ हुई। इससे देश में कई जरूरत की चीज़ों की और भी कमी होगई और उतनी ही तकलीफ़ बढ़ी।

एक तरफ़ अन्न की कमी दिन-दिन ज़्यादा होरही थी और दूसरी ओर संघ-भर में आबादी बेहिसाब बढ़ रही थी। खेती की पैदावार की मन्द प्रगति के मुक़ाबिले में आबादी का इस तेज़ी से और बेहिसाब बढ़ना ही सोवियट की प्रधान समस्या थी। क्रान्ति से पहले सोवियट संघ के मौजूदा इलाक़ों की आबादी १३ करोड़ थी। उसके बाद गृहयुद्ध में भीषण जन-हानि हुई। फिर भी इसके बाद के सालों में आबादी में जो बढ़ती हुई वह देखने की बात है :—

ने व्यक्तिगत सम्पत्ति को पवित्र और रक्षणीय बताकर अपने समय में पूँजीवादी व्यवस्था को दृढ़ करने का उद्देश्य पूरा किया है तो हम साम्यवादियों को तो सार्वजनिक सम्पत्ति को पवित्र और रक्षणीय घोषित करके नई समाजवादी अर्थ-व्यवस्था को मजबूत करने की और भी ज्यादा कोशिश करनी चाहिए।”

लोगों को आराम पहुंचाने के लिए सोवियट सरकार ने और भी उपाय किये। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कार्य था सामूहिक और व्यक्तिगत खेतों की फ़ालतू पैदावार को शहरों के बाज़ार में बेचने की इजाजत देना। इससे कुछ-कुछ उस नई अर्थ-नीति की याद आती है जो सैनिक साम्यवाद के समय के बाद १९२१ में जारी हुई थी। मगर आज के सोवियट संघ में और उस समय के संघ में ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। वह अब समाजवाद के मार्ग पर बहुत-सी मंज़िलें तय कर चुका है; वह उद्योगवादी बन गया है और उसकी खेती बहुत कुछ सामूहिक होगई है।

पिछले चार साल में २,००,००० सामूहिक खेत संगठित किये गये हैं और ५,००० सरकारी खेत भी हैं। ये खेत औरों के लिए नमूने का काम देते हैं। ये बहुत बड़े हैं। इनमें सबसे बड़ा ५० लाख एकड़ का है। इस काल में १,२०,००० जोतनेवाले एंजिन और लगाये गये हैं। लगभग दो-तिहाई किसान अब इन सामूहिक कृषि-संघों के सदस्य होगये हैं।

दूसरी प्रवृत्ति जिसकी आश्चर्य-जनक प्रगति हुई है, सहयोग-समितियों के संगठन की है। १९२८ में खरीदारों की सहयोग-समिति के दो करोड़ साढ़े छः लाख मेम्बर थे। १९३२ में यह तादाद सात करोड़ पचास लाख होगई। इस संस्था के थोक और फुटकर बिक्री भंडारों का सिलसला संघ के एक कोने से दूसरे कोने तक फैला हुआ है, कोई जगह उनसे खाली नहीं है।

रूस के बेशुमार नये उद्योगों और कारख़ानों की फेहरिस्त से इस खत को भरने की ज़रूरत नहीं है। वह सूची लम्बी और प्रभावशाली होगी। मगर इतना कहे बिना नहीं रहा जाता कि पिछले छः वर्ष में बीस लाख मजदूर-कुटुम्बों को नये मकान रहने के लिए मिले हैं। यह तो मैं तुम्हें दूसरी जगह बता ही चुका हूँ कि मजदूरों की तन्दुस्ती और जिन्दगी की रक्षा के लिए सामाजिक बीमे की बड़ी व्यापक व्यवस्था की गई है।

१९३३ की पहली जनवरी को दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू होगई। यह भी है तो लम्बी-चौड़ी, परन्तु यह पहली से आसान है। इसकी मनशा छोटे उद्योगों की तरक्की करना है और इसका नतीजा यह होगा कि लोगों का रहन-सहन का तरीक़ा जल्दी ऊँचा होजायगा। यह उम्मीद की जाती है कि पिछले चार वर्ष के कष्ट और

नहीं मरना पड़ा। नाप-तौलकर खाद्य पदार्थों के बाँटने की कड़ी व्यवस्था से सारी आबादी के पास बिलकुल जरूरी भोजन-सामग्री पहुँच जाती थी। आँखों देखनेवालों का अधिकारपूर्वक कहना है कि आबादी के इस तेजी से बढ़ने का कारण ज्यादातर यह था कि लोगों की आर्थिक निश्चिन्तता अनुभव होने लगी थी। वहाँ अब बच्चे कुटुम्ब के लिए भार-रूप नहीं हैं, क्योंकि राज्य उनकी सम्हाल रखने, उन्हें खिलाने-पिलाने और शिक्षा देने के लिए तैयार है। दूसरा कारण यह है कि सफ़ाई और इलाज की सहूलियतों के बढ़ जाने से बच्चों की मृत्यु-संख्या २७ से घटकर १२ फ़ी सदी रह गई है। मास्को में १९१३ में साधारणतः एक हजार पर २३ मौतें हुआ करती थीं; पर १९३१ में १३ प्रति हजार ही रह गई।

खाद्य पदार्थों की कमी से होनेवाली अनेक कठिनाइयों में एक और बढ़ गई। १९३१ में संघ के कुछ भागों में अकाल पड़ गया। १९३१ और १९३२ में सुदूर पूर्व में युद्ध की गरम खबरें भी उड़ती रहीं। कहीं दूसरी पूँजीवादी शक्तियों से मिलकर जापान रूस पर हमला न करदे, इस डर से सोवियट ने आडे-बक्त्त पर फ़ौज के काम आने के लिए अनाज और दूसरे खाद्य पदार्थ इकट्ठे करना शुरू कर दिया। सोवियट के खिलाफ़ जंग छिड़ने का खतरा सच्चा ही है और वह बना रहता है, मगर बोलशेविकों पर तो यह दिन-रात भूत की तरह सवार रहता है और इसी लिए बार-बार ऐसी खबरें उड़ती रहती हैं। एक पुरानी रूसी कहावत है कि 'डर से आँखें बड़ी हो जाती हैं।' यह कहावत बच्चों पर लागू करो या जातियों और राष्ट्रों पर, कितनी सच्ची है! चूंकि साम्यवाद और पूँजीवाद में सच्चा मेल नहीं होसकता, और साम्राज्यवादी राष्ट्र साम्यवाद को फुचलने पर तुले हुए हैं और उसके लिए पैंतरे बदलते और षड्यन्त्र रचते रहते हैं, इसलिए बोलशेविकों के कान सदा खड़े रहते हैं और जरा-सी उत्तेजना मिलते ही वे आँखें फाड़-फाड़कर देखने लगते हैं। अक्सर उन्हें चिन्ता का काफ़ी कारण भी मिल जाता है और उन्हें घर के भीतर भी कारख़ानों और बड़े व्यवसायों के नष्ट करने के व्यापक प्रयत्नों का सामना करना पड़ा है।

१९३२ सोवियट संघ के लिए बहुत ही नाजुक साल रहा और अब भी, १९३३ के जुलाई में, यह लिखते समय तक संकट-काल समाप्त नहीं हुआ है। बहुत-से सामूहिक खेतों पर सार्वजनिक सम्पत्ति की चोरियाँ बहुत हुईं। इन चोरियों और गुप्त विरोध के खिलाफ़ सरकार ने बहुत सख्त कार्रवाई की। मामूली तौर पर रूस में मृत्युदण्ड नहीं है, मगर प्रति-क्रान्ति के मामलों में यह सजा जारी कर दी गई है। सोवियट सरकार ने आज्ञा दी है कि सार्वजनिक सम्पत्ति का चुराना प्रति-क्रान्ति के बराबर है, इसलिए इसकी सज़ा मौत है। इस बारे में स्टालिन ने कहा है: "अगर पूँजीवादियों

महासागर से बाल्टिक समुद्र तक, पामीर पहाड़ से मध्यएशिया के हिन्दूकुश पहाड़ तक, फैले हुए सोवियट संघ में रहनेवाली मुस्लिम जातियों में एकता और एक-रसता बढ़ी ।

संघ का बुरा-से-बुरा संकट-काल तो शायद चला गया है, मगर अभी यह है ज़रूर । क्राफ़प्रान्त के कुछ हिस्सों में थोड़े ही महीनों पहले सचमुच अकाल की हालत थी । इस वक्त सारे संघ की चिन्ता और आशा-भरी दृष्टि अगली फ़सल पर लगी हुई है । पिछले यानी १९३३ के वसन्त-में बुवाई बड़े जोर की हुई थी और आशायें यही हैं कि फ़सल बहुत अच्छी होगी । यह हुआ तो चार वर्ष लम्बे दुःख और चिन्ता के शीत काल का अन्त होकर रूस में वसन्त की आशा, जीवन और उत्साह देनेवाली हवा बहेगी ।

मुझे सोवियट रूस में आम तौर पर शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति की जो प्रगति हुई है उसका हाल लिखने का लोभ तो हो रहा है, मगर इसे संवरण ही करना पड़ेगा । तुम्हें थोड़ी-सी इधर-उधर की रोचक बातें ही बताऊंगा । जो लोग निर्णय करने के अधिकारी हैं उनमें से बहुतों की मान्यता है कि रूस की शिक्षा-प्रणाली आज संसार में सबसे अच्छी और नई है । निरक्षरता का तो काला मुंह ही होगया है और उज्बकिस्तान और तुर्कनिस्तान जैसे पिछड़े हुए मध्य-एशियाई प्रदेशों में सबसे आश्चर्यजनक प्रगति हुई है । इस प्रदेश में १९१३ में १२६ पाठशालायें और ६,२०० विद्यार्थी थे । १९३२ में वहाँ ६९७५ पाठशालायें और ७,००,००० छात्र थे । इनमें से एक-तिहाई लड़कियाँ थीं । सब जगह शिक्षा अनिवार्य करदी गई है । इस ज़बरदस्त तरक्की का महत्व समझने के लिए तुम्हें याद रखना चाहिए कि कुछ ही समय पहले तक लड़कियाँ परदे में रक्की जाती थीं और उन्हें संसार के इस हिस्से में बाहर नहीं निकलने दिया जाता था । कहते हैं, इतनी जल्दी प्रगति लैटिन लिपि के जारी करने के कारण हुई । भिन्न-भिन्न स्थानीय लिपियों की बनिस्वत इस लिपि से प्रारंभिक शिक्षा आसान होगई । तुम्हें याद होगा, मैं तुम्हें बता चुका हूँ, कि कमालपाशा ने भी अरबी के बजाय लैटिन लिपि या वर्णमाला जारी करदी है । उसे यह कल्पना और दूसरी भाषाओं के अनुकूल वर्णमाला रूस के प्रयोग से मिली । १९२७ में क्राफ़प्रदेश के प्रजातंत्रों ने अरबी लिपि छोड़कर लैटिन लिपि को अपनाया । निरक्षरता दूर करने में इससे बड़ी कामयाबी हुई और चीनी, मंगोली, तुर्क, तातार, बुदयत, बश्कीर, ताजिक और अनेक दूसरी जातियों ने, जो सोवियट संघ में शामिल हैं उनमें से अधिकांश ने, लैटिन लिपि को अपना लिया । भाषा तो वही स्थानीय रही जो सदा से काम में आती थी । सिर्फ़ लिपि बदल गई ।

तुम्हें यह जानने में दिलचस्पी होगी कि सोवियट संघ की सारी पाठशालाओं के

भार सहन करने के बाद अब लोगों को ज्यादा आराम और सुखपूर्ण जीवन के रूप में थोड़ा इनाम दिया जा सकेगा। अब मशीनों के लिए बाहर जाने की जरूरत न होगी। क्योंकि रूस के बड़े कारखाने ये मशीनें मुहैया कर सकेंगे। इससे सोवियट का वह भार भी हल्का हो जायगा जो उसे खरीदे हुए माल की कीमत चुकाने के लिए बहुत-से खाद्य पदार्थ बाहर भेजने में उठाना पड़ता था।

हाल ही में सामूहिक खेतों के किसानों की परिषद् में बोलते हुए स्टालिन ने कहा था :—

“हमारा पहला काम सारे सामूहिक खेती करनेवाले किसानों को सम्पन्न बनाना है। हाँ, साथियो, सम्पन्न बनाना।.....कभी-कभी लोग कहते हैं: ‘जब समाजवाद है तो फिर हम काम क्यों करें? हम पहले भी काम करते थे, अब भी करते हैं। क्या काम करना छोड़ देने का हमारे लिए वक्त नहीं आगया?.....नहीं, समाज की रचना परिश्रम पर हुई है।.....समाजवाद चाहता है कि सब लोग ईमानदारी से काम करें, दूसरों के लिए, अमीरों के लिए, शोषकों के लिए काम न करें। मगर अपने लिए और समाज के लिए काम करें।”

काम तो रहेगा और रहना चाहिए। हाँ, वह पंचवर्षीय योजना के चार वर्ष के कठोर काल की बनिस्वत भविष्य में हल्का और रुचिकर होगा। असल में सोवियट संघ का उसूल ही यह है—“जो काम न करे वह खाये भी नहीं।” लेकिन बोलशेविकों ने काम के साथ एक नया हेतु और लगा दिया है और वह है समाज की भलाई के लिए काम करना। पहले भी आदर्शवादियों और इक्के-दुक्के आदमियों ने इसी हेतु से प्रेरित होकर काम किया है, मगर सारे समाज के इस हेतु को स्वीकार करके उसके अनुसार काम करने का पहले कोई उदाहरण नहीं मिलता। पूँजीवाद का आधार ही स्पर्धा यानी लाग-डाँट और दूसरों को नुकसान पहुँचाकर अपना फायदा करना था। सोवियट संघ में इस मुनाफ़े के हेतु का स्थान सामाजिक हेतु ले रहा है। एक अमेरिकन लेखक कहता है कि रूस के श्रमजीवी यह सीख रहे हैं कि “पारिस्परिक अधीनता स्वीकार करने से भी दारिद्र्य और भय से स्वाधीनता मिलती है।” दरिद्रता और अनिश्चितता का भय शरीरों की गर्दन पर सब जगह और सदा सवार रहता है। यह कहा जाता है कि सोवियट रूस में इस भय के निकल जाने से मानसिक बीमारियों का अन्त-सा होगया है।

इस तरह इन चार कठोर वर्षों में सोवियट संघ में सब जगह और सब तरह की तरक्की हुई है। इनमें कष्ट और विषमतायें तो हुईं, मगर फिर भी नगरों, उद्योगों, बड़ी-बड़ी सामूहिक खेतियों, जबरदस्त सहयोग-समितियों, व्यापार और आबादी तथा संस्कृति, विज्ञान और विद्या की प्रगति अवश्य हुई। सबसे बड़ी बात यह हुई कि प्रशान्त

कोलनताई को बनाया। मेरा खयाल है कि लेनिन की विधवा श्रीमती क्रुप्सकाया सोवियट के शिक्षा-विभाग की एक शाखा की अध्यक्ष हैं।

सोवियट संघ दिन-दिन और घड़ी-घड़ी होनेवाले इन परिवर्तनों के कारण एक मज्जेदार देश होगया है। लेकिन उसका भी कोई भाग इतना रोचक और मनोहर नहीं है जितना साइबेरिया का मरुस्थल और मध्यएशिया की प्राचीन घाटियाँ हैं। ये दोनों ही मानवीय परिवर्तन और उन्नति के प्रभाव से पीढ़ियों तक अछूते रहे हैं, लेकिन आज बड़ी तेजी से छलांगें भरकर आगे बढ़ रहे हैं। इन तेजी से तब्दीलियों की तुम्हें थोड़ी-सी कल्पना कराने के लिए मैं ताजिकिस्तान का कुछ हाल बताता हूँ। शायद यह सोवियट संघ के सबसे पिछड़े हुए प्रदेशों में से था।

ताजिकिस्तान पामीर पर्वत-श्रेणी की घाटियों में, आक्सस यानी अक्षु नदी के उत्तर में, अफ़ग़ानिस्तान और चीनी तुर्किस्तान से लगा हुआ है। भारतीय सीमाप्रान्त से भी दूर नहीं है। यह बुख़ारा के अमीरों के कब्जे में था और ये अमीर रूसी ज़ार के उमराव थे। १९२० में बुख़ारा की स्थानीय क्रान्ति हुई और अमीर को हटाकर प्रजा ने बुख़ारा सोवियट प्रजातन्त्र कायम कर लिया। इसके बाद ख़ानाजंगी शुरू हुई और उसी उत्पात में अनवरपाशा की मृत्यु हुई। यह किसी ज़माने में तुर्की का सार्वजनिक नेता था। बुख़ारा प्रजातंत्र का नाम उज्जबक समाजवादी सोवियट प्रजातंत्र पड़ा और वह रूसी सोवियट संघ एक अंगभूत सर्वसत्ताधारी प्रजातंत्र हुआ। १९२५ में उज्जबक प्रदेश के भीतर एक स्वशासन-भोगी ताजिक प्रजातंत्र बना। १९२९ में ताजिकिस्तान भी एक सर्वसत्ताधारी प्रजातंत्र बन गया और सोवियट संघ के सात अंगभूत सदस्यों में से एक होगया।

ताजिकिस्तान को इतना गौरव तो मिल गया, मगर वह दस लाख से भी कम आबादी का छोटा-सा पिछड़ा हुआ इलाक़ा था। वहाँ रास्ते भी अच्छे नहीं थे, सिर्फ़ जंठों के रास्ते थे। नया दौर शुरू होते ही सड़कें, आवपाशी, खेती, उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य के साधन सुधारने के उपाय किये गये। मोटरों के रास्ते बनाये गये; खेती बोई जाने लगी और सिंचाई के कारण उसमें खूब सफलता मिली। १९३१ के मध्य तक रुई की खेती के ६० फी सदी भाग में सामूहिक प्रणाली जारी होगई और अन्न-प्रदेश के बड़े भाग का संगठन भी सामूहिक खेती के तरीक़े पर होगया। विजली-घर बन गया और आठ रुई के और तीन तेल के पुतलीघर खड़े होगये। एक रेलवे बन गई और उज्जबकिस्तान में होकर सोवियट संघ की बड़ी रेलवे से मिला दी गई। हवाई जहाज़ भी चलने लगे और उनको खास-खास हवाई रास्तों से जोड़ दिया गया।

१९२९ में सारे देश में सिर्फ़ एक दवाख़ाना था। १९३२ में ६१ अस्पताल और

दो-तिहाई बच्चों को पाठशालाओं में ही गरम-गरम दुपहरी कराई जाती है, यानी दोपहर का नाश्ता कराया जाता है। इसका पैसा नहीं लिया जाता। वहाँ तो शिक्षा भी मुफ्त दी जाती है। मुफ्त दी भी क्यों न जाय ? वहाँ मजदूरों का राज जो ठहरा।

साक्षरता की वृद्धि और तालीम की तरक्की के कारण वहाँ पढ़नेवाले लोगों की तादाद बहुत बढ़ गई है और शायद रूस में और किसी भी देश से ज्यादा किताबें और अखबार छपते हैं। अधिकांश पुस्तकें गम्भीर और 'भारी' हैं, और देशों की तरह हलके उपन्यास नहीं हैं। रूसी श्रमजीवी को इंजीनियरिंग और विजली से इतनी दिलचस्पी है कि वह उनके विषय की पुस्तकें पढ़ना जितना पसन्द करता है उतना कहानियों की किताबें पढ़ना नहीं करता। मगर बच्चों के लिए बहुत मजेदार पुस्तकें हैं, परियों की कहानियाँ तक हैं, हालांकि मैं समझता हूँ पुराने खयाल के बोलशेविकों को परियों की कहानियाँ पसन्द नहीं हैं।

विज्ञान में या विज्ञान के शुद्ध स्वरूप और उसके बहुत-से प्रयोगों में रूस पहले ही प्रथम श्रेणी में आ चुका है। विज्ञान की भिन्न-भिन्न शाखाओं की बहुत-सी विशाल संस्थाएँ और प्रयोगालय बन गये हैं। लेनिनग्रेड में वनस्पति-उद्योग की इतनी बड़ी संस्था है कि उसमें अकेले गेहूँ के २८,००० अलग-अलग नमूने हैं ! यह संस्था हवाई जहाज से चावल बोने के तरीकों का प्रयोग कर रही है।

जारों और उनके उमरावों के पुराने महलों में अब लोगों के लिए अजायबघर, आरामगाहें तथा स्वास्थ्य-भवन बन गये हैं। लेनिन ग्रेड के पास ही एक छोटा-सा कस्बा है। पहले इसे 'जारको सेलो' यानी 'जार का गाँव' कहते थे। वहाँ सम्राट् के दो महल थे और गरमी में जार वहीं रहता था। अब उसका नाम बदल कर 'डेस्को सेलो' यानी 'बच्चों का गाँव' रख दिया गया है। मेरा खयाल है कि पुराने महल अब बच्चों और नवयुवकों के ही काम के रह गये हैं। आज के सोवियट रूस में बच्चों और नवयुवकों पर खास महत्वानी है। दूसरों की भले ही अभाव का कष्ट हो, पर इन छाटलों को तो हर चीज बढ़िया-से-बढ़िया मिलनी चाहिए। उन्हींके लिए तो मौजूदा पीढ़ी मेहनत कर रही है, 'क्योंकि वे ही आगे चलकर समाजवादी और वैज्ञानिक राज्य के मालिक बनेंगे, वशतकि यह उनके जीवन-काल में स्थापित होजाया।' मास्को में 'माता और बच्चे की रक्षा की केन्द्रीय संस्था' है।

रूस में स्त्रियों को शायद और सब देशों से ज्यादा आजादी है। फिर भी उन्हें राज्य की तरफ से खास संरक्षण मिला हुआ है। वे सब घन्धों में प्रवेश कर सकती हैं और उनमें इंजीनियरों की खासी बड़ी तादाद है। किसी भी सरकार ने अगर पहले-पहल एक स्त्री को राजदूत बनाया हो तो वह रूस ने बुढ़िया बोलशेविक श्रीमती

संघ के बारे में मेरा यह आखिरी खत है इसलिए इसे थोड़ा बढ़ाकर मैं तुम्हें अब सोवियट की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति बता देता हूँ। तुम्हें याद हो तो तुम पहले ही जान चुकी हो कि केलॉग-संधिपत्र पर सोवियट ने भी दस्तखत किये थे। यह संधि युद्ध को बन्द करने के लिए हुई थी। १९२९ में लिटविनोफ़ का समझौता भी हुआ था। असल में रूस किसी भी तरह शान्ति की रक्षा और युद्ध को टालने के लिए बुरी तरह उत्सुक था और इन बातों को पक्की करने के लिए वह हर मौक़े का स्वागत करता था। इन संधियों और समझौतों को काफ़ी न समझकर उसने अपने पड़ोसियों के साथ परस्पर हमला न करने के शर्तनामे भी कर लिये। १९३२ के नवम्बर में उसने इसी तरह की एक संधि फ्रांस के साथ की। योरप की राजनीति में यह एक महत्वपूर्ण घटना थी। मेरे खयाल से रूस के पड़ोसियों में अकेले जापान ने ही परस्पर हमला न करने का समझौता करने से इन्कार किया। चीन ने बहुत दिन तक शान्त विरोध करने और राजनैतिक सम्बन्ध न जोड़ने के बाद सोवियट सरकार की सत्ता को दुबारा स्वीकार किया। यह उस वक़्त की बात है जब चीन पर मंचूरिया में जापान का दबाव बहुत बढ़ गया था।

जापान के साथ सोवियट के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। जापान की सरकार सोवियट को सुदूरपूर्व में हमेशा छेड़ती और तंग करती रहती है। पिछले साल-दो साल में सुदूरपूर्व में युद्ध होने की बातें भी बार-बार उठती रही हैं, मगर रूस ने लड़ाई करने से अपमान सह लेना ज्यादा पसन्द किया है। इंग्लैण्ड और रूस का संघर्ष अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में एक स्थायी चीज़ बन गई और कभी-कभी वह चमक उठती है। कुछ महीने पहले मास्को में ब्रिटिश इंजीनियरों पर मुक्रदमा चला था। उस पर बड़ा बावेल मचा और नतीजा यह हुआ कि दोनों देशों ने एक-दूसरे से बदला लेने की कार्रवाइयाँ कीं। मगर वह तूफ़ान अब जाता रहा है, इंजीनियर छोड़ दिये गये हैं और साधारण सम्बन्ध क़ायम होगये हैं। अमेरिका ने अभी तक रूस को स्वीकार नहीं किया है, हालांकि दोनों देशों में व्यापार खूब होता है। अब अमेरिका स्वीकार कर लेगा, ऐसी बात चल रही है, और यह भी कहा जाता है कि चूँकि इंग्लैंड और जापान रूस के प्रतिस्पर्धी और भावी शत्रु हैं, इसलिए वे अमेरिका को सोवियट सरकार को स्वीकार करने से रोक रहे हैं। इधर सोवियट का बड़ा आग्रह है कि अमेरिका उसे स्वीकार करले।

जर्मनी में नाज़ी सरकार के रूप में रूस का एक नया और आगे बढ़कर चोट करनेवाला दुश्मन पैदा होगया है। अभी रूस का सीधा नुक़सान करने का तो इसमें सामर्थ्य नहीं है, मगर आयन्दा के लिए उसका ख़तरा बहुत है और वह अभी से साज़िश करने लगा है। वह दिन-दिन फ़ैसिस्ट होता जा रहा है।

३७ घाँत के बवालाने होगये जिनमें २१२५ बीमारों के रहने का इंतजाम था और २० डॉक्टर थे। शिक्षा की प्रगति का पता निम्नलिखित अंकों से लग सकता है:—

१९२५ में	सिर्फ ६ आधुनिक पाठशालाएँ
१९२६ के अन्त में	११३ पाठशालाएँ और २,३०० छात्र
१९२९ में	५०० पाठशालाएँ
१९३१ में	२०० से अधिक शिक्षण-संस्थाएँ और १,२०,००० छात्र।

अवश्य ही शिक्षा पर खर्च भी एकदम बढ़ गया है। १९२९-३० का शिक्षा का बजट ८० लाख रुबल था। (घट्टा न लगे तो, यानी बराबर का भाव हो तो, एक रुबल लगभग २ शिलिंग या १।-)॥ के बराबर होता है।) १९३०-३१ का बजट २ करोड़ ८० लाख रुबल था। साधारण पाठशालाओं के सिवा शिशुशालाएँ, ट्रेनिंग स्कूल, पुस्तकालय और वाचनालय खुल रहे थे और १९३२ में नारा यह था कि 'अगले दो वर्षों में निरक्षरता मिट जानी चाहिए'। लोगों में इत्म यानी विद्या की जबरदस्त प्यास पैदा हो गई थी।

इन हालात में स्त्रियों का परदे में रहना तो मुमकिन ही नहीं था और वह तेजी से हट रहा था।

इन सब बातों में मुश्किल से ही विश्वास हो सकता है। क्या विजली की इस तेज चाल से तरफ़फ़ी हो सकती है ? यह भी याद रहे कि इस देश की आबादी दस लाख से थोड़ी-सी ही ज्यादा है, यानी इलाहाबाद जिले से भी बहुत कम है। मैंने यह जानकारी और अंक एक योग्य अमेरिकन यात्री की रिपोर्ट से लिये हैं। वह १९३२ के शुरू में ताजिकिस्तान देखने गया था। शायद उसके बाद तो वहाँ और भी परिवर्तन हुए हैं।

मालूम होता है कि सोवियत संघ ने नवजात ताजिक प्रजातन्त्र को शिक्षा और दूसरे कामों के लिए रुपये की मदद इसीलिए दी कि पिछड़े हुए भागों को उन्नत करना संघ की नीति है। लेकिन इस प्रदेश में खनिज सम्पत्ति भी बहुत मालूम होती है। सोना, तेल और कोयला मिले हैं और ऐसा भी विश्वास किया जाता है कि सोना बहुत ज्यादा है। पुराने ज़माने में चंगेजखाँ के समय तक ये सोने की खानें चलती थीं, मगर तबसे उनका काम बन्द मालूम होता है।

१९३१ में ताजिकिस्तान में प्रतिक्रान्तिवादियों का विद्रोह हुआ और बहुत-से भूस्वामी और अमीरवर्ग के लोग, जो देश छोड़कर अफ़ग़ानिस्तान भाग गये थे, हमला करने आये। मगर यह विद्रोह सफल नहीं हुआ, क्योंकि किसानों ने साथ नहीं दिया।

यह ख़त लम्बा हो रहा है और खिचड़ी-सा बनता जा रहा है। लेकिन सोवियत

विज्ञान की बात शुरू करने से पहले मैं तुम्हें फिर याद दिला दूँ कि महायुद्ध के समय से स्त्रियों की हालत में बहुत बड़ी तब्दीली होगई है। जिसे कानून, समाज और रिवाज के बंधनों से स्त्रियों की भुक्ति कहा जाता है उसकी शुरुआत उन्नीसवीं सदी में हुई थी, जब बड़े-बड़े उद्योग क़ायम हुए और उनमें स्त्री मजदूरों को नौकर रक्खा गया। पहले तो तरक्की की रफ़्तार सुस्त थी। फिर लड़ाई के कारण उसकी गति बहुत तेज़ होगई और युद्ध के बाद तो वह क़रीब-क़रीब पूरी होगई। आज तो ताजिकिस्तान में भी, जिसका हाल पिछले ख़त में लिख चुका हूँ, स्त्रियाँ डॉक्टर, शिक्षक और इंजीनियर हैं। ये ही कुछ वर्ष पहले परदे में रहती थीं। तुम और तुम्हारी पीढ़ी तो परदे से बाहर रहने को स्वाभाविक समझ लोगी। पर यह बात न सिर्फ़ एशिया में बल्कि योरोप में भी बिल्कुल नई है। सौ वर्ष भी नहीं हुए कि १८४० में लन्दन में संसार का पहला दासत्व-विरोधी सम्मेलन हुआ था। उसमें स्त्री-प्रतिनिधि अमेरिका से आई थीं जहां ह्व्शी गुलामों के होने से बहुत लोगों में आन्दोलन मचा हुआ था। लेकिन सम्मेलन ने इन स्त्री-प्रतिनिधियों को इस बिना पर शामिल करने से इन्कार कर दिया कि किसी स्त्री के लिए सार्वजनिक सभा में भाग लेना अनुचित और बेहयाई की बात है !

तो अब विज्ञान की बात करें। सोवियट रूस की पंचवर्षीय योजना का बयान करते वक़्त मैंने तुम्हें बताया था कि यह योजना सामाजिक मामलों में विज्ञान की भावना का प्रयोग थी। कुछ ही हद तक सही, पिछले डेढ़-दो सौ वर्ष से पश्चिमी सभ्यता के पीछे यही भावना रही है। जैसे-जैसे इसका असर बढ़ता गया, वैसे-वैसे तर्क-विरुद्ध और जादू-टोना तथा अंध-विश्वास के विचार पीछे हटते गये हैं और विज्ञान के विपरीत साधनों और क्रियाओं का विरोध हुआ है। इसका यह मतलब नहीं कि जन्तर-मन्तर, वहम और ख़ामख़याली पर विज्ञान की भावना की पूरी विजय होगई है। अभी यह बात बहुत दूर है। मगर तरक्की जरूर बहुत हुई है और उन्नीसवीं सदी में इस भावना की कई बातों में बड़ी भारी जीत हुई है।

मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ कि उद्योग और जीवन में विज्ञान के प्रयोग से उन्नीसवीं सदी में कितने बड़े परिवर्तन हुए हैं। संसार और ख़ास तौर पर पश्चिमी योरोप और उत्तरी अमेरिका इतने बदल गये हैं कि पहचाने नहीं जा सकते। वे इतने बदल गये जितने पहले हजारों वर्ष में नहीं बदले थे। उन्नीसवीं सदी में योरोप की आबादी का इतना ज्यादा बढ़ जाना कम ताज़्जुब की बात नहीं है। १८०० में सारे योरोप की आबादी १८ करोड़ थी। वह कई युगों में धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते इतनी हुई थी। फिर उसमें एकदम वृद्धि हुई और १९१४ में वह ४६ करोड़ होगई है। इस बीच में लाखों आदमी योरोप से दूसरे देशों में और ख़ासकर अमेरिका में भी जा बसे

विवेशों के साथ सोवियट रूस एक सन्तुष्ट राष्ट्र का-सा व्यवहार करता रहा है। शगड़े से चक्के और किसी भी क्रीम पर शान्ति कायम रखने की कोशिश करना उसका ध्येय है। यह रबेया क्रान्तिकारी नीति से बिलकुल उलटा है। क्रान्तिकारी नीति का उद्देश्य तो दूसरे देशों में क्रान्ति को उत्तेजन देना होता है। इसलिए रूस की मौजूदा नीति अन्तर्राष्ट्रीय नहीं, राष्ट्रीय नीति है। इससे हम ट्रॉट्स्की की 'स्यायी क्रान्ति' की ओर स्टालिन की एक देश में समाजवाद फैलाने की नीति का भेद समझ सकते हैं। यह समझ में आ सकता है कि अपनी बड़ी-बड़ी भीतरी योजनाओं में दुरी तरह व्यस्त रहने के कारण रूस को बाहर शगड़े मोल लेने का अवकाश नहीं है। मगर इसका यह नतीजा लाजिमी है कि वह पूंजीवादी राष्ट्रों के सामने एक छोटी-सी सयानी लड़की का-सा व्यवहार करने की कोशिश करे और अपने माने हुए शत्रु साम्राज्यवादी और फ़ैसिस्ट राष्ट्रों से समझौते करे। इसका अर्थ हुआ अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवादी संधि की मूल नीति का त्याग। इससे यह भी परिणाम हुआ है कि रूस के बाहर अलग-अलग देशों में साम्यवादी दल कमजोर होगये हैं और उनका कोई असर नहीं है। सोवियट संधि की नीति यह है कि बाहर समाजवाद और साम्यवाद का कुछ भी हो, अपनी रक्षा किसी भी तरह करनी चाहिए।

जिस वक्त मैं यह लिख रहा हूँ उस वक्त लन्दन में संसार-भर की आर्थिक परिपक्व हो रही है। यह परिपक्व तो असफल हो रही है, मगर रूस ने इस अवसर का लाभ उठाकर संसार के सारे देशों से आये हुए प्रतिनिधियों में से अपने पड़ोसियों के साथ परस्पर हमला न करने का दूसरा समझौता कर लिया है। रूस, अफ़ग़ानिस्तान, एस्टोनिया, लटविया, ईरान, पोलैण्ड, रूमानिया, तुर्की और लियुएनिया ने १९३३ के शुरु जुलाई में इस सन्धि पर हस्ताक्षर कर दिये। जापान पहले की तरह अब भी अलग ही है।

: १८२ :

विज्ञान की प्रगति

१३ जुलाई, १९३३

महासमर के बाद के वर्षों में दुनिया-भर में जो राजनैतिक घटनाएँ हुई हैं उनके बारे में मैंने तुम्हें विस्तारपूर्वक लिखा है। थोड़ा-सा हाल आर्थिक परिवर्तनों का भी बताया है। इस चिट्ठी में दूसरे विषयों और खास तौर पर विज्ञान और उसके नतीजों के बारे में लिखना चाहता हूँ।

में एम्सटर्डम में रहता था। कहा जाता है कि उसके पुस्तकालय में साठ से कम ही ग्रन्थ थे।

इसलिए हमारा भला यह समझने में ही है कि संसार में ज्ञान-वृद्धि होजाने से यह जरूरी नहीं है कि हम पहले से अच्छे या समझदार होगये। ज्ञान से पूरा लाभ उठा सकने के लिए हमें ज्ञान का ठीक-ठीक उपयोग करना आना चाहिए। अपनी तेज गाड़ी पर चढ़कर सरपट दौड़ने से पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि किधर जाना है। यानी हमें कुछ कल्पना तो होनी चाहिए कि जीवन का ध्येय क्या है? बेशुमार लोगों को आज कोई ऐसी कल्पना नहीं है और वे इसकी कभी चिन्ता भी नहीं करते। वे रहते विज्ञान के युग में हैं और उनके विचार और कार्य बहुत पुराने जमाने के हैं। इसलिए कठिनाइयों और संघर्ष का पैदा होना स्वाभाविक है। चालाक बन्दर मोटर चलाना सीख सकता है, मगर ऐसे हाँकनेवाले के हाथों में जान सुरक्षित नहीं होती।

आधुनिक ज्ञान आश्चर्यजनक रूप में पेचीदा और व्यापक है। हजारों खोज करनेवाले लगातार अपने काम में लगे रहते हैं। हरेक अपने-अपने विभाग में खोज करता रहता है, अपने-अपने चप्पे में बिल खोदा करता है और ज्ञान-गिरि में छोटे-छोटे कण जोड़ता रहता है। ज्ञान का क्षेत्र इतना लम्बा-चौड़ा है कि प्रत्येक कार्यकर्त्ता को अपनी-अपनी दिशा में विशेषज्ञ बनना पड़ता है। अक्सर उसे ज्ञान की दूसरी शाखाओं का पता भी नहीं होता और इस तरह वह कुछ विभागों में बड़ा पण्डित होकर भी दूसरे अनेक विभागों में बिल्कुल कोरा होता है। उसके लिए मानव-प्रवृत्ति के सारे क्षेत्र के बारे में बुद्धिमत्तापूर्ण विचार करना कठिन होजाता है। पुराने अर्थ में वह सुसंस्कृत नहीं है।

अलबत्ता ऐसे व्यक्ति भी हैं जो इस संकुचित विशेषज्ञता से ऊपर उठे हैं। वे खुद विशेषज्ञ होकर भी विस्तृत दृष्टिकोण रख सके हैं। युद्ध और मानवीय झगडों से विचलित न होकर ये लोग वैज्ञानिक खोज का काम बराबर करते रहे हैं और पिछले पन्द्रह-बीस वर्ष में उन्होंने ज्ञान में काफ़ी वृद्धि की है। आज का सबसे बड़ा वैज्ञानिक एल्बर्ट आइन्स्टीन समझा जाता है। यह जर्मनी का यहूदी है और चूँकि हिटलर की नई सरकार यहूदियों को पसन्द नहीं करती, इसीलिए आइन्स्टीन हाल में जर्मनी से निकाल दिया गया है !

आइन्स्टीन ने भौतिक शास्त्र के कुछ नये सिद्धान्तों का आविष्कार किया है। इनका सृष्टि से सम्बन्ध है और ये गणित की पेचीदा क्रियाओं से निकले हैं। इनसे न्यूटन के कुछ ऐसे सिद्धान्तों में भी परिवर्तन होगया है जिन्हें दो सौ वर्ष से असंदिग्ध रूप में माना जाता था। आइन्स्टीन के मत का समर्थन भी बड़े मजबूत तरीक़े पर हुआ। उसके मत के अनुसार प्रकाश का व्यवहार एक खास तरीक़े का होता है

थे। हम इनकी तादाद चार करोड़ समझ सकते हैं। इस तरह सी से कुछ ज्यादा वर्ष में ही योरोप की आबादी १८ से ५० करोड़ होगई। यह वृद्धि योरोप के उद्योग-प्रधान देशों में अधिक मार्क की हुई। अठारहवीं सदी के आरम्भ में इंग्लैण्ड की आबादी सिर्फ ५० लाख थी और वह पश्चिमी योरोप में सबसे गरीब देश था। वह दुनिया का सबसे मालदार मुल्क होगया और उसकी आबादी चार करोड़ होगई।

इस बढ़ती और दौलत का कारण यह था कि वैज्ञानिक जानकारी के कारण प्रकृति की क्रियाओं पर अधिक नियंत्रण होगया था, या यों कहो कि उन्हें ज्यादा अच्छी तरह समझ लिया गया था। इससे ज्ञान बहुत बढ़ गया, मगर यह न समझ लेना कि अपल भी बहुत बढ़ गई। मनुष्य कुदरत की ताकत को क्राबू में रखने और उससे काम तो लेने लग गये, मगर उन्हें यह खयाल साफ़-साफ़ नहीं था कि जीवन का ध्येय यानी ज़िन्दगी का मक़सद क्या है या क्या होना चाहिए? ताक़तवर मोटर-गाड़ी काम की और वाञ्छनीय चीज़ है, लेकिन यह तो मालूम होना चाहिए कि उसमें बैठकर जाना कहाँ है। अगर उसे ठीक तरह नहीं चलाया जाय तो वह चट्टान पर से उछलकर खड्ड में जा पड़ेगी। ब्रिटिश विज्ञान-संघ के अध्यक्ष ने पिछले साल कहा था : “मनुष्य ने अपने ऊपर क्राबू करना तो सीखा ही नहीं, और कुदरत पर उसका क्राबू पहले ही हो गया।”

हममें से ज्यादातर लोग विज्ञान से पैदा हुई या बनी हुई चीज़ें काम में लाते हैं। जैसे रेल, हवाई जहाज़, बिजली, चेतार का तार और हज़ारों और चीज़ें। मगर हम यह विचार नहीं करते कि ये बनीं कैसे? हम अपना हक़ समझकर उन्हें योंही स्वीकार कर लेते हैं। हमें इस बात का बड़ा गर्व है कि हम उन्नत युग में रहते हैं और खुद भी बड़े ‘आगे बढ़े हुए’ हैं। इसमें तो कोई शक नहीं कि हमारा ज़माना पहले के ज़मानों से बहुत जुदा है और, मेरे खयाल से, यह कहना भी बिल्कुल सही है कि यह पहले से कहीं अधिक उन्नत है। मगर इसका यह अर्थ भी नहीं है कि हम व्यक्ति या समूह की हैसियत से भी पहले से अधिक उन्नत हैं। यह कहना परले दर्जे की बेवकूफी होगी कि चूँकि एंजिन हाँकनेवाला एंजिन को चला सकता है, इसलिए एंजिन हाँकनेवाला अफ़लातून या सुक्रात से अधिक उन्नत या ऊँचे दर्जे का मनुष्य है। लेकिन यह कहना बिल्कुल ठीक होगा कि अफ़लातून के रथ से एंजिन आवागमन का बढ़िया साधन है।

आजकल हम बहुत-सी किताबें पढ़ते हैं। मुझे भय है कि इनमें से ज्यादातर बाहियात किताबें हैं। पुराने ज़माने में लोग थोड़ी-सी किताबें पढ़ते थे, लेकिन वे अच्छी होती थीं और उन्हें उनका अच्छा ज्ञान होता था। योरोप के दार्शनिकों में स्पिनोज़ा बहुत बड़ा आदमी था। वह विद्या और बुद्धि का भण्डार था। वह सत्रहवीं सदी

है वह नहीं दीखता है, बल्कि वह दीखता है जो उसकी प्रकाश-किरण के रवाना होते वक्त वह था। संभव है इस किरण को अपनी लम्बी यात्रा पर निकले सैकड़ों हजारों वर्ष होगये हों। समय और स्थान सम्बन्धी हमारे विचारों में इन बातों से बड़ी गड़-बड़ होती है, इसीलिए ऐसे मामलों पर विचार करने में आइंस्टीन के मत से बड़ी मदद मिलती है। अगर हम स्थान छोड़कर सिर्फ समय का विचार करें तो भूत और वर्तमान की खिचड़ी होजाती है, क्योंकि जिस तारे को हम देखते हैं वह हमारे लिए वर्तमान है, मगर दरअसल हमें जो दिखाई देता है वह भूतचाल की चीज है। हमें जितना-सा ज्ञान है उसके हिसाब से तो संभव है प्रकाश की किरण के रवाना होने के बाद वह तारा कभी का नष्ट होगया हो।

मैंने कहा है कि हमारा सूर्य छोटा-सा महत्वहीन तारा है। लगभग एक लाख तारे और हैं। ये सब आकाशगंगा कहलाते हैं। रात को दीखनेवाले तारों में से अधिकांश इसमें हैं। परन्तु खाली आँख से हमें बहुत ही थोड़े तारे दीखते हैं, बड़े-बड़े खुरदबीनों की मदद से हमें बहुत अधिक तारे दीख सकते हैं। इस विज्ञान के विशेषज्ञों ने हिसाब लगाया है कि जगत् में ऐसी एक लाख अलग-अलग आकाश-गंगायें हैं !

और एक आश्चर्य की बात सुनो। हमें बताया गया है कि यह जगत् बढ़ती हुई चीज है। सर जेम्स जीन्स नामक गणित-शास्त्री ने इसकी साबुन के ऐसे बुल्ले से तुलना की है जो बड़ा होता जा रहा है और बिस्व उस बुल्ले की ऊपरी सतह है। यह बुल्ले या बुदबुदे के जैसा जगत् इतना बड़ा है कि प्रकाश को इसके एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुँचने में लाखों और करोड़ों वर्ष लगते हैं !

अगर तुम्हारी आश्चर्य-शक्ति थक न गई हो तो जगत् के बारे में और भी कुछ बताऊँ। यह जगत् सचमुच अद्भुत वस्तु है। केम्ब्रिज का एक प्रसिद्ध ज्योतिषी सर आर्थर एडिंगटन हमें बताता है कि हमारा जगत् धीरे-धीरे बिखर रहा है और वह घड़ी की तरह है। अगर इसमें फिर से किसी तरह चाबी नहीं भरी गई तो यह छिन्न-भिन्न होजायगा। अलवत्ता यह सब होता लाखों वर्षों में है, इसलिए हमें चिन्ता नहीं करनी चाहिए। उन्नीसवीं सदी के मुख्य विज्ञान भौतिक और रसायनशास्त्र थे। उनसे मनुष्य को प्रकृति या बाहर की दुनिया पर प्रभुत्व प्राप्त करने में मदद मिली। फिर वैज्ञानिक पुरुष अपने भीतर देखने और अपना खुद का अध्ययन करने लगा। जीवनशास्त्र का महत्व बढ़ा। मनुष्य, पशु और वनस्पति के प्राणों का अध्ययन हुआ। अबतक उसमें असाधारण उन्नति हो चुकी है और जीवशास्त्री कहते हैं कि इंजेक्शन या सुई लगाकर अथवा दूसरे साधनों से शीघ्र मनुष्यों के स्वभाव भी बदले जा सकेंगे। इस तरह शायद यह भी होसकेगा कि कायर साहसी बन जाय या अधिक

और उसकी परीक्षा सूर्य-ग्रहण के अवसर पर हो सकती है। जब ग्रहण हुआ तो प्रकाश की किरणों का व्यवहार उसी तरह का हुआ। इस प्रकार गणित के तर्क से निकाले हुए परिणाम की पुष्टि वास्तविक प्रयोग से होगई।

मैं यह उसूल तुम्हें समझाने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि यह बहुत गहन है और मुझे भी इसकी स्पष्ट कल्पना नहीं है। यह सापेक्षवाद (Theory of Relativity) कहलाता है। जगत् के बारे में विचार करते समय आइंस्टीन को पता लगा कि समय और स्थान की कल्पनाएँ अलग-अलग लागू नहीं हो सकती। इसलिए उसने दोनों को रद करके एक नया विचार पेश किया और उसमें दोनों को मिला दिया। यही स्थान-समय (Space-Time) कल्पना है।

इधर आइंस्टीन ने विश्व का विचार किया, उधर वैज्ञानिकों ने अत्यन्त असीम चीजों की खोज की। सुई की नोक को लो। यह शायद छोटी-से-छोटी चीज है जिसे आँख से देखा जा सकता है। वैज्ञानिक साधनों से यह साबित कर दिया गया कि यह सुई की नोक एक तरह से अपने भीतर एक विश्व को छिपाये हुए है। इसके भीतर एक-दूसरे के चक्कर लगानेवाले अणु हैं और प्रत्येक अणु ऐसे परमाणुओं से बना है जो परस्पर स्पर्श किये बिना घूमते रहते हैं और प्रत्येक परमाणु के बहुत-से छोटे-छोटे बिजली के अंश होते हैं। इन्हें प्रोटन और एलेक्ट्रन (विद्युत्कण) कहते हैं। ये भी सदा बड़ी तेजी से घूमते रहते हैं। इनमें भी और सूक्ष्म भाग होते हैं जिन्हें पाजिट्रन, न्यूट्रन और डेप्टन कहते हैं। और उनकी औसत जिन्दगी एक सेकण्ड का अरबवाँ हिस्सा क़ती गई है! यह सब बहुत ही छोटे पैमाने पर आकाश में घूमनेवाले ग्रहों और तारों की-सी बात हुई। याद रहे कि अणु इतना छोटा होता है कि बढ़िया-से-बढ़िया खुरदबीन से भी दिखाई नहीं देता। परमाणुओं और उनके हिस्सों की तो कल्पना करना भी कठिन है। फिर भी वैज्ञानिक यन्त्रों की इतनी उन्नति हुई है कि इन सूक्ष्मातिसूक्ष्म हिस्सों के बारे में भी बहुत-सी जानकारी इकट्ठी होगई है। हाल में परमाणु के टुकड़े किये गये हैं।

विज्ञान के नये-से-नये मतों का विचार करते समय दिमाग चक्कर खाने लगता है और उन्हें समझ सकना बहुत ही कठिन है। अब मैं तुम्हें और भी आश्चर्यजनक बात कहूँगा। हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी हमें इतनी बड़ी दीखती है, परन्तु सूर्य के लिए वह एक छोटा ग्रह है और सूर्य खुद बहुत ही नगण्य-सा छोटा तारा है। स्थान के महासागर में सारा सूर्य-मण्डल एक बूंद के बराबर है। विश्व में दूरियाँ इतनी बड़ी-बड़ी हैं कि उसके कुछ भागों से हम तक प्रकाश के पहुँचने में हजारों लाखों वर्ष लगते हैं। इस तरह जब हमें रात को कोई तारा दीखता है तो वह जो कुछ अब

एक खास संकेत पर भोजन मिलने की आशा करना सिखाया। नतीजा यह हुआ कि कुत्ते के दिमाग में इस संकेत के साथ खाने का सम्बन्ध जुड़ गया और भोजन न आने की हालत में वही परिणाम होने लगा जो भोजन से होता था।

कुत्तों और उनकी लार पर किये गये इन प्रयोगों के आधार पर मनुष्य के मानस-शास्त्र की रचना हो रही है और यह दिखा दिया गया है कि किस प्रकार बहुतासी बातें मनुष्य बचपन में अपनेआप करता है और बड़ा होने पर वे ही बातें किसी परिस्थिति या प्रेरणा से करने लगता है। असल बात यह है कि हम जो कुछ सीखते हैं उस सबका यही आधार है। हमारी आदतें इसी तरह बनती हैं और हम भाषाएँ बग़ैरा सीखते हैं। हमारे सारे काम इसी तरह होते हैं। साधारण भय की ही बात ले लो। जब कोई आदमी पास में साँप देखता है या उससे मिलता-जुलता रस्सी का टुकड़ा उसे नज़र आता है तो वह बड़ी तेज़ी में और बिना विचारे उछलकर दूर भागता है। इसमें उसे पावलोव के प्रयोगों के ज्ञान की ज़रूरत नहीं है।

पावलोव के प्रयोगों ने सारे मानस-शास्त्र में क्रांति कर दी है। कुछ प्रयोग तो बड़े मनोरञ्जक हैं, मगर इस प्रश्न पर यहाँ विस्तार से नहीं लिख सकता। हाँ, इतना और कहूँगा कि मानस-विज्ञान में खोज के और भी कई तरीक़े हैं।

मैंने यह थोड़ी-सी मिसालें इसलिए दी हैं कि तुम्हें वैज्ञानिक कार्य के तरीक़ों का कुछ ख़याल बँध जाय। पुरानी आध्यात्मिक पद्धति में बड़ी-बड़ी बातों की अस्पष्ट चर्चा की जाती थी। उन बातों को पूरी तरह समझना ही मुश्किल था, तो उनका विश्लेषण करना तो असम्भव ही था। लोग उनपर विवाद करते-करते ख़ूब गरम होजाते, मगर उनकी दलीलों की सत्यता या असत्यता की कोई अन्तिम कसौटी नहीं थी, इसलिए मामला सदा हवा में ही उड़ जाता। वे लोग दूसरी दुनिया की चर्चा में इतने लगे रहते थे कि उन्हें इस संसार की साधारण बातों पर ध्यान देने की परवा नहीं थी। विज्ञान का तरीक़ा उससे बिल्कुल उल्टा है। छोटी-छोटी और नगण्य दिखाई देनेवाली बातों को ध्यान से देखा जाता है और इसीसे महत्वपूर्ण परिणाम निकल आते हैं। इन परिणामों के आधार पर सिद्धान्त बनाये जाते हैं और इन सिद्धान्तों की परीक्षा और अधिक अध्ययन और प्रयोगों द्वारा करली जाती है।

इसका यह अर्थ भी नहीं है कि विज्ञान में भूल नहीं होती। भूल तो कई बार होती हैं और क़दम पीछे हटाने पड़ते हैं। मगर किसी प्रश्न को समझने का सही तरीक़ा वैज्ञानिक पद्धति ही मालूम होती है। आज विज्ञान का वह सारा अहंकार और संकीर्ण भाव भी जाता रहा है जो उसमें उन्नीसवीं सदी में था। उसे अपनी सफलताओं पर गर्व है, मगर उसमें यह मानने की विनम्रता भी है कि अभी तो ज्ञान का विशाल और

संभव यह है कि इस तरीके से सरकार अपने आलोचकों और विरोधियों की विरोध-शक्ति कम कर सकेगी।

जीवशास्त्र के बाद दूसरी सीढ़ी पर मानसशास्त्र अथवा मनोविज्ञान है। इसका सम्बन्ध मन से, मानवीय विचारों, हेतुओं, भय और इच्छाओं से है। इस प्रकार विज्ञान नये-नये क्षेत्रों में प्रवेश कर रहा है और हमें अपने बारे में बहुत-सी बातें बता रहा है। इससे शायद हमें अपने पर नियन्त्रण रखने में मदद मिलेगी।

सन्ततिशास्त्र भी जीवशास्त्र से आगे का एक कदम है। यह नस्ल-सुवार का विज्ञान है।

यह भी दिलचस्प बात है कि किस प्रकार कुछ पशुओं के अध्ययन से विज्ञान के विकास में सहायता मिली है। बैचारे मेण्डक को चीर-फाड़कर यह मालूम किया गया कि ज्ञानतन्तु और स्नायु किस प्रकार काम करते हैं। मक्खी एक नन्ही-सी जान है। एक मक्खी होती है जो अक्सर ज्यादा पके फलों पर बैठती है। इसीसे उसका नाम फेला-मक्खी पड़ा है। इसके जरिये पंतुक संस्कारों का जितना ज्ञान हुआ है उतना और किसी साधन से नहीं हुआ है। इस मक्खी को ध्यान से देखने पर यह पता चल गया है कि एक पीढ़ी के संस्कार दूसरी पीढ़ी को उत्तराधिकार में किस तरह मिलते हैं। इससे मनुष्यों के उत्तराधिकार-सिद्धान्त की क्रिया समझने में कुछ-कुछ मदद मिलती है।

इससे भी बड़े-सा जानवर, जिससे हमें बहुत शिक्षा मिलती है, साधारण टिड्डी है। अमेरिकन लोगों ने दीर्घकाल तक और सावधानी से अध्ययन करने के बाद दिखाया है कि पशुओं और मनुष्यों में लिंग-भेद कैसे होता है। अब हमें इस विषय में बहुत-सी बातें मालूम होगई हैं कि छोटा-सा पिण्ड-गर्भ अपने जीवन के ठेठ प्रारम्भ से ही किस प्रकार नर या मादा बन जाता है और धीरे-धीरे बढ़ता-बढ़ता नर या मादा प्राणी यानी छोटा लड़का या लड़की होजाता है।

चौथा उदाहरण मामूली घरेलू कुत्ते का है। पावलोव एक प्रसिद्ध रूसी विज्ञान-वेत्ता है। इस समय उसकी उम्र ८४ वर्ष की है, फिर भी वह अपना काम कर रहा है। उसने कुत्तों को ध्यान से देखना शुरू किया और जब खाना देखते ही उनके मुँह से लार टपकती तब वह खास तौर पर ध्यान देता। उसने कुत्ते के मुँह के इस रस को माप तक लिया। खाने को देखते ही कुत्ते के मुँह में इस तरह पानी का आना एक अपने-आप होनेवाली घटना है। यह ऐसी बात है जैसे पहले के अनुभव के बिना बच्चा छींकता, जंभाई लेता या अंगड़ाई लेता है। यह तो हुई अपनेआप होनेवाली प्रेरणा (Unconditional reflex) की बात।

बाद में पावलोव ने यही बात प्रेरणा से पैदा करने की कोशिश की। यानी उसने

के ये गहन और उच्च प्रदेश विशुद्ध विज्ञान हैं। अधिकांश लोगों को इस प्रकार के विज्ञान में बहुत रस नहीं आता। विज्ञान की जो बातें रोज़शरीर की ज़िन्दगी पर लागू होती हैं उनकी तरफ़ आम लोगों का अधिक आकर्षण होना स्वाभाविक है। पिछले डेढ़सौ वर्ष में इसी व्यावहारिक विज्ञान ने ज़िन्दगी की कायापलट की है। असल बात यह है कि आज जीवन पर विज्ञान की इन शाखाओं का शासन है, वे ही उसे बनाती-बिगाड़ती हैं, और उनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं हो सकती। लोग अक्सर बात किया करते हैं कि पुराना ज़माना बड़ा अच्छा था, सतयुग था। प्राचीन काल के कुछ भाग वेशक बहुत ही मनोहर हैं और संभव है कुछ बातों में वे हमारे समय से बढ़कर भी हों। मगर शायद यह आकर्षण भी दूरी के या और किसीकी अपेक्षा एक ख़ास अनिश्चितता के कारण हो। हम किसी युग को इस कारण भी महान् समझ सकते हैं कि उसे कुछ महापुरुषों ने सुशोभित किया था अथवा उनकी उस समय प्रधानता रही थी। मगर साधारण लोगों की हालत तो इतिहास के ठेठ उस छोर से इस छोर तक दुःख-पूर्ण ही रही है। उनका सदा से चला आरहा बोझ तो किसीने कुछ भी हलका किया है तो विज्ञान ने ही किया है।

अपने चारों तरफ़ देखोगी तो तुम्हें पता लग जायगा कि जो चीज़ें तुम्हें नज़र आ रही हैं उनमें से ज्यादा का विज्ञान के साथ कुछ-न-कुछ ताल्लुक है। हम यात्रा करते हैं तो व्यावहारिक विज्ञान के साधनों से, उन्हीं के द्वारा एक-दूसरे के समाचार जानते हैं, हमारा भोजन भी उन्हींके जरिये तैयार होता और एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जाता है। जो अख़बार हम पढ़ते हैं, हमारी पुस्तकें और हमारे लिखने के कागज़ और क़लम वैज्ञानिक उपायों के बिना तैयार ही नहीं हो सकते। सफ़ाई, तन्दुरुस्ती और कुछ बीमारियों पर फ़तह हासिल करने के लिए विज्ञान का सहारा ज़रूरी है। आधुनिक संसार का काम व्यावहारिक विज्ञान के बिना बिल्कुल नहीं चल सकता। और सब दलीलें छोड़ भी दें तो एक दलील आखिरी है : विज्ञान के बिना संसार की आबादी को पूरा खाने को नहीं मिल सकता और आधी या इससे अधिक आबादी भूखों मर जायगी। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि किस तरह पिछले सौ वर्ष में आबादी इतनी तेज़ी से बढ़ गई है। यह बढ़ी हुई आबादी तभी ज़िन्दा रह सकती है जब भोजन-सामग्री को पंदा करने और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाने के लिए विज्ञान की मदद मिल जाय।

जैसे विज्ञान ने बड़े यंत्रों का मानव-जीवन में प्रवेश कराया है तभीसे उन्हें सुधारने का सिलसिला बराबर जारी है। हर साल और माह वेदुमार छोटे-छोटे फेरबदल करके इन यंत्रों को ज्यादा काम के और मनुष्य के परिश्रम पर कम निर्भर

अनन्त महासागर अछूता पड़ा है। बुद्धिमान यही समझा करते हैं कि उनका ज्ञान बहुत थोड़ा है। मूल्य समझते हैं कि वे सब कुछ जानते हैं। यही बात विज्ञान की है। ज्यों-ज्यों वह प्रगति करता है त्यों-त्यों उसका कट्टरपन घटता है और उससे जो सवाल पूछे जाते हैं उनका जवाब वह संकोच के साथ देता है। एडिंगटन कहता है—“विज्ञान की उन्नति की माप यह नहीं है कि हम कितने सवालों का जवाब दे सकते हैं, बल्कि यह है कि हम कितने सवाल पूछ सकते हैं।” बात शायद यही है, फिर भी विज्ञान दिन-दिन ज्यादा सवालों का जवाब देता है और हमें जिन्दगी को समझने में मदद देता है। इस तरह अगर हम उससे फायदा उठाना चाहें तो वह हमें पहले से अच्छी जिन्दगी बसर करने में समय बनाता है और जीवन के उद्देश्य को एक पूरी करने योग्य चीज बनाता है। यह जीवन के अंधेरे कोनों में रोशनी पहुँचाता है और तर्क-विरुद्ध अस्पष्ट बातों के झमेले से निकालकर हमें सत्य के सम्मुख उपस्थित करता है।

: १८३ :

विज्ञान का सदुपयोग और दुरुपयोग

१४ जुलाई, १९३३

पिछले सात में मैंने तुम्हें नई-नई वैज्ञानिक प्रगति के अद्भुत संसार की झाँकी कराई थी। पता नहीं तुम्हें वह झाँकी अच्छी लगेगी या नहीं और तुम्हारा विचार और सफलता के इन क्षेत्रों की ओर आकर्षण होगा या नहीं। तुम्हें इन विषयों पर अधिक जानने की इच्छा होगी तो तुम आसानी से बहुत-सी किताबें खोज लोगी। मगर यह याद रखना कि मनुष्य के विचार में सदा तरक्की होती रहती है और वह प्रकृति और जगत् की समस्याओं को समझने और उनसे जूझने की हमेशा कोशिश करता रहता है। इस कारण संभव है जो बात में तुम्हें आज बता रहा हूँ वह शायद कल बिलकुल नाकाफ़ी और पुरानी होजाय। मानव मस्तिष्क की इस चुनौती ने मुझे तो मुग्ध कर दिया है। यह जगत् के दूर के कोनों में कैसे उड़ान मारती है, उसके गहरे-से-गहरे रहस्यों में कैसे गोते लगाती है और अत्यन्त छोटी-से-छोटी चीज से लगाकर अत्यन्त बड़ी-से-बड़ी वस्तु को नापने और हाथ में लेने का साहस करती है।

यह सब 'विशुद्ध' विज्ञान कहलाता है। इसका जीवन पर सीधा या तुरन्त असर नहीं पड़ता। यह जाहिर है कि सापेक्षवाद या स्थान-समय (Space-Time) की कल्पना या जगत् के आकार से हमारे दैनिक जीवन का कोई ताल्लुक नहीं। इन सिद्धान्तों में से ज्यादातर ऊँचे गणितशास्त्र पर अवलम्बित हैं और इस अर्थ में गणित

ज्यादा खरीद सकते हैं। उनके रहन-सहन का ढंग ऊँचा होजाता है और पक्के माल की माँग बढ़ जाती है। इसका नतीजा यह होता है कि अधिक कारखाने खुलते हैं और ज्यादा आदमियों को काम मिलता है। इस तरह मशीन हर कारखाने में मजदूरों की जगह तो लेती है, मगर सब बातों को देखते हुए ज्यादा कारखाने खुलने से बहुत ज्यादा मजदूरों को काम मिल जाता है।

यह क्रिया बहुत समय तक जारी रही, क्योंकि इसे उद्योग-प्रधान देशों के द्वारा पिछड़े हुए दूर-दूर देशों के बाजारों के शोषण से मदद मिलती रही। पिछले कुछ साल से यह क्रिया बन्द होगई दीखती है। शायद मौजूदा पूँजीवादी व्यवस्था के अब और फैलने की गुंजाइश नहीं रही है और इस व्यवस्था में कुछ परिवर्तन की जरूरत है। आधुनिक उद्योगवाद में 'सामूहिक उत्पत्ति' होती है, मगर वह जारी तभी रह सकती है जब बनाये हुए माल को सर्वसाधारण खरीदते रहें। अगर आम लोग बहुत गरीब या बेकार हों तो वे माल नहीं खरीद सकते।

यह सब होते हुए भी, यंत्रों का सुधार बराबर हो रहा है और मनुष्यों का स्थान मशीनें ले रही हैं और बेकारी बढ़ रही है। पिछले चार साल में दुनिया-भर में बड़ी मन्दी छाई हुई है, मगर इससे यंत्र-सुधार की प्रगति में बाधा नहीं पड़ी है। कहा जाता है कि १९२९ से अमेरिका के संयुक्त राज्यों में इतने ज्यादा सुधार हुए हैं कि अगर १९२९ की उत्पत्ति क्लायम रक्खी जाय तो भी जो लाखों आदमी बेकार होगये हैं वे हरगिज काम में नहीं लगाये जा सकते।

कारण और भी बहुत हैं, मगर एक कारण यह भी है कि जिससे संसार-भर में खासकर उद्योग-प्रधान देशों में बेकारी की महासमस्या पैदा हुई है। यह एक अजीब और उलटी समस्या है, क्योंकि नई-से-नई मशीनों के जरिये ज्यादा-ज्यादा माल तैयार होने का मतलब यह है—या होना चाहिए—कि राष्ट्र की सम्पत्ति बढ़े और सबके रहन-सहन का ढंग ऊँचा हो। इसके बजाय दरिद्रता और कष्ट भयंकर रूप से बढ़ गये हैं। खयाल होता है कि इस समस्या को वैज्ञानिक ढंग से हल करने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए। शायद मुश्किल न भी हो। मगर असली कठिनाई वैज्ञानिक और उचित रूप से हल करने में आती है। ऐसा करने में बहुत-से स्थायी स्वार्थों पर असर पड़ता है और उनमें अपनी-अपनी सरकार पर क़ाबू रखने की ताकत है। दूसरे, यह समस्या मूल में अन्तर्राष्ट्रीय है और आजकल राष्ट्रीय स्पर्धा के कारण कोई अन्तर्राष्ट्रीय हल निकल नहीं पाता। सोवियट रूस इसी तरह की समस्याओं को वैज्ञानिक उपायों से हल करने की कोशिश कर रहा है, मगर उसे करना पड़ता है सब कुछ राष्ट्रीय पैमाने पर ही। बाकी की दुनिया पूँजीवादी और खिलाफ है, इस कारण उसकी मुश्किलें

ऐसे समूह-शासन अलग-अलग तरह के राज्यों में बन जाते हैं । कभी तो यह शासन जाहिरा तौर पर लोकसत्ता के सिद्धान्तों का आदर करते हैं और कभी उनकी खुली निन्दा करते हैं । समूह-शासन वाले इन भिन्न-भिन्न राज्यों की आपस में मूठभेड़ होती हैं और राष्ट्रों में लड़ाई छिड़ जाती है । आज या भविष्य में ऐसी बड़ी लड़ाई हो तो वह इन समूह-शासनों की ही नहीं, सभ्यता तक को नष्ट कर सकती है । यह भी हो सकता है कि उसकी खाक में से अन्तर्राष्ट्रीय श्रमजीवी राज्य पैदा हो । मार्क्सवादियों को यही आशा है ।

युद्ध असल में इतनी भयंकर चीज है कि उसपर विचार करना रुचिकर विषय नहीं होता । इसी वजह से अच्छे-अच्छे शब्दों, बहादुरी पैदा करनेवाले संगीत और भड़कीली वदियों में सचाई छिपाई जाती है । मगर आज युद्ध का क्या अर्थ होता है, इसे थोड़ा जान लेने की जरूरत है । पिछले महायुद्ध से बहुत लोगों को लड़ाई की भयंकरता समझ में आई । फिर भी कहा जाता है कि आगे जो लड़ाई होगी उसके सामने पिछला महायुद्ध कुछ भी नहीं था । इसका कारण यह है कि अगर औद्योगिक यन्त्र-कला में पिछले कुछ वर्षों में दसगुनी तरक्की हुई है तो युद्ध-विज्ञान सौगुना अधिक बढ़ा है । लड़ाई में अब पलटन के हमलों और रिसाले के धावों की कोई गिनती नहीं रही । आज पुराना पैदल सिपाही और घुड़सवार क़रीब-क़रीब उतने ही निकम्मे होगये हैं जितने धनुष और बाण । आज के युद्ध में मशीन से चलनेवाले टैंकों और हवाई जहाजों और बम गोलों का काम रह गया है । खास तौर पर पिछले दोनों का ही महत्व है । हाँ, टैंक रेंगनेवाले पहियों पर चलनेवाला एक तरह का लड़ाई का जहाज होता है ।

वायुयानों की गति और शक्ति दिन-दिन बढ़ रही है । सिनोर डिला सिरवा नामक एक स्पेन-निवासी ने नया आविष्कार किया है । इसे 'ऑटोप्लीरो' कहते हैं । यह क़रीब-क़रीब सीधा उड़ता है और इसलिए हवाई जहाजों के अड्डे जैसे किसी चीज की जरूरत नहीं होती । यह तेज़ भी चल सकता है और धीरे-धीरे भी, और चक्कर भी लगा सकता है ।

अगर जंग छिड़ जाय तो ऐसा अन्देश है कि लड़नेवाले राष्ट्रों पर फ़ौरन दुश्मन के हवाई हमले होंगे । जंग का ऐलान होने के कुछ ही घण्टों में ये हवाई जहाज आ पहुँचेंगे या दुश्मन को और भी नुक़सान में रखने के लिए चुपके से पहले भी आ सकते हैं । और फिर वे बड़े-बड़े शहरों और कारख़ानों पर निहायत जोरदार बम गोलों की वर्षा कर देंगे । इनसे बचाव होना क़रीब-क़रीब नामुमकिन होगा । सम्भव है शत्रु के कुछ वायुयान नष्ट कर दिये जायें, परन्तु शहर को बरबाद करने के लिए तो बाक़ी बचे हुए वायुयान भी काफी होंगे । हवाई जहाजों में से फेंके हुए बम-गोलों में से जहरीली गैसें

और भी बढ़ जाती है । यह बात न होती तो उसकी कठिनाइयाँ कम होतीं । इससे ट्राट्स्की की यह बात एक हद तक समझ में आसकती है कि अकेले देश में सच्चा समाजवाद नहीं हो सकता । दुनिया की राजनैतिक रचना भले ही अभी पिछड़ी हुई और संकीर्ण राष्ट्रवादी है, फिर भी दुनिया आज दरअसल अन्तर्राष्ट्रीय बन गई है । समाजवाद सकल होना है तो उसे अन्तर्राष्ट्रीय और विश्व-व्यापी समाजवाद बनना होगा । घड़ो की सुइयाँ पीछे नहीं घुमाई जा सकतीं, इसी तरह अपूर्ण होते हुए भी आज की अन्तर्राष्ट्रीय रचना राष्ट्रीय एकान्तवाद के पक्ष में कुचली नहीं जा सकती । कुछ देशों में क्रैसिस्ट लोग राष्ट्रीयता का रंग गहरा करने की जो कोशिश कर रहे हैं, वह अन्त में नाकामयाब हुए बिना नहीं रह सकती, क्योंकि वह मूल में ही आज की संसारव्यापी अर्थ-नीति के अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप के खिलाफ है । हाँ, यह हो सकता है कि इस तरह खुद डूबकर वह दुनिया को भी साथ में ले डूवें और, आधुनिक सभ्यता की भाषा में, सबको एक-साथ आफ़त में फँसा दें ।

ऐसी विपत्ति का खतरा कोई दूर की या अकल्पनीय बात हरगिज नहीं है । हम देख चुके हैं कि जहाँ विज्ञान के साथ-साथ बहुत-सी अच्छी बातें आगई हैं वहाँ उसके कारण युद्ध की भयंकरता भी बुरी तरह बढ़ गई है । राज्यों और सरकारों ने अक्सर विशुद्ध और व्यावहारिक दोनों तरह के विज्ञान की अनेक शाखाओं की उपेक्षा की है; मगर विज्ञान के युद्ध-सम्बन्धी पहलू के प्रति उन्होंने लापरवाही नहीं दिखाई है । उन्होंने अपनेको शस्त्र-सज्जित और बलवान बनाने के लिए नई-से-नई वैज्ञानिक कला से पूरा फ़ायदा उठाया है । ज्यादातर राज्यों का पशुबल ही अन्तिम आश्रय होता है और वैज्ञानिक यंत्र-कला उन्हें इतने बलवान बना रही है कि वे आम तौर पर किसी परिणाम के भय के बिना ही प्रजा पर जुल्म कर सकते हैं । पुराने ज़माने में जालिम सरकारों के खिलाफ़ जनता बगावत कर दिया करती थी और खुले रास्तों में मोर्चे बाँधकर लड़ाई किया करती थी । फ़्रांस की महान् राज्यक्रान्ति में ऐसा ही हुआ था । मगर अब ये बातें असंभव होगई हैं । अब किसी निःशस्त्र या हथियार-बन्द भीड़ के लिए भी संगठित और सुसज्जित सरकारी सेना से लड़ना नामुमकिन है । रूस की राज्य-क्रान्ति की तरह राज्य की सेना खुद राज्य के खिलाफ़ होजाय, यह दूसरी बात है । मगर जबतक ऐसा न हो तबतक बलपूर्वक राज्य को नहीं हराया जा सकता । इस कारण अब आजादी के लिए लड़नेवाली प्रजा को दूसरे और शान्तिपूर्ण सामूहिक उपायों का सहारा लेना पड़ता है ।

इस तरह विज्ञान से राज्यों पर समूहों का नियन्त्रण कायम होता है और व्यक्तिगत आजादी और लोकसत्ता के उन्नीसवीं सदी वाले पुराने विचारों का नाश होता है ।

इन दोनों में परस्पर विरोध और स्पर्धा है। एक में सहयोग और समझदारी की प्रगति है और सभ्यता का निर्माण है। दूसरी क्रिया नाशकारी है। वह सब चीजों को तोड़-फोड़ देना चाहती है और मनुष्य जाति के लिए आत्महत्या का प्रयत्न है। दोनों की गति दिन-दिन तीव्र हो रही है और दोनों ही विज्ञान के अस्त्रों और कलाओं से सुसज्जित हो रही हैं। जीत किसकी होगी ?

: १८४ :

महामन्दी और संसारव्यापी संकट

१९ जुलाई, १९३३

विज्ञान ने मनुष्य के हाथ में जो ताकत सौंप दी है और इन्सान उसको जिस तरह काम में ला रहा है उसपर जितना ज्यादा विचार करते हैं उतना ही अधिक आश्चर्य होता है। आज सचमुच पूंजीवादी दुनिया जिस बुरी हालत में है उसे देखकर हैरत होती है। रेडियो के जरिये विज्ञान हमारी आवाज दूर-दूर के देशों में पहुँचाता है। बे-तार के तार से हम पृथ्वी के दूसरे किनारे पर बसे हुए लोगों से बात करते हैं और थोड़े ही दिन में हम 'टेलीविजन' (Television) यानी दृश्य-प्रेक्षण यंत्र से उन्हें देखने भी लगेंगे। विज्ञान अपनी अद्भुत कला के जरिये वे सब चीजें पैदा कर सकता है जिनकी मानव-जाति को बड़े परिमाण में जरूरत है और वह संसार को दरिद्रता के पुराने रोग से सदा के लिए छुड़ा सकता है। बहुत पुराने ज़माने से ही, जब इतिहास उदय होने लगा था तभीसे, मनुष्य रोज़मर्रा की कड़ी मेहनत से थोड़ा-बहुत आराम पाने के लिए कोशिश करता रहा है। इस मेहनत के बदले उसे पुरस्कार बहुत थोड़ा मिलता रहा है और इसके बोझ से वह हमेशा कुचला जाता रहा है। इससे छुटकारा पाने की उम्मीद में वह स्वर्ग के सपने देखता रहा है और एक ऐसी दुनिया में पहुँचने की कल्पना करता रहा है जहाँ दूध की नदियाँ बहती हों और सब चीजों का ठाठ हो। लोगों ने गुजरे हुए सुनहरे ज़माने की अर्थात् सतयुग की याद करके आनेवाले स्वर्ग से ये आशायें लगाई कि कम-से-कम वहाँ तो शान्ति और सुख मिलेगा। उसके बाद ही विज्ञान का अवतार हुआ। इसने उत्पत्ति के साधन तो लोगों के हाथ में खूब दे दिये, मगर फिर भी इस वास्तविक और संभवनीय वाहुल्य के बीच में भी ज्यादातर आदमियों की जिन्दगी में मुसीबत और गरीबी बनी ही रही। क्या यह अजीब गोरखधन्दा नहीं है ?

हमारा वर्तमान समाज सचमुच विज्ञान और उसकी दी हुई वैशुमार चीजों से

निकलेंगी और प्रदेश के प्रदेश में फैलकर छा जायेंगी। इसकी पहुँच के भीतर हरेक जीव दम घुटकर मर जायगा। यह निहत्थी आवादी को बड़े पैमाने पर और निहायत निर्दय और कष्टप्रद ढंग से वरवाद करना होगा। इससे असहनीय शारीरिक और मानसिक पीड़ा होगी। और इस तरह की घटना विरोधी दलों के बड़े-बड़े शहरों में दोनों तरफ़ से साथ-साथ भी हो सकती है। पिछले महायुद्ध की तरह योरोप में लड़ाई हुई तो लन्दन, पेरिस और वर्लिन कुछ ही दिनों या हफ़्तों के भीतर राख के ढेर होजायेंगे।

हालत और भी ख़राब होसकती है। हवाई जहाज़ों से जो बम-गोले फेंके जायेंगे उनमें अलग-अलग शयंकर बीमारियों के कीड़े भरे होंगे तो शहर के शहर में इन रोगों की छूत फैल जायगी। इस तरह की 'कीड़ों की लड़ाई' और तरह भी जारी रह सकती है। चीज़ों और पीने के पानी में कीटाणु मिलाये जा सकते हैं और प्लेग के चूहे जैसे रोगवाहक जन्तुओं से काम लिया जा सकता है।

ये सब बातें राक्षसी और अविश्वसनीय मालूम होती हैं और हैं भी ऐसी ही। राक्षस भी ऐसा करना नहीं चाहेगा। मगर जब लोग पूरी तरह भयभीत होकर जीवन-मरण के युद्ध में लगे होते हैं तब अविश्वनीय बातें होती ही हैं। इसी डर के मारे कि कहीं दुश्मन अनुचित और राक्षसी उपायों से काम न लेने लगे, प्रत्येक देश को सबसे आगे रहने की प्रेरणा मिलती है। इसका कारण यह है कि हथियार इतने ख़तरनाक हैं कि जो मुक्त उनका पहलेपहल इस्तेमाल करता है वह बड़े फ़ायदे में रहता है। डर की आँखें बड़ी होती हैं !

असल में पिछले महायुद्ध के समय भी ज़हरीली गैस दूर-दूर तक काम में लाई गई थी और यह बात बहुत लोगों को मालूम है कि सभी बड़े-बड़े राष्ट्रों के यहाँ आज लड़ाई के काम के लिए यह गैस तैयार करने के बड़े-बड़े कारख़ाने मौजूद हैं। इन सब बातों का एक अजीब नतीजा यह होगा कि आगामी महायुद्ध में वास्तविक लड़ाई युद्ध-क्षेत्र में नहीं होगी। सेनाओं को खाइयाँ खोदकर एक-दूसरे के सामने आने की ज़रूरत न होगी। सच्ची लड़ाई शहरों में और निःशस्त्र आवादी के घरों में होगी। यह भी मुमकिन है कि युद्ध में सबसे सुरक्षित जगह युद्ध-क्षेत्र होगा, क्योंकि सेना की तो हवाई हमलों, ज़हरीली गैसों और छूत की बीमारियों से पूरी रक्षा की ही जायगी। परन्तु पीछे रहनेवाले लोगों, स्त्रियों और बच्चों की रक्षा के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होगी।

इन सबका परिणाम क्या होगा ? विश्वव्यापी नाश ? सदियों की कोशिशों से संस्कृति और सभ्यता की जो बढ़िया इमारत तैयार हुई है उसका अन्त ?

क्या होगा, यह कोई नहीं जानता; भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है, उसे देखा नहीं जा सकता। हमें तो केवल दो क्रियायें संसार में साथ-साथ होती हुई दिखाई दे रही हैं।

ढेर लग जाता है। व्यवसाय की हालत नाजुक होजाती है और उद्योग फिर मन्दा पड़ जाता है। थोड़े समय हालत स्थिर रहती है। इस बीच में इकट्ठा हुआ माल धीरे-धीरे निकल जाता है, कारखाने फिर चेतते हैं और शीघ्र ही दूसरा सम्पन्न काल आजाता है। साधारणतः यही चक्र चलता है और अधिकांश लोग यह आशा लगा लेते हैं कि किसी-न-किसी समय खुशहाली आकर रहेगी। लेकिन १९२९ में अचानक हालत और भी बुरी होगई। अमेरिका ने जर्मनी और दक्षिणी अमेरिका के राज्यों को रुपया उधार देना बन्द करके उधार लेने और देने के कागज़ी व्यवसाय का अन्त कर दिया। यह स्पष्ट था कि अमेरिका के पूंजीपति सदा रुपया उधार देते ही नहीं रह सकते थे, क्योंकि इससे उनके कर्जदारों का कर्ज और भी बढ़ता जाता और कर्ज का कभी चुकना ही नामुमकिन होजाता। उन्होंने अबतक भी रुपया इसीलिए उधार दिया था कि उनके पास नक़द रुपये की बहुतायत थी और उसका और कोई उपयोग वे कर नहीं सकते थे। इस फ़ालतू रुपये से वे सट्टा भी ख़ूब करने लगे। लोगों को जुआ खेलने का वाक़ायदा नशा-सा आगया और हर आदमी जल्दी धनवान बनने की इच्छा करने लगा।

जर्मनी को उधार मिलना बन्द होते ही वहाँ उथल-पुथल मच गई और कुछ जर्मन बैंकों का दिवाला निकल गया। धीरे-धीरे हर्ज़नि और क़र्ज़ की अदायगी का दौर बन्द होगया। दक्षिणी अमेरिका की बहुत-सी सरकारें और दूसरे छोटे-छोटे राज्य नादिहन्द होने लगे। संयुक्तराष्ट्र के राष्ट्रपति हूवर ने जब विस्मय के साथ यह देखा कि उधार देने की सारी प्रणाली का ही खात्मा हुआ जा रहा है, तो १९३१ के जुलाई मास में साल-भर के लिए क़र्ज़ की अदायगी मुत्तवी करदी। इसका अर्थ यह हुआ कि एक वर्ष के लिए क़र्जदारों को आराम देने को ऋण और हर्ज़नि का चुकाना सरकारों के लिए आपस में बन्द कर दिया गया।

इस बीच में १९२९ के अक्टूबर में अमेरिका में एक मार्क की घटना होगई। शेयरों के सट्टे से उनके भाव बेहूदा तरीक़े पर बढ़ गये और फिर अचानक उसी तरह गिर गये। न्यूयार्क के धनी हलक़ों में बड़ी उथल-पुथल मच गई और उसी दिन से अमेरिका की सम्पन्नता का ज़माना ख़त्म हुआ। व्यापार की मन्दी से जैसे दूसरे देश कष्ट भोग रहे थे वही हाल संयुक्तराष्ट्र का भी होगया। उद्योग और व्यवसाय की मन्दी अब विशालकाय बनकर दुनियाभर में फैल गई। यह ख़याल न करना कि शेयरों के सट्टे या न्यूयार्क की आर्थिक उथल-पुथल के कारण अमेरिका का दिवाला निकल गया या इनके कारण मन्दी आगई। यह तो ऊँट की पीठ पर लदे हुए बोझों में आख़िरी तिनके का शामिल होना था। असली कारण तो बहुत गहरे थे।

परेशान है। उनका एक-दूसरे के साथ मेल नहीं बैठता। समाज के पूँजीवादी स्वरूप और नई वैज्ञानिक कला और उत्पत्ति के तरीकों में संघर्ष है। समाज ने पैदा करना तो सीख लिया, मगर पैदा की हुई चीजों का बँटवारा करना नहीं सीखा।

इस छोटी-सी भूमिका के बाद हम ज़रा योरोप और अमेरिका पर एक नज़र और डालें। महायुद्ध के बाद पहले दस वर्षों में वहाँ क्या-क्या झगड़े हुए और दिक्कतें पेश आईं, उनका थोड़ा-सा हाल मैं तुम्हें बता चुका हूँ। लड़ाई के बाद की अवस्थाओं का हारो हुए देशों यानी जर्मनी और मध्य-योरोप के छोटे-छोटे मुल्कों पर बहुत बुरा असर हुआ; उनकी मुद्रा-प्रणाली की साथ नष्ट होगई और मध्यमवर्ग के लोग बर्बाद होगये। योरोप के विजेता और साहूकार राष्ट्रों की स्थिति भी इससे थोड़ी-सी ही अच्छी थी। वे सब अमेरिका के कर्जदार थे और उनके सिर पर राष्ट्रीय युद्ध-ऋण का भार भी बहुत ज्यादा था। इन दोनों क़र्जों के बोझ के मारे वे लड़खड़ा रहे थे और हफ्के-बक्के होगये थे। वे इस आशा में जी रहे थे कि जर्मनी से हर्जाने का रुपया मिल जायगा और उससे कम-से-कम विदेशी क़र्ज चुकाने का काम निकल जावेगा। यह उम्मीद बहुत माफ़ूल नहीं थी, क्योंकि जर्मनी तो बेचारा खुद दिवालिया था। इस कठिनाई का उपाय इस तरह हुआ कि अमेरिका ने जर्मनी को रुपया उधार दिया, जर्मनी ने इंग्लैण्ड और फ़्रांस वग़ैरा को उनके हिस्से का हर्जाना चुका दिया और उन्होंने इससे अमेरिका को क़र्ज का एक हिस्सा अदा कर दिया।

इन दस सालों में संयुक्तराष्ट्र अमेरिका ही एकमात्र सम्पन्न देश था। वहाँ तो बोलत की बाढ़-सी आगई थी और इस खुशहाली का ही यह नतीजा हुआ कि लोगों ने बेहिसाब आशायें बाँध लीं और सरकारी कागज़ों (Securities) और कारख़ानों के हिस्सों (Shares) का सट्टा होने लगा।

पूँजीवादी जगत् में आमतौर पर यह ख़याल फैला हुआ था कि पहले की तरह यह आर्थिक उथल-पुथल भी निकल जावेगी और धीरे-धीरे संसार में सम्पन्नता का समय आ जावेगा। असल में ऐसा मालूम होता है कि पूँजीवाद के जीवन में संकट के बाद सम्पन्नता और सम्पन्नता के बाद संकट आते ही रहते हैं। मार्क्स ने अपने 'कैपिटल' (पूँजी) नामक ग्रन्थ में बहुत पहले ही यह बात बता दी थी और यह साबित कर दिया था कि पूँजीवाद के तरीकों में न कोई योजना होती है और न विज्ञान। इसलिए उनका इस तरह का नतीजा होना लाज़िमी है। उद्योगों की सफलता से एक समय ऐसा आता है जब चीजों के भाव बुरी तरह बढ़ जाते हैं। उस समय अधिक-से-अधिक मुनाफ़ा उठाने के लिए सब लोग ख़ूब माल पैदा करना चाहते हैं। नतीजा यह होता है कि ख़पत से कहीं ज्यादा उपज हो जाती है। तैयार माल का

पहली तिमाही	आयात का मूल्य	निर्यात का मूल्य	दोनों का मूल्य
१९२९	७९७२०	७३१७०	१५२८९०
१९३०	७३६४०	६५२००	१३८८४०
१९३१	५१५४०	४५३१०	९६८५०
१९३२	३४३४०	३०२७०	६४६१०
१९३३	२८२९०	२५५२०	५३८१०

इन अंकों से हमें मालूम होता है कि संसार का व्यापार किस तरह अधिकाधिक गिरता गया है। और इस वर्ष की पहली तिमाही में तो वह चार वर्ष पहले जितना था उसका ३५ फी सदी या एक-तिहाई के करीब ही रहगया। और यह गिरावट अब भी जारी है और ऐसा दिखाई देता है, मानों सारी पूँजीवादी सामाजिक रचना इस प्रकार खत्म हो रही है कि उसके फिर से सम्भलने की आशा ही न हो।

व्यापार-सम्बन्धी ये कठिन अंक मानवीय हिसाब से हमें क्या बता रहे हैं? ये हमें कह रहे हैं कि अधिकांश लोग इतने गरीब हैं कि जो वे पैदा करते हैं उसें खरीद नहीं सकते। ये कह रहे हैं कि बेशुमार मजदूर बेकार हैं और संसार की अधिक-से-अधिक सद्भावना के होते हुए भी उन्हें रोजगार नहीं मिल सकता। योरप और संयुक्त-राष्ट्र में ही तीन करोड़ मजदूर हैं, जिनमें से तीस लाख ब्रिटेन में और एक करोड़ तीस लाख संयुक्तराष्ट्र में हैं। हिन्दुस्तान या एशिया के दूसरे देशों में कितने बेकार हैं, इसका तो किसीको पता भी नहीं है। शायद अकेले हिन्दुस्तान में बेकारों की तादाद योरप और अमेरिका से भी कहीं ज्यादा है। दुनियाभर के इन बेशुमार बेकारों और उनके आश्रित कुटुम्बियों का विचार करो तो तुम्हें कुछ कल्पना होगी कि व्यापार की मन्दी से मनुष्यों पर कैसी मुसीबत आई है। योरप के अनेक देशों में सरकारी बीमे की ऐसी प्रणाली है कि बेकारों में दर्ज होनेवाले सब लोगों को गुजर के लायक खर्च दिया जाय। संयुक्तराष्ट्र में उन्हें धर्मादा दिया जाता है।

मगर इस खर्च और ख़रात से क्या काम चलता है और बहुतों को यह भी कहाँ मिलता है? मध्य और पूर्वीय कुछ हिस्सों में अवस्थायें भयंकर हैं। अस्ट्रिया और हंगरी रोग-पीड़ित राष्ट्र हो गये हैं। ऐसा मालूम होता है कि उनकी बीमारी प्राण लेकर छोड़ेगी। जर्मनी में विपत्ति का डंक लगने से हाल ही में एक असाधारण प्रति-प्रान्ति हुई। इंग्लैण्ड को १५० वर्ष के संसार-व्यापी साम्राज्यवादी शोषण का सहारा है, फिर भी उसका काम चलना मुश्किल हो रहा है। वह बेकारों को बीमे के रूप में खर्च देता है और कितनी तरह उन्हें शान्त रखता है। मगर इस खर्च का भार उठाना दिन-दिन भारी हो रहा है। अद्यतक हिसाब लगाने पर मालूम होता है कि जितना

दुनिया-भर में व्यापार घटने लगा और खास तौर पर खेती से पैदा होनेवाली चीजों का भाव तेजी से गिरने लगा। कहते हैं, लगभग सभी चीजों की पैदावार ज़रूरत से ज्यादा होगई थी। इसका वास्तविक अर्थ यह हुआ कि जो माल तैयार होता था उसे खरीदने के लिए लोगों के पास रुपया नहीं था, यानी माल की खपत कम होगई थी। जब तैयार माल बिक न सका, तो वह जमा होगया। इसलिए जिन कारखानों में वह तैयार होता था, उनका वन्द होना भी स्वाभाविक था। वे ऐसी चीजें बनाते नहीं रह सकते थे जिनकी बिक्री न हो। इससे योरप, अमेरिका और सभी देशों में बेकारी बहुत बुरी तरह बढ़ गई। सभी औद्योगिक देशों को गहरी हानि पहुँची। यही हाल उन कृषि-प्रधान देशों का भी हुआ जो दुनिया के बाज़ार में उद्योगों के लिए खाद्य-पदार्थ या कच्चा माल भेजते थे। इस तरह हिन्दुस्तान के कारखानों को भी कुछ नुक़सान पहुँचा, मगर भावों के गिर जाने से किसानों को बहुत ज्यादा हानि हुई। मामूली तौर पर खाने-पीने की चीजों की कीमत का घटना लोगों के लिए न्यायमत्त होता है, क्योंकि उन्हें खाने का सामान सस्ता मिल जाता है। मगर पूंजीवादी प्रणाली में उलटी गंगा बहती है। इसलिए यह वरदान भी शाप बन गया। किसानों को ज़मींदार या सरकार का लगान चुकाने के लिए नक़द रुपया देना पड़ा और यह नक़द रुपया हासिल करने के लिए उन्हें अपना माल बेचना पड़ा। माल की कीमत असाधारणतः इतनी कम होगई कि कभी-कभी उन्हें सारी पैदावार बेच देने पर भी काफ़ी रुपया नहीं मिला। अक्सर उन्हें ज़मीनों से बे-दख़ल कर दिया गया, मिट्टी के झोंपड़ों से निकाल दिया गया और उनके घरों में जो थोड़ा-सा सामान रहता है वह भी लगान चुकाने के लिए नीलाम कर दिया गया। इस तरह जिस वक़्त खाद्य पदार्थ इतने सस्ते थे उस समय भी, जिन लोगों ने उन्हें पैदा किया था, उन्हें भूखों मरना और बेघर-बार होना पड़ा।

संसार की परस्पर-निर्भरता ने ही इस मन्दी को सर्वव्यापी बना दिया। मेरा अनुमान है कि बाहरी दुनिया से अलग-थलग कोई तिब्बत जैसी जगह ही इससे बची रही होगी। महीने दर महीने मन्दी फैलती गई और व्यापार गिरता गया। ऐसा मालूम होता था कि सारे सामाजिक शरीर को धीरे-धीरे लक़वा मार रहा है और उसे बेकार कर रहा है। चार साल से लगातार यही हाल है। और, कहीं-कहीं अस्थायी सुधार होने की बात छोड़ दें तो, स्थिति बिगड़ती ही जा रही है। इस बिगाड़ की कल्पना करने का सबसे अच्छा उपाय शायद यह है कि पिछले चार साल के व्यापार के सच्चे आँकड़ों की जाँच की जासके। संसार के व्यापार के राष्ट्र-संघ ने नीचे लिखे आँकड़े प्रकाशित किये हैं। ये अंक हर वर्ष के पहले तीन मास के और लाख स्वर्ण-डालरों में हैं—

परन्तु इन मजदूरों की हालत दिन-पर-दिन बिगड़ती ही चली गई। बहुतांशों को कुछ भी मदद नहीं मिली, और वे एक शहर से दूसरे शहर मारे-मारे फिरते रहे। वे बाजारों में घूमते रहते, आने-जानेवाले मोटरवालों से उन्हें भी बिठा लेने की मिन्नत करते रहते और अक्सर धीमी चलनेवाली मालगाड़ियों पर चढ़कर उनके पायदानों पर लटकते रहते। अमेरिका में इन आवारों को 'होबो' कहते हैं। अमेरिका में पहलेपहल इन आवारा 'होबो' लोगों में हजारों स्त्रियाँ भी दिखाई दीं। वे भी रोजगार की तलाश में त्राक छानती थीं। इससे भी ज्यादा मर्मस्पर्शी बात यह थी कि कम उम्र के लड़के और लड़कियाँ और बच्चे तक अकेले या छोटे-छोटे झुण्ड बनाकर उस विशाल देश के इस किनारे से उस किनारे तक भटकते फिरते। शिशु-संघ ने हिसाब लगाया है कि अमेरिका में २१ वर्ष से नीचे के ऐसे दो लाख के करीब लड़के और लड़कियाँ मारे-मारे फिरते हैं। इससे उन हालतों का स्मरण होता है जो गृह-युद्ध के बाद रूस में भी मौजूद थीं। उस समय रूस आवारा लड़के और लड़कियों से भरा था।

बड़ी उम्र के और हट्टे-कट्टे आदमी काम की आशा लगाये और वाट देखते हुए बेकार बैठे रहते थे, और नमूने के कारखाने भी बन्द पड़े थे, फिर भी पूँजीवाद चीज ही ऐसी है कि उसी वक्त मिठाई की अंधेरी और गन्दी दुकानें खुलने लगीं और १२ से १६ वर्ष के बच्चों को उनमें थोड़ी-सी मजदूरी पर दस-दस और बारह-बारह घण्टे रोज काम में जोता जाने लगा। कुछ कारखानेदारों ने इन लड़के और लड़कियों की बेकारी की मजदूरी का फायदा उठाया और उनसे अपने कारखानों में खूब कड़ा और लम्बा काम लिया। इस तरह मन्दी के कारण अमेरिका में फिर से बच्चों की मजदूरी शुरू हुई और इस बुराई और ऐसी ही दूसरी बुराइयों को रोकनेवाले कानूनों की खुले-आम अवहेलना की गई।

यह याद रहे कि अमेरिका में या बाकी की दुनिया में खाद्य पदार्थों या तैयार माल की कमी नहीं थी, बल्कि शिकायत यह थी कि माल जरूरत से ज्यादा है और पैदावार खर्च से ज्यादा हुई है। सर हेनरी स्ट्राकोश नामक प्रसिद्ध अंग्रेज अर्थशास्त्री ने बयान किया है कि जुलाई सन् १९३१ में, यानी मन्दी के दूसरे साल में, संसार की मण्डियों में इतना माल था कि अगर अगले सवा दो वर्ष तक संसार भर के लोग कुछ भी काम न करते तो भी उनका गुजर उसी तरह से चलता रह सकता था जिस तरह गुजर करने का उनका अभ्यास है। यह बयान खूब गौर करने लायक है। फिर भी इसी काल में इतना व्यापक कष्ट और भुखभरी रही है जितनी आधुनिक औद्योगिक संसार ने कभी नहीं देखी। एक तरफ यह कष्ट और दूसरी तरफ साथ ही साथ खाद्य पदार्थों को सच-सच नष्ट कर देने का सिलसिला जारी रहा। फलतः नहीं काटी गई और उन्हें खेतों में

उसने महायुद्ध पर खर्च किया था उससे कहीं अधिक महायुद्ध के वक्त से वह बेकारों पर खर्च कर चुका है। देशभर में कारखाने खाली और बेकार पड़े हैं। लंकाशायर का रूई का महान् उद्योग, जो किसी समय आधी दुनिया को कपड़ा देता था, अब सिकुड़कर आधा रह गया है और वहाँके कारीगर श्रमजीवी बेकार बैठे अच्छे दिनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं और वे दिन आ नहीं रहे। इन रजिस्टर में दर्ज हुए मजदूरों को फिर भी थोड़ा-सा खर्च मिल जाता है। मगर इनके पीछे और कितने अधिक लोग हैं, जिन्हें कुछ भी नहीं मिलता और जो भूखों मरते हैं ?

सभी बड़े उद्योग-प्रधान देशों में अमेरिका पर मन्दी का प्रहार सबसे पीछे हुआ। परन्तु उसकी प्रतिक्रिया भी और जगहों से वहाँ अधिक हुई। अमेरिका के लोगों को व्यापार की लम्बी और लगातार मन्दी का तथा कष्ट-सहन का अभ्यास नहीं है। उनके पास हमेशा पैसे का जोर रहा है। इसलिए पहली चोट लगते ही उनके होश उड़ गये। जब बेकारों की तादाद लाखों पर पहुँचने लगी और भुखमरी का दृश्य एक मामूली बात होगई तो राष्ट्र की हिम्मत टूट गई। बैंकों और उद्योगों में लोगों का विश्वास नहीं रहा और उन्होंने रुपया निकाल-निकालकर घरों में जमा कर लिया। बैंकों की तो हस्ती ही विश्वास और साख के आधार पर होती है। विश्वास नहीं रहा तो बैंक भी गया। संयुक्तराष्ट्र में इंग्लैण्ड से विपरीत छोटे-छोटे बैंक बहुत हैं। वे अपना-अपना कारोबार स्वतन्त्र रूप से चलाते हैं। दूसरे शहरों में इनकी शाखाएँ भी नहीं होतीं। इन छोटे बैंकों का बालू की भीत की तरह ढेर हो गया। पिछले चारों वर्षों में संयुक्तराष्ट्र में करीब दस हजार बैंकों का दिवाला निकल गया। एक-एक दिवाले से स्थिति और भी विकट हुई, लोग और भी अधिक डर गये, और आमतौर पर हालत पहले से ज्यादा खराब होगई।

अमेरिका में योरप की तरह बेकारों के बीमे की पद्धति नहीं है। मगर हम हिन्दुस्तानियों की तरह अमेरिकियों को अपने बीच में लोगों को भूखे मरते देखकर उनकी उपेक्षा करने का भी अभ्यास नहीं है। यहाँ भारत में तो लोग भूखों मरें तो किसीको परवा ही नहीं होती; और लाखों भूखों मरते ही हैं। भुखमरी की क्रिया आम तौर पर धीरे-धीरे होती है। जब यह तेज और व्यापक होजाती है तब उसे अकाल का नाम दे देते हैं और फिर स्थिति का मुक्काबिला करने के लिए कुछ निर्वल-सा प्रयत्न कर दिया जाता है। अमेरिका में हजारों धर्मार्थ संस्थाओं और म्युनिसिपैलिटियों ने बेकारों को खिलाने-पिलाने का बीड़ा उठा लिया। यह उनके लिए बड़ा भारी बोझा होगया और इससे बहुत-सी म्युनिसिपैलिटियाँ दिवाले की हालत तक पहुँच गईं। अमेरिका ने किसी भी तरह अपने लाखों बेकार मजदूरों को ज़िन्दा रख लिया।

में भी तबादले के अनेक उदाहरण पैदा हुए, क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय की पेचीदा प्रणाली में तो गड़बड़ हो गई थी। इस तरह इंग्लैण्ड ने स्कैण्डिनेविया से ईंधन लेकर उसे कोयला दे दिया, कनाडा ने सोवियट रूस के तेल के बदले में एल्यूमीनियम दे दिया और संयुक्तराष्ट्र ने ब्रैजील को गेहूँ देकर क़हवा ले लिया।

मन्दी से अमेरिका के किसानों को बहुत नुक़सान पहुँचा और उन्होंने अपने खेत गिरवी रखकर बैंकों से जो रुपया उधार लिया था उसे वे न चुका सके। इसलिए बैंकों ने खेतों को नीलाम करवाकर अपना रुपया वसूल करने की कोशिश की। लेकिन किसानों ने ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने इन नीलामों को रोकने के लिए अपनी युद्ध-समितियाँ संगठित कर लीं। फल यह हुआ कि नीलाम के समय किसान की सम्पत्ति पर किसीको बोली लगाने का साहस नहीं होता था और बैंकों को विवश होकर किसानों की शर्तें माननी पड़ीं। किसानों की यह बग़ावत मध्य-पश्चिमी अमेरिका के कृषि-प्रदेशों में फैली और 'किसानों की छुट्टी' की संगठित प्रणाली शुरू हुई। इसका यह अर्थ था कि किसान हड़ताल कर देते थे और पड़ोसी शहरों को खाद्य पदार्थ देने से इन्कार कर देते थे। एक 'दूध की हड़ताल' भी हुई थी और उसमें बहुत-सा दूध इसलिए जानबूझकर फेंक दिया गया था कि वह शहरों में न जा सके। जैसे-जैसे स्थिति की विकटता बढ़ती गई है वैसे-वैसे अमेरिका के इन पुराने ख़याल के किसानों का दृष्टिकोण भी अधिकाधिक उग्र और क्रान्तिकारी बनता जा रहा है। उनकी माँग है कि खेती के सारे क़र्ज़ या तो रद्द कर दिये जायँ या अनिश्चित काल तक मुल्तवी कर दिये जायँ और सारे करों में भारी कमी कर दी जाय। उनके रणनाद ये हैं—“मानवीय अधिकार क़ानूनी और सम्पत्ति के अधिकारों से ऊपर हैं,” “गिरवी का पहला हक़ स्त्रियों और बच्चों का है” वगैरा।

अमेरिका के किसानों का यह आन्दोलन दिलचस्प है, क्योंकि यह शुद्ध स्वदेशी आन्दोलन है और समाजवाद या साम्यवाद से इसका कुछ भी ताल्लुक नहीं है। ये किसान उन पुराने अमेरिकनों की नस्ल से हैं जो देश के पुरातनतावादी वर्ग की रीढ़ हैं। लेकिन आर्थिक कष्ट के कारण ये सम्पन्न मध्यम वर्ग के किसानों से ऐसे किसान बनते जा रहे हैं जो हल जोतकर पेट भरते हैं और सम्पत्ति कुछ भी नहीं रखते। इस परिवर्तन के साथ-साथ उनकी मनोवृत्ति भी बदलती और अधिकाधिक क्रान्तिकारी बनती जा रही है। मन्दी की वजह से कारख़ानों के मजदूर-वर्ग में भी तब्दीली हो रही है। पहले होशियार मजदूर यानी कारीगर लोग इतने ख़ुशहाल रह चुके हैं कि योरप के धमजीवियों से उनकी कुछ भी तुलना नहीं हो सकती। वे छोटे-मोटे पूंजीपति और मध्यम वर्ग से अधिक मिलते-जुलते थे। यही कारण है कि अमेरिका का मजदूर-

ही खड़े-खड़े सड़ जाने दिया गया। फल वृक्षों पर छोड़ दिये गये। और बहुत-सी चीजों को तो दरअसल बरबाद कर दिया गया। तुम्हें एक ही मिसाल बताता हूँ। जून १९३१ से फरवरी १९३३ तक ब्रेजील में क़ह्वे की १ करोड़ ४० लाख बोरीयाँ नष्ट की गईं। एक बोरी में १३२ पाउण्ड वजन होता है, इसलिए कुल १ अरब ८४ करोड़ ८० लाख पाउण्ड क़हवा नष्ट किया गया। यदि एक आदमी को एक पाउण्ड दिया जावे तो यह क़हवा दुनिया की सारी आबादी के लिए काफी से भी अधिक था। तो भी हम जानते थे कि लाखों आदमी ऐसे हैं जिन्हें क़हवा मिले तो वे खुश हों, परन्तु उन्हें मिलता नहीं।

क़ह्वे के अलावा गेहूँ, रुई और कितनी ही दूसरी चीजें नष्ट कर दी गईं। रुई, रबर, चाय चाँरा की बुवाई सीमित करके भावी उत्पत्ति घटाने के भी उपाय किये गये हैं। यह सारा नाश और सीमा-व्यन्धन खेती की पैदावार की कीमत बढ़ाने ही के लिए किया गया है, ताकि माल की कमी के कारण माँग पैदा हो और भाव बढ़ जायें। इससे मण्डी में माल बेचनेवाले किसानों को तो बेशक फ़ायदा होगा, मगर ख़रीददारों का क्या हाल होगा? सचमुच हम एक अजीब दुनिया में रहते हैं। अगर पैदावार कम कर दी जाती है तो कीमतें इतनी ऊँची हो जाती हैं कि बहुतेरे लोग उसे ख़रीद नहीं सकते और उन्हें कष्ट भोगना पड़ता है। अगर पैदावार ज्यादा कर दी जाती है तो भाव इतने गिर जाते हैं कि उद्योग और खेती का काम नहीं चलता और बेकारी फैल जाती है। बेकार तो बेचारे ख़रीदें ही क्या, जब उनके पास रुपया ही न हो? अकाल और बाहुल्य, दोनों ही सूरतों में गरीबों के भाग्य में तो दुःख सहना ही बड़ा है।

मैं कह चुका हूँ कि मन्दी के समय अमेरिका में या दूसरी जगहों पर माल की कमी नहीं थी। किसानों के पास खेती की पैदावार पड़ी हुई थी और वह विक नहीं सकती थी; और शहर के लोगों के पास पक्का माल जमा हो रहा था जिसका कोई ख़रीदार नहीं मिलता था। फिर भी एक को दूसरे के पदार्थों की जरूरत तो थी ही। दोनों ही ओर धन का अभाव होने से विनिमय की क्रिया बन्द होगई। फिर अत्यंत उद्योग-प्रधान, प्रगति-शील पूँजीवादी अमेरिका में बहुत-से लोगों ने तबादले का पुराना तरीक़ा इस्तिथार कर लिया। जब रुपया काम में नहीं आता था तब, पुराने ज़माने में, यही रिवाज था। जब विनिमय की पूँजीवादी व्यवस्था रुपये के अभाव में अस्तव्यस्त होगई तो लोगों ने रुपये के बिना ही काम चलाना शुरू कर दिया। वे काम के बदले में काम और माल के बदले में माल देने-लेने लगे। सनद दे-देकर इस तबादले की सहायता करने के विनिमय-संघ खड़े होगये। तबादले की एक मज्जेदार मिसाल यह थी कि एक ग्वाले ने अपने बच्चों की शिक्षा के एवज़ में विश्वविद्यालय को दूध, मक्खन और अण्डे दिये।

दूसरे देशों में भी तबादले का रिवाज एक हद तक जारी हुआ। राष्ट्रों के बीच

संकट के कारण

२१ जुलाई, १९३३

इस महान् मन्दी के पिशाच ने संसार का गला दबा रक्खा है और लगभग सारे काम-काज बन्द या मन्द कर दिये हैं। बहुत जगहों पर उद्योग का चक्र घूमना बन्द होगया है। जिन खेतों में खाने-पीने के और दूसरे पदार्थ पैदा होते थे वे यों ही बेजुते पड़े हैं। रबड़ के पेड़ों से रबड़ चू रहा है, मगर उसे इकट्ठा करनेवाले नहीं हैं। पहाड़ियों के ढाल, जहाँ पहले चाय के हरे-भरे खेत लहलहाते थे, अब वंजर पड़े हैं और उनकी कोई सम्हाल नहीं करता। जो लोग ये सब काम किया करते थे वे बेकारों की महान् सेना में भर्ती होकर काम और रोजगार की बाट देखते हैं, मगर वह मिलता ही नहीं और वे बेचारे निराश होकर भूख और दरिद्रता का सामना कर रहे हैं। बहुतेरे देशों में आत्महत्याओं की तादाद खूब बढ़ गई है।

मैं बता चुका हूँ कि मन्दी की चोट सभी उद्योगों पर हुई। मगर एक उद्योग अछूता रहा, और वह था हथियार और युद्ध-सामग्री बनाने का। यह उद्योग भिन्न-भिन्न राष्ट्रों की जल, स्थल और हवाई सेनाओं के लिए हथियार और युद्ध के सामान तैयार करता है। यह व्यवसाय खूब चमका और इसके हितसेदारों को मुनाफ़ा भी भरपूर मिला। इस-पर मन्दी का कुछ असर नहीं हुआ, क्योंकि इसका धंधा राष्ट्रों की प्रतिद्वंद्विता और संघर्ष पर चलता है और ये दोनों बातें इस संकट-काल में खूब बढ़ गईं।

सोवियट संघ का बड़ा प्रदेश भी मन्दी के सीधे असर से बचा रहा। वहाँ बेकारी तो हुई ही नहीं और पंचवर्षीय योजना के कारण काम पहले से भी ज्यादा रहा। यह प्रदेश पूंजीवाद के नियंत्रण से बाहर था और यहाँकी अर्थ-व्यवस्था भी अलग तरह की थी। लेकिन, जैसा मैं तुम्हें बता चुका हूँ, उसपर भी मन्दी का अप्रत्यक्ष रूप में कुपरिणाम तो हुआ ही, क्योंकि खेती की पैदावार उसे विदेशों में बेचनी पड़ती थी और उसका भाव बहुत गिर गया था।

इस महामन्दी का, इस संसारव्यापी संकट का, कारण क्या था ? यह संकट अपने ढंग का भयंकर तो करीब-करीब उतना ही था जितना पिछला महायुद्ध था। इसे पूंजीवाद का अन्तकाल कहते हैं, क्योंकि इसकी चोट से पूंजीवाद की व्यापक और पेचीदा व्यवस्था छिन्न-भिन्न होरही है। पूंजीवाद का इस तरह अन्त क्यों होरहा है ? और क्या यह संकट स्थायी है ? पूंजीवाद इसके बाद भी कायम रहेगा ? या यह कि जिस महान् प्रणाली ने युग-युगान्तर से संसार पर अपना प्रभुत्व जमा रक्खा है वह अन्तिम

आन्दोलन इतना पिछड़ा हुआ और प्रतिगामी रहा। अब वे सच्चे अर्थ में जाग्रत गरीब बन रहे हैं।

मैंने संयुक्तराष्ट्र की अवस्थाओं का विस्तार से वयान किया है, क्योंकि अमेरिका कई बातों में मनोहर देश है। पूँजीवादी देशों में यह सबसे उन्नत है और यहाँ योरप और एशिया की तरह इसके प्राचीन काल पर सामन्तशाही का असर नहीं रहा है। इस कारण वहाँ परिवर्तन तेजी से होने की सम्भावना रहती है। दूसरे देशों में गरीबों को फष्ट सहने का ज्यादा अभ्यास रहा है। अमेरिका के लिए यह बात और इतने बड़े पैमाने पर होना एक नई विस्मयकारक घटना थी। मैंने अमेरिका के बारे में तुम्हें जो कुछ बताया है उससे तुम मन्दी के समय दूसरे देशों की हालत का अन्दाज़ लगा सकती हो। कुछ देशों की हालत तो बहुत बुरी थी और कुछ की ज़रा अच्छी थी। सब बातों को देखते हुए कृषि-प्रधान और पिछड़े हुए देशों की इतनी दुर्दशा नहीं हुई जितनी आगे बढ़े हुए उद्योग-प्रधान देशों की हुई। उनके पिछड़ेपन ने ही एक हद तक उनकी रक्षा की। उनकी खास मुसीबत यह थी कि खेती की पैदावार के भाव एकदम गिर जाने से वहाँके किसानों पर आफ़त का पहाड़ टूट पड़ा। आस्ट्रेलिया एक कृषि-प्रधान देश है। भावों के गिर जाने से वह अंग्रेज़ी बँकों को ऋज नहीं चुका सका और दिवाला निकलने की नीवत आपहुँची। आखिर उसने अंग्रेज़ साहूकारों की कड़ी शर्त मानकर अपनी जान बचाई। मन्दी के ज़माने में साहूकार वर्ग के ही वारे-न्यारे होते हैं और उसीका सबपर सिक्का जमता है।

दक्षिणी अमेरिका में संयुक्तराष्ट्र से उधार मिलना बन्द होने और मन्दी के कारण उथल-पुथल मच गई, और वहाँकी अधिकांश प्रजातन्त्र सरकारों या यों कहो कि वहाँके सर्वेसर्वा शासकों का तख़्ता उलट गया। दक्षिण के सारे देशों में क्रान्तियाँ हुईं। इनमें अर्जेंटीना, ब्राज़ील और चिली के तीनों प्रमुख देश शामिल थे। दक्षिणी अमेरिका में सभी क्रान्तियाँ राजमहलों तक सीमित रहती हैं और केवल सर्वेसर्वा शासक और बड़े-बड़े सरकारी अधिकारी बदल जाते हैं। ये क्रान्तियाँ भी इसी तरह की थीं। वहाँ जो व्यक्ति या दल सेना और पुलिस पर अधिकार जमा लेता है वही शासक बन बैठता है। दक्षिणी अमेरिका की सभी सरकारें बुरी तरह ऋज में फँसी हुई हैं और अधिकांश नाबिहन्द होचुकी हैं।

अंग्रेज राजनीतिज्ञ ने कहा है कि "विचारशील लोगों का विश्वास है कि समाज का हास शुरू होगया है। हमें मालूम है कि योरप में एक युग का अन्त हो रहा है।"

जर्मन लोगों की राय में इस उथल-पुथल का असली कारण युद्ध का हजाना था। और बहुत-से लोगों के खयाल से मन्दी का सबब यह था कि राष्ट्रों के विदेशी और भीतरी युद्ध-ऋण का बोझा असह्य होगया और वह सारे उद्योग को कुचलने लगा। इस तरह संसार के कष्टों के लिए मुख्यतः महायुद्ध को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। कुछ अर्थशास्त्रियों का यह खयाल है कि झगड़े की जड़ रुपये का विचित्र व्यवहार और भावों का बुरी तरह गिरना है और यह हुआ है सोने की कमी के कारण। सोने की कमी कुछ तो इसलिए हुई कि खानों से ही संसार की जरूरत के लायक सोना नहीं निकलता और ज्यादातर इसलिए हुई कि अलग-अलग सरकारों ने सोना जमा कर लिया। दूसरे लोग यह भी कहते हैं कि सारी खुराफात अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को रोकनेवाली आर्थिक राष्ट्रीयता, चुंगी और भारी कर-बन्दी की वजह से है। एक कारण यह बताया जाता है कि वैज्ञानिक कला बहुत आगे बढ़ गई है, उसके कारण बहुत कम मजदूरों की जरूरत रह गई है और इसलिए बेकारी ज्यादा होगई है।

इन सारी सूचनाओं के पक्ष में बहुत-कुछ कहा जा सकता है और यह भी मुमकिन है कि संसार की मौजूदा गड़बड़ में इन सभीका हाथ रहा हो। मगर इनमें से किसी एक पर या सब पर भी संकट का दोष लगाना उचित या न्याय-संगत मालूम नहीं होता। असल में इन बताये जानेवाले कारणों में से बहुत-से तो इस उथल-पुथल के परिणाम हैं। हाँ, संकट को गम्भीर बनाने में इनमें से एक-एक ने मदद जरूर पहुँचाई है। मगर झगड़े की जड़ बहुत गहरी है। युद्ध में हार जाना इसका कारण नहीं है, क्योंकि विजेता खुद इसमें फँसे हुए हैं। राष्ट्र की गरीबी भी कारण नहीं हो सकती, क्योंकि संसार के सबसे धनी देश अमेरिका को ज्यादा-से-ज्यादा नुकसान हो रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि संकट के जल्दी ही होने में महायुद्ध का जबरदस्त हाथ रहा है। इसके दो कारण हुए। एक तो क्रुद्ध का भारी भार और ऋणदाताओं में उसके बँटवारा का तरीका, और दूसरा कारण यह हुआ कि लड़ाई के समय और लड़ाई के बाद कुछ वर्ष चीजों के जो ऊँचे भाव रहे वे बनावटी थे और उनका एकदम से गिरना अनिवार्य था। परन्तु हम जरा और गहरे पँठकर देखें।

कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा उत्पत्ति झगड़े की जड़ है। लेकिन यह शब्द ही गलत है। जब करोड़ों आदमी नितान्त आवश्यक-से-आवश्यक चीजों की कमी के कारण तकलीफ पा रहे हैं तो जरूरत से ज्यादा उत्पत्ति कैसी? हिन्दुस्तान में करोड़ों मनुष्यों को तन टकने के लिए भी पूरा कपड़ा नहीं मिलता। फिर भी हम चुनते हैं

साँस ले रही हैं ? ऐसे कितने ही सवाल पैदा होते हैं और उनमें बड़ा आकर्षण या कशिश है, क्योंकि उनके जवाब पर मानव-जाति का और साथ ही हमारा भी भविष्य निर्भर है । इस संकट को दूर करने के लिए पिछले चार वर्ष में भिन्न-भिन्न देशों में मुहूर्तलिफ़ उपाय किये गये हैं, मगर उनसे स्थिति उलटी घिगड़ी ही है । बहुत-सी बलवर्द्धक ओषधियाँ दी गई मगर, जैसा सभी उत्तेजक दवाइयों का असर होता है, इससे भी थोड़े समय के लिए सुधार मालूम हुआ और बाद में और भी शिथिलता आई । १९३२ के दिसम्बर में ब्रिटिश सरकार ने अमेरिकन सरकार को एक खत भेजा और उसमें यह प्रार्थना की कि उसका युद्ध का कर्ज माफ़ कर दिया जाय । इस खत में यह बताया गया था कि किस तरह 'मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की' । उसमें कहा गया कि "सब जगह कर बुरी तरह बढ़ा और खर्च खूब घटा दिया गया है । फिर भी जिस नियंत्रण और मर्यादा से बीमारी का इलाज होने की उम्मेद थी उसीसे वह और बढ़ गई ।" आगे चलकर यह बताया गया कि "इस नुस्तेम और मुसीबत का कारण प्रकृति की कंजूसी नहीं है । भौतिक विज्ञान की सफलता दिनोंदिन बढ़ रही है और सच्ची दीलत के पैदा करने की छिपी हुई विशाल शक्तियाँ ज्यों-की-त्यों बनी हुई हैं ।" कसूर प्रकृति का नहीं, बल्कि इन्सान और उसकी बनाई हुई प्रणाली का है ।

पूँजीवाद की इस बीमारी का सही-सही निदान करना या इसके इलाज का नुसला तजवीज करना आसान नहीं है । अर्थशास्त्रियों को इस बारे में सब कुछ मालूम होना चाहिए, लेकिन उनके आपस में ही मतभेद है और वे अलग-अलग कारण और इलाज बताते हैं । अगर इस मामले में किसीके दिमाग में साफ़ विचार हैं तो सिर्फ़ साम्यवादियों और समाजवादियों के दिमाग में हैं । उनका कहना है कि पूँजीवाद का इस भाँति छिन्न-भिन्न होना उनके सिद्धान्तों और विचारों के अनुसार उचित है । पूँजीवादी विशेषज्ञ तो साफ़ तौर पर अपनी घबराहट और परेशानी क़बूल करते हैं । मार्टिन्ग्यू नॉर्मन अंग्रेज़ अर्थ-व्यवस्थापकों में एक बहुत बड़ा और क़ाबिल आदमी है । वह बैंक ऑफ़ इंग्लैण्ड का गवर्नर है । उसने कुछ महीने पहले एक सार्व-जनिक अवसर पर कहा था—“आर्थिक समस्या मेरे बूते की बात नहीं है । कठिनाइयाँ इतनी विशाल और नवीन हैं कि उनकी कोई नज़ीर नहीं मिलती और मैं तो इस विषय को बड़े अज्ञान और विनय के साथ हाथ में लेता हूँ । मेरे लिए यह सवाल बहुत बड़ा सवाल है । अभी तो अंधेरी गुप्त सुरंग-ही-सुरंग दिखाई देती है । आशा है आगे चलकर प्रकाश के भी दर्शन हों ।” मगर यह प्रकाश छलावे की तरह हमारे हृदयों में आशायें पैदा करता और फिर विलीन होजाता है । इस बीच दुनिया किसी महान् विपत्ति के मुख में फिसलती चली जा रही है । सर आक्लैण्ड गिडीज़ नामक मशहूर

दुनिया पर ही एक तरह से पूंजीवादी शोषण छा गया तो फैलने की यह क्रिया बन्द होगई और बड़े-बड़े राष्ट्रों के संघर्ष से लड़ाई छिड़ गई।

ये सब बातें मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन मैं इन्हें इसलिए दोहरा रहा हूँ कि तुम्हें वर्तमान संकट को समझने में मदद मिले। बढ़ते हुए पूंजीवाद और साम्राज्यवाद के इस जमाने में पश्चिम में अनेक बार संकट आये, क्योंकि एक तरफ़ लोग बहुत-सा रुपया बचाकर रखते थे और दूसरी तरफ़ लोगों के पास खर्च करने को बहुत थोड़ा रुपया रहता था। मगर ये संकट-काल निकल गये, क्योंकि पूंजीपतियों का फ़ालतू रुपया पिछड़े हुए प्रदेशों का विकास और शोषण करने में लग गया और इस तरह वहाँ नये बाज़ार खड़े होगये और माल की खपत बढ़ गई। साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अन्तिम स्वरूप कहलाया। मामूली हालत में यह शोषण-क्रिया दुनिया-भर के उद्योग-प्रधान बन जाने तक जारी रह सकती थी, लेकिन बीच में कठिनाइयाँ और रुकावटें पैदा होगई। खास मुश्किल थी साम्राज्यवादी राष्ट्रों की भयंकर प्रतिस्पर्धा। उनमें से हरेक खुद बड़े-से-बड़ा हिस्सा लेना चाहता था। दूसरी मुश्किल यह हुई कि पराधीन देशों में नया राष्ट्रवाद पैदा हुआ। वहाँके उद्योगों की उन्नति होने लगी, और वे अपने यहाँकी मण्डियों को माल पहुँचाने लगे।

हम देख चुके हैं कि इन सब क्रियाओं के परिणाम-स्वरूप युद्ध हुआ। लेकिन युद्ध से पूंजीवाद की कठिनाइयाँ न हल न हुई, हो सकती थीं। सोवियट संघ का विशाल प्रदेश पूंजीवादी संसार में से सफ़ा निकल गया और शोषण करने जैसा बाज़ार न रहा। पूर्व में राष्ट्रीयता अधिकाधिक तीव्र हो चली और उद्योगवाद फैलने लगा। लड़ाई के समय और लड़ाई के बाद वैज्ञानिककला में जो ज़बरदस्त उन्नति हुई उससे भी सम्पत्ति के असमान विभाजन में और बेकारी के पैदा होने में मदद मिली। युद्ध-ऋण भी एक प्रबल कारण हुआ।

युद्ध-ऋण भारी बहुत था और यह याद रखना चाहिए कि वह कोई ठोस सम्पत्ति नहीं था। अगर कोई देश रेलवे या आबपाशी के लिए या देश के किसी और लाभ-दायक काम के लिए रुपया उधार लेता है तो उस ऋण और खर्च के बदले में उसके पास कुछ ठोस चीज़ आजाती है। असल में इन कार्यों पर खर्च की हुई सम्पत्ति से भी अधिक पैदा हो सकती है। इसीलिए ये उत्पादक कार्य कहलाते हैं।

मगर युद्ध-काल में उधार लिया हुआ रुपया ऐसे किसी काम में खर्च नहीं हुआ। वह उत्पादक तो था ही नहीं, बल्कि विनाशक था। बेशुमार रुपया खर्च किया गया और उसके पीछे नाश-ही-नाश बाक़ी रहा। इस तरह युद्ध-ऋण खालिस भार के सिवा और कुछ न था। युद्ध-ऋण तीन तरह का था। एक लड़ाई का हर्जाना था जो

कि हिन्दुस्तानी मिलों और खादी-भण्डारों में माल भरा पड़ा है और कपड़ा जरूरत से ज्यादा तैयार होगया है। असल बात यह है कि लोग इतने गरीब हो गये हैं कि वे कपड़ा खरीद नहीं सकते। बात यह नहीं है कि उन्हें कपड़े की जरूरत नहीं है। बात यह है कि गरीबों के पास रुपया ही नहीं है। इस धनाभाव का अर्थ यह नहीं है कि रुपया दुनिया से तायव होगया है। इसका अर्थ यह है कि संसार के लोगों में रुपये का बटवारा बदल गया है और लगातार बदल रहा है। यानी सम्पत्ति के विभाजन में असमानता है। एक ओर बहुत ज्यादा धन है और उसके मालिकों को यह भी मालूम नहीं कि इस सब का क्या उपयोग करें। वे उसे केवल बचा लेते हैं और बैंकों में जमा कराते रहते हैं। यह रुपया बाजार में चीजें खरीदने के काम नहीं आता। दूसरी तरफ़ धन की बहुत कमी है और जिन चीजों की जरूरत है वे भी रुपये के अभाव में नहीं खरीदी जा सकतीं।

धुमा-फिराकर इस सब कथन का यह अर्थ हुआ कि दुनिया में गरीब और अमीर हैं। यह बात इतनी साफ़ तौर पर जाहिर है कि इसके लिए किसी तर्क की जरूरत नहीं है। इतिहास के शुरू से ही ये गरीब और अमीर बराबर चले आये हैं। फिर मौजूदा संकट के लिए उन्हें क्यों जिम्मेवार ठहराया जाय ? मेरे खयाल से किसी पिछले खत में मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि पूँजीवादी प्रणाली की सारी वृत्ति ही सम्पत्ति के विभाजन की असमानताओं को बढ़ाने की है।

सामन्तशाही में स्थिति प्रायः स्थिर रहती थी या धीरे-धीरे बदलती थी। पूँजीवाद में बड़े-बड़े यंत्र और संसारव्यापी बाजारों के कारण वेग है और उसमें परिवर्तन तेज़ी से होता है, क्योंकि दौलत व्यक्तियों और दलों के पास इकट्ठी होजाती है। सम्पत्ति के विभाजन में असमानता के बढ़ने और उसमें कुछ और कारणों के मिलने से उद्योग-प्रधान देशों में मजदूरों और पूँजीपतियों में नया संघर्ष पैदा हुआ। इन देशों के पूँजीपतियों ने मजदूरों को कई तरह की रियायतें देकर इस खिंचाव को कम किया। मगर अपने यहाँ ज्यादा मजदूरी देकर और जीवन-सम्बन्धी अवस्थाओं में सुधार करके इन लोगों ने गुलाम देशों और पिछड़े हुए प्रदेशों का ख़ूब शोषण किया। इस तरह एशिया, अफ़्रीका, दक्षिणी अमेरिका और पूर्वी योरप के शोषण से पश्चिमी योरप और उत्तरी अमेरिका के उद्योग-प्रधान देशों को दौलत जमा करने में मदद मिली। इसका थोड़ा-सा हिस्सा उन्होंने अपने यहाँके मजदूरों को भी दे दिया। जैसे-जैसे नये बाजार पैदा हुए वैसे-वैसे नये उद्योग चल पड़े या पुराने बढ़ गये। साम्राज्यवाद ने आगे बढ़-बढ़ कर इन बाजारों और कच्चे माल की तलाश करने का रूप धारण कर लिया। इसमें अलग-अलग औद्योगिक राष्ट्रों की प्रतिस्पर्धा हुई और उनके स्वार्थ टकराये। जब सारी

नहीं रखना चाहता। उन्होंने नये-नये कारखानों और यंत्रों में और दूसरे बड़े-बड़े खर्च के उद्योगों में यह रुपया जरूरत से ज्यादा लगा दिया। आमतौर पर लोगों की जैसी दिवालिया हालत होरही थी उसे देखते हुए उनका इस तरह पूंजी लगाना मुनासिब नहीं था। पर वे शेयरबजार में सट्टा भी करने लगे। उन्होंने अधिकांश बड़े और व्यापक पैमाने पर माल बनाने की तैयारी करली। मगर इससे फायदा क्या, जब सर्वसाधारण के पास खरीदने को रुपया ही न हो? इस तरह उत्पत्ति अधिक होगई, माल विक्रय न सका, उद्योगों में घाटा रहने लगा और बहुत-से बन्द होने लगे। व्यवसायियों ने नुकसान से घबराकर उद्योगों में पूंजी लगाना बन्द कर दिया और रुपया बैंकों में पड़ा रक्खा। इस तरह बेकारी फैल गई और मन्दी संसारव्यापी होगई। मैंने उथल-पुथल के बताये हुए भिन्न-भिन्न कारणों की अलग-अलग चर्चा की है, परन्तु वे सब साथ-साथ चलते रहे और इसीसे व्यापार की यह मन्दी इतनी भयंकर होगई जितनी कि पहले कभी नहीं थी। तत्त्वतः इसका कारण पूंजीवाद से प्राप्त हुई कालतू आमदनी का असमान विभाजन था। इसीको दूसरी तरह से यों कहा जा सकता है कि शरीवों ने जिस माल को अपनी मेहनत से तैयार किया था उसीको खरीदने के लिए उन्हें मजदूरी और वेतन के रूप में काफ़ी रुपया नहीं मिला। उनकी सारी आमदनी से इस माल की कीमत ज्यादा थी। अगर यह रुपया शरीवों के पास होता तो इस माल के खरीदने में काम आता। मगर यह रुपया तो उन थोड़े-से धनवान लोगों के पास जमा होगया जिन्हें यह भी पता न था कि इसका क्या करें। यही कालतू रुपया ऋण की धारा में बह-बहकर अमेरिका से जर्मनी, मध्य-योरप और दक्षिणी अमेरिका पहुँचा। इसी विदेशी ऋण ने युद्ध-जर्जर योरप और पूंजीवादी व्यवस्था को कुछ वर्ष तक कायम रक्खा। फिर भी संकट का एक कारण तो यह ऋण भी बनाही और इसी-के बन्द होने पर सारा ढाँचा अर्थात् गिर पड़ा।

अगर पूंजीवाद के संकट का यह निदान सही है, तो इलाज भी वही ठीक होसकता है जिससे सबकी आय समान हो या कम-से-कम समान होने की सम्भावना हो। यह काम पूरी तरह तो समाजवाद को अपनाते से ही हो सकता है लेकिन जबतक परिस्थिति मजदूर न करे तब तक पूंजीपति ऐसा होने देने वाले नहीं हैं। लोग संयोजित पूंजीवाद की, पिछड़े हुए प्रदेशों का शोषण करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय-संघों की बात करते हैं; परन्तु इन बातों के पीछे राष्ट्रीय लाग-डॉट और संसार के बाजारों के लिए साम्राज्यवादी राष्ट्रों का आपसी संघर्ष भयंकर होता जा रहा है। ऐसी हालत में योजना बंसी? दूसरे को नुकसान पहुँचाकर अपना फायदा करने की? पूंजीवाद का उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ होता है और स्पर्धा उसके स्वभाव में है। स्पर्धा और योजना का क्या माय?

चुकाने के लिए हारे हुए देशों को मजबूरन राजी होना पड़ा, दूसरे मित्र-राष्ट्रों पर एक-दूसरे का और खास तौर पर अमेरिका का कर्ज था, और तीसरे प्रत्येक देश ने अपने-अपने नागरिकों से रुपया उधार लिया था।

इन तीनों अलग-अलग तरह के कर्जों में से हरेक बहुत भारी था। लेकिन इन सब में प्रत्येक देश का राष्ट्रीय ऋण सबसे बड़ा था। इस तरह लड़ाई के बाद ब्रिटिश राष्ट्रीय ऋण ६ अरब ५० करोड़ पौण्ड तक पहुँच गया था। ऐसे ऋजों का व्याज चुकाना भी बहुत बड़ा भार हो गया था और उसका अर्थ हुआ बहुत भारी कर लगाना। जर्मनी ने अपना भारी भीतरी ऋज नोट छाप-छापकर उतार दिया। इससे वहाँका पुराना सिक्का मार्क खत्म हुआ और इस तरह से उसने अपना बोझ हलका कर दिया, हालाँकि जिन लोगों ने उसे उधार दिया था वे घाटे में रहे। फ्रांस ने भी नोट छाप-छापकर निकालने का वही तरीका इस्तिहार किया, मगर उस हद तक नहीं किया। उसने अपने सिक्के फ्रांक की कीमत घटाकर पाँचवें हिस्से के लगभग कर दी और इस तरह एक ही बार में अपने भीतरी राष्ट्रीय ऋण का ५ हिस्सा उड़ा दिया। यह चाल दूसरे देशों के ऋज यानी युद्ध के हर्जाने और विदेशी ऋज के बारे में नहीं चली जा सकती थी। उन्हें तो ठोस सोना ही देना पड़ा।

एक देश का दूसरे देश को इस तरह कर्ज अदा करने का अर्थ यह हुआ कि चुकानेवाले देश को उतने रुपये की हानि हो और वह और भी गरीब हो जाय। लेकिन भीतरी कर्ज अदा कर देने से देश की स्थिति में ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि रुपया किसी भी तरह देश का देश में रहता है। फिर भी एक दूसरी तरह का अन्तर तो पड़ा ही, और वह बहुत बड़ा अन्तर था। इस तरह के कर्ज देश के अमीर और गरीब सभी लोगों पर कर लगाकर जमा किये हुए रुपये से चुकाये जाते हैं। सरकार को उधार देनेवाले लोग धनवान् थे। नतीजा यह हुआ कि धनवानों का कर्ज चुकाने के लिए धनी और निर्धन दोनों पर कर लगाया गया। इससे धनवानों ने सरकार को कर के रूप में जो कुछ दिया था उससे कहीं ज्यादा उन्हें वापस मिल गया; पर गरीबों ने तो दिया ही दिया, उन्हें बदले में मिला कुछ नहीं। फलतः मालदार ज्यादा मालदार होगये और गरीब और भी गरीब होते गये।

योरप के कर्जदार देशों ने अमेरिका के कर्ज का जो कुछ हिस्सा चुकाया वह सब रुपया भी वहाँके बड़े-बड़े साहूकारों और धन-कुबेरों की जेब में गया। इस तरह युद्ध-ऋण का नतीजा यह हुआ कि बुरी परिस्थिति और भी बुरी होगई और गरीबों को नुकसान पहुँचाकर अमीर लोग धन से और भी लद गये। धनवानों ने इस रुपये को किसी काम में लगाना चाहा, क्योंकि कोई व्यवसायी अपने रुपये को बेकार पड़ा

जब संकट और मन्दी संसारव्यापी हैं, तो यही कल्पना होती है कि उनका उपाय भी अन्तर्राष्ट्रीय होना चाहिए। सहयोग का कोई-न-कोई रास्ता निकालने की कोशिशें मुत्तलिफ़ देशों ने की हैं, मगर वे सब नाकामयाब रहे। इसलिए प्रत्येक देश जगत्-व्यापी इलाज से निराश होकर आर्थिक राष्ट्रवाद के रूप में राष्ट्रीय उपाय ढूँढ रहा है। दलील यह दी जाती है कि जब अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार कम हो रहा है तो हम कम-से-कम अपने देश का व्यापार तो अपने हाथ में रखें और विदेशी माल अपने यहाँ न आने दें। बाहर के व्यापार का कोई भरोसा नहीं और वह बदलता भी रहता है, इसलिए हर मुल्क अपने घरू बाज़ार पर ही ज्यादा-से-ज्यादा ध्यान देने की कोशिश कर रहा है। चुंगी-कर लगाकर या बढ़ाकर विदेशी माल को रोका जाता है और इसमें सफलता भी मिली है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को हानि पहुँचाने में भी सफलता मिली है, क्योंकि हर मुल्क की चुंगी से दुनिया के व्यापार में रुकावट होती है। योरप, अमेरिका और कुछ हद तक एशिया-भर में चुंगी की ऊँची-ऊँची दीवारें खड़ी हैं। चुंगी का दूसरा नतीजा यह हुआ कि ज़िन्दगी का मामूली खर्च बढ़ गया, क्योंकि खाद्य पदार्थों का और उन सब चीज़ों का, जिनकी चुंगी से रक्षा होती है, भाव चढ़ गया। चुंगी से राष्ट्रीय एकाधिकार पैदा होता है और बाहर की लाग-डॉट मिट जाती है या मुश्किल हो जाती है। एकाधिकार में भाव तो बढ़ते ही हैं। जिस विशेष उद्योग को चुंगी का संरक्षण मिल जाता है उसे उस संरक्षण से लाभ होता है, या यों कहो कि उसके मालिकों को तो फ़ायदा होता है, मगर माल को ख़रीदनेवाले लोग ज्यादातर घाटे में रहते हैं, क्योंकि उन्हें ज्यादा क़ीमत चुकानी पड़ती है। इस तरह चुंगी से विशेष वर्गों को थोड़ा आराम मिल जाता है और स्थायी स्वार्थ पैदा हो जाते हैं, क्योंकि चुंगी से फ़ायदा उठानेवाले उद्योग उन स्वार्थों को क़ायम रखना चाहते हैं। इस तरह हिन्दुस्तान में कपड़े के उद्योग को जापान के खिलाफ़ बहुत भारी संरक्षण मिला हुआ है। इससे भारतीय मिल-मालिकों को बहुत लाभ है और वे ऊँचे भाव लगा सकते हैं। संरक्षण के बिना वे जापान की बराबरी नहीं कर सकते। यहाँ का शक्कर का उद्योग भी संरक्षित है। इस कारण हिन्दुस्तान-भर में, और विशेषकर संयुक्तप्रान्त और बिहार में, शक्कर के कारख़ाने घड़ाघड़ खुले हैं और खुलते जा रहे हैं। इस तरह स्थायी स्वार्थ पैदा हो गये हैं और अगर शक्कर की चुंगी उठा दी जाय तो इन स्वार्थों को धक्का पहुँचेगा और शक्कर के नये कारख़ाने शायद बन्द हो जायेंगे।

दो तरह के एकाधिकारों की वृद्धि हुई। एक तो बाहरी एकाधिकार यानी चुंगी की सहायता पानेवाले राष्ट्रों के बीच में; और दूसरे भीतरी एकाधिकार, जिसमें बड़े व्यवसाय छोटे को हट्ट कर लेते हैं।

समाजवादियों और साम्यवादियों की बात छोड़ दें तो भी कितने ही विचारशील लोग वर्तमान स्थिति में पूंजीवाद की उपयोगिता में सन्देह करने लगे हैं। कुछ लोगों ने सिर्फ मीजूदा लाभ के तरीके को बल्कि रुपया देकर माल खरीदने की मूल्य-प्रथा को भी मिटा देने के लिए अचम्भे में डालनेवाले उपाय सुझाये हैं। अमेरिका के अर्थशास्त्री इंजीनियरों के एक दल ने अपना नाम 'टेकनो-क्रेडिट्स' रक्खा है। उनका प्रस्ताव है कि रुपये के बजाय शक्ति की इकाई ही काम में लानी चाहिये। इस इकाई को अर्ग (Erg) कहते हैं। दूसरी सूचना यह है कि यह इकाई अर्न (Ern) होना चाहिए। इसका अर्थ है शक्ति की इकाई के साथ नत्रजन (Nitrogen) को मिला देना। मैं यह नहीं समझा-ऊंगा कि इनका उपयोग किस तरह से किया जाये। मैं तो इनका उल्लेख सिर्फ़ तुम्हें यह समझाने के लिए कर रहा हूँ कि किस तरह लोगों का दिमाग पुरानी बातें छोड़ता जा रहा है। डगलस साहय की सामाजिक साख का सिद्धान्त एक और ही तज-वीज पेश करता है। उसके अनुसार मजदूरी और वेतन प्राचीन काल के अवशेष-मात्र हैं, इसलिए उन्हें बिलकुल ही उठा देना चाहिए। इस मजदूरी और वेतन का चुकाना लोगों में खरीदने की ताकत बांटना है। आजकल इससे अच्छी तरह काम नहीं चलता, क्योंकि खरीदने की अधिकांश शक्ति मुट्ठी-भर लोगों के हाथ में चली जाती है। इसलिए, मेजर डगलस सूचित करते हैं कि देश की असली दौलत में साल भर में जो खालिस वृद्धि हो उसकी समूची कीमत सारे नागरिकों को राष्ट्रीय मुनाफ़े की शक्ल में बांट दी जाया करे। इस तरह सभी नागरिक खर्च की सभी चीज़ें खरीद सकते हैं—यानी वह माल जो खप सकता है, न कि रेलवे और कारखानों जैसा बड़ा माल। इस तरह वर्षभर में समूचे राष्ट्र द्वारा पैदा की हुई चीज़ें सबको मिल जायेंगी। इस प्रथा में अति उत्पत्ति तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि खर्च करने की और पैदा करने की शक्ति में समता रहता है। इस प्रणाली का आधार उधार की प्रथा को बढ़ाकर सब नागरिकों में फैला देना है।

ये सब प्रस्ताव अभी तो हवा-ही-हवा में हैं। ये हैं भी इतने क्रान्तिकारी कि पूंजीवादी लोग इन्हें नहीं अपना सकते। जिनेवा के अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर कार्यालय ने हाल में बेकारी तुरन्त कम करने के लिए यह सीधी-सी सूचना पेश की कि मजदूरों के काम के घण्टे सप्ताह में चालीस कर दिये जायें। इसका फल यह होता कि लाखों और मजदूरों को काम मिल जाता और उस हदतक बेकारी घट जाती। मजदूरों के सभी प्रतिनिधियों ने इस सूचना का स्वागत किया; परन्तु ब्रिटिश सरकार इसके खिलाफ़ थी, और जर्मनी और जापान की मदद से उसने किसी तरह इसे दाखिल दफ़्तर करवा दिया। लड़ाई के बाद के इस सारे समय में अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर कार्यालय से ब्रिटेन की कारगुजारी बराबर प्रतिगामी रही है।

ज्यादा हो गया। इन घाटों की पूर्ति या तो रुपया उधार लेने से ही हो सकी या दूसरी अमानती रकमों में से रुपया निकालकर हो पाई। इससे सम्बन्धित देशों की आर्थिक स्थिति कमजोर होगई।

साथ-ही-साथ माल के बड़े-बड़े ढेर बे-बिके रह गये, क्योंकि लोगों के पास खरी-दने को काफ़ी रुपया नहीं था और कई जगहों पर ये 'फ़ालतू' खाद्य-पदार्थ और दूसरी चीज़ें सचमुच नष्ट करदी गईं, हालाँकि और स्थानों में लोगों को उनकी सख्त जरूरत थी। यह संकट और मन्दी सोवियट संघ के सिवाय सारी दुनिया में हुई। किन्तु इसे मिटाने के लिए भिन्न-भिन्न राष्ट्रों ने अन्तर्राष्ट्रीय रूप में आपस में सहयोग नहीं किया। हरेक देश ने अपनी ही चिन्ता, दूसरों से आगे बढ़ने की कोशिश और दूसरों की विपत्ति से ख़ूब फ़ायदा उठाने की तजवीज की। इस निजी और खुदगर्जी से भरी हुई कार्र-वाई तथा दूसरे अधूरे उपायों से स्थिति और भी गंभीर होगई। संसार के मामलों में दो मुख्य बातें या प्रवृत्तियाँ और हैं, जिनका इस व्यापारिक मन्दी से तो कोई ताल्लुक नहीं है लेकिन इसपर उनका असर बहुत पड़ता है। एक तो है सोवियट संघ के साथ पूँजीवादी संसार की प्रतिद्वन्द्विता या लागडाँट, और दूसरी इंग्लैण्ड और अमेरिका की प्रतिस्पर्धा।

पूँजीवादी संकट से सारे पूँजीवादी देश कमजोर और ग़रीब होगये और एक अर्थ में युद्ध के संयोग कम होगये हैं। हर मुल्क अपना घर सुधारने में लगा हुआ है और किसीके पास जोखम के कामों पर खर्च करने के लिए रुपया नहीं है। फिर भी उलटी बात तो देखो कि इसी संकट से लड़ाई का ख़तरा बढ़ गया है, क्योंकि इससे राष्ट्र और उनकी सरकारें निराश होरही हैं। और निराश लोग अक्सर अपनी भीतरी कठि-नाइयाँ बाहर लड़ाई लड़कर हल किया करते हैं। यह बात ख़ास तौर पर उस हालत में होती है जब सत्ता सर्वेसर्वा शासक या छोटे-से दल के हाथ में होती है। सत्ता छोड़ने के बजाय वह अपने देश को लड़ाई के गढ़े में फँक देता है और इस तरह अपनी रियाया का ध्यान घरेलू झगड़ों से हटा देता है। यों देखा जाय तो सोवियट संघ के खिलाफ़ युद्ध छिड़ने की सम्भावना सदा रहती है, क्योंकि यह आशा रखी जा सकती है कि इस युद्ध में बहुत-से पूँजीवादी देश आपस में मिल जायेंगे। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि सोवियट संघ पर पूँजीवादी संकट का पूरा असर नहीं हुआ। वह अपनी पंचवर्षीय योजनाओं को पूरा करने में लगा और किसी भी तरह लड़ाई से दबने पर तुल रहा।

महायुद्ध के बाद इंग्लैण्ड और अमेरिका की लाग-डाँट लाञ्छनी होगई। ये दोनों संसार की सबसे बड़ी ताक़तें हैं। दोनों ही संसार के मामलों में अपना-अपना प्रभुत्व रखना चाहती हैं। महायुद्ध के पहले इंग्लैण्ड का प्रभुत्व निर्दिवाद था। युद्ध

अलवत्ता एकाधिकारों की वृद्धि कोई नई चीज नहीं है। यह तो महायुद्ध के पहले भी कई साल तक होती रही है। अब उसकी गति तेज होगई है। चुंगी भी अनेक देशों में पहले से मौजूद थी। इंग्लैण्ड ही बड़े देशों में ऐसा था जिसने मुक्त व्यापार (Free Trade) पर अवतक भरोसा रक्खा और चुंगी के बिना काम चलाया था। परन्तु अब उसे भी अपनी परम्परा तोड़कर दूसरे देशों की बराबरी में आना पड़ा और चुंगी-कर लगाना पड़ा। इससे उसके कुछ उद्योगों का तात्कालिक बोझा कुछ हलका होगया। इन सब उपायों से स्थानीय और अस्थायी लाभ तो हुआ, लेकिन सारे संसार की दृष्टि से देखा जाय तो हालत असल में पहले से भी खराब होगई। न सिर्फ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और भी कम होगया, बल्कि सम्पत्ति के विभाजन की असमानता कायम रही और बढ़ गई। बराबरी के राष्ट्रों ने एक-दूसरे के खिलाफ चुंगी-कर लगा दिया। इन्हें चुंगी की दीवार कहते हैं। इनसे आपस में संघर्ष बराबर बना रहा। जैसे-जैसे संसार की मण्डियाँ कम होती गईं और उनपर संरक्षण लगता गया वैसे-वैसे उनके लिए छोना-झपटी भी तेज होती गई और मालिक लोग अपने मजदूरों की मजदूरी कम करने के लिए दबाव डालने लगे, ताकि वे दूसरे देशों से लाग-डॉट कर सकें। इस तरह मन्दी बढ़ती गई और बेकारों की तादाद में वृद्धि होती गई। मजदूरी घटाने के साथ-साथ मजदूरों की खरीदने की ताकत भी कम होगई।

: १८६ :

नेतृत्व के लिए अमेरिका और इंग्लैण्ड का झगड़ा

२५ जुलाई, १९३३

मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मौजूदा मन्दी के जमाने में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार घटते-घटते सिर्फ तीसरे हिस्से तक रह गया है। लोगों की खरीदने की शक्ति कम होजाने से अन्दरूनी या देशी व्यापार कम होगया। बेकारी बढ़ती चली गई और इन करोड़ों बेकारों का पालन-पोषण करने का बड़ा भारी बोझा मुक्तलिफ्त सरकारों के सिर पर आ पड़ा। भारी कर लगाने पर भी बहुत-सी सरकारों का आय-व्यय बराबर होना तक असम्भव-सा होगया। उनकी आमदनी घटती गई और खर्च, किरायात और वेतन की कटौती के बावजूद, बढ़ा-चढ़ा रहा। इसका कारण यह था कि इस खर्च का बड़ा भार जल, स्थल और हवाई सेना के साथ और भीतरी और बाहरी कर्ज की अदायगी के साथ बँधा हुआ था। राष्ट्रीय बजटों में घाटा रहने लगा। यानी आय से व्यय

और उसका प्रधान-पद धीरे-धीरे किन्तु लगातार संयुक्तराष्ट्र के हाथों में चला जावे। यह विचार अंग्रेजों को सुखकर नहीं हो सकता कि जिन चीजों को वे इतने महत्त्व की समझते हैं उनमें से अधिकांश को वे छोड़ दें, वे अपनी प्राचीन प्रतिष्ठा और साम्राज्यवादी शोषण का लाभ खो दें और अमेरिका के सद्भाव पर निर्भर रहकर संसार में पीछे की जगह स्वीकार करें। वे बिना लड़े दबनेवाले नहीं हैं। इंग्लैंड की वर्तमान स्थिति का यही दुःखपूर्ण चित्र है। उसके पुराने बल के सारे श्रोत सूखते जा रहे हैं और भविष्य अनिवार्य पतन की तरफ संकेत करता हुआ मालूम होता है, मगर पीढ़ियों तक जिस अंग्रेज जाति को दूसरों पर हुकूमत करने की आदत रही है, वह इस तरह की स्थिति को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं है। वह इसके खिलाफ लड़ रही है और लड़ेगी।

मैंने तुम्हें आज के संसार की दो मुख्य प्रतिद्वंद्वितायें बताई हैं, क्योंकि इनसे घटना-चक्र बहुत कुछ समझ में आ जाता है। अलबत्ता और भी बहुत-सी प्रतिस्पर्धायें हैं। सारी पूँजीवादी प्रथा का आधार ही प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वन्द्विता पर है।

हाँ, तो मन्दी के कारण घटना-चक्र किस प्रकार घूम रहा है उसीका वर्णन जारी रखें। जून १९३० में फ्रांसीसियों ने राइनलैंड खाली कर दिया। इससे जर्मन लोगों की बड़ी चिन्ता दूर हुई, लेकिन यह चीज इतनी देर में आई कि उसे सद्भाव का चिन्ह नहीं समझा गया और मन्दी के अन्धकार के कारण सभी चीजों का रंग काला दिखाई देता था। जैसे-जैसे व्यापार की हालत बिगड़ती गई वैसे-वैसे ऋणी देशों के पास रुपये की कमी होती गई और हर्जाने और कर्ज का चुकाना मुश्किल ही नहीं बल्कि असम्भव होगया। अदायगी की मुश्किल को टालने के लिए राष्ट्रपति हूवर ने एक वर्ष के लिए ऋण वसूल करना स्थगित कर दिया था। कोशिश तो यह की गई कि युद्धऋण के सारे सवाल पर ही फिर से विचार किया जाय। लेकिन संयुक्तराष्ट्र की कांग्रेस ने यह मंजूर नहीं किया। फ्रांस की सरकार भी जर्मनी से युद्ध का हर्जाना वसूल करने के सवाल पर उतनी ही सहित रही। ब्रिटिश सरकार चूँकि देनदार भी थी और लेनदार भी थी, इसलिए वह इस बात के पक्ष में थी कि हर्जाने और ऋण दोनों रद्द करके हिसाब साफ़ कर दिया जाय।

सद देश अपने-अपने हिसाब से विचार करते थे। फल यह हुआ कि मिलकर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। १९३१ के बीच में जर्मनी की आर्थिक व्यवस्था टूट गई और देशों के दिवालें निकल गये। इससे इंग्लैंड में भी संकट पैदा होगया और वह अपना देना नहीं चुका सका। देश का आर्थिक पतन होने की नौबत आ गई। इस खतरे का दहाना लेकर मजदूर सरकार को उसीके मुखिया मैकडॉनल्ड ने भंग कर दिया और

से संयुक्तराष्ट्र सबसे मालदार और ताकतवर राष्ट्र होगया और स्वभावतः उसने चाहा कि संसार में जिस पद का वह अपनेआपको हकदार समझता था वह पद यानी प्रमुख पद भविष्य में उसे मिले। आयन्दा वह हर बात में इंग्लैण्ड की ही नहीं चलने देने वाला था। इंग्लैण्ड खुद भी पूरी तरह समझ गया था कि जमाना बदल गया है और उसने अमेरिका की दोस्ती चाहकर अपनेआपको समय के अनुकूल बनाने की कोशिश भी की। उसने तो यहाँतक किया कि अमेरिका को खुश करने लिए जापान के साथ की हुई मित्रता की सन्धि तोड़दी और आगे बढ़कर अमेरिका को खुश करने की कई कार्रवाइयाँ कीं। लेकिन इंग्लैण्ड अपने विशेष स्वार्थ और स्थिति और खासकर आर्थिक नेतृत्व छोड़ने को तैयार न था क्योंकि इन चीजों के साथ उसकी महानता और उसका साम्राज्य बँधे हुए थे। मगर अमेरिका को ठीक इसी आर्थिक नेतृत्व की जरूरत थी। इसलिए दोनों देशों में संघर्ष लाजिमी होगया। दोनों देशों के साहूकर ऊपर से आपस में बड़ी मीठी और प्रेम-भरी बातें करते थे, लेकिन दरपरदा अपनी-अपनी सरकारों के बल पर जगत् के आर्थिक और औद्योगिक नेतृत्व रूपी बड़े पुरस्कार के लिए लड़ते रहते थे। इस खेल में जीत और तुरप के पत्ते अधिकतर अमेरिका के हाथ में दिखाई दिये, लेकिन दीर्घ अनुभव और ग्रीड़ा-कौशल इंग्लैण्ड की तरफ़ ज्यादा थे।

युद्ध के कर्जों के कारण दोनों राष्ट्रों में कटुता और भी बढ़ गई और इंग्लैण्ड में अमेरिका को यह कहकर गालियाँ दी जाने लगीं कि वह तो अपने सेर-भर मांस के लिए शायलाक बन रहा है। बात असल में यह थी कि ब्रिटिश सरकार पर अमेरिका का कर्ज गैरसरकारी साहूकारों का दिया हुआ था। इन लोगों ने युद्ध-काल में या तो रुपया दिया था या साख दी थी। संयुक्तराष्ट्र की सरकार ने अपनी ओर से सिर्फ़ इतमीनान दिलाया था। इसलिए संयुक्तराष्ट्र की सरकार के लिए कर्ज को उड़ा देने का सवाल नहीं था। अगर वह इंग्लैण्ड को कर्ज माफ़ कर देती तो इतमीनान दिलाने-वाले की हैसियत से खुद उसको रुपया चुकाना पड़ता। अमेरिका की कांग्रेस को ऐसा कोई कारण नहीं दिखाई दिया कि वह खासतौर पर संकट के समय इस अतिरिक्त जोखिम को अपने ऊपर ओढ़े।

इस तरह इंग्लैण्ड और अमेरिका के आर्थिक स्वार्थों की खींचातानी मुहल्लिफ़ तरीकों पर हुई। आर्थिक स्वार्थ का जोर दूसरे जोरों से बढ़कर होता है। इन दोनों जातियों में बहुत-सी बातें एक-सी हैं। फिर भी उनमें आजकल भावी युद्ध की सम्भावना की चर्चा होरही है। ऐसे युद्ध में यह कल्पना नहीं की जा सकती कि इंग्लैण्ड जीत सकेगा, क्योंकि अमेरिका का बल और उसके साधन बहुत बड़े हैं। लेकिन ऐसे युद्ध के सिवाय दूसरा चारा यही दिखाई देता है कि इंग्लैण्ड के विशेष अधिकार

सिक्का होता है। इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान का आधार सोना होता है, क्योंकि दुर्लभ धातु के रूप में इसका अपना मूल्य है। अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान में सोना या तो सिक्के के रूप में दिया जाता है या पासे के रूप में। परन्तु यदि एक देश से दूसरे देश के हरेक भुगतान में सचमुच सोने का ही उपयोग करना पड़े तो बड़ी जबरदस्त दिक्कत होजाय और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास ही न होने पाय। इसके सिवा संसार-भर के सोने की वास्तविक मात्रा से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की क्रीमत या मात्रा भी सीमित होजाय, क्योंकि जब यह सीमा आ पहुँचे और भुगतान के लिए सोना और मिले नहीं तो उस वक्त तक विदेशी व्यापार का आगे लेन-देन ही नहीं हो सकता जबतक कि कुछ सोना छुट्टा होकर वापस न आजावे।

परन्तु बात ऐसी नहीं है। १९२९ में संसारभर में सारा सोने का सिक्का ११ अरब डालर था। उसी वर्ष में, जो माल एक देश से दूसरे देश को भेजा गया उस सबकी क्रीमत ३२ अरब डालर थी। ४ अरब का विदेशी ऋण भी था और ४ अरब के ही करीब का दूसरा विदेशी भुगतान था। इसमें यात्रियों का खर्चा, जहाज का भाड़ा और प्रवासियों द्वारा घर भेजा हुआ रुपया सब शामिल था। इस तरह सब मिलाकर राष्ट्रीय भुगतानों की क्रीमत लगभग ४० अरब डालर हुई। यह सोने के सिक्कों से करीब-करीब चौगुना है।

तो फिर विदेशों का भुगतान किस तरह किया जाता है ? जाहिर है कि सब-का-सब भुगतान सोने के रूप में तो नहीं किया जा सकता। आमतौर पर भुगतान एक प्रकार के सहायक रुपये या चैक और हुण्डी आदि पुर्जों के रूप में किया जाता है। ये पुर्जे व्यापारी अपने ऋण की रसीद के रूप में विदेशों को भेजते हैं। यह काम-वाज विदेशी हुण्डियों के विनिमय का काम करनेवाले बैंकों के जरिये होता है। विनिमय के ये बैंक भिन्न-भिन्न देशों के लेवा-बेची करनेवाले लोगों के सम्पर्क में रहते हैं और उनके पास जो हुण्डियाँ आती हैं उनके द्वारा लेन-देन का जमा-खर्च करते रहते हैं। यदि किसी समय बैंक के पास हुण्डियों का अभाव होजाय तो वह उसकी पूर्ति सरकारी बॉण्ड या कर्ज या अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों के हिस्सों आदि के रूप में प्रसिद्ध सरकारी कागज से कर लेते हैं। ये हिस्से तार द्वारा बेचे या दूसरों को दिलाये जा सकते हैं और इस प्रकार दूसरे देशों में भुगतान तुरन्त किया जा सकता है।

इस तरह अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भुगतान केन्द्रीय विनिमय बैंकों के द्वारा व्यापारी या सरकारी कागज के रूप में यानी हुण्डियों और सिक्कोरिट्टी आदि के रूप में होता है। इन बैंकों को रोजमर्रा की व्यापारिक आवश्यकताओं के लिए इन दोनों तरह के कागजों का यानी हुण्डियों और सिक्कोरिट्टियों का ढेर हमेशा अपने पास रखना

थोड़े और विस्तार से समझाने का प्रयत्न करें। हमें रस आवे या न आवे, इन आर्थिक घटनाओं का राष्ट्रीय और व्यक्तिगत दोनों ही दृष्टियों से हमपर खूब परिणाम होता है। और इसलिए जिन बातों से हमारा वर्तमान और भविष्य बनता-बिगड़ता है उन्हें समझ लेना ही अच्छा है। बहुत-से लोगों पर पूँजीवादी संसार की आर्थिक व्यवस्था की रहस्यमयी कार्य-प्रणाली की ऐसी छाप पड़ती है कि वे इसे बड़े भय और आदर्श की दृष्टि से देखने लगते हैं। उन्हें यह इतनी पेचीदा, नाजुक और जटिल मालूम होती है कि वे इसे समझने की भी कोशिश नहीं करते और इसलिए इसे वे विशेषज्ञों, साहूकारों और ऐसे ही लोगों के लिए छोड़ देते हैं। यह पेचीदा और जटिल तो वेशक है और यह आवश्यक नहीं कि जो चीज जटिल है वह अच्छी भी हो ही, परन्तु फिर भी हमें वर्तमान संसार को समझना हो तो इस आर्थिक प्रणाली का भी कुछ ज्ञान होना चाहिए। मैं तुम्हें सारी प्रणाली समझाने की कोशिश नहीं करूँगा। यह मेरे बूते की बात भी नहीं है। क्योंकि मैं इसका कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ, मैं तो इसका एक विद्यार्थी मात्र हूँ। और इसलिए तुम्हें थोड़ी-सी बातें बता भर दूँगा। मुझे आशा है कि इनकी मदद से तुम संसार की कुछ घटनाओं और अलखवारों की खबरें समझ सकोगे। इस कार्य में मुझे फ्रांसिस डिलायजी नामक फ्रांस के एक योग्य अर्थशास्त्री के अत्यन्त स्पष्ट वर्णन पर आधार रखना पड़ेगा। फ्रेंच लोग बड़े साफ़ दिमाग और जाग्रत बुद्धि के होते हैं। अंग्रेजों में यह बात नहीं है; उन्हें तो अपने 'दिमागी घपलेपन' और तर्कहीनता पर ही नाज है। मुझे शायद जो कुछ मैं कह चुका हूँ उसीका बहुत-कुछ हिस्सा दोहराना पड़ेगा। परन्तु तुम्हें समझने में मदद मिले तो उसकी परवा न करना। याद रखना इसका नाम पूँजीवादी प्रणाली है। इसमें हिस्सेदारी की व्यक्तिगत कम्पनियाँ होती हैं, गैरसरकारी बैंक होते हैं और शेयर बाजार होते हैं, जहाँ शेयर यानी हिस्से खरीदे और बेचे जाते हैं। सोवियट संघ में आर्थिक और औद्योगिक प्रणाली विलकुल दूसरी तरह की है। वहाँ ऐसी कम्पनियाँ, खानगी बैंक या शेयर बाजार नहीं होते। वहाँ क़रीब-क़रीब सब चीजों की मालिक सरकार है और उसीका उनपर नियन्त्रण है और विदेशी व्यापार असल में तवादले के ढंग पर है।

तुम जानती हो कि प्रत्येक देश का भीतरी व्यवसाय क़रीब-क़रीब सारा चंकों के जरिये और उससे कम बैंक-नोटों के द्वारा होता है। सोना और चांदी तो छोटी-मोटी ख़रीदारी के सिवाय क्वचित् ही काम में लाये जाते हैं (सोना तो असल में मिलता ही कम है)। यह कागज़ी रुपया साख की निशानी होता है और जबतक लोगों का नोट जारी करनेवाले बैंकों या देश की सरकार में विश्वास होता है तबतक इससे नक़द रुपये का काम निकलता रहता है। लेकिन इस कागज़ी रुपये से एक देश से दूसरे देश को रुपया चुकाने का काम नहीं निकलता। क्योंकि हरेक देश का अपना-अपना राष्ट्रीय

सकता है जब हुण्डियों का कोई ऐसा केन्द्रीय बाजार हो जहाँ अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय होता हो। ऐसा बाजार उसी देश में हो सकता है जहाँ नीचे लिखी तीन सुविधायें हों—

१. उसका विदेशी व्यापार इतना फैला हुआ और मुक्तलिफ़्ट क्रिस्म का होना चाहिए कि उसके पास सब तरह की हुण्डियों की बहुतायत रहे।

२. वहाँ हर तरह के सरकारी कागज़ मिल सकें, यानी वह पूँजी का सबसे बड़ा बाजार हो।

३. उसका सोने की भी सबसे बड़ी मण्डी होना आवश्यक है, ताकि हुण्डी और सरकारी कागज़ दोनों के न मिलने की हालत में सोना आसानी से मिल सके।

सारी १९ वीं सदी में इंग्लैंड ही ऐसा देश था जहाँ ये तीनों शर्तें पूरी होती थीं। चूँकि वह उद्योग के क्षेत्र में सबसे पहले उतरा था और एक विशाल साम्राज्य पर उसका एकाधिकार था, इसलिए संसार में उसका विदेशी व्यापार सबसे अधिक हो गया था। उसने अपने बढ़ते हुए उद्योग पर अपनी खेती का बलिदान कर दिया। उसके जहाज़ हर बन्दरगाह से व्यापार का माल और हुण्डियाँ ले जाते थे। इस महान् औद्योगिक विकास के कारण वह स्वभावतः पूँजी का सबसे बड़ा बाजार बन गया और उसके पास सब तरह के विदेशी सरकारी पुर्जों का ढेर लग गया। दूसरा सहायक कारण उसके लिए यह हुआ कि ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर—यानी दक्षिण अफ़्रीका, आस्ट्रेलिया, कनाडा और हिन्दुस्तान में—दुनिया का दो-तिहाई सोना निकलता था। इन सोने की खानों का माल लन्दन में फ़ौरन विक्रित जाता था। बैंक ऑफ़ इंग्लैंड इनका निकाला हुआ सारा सोना एक बँधे हुए भाव पर ख़रीद लेता था।

इस तरह लन्दन हुण्डियों, सरकारी कागज़ों और सोने की प्रधान मण्डी बन गया। वह संसार की आर्थिक राजधानी होगया। जिस किसी सरकार या साहूकार को विदेश से हिसाब करने की ज़रूरत हुई और अपने देश में इसका साधन न मिला, तो वह लन्दन चला जाता और वहाँ उसे हर तरह का व्यापारिक और आर्थिक कागज़ तथा सोना मिल जाता। पाउण्ड के नोट व्यापार के ठोस चिन्ह बन गये। अगर डेनमार्क या स्वीडन को दक्षिण अमेरिका से कुछ ख़रीद करने की ज़रूरत हुई तो सीदा पाउण्ड के नोटों में ही जाता था, भले ही माल कभी लन्दन न आये।

इंग्लैंड को इस धन्य से बड़ा भारी मुनाफ़ा था, क्योंकि सारी दुनिया का काम उससे निकलता था और उसके बदले में दुनिया उसे कुछ-न-कुछ कर देती थी। इससे प्रत्यक्ष लाभ तो था ही। साथ ही विदेशी व्यापारी भावी भुगतान के लिए अंग्रेज़ी बैंकों में ख़य्या जमा रखते थे। इस अमानत को ये बैंक दूसरे लोगों को थोड़े-थोड़े समय के लिए उधार देकर फ़ायदा उठाते थे। अंग्रेज़ी बैंकों को विदेशी कारख़ानेदारों के धन्य

पड़ता है। वे प्रति सप्ताह सूचियाँ प्रकाशित करके बताते रहते हैं कि उनके पास कितना सोना और कितना विदेशी पुर्जा है। साधारणतः विदेशी भुगतान के लिए सोना कभी बाहर नहीं भेजा जाता। परन्तु जब कभी ऐसा होता है कि और किसी तरह से भुगतान करने की अपेक्षा सचमुच सोना भेजना सस्ता पड़ता है तब साहूकार लोग सुवर्ण-धातु भेजते हैं।

सोने के विनिमय वाले देशों में राष्ट्रीय सिक्के का मूल्य सोने की शक्ल में मुक्रूर होता है और वहाँ उसके बदले में कोई भी सोना माँग सकता है। इसलिए ये सिक्के प्रायः स्थिर रहते हैं और उनका आपस में विनिमय होसकता है, क्योंकि उनके बदले में सोना मिल सकता है। उनकी कीमत में कमी-बढ़ती होसकती है तो वह एक देश से दूसरे देश में सुवर्ण-धातु भेजने के खर्च की वजह से ही होसकती है, क्योंकि अपने देश में कीमत ज्यादा हुई तो व्यवसायी दूसरे देश से आसानी से सोना मँगवा सकता है। सोने के विनिमय की प्रणाली यही है। इस प्रणाली में अलग-अलग राष्ट्रों के सिक्के स्थिर होते हैं और १९ वीं सदी से ठेठ महायुद्ध के समय तक इस प्रणाली के कारण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ता गया। आज यह प्रणाली टूट गई है और इसीलिए रुपये का व्यवहार बड़ा विचित्र होगया है और अधिकांश राष्ट्रों का सिक्का अस्थिर बन गया है।

मोटे हिसाब से हर देश का आयात और निर्यात का व्यापार बराबर-सा होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो, एक देश जो माल मँगाता है उसकी कीमत वह उस माल के रूप में चुकाता है जो वह बाहर भेजता है। परन्तु यह बात बिल्कुल सही नहीं है और अक्सर एक-न-एक तरफ़ थोड़ा-बहुत रुपया बाक़ी निकलता है। जब जावक से आवक का मूल्य अधिक होता है तो वह देना-बाक़ी (Advance Balance) कहलाता है और उस देश को हिसाब पूरा करने के लिए कुछ भुगतान और ऊपर से करना पड़ता है। भिन्न-भिन्न देशों के बीच में माल का आवागमन नियमित रूप से हर्गिज नहीं होता, वह बहुत बार बदलता रहता है। उसमें उतार-चढ़ाव आते हैं और प्रत्येक परिवर्तन के साथ हुण्डियों की माँग और उनका भुगतान बदलता रहता है। अक्सर ऐसा भी होता है कि किसी देश के पास ऐसी हुण्डियाँ तो बहुत होती हैं जिनकी उसे उस समय ज़रूरत नहीं होती और ऐसी हुण्डियाँ उसके पास काफ़ी नहीं होतीं जिनकी उसे आवश्यकता हो। मसलन फ़्रांस के पास जर्मनी पर जर्मनी के सिक्के मार्क में की हुई हुण्डियाँ तो काफ़ी से ज्यादा हों, परन्तु ऐसी हुण्डियाँ काफ़ी न हों जिनसे वह अमेरिका के साथ डालर के रूप में हिसाब तय कर सके, तो ऐसी हालत में फ़्रांस जर्मनी की हुण्डियों को बेचकर उनके बदले में संयुक्तराष्ट्र पर डालर की हुण्डियाँ ख़रीदना चाहेगा। ऐसा वह तभी कर

उस देश का जितना हाल उसे मालूम होता उतना वहाँकी सरकार को भी नहीं होता था। जिन सरकारी कारागृहों में किसी विदेशी सरकार का हिताहित होता उन्हें खरी-दने और बेचने के छोटे-छोटे दांव-पेचों से या थोड़ी मुद्दत के लिए खास ढंग से क्रजं देकर उस विदेशी सरकार की राजनैतिक नीति पर दबाव डाला जा सकता था। इसे ऊँचा अर्थ-प्रबन्ध (High Finance) कहते हैं। साम्राज्यवादी राष्ट्रों के हाथ में दबाव डालने के जो साधन पहले भी थे और अब भी हैं उनमें यह साधन निहायत कारगर है।

महायुद्ध के पहले यह परिस्थिति थी। लन्दन नगर ब्रिटिश साम्राज्य के बल और वैभव का केन्द्र और चिन्ह था। महायुद्ध के कारण अनेक परिवर्तन हुए और पुरानी व्यवस्था उलट गई। लन्दन यानी इंग्लैण्ड को विजय तो प्राप्त हुई, मगर उसकी क्रीमत बहुत महँगी चुकानी पड़ी।

लड़ाई के बाद बया हुआ, यह अगले खत में बताऊंगा।

: १८७ :

डालर, पाउण्ड और रुपया

२७ जुलाई, १९३३

महायुद्ध ने दुनिया के तीन टुकड़े कर दिये। दो टुकड़े तो दोनों तरफ लड़नेवाले राष्ट्रों के हुए और तीसरे में तटस्थ देश रहे। लड़नेवाले प्रदेशों में परस्पर कोई व्यापार या सम्पर्क बाक़ी न रहा। हाँ, एक-दूसरे की जासूसी करने का खुफ़िया काम चलता ही रहा। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पूरी तरह चौपट होगया। समुद्र पर क़ब्ज़ा होने के कारण इंग्लैण्ड, फ़्रांस और दूसरे मित्र-राष्ट्र तटस्थ और पराधीन देशों के साथ थोड़ा व्यापार जारी रख सके; लेकिन जर्मन पनडुब्बियों के मारे वह भी महदूद होगया था। लड़नेवाले राष्ट्रों के सारे साधन लड़ाई में लग गये और बेग़ुमार रुपया ख़र्च हुआ। फ़रवरी १९ वर्ष तक इंग्लैण्ड और फ़्रांस अपने शरीर साधियों को रुपया देते रहे और खुद अपने ही प्रजाजनों और अमेरिका से उधार लेते रहे। इसके बाद फ़्रांस तो थक गया और दूसरों को मदद न दे सका। इंग्लैण्ड १९ साल तक और बोझा उठाता रहा। मार्च १९१७ में उसकी भी थककर बैठ रहने की दारी आगई। उस वक़्त वह संयुक्त-राष्ट्र को ५ करोड़ पाउण्ड की चढ़ी हुई क़िस्त नहीं चुका सका। इस नाज़ुक अवसर पर जब और किसी के पास भी अधिक साधन शेष नहीं रहे, इंग्लैण्ड, फ़्रांस और उनके मित्रों के सौभाग्य से, अमेरिका उनकी तरफ़ लड़ाई में शामिल होगया। उस वक़्त से

का सब हाल भी मालूम होजाता था। उनके हाथों में होकर जो हुण्डियाँ गुजरती थीं उनसे जर्मन या दूसरे विदेशी व्यापारियों द्वारा लगाये हुए भावों का और विदेशों में उनके ग्राहकों के नामों तक का अंग्रेजी बैंकों को पता चल जाता था। ब्रिटिश उद्योग के लिए यह जानकारी बहुत उपयोगी थी, क्योंकि इससे उसे अपने विदेशी प्रतिद्वन्द्वियों को मात देने में सामर्थ्य मिलता था।

इस अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय को बढ़ाने और मजबूत करने के लिए अंग्रेजी बैंकों ने दुनियाभर में शाखाएँ और आढ़तें खोल दीं। विदेशों को ब्रिटिश उद्योग के प्रभाव में लाने के काम में तो ये बैंक मदद देते ही थे। ब्रिटिश दृष्टिकोण से ये एक और भी बड़ी उपयोगी सेवा करते थे। ये पूछताछ करते रहते थे और सभी बड़ी-बड़ी स्थानीय दूकानों और व्यवसायों के बारे में लिखित सामग्री रखते थे। इससे जब कभी कोई स्थानीय दूकान हुण्डी करती थी तो वहाँका ब्रिटिश बैंक या आढ़तिया उस हुण्डी का मूल्य जानता था और अगर वह उसमें कोई जोखम नहीं समझता तो उसपर अपनी साख दे सकता था। इसे 'सिकारना' कहते हैं, क्योंकि बैंक उस हुण्डी पर 'स्वीकार किया' यह शब्द लिख देता है। ज्योंही बैंक ने इसके सिकारने की गारण्टी दी कि हुण्डी आसानी से बेची या दूसरे के नाम की जा सकती थी, क्योंकि उसकी पीठ पर बैंक की साख होती थी। ऐसी गारण्टी के बिना एक अनजान विदेशी दूकान की हुण्डी को लन्दन जैसे या और कहीं के दूर के बाज़ार में खरीदनेवाला नहीं मिल सकता, क्योंकि उस दूकान को कोई जानता न था। बैंक हुण्डी को सिकार कर जोखम तो उठाता था; परन्तु वह ऐसा करता था अपनी स्थानीय शाखा द्वारा पूरी जाँच करवाने के बाद ही। इस तरह सिकारने की इस प्रथा ने हुण्डियों के लेन-देन और साधारणतः सारे व्यवसाय के लिए ही सुविधा करदी, और साथ ही दुनिया के व्यापार पर लन्दन नगर का पंजा भी मजबूत बना दिया। दूसरे किसी देश की ऐसी स्थिति नहीं थी कि वह किसी बड़े पैमाने पर यह सिकारने का काम कर सके, क्योंकि विदेशों में उसकी शाखाएँ थोड़ी थीं।

इस तरह १०० से भी अधिक वर्ष तक लन्दन संसार की आर्थिक राजधानी रहा और अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था और व्यापार की वागडोर उसके हाथों में रही। रुपया तो वहाँ बहुत था ही और इस कारण सस्ती शर्तों पर मिल भी सकता था। इससे सारे साहूकार उधर आकर्षित होते थे। बैंक ऑफ इंग्लैण्ड के गवर्नर के पास दुनिया के चारों कोनों से व्यापार और अर्थ-प्रबन्ध की रत्ती-रत्ती ख़बरें आती थीं और वह अपने बहीखातों और कासज़ों पर एक नज़र डालकर बता सकता था कि किस देश की आर्थिक व्यवस्था कैसी है। असल में कभी-कभी तो ऐसा होता था कि

कोई साधन नहीं था, और हुण्डियों का ब्रिटिश बैंकों के जरिये लन्दन पहुँच जाना स्वाभाविक था। इस कठिनाई का सामना करने के लिए अमेरिकन बैंकों ने झटपट विदेशों में शाखाएँ और आदतें खोलना शुरू कर दिया, और कई मुकामों पर बढ़िया इमारतें खड़ी होगईं। लेकिन एक कठिनाई और थी। 'सिकारने' का काम ऐसे सधे हुए आदमी ही कर सकते थे, जिन्हें मुकामी हालात और स्थानीय व्यवसाय के बारे में पूरी जानकारी हो। ब्रिटिश बैंकों ने सौ वर्ष तक प्रगति करके ऐसे आदमी तैयार कर लिये थे। इस बारे में जल्दी उनकी बराबरी करना आसान नहीं था।

तब अमेरिका वाले लन्दन के विरोध में कुछ फ्लेंच, स्विच और डच बैंकों से मिल गये। मगर इसमें बहुत कामयाबी नहीं मिली। फ्रांस बड़ा धनी देश है और वह बहुत-सी पूँजी भी बाहर भेजता है, परन्तु उसने विदेशी हुण्डियों का लेन-देन संगठित करने की तरफ़ कभी ध्यान नहीं दिया था। इस तरह न्यूयार्क और लन्दन में रस्साकशी चलती रही और सारी बातों को देखते हुए लन्दन का कुछ बिगड़ा नहीं। १९२४ में न्यूयार्क के पक्ष में एक नई बात पैदा होगई। बहुत-से नोट छाप-छापकर निकालने के बाद जर्मन मार्क की क़ीमत स्थिर करदी गई और नोटों के छापने के समय जो जर्मन पूँजी स्वीजरलैण्ड और हालैण्ड में चली गई थी (जोखम या ख़तरे के समय पूँजी हमेशा इसी तरह बाहर चली जाती है) वह जर्मन बैंकों में लौट आई। अमेरिका के आर्थिक गुट में जर्मनी के शामिल होजाने से लन्दन की स्थिति बहुत बदल गई थी, क्योंकि अब लन्दन की सहायता के बिना ही अमेरिका की हुण्डियों के बदले में योरप की हुण्डियाँ मनचाही मिल सकती थीं। और लन्दन का सिक्का आज भी अस्थिर है, यानी सोने के रूप में पाउण्ड की कोई बँधी हुई क़ीमत नहीं है। वह सोने के विनिमय से अलग होगया।

अब तो लन्दन नगर के घनकुबेर घबराये। उन्होंने देखा, अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय के व्यवसाय की सारी मलाई तो न्यूयार्क और उसके यूरोपियन साथियों के हाथ में चली जा रही है और लन्दन के हिस्से में सिर्फ़ जूठन बाक़ी रह जाती है। इस हालत को रोकने के लिए पहला काम करने का यह था कि सोने के साथ पाउण्ड को फिर बाँध दिया जाय। इससे विनिमय का फिर से अच्छा व्यवसाय आने लगेगा। इसलिए १९२५ में पाउण्ड की पुराने हिसाब से क़ीमत स्थिर करदी गई। अंग्रेज़ साहूकारों की इसमें बड़ी विजय थी, क्योंकि पाउण्ड की क़ीमत बढ़ जाने का अर्थ था उनकी आमदनी का बढ़ जाना। लेकिन अंग्रेज़ी उद्योग के लिए यह बुरा हुआ, क्योंकि इससे विदेशों में अंग्रेज़ी माल का भाव बढ़ गया और कारख़ानेदारों को अमेरिका, जर्मनी और हमारे औद्योगिक देशों के साथ विदेशी बाज़ार में स्पर्धा करने में बड़ी मुश्किल होने लगी। परन्तु इंग्लैण्ड ने जान-बूझकर अपनी साहूकारी प्रथा, या यों कहो कि संसार के

लगाकर संयुक्तराष्ट्र सारे मित्र-राष्ट्रों को लड़ाई के लिए रुपया देता रहा। उसने अपने प्रजाजनों से 'स्वाधीनता' और 'विजय' ऋणों के नाम से भारी कर्ज लिया और खुद भी खूब खर्च किया और मित्र-राष्ट्रों को भी उधार दिया। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, नतीजा यह हुआ कि जब युद्ध बन्द हुआ तो संयुक्तराष्ट्र दुनियाभर का साहूकार था और सारे राष्ट्र उसके कर्जदार थे। लड़ाई के शुरू में अमेरिका की सरकार पर योरप का ५ अरब डालर का ऋण था। लड़ाई के अन्त में अमेरिका का योरप पर १० अरब डॉलर का कर्ज हो गया।

युद्ध के जमाने में अमेरिका को सिर्फ इतना ही आर्थिक लाभ नहीं हुआ। साथ ही उसका विदेशी व्यापार बढ़ गया और इंग्लैंड और जर्मनी का घट गया। अमेरिका का विदेशी व्यापार ब्रिटिश व्यापार के बराबर हो गया। संयुक्तराष्ट्र के पास संसार का दो-तिहाई सोना और बहुत-से विदेशी सरकारों के हिस्से और बॉण्ड भी इकट्ठे हो गये।

इस तरह संयुक्तराष्ट्र की माली हालत सबसे अच्छी होगई। वह अपने कर्ज के भुगतान की मांग-भर करके अपने किसी भी ऋणी देश को दिवालिया बना सकता था। इसलिए उसे इस बात पर ईर्ष्या होना स्वाभाविक था कि दुनिया की आर्थिक राजधानी होने का प्राचीन पद लन्दन के पास क्यों रहे। वह चाहता था कि यह पद उसे मिले। वह चाहता था कि न्यूयार्क संसार का सबसे धनी शहर है, इसलिए लन्दन का स्थान उसे मिले। इस तरह न्यूयार्क और लन्दन के साहूकारों और धन-कुबेरों में भयंकर संघर्ष शुरू हुआ और उनकी पीठ पर उनकी सरकारें थीं।

अमेरिका का दबाव पड़ा तो अंग्रेजी पाउण्ड हिल गया। बैंक आफ इंग्लैंड अपने सिक्के पर सोना नहीं दे सका और पाउण्ड के नोट का सोने के विनिमय से सम्बन्ध नहीं रहा। इसलिए उसकी कीमत बदलने और घटने लगी। फ्रांस के फ्रांक का भी भाव गिर गया। ऐसा मालूम होता था कि सारी दुनिया अस्थिर होगई है और उसमें अकेला अमेरिका का डालर चट्टान की तरह स्थिर होकर खड़ा है।

यह समझा जा सकता है कि इन अवस्थाओं में रुपये का व्यवसाय और सोना लन्दन से मुंह मोड़कर न्यूयार्क चला गया होगा। मगर आश्चर्य की बात देखो कि ऐसा नहीं हुआ और विदेशी हुण्डियाँ और खानों का सोना अब भी लन्दन जाता रहा। इसका यह कारण नहीं था कि लोग डालर से पाउण्ड को ज्यादा चाहते थे, बल्कि सबब यह था कि डालर आसानी से मिलता नहीं था। तुम्हें याद होगा, मैं बता चुका हूँ कि 'सिकारने' की प्रथा के अनुसार ब्रिटिश बैंक अपनी शाखाओं और आढ़तों के जरिये दुनिया-भर में काम करते थे। अमेरिका के बैंकों की ऐसी शाखाएँ या विदेशी आढ़तें नहीं थी और इसलिए उनके पास 'सिकार कर' विदेशी हुण्डियाँ प्राप्त करने का

योरप यानी डैन्यूव और वालकन प्रदेशों के बैंकों के साथ भी सम्बन्ध जोड़ लिया। न्यूयार्क भी वहाँ थोड़ा-बहुत काम-काज करता रहा। इस समय लोग दीलत के लिए पागल हो रहे थे। लन्दन और न्यूयार्क की स्पर्धा के कारण रुपया योरप में बहा आ रहा था, और लखपतियों और करोड़पतियों की तादाद अजीब तेजी के साथ बढ़ रही थी। इसका उपाय भी लोगों ने सीधा-सा ढूँढ़ लिया था। कोई साहसी आदमी इनमें से किसी देश में रेलवे या कोई और सार्वजनिक हित का काम करने के लिए रिआयत हासिल कर लेता, या दियासलाइयाँ बनाने और बेचने या इसी तरह का कोई ठेका ले लेता। इस रिआयत या ठेके का काम करने के लिए कम्पनी बन जाती और वह अपने हिस्से निकालती। इन हिस्सों के आधार पर न्यूयार्क और लन्दन के बड़े-बड़े बैंक धन उधार दे देते। साहूकार न्यूयार्क में दो फ्रीसदी के व्याज पर डॉलर के रूप में रकम उधार लेलेते और फिर उसी रकम को बर्लिन में ६ फ्रीसदी पर और वियेना में ८ फ्रीसदी पर उधार देदेते। इस तरह चालाकी से दूसरे लोगों का धन इधर-उधर करके ये साहूकार बहुत धनवान होगये। इनमें से इवर क्रूगर नामक एक स्वीडन-निवासी बड़ा मशहूर था। उसके पास दियासलाइयों के ठेके थे, इसलिए वह दियासलाई का राजा कहलाता था। किसी समय क्रूगर की बड़ी भारी प्रतिष्ठा थी। परन्तु अब यह साबित होगया है कि वह पूरा ठग था और उसने घेमुमार रुपया गबन किया था। जब वह पकड़ा ही जानेवाला था तब, बरस दो बरस हुए, उसने आत्महत्या करली। उस समय के और भी कई मशहूर साहूकार अपने गन्दे तरीकों के कारण आफ़त में फँस गये।

इंग्लैण्ड और अमेरिका की मध्य और पूर्वीय योरप में जो स्पर्धा हुई, उससे एक लाभ हुआ। १९२९ में मन्दी शुरू हुई, उससे पहले के सालों में योरप में इस स्पर्धा के कारण दीलत की नदियाँ बह गई इससे वहाँ की हालत बहुत सम्भल गई।

इस बीच, १९२६ और १९२७ में, फ़्रांस ने भी बहुत नोट छाप डाले थे और फ़्रांक की कीमत बहुत घट गई थी। जब फ़्रांक का भाव गिरा तो धनवाले फ़्रांसीसियों ने—और धन तो फ़्रांस के सभी छोटे-छोटे अमीर भी बचाकर रखते हैं—नुबसान के डर से अपना धन बाहर भेज दिया। उन्होंने विदेशी सरकारी काग़ज़ और वृष्टिड्यों के टेर-के-डेर ख़रीद लिये। १९२७ में फ़्रांक की कीमत फिर स्थिर होगई और उसका भाव सोने के साथ बाँध दिया गया। मगर उसकी कीमत पहले से ३ रह गई। अब फ़्रांस के जिन लोगों के पास विदेशी पुर्ज़े थे उन्हें उनको फ़्रांक में बदल लेने की बड़ी उत्तुक्ता हुई। उनका व्यापार अच्छा चला, क्योंकि उन्हें अब मूल में पँचगुने फ़्रांक मिल रहे थे। इस तरह नोटों के छपने से उन्हें बरा भी हानि नहीं हुई; अगर वे आरम्भ में ही फ़्रांक

विनिमय के वाजार में अपनी आर्थिक प्रभुता, क़ायम रखने के लिए कुछ हद तक अपने उद्योगों का बलिदान कर दिया। पाउण्ड की प्रतिष्ठा एकदम बढ़ गई, परन्तु तुम्हें याद होगा कि उसके बाद इंग्लैंड में घरेलू झगड़े पैदा होगये। इनका एक कारण उद्योग को आघात पहुँचना भी था। बेकारी फैल गई और लम्बे समय तक कोयले की खानों में आम हड़ताल भी रही।

पाउण्ड का मूल्य स्थिर होगया परन्तु इतने से ही काम नहीं चल सकता था। अमेरिका ब्रिटिश सरकार से एक बड़ी भारी रकम खाते-पेटे या हाथ-उधार की माँगता था। इसे वह किसी भी समय वापस ले सकता था। इस तरह की माँग करके अमेरिका इंग्लैंड की स्थिति बहुत ही विकट बना और पाउण्ड का भाव गिरा सकता था, इसलिए बड़े-बड़े ब्रिटिश राजनीतिज्ञ, जिनमें स्टेनली बाल्डविन भी थे, दीड़े-दीड़े न्यूयार्क पहुँचे। वे क्रिस्तों के रूप में युद्ध-ऋण के भुगतान के बारे में अमेरिका से शर्तें तय करना चाहते थे। अमेरिका के ऋणी सभी यूरोपियन देश थे और उनके लिए उचित मार्ग यही था कि वे आपस में सलाह करके फिर अच्छी-से-अच्छी शर्तें प्राप्त करने के लिए अमेरिका के पास जाते। परन्तु ब्रिटिश सरकार को पाउण्ड को बचाने और लन्दन का आर्थिक नेतृत्व क़ायम रखने की इतनी चिन्ता हुई कि उसे फ्रांस या इटली के साथ मशविरा करने का वक़्त भी नहीं मिला और वह किसी भी भाव जल्दी-से-जल्दी अमेरिका के साथ कोई प्रबन्ध कर लेना चाहती थी। प्रबन्ध तो होगया, मगर हुआ भारी क़ीमत देकर। अमेरिका की सरकार ने जो कड़ी-कड़ी शर्तें रखीं वे सब उसे माननी पड़ीं। बाद में फ्रांस और इटली का समझौता, अपने क़र्ज के बारे में अमेरिका के साथ कहीं अच्छी शर्तों पर हुआ।

इन कठोर प्रयत्नों और कुर्वानियों से पाउण्ड और लन्दन नगर की रक्षा होगई। परन्तु दुनिया के सभी वाजारों में न्यूयार्क के साथ तनातनी जारी रही। धन की बहुतायत होने के कारण न्यूयार्क ने थोड़े व्याज पर लम्बी मियाद के क़र्ज देना शुरू किया, और अनेक देश जो पहले लन्दन के वाजार में उधार लिया करते थे अब न्यूयार्क के प्रलोभन में फँस गये। इन देशों में कनाडा, दक्षिण अफ़्रीका और आस्ट्रेलिया शामिल थे। न्यूयार्क की बराबरी इन लम्बी मियाद के क़र्जों में लन्दन नहीं कर सकता था; इसलिए उसने मध्य-योरप के बैंकों को छोटी मियाद के क़र्ज देने की कोशिश की। छोटी मियाद के क़र्जों में साहूकार के अनुभव और उसकी प्रतिष्ठा का महत्व अधिक होता है।

यह बात लन्दन के हक़ में थी। इसलिए लन्दन के बैंकों ने वियेना के बैंकों के साथ गहरे सम्बन्ध स्थापित कर लिये और उनके ज़रिये मध्य और दक्षिण-पूर्वीय

नतीजा यह हुआ कि अंग्रेजों का बहुत-सा धन जो जर्मनी को थोड़ी मियाद के ऋज के रूप में दिया गया था, वहीं बन्द होगया। लन्दन के साहूकारों की स्थिति बिकट होगई, क्योंकि उनके सिर पर भी देना था और वे जर्मनी से रकम मिलने पर आशा लगाये बैठे थे। फ्रांस और अमेरिका ने १३ करोड़ पाउण्ड उधार देकर उनकी मदद की, मगर यह मदद वक्त निकल जाने पर पहुँची। लन्दन के आर्थिक हलकों में घबराहट फैल गई। ऐसी घबराहट के अवसर पर सब लोग अपनी-अपनी रकम निकाल लेना चाहते हैं। इसलिए १३ करोड़ पाउण्ड बात-की-बात में साफ़ होगये। यह न भूलना कि उस समय पाउण्ड सोने के विनिमय से बँधा हुआ था और कोई भी पाउण्ड के नोट के बदले में सोना माँग सकता था।

उस समय ब्रिटेन में मजदूर सरकार थी। उसने और धन उधार लेना चाहा और चिन्तित होकर न्यूयार्क और पेरिस के साहूकारों से माँगा। मालूम होता है, उन्होंने कुछ शर्तों पर मदद करना स्वीकार कर लिया। एक शर्त यह थी कि ब्रिटिश सरकार को मजदूरों और सामाजिक सेवा-सम्बन्धी कामों में किरायात करनी चाहिए। शायद मजदूरी और वेतन घटाने की बात भी सुझाई गई थी। यह ब्रिटेन के घरू मामलों में विदेशी साहूकारों का दखल देना हुआ। मजदूर सरकार के विरोधियों ने इस स्थिति से अनुचित लाभ उठाया। उस सरकार के मुखिया और प्रधान मन्त्री रैमजे मैकडानलड ने सरकार और अपने दल दोनों को धोखा दिया और मुख्यतः अनुदार दल की सहायता से उसने दूसरी सरकार बना ली। यह 'राष्ट्रीय सरकार' कहलाई। यह संकट-निवारण के लिए ही बनी थी। योरोप के मजदूर-आन्दोलन के इतिहास में रैमजे मैकडानलड का यह काम दे-बफ़ाई का बड़े मार्क का उदाहरण था।

राष्ट्रीय सरकार पाउण्ड की रक्षा के लिए बनी थी। वचन के अनुसार फ्रांस और अमेरिका से उसे ऋण भी मिल गया। परन्तु उसकी सहायता से भी पाउण्ड की रक्षा न हो सकी। २३ सितम्बर १९३१ को सरकार को सोने का विनिमय छोड़ना पड़ा और पाउण्ड फिर अस्थिर सिक्का बन गया। पाउण्ड का भाव तेजी से गिरने लगा और लगभग १४ शिल्लिंग सोने के बराबर रहगया। यानी मोटे हिसाब से उसकी प्रीमत पट्टे से दो-तिहाई होगई।

इस घटना और तारीख का संसार में बड़ा असर हुआ। योरोप ने इन्ने ब्रिटिश साम्राज्य के भावी नाश का निशान समझा, क्योंकि इसका अर्थ था संसार के सराफ़ा-घाशार ने लन्दन की प्रभुता का अन्त होना। पाउण्ड के गिरने से अनेक देशों का सिक्का हिल गया, क्योंकि उन्होंने पाउण्ड के नोट सोना समझकर रख छोड़े थे और उनके बदले में सोना हर वक्त मिल भी सकता था। अब उन नोटों के बदले में सोना

रखते तो जरूर हानि होती। उस मौके से लाभ उठाने का फ्रेंच सरकार ने भी निर्णय कर लिया और उसने बदले में नई छपी हुई फ्रांक की टुण्डियाँ देकर ये सारी विदेशी टुण्डियाँ या सरकारी कागज खरीद लिये। इस तरह फ्रेंच सरकार इन विदेशी टुण्डियों और सरकारी पुर्जों को लेकर अचानक बहुत मालदार होगई। असल बात यह है कि उस समय ये टुण्डियाँ और पुर्जे उसीके पास सबसे अधिक थे। उसकी इच्छा भी नहीं थी और उसमें इतना दम भी नहीं था कि वह आर्थिक नेतृत्व के लिए इंग्लैंड और अमेरिका की होड़ कर सके। परन्तु दोनों पर प्रभाव डालने की स्थिति में वह जरूर होगई थी।

फ्रांस के लोग फूँक-फूँककर क्रदम रखते हैं और यही हाल उनकी सरकार का है। जो कुछ उनके पास होता है उसे भी गँवा देने की जोखिम उठाकर बड़ा मुनाफ़ा करने के बजाय वे सुरक्षित रहकर थोड़ा लाभ उठाना पसन्द करते हैं। इसलिए फ्रेंच सरकार ने सावधान होकर अपना फ़ालतू धन थोड़े व्याज पर लन्दन के अच्छे-अच्छे व्यापारियों को उधार दे दिया। इस तरह उसने ब्रिटिश बैंक से सिर्फ़ दो फ़ीसदी व्याज लिया। उसी पूँजी को ब्रिटिश बैंक पाँच-छः फ़ीसदी पर जर्मन बैंकों को दे देते और जर्मन बैंक आठ-नीं फ़ीसदी पर उसे वियेना भेज देते और वहाँसे वह धन बारह फ़ीसदी पर हंगरी या बालकन में पहुँच जाता। जितनी बड़ी जोखिम उतना ही ज्यादा व्याज। मगर बैंक आफ़ फ्रांस ने जोखिम उठाना पसन्द नहीं किया। इसीलिए उसने ब्रिटिश बैंकों के साथ लेन-देन किया। इस प्रकार फ्रांस ने अपनी खरीदी हुई विदेशी टुण्डियों के रूप में बहुत-सा रुपया लन्दन में रख दिया और इससे लन्दन की न्यूयार्क के साथ जो लड़ाई चल रही थी उसमें मदद मिली।

इस बीच में व्यापारिक उथल-पुथल और मन्दी बढ़ रही थी और खेती की पैदावार के भाव घट रहे थे। १९३० के जाड़े में गेहूँ का भाव इतना गिर गया कि पूर्वोक्त योरप के बैंक अपने कर्जदारों से रुपया वसूल नहीं कर सके और इसलिए उन्होंने वियेना में पाउण्ड और डालर के रूप में जो ऋण लिया था वह नहीं लौटा सके। इससे वियेना के बैंकों में उथल-पुथल मच गई और वहाँ के क्रेडिट ऐन्स्टाल्ट नामक सबसे बड़े बैंक का दिवाला निकल गया। इससे फिर जर्मन बैंक हिल उठे और मार्क का ढाँचा बैठने की नीबट आगई। ऐसा होता तो जर्मनी में अमेरिका और ब्रिटेन की पूँजी को खतरा होता। इसीको टालने के लिए राष्ट्रपति हूवर ने युद्ध-ऋण और हर्जाने की वसूली स्थगित रखने का ऐलान किया था। उस समय हर्जाने की अदायगी का आग्रह करने का अर्थ जर्मनी का सम्पूर्ण आर्थिक नाश होता। हुआ यह कि इतने से भी काम न चला। जर्मनी दूसरे देशों को अपना खानगी कर्ज भी न चुका सका और उसका भुगतान भी मुलतवी करना पड़ा।

सेंट्रल बैंक कहते हैं) बदले में सोना लेने के लिए अपने पास की पाउण्ड की हुण्डियाँ बेच दीं। अबतक उन्होंने पाउण्ड की हुण्डियाँ रख छोड़ी थीं, क्योंकि उनके बदले में सोना किसी वस्तु भी मिल सकता था और इसलिए उन्होंने उसे सोना ही समझ रखा था। जब ये हुण्डियाँ अचानक बड़ी तादाद में बिकीं तो पाउण्ड का मूल्य आनन-फ़ानन में ३० फ़ी सदी गिर गया। इस तरह भाव गिरने से उन कर्जदारों को, जिनपर पाउण्ड के नोटों के रूप में देना निकलता था (इनमें कुछ सरकार और बड़े-बड़े व्यापारी भी शामिल थे), सोना चुका देने की प्रेरणा हुई, क्योंकि उन्हें ३० फ़ी सदी कम देना पड़ा। इस तरह बहुत-सा सोना इंग्लैंड में आगया।

परन्तु सोने की असली बाढ़ तो इंग्लैंड में हिन्दुस्तान और मिस्र से आई। इन शरीव और पराधीन देशों को विवश होकर धनी इंग्लैंड की सहायता करनी पड़ी और इंग्लैंड की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए इनके छिपे हुए साधन काम में लाये गये। इस मामले में इनकी नहीं चुनी गई। इंग्लैंड की जरूरत के सामने इनकी इच्छाओं या हितों का मूल्य ही क्या हो सकता था ?

भारत की दृष्टि से बेचारे भारतीय रुपये की कहानी लम्बी और दर्दनाक है। ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश पूंजी के स्वार्थों की पूर्ति के लिए उसकी क्रोमट बार-बार बदली जाती रही है। मैं सिक्के के इस मामले में विस्तार से नहीं लिखना चाहता। सिर्फ इतना ही बतलाना चाहता हूँ कि सिक्के के मामले में लड़ाई के बाद ब्रिटिश सरकार ने हिन्दुस्तान में जो कार्रवाइयाँ कीं हैं उनसे हिन्दुस्तान की असीम हानि हुई है। उसके बाद १९२७ में हिन्दुस्तान में इस बात पर बड़ा विवाद खड़ा हुआ कि पाउण्ड के नोट और सोने से सम्बन्ध रखते हुए रुपये का मूल्य कितना स्थिर किया जाय। उस समय पाउण्ड का सोने के विनिमय से सम्बन्ध था। यह 'अनुपात का विवाद' कहलाया, क्योंकि सरकार तो रुपये की क्रोमट १ शिलिंग ६ पेंस रखना चाहती थी और भारतीय लोकमत लगभग १ स्वर से एक शिलिंग ४ पेंस चाहता था। सवाल पुराना था और यह था कि रुपये का मूल्य बढ़ाकर साहूकारों और पूँजीवालों को लाभ पहुँचाया जाय और विदेशी माल की आमद बढ़ाई जाय, या रुपये की क्रोमट घटाकर प्रणदाताओं का बोझ कम किया जाय और गृह-उद्योगों और निर्यात व्यापार को उत्तेजन दिया जाय ? बात हिन्दुस्तानियों की न रहकर सरकार की ही चली और सोने के रूप में रुपये की क्रोमट १ शिलिंग ६ पेंस मुज़रर होगई। इस तरह बहुत लोगों की राय में रुपये की क्रोमट थोड़ी बढ़ा दी गई। सिर्फ इंग्लैंड ने ही १९२५ में पाउण्ड को सोने के विनिमय पर लाते समय सिक्के की क्रोमट बढ़ाई थी। हम देख चुके हैं कि उसने ऐसा अपने संसार के आर्थिक नेतृत्व को हासिल रखने के लिए किया था और इसके

मिलना बन्द हो गया और उनका मूल्य भी ३० फ़ीसदी गिर गया । इसलिए कुछ दूसरे देशों के सिक्कों का भाव भी घट गया और उन्हें इंग्लैण्ड के कारण सोने का विनिमय छोड़ देना पड़ा ।

फ़्रांस की स्थिति इस समय मजबूत हो गई । उसकी सावधानी की नीति का उसे लाभ मिल गया । जहाँ अमेरिका और खास तौर से इंग्लैण्ड का उधार दिया हुआ धन जर्मनी में रुक गया और उन्हें धन की जरूरत होगई वहाँ फ़्रांस के पास विदेशी हुण्डियों और सोने के फ़्रांक से रूप में धन की बहुतायत थी । अमेरिकन और ब्रिटिश दोनों सरकारों ने फ़्रांस पर अलग-अलग प्रेम-प्रदर्शन किया और अपने-अपने पक्ष में एक-दूसरे के खिलाफ़ उसे मिला लेने की भरसक कोशिश की । फ़्रांस बहुत सावधान रहा और उसने दोनों की ही बात नहीं मानी । इस प्रकार उसने सीदे का अवसर हाथ से चला जाने दिया ।

१९३१ के अन्त में इंग्लैण्ड में पार्लमेण्ट का आम चुनाव हुआ । राष्ट्रीय सरकार की बड़ी भारी विजय हुई । वास्तव में यह विजय अनुदार दल की थी । मजदूर दल का लगभग सफ़ाया हो गया । “मजदूर सरकार उनकी पूंजी ज़दत कर लेगी,” ऐसी-ऐसी कहानियों से डरकर, और शायद वेतन की कटौती पर अटलाण्टिक प्रदेश की जलसेना के ब्रिटिश नाविकों ने जो थोड़े दिन विद्रोह कर दिया था उससे भी भयभीत होकर, ब्रिटिश नागरिक अनुदार राष्ट्रीय सरकार के पक्ष में होगये । अब भी इंग्लैण्ड में सत्ता इसी सरकार के हाथ में है । प्रधान मंत्री रैमजो मैकडानल्ड हैं, परन्तु सबसे शक्ति-शाली आदमी अनुदार दल का नेता स्टैनली वाल्डविन हैं । पार्लमेण्ट और ब्रिटिश नीति पर इसी दल का पूरा प्रभुत्व है ।

संकट और ख़तरे के होते हुए भी पाउण्ड के गिरने के बाद तीनों मुखिया राष्ट्र अर्थात् अमेरिका, ब्रिटेन और फ़्रांस या उनके साहूकार आपस में सहयोग न कर सके । सब एक-दूसरे को हानि पहुँचाकर अपनी-अपनी स्थिति अच्छी करने की चाल चलते रहे हैं । आर्थिक नेतृत्व के लिए लड़ने के बजाय वे मिलकर एक सम्मिलित अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय का वाज़ार बना सकते थे । मगर सबने अपनी-अपनी खिचड़ी अलग पकाना ही पसन्द किया । बैंक ऑफ़ इंग्लैण्ड लन्दन को उसका खोया हुआ पद वापस दिलाने के काम में जुट गया और दुनिया के लिए बड़े अचम्भे की बात है कि पिछले १८ महीनों में उसे बहुत कुछ सफलता भी मिल गई है, हालाँकि पाउण्ड अब भी सोने के विनिमय से अलग है ।

जब इंग्लैण्ड ने सोने का विनिमय छोड़ा तो दूसरे देशों के सरकारी बैंकों ने (इन्हें

कीमत बढ़ी, यानी सोने से ज्यादा रुपये मिलने लगे। देश में दुःख और गरीबी का तो ठिकाना ही नहीं। लोगों पर कर्ज था ही। इस कारण उन्हें इसे चुकाने के लिए अधिक-से-अधिक रुपये हासिल करने को ज़ेवर वगैरा के रूप में जितना भी सोना उनके पास था वह बेच डालने की प्रेरणा हुई। इसलिए थोड़ा-थोड़ा करके देशभर का सोना बैंकों में पहुँचने लगा और बैंकों ने इसे लन्दन के बाज़ार में बेचकर फ़ायदा उठाया। इस तरह हिन्दुस्तान के सोने का प्रवाह लगातार इंग्लैंड की तरफ़ हुआ और अब भी हो रहा है। कहा जाता है कि अबतक १ अरब ४६ करोड़ रुपयों का सोना हिन्दुस्तान से इंग्लैंड जा चुका है। यह १० करोड़ पाउण्ड से भी ज्यादा के बराबर है। इसी सोने और मिला से इसी तरह आये हुये सोने के तुफ़ल से बैंक ऑफ़ इंग्लैंड और ब्रिटिश पूंजीपतियों की रक्षा हुई और उन्हें १९३१ के सितम्बर में अमेरिका और फ़्रांस से उधार लिया हुआ रुपया चुकाने के साधन मिले।

यह अजीब बात है कि जहाँ दुनिया के सब देश—यहाँतक कि अधिक-से-अधिक धनी मुल्क भी—अपना-अपना सोना बचाकर रखते हैं और उसे बढ़ाते हैं, हिन्दुस्तान में इसका उलटा हो रहा है। अमेरिकन और फ़्रेंच सरकारों ने अपने-अपने बैंकों के तहख़ानों में भारी मात्रा में सोना जमा कर लिया है। यह बिल्क्षण काम है कि यानों में से निकालकर सोने को फिर बैंकों के तहख़ानों में गहरा गाढ़ दिया जाय। बहुत-से देशों ने और ब्रिटिश उपनिवेशों ने अपने यहाँसे सोने को निकासी बन्द कर दी है, अर्थात् वहाँ देश के बाहर कोई सोना नहीं लेजा सकता। इंग्लैंड ने अपने सोने की रक्षा के लिए सोने का विनिमय छोड़ दिया, मगर हिन्दुस्तान में बात ऐसी नहीं हुई; क्योंकि यहाँ की अर्थनीति इंग्लैंड के हितों के अनुसार चलाई जाती है।

अबसर ऐसी बातें बताई जाती हैं कि हिन्दुस्तान में सोना और चाँदी गढ़ा हुआ रहता है। मुट्ठीभर धनिक लोगों के द्वारे में कुछ हद तक यह सही भी है। परन्तु सर्वसाधारण तो इतने दरिद्र हैं कि वे कोई भी चीज़ जमा करके नहीं रख सकते। कुछ खाते-पीते किसान थोड़े-से ज़ेवर रखते हैं। यही उनका 'ख़जाना' है। उनको पूंजी लगाने की सहूलियतें भी हासिल नहीं हैं। ये छोटे-मोटे ज़ेवर और दूसरा सोना जो हिन्दुस्तान में था, वह मन्दी और सोने का भाव बढ़ जाने के कारण ख़िचकर चला गया है। राष्ट्रीय सरकार होती तो वह इस सोने को बचाकर देश में ही रखती, क्योंकि सोना ही अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान का माना हुआ साधन है।

हाँ तो पाउण्ड और डालर की लड़ाई का काम जारी रखते। इन उपायों और दूसरी बातों से, जिनका उल्लेख करने की स्ति जरूरत नहीं है, बैंक ऑफ़ इंग्लैंड ने अपनी स्थिति बहुत अंशों में सुधरूत करली। १९३० के शुरू में भाग्य ने उसका कुछ

लिए वह बहुत कुछ त्याग करने को तैयार था। फ्रांस, जर्मनी और दूसरे देशों ने अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सिक्के की क्रीमत घटाना पसन्द किया था।

रुपये की क्रीमत बढ़ा देने से हिन्दुस्तान में लगी हुई ब्रिटिश पूंजी का मूल्य बढ़ गया। इससे हिन्दुस्तानी उद्योग पर भी बोझ पड़ा, क्योंकि हिन्दुस्तान के माल के भाव कुछ बढ़ गये। सबसे बड़ी बात यह हुई कि जो किसान और जमींदार बनियों के कर्जदार थे उन सबका भार बढ़ गया, क्योंकि जब रुपये की क्रीमत बढ़ी तो इस कर्ज की क्रीमत भी बढ़ गई। १८ और १६ पेन्स का कर्ज २ पेन्स यानी १२॥ फ्री सदी मूल्य बढ़ने के बराबर हुआ। मान लो हिन्दुस्तान के किसानों पर ९ अरब रुपया कर्ज है। उसमें १२॥ फ्री सदी वृद्धि होजाने का अर्थ होता है १६ अरब की भारी रकम और बढ़ जाना।

रुपये के रूप में अलवत्ता कर्ज उतना ही रहा जितना पहले था। परन्तु खेती की पैदावार के मूल्य के रूप में कर्ज बढ़ गया। रुपये का असली मूल्य यही होता है कि उससे कितना गेहूं, कितना कपड़ा और कितनी और कोई चीज-वस्तु खरीदी जा सकती है। रुकावट न डाली जाय तो यह मूल्य अपने-आप ठीक होता रहता है। रुपये की खरीदने की ताकत घट जाने से सिक्के की क्रीमत घट जाती है। कृत्रिम रूप से उसका मूल्य अधिक रख देने से उसकी खरीदने की शक्ति दीखने में बढ़ जायगी, लेकिन दरअसल नहीं बढ़ती। इस प्रकार किसानों को मालूम होगया कि अब कर्ज और व्याज के चुकाने में पहले से उनकी आय अधिक चली जाती है और बहुत थोड़ी उनके पास रह जाती है। इस तरह १ शिलिंग ६ पेंस के अनुपात से हिन्दुस्तान में मन्दी और भी बढ़ गई।

जब सितम्बर १९३१ में पाउण्ड के नोटों का सोने से सम्बन्ध छूट गया तो रुपये का भी छूट गया। परन्तु उसे पाउण्ड के साथ बांधे रक्खा गया। इस प्रकार एक शिलिंग छः पेंस का अनुपात तो कायम रहा, परन्तु सोने के रूप में अब उसकी क्रीमत कुछ घट गई। पाउण्ड के नोट के साथ रुपये को इसलिए बांध रक्खा गया कि हिन्दुस्तान में लगी हुई ब्रिटिश पूंजी को आंच न आवे, क्योंकि अगर रुपये को छुड़ा छोड़ दिया जाता तो उसकी क्रीमत घटने और पाउण्ड के नोटों के रूप में लगी हुई पूंजी को हानि पहुँचने की सम्भावना थी। हुआ यह कि नुवसान भारत में लगी हुई अमेरिका और जापान आदि की गैरब्रिटिश विदेशी पूंजी को ही हुआ। रुपये को पाउण्ड के साथ बांध देने से इंग्लैंड को दूसरा बड़ा लाभ यह हुआ कि वह अपने उद्योगों के लिए जो कच्चा माल खरीदता था उसका मूल्य ब्रिटिश सिक्के में चुका सका। पाउण्ड के नोट का जितना ही बड़ा क्षेत्र उतना ही पाउण्ड का लाभ।

जैसे-जैसे पाउण्ड के साथ रुपये की क्रीमत घटती गई, वैसे-वैसे सोने की भीतरी

यह उधार का धन्धा साहूकारों के लिए फ़ायदेमन्द तो है ही, इससे धीरे-धीरे उद्योग और खेती पर उनका क़ाबू भी बढ़ता है। किसी नाज़ुक वक़्त पर उधार देने से इन्कार करके या अपना रुपया वापस माँगकर वे उधार लेनेवाले का काम चौपट कर सकते हैं। यह बात देश के भीतर और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र दोनों में लागू होती है, क्योंकि बड़े-बड़े केन्द्रीय बैंक अलग-अलग देशों की सरकारों को रुपया उधार देते हैं और इस तरह उनपर अपना दबाव रखते हैं। इसी तरह न्यूयार्क के साहूकार मध्य और दक्षिणी अमेरिका की बहुत-सी सरकारों पर नियंत्रण रखते हैं।

इन बड़े-बड़े बैंकों की बात यह है कि अच्छे और बुरे दोनों तरह के समय में इन्हें मुनाफ़ा ही-मुनाफ़ा होता है। अच्छे दिनों में सबका रोज़गार अच्छा चलता है और उसका हिस्सा इन्हें भी मिलता है। लोग ख़ूब रुपया बैंकों में जमा कराते हैं, बैंक उस पर बहुत थोड़ा व्याज देते हैं और उसी रुपये को अधिक व्याज पर दूसरों को उधार दे देते हैं। बुरे यानी मन्दी और संकट के दिनों में वे अपना रुपया दांतों से पकड़े रखते हैं। इससे मन्दी तो बढ़ती है, क्योंकि उधार के बिना बहुत-से धन्धों का चलना कठिन होजाता है, लेकिन बैंकों को दूसरी तरह फ़ायदा होता है। ज़मीन, कारख़ानों और सभी चीज़ों का भाव गिर जाता है और बहुत-से उद्योगों का दिवाला निकल जाता है। बैंक झटपट ये सब कुछ सस्ते में ख़रीद लेते हैं। इस तरह तेज़ी और मन्दी के बारी-बारी से दौर होने में साहूकारों का लाभ है।

वर्तमान महामन्दी के ज़माने में बड़े बैंकों का बराबर अच्छा हाल रहा है और उन्होंने अच्छा मुनाफ़ा (Dividend) बाँटा है। यह सच है कि संप्रुक्तराष्ट्र में हजारों बैंकों और आस्ट्रिया और जर्मनी में कुछ बड़े-बड़े बैंकों का दिवाला निकल गया है। अमेरिका में जिन बैंकों का दिवाला निकला वे सब छोटे-छोटे बैंक थे। मालूम होता है अमेरिका की बैंक-प्रणाली ही ग़लत थी। फिर भी न्यूयार्क के बड़े-बड़े बैंकों का काम ठीक-ठीक चला। इंग्लैण्ड में किसी बैंक का दिवाला नहीं निकला। अलबत्ता अगर मन्दी बनी रही तो अग्त में वहाँके बड़े-से-बड़े बैंकों की भी वही हालत होगी जो ख़ास तौर पर दिग्ग़ जाने पर जर्मनी और आस्ट्रिया में हुई थी।

इन कारणों से आज की पूँजीवादी दुनिया में सच्ची सत्ता साहूकारों के हाथ में है। इसीलिए लोग कहते हैं कि शुद्ध आर्थिक युग के बाद अब यह हमारा 'पूँजीयुग' (Financial Age) आया है। पश्चिमी देशों में और ख़ासतौर पर अमेरिका में धराधर लक्षपति और करोड़पति बन रहे हैं। अमेरिका तो करोड़पतियों का देश ही कहलाते लगा है। इन धन-बुद्धियों की दड़ी तारीफ़ होनी है। लेकिन दिन-दिन यह प्रकट हो रहा है कि बड़े-बड़े पूँजीपतियों के तरीक़े बहुत ही गंदे हैं और टाकुओं

साथ दिया, क्योंकि जर्मनी में अमेरिका का धन रुक जाने से संयुक्तराष्ट्रों के बैंकों में उयल-पुयल मच गई थी। इस उयल-पुयल में बहुत-से अमेरिकनों ने अपने डालर बेच-कर पौण्ड के नोट खरीद लिये। इस तरह ब्रिटिश सरकार को डालर की हुण्डियां बहुतायत से मिल गईं। इन्हें न्यूयार्क के सरकारी बैंक में देकर उसने बदले में सोना ले लिया। चूंकि डालर सोने के विनिमय पर था, इसलिए उसके एवज में कोई भी सोना मांग सकता था। इस तरह किसी भी आपत्ति या पाउण्ड का भाव अधिक गिरे बिना ही ब्रिटिश सुवर्ण-भण्डार भर गया और पाउण्ड का मूल्य अस्थिर रह गया और सुवर्ण विनिमय से हट गया। साथ ही लन्दन के पास भरपूर विदेशी हुण्डियों और सरकारी पुर्जों के होने से वह फिर संसार का बड़ा और मुख्य हुण्डी-बाजार बन गया। फ़िलहाल न्यूयार्क हार गया। इसका बड़ा कारण तो, जैसा मैं किसी पिछले खत में बता चुका हूँ, यह था कि वहाँ के हजारों छोटे-छोटे बैंक वर्दाद होचुके थे।

: १८८ :

पूँजीवादी दुनिया की मिलकर प्रयत्न करने की असमर्थता

२८ जुलाई, १९३३

मैंने तुम्हें आर्थिक स्पर्धाओं और चालवाजियों की कितनी लम्बी कहानी सुना डाली ! यह तुम्हें शायद ही अच्छी लगी हो। असल में मुझे खुद को भी अफ़सोस-सा ही है कि मैंने इस मज़मून पर क़लम उठाई और तुम्हें यह सलाह देने को जी चाहता है कि तुम इसे छोड़ दो। अन्तर्राष्ट्रीय साजिशों का जाला इतना गुंथा हुआ है कि इसे सुलझाना या इसमें घुसकर निकल आना आसान बात नहीं है। मैंने तो तुम्हें जो कुछ ऊपर-ऊपर दिखाई देता है उसीकी झाँकी-सी दिखाने की कोशिश की है। जो कुछ होता है उसका बहुत-कुछ हिस्सा न कभी ऊपर आता है, न जाहिर होता है।

आज की दुनिया में साहूकार और पूँजीपति का महत्व बहुत ज्यादा है। कारख़ानेवालों के दिन भी जाते रहे। अब तो बड़े-बड़े साहूकार ही उद्योग, खेती, रेलवे, ढुलाई और एक हद तक सरकार और सब चीज़ों पर नियन्त्रण रखते हैं। वजह यह है कि उद्योग और व्यवसाय के बढ़ने से उनके लिए ज्यादा-से-ज्यादा रुपये की ज़रूरत होती है और यह रुपया बैंकों से मिलता है। संसार का ज्यादातर काम आज-कल उधार या साख़ पर चलता है। और उधार देना-न देना, कम-ज्यादा देना और उसपर अधिकार रखना, यह सब बड़े बैंकों के हाथ में है। कारख़ानेदार और किसान दोनों को अपना काम चलाने के लिए रुपया उधार लेने बैंक के पास जाना पड़ता है।

के बेकारों की तादाद भी बढ़ती चली गई और डेढ़ करोड़ तक पहुँच गई। वहाँ मजदूरी की दर संसार में सबसे ऊँची थी, वह भी जल्दी-जल्दी घट गई और उसके साथ ही रहन-सहन का तरीका भी नीचा हो गया। जिस महान् देश में सबको अवसर मिलता था और जिसका नाम सुनकर दूर-दूर से स्त्री-पुरुष आते थे, वहाँ निराशा का साम्राज्य छा गया। देश में बड़े-बड़े पूँजीपतियों का बोलबाला था। इनकी अनेक सरकारी जाँच-पड़तालें में कलई खुल गई और वे पूरी तरह भ्रष्ट साबित होगये। इस तरह पूँजी और उद्योग के नेताओं पर से लोगों का विश्वास उठ गया। मन्दी के इस सारे जमाने में हरवर्त हूवर राष्ट्रपति थे, लेकिन उन्होंने विकट स्थिति का कुछ भी उपाय नहीं किया। वे बड़े-बड़े पूँजीपतियों के मित्र समझे जाते थे। इसलिए उन्होंने मनमानी करने के लिए उन्हें स्वतन्त्र छोड़ दिया। नतीजा यह हुआ कि जनता उनसे दूरी तरह नाराज होगई। १९३२ के नवम्बर में जब हर चार वर्ष में होनेवाले राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो हूवर को फ्रैंक रूजवेल्ट ने भारी बहुमत से हरा दिया। निराशा में डूबे हुए अमेरिका के मध्यमवर्ग के देशभार लोगों की रूजवेल्ट की तरफ़ दृष्टि गई और उन्हें आशा हुई कि वह हमारे फण्ट दूर करेंगे। अमेरिका के विधान के अनुसार चुनाव तो १९३२ के नवम्बर में होगया, परन्तु नये राष्ट्रपति ने अधिकांश १९३३ के मार्च तक नहीं सम्भाले। इस बीच में संसार-भर की स्थिति और भी दिगड़ गई और एक ऐसी घड़ी आया कि परिपक्व बुलाने की चर्चा जोर से चली जिसमें मन्दी के उपाय सोचने के लिए संसार के सब देश इकट्ठे हों। १९३३ के मार्च के शुरु में रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति की गद्दी पर बिठाये ही जा रहे थे कि वहाँके बैंकों में दुबारा उथल-पुथल मच गई। उथल-पुथल बड़े जोर की थी और लोगों में इतनी घबराहट फैल गई कि कुछ दिनों के लिए सारे बैंक बन्द कर देने पड़े। इससे संयुक्तराष्ट्र को सोने का विनिमय छोड़ना पड़ा। डालर को पाउण्ड का साथ देना पड़ा और सोने से अलग होना पड़ा। देश में सोने की कमी नहीं थी और असल बात तो यह है कि अमेरिका के पास और किसी भी देश से ज्यादा सोना था। लेकिन आजकाल की अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था का इतना विचित्र हाल है कि यह सब कुछ होते हुए भी अमेरिका को सोने का विनिमय छोड़ना पड़ा और सोने की निवासी बन्द करनी पड़ी। शायद इसका असली उद्देश्य यह था कि बैंकों और साहूकारों को नुक़सान पहुँचाकर भी उद्योग और खेती का भार हल्का करने के लिए डालर का भाव घटा दिया गया। मैंने तुन्हें पिछले खत में समझाया था कि रुपये का मूल्य १८ पैसे मुहर्रर कर देने से किस तरह हिन्दुस्तान में पूँजी की हीमन बढ़ गई और लोगों पर क़ाई का भार भी ज्यादा होगया। राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने डालर का भाव घटाकर इसने ख़ली बात की। तमामों की बात तो यह देखो कि डालर का भाव

और धोखेबाजों से इन लोगों में इतना ही भेद है कि ये अपना कान बड़े पैमाने पर फरते हैं। बड़े-बड़े एकाधिकार (ठेके) छोटे-छोटे धन्यों को कुचल डालते हैं। बड़ी-बड़ी पूंजी के दांव-पेंच, जिन्हें बहुत कम लोग समझ सकते हैं, उन गरीबों को खूब मूँडते हैं जो भरोसा करके अपनी पूंजी लगाते हैं। योरोप और अमेरिका के कुछ बड़े-से-बड़े श्रीमन्तों का हाल ही में भण्डाफोड़ हुआ है और वह दृश्य कोई सुहावना दृश्य नहीं था।

हम देख चुके हैं कि इंग्लैण्ड और अमेरिका के बीच आर्थिक नेतृत्व के लिए जो लड़ाई चल रही थी उसमें फिलहाल लन्दन की जीत हुई। लेकिन इस विजय से क्या हाथ आया ? इस लड़ाई के १२ वर्ष तक जारी रहने से धीरे-धीरे इससे होनेवाला लाभ कम होता गया। खास तौर पर पिछले चार साल में मन्दी खूब फैली और व्यवसाय और उद्योग को खा गई। विदेशी व्यापार पहले से एक-तिहाई रह गया। इसका अर्थ यह हुआ कि व्यापारिक काराज यानी हुण्डियां भी दो-तिहाई घट गईं। जब काराज कम हुआ तो उसके बजाय और कुछ काम में लाना जरूरी होगया और सरकारी काराज यानी सिक्योरिटिज वगैरा की ज्यादा चाह हुई। इनकी भी बड़ी कमी होगई। व्यापार और उद्योग की मन्दी के कारण नये हिस्से और सिक्योरिटियां नहीं निकलीं और पुरानी सिक्योरिटियों की कीमत पहले से आधी या उससे भी कम होगई। अब भी भाव बारबर गिर रहे हैं और यदि इस गिरावट को रोकने की कोई बात न हुई तो सम्भव है अन्त में कुछ भी मूल्य न रहे !

इस तरह व्यापारिक और सरकारी दोनों तरह के काराज कम होगये हैं। फिर भी सरकारी और खानगी कर्जों पर चुकाया जानेवाला व्याज तो ज्यों-का-त्यों बना हुआ है। ऋणी देशों की जान बड़ी आफ़त में है कि वे क्या करें और कैसे चुकावें ? चूंकि अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान के लिए और कोई साधन नहीं है। इसलिए खास-तौर पर गरीब देशों में सोने की मांग बढ़ गई। फिर भी इन देशों से सोना धनी देशों में बहा चला जा रहा है, क्योंकि गरीब देशों के पूंजी वाले लोगों ने सिक्के का भाव बदलता और गिरता हुआ देखकर अपने रुपये की रक्षा करने के लिए विदेशी सरकारी पुर्जा खरीद लिया। इस तरह धनी देशों में सोना बढ़ता जा रहा है और गरीब मुल्कों में कम होता जा रहा है। जिन देशों के पास सोना खूब जमा होगया है वे हैं संयुक्तराष्ट्र, फ़्रांस, स्वीजरलैण्ड और हालैण्ड। इंग्लैण्ड के पास भी अब तो काफ़ी सोना इकट्ठा होगया है।

लेकिन इतना सोना और धन इकट्ठा होने पर और उद्योग के नये-से-नये साधनों के होते हुए भी अमेरिका को बहुत सहायता नहीं मिली, क्योंकि मन्दी के साथ-साथ वहाँ

संयुक्तराष्ट्र के प्रतिनिधि ने घबराई हुई दुनिया की बात कही और बताया कि राष्ट्रों के लिए “आर्थिक एकान्तवास की नीति इस्तिथार करना बेवकूफी और सबका संन्यासियों की तरह अलग-अलग जिन्दगी बसर करना फ़िजूल है।” ज्यों ही लच्छेदार भाषण ख़त्म हुए, कठिनाइयाँ सामने आने लगीं। अमेरिका ने युद्ध-ऋण के सवाल पर परिषद् में चर्चा करने से इन्कार कर दिया। यह मामला ख़ानगी चर्चा का था। परिषद् पर पहला प्रहार तो यह हुआ। फिर सोने से अलग हुए सिक्कों यानी पाउण्ड और डालर का भाव मुक़रर करने के सवाल पर अपनी-अपनी स्थिति अच्छी बनाने के लिए अमेरिका, इंग्लैण्ड और फ़्रांस के बीच में चालबाजियाँ शुरु हुई। फ़्रांस और सोने के विनिमय वाले बाक़ी के देश खींच-तान करके अपना काम चला रहे थे, क्योंकि पाउण्ड और डालर सोने के विनिमय से अलग थे और वे चाहते थे कि इन दोनों सिक्कों का भाव स्थिर होजाय। लेकिन अमेरिका और इंग्लैण्ड तत्काल अपने-आपको किसी तरह बाँधना नहीं चाहते थे और एक-दूसरे के पतरे ध्यान से देख रहे थे। इन सब कार्रवायों से परिषद् का कबाड़ा बैठ गया। सहयोग का प्रयत्न विफल होगया। अब हर देश अलग-अलग दूसरों का ख़याल किये बिना, संन्यासी की तरह रहकर और सम्भवतः स्वावलम्बी अर्थनीति बनाकर, संकट का सामना करने की कोशिश करेगा। पूँजीवाद के कुछ नेताओं ने ही यह भविष्यवाणी की है। मगर तिस्रों परिषद् के असफल हो जाने से ही न तो पूँजीवाद की इमारत एकदम नष्ट-भग्न हो जायगी और न व्रान्ति फैल जायगी। लेकिन इसमें कोई शक़ नहीं कि इस नाकामयाबी ने पूँजीवाद की पीठ पर एक और लात जमाई है और अब उसका आगे का रास्ता ख़न्दक की तरह जारहा है।

जर्मन सरकार ने पहले ही सार्वजनिक रूप में कह दिया कि उसकी स्थिति सरकारी या ख़ानगी किसी भी तरह का ऋण चुकाने की नहीं है। उसने लम्बी मियाद मांगी है; लेकिन वह शायद ही भुगतान कर सके। उस तरह जर्मनी की इस कार्रवाई का मतलब न देने के ही बराबर है। इससे उसके साहूकारों की विकट स्थिति होगई है, क्योंकि कभी-कभी कर्जदारों का दिवाला निकलने से कर्ज देनेवालों पर भी आश्रत आजाती है। १९३१ में जर्मनी में उथल-पुथल होने से ही तो इंग्लैण्ड को सोने का विनिमय छोड़ना और पाउण्ड को गिरना पड़ा था।

ब्रिटिश नीति साफ़ तौर पर आर्थिक राष्ट्रीयता की नीति बन चुकी थी। ब्रिटिश अर्थ-मन्त्री कहता है—“हमें अपने देश और साम्राज्य के हितों का ख़याल रखकर स्वतंत्र मार्ग का अन्सरण करते रहना चाहिए।” उसने पाउण्ड के नोट की सोने या डालर के साथ मिलाने से इन्कार कर दिया। अमेरिका के लिए फिर भी कुछ मुमकिन है, लेकिन इंग्लैण्ड के लिए स्वावलम्बी होना मुमकिन नहीं है। इंग्लैण्ड अपने लिए बाक़ी ख़ास-

घटाने से इंग्लैण्ड नाराज हुआ, क्योंकि इससे सोने का विनिमय छोड़कर उसने पाउण्ड के लिए जो सहूलियत हासिल करली थी वह जाती रही। अमेरिका के सोने का विनिमय छोड़ने से फ्रांस को भी बहुत बुरा लगा, क्योंकि उस वक़्त फ्रांस ही एकमात्र ऐसा बड़ा देश था जो सोने के विनिमय पर क़ायम था। उसके लिए भी अब उसपर क़ायम रहना मुश्किल होगया। अगर अमेरिका और इंग्लैण्ड जैसे दूसरे बड़े-बड़े देश अपना-अपना सोना छाती-तले दबाकर बैठ जायें और उसे बाहर न निकलने दें तो जिन लोगों के पास फ्रांस के नोट थे वे उसके बदले में सोना मांगते तो उन सबको फ्रांस कहाँ-तक सोना दिये चला जाता ?

सब पश्चिमी देशों में भविष्य के बारे में शंका और अनिश्चितता फैली हुई थी। युद्ध-ऋण का मामला अभीतक तय न होने से वह और भी बढ़ गई थी। प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक परिषद् से ऐसा लगता था कि कोई रास्ता निकल आया—शायद वहाँ कुछ हो सके और आपस की स्पर्धा और गला दवाने की वृत्ति रोकने के लिए कोई समझौता होजाय। परिषद् में इकट्ठे होकर असफल होना जोखम की बात थी। क्योंकि फिर तो सहयोग की अन्तिम आशा के नष्ट होने की भी सम्भावना थी। एक मशहूर अमेरिकन अर्थशास्त्री ने कहा था कि यह परिषद् सफल न हुई तो सारी पूँजीवादी इमारत चूर-चूर हो जायगी। एक ब्रिटिश मन्त्री ने कुछ इस तरह की बात कही थी कि परिषद् कामयाब न हुई तो निराशा, प्रतिक्रिया और विद्रोह होगा। जोखम तो बड़ी थी, क्योंकि कोई सम्मिलित योजना दिखाई नहीं देती थी। लेकिन जोखम उठाने के सिवाय कोई चारा भी न था। रैमसे मैकडॉनल्ड ने कहा, “यह हालत नहीं रहने दी जा सकती। कोई-न-कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा।”

यह भी बात नहीं थी कि यह अन्तर्राष्ट्रीय परिषद् अपने ढंग की पहली ही परिषद् हो। महायुद्ध के बाद न जाने कितनी परिषदें हो चुकी हैं। असल में यह परिषदों का ही युग है। लड़ाई के बाद २७ अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक परिषदें हो चुकी थीं। यह २८वीं परिषद् होनेवाली थी। घटना-चक्र और आधुनिक उद्योग के विकास से मजबूर होकर संसार को अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग ढूँढना पड़ता है। इसके लिए बार-बार कोशिश की जाती है, लेकिन वह कामयाब नहीं होती, क्योंकि पूँजीवादी समाज का पैतृक संस्कार ही साफ़ तौर पर ऐसा है कि उसमें ऐसे सहयोग की गुंजायश नहीं रहती। परिषदें प्रस्ताव बड़े अच्छे-अच्छे कर देती हैं, मगर बाद में उनपर अमल कुछ भी नहीं होता। अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की नाकामयाबी की सबसे बड़ी मिसाल राष्ट्र-संघ से मिलती है।

१६ जून १९३३ को अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक परिषद् बड़ी शान-शौकत के साथ लन्दन में शुरू हुई। ६६ देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। जोरदार भाषण दिये गये।

चुंगी न लगाने के विरोध में हिन्दुस्तान में तीव्र भावना रही है। इसका एक कारण राजनैतिक भी हो सकता है, लेकिन साथ ही यह भावना भी है कि दूसरे विदेशी राष्ट्रों के साथ व्यापार बन्द करके सिर्फ ब्रिटिश व्यापार के भरोसे रहना हमारे लिए हानिकर है। फिर भी दिल्ली की मौजूदा व्यवस्थापिका सभा ने, जो भारतीय जनता की प्रतिनिधि नहीं है, ओटावा के समझौते का समर्थन कर दिया। इसका एक नतीजा यह हुआ कि भारतवर्ष में आनेवाले दूसरे विदेशी माल के मुकाबिले में ब्रिटिश माल के भाव घट गये, क्योंकि दूसरे देशों के माल पर बन्दरगाहों पर अधिक कर ले लिया जाता है। इस सुविधा का फायदा सरकार और ब्रिटिश-उद्योग ने ब्रिटिश माल के बहिष्कार के भारतीय आन्दोलन को दबाने में उठाया।

एक वर्ष के अनुभव ने बता दिया है कि ओटावा-नीति सफल नहीं हुई और उपनिवेशों और इंग्लैण्ड के बीच में और खास तौर पर कनाडा के साथ बड़ा संघर्ष है, क्योंकि कनाडा बढ़ते हुए उद्योगवाला देश है और संयुक्तराष्ट्र के साथ उसके गहरे ताल्लुकात हैं। ब्रिटिश उद्योग की कुछ शाखाओं की कुछ हानि भी हुई ही है और चारों तरफ चुंगी की दीवार खड़ी हो जाने से चीजों के भाव बढ़ गये हैं और निर्वाह का खर्च अधिक होगया है। इस तरह ओटावा-नीति बहुत सफल नहीं हुई। हाँ, उससे कुछ उद्योगों का भार अस्थायी रूप से हलका होगया, लेकिन ब्रिटिश राज्य की परेशानी बढ़ाने के लिए जापान ने साम्राज्य की मण्डियों पर जोर से धावा कर दिया है। उसने हिन्दुस्तान, आस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैण्ड तक को नहीं छोड़ा है। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि किस तरह जापान ने मंचूरिया और चीन में जबरदस्ती की और जान-बूझकर राष्ट्र-संघ की अवज्ञा की। जापान ऐसा कर सका, इसका बड़ा कारण यह था कि उसे गुप्त रूप से इंग्लैण्ड की सहायता मिल गई। अप्रत्यक्ष रूप से जापान को इंग्लैण्ड और अमेरिका की प्रतिस्पर्धा से भी मदद मिली। अमेरिका ने जापान की जबरदस्ती के खिलाफ कड़ा रुख दिखाया था। मगर इंग्लैण्ड की दुर्भाग्य नीति देखकर उसे भी नरम पड़ जाना पड़ा। जापान पर इससे भी बड़ी विपत्ति अपने घरेलू आर्थिक झगड़ों और पूँजी-सम्बन्धी संकट के कारण आई। जापान के सिक्के येन का भाव तेजी से गिरा और जापानी माल सस्ता हो गया। इसका फायदा उठा कर विदेशी मण्डियों को विदेशी माल से भर दिया गया। यह माल इतना सस्ता था कि चुंगी की दीवारें भी न रोक सकीं। इस सस्तेपन के कारण ही जापानी माल के चीनी बहिष्कार-आन्दोलन की कमर टूटी। पूर्व की तारी मण्डियों और दक्षिण अफ्रीका और आस्ट्रेलिया में भी जापानी माल की भरमार होगई। इंग्लैण्ड में जाकर कुर्ता एक शिलिंग में और मोझे दो पैसे में बिकने लगे। जर्मनी को भी बड़ा धक्का लगा। ऐसे भावों से स्पर्धा करना बिल्कुल नामुमकिन

सामग्री पैदा नहीं करता और उसके कारखानों के लिए कच्चा माल बाहर से आता है। इसी कारण वह मुक्त-व्यापार पर क्रायम रहा और उसने अपने यहाँ बाहर का माल बिना चुंगी लगाये या बहुत थोड़ी चुंगी लगाकर आने दिया था। संसार के व्यापार और उसके अपने व्यापार में रस्ताकशी होने और साधारण तौर पर मौजूदा संकट के कारण उसे मजबूरन मुक्त-व्यापार की नीति छोड़कर विदेशी माल पर चुंगी लगानी पड़ी। यह सरकारी आमदनी बढ़ाने और कम-से-कम ब्रिटिश माल के लिए घर के बाजार की रक्षा करने के लिए किया गया है। इससे भी ज्यादा बड़ी कोशिश की गई है पाउण्ड के नोटों के भाव के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य को एक ही आर्थिक इकाई बना देने का। साम्राज्य काफ़ी बड़ा है। उसमें तरह-तरह के देश शामिल हैं और वे इंग्लैंड के लिए काफ़ी ख़ूराक और दूसरी सामग्री पैदा करते हैं। इसलिए सिद्धान्त-रूप से तो साम्राज्य को स्वावलम्बी बनाना मुमकिन था ही। इतना बड़ा प्रदेश, जिसमें पाउण्ड के नोटों का विनिमय और सब तरफ़ से सुरक्षित बाजार हो, इंग्लैंड के लिए बड़ी सहूलियत की बात है। डालर या फ़्रांक के बारे में पाउण्ड का भाव बढ़ और घट सकता है, लेकिन इससे उस प्रदेश में कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता जहाँ पाउण्ड रुपये जैसे स्थानीय सिक्के के साथ बँधा हो।

इस ख़याल को ध्यान में रखकर ओटावा (कनाडा) में ब्रिटिश साम्राज्य की एक परिषद् की गई। इस परिषद् में जल्दी ही यह बात सामने आ गई कि साम्राज्य के देशों को बाक़ी के संसार से अलग करके एक इकाई बना देना इतनी आसान बात नहीं है। रुपये के या और किसी मामले में हिन्दुस्तान को दबाकर उससे कुछ भी करा लेना इंग्लैंड के लिए बहुत आसान था; लेकिन कनाडा, आस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ़्रीका केवल 'मातृदेश' के फ़ायदे के लिए कुछ भी त्याग करनेवाले नहीं थे। दक्षिण अफ़्रीका तो बाद में भी कुछ समय तक सोने के विनिमय पर क्रायम रहा (वह सोना पैदा करने वाला देश है) और पाउण्ड के नोट के विनिमय में शामिल नहीं हुआ। ओटावा में भाव-न्ताव और लेन-देन की बातें ख़ूब हुईं और अगर इंग्लैंड उपनिवेशों की माँगें मंज़ूर न कर लेता तो परिषद् के भंग होने की नौबत आ पहुँची थी। अपने उद्योगों को थोड़ी हानि पहुँचाकर भी उसे ऐसा करना पड़ा। उसे राज-नैतिक और साम्राज्य संबंधी कारणों से प्रभावित होना पड़ा, क्योंकि परिषद् को भंग करने से जो हानि होती उसे वह बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उससे साम्राज्य को बड़े जोर का आघात पहुँचता। इसलिए जहाँ तक मुमकिन हो साम्राज्य के माल को तरजीह देने और विदेशी सामान न आने देने की बात तय पाई। जबसे यह सवाल छिड़ा है तभीसे ब्रिटिश माल को तरजीह देने यानी उसपर कम चुंगी लगाने या

: १८६ :

स्पेन में क्रान्ति

२९ जुलाई, १९३३

अब मैं तुम्हें व्यापारिक मण्डी और कथित संकट की लम्बी कहानी से दूर ले चलूंगा। यह संकट जैसा होना चाहिए, वैसा इधर या उधर फैसला कर देनेवाला नहीं साबित हुआ। यह तो जमकर बैठ गया और क़रीब-क़रीब हमारा साथी बन गया। इससे तुम्हें हटाकर मैं पिछले दो वर्ष की दो प्रमुख घटनाओं का हाल कहूंगा। ये दो घटनाएँ हैं स्पेन की क्रान्ति और जर्मनी की प्रति-क्रान्ति।

योरप का दक्षिण-पश्चिम का कोना स्पेन और पुर्तगाल से मिलकर बनता है। योरप के पुराने इतिहास में इन्होंने महत्वपूर्ण भाग लिया है। इन ख़तों के दौरान में इसकी कुछ झलक हम देख चुके हैं। अरबों का लम्बा और तेजस्वी ज़माना और काँडोंबा और ग्रेनाडा के गौरव; साहसी नाविकों की प्रसिद्ध जल-यात्रायें; पोप द्वारा इन दोनों में संतार का बँटवारा और अमेरिका और ईस्ट-इण्डिया द्वीपों में साम्राज्यों की स्थापना; इस विस्तृत साम्राज्य के बन्दरगाहों और पूर्व के व्यापार से बहकर आनेवाली दौलत; कुछ असें के लिए योरप में उनकी प्रभुता और स्पेन के ख़िलाफ़ नेदरलैण्ड्स की आज़ादी की लड़ाई; और फिर सम्राज्य का पतन और नाश—इन सबका थोड़ा-थोड़ा हाल हम देख चुके। इस दक्षिण-पश्चिम के कोने पर पश्चिमी योरप के उद्योगवाद का बहुत ही कम असर हुआ और वह दरिद्र और पिछड़ा हुआ रहा। पादरियों का प्रभाव खूब रहा। स्पेन और पुर्तगाल दोनों का शासन कमोवेश निरंकुश राजाओं के हाथ में था और व्यवस्थापिका सभायें बहुत कमज़ोर थीं। स्पेन की व्यवस्थापिका सभा 'कोर्टे' कहलाती है। १८७० के आसपास थोड़े समय तक स्पेन में प्रजातन्त्र रहा था। लेकिन वह कामयाब नहीं हुआ और राजा किसी-न-किसी तरह फिर वापस आगया। १८९८ में क्यूबा के मामले में स्पेन की अमेरिका के संयुक्तराष्ट्र से लड़ाई हुई, उसमें वह अपना आखिरी उपनिवेश भी खो बैठा। क्यूबा आज़ाद होगया और फिलिपिन लोगों की ज़बरदस्त मुख़ालफ़त होते हुए भी अमेरिका ने फिलीपाइन टापुओं पर क़ब्ज़ा कर लिया। जहाँतक मुझे याद पड़ता है, सिर्फ़ मोरक्को में स्पेन के प्रभाव में एक प्रदेश है। और कोई उसका उपनिवेश नहीं है।

पुर्तगाल ने किसी-न-किसी तरह न सिर्फ़ गोवा-जैसे हिन्दुस्तान के छोटे-छोटे टुकड़े ही बल्कि अफ़्रीका के ये बड़े-बड़े उपनिवेश भी अभीतक अपने क़ब्ज़े में कर रखे हैं। १९१० में राजा को गद्दी से उतारकर वहाँ प्रजातन्त्र क़ायम हुआ। उस वक़्त ते

था। ब्रिटिश कारखानेदारों ने इस जापानी स्पर्धा को 'आर्थिक खतरा' बताया। हिन्दुस्तान में इसके खिलाफ बड़ा शोर-गुल मचा और जापानी माल पर नये और भारी कर लगा दिये गये। बदले में जापान जो हिन्दुस्तानी रुई खरीदता था वह उसने खरीदना बन्द कर दिया। इससे रुई पैदा करनेवाले हिन्दुस्तान के किसानों की हानि होगई।

जापानियों ने इस भयंकर रूप में भाव घटाने की क्या युक्ति की? प्रथम तो येन का भाव गिर गया। दूसरे वहाँ के कारखानों में काम करनेवाली मजदूर लड़कियों को मजदूरी बहुत कम दी जाती है। तीसरे जापानी सरकार उद्योगों को मदद देती है। और चौथे जापान की जहाजी कम्पनियाँ थोड़ा भाड़ा लेकर मदद करती हैं। लेकिन यह भी मानना होगा कि जापानियों ने व्यवसाय और उद्योग में अपनी योग्यता का भी परिचय दिया है और वे सस्ती ही नहीं अच्छी चीजें भी बना रहे हैं। यह बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि पुराने ब्रिटिश कारखाने अब बहुत पिछड़ गये हैं और उनकी मशीनें भी नई नहीं हैं। अलवत्ता नरुली रेशम और मोटर के नये उद्योग योग्यतापूर्वक चलाये जा रहे हैं। भारतीय उद्योगों की व्यवस्था आमतौर पर अच्छी नहीं होती।

जैसे-जैसे यह भयंकर जापानी लाग-उांट बढ़ती जा रही है, वैसे-वैसे दूसरे देश और विशेषतः ब्रिटिश साम्राज्य के देश अपनी मण्डियों का दरवाजा उसके लिए बन्द करते जा रहे हैं। अगर जापानी माल का इस तरह बहिष्कार किया जायगा तो जापान क्या करेगा? उसके महान् उद्योग नष्ट हो जायंगे और सारी आर्थिक व्यवस्था चौपट हो जायगी। यह बात दूसरी है कि उसे चीन के भीतरी हिस्से में उतना ही बड़ा बाजार मिल जाय। लेकिन इसकी सम्भावना बहुत कम है। वस इसी तरह की नाशकारी स्पर्धा पूँजीवादी प्रणाली में चलती रहती है। कि इससे झगडे होते हैं। आर्थिक प्रतिशोध की कारंवाइयाँ होती हैं और अखीर में युद्ध तक छिड़ जाता है। (आर्थिक प्रतिशोध की कारंवाइयाँ तो हम हिन्दुस्तान में भी देख रहे हैं।)

इसी तरह अगर ब्रिटेन के घरू बाजार का दरवाजा योरप के दूसरे मुल्कों के लिए बन्द कर दिया जाय तो उससे भी इनमें से कई देश बरबाद ही होजायेंगे। इसतरह हम देखते हैं कि हर देश अपने ही भले के लिए जो उपाय कर रहा है उनसे दूसरे देशों को और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को हानि पहुँचती है और संघर्ष और झगड़ा पैदा होता है।

मध्यमवर्ग है और अबतक इस वर्ग ने नागरिक प्रजातंत्र को कायम रक्खा है। स्पेन के मध्यमवर्ग के लोकशाही शासन के इतने अधिक दिन तक जीवित रहने का तीसरा कारण यह है कि इसने कृषि-सुधार को समस्या को जरा उत्साह के साथ हाथ में लिया है और इस तरह किसानों को थोड़ा आराम पहुँचाया है। लेकिन यह सब कुछ होते हुए भी आज स्पेन में मौलिक अस्थिरता दिखाई देती है। दमन खूब है—और चाहे स्पेन को लेलो, चाहे भारत या और किसी देश को लो, बड़े पैमाने पर होनेवाला दमन सदा इस बात का चिन्ह होता है कि शासन-यंत्र में डर घुस गया है और उसे अपनी स्थिरता का भरोसा नहीं रहा है।

स्पेन की मौजूदा सरकार उग्र दल की उदार लोकसत्ता बताई जाती है और उसपर समाजवाद की हल्की-सी छाप है। प्रधानमंत्री मेनेल अज्ञाना सरकार और देश का सबसे ताकतवर आदमी समझा जाता है। राष्ट्रपति अलकला ज़मोरा है। अज्ञाना खुद समाजवादी नहीं है, मगर स्पेनिश पार्लमेण्ट यानी 'कोर्टे' में समाजवादी दल उसका साथ देता है। यह दल सबसे सबल और सुसंगठित है। इस दल की पीठ पर मजदूर-सभायें हैं और समाजवाद में मार्क्स का अनुयायी होने पर भी यह दल साम्यवाद का विरोधी है। साम्यवादी दल स्पेन में कमजोर है, परन्तु अराजकतावादियों का दल शक्तिशाली है। ये लोग 'अराजक संघवादी' (Anarcho-Syndicalists) कहलाते हैं।

मैंने तुम्हें किसी पिछले खत में बताया था कि किस तरह उद्योगवाद में पिछड़े हुए दक्षिणी योरप के देशों में अराजकतावाद की वृद्धि हुई। इसके साथ बम फेंकने वगैरा के कामों को न मिला देना। इंग्लैण्ड और जर्मनी में मजदूर-आन्दोलन का निर्माण श्रमजीवी-संघ के ठोस ढंग पर हुआ था और इटली और स्पेन में अराजकतावाद के विचार अधिक फैले थे। कार्ल मार्क्स और बकूनिन का पुराना झगड़ा इसी विषय पर हुआ था और बकूनिन को अधिकांश अनुयायी दक्षिण से मिले थे। इसी विषय को लेकर मार्क्स ने बकूनिन को प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ में से निकलवा दिया था। परन्तु अराजकतावाद और किसी देश से स्पेन में अधिक रहा। पूर्वी समुद्र-तट पर बार्सिलोना में इसका ज्यादा जोर है। जनवरी १९३३ में अराजकतावादियों का एक बड़ा विद्रोह हुआ; मगर वह दबा दिया गया।

यह बात पूरी तरह स्पष्ट नहीं है कि ये अराजक-संघवादी लोग क्या चाहते हैं। कम-से-कम में तो उन्हें या उनकी नीति को समझ नहीं पाया। मुझे वह निरर्थक मालूम होती है। उनके सिवा स्पेन में दो तरह के विचारों के लोग और हैं। इनमें से एक के हाथ में इस वक्त सत्ता है। यह उदार लोकसत्ता की मंजिल पार करके धीरे-धीरे समाजवाद तक पहुँचना चाहता है। दूसरा दल पूरे समाजवाद या समूहवाद

वहाँ कई विद्रोह हुए। राजा के दल वाले राजा को वापस लाने की कोशिश करते रहे और उग्र दल के समाजवादों और दूसरे लोग सर्वोच्च शासकों और प्रतिगामी सरकारों से पिण्ड छुड़ाने का प्रयत्न करते रहे। मगर प्रजातन्त्र किसी-न-किसी रूप में अवतक चला आ रहा है। उसपर आम तौर पर सैनिक दल का क़ायम रहा है। महायुद्ध में पुर्तगाल ने इंग्लैंड, फ़्रांस और उसके साथियों की तरफ़दारी की थी और उसमें से वह बड़ा भारी फ़र्ज़ा मोल लेकर निकला था। नतीजा यह हुआ कि उसका दिवाला निकल गया। १९२६ से इस देश का कर्ता-धर्ता और सैनिक शासक जनरल फ़ार्मोना है। वहाँ विद्रोह होने की ख़बरें बहुत बार उड़ती हैं। जब मैं ये पंक्तियाँ लिख रहा हूँ, वैसा ही समाचार फिर निकला है। इससे यह जाहिर है कि मौजूदा शासन में स्थिरता नहीं है।

मैं पिछले ख़त में लिख चुका हूँ कि स्पेन में भी प्राइमो-द-रिवेरा के हाथ में सारी सैनिक और शासन की सत्ता थी। यह व्यवस्था मोरक्को में अब्दुलकरीम के खिलाफ़ जंग में बार-बार हार खाने के बाद क़ायम हुई। आख़िरकार उसके स्थान पर स्पेन का प्रजातन्त्र क़ायम हुआ। पुराने एकतन्त्र शासन की इमारत पूरी तरह जर्जर हो-चुकी थी और रूस की ज़ारशाही की तरह वह भी दुश्मन से लोहा लिये बिना ही चूर-चूर होगई। यहाँ का राजा बूर्बन और हैप्सबर्ग दोनों राजवंशों की सन्तान था। जब अप्रैल १९३१ में म्युनिसिपल चुनाव में प्रजातन्त्रवादियों की ज़बरदस्त जीत हुई तो इतने ही से डरकर राजा भाग गया। इस क्रान्ति की तारीख़ १४ अप्रैल १९३१ थी। उसी दिन वहाँ अस्थायी सरकार क़ायम होगई।

स्पेन की यह क्रान्ति मार्च १९१७ वाली रूस की पहली क्रान्ति से बहुत मिलती-जुलती है। दोनों ही जगह क्रान्ति सामन्तशाही का सफ़ाया करने के लिए देर से होने-वाली कोशिश थी और उसके लिए ख़ास जोर दुःखी और असन्तुष्ट किसानों ने लगाया था। क्रान्ति के बाद भी स्पेन की हालत वैसी ही हुई जैसी १९१७ के मार्च और नवम्बर की दोनों क्रान्तियों के बीच में रूस की हुई थी। स्थिरता के कहीं दर्शन नहीं होते और अलग-अलग वर्ग अपनी खिचड़ी अलग-अलग पकाते रहे। क्रान्ति के विरोध में विद्रोह हुए और दवा दिये गये। यह हाल उग्र दल के विद्रोहों का हुआ है। स्पेन का अन्त क्या होगा, यह कहना मुश्किल है। मगर रूस की समानता से यह विचार ज़रूर होता है कि शायद यहाँ भी दूसरी क्रान्ति होगी और शासन-सूत्र मजदूरों और किसानों के हाथ में आजायगा। मुमकिन है कुछ वर्ष तक यह न भी हो। रूस में जो घटना-चक्र इतनी तेज़ी से चला उसका कारण यह था कि उस वक़्त महायुद्ध जारी था और उससे बहुत बरवादी और कष्ट हुआ था। स्पेन में रूस से भी अधिक बलशाली

कि जून १९३३ में उसने अज्ञाना को प्रधान मंत्री के पद से मौकूफ कर दिया। परन्तु अज्ञाना की जगह लेने के लिए कोई नहीं था, इसलिए वह प्रधान मंत्री बनकर फिर लौट आया।

दूसरी यानी किसानों की समस्या हल होना अभी बहुत दूर की बात है। सरकार का यह इरादा था कि जिन जमींदारों की जमींदारी छीनी जाय उन्हें मुआवजा दे दिया जाय और जितनी बड़ी जमींदारी हो उतना ही कम मुआवजा दिया जाय। यह क्रिया बहुत धीरे-धीरे हुई और रूस की तरह दूर-दूर के किसानों ने कानून अपने हाथ में लेकर जमींदारियों पर कब्जा कर लिया। इससे सरकार को बड़ा धक्का पहुँचा और उसने जल्दी से कानून बना डाले। उसके सौभाग्य से ठीक उसी समय राजा के पक्ष में एक विद्रोह होगया और उसमें बहुत-से बड़े-बड़े सरदारों, उमरावों और जमींदारों ने हिस्ता लिया। विद्रोह आसानी से दबा दिया गया और जिन लोगों ने विद्रोह में भाग लिया था उनकी जायदादें जब्त करने का सरकार को अच्छा वहाना मिल गया। कुछ और बड़ी-बड़ी जायदादें छीन ली गईं, क्योंकि “वे अनियमित ढंग पर पैदा हुई थीं।” फिर ये छीनी हुई जमींदारियाँ किसानों को वाँट दी गईं।

इन सब बातों के बावजूद अब भी बड़ी-बड़ी खानगी जायदादें हैं और राज्य का साधारण आर्थिक नियन्त्रण अनुदार लोगों के हाथ में है। अभी तक इस मूल आर्थिक समस्या को सुलझाने की बात सरकार टालती रही है।

शिक्षा-सम्बन्धी कार्यक्रम में अच्छी प्रगति हुई है और १९३३ के शुरू तक १० हजार नई पाठशालायें बन चुकी हैं।

सरकार के सामने एक मुश्किल सवाल केटेलोनिया का था। यह पूर्वी समुद्र-तट का एक प्रान्त है। वासिलोना इसकी राजधानी है और अराजकतावाद का यहाँ अड्डा है। मुद्दत से इस प्रान्त ने अलग रहने का आन्दोलन किया है और जब स्पेन में प्रजातन्त्र हुआ तो केटेलोनिया ने अपने अलग प्रजातन्त्र की घोषणा कर दी। परन्तु मालूम होता है केटेलोनिया को स्पेन के प्रजातन्त्र के अधीन बहुत कुछ स्वशासन देकर समझौता कर लिया गया है।

इस तरह पुराना और कछुए की चाल चलनेवाला स्पेन दिन-दिन तेजी के साथ बदल रहा है। पादरियों का असर जाता रहा, उमरावों की शक्ति बिल्कुल क्षीण होगई और सामन्तशाही विलीन हो रही है। खेती-सम्बन्धी सुधारों से किसानों के कष्ट कुछ कम हुए हैं, परन्तु उन्हें सन्तुष्ट करने के लिए अभी बहुत कुछ करना बाक़ी है। सवाल यह है कि मध्यम वर्ग का लोकशाही प्राजातन्त्र इस सुधार-कार्यक्रम को जारी रख सकेगा या दूसरी क्रान्ति और होगी और नये सिरे से काम शुरू करना पड़ेगा ?

(Collectivism) की तरफ़ सीधा ही बढ़ना चाहता है और नये सिरे से काम शुरू करना चाहता है ।

स्पेन के नये विधान में कुछ दिलचस्प बातें हैं । व्यवस्थापिका सभा यानी 'कोर्ट' एक ही है और सभी वालिस स्त्री-पुरुषों को राय देने का हक़ हासिल है । खास बात यह है कि राष्ट्र-संघ की मंजूरी के बिना राष्ट्रपति को लड़ाई का ऐलान करने की मनाई है । जितने अन्तर्राष्ट्रीय नियम राष्ट्र-संघ में बनते हैं और स्पेन द्वारा मंजूर कर लिये जाते हैं वे तुरन्त स्पेन का क़ानून बन जाते हैं और अगर कोई निश्चित क़ानून उनके विरुद्ध पहले से होता है तो वह भी रद्द होजाता है ।

शुरू-शुरू में जो क़ानून बने उनमें यह बात भी थी कि किसी व्यक्ति या कुटुम्ब के अधिकार में २५ एकड़ से ज्यादा आवपाशी की ज़मीन नहीं रह सकती, और यह भी उसी वक़्त तक रह सकती थी जबतक कि उम्रमें काश्त होती रहे । करखानों में मजदूर-समितियों को अधिकार दिया गया था कि कुछ बातों में वे कारख़ानों की व्यवस्था पर भी देखरेख़ रखें । ख़ानगी ठेके उठाकर उनपर राज्य का अधिकार कर दिया गया । ३ वर्ष में २८ हजार नई पाठशालायें खोलने का शिक्षा-सम्बन्धी बड़ा कार्यक्रम तय किया गया । मजदूरों के लिए कम-से-कम इतनी मजदूरी मुक़रर करदी गई कि वे सुख से रह सकें ।

ये और बहुत-से और क़ानून बन तो गये, मगर सबपर अमल नहीं हुआ । फिर भी इसमें सन्देह नहीं कि पिछले दो सालों में बहुत कुछ हुआ है । प्रजातन्त्र ने जो दो बड़ी समस्याएँ हाथ में लीं वे हैं चर्च की ओर किसानों की ।

स्पेन सदियों से एक ऐसा देश रहा है जहाँ कैथलिक (सनातनी ईसाई) सम्प्रदाय का जोर है । ईसाई-धर्म में आस्था न रखनेवालों को दण्ड देनेवाले न्यायालय—'इनक्विज़िशन'—यहींसे शुरू हुए थे । जेसुइटपंथ का प्रवर्तक भी एक स्पेनी ही था । सभी कार्यों में चर्च यानी पादरियों का असर रहता था । सबसे ज्यादा असर शिक्षा-प्रणाली पर था और यह ज्यादातर उन्हींके नियन्त्रण में रहती थी । प्रजातन्त्र ने शिक्षा पर से यह पुराना पंजा हटा दिया । कोर्ट ने गिरजाघरों की ५० करोड़ डालर की सम्पत्ति को राष्ट्र की सम्पत्ति बना दिया और ८० हजार साधुओं और साध्वियों का पाठशालाओं में पढ़ाने का अधिकार छीन लिया । विचार यह है कि १ जनवरी १९३४ तक सारी प्राथमिक और माध्यमिक पाठशालायें राज्य के हाथ में आजायें ।

इस नीति का कुदरती नतीजा रोम के पोप के साथ टक्कर होना था । पोप ने राष्ट्रपति को समाज-बहिष्कृत करने की ख़ुली धमकी दी और उसे इतना भय लगा

किसी पिछले ख़त में इटली का हाल लिखते हुए मैंने फ़ैसिज़्म की चर्चा की थी और बताया था कि यह उस समय क़ायम हुआ, जब आर्थिक संकट के ज़माने में पूँजीवादी राज्य को सामाजिक क्रान्ति का ख़तरा था। मालिक पूँजीवादी वर्ग ने सामूहिक आन्दोलन खड़ा करके अपनी रक्षा का प्रयत्न किया। इसके लिए शुरु में नीचे दर्जे के मध्यमवर्ग को साधन बनाया गया और भोले-भाले किसान और मजदूरों को आकर्षित करने के लिए भ्रम में डालनेवाले पूँजीवाद के विरोधी नारे इस्तेमाल किये गये। जब सत्ता और राज्य का नियंत्रण हाथ में आगया तो सारी लोकसत्तात्मक संस्थाओं का तफ़ाया होने लगा, दुश्मन कुचले जाने लगे और सभी मजदूर संस्थायें ख़ासतौर पर नष्ट-भ्रष्ट की जाने लगीं। इस तरह उनका शासन प्रधानतः हिंसा की दुनियाद पर खड़ा है। नये शासन में मध्यमवर्ग के समर्थकों को नौकरियाँ देदी गई हैं और आमतौर पर कारख़ानों पर राज्य का कुछ-न-कुछ नियंत्रण क़ायम होगया है।

हम देखते हैं और इसकी संभावना भी की जा रही थी कि जर्मनी में यह सब कुछ हो रहा है, लेकिन ताज़्जुब की बात तो यह है कि इसके पीछे कितनी ज़बरदस्त प्रेरणा है और कितने ज्यादा लोग हिटलर से जा मिले हैं।

नाज़ी प्रतिक्रिया पाँच महीने पहले यानी मार्च १९३३ में हुई। लेकिन मैं तुम्हें इस आन्दोलन के शुरू के हालात बताने के लिए थोड़ा पीछे ले जाऊँगा।

१९१८ की जर्मन क्रान्ति, सच कहा जाय तो, नक़ली चीज़ थी; वह कोई क्रान्ति नहीं थी। क्रँसर चला गया और प्रजातंत्र की घोषणा होगई। मगर पुरानी राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक प्रणाली बनी रही। कुछ वर्ष तक नरम मार्क्सवादियों यानी लोकसत्तात्मक समाजवादियों के हाथ में राज्य का नियंत्रण रहा। उन्हें पुराने प्रतिगामी और स्थायी स्वार्थ वाले लोगों का बड़ा डर था और वे सदा उनसे समझौता करने की कोशिश करते रहते थे। उनकी पीठ पर उनके दल के ज़बरदस्त संगठन का जोर था। लाखों सदस्य और श्रमजीवी-संघ उनके हाथ में थे और बहुत लोगों की सहानुभूति उनके साथ थी। लेकिन प्रतिगामी शक्तियों के सामने उनकी नीति सदा बचाव की रही। आक्रमणकारी ख़ूब तो उन्होंने अपने ही उग्र अंग और साम्यवादी-दल के प्रति रक्खा। उन्होंने अपने काम में इस बुरी तरह घोटाला किया कि उनके बहुत-से सहायकों ने उनका साथ छोड़ दिया। मजदूर उन्हें छोड़कर साम्यवादी-दल में मिल गये और कई लाख सदस्यों के होने से वह दल ख़ूब ताक़तवर बन गया। मध्यमवर्ग के मददगार प्रतिगामी दलों में जा मिले। लोकसत्तात्मक समाजवादियों (Social Democrats) और साम्यवादियों में बराबर आपस में ठनी रहती थी। इससे दोनों की ताक़त कमज़ोर होगई।

जर्मनी में नाज़ियों की जीत

३१ जुलाई, १९३३

स्पेन की क्रान्ति पर कुछ लोगों को ताज्जुब हुआ, लेकिन असल में ताज्जुब की कोई बात न थी। यह स्वाभाविक घटना-चक्र की बात थी और ध्यान से देखनेवाले लोग जानते थे कि यह होकर रहेगी। राजा, सामन्त और पादरियों की इस पुरानी इमारत में घुन लग चुका था और कोई बल बाक़ी नहीं रहा था। आज की परिस्थिति से उसका बिल्कुल मेल नहीं घँटता था और इस तरह पके फल की तरह हाथ लगते ही वह गिर पड़ी। हिन्दुस्तान में भी अभीतक पुराने जमाने की सामन्तशाही के बहुत-से खण्डहर बाक़ी हैं। उन्हें विदेशी सत्ता का सहारा न मिले तो वे शायद जल्दी ही मिट जायें।

लेकिन जर्मनी में हाल ही में जो परिवर्तन हुए हैं वे बिल्कुल दूसरी तरह के हैं; और उन्होंने वेशक योरोप को हिला दिया है और बहुत-से लोगों के होश उड़ा दिये हैं। हमारे लिए वे अभी इतने नजदीक की चीज़ हैं कि अभी उनके बारे में तटस्थ रहकर कोई राय नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि रोज़ नई-नई ख़बरें आती हैं और उनसे या तो खोज पैदा होती है या गुस्सा आता है। दूर से देखनेवाले को कुछ ऐसा मालूम होता है कि ज्यादातर जर्मनों का सिर फिर गया है। उनके हँवानी और जंगली व्यवहार का और कोई अर्थ ही नहीं समझ में आता। और यह कोई अर्थ भी नहीं। जर्मनों-जैसे सुसंस्कृत और बड़े ही उन्नत लोगों का इस तरह का वर्तव देखकर बड़ा आश्चर्य होता है।

हिटलर और उसके नाज़ियों की जर्मनी में जीत होगई है। उनको फ़ैसिस्ट कहा गया है और उनकी जीत प्रतिक्रान्ति की जीत बताई गई है, यानी १९१८ की जर्मन क्रान्ति के बाद जो हुआ उससे उलटी गंगा बह रही है। ये सब बातें बिल्कुल सही हैं और हिटलरशाही में फ़ैसिज्म के सारे तत्त्व, भयंकर प्रतिक्रिया और सारे उदार-दलों और खासतौर पर मजदूरों पर जंगली हमलों की प्रवृत्ति मिलेगी। फिर भी इसमें इटली के फ़ैसिज्म से बहुत कुछ बातें अधिक हैं। इसमें कोरी प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि यह कुछ अधिक विशाल और सामूहिक भावना पर आधार रखनेवाला आन्दोलन है। सामूहिक भावना अधिक लोगों यांनी श्रमिकों की नहीं है बल्कि उस मध्यमवर्ग की है जो भूखों मर रहा था, जिसके पास कोई अधिकार न रहे थे, और इसलिए जो क्रान्तिकारी बन गया था।

‘तूफानी दल’ (Storm Troops) के नाम से भूरे कुर्ते की बर्दी वाली एक लड़ाकू सेना भी संगठित की। इसीलिए जैसे इटली के फ़ासिस्टों को काली कुर्तीवाले कहते हैं, वैसे ही नाज़ियों को भी अक्सर भूरी कुर्तीवाले (Brownshirts) के नाम से पुकारते हैं।

नाज़ियों का कार्यक्रम न स्पष्ट था और न रचनात्मक। वह तीव्र राष्ट्रीयतावादी था और जर्मनी और जर्मनों की महानता पर जोर देता था। बाक़ी बातों में तो वह भिन्न-भिन्न विरोधी भावनाओं की खिचड़ी था। वसाई के मुलहनामे के खिलाफ़ तो वह था ही। उसे हर जर्मनी अपमानजनक समझता था। इसलिए बहुत लोग नाज़ियों की ओर आकर्षित हुए। यह कार्यक्रम मार्क्सवादियों, साम्यवादियों और समाजवादियों सबके खिलाफ़ था और मजदूर-संघों वगैरह का विरोधी था। यहूदियों से उसे ख़ास चिढ़ थी, क्योंकि यहूदियों को विदेशी जाति समझा जाता था और कहा जाता था कि वे जर्मनी की पवित्र आर्य नस्ल को बिगाड़ते हैं और उसके ऊँचे रहन-सहन को नीचा करते हैं। अस्पष्ट रूप से वह पूंजीवाद का विरोधी भी था, लेकिन बस इतना-सा ही कि मुनाफ़ा खानेवालों और धनवानों को गालियाँ देदी जायें। इन लोगों के दिमाग़ में अगर कोई समाजवाद की, और वह भी धुंधली-सी, कल्पना थी तो यह थी कि सार्व-जनिक सम्पत्ति पर राज्य का थोड़ा-बहुत नियन्त्रण होना चाहिए।

इन सब बातों के पीछे हिंसा की एक असाधारण विचार-धारा थी। हिंसा की प्रशंसा तो होती ही थी और उसे प्रोत्साहन भी दिया जाता था। हिंसा करना मनुष्य का सर्वोच्च कर्तव्य भी समझा जाता था। जर्मनी का एक मशहूर दार्शनिक, ऑस्वाल्ड स्पेंग्लर इस तत्त्वज्ञान का भाष्यकार हैं। वह कहता है—“मनुष्य शिकारी जानवर है, वीर, चालाक और निर्दय है” “आदर्श कायरता के चिन्ह हैं”... “प्रगतिमान जीवों का शिकारी पशु ही सबसे ऊँचा स्वरूप है।” वह कहता है कि “सहानुभूति, राजीनामा, और शांति ये दन्तहीन भावनार्य हैं और घृणा ही शिकारी पशुओं की सबसे सच्ची जातीय भावना है।” मनुष्य को सदा सिंह के समान होना चाहिए जो अपनी गुफ़ा में किसी दरादरीवाले का रहता कभी सहन न करे। उसे गाय की तरह दबू बनकर न रहना चाहिए, जो झुंड बनाकर रहती है और इधर से उधर हांकी जाती है। अवश्य ही इस प्रकार के मनुष्य के लिए युद्ध सबसे बड़ा और सुख देनेवाला काम होगा।

ऑस्वाल्ड स्पेंग्लर आज के बड़े-से-बड़े विद्वानों में एक हैं। उसने जो पुस्तकें लिखी हैं उनमें भरे हुए असाधारण पाण्डित्य को देखकर आश्चर्य होता है। और इस सारी विद्वत्ता से उसने ये विस्मयकारी और घृणापूर्ण परिणाम निकाले हैं! उसके उद्धरण मेंने इसलिए दिये हैं कि उनसे हमें हिटलरवाद के पीछे काम करनेवाली मनो-

जब लड़ाई के बाद के वर्षों में जर्मनी ने घटाघड़ नोट छापकर निकाले तो जर्मनी के कारखानेदारों और बड़े-बड़े जमींदारों ने इस कारंवाई का समर्थन किया। जमींदारों पर भारी कर्ज था और उनकी जायदादें गिरची रखी हुई थीं। सिके का उस समय प्रायः कुछ भी मूल्य न था। उनके कर्ज चुक गये और जायदादें फिर उनके कब्जे में आ गईं। बड़े-बड़े कारखानेदारों ने अपने यंत्र सुधरवा लिये और बड़ी-बड़ी कम्पनियां बना लीं। जर्मनी का माल इतना सस्ता होगया कि वह हर कहीं आसानी से बिकने लगा और बेकारी शायब होगई। श्रमजीवी-वर्ग का मजदूर-संघों के रूप में प्रबल संगठन था और मार्क के गिर जाने पर भी उन्होंने अपनी मजदूरी न घटने दी। सिके के गिरजाने से मध्यमवर्ग की कमर टूट गई और वह बिल्कुल दरिद्र होगया। १९२३-२४ में यही अपहृत मध्यमवर्ग पहलेपहल हिटलर के साथ शामिल हुआ। जब बैंकों के दिवाले निकलने और बेकारी के बढ़ने से मन्दी फैली तो और बहुत लोग हिटलर के साथ शामिल होगये। वह असन्तुष्ट लोगों के लिए आश्रय-स्थान बन गया। साथियों के मिलने का दूसरा बड़ा साधन पुरानी सेना का अफसर वर्ग था। महासमर के बाद बर्साई की सन्धि की शर्तों के अनुसार यह फौज तोड़ दी गई थी और हजारों अफसर बेकार होगये थे। उनके पास कोई काम न था। उस समय अलग-अलग खानगी फौजें बन रही थीं। इन फौजों का नाम 'नाज़ी स्टॉर्म ट्रूप्स' यानी नाज़ी तूफानी दल था। राष्ट्रवादियों की फौलादी टोपियों (Steel-helmets) वाली सेना थी। ये लोग अनुवार दल के थे और क्रंसर के वापस आने के पक्ष में थे। बेकार अफसर इन सेनाओं में भर्ती होगये।

एडोलफ़ हिटलर कौन था ? आश्चर्य की बात तो है मगर, सच है कि एक दो साल पहले तक वह जर्मन नागरिक तक नहीं बना था। वह जर्मन-आस्ट्रियन था और उसने छोटी हैसियत से युद्ध में काम किया था। उसने जर्मन प्रजातन्त्र के विरुद्ध विद्रोह में भाग लिया था, मगर अधिकारियों ने रियायत करके उसे छोड़ दिया था। फिर उसने लोकसत्तात्मक समाजवादियों का विरोध करने के लिए राष्ट्रीय समाजवादियों (National Socialists) के नाम से अपना दल संगठित किया। नाज़ी शब्द इसी नाम से निकला है। 'नेशनल' (National) से ना (NA) और सोशियलिस्ट (Sozialist) (जर्मन में सोशलिस्ट की जगह यह शब्द इस्तेमाल होता है) से "ज़ी" (Zi) लेलिये गये हैं। यद्यपि इस दल का नाम समाजवादी था, परन्तु समाजवाद से इसका कतई वास्ता न था। समाजवाद का जो साधारण अर्थ है उसका हिटलर जानी दुश्मन था और है। इस दल ने अपना चिन्ह स्वस्तिक को बनाया। यह शब्द संस्कृत का है, लेकिन यह निशान प्राचीन काल से संसार-भर में प्रसिद्ध है। नाज़ियों ने

था। उसने अपनी अधिकतर शक्तियाँ साम्यवादियों के विरोध में खर्च कीं। दिल्ली में यह कि ये दोनों दल अपने-अपने ढंग पर मार्क्सवादी थे।

इस तरह जर्मनी बराबरी की फ़ौजों की एक छावनी-सी बन गया। अक्सर दंगे होने लगे और खास तौर पर नाज़ियों द्वारा साम्यवादी मजदूरों की हत्याएँ होने लगीं। कभी-कभी मजदूर भी बदला लेते। हिटलर को अपना भानमती का पिटारा कायम रखने में विलक्षण सफलता मिली। इसमें मुस्तलिफ़ क्रिस्म के लोग थे जिनकी बहुत थोड़ी बातें एक-दूसरे से मिलती थीं। इसमें एक तरफ़ निम्न श्रेणी के मध्यमवर्ग और बड़े-बड़े कारख़ानेदारों और दूसरी तरफ़ धनी किसानों की अजीब खिचड़ी-सी थी। कारख़ानेदार हिटलर का साथ और उसे रुपया इसलिए देते थे कि वह समाजवाद को कोसता था और बढ़ते हुए मार्क्सवाद और साम्यवाद के विरुद्ध एक ही स्तम्भ दिखाई देता था। ग़रीब मध्यमवर्ग के लोगों, किसानों और मजदूरों को उसके पूंजी-विरोधी नारों से आकर्षण होता था।

१९३३ के मार्च के शुरू की बात है या फ़रवरी की, मुझे ठीक-ठीक याद नहीं, जब बड़े राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने, जिसकी उम्र अब ८६ वर्ष की है, हिटलर को चांसलर बना दिया। यह प्रधानमंत्री की बराबरी का जर्मनी में सबसे ऊँचा ओहदा है। उस वक़्त नाज़ियों और राष्ट्रवादियों में मेल था, मगर बहुत जल्द यह जाहिर होगया कि सम्पूर्ण अधिकार नाज़ियों के हाथ में है और दूसरे किसी की कोई गिनती नहीं है। साधारण चुनाव में नाज़ियों और उनके मित्र राष्ट्रवादियों का रीस्टैंग में नाम मात्र का बहुमत होगया। बहुमत न भी होता तो कोई बात न थी, क्योंकि नाज़ी अपने विरोधियों को पार्लमेण्ट में ही पकड़कर जेलख़ाने भेज देते थे। इस तरह सारे साम्यवादी और बहुतसे लोकसत्तात्मक समाजवादी सदस्यों को हटा दिया गया। ठीक इसी समय रीस्टैंग की इमारत आग लगकर त्वाक होगई। नाज़ियों ने कहा कि यह साम्यवादियों का काम है और राज्य की जड़ काटने के लिए साजिश है। साम्यवादियों ने जोरदार शब्दों में इसका खण्डन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने नाज़ियों के नेताओं पर यह अभियोग लगाया कि उन्होंने साम्यवादियों पर हमला करने का वहाना ढूँढ़ने के लिए आग लगाई है।

इसके बाद जर्मनी-भर में नाज़ियों का आतंक शुरू होगया। पहलेपहल पार्लमेण्ट बन्द कर दी गई, हालाँकि नाज़ियों का बहुमत था। सारी सत्ता हिटलर और उसके मंत्रिमण्डल को सौंप दी गई। वे जो चाहें सो क़ानून बनावें या करें। इस तरह प्रजातंत्र के 'दिमर' विधान का सज़ाया करके लोकसत्ता के सारे स्वरूप को खुले तौर पर नष्ट कर दिया गया। जर्मनी में एक प्रकार का संघ-शासन था। इसका भी ख़ात्मा

वृत्ति समझ में आती है और पिछले कुछ महीनों में जो निर्दयता और पशुता हुई है उसके कारण स्पष्ट होजाते हैं। हाँ, यह नहीं मान लेना चाहिए कि सारे नाज़ियों के विचार ऐसे ही हैं। परन्तु नेताओं और उग्र अंगों के सत्पाल जरूर यही हैं, और लोग इन्हींकी नक़ल करते हैं। शायद यह कहना ज्यादा ठीक होगा कि साधारण नाज़ी विचार ही नहीं करता। उसे अपने दुःख और राष्ट्रीय अपमान ने जगा दिया और जो स्थिति थी उसपर उसे क्रोध आगया। (रूर प्रदेश पर फ्रेंच अधिकार होने से जर्मनी में बड़ा रोष था)। जो हालात मालूम हुए हैं उनसे ऐसा दीखता है कि हिटलर बड़ा विलक्षण और जोरदार बयता है। उसने अपने वेशुमार श्रोताओं की भावनाओं को जगाया और जो कुछ होरहा था उसका सारा दोष मार्क्सवादियों और यहूदियों के सिर मँढ़ दिया। जर्मनी के साथ फ़्रांस या अन्य विदेशों ने बुरा बर्ताव किया तो यही लोगों के लिए नाज़ियों में मिल जाने का एक कारण बन गया; क्योंकि जर्मनी की सम्मान-रक्षा नाज़ी ही तो करनेवाले थे। आर्थिक संकट और भी विकट हुआ तो नाज़ीदल में और अधिक लोग भर्ती होगये।

लोकसत्तात्मक समाजवादी दल ने थोड़े ही समय में शासन का नियन्त्रण खो दिया और दूसरे दलों की लाग-डाँट के कारण 'कैबलिक सेण्टर' नामक दूसरे दल के हाथ में सत्ता आई। रीस्टेग यानी जर्मन पार्लमेण्ट में कोई एक दल इतना जोरदार नहीं था कि दूसरों की उपेक्षा कर सके। इसलिए बार-बार चुनाव होते थे और दलों में आपस में साजिश और चालवाजियाँ जारी रहती थीं। नाज़ियों की बढ़ती देखकर लोकसत्तात्मक समाजवादी इतने डर गये कि उन्होंने पूँजीवादियों के केन्द्रीय दल और राष्ट्रपति के पद के लिए बूढ़े सेनापति हिंडनबर्ग के चुनाव का समर्थन किया। नाज़ियों की बढ़ती के बावजूद मजदूरों के दोनों दल यानी लोकसत्तात्मक समाजवादी और साम्यवादी मजबूत थे और दोनों के ही लाखों आदमी अन्त तक सहायक रहे, परन्तु दोनों के लिए समान रूप से विपत्ति सामने होने पर भी उनमें परस्पर सहयोग नहीं होसका। साम्यवादियों को तो यह कटु स्मृति बनी हुई थी कि १९१८ के बाद लोकसत्तात्मक समाजवादियों ने अपनी सत्ता के जमाने में उन्हें किस तरह सताया था और संकट के हर अवसर पर उन्होंने किस तरह प्रतिगामी दलों का साथ दिया था। उधर लोकसत्तात्मक समाजवादी दल ब्रिटिश मजदूर दल की तरह दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर-संघ से सम्बद्ध था। उसके पास रुपये की कमी न थी, उसका संगठन खूब व्यापक था, और उसके हाथ में कृपा करने के विपुल साधन थे। वह अपनी सुरक्षित स्थिति और प्रतिष्ठा को खतरे में डालने का कोई काम नहीं करना चाहता था। उसे क़ानून के खिलाफ़ या सीधी लड़ाई की कुछ भी कार्रवाई करते हुए बड़ा डर लगता

की गई हैं। जिन अखबारों ने ज़रा भी मतभेद प्रकट किया या टीका की, उन्हें वेवर्दी के साथ कुचल दिया गया। इस आतंकवाद का कोई समाचार नहीं छापने दिया जाता और कानाफूसी तक की कड़ी सज़ा दी जाती है।

नाज़ी दल के सिवा और सब संगठन और दल दबा दिये गये हैं। पहली वारी साम्यवादियों की आई, बाद में लोकसत्तात्मक समाजवादी, फिर कैथलिक मध्य दल-वाले और अन्त में नाज़ियों के मित्र राष्ट्रवादी भी कुचल दिये गये। जर्मनी के बल-शाली मजदूर-संघ, जिनमें पीढ़ियों का परिश्रम, बचत और त्याग लगा था, तोड़ दिये गये और उनके सारे रुपये और सम्पत्ति को ज़ब्त कर लिया गया। सिर्फ़ एक दल और एक संगठन रहने दिया गया; और वह है नाज़ी दल।

नाज़ियों की विविध विचार-धारा ज़बरदस्ती सबके गले के नीचे उतारी जाती है और आतंक इतना छाया हुआ है कि कोई चूँ तक नहीं कर सकता। शिक्षा, नाटक, कलाओं और विज्ञान सभी चीज़ों पर नाज़ी-छाप लगाई जा रही है। कप्तान हरमन गोरिंग हिटलर के खास आदमियों में से है। उसका कहना है, “सच्चा जर्मन अपने खून के साथ विचार करता है।” दूसरे नाज़ी नेता का कहना है कि “शुद्ध तर्क और राग-द्वेष-रहित विज्ञान के दिन गुज़र गये।” वच्चों को सिखाया जाता है कि हिटलर दूसरा ईसा है, मगर पहलेवाले से बड़ा है। नाज़ी-सरकार लोगों में और खासकर स्त्रियों में शिक्षा का बहुत विस्तार करने के पक्ष में नहीं है। असल में हिटलरवादियों की राय में स्त्री का स्थान घर और रसोई में है और उसका मुख्य काम राज्य के लिए लड़ने और मरने के लिए वच्चे पैदा करना है। डॉ० जोसेफ गोएवेल्स दूसरा बड़ा नाज़ी नेता और ‘प्रचार और प्रकाशन’ मंत्री है। उसने कहा है कि “स्त्री का स्थान कुटुम्ब में है और उसका उचित कार्य अपने देश और राष्ट्र के लिए वच्चे देना है। स्त्रियों को मुक्त करने में राज्य के लिए खतरा है। उन्हें चाहिए कि पुरुषों की बातें पुरुषों के लिए छोड़ दें।” इसी डॉ० गोएवेल्स ने हमें यह भी बता दिया है कि जनता को प्रकाश देने का उसका क्या तरीका है। वह कहता है—“मेरा इरादा यह है कि पियानो बाजे की तरह अखबारों को भी अपनी अँगुलियों पर नचाऊँ।”

इस सारी बर्बरता, पाशविकता और गरजने और आग उगलने के कार्यक्रम की पीठ पर वंचित मध्यमवर्ग की दरिद्रता और भूख का बल था। यह सचमुच नौकरियों और रोटियों की लड़ाई थी। यहूदी डॉक्टर, वकील, शिक्षक और दाइयों वगैरा को निकाल देने का कारण यह था कि ‘आर्य-जर्मन’ उनकी होड़ नहीं कर सकते थे। उनकी सफलता पर इन्हें ईर्ष्या थी और उनकी नौकरियों से खुद लेना चाहते थे। यहूदी दुकानों को इसलिए बन्द कर दिया गया, क्योंकि वे सफल प्रतिस्पर्धी थीं। बहुत-सी

करके सारी शक्ति बर्लिन में केन्द्रित करदी गई। सब जगह डिक्टेटर-ही-डिक्टेटर रख दिये गये। वे सिर्फ अपनेसे ऊपर वाले डिक्टेटर के प्रति ही जिम्मेदार थे। सब डिक्टेटरों का गुरुघण्टाल तो हिटलर था ही। *Over*

इधर ये परिवर्तन हो रहे थे, उधर नाज़ियों के सैनिक दलों को जर्मनी-भर में छोड़ दिया गया। ये लोग जहाँ जाते वहीं अजीब जंगली और हँवानी ढंग की हिंसा और भय-प्रदर्शन की कार्रवाइयाँ करने लगते। ऐसी बात पहले कभी नहीं हुई थी। इस तरह की मारकाट और जोर-जुल्म पहले भी हुए हैं, 'लाल आतंक' और 'सफ़ेद आतंक' का जिक्र इस किताब में पहले किया जा चुका है, लेकिन वे हमेशा उसी वक़्त हुए हैं जब किसी देश या प्रधान दल को गृह-युद्ध में अपने प्राणों के लिए लड़ना पड़ा है। भय-प्रदर्शन भयंकर ख़तरे या निरन्तर भय के कारण हुआ करते हैं। परन्तु नाज़ियों के सामने ऐसा कोई ख़तरा भी नहीं था और भय का कारण भी नहीं था। सरकार उनके हाथ में थी और उनके मुकाबिले में कोई सशस्त्र विरोध भी नहीं था। इस तरह भूरी कुर्ती वालों का आतंक क्रोध या डर का परिणाम नहीं था बल्कि जान-बूझकर बैठे-बिठाये, और अविश्वसनीय पशुता के साथ उन सब लोगों को दबा देने की बात थी जो नाज़ियों का साथ नहीं दे रहे थे।

पिछले कुछ महीनों में जर्मनी में जो अत्याचार हुए हैं और अब भी परदे की आड़ में हो रहे हैं उनकी सूची या फ़ेहरिस्त लिखने से कोई फ़ायदा न होगा। मारपीट, यातनायें, गोली मार देने, हत्यायें कर डालने वगैरा की पाशविक कार्रवाइयाँ बड़े भारी पैमाने पर हुई हैं और स्त्री और पुरुष दोनों उनके शिकार हुए हैं। बहुत बड़ी तादाद में, जो १३,००० से ६०,००० के बीच में कूती जाती है, लोगों को जेल या नज़रबन्दी में डाल दिया गया है और कहा जाता है कि उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है। सबसे जोर का हमला तो साम्यवादियों पर किया गया है, मगर उनसे नरम लोक-सत्तात्मक समाजवादियों का भी कुछ ज्यादा अच्छा हाल नहीं हुआ। यहूदियों की बुरी तरह कमबख़्ती आई है और शान्तिवादियों, उदार दल वालों, मजदूर-संघ वालों और अन्तर्राष्ट्रीयतावादियों पर भी हमले किये गये हैं। नाज़ी लोग उनके की चोट कहते हैं कि यह तो मार्क्सवाद, और मार्क्सवादियों के ही नहीं, बल्कि 'उग्र' विचार वाले सभी लोगों का नाश करने का युद्ध है। यहूदियों को सारे पवों और धन्यों से भी निकाल बाहर करना है। हजारों यहूदी अध्यापक, शिक्षक, संगीतज्ञ, वकील, न्यायाधीश, वैद्य और वाइयाँ बर्खास्त करदी गई हैं। यहूदी दूकानदारों का बहिष्कार कर दिया गया है और यहूदी मजदूरों को कारख़ानों से निकाल दिया गया है। जो पुस्तकें नाज़ियों को नापसन्द हैं वे ढेर-की-ढेर नष्ट करदी गई हैं और खुले तौर पर उनकी होलियाँ

हुई है कि लोकसत्तात्मक समाजवादियों का महान् दल मुकाबिले की ज़रा भी कोशिश किये बिना बिलकुल नेस्तनाबूद होगया। योरप के श्रमजीवीवर्ग का इससे पुराना, इससे बड़ा और इससे अधिक सुसंगठित दल और कोई न था। यह दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर-संघ की रीढ़ था। हालाँकि सिर्फ़ नाराज़गी जाहिर करने से कुछ भी होना-जाना नहीं था, फिर भी इस दल ने इतना भी न किया। वह सारे अपमान और तिरस्कार को चुपचाप सहता रहा और अख़ीर में खुद भी मिट गया। पग-पग पर लोकसत्तात्मक समाजवादी नेता नाज़ियों के सामने झुकते गये। उन्हें हर बार यह उम्मीद होती थी कि झुकने और अपमान सहन करने से मुमकिन है कुछ तो बचा रह जायगा। लेकिन उनका झुकना ही उनके लिए बेड़ी होगया और नाज़ियों ने मजदूरों को बताया कि किस नीचता के साथ विपत्ति के समय उनके नेताओं ने उनका साथ छोड़ दिया। योरप के मजदूर वर्ग की लड़ाई के लम्बे इतिहास में हार अधिक और जीत कम हुई है। लेकिन इस बेहयाई के साथ, ज़रा भी विरोध किये बिना, मजदूर-पक्ष को धोखा देने और आत्म-समर्पण करने की दूसरी कोई मिसाल नहीं मिलती। साम्यवादी दल ने लोहा लेने की कोशिश की और आम हड़ताल कराई, लेकिन लोकसत्तात्मक समाजवादी नेताओं ने साथ नहीं दिया और हड़ताल टांग-टांग फिस होगई। साम्यवादियों का दल टूट गया है, फिर भी उनका काम गुप्त संगठन के रूप में जारी है। मालूम होता है कि यह संगठन दूर-दूर तक फैला हुआ है। नाज़ियों के जासूसी विभाग के होते हुए भी साम्यवादियों के गुप्त समाचारपत्र का प्रचार कई लाख समझा जाता है। लोक-सत्तात्मक समाजवादियों के जो नेता किसी तरह जर्मनी से निकल भागे हैं उनमें से भी कुछ गुप्त उपायों द्वारा दाहर से थोड़ा बहुत प्रचार-कार्य कर रहे हैं।

भूरी कुर्ती वालों के आतंकवाद से सबसे ज्यादा कष्ट मजदूर-वर्ग को पहुँचा। लेकिन संसार का लोकमत यहूदियों के साथ होनेवाले व्यवहार से अधिक उत्तेजित हुआ था। योरप को वर्ग-युद्ध का अभ्यास-स्ता होगया है, और उसमें सहानुभूति अपने-अपने वर्ग के साथ होती है। मगर यहूदियों पर जो हमला हुआ वह जातीय आक्रमण था। वह कुछ ऐसा था जैसा मध्ययुग में हुआ करता था, या हाल के उमाने में जार-शाही रूस जैसे पिछड़े देशों में ग़ैरसरकारी तौर पर हुआ करता था। सारी जाति पर सरकारी अत्याचार होने से योरप और अमेरिका को बड़ा आघात पहुँचा। यह आघात इस बात से और बढ़ गया कि जर्मन यहूदियों में संसार-प्रसिद्ध आदमी, तेजस्वी वैज्ञानिक, डाक्टर, वकील, संगीतशास्त्री और लेखक भी थे। इस सूची में एल्बर्ट आइन्स्टीन जैसे महान् व्यक्ति का नाम भी था। ये लोग जर्मनी को अपना घर समझते थे और सब जगह जर्मन समझे जाते थे। इनको पाकर कोई भी देश अपने को

गैरयहूदी दुकानों को बन्द करके उनके मालिक गिरफ्तार कर लिये गये, क्योंकि नाज़ियों को सन्देह था कि ये लोग वेजा तीर पर ऊँचे भाव लगाकर फ़ायदा उठाते हैं। नाज़ियों का पक्ष लेनेवाले किसान पूर्वी एशिया की बड़ी-बड़ी ज़मींदारियों पर आँख लगाये बैठे हैं और उन्हें लूट बाँट ख़ाया चाहते हैं। शुद्ध-शुद्ध के नाज़ी कार्यक्रम में एक लाख मजदूर बात यह तजवीज़ थी कि १२ सौ मार्क सालाना से अधिक वेतन किसी को न दिया जाय। यह ८ हजार रुपये वार्षिक या ६६६ रुपये मासिक के बराबर होता है। मालूम नहीं इसपर कहांतक अमल किया गया है, लेकिन यह जाहिर है कि कुछ-न-कुछ हो रहा है। आजकल प्रधान मंत्री की तनज़ाह २६ हजार मार्क सालाना यानी १ हजार रुपये माहवार है। प्रस्ताव यह है कि जिन ख़ानगी कम्पनियों को सरकार से मदद मिलती है उनके संचालकों या मालिकों तक को १८ हजार मार्क वार्षिक से अधिक वेतन न दिया जाय। इन लोगों को पहले अक्सर बड़ी-बड़ी रक़में दी जाती थीं। इन अंकों की तुलना उन भारी वेतनों से करो जो दरिद्र भारत अपने कर्मचारियों को देता है। कांग्रेस ने कराची में वेतन की सीमा ५ सौ रुपये मासिक बांधने का प्रस्ताव किया है।

यह कल्पना नहीं करनी चाहिए कि नाज़ी-आन्दोलन के पीछे केवल पाशविकता और आतंक ही है। ये चीज़ें मुख्य तो हैं, परन्तु इसमें भी सन्देह नहीं कि अधिकांश मजदूरों को छोड़कर बाक़ी के ज्यादातर जर्मनों में हिटलर के लिए बड़ा सच्चा उत्साह है। यदि पिछले चुनाव के अंकों को सही मानकर चला जाय तो ५२ फ़ीसदी जनता हिटलर के पक्ष में है। ये ५२ फ़ीसदी लोग शेष ४८ फ़ीसदी या उनके एक भाग पर आतंक जमा रहे हैं। इन ५२ फ़ीसदी लोगों में अब तो शायद और भी शामिल होगये हों। ये सब हिटलर को ख़ूब चाहते हैं। जर्मनी जाकर आये हुए लोग बताते हैं कि वहाँ एक अजीब मानसिक वातावरण पैदा होगया है और ऐसा मालूम होता है जैसे कोई धार्मिक पुनर्जीवन हो गया हो। जर्मन लोग महसूस करने लगे हैं कि वर्साई की संधि से वे वर्यो तक जिस अपमान और दमन के शिकार रहे वह अब जाता रहा और अब वे फिर आज़ादी से साँस ले सकते हैं। लेकिन जर्मनी के दूसरे आवे या लगभग आधे भाग की भावना दूसरी है। नाज़ियों के भयंकर प्रतिशोध के डर से जर्मनी का मजदूर-वर्ग उनकी आज्ञा या नियंत्रण में है, लेकिन उसके दिल में घृणा और क्रोध की आग जल रही है। सारे मजदूरों को देखा जाय तो उन्होंने पशुबल और आतंकवाद के सामने घुटने टेक दिये हैं और जिस इमारत को उन्होंने बड़े परिश्रम और त्याग से साथ खड़ा किया था उसकी नवादी को उन्होंने दुःख और निराशा के साथ अपनी आँखों देखा है। पिछले कुछ महीनों में जर्मनी में जो-जो घटनायें हुई हैं उनमें सबसे आश्चर्य की बात यह

कुछ दिन तक ऐसा मालूम होने लगा कि योरप में लड़ाई छिड़ने ही वाली है। नाज़ियों के डर से योरप के राष्ट्रों में अचानक नई गुटबन्दी शुरू हुई। फ़्रांस की सोवियट रूस के साथ घुटने लगी। वर्साई की संधि से पोलैण्ड, ज़ेकोस्लोवेकिया, यूगोस्लाविया वगैरह देश या तो स्वतंत्र हुए थे या इन्हें फ़ायदा पहुँचा था। उस संधि के रद्द होने की सम्भावना से ये सब देश एक-दूसरे के नज़दीक आगये और साथ ही रूस की तरफ़ खिंचने लगे। आस्ट्रिया में आश्चर्यजनक स्थिति पैदा होगई। वहाँ (पाँच फ़ुट से भी कम ऊँचे) चांसलर डॉलफ़स के हाथ में अधिकार आचुका था, मगर इसका फ़ैसिज्म हिटलर के फ़ैसिज्म से भिन्न था। आस्ट्रिया में नाज़ियों का जोर है, लेकिन डॉलफ़स उनका विरोध करता रहा है। इटली ने हिटलर की विजय का स्वागत किया, मगर उसके सारे हौसले नहीं बढ़ाये। इंग्लैण्ड अनेक वर्षों से जर्मनी के पक्ष में रहा था, लेकिन अब अकस्मात् उसका प्रबल विरोधी बन गया। अंग्रेज़ लोग उन्हें फिर से 'हूण' कहकर पुकारने लगे। हिटलर का जर्मनी योरप में बिल्कुल अकेला पड़ गया। यह जाहिर था कि लड़ाई होती तो फ़्रांस की ज़बरदस्त फ़ौज बेहथियार जर्मनी को कुचल डालती। हिटलर ने अपनी चाल बदल दी और शान्ति की बातें करने लगा। मुसोलिनी उसकी मदद पर पहुँच गया और उसने फ़्रांस, इंग्लैण्ड, जर्मनी और इटली के बीच में चतुरंगी समझौते का प्रस्ताव रक्खा।

फ़्रांस को हिचकिचाहट हुई थी, मगर अन्त में जून १९३३ में इस समझौते पर चारों राष्ट्रों के हस्ताक्षर होगये। जहाँतक इस समझौते की भाषा का ताल्लुक है वह निर्दोष-सी है, और उसमें इतना ही कहा गया है कि कुछ अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में और खास तौर पर वर्साई की संधि पर पुनर्विचार करने के किसी भी प्रस्ताव के बारे में चारों राष्ट्र आपस में मशविरा कर लेंगे। लेकिन यह संधि सोवियट के खिलाफ़ गुटबन्दी करने की एक कोशिश समझी जाती है। यह तो साफ़ है कि फ़्रांस ने उसपर बहुत ही बेमन से दस्तख़त किये थे। शायद इस संधि के परिणामस्वरूप और इसके जवाब में पहली जुलाई १९३३ को सोवियट और उसके पड़ोसियों के बीच एक-दूसरे पर हमला न करने की संधि लन्दन में हुई थी। यह बड़ी दिलचस्पी की बात है कि सोवियट की इस संधि के प्रति फ़्रांस ने दड़ी सहानुभूति और सहमति प्रकट की है।

हिटलर का मूल कार्यक्रम जर्मन पूँजीवाद का कार्यक्रम है। वह अपनेआपको सोवियट रूस से योरप की रक्षा करनेवाला बताता है। उसे मालूम है कि फ़्रांस से तो कुछ मिलना है नहीं, जर्मनी के कहीं और इलाक़ा हाथ लग सकता है तो सोवियट संघ से छीनकर पूर्व में ही लग सकता है। लेकिन इसके पहले जर्मनी का सशस्त्र होना ज़रूरी है और इसलिए वर्साई की संधि में इस आशय का परिवर्तन होने की ज़रूरत है। कम-से-

गौरवशाली समझ सकता था। मगर नाज़ी लोग तो जातीय द्वेष में इतने पागल और अन्धे हो गये थे कि उन्होंने इन्हें भी मार भगाया। इसपर दुनिया-भर में विरोध की ज़बरदस्त आवाज़ उठी। इसके बाद नाज़ियों ने यहूदी दुकानदारों और धन्धेवालों का बहिष्कार शुरू किया। विचित्र बात यह थी कि इन यहूदियों को आम तौर पर जर्मनी छोड़कर जाने भी नहीं दिया जाता था। ऐसी नीति का यही नतीजा हो सकता था कि ये लोग भूखों मर जायें। दुनिया के शोर मचाने से यहूदियों के खिलाफ़ नाज़ियों के खुले तरीक़े तो नरम पड़ गये, मगर नीति वही हुई।

लेकिन यहूदी लोग यद्यपि संसार-भर में बिखरे हुए हैं और वे किसीको भी अपना राष्ट्र नहीं कह सकते, फिर भी वे इतने निस्सहाय नहीं हैं कि बदला न ले सकें। व्यवसाय और पूंजी बहुत-कुछ उनके हाथ में हैं और उन्होंने चुपचाप बिना शोरगुल मचाये जर्मन माल के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने न्यूयार्क में मई १९३३ में एक परिषद् करके एक प्रस्ताव किया है, जिसमें निश्चय किया गया है कि "जर्मनी के सारे माल का, सामग्री का और जर्मनी में तैयार हुई, पैदा हुई और सुधारी हुई सब चीज़ों और उनके हिस्सों का बहिष्कार किया जाय। जर्मनी के सब जहाज़ों और माल व मनुष्यों को ले जानेवाले साधनों तथा जर्मनी के स्वास्थ्य और सुखप्रद स्थानों और आरामगाहों का भी बहिष्कार किया जाय। और आम तौर पर ऐसा कोई काम न किया जाय जिससे जर्मनी की मौजूदा व्यवस्था को किसी भी तरह की आर्थिक सहायता पहुँचती है।" इसमें कमी क्या रही? यहूदियों का यह संसारव्यापी और बलशाली बहिष्कार छोटी-मोटी बात नहीं है। इससे जर्मनी की माली हालत, जो पहले से ही अच्छी नहीं थी, और भी ख़राब हो रही है।

विदेशों में हिटलरशाही की एक प्रतिक्रिया तो यह हुई। दूसरी प्रतिक्रियायें इससे भी गहरा असर करनेवाली थीं। नाज़ी लोग शुरू से ही वर्साई की सन्धि की निन्दा करते आये हैं और उसपर फिरसे विचार करने की उनकी माँग रही है। त्वांस्तौर पर पूर्वी सीमा के बारे में उनका ज़्यादा जोर रहा है, क्योंकि वहाँ जो बेहूदा व्यवस्था की गई है उसके अनुसार डेन्ज़िग तक पोलैण्ड को एक लम्बा टुकड़ा दे दिया गया है और जर्मनी के शरीर के एक अंग का विच्छेद कर दिया गया है। नाज़ियों की दूसरी जोरदार माँग यह रही है कि शस्त्रों के मामले में सब राष्ट्रों को पूरी समानता होनी चाहिए (तुम्हें याद होगा कि संधि की शर्तों के अनुसार जर्मनी बहुत कुछ निःशस्त्र कर दिया गया था)। हिटलर के गरजने और आग उगलने वाले भाषणों से और फिर से शस्त्र धारण करने की धमकियों से योरोप पूरी तरह घबरा उठा। फ़्रांस को विशेष चिन्ता हुई, क्योंकि शक्तिशाली जर्मनी से उसीको ज़्यादा ख़ौफ़ हो सकता था।

नरम दल के साथ होगया है। उसके बड़े-बड़े साथी लगभग सभी इस समय ऊँचे पदों पर विराजमान हैं। उन्हें सब तरह का आराम है। इसलिए वे परिवर्तन के लिए उत्सुक नहीं हैं। परन्तु उन वेशुमार बेकार लोगों का क्या हाल है, जो कुछ-न-कुछ मिलने की आशा से हिटलर के साथ हुए थे ? कुछ हजार लोगों की व्यवस्था की जा सकती है, लाखों की नहीं की जा सकती। यह प्रकट है कि नाज़ियों में बड़ा असन्तोष है और जबतक यह असन्तोष रहेगा तबतक कोई स्थिरता नहीं होसकती। यह नहीं कहा जा सकता कि हिटलर का विरोध होते हुए भी 'दूसरी क्रान्ति' होगी या नहीं। और अगर इस तरह की उथल-पुथल का खतरा बना रहा तो यह सम्भावना हमेशा रहेगी कि हिटलर घर के मामलों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए कोई अन्तर्राष्ट्रीय विकट स्थिति पैदा करदे।

हिटलरवाद का वर्णन लम्बा होगया। और इतनी लम्बी चिट्ठी भी मैंने दूसरी नहीं लिखी है। मगर इतना तुम स्वीकार करोगी कि नाज़ियों की यह विजय और उसके परिणाम योरप और संसार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हुए हैं और उनका दूर-दूर तक असर पहुँच सकता है। इसमें सन्देह नहीं कि यह फ़्रंसिज्म ही है और हिटलर खुद एक आदर्श फ़्रंसिस्ट है। परन्तु इटली के फ़्रंसिज्म से नाज़ी आन्दोलन थोड़ा अधिक व्यापक, दूर-दूर तक फैला हुआ और उग्र है। यह देखना है कि ये उग्र अंग कुछ रंग लाते हैं या योंही कुचल दिये जायेंगे। कुछ हद तक नाज़ी आन्दोलन की वृद्धि से पुराने मार्क्सवादियों का यह विश्वास रहा है कि सच्चा क्रान्तिकारी वर्ग श्रमजीवी-वर्ग ही है और जैसे-जैसे हालात बिगड़ते जायेंगे वैसे-वैसे निम्न-श्रेणी के मध्यमवर्ग के असन्तुष्ट और बंचित अंग भी मजदूर-वर्ग में अपनेआप आकर मिलते जायेंगे और अन्त में मजदूर-क्रान्ति होजायगी। दरअसल जर्मनी में जो कुछ हुआ वह इससे बिल्कुल उलटा है। जब उथल-पुथल हुई उस समय मजदूर बिल्कुल क्रान्तिकारी नहीं थे। उस वक़्त तो निम्न-श्रेणी के बंचित मध्यमवर्ग और दूसरे असन्तुष्ट लोगों का एक नया ही क्रान्तिकारी वर्ग बन गया। यह बात पुराने मार्क्सवाद के अनुसार नहीं हुई। परन्तु दूसरे मार्क्सवादियों का कहना है कि मार्क्सवाद को कोई ऐसा कड़ा नियम, धर्म या संप्रदाय नहीं समझना चाहिए जो अपनी बात को धर्म की तरह अधिकार के साथ अन्तिम सत्य बताता हो। यह तो इतिहास का एक तत्त्वज्ञान है, एक दृष्टिकोण है, जो दहत-सी बातें समझाता और मिलाता है और समाजवाद या सामाजिक समानता की कार्य-प्रणाली दिखाता है। इसके मूल सिद्धान्त अलग-अलग तरह से इस तरह लागू करने चाहिए जिससे भिन्न-भिन्न समय और भिन्न-भिन्न देशों के बदलते हुए हालात के साथ उनका मेल बैठ सके।

कम इतना आश्वासन तो मिलना ही चाहिए कि कोई दखल न देगा। हिटलर को इटली की मदद का भरोसा है। उसे शायद यह भी उम्मीद है कि अगर वह इंग्लैंड की मदद भी हासिल कर सके तो चतुरंगी सन्धि के अनुसार किसी भी चर्चा में फ्रांस के विरोध का बल घट जायगा। एक तरफ़ तीन और दूसरी तरफ़ एक तो हो ही जायेंगे।

इस तरह हिटलर ब्रिटिश मदद हासिल करने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए उसने खुले तौर पर यहाँतक कह दिया है कि अगर हिन्दुस्तान पर अंग्रेज़ों का प्रभाव कम हो जायगा तो विपत्ति आजायगी। वैसे उसका सोवियट-विरोधी होना ही ब्रिटिश सरकार के लिए एक आकर्षण है, क्योंकि, जैसा मैं तुम्हें बता चुका हूँ, ब्रिटिश साम्राज्यवाद को कोई चीज़ इतनी बुरी नहीं लगती जितना सोवियट रूस लगता है। लेकिन नाज़ियों की कार्रवाइयों से ब्रिटिश जनता को इतनी नफ़रत होगई है कि उसे हिटलरशाही के पक्ष में किसी भी प्रस्ताव का समर्थन करने में कुछ वज़त लगेगा।

तरह-तरह के ख़तरों से दुनिया के होशहवास पहले से ही उड़े हुए थे। नाज़ी जर्मनी ने योरोप में तूफ़ान का घर बनकर परेशानियाँ और बढ़ादी हैं। खुद जर्मनी में क्या होगा? नाज़ी शासन कबतक रहेगा? जर्मनी में नाज़ियों के प्रति घृणा और विरोध की कमी नहीं है, लेकिन यह भी साफ़ है कि संगठित विरोध बिल्कुल कुचल दिया गया है। जर्मनी में कोई दल या संगठन बाक़ी नहीं रहा है और नाज़ियों का ही बोलबाला है। खुद नाज़ियों में भी दो दल मालूम होते हैं। एक ओर पूँजीपति और व्यवसायी वर्ग है। यह नाज़ी दल का दाहिना यानी नरम अंग है। बायें यानी उग्र अंग में दल के साधारण सदस्यों का बहुमत है। इसमें हाल ही में शामिल होनेवाले बहुत-से मज़दूर भी हैं। जिन लोगों के कारण हिटलर के आन्दोलन में क्रान्तिकारी भावना आई, उनमें पूँजीवाद के विरुद्ध उग्र परिवर्तन की भावना बहुत थी। इन लोगों ने बाद में बहुत-से समाजवादियों और मार्क्सवादियों को अपनेमें शरीक कर लिया है। नाज़ी आन्दोलन के दाहिने और बायें अंगों में बहुत कम बातें मिलती-जुलती हैं। हिटलर की बड़ी सफलता इसी बात में है कि उसने दोनों को साथ रख छोड़ा है और एक को दूसरे से भिड़ाकर अपना काम निकालता रहा है। यह बात तभीतक रह सकती है जबतक सामने शत्रु दिखाई देता है। अब शत्रु तो कुचल दिया गया या उसे हज़म कर लिया गया है। अब धीरे-धीरे बायें और बायें अंगों में संघर्ष बढ़ेगा।

कुछ गड़बड़ तो अभी से शुरू होगई है। उग्र दल के नाज़ियों ने माँग की कि जब पहली क्रान्ति पूरी तरह सफल होचुकी है तो अब पूँजीवाद, ज़मीन्दारी प्रथा वगैरा के खिलाफ़ 'दूसरी क्रान्ति' शुरू होनी चाहिए। परन्तु हिटलर ने इस दूसरी क्रान्ति को वेदवर्ष के साथ दबा देने की धमकी दे डाली। इस तरह वह निश्चित रूप में पूँजीवादी

फ्रांस को जर्मनों के पिछले हमलों की याद बनी हुई है। इसलिए वह हमेशा 'रक्षा' पर जोर देता रहा है। वह कोई ऐसी व्यवस्था चाहता है जिससे बैठे-बिठाये हमला कर देना असम्भव नहीं तो कठिन जरूर होजाय। उसने यह सुझाया है, कि हमला करनेवाले देश से आज्ञा-पालन कराने के लिए राष्ट्र-संघ खुद सेना रखे। इससे राष्ट्र-संघ राज्यों के ऊपर एक नया राज्य बन जायगा; पर इस बात पर सहमत होने के लिए अधिकांश देश तैयार नहीं हैं। आज राष्ट्र-संघ की जिस तरह की रचना है उससे अक्सर उसकी यह टीका की जाती है कि वह कुछ बड़े राष्ट्रों के हाथ का हथियार है। ऐसे संगठन की ताकत बढ़ाने का मतलब यही होगा कि इन राष्ट्रों की शक्ति बढ़ जायगी और वे दूसरों का शोषण कर सकेंगे। वे नाम तो अन्तर्राष्ट्रीय हित का लेंगे, मगर असल में वे अपना काम बनावेंगे। दलील कुछ इसी तरह की दीजाती है।

प्रत्येक राष्ट्र परिषद के सामने ऐसा प्रस्ताव रखता है जिससे अपने मुक्ताविले में दूसरे राष्ट्रों की ताकत कम होजाय। ऐसी हालत में समझौता किस तरह होसकता है? सोवियट रूस ने ऐसी तजवीजें पेश कीं जो सारे मामले की तह तक जाती थीं और जिनके मंजूर कर लेने से सब जगह असली निःशस्त्रीकरण होजाता। लेकिन दूसरे राष्ट्रों ने कह दिया कि यह तो व्यावहारिक नहीं है और ऐसी आदर्शवादी योजना का मौजूदा हालात से मेल नहीं बैठ सकता। असल बात यह है कि इन दूसरे राष्ट्रों में से कोई भी सच्चा निःशस्त्रीकरण नहीं चाहता। वे तो इतनी-सी चर्चा करते हैं कि खर्च घटाकर छोटे-मोटे परिवर्तन या कमी के साथ अस्त्र-शस्त्र किस तरह कायम रखे जायें। इससे बढ़कर तमाशा और क्या होसकता है कि इधर तो ये राष्ट्र जिनेवा या लुसान में निःशस्त्रीकरण की गम्भीर चर्चा करें और उन्हींमें से एक यानी जापान मंचूरिया में खूनी युद्ध जारी रखे या दक्षिणी अमेरिका के प्रजातन्त्र आपस में लड़ते रहें या ब्रिटेन हिन्दुस्तान के सीमाप्रान्त के लोगों पर बम-वर्षा करता रहे।

केलॉग-ब्रियॉद समझौते के अनुसार युद्ध शर-क्रानूनी ठहराया गया था। अगर यह बात सही है तो फिर सेनायें रखने की क्या जरूरत है? लेकिन साम्राज्यवादी सरकारों में से कोई भी इन संधियों का ऐसा गम्भीर अर्थ नहीं लगाती और वे सब एक-दूसरे के विरोध में भयंकर रूप से फौजें बढ़ाती जा रही हैं। तुम्हें याद होगा कि केलॉग-समझौते में भी ब्रिटेन ने कई बड़ी-बड़ी बातों के बारे में इतना अधिकार अपने हाथों में रख लिया था कि उस समझौते की जान ही निकल गई थी। निःशस्त्रीकरण-परिषद् में जापानियों के बाद ब्रिटिश प्रतिनिधियों ने ही परिषद के रास्ते में सबसे ज्यादा रोड़े अटकाये हैं। जिस वक़्त जापान मंचूरिया में राष्ट्र-संघ की खुली तोहीन कर रहा था, उस वक़्त ब्रिटिश प्रतिनिधि-मण्डल दरादर जापानियों का मित्र बना

निःशस्त्रीकरण

२ अगस्त, १९३३

मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि दुनिया-भर की जो आर्थिक-परिपद् लन्दन में हुई थी, वह असफल रही। फिलहाल परिपद् का काम बन्द करके सब लोग अपने-अपने घर चले गये हैं और कहने की यह आशा प्रकट कर गये हैं कि अधिक अनुकूल परिस्थिति में शायद फिर कभी मिलेंगे।

सहयोग का दूसरा संसार-व्यापी प्रयत्न निःशस्त्रीकरण परिपद् के रूप में हुआ और वह भी इसी तरह असफल हुआ। यह परिपद् राष्ट्र-संघ के इक्करारनामे का नतीजा थी। वर्साई की संधि में यह तय हुआ था कि जर्मनी और आस्ट्रिया, हंगरी आदि दूसरे पराजित राष्ट्र भी निःशस्त्र होजायें। वे जल-सेना, हवाईसेना या बड़ी स्थल-सेना नहीं रख सकते थे। यह भी तजवीज थी कि दूसरे देश भी धीरे-धीरे घटाते-घटाते इतनी-सी फौज रखें जितनी कि राष्ट्र के लिए जरूरी हो। इस कार्यक्रम के पहले हिस्से यानी जर्मनी को निःशस्त्र करनेवाले हिस्से पर फौरन अमल किया गया। लेकिन दूसरा हिस्सा यानी आमतौर पर सेनायें घटानेवाला हिस्सा ज्यों-का-त्यों एक सपना बना हुआ है। कार्यक्रम के इस दूसरे हिस्से की पूर्ति के लिए ही वर्साई की सन्धि के करीब १३ साल बाद कहीं निःशस्त्रीकरण परिपद् बुलाई गई थी। लेकिन पूरी परिपद् के होने से पहले वर्षों तक जांच कमीशन सारे मामले की छान-बीन करते रहे थे।

आखिरकार १९३२ के शुरू में विश्व-निःशस्त्रीकरण परिपद् हुई। डेढ़ साल से बीच-बीच में इसकी बैठकें होती रहीं। अगर प्रस्ताव और रिपोर्टों की तादाद या अनन्त वाद-विवाद और व्याख्यानवाजी से इसकी सफलता का अन्दाज़ लगाया जासकता हो तो सचमुच यह परिपद् खूब सफल हुई। मैं समझता हूँ लगातार एक ही मामले के लिए पहले कभी इतनी तैयारी और बहस नहीं हुई है और न कभी पहले किसी परिपद् की कार्रवाई और रिपोर्ट के क़ाराज़ात का इतना पहाड़ इकट्ठा हुआ था। फिर भी कोई बात तय ही नहीं होती। परिपद् नित्य होती है, पर उसका कोई अन्त ही नहीं होता, क्योंकि कोई राष्ट्र इसके टूटने की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। फिर भी कोई असाधारण घटना न हुई तो यह टूटकर ही रहेगी, क्योंकि असली मुश्किल यह है कि आज की दुनिया में आपस में भयंकर लाग-डॉंट और संघर्ष जारी है और जबतक यह संघर्ष रहेगा तबतक कोई राष्ट्र सेना कम करके अपनेको कमज़ोर बनाने का साहस नहीं कर सकता।

कुछ महीनों तक बेकार कोशिशें करने के बाद निःशस्त्रीकरण परिषद् इस वुरी तरह दल-दल में फँसी कि न वह आगे बढ़ सकती थी और न उसमें से निकल सकती थी। आर्थिक संकट और व्यापारिक मन्दी के कारण सभी राष्ट्रों के लिए जल, स्थल और हवाई सेनाओं पर बड़ी रकम खर्च करते रहना बहुत मुश्किल हो रहा था। वे किफायत करना चाहते थे और फ़ौजें घटाने के पक्ष में यह प्रेरणा शान्ति की इच्छा से भी ज्यादा ताकतवर थी। फिर भी साम्राज्यवादी राष्ट्र किसी बात पर एक मत ही नहीं होते थे। वे एक-दूसरे से भी डरते थे और कुछ हद तक उन लोगों से भी डरे हुए थे जिनका वे अपने-अपने साम्राज्य में शोषण करते थे। साम्राज्य प्रेम और सद्भाव के आधार पर खड़े नहीं हुआ करते। उनकी पीठ पर तो बल और हिंसा होती है। इनके बिना वे एक दिन भी नहीं टिक सकते।

परिषद् के सामने एक कठिन समस्या जर्मनी की थी। जर्मनी दूसरे राष्ट्रों के साथ समानता माँग रहा था। या तो उसे भी औरों के बराबर सेना बढ़ाने दी जाय, या और राष्ट्र भी उसके बराबर अपनी फ़ौज घटा लें। यह दलील लाजवाब थी। क्या ख़ुद राष्ट्र-संघ ने यह नहीं कह दिया था कि जर्मनी के निःशस्त्र होने के बाद दूसरे राष्ट्र भी निःशस्त्र होंगे? अवश्य ही जर्मनी शान्ति और निःशस्त्रीकरण का कोई बड़ा प्रेमी नहीं था, मगर उसे मालूम था कि सारे राष्ट्र निःशस्त्रीकरण की किसी भी व्यापक योजना को मंजूर नहीं करेंगे और इसलिए उन्हें सख्त मारकर जर्मनी की समानता की माँग स्वीकार करनी पड़ेगी और उसे सेना रखने की इजाजत देनी होगी। जर्मनी की हालत पर बड़ी हमदर्दी दिखाई गई और बराबरी का हक़ देने का यत्न भी दिलाया गया। उसके बाद हिटलर और नाज़ी लोग अपनी धमकियाँ और आक्रमणकारी रवैया लेकर सामने आये। बस तुरन्त स्थिति बदल गई, फ़्रांस तन गया और एक हद तक इंग्लैंड और दूसरे राष्ट्रों का रुख भी कड़ा पड़ गया। दूसरे राष्ट्र कहने लगे कि अगर नाज़ी जर्मनी को हथियारबन्द होने दिया जायगा तो वह योरोप के लिए बड़ा ख़तरा बन जायगा और अगर हम सेना कम कर देंगे तो उससे भी शान्ति भंग होने की सम्भावना रहेगी। जर्मनी के पक्ष में कोई भी परिवर्तन होता तो उससे फ़्रांस की ताकत घटती और फ़्रांस को इतनी घबराहट होगई कि वह ऐसे किसी परिवर्तन को सह नहीं सकता। स्थिति यह है कि निःशस्त्रीकरण परिषद् की गाड़ी अटक गई है। आगे के लिए कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। योरोप में लड़ाई का ख़तरा बढ़ गया है और फ़ौज कम करने की किसी राष्ट्र की हिम्मत नहीं होती। शिक्षा और दूसरे जरूरी और उपयोगी कामों से रपया दबाकर भी सेनाएँ रखनी पड़ती हैं। इन कारणों से निःशस्त्रीकरण के बारे में कोई भी कारगर समझौता होना

रहा। चीन में जापानी हमले का अमेरिका ने विरोध किया। मगर ब्रिटिश रत्न के कारण उस विरोध का बहुत-सा जोर मारा गया।

जापान ने इस वहाने का सहारा लिया था कि वह कोई 'युद्ध' नहीं कर रहा है, बल्कि कुछ आवश्यक 'कार्रवाईयाँ' (!) कर रहा है। भविष्य में कोई राष्ट्र ऐसे असाधारण वहाने न बना सके, इसके लिए 'आक्रमणकारी' राष्ट्र की व्याख्या करने का प्रस्ताव हुआ। पहले सोवियट रूस ने, फिर राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने, और अन्त में राष्ट्र-संघ की एक समिति ने व्याख्या की। इन सब व्याख्याओं ने क्ररीव-क्ररीव यह असम्भव कर दिया कि कोई राष्ट्र 'आक्रमणकारी' होने का दण्ड भोगे बिना सीमा पार करके दूसरे देश में सेना भेज सके, या दूसरे देश के समुद्र-तट पर घेरा डाल सके। छोटे-बड़े क्ररीव-क्ररीव सभी राष्ट्रों ने, यहाँतक कि फ्रांस ने भी, यह व्याख्या मानली। जापान के लिए यह व्याख्या बहुत परेशान करनेवाली थी। परन्तु इसका असली विरोध इंग्लैंड की तरफ से हुआ और उसका साथ इटली ने दिया। इंग्लैंड ने 'आक्रमण-कारी' की यह व्याख्या मानने से इन्कार कर दिया और चाहा कि इस मामले को अनिश्चित रहने दिया जाय। इसका असली अर्थ यह था कि जब कभी कोई राष्ट्र इस तरह का हमला करे तो उस वक़्त सफलतापूर्वक हस्तक्षेप करने का अधिकार राष्ट्र-संघ के हाथ में देना इंग्लैंड नहीं चाहता था।

हाल में सोवियट रूस, पोलैंड, एस्टोनिया, लटविया, लियुएनिया, रूमानिया, ईरान, तुर्की, अफ़ग़ानिस्तान, जेकोस्लोवेकिया और यूगोस्लाविया के बीच में एक-दूसरे पर हमला न करने का जो 'पैक्ट' या तो राजीनामा हुआ है उसमें आक्रमणकारी की यह व्यापक व्याख्या पूरी तरह स्वीकार की गई है। इस राजीनामे के साथ फ्रांस ने भी अपनी सम्पूर्ण सहमति प्रकट की है। रूस के पश्चिमी पड़ोसियों में से अकेला फ़िनलैंड ही इस समझौते में शामिल नहीं हुआ है। उसपर ब्रिटेन का बहुत असर है।

निःशस्त्रीकरण परिपद् में हवाई जहाजों से गोले बरसाने के मामले में ब्रिटेन ने जो विरोधी रुख इस्तिथार किया वह दूसरी मशहूर मिसाल है। हालाँकि क्ररीव-क्ररीव सभी राष्ट्रों ने बम-वर्षा के इस रिवाज को बिल्कुल उठा देने की ख्वा-हिश जाहिर की (मुझे याद नहीं कि ब्रिटेन के पिट्टू इराक और हालैंड के सिवा और किसी देश ने यह इच्छा प्रकट न की हो)। फिर भी ब्रिटेन जिसे 'शान्ति-रक्षा के लिए बम-वर्षा करना' कहता है उसे क़ायम रखने पर उसका आप्रह बना ही रहा। जिस वक़्त में यह खत लिख रहा हूँ उस वक़्त भी हिन्दुस्तान की उत्तरी-पश्चिमी सीमा पर हवाई हमला होने और ब्रिटेन की शाही हवाई सेना द्वारा गाँवों पर बम बरसाये जाकर उन्हें नष्ट करने का हाल अख़बारों में आया है।

राष्ट्र-संघ चीन में जापान के हमले की निन्दा कर रहा था उसी वक्त अंग्रेजी, फ्रेंच और दूसरी हथियारों की दुकानें जापान और चीन दोनों को आजादी के साथ हथियार और लड़ाई के सामान पहुँचा रही थीं। जाहिर है कि सचमूच निःशस्त्रीकरण होजाय तो इन दुकानों का पटरा बँट जाय, क्योंकि इनका सारा व्यापार जाता रहे। इसलिए उनके ख्याल से जो बड़ी भारी विपत्ति की बात है उसे रोकने के लिए वे खूब कोशिश करते हैं। असल में वे इससे भी आगे बढ़ते हैं। राष्ट्र-संघ ने खानगी तौर पर हथियार बनाने के मामले की जाँच करने के लिए एक खास कमीशन बिठाया था। वह इस नतीजे पर पहुँचा कि ये दुकानें लड़ाई की खबरें फैलाने और अपने-अपने देशों को लड़ाकू नीति इस्तिहार करने की प्रेरणा करने में लगी रही हैं। यह भी पाया गया कि ये दुकानें अलग-अलग देशों के जल और स्थल सेना-सम्बन्धी खर्च के बारे में झूठे समाचार फैलाती हैं, ताकि दूसरे देशों को अपना फ़ौजी खर्च बढ़ाने की प्रेरणा हो। वे एक देश को दूसरे देश से भिड़ाने की कोशिश करती हैं और हथियारों के मामले में होड़ लगाने की वृत्ति बढ़ाती हैं। वे सरकारी कर्मचारियों को रिश्त देती और लोकमत पर असर डालने के लिए अखबारों को खरीद लेती हैं। इतना ही नहीं, अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियाँ बनाकर और ठेके लेकर वे हथियारों और युद्ध के सामान के भाव बढ़ा देती हैं। राष्ट्र-संघ के जाँच-कमीशन ने सुझाया कि शस्त्रास्त्रों का खानगी तौर पर बनाना बन्द कर दिया जाय। निःशस्त्रीकरण-परिषद् में भी यह प्रस्ताव किया जा चुका है। मगर वहाँ भी विरोध ब्रिटिश सरकार की तरफ से ही हुआ और लगातार हुआ। अलग-अलग देशों के शस्त्रास्त्र बनाने के इन कारखानों का आपस में गहरा ताल्लुक होता है। वे देश-प्रेम से नाजायज फ़ायदा उठाकर मौत के साथ खेलते हैं, फिर भी उनका अपना काम अन्तर्राष्ट्रीय है। उनके संगठन को 'गुप्त अन्तर्राष्ट्रीय संघ' (Secret International) का नाम दिया गया है। यह स्वाभाविक है कि ये लोग निःशस्त्रीकरण पर आपत्ति करें और इस बारे में समझौता न होने देने के लिए इनसे जितना कुछ हो सकता था वह सब इन्होंने किया ही। इनके आदमी ऊँचे-से-ऊँचे राजनैतिक हलकों में आते-जाते हैं और इनकी मनहूस शक्लें परदे के पीछे से डोर हिलाती हुई जिनेवा में दर्शन देती रही हैं।

इस 'गुप्त अन्तर्राष्ट्रीय संघ' के साथ अबसर अलग-अलग सरकारों के गुप्तचर-विभाग या खुफ़िया पुलिस का गहरा सम्बन्ध होता है। हरेक सरकार दूसरे देशों के पोशीदा हालात जानने के लिए जासूस नौकर रखती है। कभी-कभी ये जासूस पकड़े जाते हैं और उसी समय उनकी सरकार झट कह देती है कि ये हमारे आदमी नहीं हैं। आर्थर पोन्तनबी कुछ साल पहले, मेरे ख्याल से, ब्रिटिश सरकार के वैदेशिक उपमन्त्री थे। आजकल वे लार्ड पोन्तनबी बन गये हैं। इन गुप्तचर-विभागों की चर्चा करते

बहुत मुश्किल है। दूसरी ओर इस तरह का समझौता न हुआ तो जर्मनी को फिर से शस्त्र धारण न करने के लिए किस मुंह से कहा जा सकता है? और नाज़ी जर्मनी ने हथियार उठा लिये तो फिर युद्ध छिड़ने में देर नहीं लगेगी! इस तरह योरोप दल-दल में फँस गया है! इन सब बातों को ध्यान में रखने से ही यह बात समझ में आ सकती है कि हाल में इटली, जर्मनी, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच जो चतुरंगी समझौता हुआ है वह सिर पर लटकती हुई लड़ाई की तलवार को गिरने से रोकने की ओर ढालने की ही एक कोशिश है और सोवियट ने अपने पड़ोसियों के साथ आपस में हमला न करने का जो समझौता किया है वह भी आगामी युद्ध से बचने का ही उपाय है।

इस बीच निःशस्त्रीकरण परिपद् तेजी के साथ एक तरह की शस्त्रीकरण-परिपद् होती जा रही है। जर्मनी तो बीच-बीच में शस्त्र धारण करने की धमकी देता ही रहता है। जापान ने भी बड़ी शान्ति के साथ ऐलान कर दिया है कि दो वर्ष बाद जब ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस के साथ किये हुए वर्तमान समझौते की अवधि पूरी होगी तो वह अपनी जलसेना बढ़ायेगा। (यह समझौता वाशिंगटन-परिपद् में १९२२ में हुआ था)। निःशस्त्रीकरण परिपद् के सफल होने में बहुतेरी दिक्कतें हैं। इन्हें बढ़ाने के लिये परदे की आड़ में वेशुमार पड़्यंत्र चलते रहते हैं। ये कार्रवाइयाँ शस्त्रास्त्र बनानेवाले व्यापारियों के बड़ी-बड़ी तनख्वाहें पानेवाले आदमी खास तौर पर करते रहते हैं। आज की पूंजीवादी दुनिया में अस्त्र-शस्त्र और नाशकारी यंत्र बनाने का धन्धा बड़े ही मुनाफ़े का उद्योग है। ये हथियार बनाये तो जाते हैं अलग-अलग देशों की सरकारों के लिए, क्योंकि आमतौर पर लड़ाई सरकारें ही करती हैं, फिर भी विचित्र बात यह है कि हथियार बनानेवाले खानगी व्यापारी होते हैं। इन कारखानों के मुख्य मालिक खूब मालदार होजाते हैं और उनका सरकारों से गहरा सम्पर्क रहता है। शुरू की किसी चिट्ठी में सर वेसिल ज़हरोफ़ नाम के एक ऐसे ही आदमी का थोड़ा-सा हाल मैं तुम्हें बता चुका हूँ। हथियार बनाने वाले कारखानों के हिस्सों पर बड़ा मुनाफ़ा मिलता है और उनकी अक्सर माँग रहती है। उस दिन यह साबित हुआ था कि इंग्लैंड के बहुत-से बड़े-बड़े कर्मचारियों, यहांतक कि मंत्रियों, लट्-पादरियों, पार्लमेण्ट के सदस्यों और दूसरे बड़े-बड़े सार्वजनिक व्यक्तियों के हिस्से भी इन कम्पनियों में हैं।

लड़ाई से और लड़ाई की तैयारियों से इन हथियार बनानेवाले कारखानों को फ़ायदा होता है। वे सामूहिक मृत्यु का व्यापार करते हैं और जो कोई उन्हें क़ीमत देता है निष्पक्ष होकर उसीके हाथों वे अपने नाशकारी यन्त्र बेच देते हैं। जिस वक़्त

इलाक़े अपने राज्य में मिला लिये हैं। इसलिए एशिया और अफ़्रीका में मौजूदा हालत बनी रहने का मतलब यह है कि साम्राज्यवादी शोषण जारी रहे

इस वर्तमान स्थिति को कायम रखने के लिए जो समझौते या कार्रवाइयाँ योरोप में हुई हैं उनसे अबतक अमेरिका का संयुक्तराष्ट्र अलग रहा है। लेकिन मालूम होता है वह भी अब योरोप की प्रणाली में थोड़ा-थोड़ा फँसता जा रहा है।

: १६२ :

राष्ट्रपति रूज़वेल्ट का रक्षा का प्रयत्न

४ अगस्त, १९३३

यह किस्सा ख़त्म करने से पहले मैं तुम्हें अमेरिका के संयुक्तराष्ट्र की एक झाँकी और करा देना चाहता हूँ (और अब इस कहानी के पूरा होने में बहुत देर नहीं की जा सकती)। इस वक़्त अमेरिका में एक महान् और मनोहर-सा प्रयोग हो रहा है। दुनिया की आँखें उसपर लगी हुई हैं, क्योंकि उसके परिणाम पर यह बात निर्भर है कि भविष्य में पूँजीवाद किधर जायगा। मैं यह फिर से कहूँ कि अमेरिका अभीतक सबसे उन्नत पूँजीवादी देश है। मालदार भी वही सबसे ज्यादा है और उसके औद्योगिक यंत्र और कला दूसरे देशों से उन्नत हैं। उसे किसी और मुल्क का ख़याल देना नहीं है और उसपर अगर किसीका क़र्ज़ है तो वह अपने ही नागरिकों का है। उसका निर्यात-व्यापार बहुत है और बढ़ रहा है; फिर भी यह उसके बड़े भारी भीतरी व्यापार का एक छोटा-सा भाग (१५ फ़ीसदी के करीब) है। यह देश लगभग सारे योरोप के बराबर बड़ा है। मगर बड़ा भारी फ़र्क़ यह है कि जहाँ योरोप कई छोटे राष्ट्रों में बँटा हुआ है, जिनकी सीमाओं पर भारी चुंगी लगती है, वहाँ संयुक्तराष्ट्र के अपने इलाक़े के भीतर ऐसी कोई व्यापारिक बाधाएँ नहीं हैं। इसलिए योरोप की बनिस्बत अमेरिका में ख़बरदस्त भीतरी व्यापार का बिकास बहुत आसान था। योरोप के दरिद्र और क़र्ज़ से दबे हुए देशों से अमेरिका को ये सब सहूलियतें ज्यादा थीं। उसके पास सोने, रुपये और माल की बहुतायत थी।

यह सब होते हुए भी पूँजीवादी संकट ने उसे आदवाया और उसका सारा घर तोड़ दिया। जिस राष्ट्र के जीवट और कार्य-शक्ति का कोई पार नहीं था उसपर भाग्यवाद छा गया। सारा देश तो फिर भी धनी बना रहा और ख़या भी कहीं ग़ायब नहीं होगया, मगर वह थोड़े-से स्थानों में जमा होगया। न्यूयार्क में फिर भी करोड़ों-अरबों की पूँजी के ढेर दिखाई देते थे। जे०पियरपोंप्ट नागन नामक बड़ा साहूकार अब

हुए पोन्सनबी ने मई १९२७ में कामन्स सभा में कहा था—“जब हम नैतिकता की बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, उस समय हमें इन सचाइयों का वास्तविक खयाल रखना चाहिए कि जालसाजी, चोरी, झूठ, रिश्वत और भ्रष्टाचार दुनिया के सभी वंदेशिक विभागों और मंत्रिमण्डलों में मौजूद हैं।..... में कहता हूँ कि माने हुए नैतिक नियमों के अनुसार हमारे जो प्रतिनिधि विदेशों में रहते हैं वे वहाँके गुप्त कागजात के भेद मालूम न करें तो यह समझा जायगा कि उन्होंने अपना कर्तव्य पालन नहीं किया।”

चूँकि इन गुप्तचर-विभागों का काम छिपकर होता है इसलिए उनपर क़ाबू रखना मुश्किल है। उनका अपने-अपने देशों की विदेशी नीति पर बड़ा असर होता है। इनका संगठन व्यापक और बलशाली होता है। शायद इस समय ब्रिटिश खुफिया विभाग सबसे प्रबल और दूर-दूर तक फैला हुआ है। एक मिसाल ऐसी भी मिलती है कि एक मशहूर ब्रिटिश जासूस रूस में एक उच्च सोवियट कर्मचारी बन गया था। वर्तमान भारत-मन्त्री सर सेम्युअल होर युद्ध-काल में रूस में ब्रिटिश खुफिया विभाग के सरदार थे। उन्होंने हाल ही में कुछ गर्व के साथ खुले तौर पर कहा है कि ख़बरें मालूम करने का उनका तरीक़ा इतना बढ़िया था कि रासपुटिन के खून का हाल और किसीकी वनिस्वत उन्हें बहुत पहले मालूम होगया था।

निःशस्त्रीकरण-परिपद् के सामने असली कठिनाई यह थी कि दो तरह के देश हैं—सन्तुष्ट और असन्तुष्ट, शासक और शासित, मौजूदा स्थिति को क़ायम रखना चाहनेवाले और उसमें परिवर्तन चाहनेवाले। जिस तरह प्रभुता-प्राप्त वर्ग और दलित-वर्ग में सच्ची स्थिरता नहीं हो सकती, ठीक उसी तरह इन दो तरह के मुल्कों में कोई स्थायी समझौता नहीं होसकता। सब बातों को देखते हुए राष्ट्र-संघ इन जोरावर राष्ट्रों की चीज़ है। इसलिए उसकी कोशिश मौजूदा स्थिति को क़ायम रखने की ही है। रक्षा के समझौतों और ‘आक्रमणकारी’ राष्ट्र की व्याख्या के प्रयत्नों का यही उद्देश्य होता है कि जो हालत है वह बनी रहे। कुछ भी हो जाय, जिन राष्ट्रों का राष्ट्र-संघ पर नियंत्रण है उनमें से किसी एक को भी शायद संघ ‘आक्रमणकारी’ कहकर बुरा नहीं बतायगा, वह हमेशा ऐसी चालवाज़ियाँ करेगा कि दूसरा पक्ष ही ‘आक्रमणकारी’ घोषित हो जाय।

शान्तिवादी और दूसरे लोग, जो युद्ध रोकना चाहते हैं, इन रक्षा के समझौतों का स्वागत करते हैं। इस तरह वे एक अर्थ में अन्यायपूर्ण वर्तमान स्थिति को क़ायम रखने में मदद देते हैं। योरोप के बारे में अगर यह बात सही है तो एशिया और अफ़्रीका के बारे में और भी सही है, क्योंकि वहाँ साम्राज्यवादी राष्ट्रों ने बड़े-बड़े

संगठित अपराधों में सबसे मशहूर और दिल दहलानेवाला अपराध यह था कि धनवानों के छोटे-छोटे बच्चों को गुण्डे उड़ा लेजाते थे और अपने क्रव्जे में रखकर उनके बदले में रुपया ऐंठते थे। एक-दो साल पहले की ही बात है, लिण्डबर्ग का दूध पीता लड़का इसी तरह उड़ाया गया था और उसकी पाशविक दंग से हत्या की गई थी। इस घटना से संसार के हृदय पर बड़ा आघात पहुँचा।

इन सब बातों के साथ व्यापारिक मन्दी मिल गई और यह भी मालूम होगया कि बहुत-से बड़े-बड़े राजकर्मचारी और व्यवसायी भ्रष्ट और अयोग्य हैं। इससे अमेरिका के लोग घबरा उठे। १९३२ के नवम्बर में राष्ट्रपति के चुनाव के अवसर पर लाखों आदमियों की दृष्टि रूजवेल्ट की ओर गई और उन्हें आशा हुई कि वह उनका कष्ट कम करेगा। रूजवेल्ट 'गिले' पक्ष में था और लोकशाही दल (Democratic Party) का आदमी था। इस दल के आदमी क्वचित् ही संयुक्तराष्ट्र के राष्ट्रपति हुए हैं।

अलग-अलग देशों के विशेष लक्षणों को सदा ध्यान में रखकर उनकी तुलना करना दिलचस्प और फ़ायदेमन्द होता है। इसलिए संयुक्तराष्ट्र की हाल की घटनाओं का जर्मनी और इंग्लैंड की घटनाओं से मुकाबिला करने का लोभ होता है। जर्मनी के साथ अमेरिका की बड़ी समानता है, क्योंकि ख़ूब औद्योगिक देश होते हुए भी दोनों में ही किसानों की आबादी बहुत है। जर्मनी की सारी आबादी में २५ फ़ीसदी और संयुक्तराष्ट्र में ४० फ़ीसदी किसान हैं। राष्ट्रीय नीति के निर्माण में इन किसानों का असर पड़ता है। इंग्लैंड में यह बात नहीं है, क्योंकि वहाँ थोड़े-से किसान हैं और उनपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। हाँ, अब ज़रा उनकी उन्नति की कोशिश की जा रही है।

जर्मनी के नाज़ी आन्दोलन का मुख्य कारण यह था कि नीचे दर्जे के वञ्चित मध्यमवर्ग की तादाद बहुत बढ़ गई थी और जर्मन सिक्के का भाव गिर जाने के बाद यह तादाद और भी तेज़ी से बढ़ रही थी। जर्मनी में यही वर्ग क्रान्तिकारी बना। ठीक यही वर्ग आजकल अमेरिका में बढ़ रहा है। ये 'सफ़ेद कॉलर के गरीब' ('White Collar proletariat') कहलाते हैं, ताकि मजदूर-वर्ग के गरीबों से इनका भेद किया जा सके। मजदूर वर्ग शायद ही कभी सफ़ेद कॉलर लगाता है।

तुलना करने की दूसरी बातें हैं सिक्के सम्बन्धी संकट, मार्क, पाउण्ड और डालर का सोने के विनिमय से हटना, नोटों का ख़ूब छपा जाना और बैंकों का दिवाला निकलना। इंग्लैंड में बैंकों का दिवाला न निकलने का कारण यह था कि वहाँ छोटे-छोटे बैंक बहुत नहीं हैं और साहूकारी के व्यवसाय का नियन्त्रण चार बड़े बैंकों के हाथ में है। दाढ़ी दातों में घटना-चक्र तीनों में एकसा ही रहा। पहले जर्मनी में संकट आया, फिर इंग्लैंड में और बाद में संयुक्तराष्ट्र में। मामूली तौर पर नाटियों के, १९३१ के

भी अपनी विलास-सामग्री से सजी बढ़िया नाव का दिखावा करता था। कहते हैं, उसपर ६० लाख पाउण्ड खर्च हुआ है। फिर भी न्यूयार्क की हाल ही में 'भूखा शहर' बताया गया है। शिकागो जैसे बड़े-बड़े नगरों की म्यूनिसिपैलिटियां लगभग दीवालिया हो चुकी हैं और वे अपने हजारों नौकरों का वेतन नहीं चुका सकतीं। इसी शिकागो शहर में 'उन्नति की शताब्दी' (The Century of Progress) के नाम से एक शानदार नुमाइश या 'विश्व-मेला' भर रहा है।

ये विषमतायें अमेरिका तक ही महद्वद नहीं हैं। लन्दन में जाकर देखो, उच्च-वर्ग के अंग्रेजों में सर्वत्र वैभव और विलास के दरिया बहते दिखाई देंगे। अलबत्ता वहाँकी शरीर वस्तियों में यह बात नहीं है। लंकाशायर या उत्तरी या मध्य इंग्लैण्ड के कुछ भागों में जाकर देखोगी तो तुम्हें बेकारों की लम्बी-लम्बी कतारें, पिचके हुए गाल और जीवन के दुःखपूर्ण दृश्य ही दिखाई देंगे।

इन वर्षों में अपराधों की वृद्धि, लास तीर पर संगठित दलों द्वारा होनेवाले जुमों की वृद्धि, खून हुई है। यानी गुण्डों के दल-के-दल मिलकर काम करते हैं और जो लोग बाधक होते हैं उन्हें अक्सर गोली से उड़ा देते हैं। कहते हैं कि ये जुर्म उस वक़्त से ज्यादा बढ़े हैं जबसे कि शराब-बन्दी का क़ानून पास हुआ है। मदिरा-निषेध का यह क़ानून महायुद्ध के बाद ही बन गया था। इसका एक कारण यह था कि बड़े-बड़े फ़ारख़ानेदार अपने मजदूरों को शराब से इसलिए दूर रखना चाहते थे कि वे लोग ज्यादा अच्छा काम कर सकें। परन्तु धनवान लोग स्वयं इस क़ानून की अवहेलना करते थे और बाहर से मँगा-मँगाकर शराब पीते थे। धीरे-धीरे शराब का शैरक़ानूनी व्यापार बहुत बढ़ गया। यह इस तरह होता था कि शराब बाहर से भी छिपकर मँगाई जाती थी और देश में भी गुप्त रूप से बनाई जाती थी। आम तौर पर छिपकर तैयार की हुई शराब असली शराब से कहीं घटिया और हानिकारक होती थी। यह शराब गुप्त स्थानों पर बहुत ऊँचे दामों में बेची जाती थी और इस तरह के ख़ानगी शराबख़ाने सभी बड़े-बड़े शहरों में हजारों की तादाद में होगये। ये सब कार्र-वाइयाँ शैरक़ानूनी तो थीं ही, इन्हें जारी रखने के लिए पुलिसवालों और राज्याधिका-रियों को रिश्वत दी जाती थी और कभी-कभी उन्हें डराया-धमकाया भी जाता था। क़ानून की इस व्यापक अवहेलना से गुण्डों के दल बढ़ गये। इस तरह 'मदिरा-निषेध' का एक ओर तो यह नतीजा हुआ कि मजदूरों और देहातियों को फायदा पहुँचा। दूसरी ओर बड़ा नुक़सान भी हुआ। यानी चोरी से शराब बनानेवालों का एक ज़बरदस्त स्वार्थी दल पैदा होगया। सारा देश दो दलों में बँट गया। मदिरा-निषेध के पक्ष वाले 'ड्राई' (Drys) कहलाये जाने लगे और उसका विरोध करनेवाले 'वील्स' (Wets) कहलाये।

लोगों को काम देने के लिए उधार लेकर सार्वजनिक कामों में लगाने के लिए थी।

(६) मदिरा-निषेध का कानून रद करने की कार्रवाई जल्दी से पूरी करली।

ये बड़ी-बड़ी रकमों धनवान लोगों से उधार ली जानेवाली थीं। रूजवेल्ट की सारी नीति यही थी और यही है कि लोगों की खरीद करने की शक्ति बढ़ाई जाय। उनके पास रुपया होगा तो वे खरीदेंगे और व्यापारिक मन्दी अपनेआप कम हो जायगी। इसी उद्देश्य से वह सार्वजनिक कामों की बड़ी-बड़ी योजनाएँ हाथ में ले रहा है, ताकि उनमें मजदूर लगाये जा सकें और वे रुपया कमा सकें। इसी उद्देश्य से वह मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने और उनके काम के घण्टे घटाने की कोशिश कर रहा है। रोजाना काम के घण्टे जितने कम होंगे उतने ही अधिक आदमियों को काम मिलेगा।

यह रवैया उस रवये से बिल्कुल उलटा है जो संकट और मन्दी के समय कारखाने के मालिकों का रहा करता है। वे प्रायः उत्पत्ति का खर्च कम करने के लिए मजदूरी घटाने और काम के घण्टे बढ़ाने की कोशिश किया करते हैं। मगर रूजवेल्ट का कहना यह है कि अगर हमें फिर से सामूहिक रूप से माल पैदा करना है तो हमें सामूहिक रूप से ऊँची मजदूरी देकर जनता में उस माल को खरीदने की शक्ति पैदा करनी चाहिए।

रूजवेल्ट की सरकार ने सोवियट रूस को भी अमेरिका की रुई खरीदने की गरज से कर्ज दिया। दोनों सरकारों में इस बात की भी चर्चा चल रही है कि दोनों देशों में बड़े पैमाने पर माल का लेन-देन कैसे होसकता है।

अबतक अमेरिका की सरकार विशुद्ध पूंजीवादी सरकार रही है। वहाँ पूरी अबाधित स्पर्धा यानी बेरोक लाग-डाँट रही है। वह 'व्यक्तिवादी' राज्य (Individualistic State) कहलाता रहा है। रूजवेल्ट की नई नीति का इसके साथ मेल नहीं बैठता, क्योंकि वह कई तरह व्यवसाय में दखल दे रहा है। इसलिए वह एक प्रकार से उद्योग-धन्यों पर राज्य का बहुत-कुछ नियंत्रण स्थापित कर रहा है। मगर वह इसे दूसरे नाम से पुकारता है।

असल में ये कार्रवाइयाँ सरकारी समाजवाद की हैं। यानी सरकार इस बात की व्यवस्था कर रही है कि काम के घण्टे कितने हों और मजदूरी की शर्तें क्या हों और उद्योगों पर सरकार का नियंत्रण रहे और भयंकर प्रतिस्पर्धा या लाग-डाँट बन्द हो। ऐसे वह यों कहता है कि "योजना में सब शामिल हों और सब उसे पूरी करने की कोशिश करें।"

यह काम अब अमेरिका वाले अपने स्वभाव के अनुसार पूरे जोर और जोश से साथ कर रहे हैं। दूच्चों से काम लेने की प्रथा उठाती गई है। (मजदूरों के मामले

चुनाव में ब्रिटिश राष्ट्रीय सरकार के, और नवम्बर १९३२ के चुनाव में राष्ट्रपति रूजवेल्ट के सहायक अपने-अपने देश में एक ही वर्ग के लोग थे। यह वर्ग या नीचे दर्जे का मध्यमवर्ग। इसके बहुत लोग पहले दूसरे दलों में रह चुके थे। इस तुलना को बहुत दूर तक नहीं खींचना चाहिए। इसका एक कारण तो यह है कि राष्ट्र-राष्ट्र में भेद होता है, और दूसरा कारण यह है कि स्थिति जर्मनी में जहाँ तक पहुँच चुकी है वहाँ तक इंग्लैंड और अमेरिका में अभी तक नहीं पहुँची है, मगर खास बात यह है कि उद्योगवाद में ख़ूब आगे बढ़े हुए इन तीनों ही देशों से बहुत मिलते-जुलते आर्थिक प्रभाव काम कर रहे हैं। इसका परिणाम भी एक-सा हुए बिना नहीं रहेगा। यह हाल फ़्रांस में (या दूसरे देशों में) उसी हद तक नहीं है, क्योंकि फ़्रांस अभी तक कृषि-प्रधान ज्यादा और औद्योगिक दृष्टि से कम उन्नत है।

“रूजवेल्ट ने १९३३ के मार्च के शुरू में राष्ट्रपति का ओहदा सम्हाला। काम सम्हालते ही उसे बैंकों की ज़बरदस्त उथल-पुथल का सामना करना पड़ा। भयंकर मन्दी तो पहले से थी ही। काम सम्हालने के वृत्त देश की जो हालत थी, कुछ सप्ताह के बाद उसका वर्णन करते हुए उसने कहा था कि देश इस समय “धीरे-धीरे मर रहा है।”

रूजवेल्ट ने तुरन्त निश्चित कार्रवाई की। उसने अमेरिका की कांग्रेस से बैंकों, फ़ारख़ानों और किसानों के सम्बन्ध में कार्रवाई करने के लिए अधिकार माँगे। कांग्रेस उथल-पुथल यानी अर्थ-संकट से बिल्कुल घबराई हुई थी और रूजवेल्ट के पक्ष में लोगों की भावनाओं का उसपर असर था, इसलिए उसने उसे अधिकार देदिये। रूजवेल्ट सर्वेसर्वा बन गया। सब उसकी ओर देखने लगे कि वह उन्हें विपत्ति से बचाने के लिए कोई-न-कोई कारगर उपाय फ़ौरन करेगा। हुआ भी वैसा ही। उसने बड़ी तेज़ी से काम किया और महीने-बीस दिन के भीतर-भीतर अपने अलग-अलग तरह के कामों से सारे संयुक्तराष्ट्र को हिला दिया। उसका आत्मविश्वास भी ख़ूब बढ़ गया।

राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने जो अनेक निर्णय किये उनमें से ये भी थे:—

(१) सोने का विनिमय छोड़ दिया और डालर का भाव गिर जाने दिया। इससे कर्जदारों का बोझा हलका होगया।

(२) विशेष सहायता देकर किसानों का कष्ट दूर किया और कृषि का बोझा हलका करने के लिए दो अरब डालर का बड़ा भारी कर्ज जारी करवाया।

(३) जंगलात के लिए और बाढ़ों के रोकने के काम के लिए तुरन्त ढाई लाख मज़दूर भर्ती किये। इसका उद्देश्य बेकारी कम करना था।

(४) बेकारी घटाने के लिए कांग्रेस से अस्सी करोड़ डालर माँगे। ये मंजूर होगये।

(५) लगभग तीन अरब डालर की ज़बरदस्त रक़म अलग रखदी। यह

हिटलर नरम पड़ गया है। वह सोवियट रूस के साथ भी सम्पर्क बढ़ा रहा है।

आज अमेरिका में और दूसरे देशों में भी बड़ा सवाल यह है, "क्या रूजवेल्ट को कामयाबी मिलेगी?" वह बड़ी बहादुरी से पूंजीवाद को कायम रखने की कोशिश कर रहा है; लेकिन उसकी सफलता का अर्थ यह है कि बड़े-बड़े व्यवसायियों की गद्दी छिन जावे। और यह मुमकिन नहीं दीखता कि बड़े व्यवसायी इसे चुपचाप वर्दाश कर लें। अमेरिका के इन बड़े व्यवसायियों के स्थायी स्वार्थ आज की दुनिया में सबसे प्रबल समझे जाते हैं, और ये लोग राष्ट्रपति रूजवेल्ट के कहने से ही सत्ता और विशेष अधिकार छोड़नेवाले नहीं हैं। अभी तो लोग लोकमत को देखकर चूप हैं और राष्ट्रपति की लोकप्रियता के कारण दबे हुए-से हैं। परन्तु वे अपने मौके की घात में जरूर हैं। अगर कुछ महीनों के भीतर हालत में कुछ सुधार नहीं हुआ तो यह उम्मीद रक्खी जाती है कि लोकमत रूजवेल्ट के खिलाफ हो जायगा और उस समय ये बड़े व्यवसायी खुलकर सामने आयेंगे। बहुत-से अधिकारपूर्ण राय रखनेवालों का खयाल है कि राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने असम्भव कार्य हाथ में लिया है और उसे सफलता नहीं मिलेगी। वह असफल हुआ तो संसार की मन्दी और भी बढ़ जायगी और अमेरिका में बड़े व्यवसायियों की सत्ता फिर सर्वोपरि होजायगी। शायद उनका बल पहले से भी बढ़ जाय, क्योंकि रूजवेल्ट सरकारी समाजवाद का जो ढाँचा खड़ा कर रहा है वह उस बहुत बड़े व्यवसायियों के व्यक्तिगत लाभ के लिए काम में लाया जायगा। अमेरिका में मजदूर-आन्दोलन तो जोरदार है ही नहीं, उसे आसानी से दबाया जा सकता है।

दूसरा खयाल यह है कि अमेरिका (और शायद इंग्लैण्ड भी) जर्मनी की राह पर जायगा और फ्रैसिस्ट प्रवृत्तियाँ बढ़ेंगी। रूजवेल्ट के सिक्के का भाव घटा देने की नीति से कई समुदायों को फ्रायदा है, लेकिन मध्यमवर्ग के लोगों को नुकसान है; क्योंकि उनकी आमदनी बंधी हुई है और डालर की क़ीमत घटने पर भी इन्हें तो वही तनख्वाह मिलती है। इस तरह 'सफ़ेद कॉलर' वाली जनता बढ़ती जा रही है और मजदूरों से भी कहीं अधिक भ्रान्तिकारी बनती जा रही है। मध्यमवर्ग के ये भ्रान्तिकारी अंग किसानों के साथ मिलकर अमेरिका में फ्रैसिस्ट परिस्थितियाँ पैदा कर सकते हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि जर्मनी के हालात की नक़ल की जायगी; लेकिन यह सम्भावना है कि बेचारे हटिश्यों की और भी कमबख़्तता आयगी, विदेशी और यहूदी लोगों के प्रति सहिष्णुता कम होगी और दमन बढ़ जायगा। यानी भाषण देने और नमाचारपत्र निकालने दंगरा के नागरिक अधिकार छीन लिये जायेंगे। उडरो विल्सन के बाद अमेरिका में रूजवेल्ट जैसा उदार और सुसंस्कृत राष्ट्रपति नहीं हुआ है। अगर वह ऐसी शक्तियों का प्रतिनिधि मालूम होता है जो उपल-नुपल तीव्र होने के साथ-साथ

में वच्चों की उम्र सोलह साल तक की मानी गई है) । अधिक मजदूरी, ज्यादा वेतन और कम घण्टे काम, यही मूल मंत्र बने हुए हैं । खुशहाली के इस आन्दोलन में, कहते हैं, सारा देश एक बड़ा भर्ती का विज्ञापन-केन्द्र बना हुआ है । हवाई जहाज इधर से उधर दौड़ते और कारखाने के मालिकों और दूसरे लोगों से बेतार के तार द्वारा अपीलें करते फिरते हैं । प्रत्येक बड़े-बड़े उद्योग को प्रेरणा की गई है कि वे ऊँची मजदूरी देने के अलग-अलग नियम बनावें और उनपर अमल करने की प्रतिज्ञा करें । जो उचित ढंग के नियम नहीं बना पाते हैं उन्हें हलकी-सी धमकी देदी जाती है कि वे नहीं बनायेंगे तो सरकार बना देगी । मालिकों से अलग-अलग प्रतिज्ञा-पत्रों पर भी हस्ताक्षर कराये जा रहे हैं कि वे अपने-अपने नौकरों की तनकाहें बढ़ायेंगे और काम के घण्टे घटायेंगे । जो मालिक इस मामले में आगे बढ़कर काम करेंगे उन्हें सरकार सम्मान के बिल्ले देना चाहती है और जो पीछे रहेंगे उन्हें शर्माने के लिए हर शहर के डाकखाने में सम्मान-प्राप्त लोगों की सूची रखी जायगी ।

इन सब उपायों से भावों और व्यापार में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन असली और मार्क का सुधार यह हुआ है कि व्यवसाय की भावना और साहस बढ़ गया है । हार का खयाल बहुत कुछ जाता रहा है और आमतौर पर साधारण जनता में और खासतौर पर मध्यमवर्ग में राष्ट्रपति रूजवेल्ट के प्रति खूब श्रद्धा है । अभी से ही लोग उसकी तुलना अमेरिका के महान् वीर राष्ट्रपति लिंकन से करने लगे हैं । उसने भी बड़े संकट यानी गृह-युद्ध के समय काम सम्भाला था ।

योरप तक में बहुत लोग रूजवेल्ट की तरफ़ देखने लगे थे और यह आशा करने लगे थे कि मन्दी को दूर करने के लिए वह दुनिया को रास्ता दिखायगा । मगर अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक परिपद के समय दूसरे देशों के प्रतिनिधियों में उसकी लोकप्रियता ज़रा घट गई, क्योंकि उसने अपने प्रतिनिधियों को यह हिदायत करदी थी कि वे डालर का भाव सोने के साथ बाँधने या और कोई ऐसा काम करने से इन्कार कर दें जिससे संयुक्तराष्ट्र में उसकी बड़ी-बड़ी योजनाओं में बाधा पड़ने की सम्भावना हो ।

रूजवेल्ट की नीति निश्चित रूप से आर्थिक राष्ट्रवाद की नीति है और वह अमेरिका की स्थिति सुधारने पर तुला हुआ है । योरप की कुछ सरकारों को यह पसन्द नहीं है और बैंक वाले, खासतौर पर फ़्रांस के बैंक वाले, इस बात पर नाराज़ हैं कि उनके सोने के विनिमय को खतरा है । अंग्रेज़ लोग उसको ध्यान से देख रहे हैं ।

फिर भी रूजवेल्ट अपने पहले के राष्ट्रपति की बनिस्बत संसार के मामलों में ज्यादा अमली-हिस्सा ले रहा है । निःशस्त्रीकरण और दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में उसका रवैया इंग्लैण्ड से आगे बढ़ा हुआ और निश्चित है । उसकी मीठी चेतावनी से

ज्यादातर देशों में मजदूरों की वनिस्वत नीचे दर्जे के मध्यमवर्ग के लोग ज्यादा उग्र हैं। यह बात सबसे ज्यादा जर्मनी में और उससे कम इंग्लैण्ड और संयुक्तराष्ट्र और दूसरे देशों में दिखाई देती है। कमी-वेशी का कारण यह है कि राष्ट्रों के स्वभाव अलग-अलग हैं और अर्थ-संकट भी अलग-अलग मात्रा में आया है।

लड़ाई के बाद के कुछ वर्षों तक जो मजदूर-आन्दोलन इतना उग्र और क्रान्ति-कारी था, वह इतना नरम और भाग्यवादी क्यों बन गया ? जर्मनी का लोकसत्तात्मक समाजवादी दल बिना लोहा लिये ही क्यों टूट गया और उसने नाज़ियों के हमले से अपनेआपको चूर-चूर क्यों होजाने दिया ? अंग्रेज़ी मजदूर दल इतना नरम और प्रतिगामी क्यों है ? मजदूर दल के नेताओं पर अक्सर यह दोष लगाया जाता है कि वे अयोग्य होते हैं और मजदूरों को धोखा देते हैं। उनमें से बहुत-से जरूर इस दोष के पात्र हैं और यह देखकर दुःख होता है कि उनमें से कई लोग दुश्मन से मिल जाते हैं और मजदूर-आन्दोलन को अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का साधन बनाते हैं। वदग्रस्तनी से इन्सान के सभी कामों में मौक़ा देखकर काम निकालने की प्रवृत्ति मौजूद है। लेकिन यह प्रवृत्ति उस हालत में बहुत ही खेदजनक होजाती है जब अपनी भलाई के लिए लाखों पददलित और दुःखी मनुष्यों की आशाओं, आदर्शों और कुर्बानियों से अनुचित लाभ उठाया जाता है।

नेताओं का दोष होसकता है। मगर नेता भी तो आखिर मौजूदा हालत की ही पैदावार होते हैं। आमतौर पर कोई देश जिस योग्य होता है वैसे ही उसे शासक मिलते हैं और किसी आन्दोलन को नेता भी वैसे ही मिलते हैं जैसी कि अनुयायियों की सच्ची इच्छा होती है। असल बात यह है कि इन साम्राज्यवादी देशों में न तो मजदूर नेता और न उनके अनुयायी ही समाजवाद को एक जीवित धर्म के रूप में मानते थे और न यह समझते थे कि यह कोई तुरन्त चाहने लायक चीज़ है। उनका समाजवाद पूंजीवादी प्रणाली के साथ बहुत ज्यादा उलझ गया और बँध गया। पराधीन देशों के शोषण से जो क़ायदा हुआ उसका थोड़ा-सा हिस्सा उन्हें भी मिल गया और वे यह समझते रहे कि रहन-सहन के ऊँचे ढंग के लिए पूंजीवाद का क़ायम रहना जरूरी है। समाजवाद एक दूर का आदर्श बन गया। वह एक ऐसा स्वर्ग होगया जिसके सपने देखते रहें और वर्तमान से उसका कोई ताल्लुक न हो। स्वर्ग की पुरानी कल्पना की तरह समाजवाद भी पूंजीवाद का दास होगया।

इस तरह मजदूर दल, धर्मजीवी संघ, लोकसत्तात्मक समाजवादी लोग, दूसरा अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर-संघ और इस तरह के सारे संगठन मुद्यार के छोटे-छोटे प्रयत्नों में इतने फँस गये कि पूंजीवाद की सारी इमारत अछूती रह गई। उनका आदर्शवाद

अधिकाधिक फ़्रीसिजन की ओर झुक सकती हैं। लेकिन अभी तो वह एक तरह से संयुक्तराष्ट्र का सर्वेसर्वा हैं और नीचे पड़े हुए लोगों को ऊपर उठाने की भरसक कोशिश कर रहा है। संसार उसके महान् प्रयोग को देख रहा है।

: १६३ :

पार्लमेण्टों की असफलता

६ अगस्त, १९३३

हाल की घटनाओं की हमने ज़रा तफ़्तील के साथ देख-भाल की है और बहुत-सी ऐसी शक्तियों और प्रवृत्तियों पर विचार किया है जो हमारी आज की बदलती हुई दुनिया का रंग-रूप बना रही हैं। दो बातें खास तौर पर सामने आई हैं, जिनका ज़िक्र तो मैं पहले ही कर चुका हूँ लेकिन उनपर ज्यादा विचार करने की ज़रूरत मालूम होती है। इनमें से एक तो है लड़ाई के बाद के वर्षों में मज़दूर-आन्दोलन और पुराने ढंग के समाजवाद की असफलता, और दूसरी बात पार्लमेण्टों की असफलता या उनका ह्रास है।

मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि किस तरह जब १९१४ में महापुद्ग छिड़ा उस समय संगठित मज़दूर दल कुछ न कर सका और दूसरा अन्तर्राष्ट्रीय मज़दूर संघ (Second International) छिन्न-भिन्न हो गया। इसका कारण यह बताया गया था कि अचानक लड़ाई का धक्का लगने से भयंकर राष्ट्रीय भावनाएँ उत्तेजित हो गई थीं और लोगों पर थोड़े समय के लिए पागलपन सवार हो गया था। पिछले चार सालों में जो घटनाएँ हुई हैं, वे बिल्कुल दूसरी ओर कहीं ज्यादा आँखें खोलनेवाली हैं। इन चार वर्षों में जितनी महान् मन्दी रही है उतनी पूँजीवादी संसार ने पहले कभी नहीं देखी थी। इसलिए मज़दूरों पर मुसौबत का बोझ बढ़ता जा रहा है। फिर भी साधारण तौर पर कहीं भी और विशेषकर इंग्लैंड और संयुक्तराष्ट्र में साधारण मज़दूरों में सच्ची क्रान्तिकारी भावना पैदा नहीं हो पाई।

यह जाहिर है कि पुराने ढंग के पूँजीवाद का ढाँचा बिखर रहा है। जहाँतक बाहरी बातों का ताल्लुक है वहाँतक स्थितियाँ समाजवादी अर्थ-व्यवस्था की शकल में तब्दील होने के बिल्कुल मुआफ़िक मालूम होती हैं, मगर जिन लोगों को क्रान्ति की सबसे ज्यादा इच्छा हो सकती है उन मज़दूरों में से ही ज्यादातर का ऐसा कोई इरादा नहीं मालूम होता। क्रान्तिकारी भावनाएँ मज़दूरों से कहीं ज्यादा अमेरिका के पुराने ख़ाल के किसानों में दिखाई देती हैं और, जैसा मैं तुम्हें कई बार बता चुका हूँ,

होता था कि पूंजीवाद और पूंजीपति उनका शोषण करते हैं और इसलिए इन्हें उनपर थोड़ा गुस्सा आता था। लेकिन उन्हें मजदूर-वर्ग का और साम्यवादियों के हाथ में सत्ता आजाने का कहीं अधिक डर था। पूंजीपति लोग आम तौर पर इस फ्रैंसिस्ट लहर के साथ समझौता कर लेते थे क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था, कि साम्यवाद को रोकने का और कोई उपाय नहीं है। धीरे-धीरे जिस किसी को भी साम्यवाद का भय था वह इस फ्रैंसिज्म के साथ मिल जाता। इस तरह से कहीं कम और कहीं ज्यादा, जहाँ कहीं पूंजीवाद को खतरा है और साम्यवाद के मुकाबिले की सम्भावना दिखाई देती है, वहीं फ्रैंसिज्म का प्रचार होजाता है। फ्रैंसिज्म या उग्र राष्ट्रवाद और कम्यूनिज्म या साम्यवाद चक्की के दो पाट हैं जिनके बीच में पार्लमेण्टरी सरकारों या प्रतिनिधि-शासन का कचूजर निकल रहा है।

अब हम उस दूसरी मुख्य बात तक आ पहुँचे हैं जिसका मैंने इस खत के शुरू में जिक्र किया है। वह बात है पार्लमेण्टों की असफलता या उनका टूटना। पिछले खतों में सर्वोसर्वा शासकों के बारे में और पुराने ढंग की लोकसत्ता की असफलता के बारे में मैं तुम्हें काफी बातें बता चुका हूँ। यह बात रूस, इटली और मध्य-योरप में खूब अच्छी तरह जाहिर होगई है। जर्मनी में तो नाज़ियों के हाथ में सत्ता आने से पहले ही प्रतिनिधि-शासन का आत्मा होचुका था। संयुक्तराष्ट्र में हम देख चुके हैं कि किस तरह कांग्रेस राष्ट्रपति रूजवेल्ट को पूरे अधिकार दे चुकी है और एक तरह से उसे सर्वोसर्वा बना चुकी है। यह सिलसिला फ्रांस और इंग्लैंड में भी दिखाई देने लगा है। ले-वेकर योरप में यही दो देश ऐसे हैं जहाँ लोकसत्ता की लम्बी-से-लम्बी और मजबूत परम्परा रही है। आओ, पहले इंग्लैंड का ही विचार करें।

योरप के दूसरे देशों से इंग्लैंड का काम करने का तरीका बिल्कुल जुदा ही है। अंग्रेज़ लोग सदा पुरानी सूरतें ज़ायम रखने की कोशिश किया करते हैं और इसीलिए उनके यहांके परिवर्तन साफ़ नहीं दिखाई देते। साधारण दृष्टि से देखनेवाले को ऐसा लगता है कि ब्रिटिश पार्लमेण्ट का वही हाल है जो पहले था। मगर सच्ची बात यह है कि उसमें बहुत परिवर्तन हो गया है। पुराने जमाने में कामंस सभा अपनी सत्ता को सीधे तौर पर काम में लाती थी और उसके हरेक सदस्य की हर मामले में कुछ-न-कुछ चलती थी। अब मंत्रि-मण्डल या सरकार ही दड़े-दड़े सवाल तय करती है और कामंस सभा केवल 'हां' या 'न' कह सकती है। अबश्य ही सभा 'न' कहकर सरकार को खदेड़ सकती है, मगर यह कार्रवाई इतनी गम्भीर है कि बहुत ही कम होती है, क्योंकि इससे दली झंझट पैदा होती है और आम चुनाव करना पड़ता है। इस तरह किसी सरकार का कामंस-सभा में दहमन हो तो वह जो चाहे सो कर

जाता रहा और वे बड़े-बड़े नौकरशाही संगठन होगये। उनमें न प्राण रहा, न सच्चा बल।

नये साम्यवादी दल की दूसरी स्थिति थी। यह मजदूरों के लिए ऐसा सन्देश लेकर आया था, जिसमें अधिक जीवन और प्रेरणा थी और उसके साथ सोवियत-संघ की आकर्षक पाश्चभूमि थी। मगर इतना होते हुए भी उसे बहुत कम सफलता मिली। यह योरप या अमेरिका के साधारण मजदूरों को अपने साथ न ले सका। इंग्लैण्ड और संयुक्तराष्ट्र में इसकी ताकत इतनी कम थी कि देखकर ताज्जुब होता है। जर्मनी और फ्रांस में इसका कुछ जोर था। फिर भी हम देख चुके हैं कि कम-से-कम जर्मनी में यह अपनी ताकत से कितना कम फायदा उठा सका। अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से साम्यवादी दल की दो बड़ी हार हुई,—एक तो १९२७ में चीन में और दूसरी १९३३ में जर्मनी में। व्यापारिक मन्दी, बार-बार के अर्थ-संकट, थोड़ी मजदूरी और बेकारी के इस जमाने में साम्यवादी दल क्यों असफल हुआ, यह कह सकना कठिन है। कुछ लोग कहते हैं कि कार्यकुशलता की कमी थी और काम करने का तरीका गलत था। दूसरे लोग यह बताते हैं कि यह दल सोवियत सरकार से बहुत ज्यादा बंधा हुआ था और उसकी नीति होनी चाहिए थी अन्तर्राष्ट्रीय परन्तु रह गई अधिकतर राष्ट्रीय। सम्भव है बात यही हो। परन्तु इस स्पष्टीकरण से सन्तोष नहीं होता।

साम्यवादी दल का मजदूरों में तो जोर नहीं बढ़ा, परन्तु साम्यवादी विचार दूर-दूर तक और खास तौर पर पढ़े-लिखे लोगों में फैले। सब जगह, यहाँतक कि पूँजीवाद के समर्थकों में भी, इस तरह की आशा और आशंका होने लगी कि संकट से शायद किसी-न-किसी रूप में साम्यवाद की स्थापना होकर रहेगी। आम तौर पर यह मान लिया गया कि पुराने ढंग के पूँजीवाद के दिन लद गये। जिसके जो हाथ लगा वही ले भागने की नीति, कोई योजना नहीं, विनाश और संघर्ष का सदा बना रहना और बार-बार उथल-पुथल होना, यह हालत अब कायम नहीं रह सकती। इसके स्थान पर किसी-न-किसी रूप में एक योजना के अनुसार समाजवादी अर्थ-व्यवस्था या सहयोग-प्रणाली कायम करनी पड़ेगी। इसका यह अर्थ नहीं है कि इससे मजदूर-वर्ग की जीत हो ही, क्योंकि मालिक-वर्ग के फायदे के लिए भी शासन का संगठन अर्द्ध-समाजवादी ढंग पर किया जा सकता है। सरकारी समाजवाद और सरकारी पूँजीवाद एक-सी ही बात है। असली सवाल यह है कि राज्य में चलती किसकी है और लाभ किसको पहुँचता है, सारे समाज को या एक खास मालिक-वर्ग को ?

पढ़े-लिखे लोग बहस ही करते रहे और पश्चिम के उद्योग-प्रधान देशों में निम्न-श्रेणी के मध्यमवर्ग व छोटे अमीर काम कर गये। इन वर्गों को धुंधला-सा अनुभव

तरह के परिवर्तन बहुत दूर तक मार करनेवाले दीखते हैं और स्वामी-वर्ग की स्थिति डांवाडोल होने का या उसपर बहुत बड़ा बोझ आपड़ने का अन्देश हो। सितम्बर १९३१ में इंग्लैण्ड में यही हालत हो गई थी। उस वक्त संकट शुरू होगया था और उसके कारण आगे चलकर पाउण्ड को सोने का विनिमय छोड़ना पड़ा। इसकी प्रतिक्रिया यह हुई कि समाजवाद के खिलाफ पूंजीवाद की सारी ताकतें एक होगईं। मध्यम-वर्ग की जनता को यह भय दिखाकर कि अगर मजदूर दल की जीत हुई तो तुम्हारी सब वस्तु जप्त कर ली जायगी, राष्ट्रीय सरकार ने इन छोटे अमीरों को पूरी तरह भयभीत कर दिया और भारी बहुमत से चुनाव जीत लिया। मैकडानल्ड और उसके समर्थकों ने कहा कि राष्ट्रीय सरकार न रहेगी तो साम्यवाद आवेगा। असल बात यह है कि ब्रिटिश मजदूर दल की नरमी मशहूर है। वह प्रतिष्ठित संस्था है। उसे जितना डर साम्यवाद का लगता है उतना और किसी का नहीं लगता।

इस तरह इंग्लैण्ड में भी पुरानी लोकसत्ता की कमर टूट गई है और पार्लमेण्ट का पतन हो रहा है। लोकसत्ता का दिवाला उस समय निकलता है जब जीवन-मरण के सवाल यानी लोगों के हृदयगत भावों को उभाड़नेवाले सवाल सामने आते हैं। जैसे धार्मिक संघर्ष हैं या राष्ट्रीय और जातीय संघर्ष हैं (उदाहरणार्थ आर्य-जर्मन बनाम यहूदी) या इनसे भी अधिक आर्थिक संघर्ष हो (मिसाल के लिए गरीब-अमीर का संघर्ष)। तुरन्त याद होगा कि जब आयरलैण्ड में अल्स्टर और दूसरे भागों के बीच १९१४ में ऐसा ही धार्मिक और राष्ट्रीय सवाल खड़ा हुआ था तो ब्रिटिश अनुदार दल ने सचमुच पार्लमेण्ट के निर्णय को मानने से इन्कार कर दिया था और गृह-युद्ध तक को उत्तेजन दिया था। इस तरह जबतक जाहिरा तौर पर लोकसत्तात्मक कार्रवाई से अमीरवर्ग का काम बनता है, तबतक वह अपने स्वार्थों की रक्षा के लिए उसे काम में लेकर फायदा उठाता रहता है। जब इससे बाधा होने लगती है और उसके विशेषाधिकारों और स्वार्थों को धक्का पहुँचने का अन्देश होता है तो वह लोकसत्ता को ताक में रखकर निरंकुश उपाय करने लग जाता है। यह बिल्कुल सम्भव है कि भविष्य में ब्रिटिश पार्लमेण्ट में आमूल सामाजिक परिवर्तनों के पक्ष में बहुमत होजाय। ऐसा हो और वह बहुमत स्थायी स्वार्थों पर हमला करे तो इन स्वार्थों के मानिक पार्लमेण्ट की बात मानने से भी इन्कार कर सकते हैं और उसके निर्णय के खिलाफ दगावत का झण्डा खड़ा करवा सकते हैं। अल्स्टर के सवाल पर १९१४ में उन्होंने यही तो किया था।

तो हमने समझ लिया कि अमीर लोगों की दृष्टि ने पार्लमेण्ट और लोकसत्ता तभीतक वास्तविक समझी जाती है जबतक कि वह मौजूदा हालत को फायदा रखती है। अदम्य ही यह सच्ची लोकसत्ता नहीं होती। यह तो लोकसत्ता के विपरीत उद्देश्यों के

सकती है, सभा से भी करवा सकती है और क़ानून बना सकती है। इस प्रकार सत्ता धारासभा के हाथ से निकलकर शासन-विभाग के हाथ में चली गई है और चली जा रही है।

दूसरे, आजकल पार्लमेण्ट को इतना काम करना पड़ता है, और उसके सामने इतने पेचीदा सवाल रहते हैं, कि परिपाटी यह पड़ गई है कि पार्लमेण्ट तो सिर्फ किसी क़ानून या प्रस्ताव के साधारण सिद्धान्त-मात्र निश्चय करदे और बाकी की सारी तफ़्सील पूरी करने का काम सरकार या उसके किसी विभाग के लिए छोड़दे। इस तरह शासन-विभाग के हाथ में ज़बरदस्त अधिकार आगये हैं और विशेष परिस्थिति में वह जो चाहे सो कर सकता है। यों शासन के महत्वपूर्ण कार्यों के साथ पार्लमेण्ट का सम्पर्क दिन-दिन घटता जा रहा है। उसका मुख्य काम अब यह रह गया है कि सरकार के काम-काज की टीका करती रहे, पूछताछ और जाँच-पड़ताल करती रहे और सरकार की सामान्य नीति का समर्थन करती रहे। जैसा हेराल्ड जे० लास्की नामक प्रसिद्ध लेखक कहता है—“हमारी सरकार शासन-विभाग की निरंकुश सत्ता होगई है, उसे सिर्फ पार्लमेण्ट के विद्रोह का किंचित् डर है।”

सितम्बर (या शायद अक्टूबर) १९३१ में मजदूर सरकार का अचानक पतन होगया। यह जिस अजीब ढंग से हुआ उससे मालूम होता है कि इस मामले में पार्लमेण्ट का कितना कम हाथ था। आमतौर पर इंग्लैण्ड में सरकार का पतन कामन्स सभा में हार होने पर हुआ करता है। १९३१ में कोई बात सभा के सामने ही नहीं आई। किसीको, यहाँतक कि मंत्रि-मण्डल के अधिकांश सदस्यों तक को, मालूम नहीं हुआ कि क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री रैमजे मैकडानलड की दूसरे दलों के नेताओं से कुछ गुप्त बातचीत हुई। वह राजा से मिले, पुराना मंत्रिमण्डल बात-की-बात में सायब हो गया और नये की अल्लवारों में घोषणा हो गई ! पुराने मंत्रिमण्डल के कुछ सदस्यों को यह सारा हाल पहले पहल अल्लवारों से मालूम हुआ। यह सारी कार्रवाई असाधारण और लोकसत्तात्मक प्रणाली के विलकुल खिलाफ़ थी। आखिरकार कामन्स-सभा ने इसकी तारीफ़ करदी। इससे स्थिति में कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता। तरीक़ा तो निरंकुशता का ही रहा।

इस तरह रातों रात मजदूर सरकार के स्थान पर राष्ट्रीय सरकार आगई। रैमजे मैकडानलड साहब प्रधानमंत्री बने रहे और उदार और अनुदार दल उनके साथ शरीक होगये। ‘राष्ट्रीय सरकार’ का सीधा अर्थ है ऐसी सरकार जिसमें मालिकवर्ग यानी सम्पत्ति के स्वामी अपने आपस के झगडे भूलकर समाजवादी परिवर्तनों का मुकाबिला करने के लिए एक होजाते हैं। ऐसी सरकार उस वक़्त कायम होती है जब इस

कुछ लोग समझते हैं कि अगर थोड़े-से समझदार आदमियों के हाथ में अलग-अलग शासन दे दिये जावें तो यह सारा झगड़ा, संघर्ष और दुःख मिट जाय। वे यह भी समझते हैं कि इस सारे झगड़े की जड़ राजनीतिज्ञों की मूर्खता या दुष्टता है। उनका खयाल है कि भले आदमी इकट्ठे हों तो वे सदाचार के उपदेश देकर, और भूल सुझाकर दुर्जनों की कायापलट कर सकते हैं। यह कल्पना बड़ी भ्रमपूर्ण है; क्योंकि दोष व्यक्तियों का नहीं है, बुरी प्रथा का है। जबतक यह प्रथा बनी हुई है, इन व्यक्तियों का आचरण वैसा ही रहेगा जैसा अबतक रहा है। सत्ताधारी समूह दो तरह के होते हैं। एक तो विदेशी होकर दूसरे राष्ट्रों पर शासन करते हैं। दूसरे राष्ट्र के भीतर आर्थिक साधनोंवाले लोग होते हैं। ये लोग अजीब आत्म-वंचना और वम्भ से यह विश्वास कर लेते हैं कि उनके विशेषाधिकार उनकी योग्यता का उचित पुरस्कार है। जो कोई इस स्थिति को मानने से इन्कार करता है वह उन्हें दुष्ट, बदमाश और शान्ति भंग करनेवाला मालूम होता है। किसी प्रभुता-प्राप्त समूह को यह समझा सकना असम्भव है कि उसके विशेष अधिकार अन्यायपूर्ण हैं, और उन्हें उसे शान्तिपूर्वक छोड़ देना चाहिए। व्यक्ति फिर भी कभी और वह भी क्वचित् ही यह विश्वास कर सकते हैं, परन्तु समूह कभी नहीं कर सकते। इसलिए भिद्यन्त, संघर्ष और क्रान्ति और साथ-ही-साथ अनन्त कष्ट और दुःख भी अनिवार्य रूप से आते हैं।

: १६४ :

दुनिया पर एक आखिरी नज़र

३ अगस्त, १९३३

जबतक कलम, कागज़ और स्याही है तबतक चिट्ठियाँ लिखने का कोई अन्त नहीं। और संसार की घटनाओं पर लिखने का भी कोई अन्त नहीं; क्योंकि यह घटना-चक्र तो चलता ही रहता है और स्त्री, पुरुष और दत्तों का हँसना और रोना, आपस में प्रेम और घृणा करना और लड़ना-झगड़ना कभी बन्द नहीं होता। यह कहानी जारी रहती है, उसका खात्मा ही नहीं होता। आज जिस उमाने में हम रहते हैं, जीवन का प्रवाह और भी गतिशील, उसकी रफ़्तार और भी तेज़ है और एक के बाद दूसरे परिवर्तन जल्दी-जल्दी होते हैं। मेरे लिखते-लिखते परिवर्तन हो रहे हैं और जो कुछ मैं आज लिख रहा हूँ वह शायद कल ही पुराना पड़ जाय। जीवन की नदी कभी स्थिर नहीं रहती। वह तो बहती ही रहती है। आज की भाँति कभी-कभी वह दूर और से, निर्दयता से, राक्षसी शक्ति से हमारे छोटे-छोटे इरादों और मनोरथों

लिए लोकसत्ता की कल्पना का दुरुपयोग करना हुआ। अबतक सच्ची लोकसत्ता को तो अवसर ही नहीं मिला है, क्योंकि पूंजीवादी प्रणाली और लोकसत्ता में मौलिक विरोध है। लोकसत्ता का कोई अर्थ होसकता है तो समानता होसकता है, और समानता भी केवल मताधिकार की ही नहीं बल्कि आर्थिक और सामाजिक समानता भी। पूंजीवाद का अर्थ इससे बिलकुल उल्टा है। उसमें मुट्ठी भर लोगों के हाथ में आर्थिक सत्ता होती है और वे अपने ही क्रायदे के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। वे अपनी विशेषाधिकार-पूर्ण स्थिति को सुरक्षित रखने के लिए कानून बनाते हैं और जो कोई इन कानूनों को तोड़ता है वह शक्ति और व्यवस्था का भंग करने वाला ठहराया जाकर समाज के दण्ड का पात्र बनता है। इस तरह इस प्रणाली में समानता का नामोनिशान तक नहीं होता और जितनी-सी आजादी दी जाती है वह पूंजीवादी कानूनों की सत्ता के भीतर ही दीजाती है। इन कानूनों का उद्देश्य पूंजीवाद की रक्षा करना होता है।

पूँजीवाद और लोकसत्ता के बीच का संघर्ष आन्तरिक और स्थायी है। अक्सर भ्रमपूर्ण प्रचार और पार्लमेण्ट वगैरा लोकसत्ता के बाहरी स्वरूप के कारण यह संघर्ष छिपा रहता है। मालिक-वर्ग के लोग दूसरे वर्गों को थोड़ा बहुत सन्तुष्ट रखने के लिए टुकड़े भी फेंकते रहते हैं। ऐसा समय भी आजाता है कि फेंकने के लिए टुकड़े नहीं बचते। उस वक़्त दोनों दलों में संघर्ष खूब जोर का होता है। क्योंकि उस समय युद्ध असली चीज़ के लिए, यानी शासन में आर्थिक सत्ता हासिल करने के लिए, होता है। जब यह नीवत आती है तो पूँजीवाद के सारे हिमायती, जो अबतक अलग-अलग दलों के साथ खिलवाड़ करते रहे हैं, अपने स्थायी स्वार्थों के खतरे का मुक़ाबिला करने के लिए एक होजाते हैं। उदार और इसी तरह के दूसरे दल रायब होजाते हैं और लोकसत्ता के क्रायदे ताक में रख दिये जाते हैं। योरप और अमेरिका में यह नीवत आ पहुँची है, फ़्रैंसिज्म का अधिकांश देशों में किसी-न-किसी रूप में बोलवाला हो चला है और यह उस नीवत की निशानी है। मजदूर-दल सब जगह अपना बचाव कर रहा है। उसमें पूँजीवादी शक्तियों के इस नये और जबरदस्त संगठन का मुक़ाबिला करने की ताकत नहीं है। फिर भी अजीब बात यह है कि पूँजीवाद की इमारत खुद लड़खड़ा रही है और वह अपनेआपको नई दुनिया के अनुकूल नहीं बना सकती। यह निश्चित दिखाई देता है कि पूँजीवाद किसी तरह जीवित रह भी गया तो उसका स्वरूप बहुत ही बदला हुआ और कठोर होगा। यह भी लम्बे संघर्ष में एक दूसरी मंज़िल होगी; क्योंकि पूँजीवाद के किसी भी रूप में आधुनिक उद्योग ही क्या, आधुनिक जीवन तक ऐसा युद्धक्षेत्र रहेगा जिसमें सेनाओं की आपस में सदा भिड़न्त होती रहेगी।

जर्मनी या शत्रु-सेना के अधिकार में हारे हुए युद्ध-क्षेत्र में भी नहीं हुआ है। आज ब्रिटिश राज्य में सचमुच हमारी ऐसी हालत होगई है कि हमें जाने-आने के लिए भी छुट्टी का परवाना लेना पड़ता है और हमारे सीमाप्रान्त के उत्तपार हमारे पड़ोसियों पर ब्रिटिश वायुयान बम-वर्षा कर रहे हैं।

दूसरे देशों में हमारे देशवासियों की कोई इज्जत नहीं की जाती। उनका शायद ही कहीं स्वागत हो। इसमें कोई आश्चर्य की बात भी नहीं है; क्योंकि जिनका आदर घर पर ही न हो उनका बाहर कैसे हो सकता है? दक्षिण-अफ़्रीका में वे जन्मे और पले और वहाँके कुछ हिस्सों को, खास तौर पर नेटाल को, उन्होंने अपनी मेहनत से बनाया था; पर वहाँसे भी उन्हें निकाला जा रहा है। रंग-भेद, जातीय द्वेष और आर्थिक संघर्ष, सबने मिलकर दक्षिण अफ़्रीका के इन हिन्दुस्तानियों को ऐसा अछूत-सा बना दिया है, जिनका न कोई घर है और न जिनमें कहीं गरण मिल सकती है। दक्षिण-अफ़्रीका की यूनियन सरकार उन्हें कहती है कि दक्षिण-अफ़्रीका को सदा के लिए छोड़ दो। तुम्हें जहाज़ में बिठाकर कहीं दूसरी जगह भेज दिया जायगा। फिर भले ही तुम ब्रिटिश गायना में जाओ, हिन्दुस्तान में वापस जाओ, या और कहीं जाओ, और भले ही भूलों मरो।

पूर्वी अफ़्रीका में केनिया और चीतरफ़ के इलाक़ों को बनाने में हिन्दुस्तानियों का बड़ा हिस्सा रहा है। लेकिन वहाँ भी उनका रहना पसन्द नहीं किया जाता। इस-लिए नहीं कि अफ़्रीका के दाशिनदों को आपत्ति है, बल्कि इसलिए कि मुट्ठीभर यूरो-पियन दग़ीबेवाले नहीं चाहते। वहाँके अच्छे-से-अच्छे यानी पहाड़ी प्रदेश इन दग़ीबे-वालों के लिए सुरक्षित है। वहाँ अफ़्रीकन और हिन्दुस्तानी ज़मीन नहीं ख़रीद सकते। बेचारे अफ़्रीकनों की तो बहुत ही दुरी हालत है। शुरु में सारी ज़मीन उनके ब्रह्मे में थी और यही उनकी आमदनी का जरिया था। इस ज़मीन के बड़े-बड़े टुकड़े सरकार ने ज़ब्त कर लिये और योरोप से आकर बस्नेवालों को मुफ्त देदिये। आजकल ये दग़ीबे-वाले बड़े-बड़े ज़मींदार होगये हैं। उन्हें आय-कर नहीं देना पड़ता और दूसरे कर भी ये शायद ही देते हैं। कर का लगभग सारा भार ग़रीब पददलित अफ़्रीकनों पर पड़ता है। उनपर कर लगाना आसान काम नहीं है, क्योंकि उनके पास कुछ होता ही नहीं। इसलिए आटा और कपड़े जैसी ज़िन्दगी की कुछ जरूरी चीज़ों पर कर लगाया गया और जब वे उन्हें ख़रीदते तो अप्रत्यक्ष रूपसे उन्हें यह कर भी चुदाना पड़ता। लेकिन सबसे ग़ैरमानूनी दंडन, और वह भी सीधा दंडन, यह था कि प्रत्येक घर और १६ वर्गमें ऊपर के हर एक स्त्री-पुरुष पर कर लगा दिया गया। कर लगाने का उद्देश्य यह है कि लोग जो बग़ावत या जो कुछ उनके पान हो उनपर कर लगाया जाय। अफ़्रीकनों के पान

की उपेक्षा करती हुई, हमारी तुच्छताओं का निर्दय उपहास करती हुई, और हमें अपनी उत्ताल तरंगों पर तिनकों की तरह इधर-उधर फेंकती हुई आगे बढ़ती है। यह जीवन की नदी आगे कहां जायगी, इसका किसीको पता नहीं। किसी बड़ी और पनी चट्टान से टकराकर सहज धाराओं में बंट जायगी या उस विशाल, गम्भीर, गौरवशाली, शान्त, सदापरिवर्तनशील और फिर भी कभी न बदलनेवाले समुद्र में जा समावेगी ?

जितना लिखने का मैंने कभी इरादा किया था, या जितना मुझे लिखना चाहिए था, उससे कहीं ज्यादा मैं अबतक लिख चुका हूँ। मेरी लेखनी चलती ही रही है। अब हम अपना लम्बा चपकर काट चुके हैं और आखिरी मंजिल तय कर चुके हैं। आज के बीच में पहुँच चुके हैं और कल के किनारे पर खड़े हुए अचरज कर रहे हैं कि जब इस कल की भी आज बनने की घाटी आयगी तब इसकी क्या शफल होगी ? जरा देर ठहरकर संसार पर एक दृष्टिपात करें। १९३३ के साल के अगस्त मास के सातवें दिन इसका क्या हाल है ?

हिन्दुस्तान में बापू फिर गिरफ्तार हो गये हैं और सजा पाकर यरवडा-जेल में वापस पहुँच गये हैं। सीमित रूप में ही सही, सविनयअवज्ञा फिर शुरू होगई है और हमारे साथी फिर जेल जा रहे हैं। एक वीर और प्रिय साथी और मित्र हमें अभी-अभी छोड़कर चल बसा। वह ब्रिटिश सरकार की क़ैद में मरा है। उससे मैं पहले-पहल २५ वर्ष पहले, जब मैं केम्ब्रिज में गया-ही-गया था, मिला था। वह थे यतीन्द्रमोहन सेनगुप्त। जीवन मृत्यु में समा जाता है, परन्तु भारतवासियों के लिए जीवन को जीने योग्य बनाने का महान कार्य जारी है। हिन्दुस्तान के हज़ारों अत्यन्त जोशीले और प्रतिभाशाली पुत्र और पुत्रियाँ जेल या नज़रबन्दी में पड़ हैं। वे लोग अपना यौवन और बल हिन्दुस्तान को गुलाम बनानेवाली वर्तमान प्रणाली से जूझने में खर्च कर रहे हैं। यह जीवन और शक्ति निर्माण में, रचनात्मक कार्य में लगी होती ! इस दुनिया में कितना काम बाक़ी पड़ा है। परन्तु रचना से पहले नाश करना ही पड़ता है, ताकि नई इमारत के लिए ज़मीन साफ़ होजाय। हम किसी घूरे की कच्ची दीवारों पर बढ़िया इमारत खड़ी नहीं कर सकते। हिन्दुस्तान की आज की स्थिति का अन्दाज़ा इस बात से बहुत अच्छी तरह लगाया जा सकता है कि बंगाल के कुछ भागों में कपड़े भी सरकारी आज्ञा के अनुसार पहनने पड़ते हैं। दूसरी तरह की पोशाक पहनने का अर्थ होता है जेलखाने जाना। चटगाँव में बारह-बारह बरस और उससे ऊपर के छोटे-छोटे लड़कों को (और शायद लड़कियों को भी) जहाँ कहीं जाना होता है वहाँ अपनी शिनाख्त के कार्ड ले जाना पड़ता है। मुझे मालूम नहीं कि ऐसी असुधारण आज्ञा और भी कहीं जारी की गई है या नहीं। ऐसा तो शायद नाज़ियों के

ख़ास टुकड़े में बहुत सोना मिले, या न मिले यह उसके भाग्य पर निर्भर है। यह तरीका पूंजीवाद का नमूना है। बैसे होना तो यह चाहिए कि देश की सरकार सोने के क्षेत्र को अपने हाथ में लेले और सारे राज्य के फ़ायदे के लिए उसपर काम करावे। ताजिकिस्तान और दूसरी जगहों के अपने यहाँके सोने के क्षेत्रों के बारे में सोवियट सरकार ऐसा ही कर रही है।

इस अन्तिम विहंगावलोकन में मैंने तुम्हें केनिया का कुछ हाल बताया है, क्योंकि इन ख़तों में हमने अफ़्रीका की उपेक्षा की है। याद रहे कि यह एक विशाल महादेश है और इसमें अफ़्रीकन जातियाँ भरी पड़ी हैं। इन जातियों का विदेशी लोग सैकड़ों वर्षों से आज तक निर्दय शोषण कर रहे हैं। ये बुरी तरह पिछड़ी हुई जातियाँ हैं। लेकिन उन्हें दबाकर रक्खा गया है और आगे बढ़ने का मौक़ा नहीं दिया गया है। जहाँ उन्हें अवसर दिया गया है, जैसा कि पश्चिमी किनारे पर स्थापित एक विश्वविद्यालय में अभी-अभी हुआ है, वहाँ उन्होंने अच्छी तरक्की की है।

पश्चिमी एशिया के देशों का हाल तो मैं तुम्हें फ़ाफ़ी बता चुका हूँ। वहाँपर और मिस्र में आजादी की लड़ाई मुसलमान सूरतों में और भिन्न-भिन्न स्थितियों में चल रही है। यही हाल दक्षिण-पूर्वी एशिया का, भारत के उसपार के देशों का और इण्डोनेशिया यानी स्याम, इण्डोचीन, जावा, सुमात्रा, उच्चइण्डोच और फिलिपाईन द्वीपों का है। इनमें से स्याम तो स्वतंत्र है। उसके सिवा इन सब देशों में आन्दोलन के दो पहलू हैं। एक तो विदेशी शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय भावना और दूसरा सामाजिक समानता या कम-से-कम आर्थिक सुधार के लिए दलित-वर्ग की तड़प।

एशिया के सुदूरपूर्व में विशाल चीन हमला करनेवालों के सामने निस्सहाय हो रहा है और भीतरी फूट के कारण उसके टुकड़े-टुकड़े हो रहे हैं। उसका एक अंग तो कुछ करना चाहता है और दूसरे ने इस ओर से मुँह फेर रक्खा है। इस बीच में जापान आगे बढ़ता जा रहा है। उसे कोई रोकनेवाला नहीं दीखता और वह चीन के बड़े-बड़े इलाक़ों पर अपना पंजा जमाता जा रहा है। लेकिन चीन के लम्बे इतिहास में उसपर कितनी ही बार ज़द्वंस्त हमले हुए हैं और बड़ी आपत्तें आई हैं; फिर भी उनकी हस्ती कायम रही है। अब इस ही जापानी हमले के बाद भी चीन जिन्दा रहेगा।

साम्राज्यवादी जापान विश्वव्यापी साम्राज्य के बड़े-बड़े सपने देख रहा है। वहाँ एक तरफ़ सामन्तशाही और सैनिकवाद का जोर है और दूसरी ओर उनके उद्योग-धंधे बहुत बढ़े-चढ़े हैं। वह नये और पुराने की अजीब खिचड़ी है। परन्तु इन सपनों में एक अतली ख़तरा छिपा हुआ है, और वह यह है कि उनकी बढ़ती हुई आवादी भयंकर बरत में है और उसकी आर्थिक स्थिति गिरती जा रही है। इन आवादी को

और तो प्रायः कुछ नहीं था, इसलिए उनके शरीर पर ही टैक्स लगा दिया गया। मगर उनके पास रुपया न हो तो यह क़ी आदमी १२ मिलियन सालाना का कर वे कहाँ से देते ? वस, इसी में इस कर की मक्कारी भरी थी, क्योंकि यूरोपियनों के बगीचों में काम करके उन्हें कुछ-न-कुछ रुपया कमाना पड़ता और उससे वे कर चुकाते। यह न सिर्फ रुपया वसूल करने की बल्कि बगीचों के लिए सस्ते मजदूर हासिल करने की भी तरकीब थी। इस तरह इन अभाग्य अफ़्रीकियों को कभी-कभी बड़ी दूर से सफ़र करके देश के भीतरी हिस्से में से समुद्र-तट के पास सात-आठसी मील चलकर बगीचों में आना पड़ता है (भीतरी भाग में रेलें नहीं हैं और जो थोड़ी-सी हैं वे समुद्र के किनारे के पास हैं)। इस तरह कमाई करके इन लोगों को शरीर-कर चुकाना पड़ता है।

इन ग़रीब शोषित अफ़्रीकियों के बारे में मैं तुम्हें और भी बहुत-सी बातें कह सकता हूँ। इन्हें इतना तक मालूम नहीं कि अपनी पुकार बाहरी दुनिया को किस तरह सुनाई जाती है। इनकी दुख-गाया लम्बी है और ये चुपचाप कष्ट सह रहे हैं। इनकी अच्छी-अच्छी ज़मीनें इनके हाथ से छीन कर और यूरोपियनों को मुफ़्त दे दी गई हैं। अब उन्हीं ज़मीनों पर उन्हीं यूरोपियनों के कर-दाता बनकर इन विचारे अफ़्रीकियों को काम करना पड़ता है। ये यूरोपियन ज़मींदार मध्यकालीन जागीरदार बने हुए हैं और कोई भी प्रवृत्ति जो उन्हें नापसन्द होती थी, दबा दी गई है। अफ़्रीकन लोग सुधार-कार्य के लिये भी कोई मण्डल नहीं बना सकते। क्योंकि रुपया जमा करने की मनाई है। नाचने की मनाई का भी एक विशेष क़ानून या आर्डिनेन्स है क्योंकि अफ़्रीकन कभी-कभी अपने नाच-गान में यूरोपियन रहन-सहन की नक़ल किया करते हैं और उसकी हँसी उड़ाया करते हैं। किसान बहुत दरिद्र हैं और उन्हें चाय या कहवे की खेती नहीं करने दी जाती क्योंकि इससे यूरोपियन बगीचों वालों के साथ स्पर्धा होती है। तीन वर्ष हुए ब्रिटिश सरकार ने शपथपूर्वक घोषणा की थी कि वह अफ़्रीकन लोगों की रक्षक है और भविष्य में उनकी ज़मीन नहीं छीनी जावेगी। अफ़्रीकनों के दुर्भाग्य से केनिया में सोना निकल आया। वस, पवित्र वचन भुला दिया गया। यूरोपियन बगीचे वाले इस ज़मीन पर टूट पड़े। उन्होंने अफ़्रीकन किसानों को खदेड़ दिया और सोने की ख़ुदाई शुरू कर दी। अंग्रेज़ों के वादे ऐसे होते हैं। हमसे कहा जाता है कि अन्त में तो इस सारी कार्रवाई से अफ़्रीकनों का फ़ायदा ही होने वाला है और वह अपनी ज़मीन खोकर बिलकुल सुखी हैं।

स्वर्ण-प्रदेश से लाभ उठाने का यह पूँजीवादी तरीक़ा बड़ा अजीब है। एक निश्चित स्थान से लोगों को सचमुच वहाँ तक दीड़ाया जाता है और हरेक उस प्रदेश के कुछ हिस्से पर अधिकार कर लेता है। फिर वहाँ काम शुरू कर देता है। उस

मूलतः जातियाँ एक-दूसरे में खूब मिल गई हैं। दक्षिणी योरप, स्पेन, पुर्तगाल और इटली के लोग और अमेरिका के आदम-निवासी 'रेड इंडियन' और हब्सी सब दूध-पानी की तरह मिल गये हैं। ये रेड इंडियन लोग कनाडा और संयुक्तराष्ट्र में तो अपनी हस्ती बहुत कुछ खो चुके हैं, लेकिन दक्षिणी अमेरिका में और खासतौर पर वेनेजुएला में अब भी इनकी बहुत बड़ी तादाद है। वे ज्यादातर बड़े शहरों से दूर रहते हैं। तुम्हें यह जानकर शायद आश्चर्य हो कि व्यूनोआयर्स और रायोदिजनेरो जैसे कुछ शहर न केवल बहुत बड़े ही हैं बल्कि बहुत सुन्दर भी हैं और उनमें बड़ी शानदार और चौड़ी-चौड़ी छायादार सड़कें भी हैं। अर्जेण्टाइन की राजधानी व्यूनोआयर्स की आबादी २५ लाख और ब्रेजील की राजधानी रायोदिजनेरो की आबादी करीब २० लाख है।

यद्यपि वहाँ नरलें मिल रही हैं, फिर भी शासकवर्ग तो गोरे अमीरों में से ही है। जिस समूह के हाथ में फ़ौज और पुलिस आजाती है आमतौर पर वही राज्य करता है। और, जैसा मैं तुम्हें बता चुका हूँ, वहाँ ऊपर-ही-ऊपर कई बार क्रान्तियाँ भी हुई हैं। दक्षिण अमेरिका के सारे देशों में खनिज पदार्थों की बहुतायत है और इसलिए वे कभी भी बहुत धनी हो सकते हैं। परन्तु अभी तो वे क्रूर में डूबे हुए हैं और चार वर्ष पहले, ज्यों ही संयुक्तराष्ट्र ने उन्हें अपना उपार देना बन्द कर दिया, उनके यहाँ बुरी तरह गड़बड़ मच गई और सब जगह क्रान्तियाँ हो गईं। आर्थिक कठिनाइयों के कारण वहाँ के तीनों मुख्य देश अर्जेण्टाइन, ब्रेजील और चिली भी क्रान्ति के शिकार हुए।

१९३२ की गरमियों के बाद से दक्षिणी अमेरिका में भी दो छोटे-छोटे युद्ध हो चुके हैं। लेकिन मंचूरिया के जापानी युद्ध की तरह इन्हें भी मरकरी तौर पर युद्ध नहीं कहा गया। राष्ट्र-संघ के इकरारनामे, केलॉग की शान्ति की मंथि और दूसरे समझौतों के बाद अब 'लड़ाइयाँ' बहुत कम होती हैं। जब एक राष्ट्र दूसरे पर हमला करता है और उसके नागरिकों को मार डालता है तो वह 'संघर्ष' कहलाता है। और चूँकि समझौते में संघर्षों की मनाई नहीं हुई है इसलिए किसी को कोई चिन्ता नहीं। मंचूरिया के युद्ध की तरह इन छोटी-छोटी लड़ाइयों का कोई मनाकरवापी महत्व नहीं होता। लेकिन इनसे यह प्रमाण मिल जाता है कि राष्ट्र-संघ ने लगाकर अनेक समझौतों और सन्धिपत्रों तक सत्तार में शान्ति स्थापन करने के जो उपाय किये गये हैं और जिनकी इतनी बड़ाई की जाती है, वे कितने दुर्बल और निरक्षम हैं। राष्ट्र-संघ का एक सदस्य दूसरे सदस्य पर हमला करता है और संघ या तो निष्मत्त होकर बैठ रहता है या मगड़े को निपटाने की कमजोर और दिलकुल क्रिद्ध कोशिशें करता है।

न अमेरिका में घुसने दिया जाता है और न आस्ट्रेलिया के विशाल निर्जन प्रदेशों में घुसने दिया जाता है। इन सपनों के पूरा होने में बड़ी जबरदस्त रुकावट यह है कि आजकल का सबसे ताकतवर राष्ट्र अमेरिका उसके खिलाफ है। जापान के एशिया में बढ़ने में दूसरी जबरदस्त विकसित सोवियट रूस की है। मंचूरिया में और प्रशान्त महासागर के गहरे पानी पर महायुद्ध की छाया कितने ही दूरन्देश लोगों को अभीसे दिखाई देरही है।

सारा उत्तरी एशिया सोवियट संघ का हिस्सा है और वह एक नई दुनिया की रचना करने और नई समाज-व्यवस्था कायम करने के काम में लगा हुआ है। यह विलक्षण बात है कि ये पिछड़े हुए देश, जिन्हें सम्भता अपनी कूच में पीछे छोड़ गई थी और जहाँ अबतक एक तरह की साम्राज्यशाही मौजूद थी, एकदम छलांग मारकर ऐसी मंजिल पर पहुँच गये जो पश्चिम के उन्नत राष्ट्रों से भी आगे है। आज सोवियट संघ योरोप और एशिया में खड़ा होकर पश्चिमी संसार के लड़खड़ाते हुए पूँजीवाद को चुनौती दे रहा है। जहाँ एक ओर व्यापारिक मन्दी, बेकारी और बार-बार का संकट पूँजीवाद का गला घोट रहा है और पुरानी व्यवस्था अन्तिम साँस ले रही है, वहाँ सोवियट-संघ के इलाके में आशा, शक्ति और उत्साह का संचार हो रहा है और वह बड़े वेग से समाजवादी व्यवस्था के निर्माण और स्थापना में लगा हुआ है। इस विपुल यौवन और जीवन की, तथा सोवियट को जो सफलता मिली है उसकी छाप सारे संसार पर पड़ रही है और विचारशील लोगों का ध्यान उसकी तरफ खिंच रहा है।

एक दूसरा महान् प्रदेश यानी अमेरिका का संयुक्तराष्ट्र पूँजीवाद की नाकाम-याबी का नमूना है। बड़ी-बड़ी कठिनाइयों, संकटों, मजदूरों की हड़तालों और बे-मिसाल बेकारी से घिरकर भी अमेरिका किसी तरह काम चलाने और पूँजीवादी प्रणाली की रक्षा करने की कोशिश कर रहा है। इस बड़े प्रयोग का नतीजा अभी देखना बाकी है। लेकिन कुछ भी हो, अमेरिका को जो बड़ी-बड़ी सहाूलियतें मिली हुई हैं उन्हें उससे फौन छीन सकता है? उसका इलाका लम्बा-चोड़ा है। मनुष्य को जिस चीज की भी जरूरत होसकती है वह वहाँ बहुतायत से मिलती है। उसके कला-कौशल और सब देशों से बढ़े-चढ़े हैं और वहाँ के लोग बड़े कारीगर और तालीम पाये हुए हैं। संयुक्तराष्ट्र और सोवियट-संघ दोनों ही संसार के आनेवाले मामलों में बहुत महत्वपूर्ण भाग लिये बिना नहीं रह सकते।

और दक्षिण अमेरिका का महान् देश, जिसमें लैटिन जातियाँ रहती हैं, उत्तरी अमेरिका से कितना भिन्न है? उत्तर की तरह वहाँ जातीय द्वेष का भाव नहीं है और

जाता रहा, और जो कुछ बच रहा है उसकी हिफाजत के लिए वह खूब कोशिश कर रहा है। उसकी समुद्री ताकत जैसी पहले थी, अब नहीं रही। इसीके कारण उसकी रक्षा थी और दूसरे राष्ट्रों पर उसकी प्रधानता रहती थी। इसीके सहारे वह अपना साम्राज्य बना पाया था। बहुत वक्त नहीं गुजरा, एक दिन ऐसा था कि उसकी जल-सेना किन्हीं दो बड़े राष्ट्रों की जल-सेना से बड़ी और ज्यादा ताकतवर थी। आज तो वह संयुक्तराष्ट्र की जल-सेना के साथ सिर्फ बराबरी का दावा कर सकती है और जरूरत पड़े तो संयुक्तराष्ट्र के पास इंग्लैंड से बड़ी जल-सेना जल्दी से बना लेने के साधन हैं। आज समुद्री ताकत से भी हवाई ताकत का महत्व ज्यादा है। इस बारे में इंग्लैंड और भी कमजोर है। कई राष्ट्रों के पास उससे ज्यादा जंगी हवाई जहाज हैं। उसकी व्यापारिक प्रभुता भी चली गई और उसके लौटकर आने की कोई उम्मीद नहीं है। उसका विशाल निर्यात-व्यापार दिन-दिन गिरता जा रहा है। अब तो वह ऊँची चुंगी और संरक्षण-कर लगाकर अपने माल के लिए साम्राज्य के बाजार की रक्षा करने की कोशिश कर रहा है। इसका अर्थ यह है कि उसने साम्राज्य के बाहर संसार-व्यापी व्यापार के हीसले छोड़ दिये हैं। इस सीमित क्षेत्र में उसे कामयाबी मिल भी गई तो इससे उसकी पुरानी प्रभुता थोड़े ही वापस आजाती है। वह तो सदा के लिए जाती रही। साम्राज्य के भीतर भी उसे कितनी सफलता मिलेगी और वह कितने दिन टिकेगी, इसमें सन्देह ही है।

अमेरिका के साथ भयंकर द्वन्द्व-युद्ध होजाने के बाद भी इंग्लैंड संसार के व्यापार का सराफा-केन्द्र और लन्दन नगर हुण्डी की मण्टी बना हुआ है। लेकिन जैसे-जैसे संसार का व्यापार घटता और मिटता जा रहा है वैसे-वैसे इन आर्थिक प्रधानता का खिचाव और मूल्य भी कम होता जा रहा है। इंग्लैंड और दूसरे देश खुद अपने आर्थिक राष्ट्रवाद और चुंगी बगैरा की नीति से संसार के व्यापार के इस तरह घटने में मदद कर रहे हैं। संसार का बहुत-सा व्यापार बना रहा और मौजूदा पूंजीवादी प्रणाली कायम रही तो भी इसमें सन्देह नहीं कि संसार का आर्थिक नेतृत्व अन्त में लन्दन के हाथ से निकलकर न्यूयार्क के हाथ में चला जायगा। मगर शायद उससे पहले पूंजीवादी प्रणाली में विशाल परिवर्तन हो चुके होंगे।

इंग्लैंड की यह तारीफ है कि वह अपने-आपको बदलने हुए ज्ञान के अनुकूल बना लेता है। लेकिन यह गुण उन्नी वक्त तक है जबतक कि उसकी सामाजिक दृष्टिवाद नहीं हिलती और उसके सम्प्रदाय की विशेष स्थिति बनी हुई है। अनुकूल बन जाने की यह ताकत मौलिक सामाजिक परिवर्तनों के बीच भी कायम रहेगी या नहीं, यह अभी ही देखा जायगा। इसकी बहुत कम सम्भावना मान्य होनी

दक्षिण अमेरिका की इन लड़ाइयों या 'संघर्षों' में से एक संघर्ष बोलीविया और पेरानुए के बीच में है। झगड़ा चाको नामक एक छोटे-से जंगली इलाके के कारण है। एक विनोदप्रिय फ्रांसीसी ने कहा है—“चाको जंगल के बारे में बोलीविया और पेरानुए के बीच जो झगड़ा चल रहा है उससे मुझे उन दोनों गंजों की याद आती है जो कंधे के लिए झगड़ रहे थे।” झगड़ा तो है, लेकिन वह इतना ही चेहड़ा तो नहीं है। इस विशाल जंगली इलाके में तेल-सम्बन्धी स्वार्थ ग्रंथे हुए हैं और पेरानुए नदी जो इसमें बहती है वह बोलीविया को अटलाण्टिक महासागर से मिलाती है। दोनों देशों ने राजीनाम नहीं किया और अभी तक हजारों जानें क्रूरवान कर चुके हैं।

दूसरी भिड़न्त कोलम्बिया और पेरू के बीच हो रही है। यहां झगड़े की जड़ लटोशिया नामक छोटा-सा गांव है। इसपर पेरू ने बड़े अनुचित ढंग से कब्जा कर लिया था। मेरा खयाल है कि राष्ट्र-संघ ने भी पेरू की फडी टीका की थी। शायद यह झगड़ा अब तय होगया है।

लैटिन अमेरिका (और इसमें मैक्सिको शामिल है) घमं से कैथलिक है। मैक्सिको में राज्य और कैथलिक पादरियों के बीच में बड़ी जोर की टक्करें हुई हैं। स्पेन की तरह मैक्सिको की सरकार भी शिक्षा और लगभग सभी बातों में रोमन पादरियों की बड़ी शक्ति को दबा देना चाहती थी।

दक्षिण अमेरिका की भाषा स्पेनिश है। सिर्फ ब्रेजील में पुर्तगाली सरकारी भाषा है। चूंकि इस विशाल प्रदेश में स्पेनिश भाषा का ही बोलवाला है, इसलिए यह संसार की बड़ी-से-बड़ी भाषाओं में से एक है। शायद तादाद के लिहाज से अंग्रेजी के बाद इसीका दर्जा है। यह एक सुन्दर आनुनासिक भाषा है। इसमें बढ़िया आधुनिक साहित्य है और अब तो दक्षिण अमेरिका के कारण यह एक बहुत महत्वपूर्ण व्यापारिक भाषा भी बन गई है।

: १६५ :

युद्ध की छाया

८ अगस्त, १९३३

पिछले तख्त में हमने एशिया, अफ्रीका और दोनों अमेरिका के महादेशों पर सरसरी नज़र डाली थी। योरप बाक़ी रह गया था। योरप में झगड़े-टण्डे बहुत हैं; पर उसमें अनेक गुण भी हैं।

इंग्लैंड अबतक संसार का मुखिया राष्ट्र था। मगर अब उसका पुराना प्रभुत्व

goodwill. We should never sell goods to India by cotton streamers on the end of a bayonet."

अर्थात् "वे दिन लड़ गये जब हम हिन्दुस्तान को आज्ञा देकर कह सकते थे कि उसे कब और कहाँ से माल खरीदना है। व्यापार की रक्षा सम्भव से ही हो सकती है। संगीनों के सहारे जहाज़ भर-भरकर हिन्दुस्तान को कपड़ा बेचने की आज्ञा नहीं रखनी चाहिए।"

हिन्दुस्तान की अन्दरूनी हालत की बात छोड़ें तो भी इंग्लैण्ड को यहाँ, पूर्व के सभी देशों में और कुछ उपनिवेशों में जापान की भयंकर लागू-डॉट का सामना तो करना ही पड़ेगा।

इसलिए इंग्लैण्ड जो उसके पास बच रहा है उसे बनाये रखने की खूब कोशिश कर रहा है। इसके लिए वह अपने साम्राज्य को एक आर्थिक इकाई बना रहा है और उसमें डेनमार्क या स्कैण्डिनेविया सरीखे और भी छोटे-छोटे देश जो उससे सम-प्रौढ़ता कर लेते हैं उन्हें भी अपनेमें मिला रहा है। यह नीति उसे घटना-चक्र से मजबूर होकर इस्तिथार करनी पड़ रही है। उसके लिए और कोई मार्ग ही नहीं है। युद्ध में अपनी हिकाज़त करने के लिए भी उसे अधिक स्वावलम्बी बनना पड़ेगा। इसलिए वह अब अपनी खेती की भी तरफ़ की कर रहा है। आर्थिक राष्ट्रवाद की यह साम्राज्यव्यापी नीति कहां तक कामयाब होगी, यह अभी कोई नहीं बता सकता। मैंने कई कठिनाइयाँ बताई हैं, जो इसकी सफलता में बाधक होंगी। अगर असफलता हुई तो साम्राज्य का सारा ढाँचा ही बँट जायगा और अंग्रेज़ लोगों को बहुत गरीबी से रहना पड़ेगा। इस नीति की कामयाबी भी ख़तरों से ख़ाली नहीं है, क्योंकि इसके कारण बहुत-से यूरोपियन देशों की बर्बादी हो सकती है। वह इस तरह से कि इन देशों के व्यापार को तो काफ़ी बाज़ार नहीं मिलेगा और इंग्लैण्ड के कर्जदार देशों का दिवाला निकालने से खुद इंग्लैण्ड की हालत को ठेस पहुँचे बिना नहीं रह सकती।

जापान और अमेरिका के ख़िलाफ़ भी आर्थिक संघर्ष पैदा होकर रहेंगे। संयुक्तराष्ट्र के साथ कई बातों में स्पर्धा मौजूद है और, ज़मीन दुनिया की आज हालत है और संयुक्तराष्ट्र के पास जितने विशाल साधन हैं उनको देखने हुए, ज्यों-ज्यों इंग्लैण्ड की अवतति होगी त्यों-त्यों अमेरिका की उन्नति होगी। इस प्रिया का परिणाम यह हो सकता है कि या तो इस झगड़े में इंग्लैण्ड चुपचाप हार मानले या जो कुछ उसके पास रह गया है उसके भी हाथ से निकल जाने में पहले और अपने दरदारीवालों का मुँहादिला करने की ताक़त खो देने के पहले अपनी रक्षा के लिए युद्ध की जोखिम उठावे।

इंग्लैण्ड का दूसरा दृष्टा प्रतिक्रिया मोडिफ़ाई-मैण्ड है। इन दोनों की नीति में

है कि इस तरह के परिवर्तन चुपचाप और शान्तिपूर्वक होजायेंगे । क्योंकि जिनके पास सत्ता और विशेष अधिकार होते हैं वे उन्हें राजी-खुशी से नहीं छोड़ा करते ।

अभी तो इंग्लैंड बड़ी दुनिया से सिकुड़कर अपने साम्राज्य में सीमित हो रहा है । इस साम्राज्य को बचाकर रखने के लिए उसने इसकी रचना में बड़ी-बड़ी तब्दीलियाँ मञ्जूर करली हैं । उपनिवेश कितनी ही तरह से ब्रिटेन की अर्थ-प्रणाली से बंधे हुए हैं, फिर भी उन्हें एक हद तक आजादी मिल गई है । इंग्लैंड ने अपने बढ़ते हुए उपनिवेशों को सन्तुष्ट रखने के लिए बहुत-सा त्याग किया है, फिर भी उनमें संघर्ष हो ही जाता है । आस्ट्रेलिया बँक आफ इंग्लैंड से बुरी तरह बँधा हुआ है और जापानी हमले के डर के कारण इंग्लैंड के साथ उसका मजबूत गठ-बन्धन है । कनाडा के बढ़ते हुए उद्योगों की इंग्लैंड के कुछ उद्योगों के साथ लाग-डॉट है और वह इस मामले में इंग्लैंड के सामने झुकने को तैयार नहीं है । कनाडा के अपने पड़ोसी संयुक्तराष्ट्र के साथ भी कई तरह के ताल्लुकात हैं । दक्षिणी अफ़रीका में पुरानी कटुता तो अब नहीं रही, पर वहाँ साम्राज्य के लिए बहुत प्रेम भी नहीं है । इंग्लैंड ने आयर्लैंड के माल पर कर लगाये तो इसलिए ये कि वह डरकर घुटने टेक देगा, मगर नतीजा उलटा ही हुआ । इन करों से आयर्लैंड के कारखानों और खेती को ख़ूब उत्तेजन मिला है और आयर्लैंड को स्वावलम्बी राष्ट्र बनने में बड़ी कामयाबी मिल रही है । वहाँ नये-नये कारखाने खड़े होगये हैं और जहाँ पहले घास उगती थी वहाँ अब अनाज की खेती होने लगी है । हल फिर से चलने लगा है । जो खाद्य-पदार्थ पहले इंग्लैंड भेज दिये जाते थे उन्हें लोग खुद काम में लेने लगे हैं और उनके रहन-सहन का ढंग ऊँचा होरहा है । इस तरह डि वेलरा ने सफल होकर अपनी नीति को ठीक साबित कर दिया है । आज आयर्लैंड उग्र और मुक्ताविले के लिए तैयार होकर ब्रिटेन की साम्राज्यवादी नीति में काँटे की तरह चुभ रहा है । ओटावान्तरीखे समझौते के साथ उसका बिल्कुल मेल नहीं बैठता ।

इस तरह उपनिवेशों के साथ व्यापारिक सम्बन्ध रखकर इंग्लैंड को कोई फ़ायदा नहीं होरहा है । हिन्दुस्तान से वह बहुत फ़ायदा उठा सकता था, क्योंकि यहाँ फिर भी उसके लिए लम्बा-चौड़ा बाज़ार था । लेकिन हिन्दुस्तान की राजनैतिक स्थिति और यहाँका आर्थिक कष्ट ब्रिटिश व्यापार के लिए अनुकूल नहीं है । लोगों को जेल भेजकर ब्रिटिश माल ख़रीदने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता ।

श्री स्टैनली बाल्डविन ने हाल ही में मँचेस्टर में कहा था:—

“The day when we could dictate to India and tell her when and where to buy her goods was gone. The safeguard for trade was

शरण है। यह बात सच हो सकती है, क्योंकि अब जर्मनी के लिए हिटलरशाही के सिवा दूसरा रास्ता साम्यवाद का ही है।

मुसोलिनी के अधीन इटली का दृष्टिकोण अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में बहुत व्यावहारिक और स्वार्थपूर्ण है। उसमें भावना का कोई स्थान नहीं है। वह दूसरे राष्ट्रों की तरह शान्ति और सद्भाव की बड़ी-बड़ी बातें भी नहीं बनाता। वह लड़ाई के लिए जी-जान से तैयारी कर रहा है, क्योंकि उसे विश्वास है कि थोड़े समय बाद लड़ाई होकर रहेगी। इस बीच में वह अपनी हालत मजबूत करने के लिए चालें चल रहा है। खुद फ्रंसिस्ट होने के कारण उसने जर्मनी में फ्रंसिज्म का स्वागत किया है। हिटलर के अनुयायियों से उसकी दोस्ती है। मगर आस्ट्रिया के साथ एक होने का जर्मन नीति का जो बड़ा उद्देश्य है, उसके इटली खिलाफ है। इस तरह की एकता होजाने से जर्मन सीमा ठेठ इटली की सरहद से मिल जाती है और मुसोलिनी जर्मनी के अपने फ्रंसिस्ट द्रष्टु का इतना नजदीक आना पसन्द नहीं करता।

मध्ययोरप के छोटे-छोटे राष्ट्र मन्दी के पंजे में फँसे हुए हाँक रहे हैं और महायुद्ध के बाद के अस्तर से दुःख भोग रहे हैं। हिटलर और नाज़ियों के डर के मारे तो अब इन देशों के पूरी तरह होश उठे हुए हैं। मध्य-योरप के इन सब देशों में, और खासतौर पर जहाँ जर्मनी या आस्ट्रिया की तरह जर्मन या फ्रेंच लोग हैं वहाँ, नाज़ी-दल बढ़ रहे हैं। लेकिन साथ ही नाज़ी-विरोधी भावना भी बढ़ रही है और इनका नतीजा संघर्ष है। आजकल इस भिड़न्त का खास मैदान आस्ट्रिया बना हुआ है।

कुछ समय हुआ, शायद १९३२ में, मध्य-योरप और डेन्प्य प्रदेश के फ्रान्स के समर्थक तीनों देश जेकोस्लोवेकिया, रमानिया और युगोस्लाविया ने अपना एक मंच बनाया था। महायुद्ध का जो निपटारा हुआ था उनमें इन तीनों राज्यों को फायदा हुआ था और उन्हें जो कुछ मिला था उसकी वे रक्षा करना चाहते थे। इस काम के लिए वे आपस में मिल गये हैं और सचमुच युद्ध के लिए उन्होंने आपस में मित्रता करली है। उनके गुट को लघु राष्ट्र-संघ (Little Entente) कहते हैं। इन तीनों राज्यों का यह गुट एक तरह से योरप में एक नई महाशक्ति बन गया है। यह शक्ति फ्रान्स के पक्ष में और जर्मनी और इटली के खिलाफ है।

जर्मनी से नाज़ियों की जीत इस लघु राष्ट्र-संघ और पोलैण्ड के लिए ख़तरे की घण्टी थी, क्योंकि नाज़ी लोग वर्साई की सन्धि पर पुनर्विचार तो कराना चाहते ही थे (यह बात सभी जर्मन चाहते थे)। साथ ही वे दोलने भी ऐसी भाषा में थे जि जिसमें युद्ध नजदीक आना हुआ दिखाई देता था। नाज़ियों की भाषा और दूसरी वार्तादायक इनकी हथ और हिमायत की कि वर्साई के अहंताओं से नजदीकी चाहनेवाले आस्ट्रिया और

आकाश-पाताल का अन्तर है। ये एक-दूसरे पर आँखें निकालते और योरप और एशिया-भर में एक-दूसरे के खिलाफ़ साजिश करते रहते हैं। इन दोनों शक्तियों का थोड़े समय के लिए परस्पर शान्तिपूर्वक रहना सम्भव है, मगर इनमें हमेशा के लिए मेल होता बिल्कुल नामुमकिन है; क्योंकि इनके आदर्श बिल्कुल अलग-अलग हैं। अगर इन दोनों में कोई बड़ी भिड़न्त होनी हो है तो इंग्लैण्ड यह नहीं चाहेगा कि उसमें बहुत देर हो, क्योंकि सोवियट की ताकत हर साल बढ़ती जाती है। उधर रूस कुछ दिन ठहरकर, यानी थोड़ा चलवान और पूरी तरह तैयार होकर, दो-दो हाथ करना चाहेगा।

इंग्लैण्ड आज एक सन्तुष्ट शक्ति है, क्योंकि उसे जो कुछ चाहिए वह सब मिला हुआ है। उसे डर है कि कहीं यह सब हाथ से जाता न रहे; और यह डर सच्चा है। वह वर्तमान स्थिति को क्रायम रखने की खूब कोशिश करता है और इस काम के लिए राष्ट्र-संघ का उपयोग करता है। लेकिन घटना-चक्र को रोकना उसके या और किसी राष्ट्र के बस की बात नहीं है। वेशक आज वह मजबूत है, लेकिन इसमें शुबहा नहीं कि साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में वह कमजोर हो रहा है और उसके दिन ढल रहे हैं। हम उसके महान साम्राज्य को अस्त होते हुए देख रहे हैं। (कहीं यह बात तो नहीं है कि चूँकि मैं ऐसा चाहता हूँ इसीलिए मैं ऐसा सोचता हूँ ?)

इंग्लिश चैनल के उस पार योरप के महादेश में पहुँचने पर पहलेपहल फ़्रांस आता है। यह भी एक साम्राज्यवादी राष्ट्र है। अफ़्रीका और एशिया में उसका बड़ा साम्राज्य है। सैनिक अर्थ में एक प्रकार से वह योरप में सबसे प्रबल राष्ट्र है। उसके पास बड़ी शक्तिशाली सेना है और वह पोलैण्ड, जेकोस्लोवेकिया, बेलजियम, रूमानिया और यूगोस्लाविया वगैरा दूसरे देशों के एक समूह का नेता है। फिर भी उसे ख़ास तौर पर हिटलर के शासन के समय से जर्मनी की लड़ाकू भावना का डर है। सचमुच हिटलर ने पूँजीवादी फ़्रांस और सोवियट रूस की आपसी भावनाओं में मार्क का परिवर्तन कर दिया है। समान शत्रु सामने होने के कारण दोनों आपस में बड़े मित्र हो-गये हैं।

जर्मनी में नाज़ियों का आतंक अभी जारी है और नित नये अत्याचारों की ख़बरें आती रहती हैं। यह पाशविकता कबतक बनी रहेगी, यह नहीं कहा जा सकता। पाँच महीने तो हो चुके हैं और उसमें कमी नहीं हुई है। ऐसा दमन स्थायी शासन का निशान कभी नहीं होसकता। मुमकिन है जर्मनी की फ़ौजी ताकत काफ़ी होती तो कभी की योरप में लड़ाई छिड़ गई होती। शायद आगे चलकर छिड़ भी जाय। हिटलर को यह कहने का शौक है कि वह साम्यवाद को छोड़कर आये हुआँ के लिए अन्तिम

की सभी चीजें तैयार कर सकता हो। लेकिन प्रवृत्ति यह है कि जो कुछ चाहिए वह अपने ही यहाँ पैदा या तैयार कर लिया जाय। कुछ जरूरी चीजें ऐसी हो सकती हैं जो आबोहवा के कारण देश के भीतर तैयार न हो सकें। मिसाल के लिए इंग्लैंड रुई, सन, चाय, क़हवा और कई ऐसे पदार्थ पैदा नहीं कर सकता जिनके लिए गरम आबो-हवा की जरूरत होती है। इसका यह अर्थ हुआ कि भविष्य में व्यापार ज्यादातर उन्हीं देशों के बीच में होगा जिनके जल-वायु भिन्न होंगे और इसलिए उनमें पैदावार भी अलग-अलग तरह की होगी और माल भी भिन्न प्रकार का बनेगा। एक ही तरह की चीजें तैयार करनेवाले देशों का माल उनके आपस में काम नहीं आयगा। इस तरह व्यापार उत्तर और दक्षिण के बीच में होगा। पूर्व और पश्चिम के बीच में न होगा, क्योंकि आबोहवा उत्तर और दक्षिण के हिसाब से बदलती है। गरम देश का ठण्डे देश के साथ व्यापार हो सकेगा, परन्तु दो गरम देशों का या दो समशीतोष्ण देशों का आपस में व्यापार नहीं हो सकेगा। अवश्य ही देश के खनिज साधनों जैसे दूसरे कारण भी हो सकते हैं। लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के मामले में मुख्यतः उत्तर और दक्षिण वाली बात ही लागू होगी, चुंगी की दीवारें और सब तरह का व्यापार रोक देंगी।

आज यह प्रवृत्ति अनिवार्य दिखाई देती है। जब सब देशों के उद्योग काफ़ी उन्नत होजायेंगे तब औद्योगिक क्रान्ति की यह आखिरी मण्डल होगी। यह सच है कि अभी एशिया और अफ़रीका का उद्योगवादी होना बहुत दूर की बात है। अफ़रीका तो इतना पिछड़ा हुआ और गरीब है कि वहाँ बहुत पक्का माल नहीं खप सकता। अलग-अलग भारत, चीन और साइबेरिया ये तीन बड़े प्रदेश ऐसे हैं जहाँ हम विदेशी माल की खपत की गुंजाइश रहेगी। बाहर के उद्योगवादी देश इन तीनों बड़ी मण्डियों पर उत्तुंग दृष्टि लगाये हुए हैं। इन देशों के मामूली बाज़ार उनके हाथ में छिन गये हैं, इसलिए अपना प्रालम्बू माल ठिकाने लगाने और इस उपाय से अपने जर्जर पूंजीवाद को जीवित रखने के लिए वे एशिया पर हल्ला बोलने का विचार कर रहे हैं। परन्तु अब एशिया का शोषण करना इतना आसान नहीं रहा; क्योंकि एक तो एशिया के उद्योग बढ़ चले हैं और दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्धा भी खूब है। इंग्लैंड तो चाहता है कि हिन्दुस्तान में उसका माल बिके। लेकिन जापान, अमेरिका और जर्मनी चाहते हैं कि उनका भी बिके। यही बात चीन के बारे में है। वहाँ एक कठिनाई व्यापार के रास्ते में और है; और यह यह है कि आजकल उसकी स्थिति बड़ी अमान्य है और आमद-गन्त के जैसे साधन चाहिए वैसे साधन भी नहीं हैं। नोबिस्ट हम बाहर का बहुत-सा तैयार माल लेने को चाहते हैं, मगर उसे उधार मिलना चाहिए, यानी उसकी हीनत उसे तुरन्त न देनी परे। थोड़े समय बाद तो नोबिस्ट सच अपनी इच्छा की चीज़ें तैयार करने लगेंगे।

हंगरी जैसे राज्य भी डर गये। हिटलरवाद और उसके खोफ की वजह से मध्य-योरप और पूर्व के सारे राज्य, जिनमें अबतक आपस में बड़ी नफरत थी, एक-दूसरे के नजदीक आगये। 'लघुराष्ट्र' पोलैण्ड, आस्ट्रिया, हंगरी और बालकन राज्य सबमें मेल होने लगा। इनमें आर्थिक एकता और सहयोग की चर्चायें भी चली हैं। जबसे जर्मनी में नाज़ी ज्वालामुखी फटा है तबसे ये देश और खास तौर पर पोलैण्ड और चेकोस्लावे-किया भी सोवियट रूस के अधिक मित्र बन गये हैं। इसका एक नतीजा यह हुआ कि कुछ हफ्तों पहले रूस और इन देशों के बीच में एक-दूसरे पर हमला न करने का सम-झौता हो गया है।

स्पेन के बारे में मैं तुम्हें बतता चुका हूँ कि वहाँ हाल ही में क्रान्ति हुई है। अभी वह स्थिर नहीं हो सकता और मालूम होता है कि उसके सिर पर दूसरे परिवर्तन के बादल मंडरा रहे हैं।

इस तरह तुम देखती हो कि योरप में आजकल आपस के संघर्ष और घटना के कारण कौसी अजीब और रंग-विरंगी हालत हो रही है और विरोधी राष्ट्र-समूह किस तरह एक-दूसरे पर आँखें लाल कर रहे हैं। निःशस्त्रीकरण की बातों का कोई अन्त नहीं आता। फिर भी सब जगह फ़ौजें बढ़ाई जा रही हैं और युद्ध और विनाश के लिए नये और भयंकर अस्त्र ईजाद किये जा रहे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की भी बहुत चर्चा होती है। परिपक्व तो वेशुमार होती है, मगर सब बेकार। राष्ट्र-संघ खुद इस बुरी तरह असफल हुआ है कि देखकर दया आती है। अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक परिपक्व भी हो चुकी और मिलकर काम करने की आखिरी कोशिश भी बेकार गई। एक प्रस्ताव यह है कि योरप के भिन्न-भिन्न देश, या यों कहो कि रूस को छोड़कर सारा योरप, मिल जायें और एक तरह से योरप को संयुक्त राज्य बना लें। यह आन्दोलन असल में इसलिए है कि एक तो सोवियट के विरोध में गुट बना लिया जाय और दूसरे इतने अधिक छोटे-छोटे राष्ट्रों के होने से जो वेशुमार कठिनाइयाँ और उलझनें होती हैं वे बन्द हो जायें। लेकिन राष्ट्रों को एक-दूसरे से इतनी जबरदस्त नफरत है कि कोई ऐसे प्रस्ताव पर ध्यान नहीं दे सकता।

असल बात यह है कि हर मुल्क दूसरे मुल्कों से और अधिक जुदा होता जा रहा है। संसार-व्यापी मन्दी और संकट के कारण इस क्रिया की गति और भी तेज होगई है और सभी देश आर्थिक राष्ट्रवाद के रास्ते पर सरपट दीड़े जा रहे हैं। सभी ऊँची-ऊँची चुंगी की दीवारें खड़ी करके उनके पीछे बैठे हैं और विदेशी माल को अपने यहाँ न घुसने देने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। अवश्य ही कोई देश सारे विदेशी माल का बहिष्कार नहीं कर सकता, क्योंकि कोई देश ऐसा स्वावलम्बी नहीं है जो अपनी जरूरत

भी चले जाओ, ऊँची-ऊँची वाजियाँ लगी हुई हैं और भले ही पुरानी प्रणाली की जड़ थोड़ी देर के लिए मजबूत जमी हुई मालूम देती हो फिर भी उसे शक्ति की दशा लग गई है। आज तो साम्राज्यवाद और पूँजीवाद की सारी इमारत की जड़ हिल चुकी है और उसपर जो कर्ज चढ़ा हुआ है और उससे जो मार्गों की जारही हैं उनका निपटारा करने की भी उसमें ताकत नहीं है। ऐसी हालत में छोटे-मोटे सुधारों से आज की समस्या हल नहीं हो सकती।

इन बेधुमार राजनैतिक, आर्थिक और जातीय संघर्षों ने आज संसार को अन्ध-कारमय बना रखा है और युद्ध के काले बादल इनके साथ हैं। कहा जाता है कि सबसे बड़ा और मौलिक संघर्ष साम्राज्यवाद और फ्रैंसिज्म की सम्मिलित शक्ति और साम्यवाद के बीच में है। इन दोनों का दुनिया-भर में मुकाबिला है और इनके बीच समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है।

सामन्तशाही, पूँजीवाद, समाजवाद, संघवाद, अराजकतावाद और साम्यवाद इन सब 'वादों' की आड़ में अपना काम बनाने की प्रवृत्ति भी जारी है। मगर एक आदर्शवाद और भी है। यह उन्हीं लोगों के लिए है जो सचमुच इसे चाहते हैं। यह आदर्शवाद फोरी कल्पनाओं और खाली पुलकों का खेल नहीं है, बल्कि किसी बड़े मानवीय उद्देश्य के लिए काम करने का आदर्शवाद है—एक महान् आदर्श जिसे हम वास्तविक बनाना चाहते हैं। जार्ज बर्नार्ड शा ने कहीं कहा है :—

“जीवन का सच्चा आनन्द यह है कि जिसे तुम कोई महान् उद्देश्य मानने हो उगीमें जीवन को लगादो; कचरे में फेंक दिये जाने से पहले अपने शरीर का यथ-कायण हम काम में जर्जर हो जाने दो और प्रकृति के हाथ में एक शक्ति बनकर रहो। हममें क्या धरा है कि तुम विकार और स्वार्थ के पुतले बनकर अपने दुःख-दर्द रोते रहो और यह शिकायत करते रहो कि दुनिया तुम्हारे सुख के लिए नहीं बनी रही है ?”

इतिहास की खोज से मालूम होता है कि किन तरह संसार एक होता आया है। किस प्रकार भिन्न-भिन्न भाग मिलते रहे हैं और एक-दूसरे पर निर्भर रहते आये हैं। दुनिया सचमुच एक ऐसी चीज बन गई है कि उसके टुकड़े नहीं किये जा सकते और उतने सब हिस्सों का आपस में असर पड़ता है। अब राष्ट्रों का अलग-अलग इतिहास बनाना बिल्कुल असम्भव है। वह मंजिल पार हो चुकी। अब तो ऐसे ही इतिहास ने कोई काम होसकता है जो सारे संसार को एक समझकर लिखा जाय, जिसमें सारे राष्ट्रों के अलग-अलग सूत्र आपस में मिलाने जाय और जिसमें राष्ट्रों की प्रेरणा करनेवाली अमूर्त शक्तियों की खोज की जावे।

प्राचीन काल में भी राष्ट्र अनेक भौतिक और दमनकी स्वायत्तों के कारण एक-

पिछली सारी प्रवृत्ति यह रही है कि राष्ट्र एक-दूसरे पर अधिक निर्भर रहें और अन्तर्राष्ट्रीय भावना बढ़े। यद्यपि अलग-अलग स्वतंत्र राज्य रहें, फिर भी अन्तर्राष्ट्रीय मन्व्य और व्यापार की एक बड़ी भारी और पेचीदा इमारत खड़ी होजाय। यह तलसिला यहांतक पहुँचा कि राष्ट्रीय राज्यों और खुद राष्ट्रवाद के साथ इसका घर्ष होने लगा। इसके आगे की सोढ़ी क़ुदरती तीर पर यही है कि समाजवाद की अन्तर्राष्ट्रीय रचना की जाय। पूँजीवाद के दिन पूरे हो चुके और वह एक ऐसी मंजिल पर पहुँच गया है, जहाँ उसे समाजवाद के लिए जगह खाली कर देनी चाहिए। लेकिन दक्किस्मती से इस तरह अपने-आप कोई संन्यास नहीं लेता। संकट के कारण मीत ज़दीक आती देखकर पूँजीवाद अपनी खोल में घुस गया है और वहाँ बँठा-बँठा सहयोग की वृत्ति को उलट देने की कोशिश कर रहा है। आर्थिक राष्ट्रवाद का यही कारण है। सवाल यह है कि क्या इसमें कामयाबी मिलेगी और मिलेगी तो वह कब तक टिकेगी ?

सारी दुनिया एक अजीब खिचड़ी बन गई है। संघर्ष और ईर्ष्या-द्वेष का भयंकर ताना-बाना लगा हुआ है और नई-नई प्रवृत्तियों के कारण संघर्ष के क्षेत्र का विस्तार बढ़ता जा रहा है। प्रत्येक महादेश में और हरेक मुल्क में कमज़ोर और पीड़ित लोग जीवन की अच्छी चीज़ों में हिस्सा बँटाना चाहते हैं। इन्हें वे ही तो पैदा करते हैं। वे कहते हैं कि हमसे क़र्ज़ा लिए बहुत दिन होगये, अब वह चुका दिया जाय। कहीं यह माँग बहुत जोर की, कर्कश और उग्र भाषा में की जा रही है, और कहीं ज़रा शान्त शब्दों में। उनके साथ इतने दिन जैसा व्यवहार किया गया है और जिस तरह उनका शोषण हुआ है उसपर उनके हृदय में रोष और कटुता हो और वे कोई अवाञ्छनीय व्यवहार करें तो क्या हम उन्हें दोष दे सकते हैं ? वे तो उपेक्षा और तिरस्कार के शिकार रहे हैं। उन्हें ड्राइंग रूम यानी बैठक की सभ्यता सिखाने की तकलीफ़ किसने गवारा की ?

शरीरों और पीड़ितों में यह उथल-पुथल देखकर सभी जगह के सम्पन्न वर्ग घबरा उठे हैं और मिलकर इसे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। फ़ैसिज़्म की वृद्धि इसी तरह हो रही है और साम्राज्यवाद विरोध मात्र को इसी तरह कुचल रहा है। लोकसत्ता, लोक-कल्याण और ट्रस्टीशिप यानी थाती की अच्छी-अच्छी बातें ताक़ में धरी जा रही हैं और स्थापित स्वार्थ रखनेवाले सम्पन्न वर्ग का निरंकुश शासन असली रूप में सामने आ रहा है। बहुत जगहों पर उसकी जीत भी होती दिखाई दे रही है। एक ज्यादा कठोर युग—उग्र हिंसा का एक युग—अपना मुँह निकाल रहा है, क्योंकि सर्वत्र नये और पुराने में जीवन-मरण का युद्ध चल रहा है। योरप, अमेरिका या हिन्दुस्तान कहीं

हम सभी, या कम-से-कम जो विचारशील हैं वे, भावी पर आशा लगाये देख रहे हैं कि आगे चलकर क्या-क्या होता है और भविष्य का वर्तमान कैसे बनता है। जो कुछ होनेवाला है उसकी कुछ लोग आशा के साथ और दूसरे लोग भयभीत होकर बाट जोह रहे हैं। क्या यह आनेवाला संसार अधिक सुन्दर और अधिक सुखी होगा और उसमें जीवन की अच्छी-अच्छी चीजें मूढ़ीभर लोगों के लिए ही सुरक्षित न रहकर आजादी के साथ आम लोगों के काम भी आयेंगी ? या वह संसार आज से भी ज्यादा कठोर होगा और मौजूदा सभ्यता की दी हुई बहुत-सी सुख-सामग्री भयंकर और नाशकारी युद्ध में खप जायगी ? इन दोनों बातों में ज़मीन-आसमान का अन्तर है और इनमें से कोई भी होसकती है। यह तो मुमकिन नहीं दिखाई देता कि कोई बीच का रास्ता निकल आयगा।

हम ध्यान से देखते और इन्तज़ार करते हैं और साथ ही हम जिस प्रकार का संसार चाहते हैं उसके लिए काम भी करते हैं। पशु की हालत से निकलकर मनुष्यत्व की दिशा में प्रगति इस तरह नहीं हुई है कि प्रकृति के सामने लाचार होकर सिर झुका दिया जाय, बल्कि अप्सर इस प्रकार हुई है कि प्रकृति का सामना किया जाय और मनुष्यों के हित के लिए प्रकृति पर हावी होने की इच्छा रखी जाय।

आज की हालत तो यह है। कल का बनना और बिगड़ना तुम्हारे और तुम्हारी पीढ़ी के लाखों लड़कों और लड़कियों के हाथ में है, जो दुनियाभर में बड़े हो-होकर कल के काम में भाग लेने के लिए तालीम पा रहे हैं।

: १६६ :

आखिरी ख़त

९ अगस्त, १९३३

लो बेटो, हमारा काम ख़त्म हुआ। यह लम्बी कहानी समाप्त हुई। अब मुझे और नहीं लिखना है। लेकिन ख़त्म करते-करते सारी बात को सँवारने के टंग पर एक छत और लिख डालने की इच्छा होती है। यह आखिरी ख़त है।

बैसे ख़त्म करने का समय भी होचुका, क्योंकि मेरी दो माल की मियाद भी पूरी होने आई। आज से तीस दिन में मैं छूट जाऊँगा। जेलर तो कभी-कभी यह धमकी भी देता है कि शायद इन्हने पहले ही छोड़ दिया जाऊँ। अभी पूरे दो बरस तो नहीं हुए हैं, मगर अच्छी चाल-चलनवाले इंदियों को जो छूट मिलती है उसके अनुसार मेरी मला में भी साढ़े तीन महीने घट गये हैं। मैं जेलराने में भला-भा-

दूसरे से जुदा रहते थे; परन्तु हम देख चुके हैं कि उस समय भी अन्तर्राष्ट्रीय और अन्तर्देशीय सामान्य शक्तियाँ कितना असर डालती थीं। महान् व्यक्तियों का इतिहास में सदा ही महत्त्व रहा है, क्योंकि भाग्य-चक्र में मनुष्य बड़ी चीज है ही। परन्तु बड़े-से-बड़े व्यक्तियों से भी बड़ी वे प्रबल और सक्रिय शक्तियाँ होती हैं जो अन्वी और निर्दय होकर हमें इधर-उधर धकेलती हुई आगे बढ़ाती रहती हैं।

हमारा भी आज यही हाल है। करोड़ों मनुष्यों के हृदयों में ज्वरदस्त शक्तियाँ काम कर रही हैं और वे भूचाल या क्रुदरत की ओर किसी उथल-पुथल की तरह आगे बढ़ रही हैं। हम लाख कोशिश करें तो भी उन्हें नहीं रोक सकते। फिर भी हम अपनी दुनिया के छोटे-छोटे कोनों में उनकी गति या दिशा में कुछ अन्तर कर सकते हैं। हम उन शक्तियों का सामना अपने अलग-अलग स्वभाव के अनुसार करते हैं। कुछ लोग उनसे डर जाते हैं, कुछ उनका स्वागत करते हैं। कुछ उनके साथ लड़ने की कोशिश करते हैं, और कुछ लाचार होकर भाग्य के प्रबल हाथों के सामने हाथियार डाल देते हैं। कुछ लोग उन शक्तियों का सीधा सामना करते हैं और उनपर क्रावू करके एक खास दिशा में उन्हें लेजाने की कोशिश करते हैं। ये लोग उन तमाम आपत्तियों को खुशी से बर्दाश्त करते हैं जो किसी बड़ी क्रिया में प्रत्यक्ष सहायता करने के काम में आती हैं। इसका आनन्द भी वे ही भोगते हैं। यह बीसवीं सदी अशान्ति और कोलाहल का युग है। इसमें हमारे लिए कहीं अमन-चैन नहीं है। इस सदी का तीसरा भाग बीत चुका है और उसमें युद्ध और क्रान्तियों की भरमार रही है। महान् फ्रैंसिस्ट मुसोलिनी कहता है कि 'सारी दुनिया में क्रान्ति होरही है। घटनाओं में इतनी जबर-दस्त शक्ति है कि वह अटल भाग्य की तरह हमें आगे धकेलती लेजा रही है।' महान् साम्यवादी ट्राट्स्की भी हमें सचेत करता है कि इस शताब्दी से आराम और शान्ति की बहुत आशा नहीं रखनी चाहिए। वह कहता है—“यह साफ़ है कि इतनी अशान्ति पिछली किसी सदी में नहीं हुई जितनी बीसवीं सदी में होरही है। अगर हमारे समय का कोई आदमी और सब बातों से पहले सुख और शान्ति चाहता है तो उसने संसार में जन्म लेने के लिए बुरा वक्त चुना है।”

सारा संसार प्रसव-पीड़ा भोग रहा है। सब जगह युद्ध और क्रान्ति के काले बादल छाये हुए हैं। अगर यह सब कुछ होना ही है और इससे बचने का कोई उपाय ही नहीं, तो इसका सामना कैसे किया जाय? क्या शूतुरमूर्ख की तरह मुंह छिपाएँ? या यह कि वीरों की भाँति घटना-चक्र को बनाने की कोशिश करें, जरूरत हो तो जोखिम और विपत्ति उठाएँ, एक बड़ा, पवित्र और साहस का काम करने का आनन्द भोगें और यह अनुभव करें कि “हमारे कदम भी इतिहास के साथ मिल रहे हैं?”

सत्रहवीं सदी का एक मशहूर कानून-दाँ और तत्त्वज्ञानी था। उसे उमर-रूंद की सजा हुई थी, लेकिन वह किसी तरह दो वर्ष बाद ही निकल भागा था। उसने ये दोनों साल जेल में तत्त्वज्ञान और साहित्य-सम्बन्धी काम में बिताये थे। और भी बहुत-से प्रसिद्ध साहित्यिक लोग जेल की हवा खा चुके हैं। शायद इनमें से सबसे मशहूर दो आदमी हुए हैं। एक तो स्पेन-निवासी सर्वदोषी जिसने “डॉन क्विजोट” लिखा, और दूसरा जॉन वनियन अंग्रेज था जिसने “दि पिल्ग्रिम्स प्रोग्रेस” लिखा था।

मैं कोई साहित्यिक आदमी नहीं हूँ और यह कहने के लिए भी तैयार नहीं हूँ कि मैंने जो अनेक वर्ष जेलखाने में काटे हैं वे मेरे जीवन के सबसे मधुर वर्ष थे। मगर मैं यह जरूर कहूँगा कि यह वक़्त गुजारने में मुझे लिखने-पढ़ने के काम से अद्भुत सहायता मिली। मैं साहित्यकार भी नहीं और इतिहासकार भी नहीं। तो मैं असल में हूँ क्या? मुझे इस सवाल का जवाब देने में कठिनाई होती है। मैं बहुत बातों में दखल देता रहा हूँ। मैंने कालेज में विज्ञान शुरू किया, फिर कानून पास किया, और अन्त में जीवन की भिन्न-भिन्न बातों में रस लेने के बाद जेल जाने का धन्या ग्रहण कर लिया। हिन्दुस्तान में यह पेशा बहुत लोग करने लगे हैं!

इन चिट्ठियों में मैंने जो कुछ लिखा है उसे तुम किसी भी विषय पर आखिरी बात न समझना। राजनीतिज्ञ लोग हर विषय पर कुछ-न-कुछ कहा चाहते हैं और उन्हें दर-असल जितना ज्ञान होता है उससे अधिक दिखाया करते हैं। इसलिए उनपर कड़ी नज़र रखने की जरूरत है। मेरी इन चिट्ठियों में अलग-अलग विषयों का सिक्र ऊपरी स्याफ़ा खींचा गया है और एक हल्का-सा सिलसिला मिला दिया गया है। मैं तो जो जी में आया लिखता गया हूँ। कहीं तो मैंने सदियों का और अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का थोड़ा-सा जिक्र कर दिया है और कहीं किसी एक ही घटना पर मुझे दिलचस्पी हुई तो बहुत समय लगा दिया है। तुमने देखा होगा कि यह बात खूब स्पष्ट है कि कौनसी बातें मुझे पसन्द हैं और कौनसी बातें मुझे नापसन्द हैं। इसी तरह से मुझपर जेल में कभी कुछ और कभी कुछ धुन सवार होती रही है। मैं नहीं चाहता कि तुम ये सब बातें ज्यों-की-यों मान लो। मुमकिन है मेरे वर्णन में सचमुच बहुत भूलें हों। जेल में न पुस्तकालय होता है और न ऐसी पुस्तकें पास होनी हैं जिन्हें देखकर आदमी अपनी जानकारी को सही या ताज़ा कर सके। इसलिए इतिहास के विषय पर लिखने के लिए घर जगह बहुत अन्कूल नहीं होती। मुझे बहुत-कुछ उन याददाश्यों पर निर्भर रहना पड़ा है जो मैंने दारुह वर्ष पहले जेल-यात्रा शुरू करने के समय में ही इकट्ठी कर रखी थी। मेरे पास यहाँ बहुत-सी किताबें भी आईं, लेकिन वे जैसी आईं वैसी ही चली गईं। क्योंकि मैं यहाँ उग्रे इकट्ठी नहीं रख सकता था। मैंने उन किताबों में से विचार

नुप समझा जाता हूँ, हालाँकि मैंने यह नाम कमाने के लिए सचमुच कुछ नहीं किया है। इस तरह मेरी छठी सजा पूरी होती है और मैं विशाल संसार में यहाँसे निकलकर फिर आऊँगा। मगर किस लिए ? उससे फ़ायदा क्या ? (Quoi Bon ?) जब मेरे ज्यादातर साथी और दोस्त जेलों में पड़े हुए हैं और सारा देश एक बड़ा जेलखाना-सा दिखाई देता है, तो मैं ही बाहर क्या करूँगा ?

मैंने छतों का पहाड़-सा खड़ा कर दिया ! और कितने स्वदेशी क्रागज़ पर कितनी स्वदेशी स्पाही फँदावी ! आश्चर्य होता है कि यह काम इस लायक था या नहीं ? क्या इस सारे क्रागज़ और स्पाही से तुम्हें कोई रोचक सन्देश मिलेगा ? तुम ज़रूर 'हाँ' कहोगी क्योंकि, तुम समझोगी कि और किसी जवाब से मेरा जी दुखेगा और तुम्हारा मेरे साथ इतना पक्षपात तो है ही कि तुम इस तरह का जोखिम नहीं उठा सकतीं। मगर तुम्हें यह अच्छा लगे या न लगे, तुम्हें इतना तो ख़याल होगा ही कि दो साल की इस लम्बी अवधि में रोज़-रोज़ इन्हें लिखकर मैं सुखी हुआ हूँ। जब मैं यहाँ आया था, जाड़े के दिन थे। सर्दी के बाद थोड़े दिनों के लिए वसन्त-ऋतु आई और फिर गर्मी के मौसम ने उसकी जल्दी ही हत्या कर डाली। बाद में जब ज़मीन सूख गई और गर्मी के मारे मनुष्य और पशुओं का साँस लेना मुश्किल होगया तब वर्षा-ऋतु आई और उसने सब जगह ताज़ा और ठण्डा पानी-ही-पानी बरसा दिया। उसके बाद फिर जाड़ा आया और आकाश निहायत साफ़ और नीला होगया और तीसरे पहर का वक़्त सुहावना मालूम होने लगा। वर्ष का चक्र ज़ात्म होकर फिर शुरू हुआ। जाड़े के बाद वसन्त, वसन्त के बाद गर्मी और गर्मी के बाद वर्षा—यही दौर रहा। मैं यहाँ बैठा-बैठा तुम्हें लिखता रहा हूँ, तुम्हारी याद करता रहा हूँ, ऋतुओं को आते और जाते देखता रहा हूँ और अपनी बरक की छत पर मैं ही की तड़ातड़ सुनता रहा हूँ :

“O doux bruit de la pluie.

Par terre et sur les toit's!

Pour un Coeur quis'ennuie,

Oh! le chant de la pluie !”

अर्थात्—“पृथ्वी और छतों पर होनेवाले वर्षा के ऐ मुलायम शब्द ! एवं हृदय, जो प्यासा और उत्सुक है, उसके लिए है वर्षा के संगीत !”

वेंजमिन डिज़रैली उन्नीसवीं सदी का एक बड़ा अंग्रेज़ राजनीतिज्ञ था। उसने लिखा है कि “और लोग अगर देश-निकाले और क़ैद की सज़ा भुगतने के बाद ज़िन्दा रहते हैं तो निराश होजाते हैं। लेकिन साहित्यिक लोग उन्हीं दिनों को जीवन का सबसे मधुर काल समझ सकते हैं।” वह दृचूगो ग्रीटिज़ के बारे में लिख रहा था, जो

लन, निनेवा, भारत की प्राचीन सभ्यता, आर्यों का हिन्दुस्तान में आना और योरप और एशिया में फैल जाना, चीनी संस्कृति के अद्भुत कारनामे, नोसास और यूनान, शाही रोम और वेजेंटीर, अरबों का दो महादेशों में विजय-दुन्दुभी वजाना, भारतीय संस्कृति का पुनर्जीवन और पतन, अमेरिका की माया और आज़्टेकी सभ्यताएँ, जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं, मंगोलों की विशाल विजयों का सिलसिला, योरप का मध्ययुग और उसमें बने हुए गोथिक ढंग के विलक्षण गिरजे, इस्लाम का हिन्दुस्तान में आना और मुग़ल साम्राज्य, पश्चिमी योरप में विद्या और कला का पुनर्जीवन, अमेरिका का आविष्कार और पूरब में आने के लिए समुद्री मार्गों का मालूम होना, पूर्व में पश्चिमी हमलों की श्रृंखला, बड़ी मशीनों का पैदा होना और पूंजीवाद का विकास, उद्योगवाद का फैलना और योरप का प्रभुत्व और साम्राज्यवाद, और आज की दुनियाँ में विज्ञान की अद्भुत करामातें ।

बड़े-बड़े साम्राज्य चढ़े हैं और गिरे हैं । हजारों वर्ष तक मनुष्य ने उन्हें भुला भी दिया । बाद में किसी धैर्यवान अन्वेषक ने रेत के नीचे ढके हुए उनके खण्डहरों को फिर खोद निकाला । परन्तु साम्राज्यों की अपेक्षा अनेक विचार और कल्पनाएँ अधिक बलवान और दृढ़ सिद्ध हुई हैं ।

मेरी कालरिज ने गाया है :—

“Egypt's might is tumbled down
Down a-down the deeps of thought ;
Greece is fallen and Troy town,
Glorious Rome hath lost her crown,
Venice's pride is nought !
But the dreams their children dreamed
Fleeting, unsubstantial, vain,
Shadowy as the shadows seemed,
Airy nothing, as they deemed.
These remain ”

अर्थात्—“मिस्र की शक्ति उलट गई, यूनान का आज पतन हो गया है, और त्राय नगर धूल में मिल गया है; ऐश्वर्यशाली रोम का मुकुट नष्ट हो गया है; वेनिस का वह अभिमान अब बाकी नहीं रहा; पर उनके बच्चों ने जो उड़ने, धुंधले और छाया के समान दिखार देनेवाले स्वप्न देखे थे वे आज भी जीवन हैं ।”

प्राचीन काल से हमें बहुत-सी चीज़ें देन के रूप में मिली हैं । मच दान तो यह है कि संस्कृति, सभ्यता, विज्ञान या सत्य के कई पहलुओं के ज्ञान के रूप में आज जो हमें मिला हुआ है वह दूर या निकट के भूत की देन है । हम इन रूपों को स्वीकार करें, या दोष ही है । परन्तु हमारा कर्तव्य प्राचीन के साथ ही खत्म नहीं हो जाता ।

और अंक निःसंकोच होकर लिये हैं। मैंने जो कुछ लिखा है उसमें कुछ भी मौलिक नहीं है, शायद कहीं-कहीं मेरे पत्र समझ सकना तुम्हें मुश्किल भी पड़ता होगा। उन हिस्सों को जल्दी-जल्दी देख जाना और कोई खयाल न करना। कभी-कभी मुझपर अपनी बड़ी उम्र का असर ज्यादा रहा और मैं यह भूल गया कि मैं ये चिट्ठियाँ एक लड़की के लिए लिख रहा हूँ। इस कारण मैं कहीं-कहीं इस ढंग से लिख गया, जिसमें कि मुझे नहीं लिखना चाहिए था।

मैंने तुम्हारे सामने सिर्फ रूप-रेखा रखदी है। यह इतिहास नहीं है। इसमें तो लम्बे भूतकाल की केवल उड़ती हुई झलक दिखाई गई है। अगर तुम्हें इतिहास में रुचि हो और तुमपर उसका कुछ भी जादू होता हो, तो तुम्हें बहुत-सी ऐसी किताबें मिल जायेंगी जिनसे तुम्हें प्राचीन काल का सिलसिला बाँधने में मदद मिले। मगर सिर्फ किताबें पढ़ने से ही काम न चलेगा। अगर तुम्हें प्राचीन काल का हाल जानने की इच्छा हो तो तुम्हें उसे सहानुभूति और समझ की दृष्टि से देखना होगा। जो आदमी बहुत समय पहले हुआ हो उसे समझने के लिए तुम्हें यह समझना होगा कि वह कैसे वातावरण और कैसी परिस्थिति में रहा था और उसके दिमाग में क्या-क्या विचार भरे हुए थे। प्राचीन काल के मनुष्यों के बारे में इस तरह से राय बनाना मानों वे आज जीवित हैं और उनके विचार भी हमारे ही जैसे हैं, बेहूदा बात है। आज गुलामी का समर्थक कोई नहीं मिल सकता। मगर महान् अफ़लातून समझता था कि दास-प्रथा जरूरी है। बहुत समय नहीं हुआ, जब संयुक्तराष्ट्र में गुलामी की रक्षा के लिए हजारों आदमियों ने अपने प्राण देदिये थे। हम आज की नाप से पुरानी बातों का निर्णय नहीं कर सकते, यह बात हर शब्द खुशी से मञ्जूर करेगा। लेकिन सब लोग यह क़बूल नहीं करेंगे कि वर्तमान के बारे में पुराने समय की नाप से राय बनाना भी उतनी ही बेहूदा आदत है। त्नासतौर पर विभिन्न धर्मों ने भी पुराने विश्वासों और रीति-रिवाजों को सड़ा दिया है। इनका देश-काल के अनुसार उपयोग रहा होगा, मगर हमारे वर्तमान युग के लिए तो यह जर्रा भी अनुकूल नहीं है।

इसलिए तुम पुराने इतिहास को हमदर्दी की नज़र से देखोगी तो सूखी हड्डियों पर मांस और खून चढ़ जायगा और तुम्हें एक ज़िन्दा और जंगी जुलूस दिखाई देगा। इसमें हर मुल्क और हर ज़माने के स्त्री-पुरुष और बच्चे मिलेंगे, जो हमसे भिन्न पर फिर भी हम-जैसे ही होंगे और वे ही मानवीय गुण और कमज़ोरियाँ उनमें भी मिलेंगी। इतिहास कोई जादू का खेल नहीं है, मगर जिनकी आँखें हैं उनके लिए उसमें जादू खूब है।

इतिहास के अजायबघर के बेशुमार चित्र हमारे दिलों पर अंकित हैं। मिला, बेबि-

बहुत-से भ्रम दूर होगये हैं और कोई बात निश्चित नहीं है। हमारा बहुत-सी पुरानी बातों पर विश्वास नहीं रहा। एशिया, योरप, अमेरिका, सभी जगह पुराने विश्वासों और रीति-रिवाजों को स्वीकार नहीं किया जाता। इस तरह हम अपनी परिस्थिति के अनुकूल सत्य के नये तरीकों और नये पहलुओं की खोज करते हैं। हम एक-दूसरे से सवाल करते हैं, बहस करते हैं, झगड़ा करते हैं और वेगुमार 'वाद' और दर्शन बना लेते हैं। सुकरात के जमाने की तरह हम भी पूछताछ के युग में रहते हैं, मगर यह पूछताछ एथेन्स जैसे एक शहर में ही महद्वद नहीं है, यह दुनिया भर में फैली हुई है।

कभी-कभी दुनिया के अन्याय, दुःख और पागलिकता से हमारा जी दुखता है, हमारे मस्तिष्क में अंधेरा छाजाता है और हमें कोई रास्ता नहीं सूझता। मैथ्यू आर्नाल्ड की तरह हमें भी लगता है कि इस संसार में कोई आशा नहीं है, हम इतना ही कर सकते हैं कि एक-दूसरे के प्रति सच्चे रहें :

“For the world which seems
To lie before us, like a land of dreams,
So various, so beautiful, so new,
Hath really neither joy, nor love, nor light,
Nor certitude, nor peace, nor help for pain;
And we are here, as on a darkling plain
Swept with confused alarms of struggle and flight,
Where ignorant armies clash by night.”

अर्थात्—“यह दुनिया जो हमारे सामने स्वप्नों के एक देश के समान फैली हुई है—इतनी विविध, इतनी सुन्दर, इतनी नवीन—इसमें न आनन्द है, न प्रेम है, न प्रकाश है, न स्थिरता है, न शान्ति है, न दुःख-दर्द में महायत्ना है। और हम मानों अन्धकार से घिरते हुए मैदान में, युद्ध और पलायन की अस्पष्ट ध्वनियों के बीच, लड़ाई रहे हैं—उस अन्धरे मैदान में जहाँ अज्ञानी सेनायों रात के अन्धकार में लड़ती हैं।”

फिर भी हम इस तरह की निराशाभरी निगाह रखें तो कहना होगा कि हमने जीवन या इतिहास किसीसे भी ठीक-ठीक शिक्षा ग्रहण नहीं की है। इतिहास तो हमें यह सिखाता है कि दृढ़ि और उन्नति होती रहती है और मनुष्य की प्रगति कितनी होसकती है इसका तो अन्त ही नहीं। इसी प्रकार जीवन भी निम्न-निम्न तत्त्वों से भरा हुआ है। जहाँ उससे बहुत जगह बलबल और कीचड़ है, वहाँ उसमें महासागर, पर्वत, दर्फ, वर्षा की नदियाँ और (कासकर जेल में !) तारों-भरी अद्भुत रातें हैं, कुटुम्ब और मित्रों का प्रेम है, एक ही उद्देश्य के लिए बान बरनेवाले साथियों का साथ है, संगीत है, पुष्पों के हैं और दिखारों का सागराण्य है। इन सब चीजों को देखकर हम कह सकते हैं कि—

हमारा भविष्य के प्रति भी कुछ कर्तव्य है, और शायद यह कर्तव्य उससे भी बड़ा है जो हमारा प्राचीन काल के प्रति है; क्योंकि जो बात हो चुकी, सो हो चुकी, उसे हम बदल नहीं सकते। भविष्य तो अब आयगा। मुमकिन है हम उसे थोड़ा बना सकें। अगर भूतकाल ने हमें सत्य के कुछ दर्शन कराये हैं तो भविष्य के गर्भ में भी उसके कुछ पहलू छिपे हुए हैं और वह हमें उनकी खोज का आमंत्रण देता है। मगर अक्सर गुजरे हुए जमाने को आनेवाले समय से ईर्ष्या होती है और वह अपने पंजे में हमें जकड़े रखना चाहता है। हमारा काम है कि हम उससे अपनेआपको छुड़ाकर भविष्य से मिलने और उसकी ओर बढ़ने की कोशिश करें।

कहते हैं कि इतिहास हमें अनेक पाठ पढ़ाता है। दूसरी कहावत यह है कि इतिहास बार-बार अपने-आपको नहीं दोहराता। ये दोनों कहावतें सच हैं, क्योंकि हम न तो पुरानी बातों की अन्धे होकर नक़ल करने से ही कुछ सीख सकते हैं और न यह उम्मीद रखकर कोई लाभ उठा सकते हैं कि इतिहास अपनेको दोहराया या जहाँ-का-तहाँ रहेगा। हम थोड़ा-बहुत सीख सकते हैं तो इसी तरह सीख सकते हैं कि हम भूतकाल के भीतर घुसकर देखें और जो शक्तियाँ उसमें काम कर रही थीं उनकी खोज करें। इतना सब कुछ करने पर भी हमें सीधा उत्तर नहीं मिलनेवाला है। कार्ल मार्क्स कहता है—“इतिहास तो उत्तर देने का एक ही तरीका जानता है, और वह है पुराने सवालों के जवाब में नये सवाल पेश कर देना।”

पुराना जमाना श्रद्धा का, अन्धविश्वास का, बिना पूछे-ताछे मान लेने का जमाना था। अगर कारीगरों, बनानेवालों और साधारणतः सभी लोगों में श्रद्धा न होती, तो क्या पिछली सदियों के ये अद्भुत मन्दिर, मस्जिद और गिरजे बन सकते थे? जिन पत्थरों को उन्होंने भक्ति-भाव से एक-दूसरे पर चुना या जिनके उन्होंने सुन्दर चित्रण किये, वे उस श्रद्धा के धोलते-चालते प्रमाण हैं। पुराने मन्दिरों के शिखर, मस्जिदों की नाजूक मीनारें, गोथिक ढंग के गिरजे एक ऐसी गहरी भक्ति-भावना का प्रमाण दे रहे हैं जिसे देखकर हम चकित रह जाते हैं और ऐसा मालूम होने लगता है मानों ये पत्थर और संगमरमर आकाश की तरफ मुँह करके प्रार्थना कर रहे हों। भले ही उनके जैसी श्रद्धा हममें न हो, पर इन्हें देखकर हमें रोमाञ्च होता है। लेकिन उस श्रद्धा के दिन गये, और उनके साथ ही पत्थर का वह मुँह-बोलता जादू भी चला गया। हजारों मन्दिर, मस्जिद और गिरजे बन रहे हैं, मगर उनमें वह भावना कहाँ है जो मध्ययुग के पूजास्थानों को सजीव करती थी? उनमें और हमारे युग के निशान व्यापारिक दपतरों में बहुत कम अन्तर है।

हमारा युग दूसरी ही तरह का है। यह तो शंका और तर्क का युग है। इसमें

“Where the mind is without fear and the head is held high;
Where knowledge is free;
Where the world has not been broken up into fragments by
narrow domestic walls;
Where words come out from the depth of truth;
Where tireless striving stretches its arms towards perfection;
Where the clear stream of reason has not lost its way into the
dreary desert sand of dead habit;
Where the mind is led forward by thee into ever-widening
thought and action—

Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake.”

“जहाँ मन निर्भय है और सिर ऊँचा उठा हुआ है;
जहाँ ज्ञान बन्धन-मुक्त है;
जहाँ संकुचित घरेलू दीवारों से दुनिया तुच्छ टुकड़ों में विभाजित नहीं है;
जहाँ शब्द सत्य की गहराई से आते हैं;
जहाँ परिपूर्णता के लिए निरन्तर चेष्टा अपनी भुजायें फैला रही है;
जहाँ विवेक का उज्ज्वल सोता निर्जीव प्रथा के गुच्छ मरस्यल में गूँसकर
नष्ट नहीं होगया है;
जहाँ तेरे द्वारा मन प्रतिक्षण विकसित होने हुए विचार और कार्य की ओर
जा रहा है;
हे मेरे पिता ! उस मुक्ति के स्वर्ग में मेरे देश को जाग्रत कर ।”

१. श्री. गुधीन्द्र ने इस गीत का अनुवाद यों किया है :—

स्वतंत्रता-स्वर्ग में पिता हे, जगे जगे देश यह हमारा !
असंक मन हो, उठा हुआ सिर,
स्वतंत्र हो पूर्ण ज्ञान जिममें
जहाँ घरों की न भित्तियाँ ये करें जगत् खण्ड-वण्ड न्याय
स्वतंत्रता-स्वर्ग में पिता हे, जगे जगे देश यह हमारा !
सदैव ही सत्य के तले में
जहाँ पिता, शब्द-शब्द निकले
एक बड़ा हाथ पूर्णता को जहाँ पश्चिम अजक हमारा
स्वतंत्रता-स्वर्ग में पिता हे, जगे जगे देश यह हमारा !
सिने भवक कर बुद्धि-धारा
न रुद्धियों के दुग्ध मर में
सिने-सिने विचार-रति में जगे जहाँ चित्त, पा रात्राण
स्वतंत्रता-स्वर्ग में पिता हे, जगे जगे देश यह हमारा !

“Lord, though I lived on earth, the child of earth,
Yet was I fathered by the starry sky.”

अर्थात्—“हे प्रभु, यद्यपि मैं पृथ्वी की सन्तति हूँ और पृथ्वी पर ही पैदा हूँ,
पर मुझे तारिका-जटित आकाश का वात्सल्य प्राप्त हुआ।”

विश्व के सौन्दर्य की तारीफ़ करना और विचार और कल्पना के जगत् में रहना आसान है। मगर इस तरह औरों के दुःखों से जी चुराना, उनका क्या हाल है इसकी परवा न करना, साहस या हमदर्दी की निशानी नहीं है। विचार की अच्छाई और सचाई इसीमें है कि उसके अनुसार अमल किया जाय। हमारे मित्र रोम्यां रोलां कहते हैं—“कार्य विचार का अन्त है। जिस विचार की दृष्टि कार्य की ओर नहीं होती वह, फँसा भी हो, निरर्थक है और धोखाधड़ी है। इसलिए हमें अगर विचार के सेवक बनना है तो कार्य के सेवक भी बनना ही होगा।”

अक्सर लोग कार्य से इसलिए कन्नी काटते हैं कि उन्हें नतीजे का डर होता है, क्योंकि कार्य का अर्थ है जोखिम और खतरा। खतरा दूर से ही भयानक दीखता है। नजदीक से देखने पर वह इतनी दूरी चीज नहीं है; ज्यादातर तो वह सुहावना साथी ही होता है और उससे जीवन का स्वाद और आनन्द बढ़ता है। कभी-कभी जीवन का साधारण क्रम बड़ा सुस्त होजाता है। हमें बहुत-सी चीजें योंही मिल जाती हैं और उनसे हमें कोई आनन्द नहीं मिलता, परन्तु जब उन मामूली चीजों के बिना हम थोड़े दिन रह लेते हैं तब हमें उनकी कितनी कद्र होजाती है ! बहुत लोग ऊँचे-ऊँचे पहाड़ों की चढ़ाई करते हैं और चढ़ाई का आनन्द लेने के लिए प्राण और शरीर को जोखिम में डालते हैं। जब वे किसी कठिनाई को पार कर लेते हैं, किसी खतरे को जीत लेते हैं, तब उन्हें कितनी खुशी होती है ! जिन खतरों से वे चारों ओर घिरे रहते हैं उनके कारण उनकी इन्द्रियाँ कितनी तेज होजाती हैं, और जो जीवन कच्चे घागे से लटकता रहता है उसका आनन्द कितना तीव्र होजाता है !

हम सबके सामने दो मार्ग हैं। हम जिसे चाहें पसन्द कर लें। एक तो नीची घाटियों में रहना, जहाँ धुन्ध और कोहरे से तंग होना पड़ता है परन्तु जहाँ शरीर की रक्षा ठीक-ठीक होती है। दूसरा ऊँचे पर्वतों पर चढ़ना, जोखिम और खतरे में पड़ना और साथियों को डालना, आकाश का शुद्ध वायु सेवन करना, दूर-दूर दृश्यों का मजा लूटना और उगते हुए सूर्य का स्वागत करना।

मैंने इस खत में कवियों और दूसरे लेखकों के कई उद्धरण दिये हैं। अन्त में एक और दे देता हूँ। यह गीताञ्जलि का है। यह रवीन्द्रनाथ ठाकुर की कविता या प्रार्थना है :

परिशिष्ट—१

विश्व-इतिहास का तिथि-क्रम

[१]

मानवी इतिहास के बहुत शुरु के जमाने की तिथियाँ कभी-कभी बिल्कुल अन्दाज-ही-अन्दाज होती हैं। कभी-कभी वे इतनी अनिश्चित होती हैं कि विशेषज्ञों में एक-दूसरे से हजार वर्षों का मतभेद होता है। मानव-संस्कृति के सबसे प्रारम्भिक जो चिन्ह मिलते हैं वे हमें ईस्वी सन् के ५००० वर्ष पूर्व यानी अबसे लगभग ७००० वर्ष पूर्व तक लेजाते हैं। खयाल किया जाता है कि मिस्र के इतिहास का आरम्भ उस समय हुआ था। यह प्रस्तर-युग का अन्त था। उस समय मिस्र कई छोटे राज्यों में बँटा हुआ था। प्राचीन वस्तु-विद्या के पण्डितों ने भी कँलिया अथवा एलम (मेसोपोटामिया) में एक ऐसी सभ्यता के भग्नावशेषों का पता लगाया है जो ईसा के पाँच हजार वर्ष पहले शुरू हुई थी। इसका राजनगर सूसा था। प्राचीन वस्तुओं के सम्बन्ध में ज्यादातर खोज मिस्र और मेसोपोटामिया में ही हुई हैं, क्योंकि ज्यादातर खुदाई भी वहीं हुई है। सम्भवतः इतनी ही पुरानी तिथि वाली खोज दूसरे देशों में भी की जायगी। प्राचीन वस्तुओं के दूसरे समूह का पता लगने से भी, जिनकी तिथि लगभग ३५०० वर्ष ईसा के पूर्व बताई जाती है, इस धारणा की पुष्टि होती है। ये खोजें हमें एशिया के आर-पार—मिस्र, कँलिया, पूर्वी प्रारस, भारत की सिन्धु घाटी, पश्चिमी तुर्किस्तान से चीन की ह्यांगहो या पीत नदी तक ले जाती हैं। इन सब स्थानों पर विकास की एकही अवस्था का पता चलता है। यह पालिश किये हुए पत्थरों के युग के अन्त की बात है, जब कि ताँबे का इस्तेमाल शुरू हो रहा था। इनमें कृषि है, धरेलू एवं पालतू चौपाये हैं, व्यापार है, एक ही तरह के औजार हैं, सोने-चाँदी के सुन्दर आभूषण हैं और कई तरह के समान चित्रों से चित्रित मिट्टी के रंगीन पात्र हैं। लेखन-कला या लिपि का आरम्भ हो चुका था। जान पड़ता है इस जमाने में, लगभग ५५०० वर्ष पहले, मिस्र ने उत्तर-भारत और चीन तक एक ही सभ्यता का प्रसार था। मिट्टी के एक-ले पात्रों के मिलने से इस सभ्यता को “मिट्टी के रंगीन वस्तुओं की सभ्यता” (Painted Pottery Civilization) कहते हैं। यह सभ्यता इस वक़्त भी इतनी उन्नत थी, इसकी संस्कृति और ललित कलायें इतनी विकसित हो चुकी थी, कि इनके पीछे संस्कृति की दाढ़ के हजारों वर्ष पहले ही पीत रूके होंगे। हिन्दुस्तान में यह सोहेनजोदारो का युग था जिसमें सुन्दर भवनों, मट्टियों और कला के विधान का दर्शन होने होता है। इन समय मिस्र में एगोहाज़ो यानी देव-

तो अपना काम खत्म हुआ और यह आखिरी खत भी । आखिरी खत ! हरगिज नहीं ! मैं तुम्हें और भी बहुत-से खत लिखूंगा । परन्तु यह सिलसिला यहीं समाप्त होता है और इसीलिए—

तमाम शुद्ध !

१३५२
१३५३

इटली, सिसली, सोर और फ्रांस के दक्षिणी भाग में हेलेनिक उपनिवेश खड़े होगये। होमर ने अपने महाकाव्य ईसा-पूर्व की ग्यारहवीं शताब्दी में लिखे थे।

इस बीच पूर्व में सभ्यता के प्राचीनतर केन्द्रों में बहुतेरी घटनायें घट गई थीं। मिस्र और कैलिडिया में साम्राज्यों का विकास भी हुआ और पतन भी होगया। भारत में उत्तर में आर्यों का प्रभुत्व स्थापित होचुका था और वे दक्षिण की ओर बढ़ रहे थे। जब वे यूनान में पहुँचे, उससे बहुत पहले वे भारत में आ चुके थे। यहाँ आने पर उन्होंने सभ्य और संस्कृत द्रविड़ों को इस देश में बसा हुआ पाया और उन्हें दक्षिण-भारत की तरफ़ खदेड़ दिया था। वेद आर्यों के आक्रमण के प्रारम्भिक दिनों में लिखे गये थे और वेदों के बहुत दिनों बाद महाकाव्य—रामायण आदि—लिखे गये थे। चीन संगठित हो रहा था और एक महान् राज्य विकसित हो रहा था। रेशम के कीड़े पालने और रेशम निकालने की कला निकल चुकी थी।

अब हमें अपने नक्शे पर आना चाहिए। लेकिन याद रखो कि सभ्यताओं और ऐतिहासिक युगों के विभिन्न नामों (जैसे मिनोयन, माईसीनियन, एजियन इत्यादि) को एक-दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र अथवा स्पष्टतः निश्चित युगों के रूप में ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये अस्पष्ट शब्द हैं जिनका उपयोग आजकल के प्राचीन वस्तु-विद्या के विशेषज्ञ और इतिहासकार विभिन्न सभ्यताओं और युगों को एक-दूसरे से अलग करने या एक-दूसरे की अलग पहचान के लिए करते हैं, पर ये सभ्यतायें और युग अक्सर एक-दूसरे की सीमा में मिल या प्रवेश कर जाते हैं। यह भी याद रखो कि चार्ट या नक्शे में तिथियों को समान अन्तर से यानी एक काल को समान ही जगह देना असम्भव है। ऐसी माप रखना बहुत अच्छी और ज्यादा सही चीज़ होगी, क्योंकि इससे इतिहास के बारे में ज्यादा सही धारणा बनाई जा सकेगी, पर ऐसा नक्शा बहुत ज्यादा लम्बा होजायगा, क्योंकि इतिहास की प्रारम्भिक अवस्थाओं में हमें हजारों वर्षों से काम पड़ेगा और प्रागैतिहासिक अथवा इतिहास के पहले के काल तो बहुत ज्यादा बड़े-बड़े हैं। इसलिए हमें एक ही माप का खयाल छोड़ देना पड़ेगा। कभी तो एक इञ्च हजार वर्षों या उससे भी ज्यादा समय के प्रति कर्त्तव्य-पालन करेगा और दूसरी जगह वही एक इंच सिर्फ़ दस वर्षों या उससे भी कम समय का काम देगा।

नोट—किसी तिथि के पूर्व 'ल०' का का मतलब यह है कि वह तिथि बिल्कुल निश्चित नहीं है, बल्कि लगभग है। यह लगभग का संक्षिप्त रूप है।

सम्राटों की मातृहती में अलग-अलग राज्य एक बड़े राज्य में मिल जाते हैं। इसी वक्त के फ़रीव फ़ैलिया में सुमेर और अक्कद नाम के दो शक्तिमान और ऊँची संस्कृतिवाले राज्यों का जन्म होता है। फ़ुरात (Euphrates) नदी के तटों पर 'उर' नाम का मशहूर शहर उठ खड़ा होता है, जिसे बाइबल में 'फ़ैलिया का उर' कहा गया है। इसी 'मिट्टी के रंगीन वर्तनों की सभ्यता' से मिस्री, मेसोपोटामियन या इराक़ी (इसमें फ़ारसी अथवा ईरानी सभ्यता भी शामिल है), भारतीय और चीनी नामक पूर्व की चार महान् सभ्यतायें निकलती हैं और अलग-अलग विकसित होती हैं। इस तरह हम निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुँचते हैं :—

तिथि (ईसा के पूर्व)	मिस्र	फ़ैलिया या एलम (मेसोपोटामिया)	भारत	चीन
	मिट्टी के रंगीन वर्तनों की सभ्यता			
ल० ३५०० वर्ष ल० ३३०० वर्ष	फरोहाओं की मातृहती में एक राज्य बन जाता है।	सुमेर और अक्कद नामक दो शक्ति- शाली राज्य। उर नगर	सिंधु की घाटी में मोहेन- जोदारो और हरप्पा (ईसा के ३३०० वर्ष पूर्व से २७ वर्ष पूर्व तक के ऊपर एक करके तीन नगर।)	हवांगहो या पीत नदी के तटों की वस्तिyaँ

यह संभव है कि पूर्व की 'मिट्टी के रंगीन वर्तनों की सभ्यता' के ही समकालिक उसी तरह की सभ्यता पूर्वी भूमध्यसागर में यूनानी टापुओं में और एशिया-माइनर के पश्चिमी किनारों पर रही हो। इस प्रारम्भिक भूमध्यसागरीय सभ्यता से २००० ईसापूर्व से १५०० वर्ष ईसापूर्व की नोसॉस लोगों की ऊँची मिनोयन सभ्यता निकली जो धीरे-धीरे नष्ट होगई और ग्रीक द्वीपों की माईसीनियन (Mycenaean) या एजियन (Aegean) सभ्यता में बदल गई, जिसका समय ईसा पूर्व १६०० से ११०० तक बताया जाता है। इसी समय के लगभग (ल० १३०० वर्ष ईसा पूर्व के बाद) प्राचीन पश्चिमी दुनिया के महान् व्यापारी सेमिटिक फोनिशियन प्रधानता प्राप्त करते हैं और भूमध्यसागर के तट पर सब जगह उनकी वस्तिyaँ बस जाती हैं। एशिया-माइनर में टायर नामक नगर इन वस्तियों में सबसे प्रधान बस्ती थी। इसी समय के लगभग आर्य लोग योरोप में फैले। वे यही आर्य यूनानी, हेलेनीज़, थे जिन्होंने ईसा के पहले की बारहवीं शताब्दी में ट्राय का घेरा डाला था। धीरे-धीरे हेलेनिक सभ्यता का विकास हुआ और एशिया-माइनर, दक्षिण-

पश्चिमी एशिया कैलिडिया-फिलिस्तीन-फारस	भारत	चीन, कोरिया और जापान
...	उत्तर-पश्चिम में सिंधु की घाटी की सभ्यता ।	२३५६ याओ सम्राट ।
२१०० हम्मूरब्बी द्वारा बेबिलोनियन साम्राज्य की स्थापना । बेबिलन नगर ।	भारत के अधिकांश भागों में द्रविड ।	२२०५ हसिया वंश का आरंभ (१७६५ तक) रेशम की उत्पत्ति ।
...	उत्तर-पश्चिम से आर्यों का निरन्तर प्रवाह आता है और उत्तरमें बसता जाता है	
१९२५ हिट्टाइट लोग बेबिलोनियन साम्राज्य को नष्ट कर देते हैं ।	वैदिक काल ।	१७६५ शांग अथवा यीन वंश (११२२ तक)
...	महाकाव्य काल—रामायण और महाभारत (परन्तु ये पुस्तकें लिखी बहुत बाद में गईं)	
...	दक्षिण भारत का आर्यकरण	
असीरियनों का उत्थान— सम्राट तिगलथ—पिले- सर ।		

तिथि या काल	भूमध्यसागर-तट यूनान-फार्येज-रोम	मिल
(ई० पू०) २८००		मेम्फाइट साम्राज्य २८००- २३०० चियोपों-द्वारा महान् पिरामिडों का नि- र्माण । गिजेह का महान् स्फिक
२३००	भूमध्यसागर की प्रारम्भिक सभ्यता	... मिल पर हाइक्सो-आक्र- मण । २१६०से १६६० तक प्रथम थीवन-साम्राज्य
२१००		रैमेसेस द्वितीय द्वारा कर्नाक और लक्सर मन्दिरों का निर्माण
२०००	नोसॉस की मिनोयन सभ्यता (ल० २०००-१५००)	...
१७००		
	मार्ईसीनियन सभ्यता (ल० १६००- ११००)	१५८० द्वितीय थीवन साम्रा- ज्य (११०० तक)
१५००		
१३००	एशिया-माइनर का टायर नगर । भूमध्य- सागर की फोनीशियन वस्तियाँ	

पश्चिमी एशिया कैलिडया-फ़िलिस्तीन-फ़ारस	भारत	चीन, कोरिया और जापान
<p>...</p> <p>७२८ असीरियनों द्वारा बैबिलन की विजय और असीरियन साम्राज्य की स्थापना। राजधानी निनीवे।</p> <p>ल० ७०० (अथवा पहले) जरथुस्त या जोरोस्टर</p> <p>६१२ आर्य मीड निनीवे पर क़ब्ज़ा कर लेते और एवीसीनियन साम्राज्य को नष्ट कर देते हैं।</p>	<p>प्राचीन भारत के ग्राम्य प्रजातंत्र।</p> <p>महान् वैयाकरण पाणिनि</p>	<p>११२२ चोन वंश (२५५ तक)</p> <p>११२२ कोरिया : कित्से द्वारा चोसेन राज्य की स्थापना (जो १९३ई० पूर्व तक चलता है)</p> <p>६६० जापान : छोटा यामातो राज्य। प्रथम काल्पनिक सम्राट जिम्मू टिन्नू।</p>

सभ्यता का आरम्भ लगभग इसी समय—ईसा-पूर्व की छठी सदी में—हुआ]

तिथि या काल	भूमध्यसागर-तट यूनान-कार्थेज-रोम	मिल
(ई० पू०)	योरप में आर्यों का फैल जाना हेलेनिक यूनानियों द्वारा द्राप का घेरा ११४८	...
११००	ल० १००० होमर ईलियड और ओडेसी महाकाव्यों की रचना करता है । एशिया-माइनर, दक्षिण-इटली, सिसली और दक्षिण-फ्रांस में हेलेनिक उपनिवेश	
८००	८०० फोनीशियन लोग उत्तरी अफ्रीका में कार्थेज की स्थापना करते हैं । यूनानी नगर-राज्य : एथेंस, स्पार्टा, थीब्स, कोरिन्थ इत्यादि । ७७६ यूनान में ओलिम्पिक खेलों की स्थापना । ७५३ रोम का निर्माण हुआ ।	
७००		
६००	ल० ६०० ल्यूडोस में महान् कवयित्री सैफ्रो	

[सम्भवतः मध्य-अमेरिका के मैक्सिको की ओर पेरू की प्राचीन अमेरिकन

1000

तिथि या काल	यूनान, रोम और कार्थेज	मिस्र
(ई० पू०)		
६००	कार्थेज महान् व्यापारिक केन्द्र—भूमध्यसागर में प्रधान शक्ति	
	समोस में पाइथागोरस ल० ५७०—५०४	५५२ फारस का सम्राट् कैंबिसेस मिस्र विजय कर लेता है ।
५००	रोमन प्रजातंत्र का आरम्भ ल० ५०० ४९० मैराथान का युद्ध—यूनानी फारसियों को खदेड़ देते हैं ४८० बर्मापोली और सेलेमिस	...
४००	यूनान का सुवर्ण-युग : सुकरात, यूरीफाइड्स, मेरोसिलस, एस्किलस, सोफोक्लस, प्लेटो, पिण्डार, अरिस्टोफेनिस फीडियास । ४०४ स्पार्टा द्वारा एथेंस का विनाश । ३५९ मेसीडोनिया का बादशाह फिलिप ३३६ सिकन्दर महान्	... ३३२ मिस्र में सिकन्दर मिस्र पर यूनानी टालमी का राज्य

पश्चिमी एशिया फारस	भारत (और मध्य एशिया)	तिथि या काल
		(ई० पू०)
	३०३ सेल्यूकस की पराजय । पाट- लिपुत्र का महान् राजनगर । तक्ष- शिला—उज्जैन—मथुरा ।	३००
२५० ईरानी पार्थियन सेल्युसिदों से अपनेको स्वतंत्र कर लेते और आर्सासिद साम्राज्य की स्थापना करते हैं (जो सन् २२४ ई० तक रहा है) ।	२६८ अशोक (२२६ तक) का महान् साम्राज्य जिसमें प्रायः सम्पूर्ण भारत और मध्य-एशिया का कुछ भाग शामिल था । बौद्धधर्म के प्रचारक विदेशों में भेजे गये ।	
	२२० दक्षिण में आंध्रशक्ति का उत्थान । महान् दक्षिणी साम्राज्य जो ई० सन् की तीसरी सदी तक चलता है । विलकुल दक्षिण में पल्लव ।	२००
	उत्तर-पश्चिम से इण्डो-सीथियन आते हैं और पंजाब, राजपूताना तथा काठियावाड़ में बस जाते हैं । ल० १५० पतंजलि	
एशिया-मइनर इत्यादि में रोमनों की विजय । ५३ कंरे में पार्थियन लोग रोमनों को हरा देते हैं ।	उत्तर-भारत और मध्य-एशिया में— वनारस से यारकंद तक—कुशन- साम्राज्य । बौद्ध तुर्की राजवंश राजधानी पेशावर (पुरुषपुर)— ईसवी सन् की तीसरी सदी तक चलता है । दक्षिण के आंध्र साम्रा- ज्य का समकालिक । भारत, यूनानी-रोमन दुनिया और मध्य-एशिया में घनिष्ट सम्पर्क और आमदरपत्त ।	१००

तिथि या काल	यूनान, रोम और कार्थेज	युद्ध
(ई० पू०)		
३००	२६४ (से २४१ तक) प्रथम प्यूनिक युद्ध । कार्थेज के विरुद्ध रोम ।	ग्रीस का एक अलेग्जेण्ड्रिया
२००	२१९ (से २०२ तक) द्वितीय प्यूनिक युद्ध । हर्नीयाल । रोमन साम्राज्य का स्पेन, यूनान, एशिया-माइनर में विस्तार ।	
१००	१४९ तृतीय प्यूनिक युद्ध । कार्थेज नष्ट कर दिया जाता है ।	
	९१ इटली में गृह-युद्ध ।	
	७३ रोम में स्पार्टेकस के नेतृत्व में गुलामों का विद्रोह । गॉल-विजय । जूलियस सीज़र द्वारा ब्रिटेन और पाम्पी द्वारा पूर्वी प्रदेशों की विजय ।	
	४८ सीज़र फारसेलू स्थान पर पाम्पी को हरा देता है ।	पाम्पी विलयो- ग्न ।
	४४ रोम में सीज़र मारा गया ।	रोम साम्राज्य बढ़ जाता है ।

भारत	बृहत्तर भारत; मलाया इत्यादि	चीन	जापान और कोरिया
<p>बौद्धधर्म का महान् कलह— महायान और हीनयान</p> <p>मलाया और पूर्वी द्वीपों में उपनिवेशों की स्थापना के लिए पल्लवों की संगठित धात्रायें । समुद्री व्यापार का विकास ।</p>	<p>महत्वपूर्ण भार- तीय (पल्लव) उपनिवेशों की विशेषतः कम्बो- डिया में स्थापना । सुमात्रा में श्री- विजय ।</p> <p>दक्षिण मलाया मध्य जावा पूर्वी बोर्नियो</p> <p>.....</p>	<p>चीन में बौद्धधर्म का प्रवेश । उत्तर- काल के हन् सम्राट् तातारियों को पश्चिम में भगा देते हैं (और ये बाद में हूण की शक्ल में योरप और भारत में जाते हैं) ।</p> <p>२२१ हन् राज- वंश का पतन । तीन राज्य ।</p>	

तिथि या काल	रोमन साम्राज्य	पश्चिमी एशिया
(ई० पू०) १००	२७ ई० पूर्व। आपटेवियन सीज़र सरदार या प्रिमेप् बन गया है। प्रिसेप् और सम्राट्। रोमन साम्राज्य का आरम्भ।	
ईसा-पूर्व ईसा के पश्चात्	१४-१८० सम्राट् टाइबेरियस, फ़लीगुला, क्लाडियस, नीरो, वेस्पेशियन, टोटस, डोमिशियन, नर्वा, ट्रेजन, हैड्रियन, एण्टोनियस, मार्कस ऑरेलियस।	क्रिस्तीन में नज़रेय स्थान पर ईसा की पैदाइश
ई०-पू० १००		
२००	[माया और अज़टेक सभ्यतायें ईसा की दूसरी सदी में अमेरिका में विकसित होती हैं। मजदूती के साथ संगठित राज्य कायम होते हैं। अनेक नगर-कला-शिल्प इत्यादि।]	
		२२४ फ़ारस में सासानी साम्राज्य का आरम्भ। अपनी प्रवृत्ति में पूर्णतः राष्ट्रीय ईरानी और ज़रयुस्ती (६५२ तक चलता है।) २७२ पालमीरा के अरब रेगिस्तानी राज्य का अन्त। रानी ज़ेनोबिया।

भारत	बृहत्तर भारत; मलाया इत्यादि	चीन	जापान और कोरिया
<p>३२० उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य का आरम्भ । राष्ट्रीय पुनरुत्थान । राज-धानी अयोध्या । संस्कृत का सुवर्ण काल ।</p> <p>३२० चन्द्रगुप्त । ३३५ समुद्रगुप्त । दूर-दूर तक विजय । ३८० विक्रमादित्य । कवि कालिदास</p> <p>चीनी यात्री फ़ाहियान का भारत में आगमन । ल० ४५० भारत में हूणों का आक्रमण ।</p> <p>४९५ हूण तोरमान उत्तरी भारत पर क़ब्ज़ा करलेता है</p>			<p>यामातो (जापान) ३५० के लगभग फैलता है ।</p>
<p>हूण मिहिरगुल ५१०-५२८ ५२५ चीन में आबाद होने के लिए भारतीय बौद्धधर्म के प्रधान धर्माध्यक्ष बोधि-धर्म का भारत से प्रस्थान ।</p>	<p>हिन्दीचीन में हिंदू राज्य ।</p>	<p>बोधिधर्म कैप्टन पहुँचते हैं ।</p>	

तिथि या काल	रोमन साम्राज्य	पश्चिमी एशिया
(ई० प०) ३००	<p>३०६ महान् सम्राट् कांस्टेण्टाइन राजधानी बिजेंटियम ले जाई गई, जिसका नाम कुस्तुन्तुनिया हो जाता है।</p> <p>ईसाई धर्म साम्राज्य का राजधर्म बन जाता है। साम्राज्य पश्चिमी और पूर्वी दो भागों में बँट जाता है।</p>	
४००	<p>ल० ४०० रोम पर बर्बरों के हमले।</p> <p>४१० एलेरिक के नेतृत्व में गॉथ लोग रोम पर कब्जा कर लेते और उसे तबाह करते हैं।</p> <p>४५०ल एटिला के नेतृत्व में हूण गाल और इटली को पामाल करते हैं और ४५७ ई० में फ्रांस में शालों के युद्ध में अन्तिम रूप में पराजित होते हैं।</p> <p>४५५ जेनसेरिक के नेतृत्व में वण्डाल लोग रोम को तबाह करते हैं।</p> <p>४७६ पश्चिमी साम्राज्य की हस्ती खतम हो जाती है। गॉथ ओडोका इटली का राजा। अन्य गॉथ वादशाह।</p> <p>४८१ फ्रांस का क्लोविस।</p>	
५५०	<p>बर्बरों और हूणों के हमलों से बहुत कमजोर हो जाने पर भी पूर्वी रोमन साम्राज्य कायम रहता है। उसकी राजधानी कुस्तुन्तुनिया है। जस्टीनियन के समय में, जो ५२७ से ५६५ तक राज्य करता है, वह फिर सबल होता है।</p>	

तिथि या काल	पश्चिमी योरप	पूर्वी योरप	पश्चिमी एशिया
ई.सन् ५५०		विजेण्टाइन (कुस्तुन- तुनिया) साम्रा- ज्य और ससानी (फारसी) साम्रा- ज्य के बीच अक्सर लड़ाइयां जिनसे दोनों कमजोर होजाते हैं।	५७० मक्का में मुहम्मद का जन्म (मृत्यु ६३२); खुसरो द्वितीय के राज्य में ससानी साम्राज्य मिला, सीरिया, एशिया माइनर, फारस तक फैल जाता है। ६१९
६००		अरबों द्वारा विजे- ण्टाइन साम्राज्य की पराजय। पर वह अपने को सुरक्षित रखता है।	६२२ हिजरत। मुहम्मद साहब की मदीना यात्रा ६३२ अबूबकर खलीफा। ६३४ उमर खलीफा।
७००			६३२—६७० अरब लोग विजे- ण्टाइन साम्राज्य को हराते और फारस, मिला, उत्तरी अफ्रीका और मध्य एशिया के कुछ भागों को विजय कर लेते हैं। राजधानी दमिश्क। उम्मैया खलीफे (अरबों की विजय से ससानी साम्राज्य का अन्त)।
	७११ उत्तरी अफ- रीका से अरबों की स्पेनविजय। फ्रान्स पर आक्रमण		

तिथि या काल	पश्चिमी योरोप	पूर्वी योरोप	पश्चिमी एशिया
ई.सन्	<p>७३२ फ्रांस में दूनों का युद्ध । चार्ल्स मार्टल अरबों को हरा देता और अरब हमले को रोक देता है ।</p> <p>७५० स्पेन में फार-डोवा का अरब राज्य । प्रसिद्ध नगर और विश्वविद्यालय</p>		
८००	८०० पश्चिमी पवित्र रोमन साम्राज्य आरम्भ होता है और शार्लमेन उसका सम्राट बनता है ।	पूर्वी रोमन (बिजेंटाइन) साम्राज्य चारों तरफ से कठिनाइयों में पड़ जाने के बावजूद सिकुड़े रूप में कायम रहता है ।	<p>७५० उर्मिया खलीफा अविकार-च्युत कर दिये गये । अब्बासी खलीफों का आरम्भ । स्पेन स्वतंत्र हो जाता है । वहाँ का अरब-राज्य उर्मियों के कब्जे में । अरब साम्राज्य छोटा पर संगठित होजाता है । राजधानी बगदाद चली जाती है ।</p> <p>७८६ (से ८०९ तक) खलीफा हारुनल रशीद । उज्ज्वल शासन । चीन और शार्लमेन के पास राजदूतों का भेजा जाना ।</p> <p>८५० अब्बासी खलीफाओं और अरब साम्राज्य का ह्रास । स्वतंत्र मुस्लिम राज्यों का उदय ।</p>
९००	<p>९६२ जर्मनी का महान् ओटो पवित्र रोमन साम्राज्य का सम्राट बन जाता है</p> <p>९८७ ह्यूकैपेट फ्रान्स का राजा बन जाता है ।</p>		<p>पश्चिमी एशिया में सेलजूक तुर्क</p> <p>९६९ मिस्र स्वतंत्र होजाता है ।</p> <p>अलग फातिमाई खिलाफत पश्चिम एशिया पर सेलजूक तुर्कों का प्रभुत्व</p>

तिथि या लाल	पश्चिमी योरोप (और अमेरिका)	पूर्वी योरोप
ईस्वी सन् १०००	<p>[मध्य अमेरिका: महान् नगर उदामल का उदय : १००० तीन मध्य अमेरिकन राज्यों के संघ- मायापान संघ—का निर्माण]</p> <p>१०६६ नार्मण्डी के विलियम द्वारा इंग्लैण्ड पर विजय ।</p> <p>१०७३ हिल्डेब्रेण्ड ग्रेगोरी सप्तम के नाम से पोप बनता है ।</p> <p>१०९६ प्रथम क्रूसेड । (जिहाद) बहुत ज्यादा आदमी मारे गये । बारहवीं-बारहवीं सदियों में पश्चिमी योरोप में माथिक शिल्प ।</p>	<p>ईसाई जिहादी (क्रूसेडर्स) पूर्वी योरोप को लूटते और वहाँ अस-भ्याचरण करते हैं ।</p>
११००	<p>११४७ दूसरा क्रूसेड ।</p> <p>११४७ कार्डोवा के मुसलमान राज्य से पुर्तगाल जीत लिया जाता और वहाँ ईसाई राज्य कायम किया जाता है ।</p> <p>११५२ होहेनस्टाफन वंश का फ्रेडरिक बार्बरोसा । पवित्र रोम साम्राज्य का सम्राट</p> <p>११८९ तीसरा क्रूसेड । इंग्लैण्ड का शेरविल रिचर्ड प्रथम [मध्य अमेरिका: ल० ११९० मायापान का विनाश]</p>	<p>.....</p>

तिथि या काल	पश्चिमी योरोप (और अमेरिका)	पूर्वी योरोप
ईसवी सन् १२००	<p>१२०२ चौथे क्रूसेड द्वारा पूर्वी (विजेण्डाइन) साम्राज्य पर हमला</p> <p>१२१२ लड़कों का क्रूसेड</p> <p>१२१५ इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा मंगनाचार्ज पर हस्ताक्षर।</p> <p>१२२१ पांचवां क्रूसेड (जिहाद)।</p> <p>१२२८ होहेनस्टाफन वंश का फ्रेडरिक द्वितीय, पवित्र रोमन साम्राज्य का सम्राट, (१२१२-१२५०) छठे क्रूसेड का नेतृत्व करता है यद्यपि पोप उसे समाज से बहिष्कृत कर देता है।</p> <p>१२३३ स्पेनिश 'इनक्वीजिशन' की स्थापना</p>	<p>१२०४ क्रूसेडवाले कुस्तु-नुनिया पर कब्जा कर लेते हैं और एक लैटिन सम्राट खड़ा किया जाता है (१२६१ तक)।</p> <p>चंगेज के नेतृत्वमें मंगोल दक्षिण रूस पर हमला करते हैं।</p>
१२५०	<p>१२५० फ्रेडरिक द्वितीय की मृत्यु। होहेनस्टाफन वंश का अन्त।</p> <p>१२५० स्पेन के कास्टीला राज्य का अन्त। दक्षिण स्पेन में ग्रेनाडा नामक छोटे अरब राज्य का आरंभ।</p> <p>१२६५ दांते का जन्म।</p> <p>१२७३ हैप्सबर्ग का रुडोल्फ पवित्र रोमन साम्राज्य का सम्राट चुना जाता है।</p> <p>१३ वीं-१४ वीं सदियों में यूरोपियन नगरों का विकास : वेनिस, जिनोआ, फ्लोरेंस, वोलोन, पीसा, मिलन, नेपल्स, पेरिस, एण्टवर्प, हैम्बर्ग, फ्रैंकफुर्ट, कोलोन, म्यूनिच आदि प्रजातंत्र।</p>	<p>१२४० रूस, पोलैंड पर मंगोलों का हमला। रूस मंगोलों को खिराज देता है।</p> <p>१२४१ साइलेशिया के लिगनिज में मंगोलों की विजय।</p>
१३००		<p>१२६१ यूनानी लैटिनों से कुस्तुनुनिया फिर छीन लेते हैं।</p> <p>रूस के अधिकांश हिस्सों में सुनहरे कबीले के मंगोलों की स्थापना</p>

तिथि या काल	पश्चिमी योरोप (और अमेरिका)	पूर्वी योरोप
ई० सन् १३००	<p>[मध्य अमेरिका और मैक्सिको । ल० १३२५ अज़टेक लोग माया देश को जीत लेते हैं और 'टेनोच्त्तेटन' नामक महानगरी बसाते हैं]</p>	
१३५०	<p>ल० १३४८ योरोप, उत्तरी अफ़्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों में महाप्लेग—'काली मौत' । इन देशों में आबादी का भयंकर विनाश ।</p>	<p>दक्षिण रूस में महाप्लेग ।</p>
१४००	<p>१३७८ पश्चिमी ईसाई धर्म में महाविभेद । दो पौप—एक रोम में, दूसरा फ्रांस के एविग्नन में । १४१७ में समझौते से क्षगड़ा समाप्त होता है ।</p>	<p>१३५३ उस्मानी तुर्क योरोप में घुस जाते, बालकन विजय कर लेते और एड्रियानोपुल को राजधानी बनाते हैं ।</p> <p>फुस्तुनुनिया में बिज़ेण्टाइन साम्राज्य अब भी क़ायम रहता है ।</p>



तिथि या काल	पश्चिमी योरोप (और अमेरिका)	पूर्वी योरोप
ई० सन् १४५०	<p>१४३० सन में अंग्रेजों द्वारा जोन ऑफ आर्क का जलाया जाना ।</p>	
१४५०	<p>१४७३ कोपरनिकस की पंदाइश ।</p> <p>१४८६ डायज गुडहोप के अंतरीप के गिर्द घूमकर जाता है ।</p> <p>१४९२ ग्रेनाडा के अरब राज्य का अंत । मूर (मुसलमान) स्पेन के बाहर खदेड़ दिये जाते हैं ।</p> <p>१४९२ कोलम्बस अटलाण्टिक पार करके अमेरिका पहुँचता है ।</p> <p>१४९८ गुडहोप के अंतरीप होता हुआ वास्को डि गामा भारत पहुँचता है । इटली में 'रिनेसाँ' (पुनर्जागरण) का आरंभ : ल्यूनार्डो दाविंची, माइकेल एंजेलो, राफेल ।</p>	<p>१४५३ उस्मानी तुर्क क्रिस्तु-न्तुनिया पर कब्जा करलेते हैं । पूर्वी रोमन (बिजेंटाइन) साम्राज्य का अन्त ।</p> <p>दक्षिण-पूर्व योरोप में उस्मानी साम्राज्य का प्रसार ।</p> <p>...</p>
१५३०	<p>१५१३ बलबोआ प्रशांत सागर में पहुँचता है ।</p> <p>१५१९ मैगेलन दुनिया की परिक्रमा करता है</p> <p>१५१९ कोर्टे मैक्सिको के अजटेकों की विजय कर लेता है ।</p> <p>१५३० पेरू के 'इनका' पर पिजारो की विजय । स्पेनी अमेरिकन साम्राज्य का उदय ।</p> <p>१५३० हैप्सबर्ग चार्ल्स पंचम : पवित्र रोमन साम्राज्य का सम्राट; स्पेन, निदरलैण्ड, अमेरिकन राज्य इत्यादि का राजा ।</p>	<p>१५२० उस्मानी साम्राज्य का सुलतान सुलेमान । उस्मानी साम्राज्य फैलता है और हंगरी एवं बालकन उसमें आजाते हैं ।</p>

तिथि या शताब्दी	उत्तर और दक्षिण अमेरिका	पश्चिमी योरोप	पूर्वी योरोप
ई० सन् १५२०		मार्टिन लूथर (मृत्यु १५४६)। उत्तर-पश्चिम योरोप में रिफॉर्मेशन और प्रोटेस्टेण्ट सम्प्रदाय का आरम्भ।	
१५५०	१५७७ फ्रांसिस ड्रेक जहाजी विश्वभ्रमण आरम्भ करता है।	१५५८ (से १६०३ तक) इंग्लैण्ड में एलिजाबेथ का राज्य। १५६४ शेपतपीयर का जन्म। १५६७ स्पेन के खिलाफ निदरलैण्ड्स की बग़ावत।	... ल १५८१ रूसी डाकू यरमक अपने क- ज्जाक सिपाहियों के साथ यूरल पार करता और पूर्व की ओर बढ़ता है। ...
१६००		१६०० ब्रिटिश ईस्ट-इंडिया कम्पनी की स्थापना। १६०२ डच ईस्ट-इण्डिया कम्पनी की स्थापना।	...
	१६२० 'मेपलावर' इंग्लैण्ड से उत्तरी अमेरिका को प्यू- रिटन (फट्टर ईसाई) लोगों को बसने के लिए लाता है।		बालकन, हंगरी आदि पर उस्मानी साम्राज्य। १६३६ रूसी पूर्व की ओर बढ़ते हैं और प्रशान्त सागर तक पहुँच जाते हैं।

तिथि या काल	उत्तर और दक्षिण अमेरिका	पश्चिमी योरोप	पूर्वी योरोप
६० सन्		१६४२ फ्रांस का 'महान् वाद- शाह' चौदहवां लुई अपने ७२ वर्ष लम्बे राज्यकाल का आरम्भ करता है । १६४८ वेस्टफेलिया की संधि । हालैंड और स्वीडनलैंड स्वतन्त्र राज्य के रूप में स्वीकृत कर लिये जाते हैं । १६४९ इंग्लैंड में गृहयुद्ध । वादशाह पर पार्लमेण्ट की विजय । चार्ल्स प्रथम को फांसी । अंग्रेजी प्रजातन्त्र १६६० तक । ओलिवर क्रामवेल ।	१६८३ वियेना के फाटकों पर उस्मानी तुकें रोक लिये जाते हैं । १६८९ रूस में महान् पीटर १६८९ से १७२५ तक राज्य करता है । चीन से सन्धि । चीन को राजदूतों का भेजा जाना । पीटर रूसी स्त्रियों का परदा छुड़वा देता है ।
१६५०		१६८८ ब्रिटिश क्रान्ति ...	
१७००	उत्तरी अमेरिका के पूर्वी समुद्र-तट पर यूरोपियन वस्तियों का बढ़ना । ब्राजील के अतिरिक्त सारे दक्षिण-अमेरिका में स्पेनी साम्राज्य । ब्राजील में पोर्चुगीजों का राज्य ।		१७३० रूसी-तुर्की युद्ध (सारी अठार- हवीं-उन्नीसवीं सदी भर होनेवाली लड़ा- इयों में से एक)
१७३०			

निधि या
काल

उत्तर और दक्षिण अमेरिका

पश्चिमी योरोप

६० सन्
१७३०

यूरोपियन देशों द्वारा सारी अठारहवीं सदी भर अफ्रीकन गुलामों का व्यापार होता रहा। अठारहवीं सदी के अंत में यह व्यापार पूरे जोर पर था। लिवरपूल और न्यूयार्क इस व्यापार के केन्द्र थे।

१७५०

१७६३ फ्रांस इंग्लैण्ड को कनाडा दे देता है।

१७७५ उत्तरी अमेरिकन उप-निवेशों का इंग्लैण्ड से युद्ध।

१७७६ अमेरिकन क्रांति। स्वतंत्रता की घोषणा।

जॉर्ज वॉशिंगटन।

१८००

दक्षिण अमेरिका में क्रांतियाँ। स्वतंत्र प्रजातंत्रों की स्थापना। साइमन बोलिवर।

१७४० प्रशा के फ्रेडरिक महान् के राज्य-काल का आरम्भ। वाल्टेयर (१६९४-१७७८)

गटे (१७४९-१८३२)।

१७५६-१७६३ सप्तवर्षीय युद्ध—प्रभुत्व के लिए अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच होनेवाले विश्वव्यापी संघर्ष में अंग्रेजों की विजय।

बीथोवेन, महान् संगीतकार (१७७०-१८२७)

१७८९ पेरिस में वैस्तील पर धावा। फ्रेंच राज्यक्रान्ति का आरम्भ।

१७९२ फ्रांस प्रजातंत्र बन जाता है।

१७९९ नेपोलियन बोनापार्ट। प्रथम कौंसल।

१८०४ नेपोलियन सम्राट्।

१८०६ 'पवित्र रोमन साम्राज्य' का बाकायदा अन्त।

१८१५ वाटरलू का युद्ध। वियेना की संधि।

तिथि या काल	उत्तर और दक्षिण अमेरिका	पश्चिमी योरोप
६० सन्	स्पेनी और पुर्तगाली अमेरिकन साम्राज्यों का अन्त ।	इंग्लैण्ड में औद्योगिक क्रान्ति (अठारहवीं सदी के अन्त से आगे) ।
१८५०	संयुक्तराष्ट्र अमेरिका पश्चिम की तरफ फैलता है और कैली- फोर्निया लेलेता है ।	१८२५ पहली रेलवे (इंग्लैण्ड में) । १८३० योरोप में क्रान्तियाँ । लुई फिलिप फ्रांस का बादशाह होजाता है । बेल- जियम स्वतंत्र होजाता है । १८३२ ब्रिटिश रिफार्म बिल । कार्लोमाक्स (१८१८-१८८३) । १८४८ योरोप में क्रान्ति-वर्ष । फ्रांस में प्रजातंत्र की स्थापना । चार्ल्स डार्विन (१८०९-१८८२) १८५२ द्वितीय फ्रेंच प्रजातंत्र का अन्त । फ्रांसीसियों का सम्राट् नेपोलियन तृतीय ।

विधि या कार्य	उत्तर और दक्षिण अमेरिका	पश्चिमी योरोप	पूर्वी योरोप
१८६१-१८६०	१८६१-६५ अमेरिकन गृह-युद्ध, हर्षाशियों का उत्थार । राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ।	१८६१ इटली संघुन और मिलाव हो जाना है । मैक्सि- मेरो-यास्को-कावूर ।	
	सारी उत्तरीयों सारी भर गाम तोर में उत्तरी अमेरिका और उत्तर-पश्चिमी योरोप में तथा थोड़े-बहुन दूसरी जगहों में विज्ञान, उद्योग तथा कृषिक आयात- निर्वात की उत्थान । प्रजासत्तागद्, पूंजीवाद, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद का विकास ।		बाल्कन में राष्ट्रीय- ता । तुर्की की अधीन जातियां धीरे-धीरे अपनेको स्वतंत्र करती हैं ।
		१८७०-१८७१ फ्रांस-प्रशा युद्ध—फ्रांस की हार । घर्माई में जर्मन साम्राज्य की घोषणा । बिस्मार्क । फ्रांस प्रजातंत्र बनता है । पेरिस की अल्पजीवी पंचायत ।	१८७६ मुल्तान तुर्की को विधान देता और फिर उसे स्थगित कर देता है ।
		१८७७ रूस-तुर्की युद्ध ।	१८७७ रूस-तुर्की युद्ध ।
		१८७८ रूस-तुर्की युद्ध के बाद बालिन की सन्धि । विशेषतः उत्तर-पश्चिमी योरोप में मजदूर-आन्दोलन की वृद्धि । मजदूर-संघ— अन्तराष्ट्रीय संघ-समाज- वाद । कार्ल मार्क्स ।	१८७८ बल्गेरिया, सर्बिया, रूमानिया और माण्डेनिप्रो तुर्की शासन से स्व- तंत्रता प्राप्त कर लेते हैं ।
	१८९८ स्पेनी-अमेरि- कन युद्ध । संयुक्त- राष्ट्र फिलिपाइन पर कब्जा कर लेता है । क्यूबा स्वतंत्र हो जाता है ।	१९वीं सदी के उत्तरार्द्ध में अमेरिका पर कब्जे के लिए पाश्चात्य शक्तियों की भाग-दौड़ ।	१९०५ जापान द्वारा रूस की हार के कारण रूस में अस- फल क्रांति होती है । ड्यूमा की स्थापना ।
१९००		१८९९-१९०२ दक्षिण अफ्रि- का में अंग्रेज और बोअ- रों का युद्ध ।	१९०८ तुर्की-क्रान्ति । १८७६ के विधान की पुनः स्थापना । ऐक्य और उन्नति की समिति ।



दिनांक या काल	उत्तर और दक्षिणी अमेरिका	पश्चिमी योरोप	पूर्वी योरोप
ई० सन्	१९१७ संयुक्तराष्ट्र महायुद्ध में शामिल होता है।	१९१४-१९१८ महायुद्ध।	१९११ ट्रिपोली के सम्बन्ध में तुर्की से इटली का युद्ध।
	१९१९-१९२९ संयुक्त राष्ट्र में महान् वैभव के दश वर्ष।	१९१८ जर्मनी, आस्ट्रिया आदि में क्रान्तियाँ। राजवंशों का अन्त। प्रजातंत्रों की स्थापना।	१९१२ बालकन युद्ध। तुर्की प्रायः योरोप से सदैव दूरी दिया जाता है।
	१९२९ अर्थ-संकट या मंदी।	१९१९ बर्साई की गुलह। योरोप में अनेक नये राष्ट्र। हजाने-शासनादेश-राष्ट्रसंघ। मजदूरों की हलचलें, हड़तालें, आर्थिक कठिनाइयाँ—मुद्रा का पतन—अनेक अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेसें।	१९१४-१९१८ महायुद्ध
	१९३० दक्षिण अमेरिका में अजॅण्टाइन, ब्राजील, चाइल इत्यादि में क्रान्तियाँ। सरकारों का दिवाला।	१९२०-२२ एंग्लो-आयरिश युद्ध। शिनफीन 'आयरिश फ्री स्टेट' की स्थापना।	१ ९१७ दो रूसी क्रान्तियाँ। बोल्शेविक राज्य पर कब्जा कर लेते हैं। गृह-युद्ध। रूस और साइबेरिया में हस्तक्षेप की लड़ाइयाँ।
१९३३	१९३३ मंदी और अर्थ-संकट का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस द्वारा राष्ट्रपति रूजवेल्ट को सर्वसत्ता दिया जाना। राष्ट्रपति मजदूरी की वृद्धि का महान् कार्य शुरू करते हैं। उद्योगों पर राज्य का नियंत्रण।	१९२२ इटली में फ़ैसिज्म की विजय : बेनिटो मुसोलिनी। योरोप के अनेक देशों में डिक्टेटोरशिप।	१९२३ यू. एस. एस. आर की स्थापना।
		१९२६ ग्रेट ब्रिटेन में आम हड़ताल।	१९२९ तेजी से औद्योगीकरण के लिए सोवियट संघ की पंचवर्षीय योजना।
		१९२९ समस्त विश्व में महान् व्यापारिक मंदी और संकट का आरंभ। भावों का गिरना। सरकारों का दिवाला। बैंकों का टूटना अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का नाश (अभीतक मंदी है)।	१९३३ सोवियट की द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आरंभ।
		१९३१ स्पेन में क्रान्ति। प्रजातंत्र की स्थापना।	
		१९३३ जर्मनी में नाजी-विजय। एडोल्फ हिटलर। प्रजातंत्र को दबा दिया गया। मजदूरों और यहूदियों पर अत्याचार। योरोप के अनेक देशों में फ़ैसिज्म की वृद्धि।	

निर्देशिका

अ-अ

अंकारा—१३८, १०१२
 अंगकोर—६९४
 ———और श्रीविजय—१९५, २००
 ———थाम—१९६
 ———पर भयंकर आक्रम—१९६
 ———वाट, मंदिर—
 अंगोन्—१३८, ८४३, ८५१, ८९८,
 १०००-०२, १००४, -०५, १०१२
 १०९४, ११११
 अंग्रेज (लोग)—(देखो लोग में)
 अंग्रेजी तालीम (हिन्दुस्तान में)—६२३,
 ६२५-२६,
 अंग्रेजों की छत्रछाया में आजादी का तात्पर्य
 १०६०-६८
 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक परिषद—१२२०,
 १२८०, १३१६, १३३८
 ———न्याय की अदालत—९७०, ९९१
 ———मजदूर कार्यालय—९७०, १२५२
 ———मजदूर-संघ—१२८७, १२९४, १२९९
 ———यहूदी समाज—१०८७
 अंतर्राष्ट्रीयता—५७५, ७१०
 ———मुस्लिम—१०९४
 अदीयना—६७०
 ———का इच गवर्नर—६७०
 ———का हत्याकांड—६७०
 अगार—२१०
 अगारी. ए० एम० ए०—२१० ८९१
 अकबर—१८३, २९९, ३५७, ३६६,

३७८, ४०९, ४२४, ४३५-४६,
 ४४८-४९, ४५५, ५५६, ५९१, ६०५,
 ६९५, ७०३
 अकबर, इलाहाबादी शायर—१०५०
 ———, हिन्दुस्तान में राष्ट्रीयता का
 जन्मदाता—४३७
 अकाल, आयर्लैंड का—८२४
 ———, उत्तर मध्य और दक्षिण भारत में—
 ६०९
 ———दक्षिण गुजरात में—४४७
 ———पैट्रोग्रेड का—९१२
 ———, बंगाल और बिहार में—४६२, ६०६
 ———, रूस का—९३७
 अकाली सिक्ख—१०२९
 अकबद—६९२
 'अकतूबर' गीत—१४१, ९४२
 अधुनदी—७००, १२१७
 अधुपार—७०१-०३
 अखिल इस्लामवाद—८५०, ८९१
 अगस्त्य ऋषि—४१
 अजंता—१२५, १४९, १५७, ६९४, ६९८
 अजमलखाना, हकीम—१०२४
 अजाना, मेनेल—१२८७, १२८९
 अजेफ—८५६
 अजोस—३४८
 अटोला—(देखो एटोला)
 अदन—१९७, ३७८, १०७६, १०९२
 अधिग्रहणवाद—३३०, ७८९
 अन्तर्जाल—८८९,

तिथि-क्रम की सूची

		पृष्ठ सं०
गणना नं० १-	परिचय	१३५३
॥ २-	ईसा-पूर्व २८०० से ईसा-पूर्व ६०० तक	१३५६
॥ ३-	ईसा-पूर्व ६०० से ईसा-पूर्व १०० तक	१३५८
॥ ४-	ईसा-पूर्व १०० से ईसा-पश्चात् ५५० तक	१३६०
॥ ५-	५५० ई० से १००० ई० तक	१३६२
॥ ६-	१००० ई० से १३०० ई० तक	१३६४
॥ ७-	१३०० ई० से १५३० ई० तक	१३६६
॥ ८-	१५३० ई० से १७३० ई० तक	१३६८
॥ ९-	१०३० ई० से १८६० ई० तक	१३७०
॥ १०-	१८६० ई० से १९३३ ई० तक	१३७२

अन्वास—२१८

—शाह—७०२, ७०३

अमानुल्ला, अमीर—११०८-११

अमाँय—६३६

अमृत—७३९

अमृतसर—४५५, ५३८, ५८५, १०१७-

१९, १०२९

अमरावती—६९४

अमीरअली, जज—१००५

अमीरुल मोमनीन—२१८, २३१

अमॅडोला—११५९

अमेरिका—३४, १०२, १५०, १५२,

१७०, १७२, २४०, २६३-६४,

२६७, २७६, २९२, ३०५, ३२५,

३४३-४४, ३४६, ३४९, ३७६-७८,

३९१, ४०१, ४०७, ४१२, ४२२-

२३, ४३१, ४७६, ४७५-७६, ४८१-

८२, ४८६-८८, ५०३-०५, ५०७-

०९, ५१६, ५२१, ५३८, ५४८,

५६२, ५७५-७६, ६४०, ६४७,

६४९-५०, ६५६-५७, ६६१-६२,

६६५, ६६८, ६८१-८२, ६८४-८५,

७०८, ७३०, ७४०, ७४७, ७४९-

५०, ७६२-६३, ७६०-७१, ७८८-

८९, ७९२-९६, ७९७, ८००-०३,

८०७-०८, ८१०-१२, ८१५, ८२१,

८२१-२५, ८३३, ८६८, ८६२,

८६९, ८९५-९८, ९०५, ९०७,

९०९, ९३०-३३, ९३७, ९४६-४८

९०१, ९४७-४९, ९९२, ११२६-

३१, ११३३-३५, ११३९, ११४५,

११५०-५१ ११६२, ११७१,

११८२-८३, ११८८-८९, ११९३,

११९५, ११९७, १२०७, १२११,

१२१९, १२२१, १२३०-३१,

१२३६-३८, १२४०-४४, १२४७,

१२५०-५३, १२५५-५७, १२५९,

१२६२, १२६७-७२, १२७४-८१

१२८३, १२८५, १२९९, १३०६,

१३०८, १३११-१८, १३२०,

१३२४, १३३०-३३, १३३५,

१३३९-४०, १३४७, १३४९

अमेरिका, उत्तरी—२६४, ३४४, ५०४-०५

५०८, ५६२, ५६२, ५६४, ५८०,

८०१, ८११, ८१२, ८१८, १०७६,

११२९, १२४८, १३३०

—और इंग्लैण्ड का नेतृत्व के लिए

सगड़ा—१२५४-६५

—का अदृश्य साम्राज्य—८०९-१५

—का आविष्कार—१३४७

—का इंग्लैण्ड से सम्बन्ध विच्छेद—

५०३-१०

—का गृहयुद्ध—८००, ८०९

—का दुनिया पर आर्थिक नियन्त्रण—

९८०

—का मजदूर-आन्दोलन—१३१७

—की 'मादा' सम्मेलन (संस्कृति)—

२४१, २६३-६७, ३४६, १३४७

—की न्यायीनता की घोषणा—५०९-

१०, ५२०, ७८७, ७८९, ८०९

—के उत्तरी राज्य—८०१-०२, ८०८

—के विमानों का आन्दोलन—१०८३

अनामक भाषा—१९३

अनामोनिषा—१९६-१९७, १९७, १००३,

१०३१

अनाम—१९६

अनाम नदी—३१०

अनाम—१०३, १६३, १९५, १९७,

३१८, ३५०, ३७२, ४७१, ५६६,

६६६, ६५३, ६५५, ६७६

अनाम (लोम)—१५४

अनीलनद्याद—१८९

अनुसूतपुर—८७, ९९

अपोलो—१०३

अफगानिस्तान—४१, ८०, १०३, २२५,

२९८, ३०३, ४५८, ५६३, ५८६,

५८७, ५९२, ७०३, ७८७-८८,

८५७, ८६४, ९३८, ९५३, ९८१,

११०६-४९, ११९१, ११९६,

१२००, १२१७-१८, १२२०

—का हिन्दुस्तान से अलग होना—

४५८

—के अमीर—५८६, ११०७

अफरीया—१९, २६, २८, ३४, ९९,

१०२, १०४, १४४, २०१, २०९-११

२१४, २१९, २२१, २५८, २७०-७१

२७४-७५, ३०७, ३४२-४५, ३७६,

४८८, ५०५-०६, ५६७, ५७३-७४,

५८०, ५९४, ६४३, ६४७, ६६८,

६८९-९०, ७४३, ७९२, ७९९,

८०२-०३, ८३३, ८४१, ८४३, ८६८

८७३, ८७७, ८९१, ९६५, ९८१,

१०६८, १०७१, १०७३, १०७५,

१२८८, १२८९, १३१०-११, १३२७

१३२९, १३३२, १३३६, १३३९,

अफरीया 'अंग्रेज महाद्वीप'—८४१

—उत्तरी—१११, ११७, १४०, १८५,

२०६, २१३-१४, २१८, २३४, २५४

२६३, ३३६, ६९०, ६९८, ८३५,

८८९, ९८०, ९८१, १०७१, ११५३

—दक्षिण—६१७, ८००, ८६५,

८८७, ८८९, ९८९, १०१६, १०२०,

१२६३, १२६८, १२८२-८३, १३२७

१३३६

—दक्षिण, में गांधीजी का अहिंसापूर्ण

संग्राम—८९०

—दक्षिण, में हिंदुस्तानी मजदूरों का

आन्दोलन—८८९

—पूर्वी—८८७, ९६५, १०७५, १३२७

अफगानतून—७१, ७२, ९५, २०४, २०५,

५५६, १२२२, १३४६

—के विचार—६३

अवीसीनिया—(देखो एवीसीनिया)

अबुलफजल—४४०, ४४१

अबूवकर—२१२, २१५

अबदुर्रज्जाक—३६७

अबदुर्रहमान, अमीर—११०७

अब्दुलकरीम—९८१, १२८६, ११६३

अब्दुल गफ्फार खाँ, खान—१०४४

अब्दुलमजीद, सुलतान—९९४, १००५

अब्दुलहमीद (द्वितीय)—८५०, ८९१,

९९५

—, सुलतान—१०७९, १११२

अब्दुल्ला, अमीर—१०९०, १०९४, ११०४

अर्थशास्त्र, कीटिलीय—७८, ८०, ८१,

९६, १४९, १९०, १९१, ३७१,

अर्ल, वीकंसफील्ड—७९१.

अलकाहिरा—२२१.

अलजन्ना—१९४, २८६, १०४८

अलजमीन—२१०

अल्फो—१०७३, १०९७

अल्फेजो—११६३-६४

अलबुकर्क—३६५, ३७६, ३८२, ६१५.

अलबेल्नी—१८८, २२१, ३०३.

अलसेन—४२०, ५६९, ७२८

——लारेन—७२७, ७२९, ९६२, ९६७

११२३

अल्मटर—४२८, ८१९, ८२२, ८२३,

८२६, ८३०-३१, ८७९, ९८४,

९८६, १३२३

‘——की बस्तियाँ’—८१९

——, प्रोटेस्टेंट—८२३, ८२६, ९९२

——विद्रोह—८३१-३३, ८७९

अल्हम्ब्र—२७३

अलाउद्दीन खिलजी—३०५-०६

——के समय की शासन-प्रणाली—३०६

अलादीन—२५२

‘अलावामा’ जहाज—११९५

अलान्बा—२६४, ४७३, ४८८,

‘अलिफ़लैला’—२३, २१९, ३१७, ८७०,

१०९७

‘——बलैला’—२२१

अली (खलीफ़ा)—२१५

अलीगढ़—६२९

अलीबंदू—१०२०-२१

अली, मौ० मुहम्मद, १०२०

——मौ० शौकत—१०२०

अलेक्जेंडर (प्रथम) ८५५, ८५८, ८७९

अलेक्जेंड्रिया—८३४, १०६२, १०६४

अल्कमार का घेरा—४१७

अल्तमश—३०४-०५

अल्तस—२८

अल्मोड़ा—३३

अयुध्या—६७५

‘अवंती’—११५५

अवध—२४६, ४५७, ५८७, ६०७,

८८५, १०१४

——के नवाब वजीर—५८७

अवेस्ता—६९७

अजोक—५२, ८३, ९६-१०५, ११७-१९,

१२२, १४३, १५३-५४, १७३,

१९०, २८५, ३०३, ४३६, ४३९,

४८९, ४९०, ६९७

——का राज—१०५, ३०३

——की मृत्यु—१००

——की राजन्यायें—९८-९९, १०१,

——‘दिवानाम् प्रिय’—८३, ८६-१०१,

——, धर्म राज—९८

——स्तंभ—५२, ९८, १५४

अश्वमेध यज्ञ—१४३

अष्टांगिक मार्ग—६९४

अमर (या प्रभाव) अरबी सन्ध्या का—

२७६, ६९८

——अरबों का—३७३-७३

——आधुनिक शान्ति का—६३३

——ईरान का—६५४

- अमेरिका के दक्षिणी राज्य—८०१, ८०३
 —को मजदूर-संग—३३४
 —को मणिमणि राज्य—८०५
 —दक्षिणी—१०२, २४१, २६३,
 ३४४-४६, ३७६, ५६१-६२, ५६६,
 ७४१, ७९२, ८०१, ८१०-१२,
 ८१५, ८८३, ११२९, ११६४,
 १२३३, १२४८, १२८८, १२५१,
 १२६३, १२७३, १३३०-३२
 —मध्य—२४१, २६४-६५, ३४८,
 ८११-१२, ८१४, १२७३
 —, मध्य-पश्चिमी—१२४३
 —लैटिन—८११-१२, ८१४, ११२९,
 १३३२
 —, संयुक्त राष्ट्र (राज्य)—१५०,
 १५२, ४२२-२३, ४८८, ५०९,
 ५६१-६२, ५६६, ५६९, ५७८,
 ६०२, ६३९, ६४३-४८, ६४९,
 ६५६, ६५९, ६६२, ६८०-८५,
 ७८४-८५, ७९३, ७९५, ८००-०३,
 ८०५, ८०७, ८१०-१२, ८१४-१५,
 ८७३, ९४७-४८, ९५३, ९६४,
 ९७७, १०३६, ११२४, ११२९-३०,
 ११४५, ११६५, १२३१, १२३६,
 १२६५-६६, १२७६-७९, १२८१,
 १२८३, १२८५, १३११-१४,
 १३१६, १३१८, १३२१, १३३०-३१
 १३३३-३५, १३४६
 —स्पेनिश—३७७, ३८८, ४०३,
 ५६२, ६७०, ८०२
 अयोध्या—४४, ११५, १५०, १५५, ६७५,
 अरब (अरबिस्तान)—१९, २३, १०७,
 १४०, १८५, १८७, १९४, २०१,
 २०८, २०९-१०, ११२, २१४,
 २१६, २२४, २३४, २५८, २६०,
 २८६, ३०२, ३१३, ३१७, ३७४,
 ५६८, ५७१, ५८०, ५९४, ६९५,
 ६९८, ७०८, ८५०, ९००, ९६१,
 ९६३, ९६८, ९८१, ९९३, १००२,
 १०५१, १०६७-६९, १०७१-७२,
 १०७४, १०७९-८०, १०८७-८८,
 १०९०-९७
 —दक्षिण—१०९७
 —देश—१००६, १०५१, १०६७,
 १०७८-११०६
 —की मध्ययुग से सहसा प्रगति—
 १०९१-९७
 —फिलासफी—२७२
 —में स्त्रियों के परदे की रस्म—२१६
 —(लोग)—(देखो लोग में)
 अरबी आयतें—२७४
 —पाशा—८३८, १०५१, १०५३
 —फिलासफर—२६६
 —हिन्दु—२८६
 अरबों की विजययात्रा—२१०
 अरबेस्क—२७३
 अरस्तू—७३
 आराजकतावाद का आन्दोलन की हैसियत
 से खत्म हो जाना—७६५
 —का आदर्श—७६५, ७७९
 अरेबिया फेलिक्स—१०९७
 अर्जेंटाइन—७९२, ८११, १२४४, १३३९

- असेम्बली, कांस्टीट्यूण्ट—१०८३-८४,
११०१
—नेशनल (फ्रेंच) ५२१-२५, १००५
—पीपुल्स (स्याम की) १११२
—लेजिस्लेटिव (फ्रांस की)—५२४-
२५, ५४५, ७१७.
—लेजिस्लेटिव (हिन्दुस्तान की)—
१०३१, १०४०-४१
अहमदनामा, पुराना (वाइविल का)—२३,
२८
—, नया १२६, १४७
अहमदगनर—३६४, ४५५
—की रानी ४४०
अहमदशाह—३६३
—दुर्रानी ४५८
अहमदवाद—३५९, ३६३, ४४०, ६१६
१०२४.
—का बढ़ता हुआ उद्योग—६१६
अहल्याबाई—५८४
अहिंसा—५८, १३१, ८६५, ८९०.
—पूर्ण संग्राम, गांधीजी का ८९०
- आ**
- आंदोलन, अकाली—१०२९
—अधिकार (इंग्लैंड का) ७१८
—अवध का किसान—१०१४
—असहयोग—९८२, १०००,
१०२७-२८
—आयर्लैंड का प्रजातंत्रवादी—९८९
—इंग्लैंड में मजदूरों का—९५६
—इंग्लैंड में स्त्रियों के मताधिकार का
—८७१
आंदोलन, खादी—४९५
—गुलामी को दूर करने का,—८०४.
—चार्टिस्ट—७६२
—चीनी बहिष्कार—१२८३
—जर्मनी में मजदूरों का—९८०
—जियोनिस्ट—१०८७-८८
—तुर्की में वैधानिक सरकार स्थापित
करने का—८४८
—नाज़ी—१२७८, १३०३, १३१३
—नीजवान तुर्क—९९४, १०१०
—पैन इस्लामी—८५०
—प्रोटेस्टेंट—४०४
—फैमिनिस्ट—८७१
—मिस्र और हिन्दुस्तान के राष्ट्रीय—
१०५०
—वपद—१०६७
—समाजवादी—७६७
—समाजवादी मजदूर—११७०
—सहकारिता—८७०, ८७१, ८७७
—स्त्रियों की उन्नति का—७८८.
—हिन्दुस्तान का राष्ट्रीय—९८२.
आंध्र—३९, १२२, १४९-५०, ६९४
—के सिक्के १४९
आइंस्टीन, एल्बर्ट—७४६, १२२३-२५
१२९९.
आइजाबेला—२७४, २७६, ३४२, ३४३,
४०७.
आइरीन—१४४, २३१
आइरोकोईन—५०५
आइवन, भयंकर—३५०
—महान्—३५०

- अगर, ईस्ट-इंडिया-कम्पनी की नीति का
—६०३
- उद्योगवाद की तरफ़ की का—७५९
- कान्टे के विचारों का—७५२
- न्याय की आत्मा का—४६४
- चीनी और हिंदुस्तानी सभ्यता का
१५१-५२
- जापान की विजय का—६६३
- तुर्की शासकों का—१२०, २९
- नये विचारों का बौद्ध सिद्धान्तों
पर—१२४
- पश्चिमी विचारों का—६२३
- पादरियों का रंग की शिक्षा
प्रणाली पर—१२८८
- पुनर्जागृति का—३६७
- फारस और चीन के मंगोलों के
संसर्ग का—७०१
- फ्रेंच दार्शनिकों का फ्रांसीसी राज्य-
क्रांति पर—५१३
- बुद्ध-धर्म और हिंदुस्तानी विचारों
का—१६७
- ब्राह्मण या यूनानी—१२४
- भारतीयता का—१८०
- मशीनों के कारख़ाने और उद्योग-
वाद का—५९७-९८
- महायुद्ध का—६३३, ९५७
- मुसलमानी विचारों का—३०४
- मुस्लिम हमलों का हिंदुस्तान के
लोगों पर—३००
- यतीन्द्रनाथ दास के आत्म-बलिदान
का हिंदुस्तान पर—१०४०
- अगर, यूनानियों का—६९७
- राजनैतिक लड़ाइयों का—१६५
- रूसी क्रांति का, महायुद्ध और संसार
के इतिहास पर—९०९
- रंग के उठने और गिरने का, चीन
पर—१६२
- विदेशी हमलों का दक्षिण भारत
पर—१२९
- हिंदुस्तान और चीन का राजनैतिक
और सांस्कृतिक—३७३
- हिंदुस्तान का—६८२, १११२
- हिंदुस्तानी विचारों का—२१६
- हिंदुस्तानी शिल्प कला का—१६७
- हिंदुस्तानी पूंजीपति-वर्ग और ऊँचे
मध्यमवर्ग की ताकत का—९५९
- हूणों की भयंकरता का—१५८
- असहयोग—१०९, ७१७, १०३०, १०८८
१०२८-९९, ११०१
- आंदोलन—९८२, १०००, १०२७-
२८
- आयरलैंड का—८२९, ९८६
- का कानून तोड़नेवाला कार्यक्रम
स्थगित होता है—१०२४
- का कार्यक्रम—१०२०, १०२३-२३
- की पहली अवस्था का ख़तम होना—
१०२४
- के नये सिद्धांत—१०२१
- हिंदुस्तान का—८२९
- असाइबेड्स—५२९
- असीरिया—१९-२३, २८.
- असीसी—३२७

—, उत्तरी—८१९, ८३०, ९८७
 —और इंग्लैंड का व्यापारिक युद्ध—
 १२५९
 —और इंग्लैंड के संघर्ष के ७०० वर्ष
 —८१६-२५
 —का सतयुग—८१७
 —की प्रजातंत्र के लिए लड़ाई—
 ९८४-९२
 —की राष्ट्रीय क्रांति—८२२
 —कैथलिक—८१९, ९८६, ९९२
 —दक्षिणी—९८४
 —में गृहयुद्ध—८७९, ९८४
 —में बलवा और घरेलू लड़ाई—८२०
 —में होमरूल और सिनफ़ेन—८२५-
 ३३
 आया सूफ़िया—३३८
 आयुर्वेद—१८२, २२०, २२४
 आयेयासू—३८९
 आरकस—११४९, ११९१, ११९३.
 —रेड—११४९, ११९३.
 आरगोन—(देखो एरेगॉन)
 आरटावानस—६५-६६.
 आरमीनिया—२१३, ३२१, ८५०,
 १०७९, ११९९, १२००
 आरबिले राइट—८७०
 आरेंज का शाहजादा—४२६
 आर्क बिपप, बेलेंशिया के—२७५
 आर्कटिक क्षेत्र—८७७
 आर्पर प्रिप्रिय—८२९
 आर्सेनर. प्रथम—१४६
 आर्नाल्ड, मैथ्य—१३४९

आर्मिस्टीज़—९६२
 —तुर्की की—९९३
 आर्मेटा, अजेय—३७८, ४१२
 आर्य (लोग)—१७, १८, २६, ३९, ४१-
 ४४, ४९, ८१, १०८, ११९-२०,
 १५८-५९, १६४, २६९, ६९३,
 ६९६, १३४७
 —जर्मन—१३२३
 —फ़ारसी—६९६
 —भारतीय—२६, ४०, ४२, १२१
 १५३-५४, १५८, २२५, ६९६
 —दृष्टिकोण (भारतीय)—१५५
 —नस्ल (जर्मनी की)—१२९३
 —परम्परा (भारतीय)—१५३
 —यूनानी—२६, ४२
 —राज्य व्यवस्था (प्राचीन)—१२५,
 १९२, ३९२
 —विचार (प्राचीन)—२३९
 —सत्य—६९४
 —समाज—६२४, ८८९, १०१७
 —सिद्धांत (भारतीय)—१५५
 आर्यावर्त—२५, १५३.
 आर्लियंस—६, २९५, ३३५
 —, मेड ऑफ़—३३५
 आल्प्स—३३, ५४३
 आल्सस—(देखो अल्सेस)
 आवा—५८५
 आविष्कार, आग का—२५०
 —कपड़े रंगने के पक्के रंग का—१६०
 —कानने की 'जैनी' का—४९६
 —खाद्य पदार्थों को पैदा करने के नये

आइसिया—१०४
 आउटरम, जगत्—५१०
 आकाश गंगा—१२२५
 आमेगियन—११५-१६, १३२
 आन्सफोर्ड—२९७, ४९४
 ——इंग्लिश शिगरी—४६७
 आन्स—१२१७
 आगरा—३६५, ४०९, ४३३, ४६०-४१,
 ४४४, ४४६-४७, ४५४, ४५६-५७,
 ६०७, ७०२
 आगा गां, सर—२९१-९२, १००५-०६
 आजर वायजान—११०२, ११९७
 आजादी, अंतःकरण और भाषण की (पुराने
 आर्य सिद्धांत में)—३३२
 —, गांव की—३३३
 —(गांवों की) में दलाल देने की
 शुरुआत—३३३
 —, मजहबी—४४३
 —, राजनैतिक—४४३
 —का दिन—८३
 —की लड़ाई, अमेरिका की—५१४
 —, अरबों की—९६८
 —, आयरलैंड की—८१६, ९८८
 —, आर्थिक—३३१
 —, इंग्लैंड की—२२८
 —, इटली की—७२२
 —, कोरिया की—६६४
 —, चीन की—६६८, ९८१
 —, जर्मनी की—५४९, ७३०
 —, तुर्की की—९९३, १००८,
 १०८०

आजादी की लड़ाई, निदर्शकों की—४११,
 ४१३-२०, ४२६, ४९३, १२८५
 —, फिलिपाइन की—६८८-८५
 —, मिस्र की—९८१, १०५४,
 १३२९
 —, मोरक्को की—९८१
 —, यूनान की—७२२, ७३६,
 ८४६
 —, रूस की—६६१-६२
 —, हालैंड की—४१९
 —हिंदुस्तान की—२६३, ६६९,
 ९८१, ९८३
 'ऑटोजीरो', वायुयान—१२३३
 आतंकवाद—७६५, ७९८, ८५६, ८५८
 —, व्यक्तिगत—७६५, १०२२
 आनंद मठ—६२७
 आनटून—१६२
 आबू—५८
 आमूर नदी—४६९
 आयरिश नेता, (कैथलिक)—८२०-२१, ९८४
 —कामन्स सभा—८२५
 —पार्लमेण्ट—८२२-२३
 —प्रजातंत्र—९८४-८६, ९८८
 —प्रोटेस्टेण्ट—८२१
 —फ्री स्टेट—९८८, ९९२
 —संधि—९८९-९०
 —होमरूल पार्टी—८२७,
 आयरलैंड—३३६, ४१०, ४२८, ७१७,
 ७२२, ७९०-९१, ८१७-३३, ८७९,
 ९३२, ९६३, ९८४-९३, १०२२,
 १२५९, १३२३, १३३४

७५४, ७५९-६०, ७६२-६५, ७६७,
 ७७०-७३, ७८३-९१, ७९३-९७,
 ७९९-८०३, ८११, ८१५-८१९,
 ८२१-२७, ८३२, ८३८, ८४१,
 ८४६-४७, ८५०, ८६३-६४, ८६८,
 ८७०-७५, ८७७, ८७९-८२, ८८६,
 ८९१-९८, ९०२-०५, ९०७-१०,
 ९१७, ९२०, ९२५, ९३२, ९३५,
 ९३७-३८, ९४७, ९५२, ९५५-५८,
 ९६५, ९६९, ९७२-७३, ९७७-७८,
 ९८३-९१, ९९५-९६, ९९९, १०००
 १००७, १००८, १०१४, १०१९,
 १०३३, १०३६, १०४०, १०४९,
 १०५४-५५, १०५७-५८, १०६०,
 १०६४-६५, १०६७, १०७२-७३,
 १०७५-७६, १०८०, १०८५,
 १०९३, १०९८-९९, ११०१-०२,
 ११०४-०५, ११०९, ११११,
 १११४-१५, ११२३, ११२६-२८,
 ११३१-३३, ११३५-३६, ११४२,
 ११४४, ११४५-४९, ११५१,
 ११५३, ११६२, ११६५-६६,
 ११७०, ११८२, ११८६-८९,
 ११९३, ११९५-९६, १२०३,
 १२०६, १२१९, १२२२, १२३६,
 १२३९-४०, १२४३, १२५४-५९,
 १२६३, १२६५-६६, १२६८-७०,
 १२७२-७३, १२७५, १२७७-७८,
 १२८०-८३, १२८६-८७, १३०१-
 ०२, १३०६-०८ १३१३-१४,
 १३१६-२३, १३३२-३६, १३३९,

इंग्लैण्ड, उत्तर—१५०, ८१७
 —और आयर्लैण्ड का झगड़ा—९९२
 —का औद्योगिक नेतृत्व—५७०
 —का मजदूर आंदोलन—७१९,
 ७५३
 —का विक्टोरिया युग—७८३-९१
 '—की मुसीबत आयर्लैण्ड का सुअव-
 सर'—८१८
 —के घरेलू उद्योग—४९३-९५
 —ने अपने वादशाह का सिर उड़ा
 दिया—४२०-२९
 —में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत—
 ४९५-५०३
 —में कताई का प्रचार—४९४
 —में मजदूरों की लड़ाई—७६१
 —में मशीन और कारखानों का
 विकास—४९७
 —में व्यापार की मंदी की शुरुआत—
 ७७२
 —, संसार का साहूकार—७९२-८००
 'इंटरनेशनल', गीत—७७४
 —फर्स्ट—९३८
 —सेकण्ड—९३८-३९, १०३५
 —थर्ड—९३८, ९३९, १०३५
 —इकोल—११४७
 —, कम्यूनिस्ट—९३८
 इंडलजैन्स—२९०-९२
 इंडस—१७८
 इंडास—७८
 इंडिगो—१६०
 इंडियन मिनिस्त्र नॉमिन—१४१, ६१९-२०

और सैज तरीकों का—५४
 आधिपत्य, रोमी का—५३, २५०
 ——रूपों में लुप्त की कला का—१०८
 ——भाषा के लुप्त का—४७२, ४९६
 ——मजीन का—४८९, ४९५, ५७२
 ——सांख्यिक—४९५
 ——जोड़े के इतिहास बनाने का—१६०
 ——सरकारी करकी (फार्म गटल)
 का—४९६

आश्रम—४९
 ——भारद्वाज—४८
 ——सायनमती—१०१६
 आसक्रमण, यजीर—४५७
 ——का वंश—४५७
 आसाम—४०, ५६३, ५८५, ६१७,
 ६७३, ८८७
 ——के चाय के बगीचे—६१७
 ——के नील के खेत—६१७
 आस्ट्रेलिया—५४७
 आस्ट्रिया—४०३, ४१०, ४१३, ४८३-
 ८६, ४८८, ५१३, ५२४-२५, ५२८,
 ५४३, ५४७, ५५०, ५५३, ५६०,
 ५६८-६९, ७१६-१७, ७१९-२०,
 ७२५-२६, ७२९-३०, ७७०, ७७३-
 ७४, ७८५, ८००, ८४६-४७, ८४९,
 ८६४, ८७५-७६, ८७९-८२, ८९५,
 ९०२-०४, ९६३, ९६५-६७, ९७१,
 ९९३, १११६-१७, १२२१, ११३१,
 ११४३, ११६४, १२३९, १२७७,
 १३०१, १३०४, १३३७-३८
 ——का इनफ्लेक्शन—११३१

आस्ट्रिया-हंगरी—२८७, ९३२, ९६६,
 १०७८
 आस्ट्रेलिया—२६३, ६६९, ७८६, ७९२,
 ८३७, ८८७, १०७४-७५, ११४५,
 ११८३, १२४८, १२६३, १२६८,
 १२८२-८३, १३३०, १३३४

इ

इंग्लिश चैनल—८७०, ८८१, १३३६
 इंग्लैण्ड—७, २६, २७, ३३, ५४, ११२,
 ११५, १३१, २३३-३४, २५५-५६,
 २७९, २८१, २८७-८८, २९३,
 २९५, २९७, ३११, ३२८, ३३४-
 ३६, ३४०, ३४६, ३७० ३७७-७९,
 ३९३, ३९९, ४००, ४०३, ४०५,
 ४०७-८, ४१०-१३, ४२०-२१,
 ४२३, ४२५-२९, ४३१, ४३६,
 ४५०-५३, ४६२-६३, ४७०, ४७२-
 ७६, ४८०, ४८४-८६, ४८८-८९,
 ४९१-९२, ४९४, ४९७-९८, ५०२,
 ५०९, ५११, ५१३, ५१६, ५२०-
 २१, ५२९, ५३३, ५३८, ५४४-४५,
 ५४८-४९, ५५१, ५५४, ५५६,
 ५५९-५६१, ५६३-६४, ५६६-७०,
 ५७२, ५७६-७७, ५९१-९७, ५९९,
 ६०१, ६०६, ६१२-१३, ६१६,
 ६१८-१९, ६२२-२३, ६२८, ६३४-
 ३५, ६३७, ६४४, ६४६, ६५१-५२,
 ६५५, ६५९-६१, ६६६, ६७०, ६७४-
 ७६, ७०६, ७०८, ७१०-११, ७१७-
 १८, ७२४, ७२६, ७२९, ७३३-३४,
 ७३७, ७४०-४२, ७४६, ७४९-५०,

इतिहास, कश्मीर का—१५८
 —की रूपरेखा—९६
 —की शिक्षा—१२, १४, ५८८
 —कोरिया का—१७३, १७५
 —चीनी—४७, १७३, ३८०, ४८४
 —जापान का कला सम्बन्धी—१७६
 —जापानी—१७३, १७६-७७
 —दक्षिणी हिन्दुस्तान का—३०२
 —दक्षिणी हिन्दुस्तान का (प्राचीन)—११
 —पूर्वी रोमन—७२०
 —प्राचीन—१०२
 —फ्रांस का—५३६
 —भारतीय—६३६
 —मंगोलों का गुप्त—३०९
 —मराठों का—४५४
 —मुगलों का—३०९
 —यहूदी—१०२
 —यूनानी—३५, ६४, ७१, ७५,
 १०२, ११७, ६९६
 —यूरोपियन—३४८, ७२४, ७३२
 —योरप का—३९४, ४१२
 —राजपूत—४३५
 —रूस की क्रांति का—१२०३
 —रोम का—१०२, ११७
 —विजयनगर का—३६७
 —स्पेनवालों का—२७४
 —हंगरी का—७१६
 —हिन्दुस्तान का—९७, ११८, २२७
 ४५७, ६०९
 इतिहास-लेखक. अंग्रेज—२७६, २८२, ३६९
 —अरब—२२१, ३१३

इतिहास, ईरानी—३१३
 —जापानी—३८६
 —पश्चिमी—३७१
 'इनका'—२४१, २६७
 इन-तू—१८०
 'इन्किलाव जिन्दावाद'—१५-१६
 इन्विजिशन—६, १४६, २७४, ३२८,
 ३३६, ३३८, ३९८, ४०१, ४०७,
 ४१२, ४१५-१६, ४४२, ४७७,
 ५४९, ५६०, १२८८
 इन्वेलिद—५४१
 इफ्रीकिया—२१८
 इन्न वतूता—३०७, १०७०-७२
 इन्नरद—२७३
 इन्सऊद, सुलतान—९८१, १०९२-९६
 इन्सिना—७००
 इराक—२२, ४१, ४६, ४९, ७७, ९४,
 १०३, १०७, ११४, ११७, १४५,
 १८४, २०७, २१२, २१९, २२२,
 २५८, २६८-६९, ३१०, ३१९,
 ३२१, ३४९, ३५२, ५३९, ५८०,
 ६९९, ७०८, ९०२, ९६८, ९८१,
 ९९३, १००२, १००७, १०५१,
 १०६७-६८, १०७२, १०७६-७७,
 १०७९-८०, १०९१-९२, १०९४,
 १०९७, ११०६, ११०७, १३०६
 इरैस्मस—४७५
 इल्लान—७०१
 इल्हावाद—८, २१, ५२, ८८, ९८,
 १३१, १५४, १८३, ३५९, ३६१,
 ३६२, ३६९, ४८१, ५९०, ६३३,

ईस्ट इंडीज (डच)—९८३, १११३, १३२९
 ईस्टर विद्रोह—९८५
 ईसा—८६५, ९४१
 —, एक राजनैतिक बासी—१२८
 —, एक सामाजिक विद्रोही—१२८
 —का पर्वत पर का उपदेश—१३१
 —की पवित्र समाधि—२८२
 —की शिक्षा—१३१
 —के देवत्व—१३०
 —के सिद्धांत—१२७, १२९, १३०
 —पूर्व छठी सदी में मतमतांतर—
 ७५-६३
 —ईसाइयों के खिलाफ राजाज्ञा—३८८
 ईसाई—२८, ५८, १२९, १३९, २०४,
 २१२, २७७, ४४३, ४४६, ४७९,
 ८३५, १०१५, १०८०-८१, १०८३,
 १०८५, १०८७-८८, १०९२, ११६१
 —किसान—२७९
 —, चीनी ६५८
 —जनता—२९०
 —जिहादी—२७७, ६९९
 —धर्म का राजधर्म होजाना—१३८
 २०४, ८३५
 —धर्म-जगत् की भावना—२३५
 —नेस्टोरियन—३१६
 —पश्चिमी—३३८
 —प्रचारक—१७३, ६५७
 —प्रोटेस्टेंट—६८३
 —मठ—२०६
 —मिशनरी—४६७
 —रोमन कैथलिक—६८३

ईसाई शहीद—१३०
 —संघ—१३०
 —संप्रदाय—२०५, २७३
 —समाज या गिरोह—२३५
 —सिद्धांत, पुराने—३२६
 —स्पेन के—२७५, ८७५
 ई-हो-चुआन—६५७
 —तुआन—६५७

उ

उक्रवा—२१४
 उक्रेन (देखो युक्रेन)
 उक्षमल नगर—२६५
 उज़बकिस्तान—११९९, १२००, १२१५,
 १२१७
 उज़्जैन—४४
 उड़ीसा—४०, १५१, ४४०
 उदयपुर—४८
 —के महाराणा—६१४
 उद्योग की वृद्धि—६१६
 —एशिया के—१३३९
 —पुराने घरेलू—५६६, ६०८
 —पूँजीवादी—५७५-७६
 —ब्रिटिश—५९५, ६२०, ६२७, ९५७
 —, योरप के मशीन—५६६
 —धन्धों की हत्या—५६७
 उद्योगवाद—४९१, ४९३, ४९५, ५०१,
 ५६८, ५७३, ५८०, ५९४, ६१३,
 ६१६, ६५२, ६८१, ६८७-८८,
 ७१०-११, ७५०, ७६५, ७८९,
 ७९७, ८७४
 —का फैलना—१३४७

१०४४, १०५०, १०७५, १२१८

इलाहाबाद का क़िला—४४१

इसफ़हान—७०२, ७०५

इसलाम (धर्म)—(देखो धर्म में)

—का झंडा—२१७

—के सिद्धान्त—३३२

इसलामी रवायतें—६२५

इसा, उस्ताद—६९५

इसिपत्तन—६९३

इस्टोनिया—९६६-६७

इस्ताम्बुल—८५१, ८६६, ९९७-९९,

१००१, १००४, १००५, १०१२,

१२०३

इस्थोनिया—११५१

इस्पहान—(देखो इसफ़हान)

इस्मत पाशा—१००२, १००९

इस्मीर—१०१२

ई

ई-ताई-जो—३८५

ईमिग्रिस—५२०

ईयेयासू—६४९

ईरान—१९, २२, २३, २४, ३१, ३४,

३५, ३८, ४१, ४९, ५७, ५८, ६५,

६६, ६८, ६९, ७४-७८, ९४, १०३,

१०७, १२३, १४५, १४७, १५९,

१६९-१७०, १८०-८१, १८४,

२१०-१४, २१६, २२४, २५८,

२६८, ३०२, ३०७, ३१०-१३,

३१६, ३१९, ३२१, ३२३, ३५२,

३७५, ३७७, ३७८, ३८१, ४०९,

४३६, ५६७, ६९४-९५, ७००-

७०२, ७०४-०७, ७८७-८८, ७९९,

८५२, ८६४, १०६८-६९, १०७१-

७२, १०७६-७७, १०९९, ११०२,

११०६, ११०९-१०, ११४९,

११५१, ११९१, ११९६-९७, १२२०

ईरान और यूनान—६३-६८.

—का शाह—४५८, ५४५,

—की खाड़ी—३२७, ३७८, ७०५,

१०९२, १०९७

—की पुरानी परम्पराओं की दृढ़ता—

६९६, ७०३

—की फाँसी—७०८

—, प्राचीन—६४

—में जरथुस्त्र धर्म, राजधर्म हो गया

—२१०

—में सभ्यता का सम्मिश्रण—२५८

—में साम्राज्यवाद और राष्ट्रीयता—

७०४-०९

ईलियड—२७

ईश्वर के नाम पर हत्या और अत्याचार,

(पोपों के)—३२८

ईस्ट इंडिया कंपनी (अंग्रेजी)—३७९,

४३१, ४५०, ४५९, ४६१-६२,

४६४, ४७१, ५०२, ५६३, ५६७,

५८७-८८, ५९१-९६, ६०१, ६०३,

६०५-०८, ६१८, ६३५, ६६९-७१

—का खात्मा—६७१

—की चाय—५०७

—(डच)—३७९, ४३१, ६६९-७१

ईस्ट इंडीज—६६८-७१, ६८०, ६-६,

८७७, १२८५

एरेगॉन—२७४, ३२३

एरेगम—३४२

एर्नाल्ड—३२६

एल्प्पो—३१७

एलम—६९१

एलिजावेथ—३७९, ४१२, ४२२-२३,

४२८, ४३१, ४९३, ८१९,

—त्रैरेट वोरिंग—७२२-२३

एलिफेन्टा—६९४

‘एलिस इन दी वंडरलैण्ड’—२३०, ९८३

एलिस्सा—३१७

‘एलेक्ट्रन’ १२२४

एलेनबी, लार्ड—१०६०-६१

एलैरिक—१६१, २०१

एलोरा—१८७, ६९४

एल्वा—४१५-१६, ४१८, ५५२-५४,

५६४, ८०१

एवरोज़—२७३

एविग्नन—३२९

एवीसेना—२८२

एशिया—१८, २०, २३, २६, ३४, ३५,

९४, १०१, १०७, ११७-१९, १२३

१३६-३७, १४५, १६०, १७०-७२

२००, -०१, २०९, २११, २१९,

२२२, २४४, २४७, २५२-५३,

२५५, २५८-५९, २६२-६५, २७०,

२७६-७७, २९३-९४, ३०१-०२,

३०८-१०, ३१२, ३१६, ३१९,

३२१, ३२३, ३३७-३८, ३४३-४४,

३४६, ३४८-५०, ३७३, ३८१,

३९१, ४११, ४२०, ४३१-३२,

४६८-६९, ४७३, ४७६, ४८४,

४८६, ५१०, ५६२, ५६७-६८,

५७१, ५७४, ५८०, ५८१, ५९३,

६३०, ६३४, ६४२-४३, ६४५-४७

६६१, ६६३, ६६९-७०, ६७३-७६,

६८०, ६८३-८४, ६८८-९१, ७००,

७०६, ७०९, ७१२, ७४३-४४,

७८७, ७८९, ७९७, ७९९, ८१०,

८३७, ८४२-४३, ८४६, ८५०,

८५३, ८७२-७३, ८९१, ९००,

९४७, ९७६, ९८०-८१, १००३,

१०६९-७१, १०७५, ११०६,

११०८, १११२, १११४, १११६,

११३०-३१, ११८२-८४, ११९१,

११९८, १२२१, १२३९, १२४४,

१२४८, १२५३, १३१०-११, १३२९-

३०, १३३२, १३३६, १३३९,

१३४७, १३४९

एशिया, उत्तरी—१२०, ३०९, ७८७,

८६१, ९४७, १३३०

—‘एशिया’ वालों के लिए—६६३

—की राष्ट्रीय जागृति—१०७७

—दक्षिण-पूर्व—५० ४३१, ५६३,

५६७, ६७६, ६८७, १३२९

—दक्षिणी—७८७, ११११

—पश्चिमी—३५, ९६, ९७, ९९, १००,

१०२-०३, १२१, १२३, १५९,

१८५, २०४, २३४, २४०, २५४,

२५८, २६९, २७२, २८२-८३,

२९९, ३०८, ३१७, ३३७, ३५२,

४३३, ६८७-९० ६९५, ७०३,

उन्नति, कला कौशल की—५५

——मनुष्य की—५५

——विचारों की—५५

——शासन-कला की—७९

——संस्कृति की—५५

——सभ्यता की—५५

उपनिषद्—३८, ४९, ७०, २५१

उमर—२१२, २१५, २१७

——खैय्याम—७००

उम्मैया—२१८, २७१

——खलीफा—२७१

उर—६९२

उरू से जन्नत—२२७

उल्फ्टोन—८२२

उस्मान—९९३

उस्मानी शिल्पकार—४३३

ए-ऐ

एंग्लो पर्शियन आइल कम्पनी—७०६,

७०८, १०७७, ११९७

एंग्लो-सेक्शन—५६६

——कानून—१५३

——न्याय—१५३

एंजेलो, माइकेल—३९६

एंजेलस, फ्रेडरिक—५७८, ७६७-६८

एंटरप्राइज—२९५, ४१५, ४१८

एंटीआक—२०७

एंटीओकस—९७

एंटीगोनस—१०३

एंटी पोप—३२९

——पोपरी—४२२

एंतोइनेत, मेरी—५१३-१४, ५१६, ५१८,

इन्तोइनेत, मेरी—५२४

एक्ट ऑफ यूनियन—८२२, ८२३

——इंडियन भाइन्स—१०३४

——इंडेम्निटी—१०५६

——कांस्क्रिप्शन—१०५३

——ट्रेड यूनियन—१०३५

——डिसार्मिमेंट—१९५३

——वर्कमैन्स कंपेन्सेशन—१०३५

एकयूलिया—२९४

एगमौट, काउन्ट—४१६

एटिला—१५७, २०२, २२९, २४१,

२९४, ७४३

एडगर-एलन-पो—८४

एडम स्मिथ—५९३, ७४७

एडवर्ड, सप्तम—४२८

एडिंघ्टन, सर आर्थर—१२२५, १२२८

एड्रियानोपल—३३७, ८४९

एथेंस—२७, ६४, ६९, ७१, ७२, १०३,

२०५, ७३४, ८४४, १३४९

एदमाँ रोस्ताँ—९०३

एनी (इंग्लैण्ड की रानी)—४२७

एपियन-वे—११४

एफिल टॉवर—८७०

एवाट—२३८

एबीडोस—६६

एबीसीनिया—२०५, ७९९, ८४१, १०५७

एमडन—९०१

एमस्टर्डम—१०७५, १२१३

एम्बूलियस—२८

एम्हर्स्ट, लार्ड—६३५

एरिस्टोफोनीज—६९

क

कंधार—२२६, ४३४	कमीशन, ब्रिटिश—१०३७-३८
कंबोज—१५०-५१, १९५, २००	—मिलनर—१०५४
कंबोडिया—१५०-५१, १६९, १९६, २५३, २५८, ३६९-७०, ३७२, ६७४-७५,	—राँयल—१०३६
कनफ्यूशियन महाग्रंथ—१७६	—राष्ट्रसंघ—१३०९
—शास्त्र—१०८, २४३	—साइमन—१०३८, १०४०
कनफ्यूशियस—२०, ४७, ५७, ५८, ९४, १०५-०६, १७४, २४३, ४६५-६६ ४७९, ६४८	कम्यून—५२५-३०, ५३१, ५३३
—का तत्वज्ञान—१७४	—पैरिस की—५३१
—की राजाज्ञा—१०५	कराकुरम—३१२, ३१६, ३१८, ३२०
कनाडा—४६०, ४७४, ४७६, ४८६, ५०२, ५०५, ५६२, ६०२, ७८५- ८६, ७९२, ८११, ९५३-५४, ११२९, ११४५, ११८३, १२४३, १२६३, १२६८, १२८२-८३, १३३१, १३३४	कराची—६०१, १०७४, १२९८
—पश्चिम—९५३	करेंस्की—९१०, ९२३
कनिष्क—१२३, १२५	कर्जन, लार्ड—७९७, १००२, १०५०, १०५७
कनौजा—२५६-५७, २८४, ३२९	कर्ण सुवर्ण—४
कन्नौज—४४, १७८, १७९, २२३, २२७ २९८	कर्नाटक—४०, ३६४, ३६६
कन्याकुमारी—८८, १४८	कर्वाला—२१५
कन्वेन्शन, फ्रेंच नेशनल—५२५	कलकत्ता—३६, २२१, ४५१, ४६०-६१, ६०१, ६२१, ७३७, ९५४, ९५९, १०२०, १०३८, १०४०, १०७५
कपिलवस्तु—१५६,	कला, अरब की—६९८
कबीर—३५७, ३५९, ४३८	—, अरबी-फ़ारसी—७००
कमालपाशा—(देखो मुस्तफा कमाल)	—, इंग्लियो—२६९-७०
कमीशन, इंडियन इंडस्ट्रियल—९५७	—, ईरानी—७०३-०४
—प्रिपेयरेटरी—११५०	—, ईरानी चित्र—४६९
	—एकेमेनीदी—६९७
	—इलेक्टिक—२७०
	—कोरिया की—१७४
	—गुप्त—१५७, ६९८
	—गोधिक—२९३
	—ग्लिटिक—२७०
	—चीनी—४८, ४९, १६७-६८, १७३, २४८, २५३, ६४१

८४३, ८७५, ९००, ९५१, ९६५,
 ९६७-६८, १०५१, १०६८-७०,
 १०७२-७४, १०७६-७७, १०९८,
 ११११, १११६, १३२९
 एशिया (पूर्व) का राजनीति में पुनः प्रवेश—
 १०६८-१०७८
 —पूर्वी—४५, १६९, १७६, ३७५,
 ५६७, ६६७, ६८७, ६९४, १२९८
 —में पश्चिमी साम्राज्यवाद के खिलाफ
 क्रांती बगावत—१११६
 —में सभ्यता और संस्कृति का परि-
 वर्तन—२६१-६२, २६९
 —और योरप—१७-२०, २६, ५१२
 —का विद्रोह—५७२
 —के देशों में राष्ट्रीयता का जोर—९८०
 —के मुल्कों में राष्ट्रीय आन्दोलन की
 शुरुआत—५७१, ५७५
 —मध्य—३६, ४६, ७४, ७६, ९५,
 ९७, १०२, १०७, ११९-२०, १२३,
 १२६, १४३, १४५, १४८, १५३,
 १५८, १६२, १७१, १७९, १८१,
 १८४-८५, १८७, २०१, २०८,
 २११, २१३-१४, २२२-२३, २२५,
 २२८, २४१, २५३, २५८, २६०,
 २९९, ३००, ३०३-०५, ३०८,
 ३१२-१३, ३१६, ३१९-२०, ३२२,
 ३२४, ३५०-५३, ३६६-६७, ३७१,
 ४०९, ४३२, ४६९, ४७१, ५६३,
 ५६९, ६४६, ६८७-८८, ६९१,
 ६९५, ६९७-९८, ७८७, ८५२,
 ८५७, ९४७, ९७६-७७, १०११,

११०६, १११६, ११८२, ११९८,
 १२००, १२१५, १२१७
 एशिया भाइनर—२७, ३४, ३५, ३८,
 ६४, ६६, ७७, ८०, १०३, ११७,
 १३१, १३७-३८, १४२, १४५,
 २०७, २२२, ३३४, ३५१, ६९९,
 ८४२-४३, ८९५, ९९४-९७, १०००-
 ०१, ११५३
 एस्किलस—६९
 एस्टोनिया—११९८, १२२०
 'एस्पित-द-लोई'—४८०
 ऐतमादुद्दीला—४४६

ओ-औ

ओगताई—३१५, ३१६
 ओटावा—१२८२-८३,
 —का समझौता—१२८३, १३३४
 —की नीति—१२८३
 ओटो, महान्—२३३
 ओडेसियस—२७
 ओडेसी—२७
 ओलंपस—३१, ३२
 ओलंपिक खेल—३१
 ओलंपिया—९५
 'ओलिव ब्रांच पिटीशन'—५०८
 ओल्ड सारम—४२७
 ओविड—१३४
 ओवेन, रावर्ट—७६१-६३, ७६७
 ओसिरिस—१०४
 औद्योगिक पूंजी—५०१
 औरंगजेब—४४६-५२, ४५४-५७, ४६०

कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन—१०३८,

१०४१

—की पूर्ण स्वाधीनता की घोषणा—

५०८, १०३८, १०४७

—की स्थापना—६२८

—के प्रान्त—३९

—, गैर कानूनी घोषित की गई—१०४४

—, ट्रांस जोर्डन की राष्ट्रीय—१०९०

—फिलिपाइनो—६८४

—, मक्का में मुसलमानों की—

१०९४-९५

—, रूस की—११३६

—लीग योजना—९६०

—, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की—

६८४-८५, ८०१, ८०६-०७, ९९७,

१२५६-५७, १३१४, १२१९

—, सिवास की तुर्की—९९७

—सीरियन राष्ट्रीय—१०८१

कांचीपुर—१८६

काजीवरम्—१८६-८७

कांट, इम्मेन्युअल—७३३

कापेनवन—९६२

कान्फ्रेंस, वाक—१०११

—राउण्डटेबुल (प्रथम)—१०४२

—, (द्वितीय)—१०४३

—, वार्शिंगटन—९४८-४९,

११५४, ११८२, ११८४, १३०८

कांस्टेन्टाइन—९६, १३०, १३६-३८,

१५७, १६३, २०१, २०४, ८३५,

कांस्टेण्टिनोपुल—१३०, १३६, (देखो

कुस्तुन्तुनिया)

कांस्टेन्स—३३०

काउ-मिंग-तांग—६६६, ६६८, ९४३,

९५०, ९८२, ११७२, ११७६-७९,

—का प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन—९५०

काओत्सु—१६९, २४२

काकातोमी नो कामातोरी—१७७

काकेशस—८३५-३६, ८५०

कागन—३०९-१०, ३१५

काठियावाड़—५८, १२०, १२२, १५५

कानपुर—४४, ८६ १७८, ५९०, ६१८

—का दंगा—८६

कानून, आयर्लैण्ड का होमरूल—८३२,

९८७

—, इंग्लैण्ड का शराबवन्दी—१३१२

—, और व्यवस्था—७६०

—, कारखानों का (भारतीय)—

८८७

—, किलकैनी का—८१८

—, केनेडियन—९५४

—, चीन का शांतिरक्षा—११८३

—, नमक का—१०४७

—, प्रेस का—६३२

—, पंजाब का फौजी—९८२, ११०८

—, पुराना इस्लामी—१००९, ८६१,

८६८

—, फैक्टरी—१०३४

—, ,, (भारत) का—९५१

—, मजदूरों के मुआवजे का—१०३५

—, समाजवाद विरोधी—७३०

—, सम्मिलन—७६०

—, सुधार—७६१

- कला, तंगों की—२४४
 —, दक्षिणी संगों की—२५२-५३
 —, लिखने की—१७४
 —, पुरानी चीन की—१६८
 —, ,, भारतीय—१२१
 —, पेकिंग की—६५९
 —, पेरू की—२६७
 —, फारस की—६९६, ७००, ७०२-०३
 —, ,, की सासानी—६९७
 —, फीयेस—२६९-७०
 —, विजैण्टियन—२९३
 —, भारतीय—१२५, १४८, १५०,
 ४६२, ६९५
 —, भारतीय आर्य—१५५
 —, ,, ईरानी—६९५
 —, ,, मुसलिम—६९५
 —, मलेशिया की—१५२
 —, माया—१५२
 —, मौय्यों की—६९७
 —, रिनैसाँ-युग की—४०९
 —, रूसी—८६५
 —, संबंधी, तंगों की परिपाटी—२४४
 —, सासानी—६९८
 —, सिंध घाटी की—२६९
 —, हिंदुस्तानी—१०८, १५२, १६७-
 ६८, २०१, ३०४
 —, हिंदू—३००
 —, मुस्लिम—३००
 कलिंग देश—९७, ९८, १५१
 'कल्चर सिस्टम'—६७२
 कल्हण—३९, १५८
 कवाद—२१०
 कश्मीर—३३, ३९, १२३, १२५-२६,
 १५८, १८१, २२६-२७, ३५२,
 ३६६, ४४०, ४४६, ५८४-८५,
 ६४६, ११९०
 कांग-ही—४६६-६८, ४८१
 कांगो—८७७
 —, बेलजियन—८४१
 कांग्रेस, अखिल रूसी सोवियट—९२०,
 ९२४-२५, ९३०
 —, अरब—१०८८
 —, ,, स्त्रियों की—१०६७
 —, आल इंडिया ट्रेड यूनियन (या-
 मजदूर संघ)—१०१५, १०३५
 —, औपनिवेशिक, अमेरिका की—५०८
 —, इंग्लैण्ड की ट्रेड यूनियन—११३५
 —, इंडियन नेशनल (भारतीय राष्ट्रीय-
 महासभा)—३९, ४९४, ५०८,
 ५७२, ६३०-३२ ८८८, ९५९-६१,
 ९८२, १०१९-२१, १०२३-२५,
 १०२७, १०२९-३२, १०३७-४५,
 १०४८-४९, ११०४, १२५९, १२९८
 —, का अमृतसर अधिवेशन—१०१९
 —, का अहमदाबाद ,, —१०२४
 —, का कलकत्ता ,, —९५९२
 —, का कलकत्ता विशेष अधिवेशन—
 १०२०, १०३८, १०४०
 —, का ध्येय 'पूर्ण स्वतंत्रता'—९८२
 —, का नागपुर अधिवेशन—१०२०
 —, का मदरास ,, —१०३७-३८
 —, का लखनऊ ,, —९५९-६०

किस्से—४७, ४८, १७३
 किनकाकूजी—३८७
 किपलिंग रुडयार्ड—७९९
 कियाचू—६५५
 कियानचन—९००, ९४३, ९४६, ४७३
 किसान, सभा—१०३२
 —, हिंदुस्तान के—५९९-६११
 'किसानों की छुट्टी'—१२४३
 कीट्स—७३४, ७३६, ८६५
 कीफ़—२९६, ३११-१२, ३१५
 कील—९०७, १११८-१९
 कुतुब मीनार—१५५, ३०४
 कुम्भ मेला—१८७
 कुतल अमारा—१०१९
 कुतुबुद्दीन—३०४
 कुबलाई खां—३१६, ३१८, ३२१, ३२३-
 २५, ३४८, ३५०, ३७०-७१,
 ३८०, ३८५, ४४५,
 कुमाऊँ—५८४
 कुमारी देवी—१५४, १५७
 कुरान पाक—२७४, ३३३
 कुरुलताई—३०९
 कुर्तुवा—२५४
 —और ग्रेनाडा—२७१
 कुर्दिस्तान—१००७-०८, १०८०, १०९७-
 ९८
 कुलक—११७६, १२०३
 कुस्तुन्तुनिया—१३०, १३३, १३६-४०,
 १४४, १४६, १५७-५८, १६२,
 २०१-०२, २०५, २०७, २१०-
 १६, २१९, २२१-२२, २२९,

२३१-३४, २४१, २५४-५५, २५७-
 ५९, २७७-७८, २८०, २८३, २८९
 २९०, २९४, ३११, ३१८, ३२३,
 ३३७-४०, ३४२, ३४८-५०, ३५३,
 ४०७-९, ४३३, ५६९, ६४४, ६९५,
 ६९७, ७०२-०३, ७८८, ८३६-३७,
 ८४३, ८४६-४९, ८५१, ८६६,
 ८७५, ८९५, ९००, ९६८, ९९३-
 ९५, ९९७, १०६९, १०७१-७२,
 १११५
 कुलपति—२०८
 कूक्लक्स क्लैन—८०७
 कूचा—१८१
 कूफ़ा—२२१
 कूलिज, प्रेसिडेंट—११३०
 कृष्ण—१९, १५९
 —की पूजा—१९०
 कृष्णदेवराय—३६८
 कृष्णा नदी—९७
 केंब्रिज—२९५, ४२१, ७३६, १२२५,
 १३२६
 केंस—५५३
 केंसिंगटन, दक्षिण—७४२
 के—४९६
 केटेलोनिया—१२८९
 केदारनाथ—१८८
 केनिया—१३२७-२९
 केप—८७३
 —ऑफ़ गुडहोप—३२५, ३४३-४५,
 ३६३, ३७६, ३७८
 —कामोरिन—८८

क्रान्तन, स्वीजरलैण्ड का दीवानी—
१००९

—, हथियार रखने का—६३०

—, हिन्दुस्तानी खान—१७३४

कान्यकुब्ज—४४, १७८

काफ़—१२११

—पहाड़—१२००

—प्रान्त—१२१५

काफ़िर—३००

काबा—२०८-०९

काबुल—७५, ८०, १२०, १२३, २१४,

२२६, ३२०, ३६२, ४३२, ४३४-

३५, ४३८, ५८६, ७७३, १११७

—नदी—१८१

कामंस सभा (हाउस), ब्रिटिश—

२८८, ४२१, ४२४, ४२६-२७,

८२५-२७, ८२९-३०, १३१०,

१३२१-२२

कामदेव—६९४

कामिटर्न—९३८, ११९३

कामोडस—१३५

काम्टे आगस्टे—७५१-५२,

कायल—३०२, ३०३, ३२३

कारडोवा (वा)—२२१, २७०-७३,

१२८५

—और ग्रेनाडा—२७९-७६

कारिथ—२७

कारूँ—३५

कार्क—९८६

कार्डिनल—२३६, २८४, ४०४, ४१३

—रिशाल—४१३

कार्थेज—२८, ४९, १०४, १०८, १११-

१३, ११७, २०१

—'भूमध्य सागर की रानी'—११३

कार्नवालिस, लार्ड—६०६-०७

कार्निलफ़—९२४

कार्मोना, जनरल—१२८७

कार्ल—१४०

कार्लाइल—४१४, ४२४, ५०१, ५१४,

५२८

काल कोठरी—४६१

कालरिज—७३६

—मेरी—१३४७

कालविन—४०४, ४०६, ४७७

कालविनिस्ट (लोग) ४४२

कॉलिंस माइकेल—९८६, ९८८

कालिदास—१५५, ३५९, ६९७

कालीकट—३४३, ३६३

कालेज, ट्रिनिटी—७३६

कावूर—४२०, ७२१, ७२२

कावेरी, नदी—१८६

—पड्डिन्म्—१८६

काशगर—१२३, ३२१, ९४७, ११९०

काशी—४४, ५२, ५९, १४४

कासग्रेव—९८८, ९९०

काहिरा (काहुरा)—३४९, ५४४, ६९८,

८७३, १०५१, १०५४, १०६१,

१०७१, १०७३-७४

—की पुलिस १०६१

किंग जॉन—२८८

—जार्ज—११५

किचलू, डॉक्टर—१०१७

- कोलंबिया—१३३२
 ———ब्रिटिश—९५३
 कोलचक, एडमिरल—९३३-३४, ९३९,
 ९४७
 कोलनताई, श्रीमती—१२१६-१७
 कोलोजियम—१३५, २५९
 कोलोन—२३९, २८५, २९३, २९५,
 ९०७, ९६२
 कोशल—४४
 कोहकाफ़—११९७-९८ १२००
 कौंसल्स—९०९-९०
 कौंसिल ऑफ़ टेन—९२४
 ———ऑफ़ फ़ोर—९६४
 ———फ़ैसिस्ट ग्रैण्ड—११६०
 ———लेजिस्लेटिव (अरब की)—१८ ८
 ———, हिंदुस्तान की—१०४१
 कौटिल्य—(देखो चाणक्य)
 क्रौम—(देखो जाति)
 क्यूबा—८१४, १२८५
 क्यूवेक—५०५
 क्योटो (क्योतो)—१७७, २४५-४६, ६५०
 क्रान्ति, अक्टूबर की—९४९
 ———अठारवीं सदी की औद्योगिक (इंग्लै-
 ण्ड की)—४७२, ४८७, ४७९-९१,
 ५०१-०३, ५११, ५१३, ५६४-६५,
 ५९२, ६१३, ६३३, ६५२, ६७०,
 ७४०, ७४६, ७७७, ७८४, ८०३,
 १२३०
 ———, अठारवीं सदी की राजनैतिक
 (अमेरिका की)—४८७, ७१३,
 ७४९
 क्रान्ति, अठारवीं सदी की सामाजिक
 (फ़्रान्स की)—४८७, ५४०, ७१२-
 १५
 ———, अमेरिका की राज्य—५७६,
 ७४९
 ———, अमेरिका की विद्युत—१२३०
 ———, इंग्लैण्ड की प्रथम—४२६, ४५२,
 ४९२, ५१३
 ———, इंग्लैण्ड की राज्य—७१३, ७६२
 ———, ईरान की—७०७
 ———, का विकास—५१३
 ———, की पेरिस में शुरुआत—४७६
 ———, के लक्षण—५१२
 ———, कोरिया की—३८५
 ———, चीन की—६६६
 ———, जर्मन—१२९०-९१
 ———, डच ईस्ट इंडीज की—६७३
 ———, नौजवान तुर्क—१००७
 ———, पेट्रोग्रेड की—९२४
 ———, फ़्रान्स की (फ़्रेंच) राज्य—४१४,
 ४५२, ४८५, ४९२-९३, ५०३,
 ५११-१४, ५१८, ५२३, ५३६,
 ५४०, ५४९, ५६०, ५७६, ७११,
 ७१३, ७१७, ७२७, ७४०, ७४७,
 ७४९-५१, ७६०, ७६८, ८०९,
 ८२२, ८२५, ८८१, ८२, १०१३
 १०८२, ११६५, १२३२
 ———, वोल्शेविक—१११५, ११४९,
 ११५३, ११९७
 ———, वोल्शेविक (नवम्बर की)—
 ९२५ ९४७, ९४९

—टाउन—१०७३, १०७५
 केरल—४०
 केलोंविजियंस—२३३
 केलांग—११५१, १३०५
 —की शांति-संधि—१३३९
 —त्रियांद इकरारनामा—११५१-५२
 ११८५, १२१९, १३०५
 केलिफोर्निया—६४५, ६८१, ८०१, ९५३
 केवेलियर—५०४
 केसमेंट, सर रोजर—९८५
 कैटन—१६९-७०, १९९, ३८२, ३८४,
 ४६७-६८, ४७१, ६३५, ६३६,
 ६४०, ९५०, ११७१-७५, ११७८-
 ७९, ११८६, ११९०
 कैडी—८७
 कैथराइन ऑफ ब्रेगेजा—४५०
 —(द्वितीय)—८५४
 कैथलिक (लोग)—३९२, ४१२, ४४२,
 ४७७
 —रोमन—४२८, ११९३
 कैथै—१०२—
 'कैप पुश'—११२०
 —दल—११२०
 'कैपिटल',—७६९, १२३६
 —सवन—८०९
 कैरो—२२१, १०५१, १०५४
 कैरोलिना—५०६
 कैल्डिया—१२२, ६९१-९२, १०६८
 कैवेलियर (लोग)—५०४
 कैसर—११५, ७२७, ८७४-७५, ८८०
 ८९३-९४, ९६२, ९६९, १२९१-९२

कैसर, आस्ट्रियन—११५
 —जर्मन—११५-५८, ६५९, ७३०-
 ३१
 —तुर्की—११५
 —रूमी—११५
 —रूसी—११५
 कैसर्रे हिंद—११५, ४४९, ५९१, ६१८
 कैसलरे—५५६, ५६०
 कैस्टाइल—२७३-७४, ३४२
 कैस्माइल दैस्मुलिन—५३१ ५३४
 कोचीन—८८
 कोटकमालिया—५१
 कोतो—६३४
 कोतो-इन—६३४
 कोपरनिकस—३९८
 कोमा गाटा मारु—९५४
 कोमिण्टर्न—(देखो कामिण्टर्न)
 कोरिया—४५, ४७-४९, १०७-०८,
 १६८-६९, १७२-७५, २४७, २५३,
 २५८, ३११, ३५०, ३८१, ३८५-
 ८७, ३९०, ४७१, ६५३-५४, ६६०-
 ६४, ९४३-४४, ११८३-८४, ११९७
 —, दक्षिण—१६९
 कोर्टे, हर्नेन—२६६-७, ३०५, ३४६,
 ४१२
 —(स्पेनी पार्लमेण्ट) ६८३, १२८५,
 १२८७-८८
 कोसिका—५४०-४२
 कोलंबो—१९७
 कोलंबस—३४, १०२, २६४, ३४३-४४,
 ३४६, ३९१, ४१२, ८४४

खलीफ़ा, उम्मैयों के—२७१

—बगदाद के—२२५-२६, २३२,
२७१, ३१६

—मिस्र के—२३४

—और खिलाफ़त का खात्मा—३३९

खादी—४९५, १०२०, १०३१

—भंडार—१२४८

खान का नगर—३१८

खानबाबा—४३६

खान बालिक—३१८

खान महान् (बड़ा खान),—१८१, ३०९-
१०, ३१३, ३१५-१६, ३१८, ३२०-
२२, ३२५, ३४८, ३७०

खारकफ़, जनरल—९३३

खारज़म—३११-१३, ७००

खिलाफ़त—२३४, ९८१-८२, १००४,
१००६, १०२०, १०२४, १०२६
१०९४

—कमिटी—१००६, १०२१, १०९४-
९५

—का खात्मा—९८१

—बगदाद की—८३५

खुतन—१२३, १७९, ३२१

‘खुदाई ख़िदमतगार’—१०४४

खुरासान—१८४, २२२, ४०९

खुसरो (द्वितीय)—१५९, २१०

‘खूनी रविवार’—६६२

खेड़ा ज़िला—१०१६

खेदिव—८३६-३८

‘खैवर का दर्रा’—७६

‘खोया हुआ नेता’—१०३९

ग

गंगा—२५, ३७, ४१, ४४, ७६, ८१,
८४, १८३, २९१

गंगू तेली—२२३

गज़नी—२२५-२७, २५४, ३००, ३१३,
४३४

—उत्तर-पश्चिम—२९८

—महमूद—२२३, २२५-२८, २३२,
२३४, २५३, २६०-६१, २७७, २९८
३००, ३०३-०४, ३५२, ६९९

गणेश शंकर विद्यार्थी—८६

गवैल—५१५

गया—५९, ९९, १५६

गवर्नर, अंबोयन का—६७०

—अमेरिकन—६८५

—हिन्दुस्तान का—६००

—जनरल (हिन्दुस्तान का)—५९७

गवालियर—४४, ४५८, ४६३, ५८३

गस्टावस अडोल्फ़स—४१९

गांधार—४१, ८०, १५०-५१, १५८
१८४, ४५८, ६९४

—उत्तर पश्चिम—१२५

गांधी, महात्मा—६६४, ८८९, १०१३,
१०१६, १०२१-२५, १०३०

‘गांधीजी की जय’—१०२९

गाडफ़े—२७९

गाज़ीपाशा—१००८

गायकवाड़—४५८

गायना (त्रिटिश)—८८७, १३२७

गाल—११४, ११७, १३७, २०२

गिजेह—२२

क्रान्ति, यांत्रिक—५६८
 —, योरप की (१८४८ की)—७१०,
 ७१८
 —, योरप में आर्थिक—३९२-९३, ४०७
 —, रूसी (१९०५ की) ६६२, ७०७,
 ८५८-६५, ११९४
 —, रूसी (१९१७ की)—३५०,
 ५१४, ५३६, ६६२, ९०५-०६,
 ९०९, ९१३, ९१७-१८, ९२०,
 ९२५, ९६२, ९६६-६७, १०३५,
 १२०२, १२५८
 —, रूसी (पहली)—१२८६
 —, रोम में (धार्मिक और आर्थिक)—
 ३९२
 —, सोवियट—९४७, १११८
 —, स्पेन की—१२८५-९०
 —, स्याम की शांतिपूर्ण—६७६, १११३
 —, हंगरी की—११२१
 क्राइलेंको—९२८
 क्राकाऊ—३१५
 क्रामवेल, ओलिवर—४२४-२६, ४२८,
 ८१९-२०
 क्रॉस—२५८, २७७
 क्रीट—२१
 क्रीमिया—८४६, ८५३, ९३२
 क्रीसस—३५
 क्रुप्सकाया, श्रीमती—१२९७
 क्रूगर इवर—१२६९
 क्रूसेड—२५८, २७७-८२, २९०, २९८,
 ३११, ३१८, ३२६, ३३०, ३३४,
 ८३५, ८४४, १०६९

क्रूसेड का जमाना—२७९, २९०
 —की फ़ौज—२७९
 —के समय का योरप—२८३-९०
 —, वच्चों का—२८०
 क्रूसेडर—२८१-८२
 —, लैटिन—३३७-३८
 क्रेकोविया (जहाज)—८३, ८५, ८७
 क्रेडिट एनस्टालट—१२७०
 क्रोपाटकिन, पीटर—७६६, ७७४
 क्रोमर, लॉर्ड—८३९
 क्रोशिया—११४३
 क्लाइव—४५९, ४६१, ४६३-६४, ५०२,
 ५९४, ७९४
 क्लियोपेट्रा—११६, ८३५
 क्लेमेंशो—९६४-६५
 क्लोविस—२२९
 क्वांगटंग—११७९
 क्वेकर—५०४, ८९३
 क्वे द ओज—८५१
 क्षत्रिय (लोग)—४२, १००, १५३,
 १९३, ६४८
 —सरदार—१५६

ख

खलीफ़ा—२१५, २१७-१८, २२१-२२
 २३१, २३४, २५४, २७१, २७७,
 ३१७-१८, ३३९, ६९८-९९, ८५०,
 ९९८, १००५-०७, १०९४-९५
 —अब्बासी (वग़दाद के)—२१८-१९,
 २२१, २३२, २३४, २५४, २७१,
 २७७
 —अरब के—६९८

- गैलिली—१२६
 गैलीलियो—३९८, ७३८
 गोएबेल्स, डॉ० जोजोफ़—१२९७
 गोखले, गोपालकृष्ण—६२०, ६३२, ९६०
 गोगल—८६५
 गोरखपुर—१०२४
 गोरिंग, हरमन—१२९७
 'गोरे अमीर'—७०१
 'गोरों का भार'—७९९, ८७४
 गोर्की, मैग्ज़िम—८६५, ९३६, ९४१
 गोलकुण्डा—३५९, ३६४-६५, ४४८
 गोलगोथा—१२८
 गोलमेज़ परिषद् (कांफ़ेस)—६६१, १०४९
 गोलडन हिन्द—३७८
 'गोल्ड स्टैण्डर्ड'—११३१-३२
 गोवा—३४४, ३६४-६५, ३७८, ४५०,
 ६१५, १२८५
 गोस्पेल—१२६
 गौड़ का सूबा—३५१
 गौरी शंकर—२०४
 ग्रथसाहब—४५५
 ग्रहण, चन्द्र—२६५
 —, सूर्य—२६५
 ग्राउजे—एम०—१८१
 —, रैने—६९०, ६९५, ७०४
 ग्राम-पंचायत—४२, १५९, १६५, ६००
 —————पुरानी—७६१
 —————प्रणाली—३०२
 —————हिन्दुस्तान की—४२, १९०
 १९२, १९४, २२८, ३०२, ३५६,
 ६००, ६०५
 ग्राम-प्रजातंत्र—१६५, १९२, ३०२
 —————भारत के प्राचीन—४९
 ग्रामप्रणाली, आयों की—४१
 —————द्राविड़ों की—४२
 ग्राम प्रथा, पुरानी—६०२, ६०३
 —————संघ—९१
 —————आर्य—१२१
 —————द्रविड़—४९
 —————संस्था—१६५, ६००
 —————सीमाप्रांत के—५३९
 ग्रामीण-पाठशालायें (हिन्दुस्तान की) ६२१
 —————स्वराज्य—१९२
 ग्रीफ़िथ्स—९८६, ९८८
 ग्रीनलैण्ड—३४६
 ग्रीस—१४९, १६२ १०७९ (देखो यूनान)
 ग्रेगोरी, (सप्तम)—२८४
 ग्रेट ब्रिटेन—९४८, ९६४
 ग्रैनाडा (राज्य)—२७३-७४, ३१७
 ३४२, ४०७, १२८५
 ग्रैन्स, जनरल—९३३
 ग्रैंड आर्मी—५५१-५२
 —————ड्यूक—३१२, ३५०
 ग्लेडियेटर—११४, १२९, १३४
 ग्लैंडस्टन—७९१, ८२७, ८५०
 ग्रीटिज़, ह्यूगो—१३४४
 घ
 घरेलू उद्योगों का विकास—४९८, ६१३
 घूँसेवाज—(देखो वाक्सर्स)
 घेंट—२९५, ४१५
 घेटो—१०८६
 घोष, अरविन्द—३९६

गिडीज़, सर आँकलैण्ड—१२४६
 गिवन—१३३, १३५, ४८१
 गिरजा (जे), गॉथिक—२९३-९४, १३४७-४८
 —नात्रदेम का—२९३, ५३३
 —विजेंटाइन का—२०५
 —सेंट पीटर के—३९६
 —सेंट पैट्रिक का—८२१
 —सेंट सोफिया के—३३८
 गिरौदें—५२०, ५३०
 गिल्ड हाल—२३९
 गिल्बर्ट—६२०
 'गीतांजलि'—१३५०
 'गीतारहस्य'—६३२
 गुजरात—१४९, १५५, ३०६, ३६२-
 ६३, ४४०, ४५७, १०१६, १०३८
 —, दक्षिण—४४७
 गुरु—४५५
 —अर्जुनसिंह—४५५
 —का वाग—१०२९
 —गोविंदसिंह—२५८, ४५५
 —तेग बहादुर—४५५
 —नानक—३५८, ४३८, ४५५
 —हरगोविंदसिंह—४५५
 गुरुदत्तसिंह, बाबा—९५३
 गुलवर्गा—३६१, ३६४, ३६६
 गुलाबसिंह, (कश्मीर का राजा)—५८६
 गुलाम, स्पेन के—७३४
 —तुर्क—८३५
 —यूनानी—१३४
 गुलामों का व्यापार—१३४, २८१, ४५०,
 ४८८, ५०५, ८०२-०४

'गुलामों का किनारा'—८०२
 —का गदर (रोम में)—२०३
 —की मण्डी—१३५
 —की मुक्ति की घोषणा—८०६
 'गुलिवर्स ट्रेवल्स'—४२८, ४८१, ८२१
 गुलिस्तां—७००
 गृहयुद्ध, अमेरिका का—८००-८०९,
 ११९५, १३१५
 —इंग्लैण्ड में—१२६८
 —उत्तर और दक्षिण चीन में तूशनों
 के—९४३, ९५०
 —चीन में—११७८
 —तुर्की में—९९८-९९
 —तूशनों के—११८५
 —मंगोलिया में—९४७
 —रूस के—११९५, ११९८, १२४१
 —रूस में—९२७-२८, ९३२, ९३५-
 ३७, ९३९
 —आयरलैण्ड—९८४, ९८८
 गेथसीमेन—१२८
 गेटे—७३१-३३, ७३७
 गेलीपोली—९००
 गैरीजन, विलियम लाइड—८०४
 गैरीवाल्डी—२८२, ७२०-२२, ७२५
 '—और इटली निर्माण'—७२२
 '—और उसके हजार सिपाही'—७२२
 '—रोमन प्रजातन्त्र के लिए युद्ध'—
 ७२२
 गैलिक आन्दोलन—८२९
 —युद्ध—११७
 —लीग—८२८

चार्ल्स (पंचम)—४०३, ४०८-०९,
 ४१२-१३, ४१५
 —नेपियर, सर ५८७
 —महान्—१४०
 —मार्टल—२१४, २२३, २२९, २३२
 २५४, २७१
 —मेटकाफ़—६००
 चार्वाक—१८९
 चासर—२९६, ३९९
 चाल्से—२९३
 चित्तीङ्ग—६७, २२८, ३०६, ३६३, ४३५
 ४४०
 —के राणा—३६३
 चिन (लोग)—१०५
 चिली—(देखो चाइल)
 चीता (संवत्)—३०९
 चीन—१, १३, १९, २०, २२, २४, २९,
 ३४, ४५-४७, ४९, ५०, ५७, ५८,
 ६०, ७६, ७७, ८२, ९३, ९४, ९६,
 १००, १०२-०३, १०५-०८, ११३,
 ११७-१८, १२१, १२३, १२५-२६,
 १३२, १३५, १४२, १४५, १५२-
 ५३, १५६, १५९, १६१-७७, १८०-
 ८३, १९५, १९९, २००, २०३,
 २०५, २०७, २११, २१९-२१,
 २२३, २३८, २४०-४३, २४५,
 २४७-४८, २५२-५३, २५८-६२,
 २६४, २९४, ३०१-०२, ३०७-०९,
 ३१५-१८, ३२१, ३२३-२५, ३३४,
 ३४१-४२, ३४४, ३५०, ३५२,
 ३७०, ३७२, ३७४, ३७६, ३८०-

८३, ३८५-८७, ३९०-९१, ३९४,
 ९५, ४०२, ४०९, ४२९-३२, ४४५,
 ४६५-७१, ४७३, ७४, ४८१, ५६३-
 ६४, ५६७, ५८०, ५८४-८५, ५९४,
 ६१३, ६३३-४१, ६४४-४७, ६४९-
 ५०, ६५२-५८, ६६०-६५, ६७४,
 ६८०, ६८१, ६८६-८८, ६९८, ७००,
 ७०१, ७०४, ७१४, ७९२, ७९९,
 ८१६, ८९५, ९००-०१, ९०७, ९३८,
 ९४२-४९, ९५३, ९५८, ९८१-८३,
 १०७०-७१, ११०९, १११३-१४,
 ११३०, ११४५, ११४८, ११४९,
 ११७१-७५, ११७७-८१, ११८३-
 ८६, ११८८-९१, ११९४, १२१९,
 १२८३-८४, १३०६, १३०९, १३२०,
 १३२९, १३३९
 चीन उत्तर—२४४, ३०८-०९, ३११,
 ३८३
 —का एक बड़ा मंचू राजा—४६४-
 ७०
 —की क्रान्ति और प्रति-क्रान्ति—
 ११७१, ११८०
 —की बड़ी दीवार—१०७, २४१,
 ३२५, ३८०
 —की बड़ी राज्यसभा—४६८
 —की शासनप्रणाली—२४५
 —की सामाजिक प्रणाली—१६६
 —के सरदार—१०५
 —दक्षिण—१६९, १९७, २४४,
 ३१५, ३२३, ३२५, ६६७-६८,
 ११७१

च-छ

चंगेज खां—२२२, ३०५, ३०८, ३१५,
३२०, ३५०, ३५२-५३, ३६२,
३७१, ४१६, ४३२, ४६९, ५४२,
६८८, ६९९, ७००-०१, ७४३,
८५३, १०६९, १२१८

—का वंश—३२०, ३५१, ३६२,
४३२

चन्द्रगुप्त, प्रथम—१५७

—द्वितीय (विक्रमादित्य)—१५५-५७

—महान्—७९, १४८, १५३-५४,
१५७

—मौर्य—७८, ८०, ८२, ८३, ९६,
९७, १०३, १४९, १५३, १९०

—और कौटिलीय अर्थशास्त्र—
७८-८२

चंद्रनगर—४५९-६०

चंद्रवंशी राजघराने—४८

चम्पा—१९५

चंपारन—१०१६

चटगांव—११४०, १३२६

चटर्जी, बंकिमचन्द्र—६२७

चनक—१००१

चरखा—२६, ४९५, ५९८, १०२०

चर्च—२७७, २९०, २९६, ३२६, ३३६,
३३९, ३४१-४२, ३९२, ३९८,
४०१, ४०३-०४, ४०७, ४३०,
४७७, ५१९, ५२१-२२

—ऑफ इंग्लैण्ड—४०५, ४२२-२३

—आर्थोडाक्स—१३९-४०, २५७

—, ईसाई—१४०

—, कट्टर यूनानी—३३८, ४०२,
८५२

—के अधिकार—३२६

—के ऊँचे अफसर—३२७

—, कौंसिल—२७७, ३२९-३०

—प्रोटेस्टेंट—८५२

—, यूनानी—१३९

—, रोमन—१४०, १७४, २९०,
३२५, ४०१-०२, ४०४, ४३०, ८५२

—, रोमन कैथलिक—१३९-४०,
२७४, २८०, २९०-९१, ३२६,
३३६, ४०१-०३,

—, लेटिन—१३९

चांग कार्ई शेक—११७४, ११७६-७७,
*११८६-८७

चांडाल—६९३

चाँद (चंद्रलेखा पंडित)—६४

चाँदनी चौक—१०१७

चाँदबीबी—४४०

चाइल—८११, १२४४, १३३१

चाओ मुल्तन—२६५

चाको—१३३२

चाणक्य (कौटिल्य या विष्णुगुप्त)—
७८-८२, ९६, १४९, १९० ८७२

—और चन्द्रगुप्त—८२

चाय का व्यापार—४७१

—की खेती—४७१

चार्ल्स (प्रथम)—४२३-२५, ४५२,
४७५, ४९४, ८१९

—(द्वितीय)—६, १४०, २७६,
४०८, ४२५-२६, ४५०, ४७०

- जयपाल—२२६
जयपुर—४४१
जयमल—४४०
जयवर्मन—१९६
जरथुस्त—१९, ५७, ५८, ९४, २१०
——लोग—१४७, १४८
——वंश—१४६
जरूसलम—१०१५, १०८६-८७
जर्मन, (लोग)—(देखो लोग में)
——कमर्शल कोड—१००९
जर्मनी—२६, ११७, १४६, २२९, २३२-३४, २३६, २५५-५६, २८०, २८४-८७, २९३, २९५, ३१५, ३३६, ३७०, ४०२-०४, ४०६-०८, ४१०, ४१३, ४१९-२०, ४२७, ४५२-५३, ४९७, ५४७, ५४९, ५६१, ५६९-७०, ५७२, ४७८, ५९९, ६४२, ६५४-५५ ६५८, ७०८, ७१७, ७२३-२६, ७२९-३१, ७३३, ७४०, ७४६, ७६२-६३, ७६५, ७६९-७१, ७७३-७४, ७८३-८५, ७८७, ७९५-९७, ७९९, ८००, ८०९, ८३०, ८४१, ८५१, ८५८-५९, ८६४, ८७३-७७, ८८०-८२, ८९२-९६, ८९८, ९००, ९०२-८, ९१०, ९१६-१७, ९२०, ९२६-२७, ९२९, ९३३, ९४३, ९४६-४७, ९५२-५३, ९६३, ९६५, ९६८-६९, ९७१-७२, ९८०, ९८५, ९९३, ९९९, १०७८, १११५-१९, ११२१-२२, ११२४-२९, ११३१-३४, ११३९, ११४३-
- ४४, ११४६-४७, ११४९, ११६२, ११७०, ११८८, ११९३, ११९६, १२०६, १२१९, १२२३, १२३६-३७, १२३९, १२५०-५२, १२५७-५८, १२६२, १२६६-६७, १२७०-७२, १२७४, १२७६-७७, १२८१, १२८३, १२८७, १२९०, १३०४, १३०६-०७, १३१३-१४, १३१७, १३१९-२१, १३२७, १३३६-३९
- जर्मनी, उत्तर—३४६, ७२५-२६, १११८
——का इनफ्लेशन—११२४-२५
——का उत्थान—७२३-३१
——का निःशस्त्रीकरण—९७०
——का व्यापारिक विधान—१००९
——का 'संस्कार'—८७४
——की आर्थिक मुसीबत—११२५
——की प्रतिक्रान्ति—१२८५
——की 'यू' नौकायें—९६२
——की संघशक्ति—५६०
——के व्यापारिक वेड़े—८७४
——दक्षिण—१११८
——नाज़ी—१३०२, १३०७-०८
——में नाज़ियों की जीत—१२९०-०३
——में प्रजातंत्र की घोषणा—९६२
——में प्रजातंत्र की स्थापना—७२६
——में प्रजातंत्र राज्य—७३१
——में मजदूरों का आंदोलन—९८०, १२८७
——में मजदूरों का संगठन—७३०
——संयुक्त—७२७
जम्मू—५८६

चीन, दक्षिण पूर्वी—३१०
 —पर ब्रिटेन का ज्वरदस्ती अफ्रीम
 लादना—६३३-४१
 '—पुनरुद्धार सभा' की स्थापना—
 ६६६
 —पूर्वी—१०४
 —मध्य—६६७
 —ब्रिटिश—५६३
 —मुसीबत का मारा—६४२-४७
 —में चाय पीने का फैशन—१६४
 —में छपाई का इस्तेमाल—१६४
 —में प्रजातंत्र का आगमन—१४४
 —में ,, की स्थापना—६६३-६८
 —में लेखनकला—४७
 —में शांति और समृद्धि का युग—
 ३७९-८५
 चीनी (लोग)—(देखो लोग में)
 —उपन्यास—४७०
 —वरतन—४७०
 —भिक्षु—१६७
 —राष्ट्रवादी—११७५-७६
 —विचार पद्धति—१६८
 —शास्त्र पद्धति—१७७
 चीपंगो—१७८
 चेंगहो—३७५, ३८१
 चेका, (बोलशेविकों की राजनैतिक
 पुलिस)—९३९
 चेखोव—८६५
 चेपेई—११८६-८७
 चेशायर विल्ली—२३०, ४५२, ९८३
 चेस्टरटन, जी० के०—१११४

चेंग सो-लिन—११७७, ११८५
 चैतन्य—३५८
 चैल्लिया—(देखो कैल्लिया)
 चोरी चोरा—१०२४
 चोलापुरम्—१८८
 चोसेन—४७, ४८, १७३-७४, ६६४
 —और दाई निपन—१७२-७८
 'चौथ'—४५६, ४५८
 'छरों का झोंका'—५४३

ज-झ

जकरिया, बेसीलोस—९९६
 जगलुल पाशा, सैद—८४०, १०५३-५५,
 १०५७-५९, १०६१-६३
 —सफिया, श्रीमती—१०६४
 जजिया—३०६, ३५६, ४३८, ४४६,
 ४४८
 जजीरत-उल-अरब—१०१५
 जद्दाह—१०७४, १०९२, १०९४
 जनमेजय—७६
 जबल-अद्-हुज—१०८२
 जबल-उत्-तरीक—२१४, २७१
 जमशेदपुर—८८७
 जमालुद्दीन, अफगानी—८४०, १०५१
 जर्मीदार—१६५-६६, २३४, २३८,
 ४४१, ६०४-०५, ६०७
 —, अंग्रेज—६०६-०७
 जर्मीदारी प्रथा—७८०
 जमुना नदी—१०, ३७, ४४, ५२, १८३,
 ३६१, ४४७
 जमोरा, अलकला (राष्ट्रपति)—१२८७
 जयचंद—२९८

जाति, हंगेरियन—१०७८
 —हूण—१३८, २४१
 —भेद, (जन्म से नहीं कर्म से)—१९१
 जॉन, एडम्स—५१०
 —मैडीसन—५१०
 —हंस—३३०, ४१०
 जानिसार—३३८-३९, ८४४
 जापान—१९, ४५, ४८, ४९, ९३, ९६,
 १०८, १२५, १६८-६९, १७२-७८,
 २४५-४८, २५८, २६२, ३१८,
 ३२४-२५, ३४३-४४, ३८१-८२,
 ३८५-८७, ३८९-९१, ४३१-३२,
 ४५७, ४६८, ५६३, ५६७, ५७०-
 ७१, ५८०, ५९४, ६१४, ६१६,
 ६३०, ६३९, ६४५, ६४७, ६५०-
 ५७, ६६०-६६, ६८५-८६, ६९०,
 ७०७, ७८९, ८६१, ८६४, ८७८,
 ८९५, ९००, ९३२, ९४२-५०,
 ९५३, ९६४, ९७३, ९८२, १०५९,
 ११३३, ११३९, ११४५-४६,
 ११७१, ११७९-८९, ११९१,
 १२१२, १२१९-२०, १२५२-५३,
 १२५६, १२७४, १२८३-८४,
 १३०५-०६, १३०८-०९, १३२९-
 ३०, १३३५, १३३९
 —अपने को वन्द कर लेता है—३८५-९०
 —की अद्भुत उन्नति—६४७-५६
 —की २१ भागें—९४६
 —चीन को दवाता है—९४२-१५०
 —में घरेलू उद्योग—६४८
 —में शोगन शासन—२४५-४८

—रूस को हराता है—६५५-६६३,
 —सारी दुनिया को अंगूठा दिखाता
 है—११८०-९१
 जापानी (लोग)—(देखो लोग में)
 जामा—११३
 जार—३५०, ६६१-६२, ७१०, ७८४,
 ८५१, ८५३-५८, ८६१, ८७६,
 ८८०, ९०५, ९१४-१६, ९६६,
 १०४५, ११६४, ११९३-९४,
 ११९७, ११९९, १२१७
 —की हत्या की कोशिश—८५७
 —के खुफिया अहदनामे—९२७
 —निकोलस—९११-१२
 —रूस के—५१४, ५५०, ५५१,
 ५५९-६०, ७१०, ७८४
 जारविच—९११
 ज़ारीना—५१४, ९११, ९१४
 जार्ज—(प्रथम)—४२७
 —(द्वितीय)—४२७
 —(तृतीय)—४७२-७३, ५०८, ६३४
 —(पंचम)—४२८
 जॉर्जिया—५०६, ११९७, ११९९
 जालियांवाला बाग—५३८, ९८२,
 १०१८, १९
 —का हत्याकांड (कत्लेआम)—९८२,
 १०१८-१९
 जावा—१५०-५२, १९७, १९९, ३२४,
 ३४४, ३७०-७२, ३७४-७५, ३८१,
 ३८३, ५६४, ५६७, ६६९, ६७१-
 ७३, ६८२, ६९४, ८७७, ९८३,
 १०७५, १११३, १३२९

- जलालुद्दीन—३१२
 —रूमी—७००
 जस्टीनियन—२०२, २०५, ३३८
 जहरोफ़, सर वेसिल—९९६, १०००,
 १३०८
 जहांगीर—४४६-४७, ४५५, ७०३
 जातक कथा—६९२,
 जाति— (कौम)
 —अंग्रेज़—१४५, ४२५, ६१२
 —अफ़रीकन—१३२९
 —अरब—२०९, २२५, २७१, १०७९
 —आइनस—१७४
 —आयरिश—८१८
 —आरमीनियन—१०७९
 —आर्य—२६, ४५, १५४, १५७, ७८३६
 —इंडो-एरियन—३८
 —ईरानी—६९८
 —ईसाई—२२२, २७१, ८४४
 —उत्तरी योरप की—२१०
 —उस्मानी तुर्क—२४१
 —एशियाई—३४९
 —ऐंग्लो सैक्सन—८१८
 —किन या सुनहरे तातारी—२४४
 —कुर्द—१००७, १०९७
 —कुशान—१२०
 —क्षत्रिय—१५४
 —खित्तन—२४४
 —गॉथ—१३७, १४३, १६१, २०१-
 ०३, २०५
 —गाल—१०३
 —चीनी—१२१५
 जाति, आर्य जर्मन—१३७, १४०, २०१,
 २०३, २३४, २८७
 —जर्मन-आस्ट्रियन—१०७८
 —जापानी—६४७
 —जैक—११२३
 —ताजिक—१२१५
 —तातारी—१०११, १२१५
 —तुर्क—१२५, १००७, १२१५
 —,, खानाबदोश—१२०
 —पोल—२३३, ११२३
 —फ़्रैंक—१४३, २०२, २२९, २७१
 —फ़्रेंच—२०३
 —वश्कीर—१२१५
 —बालकन—८७८, १०७९
 —बाल्टिक—११२३
 —बुदयत—१२१५
 —ब्रिटिश—७९७, ११४४, १२५७
 —मंगोल—४५, १२३, १७४, २४७,
 ४६९, १२१५
 —मध्यएशिया की खानाबदोश—१२०
 २२८
 —यूनानी—१५५
 —यूरोपियन—२५३, ३९०, ६४३
 —राजपूत—१५८, २२८
 —लिच्छिवी—१५४
 —लैटिन—१३३०
 —शक—१२२, १२५
 —सिक्ख—४५५
 —सीदियन—१२२
 —स्पेनिश—२७५
 —स्लाव—२३२, २८३, ८४६

जेकोविन—५२०, ५२४, ५३०, ५३२-३४
 —कमिटो—५३३
 —दल—५३२, ५३४, ५४२
 जैज, संगीत—८०८
 जैपलिन—९०२, ९०४
 जैफरसन, डेविस—८०५
 जोन्स विल—६८४-८५
 जोजेफ़, फ़्रांसिस—७८५
 जोन ऑफ़ आर्क—३३५-३६
 जोनाथन स्विफ़्ट—४२८-२९
 जोर्डन नदी—१०८९
 जोर्डानो ब्रूनो—३९८, ७३८
 जोसरिजल, डॉ—६८३-८४
 जोसेफ़ाइन—५५०
 जौनपुर—३५९, ३६१, ३६२
 जौहर—३०६, ४४०
 —हिंदू-मुसलमानों का—३५१
 ज्योतिष विज्ञान—२६५
 झरिया—५३९
 झांसी—५९१

ट-ठ

टर्की—(देखो तुर्किस्तान)
 टॉकिंग—३१८, ३५०
 टांगानिका—९६५
 टाइग्रिस—२०७, ३१७, १०९७
 टाइवर नदी—२८, १०८, ३२६
 टाइवेरियस—१२८
 'टाइम्स' अख़बार—८३७, ९००, ११०३,
 ११८६
 टाउनशेण्ड, जनरल—१०९९
 टॉनी आर० एच०—७९८, १०४९

'टॉम काक की कुटिया'—८०८
 टॉमस, जैफ़रसन—५१०
 —पेन—५१०, ७५०
 '—रो, सर—४५०
 —स्टैफ़र्ड रैफ़ल्स—६७१
 टाराइड, राजमहल—९१५
 टालमी—७७, ९५-९७, १०३, ८३५
 टाल्स्टाय, लियो—८६५,
 टिरोल (टाइरोल)—११२१, ११२३,
 टीटानिक—५६६
 टीपू सुलतान—५४५, ५६३, ५८२-८३
 टूरिन—७२१
 टूलोज़ नगर—३२७
 टेनिस कोर्ट की शपथ—५१६
 टेनीसन, लार्ड—७८३
 टेनोचिलटलन—२६५-६७
 टेम्स नदी—४२६, ४९५
 टेरिफ़ बोर्ड (हिंदुस्तान में)—१०३३
 टेलिस मेन—२८०
 टेलीविजन—१२३५
 टेस्टामेण्ट (ओल्ड)—१०८५-८६
 टैजियर—१०७०
 टैग्नी हाल—८५९
 टोकियो—१७७, ३८७, ६५०, ११८२
 टोडरमल, राजा—४४१, ६०५
 टोरी—७९०
 टचूडर—४१२-१३, ४२१-२२
 ट्रस्टीशिप का सिद्धांत—४७७
 ट्रांस एक्विनयाना—७००-०३
 —जोर्डन—९८१, १०८५-९२,
 १०९४, १०९८, ११०४

- जावा, पश्चिमी—१९९
 —पूर्वी—१९९, २५३, ३७०
 जिगो—१७४-७५
 जिगोवाद—१७५
 जिनकाकूजी—३८७
 जिनेवा—२७८, २९५, ३२३-२४, ३४३,
 ४०४, ४७९, १०७२, ११०३,
 ११०६, १११३, ११४७, ११५०,
 १२५२, १३०५, १३०९
 जिनोविया—१४७
 जिनोवीर—११४७-४८, ११९१
 जिब्राइल, फ़रिस्ता—२९२
 जिब्राल्टर—२७, १९७, २१४, २५४,
 २७१
 जिम्बू-टिन्नु—४८
 जियोन—१०८७
 जियोनिज्म—१०८७-८८
 जिहाद—१५३-५४, २५८, ९९८
 —ईसाई कौमों के—२२२
 जीन-द-आर्क—५, ६
 जीन्स, सर जेम्स—१२२५
 जूज—९५
 जूपिटर—१०३
 जूलियन—२०४
 'जूलियस सीज़र' (नाटक)—११५
 जू-सी, राजमाता—६४७
 जेंटाइल जियोवानी—११६८-६९
 जेंदावस्ता—१९
 जेकिल, डॉ०—६७७
 —और मि० हाइड—६७७
 जेकेरी—(फ़्रांस का किसान बलवा)—३३५
- जेकोस्लोवाकिया—३२९-३०, ८६६,
 ९३०, ९३२, ९६६, ११४४, १३०१
 १३०६, १३३६-३८
 जेदो—६५०
 जेम्स (प्रथम)—४२३, ४२८, ४५०,
 ४९४, ५०४, ८१९
 —(द्वितीय)—२२६, ४५२, ४७५
 —वांट—४९६
 जेरक्सीज़—६५, ६६, ६८, ७५, ६९६,
 १०६९
 जेरुसलम—१२६, २१२, २१७, २२२,
 २५७-५८, २७७, २७९, २८१
 जेल, देहरादून—२४९, २७०, २९७,
 ६९१, ९८४, ९९२
 —नैनी—३, ९, १०, १४, ३७, ६३
 ८३-८५, ८७, ९६, १०४, १४९,
 ६७८
 —पेरिस की—७५०
 —बरेली ज़िला—२००, २४८-४९
 ६७८
 —ब्रिटिश—९८६
 —मलाका (मलक्का)—१४, २०-२१
 —मांडले—६३२
 —यरवड़ा—११, ९९२, १०३०,
 १३२६
 —लखनऊ ज़िला—२०, ८४, १३३
 १००३
 —हिंदुस्तानी—१०४३
 जेसुइट—३८८, ४०२, ४३७, ४३९-४०,
 ४४३, ४४५-४६, १२८८
 जेहोल, प्रांत—११८८

डैनियल ओ'कोनेल—८२३

डैन्यूव नदी—२०२, ९६७

—प्रदेश—१२६९

डोमिनिकन—४०२

—आर्डर—४०२

डोलअम्मा—१३१

ड्यूक ऑफ अलवा—४१५-१६, ४१८

—वर्गण्डी—६

ड्रेक, सर फ्रांसिस—३७८, ४२२

ड्रेगा महारानी—८७८

ढाका—५९४

त

तजौर—१८७

तक्षशिला—७६, ७८, ७९, ९९, १२१,

१२३, १५०, २२०, २२४, ३५८

तख्त ताऊस—७०५

तरीक—२१४, २७१

तलाअत बेग—९९३

ताई-नी-पुंग-कोक—१७७

ताई-त्सांग—२११

ताओ-चिंग—१५६

ताजकिस्तान—११९९, १२००, १२१७-

१८, १२२१, १३२९

ताजमहल—३६५, ४४७, ६९५-९६, ७०३

ताता आयरन एण्ड स्टील कम्पनी—८८७,

९५५

—जमशेदजी नसरवानजी—८८७

—नगर—८८७

तानसेन—४४१

तानाशाही, फैसिल्टों की—११६४-६५

—, साम्यवादियों की—११६४-६५

तानाशाही, सेना की—११६४-६५

तामिल देश—१५१, ३०१

—नाड—३९

तायरा—२४६

तारिन नदी—३२२

तालिवशाह, सैयद—११००

ताली कोटा—३६४

तिब्बत—१९, ९६, १२५-२६, ३१८-१९,

३५०, ३९०, ४७१, ५८४, ११३३,

११९०, १२३८

तिमोचिन—३०९ (देखो चंगेज खां)

तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर—६३१-

३२, ८८८, ९५९, १०१९-२१

—सेनापति—३००

तुकाराम—४५६

तुगलक (पागल)—३५८

तुगलकाबाद—५२, ३०८

तुरफान—१८०-८१, ६४६

तुर्क (लोग)—(दे० लोग में)

तुर्कमीनिस्तान—११९९, १२००, १२१५

तुर्किस्तान (टर्की)—१०३, १३८, १७१,

२०५, ४०९, ४७१, ५४४, ५६०-

६१, ५६६, ५६९, ६८९, ६९१,

६९९, ७०८, ७३६, ७८८, ८३८-

३९, ८४१-५२, ८५७, ८७५,

८७८, ८९०-९१, ८९५, ९००,

९३८, ९५१-५२, ९६१, ९६५,

९६७, ९७१-७२, ९८०-८३, ९९२-

९३, ९९५, १०१३, १०१५, १०५२,

१०५८-५९, १०६८, १०७२-७३,

१०७७, १०७९, १०८१, १०९४,

ट्रांसवाल—८००

ट्राटस्की—८६०-६१, ९२१, ९२३-२६,
९२९, ९३२, ९३५-३६, १२०१-०३,
१२२०, १३४२

ट्राय—२७, ६६, २०२, १३४७

ट्रावनकोर—८८, ३६८

ट्रिनीडाड—८८७

ट्रिपोली—८४९

ट्रिमटी—११६१

ट्रूस—१०४३

ट्रेड यूनियन—५७५, ७६०, ८६९, १०१५,
१०३५

ट्रेफल्गर—८७५

——अंतरीप—५४८

——स्क्वेयर—५४८

ट्रेवीलीयन, जी० एम०—७२२

——, जी० डबल्यू०—२८१-८२

ठाकुर, महर्षि देवेन्द्रनाथ—६२३

——रविन्द्रनाथ, डॉ०—६२३, ७३५,
८८९, १३५०

ड-ढ

डगलस, मेजर—१२५२

डच (लोग) — (देखो लोग में)

डबलिन—८१७, ८२०-२२, ९५०, ९८६

डर्सी—७०६

डार्जनिंग स्ट्रीट—८५१

डॉज़ योजना—११२६

डॉज़े—२९५

‘डॉन क्विक्सॉट’—४००, १३४५

डायज़—८४४

डायर, जनरल—१०१९

डायरेक्टरी सरकार—५३५, ५४२, ५४५

डार्विन—५७८, ७३८, ७७९, ७९८,
८६७

——और विज्ञान की विजय—७३८-४६

डालफ़स, चांसलर—१३०१

डिकेंस—७३७

‘डिक्लाइन एण्ड फॉल ऑफ़ रोमन एम्पायर’
——४८१

डिलायजी फ्रांसिस—१२६०

डि वेलरा—९८६, ९८८, ९९०-९२,
१३३४

डिसरेली बेंजामिन—७९१, ८३८, ८४७,
१३४४

‘डिसेम्बरिस्ट’—८५५

डिस्पेन्सेशन—२९०

डीक—७१७

डीयर पार्क—५९

डुप्ले—४५९

डूमा—८६१-६३, ९१५, ९१७-१८

डेंटन—१२२४

डेन कैन्यूट—२१५

डेनमार्क—४७३, ७२५, ७७३, ७८४,
८७१, ८७७, १२६३, १३३५

डेनियल डिफो—४२९

डेरियस—१९, ३६, ६४, ६९६, १०६९

डेरी शहर—८१९

डेल आयरीन—९८६, ९८८, ९९०

डेलोस टापू—१३५

डेस्कॉर्ट—४००

डैनजिग—२९५, ९६६, ११२३, १३००

——की नगरसभा—४९७

- दरबार, चीन का—४६९-७०
 —जापानी सम्राट का—३९०
 —दिल्ली—४४९, १०५०
 —फ्रांसीसी—८५४
 —मुगल—४०९, ४५०, ७०२
 दरिद्रनारायण—६२४
 दर्रे दानियाल—३४, ६६
 दर्शनशास्त्र—१८२
 दशमलव की प्रणाली—१९४
 दल, अनुदार (ब्रिटिश कंज़र्वेटिव)—
 ७६४, ७९०-९१, ८२६-२७, ८३०
 १०२२-२३, १२४७, १२५८,
 १२७१-७२, १२९२
 —अपरिवर्त्तनवादी—१०२५
 —आयरिश राष्ट्रीय—८२८
 —उदार (ब्रिटिश लिबरल)—७६३-
 ६४, ७७२, ७७६, ७९०-९१ ७९५,
 ८००, ८२६-२७, ८३०, १३२२
 —कंज़र्वेटिव—८२६
 —कांग्रेसी—१०३१
 —काउन्सिल-तांग (जनता का दल)
 ९५०, ११७६-७७, ११८९
 —काला हाथ (हत्यारा)—८७८-७९
 —कैथलिक सेंट्रर (मध्य) १२९४,
 १२९७
 —क्रांतिकारी—७७६
 —चीन का साम्यवादी—११७१
 —जगलुल—१०६३
 —जर्मनी का समाजवादी लोक-
 सत्तात्मक—७७३, १३१९
 —जर्मनी का साम्यवादी—१२९९
 दल, जेकोबिन—५२०, ५२४
 —ट्राटस्की का—१२०३
 —डेमोक्रेटिक (अमेरिका के) ८१५
 —नाजी—१२९७, १३०२
 —नौजवान तुर्की—८४८
 —परिवर्त्तनवादी—१०२५
 —फैसिस्ट—११५६-५७
 —मजदूर (ब्रिटिश लेबर) ७६३,
 ७७३-७४, ७७६, १०४९, ११४७,
 १२७२ १२९४, १३१९, १३२३-२४
 —रिपब्लिकन (अमेरिका के)—
 ८१५
 —लालकुर्ती—१०४४
 —लिबरल—८२६
 —लोकशाही—१३१३
 —वतनी (मित्र का)—१०५४
 —वपद—१०५७, १०६२, १०६४-६६
 —श्रमजीवी—७७२
 —समाजवादी प्रजासत्तात्मक मजदूर—
 ८५७
 —समाजवादी लोकसत्तात्मक—७३०
 —सम्राट का विरोधी—७९०
 —साम्यवादी—९३८, १२०१-०२,
 १२०७
 —सिनफेन—९८८
 —स्पेन का समाजवादी—१२८७
 —स्वराज—१०२५, १०३१
 —हिन्दुस्तानी मुस्लिम पूंजीपति—
 १०९६
 —हिटलर का 'नैशनल सोशलिस्ट'—
 ११२५

१०९६-९९, ११०१-०२, ११०९-
 १०, ११४७, ११४९, ११५१,
 ११५३, ११५५, ११६४, ११९१,
 ११९६, १२०३, १२२०
 तुर्की (टर्की : नवीज) का उत्थान—
 ९९२-०३
 —की महान राष्ट्रीय सभा—९९८
 १००४-७
 '—खुदा का क्रहर'—६८९, ८४२,
 —, चीनी—११९०, १२१७
 —टोपी—१००९
 —योरपका मरीज—६८९, ८४२-५१
 तुर्गनेव—८६५
 तुलसीदास—४४४
 तूताखामन—६९२
 तूशन—९४३-४४, ९८२, ११७१, ११७४
 —, उत्तरी—९५०, ११७१, ११७३
 —, महा—९५०
 तेलगू—३०२
 तैमूर—३०५, ३५१-५३, ३५५, ३६१-
 ६२, ४१६, ४३२, ४६८, ५९१,
 ६८८, ७०१, ८४३
 —का वंश—३६२, ४३२, ४६९
 तैमूरिया (लोग)—४६९, ७०१-०२
 तैली रैंद—५५१-५२, ५६०
 तोकूगावा आयेयासू—३८७
 तोरमान—१५८
 तोलों—५४२
 त्यूलरीज—५१८
 त्रिपोली प्रदेश—११५३
 त्रिमूर्ति—१३०, २३६

त्रियमवीर—७२०

त्रिवेणी—३७

थ

थर्मापली—६७-६९

थानेश्वर—२२६

थियोडोरिक—२०२

थियोडोसियस—२०४, २१३

थीक्स—२७, ७४

थैंकरे, विलियम—४६२, ७३७

थोरो—७६४

थ्रोस—१००२

द

दंगे (गा) अरवों और यहूदियों के—
 १०८८

—कानपुर का—८६

दज्जला नदी—२०७, ३१७, ६९९, १०९७

दत्त, बटुकेश्वर—१०४०

—रमेशचंद्र—५९३-९४

दमिश्क—२०७, २१६-१७, २१९, ५४४
 ६९८, ७०१, १०६७, १०८०,
 १०८३

दयानंद, स्वामी—६२४

दरबार, अकबर का—४४१, ४४९, ४८९

—अफगानी—११०८

—अरब के खलीफों का—६९८

—इंग्लैंड का शाही—७८९,

—ईरान के बादशाही—२१२

—उस्मानी—१०१२, १०५०

—औरंगजेब का—४५६

—कुस्तुनतुनिया के बादशाही—२१२

—खान महान् का—३३१, ३३६

२५, ६८७-८८, ६९६-९८, ७०१,
 ७०९, ८४०, १००६-०७, १०१०,
 १०५१, १०६६, १०७३, १०७९,
 १०९१-९२, १०९४, १३४७
 धर्म, ईसाई—१९, ६०, १२६, १२९-३१,
 १३८-४०, १६३-६४, १७०, २०४,
 २०६, २१०, २१२, २१४, २२२,
 २२९-३०, २३५, २५४, २७७,
 २८३, २९१, २९८, ३१६, ३२१,
 ३२७, ३३२, ३८३, ३८८, ३८९,
 ४०२, ४६७-६८, ४७९, ५३३,
 ५५६, ५८०, ६१४, ६२३, ६४८,
 ६८३, ६९०, ७४८, ८१७, ८३५,
 १०५९, १०६९, १०७९, १२८८
 —और ईश्वर के नाम पर खूनखराबी
 —९९
 —कनफ्यूशियन—३८२
 —का अर्थ अशोक की दृष्टि में—९९
 —काष्ट—१०६६
 —के नाम पर पाखण्ड और अत्या-
 चार—६०
 —कैथलिक—८१९-२३, १३३२
 —(मजहब) जनता की अफ्रीम है—
 १२७, ७८३
 —जरथुस्त—१४६, ६९६-९८, १०६९
 —जैन—५८
 —जोराष्ट्रियन—१९
 —ताव—३१३
 —पारसी—५८, ६०, १२५, १४६,
 २९१
 —पूर्वी ईसाई—२०५

धर्म, प्रोटेस्टेण्ट—८१८-१९, ८२३
 —, फ्रांस का सभ्यता सिखाने का—८७४
 —बुद्ध (बौद्ध)—६०, ९९, १००,
 १०८, ११८-१९, १२४, १२७,
 १४७, १५१-५२, १५६, १५९,
 १६७-६९, १७४-७६, १७९-८०,
 १८८, १९५, १९७, २२३-२४,
 ३७३, ६४८, ६८७, ७०१, ११८१
 —ब्राह्मण—६०, ११८-१९
 —यहूदी—६०, १०६९
 —युद्ध—१५३
 —ईसाइयों के—२७७-८२, २९०
 '—रक्षक' (अंग्रेजों का राजा)—२३१
 —रोमन कैथलिक—५३३, ८१८
 —वैदिक—५९, ९४, ६९६
 —वैष्णव—१९०, ३५७
 —शिण्टो—१७५-७६, ११८१
 —सिक्ख—६०, ३९८, ९५३-५४
 —हिन्दुस्तान का (हिन्दुस्तानी)—
 १५३, १६८, २०१, २७०
 —हिन्दू—१९, ५८, ६०, ११९, १२४-
 २५, १४७, १५१-५२, १५६, १८८,
 १९०, १९४, २२३, २२५, २७०,
 २९१, ३५६, ४३८, ४५५, ६१४-
 १५, ६२३-२५, ६३१, ८४०, १०५१
 धार्मिक संस्थायें—१९३
 ध्रुव उत्तरी—१८४
 —, दक्षिणी—१८४
 न
 नंद, राजा—७८, ७९
 —वंश—७८

दांडी—१०४१
 —की यात्रा—५०७, १०४१
 दांतन—५२६, ५२९, ५३१-३३
 दांते—३९५, ३९७
 —अलीघेरी—२९६
 दाइम्यो—२४६-४७, ६४८
 —प्रथा ६५०
 दाईनिपन—१७७, २४५
 दाऊद—२९, ४९, १२७
 दाहू (पं० मोतीलाल नेहरू)—११, २१,
 २५, ३२, ६३, ८३, ८५, १०११,
 १०२१, १०३८
 —की मृत्यु—८४
 'दायमी बंदोबस्त'—६०७
 दारा—१९, ३६, ४९, ६४, ६५, ७५,
 ९४, ६९६-९७, १०६९
 दास, देशबन्धु चित्तरंजन—१०२४-२५
 —, जतीन्द्रनाथ—१०४०
 दास्तोवेस्की—८६५
 दिजन—५१५
 दिदरोत (फ्रान्सीसी लेखक)—४८०
 दिहाजी (श्रीमती स्वरूपरानी नेहरू)—
 २९७
 दिल्ली—४०, ५१, ५५, ७३, १५५,
 २९८, ३०४, ३०६-०८, ३१०,
 ३१२, ३५१-५२, ३५५, ३५८,
 ३६१, ३६४-६५, ४०९, ४३२,
 ४३४, ४३९, ४४७, ४४९, ४५५-
 ५८, ४६०, ४६२-६३, ५८७, ५८९-
 ९०, ५९१, ६०६, ६३३, ७०१,
 ७०५, ८४५, १०१२, १०१७,

१०२५, १०३०, १०४०, १०४३-
 ४४, १०५०, १०७१, १०७४,
 ११८०, १२८३
 दिल्ली, नई—५२
 दीनार—२२७
 दीने इलाही—४४३
 दीवानी पट्टे—६०५
 दीवाने आम—४४७
 —खास—४४७
 दुर्गावती, रानी—४४०
 'दूध की हड़ताल'—१२४३
 देवगिरी—३०७, ३५८
 देवी-देवता—१०४
 —प्राचीन मिस्र के—१०४
 —यूनान के—१०४
 —, रोमन, की पूजा—२०४
 —वैदिक—१०४
 देहरादून—२४९, २७०, २९६, ५८४
 दीलताबाद—३०७, ३५८, १०७१
 द्रुज—१०८२-८३
 द्रोणाचार्य—४५
 धर्म, आकाश—७०१
 —आर्य—१९, ४१, ९६६
 —इसलाम—६०, १४०, १४६-
 ४७, १५१-५२, १६९-७०, १८५,
 २००-०१, २०७, २०९-१३, २१५-
 १७, २२२, २२६, २२८, २३४-
 ३५, २५४, २५८, २६१-६२, २७४,
 २७७, २८३, २९१, २९८-३००,
 ३०५-०६, ३३२, ३५५-५८, ३७५,
 ४३८, ४५५, ४५६, ६१४, ६२४-

निहिलिज्म—८५६

नीति, अंग्रेजों की (या ब्रिटिश) ४६२,
४६४, ५९८-६०१, ६०८, ७०५,
७९६, ९५५, ९५७, ९८२, ९८८,
९९१, १०१४-०१५, १०४६, १०६७,
१०७४, १२७२, १३३४

—, अफ़ग़ानिस्तान की परराष्ट्रीय—

११०७

—असहयोग और बहिष्कार की—

१०८८, ११०४

—आर्थिक राष्ट्रवाद की—९७८

—नई आर्थिक—९३७, ११९२, ११९६

—भारत सरकार की—६२३, १२८१

—, मुक्तद्वार (चीन में अमेरिका की)

—६५७

‘नीतिसार’—१९१-९३, २३९, २८५

नीपर—११२३

—का अल्सेस लॉरेन—११२३

नीपुंगकोक—१७८

नीरो—१४४

नील का व्यापार—६०७-०८

—की खेती—६०७-०८, ६७२

—, जनरल—५९०

—, दर्पण—६२७

—नदी—८३३-३४, १०५७

नुआंग्स—१०११

नुवाराईलिया—८७

नूह—७४२

नेटाल—१३२७

नेपल्स—२९५, ४०३, ४०८, ७१९-२०

नेपाल—४७१, ५८४

नेपिंग—६३७

नेपोलियन (बोनापार्ट)—१४१, १५७,

२९५ ५२०, ५३५, ५४०-६४, ५७६,

५८२, ६३३-३४, ६६१, ६७१,

७१०-११ ७१७, ७१९-२०, ७२३,

७२६, ७३२, ७६०, ८०१, ८३६,

८५५, ८७५

—का ज़माना—७२३

—का पतन और उसका कारण—

५४९

—का वसीयतनामा—५५८

—के पतन के समय की दुनिया—

५५९-६४

—कोड—५४६

—(दूसरा)—७१७

—(तीसरा)—७१७, ७२०,

७२५, ७२७, ७८७

—लुई—७३३

नेबूचडनेज़र—२३

नेलसन, होरेशियस—५४४, ५४८

नेवा नदी—४८४, ८५३

नेशनल असेम्बली—५२१-२४, १००५

—कन्वेन्शन—५२५-२६, ५३०-३४

‘ —पेक्ट ’ ९९७-९८, १००२

नेस्टोरियन (लोग)—१७०, ३२४

नेहरू-रिपोर्ट—१०३८

नैज़रथ—१२६

नैनीताल—५८४

नैशापुर—७००

नोटों का चलन—३२४, ३८१

नोवगोरोड—२९४, ३११, ३५०

नज्द प्रदेश—१०९२

नटराज—१८८

नमक—५१५

—कर—५१५

—की लड़ाई—५०७

नमाज और अज़ा—१०१२

नवरत्न—१५५

नसरुल्ला, अमीर—११०८

नहर, पनामा—७८४, ८१४-१५, ८३७,
९००—स्वेज—४४५, ५६७, ५९६, ६८९,
८१४, १०५१, १०६८

नहस पाशा, मुस्तफ़ा—१०६४-६६

नाइटिंगेल, फ्लोरेंस—७८८

नाइन पावर ट्रिटी—९४८

नाउट—८५२

नागपुर—१०२०

नागासाकी—३८९

नाज़ियों का आतंक—१३३६

नाज़ी—११२०, १२९०, १२९३, १२९९,
१३००-०३, १३०७, १३२१, १३२६,
१३३६-३७

—आन्दोलन—१२९८, १३०३, १३१३,

—स्टार्म ट्रुप्स—१२९२

नादिर खाँ—(शाह) ७०५, ११११

—दुर्रानी—४५८, ४६०, ७०५

नानकिंग—३२५, ६६७, ११७६-७९,
११८६, ११९०

नाना फड़नवीस—५८३

—साहव—५९०

नावो पोलासार—२३

नायडू, श्रीमती सरोजिनी—९५९

नारबुनागा—३८७

नारा—१७६-७७, २४५

नार्थमेन—(देखो लोग में : नार्मन)

नार्मण्डी—२३४, २५५-५६

नार्मन, मांटैग्यू—१२४६

नार्वे—८७७, ११४२

नार्समेन—(देखो नार्थमेन)

नायक—(देखो कुलपति)

'नास्तिकता की ज़रूरत' (पुस्तक)—७३५

निंगपो—६३६

निकोलस (द्वितीय)—८७६

निकोलो काण्टी—३६६-६७

—पोलो—३२१

निज़ाम—४५७, ४६०, ५८९

निटी—११५९

निदरलैण्ड्स—२९५, ३७७, ३९२, ४०३,

४०६, ४०८, ४११-१२, ४१४-

१६, ४१८-१९, ४२६, ४३६, ४४२,

४९३, ५२४, ५२८, ५४७, ५६०,

५९४, ६७३, १२८५

निनीवे—२३, २४, ६९२—९४, १०६८,

१०९८, १३४७

नियागरा—८०९

निःशस्त्रीकरण—९३, ९०७, ११२०,

११४९-५०, ११६०, १३०४, १३११

१३१६

—कांफ़ेंस (परिपद)—११०६,

१११३, १३०४-१०, १३३८

निशात वाग़—४४६

निष्क्रिय प्रतिरोध—८९०

- पतन, खारजम के साम्राज्य का—३१२
 —, खिलाफत का—१००६
 —, गुप्तवंश का—१७८
 —, गुलाम बादशाहों का—३०५
 —, चीन के युआन राजवंश का—३२५
 —, चोल साम्राज्य का—१८६, ३०२
 —, जर्मन साम्राज्य का—९६२, ९९३
 —, तंग वंश का—१७१, २४२
 —, तैलंगी आंध्रों का—३०३
 —, नेपोलियन का—५६४, ५८२, ६७१, ६८६, ७२६, ८५५, ९७६
 —, पवित्र रोमन साम्राज्य का—२८६
 —, पश्चिमी रोमन साम्राज्य का—
 १३७, २०२
 —, पुरानी शोगनशाही का—३८६
 —, पूर्वी रोमन साम्राज्य का—१३८
 २९०
 —, पेकिंग का—११७८
 —, पेरु राज्य का—२६७
 —, वसुदाद के साम्राज्य का—२२२
 —, वैबीलन का—६९२
 —, वैस्तील का—५११-१८, ५२१,
 ५५२
 —, दोर्वन वंश का—७११
 —, ब्रिटिश उद्योगों का—७७१
 —, ब्रिटिश साम्राज्य का—९८२-८३,
 ९८९
 —, भारत में बौद्धधर्म का—१५६
 —, मगध साम्राज्य का—१२२
 —, मंगोल साम्राज्य का—३४७-५३
 —, मलेशिया के दूसरे साम्राज्य का—१९९
- पतन, महमूद गजनवी के साम्राज्य का
 —२९८
 —, मायापान संघ का—२६५
 —, मिग-युग का—३८३
 —, मुगल साम्राज्य का—४४४-५१,
 ५९३, ६०५, ६२२
 —, मेक्सिको की सभ्यता का—२६६
 —, युआन वंश का—३५०
 —, यूनानियों का—९५
 —, यूनानी पूर्वी साम्राज्य का—३३८
 —, यूनानी रोमन साम्राज्य का—२९४
 —, रूस की अस्थायी सरकार का
 —९२५
 —, रूसी साम्राज्य का—९६२, ९९३
 —, रोम का—१६२, १६४
 —, रोम का अन्धकार में—२००-०७
 —, रोमनोफ वंश का—९१४, ९६२
 —, विजयनगर साम्राज्य का—३६९
 —, श्रद्धा और विश्वास के युग का
 —२९६
 —, श्रीविजय का—१९९
 —, ,, साम्राज्य का—३७०, ३७४
 —, सफावियों का—७७५
 —, सिकन्दर के साम्राज्य का—९५
 —, सोवियट सरकार का—९२९
 —, हिंदू आर्य भारत का—२२८
 —, हैप्सबर्ग वंश का—२८७, ९६३
 —, होएनजोलर्न वंश का—९०७
 पनामा—३४४
 पर्सिकार्वस, सर—११००-०९

नोसास—१३४७

नौकरशाही—६१९, ८८३

नौरोजी, दादाभाई—६२९, १०३६

न्याय—१८२

न्यू एम्स्टर्डम—५०४

न्यूटन, सर आइज़क—३९८, ७४०, ७४६,

१२२३

न्यूटन—१२२४

न्यू प्लेमाउथ—४२३, ५०४

न्यूयॉर्क—१५०, ५८१, ६०४, ७६८,

७७०, ८०१, ८०४, ८५९, ९२१,

११३२, ११३४, १२३७, १२६६-

७१, १२७६-७७, १३००, १३११-

१२, १३३३

न्यूरेम्बर्ग—२९५

प

पंचवर्षीय योजना—१२००-११, १२१४,

१२२१, १२४५, १२५५

पंचहिंद—१८३

पंचायत (तैं) ४३, ८२, १९२-९३, ३३३,

१०२०

—का चुनाव—३०१-२

—, कारीगरों की—१९२

—, ,, तथा दस्तकारों की—

७६०

—, व्यापारी—२९५

—घर—४३, १८७

पंचायती हॉल—२९४

पंजाब—४०, १२०, १२३, २२६, २५३

२६९, २९८, ३०३, ३०५, ३५५,

४५८, ५६३, ९५३-५४, ९८२,

१०१८-२०, १०२४-२५, १०२९,

१०३९, १०४३, ११०८, ११८०

पंजाब का फौजी कानून—१०१८, १०४३

—, पश्चिम—२२४, २६८, ४५५,

५५०, ५८२, ५८६, ६०५, ६०९,

६२४

पगान—(बरमा की पुरानी राजधानी)

—३७३

पटना—४, ७८, १००

पटेल, सरदार वल्लभभाई १०३८

पतन (अंत अथवा खातमा)

—, अज़टेक राज्य का—२६६

—, अरब साम्राज्य का—२७४

—, अरबी सभ्यता का—३१७

—, अलिफ़ लैला के शहर बग़दाद का

—३१७

—, आस्ट्रिया का—७२५

—, आस्ट्रिया के साम्राज्य का—९९३

—, आस्ट्रिया-हंगरी के साम्राज्य का

—९६३

—, इंग्लैण्ड का—९८९

—, इंग्लैण्ड की पार्लमेंट का—१३२३

—, ,, की मजदूर सरकार का १३२२

—, इंग्लैण्ड के प्रथम प्रजातंत्र का—४२५

—, उत्तर भारत की सभ्यता का—३०५

—, उन्नीस सौ पाँच की रूसी क्रांति

का—८६२

—, उर का—६९२

—उस्मानी साम्राज्य का—९९३

—, कुस्तुनतुनिया का—२९०, ३३८-

४०, ३४२

पार्लमेण्ट, पोल (पोलैण्ड की)—४८७, १६४
 —फ्रीस्टेट की—९८८, ९९०
 —ब्रिटिश—४६३-६४, ४७५, ५०१,
 ५१६, ६१८-१९, ७६१, ७८९,
 ८०३, ८२२-२३, ८२५-२९, ८७१,
 ९८४, ९८६, ९८७, १०३७, १०५७,
 १३२१, १३२३
 —, मिस्र की—१०५९, १०६२, १०६४
 —, रम्प—४२४
 —स्पेन की कोर्टे—६८३, ११६२,
 पार्लमेण्टों की असफलता—१३१८, २५
 पॉल—१२९
 पालमीरा—२०८
 पालेमबांग नदी—१९७
 पावलोव—१२२६
 पावोचिया—२४४
 पिंडार—७०
 पिंडारी ग्लेशियर—३३
 पिजारो—२६७, ३०५, ३४६, ४१२, ६५९
 पिटीशन ऑफ़ राइट—४२३
 पिरेमिड—२२, ४८, ९३, १६७, ३५१,
 ५४४, ८३४
 पिल्ग्रिम फ़ादर्स—५०४, ५०६
 'पिल्ग्रिम्स प्रोग्रेस'—१३४५
 पिल्सुदस्की—७७३, ८५७, ११६४
 पीको नदी—६४०
 पीटर—१३९
 —महान्—४६९, ४८४, ८५३-५४
 पीटर्सवर्ग—(दे० सेंट पीटर्सवर्ग)
 पीडमांट—७१९-२१
 पीपिंग—११७८, १ १८८-९०

पीली नदी—६९७
 पीसा—२९५
 'पुण्य भूमि'—१९०
 पुनर्जागृति—३६७
 —की शुरुआत—३३९
 पुराण भारतीय—४४४
 पुरु (पोरस)—७५-७६
 पुरुषपुर—१२३, १४८
 पुर्तगाल—१४६, २७१, ३४२-४४, ३४६,
 ३७५-७८, ३९१, ४२२, ४५०,
 ५६२, ८९५, ९४८, ११६४, १२८५-
 ८६, १३३१
 पुलकेशिन्—१५९, १७८
 —द्वितीय—३०१
 पुश्किन—७३३, ८६५
 पुष्यमित्र—११८, १२०
 पूंजी—७६९-७०, ७८०
 पूंजीवाद—७३, ९३, ५०१-०३, ५६८,
 ५७२, ५७५, ५७७-७८, ७१०, ७६२,
 ७७४, ७७६, ७७९, ७८१-८२, ७९७,
 ७९९, ८६७-७०, ८७४, ८८२, ८८४,
 ९१८, ९३८-३९, ९७९-८०, १११७,
 ११२२, ११३६, ११३९-४०, ११५२,
 ११५६-५७, ११६९-७०, ११९३,
 १२०१, १२०६, १२०९, १२१२,
 १२१४, १२३६, १२४१, १२४५-४६,
 १२४८-४९, १२५१-५२, १२८१,
 १२९१, १२९३, १३०१-०२, १३-
 ११, १३१७-२१, १३२४, १३२९,
 १३३०, १३३९-४१,
 —औद्योगिक—५७०, ५७२-७३,

पर्सिपोलिम—६९१, ६९७, ८३४, १०६९

पल्लव प्रदेश—१५१, २००

पवित्रसंघ—२८४

पांचाल—४४

पांडव—४५

पांडीचेरी—४५१, ४५९-६१

पांडुरंगम्—१९५

पाम्पि-ए-हिंद—११५

पाम्पी—११४-१५

—जर्मन, ११५

पाइज़ (पोर्चुगीज़ मुसाफिर)—३६६-६८

पाइटियर्स—२७१

पाइथागोरस—५७, ५८, ९४

पाटलिपुत्र—४, ४४, ७८, ७९, ८२,

१०-००१, १४८, १५३, १५५-

५६, २२६, ५८०

पाट्रिजन—१२२४

पादरी (या उपदेशक)—५१५

—ईसाई—३८२, ३८८, ६१५,

६३७-३८

—कैथलिक—४१३, ८२०, १३३२

—जेसुइट—३८२, ४३९

पोर्चुगीज़—४४४, ४४९

—रोमन—४४६, ४४९, ११६२,

१३३२

‘पानसुपारी’—१०७१

पानीपत—३६२

पामीर—१४७, १२१५, १२१७

‘पायाटिलेटका’—१२००-०८

पारनेल, चार्ल्स स्टीवर्ट—८२६-२७

पारस, पत्थर—७३९

पारसी (लोग)—५८, १२५, ४३९

पार्टी, आयरिश राष्ट्रीय—८२८

—आयरिश होमरूल—८२७

—, कंजरवेटिव—८२६

—कम्यूनिस्ट—९३८

—, गिरोंदे की—५२०

—, जर्मनी की सोशल डेमोक्रेट—

१११७

—, नाजी—११२५

—, वोल्शेविक — ८६०, ९१६,

११९८, १२०१

—, ब्रिटिश लिबरल—८६३

—, मेनशेविक—८६०, ८६४, ९२०

—, रायलिस्ट—५२०-२१, ५२४,

५२९

—, लिबरल—८२७, ८२९

—, वफ़द—१०५४

—, सोशल डेमोक्रेट लेबर—८५७-६०

—, सोशल रेवोल्यूशनरी—९२०

पार्थिया—११४, १२०, १२३, १४५-४६

पार्लमेण्ट, अंग्रेज़ी—५९२, ७१३

—, ‘की इमारत’—२६४

—, की शुरुआत—२८८-८९, ५०६

—आयरिश—८२२-२३, ९८८

—इटली की—७२१

१२८५, १२८७-८८

—चीनी—६६६

—जर्मन—७७२

—जापानी—६५०

—तुर्की की—९९३, ९९७, १०९४

- पैस्कल—११६
 पोग्रो (मस)—८५२, १०८७, ११९८
 पोन्सन वी. आर्थर—१३०९-१०
 ————लार्ड—१३०९
 पोप—१३९-४०, २२३, २२९, २३१
 २३६, २५७-५८, २७७-७८, २८०-
 ८१, २८४-८६, २८९-९२, २९६,
 २९८, ३१६, ३२१, ३२५-२६,
 ३२९-३०, ३३२, ३३८, ३४४,
 ४०१, ४०४, ४०७, ४१०, ४२६,
 ४७७, ४८५, ५६९, ७१९-२०,
 ११६१, १२८५, १२८८
 ————की ज़मींदारी—४०८
 ————की धर्माज्ञा—३२८
 ————के अत्याचार (ईश्वर के नाम पर)—
 ३२८
 ————के चुनाव का तरीका—२८४
 ————राज्य—३३१ ७१९
 ————रोमन—२५६
 पोपीज, सेम्युअल—४७०
 पोर्चुगीज (लोग)—(देखो लोग में)
 पोर्ट आर्थर—६५४-५६, ६६०-६२
 पोर्टमाउथ—६६२
 पोलिश कॉरिडर—११२३
 पोलैण्ड—२५५, ३०९, ३११, ३१५,
 ३१९, ३५०, ४०८, ४८४-८७,
 ५२४, ५४७, ५६०-६१, ५६८,
 ७१६, ७७३, ८५६-५७, ९०१,
 ९३२, ९३६, ९६६-६७, १११७,
 ११३१, ११४४, ११४६, ११४९,
 ११५१, ११६४, ११९८, १२००,
 १२२०, १३००-०१, १३०६,
 १३३६-३८
 पोलैण्ड, रूसी—७२५
 पौजा टापू—११६१
 पॉटियस पाइलेट—१२६, १२८-२९
 प्यूरिटन—४२४, ४७७, ८१९, १०९३
 प्रजातंत्र, अमीरों का—२९५
 ————, अमेरिका का—५०८-०९
 ————, आयरिश—९८४, ९८६, ९८८
 ————, आरमीनिया का (सोवियट)—
 ८५०, ९९५
 ————इंग्लैण्ड का पहला—४२५, ४५२
 ————इटली का—७१९
 ————, उज्रवक समाजवादी सोशलिस्ट—
 १२१७
 ————, उन्नीसवीं सदी का एक आदर्श—
 ५७६
 ————, क्राफ़ प्रदेश के—१२१५
 ————, की रूपरेखा—१३२
 ————, की सदी—५७६
 ————, कोहकाफ़ के पार का—१२००,
 १२१५
 ————, चीन का—९४२, ९४५
 ————, चीन का नया—११७१
 ————, चीनी सोवियट—११८०
 ————, जर्मन—७२६, ७३०, ८९९,
 ९०७, ९६५, १११८, ११२०,
 १२९२, १२९४
 ————, ताजिक—१२१७-१८
 ————, तुर्की का—१३८, १००५,
 १०६२, १०५२

- ५७५, ५७७, ५८१, ५८८
 पूँजीवाद का विकास—१३४७
 —की कामयाबी—७६२
 —के खिलाफ लड़ाई—९१८
 पूँजीवादी उद्योग—५७५, ७६२
 —प्रणाली—५७४, ५७६, ७१०, ७६८
 —व्यवस्था—७६३
 पूना—२७०, ३७९, ४५६
 'पूर्णस्वराज' का दिन—८३
 पृथ्वीराज चौहान—२९८, ३०४
 पेकिंग (या पेकिन)—२४४, ३०९-११,
 ३९८, ३२०-२३, ४७२, ६४०-४२,
 ६५८-६०, ८६६, ११४८, ११७६-
 ७८, ११८५
 —का आदर्श मसविदा—६६०, ६६५
 पेगू—३७३
 पेटरकिन—९०९
 'पेटिट कारपोरल'—५५३
 पेट्रार्क (कवि)—२९६, ३९५
 पेट्रिक सार्सफील्ड—८२०
 पेट्रोग्रेड—४८४, ८६६, ९११-१३, ९१७
 ९२०-२१, ९२३-२४, ९२६, ९२९
 ९३३, ९३६, ९४०, ११९७
 पेपिंग—८६६
 पेपिन—२२६
 पेरागुए नदी—१३३२
 पेरिस—२७, २५६, २७२-७३, २९२,
 २९५, ४००, ४१४, ४७६, ४८०,
 ४८२, ५१७-१८, ५२०, ५२२-२५
 ५२८-३१, ५३४-३५, ५३७, ५४१,
 ५५३, ५५९, ५८१, ६९०, ७१७,
 ७२६-२९, ७५०, ७६७, ७७०,
 ८७०, ८९७-९९, ९६३, ९६५,
 १०७५, १११०, ११३२, ११५१
 ११६५, १२३४, १२७१
 पेरिस का इकरारनामा—११५०-५१
 —का फेडरेशन का जल्सा—५२३
 —का शांति सम्मेलन—१०५४,
 ११५३
 —की पञ्चायत (कम्पून)—७७०
 —का पञ्चायती राज्य—७२७-२८
 ७३३, ७६९
 पेरू—१०२, २४०-४१, २६४, २६७,
 ३४६, ३७७, ४१२, १३३२
 'पेल'—८१८
 पेशवा—७५७-५८, ५८३, ५९०
 पेशावर—९९, १२३, १४८, ५३९,
 १०४२, ११८०
 पैगंबर मुहम्मद—१९, १३०, १६९, १८५
 २०९-१२, २१४, २१७-१८, ६९८,
 १०९३
 पैगन—८३५
 पैट्रिक, हैनरी—५१०
 पैन (क्वेकर नेता)—५०४
 —इस्लामी—१००७
 —टयूरेनियनिज्म—१००७
 पैनसलवेनिया—५०४
 पैपल स्टेट्स—४०८
 पैपसी—३३१
 पैरिक्लीज—७१, ७२
 पैरेगैमस—१०३, ११७, १४२
 'पैरेडाइज लॉस्ट'—४००

प्रथा, दास—४०४

——, प्लांटेशन की—६०७-०८

——, बेगार—६७२

——, सती—६१५, ६२३, १०७१

——, सरकारी नौकरियों के लिए
परिक्षा की (चीन में)—१०८,

१६७, १७७, २३८, २४३, ६६५

——, हरम की (अरबों में)—२१६-१७

प्रमेय—५७

प्रयाग—४४१

प्रशा (शिया)—४२०, ४७९, ४८३,

४८५-८६, ५२४-२५, ५४७, ५५३,

५६०, ५६९, ७१६, ७२३-२७,

७८४, ७८९, ८७४, ८९२, ९६२,

९६६, ९८३

——, पूर्वी—८९८-९९, ९६६

प्रहा—८६६

प्राइड, कर्नल—४२४

'प्राइड्स पज' (प्राइड की सफाई)—४२४

प्राउडन पायरे—७६६

प्राणियों की उत्पत्ति—५७८, ७४१

प्रक्रिपो—१२०३

'प्रिस' (पुस्तक)—४००

——ऑफ वेल्स—१०२३

——उपाधि—७३९

प्रिसेप्—११५

प्रियदर्शिनी (देखो इंदिरा)

प्रेम—३३०, ४०१, ८६६

प्रेस्टर, जॉन—३२४

प्रोटन—१२२४

प्रोटेस्टेंट—३९२, ४१३, ४१८, ४२३,

९१

४२८, ४७७, ४९३, ९८४

——आंदोलन—४०४, १०९७

——सिद्धान्त—४०४

प्लासी—४६१, ७९४

प्लीवी—१२४

प्लेटो—४८०

फ

फतेहपुर सीकरी—४४१

फर्डीनेंड—२७४, २७६, ३४२-४३

——डि लेसेप्स—८१४

——फ्रांसिस आर्च ड्यूक—८७९

——फ्रेंज ड्यूक—२८७, १११७

——मैंगलेन—३४४-४६, ४०७

——लैसले—७२९

फरोहा—८३४-३५

फर्नी—४७९

'फाउस्ट'—७३२, ७३७

फातिमा—२१५

फारमूसा—१५२, १९७, ६५४

फारस—१४५, ६८८, ६९०, ६९५-७०३

९३८, ९६८, ९८१, १००३, १००७

११०६

——के सफावी—७०२

——, पूर्वी—६९१

फारसेल्स—११५

फाहियान—१०१, १५६, १६८

फिजी—६१७, ८८७-८८

फिनलैण्ड—८६३, ९६६-६७, ११९८,

१३०६

——की खाड़ी—४८४, ८५३

फिर्दासी—७५, २२७, ३०३, ६९९, ७००

प्रजातंत्र, दक्षिण अमेरिका का—५६६

८११, ८३२, ११६४, १३०५

—, नोवगोरोड का पुराना—३५०

—, पनामा का—८१४-१५

—, पेरिस का—७२६, ७२८

—, प्रणाली—१६५, ५६१

—, फ्रांस का (के)—५३८, ५४३,

७२८, ७८४, ९३२

—, ववेरिया का—१११८

—, बुखारा का सोवियट—१२१७

—, वोअर—८००

—, बोलीविया का—५६२

—, मजदूरों का—१०२२

—, मध्य एशियाई—१२००

—, 'मुकुटधारी'—७८८

—, रूसी—१२००

—, रोम का—७२०

—, रोमन, के आखिरी निशान मिट
गये—१३३

—, लेवनीज—१०८५

—, लैटिन—५६६, ८११

—, विश्व—१४३

—, वेनिस का—२९४-९५, ३२३,
४०८, ५४३

—, संयुक्त राज्य का—५०९

—, सीरिया का—१०८४

—, सोवियट का—९३२, १०७९,
११९७-९८, १२००

—, स्पेन का—९८०, १२८६-८७,
१२८९

—, स्वीजरलैंड का—४०८, ४११,

४२०, ५०९

प्रजातंत्र, हालैंड—४१९-२०, ४२७, ५०९,
५६०

—, हैफंग सोवियट—११७९

प्रजाधिपक, राजा—१११२

प्रणाली, अनिवार्य सैनिक भरती की—
८८१, ८९२

—, औद्योगिक—७६२

—, कोलोनियल शासन—१०८८

—, जातिपांति की—८८९

—, लगान, रयतवारी—४४१

—, ,, शेरशाह की—४३६

प्रथा, इंडेंचर की—८८८

—गुलामी की—१६७ ८०२-३, ८०५

—(प्राचीन चीन में)—११०

—, प्राचीन मिस्र में—११०

—, प्राचीन रोम में—११०

—, प्राचीन हिंदुस्तान में—११०

—, का खात्मा—४८८, ५१०

—, गांवों और शहरों की स्वशासन
(भारत में)—१९३

—, जमींदारी—४४१, ६०४-०५ १३०२

—, जमींदारी (बंगाल में)—६०४

—, विहार में—६०४

—, मदरास में—६०७

—, संयुक्तप्रांत में—६०४-०५

—जातपांति की—२२८

—, जाति—१६६-६७

—, जूरी की शुरूआत—२ ८

—, दास (इंग्लैंड की)—८०४

—, दूत भेजने की—१५९

फ्यूनीशियन—२७

फ्रांस—५, ६, १६, २६, २७, ११४,
२०१, २१४-१५, २२३, २२९,
२३२-३४, २५४-५६, २७१, २७५,
२८०-८१, २८७-८९, २९३, २९५,
३११, ३१८, ३२९, ३३५-३६,
३४०, ३४६, ३७९, ४००, ४०४,
४०७, ४१०, ४१३-१४, ४१९-२१,
४२५, ४४६-४७, ४५१-५२, ४५९-
६०, ४६६, ४७३, ४७५-७६, ४८०-
८३, ४८५-८६, ४८९, ४९३, ५०५,
५०९-११, ५१३-१५, ५१७-२१
५२३-२६, ५२८-२९, ५३१, ५३५-
३८, ५४०, ५४२, ५४४-४९, ५५१-
५३, ५५५, ५५८-६१, ५६६,
५६९-७०, ५७६, ५७८, ५९४,
६३९-४०, ६४२, ६४४, ६४६,
६५१, ६५३-५५, ६६१, ६६९,
६७४-७६, ७०८, ७१०, ७१७,
७१९, ७२१, ७२५-२९, ७३३,
७४०, ७४६-४७, ७४९-५१,
७६२-६३, ७६७-६८, ७७३,
७७९, ७८३-८५, ८८७, ७९५, ७९९,
८००, ८१८, ८२७, ८४१, ८४६,
८५१, ८६४, ८७०, ८७४-७७,
८७९-८२, ८९२, ८९५, ८९७-९९,
९०१, ९०९, ९१७, ९२०, ९२७,
९३०, ९३२, ९४७-४८, ९६४,
९६७-६९. ९७२, ९८१, ९९५,
९९९, १००१, १०७३-७४, १०७८,
१०८०, १०८२, १०८३-८५, ११०४-

०५, १११५, ११२३, ११२६-२८,
११३१, ११३३, ११४३-४४, ११४६
११४९-५१, ११५३-५४, ११६०,
११६३, ११६५, ११८८, ११९४-
९६, १२०६, १२१९, १२३२, १२३६
१२५०, १२५९-६०, १२६२, १२६५
-७२, १२७४-७५, १२७८, १२८०-
८१, १२८७, १२९४, १३००-०२,
१३०६-८. १३१४, १३१६, १३२०-
२९, १३३६-३७

फ्रांस, उत्तर—९६२, ९८४

—का मजदूर आन्दोलन—११५४

—का राष्ट्रीय त्यौहार—५१७

—की मुद्राप्रणाली—५२९

—की राज्यक्रांति—५१८-२६

—की ,, का खात्मा—५३४-३५,
५४७

—की राष्ट्रीय परिषद्—७२७, ११९४

—के अधिकारों की घोषणा—७४७,
७४९-५०

—के दूसरे प्रजातंत्र का खात्मा—७१७

—दक्षिण—२७, २०२, २१४, २७३
२७५, ३२७

—पश्चिमी—३३५

—प्रजातंत्र का नया कैलेंडर—५३३

—प्रजातंत्र के जाली नोट—५२९

—में दूसरे प्रजातंत्र की स्थापना—
७१७

—में प्रजातंत्र का ऐलान—५२६

—में राष्ट्रीयता की गुरुआत—३३६

फ्रांसिस—३२७

फिरोज़शाह—३६१

फिरोज़ाबाद—३६१

फिलिस्तीन—१९, २८, २९, ४९, १२९,

२२२, २५७-५८, २७७, २७९-८१

२८४, २८६, २९०, ३११, ३१७,

३२१, ३२७, ९००, ९६८, ९८१,

१००२, १०५१, १०६७-६८,

१०७२-७४, १०७९-८०, १०८५-९२

१०९८-९९

फिलिप (द्वितीय)—४१२, ४१५, ४१८-

१९, ५०८

—, लुई—५६१, ७१७, ७६७

—, सिकंदर का पिता—७४

फिलीपाइन—१५२, १९७, २००, ३४५,

३७५, ३७७, ३७९, ३८८, ४६८,

४८३, ५६३, ५६७, ६६९, ६७६,

८१४, ९३२, १३२९

—और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका—६८०-

६८५

—का राष्ट्रीय संगठन—६८३, ६८४

फिश्टे—७२३

फीडियास—६९, ९५

फुआद, किंग (शाह या बादशाह)—१०५६,

१०६२-६७, १०९५, ११०४

—डॉ०—१००८

फुरात नदी—२०७, १०९७

फूचू—४७१, ६३६

फूसंग—१६८

फेल्लाह—१०५३

फैज़—१००९

फैजी—४४०

फैवियन—११२, ७७०, ७७६

—तरीका—११२-१३

—वाद—७६३

—सोसाइटी—११२, ७७०

फैवियस—११२

फैब्रे दि इंग्लैंटाइन—५३१, ५३३-३४

फैसल, अमीर—१०८१, १०९०, १०९४

११००

—बादशाह—११०२, ११०४

फ़ैसिज्म—९७९-८०, ११४४, ११५६-

५९, ११६८, ११७०, १२९०-९१,

१३०१-०३, १३१८, १३२१, १३-

२४, १३३७, १३४०-४१

—, अंग्रेजों का—११६५

—और साम्यवाद—११५८

—का उद्देश्य—११६९

—की विजय—११५७

—फ्रांस का—११६५

फ़ैसिस्ट (लोग)—९४९, ९८०, ११५४,

११५७-५९, १२१९, १२३२,

१२९१, १२९३, १३१७, १३३७

—ग्रैंड कौंसिल—११६०

—सलामी—११५८

फोकिये तिनवली—५३१

'फोर पावर्स पैक्ट'—९४८

फोरम—११५

फोर्ड—११९७

—कंपनी—११९७

फ्रोस्च्यूल्स—२८

फोशे—५५१

फ्यूचू—(देखो फूच)

- बनारस—१०१, १२३, १८०, १८८,
३५८, ६९३, ६९७, ११८०
- बनियन, जॉन—१३४५
- बमरौली—१०७५
- बरकनहेड, लार्ड—८३१, ११९४
- बरगंडी—३३५-३६
- बरमा—१९, ४५, ८२, १२५, १५०,
१५२, ३०१, ३१८, ३२४, ३५०,
३७१, ३७३, ५६४, ५६७, ५८५,
५९२, ५९४, ६३२, ६४६, ६६९,
६७३, ६७५, १०५०, १११२,
११४६
- उत्तर—३७३, ५८५, ६३३, १०५०
- दक्षिण—१८६, २५३, ३७३,
५८५, ६७३
- ब्रिटिश—११११
- बरार—३६४, ५८९
- बर्नादोत—५५१
- बर्मिंघम—६०१
- बर्लिन—५८१, ७२६, ८४७, ८४९, ८९९
९०७, ९५२, ११११, १११८-१९,
११४८, १२३४, १२६९, १२९६
- बर्लिनगेम—६४५
- बलख—१७२, १९१, २१४, २५४,
३१२, ३२१, ७००
- बल्गेरिया—२८३, ३३७, ८४६-५०,
८९५, ९०१, ९६५, ११६४
- बलबोआ—३३४
- बलवा (वे), (वगावत (तें) या शहर)
- अमेरिकन उपनिवेशों का—४८७,
५०३
- बलवा (वे), अटलांटिक प्रदेश की जल
सेना के ब्रिटिश नाविकों का—१२५८
- , अरबों का—१०७३, १०९३,
११००
- , आयरलैंड के एकट ऑफ यूनियन के
खिलाफ—८२३
- , इंग्लैंड में किसानों का—३३५
- , कनाडा का—७८५
- , किसानों का प्लांटर्स के खिलाफ—
६०८
- , किसानों के पश्चिमी योरप में—
३३५, ३९२
- , कुर्दों का—१००८
- , कोरिया का—६६४
- , क्रांस्टाट का—९३७
- , गुजरात का—४४०
- , जबल-अद्-द्रुज का—१०४२
- , जर्मनी की नौ सैना की—१११८
- , जर्मनी में—७७०
- , जाट किसानों का—४५४
- , जॉन हस के अनुयायियों का—
४०१
- , जार और डच इंडीज का—९८३
- , डच ईस्टइंडीज में—१११३
- , डवलिन में—९८५
- , तुर्की के कुर्द प्रदेश में—१००७
- , तेपिंग का—६३७-४०, ६४४-
४५
- , निदरलैंड का—४९३
- , पोलैंड, इटली बोहेमिया और
हंगरी के—७१६

फ्रांसिस जोजफ—२८७, ७१७, ८८०

फ्रांसिसकन—४०२

फ्रांसिसी (लोग)—(देखो लोग में)

फ्रेंकफुर्ट—२३९, २८५, २९५

फ्रेडरिक (द्वितीय)—२८१, २८६-८७

२९६, ३११, ३१५, ३२५-२६, ४०१

—ग्रेट—४८३, ४८६

—वारवरोसा—२८१, २८४-८६

फ्लॉरिडा—८०१

फ्लेडर्स—९०४

फ्लोरेंस—२९५, ३९५-९७, ४००, ४०९

८७२

—नाइटिंगल—६०९

ब

बंगविच्छेद—६३३

बंगाल—३०, ५०, ८०, १४९, १५१,

१८६, २२८, २५३, २९८, ३०१,

३०४-५, ३०८, ३५८, ३६१-६२,

४४०-५१, ४५७, ४६०-६३, ५०६,

५९४, ६०४-०७, ६१६-१७, ६२०,

६२३, ६२६-२७, ६२९-३३, ६७२,

८८५, ८८९, १०१४, १०३९-४०,

१०४२-४३,

—आर्डिनेंस—१०३९

—का नवाब—४६०

—का सन का उद्योग—६१६

—की खाड़ी—८८, १२३, १७९,

१८६, २५३

—के नजरबन्द—१०४३

—पूर्वी—४५०, ६३१, १०४०

—में अंग्रेजी शिक्षा—६२१

—में जहाज बनाने का व्यवसाय—

४५०

बंदूकों का इतैमाल शुरू हुआ—३१७,

३३८

बंदोवस्त, अस्थायी—६०७

—, दायमी—६०७

बंबई—३६, ४०, ८५, ८८, २२१, ४०८

४५१, ६०१, ६१६, ६७८, ६२१,

६२९ ६९४, १०३५, १०४२, १०७४

—का टापू—४५०

—प्रान्त—३९

—में पहली रेल—६०२

बक्सर—४६२

बगदाद—२३, २१७, २१९, २२२, २२४-

२६, २३१-३२, २३४, २४०-४१,

२५३, २६२, २७१-७२, २७५, २७७,

३०१, ३०९, ३११-१२, ३१५-१७,

३४८-४९, ३७१, ६८८, ६९८-९९,

७००-०१, ८३५, ८७५, १०६९,

१०७२-७६, १०९७, ११०२

बन्वा-ए-सक्का—११११

बजबज—९५४

बटाविया—३८३, १०७५

बतलामूसी (देखो टालमी)

बड़ा खान—(देखो खान महान)

बड़ीवा—४५८, ४८४

बदरुद्दीन तैयबजी—६२९

बदामी—१८५, १८७

बदायूनी—४४२

बनर्जी, उमेशचंद्र—६२९

—सुरेन्द्रनाथ—६२९

वस्तियाँ, स्पेन की—३७८, ५६२
 —, हिंदुस्तानी—१५०-५१, १९५,
 १९७, २५३, ३६९, ३७२-७३
 —, हेंकन की ब्रिटिश रियायती—
 ११७५
 बहादुरशाह—५८९, ५९१
 बहिष्कार, जापानी माल का—९४८,
 ११८६
 —ब्रिटिश माल का ५९५, ६३१-३२,
 ११७४
 बाइबिल—२३, २८. ४९, ५८, १२६,
 १२९, ३२९, ३९४, ५६८, ६९२,
 ७४२, ८१३, १०८५-८६
 बाकू—१०११, १०७६, ११९७, १२११
 बाक्सर्स—६५७-५८
 —आन्दोलन—६५८-५९, ६६४
 बानरसेना—१६
 बापू (महात्मा गांधी)—६, ७, ११,
 १३१, ४६४, ४९५, ५०७, ५२१
 ६२६, ६४३, ६६४, ६८०, ७१७
 ७३५, ८६०, ८६५, ८९०, ८९३,
 ९५९, ९८२, ९९२, १०००, १०१६-
 १७, १०१९, १०२४, १०२६,
 १०४१, १०४३-४४, १०५०, ११०४
 १३२६
 —भारतीय राष्ट्रीयता के एकमात्र-
 नेता—९८२,
 बाबर—३२०, ३६२, ४०९, ४२९-४३५
 ४३७, ४४५, ४४९, ४५५, ४६९,
 ५९१, ६९५ ७०३
 —के संस्मरण—४३३, ४६४, ७०३

बायरन—५६१, ७२२, ७३४, ७३६, ८६५
 बारडोली—१०३८
 बाबिये—५४०
 बार्सिलोना—१२८७, १२८९
 बालकन—८४४, ८६४, ८७५, ८७९,
 ९०१, ९९६, १२७०
 —प्रदेश—५६९, ७९१, ८४४, ८४६,
 ८५० ९०१, १२६९
 —प्रायद्वीप—२८७, ८५०
 —युद्ध—८४९
 —राज्य—१३३८
 —लीग—८४९
 —स्टेट्स—८४७, ८४९, ९३२
 बालसभा—१६
 बाल्कनाइज्ड—९६७
 बालजैक आर० द०—७३४
 बालफोर घोषणा—१०८७, १०९१
 बालवक—१४७
 बालबैन, काउंट—५५४-५५
 बालादित्य—१५८, १५९, १७८
 बालिका सभा—१६
 बालिग मताधिकार—७४९
 बाल्टिक—८५३, ९३३
 —राज्य—९६६-६७
 बाल्डविन स्टैनली—११४७-४८, १२६८,
 १२७२, १३३४
 बास्फोरस—३४, १३६, २०१, २५५,
 ३५२, ७८८, ९९३
 बारूद का इस्तेमाल—१७१
 बिदुसार—९७
 बिजेंटाइन—१०६९, १०७१, १३४७

- बलवा (वे), पोलैंड का—७२५
 —, प्रोटेस्टेंटों की—४०१-०६, ४१०
 —, फ्रांस का—७२७
 —, फ्रांस में किसानों का—३३५
 —, बरमा के किसानों का—९९२, १०८५
 —, बल्गेरिया का—८४८
 —, बेलजियम का—५६१
 —, बेलजियम में स्पेन की हुकूमत के खिलाफ—३७७
 —, मध्यमवर्ग का—३९२
 —, मिस्र में—९८१
 —, मुसलिम कबीलों का तुर्किस्तान में—६४५
 —, यूनान का—५६१
 —, योरोप के राजाओं की—३९३
 —, योरोप में—३३०
 —, रूस के नौजवान फ्राँज के अफसरों का—८२५
 —, रोमन चर्च के खिलाफ—२९३
 —, लायंस में क्रांति के खिलाफ—५३०
 —, बंदी के किसानों का—५२९
 —, सतनामियों का—४५४
 —, सफावियों का—७०५
 —, सिंगापुर की हिंदुस्तानी रेजिमेंट का—९५४
 —, सिक्खों का—४५५
 —, स्पेन की १९२३ की फ्राँजी—११६३
 —, स्विस् किसानों का—३३७
 —, हिन्दुस्तान का १८५७ का—५०८, ५८८-८९, ५९१-९१, ६१८, ६२७, ६३०, ६४०, ६४३, ६७१, ७८५, १०१८
 ववेरिया—६७३, १११८, ११२०-२१
 वसरा—२२१, १०९७, ११०२
 वस्तियाँ (या उपनिवेश) अंग्रेजी—७८६, ७९२-९३, १०८८-८९
 —, अमेरिकन—५०३, ५०६, ५०८-०९, ५६२
 —, अरबों की—२००, २२१, २२४
 —, अलस्टर की—८१९
 —, आर्यों की—४१, ४३
 —, कनाडा का—५६२
 —, कैथलिक—५०४
 —, क्वेकर—५०४
 —, जर्मन—९००, ९६५
 —, डच—६७१, ६८३
 —, दक्षिण भारत की—१४८-५३, १९५
 —, पल्लव—१५१, १९७, १९९, २००, ३७१
 —, पुर्तगाल के—३७७-७८, ५६२, ६८३
 —, पूर्व के हिंदू—१५१, १९५
 —, ब्रिटिश—६८३, ९८७, १०३९, १२७५
 —, मलेशिया की हिंदुस्तानी—२५३, ३०३
 —, यूनानी—४९, १११, १८६
 —, रोमनों की—१०८, १७९
 —, सिकंदरिया निवासियों की—१२२
 —, सुमात्रा राज्य की—१९८

६१, ५९९, ७७३, ७८४, ८५९,
८७७-७८, ८८०-८१, ८९२, ८९५-
९६, ८९८, ९०१, ९४८, ९८४,
११२६, ११४४, १३३६

बेलाकून--११२१

बेलूर--३६७

बेसारेविया--११२३

बेसैंट, श्रीमती एनी--९५९

बैंक ऑफ़ इंग्लैण्ड--१२४६, १२६३-६४,

१२६६, १२७२, १२७५, १३२४

—, ऑफ़ फ़्रांस--१२७०

—सरकारी--९२५

—नोटों और चेकों का चलन--९२

बैकाक--६७५, १११२

बैंकिंग कारपोरेशन--१९२-९३

बैजामिन--डिज़रैली--५७४

—फ्रैकलिन--५१०

बैटोलीन टापू--११६१

बैकाल झील--४७४

बैंकिट्टया--१२०

बैथलम्यू डायज़--३४३

बैजाद--(देखो बिहजाद)

बैनकवर्न--३३६

बैरामखां--४३६

बैरेन वॉन स्टीन--५४९, ५५१

बैस्तील--५११, ५१७, ५२३, ५३१

—का पतन--५११-५१६

—की हार की सालगिरह--५२३

बोधि-धर्म--१४१

—बृक्ष--५९ ९९

—सत्त्व--१२४, १८०-८१

बोरोडीन--११७२-७३, ११७६, ११७८

बोरोबुदर--१५२, ३७०, ३९४

बोडियो--२९५, ८९८

बोर्नियो--१५०, १५१, १९७, २००,

५६७, ६६९

बोलोना--२९५

बोलशेविक--८६४-६५, ८९५, ९०६,

९१०, ९१२, ९१६-१७, ९२०-२१,

९२३ ९२६, ९२८-३९, ९४१, ९४७,

९९४, १११५, ११४७-४८, ११७२,

११९२-९३, ११९५, ११९८, १२०२

१२०७, १२१२, १२१४, १२१६,

—अधिकार छीनते हैं--९१९, ९३०

बोलशेविज्म--१३९, ८६४, ९६६, १२५८

बोलीविया--५६२, १३३२

बोलोगडा--९२९-३०

बोसनिया--२८७, ८४६, ८७९

बोसिना--८४७, ८४९

बोस्टन--५०७

—टी पार्टी--५०७

बोस्तां--७०५

बोहेमिया--३२९-३० ४०१, ७१६,

८६६, ९६६

बौद्ध--९९, १५१, १५३, १५८, १७९,

१८३, १९५, १९९, ३७४-७४

—कथा--१२४

—कला--६९०

—काल--६९७, ७४५

—ग्रंथ--१०८

—धर्मग्रन्थ--६८७

—धर्म, जापान का राजधर्म--१७६

जैटियम—१३६, २०१, २८३, ३५०
लोचिस्तान—१८५, ७०८, ११०६-०७
टैनिया—४८५
शप—२३८
—पद—१३९
स्मार्क प्रिंस ओटो वान—७२४-३१,
७७२, ८४७
हिजाद—६९५, ७०२
हार—४०, ७८, ९७, १००, ३०४,
३६१-६२, ४६२, ५३९, ६०४-
०७, ६३१, ८८७, १०९६, १२५३
—उत्तरी—४०
—दक्षिण—४४
एट्रिस—३९७
जगणित—१९४, २८६
जापुर—३५९, ३६४-६६, ४४९,
४५५-५६
थोवन—४८९
—मोजार्ट—४८९
दर—३६४
बी नैला—३६१
मेन—२९५
रवल—४४१
इलों—२७९
बुक ऑफ केल्स—८१७
खारा—३६, २५४, ३१२, ३२१, ६९९,
७००-०१, १२००, १२१७
—के अमीर—१२१७
बुद्ध—अवतार के रूप में—११९
—कथा (जातक कथा)—६९२, ६९४
—का जन्म—५८

बुद्ध की मूर्ति—१०८, १७५, ६९४
—गीतम—१९, ५२, ५७, ५८, ९४,
११९, १५२, १८१, १८३, २०७,
३५६, ४६५, ४७९, ६८७, ६९३-
९४, ८३४
—का प्रस्थान—५९
—का सम्यक् ज्ञान—५९
—के सिद्धान्तों का प्रचार—५९
—सुधारक के रूप में—५९
बुद्धिवाद का विकास—४७९
बुलन्द दरवाजा—४४१
बुल—३४४
बुलोन—२९५
‘बुशीदो’—११८१
बृहत्तर भारत—१५०, १९५, ६९४,
७९९
—और ईस्ट इंडीज—६६८-७६,
६८६ १०५५, १०८०
बेकुनिन, माइकेल—७६६, ७६९-७०,
७७२, १२८७
बेक्स स्कूल—८५
बेवर—३१७, ३१९
बेविलोनिया—१९, २३, २८, ४१, १२२
बेबीलन—२३, २४, ७६, १२२, १४७,
६९२, १०६८, १३४६-४७
—नदी—१०८६
बेरिंग, मेजर—८३९
—का जलडमरूमध्य—८५
बरूत—१०७५, १०८०
बेलजियम—२२९, २३२, २९५, ४१८-
१९, ४९३, ५२४, ५२८, ५६०

१२५२, १२५८, १२७०, -७२,
१२८४, १३०५-६, १३०८, १३३४

ब्रिटेन का आर्थिक साम्राज्य—९९०

—ग्रेट—९४८, ९६४

ब्रियांद—७७३

ब्रियान बोखना—८१८

ब्रीमेन—८४७

ब्रुक्स—४१५

ब्रूजेज—२९५,

ब्रूटस—११५

ब्रूनो—३९८

ब्रूजेल्स— (देखो ब्रसेल्स)

ब्रेशिया—३२६

ब्रेसलाउ—२९५

ब्रेस्ट लिटोस्क—९२६, ९३६

ब्रैगेंजा—४०८

ब्रोमाइड—९३०

ब्लाडीवास्तक—६४४

ब्लूशर—५५३

ब्लेरियट फ्रांसिसी—८७०

'ब्लैक एण्ड टैन', (फौज)—९८७

भ

भगतसिंह—१०४०

भगवद्गीता—३०४

भरत (पौराणिक राजा)—१४३

भवभूति—२२३

भागलपुर—४

भागवत—६१, ३५९

भाप के ऐंजिन और मशीन—१६०

भारत (अखबार)—२०, २१

भारत (देखो हिन्दुस्तान)

भारत में शान्तिपूर्णविद्रोह—१०३६

—सचिव—८३२, ८८४, ८८८, ९६१

भारतमाता—८३, ८६, ८८, ४८५, ६६९

भारतवर्ष—२५, १४३

भारतीय—(हिन्दुस्तानी)—१९०, ६८२,

—आर्य परम्परा—१२१

—अर्यशक्ति के केन्द्र—१२१

—आर्य सिद्धान्त—१५५

—उद्योग—५९५, १०३२

—उद्योगधंधों को प्रोत्साहन—५९५

—उपनिवेश (या वस्तियाँ)—१५०,

२५३

—कपड़े—१६१

—कपड़े का बहिष्कार—५९५

—करघे—५९३

—कलाकार (कारीगर)—१५०,

१५२, १६७, २२७, ३००, ३०४,

३५२, ६९५

—कला संबंधी संस्कार—१७४

—कारीगरी—१६०

—कारीगरों की तवाही—५९१-९९

—किसान—१३८

—ग्रामीण प्रथा का अंत—६०२-०३

—घरेलू उद्योगधंधों का नाश—५०३,

५९६-९९, ६०२

—जहाजी व्यवसाय—१४९

—जाति व्यवस्था—२३८

—दर्शनशास्त्र—३०४

—दृष्टिकोण—३०४

—,, धर्म, और जिंदगी के मामले

में—१६६

- बौद्ध धर्म-प्रचारक—१७५
 —धर्म में प्रजातंत्र का भाव—१५५
 —धर्म में मूर्ति पूजा की शुरुआत—
 ६९४
 —प्रचारक—१६७, १७५
 —भिक्षु—१००, ११८, १५९, २४८
 —मंदिर—११४, १५२, ६९४
 —राज्य—१९६
 —विचारधारा—१२४
 —विद्या—१२३, १०८
 —विहार—१२४, १५६, १८४,
 ३८८, ८१७
 —संघ—६०, ११८, १८८, २०६,
 ३२७
 —सिद्धान्त—१२४, १२७,
 ब्यूनो आयर्ज—१३३१
 ब्रसेल्स—४१६, ५५३, ८७७
 ब्रह्मगुप्त—१९४
 ब्रह्मसमाज—८८९
 ब्रह्मावर्त—२५
 ब्राउनिंग, रावर्ट—१०३१
 ब्राजील—५६२, ८११, १२४२-४४,
 १३३१-३२
 ब्राह्मण—१००, १२४, १७९, १८२,
 १८७-८८, १९३-९४, ६९३
 —परोहित—३७१
 —विचारधारा—१२४-२५
 —विद्या—१८०
 ब्राह्मसमाज—६२३-२४
 ब्रिटिश इंपीरियल एवरवेज—१०७४,
 १०७६
 ब्रिटिश एक्सपीडेशनरी फ़ोर्स—८८१
 —कमीशन—१०३७-३८
 —कामनवेल्थ ऑफ नेशन्स—९८९
 —खुफिया विभाग—१३१०
 —पार्लमेण्ट, पार्लमेंटों की जननी—७८९
 —पूँजीपति—९५७
 —मंत्रिमंडल—८७१
 —माल का बहिष्कार—५९५, ९३१-
 ३२
 —म्यूजियम—७६७
 —राष्ट्रसंघ—९८९
 —लडाकू जहाज—१००५
 —वार मिशन—८९७
 —विज्ञानसंघ—१२२२
 —साम्राज्य के अंदर स्वशासन—९६०
 —हवाई फ़ौज—५३९ ११००,
 ११०२-०३, १३०६
 —हवाई मार्ग—१००४
 ब्रिटेन—११४-१५, १३७, ३७८, ६३३
 ६३६-३८, ६४०, ७०६, ७४९, ७८५
 ८०४, ८०९, ८१४, ८१९, ८२२-
 २३, ८३८, ८४०, ८४८, ८५०
 ८५९, ८७५, ८९५, ९००, ९०२,
 ९३०, ९३३, ९४८, ९५१-५२,
 ९५६-५७, ९६१, ९६४-६५,
 ९६८, ९८१, ९८७, ९८९, ९९१,
 १००३-०४, १०३२, १०३६,
 १०५०-५१, १०५७-५९, १०६३,
 १०७२, १०७९, १०९३, ११०१-०२
 ११०६, ११३३-३५, ११३९, ११४७
 ११७१, ११९०-९१, ११९५, १२३९

भाषा, पश्तो—११०७
 ———पाली—१९८
 ———पुरानी—१८१
 ———,, फारसी—१८१
 ———,, लैटिन—२०५
 ———पुर्तगाली—८११, १३३२
 ———पोलिश—५६१, ८५६
 ———प्राकृत—१५५, ३५९
 ———फ़ारसी—७५, १८१, २२७, ३०३,
 ३०७ ३५९, ३६६, ४३२, ७००,
 ७०३, ८८९, १०१२, ११०६
 ———फ्रेंच—२०३, ३९९, ४८३, ५०५,
 ५२७, ७०३
 ———बँगला (बंगाली)—४०, ३५९,
 ३६२, ३९९, ६२७, ८८९
 ———भारतीय यूरोपियन—१९१
 ———मंगोलियन—१८१
 ———मंचू—६३५
 ———मराठी—४०, ३५९, ३९९, ४५४,
 ४५६,
 ———मलयालम—३९, ४०, ३५९
 ———मिस्री—८३५
 ———यूनानी—१३९, २०५, २८९
 ———यूरोपियन—३९३-९४, ३९९, ४००
 ———रोमन—११५८
 ———लखनऊ की—१०१२
 ———लैटिन—११७, १३९, १८१,
 २०५, २८९, २९६, ३११, ३९४,
 ३९९, ५१४
 ———वर्नाक्यूलर—३९०
 ———संस्कृत—१४, ३९, ४०, ४२, ६६,

७९, १३२, १५४, १८०, -८१, १८९,
 १९८, २२०, २२३-२४, ३०४, ३५८-
 ५९, ५१४, ६२३, ६८२, ९६६,
 १०११, १२९२
 भाषा, संस्कृत (राजभाषा)—१५५
 ———स्पेनिश—२७५, ३९९, ८०१,
 ८११, १३३२
 ———हिंदी—४०, १२१, ३५७, ३५९,
 ३६२, ३९९, ४५४
 ———हिन्दुस्तानी—४०, ९७, ११५,
 १२१, ३५९, ३९९, ४३८, १०१२
 ———हिब्रू—१०८६-८७
 भास्कराचार्य—१९४
 भिक्षु—६०
 भिक्षुगिर्या—६०
 भूमध्यरेखा—८७, ३७६
 भोंसले, शाहजी—४४५
 भोज (राजा)—२२३
 भोपाल—६९३

म

मंगलीर—३६७
 मंगूखां—३१६, ३१८
 ———का दरबार—३१६
 मंगोल सौदागर—३११
 मंगोलिया—१२३, २०१, २१४-१५,
 २२२, २४१, २५४, २७१, ३०८-
 १०, ३१२, ३१५-१६, ३१९-२०,
 ३२४, ६५०, ४६८-४६९, ४७१,
 ५७१, ९४६-४७, ११४९, ११९०,
 ११९८
 मंगोलों का दुनिया पर छा जाना—३१५-३२०

- भारतीय नाविक—१५९
 —नील—९७, ३६०
 —पंचायतों को अदालती अधिकार—
 १९२
 —पूँजीपति—६२७-२८
 —पोशाक—१८१
 —फौलाद—७५, ३६०
 —बौद्ध—१६८
 —भिक्षु—१६८-६९
 —मलमल—९७, ३०२, ५९३
 —रंग—१६१
 —राज संगठन—१९१
 —राजा—२८५, ६१३
 —राज्य—१८२
 —राष्ट्रीयता—४३७, ६२१
 —रियासतों के राजा-महाराजा—२३८
 —रीतिनीति—१९०
 —विचार—१६८
 —,, पद्धति—१९०
 —व्यापारी—१०४, ३२१
 —व्यापारियों की बस्तियाँ—१०४
 —शिल्पकला—३०४
 —समाज संगठन—१६६
 —सरहद—१२३
 —सामंत वर्ग—५८८
 भारतीयकरण (नौकरियों का)—६२८
 भारद्वाज आश्रम—४४
 —ऋषि—४४
 भाषा (जवान), अंग्रेजी—३५, ३८, ३९,
 ४१, १३२, १७५, २९६, ३२९,
 ३९९, ४२२, ४२७-२८, ४७०,
 ६२८-३०, ७००, ७९७, ८२८, ९४१,
 १०८६, १११४, १३३२
 भाषा अरबी—१९४, २०९, २२०, २२४
 २७३, २८१, ३०७, ३१६, ६२३,
 ६९८, ८३५, १०१२, १०७९,
 १०९१
 —आर्य्य—४०, ६९८
 —आसामी—४०
 —इटैलियन—३९५, ३९९, ६९४,
 ११५४
 —ईरानी—१००७
 —जड़िया—४०
 —उर्दू—४०, १२१, ३४९, ३९९,
 ४३८, ८८९
 —कन्नड़—३९, ४०, ३५९
 —कैल्टिक (योरप) की—१८१
 —गुजराती—४०, ३९९
 —गैलिक—८२०, ८२८
 —चीनी—१७५, १८०, १८४, ३२२,
 ३८२, ४६७, ६३५
 —जर्मन—३९९, ५७८, ७३२, ७३७,
 ७६९, ११२०
 —तमिल—३९-४०, १४९, १८६,
 ३५९, ३७३
 —तातारी—१०११
 —तुर्की—१०११-१२, १०८१
 —तेलगू—३९, ४०, १२२, ३०२,
 ३५९
 —दिल्ली की—१०१२
 —द्रविड़—४०, ३५९, ३९९
 —पंजाबी—५४५

९०१, १०३४, १०७४
 मदरास उत्तरी,—३९
 —दक्षिणी—३९
 —का किला—४६३
 —की स्त्रियाँ—७८८
 —गरीब—७६१
 —, संपन्न—७६१
 मदिरा निषेध—१३१२
 मदीनत-उन-नबी—२१०
 मदीना—२१०, २११, २१६, १०१५,
 १०७३, १०९२, १०९४, १०९७
 मध्य पूर्व (पश्चिमी एशिया तथा फ़ारस)
 —६९०, ६९२, ८५१, १०६८-६९,
 १०७२, १०७७, १०९९, ११०९-१०
 मध्यप्रान्त—४०
 मध्यम वर्ग—३४१, ३९२-९३, ४०१,
 ४०४, ४०६-४०७, ४२७, ४२९-
 ३०, ४५३, ४९१-९२, ५१०, ५१६,
 ५२३, ५३५, ५९५, ६३०-३१,
 ६६१, ६७२, ६७६, ७१०-११,
 ७१३, ७१८, ७३४, ७८८, ७९२,
 ७९६, ८४०, ८४५, ८५४, ८८६,
 ८८८-८९, ९१५, ९१७, ९३१, ९५२,
 ९५९-६०, १०१३, १०१५, १०२६,
 १०२८, १०३२, १०४५, १०४७-
 ४८, १०५३, १११२, १११५,
 ११२५, ११५६, ११६९, ११८३,
 १२०७, १२०९, १२२६, १२४३,
 १२८७, १२८९, १२९१, १२९२,
 १२९५, १२९७, १३१३, १३१४,
 १३१६-१७, १३१९-२०, १३२३

मनरो—५६२, ८१०
 '—सिद्धान्त'—५६२, ५६६, ८१०-
 ११, ११५१
 मनिला—१५२
 मनिल्ला गैलियन—३७७, ३८८
 मनु—१५३
 मनुष्य, अपना कुटुम्ब बनाता है—९१
 —का प्रकृति और जंगली जानवरों
 के खिलाफ़ संघर्ष—९१
 —का वंश,—७४१-४३
 —के अधिकार—७५०
 —के अधिकारों की घोषणा—५२१,
 ५२२, ५२५, ५३५-७५०
 ममी (श्रीमती कमला नेहरू)—८, ११,
 १४, २०, २१, ६३, ७३, ८९, २९७,
 ३७९
 मर्दुमशुमारी—१६९-७०
 —, अमेरिका की—१७०
 —, चीन की—१७०
 मर्साई-वेरुत—१०७५
 मलक्का—३४४, ३७२, ३७४-७५, ३७७-
 ७८, ३८१, ४५०, ५४८, ६६९-७०
 ६७४
 मलावार—४०, ४१, ८८, १०४, १२२,
 २४३, २४९, १०७१
 मलाया—१५०-५२, १९७, ३४४, ३७३-
 ७५, ३७८, ४३१, ५६४, ५६७,
 ६६९, ६७३-७५, ८८७
 —द्वीप—५०, ६७३-७५
 —प्रायद्वीप—१५१, १९७, ३८४,
 ३७३-७५, ६६९, ६७३-७४

मंगोलों की सभा—३१३
 मंचूकुओ—११८८-९०
 मंचूरिया—१७२, ३११, ३१९, ३५०,
 ३८३-८४, ४६८, ४७१, ६५३-५४,
 ६५६, ६६०, ६६२-६३, ६६५, ९४४,
 ९४६, ११७९, ११८३-९०, १२१९,
 १२८३, १३०५, १३३०-३१
 —उत्तरी—६५५
 मंडाले—८५५
 मंदिर, अंगकोरवाट—१९६-९७, ६९४
 —आनन्द—३७३
 —कैलाश—१८७
 —जैन—३६३
 —बौद्ध—१२४, १५२, ६९४
 —लक्सर का—६९२
 —शिव के—१९०, ३७२
 —हिन्दू—४४८
 —हैरोड का—१०८९
 मकदूनिया—७४, ७६, ९४, १०३, ११६,
 ६९६, ८३४
 मकाओ—३८२-८३
 मक्का—१९, २०८-०९, २११, १०१५,
 १०७३, १०८०, १०९२-९६
 मगध—४, ४४, ७८, ११९, १२२, १५६
 मजदूर, अंग्रेजी—७६०, ७७२,
 —का नेता—७६१
 —आन्दोलन—७६०, ७६३, ७७०,
 ७७३, ११५४, १३१९
 —आन्दोलन की असफलता—१३१८
 —चीनी—६४५
 —ब्रिटिश—७६३

मजदूर वर्ग की उत्पत्ति—७६५
 —संगठन—७६०, ७६८, ८६०
 —संघ—५७५, ६१८, ७६०-६१,
 ७६३, ७६५, ७७१-७४, ७७६,
 ८६९, १०१५, १०३२, १०३४-३५
 ११५४, ११७२, ११७६, ११७८
 १२९२, १२९६-९७,
 —संघ का आन्दोलन—७६३,
 —संघों का संगठन—७७१
 मजदूरों की श्रेणी का जन्म—५७४
 —की सहयोग समितियाँ—७६०
 मजलिस—७०७, ७०९
 मज्जापहित—१५०, १९९, ३७०, ३७२,
 ३७५, ३८१
 मठाधिकारी—२३८
 मथुरा—४४, ९९, १२१, २२६-२७, ४५४
 मत, ओमोटोक्वो—११८१
 —, ईसाई—१३०-३१, १६४,
 १७०, २८३, ३१६, ८१७
 —, कनफ्यूशियस—१०५-०६
 —, ग्रीक आर्थोडॉक्स—१०८३
 —, ग्रीक कैथलिक—१०८३
 —, राजकीय ईसाई—१६३
 —, लैटिन—१३९
 —, वहाबी—१०९४
 —, शमा—३१३
 —, शिटो—६४८, ११८१
 —, शैव—१८८, १९०, ३५७
 मत्स्य न्याय—५०१
 मदरास, प्रान्त—३९, ३६८, ६०७
 —शहर—१२२, ४५०-५१, ६०१,

- ४६९, ४८४, ५०५, ५६६, ६४९,
६५६, ६८१, ६८५, ७४१, ८०१,
८१४, ८५७, ८६१, ९४८, ९७६,
११४५-४६, ११८२, १२१४-१५,
१३३०, १३३२
- महासागर भारतीय (हिंद) — ३७८, ३५०,
११४६
- महेंद्र — ९९
- मांटकार्लो — ९९६
- मांटगुमरी — ५१
- मांटिनिग्रो — ८४६-४७, ८४९
- माटेगु-वेम्सफ़ोर्ड रिपोर्ट — ९६७, १०१४
- सुधार — १०२०, १०२३
- माटेस्व्यू — ४८०, ५१२, ६७९
- मांट्रील — ५०५
- मांडव — ३६३
- माइनास — २१
- माइरस — १०६९
- ‘माई लाइफ़’ — ९२१
- माउण्ट एवरेस्ट — २०४
- ब्लैक — ३३
- माडरेट — ९५९, ९६०
- माडर्न सर्कस — ९२१-२३,
- मानसिंह, राजा — ४३८, ४४१
- मायापान — २६५
- माया, महारानी — ५८
- संघ — २६५
- सन्न्यता — २६३-६७
- मारत — ५२४, ५३१
- मारसार् — २७, ५२७
- मारियान — ६१७, ८८७
- मार्क एंटनी — ११५-१६
- मार्कोपोलो — १७८, ३०२, ३२०-२५,
३४१, १०७०
- ‘————— का यात्रावर्णन’ — ३२४
- मार्क्स ओरेलियस एण्टोनिनस — १४४,
१६२, ४७०
- मार्क्स, कार्ल — १२७, ५७८, ७२९-३०,
७३३, ७६३, ७६६-७२, ७७४,
७७८-८३, ८५७-५९, ९१०, ९१७-
१८, ९३८, १११५, १२०१, १२३६,
१२८७-३४८
- और मजदूर संगठनों की वृद्धि —
७६७-७४
- के सिद्धान्त — ५७८
- मार्क्सवाद — ७७०, ७७२, ७७५-८३,
८५९, १०२२, १११६, ११५८,
११६२, १२९६, १३०३
- जर्मनी और इंग्लैंड का — ११६२
- मार्गन पियर पाण्ट जे० — १३११
- शुस्टर — ७०८
- मार्टिन लूथर — ४०२, ४०४-०५
- मार्न नदी — ९०६
- मार्ले-मिण्टो सुधार — ६३२
- मार्शल फोक — ९०६
- मार्शल सर जॉन — २६८-२६९
- मार्नेलीज़ — २७, २८०, २९५, ३२७,
१०७५
- मालवा — ३६२-६३, ४५७
- मालवीय, पंडित मदनमोहन — ६२९
- माल्टाटोन्टा एनरीको — ७६६, ७७३
- माल्दिनोवस्की — ८६५

मलाया राज संघ—६७४

मलिक काफूर—३०६

मलेशिया—१७२, १७४, १८६, १९५,

१९७, १९९-२०१, २५८, ३०१,

३०३, ३१८, ३६९, ३७२-७६,

३७९-८१, ३९१, ४३२, ६६९

—, हिंदू—१९७

मशीन, आधुनिक—१६१

—का आगमन—४८९-९५

—की खोज पर योरोप में दंगे—४९७

—की तरक्की की सदी—५६५-६७

—के करघे की खोज—४९७

—तोड़नेवाले—४९७

मसजिद, जामा (दिल्ली की)—४४७,

१०१७

—, जामी (अहमदाबाद की)—३६३

—, मोती (आगरा की)—४४७

मसाले के द्वीप—३४५, ३७६-७७, ६६९

मसीहा—१२८

मसूरी—८-१०, ५२, २४९, २५२

महमूद गज़नी—२२३, २२५-२८, २३२,

२३४, २५३, २६०-६१, २७७,

२९८, ३००, ३०३-०४, ३५२, ६९९

'महात्मा गांधी की जय'—६१०

महादेवी (गुप्त सम्राटों की पाल्तियों की

उपाधि)—१५७

महानदी—९७

महान् खान—(देखो खान महान)

—झगड़ा—३२९

—मुगल—४३७, ४७०

'—हत्यारा'—८५०

महाभारत (ग्रंथ)—२७, ३८, ४५, ७६,

७९, १०४, १४३, १५५, १८६,

३५९, ४५८

महायुद्ध—(१९१४ से १९१८ का)—

१३७-३८, २८१, २८७, ३१७,

३५३, ४२०, ४८७, ५६५, ६१७,

६३३, ६५८, ६५८, ९८९, ७०८,

७२६, ७४४, ७६०, ७६९, ७७२-

७४, ७७६, ७८५, ८१५, ८३२,

८४१, ८४८, ८५०-५१, ८६५,

८८२-८३, ८८७-९८, ९०१, ९०९,

९४२-४३, ९४६-४८, ९५१, ९५३,

९५६-५८, ९६१-६३, ९६७, ९७४-

७६, ९७९, ९८२-८४, ९८६-८७,

९९३, ९९६

—का कारण—२८७

—की गति—८९८-९०९

—की शुरुआत—८७३-८३

—के बाद की दुनिया—९७५-८४

—से पहले के सौ वर्ष—५६४-७२, ५८२

महायानी मूर्तियाँ—१२५

महाराष्ट्र प्रदेश—१८५, ३०१, ३०३,

३६४, ६३०, ६३१,

महावीर—५७-५८, ९४

महासागर, अटलांटिक—२१४, ३४४-

४५, ४२२-२३, ५०४, ५५५, ५६१,

८००, ८०२, ८१४, ८१६, ८२१,

८३३, ८७०, ९०२, ९०६, ९५४,

१३३२

—प्रशांत या पैसिफिक—१६९, १७२,

३१२, ३२५, ३४४-४५, ३७७-७८,

- ८७, २११, २२२, २२४-२५, २२८,
२३५, २५४, २७५, २७७, २८१,
२८९, ३०६, ३१३, ३१६, ३३२-
३३, ३५५-५७, ४३१, ४३९, ४४३,
५८९, ६२१, ६२४, ६२९-३१, ६४५,
६९५, ८४०-४१, ८४४-५०, ८८८,
८९१, ९६१, १००६-०९, १०१२,
१०१५, १०२१, १०२६-२८, १०३०,
१०८०-८१, १०८३-८५, १०८७,
१०८९-९१, १०९३-९४, ११०७-
०८, ११३८
- मुसलमान, अफगानी—३०५
- , अरबी—१७१, १८५, २१७, २२५
- ईरानी—२९९
- प्रचारक—२६१
- शिया—७०९
- स्पेनिश—३३२
- हिंदुस्तानी—८९०-९१, १००५-६,
१०५२
- मुसलमानी दुनिया—२३५
- सिक्का—२२६
- मुसलमानों का शोषण—२१२
- मुसलिम लीग—९६०
- शरियत—४३९, १००९
- मुसोलिनी, बैनिटो—७७३, ८०९, ११४४,
११५२, ११५४-५७, ११५९-६३,
११६७-६८, १३३७, १३४२
- इल डचूस—११५९
- और इटली का फ़ैसिज्म—११५२-६२
- मुस्तफ़ा कमालपाशा—१३८, २१७, ३१८,
२३९, ७०८, ८४९, ९००, ९६५,
- ९६८, ९८०, ९९४-९५, ९९७,
१०१३, १०२४, १०५९, १०७२,
१०८०, ११०९-११, ११६४, १२१५
- मुस्तफ़ा कमालपाशा का अतीत से विच्छेद—
१००४-१३
- मुहम्मदअली—८३६-३७
- मुहम्मद बिन कासिम—२२४
- (बिन)तुगलक—३०७-०८, ३५८,
३६०, ३६१, १०७१
- मुहर्म्म—२१५
- मूर्तिपूजा—१३९
- मैंगत्सी—२८५
- मैचेस्टर—६०१, ७६१, १३३४
- मैंडेट—९७२
- इंग्लैण्ड के (ब्रिटिश)—१०८०,
१०९९, ११००
- फ्रेंच—९९९, १०८०-८१, १०८५
- मेकार्टनी, लार्ड—४७२
- मेकियावेली—१२७, ४००, ४०९, ४४७,
८७२,
- मेक्सिक्की टिरेंस—९८६
- मेगस्थनीज—८०, ८२, ९७, १२२, १४९
- मेघवर्ण (सीलोन का राजा)—१५६
- मेज़िनी ग्वीसेप—७१९-२२, ७५४, ११६७
- मेटिमोरी गियाकोमो—११५९
- मेनशेविक—८६४, ९१७-१८, ९२०-२१
- मेनांडर—७०, १२०
- मे-पलावर जहाज़—४२३, ५०४, ५०६
- मेरठ—३५५, ५८९, १०३९, १०४३
- ‘—केस’—१०३९
- पड्यन्त्र—११८४

माल्टा—९९८, १००८, १०६४
 मास्को—२९६, ३१५, ३५०, ४८४,
 ५५१-५२, ७७४, ८५२, ८५४,
 ८५७, ८६१-६२, ९१४, ९२९-३१,
 ९३३, ९३८-४०, १०७६, १११०,
 ११७८, ११९८, १२११-१२, १२१६,
 १२१९

मिटो-माल्ले सुधार—८८८

मिकाडो—१७६, ६१४, ६२०

मिडी—२७५

मिदहत पाशा—८४८

मिनामोतो—२४६

मिराबो—५१२, ५२३-२४

मिल जॉन स्टुअर्ट—७५२

मिलन (या मिलान)—२९५, ११५५,
 ११५७, ११६१

मिलनर, लॉर्ड—१०५४, १०५७

मिल्टन—४००

मिस्र—१३, १८, २१-२४ २६, २९, ३४,
 ३६ ३८, ४६, ४८, ६४, ७४, ७५,
 ७७, ९३, ९५, ९७, १०२-०४, ११६-
 १७, १२२, १३६, १४२, १४४, १४६,
 १६७, २०३, २०६-०७, २१०, २१३,
 २१७, २१९, २२२, २३४, २५४,
 २६८, ६९, २७९, २८१, २८६, ३११,
 ३१७-१९, ३२७, ३३४, ३३९, ३४२,
 ३४८, ३७७, ५४२-४५, ५५६, ५६०,
 ५६७-६८, ५८०, ५९३, ६१३, ६९१,
 ६९६, ६९८, ७०४, ७०६, ७२२,
 ७८६, ७९९, ८३३-४२, ८४४-४५,
 ५८०, ९००, ९३२, ९५८, ९६३,

९६५, ९६८, ९९८-९९, १००२,
 १००७, १०५०-६८, १०७१-७२,
 १०७७, १०७९, १०९१, १०९५,
 १०९९-११००, १११४, १२५८,
 १२७३, १२७५, १३१९

मिस्र का प्राचीन इतिहास—८३३

—की आज़ादी की लड़ाई—१०५०-६०

—की चित्रलेख पद्धति—५४५

—की व्यवस्थापक सभा—९००

—की स्वतंत्रता का ऐलान—१०५६

—प्राचीन—१०४, ११०, १३५

—पर ब्रिटिश अधिकार की शुरुआत—
 ८३८

—पर ब्रिटेन का कब्ज़ा—८३३,
 ८४२

मिहर गुल—१५८

मीकांग नदी—१९६

मीटर प्रणाली—५३२-३३

मीडास—८००

मीर जाफ़र—४६१

मुक्त व्यापार (अमेरिका का)—
 ६९५

मुत्शीहितो—६४९

मुद्राप्रणाली की गड़बड़ी—११३१-४०

मुमताजमहल—४४७

मुरा—७९

मुरावीफ़—६४४

मुरासाक्री—३९०

मुशिदावाद—४६०, ५९४

मुलतान—२२४, ३६२

मुसलमान—१४७, १५०, १७०, १८६-

- यहूदी—६९, ६९२, ७९१, ८०९, ८१३,
 ८५२, ८५६, ८६२, १०१५,
 १०८३, १०८५-८९, ११२२,
 ११६८, ११९८, १२२३, १२९३-
 ९४, १२९६, १२९९, १३००
 १३१७, १३२३
 —फिलासफर—२८६
 —वतन—१०८७-१०८८
 यांगसी (त्सी) नदी—६६७, ११७५
 याओ—४६
 याकूब वेग—६४५-४६
 यामातो—१७५, १७७
 यारकंद—१२३, १७९, ६४६, ११९०
 यार्क—१५०
 युंगलो—३८०-८१
 युआन शी कार्ई—६६६-६८, ९४३
 युक्तप्रान्त (संयुक्त प्रान्त)—२०, ४०,
 १२३, १५४, ३५५, ४४४, ५८९,
 ६०४-०५, ६०९, ९०८, १०२४,
 १०३८-३९, १०४२, १०४४,
 १०५६, ११८०, १२५३
 युक्लिड—१०३
 युग, अंधकार का—१६३-६४, २०४-०५
 ३३९
 —अव्वासी—२१८, २२०
 —आगस्टस—१३४
 —आरंभिक ताम्र—६९२
 —आरंभिक बौद्ध—६९३
 —एलिजावेथ का—४२३
 —औद्योगिक—१२७७
 —कलि—७४४
 युग, कुशान—६९७
 —गाँधी—९८२
 —गुप्त—१५५, १५७
 —तंग—१७६
 —तर्क—७५०
 —थीवन—६९२
 —नया साम्राज्यवादी—५६८
 —पूँजी—१२७७
 —प्रकाश—६४९
 —प्रस्तर, (पाषाण)—१६०, २६४
 —प्राचीन—१४९, १५९
 —मध्य—२२०, २७६, २९२, २९७,
 २९९, ३३४, ३४०, ३४७, ३९५,
 ४०१, ४०७, ४२०, ४७६-७७,
 ४९५, ६८९, ७३९, १२९९, १३४८
 —का अन्त—३३४-४०
 —मशीन—४९०, ४९७, ५९४
 —मिंग—२४५, ३८१-३८४, ४६५
 —मेइजी—६४९
 —मौर्य—९७, १००, १४९
 —यंत्र—१२३०
 —रामायण—४४१
 —रिनैसां का—३८२
 —विक्टोरिया—७८३-९१, ७९६-९८
 —वैदिक—१८३
 —शक्ति—१२३०
 —सफ़ावी—७०२
 —सहस्रवर्षिक—१६३
 —सुवर्ण, (सत)—१२८, १३४,
 ७४४, १२२९, १२३५
 —हिंदू—२२८

मेरिडिय, जार्ज—७२२-२३
 मेरिया थैरैसा—४८३
 मेरी (ईसा की माता)—१४०
 ———लुइसी—५५०, ५५३
 ———(विलियम द्वितीय की रानी)—
 ४२६-२७
 मेसपाँट—१०९९
 मेसिडोनिया—१०६९
 मेसीना—१०९, १११
 मेसोपोटामिया—३४, १३२, ६९१, ६९८
 १०७३, १०९७
 मेहता, फ़िरोज़शाह—६२९
 मेहमतअली—(देखो मोहम्मदअली)—
 मैकी, मेजर—९०३
 मैकडानल्ड, रेम्से—७७३, ९६८ ११४७,
 १२५७, १२७१-७२, १२८० १३२२-
 २३
 मैक्सिको—१६९, २४०-४१, २६४-६७,
 ३४६, ३७७, ४१२, ८०१, ८११,
 ११२९, १३३२
 ———का पंचाग या संवत्—२६४
 मैगलन का जलडमरूमध्य—३४५
 ———विट्टोरिया जहाज—३४५, ३७७-७८
 मैग्नाचार्टा—२८८, ३११, ४१२, ४२१
 मैज़ारिन—४१४, ४७६
 मैटरनिख—५५३, ५६०
 मैटरलिक—१३
 मैटियोरिक्की—३८३
 मैडम गिलोटिन—५१९
 ———डैफीसिट—५१६
 मैफियोपोलो—३२१

मैरेथान—६४, ६५, ६७, ६८
 मैसूर—८८, ३६८, ४६३, ५६३, ५८२-
 ८३
 मोजार्ट—४८८-८९
 मोटले, जे० एल०—४१४
 मोमियार्ड—१८, २२
 मोमिन (लोग)—२२७
 मोरक्को—२१४, ८३९, ८४१, १०७०-
 ७१, ११६३, १२८५-८६
 ———पश्चिम—९८१
 मोसल—१८४, १००३, १००७, १०७३
 १०७७, १०९७-९९, ११०२, ११४७
 मोहेनजोदारो—१७, २६, ३९, ४९, ५१
 ८६, १०१, २६८-७०, ६९१-९३
 मीर्यकाल—१४९
 मौलाना अबुलकलाम 'आज़ाद'—९६१
 ———मुहम्मदअली—९६१, १०९५
 ———शौक़तअली—९६१
 मौलियर—४००
 म्यूज़ी गाइमे—६९०
 म्यूनिच—२९५
 म्लेच्छ—१२०, १४३, १५४
 य
 यंग योजना—११२६
 यथरीव—२०८-०९
 यमन—१०९२-९३, १०९७
 ———का इमाम—१०९३
 यरमक—४६९
 यवन—१४९
 यशोधर्मन—१५८
 यशोवर्मन—१९६

२८९, २९०, २९२-९८, ३०३, ३०८,
 ३१०, ३१२, ३१५-१७, ३१९, ३२१,
 ३२४-२६, ३२८-३१, ३३३-३५,
 ३३७-४४, ३४७-५०, ३५२, ३६०,
 ३७५-७८, ३८०, ३८२, ३८५,
 ३८७, ३९१-९४, ४००, ४०१,
 ४०३, ४०६-१४, ४१९-२२, ४२५-
 २६, ४२९, ४३१-३३, ४३६, ४४२,
 ४४९, ४५२-५३, ४५९, ४६९, ४७३-
 ७९, ४८२-८८, ४९३-९४, ५०३,
 ५०५, ५०९-११, ५१३, ५१७-२०,
 ५२२, ५२४, ५२६, ५३५, ५४२-
 ४३, ५४८, ५५०, ५५२-५५, ५५७-
 ५५९, ५६१-६२, ५६४, ५६६-७३,
 ५७५, ५८०-८१, ५९३-९५,
 ५९९, ६०१, ६१३, ६३०, ६३३-
 ३४, ६३७, ६४४-४५, ६४७-४८,
 ६५०, ६६१, ६६३, ६६५, ६६८,
 ६७०-७३, ६७६, ६८१, ६८९-९०,
 ७०३-०५, ७०९-१२, ७१४, ७२३-
 २६, ७२८, ७३८-४०, ७४२-
 ४४, ७४८, ७६३-६४, ७६६-७०,
 ७७४-७५, ७८३-८५, ७८७, ७८९-
 ९०, ७९७, ७९९, ८०१-०४, ८०६,
 ८१०-११, ८१५-१७, ८३६-३७,
 ८३९, ८४२-४३, ८४६-५०, ८५३,
 ८५५, ८६४, ८६६, ८६८, ८७१-
 ७३, ८७५-७९, ८८१-८२, ८८९,
 ८९१, ८९४, ९१६, ९३३-३४, ९३९,
 ९५२, ९६३, ९६५-६७, ९६९,
 ९८०, ९८४, ९९६, १००३, १००७,

१०३९, १०५१, १०६९-७०,
 १०७२-७५, १०७८, ११०८-११,
 १११४-१७, ११२२-२३, ११२७-
 ३२, ११३४, ११४१-४२, ११४४,
 ११४९-५२, ११६२-६५, ११७०-
 ७१, ११८२, ११९१, ११९८,
 १२१९, १२२१-२२, १२३४,
 १२३६, १२३८-४०, १२४३-४४,
 १२४७, १२५१, १२५३, १२५८-
 ५९, १२६६-६७, १२६९-७१,
 १२७८, १२८४-८५, १२९०, १२९९,
 १३०३, १३०७, १३१०, १३१६,
 १३२०-२१, १३२४, १३२७, १३३०,
 १३३२, १३३६, १३३८, १३४०,
 १३४७, १३५९

योरप उत्तरी—३३, ३४, ५०, १०२,
 ११३, ११७, १४२-४३, २१०,
 २३३, २९४, ३२९

—और एशिया—११०८

—का अंधकार युग—१०६९

—का नया नक्शा—९६२-७४

—का प्रभुत्व—२२५, १३४७,

—का मजदूर आंदोलन—१२७१

—का मध्ययुग—२२५, ४७६ १३४७

—का मरीज,—५६७, ८४२, ९४४

—का संगीत—४८८

—की क्रांतियाँ—७८५

—के कलाकार—६९५

—के देशों का निर्माण—२२९-३४

—के मजदूर—७६७

—के मजदूर आंदोलन का पतन—७७०

युग, हिंदू साम्राज्यवाद का—१४८

—हिम—३२, ३३

युद्ध—(देखो लड़ाई)

युधिष्ठिर—१४३

यू. एस. एस. आर.—९७६, ११९८

यूकेतान—२२६

यूक्रेन—९३०, ९३३, ९६६, ११२३,

११४३, ११९९, १२००

यूगोस्लेविया—८७८, ९६६-६७, ११४३-

४४, ११६४, १३०१, १३३६-३७

यूडनिच—१९३५-३६

यूफ्रेटीज़—२२, २३, २०७, १०९७

यूनिमिंगयून—६४१

यूनान—१३, २२, २४, २६, २७, ३०-

३२, ३४, ३५, ३८, ४०, ५०, ५७,

६४-६७, ६९, ७०, ७५, ७८, ९३-

९५, १०२, १०९-१०, ११५-१७,

१२२, १२४, १४४, १६२, १६७,

२०३, २०७, २५१, २७०, ३४०,

३९५, ५६१, ५८०, ६९०, ६९४,

७३६, ७८४, ८३४, ८४४, ८४६,

७४९, ८९५, ८९६, १०००-०१,

१००३, १०६९, ११६४, १३४७

—का सुवर्ण युग—९४

—के नगरों का अभ्युदय—२९०

—प्राचीन—१०४, १३४, २२०, ३३९,

७४४

यूनानी—१२२, १२३, १२४

—आग—२५५

—गाथायें—२१३

—दर्शन—३०७

यूनानी पोशाक—१८१

—विद्या—८३४

यूनियन आफ सोशलिस्ट एण्ड सोवियट

रिपब्लिक्स—९७६

यूनियनिस्ट—७९१

यूनिवर्सिटी—(देखो विश्वविद्यालय)

यूराल पहाड़—४६९, ९३१

यूरिपिडीज़—६९

यूरेशियन—८५३

यूरोपियन (लोग)—(देखो लोग में)

—देश—२३८

—प्रतिद्वंदी—३८८

—शैली—१८१, ३८८

यूलीसस—२७

युसुफ़—४३३, ६९५

येगूसी बगातुर—३०९

यैदो—३८७, ३८९

योआकिम दु वेले—३९९

योकोहामा—११८२

योरप—१८, १९, २४, २६, २८, ३२,

३४, ४०, ६१, ७०, ८५, ९४, ९९,

१०२, १०८, ११७, ११९, १२२,

१३१, १३७-३८, १४०, १४२,

१४५-४७, १५७, १५९-६०, १६२-

६४, १७०-७१, १७३, १८०, १८९,

१९४, २००, २०१, २०३-०४, २०६,

२०९, २१०-११, २१४-१५, २१७,

२१९, २२२-२३, २२५, २२९-३०,

२३३-३४, २३६, २३८-४२, २४४,

२४७, २५४-५८, २६२-६४, २६७,

२७०-७३, २७६-७९, २८१-८६,

योरप में विद्या की तरक्की और पुनर्जागृति
 २९६-१७, ३३९
 —में शस्त्रीकरण की दौड़—८७६
 —में श्रद्धा और विश्वास का युग—
 २९०, २९२-९३
 —में संगीत की उन्नति—४८८
 —में सामाजिक क्रांति का अंदेशा—
 १११६
 —में सार्वजनिक शिक्षा की तरक्की
 —५८०

र

रंगून—१०७४
 रंजीत फूफा (आर० एस० पंडित)—३९
 रजफवेग—९९७-९८, १००८
 रणजीतसिंह—४५५, ५६३, ५८५
 रनी मीड—२८८
 रमण, चन्द्रशेखर व्यंकट—८८९
 रसायन शास्त्र—१६०
 रस्किन—८९३-९४
 'राइज ऑफ़ दी डच रिपब्लिक—४१५'
 राइन नदी—११७, ९६२
 —का कान्फिडरेशन—५४७
 —लैण्ड—९०७, ९६२, ११२६,
 १२५७
 राउलट विल—१०१५-१६
 राजन—३३६
 राकेट (एंजिन)—४९८
 राजधर्म—१४६
 राजतरंगिणी—३९, १५८, ३६६
 राजपूत रानी—४४६
 —(लोग)—६७, १२२, ३६३,

४३५, ४३९, ४४८
 राजपूत सरदार—४३८, ४४८
 —सूर्यवंशी—६१४
 —स्त्रियाँ—३६१
 राजपूताना—४०, ५८, १२०, १५८,
 ३६३, ४४०
 राजराज चोल—१८६-८७, २५३, ३०१
 राजवर्धन—१८९
 राजशेखर—२२३
 राजा—(बादशाह)—४२, ५३,
 ८०, ८१, ९०, ९१, ९६, २३६,
 २३८, २५६, ३३४, ४७५, ४९१
 —, अंग्रेजों का—२३१, ४२७
 —, आर्य—१५४
 —, इंग्लैण्ड का (के) २७९, २८१,
 २८७, ३३५, ४२५, ४२८, ४५०,
 ४७२, ४७५, ५०४, ५०६, ६१८,
 ६३५, ६३७
 —, इटली के—४०९, ७२०-२१
 —, ईरान के सासानी—२१२
 —, ईरानी—६६, ७५, ४३६, १०६९
 —, एकेमेनीद—६९७
 —, कंबोजी—१९६
 —काब्रोज के—२९८
 —, काश्मीर के—२२७
 —का कर्तव्य—१९१
 —, कुशान—१५६
 —के ईश्वरीय अधिकार—८१, १९१,
 २३०-३१, २८६, ३३३, ४११,
 ४२३-२५, ४२९, ४२४, ५१४,
 ७११, ८५२

योरप के युद्ध—७६८

—दक्षिण—१८५, ६९०, ७६९,
१२८७, १३३१

—दक्षिण-पूर्वी—१०२, १६२, २२९,
२८१, २८३, ३११, ३४१, ३४८,
४०२, ४०८, ४३०, ४८५, ५६८,
६८८, ७६५, ८४२, १२६८-६९

—पश्चिमी—९६, १३१, १३९-४०,
१६२, २१४, २२९, २३२, २४१,
२५७, २६२, २८९, २९२, २९४,
३१८-१९, ३३५, ३४१, ३४८-४९,
३९१, ४०२, ४०७, ४२९-३०,
४६८, ४८४, ४८७, ५६६-६७,
५७२-७३, ५७६, ५७८, ५८०-८१,
५९४, ५९८, ६५२, ७१०, ७५३-
५४, ७५९, ७७३, ७७६, ७९७,
८१७, ८५१, ८५३-५५, ८५९-६०
८६३, ९१७, ९४९, ९६७, ९७७,
९७९, ९९९, १११४-१५, ११४२,
११४९, १२०२, १२०७, १२४८

—, विद्या और कला का पुनर्जीवन—
१३४७

—पूर्वी—७११, ९६३, ९६७, १०८७,
११२३, ११४३, १२४८, १२६९,
१२७०

—प्राचीन—२८५

—मध्य—३३, ४३, १०२, ११३,
११७, १४०, ३०९, ३१५, ३२५,
५६०, १११५, ११२२-२३, ११३१,
११४२, १२३६, १२५१, १२६८,
१३२१, १३३७-३८

योरप में अन्तःकरण और भाषण की
आज्ञादी—३३०-३१

—में अन्वेषण की भावना—२९७

—में आनेवाली सामाजिक क्रांति—
९६३

—में किताबों की छपाई की शुरुआत
—३९३

—में क्रांतियों का वर्ष—७६८

—में खलवली—३९१-९५

—में तानाशाही, (१६ वीं और १७ वीं
सदी में)—४०६

—में नेपोलियन की लड़ाई के बाद
आर्थिक मंदी—७६०

—में प्लेग की भयंकर महामारी—
३३४

—में मजहूबी और राजनैतिक आज्ञादी
के लिए लड़ाई—३३०-३१

—में मशीन तोड़ाई का इतिहास—
४९७

—में महायुद्ध के बाद की क्रांति जो
नहीं हुई—१११४-१५

—में राजनैतिक और आध्यात्मिक
हुकूमत के खिलाफ आज्ञादी की
भावना—२९६

—में राज्यक्रांति का वर्ष—५६१

—में राष्ट्रीयता का जन्म—४७६

—में राष्ट्रीयता और साम्राज्यवाद के
बीच लगातार संघर्ष—१११४

—में लड़ाई का खतरा—१३०७

—में विज्ञान और बुद्धिवाद का उदय
—४७७

राजा, हिन्दुस्तान के गुलाम—३०८
 —, ,, के सामन्त—४५३
 —, हिन्दुस्तानी—७५, २१४, २२४,
 ९५२
 —, हिन्दू—३५५
 राजाशाही—७९८
 राजेन्द्र—१८६, १८८, २५३, ३०१
 राज्य (सल्तनत)
 —, अजटेक—२६६
 —, अफ्रीका के—९६८
 —, अरब—२०८, २७१, २७५,
 १०७९-८०,
 —, अल्जेरिया—१०८१
 —, आंध्र—१२२-२३, १४८, ३०३
 —, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का
 सम्मिलित, ४२३
 —, इटली के—७८५
 —, 'इनका'—२६७
 —, ईसाई—२५४, २५७, २७३,
 २७८, २८१
 —, उत्तरी अफ्रीका का मुसलमानी—
 २५४
 —, कंबोडिया का—१९६
 —, कुवलाई का—३१८
 —, कोरिया का संयुक्त स्वतन्त्र—
 २५३
 —, खीवा या खारजम का (मुसल-
 मानी)—३११, ६९९
 —, गुप्त—१५९
 —, गौड़ों का—३६२
 —, ग्रेनाडा के—२७४

राजा, चालुक्य—१५९
 —, चीन का—४७, ७७, १५३,
 —, चोल—३०३
 —, जावा का—३७०, ३७२
 —, तुरफान का—१८०
 —, तुर्की का—७०८
 —, तुर्कों का—१३८
 —, दक्षिण भारत के—१२१, ३६०-
 ६५
 —, दक्षिण भारत के पुराने—३६४
 —, पक्चे का—१७५
 —, पल्लवों का—३०१, ३०३
 —, पांचाल—२२७, ३२७
 —, पाण्ड्य—३०२-०३,
 —, पश्चिम यूरोपीय—३१८
 —, पामीर का रेगिस्तानी—१४७
 —, पूर्वी जावा का स्वतन्त्र हिंदू—२५३
 —, पेरू का—२४१
 —, पोलैंड और हंगरी के—५०४
 —, पोलैंड के पुराने—५२४
 —, बहमनी—३६४
 —, बीजापुर का—३६५
 —, ब्रिटिश—२८८, ६१५, ७९२,
 ८८३, १२८३, १३२७
 —, भारतीय आर्य—१५४
 —, मध्य एशिया के—२२५
 —, मध्यम श्रेणी के अमीरों का—
 ७६८
 —, मलक्का का मुसलमानी—३७२,
 ३७४-७५, ३८१
 —, महाराष्ट्र का—३०१

- राजा, केलोविजियन—२३३
 —, केस्टाइल के ईसाई—२७३
 • —, कैथलिक—४१०
 —, खार्जम का—३११-१२
 —, गुप्त—१५७, १६२, ३५९
 —, गुलाम—३५५
 —, चक्रवर्ती—७९, १४२-४३
 —, चालुक्य—३०१
 —, जयपुर का—४४१
 —, जर्मनी का—२८७, ४०३
 —, तंग—२४२
 —, 'ताई-नी पुंग-कोक' के—१७७
 —, तैमुरीय—४६९
 —, थीवन—६९२
 —, दिल्ली के गुलाम—३०३-०८, ८४५
 —, दैवी—२६७
 —, निदरलैंड के—४१५
 —, पीडमाण्ट के—७२०
 —, पौराणिक—१४३
 —, प्रशिया का—७२७
 —, प्रोटेस्टेण्ट—४१०
 —, फ्रांस का (के)—२८१-८२, ३२९, ३३५-३६, ४०४, ४१९, ४२६, ४८२
 —, बहमनी—३६६
 —, बोर्वन—५३५, ५५३, ५५८, ५६०-६१, ७१९
 —, ब्रिटिश—४२६
 —, भोज और गंगू तेली—२२३
 —, मंचू—४६६, ४८१
- राजा, महमूदी—३१३
 —, मिग—४०९, ४३१, ४६६-६७
 —, मुगल—३६४, ४३५, ४४५-४६, ४५५, ४५७, ५८५, ५८७, ६०५-०६, ८३८
 —, मुसलमान—३५५, ३५९
 —, मैसूर के—४६३
 —, यूनान का—५६१
 —, योरप के—२७९, २८१, २८६, ३१५, ३४८, ४०१, ४२५, ४७५, ५१७, ५२०, ५२६, ५४०, ५५९, ५६२
 —, राष्ट्रकूटों का—३०१
 —, रोम का—५५४, ५५८
 —, लाहौर का—२२६
 —, विजयनगर के—३६८
 —, शरकी—३६२
 —, समरकंद का—४३२
 —, सर्वशक्तिमान (योरप में)—२८६
 —, साम्राज्यवादी—१४३
 —, सासानी—१५९, २१०
 —, सिन्ध के मुसलमान—२२६
 —, सीलोन का—३७५
 —, सुमात्रा के—१९८
 —, सेलजुक—२७८
 —, स्काटलैंड का—४२३
 —, स्पेन के—२७३, ३४४, ३४६, ३८८, ४१८
 —, 'स्वर्ग का पुत्र' (चीन में)—२८५
 —, स्वीडन का—४१९
 —, हिन्दुस्तान के अफगान—४३६

- रायो दी जनेरो—१३३१
 रावलपिंडी—७६
 रावी नदी—५१
 राष्ट्रसंघ—५५८, ६६१, ७०६, ९०७,
 ९६५-६६, ९६९-७३, ९७८, ९८१,
 १००३, १०६२, १०७७, १०८०-
 ८१, १०८५, १०८९, १०९८,
 ११०१-४, ११०६-१२, ११४७,
 ११४९-५०, ११६०, ११८५-८९,
 १२३८, १२८०, १२८३, १२८८,
 १३०४-०७, १३०९-११, १३३१-
 ३२, १३३६, १३३८
 —का शर्तनामा—९७०, ११४९
 —, लघु—१३३७
 राष्ट्रीय आंदोलन, हिन्दुओं का धार्मिक—
 ४५४
 —इकरारनामा—१०९०
 —दिवस—१०१९
 —महासभा (देखो इंडियन नेशनल
 कांग्रेस)
 —लड़ाई—२३५
 —सप्ताह—१०१९
 राष्ट्रीयता की उत्पत्ति—८६९
 —की भावना—२३४-३५, २३९,
 २५७, ४८५
 —————(जापान में)—६४८
 —————(हिंदुस्तान में)—६२३
 —की हिंदू धारणा—१०२६
 राष्ट्रीयता, अरबी—१०८५, १०८८,
 १०९४
 —, आर्थिक—११३३, ११३९
 राष्ट्रीयता, मुस्लिम—१०२६, १०२८
 —, यहूदी धार्मिक—१०८५,
 —, सिख—१०२९
 —, हिंदू—६२४-२५, ६२९
 —, पश्चिमी ढंग की, का जन्म—५७०
 रासपुटिन, ग्रीगोरी—९११-१२, १३१०
 रिचर्ड—२८८
 —आर्क राइट—४९६
 —लायन हार्टेड—२८०
 रिजाखाँ (शाह) पहलवी—७०९, ९८१
 रिनेसां—३३९-४०, ३४८, ३६७, ३८२,
 ३८५, ३९१, ३९५, ४००, ४०१,
 ४०७, ४०९, ४२०, ६९५, ७०२
 (देखो पुनर्जागरण)
 रिफार्म विल—४२७, ४५७
 रिफार्मेशन या सुधार—३९३, ४०२-०४,
 ४०७, ४१०, ४१५, ४७६
 रियासत, अहमदनगर की—४५५
 —कश्मीर—६१४
 —गुलवर्गा की—३६१
 —ग्वालियर—६१४
 —जर्मन—४०७, ५६१
 —जौनपुर की मुसलमान—३६२
 —दक्षिण की हिंदू—३६५-६६
 —प्रशिया की—४८३
 —वड़ीदा की—६१४
 —वाल्कन—४८४
 —विजयनगर—३०८, ३५५, ३६१,
 ३६४-६५
 —बीजापुर की—३६५, ४५५
 —मुसलमान—३५५, ३६४

राजा, मालवा का—३६२-६३
 —, मुगल—७०५
 —, मुसलमानी—३१८, ३६६
 —, मूरों का—२७६
 —, मैमलूकों का—८३६
 —, यामातो—१७४-७७
 —, यूनान के शहरी—१०९
 —, यूनानी—११३, ११७
 —, राष्ट्रकूटों का—३०१
 —, रूसी—२३३, ८५७
 —, रोमन—१०९, ११४, ११६,
 १३५, १४२
 —, लेबेनन का—१०८१
 —, लैटिन—२८०
 —, वर्जीनिया का—५१०
 —, सर्व लोगों का—२५५
 —, सलादीन के वारिसों का—३११
 —, सामूहिक—११६९
 —, सासानियों का—६९७
 —, सिकन्दर का—७७
 —, सिक्ख—५८५
 —, सिसिलिया (या सिसिली के)—
 २५६, ४०८, ७१९
 —, सुमात्रा के—१९७
 —, स्पेन का—४१६
 —, स्पेन के ईसाइयों का—२७४
 —, स्पेनवालों का—६६९
 —, हांगवू का—३८०
 —, हिन्दुस्तान का अंग्रेजी—५८७,
 ५८९, ५९२, ६०७
 —, हिन्दू—१५०, १९६, १९९, ३७०

राजा, हिन्दू चक्रवर्ती—१५५
 राज्यश्री—१७९, १८३
 राणा प्रताप—४३१
 —सांगा—४३५
 राश्रस चाइल्ड—५४८
 रानपुर—३६३
 राफैल—३९६
 रावर्ट इम्मेट—८२३
 रावर्ट ब्रूस—३३६
 रावर्ट हार्ट, सर—६५८
 रांन्सपीयर—५३२-३४, ५३७, ५४२,
 ७५०
 राम (प्रथम)—६७५-७६, १११२
 राम (द्वितीय)—१११२
 रामकथा—१५५
 रामकृष्ण परमहंस—६२४
 —सेवाश्रम—६२४
 रामचंद्र—४४, १५९
 रामचरितमानस—४४४
 रामदास—४५६
 राममोहनराय, राजा—६१५, ६२३
 रामराज्य—७४४
 रामानंद—३५७, ४३८
 रामानुज—३५७
 'रामायण'—२७, ३८, ४९, १५५, ४४४
 रायगढ़—४५६
 रायल एयरफोर्स—११०३
 —एशियन सोसाइटी—११०३
 —डच शेल कंपनी—११९७
 रायलिस्ट—५२०-२१, ५२४, ५२९
 रायसीना—५२

रूस का पचांग—१४१
 —का राजदूत मण्डल—४७०
 —की क्रांति का इतिहास—१२०३
 —की क्रांति के खिलाफ प्रतिक्रान्ति—
 १२४
 —की पंचवर्षीय योजना—१७७,
 १२००-०८
 —की रक्षा समिति—१३६
 —की सिविल सर्विस—१२८
 —, जारशाही—६६१, ७८७, ८४२,
 ८४७, ८५१-५८, ८६०, ८६५,
 ९५६, १०७९, १११५, १२९९
 —, दक्षिण—८६१, ९३०, १०७१,
 ११९७
 —, दक्षिण-पूर्व—९३७
 '—, पवित्र'—८५२
 —, पश्चिमी—९६६, ११२३
 —, पूर्वी—९३१
 —, प्रथम समाजवादी देश—१७७
 —, बोलशेविक—९७१, १०७२
 —में आतंकवाद की शुरुआत—८५६
 —में किसानों की गुलामी का अंत—
 ८५५
 —में मार्क्सवादी क्रांति—८६१
 —में जारशाही का खात्मा—९०९-१९
 —सफ़ेद—११९९-१२००
 —, सोवियट—९०६, ९३१, ९३३,
 ९३८, ९५०, ९५७, ९६५, ९७६,
 ९७७, ९८३, १०००, १००२-०३,
 १०१३, १०७३, ११०३, ११०९-
 १०, १११६, ११२२-२३, ११३६,

११४२, ११४५, ११४७, ११७२,
 ११७९, ११९०, ११९४, १२००,
 १२०३, १२०६, १२०९, १२१४-
 १६, १२२०-२१, १२३१-४३,
 १३०१, १३०२, १३०५-०६, १३-
 १५, १३१७, १३३६, १३३८-३९
 रूसी खुफिया पुलिस—८५६
 —तेल—११९७
 —पूँजीवाद—८५७
 —मजदूरों का प्रजातंत्र—९१७
 रूसे दि लाइली—५२७
 रूसो, जीन जैकस—४७९-८०, ५१०,
 ५१२, ५४०, ७४०
 रेखागणित—४३, ५७, १०३
 रेगिस्तान, अरब का—१०६९, १०९७
 —, ईरान का—१०९७
 —, गोबी का—१७९-८०, ३१०,
 ३२१, ३४६, ६९८
 —, राजपूताना का—४३५, ४४०
 —, सहारा का—१०७१, १०७५
 —, सीरिया का—१४७
 रेमस—२८
 रेलवे चीनी ईस्टर्न (पूर्वी)—९४४,
 ११७९, ११८४
 —ट्रांस साइबेरियन—६५५
 —दक्षिण मंचूरियन—९४४, ११८४
 —वगदाद—१०७३-७४, १०९७
 —साइबेरिया में—८६१
 —हेजाज—१०७३, १०९७
 रेवोल्यूशन (देखो क्रांति)
 'रैड क्रैसैण्ट मिशन—८९१

रियासत, मैसूर—४६०, ६१४

—यूक्रेन की—९३०

—राजपूत—३६३

—सार्डिनिया—५६०

—सिख—४५५, ५६३, ५८५

—हैदराबाद—६१४

रिवाज—गुलाम रखने का—३५८

—परदे का—३५६

—मंचुओं का लम्बी चोटी रखने का—
३८४

—विधवाओं के सती होने का—४४३

रिवियरा—५५३, ५६०

—फ्रैंच—७९३

रिवेरा, प्राइ मो दि—११६३, १२८६

रिशेलू—४०४, ४७६

रीड—९२५

रीस्टैंग—१२९४-९५

रडोल्फ—२८७, ३२६

रुद्रमणि देवी—३०२

रुस्तम—७००

रुहेलखंड—४५७

रुजवेल्ट, फ्रैंक—१२७९, १३०६, १३११

१३१३-१७, १३२१

—का रक्षा का प्रयत्न—१३११-
१८

रुटर—११०६

रून—६

रूमानिया—११२३, ११४४, ११५१,
१२२०, १३३६-३७

रूर प्रदेश—११२६, ११४४, ११४६,
१२९४

रूरिक—२३३

रूस—६, १६, ११७, १३९, १८९,

२३३-३४, २५५, २५७, २८३,

२८९, २९६, ३०९, ३११-१२,

३१५-१६, ३१९, ३३१, ३३४,

३५०, ४०२, ४०८, ४१२, ४६८-

७०, ४७३, ४८३-८६, ५४७, ५५०,

५५२, ५५४, ५५९-६०, ५६३,

५६७, ५६९, ५७१, ५७८, ५८६,

६३०, ६४०, ६४४, ६४६, ६५१,

६५४-५६, ६६०-६३, ७०५-०८,

७११, ७३३, ७८२-८४, ७८८,

८००, ८४६, ८६०-६१, ८६५-६६,

८७५-७६, ८७९-८२, ८९२, ८९५-

९६, ८९९, ९०५-०७, ९१०-११,

९१३-१४, ९१६-१७, ९१९, ९२३,

९२७-३७, ९३९-४१, ९४४, ९४७,

९४९, ९६५-६७, ९७५, ९७७,

९९३-९४, १००३, १०२२,

१०४५, १०७०, ११०६, १११५,

१११७-१८, ११२६, ११३१,

११३७, ११४६-५१, ११५३,

११६२, ११६७, ११७०-७१,

११७७-७९ ११८२, ११८४,

११८९-९१, ११९३-९८, १२००-

०२, १२०५-०६, १२०८-०९,

१२११-१३, १२१६, १२९९-२०,

१२४१, १२८६, १२८९, १३०१,

१३०५-०६, १३१०, १३२१, १३-

३०, १३३६, १३३८

—उत्तर—२९०, ९३१

लंदन डेरी—८१९-२०
 लक्ष्मीवाई, रानी—५९१
 लखनऊ—५९०, ९५९-६०, १०१२
 लग्जैमवर्ग रोजा—१११९
 लटविया—९६६-६७, ११५१, ११९८,
 १२२०, १३०६
 लटीशिया—१३३२
 लड़ाई (या युद्ध) अंग्रेजों की नेपाल से—
 ५८४
 —अधिकारवाद के खिलाफ—३३१-३३
 —अफगानों से अंग्रेजों की—५८७,
 ७८७, ११०८
 —अफ्रियम कुराहिसार का—१००३
 —अफ्रीम की—५६३, ६३६, ११७५
 —अमेरिका की—७८५
 —अमेरिका के वागी उपनिवेशों और
 इंग्लैंड के बीच—५०७-०८
 —आत्मनिर्णय के लिए—७९४
 —आयर्लैंड और इंग्लैंड की—९८६-८७
 —आस्टरलीज की—५४७
 —इंग्लैंड और फ्रांस के बीच—३३५
 —इंग्लैंड की घरेलू—४२८
 —इटली की—७२३
 —ईरान और इंग्लैंड की—७०६
 —ईरान और रूस की—७०६
 —ईरान की—६९
 —उपनिवेशों के हिंदू और बौद्ध राज्यों
 में—१९६-९७
 —,उल्म की—५४७
 —का ऐलान, अमेरिका का जर्मनी के
 खिलाफ—९०५

लड़ाई का ऐलान, आस्ट्रिया का सर्बिया के
 खिलाफ—८८०
 —का ऐलान, इंग्लैंड का जर्मनी के
 खिलाफ—८८१
 —का ऐलान, जर्मनी का रूस और
 फ्रांस के खिलाफ—८८०
 —का ऐलान, जापान का जर्मनी के
 खिलाफ—९४३, ९४६
 —, किसानों की—४०१—४०६
 —, क्रिमिया की—६४४, ७८८, ८४७
 ८५५
 —कैथलिकों और प्रोटेस्टेंटों की
 मजहबी—४७७
 —, कैंनी की—११२
 —कैरे की—११४, ११७, १४५
 —गाल—११७
 —गालिक—११७
 —चीन और जापान का—६५४
 —, और फ्रांस की—६४६
 —, की दूसरी—६४०
 —, चीनियों और मुसलमान अरबों के
 बीच—१७१
 —जर्मन की—९२६
 —जापान और रूस की—६५४, ६६०
 ६६२, ६६४-६५, ११८४
 —जामा की—११३
 —जैटलैंड की—९०४
 —टूर्स की—२१५, २२३, २२९, २७१
 —टैननवर्ग की—८९९
 —ट्राय की—२०२
 —टीक की—७१७

रेड-फ्रंट—११२०

—संडे—

८६१

—स्क्वायर—९४०

रैम ब्रैण्ड—३९७

रैले, सर वाल्टर—४२२

रोजर वैकन—२९७

रोम—२८, ४९, १०२, १०४, १०७-

१८, १२२-२४, १२९, १३२, १३४-

४०, १४२-४४, १४७, १५८,

१६१-६४, १६७, १७०, १७५,

२०१, -०५, २१०, २२०, २२९-३०,

२३२, २३४-३५, २४०, २५९-६०,

२७८, २८०, २८४, २८९, २९३-

९४, ३०१, ३१६, ३२९, ३६८,

३९२, ३९८, ४०१-०५, ४०७-०८,

४१०, ४२२, ५४५, ५६८, ५८०,

७१४, ७१८-१९, ७२१, ७२३,

७३४, ७३८, ७४४, ८३५, १०६९,

१११०-११, ११४९, ११५७-५८,

११६०-६१ १२८८, १३४७

—की बढ़ती—११०-११

—के किसान—२०३

—बनाम कार्येज—१०८-१३

—‘संसार की स्वामिनी’—१०७

रोमक देश—१३२

रोमन अधिकारी—१२८

—क्रानून—१४४

—चुनाव—११७

—पोष—२५७

—विशेष—१४०

—व्यवस्था—२९४

रोमन शान्ति—१३५

—सलामी—११५८

—साम्राज्य का उच्छेद—१३६-४१

—साम्राज्य का पतन—१३३, ४८१

—सिक्के—१२२, १२४

रोमुलस—२८

रोम्यां रोलाँ—१३५०

रोविनसन क्रूसो—४२९, ४८१

ल

लंका—१९, ६०, ८५, ८७, ९९, १२५,

१४९, १५६, १७९, १८६, १९७,

१९९, २४९, २५३, ३०१, ३२४,

३७०, ३७५-७६, ३७८, ४७१,

६१७, ८८७, १०७१

लंकाशायर—५०३, ६१६, ७९६, ८०३,

८०६, ८६७, ९५६-५७, ११३४,

१२४०, १३१२

लंदन—२३९, २९२, २९४-९५, ४२४-

२५, ४३१, ४६४, ४८६, ४९४,

५४८, ५८१, ५९४, ६९३, ७३६,

७६९, ७९३, ८१९, ८२३, ८९७,

९००, ९८५-८६, १००५-६,

१०४२-४४, १०४९, १०५४,

१०५७, १०६१, १०६५, १०७४,

११०३, १११०, ११३२-३४,

११४९, ११६५, ११७७, ११८६,

१२२०-२१, १२३४, १२५८,

१२६३-७२, १२७५-७६, १२७८,

१२८०, १३०१, १३०४, १३१२,

१३३३

—के लार्ड मेयर—४९४, ७४२

लड़ाकू जहाज, अमेरिकन—९९७
 ———जहाज, फ्रांसिसी—९९७
 ———, ब्रिटिश—९९३, ९९७
 लद्दाख—१२६, ११९०
 ला आफ ग्रेविटेशन—३९८
 ———सस्पेक्टस्—३९८
 लाइली रूसे दि—५२७
 लाउलन—३२२
 लाओजे—२०, ४७, ५७, ५८
 लाओतुंग—६५४, ६६२
 लॉकहार्ट—९४०
 लाजपतराय, लाला—६३०, १०३८
 लाजेन—१२५८
 लाठी चार्ज—११६९
 ———प्रहार—८३, १३१
 लापनोर झील—३२१-२२
 लाफ्रायेत—५३८
 लाबुआ—२६५
 'लॉ मिज़रेवल'—७३३
 लायंस—२७४, २९५
 लायड लॉर्ड—७९२,
 ———जार्ज—९०७, ९३३, ९६४-६५,
 ९६९, ९८७, ९९६, १०६३-६५,
 लारेन—५६९, ७२७-२९,
 लारेंस कर्नल टी० ई०—९००, १०८०
 लार्ड्स हाउस—२८८, ४२१, ४२६
 लाल झंडा—५२५
 ———सेना—९३५, ९३६,
 ———हफ्ता—१११९,
 लास्की, हेरल्ड जे०—१३२२
 लाहौर—२२६, २९८, ३०५, ४४१,

१०१८, १०३८, १०४०-४१
 लाहौर का राजा—२२६
 लिंकन, अब्राहम—८०५-०७, १३१६
 लिंडवर्ग—१३१३
 ———चार्ल्स—८७०
 लिखने की कला—१७४, २००
 लिटन कमीशन—११८८
 ———रिपोर्ट—११८९
 ———, लॉर्ड—११८७
 ———स्ट्रॉची—४२३
 लिटविनोफ़ का समझौता—१२१९
 लियूएनिया—९६६-६७, ११९८, १२२०,
 १३०६,
 लिन-सी-हो—६३५-३६
 लिपि-अंग्रेज़ी—४७
 ———अरबी—२७४, १०११, १२१५
 ———उर्दू—१०११
 ———ग्रीक—५४५
 ———चीनी—४७, १७४
 ———देवनागरी—१९८
 ———द्रविड़ भाषाओं की—१९८
 ———फ़ारसी—१०११
 ———फ़ैच—४७
 ———रोमन—१०११
 ———लैटिन—१०११, १२१५
 ———हिन्दुस्तानी—१९८
 लिवनिज़—३१५
 लिवरेटर—८०४
 लिमेरिक—८२०-२१
 लियोनीड्स—६७
 लिवरपूल—६०१, ८०२-०३, ११९५

लड़ाई, तालीकोटा की ३६४
 —तीस साल की—४१९
 —तुर्की और ब्रिटेन की—१००१
 —तोलों की—५४२
 —नील नदी की—५४०, ५४८
 —नेपोलियन की—५६२, ५८२,
 ६३४, ६७१, ७६०, ८०१
 —पलासी की—४६१, ५०२, ५९२,
 ५९४, ६०६
 —पानीपत की—४५८
 —पिरेमिड की—५४४
 —पूर्वी रोमन साम्राज्य और ईरान के
 सासानियों के साथ—२१०
 —पोलैंड से रूस की—९३६
 —प्लूनिक्—११२-१३, २०९
 —फ्रांस, आस्ट्रिया और प्रशिया की—
 ५२४
 —फ्रांस और इंग्लैंड की ७ साल की—
 ४८६, ५०२, ५०५-०७, ५१४
 —फ्रांस और जर्मनी की—७२८
 —फ्रीडलैंड की—५४७
 —वरमा की—५८५
 —वरमा की अंग्रेजों के साथ—६७३
 —वालकन की—८४९-५१, ८७८,
 ८९१, ९०१, ९९४
 —भारत की आजादी की—७, १४
 —मंचूरिया की—६६२
 —मारेंगो की—५४७
 —मार्न की—८९९
 —मालवा और गुजरात की—३६३
 —मेरेथान की—६४, ६७-६८

लड़ाई मेसोपोटेमियन—१०९३
 —मैसूर की—४६३
 —यूनानी तुर्की—१०००
 —यूनानी राज्यों की—७०
 —योरप की धार्मिक—४०७, ४९३
 —योरप की ३० साला—४५३
 —योरप में विचारों की—४७४-८१
 —रूस-जापान—८६१
 —रूसी-तुर्की—८४६, ८४८
 —रोमन साम्राज्य और सासानियों
 की—१४६
 —लुई की—५४७
 —वाटरलू की—५५३, ५६४, ७२४
 —वाल्मी की—५२५
 —वेनिस और जिनेवा के शहरों की—
 ३२३
 —वैना की—५४७
 —सकरिया की—१००१
 —सिंधियों के साथ अंग्रेजों की—५८७
 —सिक्ख और अंग्रेजों की—५५०
 —सीरियन आजादी की—१०८२
 —सैलेमिस की—६८
 —सौ वर्षों की—३३५
 —स्पेन और इंग्लैंड की—३७८
 —हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में—१४७
 २२३
 —हिंदुस्तान की—५९१
 —हिंदुस्तान में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों
 की—४५९
 —हूणों की—१५८
 —होमरुल के खिलाफ आयर्लैंड में ३०८-

लोकतंत्र, रूस में मध्यवर्गीय प्रजा सत्ता-
त्मक—९१७

—, रोमन—१०९, ११३, ११५-१६

—, सोवियट का—९३२

लोकमान्य—(देखो तिलक)

लोकसत्ता और निरंकुशशासन—११६२-
७०

—का अर्थ—११६७

—का आदर्श—११६७

—की प्रगति—७५९

लोक सेवा समिति—९६०

लोकानर्त—११४६-४७

लोग, अंग्रेज—९९, १३७-३८, १४५,

१५०, १७५, १९७, २३४, २४६,

२५६, ३१७, ३३५-३६, ३६४,

३७७-८०, ३८३, ३८८, ४२५-२६,

४२८, ४३२, ४४१, ४४९-५२,

४५४-४५६, ४५९-६४, ४७१, ४७५,

४८०-८१, ४९३, ५०२-०६, ५४२,

५४७, ५६२-६४, ५८२-९४, ५९७,

५९९ ६०५-०७, ६११-१५, ६१८-

१९, ६२२-२३, ६२६-२७, ६३०-

३१, ६३४, ६३६, ६४०, ६४२, ६४४,

६४९, ६५८-५९, ६६९, ६७१,

६७३-७५, ६८२-८३, ६८८, ७८४,

७८९, ७९१-९७, ८००, ८०२-३,

८१३, ८१८, ८२०-२१, ८२६, ८३७-

३९, ८४१, ८४६, ८५४, ८५७,

८७४-७५, ८७९, ८८२-८४, ८८८,

८९५, ८९७, ८९९, ९००, ९०२,

९०५-०६, ९१६, ९२१, ९४०,

९४३, ९४७, ९५३ ९५५, ९५८,

९६७-६९, ९८३, ९८५-८६, ९९४-

९५, ९९८-१०००, १००२, १००४-

०६, १००८, १०१८, १०३६,

१०५०, १०५३-५५, १०६०, १०६२,

१०६४, १०६६-६७, १०७३, १०७६-

७७, १०८०-८२, १०८५, १०८८-

८९, १०९२-९४, १०९८-११०४,

११०७-०८, १११०, ११४६, ११४८,

११५१, ११७४-७५, ११९५, १२६०,

१२७१, १३०१-०२, १३१२, १३१६,

१३२१, १३२८, १३३५

लोग, अज़टेक—२६५-६६, २१८-१९

—अनामी—१९६

—अफ़ग़ान—२९९, ४६४, ५८६-
८७, ७०५, ११०८-११

—अफ़रीकन—७९७, ८०२, १३२७-
२८

—अव्वासी—२१८, २७१, ३३९

—, स्पेन के—२१८

—अमेरिकन—१५०, २६४, ५६६,
६४५, ६४९, ६५६-५७, ६८४-८५,
७५०, ८१५, ९०२, ९९०, ११२८,
१२२६, १२४०, १२६६, १२७६,
१३५०

—अरब—१८, १३८, १४०, १६९-
७१, १८५, २००, २०७, २०९,
२१२-१३, २१५-२१, २२३-२५,
२२८, २३२, २३४, २४०, २५९,
२६२, २७०-७६, २९४, २९९,
३१७, ३३२ ३४२, ३४८, ३७६,

लिंविंग्स्टन डेविड—८४२
 लिस्वन—३७६
 लीडन—४१७
 लीडिया—३५
 लीलावती—१९४
 ली, जनरल—८०५
 —बुर्जे—८७०
 —हुंगचांग—६४४, ६४७
 लुइज़ियाना—८०१
 लुई, नौवाँ—३११, ३१८,
 —चौदहवाँ—४१४, ४४६-४७, ४५२
 ४६६, ४७५, ४८१, ५१३, ५३७
 ५६०
 —पंद्रहवाँ—४५९, ४८१-८२, ४८६
 —सोलहवाँ—४८२, ५१३-१८, ५२०
 ५२३-२४, ५२६, ५३७, ५५२, ७२७,
 ७५०
 —अठारहवाँ—५५२
 —फ़िलिप—५६१, ७१७, ७६७
 —बोनापार्ट—७१७
 लुसीटानिया—९०२
 लूथरन—४०३
 लूनाचास्की—९४०
 लूसान—१००२, १३०५
 —का शांति सम्मेलन—१००२
 —की संधि—१००२-०३
 लूसियन—५४५, ५५०-५१
 लूसिली—५३१
 लेजिस्लेटिव-असेम्बली (फ्रांस की)—५२४
 —कौंसिल—१०८८
 लेनपूल—२७६

लेनिन—७७४, ७८२, ८५८-६०, ८६४-
 ६५, ९१०-१२, ९१६-१८, ९२१,
 ९२३-२८, ९३१, ९३४, ९३६-
 ३७, ९३९-४२, १११५, ११२१,
 ११९१, ११९६-९८, १२००-०१,
 १२१७, १२३०
 —लेनिन की नई आर्थिक नीति—
 ९३७, ११९२, १११६
 —की मृत्यु—९३९
 लेनिनग्रेड—४८४, ८६६, ९४०, ११९८,
 १२००, १२१६
 लेवेनन—१०८१, १०८५, १२११
 लेवकनेच्, कार्ल—१११९
 —, विल्हेम—१११९
 लेसे फेयर का सिद्धांत—५००-०१, ५१६
 ५७७
 लेह नगर—११९०
 लोअर साइलेशिया—३१५
 लोकतन्त्र, इस्लाम का—२१२
 —का अन्त—११५
 —की प्रगति—७४६, ७५४, ७५९
 —ग्रामीण—१२१
 —, चीन का—९४२, ९४५
 —, जर्मन—८९९
 —पोर्चुगीज—३७८
 —फोनीशियन—१११
 —, फ्रांस का—५४५
 —, फ्लोरेंस का—३४७
 —, वोअर—८००
 —, भारत के ग्रामीण—३३३
 —, मिस्र का—११६

- ८४१, ८८२, ८९२, ८९६-९०३,
९०५-०६, ९१६, ९२३, ९२६,
९२८-३१, ९३६, ९४३, ९६५,
९६८, १०७१, ११४३- ११५३,
१२४७, १२५७, १२६४, १२९०,
१२९३, १२९८, १३०५, १३३७
- ग, जर्मन-आस्ट्रियन—११२१
- जर्मन-हूण—८९६
- जापानी—१७३, १७७, ३८६,
३८८, ३९०, ६४७, ६५२, ६६०,
६६४, ८१०, ९४४, ९४६-४७,
९४९, ११४५, ११७८, ११८३-८८
- जोक—३३०, ९३१
- टालमी—१०३, ११६
- ट्यूटन—१६६
- डच—१५०, ३७७-७८, ३८०,
३८३, ३८८-९०, ४५०, ५०४, ५६३
-६४, ६३५, ६४९, ६६९, ६८३
- डागो—८१५
- डेन—२३२-३३, ५०५, ६८७-८९
७०२, ८१७-१८
- तंग—२४४, ३१२
- तातारी—१०७, १६७, २४२,
३०८, ३८४, ८६२
- तुर्क—११८-१९, १२२, १३८,
१५४, १८१, १८४, २०१, २२२,
२५७, २६२, २६८, २८०-८१, ३१७
३३८-३९, ३४२, ३४८-४९, ४०७-
०८, ४८५, ७८८, ७९१, ८४२-४५,
८४८, ८५०, ८७८-७९, ९००, ९५१
८३६, ९९५, ९९८-१००१, १००३
- १००४-०६, १००८-०९, १०५२
१०७९-८०, १०९९, ११०९, १११५
११९०, १२००
- लोग, तुर्क, आरमीनियन—८५०
- तुर्क, उस्मानी—२९०, ३३७-३८,
३४८-४९, ३५२-५३, ३६४, ४०८,
४८४, ६८८, ७०२, १०७२, १०८९
१०९७, १२८५
- तुर्क, मुसलमानी—११९०
- तुर्क, सेलजुक—२२२, २३४, २४१
२५३-५५, २५७, २५९, २७७-७८,
२८१, २९०, ३०८, ३११-१२,
३१५, ३१९, ३३७-३८, ३४८-
४९, ६६८, ६८८, ६९९
- ब्रविड—१७, ४९, १२२, १९४
- ब्रुज—१०८२-८५
- नार्थमेन—२३२-३४
- नार्मन—२५५, ८१८
- नार्समेन—८१७
- पंजाबी—९५३
- पठान—१०४२
- पल्लव—१८५-८६, १९७, २२३,
३०१, ३०३, ३७१
- पार्थियन—१०७, ११७, १४५-
४६, १५४
- पेट्रीशियन—१०९-११
- पोर्चुगीज—१५०, ३४२, ३४४-
४६, ३६३-६६, ३७५, ३७७-७८,
३८०, ३८२-८३, ३८७-८८ ४३१,
४५०, ४८८, ५०५, ५६३, ५६६,
६६९-७०, ६८३, ८०२, ८४१

- ३९३, ६८८, ६९०, ६९२, ६९८, लोग, कज्जाक—५५२, ७०७
 ७३९, ८३५, ९००, ९६८, ९८१, —कश्मीरी—५८६
 १०६९, १०७९-८०, १०८५, —काष्ट—८४०, १०५३, १०५९
 १०८७-८८, १३४७, —किन (सुनहरे तातारी)—२४४,
 लोग, अरब (स्पेन के)—२१८ २५२, ३०९, ३११, ३१५, ३८३
 —अलविगुइस—३३७, —कुर्द—१००७-८, १०९७, ११०३
 —अलविजे—(देखो अलविगुइस) —कुशान—११९, १२३-२५, १४८,
 —अलवेनियन—८३६ १५३-५६, ३०३, ६९७
 —अलावी—१०८१, १०८४-८५, —केण्ट—८१८
 —असीरियन—१०६८, १०९८, —कोरियन—१७३-७४, ६६४, ११८४
 —आंध्र—११८, १४८, —खितन—२४४, २५२
 —आयरिश—८०९, ८१६-२३, ८२५, —गाथ—२०२
 ८२८, ९५०, ९८७-८८, ९९१, —गाल—१०३, १३७
 —आरमीनियन—८४८, ८५०, ८६२, —गुजराती—१५१
 ९५५, १२००, —गुप्त—१४८, १५६-५७, १९०
 —आरमीनियन तुर्क—८५०, —गुरखे—४७१, ५८४, ५८९
 —आस्ट्रियन—३३७, ७२०-७२१, —चालुक्य—१८५, २२३, ३०१,
 ८९९, ९०१, ९१६, ३०३
 —इटैलियन—५४३, ६९५, ७२१, —चीनी—४६, ४७, १०७, १४२,
 ८०९, ८१५, ८४१, ९०१, ९९५, १५०, १५२, १७१, १७३, १७५,
 —इराकी—११००, २४२, २५९, ३१७-१८, ३२४,
 —ईरानी—६४, ६६-६८, १४६, ३७१, ३७३, ३८१-८३, ३९०,
 १७८, १८४, २११, २२५, २५९, ३९२, ४६८-६९, ५६३, ६३८,
 ६९६, ७०४, ७०७-०९, ८३४-३५, ६४१, ६४५, ६५७-५८, ६६५-६६,
 —उजबेग—७०२, ७३९, ८४५, ८१०, ९४४-४५,
 —उस्मानली—१३८, ९४८-५०, ११७४-७५, ११७८,
 —एंग्लो नार्मन—८१८, ११८४-८६, ११८८
 —" सैक्सन—१५०, ५०५, ८०९, —चीनी मंगोल—३७१
 —एकेमेनीद—६९७, १०६९, —चोल—१८६, ३०१-०२
 —एथेंस के—६४, ६५, ६८, ७२, —जर्मन—१३७, २३४, २५६, ४८८,
 —एशिया के—७९७, ५४९, ६५८, ७२४, ७२६, ८०९,

लोग, मुगल—३१५, ३२०, ३८०, ४३७,
 ४४७, ४५१, ४५६, ७०५, ७८४
 —मैमलूक—८३५-३६, ८४४
 —यूक्रेनियन—९६७
 —यूनानी—६४, ६६-७०, ७४, ७६,
 ७८-७९, ९५, १०३, १०९, १११,
 १५५, १७८, १८६, २२५, २५५,
 २५७-५८, २८९, ६९३, ६९७, ७३९,
 ९९५-१००१, १००३, १०१३
 —यूरोपियन—१०२, ११७, २१५,
 २४०, २६४, २९८, ३१६, ३२५,
 ३४९, ३६३-६४ ८०, ३८५,
 ३८९, ४६७, ५०५, ५४६, ५६७,
 ६३५, ६३९, ६४२, ६५२, ६५७-
 ५८, ६७५-७६, ६८३, १०६५,
 ११७८, १३२७-२८
 —यूरोपियन, पश्चिमी—२०३
 —राष्ट्रकूट—१८५-८६, २२३-२४,
 २२७, ३०१, ३०३
 —रीफ़—११६३
 —रुमानियन—११२१
 —रूसी—२५५, ४६९, ५५१, ५६१,
 ६४९, ६६२, ७०६-०७, ८४६,
 ८४८, ८५८, ८६२-६२, ८७९,
 ८९५, ८९९, ९३४, ९३८, ९४४,
 ११०७, ११८४, १२०४
 —रेड इंडियन—३४३, ५०५-०७,
 १३३१
 —रोमन—१०८, १११-११५, १२७-
 २९, १३५-३६, १३९, १४२-४३,
 १४५, १४७, २०२, २५८, २६५,

३४९, ३७६, ४०३, ८३५
 लोग, लिथुएनियन—९६६
 —वंडाल—१३७, २०१, ८१७
 —वालून—४९७
 —शक—१८, ११९-२०, १२२-२३,
 १५३
 —शान—१९६
 —संग—२२४, २५२, ३१५, ३८३
 —, वक्षिणी—३४४, ३१०
 —, सफ़ावी—७०५
 —, सफ़ेद हूण—१५८, २०२, २४१
 —, समूराई—६४८
 —, सरासीन—२१५, २२३, २२९,
 २३१-३२, २७४-७६, ४०७
 —, सर्बियन—२३३, २५५
 —, सासानी—१४५-४६, १०६९
 —, सिंधी—५८७
 —, सीथियन—११९, २४१, ३०८
 —, सीरियन—१०५२, १०८१-८३
 —, ,, अरब—१०८७
 —, सुनहरे कबीलों के—३५२, ८५३
 १०७१
 —सुनहरे तातारी—(देखो किन)
 —, सेमेटिक—६९८
 —, स्कॉच—८१८
 —, स्केण्डिनेवियन—८०९
 —, स्पार्टन—६४
 —, स्पेनिश—(स्पेन के) १५०,
 १५२, २००, २६६-६७, ३४२,
 ३७६-७७, ३८०, ३८८-८९, ४१७,
 ४८८, ४९३, ५०५, ५४९, ५६३,

लोग, पोल—१२९, ४८७, ७२५, ८०९,

८५६

—फिलिपियन—१२८५

—प्रवासी भारतीय—६१७

—प्राचीन यूनानी—१०३, १३५

—प्लीवियन—१०९-११

—फारसी—१०५२

—फूजीवारा—२४६, २५३

—फैटन—१३३७

—फेनियन—८२५, ८२८

—फोनीशियन—१११

—फ्रांसीसी—१३७, २३४, २५६,

२७५, ३६४, ४५२, ४५९, ४६०,

४६३, ४७९-८०, ५१४, ५२०, ५४६

५५५, ५६९, ५८२, ६४०, ६४२,

६४४, ६७४-७५, ७२०, ७३०, ७४०

७९९, ८३७-३९, ८४१, ८६३,

८७५, ८९५-९६, ८९९, ९०५-६,

९१६, ९६८, ९८१, १०७२, १०७४

१०८०-८४, १०९४, ११२६, ११५०

-५१, ११६३, १२५७, १२६०, १२६२

१२७०

—फ्रैंक—२०२, २२९

—फ्रेंच—१४०, २०३, २२९

—बंगाली—६३३, ८८८

—बदाऊन—१०९२, १०९५

—बद्ध—२०८-०९

—बरमी (बरमा के)—१५२,

४६४, ६७३, ६७५

—बर्वर—१३६, १३९, १४२-४३,

१५४, १५७, २०२, २०४, २०५,

२३८, २५२, २६०, २६२, २८९,

लोग, बलगोरियन—२३३, २५५, २८३,

२८९, ३७७, ८७८

—विजेटाइन—२२१, २८३, ३३९

—वेवीलोनियन—८१३

—वेलजियन—४१, ८९८, ११२६

—वैक्ट्रियन—११९

—बोअर—८८९

—ब्रिटिश—७६९, ७८७-८८, १०६१,

१०६६, १०७३

—मंगोल—१८, ४५, ११७, १९६,

२२२, २४१, २४४, २४७, २६०,

२९०, ३०५, ३१०, ३१३-१४,

३१६, ३१८-२०, ३२५, ३३४,

३३७, ३४८-५१, ३५३, ३७१,

३७३-७४, ३८३, ३८५, ४१६,

४३२, ४६८-६९, ५६८, ६४१,

६६४, ६८८, ६९९, ७०१-०२,

७७०, १०७०, १३४७,

—मंगोली खानाबदोश—३०९, ११८४

—मंचू—३८३, ४३१, ४६६, ५६३,

९०७, ९४४, ११८४

—मगियार—२३३, २५५

—मराठा—४४९, ४५१, ४६०, ५६३,

५८२-८४, ६१५

—महाराष्ट्रीय—१८५

—मिंग—३७४, ३८३, ३८६

—मिशनरी—४६७

—मिस्त्री—९७, २६९, ८३८-३९,

१०५२, १०५४-५५, १०५७,

१०५९, १०६६

वंश, मंचू—६४५, ६६६-६७
 —मिंग—३८०
 —मुगल—४३१, ४३७, ४४५, ४४७
 ५९१
 —मेडीसी—२९५, ४०९
 —मेरोविजियन—२२९
 —मौर्य—७९, १५३
 —यार्क—३३४
 —युआन—३१८-१९, ३२५, ३५०
 ३८०, ४४५
 —रोमनॉफ़—९१४, ९६२, ९९३
 —लिच्छिवि—४४
 —लैंकेस्टर—३३४
 —शका—१५३, १५५
 —शैंग (या ईसन)—४६, ४७, १०४
 —संग—२४२-४४, २५२, ३५८
 —सफावी—७०२-०३, ७०५
 —सासानी—१४६, ६९७
 —सीदियन—११९, १२२, १५३
 —सूर्य—६४८
 —हन्—१०७-०८, ११७, १२०,
 १२६, १६७, १७०, ६६५
 —हनोवर—४२८, ७८५
 —हसिया—४६
 —हिद्द—१५९
 —हिस्पा—१०४
 —हैप्सवर्ग—२८७, ४०३, ४०८,
 ४८३, ७१७, ७२३, ७८४-८५,
 ९६३, ९८०, ९९३, १११७, १२८६
 —होएनजोनलर्न—४२०, ४८३, ७२७,
 ८७४, ९०७, ९९३

वंश, होहेनस्टाफेन—२८४, २८६, ३११
 वर्ग, कारीगरों के—५००
 —गरीब—५७३
 —जमींदारी, की उत्पत्ति—२४६, ६१३
 —दलित—६२६, ६४४, १०३०
 —बुर्जुआ (देखो मध्यमवर्ग)
 —मजदूर—७१४, ७१६
 —व्यापारी, की उत्पत्ति—२३९
 —शासक—५८०
 —सामंत—४५३, ५१५, ६१३
 —हिंदुस्तानी औद्योगिक पूंजीपति—
 ६२७
 वर्गयुद्ध—७७०, ७७९-८०, १२९९
 —का इतिहास—७७७
 बर्जिल—१३४
 बर्जीनिया—४२२, ५०६, ८०८
 बर्ड्सवर्थ—७३६
 बर्डे का अन्तरीप—३४२-४३
 वर्ण चार—४२
 —ब्राह्मण—४२
 —क्षत्रिय—४२
 —वैश्य—४२
 —शूद्र—४२
 —व्यवस्था—१६६, १०५१
 वर्णमाला, लैटिन—१०११
 वर्दून—५२४
 वर्धमान—५८
 वर्साइ—४१४, ४४६, ८५४, ९६३,
 १००७
 —का शानि सम्मेलन—१००७
 —की शानि—९७६

- ५६६, ६७०-७१, ६८२-८४, ६९८,
 ८०२, ८११, ९८१
 लोग, हंगेरियन—२३३
 —, हब्शी—४८८, ५०५-०६, ५१०,
 ८०२-०४, ८०७-८, ८१०-११,
 १३१८, १२३१
 —, हिंदुस्तान के अंग्रेज—५८६
 —, हिंदुस्तानी (भारतीय)—११७,
 १५०-५२, १५९, १८२, १९०,
 २०१, २२५, २४८, २५९, २९९-
 ३००, ३५६, ४१८, ४३३, ४३७,
 ४६५, ५००, ५३३, ५४९, ५८४,
 ५८९-९०, ५९२, ६१२, ६२३,
 ६२७-२८, ६३०-३१, ६५०, ६६५,
 ७०७, ७४२, ७९४, ८१०, ८३९,
 ८९०, ९५२, ९५५, १०१५, १०२३
 १०४३, ११६१, १२४०, १२७३,
 १३२६-२७
 —, हूण—१८, १३७, १५४, १५७,
 १५९, १७८-७९, २०१, २४८,
 ३०८, ६४१, ६५८, ७४३, ८१७,
 १३०१
 लोजोस कोसूथ—७१६
 लोयंग—१६९
 लोयोला—४०२
 लोसेन—११४९
 लोक लेमन झील—१३३
 ल्यूनार्डो द विंसी—३९६-९७
 व
 वंग-भंग—८८८
 'वंदेमातरम्'—६२७
 वंश (या खानदान), अक्वासी—२१८
 —अरब—१०७९
 —इन—१०४
 —इलखान—७०१
 —उम्मैया—२१६-१८
 —उथमान (देखो उस्मान)
 —उस्मान—१००५
 —एकेमेनीद—६९६-९७, ८३४
 —गुप्त—१४३, १५४, १५८-५९,
 १७८
 —चाऊ—४७, १०४-०५
 —चिन—१०५-०६
 —, और हन—१०४-०८
 —चीनी कट्टर—३१८
 —चोल—१८६
 —जर्मन—४८३
 —टालमी—१०३
 —तंग—१६७, १६९-७१, १८१,
 २४२
 —ताइमिंग—३२५
 —तुर्की—१५३, १५५, ६९९
 —पल्लव—१५१
 —पहलवी—७०९
 —पाण्ड्य—१८६
 —फूजीवारा—१७७, २४५, २५३
 —बतलामूसी—८३५
 —बोर्जिया—४०९
 —बोर्वन—५३५, ५५२, ७११, ७१७
 ९८०, १२८६
 —ब्राह्मण—१९१
 —मंगोल—२४१

विलियम टेल—३३७
 ————दि'साइलैण्ट—४१६
 ————'विजेता'—८१८
 विल्सन उडरो, राष्ट्रपति—९०५, ९०७
 ९३०, ९३२, ९६४-६५, ९६९,
 ९७१-७२, १३१७
 ————सर आरनल्ड—११०३
 विल्हम द्वितीय—७३
 ————क्रैसर—८७४, ८८०, ९०७
 ————लीबनेट—७२९
 विवेकानन्द, स्वामी—६२४
 विश्वराज्य की भावना—१४१-४५
 विश्वविद्यालय, अलीगढ़—६२९
 ————आक्सफोर्ड—२७२, २९५, २९७,
 ३२९, ४२१, ७३५
 ————इटली के—२७२
 ————उज्जैन—१००
 ————कलकत्ता—६२१
 ————कारडोवा का—२७२
 ————कुस्तुन्तुनिया—२०५
 ————कम्ब्रिज—२९५, ७३४
 ————तक्षशिला—९९, १२७, २२०,
 २२४, ३५८
 ————नालंदा—४, १००, १८०, ३५८
 ————नेपल्स—२८६
 ————पेरिस के—२७२
 ————प्रेग—३३०
 ————वंवई—६२१
 ————बोलोना का—२९५
 ————मथुरा—९९
 ————मद्रास—६२१

विश्वविद्यालय, लीडन—४१७
 ————लूवेन का—८९७
 ————सेलर्नो—२८६
 विहार—१००
 वीहार्ड-वी—६५५
 वू-ती—१०७
 वू-सान-क्वी—३८३, ३८४
 वूहन—११७५
 वंगचैन—१०५
 वेक्स स्कूल—८५
 वेट टाइलर—३३५
 वेद—३८, ४९, ५८, १५५, ६९३
 वेनजेलो—९९६, १०००
 वेनिटी फ्रेयर—४६२
 वेनिस—८५, २७८, २९३-९५, ३०२,
 ३२०, ३२२-२३, ४०८, ५४३,
 ५६०, ७१९, ७२१, ९०१, १०७०,
 १०७२, १३४७
 वेनेजुएला—१३३१
 वेमर—१११९
 ————, विधान—१११९, १२९५
 वेरनीस—५२४
 वेरोना—२९५
 'वेलिंगवॉल'—१०८९
 वेलिंग्टन—५५३
 वेलेंशिया—२७५
 वेलेस्वीज—३९८
 वेल्स, एच० जी०—९६, ९८, ३३०,
 ५३८, ५४१
 वेवर्ली—७३६,
 वेस्टइंडीज—३४३

वर्सि की संधि—९६५-६६, ९६८-६९,
 ९७३, ९७७
 वसंतपंचमी—७३
 वसु, सर जगदीशचन्द्र—८८९
 वहावी (लोग)—१०९२-९४
 वहीदउद्दीन खलीफा—९९७
 —सुलतान—१००४-०५
 वांग-आन-शी—२४३-४४
 वांगकीन—१७४
 वाइक्लिफ—३२९, ४२१
 वाइप्स बेरिंग—४७३
 वाइसराय—२८८, १०१७, १०२५
 —अंग्रेज—४२३, ४४९, ५००, ५९१,
 ६१८
 —पूर्व का—३६५
 —हिंदुस्तान का—६१८, ७९७,
 ९६१, १०१७, १०२५
 वाटरलू—५५३, ८७७
 वारसा—५४७, ११४९
 वारेन हेस्टिंग्स—४६३
 वाल्टेयर—५५, १४१, ४७९-८०, ४८३,
 ५१०, ५१२, ५३६, ७४०, ७४६,
 ८५४
 वाल्डेसेस—३२७
 वाल्मीकि—१५५
 वाशिंगटन, कान्फरेंस (परिषद्)—९४८-
 ४९, ११८२, १३०८
 —जार्ज—५०८-१०, ८०१, ११४६
 —नगर—९४८
 वास्कोडिगाया—३४३, ३६३, ३७६,
 ३९१

वास्तविकतावाद—७५२
 विध्याचल—१२३, १७९
 विकासवाद—७७९
 विक्टर इम्मेन्युअल—७२०
 —ह्यूगो—७३३-३४
 विक्टोरिया, महारानी—४२८, ६३७,
 ७८५-८६, ७९१
 विक्रमादित्य—१५५-५६
 —का विजयस्तंभ—१५५
 विजय—१४९
 विजयनगर—२९९, ३०८, ३५५, ३५९,
 ३६१-६९
 विजयस्तंभ—३६३
 विजयालय—१८६
 विज्ञान की प्रगति—१२२०-२८
 —की विजय—७३८, ७४६
 विट्टोरिया (जहाज)—३४५
 विदेह—४४
 वियेन्ना—१३८, २४१, २९६, ३३८,
 ३४८-४९, ४०८, ४८५, ५५२-५४,
 ५५८-५९, ५६३, ५६८-६९, ८४२,
 ८७५, १२२१, १२६८-७०
 —कांग्रेस—५५२-५३, ५५९-६०,
 ५६४, ५६८, ७११, ७१९
 —की शांति—९७६
 विलवर—८७०
 —ऑफ ऑरेंज—४१६, ४१८-१९,
 ४२६
 विलियम द्वितीय—११५, २३४, २५५,
 ४२७
 —चतुर्थ—४२८

शासक, स्पेन के—४१८
 —, हगोवर का—४२७
 शासकवर्ग ब्रिटेन का—७६०
 शासन, अंग्रेजी—६२५
 —, अवध का—५८७
 —, उस्मानी—६८९
 —, कुशानों का—१२३
 —, चीन का—६५१
 —, तंगवंश का—१६७, १७१
 —, तुर्की का—११६४
 —, नाजी—१३०२
 —, पल्लवों का—१५१
 —, पन्द्रहवें लुई का—४८२
 —, प्रणाली कौटिल्य के समय की—
 १९०
 —, रूसी—११४२
 —, ब्रिटिश—२६६, ८३२
 —, शोगन—२४७
 —सभा (देखो पार्लमेण्ट)
 —सासानी—१४७
 —सुधार—६३२
 —, सोवियट—९२८-२९, ११४२
 —, स्पेनिश—११६३
 —, हिन्दुस्तान में अंग्रेज—४६८
 शास्त्र, पाँच, (व्याकरण, याय, कलाकौशल
 आयुर्वेद, दर्शन आदि)—१८२
 शाहजहाँ—४०९, ४४३, ४४७, ४५०,
 ४५५, ४७०, ७०५
 शाहजहानाबाद—५२
 शाह तामस्य (स्प)—४३६, ७०२
 शाहनामा—७५, २२९, ३०३, ७००

शाहबुद्दीन गोरी—२९८-९९, ३०४
 शाहख—७०२
 शाही पुस्तकालय—२७२
 शिकागो—१३१२
 शियनलुंग—४७०-७३, ४८१, ६३७,
 ६४१
 शिलर—७३२-३३
 शिव का जीवन नृत्य—१८८, ३८६
 शिवाजी, छत्रपति—४५६
 शिशुबुद्ध की मूर्तियाँ—६९४
 शीराज—७००-०१
 शीह-व्हांग-टी—१०५-०७, १७३
 शुक्राचार्य—१९१, २३९, २८५
 शूद्र—४३, १९१, १९३
 —राजा हुए हैं—१९३
 शेक्सपियर—११५, ४००, ४२२, ४३६
 शेख सईद—१००८
 शेख सलीम चिश्ती—४४१
 शेख सादी—७००
 शेफील्ड—६०१
 शेरशाह (खां)—४३५-३६, ७०२
 शैली—७३४-३६, ७५०, ८६५
 शैव—३५७
 शोगन—२४६, २५३, ३८१, ३८६,
 ३८९, ४५७, ६४८-४९
 —शाही—२४६, ३८६-८७, ५६३
 —, आग्रीकागा—३८६
 —कामाकुरा—२४७, ३८६
 —तोक्कावा—३८७, ६४९
 —मी० ए० तार्ई—२४६
 शोतुकू तैंगी—१७६-७७

वेदी—५२९
 वैज्ञानिक भावना की शुरुआत—२९७
 वैटिकन—११६१
 —महल, ११६१
 वैथमैन हालवैग—९०७
 वैशाली—४४
 वैष्णव—३५७
 वोल्गा—९६
 व्याकरण—१८२
 व्यापार अफीम का—५६३
 —, गुलामों का—१३४, २८१, ४५०
 ४८८, ५०५, ८०२-०४
 —, चाय का—४७१
 —, नील का—६०७-०८
 व्हाइट हाल—४२५, ४६४
 —पेपर—१०४९
 —हाउस—८०१
 व्हिग—७९०

श

शंकराचार्य—१८८-९०, २२३-२४, ३५६-५७
 शंघाई—६३६, ६४४, ९५०, ११४८, ११७०, ११७४-७८, ११८६-८७
 शन हेक वान—११८८
 शमावाद—३१३
 शमीन—११७४
 —का हत्याकांड—११७४
 शरियत—१००९
 शस्त्रीकरण—८७६
 शहर, अंग्रेजी—१५०
 —अमेरिका के—१५०

शहर, योरप के पुराने—२९६
 —अरबी—२७२
 —चीन के—३१३
 —यूनानी—६४, ६८, ७४
 —हिंदुस्तानी—६०१
 —जेद—२१९
 शहरों की सभ्यता और खानाबदोशी जिंदगी का मेल—३१३
 शांति-निकेतन—९४७, ९६३, ९६५
 —का संधिपत्र—९४८
 शा, जॉर्ज वर्नार्ड—१३४१
 शातुंग (शाटुंग)—६५५, ९४६-४८
 शायलॉक—११२८, १२५६
 शारलौती कॉरदे—
 शार्लमेन—९६, १४०, २३०-३३, २७१
 शालिमार—४४६
 शासक, काबुल के—३६२
 —, जापानी—१७७
 —, द्यूडर—४२१
 —, पोर्चुगीज—६१५
 —, बगदाद के—२३४
 —, बौद्ध—१५०
 —, ब्रिटिश—६२६
 —, मंगोल—३२३
 —, मंचू—६३९, ६४५, ६४७, ६६७
 —, मध्य एशियाई—३७५
 —, मुसलमान—३६१
 —, विजयनगर का—३६५
 —, विदेशी—१५४
 —, समरकन्द के—३५१
 —, सिंध के अरब—३०१

- संधि, रैफेल की—११४६, ११९३
 —, लिमेरिक की—८२०
 —, लिटविनोफ की—१२१९
 —, लूसान की—१००२-०३
 —, लोकानों की—११४७
 —, वासाई की—११२०, ११२३-
 २४, ११२६, ११४४, ११४६,
 १२९२-९३, १२९८, १३००-०१,
 १३०४, १३३७
 —, वेस्ट फ्रेलिया की—४२०, ४७५,
 ४८३
 —, सेवरे की—९९९
 —, सोवियट-अफगान—११०९
 —, सोवियट-ईरानी—११०९
 —, सोवियट-तुर्की—११०९, ११४०
 सम्पर्क, अमेरिका के लोगों का एशिया
 और योरप से—२६४
 —, अरब और हिन्दुस्तान का—२२४
 —, आर्यों और द्रविड़ों का—१९४
 —, एशिया और योरप का—३१६
 —, चीन का पश्चिमी देशों से—१०२
 —, पूर्व और पश्चिम के बीच—९५
 —, बौद्ध विचारों से पश्चिम एशिया
 का—१२३
 —, यूनानी जगत् से विद्वत्कार का—९७
 —, धीविजग और चोल साम्राज्य में—
 १९८
 सम्प्रदाय, ईसाई—१३१, २०८, २१०,
 २१३, १०८९
 —, ईसाई, कट्टर—२७८, २८३
 —, ईसाई, मेरोनाइट—१०८१
 सम्प्रदाय, कालविन—४०४, ४०६
 —, कैथलिक—३३०, ४१०, ४१९,
 ४२१, ११६१, १२८८
 —, जैकोविन—७५०
 —, नेस्टोरियन—१७०, ३२४
 —, प्यूरिटन—४०४
 —, प्रोटेस्टेंट—३३०, ४०७, ४१०,
 ४१५, ४१९, ४२१, ४२८
 —, महायान—१२४-२५, १५६
 —, रोमन—२७८
 —, रोमन कैथलिक—२८०, ४०७, ४२८
 —, वैष्णव (चैतन्य का)—३५८
 —, शिया—२१५, ६९८
 —, सुन्नी—२१५, ६९८
 —, हीनयान—१२४-२५
 संभाजी—४५६
 संरक्षणवाद—७९५
 संस्कृत विद्या—१५५, ३०४
 संस्कृति, अरबी—२५८, २६२, ८३५,
 १०६९, १०९१
 —, अरबी-फारसी—७००
 —, अरबी, नवीन—२५८
 —, आर्य—२८, ३९, ४१, १२१,
 —, प्राचीन आर्यों की—१२१
 २२४, २२८, ३००
 —, ईरानी—१८१, २२५, २५८, ३०४
 —, ईरानी-आर्य—२२४
 —, एशियाई—१२३
 —, का पुनर्जीवन और पतन—१३८३
 —, गैलिक—८१५-१८
 —, चीनी—१५१-५२, १६४, १६३,

श्रद्धानन्द, स्वामी—१०१७
 श्रीनगर—४४६, ११९०
 श्रीविजय—१५०, १९५, १९७-९८, ३६९-
 ७०, ३७२

—का बौद्ध साम्राज्य—१९७

—का हिन्दू राज्य—१५२

श्रेणी-संघर्ष की वृद्धि—९७९, ९८४

स

संगम, गंगा-यमुना का—१८३

संघ-अंतर्राष्ट्रीय (प्रथम)—७६६, ७७०

—, ,, (द्वितीय)—७७२-७४ १०३५,
 १३१८-१९

—, ,, (तृतीय)—७७४, ९३८
 १०३५

—कारीगरों के—१९२, २३९, ४२९

—गुप्त अंतर्राष्ट्रीय—१३०९

—चर्च—४०२

—चीनी किसान—११७३, ११७९

—जीसस का—४०२

—पादरियों का—३२९

—मजदूर और समाजवादी अंतर्राष्ट्रीय
 —७७२

—राज्य—१०४९

—रूसी सोवियट—११९०-९१

—व्यापारी—१९३, २३९, २९५

—शिल्प—४२९-३०

—संत फ्रांसिस का—३२७, ४०२

—सेंट डोमीनिक का—३२७, ४०२

—सोवियट—७८३, १३३०, १३३५,
 १३३९

—सोवियट प्रजातंत्र—९४९

संघ, स्त्रीमताधिकार—१०६७

—, हिन्दुस्तानी ग्राम पंचायतों का—
 ६००

संघमित्रा—९९

संघवाद—७७१

संधि (या मुलह) अंग्रेज-रूसी १९०७
 की)—८६४, ९३८

—, इंग्लैण्ड, फ्रांस और जापान की
 गुप्त—९४७

—, ईरानी-अफगानी—११०९

—, एंग्लो-जापानी (इंग्लैण्ड जापान
 की)—६६०, ११८२

—, चार राष्ट्रों की—११४५

—, चीन और अमेरिका की—६४५

—, जापान और सोवियट यूनियन
 के बीच—११४६

—, तुर्की-अफगान—११०९

—, तुर्की-ईरानी—११०९

—, दिल्ली की—१०४३-४४

—, नरस्त्रिन्स्क की—४६९, ४७३

—, नानकिंग की—६३६, ६३८

—, नौराष्ट्रों की—११४५, ११८५

—, पेरिस की—५०९

—, पोर्टमाउथ की—६६२

—, ब्रलिन की—८४७, ८४९

—, ब्रेस्ट लिटोस्क की—९२६-२७
 ९३९

—, मित्रपक्ष और जर्मनपक्ष की (११
 नवंबर १९१८ की)—९३२

—, यूट्रेक्ट की—८०२

—, रूस तुर्की—१००३

- सभ्यता, पश्चिमी—६५१-५२, ६५९, ८३८, ९४५
 —पश्चिमी योरप की—२२९
 —पूजीवादी—५६८, ५७३, ९७९
 —, पूर्वी—४३१
 —, पेरू की—२६७
 —, प्राचीन—१७, २०-२१, २४, ३१, ३४, ५८१
 —प्राचीन आर्य—१००, १५५
 —प्राचीन इराक—२२, २४
 —, ईरान की (या ईरानी)—२४, २५८
 —, चीन की—२२, २४, ३४, २५८, ६८८, ६९०
 —, नोसास की—४९
 —, भारत की—१७, २२, २४, ३४, ४९
 —, मिस्र की—२२, २४, ३४, ४८
 —, मेसोपोटामिया की—३४
 —, यूनान की—२२, ७०
 —, हिन्दुस्तानी—२०१, २५८, २६८
 —फारस की—७०२
 —फारसी अरबी—६९९
 —फिलीपाइन की—१५३
 —भारतीय (हिन्दुस्तानी)—२८, १४८, १५०-५३, ६९५
 —, भारतीय आर्य—१५१, २२८
 —, मध्यमवर्गीय—५८१-८२
 —, मनीनों की औद्योगिक—३३०
 —, मनीनों की नदी—५६६
- सभ्यता, 'माया' (अमेरिका की)—२६५-६६, १३४७
 —, मिस्र की—२६९
 —, मूरों की—२७२
 —, मोहेन-जो-दारो की—२६९
 —, यूनानी—७८, १४४
 —, यूनानी रोमन—२१०, २५८
 —, यूरोपियन (या योरप की) २६३, ५८१, ६९०, ७१०
 —, रोमन—१३५, १४४, ८१७
 —, हिन्दुस्तानी—७८, १५१, २०१, २६२, ६६९, ६८२, ६९२, समरकंद—३६, ७५, १७९, १८१, २२६, २५४, ३१२, ३५१-५२, ४३२, ७०१, ७७३, ११८२, १२००
 समष्टिवाद—७६२
 समकोण त्रिभुज—५७
 —चतुर्भुज—५७, ६९९
 सम्मेलन, मंसार का पहला दासत्वविरोधी—१२२१
 समाजवाद—११२, ५२५, ७१०, ७२९-३०, ३३, ७५३, ७६२, ७६४-६५, ७६७, ७६८, ७७१, ७७५, ७७९, ८५७, ८६७, १११७, ११५३, ११५५-५७, ११६२, ११७०, ११९७, १२०१, १२०२, १२०३, १२१३-१४, १२२०, १२३०, १२४३, १२५१, १२८७, १२९२-९३, १२९५, १३१५, १३१६-२०, १३२३, १३४०, १३४१
 —अंग्रेजों का—७६३, ७७०, ७८३

- २५८, ३७३, ३८६-८७, ४६६, सत्याग्रह की लड़ाई—१८२, १०१६, १०४७
 ६४१, ६६९, १३४७ —, जर्मन सरकार का—११२६
 संस्कृति, तुरफान की—१८० —, दक्षिण अफ्रीका का—१०२०
 —, द्रविड़—११९ —, दिवस—१०१७
 —, पश्चिमी योरोप की—८५४ —, सभा—१०१६
 —, प्राचीन चीन की—४७, ९४५ सत्याग्रही उपाय—७१७
 —, प्राचीन, भारतीय-आर्य—२२४ सनयातसेन, डॉ०—६६६-६८, ९४३,
 —, प्राचीन यूनानी—७३३ ९५०, ११७१-७३, ११७८
 —, फारस की—७०० —, श्रीमती—११७८
 —, फ्रांस की—४८३, ५०५ सवूताई—३१५
 —, बौद्ध—११९, १२३ सव्लाइम पोर्ट—८५१
 —, भारतीय—२४ सभ्यता, अजटेक—१३४७
 —, भारतीय आर्य—२२५ —अमीरों की—१३४, २०२, २७३
 —, माया (अमेरिका की)—२४१, —, अमेरिकन—२६४
 ३४६ —, अरबी—२६०, २७३, २७५,
 —, मिंग—४६६ ३१७, ६९८, १०९१
 —, मूरों की—२७२ —, आधुनिक—९२
 —, यूनानी—९४, १०३, २२३-२५, —, आर्य—४१, १००, १५६
 ८३४, १०६९ —, आर्यों की नवीन—४९
 —, सरासीनों की—२२५ —, इराक की—२६९, ६९२
 —, हिंदुस्तानी—१५३, १५५, २०१, —, ईरानी—७०३
 २५८, २६२, ३७१-७३, ६६९ —, एशिया की (एशियाई) २५९,
 —, हिंदू—६२४ ६९०
 —, हिंदू आर्य—२२८ —, चीन की (चीनी) १५१, १६४,
 —, हिंदू-मुसलिम, का मेल—१२१ १७२, १७५, ६५१, ६६९, ६९९,
 अकरिया नदी—१००० ९४५
 सतनामी (लोग)—४५४ —, जापान की—६९०
 सत्यपाल डॉ०—१०१७ —, द्रविड़—२६, ३९, ४९
 सत्याग्रह—८९० —, नक्काशीदार मिट्टी के बर्तनों की—
 —आन्दोलन—८३, १०१७, १०४० ६९१
 १०४३, १०५० —, नोसास की—२६

- ७९८, ८२४, ८२९, ८३३, ८३७-
३९, ८५१, ८७९, ८८५-८८, ९४४,
९४७, ९५४-५८, ९६१, ९६८,
९७१, ९८४-८६, ९८८, ९९०-९३,
१००१, १००४
- रकार, अफ्रीका की यूनियन—१३२७
- अमेरिकन (अमेरिका की)—६४५,
६६९, ६८४, ८०४, ८१२, ९४९,
१३१५
- अरब—१०८१
- आजकल की साम्राज्यवादी—६५६
- आयरिश—९९१
- आस्ट्रिया की—८७९, ८९९
- इंग्लैण्ड की राष्ट्रीय—१३२२-२३
- इटली की ११६१
- इराक की—१०७६, ११०३
- इस्ताम्बूल की—१००१
- इरानी—७०६, ७०८-०९, १०७६-
७७
- उत्तरी चीन की—९४६
- एथेस की—७२
- कनाडा की—९५३
- कुस्तुतुनिया की—२२९, २७७
- कैण्टन की—११७२-७४, ११८६
- कोरिया की अस्थायी प्रजातंत्र—
११९१
- चीन की ६३५-३६, ६३८, ६८०-
८१, ६४४-४६, ६५३, ६५७-५९,
६६६, ६८१, ९४६-४९.
- चीन की राष्ट्रीय—९५०, ११६५,
११८५
- सरकार, चीन की, साम्यवादी—११८६, ११९०
- चीन की, तूशनो की—९५०
- जर्मन—७७२, ८७९-८०, ९१६,
९५२, ९६९, १०७२, १११५,
११२४-२६, १२८१
- जर्मनी की, नई सोशल डेमोक्रेटिक
—१११९
- जर्मनी की नाजी—१२१९
- जापान की—६६४, ६८५, ९४९,
९७३, ११८३, ११८५, ११८९,
१२१९, १२८४
- जार की (रूसी)—६६०, ७६२,
८५२, ८५५-५६, ८६१-६३, ८८०,
८९९, ९१०
- डच—६७०, ६७२, १११३
- डायरेक्टरी—५४५
- तुर्की—८४८, ८५१, १०१२-१३
- दक्षिणी चीन की ९५०
- नाजी—१२९७
- नानकिंग की राष्ट्रीय—११७८-७९,
११८६-८७, ११८९
- निदर्लैंड की—६७१-७२
- पल्लव—१५१
- पेकिंग की—९४७-४९
- प्रगिया—७२६
- फ्रांसीसी—६८०, ७६७, ८३७,
८९८, ९४९, १००१, १०८१, १०८३-
८८, १११३, १२५७, १२७०,
१२७५
- बर्मा की—६७३
- बेल्जियम की—११२१

समाजवाद का आगमन—७५९-६६

—का आदर्श—७७५

—का विकास—७६३

—की असफलता—१३१८

—की मूल कल्पना—७७५

—के अन्तर्राष्ट्रीय आदर्श—१११७

—, ब्रिटिश छाप का—७६३

—, मार्क्स का—७७०

—यूरोपियन देशों का—७६३

समाजवादी सोवियट प्रजातंत्र संघ—११९८

—, उक्रेन—११९९

—, उज़बेक—११९९

—, काफ़ के पार का—

११९९

—, तुर्कमीन—११९९

—, ताजिक—११९९

—, सफ़ेद रूसी—११९९

समारा—६९९

समिति, चीन की गुप्त—४७१

—दैवी न्याय—४७१

—इवेत कमल—४७१

—इवेत पंख—४७१

—स्वर्ग और पृथ्वी की—४७१

समुद्रगुप्त—१५४-५७

समूराई—६४८

सम्राट् अंग्रेज—४४९

—, आस्ट्रिया के—५६०

—, आस्ट्रिया-हंगरी का—२८७

—, इराक के—४६

—, ईरानी—२१८-१९

—, कुशान—१२४-२५

सम्राट्, कुस्तुनतुनिया के—२११, २१३,
२१८

—गुप्त—१५७

—चीनी (चीन के)—१०७-०८,

१४२, १७०, १७३, १७७, १८०,

१९८, २२०, ५६३

—जर्मन—२५६-५७, २८७, २९५

—जापानी—४८, १७६

—डोमिशियन—१३५

—तंग—१६९, २४०

—दिल्ली के—४३९

—पूर्वी रोमन साम्राज्य के—२०५

—फ्रांस के—४६६

—विजेण्टाइन—३३९, ८४६

—बौद्ध—१७९

—मंचू—४६६, ४७०

—मिंग—२४५, ३७५, ३८१, ३८३,

३८६, ४६९

—मिस्र के—४६

—मुग़ल—३७९, ४०९, ४४९,

५८९, ६०६

—याओ—४६

—यूनानी—२१०, २८०

—रोमन (रोमन के)—११६, १२८,

१३०, १४०, १४३, १४६, १५७,

१६३, २०१, २३०, ४७० ११५८

—हनु—२४२

—हैप्सबर्ग के—४०८, ५१३

सरकार, अंगोरा की—१००३-०४

—अंग्रेज़ी—३९, २४३, ४११, ५५५

६०८, ६६०-६९, ७८१, ७८८

सवाल (प्रश्न), खिलाफत का—१०००,
 १०२४, १०२८, ११०८
 ————प्रवासी भारतीयों का—८९०
 ————मंदिर प्रवेग का—१०४६
 ————सांप्रदायिक—१०३०, १०३८
 ११३८
 ————, स्वराज्य का—१०२०, १००५
 ————हिन्दुस्तान का—३३३
 ————, हिंदू मुसलिम—१०२६, १०२८
 सहसराम—४३५
 सांची—६९३
 साइप्रस—८४८
 साइबेरिया—६, २५८, ३५२, ८६८,
 ४७४, ४८४, ६६०, ७६९, ८५२,
 ८५६-५८, ८६०-६१, ८७६, ९१०,
 ९२१, ९३३, ९३९, ९४०, ९४७,
 ९४९, ९७६-७७, ११८२, ११९०
 ११९८, १२००, १००२, १२१७,
 १३३९
 ————पूर्वी—९३३
 साइमन कमीशन १०३८, ११४०
 —बोलिवर—५६२
 '——लौट जाओ'—१०३८
 —सर जॉन—१०३८, ११०६
 साइरम—३५, ६९६
 नाउदे—९०९
 नावची—८८७
 नाक्वेटाज—(देखो मुकगन)
 नाग्वोलीन टाप्—६६०
 नागर, (या समुद्र) अरब—८०, ८५,
 ८७, ८८, १२३, १७९, १८६, २५३,
 १०९२

नागर, आर्कटिक—८५३
 ————ईजियन—३४
 ————उत्तरी—९०४
 ————एड्रियाटिक—३९४
 ————काला—३४, १३६, ३१२, ७८८,
 ८४६, ९९४, १०७९, ११४३, १२००
 ————कैस्पियन—३५, १०७, ११७,
 १४२, १६९, २११, २४१, ११७९,
 १२००
 ————पीला—२४५
 ————बाल्टिक—९६७, ११९८, १२१५
 ————भूमध्य—२१, २६, ३०, ३४, ३८,
 ४०, ५०, १०२, १०४, १०९, ११२
 १३, ११७, १३०, १३५-३६, १८२
 २३४, २५५, २९४, ३४२, ५४४,
 ५५०, ६९०, ७८०, ८३७, ८४२,
 ८६७, ९५४ १०७०-७३, १०७५,
 १०८०
 ————लाल—१४४, २५४, ३४०, ३७८
 ८३७, १०७४, १०९२
 नाथु पीटर—२५७, २८०
 नावेक्ष्यवाद—१२२८
 नामन्—२३६
 ————प्रथा (प्रणाली)—२३८, २४०,
 ५८७, ६१३-१८, ६८८, ६५०,
 ६५१, ६५०, ६६५, ६६६, ७०५,
 ७५०, ८४५, ८५४, १०३९
 ————प्रथा का अन्त—३१८
 ————गाही—२५६, २५७, २७३, २८१,
 २९८, ३१८, ३३६, ३४१, ३५१,
 ३९२, ४३०, ४५३, ४६७, ४९०,

- सरकार, बोलशेविक—१२६, १२८, १३२
 —ब्रिटिश—४७२, ५०७, ५९१ ५९२,
 ६१५-१६, ६१८, ६३३-३५, ६४०,
 ६७३, ७०६, ७५०, ७८१, ७८८,
 ७९८, ८२४, ८२९, ८३३, ८३७-
 ३९, ८५१, ८७९, ८८५-८६, ८८८,
 ९४४, ९४७, ९५४-५८, ९६१, ९६८,
 ९७१, ९८४-८६, ९८८, ९९०-९३,
 १००१ १००४, १००६-७, १०१४-
 १५, १०१७, १०२२, १०२६-२७,
 १०३७-३९, १०४१-४२, १०४६,
 १०४९-५०, १०५३-५६, १०५९-
 ६१, १०६५, १०७७, १०८५ १०८७-
 ८८, १०९०, ११०५-०६, ११०८,
 १११०, ११३४, ११४४, ११४६,
 ११५१, ११७५, ११७७, ११८२,
 ११९०, १२४६, १२५२, १२५६-५८,
 १२६८, १२७१-७३, १२७६, १२८२,
 १२८४, १३०२, १३०९, १३२६,
 १३२८
 —ब्रिटिश राष्ट्रीय—१३१४
 —भारत की—१०९९
 —भारत की ब्रिटिश—६६१, ६७१
 —मंच—४७३, ६३८
 —मिस्र की—१०५६, १०५८. १०६०-
 ६१
 —मैक्सिको की—१३३२
 —यूनान की—९९५
 —योरप की—४६८, ७७०
 —राष्ट्रीय—१२७१, १२७३
 —रूस की—६६०-६१, ११०७
- सरकार, संयुक्तराष्ट्र अमेरिका की—११९५
 १२४६, १२५६, १२५९, १२६६,
 १२६८, १२७२, १२७५
 —सम्राट की—७९०
 —सर्बिया की—८७९, ८९९
 —साम्यवादी—११७९
 —सोवियट—१२८-३०, ९३७, ९५०
 ९६६, ९८२, १११५, १११९,
 ११४३, ११४६-४८, ११७९, ११९०
 ११९३-९५, ११९७-९८, १२०३,
 १२०९, १२१२
 १२०५, १२०७, १२०९, १२१२-
 १३, १२१९, १३२०, १३२९
 —स्पेन की—३७७, ६८४, ११६३
 —हांगकांग की—६४०
 —हैंकन की—११७७
 सरस्वती नदी—३७,
 सर्फ—४८८
 सर्वदल सम्मेलन—१०३८
 सर्वोदय—४००, १३४५,
 सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसायटी—९६०
 सर्बिया—३३६, ८४६-४७, ८४९, ७७८-
 ८१, ८९५, ९०१, ९३२, ९६६,
 ११४३
 सविनय अवज्ञा—१३२६
 सलवियन, सर ऑर्थर—६२०
 सलादीन (मिस्र का सुलतान) २७९-८२,
 ३११, ८३५, ८४५
 सलेव—२५८, २७७
 सवाल (प्रश्न), आयरलैंड का—३३६
 —किसानों का—१०४२

साम्राज्य, चगाताई—३२०

—चार्ल्स का—२७६

—चालुक्य—१५९ १७८, १७९,
१८५, २२३

—चीनी—१२०, १७४, २११, २४१
-४२, ३१९, ३५०, ४७१, ६४५,
६५३

—चोल—१८६, १९८, २२३, २५३
३०१-०२, ३०४, ३५६

—जर्मन (जर्मनी का)—३४८,
४०८, ७८५, ८७४, ९६२-६३, ९९३

—जापानी (जापान का)—१७२
६५०, ६६४, ९४४

—ज़ार का—११८२, ११९७-९८

—जावा का—१९९

—तपों का—३९०

—तुर्की—३४८-४९, ४८५, ५६०,
५६७, ५६९, १०५८, १०७८-८०

—तुर्की, पुराना—९६७, १००२

—नैमूर का—३५२

—थीबन—६९३

—दक्षिण भारत के—१८५

—दारा का—४९, ६४, ९४

—दिल्ली का—३६१, ४५६, ४५८४६०

—नेपोलियन का—५४८

—पल्लवों का—२२३

—पवित्र रोमन—१४०-४१, २३०-
३१, २३३, २५५, २८१, २८४,
२८७-८९, २९४, ३११, ३२८,
३३१, ३४८, ४०३, ४०८, ४००
५११, ५४७

साम्राज्य, पश्चिमी एशिया का—३२-३६, ९६

—, योरप का ईसाई—४०७

—पोर्चुगीजों का पूर्वी—३७८, ४३१

—फ्रांस का—७८४

—फ्रांसीसी (दूसरा)—७२६-२७

—बगदाद का—२२२, २४१, २५४,
२७७, ३०९, ६९९

—बगदाद का अरब—१०६९

—ब्रिजैण्टाइन का—३११, ५९१,
६९७-९८, ९९५, १०६९

—ब्रेवेलीनियन—२३, ३६

—बौद्ध—१२३, १४८

—ब्रिटिश—१४५, १९७-९८, ४६४,
५९५, ७८६-८७, ७९७, ८००,
८१३-१८, ८४१, ८७३, ९५१,
९८४, १०५५, १०७३, १०९०,
११००, ११०२, ११४५, ११५०,
१२६३, १२६५, १२८२

—भारतीय—७९

—मंगोल—३१६, ३१७-२०, ३२५,
३५०, ४६९, ८५३

—मंचू—८६८

—मज्जापहित—१९९, ३७१-७२,
३७४-७५

—मज्जापहित और मलक्का का
मलेगिया—३६९-७५

—मध्यपूर्व—९६८

—मध्यपूर्वी ब्रिटिश—३०८

—मलक्का का—३७५-७६

—महमूद गजनवी का—३०८

—मिगनगियों का—६८३

- ४९२, ५१०, ५१५, ५१९, ५२१,
५३९, ७७९, ८४५, १११२, १२९०
सामन्ति सरदार—३१४
सामोस—५७
साम्यवाद—७३, ८१५, ८५७, ९३८,
९४९, ९८०, ९८३, १०१३, १११२-
१३, १११६-१७, ११५३, ११५६-
५७, ११६५, ११६७-६८, ११७०
७२, ११८०, ११८२-८४, ११९२-
९३, १२०३, १२१२, १२२०,
११४३, १२८७, १२९५, १३२०,
१३२१, १३२३, १३३६, १३३७,
१३४१
—प्रारंभिक—७६१
—सैनिक—९३२, ९३६, ९३७,
११९२, ११९६
'साम्यवादी घोषणा पत्र'—५७८, ७६८
साम्राज्य, अंगकोर का—६७४
—अंग्रेजों का हिंदुस्तानी—१०७६
—अकबर का—४४५
—अजटेक—२६५-६६, ३४६
—अब्बासी—२२०-२१, २५३-५४, ३१७
—अरब—३७, २१२, २१४, २१८,
२२१, २७१, २७३-७४, २८२,
४३१, ६८८
—असीरियन—२३, ३५, ६६९
—अधुनिक ढंग का अदृश्य आर्थिक—
८१३
—आस्ट्रियन—१११७
—आस्ट्रिया-हंगरी का—५६८, ९६३
९९३, १०७८
साम्राज्य, 'इनका'—३४६
—इलखान—३१९, ३२३
—ईरानी—३५, ६४, ६८, ९४, ९५,
२१६
—ईरानी-सासानी—१०६९
—ईसाई—१४०
—उस्मानी—३३७, ६८९, ८३६,
८४२-४४ ८४६, ९९३, १०७८
—उस्मानी तुर्कों का—३१७, ४०८,
५४४, ६८८
—ओटो का—२३३
—कंबोजी—१९६
—कंबोडियन—३७०
—कारडोबा का—२७२, ३६९
—किन—२४४, ३०९, ३११, ३१९
—कुबलाई खां का—३५०
—कुशानों का—१२३, १२६, १४८,
१५३, ३०३, ६९७
—कुशानों का सरहद्दी—१२२-२५,
१४८, ३०३, ६९३
—कुस्तु-तुनिया का पूर्वी—२८०
—कैलडियन—२३
—खलीफों का २२५, ३०१, ८३५
—खारजम का—६८८
—गजनवी—२९८
—गुप्त—१५४-५५, १५७, १७१,
१८६, ६९७
—ग्रेनाडा का—२७३
—चंगेजखां का—३१२
—चंद्रगुप्त का—८०
—चक्रवर्ती—१४३

७८०, ७९१, ७९९, ८१३ ८३७
 ८४१, ८६७, ८८४, ९३८, ९४९,
 ९७३, ९८३, १०५१, १०५३,
 १०६०, १०६५, १०६७, १०८१
 १०९१, १०९९, १११४, ११३४,
 ११४०, ११९३, १२४८, १२४९,
 १३०२, १३४०-४१, १३४७

साम्राज्यवाद, अरब का—५६८
 —आर्थिक—६८२, ८१४
 —, ईरान में—७०४ ७०९
 —, औद्योगिक—६८०
 —का जन्म—५६८
 —की उत्पत्ति—८६९
 —की सदी—५६८
 —, तेल—१८७७
 —, ब्रिटिश—८१६, ८३३, ९५५,
 ९६१, १०१४, १०८८ १०९९,
 १३०२
 —, मंगोलों का घुसना—५६८
 —, योग्य का—५७१, ७०५, ८३७,
 ८८१
 —, हिन्दुस्तान का—५६८
 —, हिन्दुस्तान में ब्रिटिश—७८०
 —, हिन्दू—१४८, १५३-५७

मारोन् मोशिये—१११३
 सार्डीनिया—७१९
 नाल—१९
 नाल्म—२९
 नावर स्टेट, आस्ट्रियन—९८८
 नाहित्य, अंग्रेजी—७३१, ७३३
 —अरबी—१०६९

माहित्य, चीनी—४६७, ६४१
 —तुर्की—७०२
 —फारम का—७००, ७०२
 —फ्रेच—४८३
 —यूनानी—३४०
 —यूरोपियन—७३१
 —रूसी—८६५
 —संस्कृत—१५५

सिंगापुर—१९७-९९, ५६४, ६६९, ६७३,
 ६७४, ९५४, १०७३, ११४५, ११८२
 सिंध (प्रान्त)—८६, ९४, १३०, १८५,
 २१४, २१७, २२३-२४, २२६,
 २६२, २६९-७०, २९८, ३०१,
 ८८०, ५८७, ५९०

सिंधिया—४५८, ६६३, ५८३-८४ ५८९,
 —महादजी—५८३
 सिंधु नदी—३६, ६१, ६९, ६४, ७५,
 ७६, ८०, ८६, १५४, १७८,
 १८४, २१४, २३८, २६९, ३०५,
 ३१२, ८३७, ८३८, ८५८, ८९१,
 ८९६, ८६४

सिन्धु—१९८
 सिंहलद्वीप—१४९
 सिन्धोल—३८६, ६६४
 सिक्किम महान्—१९९, ३१, ३५, ६४,
 ६९, ७३-७६, ९४-९६, १०३, ११३,
 १२३, १२५, १४५, १६०, १८१,
 ३१०, ३१५, ३५७५७० ६६३,
 ६९६-९७ ८३३-३४

सिक्किम—१४९
 सिक्किमिया—३० ३३ १०३-१४

साम्राज्य, मिस्त्र—९५

—मिडियन—३५

—मुगल—३६२, ३६५, ३७९,
४३२, ४४८-५०, ४५२-५५, ४५७,
५८७, ६३४, १३४७

—मुसलमान—३७४

—मुहम्मद बिन तुगलक का—३०८

—मेक्सिको—२६६

—मौर्य—७८-७९, ८१-८३, ९६,
११८, १२१

—यूनानी—१३९, २०५, २८०,
६९३

—यूनानी, पूर्वी—२८०, ३३८

—यूनानी रोमन—३९४

—राष्ट्रकूटों का—२२३

—रूसी—३५०, ५६७, ५८६, ९६२,
९९३, ११०७

—रोमन—१०९, ११३, ११६-१७,
१२३-२४, १२८, १३०, १३८,
१४१-४२, १४४-४६, १५७, १६२,
२०१, २१३, २५७-५८, २८५,
२९४, ३११, ४८१, ६९०, ६९७,
८१७, ८३५, ११५८, ११६१

—रोमन नया—१४०

—रोमन, पश्चिमी—१३७, १३८,
१४०, १५७, २०१-०४, २३०

—रोमन पुराना—१४०

—रोमन पूर्वी—१३८-४०, २०१-०२
२०४-०५, २१०, २१२, २१५-१६,
२२९, २३१, २३३, २५०, २५४,
२८०, २८९-९०, २९४, ३३७-३८,

साम्राज्य, विजयनगर का (हिंदू)—२९८,

३६५, ३६८, ४६०

—ध्रीविजय का (बौद्ध)—१९७-

२००, २४०, २५३, ३२३, ३७०,

३७४-७५

—संग—२४४, ३१०

—संयुक्तराष्ट्र अमेरिका का—६८२

—साइबेरियन—३२०

—सासानी—१४६

—सिकन्दर का—७७, ९५, १०३

—सुनहरे कबीलों का—३१९-२०,
३५०

—सुमात्रा का (बौद्ध)—२५३

—सेलजुक—२८१

—सेल्यूकस का—८०

—स्पेन का—२६७, ४१२-१३

—स्पेन का अरब—२७३

—स्पेन के अमीर का—२७३

—हसिया या तंगुओं का—३१०

—हिंदुस्तान का—३६२, ४३४,
६८०, ७०५

—हिंदुस्तान का नया—५६९

—हिंदुस्तान का ब्रिटिश—४६१,
५८५, ५८८, ६७३, ६९८, ७०५,
७८६, ८१४

—हिंदू—१५०

साम्राज्यवाद—१२७, १३१, १४३, १४८,

१७५, ३४९, ३८९, ५०३, ५६४

५६८, ५७२-७४, ५८२, ६१२-१४,

६३३, ६३७, ६४३, ६५५, ६८०-८२,

६८७, ७०५, ७०७, ७१०, ७४३,

८४४, ८५०, १०७९
मुलतान, गुजरात के—३६४
—, तुर्की के—३१८, ३३८, ४०८,
५५४, ८३७, ८४३, ८४८-४९,
८७९, ८९१, ८९७, ९९८
—, पागल—३०८
—, मांडव के—३६३
—, मिला के—३१७-१९, ३३९,
८३५-३६, ८४५
—, मैमलूक—८३६
—, रजिया—३०५
—, महमूद—(दे. महमूद गज़नी)
—, मुल्मान, शानदार—२९, ४९,
१२७, ३३८, ३८८-८९, ८०८,
४०९, ४३३
मुल्तानियन—१००५
—, का खात्मा—९८१, १००८
मुहिता, महारानी—३७१
मूडान—१०५५, १०५७-५८, १०६०-
६२, १०६५
—, एग्लो-रजिफियन—१०५७
मूरत—८५०, ८५६, ४५६
मूर्य ग्रहण—१२२८
—, महल—१२२८
मूर्यदशी—८८
मूसा—६९६
मेवश मोपिया—२०५, ३३८
मेड डोमीनिका—३३७
—, पीटिका—३९६
—, पीटिको—४८३-८४, ५५५,
५२२, ८५३, ८५६, ८५९-८६३

८६६, ९११, ९३७
मेड पैट्रिक—८१७
—, फामिम जेवियर—३८२, ३८८
—, का आर्डर—३२७
—, वनोर्ड की घाटी—५४७
—, यार्क—२९३
—, हेलेना—५५४-५५, ५५७-५८
मेदान—७२६
मेन, केमवचंद—६२४
मेनकेटिव—२३
मेनगुप्त, यनीन्द्र मोहन—१३२६
मेफोवरीज—६९, ९५.
मेमटिका—६९०
मेम्यूअल पोरीज—४७०
मेगरी—८७९
मेनेपिन—६०४
मेलेवीज—१९७, ३६९, ३७०
मेलेमीन—३८, ६९
मेनो डेम्का—१२६६
—, जगो—१२६६
मेल्बुर्न—७३, ७९, ८०, ९६, ९७,
१०३, १२०, १४९, ३९७
मेम्बरी लाई—८३९, ८८४
मेविके—३९५
मेमबुलोम—५३७
मेमनी—११३१
मेम (मेम)—६३७, १०७७
मेम क्रमिसको—६३९, ८०१
मेको—७०
मेम उज्ज्वलता मर—६३९
मेम—७०६

- १२२, २०७, २१३, ५४४, ८३४-
३५, ८३८, १०६२, १०६४
- सिकियांग—११९०
- सिक्के की उत्पत्ति—९२
- सिक्ख—४४९, ४६४, ५८२, ५८५,
५८९, १०१५, १०२९-३०, ११३८,
११७४,
- अकाली—१०२९
- और मराठे—४५१-५७
- सिडनी वेव—७७०
- सितम्बर की हत्यायें—५२५
- सिद्धार्थ—५८ (देखो बुद्ध)
- सिनफेन (या सिनफीन) ८२५, ८२९,
९८५-८७, १०२२
- आन्दोलन—९८६
- सिनेट—१०९-१०, ११३, ११८, १३३
- सिनेटर—१०९
- सिनेमैडोम—८०१
- सियस्को—४८७
- सिरवा, सिनोर डिला—१२३३
- सिराजुद्दौला—४६०
- सिराजेवो—२८७
- सिवास—९९७
- सिविर—४६९
- सिविल डिफेंस ओवोडियन्स इन्क्वायरी
कमिटी—१०२५
- सिसली—२७, ३०, १०९, १११, २०२,
२०५, २३४, २५६, ४०३, ४०८,
७२०-२१
- सी० आई० डी०—६३२
- सी-आन-फू—१६९, १७६, १८२, १८६,
- सीज़र—११५-१६, १३२, १५५, ३३८,
३५०, ४२५,
—आगस्टस—११५-१६, १२४, १३२-
३४, १३६, १४०,
—जूलियस—११४-११७, १२३, १३२,
२१३, ४८९, ४९०
—विजेटाइन—४०८
- सीनन—४३३, ६९५
- सीमाप्रान्त—९५३, १०४२, १०४४,
११८०, १२१७, १३०५, १३२७
- सीरियस—१९
- सीरिया—१४७, १८४, २०७-०८, २११-
१३, २१६, २२२, २५८, ३८१-८२,
६९२, ६९८, ८३७, ९००, ९६८,
९८१, १००१, १००२, १०५१,
१०६७-६८, १०७१-७२ १०७४,
१०७८-८५, १०९०-९२, १०९४,
१०९७-११००
- सीलोन—(देखो लंका)—८८७
- सी-संग-तंग—६४६
- सुंगयुन—१८४
- सुकरात—७२, ७३, ७८, १२२२, १३४९
- सुबुक्तगीन—२२६
- सुमात्रा—१५०-१५२, १९७-९८, २५३,
३२३-२४, ३६९, ३७१, ३७५, ३८१,
५६७, ६६९, ६८२, ८७७, १३२९
- सुमेर—६९२
- सुरैया वेगम—११०८, १११०-११
- सुलतान,—९९४
—, अफगान—४३२, ४३५
—, उस्मानी—३३९, ३४८, ८३६,

- १२२, २०७, २१३, ५४४, ८३४-
३५, ८३८, १०६२, १०६४
- सिकियांग—११९०
- सिके की उत्पत्ति—९२
- सिक्ख—४४९, ४६४, ५८२, ५८५,
५८९, १०१५, १०२९-३०, ११३८,
११७४,
- अकाली—१०२९
- और मराठे—४५१-५७
- सिडनी वेव—७७०
- सितम्बर की हत्यायें—५२५
- सिद्धार्थ—५८ (देखो बुद्ध)
- सिनफेन (या सिनफीन) ८२५, ८२९,
९८५-८७, १०२२
- आन्दोलन—९८६
- सिनेट—१०९-१०, ११३, ११८, १३३
- सिनेटर—१०९
- सिनेमैडोम—८०१
- सियस्को—४८७
- सिरवा, सिनोर डिला—१२३३
- सिराजुद्दीला—४६०
- सिराजेबो—२८७
- सिवास—९९७
- सिविर—४६९
- सिविल डिस ओबोडियन्स इन्क्वायरी
कमिटी—१०२५
- सिसली—२७, ३०, १०९, १११, २०२,
२०५, २३४, २५६, ४०३, ४०८,
७२०-२१
- सी० आई० डी०—६३२
- सी-आन-फू—१६९, १७६, १८२, १८६,
- सीज़र—११५-१६, १३२, १५५, ३३८,
३५०, ४२५,
—आगस्टस—११५-१६, १२४, १३२-
३४, १३६, १४०,
—जूलियस—११४-११७, १२३, १३२,
२१३, ४८९, ४९०
—विजेटाइन—४०८
- सीनन—४३३, ६९५
- सीमाप्रान्त—९५३, १०४२, १०४४,
११८०, १२१७, १३०५, १३२७
- सीरियस—१९
- सीरिया—१४७, १८४, २०७-०८, २११-
१३, २१६, २२२, २५८, ३८१-८२,
६९२, ६९८, ८३७, ९००, ९६८,
९८१, १००१, १००२, १०५१,
१०६७-६८, १०७१-७२ १०७४,
१०७८-८५, १०९०-९२, १०९४,
१०९७-११००
- सीलोन—(देखो लंका)—८८७
- सी-संग-तंग—६४६
- मुंगयुन—१८४
- सुकरात—७२, ७३, ७८, १२२२, १३४९
- सुवुक्तगीन—२२६
- सुमात्रा—१५०-१५२, १९७-९८, २५३,
३२३-२४, ३६९, ३७१, ३७५, ३८१,
५६७, ६६९, ६८२, ८७७, १३२९
- सुमेर—६९२
- सुरैया वेगम—११०८, १११०-११
- सुलतान,—९९४
- , अफ़ग़ान—४३२, ४३५
- , उसमानी—३३९, ३४८, ८३६,

- स्थापत्य कला, गॉथिक—२९२-९४, ३४१
 —, चीनी—३८६
 —, जावा की—१९९
 —, बौद्ध—२७३, ३७३
 —, भारतीय—३०४
 —, मुगल—४४७
 —, सरासानी—२१६
 —, हिन्दुस्तान की प्राचीन—
 ३५३, ३५८-५९, ३६३, ४३८
 स्नाउडन, वाइकाउंट फ़िलिय—९७३
 ग्नाटी—२७, ६७, ६९
 ग्नाटैक्स—११४
 स्पिनौजा—१२२२
 स्पेंगलर ऑस्वान्ड—१२९३
 स्पेन—११३, ११७, १४०, १४६, १५३,
 २०१, २१३-१७, २१९-२०, २३१-
 ३२, २३८, २४०, २५८, २७०-७६,
 २९४, ३३२, ३४२-४६, ३७५-७९,
 ३८८, ३९१, ३९७, ४००, ४०३,
 ४०७-०८, ४१०-१८, ४१६-१८,
 ४२२, ४२५-२७, ४४२, ४८२,
 ४८६, ५०५, ५०८-०९, ५४७-६७,
 ६८८, ६९०, ७६५, ७६९, ८०१-
 ०२, ८१०, ८१८, ८१८, ८८१,
 ९८०, ११६२-६८, १२३३, १२८५-
 ८९, १३३१, १३४५
 —अरबी—२२०-२१
 —उत्तरी—२७३
 —का लोकतंत्र राज्य—२७३
 —के अमीर—२७३
 —के सिार—२७५
 स्पेन, दक्षिण—३१७
 —में क्रांति—१२८५
 —में प्रजातंत्र शासन की स्थापना—
 ११६३
 स्फिक्म—२२
 स्फोरजा काउंट—११४८
 स्मर्ना—१९४, १९५, १९७, १९८, १००१-
 ०३, १००४, १०१२
 स्मानली इंस्टीट्यूट—९२४-२५
 स्मिथ एफ. ई.—८३१
 स्याम—८५, १५०, १५२, १९७ ३२८,
 ३७२-७४, ३८१, ४७१, ५६४, ५६७,
 ६६९, ६७३-७६, ९८३, ११११-१३,
 १३२९
 स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा—८३
 —की लड़ाई—८८
 '—पर'—७५२
 स्वदेशी आंदोलन—६३१-३२
 स्वदेशीवाद, अरबी—१०६७
 'स्वराज्य'—६२९
 —आपनिवेगक भारत में—५०८
 —, पूर्ण, की घोषणा—५०८
 स्वराज्यपार्टी या दल—१०३०-३१
 'स्वर्गपुत्र'—१४२
 'स्वभिनिक'—१२९२
 स्वाधीनता की घोषणा (अमेरिका की)
 —५०९-१०, ५०२, ७८३, ७८९,
 ८०७
 —द्विज—१०६१
 स्विनबर्न—७२२-२३
 स्विन-मघनन—३३७

सोमा—१७६-७७

सोनले—७४५

सोमनाथ—२२६, ३११

सोयाबीन—९४४

सोवियट,—६६२, ७३५, ८५१, ८६१-

६२, ९०६, ९१६-२०, ९२३-२७,

९३०-३४, ९३६, ९३८, ९४०, ९४७,

९४९, ९६६, ९६८, ९७५, ९७७,

९८१, ९८४, १००१, १०११,

१०२२, ११०२, १११४, १२५९,

१३०८

—की कठिनाइयाँ आदि—१२०९-२०

—की विजय—९३०-४२

—की शुरुआत—९१५

—, चीनी—११७९

—पंचायतें—११६७, ११९१, ११९७

—पीटर्सबर्ग की—८६१-६२

—पेण्टोग्रेड की—९२१, ९२३

—प्रजातंत्र—१०७९

—प्रणाली—७०८, ७२७

—फेडरेशन—९६७

—मास्को की—८६२

—यूनियन—३३१, ५०१, ९४७,

९७६, ९७९-८०, ९९५, १०११,

१०७९, ११०७, ११५०-५१,

११६४, ११६७

—रूसी—९४९

—शासन प्रणाली—९७६

—संघ—७८३, ११९९, १२००,

१२०३, १२०५-०८, १२१०-१५,

१२१७-२०, १२४५, १२४९, १२५५,

१३०१, १३२०

सोवियट सरकार—१११५, १११९, ११४६-

४८, ११७९, ११९०, ११९३-९५,

११९७-९८, १२०३, १२०५,

१२०७, १२०९, १२१२-१३, १२१९

'सोशल कंट्रैक्ट'—४८०

स्कंदगुप्त—१५६, १५८

स्काटलैण्ड—२८०, ३२८, ३३६, ४२३,

४२८, ७९२, ८१९, ८२६, ८४२

स्कैंडिनेविया—८७७, १२४३, १३३५

स्केपाल्फो—९६९

स्कॉट सर वाल्टर—२८०, ७३६-३७

स्टॉक सर ली—१०६०-६१

स्टाकहोम—८९७

स्टालिन—८५७, १२०१-०४ १२०७

१२१२, १२१४, १२२०

स्टीफेंसन—४९८

स्टील हैलमेट—११२०

स्टेंडर्ड आयल कंपनी—११९७

स्टेड्स जनरल—५१६

स्टेनली हैनरी—८४२

स्टो हैरियट बीचर—८०८

स्ट्राकोश, सर हैनरी—१२४१

स्ट्रासबर्ग—७२९

स्त्रियों की जागृति पश्चिम में—९८३

—पूर्व में—९८३

स्थापत्य कला (या गृह निर्माण शैली)

—अमेरिका की—२६४

—अरब की—२९२

—आर्यों की—४१

—उस्मानी—७०३

हमला, वालकन लीग का—८४९
 —, ब्रिटिश लोगों के—७८७
 —, मंगोलों का—३०५, ३१५, ३७३
 —, मध्य एशिया की जातियों के—
 ११९, ७१२
 —, मध्यमवर्ग का—३४१
 —, महमूद गजनवी का—२२८,
 २३४, २९९
 —, मुसलमानों का—१८५, १८७, २८९
 —, मेनाण्डर का—१२०
 —, यूनानियों का—७४
 —, यूरोपियन, शक्तियों के—९३२
 —, यूरोपियनों का—३६४, ५७१
 —, रूस का टर्की पर—६४४
 —, रूसी बलगेरियन भरव या सेल-
 जुक तुर्कों के—२८९
 —, शकों का—१२०
 —, सिकन्दर का—७४-७६, ७८, ९५
 —, सुवुक्तगीन का—२२६
 —, सेलजुक तुर्कों का—२५७
 —, सेल्यूकस का—८०
 —, हूणों का—१३८, १५८, २०२
 हरक्यूलीज का स्तम्भ—२१४
 हरजीगोवीना—८४७, ८४९
 हरप्पा—५१. २६८-७०, ६९१
 हरिजन—६४४
 —, मन्दिर प्रवेश—६४४
 हर्षवर्धन—१७८-७९, १८३, १८५, २००,
 २११, २२३-२४, २२७, २४०
 हल्पाकू—३१६-१७, ३१९, ३२१. ३३१,
 ७००-०१

हस्तिनापुर—५२, १३०
 हांगकांग—१९७, ६२६, ११७१, ११७४
 हांग-वू—३८०
 हाइड, मि०—६७७
 हाउस ऑफ कामन्स—४२१, ५१६,
 ८२३, ८६३, ९३३
 —, ऑफ लार्ड्स—४२१, ५१६,
 ८२७, ८२९-३०, ८३२, १०१९
 हाफिज—७०१,
 हारघीन्ज—४९६
 हारवे—३९८
 हारुनल रशीद—२१७, २१९-२१, २२४-
 २५, २३१, १०९७
 हाल्लेम नगर—४१६
 हाल्लैंड—८२१, ८७७, ९०७, ९४८,
 १०७५, ११४२, ११४६, १२६७,
 १२७८
 —, का राजदूत मण्डल—४७०
 हिडैनवर्ग, वॉन—१२९४-९५
 हिन्दीचीन—९५, १५०-५२, १९५,
 १९७, २००, ३६९, ३७३, ३८१,
 ५६७, ६७५ ६८०, १०७५, ११६५,
 १३३९
 —चीन, फ्रांसीसी—६६९, ६७४,
 १११२-१३
 हिन्दुओं की पौराणिक कथायें—३१, ६२२
 हिन्दुत्व—१५८, ६१५
 हिन्दुस्तान (भारत) ३, ४, ६-८, १३-
 १७, १९, २२, २४-२६, २९, ३१,
 ३८-३९, ३८, ३९-४१, ४८, ४५,
 ८९-५२, ५३-६०, ६३, ७५-८०,

सिविल कोड—१००९

स्वीडन—३२१, ४१९, ७७३, ८५३,

८७७, ८९७, ११४२, १२६३, १२६९

स्वीज़रलैण्ड—८५, १३३, २३२, २७५,

३३०, ३७०, ३३७, ५४७, ५६०,

४०६, ४०८, ४११, ४२०, ४७५,

७९३, ९१६, ९१६, ९२३, ११४२

११५५, १२६७, १२७८

———— का अमरसंघ—३३७

स्वेनहेडेन—३२१-२२

हंगरी (हंगेरी)—२५५, ३११, ३१५,

३१६, ३१९, ३४८, ३५०, ३९३,

४०७-०८, ४८५, ५६८, ५९९,

७१६-१७, ७८५, ८२९, ९६५-

६७, १११६, ११२१-२२, ११४३,

११६४, १२३९, १२७०, १३०४,

१३३८

हजरत मुहम्मद (दे० पैगम्बर मुहम्मद)

हडसन—५९१

———— की खाड़ी—४७४

हनोवर—४२७, ५६१, ७८५

हबीबुल्ली, अमीर—११०७-०८

हमला (ले) या आक्रमण, अंग्रेजों का—

३७८, ५८५

————, अकबर का गोवा पर—४५०

————, अफगानों का हिन्दुस्तान पर—

२९७, ३०३

————, अरबों का—१४०, २१४, २७१

————, अशोक का—९७

————, इटली का—८९०

————, ईरानियों का—६४

हमला (ले), उत्तर के तातारियों का—१६७

————, उस्मानी तुर्कों का—३४९

————, एंग्लो नार्मनों का आर्थर्लैंड पर—

८१८

————, एटिला का पश्चिमी रोमन

साम्राज्य पर—२०२

————, कमालपाशा का—१००९

————, गॉल और दूसरी जातियों का

मकदुनिया पर—१०३

————, चन्द्रगुप्त का यूनानियों की फ़ौज

पर—७९

————, चन्द्रगुप्त के सहायकों का पाटलि-

पुत्र पर—७९

————, चीनियों का मञ्जापहित पर—

३७१

————, जापान के—१७२, ३८७, ६५३,

९४९, ११८५

————, ज़ार का—८४६

———— डचों का—३७८

———— तुर्कों के—१३८

————, तैमूर का—२५१

————, नादिरशाह का—४५८, ७०५

————, नेपोलियन का—५५१

————, नेपोलियन (तीसरे) का—७२५

————, पांचालों और राष्ट्रकूटों के—२२७

————, पोलैण्ड के राजा का—४८५

————, फिरोजशाह के पिता का—३६१

————, फेसिस्टों के दल का—११५७

————, फ्रान्स का—६७४

————, बर्मा के राजा का—६७५

————, बर्वरों का—२०४

- ३५१, ३५९, ४३३, ४४०, ४४४,
४५७-५८, ४६२, ५८५, ५८९,
६०९, १०१२, १०२६, ११०६
हिन्दुस्तान, उत्तर-पश्चिम—१७, ७७-७८,
१२०, १२६, ६९१
——, उत्तर का राजनैतिक पतन—२२३
——, दक्षिण—४, ३९, ४१, ५०, ८०
९७, १०४, १२१-२३, १२५-२६,
१३१, १४४, १४८-५२, १५९,
१६१, १६९-७०, १८५-८८, १९२
१९५, १९७-९८, २२३, २३९-४०
२५३, ३००-०१, ३२३-२४, ३५५
३५७, ३६२, ३६४, ३६६, ३६८,
३७१, ३७६, ४३३, ४४०, ४५९,
५४५, ६०९
——, दक्षिण उत्तर को मात करता है—
११८-२२
——दक्षिण, का पश्चिमी दुनिया से
व्यापारिक संबन्ध—१४९
——, के शिलालेख—२३९
——दक्षिण-पूर्वी—९७
——पश्चिम—५८, २२४, ३५५, ३६२
३७८, ६३१, १०४२
——पूर्वी—३५५, ३६२
——का अंग्रेज वाइसराय—४२६
——का असहयोग आंदोलन—९८२
——का औद्योगीकरण—९५६-५७
——का पुनर्जागरण—६२२-३३
——का मध्ययुग—२३९
——का राष्ट्रीय आंदोलन—९२०
——का विदेशी बाजारों पर कब्जा—
३६०, ४६८
हिन्दुस्तान का व्यापार—१५९
——की आजादी का मसला—८५
——की आजादी की लड़ाई—२३४-३५
——की उत्तर पश्चिम सरहद—१५३,
१८४-८५, ११०५, १३०६
——की खुफिया पुलिस—९३९
——की गरीबी की समस्या—५९५
——की तिज्जारत—१०७१
——की देशी रियासतें—१०६२, १०९०
——की पंचायत प्रथा—३०१
——की पौराणिक कथायें—६९४
——की ब्रिटिश सरकार—९७१
——की सरकार का तिज्जारती और
व्यवसाय विभाग—६१७
——के उद्योग पर नियंत्रण—९५८
——के गाँव, किसान और जमींदार—
५९९-६१०
——के घरेलू उद्योग और शिल्प—४९४-
९७, ५९६, ५९८, ५९९
——के जहाज बनाने के हुनर का नाश—
५९६
——के नये शहर—६०१
——के पारसी—१४६
——के मजदूर संघ—७७८
——के विश्वविद्यालय—१२६-२६
——के वैदेशिक व्यापार में अव्यवस्थितता
—९५८
——के समुद्री मार्ग पर इंग्लैण्ड का
कब्जा—५६८
——के गवर्नर जनरल—५९३

८३, ८५, ८६, ८८, ९३-९७, ९९-
 १०३, १०५-०६, ११०, ११७-२७,
 १३१-३२, १३५, १४२-७२, १७४-
 ८५, १८८-९०, १९३-९५, १९९,
 २००-०३, २०६-०७, २११, २१४,
 २१६-१७, २१९, २२१, २२३-२८,
 २३२, २३४, २३८-४३, २४७,
 २५१, २५३, २५८-६३, २६५-६६,
 २६८-६९, २७७, २८५-८६,
 २८८, २९३-९४, २९७-९९, ३००-
 ०६, ३०८-१०, ३१२, ३१९-२१,
 ३२३-२५, ३३१-३४, ३३७, ३४१-
 ४४, ३४७, ३४९, ३५१-५३, ३५५-
 ६०, ३६३-६४, ३६६-६७, ३७०,
 ३७२, ३७५, ३७.-८०, ३८३,
 ३९१, ३९४-९५, ३९९, ४०९,
 ४११, ४२३, ४२९-३५, ४३७-३८,
 ४४५, ४४८-५३, ४५५, ४५७-६५,
 ४६८-६९, ४७१-७३, ४७६-७८,
 ४८१, ४८४, ४८६-८७, ४९४-५५,
 ५००, ५०२, ५०३, ५०५-०९, ५१५,
 ५२१, ५४३, ५६२-६३, ५६७-६९,
 ५७१-७२, ५८०-८२, ५८४, ५८६-
 ८९, ५९१-६०१, ६०४-०७,
 ६०९, ६११-१४, ६१७-२३, ६२६,
 ६२८-३१, ६३३-३५, ६३८, ६४८,
 ६५१, ६५६, ६६१, ६६८, ६७०-
 ७१, ६७३, ६७५, ६८२, ६८५-
 ८८, ६९०-९१, ६९३-७०६, ७०८,
 ७१४, ७१६, ७२२, ७३५, ७४४,
 ७५१, ७६०-६१, ७६३, ७८०-८१,

७८४, ७८६-८९, ७९३-९४, ७९६-
 ९९, ८१३-१४, ८१६-१७, ८२९,
 ८३७-३८, ८४०-४१, ८४६-४७,
 ८५४, ८६५-६६, ८६९, ८७२, ८७९,
 ८८३-८४, ८८६-९१, ९११, ९२९,
 ९३२, ९३९, ९४३-४४, ९४६,
 ९५१, ९५४-५८, ९६१-६२, ९६६,
 ९६८, ९७१, ९७७, ९८१-८३, ९९०
 ९९९, १००२, १००३, १००६-०७,
 १०१२-२०, १०२२-२६, १०२८-३०
 १०३२-३३, १०३५-३८, १०४२-४३
 १०५४-५७, १०४९-५३, १०५५,
 १०६२, १०६६, १०६८, १०७१-
 ७७, १०८२-८३, १०८८, १०९०-
 ९१, १०९३-९५, १०९९, ११००,
 ११०२, ११०४-०८, १११२-१३,
 ११२३, ११३०-३१, ११३४, ११३८
 ११४१, ११४५-४६, ११६५, ११६९
 ७०, ११७२-७३, ११८०, ११८३-
 ८४, १२००, १२०५, १२३८-४०,
 १२४७, १२५३, १२५८-५९,
 १२६३, १२७३-७५, १२७९, १२८२-
 ८४, १२८७, १२९०, १२९८, १३०२
 १३०५-०६, १३२६, १३२९, १३३४-
 ३५, १३३९-४०, १३४५, १३४७

हिन्दुस्तान, उत्तर—३९-४१, ४९, ८०, ९६,

१२०-२३, १२५, १४८-४९, १५१
 -५२, १५४, १५६, १५८-५९, १६५
 १७८-७९, १८६-८८, २००, २११,
 २२०, २२३-२४, २२६, २२८,
 २४०, २९८, ३००-०१, ३०५,

- हिन्दुस्तानमें हिंसा के विचार पैदा हुए—६३१
 —, युद्ध काल में—९५१-६१
 —, स्वतंत्र—९८९
 हिन्दुस्तानी, उद्योग—५९५-९६, ६१६,
 ६३१, ९५७, १०१४
 —उद्योगों का खातमा—५९६-९७
 —उद्योगों की रक्षा—९५७
 —उद्योगों के प्रति ब्रिटिश नीति—
 १०१४
 —कमिटि (जर्मनी की)—९५२
 —कहानियाँ—८७०
 —कारखाने—८६०
 —क्रांतिकारी—९५२-५३
 —प्रवासी—९५३
 —पूँजी—६१६, ६२७, ६३१
 —पूँजीपति—९५५, ९५७, ९५९
 —वर्ग—१०१४
 —व्यापार—६१६
 —लिवरल—९५९, १०२३
 —सरहद—११९१
 —स्त्रियाँ—७८८, ८७१
 —स्त्रियों की जागृति—१०४२
 हिन्दू—५८, १५०, १५९, १७८, १९५,
 १९९, ३०६, ३०९, ३३३, ३५५,
 ३५७, ४४३, ४४६-४८, ५२१,
 ५८९, ६३०-३१, ९६०, १००६-
 १५, १०२६-३०, १०५२, १११३
 —और मुसलमानों में भाईचारे के
 दिन—१०१७, १०२६-२७, १०३२
 —तिजारत—१०७१
 —दार्शनिक—१८९
 हिन्दू परिपाटी—३७१
 —पुस्तकें—८६५
 —मन्दिर—४४९
 —मुस्लिम एकता—९६०, १०२०,
 १०४८
 —विचार—१२४
 —शास्त्र—६१५
 —समाज—६१५
 हिन्दूकुश—११०६, १११५
 हिंसा के बारे में नेपोलियन—५५७
 हिजरत—२०९, २११-१२
 हिजरी संवत्—२०९
 हिटलर, एडोल्फ—११२०, ११२५,
 १२२३, १२९०-९२, १२९४-१३०३
 १३०७, १३१७, १३३६-३७
 —वाद—१२९३, १३०३, १३३८
 —आही—१२९०, १३००, १३०२
 हिंदियाशी—३८७-८८
 हिमालय—३३, ८८, १४८, १८८, ४७१,
 ५८४
 हिरान—३१२, ७०१-०२
 हिरेक्लियम—२१०-११
 हिलाल—२५८, २७७
 हिल्डेब्रेड—२५७
 हीनरिय—७३२-३३
 हीवर्त—५३४
 हुईयेंग—१६८-६९
 हुगली—४५०
 हुमायूँ—४३५-३६, ५०२
 हुमैन—२१५
 —गरीफ—१०८०, १०९३-९५

हिन्दुस्तान, गांधीजी का अनुकरण करता है—

१०१३-२४

—, निदरलैण्ड का—६७३

—पर ब्रिटेन का आर्थिक प्रभुत्व—
१०३२

—, 'पुण्यभूमि'—१९०

—, 'पूर्वी दुनिया का लंकाशायर'—
५९६

—, प्राचीन—४१, ८१, १५३,
२४४, ७३९

—, फ्रेंच—६३१

—, ब्रिटिश—६१८, १०४९

—मध्य (भारत)—४०, ४९, ९६,
९७, ९९, १५८, ३०१, ३५५, ३५९,
३६२, ३९०, ४४०, ४५७, ४६०,
५८४, ५८९, ६०९

—, मध्य युग का—१९०-९४

—, महायुद्ध शुरू होने के वक्त—
८८३-८९१

—में अंग्रेजी तालीम या शिक्षा—
६२३, ६२५-२६

—में अंग्रेजों की नीति—५९१-६०१,
६०८

—में अंग्रेजों ने कैसे शासन किया—
६११-२१

—में अंतःकरण और भाषण की
आज्ञादी—१८९, ३३१

—में अहिंसा का संदेश—११२३

—में आजकल के मजहूबी झगड़े—३३३

—में आधुनिक उद्योग-धंधों की
उन्नति—६१७

हिन्दुस्तान में ग़दर (१८५७) के बाद की
पहली ग़ावत—९९९

—में जहाज़ बनाने का व्यवसाय—
१४९

—में टेरिफ़ बोर्ड—१०३३

—में धार्मिक, सांस्कृतिक, कला और
अपसी मेल और सामंजस्य की
कोशिश—३५५-६०, ३६२-६३, ४३८

—में बड़े उद्योगों को प्रोत्साहन—९५६

—में ब्रिटिश नीति का परिवर्तन—

—में ब्रिटिश पूँजी का संरक्षण—९५७

—में ब्रिटिश माल के बहिष्कार का
आन्दोलन—६३२ १२८३,

—में ब्रिटिश राज्य की शुरूआत—४६१

—में मजदूर आन्दोलन कमजोर होगया—
१०३५

—में मशीन, उद्योग बढ़ने लगा—६१३

—में मुसलमानी हुकूमत की शुरू-
आत—२९९

—में युद्ध और विद्रोह—५८२-९१

—में राष्ट्रीय आन्दोलन की बढ़ती—
६२३

—में राष्ट्रीय महासभा (काँग्रेस) का
जन्म—५७२

—में वायसराय—९६१, १०१७,
१०२५

—में सांस्कृतिक एकता—१८९-९०
३५७

—में स्थापित स्वार्थों के वर्ग का
निर्माण—८८३

—में हिन्दू-मुसलमानों के दंगे—१०२६

‘सस्ता साहित्य मण्डल’ के प्रकाशन

सस्ता साहित्य मण्डल के ये उच्चकोटि के सस्ते और जीवन निर्माणकारी प्रकाशन, १) प्रवेश फ्रीस देकर स्थायी ग्राहक बन जाने पर सबको पौने मूल्य में मिल सकते हैं। ग्राहकों को प्रत्येक पुस्तक की एक-एक ही प्रति मिल सकती है। विशेष जानकारी के लिए बड़ा सूचीपत्र मंगाइए।

—व्यवस्थापक

- १—**दिव्य जीवन**। प्रसिद्ध लेखक श्री स्वेट मार्टिन के The Miracle of Right Thought का अनुवाद। जीवन की कठिन समस्याओं से निराश युवक के लिए संजीवनी विद्या। मूल्य १।=)
- २—**जीवन-साहित्य**। गुजराती के महान् विचारक काका कालेलकर के शिक्षा, संस्कृति, सभ्यता, राजनीति आदि महत्त्वपूर्ण विषयों पर लिखे निबन्धों का संग्रह। दो भागों में। १।)
- ३—**तामिलवेद**। दक्षिण के अछूत ऋषि तिरुवल्लुवर का उत्तम और उत्कृष्ट नैतिक, धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक, शिक्षाओं से भरा हुआ ग्रंथ। मूल्य ॥।)
- ४—**भारत में व्यसन और व्यभिचार**। [रीतान की लकड़ी] भारत में व्यसन और व्यभिचार सम्बन्धी हिन्दी की सर्वोत्तम पुस्तक। इन दुर्व्यसनों में फँसे देश का नग्न दर्शन तथा उन व्यसनों को दूर करने का उपाय। मूल्य ॥।=)
- ५—**सामाजिक कुरीतियाँ**। [जवतः अप्राप्य] मूल्य ॥।)
- ६—**भारत के स्त्री-रत्न**। प्राचीन भारतीय देवियों के आदर्श जीवन चरित्र, तीन भागों में। मूल्य ३।)
- ७—**ग्रनोखा**। फ़्रांस के प्रसिद्ध उपन्यासकार विक्टर ह्यूगो के ‘लाफ़िंग मैन’ नामक उपन्यास का अनुवाद। राजाओं तथा दरबारियों की कुटिल क्रीड़ाओं का नग्न दर्शन। मनोरंजक, करुण और गम्भीर। मूल्य १।=)
- ८—**ब्रह्मचर्य-विज्ञान**। ब्रह्मचर्य पर अत्युत्तम पुस्तक। उपनिषदों, पुराणों तथा बह्म से अन्य धार्मिक ग्रन्थों के प्रमाणों से युक्त। मूल्य ॥।=)
- ९—**योरप का इतिहास**। अर्थानुबल्लिदान, राजनीति, देशप्रेम तथा स्वाधीनता का इतिहास। तीन भागों में। मूल्य २।)
- १०—**समाज-विज्ञान**। समाज की रचना उसके विकास तथा निर्माण पर लेखक ने

हुसैन (शाह)—१०८१, १०९०, १०९३-९५, ११००, ११०५	हैनिवाल—११२-१३
हुंगसिन-चवान—६३७	हैप्सवर्ग—२८७, ३२६, ४११, ४८३, ५१३, ५२८, ५५०, ७८४, ७८५
हुवर, राष्ट्रपति—१२३७, १२५७, १२७०-१२७९	हैगे (स्कूल)—७३६
हेग—८७७, ९७०, ९९१	हैरोडोटस—३५, ६४-६६, ६८, ७१
हेजाज—१०७३, १०८०-८१, १०९०, १०९२, १०९४-९५, ११००, ११०५	'होवो'—१२८१
हेटी—८१४	होमर—२७, १०४
हेनरी (अष्टम)—४०३, ४०७, ४१२, ४२१—ग्रेटेन—८२२	होमरूल, आयरिश—७९१, ८२६-२७ ८३२
हेफंग—११७९	——, कानून—९८७
हेरात—७५, ८०, २१४, २६६, ३६६	——, विल—८२७, ८३०-३१, ८७९
हेलन—६६	९८४, ९८७
हेवलॉक—५९०	——लीग, हिन्दुस्तान की—९५९
हेंकन—११७५, ११७८	होमो आजजन या होमोई आजजन—१३०
हैंबर्ग—२३९, २८५, २९५	होर, सर सेम्युअल—१३१०
हैगल—७३३	होरस—१०४, १३४
हैदरअली—४६०, ४६३, ५८३	होलकर—४५८, ५८३-८४
हैदराबाद (दक्खन)—८८, ३०७, ३५९-३६५, ४६०, ५८४	ह्यूएनत्सांग—३, ५, १५६, १६८-८५, २०७, २११, २२१, ३०१, ३२१
	ह्यू कैपे—२३३, २५५, २९५
	ह्यूजीनाट—४९३
	हवाहू (हो), नदी—४६, १०४, ६९१

कुल पृष्ठ-संख्या

१४९६ + ३२ (पृष्ठ १३५८ से १३७३ तक तिथिक्रम के नक्शों में ज्यादा लगे)
= १५२८

- २४—हमारे ज़माने की गुलामी । [जन्तु : अप्राप्य] मूल्य ॥
- २५—स्त्री और पुरुष । स्त्री और पुरुष के पारस्परिक सम्बन्ध तथा ब्रह्मचर्य पर टाल्स्टाय के उत्तम विचार । मूल्य ॥
- २६—सफ़ाई । घरों, गाँवों तथा शरीर की सफ़ाई पर उत्तम पुस्तक । मूल्य ॥
- २७—क्या करें ? टाल्स्टाय की मशहूर पुस्तक What to do ? का अनुवाद । मूल्य ॥
- २८—शरीरों एवं पीड़ितों की समस्याएँ और उनका हाल । मूल्य १॥
- २९—हाथ की कतई-चुनाई । [अप्राप्य] मूल्य ॥
- २९—आत्मोपदेश । यूनान के प्रसिद्ध विचारक महात्मा एपिक्टेटस के उत्तम और महत्वपूर्ण उपदेशों का संग्रह । मूल्य ॥
- ३०—यथार्थ आदर्श जीवन । [अप्राप्य] मूल्य ॥
- ३१—जब अंग्रेज़ नहीं आये थे—तब भारत हरा-भरा था । भारत की दुर्दशा तो अंग्रेज़ों के यहां आने के बाद से शुरू हुई है । पार्लमेण्ट द्वारा नियुक्त रिपोर्ट के आधार पर लिखित । मूल्य ॥
- ३२—गंगा गोविन्दसिंह । [अप्राप्य] मूल्य ॥
- ३३—श्रीरामचरित्र । श्री० चिन्तामणि विनाशक वैद्य लिखित रामायण की कहानी । कर्ण और मधुर । मर्यादा-पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्रजी का उत्तम जीवन-चरित्र । मूल्य १॥
- ३४—आश्रम-हरिणी । पीराणिक उपन्यास । विधवा-विवाह-ममस्या पर पीराणिकों के विचार । मूल्य ॥
- ३५—हिन्दी-मराठी-कोष । मराठी भाषा-भाषियों को हिन्दी सीखने में बड़े काम की चीज़ है । मूल्य २॥
- ३६—स्वाधीनता के सिद्धान्त । आयरलैण्ड के अमर गद्दीद टिरेन्स मेक्स्विनी के Principles of Freedom का अनुवाद । आज़ादी की इच्छावालों की नसों में नया खून, नया जोश और स्फूर्ति भरने वाली पुस्तक । मूल्य ॥
- ३७—महान् मातृत्व की ओर । स्त्री-जीवन की प्रारम्भिक कठिनाइयों का दिग्दर्शन कराती हुई मातृत्व की जिम्मेदारी का दिग्दर्शन करानेवाली स्त्री-उपयोगी उत्तम पुस्तक । मूल्य ॥
- ३८—शिवाजी की योग्यता । छत्रपति शिवाजी का चरित्र-दिग्दर्शन । मूल्य ॥
- ३९—तरंगित हृदय । गुरुकुल कांगड़ी के आचार्य श्री देवगर्माजी के अनुपम विचार । मूल्य ॥

वृद्ध अच्छा प्रकाश डाला है। 'समाज-शास्त्र' पढ़नेवाले विद्यार्थियों के लिए यह अत्युत्तम ग्रन्थ है। मूल्य १।।)

१—खदर का संपत्तिशास्त्र। खादी के अर्थशास्त्र पर श्री० रिचर्ड वी० ग्रेग लिखित The Economics of Khaddar का हिन्दी अनुवाद। खादी को उपयोगिता अपने वैज्ञानिक तथा आर्थिक ढंग से सिद्ध की है। मूल्य ॥३॥

१२—गोरों का प्रभुत्व। इसमें बतलाया गया है कि संसार की सवर्ण जातियाँ अपनी आजादी के लिए किस प्रकार गोरी जातियों के शोषण से लड़ रही हैं और अपने को स्वतन्त्र कर रही हैं। मूल्य ॥३॥

१३—चीन की आवाज़। [अप्राप्य] मूल्य १७

१४—दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास। सत्याग्रह की उत्पत्ति तथा उसके प्रयोग का स्वयं गांधीजी द्वारा लिखा इतिहास पढ़ें कि किस प्रकार इस शास्त्र द्वारा अफ्रीकावासियों ने अपने अधिकारों की बहादुरी से और बिना दूसरों को तकलीफ पहुँचाते हुए रक्षा की। मूल्य १।।

१५—विजयी वारडोली। [अप्राप्य] मूल्य २)

१६—अनीति की राह पर। ब्रह्मचर्य तथा अप्राकृतिक संतति-निरोध पर लिखी गई महात्मा गांधीजी की सर्वोत्कृष्ट पुस्तक। मूल्य ॥२॥

१७—सीता की अग्नि परीक्षा। लंका विजय के बाद सीताजी की अग्नि-शुद्धि का यह वैज्ञानिक विश्लेषण है। इसमें विज्ञान का हवाला देकर यह बताया है कि वह घटना सच्ची है। मूल्य १७

१८—कन्या शिक्षा। इसमें बताया गया है कि छोटी बालिकाओं को अपने बाल्य जीवन के विषय में किस तरह शिक्षा देनी चाहिए। मूल्य १।।

१९—कर्मयोग। श्री अक्षयकुमार मंत्रेय लिखित गीता के कर्मयोग का सरल विवेचन। मूल्य १७

२०—कलवार की करतूत। महापि टाल्स्टाय की सरल भाषा में शराब के आविष्कार की मनोरंजक कहानी। मूल्य २७

२१—व्यावहारिक सभ्यता। युवकों, वृद्धों तथा अवस्थाप्राप्त लोगों के लिए रोज के व्यवहार में आनेवाली शिक्षाओं की पोथी। बोधप्रद शिक्षाप्रद तथा ज्ञानप्रद। मूल्य १।।

२२—अँधेरे में उजाला। महापि टाल्स्टाय के नाटक का अनुवाद। हृदय-मन्यन की अनुपम कहानी। मूल्य १।।

२३—स्वामीजी का बलिदान। [अप्राप्य] मूल्य १७

- ५३—युगंधर्म । [जप्त : अप्राप्य] मूल्य १=)
- ५४—स्त्री-समस्या । नारी-जीवन की जटिल समस्याओं का गम्भीर अध्ययन । मूल्य १।।।) २)
- ५५—विदेशी कपड़े का मुकाबला । प्रसिद्ध अर्थशास्त्री श्री मनमोहन गांधी लिखित । इसमें बताया गया है कि किस प्रकार भारत आनी आवश्यकतानुसार पूरा कपड़ा तैयार कर सकता है । मूल्य ॥=)
- ५६—चित्रपट । श्री शान्तिप्रसाद वर्मा के गद्य-गीतों का संग्रह । भावनामय, कर्षण और मधुर । मूल्य ॥=)
- ५७—राष्ट्रवाणी । [अप्राप्य] मूल्य ॥=)
- ५८—इंग्लैण्ड में महात्माजी । श्री महादेव देसाई का लिखा हुआ महात्मा गांधी की इंग्लैण्ड की यात्रा का सुन्दर, सरस और सुबोध वर्णन । हिन्दी में अपने ढंग का सर्वोत्तम यात्रा-वृत्तान्त । मूल्य १)
- ५९—रोटी का स्वाल । मशहूर रूसी क्रांतिकारी लेखक प्रिंस क्रोपाटकिन की अमर कृति Conquest of Bread का सरल अनुवाद । समाजवाद का सुन्दर, सरल और सुबोध विवेचन । मूल्य १)
- ६०—दैवी-सम्पद् । सर्वोत्तम नैतिक एवं धार्मिक पुस्तक । 'दैवी-सम्पद् से मनुष्य को मोक्ष होती है ।' गीता की इस उक्ति का सुन्दर विवेचन है । मनुष्य को मोक्ष का रास्ता बतानेवाली पुस्तक । मूल्य १=)
- ६१—जीवन-सूत्र । अंग्रेजी में थॉमस केम्पिस लिखित सर्व प्रसिद्ध पुस्तक 'डिमिटेशन ऑफ़ क्राइस्ट' का अनुवाद । जीवन को उन्नत और विचारों को सात्विक बनानेवाली । मूल्य ॥।।)
- ६२—हमारा कलंक । अस्पृश्यता-निवारण पर महात्माजी के विचारों एवं लेखों का संग्रह, उनके महान् उपवास की कहानी । महात्माजी के आशीर्वाद सहित । मूल्य ॥=)
- ६३—बुद्बुद् । (हरिभाऊ उपाध्याय) अपने आदर्शों से जीवन का मेल मिलानेवाले युवकों के लिए विचारणीय पुस्तक । मूल्य ॥।।)
- ६४—संधर्ष या सहयोग ? प्रिंस क्रोपाटकिन की Mutual Aid नामक पुस्तक का अनुवाद । इसमें दिखलाया है कि पशु और पक्षियों ने लेकर मनुष्य तक नदके जीवन का आधार सहयोग है; संधर्ष नहीं; एकता है, लड़ाई नहीं । मूल्य १।।।)
- ६५—गाँधी-विचार दोहन । श्री किशोरलाल घ० मगसवाल, इनमें महात्माजी के

होलैंड की राज्यक्रान्ति [नरमेध] डच-प्रजा के आत्मयज्ञ का पुनीत और रोमांचकारी इतिहास । हृदय में उथल-पुथल मचा देने वाली क्रान्तिकारी पुस्तक । मूल्य १॥)

४१—दुखी दुनिया । गरीब और पीड़ित मानवी दुनिया के करुण चित्र । चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य की सच्ची घटनाओं पर लिखी कहानियाँ । मधुर, करुण और सुन्दर । नया और सस्ता संस्करण । मूल्य १=)

४२—जिन्दा लाश । टाल्स्टाय के The Living Corpse नामक नाटक का अनुवाद । मूल्य १॥)

४३—आत्म-कथा । महात्मा गांधी लिखित । संसार के साहित्य का एक रत्न । उपनिषदों की भांति पवित्र और उपन्यासों की भांति रोचक । चरित्र को ऊँचा उठानेवाली । हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा किया गया प्रामाणिक अनुवाद । दो खण्डों में । बढ़िया जिल्द, सुन्दर छपाई । मूल्य १॥)

४४—जब अंग्रेज़ आये । [जप्त : अप्राप्य] मूल्य १॥=)

४५—जीवन-विकास । विकासवाद को विपद रूप से समझाने वाली हिन्दी की एक ही पुस्तक । मूल्य १॥) १॥)

४६—किसानों का विगुल । [जप्त : अप्राप्य] मूल्य =)

४७—फाँसी । विक्टर ह्यूगो लिखित । फाँसी की सज़ा पाये हुए एक युवक के मनोभावों का चित्रण । करुण और रलानेवाला । मूल्य १=)

४८—अनासक्तियोग और गीता-बोध । गीता पर गांधीजी की व्याख्या । मूल श्लोक, अनुवाद तथा महात्माजी के गीता के तात्पर्य—गीताबोध—सहित ३५० पृष्ठों में मूल्य केवल १=) केवल अनासक्तियोग =), सजिल्द १) गीताबोध -)॥

४९—स्वर्ण विहान [जप्त : अप्राप्य] मूल्य १=)

५०—मराठों का उत्थान और पतन । मराठा साम्राज्य का विस्तृत और सच्चा इतिहास । मराठी इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान श्री गो० दा० तामसकर लिखित । मराठी भाषा में भी मराठों का ऐसा इतिहास नहीं है । मूल्य २॥)

५१—भाई के पत्र । स्त्री-जीवन पर प्रकाश डालने वाली, उनकी घरेलू एवं रोजमर्रा की कठिनाई में पथप्रदर्शक बहनों के हाथों में दिये जाने योग्य एक ही पुस्तक । अपनी बहनों, बहुओं और बेटियों को इसकी एक प्रति अवश्य दें । मूल्य १॥) २)

५२—स्वगत । (हरिभाऊ उपाध्याय) चरित्र को गढ़नेवाले उच्च तथा युवकों को सच्चा रास्ता दिखानेवाले उत्तम विचार । मूल्य १=)

दुनिया का इतिहास बड़ी सरलता से बताया है । हिन्दी साहित्य का एक बेजोड़ ग्रन्थ । दो भागों में ।

मूल्य ८)

७५—हमारे किसानों का सशल । भूमिका लेखक पण्डित जवाहरलाल नेहरू । ले० डॉ० अहमद । इसमें हमारे गरीब किसानों के सवाल और उसके हल को बहुत अच्छी तरह समझाया गया है ।

मूल्य केवल १)

आगे प्रकाशित होनेवाले ग्रन्थ

१—गांधीवाद : समाजवाद—सम्पादक आचार्य काका कालेलकर ।

२—विनाश या इलाज—ले० म्यूरियल लिस्टर ।

३—गीता-मंथन—ले० किशोरलाल मशरूवाला ।

४—राजनीति का परिचय—ले० हेराल्ड लास्की ।

५—जब से अंग्रेज आये—ले० डॉ० अहमद ।

६—महाभारत के पात्र (५ भागों में)—ले० नानाभाई ।

७—संतवाणी—वियोगी हरि ।

८—गांधी साहित्य माला । (१५ भागों में)

९—भारत का नया शासन-विधान ।

(प्रांतीय स्वराज्य)—ले० हरिश्चन्द्र गोयल

१०—हमारे गाँवों की कहानी—ले० स्व० रामदास जोशी ।

~~१७~~—**सागर राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक एवं नैतिक विचारों का बड़ा सुन्दर दोहन किया है।** मूल्य ॥१॥

६६—**एशिया की क्रान्ति।** [जूवत : अप्राप्य] मूल्य १॥१॥

६७—**हमारे राष्ट्र-निर्माता।** लो० तिलक, स्व० मोतीलालजी, मालवीयजी, महात्मा जी, दास बाबू, जवाहरलालजी, मौ० मुहम्मदअली, सरदार और प्रेसिडेंट पटेल की जीवनियाँ—उनके संस्मरण, जीवन की झाँकियाँ एवं व्यक्तित्व के विश्लेषण के साथ—लिखी गई हैं। हिन्दी में अपने क्रिस्म की एक पुस्तक, मूल्य २॥१॥ ३॥

६८—**स्वतन्त्रता की ओर—**(हरिभाऊ उपाध्याय) इसमें बताया गया है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है ? हम उस लक्ष्य—स्वतन्त्रता—को किस प्रकार और किन साधनों से प्राप्त कर सकते हैं। हमारा समाज कैसा हो; हमारा साहित्य कैसा हो, हमारा जीवन कैसा बने जिससे हम स्वतन्त्रता की ओर बढ़ते चले जाते। हिन्दी में इस पुस्तक का बड़ा आदर हुआ है। मूल्य १॥१॥

६९—**आगे बढ़ो।** स्वेट् मार्टेन के Pushing to the Front का संक्षिप्त अनुवाद। कठिनाई में पड़े युवकों को सच्चे साथी के समान रास्ता बतानेवाली। मूल्य ॥१॥

७०—**बुद्ध-व्राणी।** (वियोगीहरि) भगवान् बुद्ध के चुने हुए वचनों का संग्रह। बुद्धधर्म का सार तत्त्व। बौद्ध-धर्म के हिन्दी में मिले सब ग्रन्थों का सार। मूल्य ॥२॥

७१—**काँग्रेस का इतिहास।** डॉ० पट्टाभिषीतारामैया की लिखी तथा काँग्रेस की स्वर्ण-जयन्ती पर प्रकाशित अंग्रेजी पुस्तक History of the Congress का यह प्रामाणिक अनुवाद है। इसकी भूमिका राष्ट्रपति श्री राजेन्द्र बाबू ने लिखी है। हिन्दी अनुवाद तथा संपादन श्री हरिभाऊ उपाध्याय ने किया है। यह दूसरा संस्करण है। बड़े आकार के ६५० पृष्ठों की सजिल्द पुस्तक। मूल्य केवल २॥१॥

७२—**हमारे राष्ट्रपति।** काँग्रेस के पहले अधिवेशन से अवतक के तमाम सभापतियों के जीवन-परिचय संक्षेप में इस पुस्तक में दे दिये गये हैं। हिन्दी में अपने विषय की यह उत्तम तथा एक-मात्र पुस्तक है। इसकी भूमिका श्री राजेन्द्र बाबू ने लिखी है। सब सभापतियों के चित्रों के साथ, पृष्ठ संख्या ४०० मूल्य १॥

७३—**मेरी कहानी।** पं० जवाहरलाल नेहरू की आत्म-कथा। हिन्दी अनुवाद और संपादन हरिभाऊ उपाध्याय ने किया है। इस पुस्तक के प्रकाशित होने से हिन्दी और अंग्रेजी साहित्य में एक जीवन पैदा हो गया है। वर्तमान समय की एक ही पुस्तक। बड़े आकार में, पृष्ठ—संख्या ७७५। सजिल्द मूल्य ४॥

७४—**विश्व-इतिहास की झलक।** पण्डित जवाहरलालजी के अपनी पुत्री इंदिरा के नाम लिखे पत्रों का संग्रह। इसमें १९६ पत्र हैं और इसमें उन्होंने सारी

